

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two
weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

अर्थशास्त्र का दिग्दर्शन

(भारतीय अर्थशास्त्र सहित)

इंटरमीडियेट, हायर सेकेण्डरी तथा प्रिवैरैटरी या प्रो-यूनिवर्सिटी स्टाटम एव
एग्रीकल्चर परीक्षाओं के लिये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
दिल्ली, अजमेर, पश्चिमी बंगाल आदि परीक्षा बोर्डों,
राजस्थान सागर, नागपुर, जबलपुर, बिहार-पटना आदि
विश्वविद्यालयों के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार

लेखक

प्रो० जी० एल० जोशी एम० ए०, एम० काम०

एफ० आर० ई० एस० (सन्दन)

अध्यक्ष

स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग,

दयानन्द कॉलेज, अजमेर

द्वितीय सज्जीधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

आगरा बुक स्टोर

प्रकाशक, विक्रेता एवं मुद्रक

आगरा
मेरठ

अजमेर
दिल्ली

इलाहाबाद
लखनऊ

कानपुर
वाराणसी

नागपुर
पटना

प्रकाशक—
आगरा बुक स्टोर,
राबतपाडा, आगरा ।

तृतीय संस्करण १९६१

मूल्य आठ रुपये

Printed on paper of
The Titagbur Paper Mills Co Ltd Calcutta
Supplied by
Mr Gopinath Bhargava Branch Sales Manager Delhi

मुद्रक—
शिव नारायण माहेश्वरी
अग्रवाल प्रेस, आगरा ।

तृतीय संस्करण की भूमिका

पाठकों के समस्त 'अर्थशास्त्र का दिग्दर्शन' का यह नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस संस्करण में कई अध्याय नये सिरे से लिखे गये हैं। पाप सामग्री को पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्द्धित का नवीनतम तथ्यो एवं मौनको से सुसज्जित कर दिया है। इस संस्करण में अनेक नवीन चित्र, चार्ट, नक्शे आदि जोड़ दिये गये हैं जिसमें विषय सरल एवं बोधगम्य हो गया है।

प्राशा है यह नवीन संस्करण विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को अधिक लाभप्रद एवं उपादेय सिद्ध होगा।

सन्नेर
११ जनवरी, १९६१}

जी० एल० जोशी
लेखक

प्रथम संस्करण की भूमिका

देश की वस्तुमूँची उन्नति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भावी सन्तति का निष्काप भी बहुमिधि हो। जहाँ उसके शारीरिक गठन और चरित्र निर्माण की आवश्यकता है वहाँ उसके मस्तिष्क के विकास के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा भी आवश्यक है। इन शिक्षाओं में अर्थशास्त्र की शिक्षा का महत्त्व कहीं अधिक उपयोगी है। आज जो देश इस शिक्षा से परिपूर्ण है उनका राष्ट्र उतना ही उन्नत और अग्रणी बन रहा है। इंग्लैंड ने इसी के आधार पर मसार के एक बड़े भू भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अमेरिका ने भी इसी के बल से मसार में अपनी महत्ता स्थापित कर रखी है। अतः यह परमावश्यक है कि स्वतन्त्र भारत के भावी नागरिक भी इस शिक्षा से पूर्ण लाभ उठाकर अपने देश को एशिया का ही नहीं, मसार का नया बनाएँ।

भारतवर्ष एक निर्धन देश है। यहाँ करोड़ों देशवासियों को कठिन परिश्रम करने पर भी भर-पेट भोजन नहीं मिल पाता और न उनको पक्का कपड़ा ही मिल पाते हैं। यहाँ समय-समय पर दुर्भिक्ष का आरम्भ होता रहता है। विचारों की व्यापक व्यवस्था के अभाव में यहाँ का कृषि-उद्योग 'बपा का जुआ' बना हुआ है। औद्योगिक दृष्टि में देश कितना पिछड़ा हुआ है यह बात किसी ने छिपी हुई नहीं है। देश व्याप्त निर्धनता ही इस पतित अवस्था का मुख्य कारण है। अस्तु, देश की निर्धनता दूर करने के लिए, देशवासियों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए तथा देश के आर्थिक विकास के लिए, जिनमें अर्थशास्त्र के ज्ञान के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु यह कार्य हम कैसे ? अर्थशास्त्र की उत्तम पुस्तकों का प्रसार अंग्रेजी में है। भारतवर्ष में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम है तथा और भी कम हो रही है। अतः अंग्रेजी में

विषय-सूची

पृष्ठ

गद्या

विषय-प्रवेश

१-विषय परिचय	१
२-अर्थशास्त्र का विज्ञानात्मक एवं नैतिक दृष्टिकोण	१४
३-अर्थशास्त्र का क्षेत्र	१६
४-अर्थशास्त्र के विभाग और उसका पारस्परिक सम्बन्ध	२३
५-अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध	२६
६-अर्थशास्त्र के नियम	३७
७-अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व	४५
८-आधुनिक जीवन का विकास	५४
९-कुछ पारिभाषिक शब्द	६८
१०-यह या नहीं	७६

उपभोग

११-उपभोग का अर्थ	८१
१२-आवश्यकताएं	८६
१३-आवश्यकताओं का वर्गीकरण	११६
१४-उपभोग के नियम—उपयोगिता, हानि, समय	१२६
१५-सम-सामान्य उपभोगिता नियम	१३८
१६-उपभोक्ता की वृत्ति	१४७
१७-जीवन स्तर	१५४
१८-आय, व्यय और वृत्ति	१६४
१९-वित्तीयताएं और अव्यय	१७५
२०-पारिवारिक बजट (आय-व्यय)	१८१

उत्पत्ति

२१-उत्पत्ति—अर्थ, महत्व, उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति की कार्यक्षमता	१९५
२२-भूमि—अर्थ, विशेषताएं, महत्व, कार्यक्षमता, ऐसी करने की विविध रीतियां भूमि की गतिशीलता	२०४
२३-उत्पत्ति के नियम—उत्पत्ति-हानि नियम, उत्पत्ति-वृद्धि-नियम और उत्पत्ति स्थिर नियम	२१२

अध्याय

२४—भारतवर्ष के प्राकृतिक साधन— भारतवर्ष की स्थिति,
प्राकृतिक या भौगोलिक विभाग भूमि, भूमि की सम्पत्ति—
भूमि का कटाव, भूमि ग्रान्ति, भारतवर्ष की जलवायु—
व्याधिक प्रभाव, जनवृष्टि मानसून

२५—भारतवर्ष के वन

२६—भारतवर्ष की कृषि सम्पत्ति

२७—भारतवर्ष में सिंचाई

२८—क्षेत्र विभाजन एवं भूखण्डन

२९—भारत की खनिज सम्पत्ति

३०—भारतवर्ष में शक्ति के साधन

३१—धम

३२—जनसंख्या

३३—भारतवर्ष की जनसंख्या

३४—धम की कार्य-कुशलता

३५—धम की गतिशीलता

३६—पूँजी ...

३७—मशीन का उपयोग ...

३८—संगठन ...

३९—धम विभाजन

४०—उद्योगों का स्थानीयकरण

४१—उत्पत्ति का परिमाण -

४२—व्यवसाय संगठन के रूप

४३—गाहक

४४—भारतवर्ष में लघु एवं कुटीर उद्योग

४५—भारतवर्ष में बृहद् उद्योग

विनिमय

४६—विनिमय

४७—मण्डी अथवा बाजार (प्रियाणि)

४८—भोंग और पूर्ति

४९—मूल्य निर्धारण

५०—मुद्रा

अध्याय

कुल संख्या

११—मुद्रा का गान, प्रेशम का नियम, मुद्रा का परिमाण	
सिद्धान्त, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन	६०८
१२—भारतीय चलन प्रणाली	६१८
१३—घास एवं साय पत्र	६१९
१४—घैस और बेकिंग प्रणाली	६७१
१५—ग्राम्य ऋण प्रस्तुता	७१०
१६—सहकारिता आन्दोलन	७२०
१७—वालावात	७४६
१८—नारत का व्यापार	७७८

वित्त

१९—वितरण की समस्या	७६५
२०—लगाव	८०७
२१—भारत में भू धारण पद्धति एवं मानगुजारी प्रथा	८३१
२२—मजदूरी (भुति)	८५१
२३—व्याज	८८२
२४—लाभ	९०५

राजस्व

२५—राजस्व और कर	९२३
२६—भारत में वैदेशीय राजस्व	९४३
२७—भारत में राजस्व का राजस्व	९४६
२८—भारत में स्थानीय राजस्व	९६८

आर्थिक नियोजन

२९—भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, माधुदायिन योजनाएं	
महान् गन्तव्य, मन्त्रिमण्डल, मन्त्रिमण्डल	९६९
३०—भारत में दण्डमाला प्रणाली, मीटर प्रणाली के नए बाट	
और पंमाने	१०११
परिगिष्ट १—मिकरी की परिवर्तन तात्त्विक	१०१७
परिगिष्ट २—तोल परिवर्तन तात्त्विक	१०१८

विषय परिचय (INTRODUCTION)

अर्थशास्त्र का परिचय

जिसी नवीन विषय को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके विषय में परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता एवं इच्छा पाठकों में प्रायः देखी जाती है। अतः वही उत्सुकता अर्थशास्त्र के विषय में परिचय प्राप्त करने के लिये भी होना स्वाभाविक है। विषय परिचय के पूर्व इस बात को जानने की उत्कृष्ट सहज उत्पन्न हो जाती है कि यह क्या विषय है और इसमें किन किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर ढूँढ़ निकालने के लिए यदि हम अपनी दृष्टि मनुष्य के दैनिक कार्यों पर डालें तो हमें मरलता से ज्ञात होगा कि वह प्रातःकाल में सायंकाल पर्यन्त धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, परोपकार और धनोपार्जन सम्बन्धी व्यवसाय आदि विविध कार्यों में मग्न रहता है। अर्थात् जब वह मन्दिर जाता है तो धार्मिक कार्य करता है, म्युनिमिपल बोर्ड के अधिवेशन में उनकी बायेंवाही में हचिपूर्वक भाग ले, तब नागरिक अथवा राजनीतिक कार्य सम्पादित करता हुआ रागभरा जाता है। इसी प्रकार जब वह उद्योग-शाला, कार्यालय अथवा किसी व्यापारिक स्थान में जाकर जीवन यापन करता है, तो आर्थिक कार्यों में व्यस्त समझा जाता है। भूकम्प, बाढ़, दुर्भिक्ष आदि आपत्तियाँ में जन-समाज को रक्षा करने, भय, धूम्रपान आदि व्यसनों से होने वाली हानियों के प्रति मनुष्य को सतर्क करने में जब साहसी, धीर-वीर वर अपना साधन और समय लगाने हैं, तब वे सामाजिक कार्य करते हुए कहे जाते हैं।

उपरोक्त नाना प्रकार के कार्यों का विवेचन एवं विशिष्ट प्रकार के शास्त्र में किया जाता है, जैसे धर्म सम्बन्धी बातों का विवेचन धर्म शास्त्र (Theology) में और राजनीति सम्बन्धी कार्यों का राजनीति शास्त्र (Political Science) में उल्लेख होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन-यापन सम्बन्धी समस्त क्रियाओं, व्यवहारों और उनके साधनों का विवेचन एक विशिष्ट प्रकार के शास्त्र में जिसको 'अर्थशास्त्र' (Economics) के नाम से सम्बोधित करते हैं, किया जाता है। दूसरे शब्दों में या कहना चाहिए कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत मनुष्य के धन-सम्बन्धी प्रयत्नों और निदानों का विवेचन होता है। मनुष्य भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से धनोपार्जन में प्रयत्नशील रहता है और फिर उस उपार्जित धन का किस प्रकार उपभोग करता है, इन बातों का ज्ञान अर्थशास्त्र का अध्ययन कराता है।

संक्षेप में, अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन का सर्वांगीण अध्ययन न होकर केवल उसके एक भाग मान का अध्ययन है, अर्थात् यह उसकी केवल आर्थिक क्रियाओं पर ही प्रकाश डालता है। उसके दैनिक जीवन की अन्य प्रकार की क्रियाओं का विवेचन अन्य विशिष्ट प्रकार के शास्त्रों में किया जाता है।

आर्थिक जीवन का मूल आधार (Basis of Economic Life)

आर्थिक जीवन का आधार मनुष्य की विविध आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के लिए साधनों का समूह ही है। उदाहरणार्थ, उनकी भोजन की आवश्यकता उसे इस बात के लिये बाध्य करती है कि वह धान पैदा करे। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाओं का अस्तित्व मनुष्य की आवश्यकताओं पर ही निर्भर है। यदि मनुष्य आवश्यकता धून्य हो जाय, तो निःसन्देह उसका जीवन भी क्रिया धून्य हो जायगा। गमरत मानव-जगत् को निरन्तर क्रियाशील रखने वाली वस्तु 'आवश्यकता' (Wants) है। इस प्रकार सर्वसाधन का सम्पूर्ण ढाँचा आवश्यकताओं पर ही स्थिर है।

आर्थिक प्रयत्न (Economic Activities)—उत्पत्ति विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ न कुछ प्रयत्न आवश्यक करने पड़ते हैं, और प्रयत्नों को मुनाफ़ा रूप से क्रियात्मक बनाने के लिए उसे सभी साधन जुटाने होंगे। भौतिक गुप्त की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न धनोपार्जन कहाने में समर्थ हैं तथा जिन साधनों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सर्वसाधन में उन्हें 'आर्थिक प्रयत्न' (Economic Activities) कहते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नकार यदि मनोरंजन के उद्देश्य में रहित होकर अर्थप्राप्ति के लिए चित्र बनाता है तो वह उसकी 'आर्थिक क्रिया' (Economic Activity) है। इसी प्रकार अन्य प्रयत्नों में भी यह भेद प्रकट किया जा सकता है।

आर्थिक प्रयोजन (Economic Motive)—प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन में सम्पन्न किया जाता है। विद्यार्थी खेल कूद में भाग आनन्द-प्रमोद के लिए लेते हैं। श्रमिक दिन भर उद्योगशाला (Workshop) में जीवन यात्रा के साधन धन की प्राप्ति के लिए व्यस्त रहता है। इसी प्रकार बड़े परिश्रम के साथ धन उपजाने में लगान रहता है। प्रथम उदाहरण में प्रमोद प्रमोद एक मनोरंजन कार्य सम्पन्नता का मुख्य कारण है और दोपे दो में अर्थोपार्जन मुख्य उद्देश्य है। अतः अर्थोपार्जन उद्देश्य वाली क्रियाओं की सम्पन्नता 'आर्थिक प्रयोजन' (Economic Motive) कहलाती है और जिन कार्यों के पीछे 'आर्थिक-प्रयोजन' होता है उनको हम 'आर्थिक-प्रयत्न' कहते हैं।

आवश्यकताओं और प्रयत्नों का पारस्परिक सम्बन्ध

आवश्यकताओं और प्रयत्नों के मध्य एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। अन्य जीव-धारियों की भाँति ही मनुष्य की भी कुछ आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें पूरा किये बिना वह जीवित नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, मनुष्य का खाने के लिए भोजन, शरीर रक्षा के लिये वस्त्र, साँस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी और रहने के लिये मकान आदि। इन आवश्यकताओं पर मनुष्य का जीवन स्थिर है, अतः इन्हें 'प्राथमिक आवश्यकताएँ' (Primary Wants) अथवा 'अनिवार्य आवश्यकताएँ' (Necessaries of Life) कहते हैं। किन्तु मानवीय प्रयत्न इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि तक ही सीमित नहीं है। वह आगे बढ़ता है और 'सुख-वस्तुओं' (Comforts) की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है। इनके पश्चात् 'विलास-वस्तुओं' (Luxuries) की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार आवश्यकताएँ उत्तरात्तर बढ़ती ही जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी पूर्ति के साधन पिड़्ड जाते हैं।

स्वल्प साधन और असीमित आवश्यकताएँ (Scarce Means and Unlimited Wants)—हम देखने हैं कि हमारी आवश्यकताएँ बहुत हैं और उनमें प्रतिदिन वृद्धि हो होती जाती है। उनकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन समय और शक्ति पूर्ण अथवा पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे प्रकृति में प्राप्त होती हैं। प्रकृति-दत्त कुछ वस्तुएँ तो ससार में इतनी प्रचुरता में दृष्टिगोचर होती हैं कि उनके प्राप्त करने के लिए न तो कोई प्रयत्न करना पड़ता है और न कुछ ग्यय ही उदाहरणार्थ वायु, जल, धूप, और प्रकाश आदि ऐसी वस्तुओं की 'निःशुल्क प्रकृति-दत्त वपार्थ' (Free Gifts of Nature) कहते हैं। प्रकृति की यह उदारता केवल कुछ ही वस्तुओं तक सीमित है। अन्य वस्तुओं की प्रकृति उस समय तक नहीं देती जब तक मनुष्य उनके लिए प्रयत्न नहीं करता। ऐसी श्रम साध्य वस्तुएँ मूल्यवान होने के कारण 'धन', 'अर्थ' या 'सम्पत्ति' के (wealth) नाम से कही जाती हैं। मानव जीवन जो स्थिर रखने और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसी के ही प्रभाव से राज समस्त भूमंडल क्रियाशील है।

अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव एवं विकास—अर्थशास्त्र बहुत प्राचीन है। इसका प्रादुर्भाव स्व से प्रथम भारतावर्ष में हुआ। सभ्यता दो हजार तीन सौ वर्ष पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र तीर्थ के शासन काल में आचार्य कौटिल्य ने इस विषय पर समार के समुदाय सर्व प्रथम एक अलम्ब्य अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया जो अब भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से सुविख्यात है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे पूर्व भारतावर्ष में अर्थशास्त्र का अस्तित्व नहीं था। आचार्य बृहस्पति, शुक्र, उशनस, अगिरस, बाहुदन्तिपुत्र आदि अनेक अर्थशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान प्राचीन भारत में इनमें भी पूर्व हो चुके हैं। अर्थ सम्बन्धी मानवीय भौतिक गुण के निमित्त जो विवेचन वेद, स्मृतियों आदि ग्रन्थों में मिलता है वह इस बात की शोषित करता है कि अर्थशास्त्र का विषय इस देश में अति प्राचीन काल से विद्यमान है, जबकि वर्तमान उन्नत देशों में सम्मता का प्रारम्भ भी न हुआ था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थ सम्बन्धी विषयों के अतिरिक्त कतिपय अन्य विषयों पर भी जैसे शासन तथा मत्त-व्यवस्था, गुप्तचर तथा गुप्तिस प्रबन्ध राजाओं के कर्त्तव्य, न्यायपालन का प्रबन्ध, नगर-व्यवस्था, धन-विधि, गाँवों की बसावट, कुपि, पशुपालन, विविध शैलियों के कुर्गों के निर्माण आदि आदि विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। अतः हमसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र विषय द्रव्य व्यापक था। वह इतना सुचिन्तित नहीं था जितना आधुनिक अर्थशास्त्र। इसी आधार पर प्राचीन तथा मध्यकालीन पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने भी इसे 'राजनैतिक-अर्थशास्त्र' अथवा 'राष्ट्रीय वित्तव्यवस्थाशास्त्र' (Political Economy) कह कर पुकारा है। आज जिस रूप में हम अर्थशास्त्र प्राप्त हैं उसका विकास सबसे पहले पाश्चात्य देशों में, विशेषतया, इंग्लैंड में हुआ।

अर्थशास्त्र की कुछ वर्तमान प्रचलित परिभाषाएँ

(१) प्रो० मार्शल की परिभाषा—इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल (A. Marshall) की परिभाषा अत्यन्त लोकप्रिय है। वे अर्थशास्त्र की निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं :—

"अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है, यह इस बात का विवेचन करता है कि वह किस प्रकार धनोपायन करता

है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है " " " "। इन प्रकार यह एक और धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।¹

(२) प्रो० एली की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के धन की आपूर्ति और निर्यात सम्बन्धी क्रियाओं का सामाजिक घटनाओं की दृष्टि में वर्णन करता है।”²

(३) डा० फेयरचाइल्ड की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा भौतिक साधन सम्पन्न मनुष्य संश्लेषित होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त ज्ञान प्राप्त करता है।”³

(४) डा० केनन की परिभाषा—“अर्थशास्त्र भौतिक सुख अर्थात् मनुष्य की भौतिक समृद्धि के कारण का अध्ययन है।”⁴

(५) डा० सीमर की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानवीय प्रयत्नों के उस भाग का विवेचन होता है जिसका जीविकोपार्जन से सम्बन्ध है।”⁵

✓ (६) प्रो० वेंपमैन की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के कर्मान और खर्च करने की क्रियाओं का अध्ययन करता है।”⁶

(७) डा० रिचार्ड की परिभाषा—“अर्थशास्त्र हमारे आवश्यकताओं, क्रियाओं तथा संतुष्टि का अर्थात् जीवन की व्यपार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन करता है।”⁷

1—“Economics is the study of man's actions in the ordinary business of life, it enquires how he get his income and how he uses it . . . Thus it is on the one side a study of wealth and on the other, and more important side, a part of the study of man ”—

—Marshall

2—“Economics is the science which treats of those social phenomena that are due to the wealth getting and spending activities,”

—Ely

3—“Economics is the science of man's activities devoted to obtaining the material means for the satisfaction of his wants ”

—Fairchild

4—“Economics is a study of the causes of material welfare.

—Cannan

5—“Economics is the social science which treats of that portion of human activity which is concerned with making a living ”

—Seager

6—“Economics is the science which studies the wealth-earning and wealth spending activities of human beings

✓ —Chapman

7—“Economics deals with our wants, our efforts and our satisfactions—with our activities in the business of life ”

—Rich⁸

(८) प्रो० पेन्सन की परिभाषा—“अर्थशास्त्र भौतिक गुण का विज्ञान है।”⁸

(९) प्रो० पीगू की परिभाषा—“अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण का वह भाग है जिसका मुद्रा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापदण्ड से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।”⁹

परिभाषाओं की व्याख्या—उपरोक्त विविध परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन की अर्थ-सम्बन्धी क्रियाओं का सामाजिक दृष्टि से अध्ययन है।

इन परिभाषाओं का बिस्तेरण करत में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हन है —

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन के आधारण व्यवसाय में सम्बन्ध रखता है न कि असाधारण व्यवसाय से, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि असाधारण व्यवसाय से क्या तात्पर्य है ?

(२) हमने अतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं का ही विवेचन होना है न कि अनार्थिक क्रियाओं का।

(३) मनुष्य के सामाजिक जीवन को प्रकट करता है, अर्थात् इसमें मनुष्य का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में न होकर सामाजिक दृष्टि से होता है।

(४) अर्थशास्त्र मनुष्य और धन दोनों का ही अध्ययन है परन्तु हमें प्रमुखता मनुष्य को ही देखना है न कि धन को। धन का अध्ययन मनुष्य के आर्थिक कल्याण का एक भाग मान्य होने के कारण ही किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव का आर्थिक कल्याण है।

इन आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों ने प्रधानता मनुष्य को दी है और धन को गौण रखा है। प्रो० पेन्सन ने शब्दों में अर्थशास्त्र का आरम्भ और अन्त मनुष्य ही है न कि धन या धन जो कि आरम्भ और अन्त के मध्य में आने वाले मनुष्य के पात उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र है।

प्रो० मार्शल की परिभाषा की आलोचना—प्रो० मार्शल द्वारा प्रस्तावित अर्थशास्त्र की परिभाषा का काफी समय तक बोल बाला रहा। यह परिभाषा पूर्ण तथा वैज्ञानिक मानी जाने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में कोई मतभेद भविष्य में भी पैदा न होगा। इस तथ्य के अनुसार कि, अर्थशास्त्र की परिभाषा समय और परिस्थिति के साथ बदलती रही है, कुछ अर्थ-शास्त्रियों ने इस परिभाषा पर भी अमन्ताप प्रकट किया और इसके विपरीत अपने विचार प्रकट किए। इन आलोचकों में से सर्वप्रथम अर्थशास्त्र विचारधारा (London School of Economics) के प्रोफेसर रॉबिन्स प्रथम हैं। इन्होंने मार्शल की परिभाषा पर सीधा आक्रमण किया और उनकी अनेक त्रुटियों को धारा से निकाला जो निम्नलिखित हैं :—

8—“Economics is the science of material welfare” —Penson

9—“Economics is a study of economic welfare, economic welfare being described as that part of welfare which can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money” —Pigou

(१) प्रा० मार्शल ने माध्यम्य जीवन में व्यवहार सम्बन्धी क्रियाओं को तो अर्थशास्त्र के अन्तर्गत न माना है, परन्तु अन्तर्गत व्यवसाय सम्बन्धी क्रियाओं का स्थान न उन में दूना ही है। क्या बुद्धिमत्त्वपूर्ण व्यवसायिक क्रियाओं का इनमें समावेश नहीं होना ?

(२) यह परिभाषा भौतिकता के जान में पड़ती हुई है। क्या उन मान्य में अर्थशास्त्र के अन्तर्गत व्यवसाय की क्वालिटी (Goodwill), रेवाय, आदि का सम्बन्ध नहीं होता ?

(३) इसमें मानवीय क्रियाओं को आर्थिक और अ-आर्थिक मार्गों में विभक्त करना दूना ही है। क्या दान, धर्म की क्रिया अ-आर्थिक होना ही है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में धन में सम्बन्धित नहीं है ?

(४) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के अन्तर्गत वास्तविक मानव जीवन का अन्वेषण करना है। किन्तु अर्थशास्त्र तो विज्ञान है जिसे शिष्ट-मनस्क और नैतिक धर्मात्मिक बातों से बाँटा सम्बन्ध नहीं। इसमें तो शिष्ट-मनस्क जैसे दान, धर्म, न्याय आदि तथा शान्तिवाचक वस्तुओं जैसे अफीम, मरिचा आदि दोनों प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है।

(१०) प्रो० रॉबिन्स की परिभाषा—यह हम प्रो० रॉबिन्स की इस परिभाषा का विश्लेषण करने हैं जिसमें वर्तमान अर्थशास्त्र के पंडितों की धारणाओं में उल्लेख-मुक्त सब कर दिया है और जिसमें अतिव्यापक अर्थशास्त्री अनुयायी भी होते जा रहे हैं। वे अर्थशास्त्र का निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं :—

"अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जो मनुष्य और स्वयं मनुष्यों के बीच के सम्बन्धों की दृष्टि में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है।"¹

उपरोक्त परिभाषा में प्रो० रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है, जिसमें मनुष्य, मौसम, समय और मनुष्यों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करना है, यह बताया जाता है कि अधिकतम मात्रा की दृष्टि में मौसम, समय और स्वयं-मानव का उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसे एक उदाहरण में समझ लेना चाहिए। मनुष्य अपनी इच्छा में २४ घण्टों में पढ़ना-लिखना, खाना-पकवान, धोना-धोना, बिना सोया जाता आदि कार्य करता है। इसी प्रकार वह अपनी शक्ति का उपयोग खाने, पीने, सुने, दान-पूजा करने आदि बातों में करता है, परन्तु मनुष्य की शक्ति उसका समय और उसकी शक्ति मौसम है, इसलिए वह उन बातों में से जो अधिकतम लाभकारी और आवश्यक है, उनका सर्वप्रथम उपयोग करता है। जितना जितना अनुपात में उसका काम और आवश्यकताओं के अनुसार करना है, उतना उपयोग करता है उतना ही उत्तमतर वीर्य करना पाया जाता है।

प्रो० रॉबिन्स की परिभाषा के लिये

(१) असीमित आवश्यकताएँ (Unlimited Wants)—अर्थशास्त्र की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएँ (Wants) अनेक प्रकार की होती हैं और उनकी पूर्ति के लिये सीमित हैं। दान, अफीम, मरिचा, दवा, मनुष्य की शक्ति, समय, धन, आदि सीमित हैं।

10.—Economics studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses

—Robbins

(२) स्वल्प साधन (Scarce Means)—हमारी प्रसीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे साधन स्वल्प और सीमित हैं। यदि हमसे अधिक वस्तुएँ बचेष्ट परिणाम में मिल सक, तो हमारे समस्त आर्थिक गणन्याएँ गलत हो जावगी।

(३) स्वल्प साधनों का वैकल्पिक उपयोग (Alternative Uses)—स्वल्प साधनों का अनेक प्रकार से उपयोग होने के कारण उनकी मूल्यता की ओर भी अधिक अनुभव होता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का बिस्तृत सीमित उपयोग हो तो वे आर्थिक समन्याएँ उत्पन्न ही न हवगी।

प्रो० मार्शल और प्रो० रॉबिन्स की परिभाषाओं पर तुलनात्मक दृष्टि

मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में विशेष अन्तर नहीं है। (स्वल्प-साधन' (Scarce Means) का अर्थ धन या सम्पत्ति से है और साधन (Ends) मानवीय सृष्टि अर्थात् आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है।

(१) प्रो० मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त है और प्रो० रॉबिन्स की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टि से।

(२) प्रो० मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक व असाधक क्रियाओं में विभक्त कर दिया है, परन्तु प्रो० रॉबिन्स ने इस प्रकार का भेद नहीं किया है।

(३) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, परन्तु प्रो० रॉबिन्स के अनुसार प्रत्येक क्रिया के आर्थिक पहलू (Economic Aspect) का अध्ययन किया जाता है।

(४) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, सामान्य तथा वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, परन्तु रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य मात्र का अध्ययन किया जाता है।

(५) मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के वैयक्तिक सामान्य आचरण का अध्ययन किया जाता है, परन्तु रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य के उन सभी आचरणों का अध्ययन किया जाता है जिनका उद्देश्य सीमित साधनों का प्रसीमित साधन पर प्रयोग करना होता है।

(६) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र न केवल एक वास्तविक विज्ञान ही है, बल्कि यह एक सीधे प्रधान विज्ञान तथा कला भी है। इस शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान-वृद्धि के लिए ही नहीं अपितु लाभ प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। प्रो० रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है और केवल ज्ञान-वृद्धि ही इसके अध्ययन का उद्देश्य है।

रॉबिन्स की परिभाषा पर आलोचनात्मक दृष्टि—(१) रॉबिन्स की परिभाषा के अन्तर्गत सभी कार्य आ जाने हैं जिनमें समता क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। यह परिभाषा इसकी व्यापक है कि इसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्य का विवेचन चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक क्या न हो अर्थशास्त्र में समाविष्ट हो जाता है।

(२) इस परिभाषा में धन की जो सभी आर्थिक कार्यों का माप दंड है, पृथक् कर दिया है। स्वल्प साधन धन का स्थान नहीं ले सकते हैं। वे व्यभिचर हो सकते हैं और इसलिये वे अविनिमेय हैं। अतः अर्थ विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। परन्तु इस अपने अपने बिस्तृत क्षेत्र में सीमा नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी समस्या में अपने माप-दण्ड को स्थान में ले लिये सक्षम नहीं हैं।

(३) उमम यह स्पष्ट नहीं है कि माध्य का धर्म तात्कालिक साध्य से है या अन्तिम साध्य से ।

(४) गैरिजम की परिभाषा की एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान माना है । उममे केवल उन्हीं परिस्थितियों का विवेचन हुआ है जहाँ कार्य कारण का सम्बन्ध प्रस्ट करता है । उन परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होता चाहिए और इसकी क्या गैतियाँ हैं, इन सम्बन्धों विषयों पर विचार उमम नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सब कार्य विज्ञान के क्षेत्र में पर हैं ।

(५) अर्थशास्त्र में 'मार्ग प्रदर्शन' उमका एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और इसी भाग का गणितीय की परिभाषा में समाज जना उमको एक भारी प्रभुगति मिल्द करता है । इसी न्यूनता के कारण रोजिन् की दृष्टि में अर्थशास्त्र का यह धर्म जन्ता के लिये लाभकारी भी नहीं हो सकता ।

(११) प्रो० जे० के० महुता की परिभाषा—भारत के प्रयाग विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० जे० के० महुता ने ज्ञान ही में अर्थशास्त्र की परिभाषा एक मय ढंग में दी है जो इस प्रकार है :

‘अर्थशास्त्र यह विज्ञान है जो मानव-व्यवहारों का अध्ययन करता है जो आवश्यकता-विहीनता की अवस्था की प्राप्ति के लिये किए जाते हैं ।’

प्रो० महुता का यह मत भारत के प्राचीन विचारों और मान्यता का ध्यान है । उनका कहना है कि मनुष्य अपने जीवन में अधिकतम उत्तोष (Maximum Satisfaction) तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण कर उन्हे कम ग कम रखे, क्योंकि मनुष्य की निम्न वंशी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक मान में एक बहन समस्या हो गई है । अतः मनुष्य का अधिकतम उत्तोष प्रदान साम्बिक सुख और प्राप्ति आवश्यकता विहीनता (Wantlessness) की अवस्था में ही सम्भव है न कि आवश्यकताओं की अधिकता की अवस्था में ।

प्रो० महुता के मत का समर्थन—‘सादा जीवन उच्च विचार’ (Simple living and high thinking) की विचारधारा भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से ही प्रचलित है । सामान्य रूप में भी अज्ञानता गंभीर आचार्य विनायक भाव प्रादि इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं । प्रो० महुता के समर्थकों का कहना है कि मनुष्य जब अपनी वंशी हुई भीजित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने-आपको समर्पण पाता है, तो वह उच्च चिन्ता और समताप का अनुभव करता है । इन आवश्यकताओं ही हमारे दुःख चिन्ता और समताप का कारण हैं । ऐसी दशा में हम अपनी आवश्यकताओं को एक उचित सीमा तक ही सीमित रखना चाहिये । आवश्यकताओं की उचित सीमा क्या हो, यह दण विवेक व साहसिक विचारों पर निर्भर होगा । उनके अनुसार आवश्यकताओं का निर्धारित उचित सीमा में भी पर बढ़ाया जा सकता है, परन्तु तभी जब कि यह दण दिया जाय कि सभी दणवित्तों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है । ऐसा कार्यक्रम यदि कार्यरूप में परिणत हो जाय, तो निस्सन्देह समार का बनावरण आदर्श और सुवर्ण हो जाएगा जहाँ मनुष्य का क्या दणवित्त भी निवास के लिये सामान्य रहेगा ।

प्र० महत्ता के मत की आलोचना—प्र० महत्ता के दृष्टिकोण में दार्शनिकता एवं धार्मिकवाद का तत्त्व अधिक है और व्यावहारिकता बहुत कम पाई जाती है। आलोचकों के मतानुसार आवश्यकताएँ धार्मिक प्रयत्नों का आधार हैं। इसलिए आवश्यकताओं में कमी करने का अर्थ धार्मिक जीवन में शिथिलता पैदा करना होगा। चूँकि आवश्यकताएँ भौतिक सम्पत्ता का मापदण्ड माना जाता है, इसलिए आवश्यकताओं को भीमित रखने का कोई भी प्रयास धार्मिक सम्पत्ता की प्रगति में बाधक सिद्ध होगा जिसे पणस्वरूप आज का गम्य मानव समाज पुनः सम्पत्ता के पूर्वजन्म को प्राप्त कर लेगा।

निष्कर्ष—प्र० महत्ता का दार्शनिक (Philosophical) दृष्टिकोण भौतिक-वादी दृष्टिकोण में मैन नहीं खाता। इसलिए दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाना ही वांछनीय है। आवश्यकताओं में अत्यधिक वृद्धि तथा अत्यधिक कमी दोनों ही उचित नहीं। आवश्यकताओं की वृद्धि को एक सीमा होनी चाहिये और वह सीमा देश की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है।

अर्थशास्त्र की प्राचीन परिभाषाएँ

प्राचीन आर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'धनशास्त्र' या 'सम्पत्ति विज्ञान' के नाम से पुकारा है। अर्थशास्त्र के जनक आदम-स्मिथ (Adam Smith) ने कहा है कि "अर्थशास्त्र ज्ञातियों की सम्पत्ति का विश्लेषण है।" जे० बी० से (J. B. Say) कहते हैं कि "अर्थशास्त्र यह विज्ञान है जो धन या सम्पत्ति का विश्लेषण करता है।" वाकर (Walker) ने कहा है कि अर्थशास्त्र "ज्ञान की वह शाखा है जो धन में सम्बन्धित है।" इन प्राचीन परिभाषाओं ने 'धन' को अनुचित प्रधानता दी है और इसके प्रधान अंग धन में सम्बन्ध रखने वाले 'मानव' की ओर उदासीन रहे हैं। इन लेखकों ने अनुभव नहीं किया कि मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं मानवीय स्तर को ऊँचा करने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए मानव-अभ्ययन ही प्रमुख और सम्पत्ति का अध्ययन गौरव है।

प्राचीन परिभाषाओं की आलोचना—धन की इस अनुचित प्रधानता का हृत्परिणाम यह हुआ कि १९ वीं शताब्दी के कुछ विद्वानों ने जिनमें कार्लिल (Carlyle), रस्किन (Ruskin), विलियम मोरिस (William Morris) और चार्ल्स डिकिन्स (Charles Dickens) आदि प्रमुख हैं, इस विषय की कड़ी आलोचना की, और इसे 'कुबेर का सन्देश' (Gospel of Mammon), 'घृणित' या 'शोकपूर्ण विज्ञान' (Dismal Science), 'रोटी दाल का शास्त्र' (Bread and butter Science) आदि कौतुहलव्यापक नाम रखे हैं।

मनुष्य और धन का सापेक्षिक महत्व

इस आलोचना या अर्वाचीन अर्थशास्त्रियों पर इतना उत्तम प्रभाव पड़ा कि

1—"Economics is concerned with the enquiry into causes of the wealth of nations."
—Adam Smith.

2—"Economics is a science which treats of wealth."

—J. B. Say

3—"Economics is that body of knowledge which relates to wealth."
—Walker

उन्होंने तुरन्त धन की अपेक्षा मनुष्य पर अधिक बल देकर अपने पूर्व-गामिनी को भूल को मुधार दिया। वर्तमान सब अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि हमारा लक्ष्य धन या सम्पत्ति नहीं, यद्यपि मनुष्य का आर्थिक कल्याण है। अर्थशास्त्र में धन या सम्पत्ति का केवल इसलिए अध्ययन होता है कि धन मनुष्य के भौतिक सुख और आवश्यकताओं की पूर्ति का एक प्रमुख साधन है। यदि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन या सम्पत्ति की तकनीक भी आवश्यकता न हो, तो धन या सम्पत्ति का अर्थशास्त्र में वदोष उल्लेख न होगा। धन की उत्पत्ति स्वयं अपने लिए नहीं होती। वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है और वही तक इसका महत्व सीमित है। अतः यह स्पष्ट है कि धन या सम्पत्ति मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन या सम्पत्ति के लिए नहीं है। अर्थ जगत् का जनोद्धार—“विष्णु गुप्त”। इस भ्रम का निवारण करने की दृष्टि से इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० मार्शल ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि “अर्थशास्त्र एक ओर तो धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है।”

एक पूर्ण परिभाषा के मूल तत्त्व

इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र की मित्र मित्र परिभाषाओं का अध्ययन किया और उनके गुणों व दोषों पर प्रकाश डाला। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा दोष-रहित है। हमें चाहिए कि हम ऐसी परिभाषा दें जिसमें उपरोक्त दोषों का प्रभाव हो। अतः, अर्थशास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित तत्त्व होने चाहिए:—

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य की अनन्त आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के स्वल्प साधनों का नियमित विस्तार करता है।

(२) अर्थशास्त्र के अन्तर्गत केवल सामाजिक, वास्तविक व सामान्य अर्थिकता का अध्ययन होता है।

(३) अर्थशास्त्र केवल ऊँची मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका सम्बन्ध धन की प्राप्ति एवं उसके उपयोग में है।

(४) अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों ही हैं।

(५) अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण करना है।

अतः अब हम अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।

अर्थशास्त्र वह कला तथा विज्ञान है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों की धन-सम्बन्धी उन क्रियाओं का अध्ययन जाता है जिनका उद्देश्य मानव-कल्याण है।

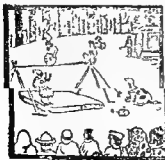
अर्थशास्त्र की विषय सामग्री

(Subject Matter of Economics)

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है—यह विज्ञान निश्चय रूप से निर्दिष्ट (प्रबन्ध) करता है कि समाज में ज्ञान और कला हो रहा है? हम देखते हैं कि कौन-कौन सी चीजें, वास्तव-वास्तविकताएँ भी अपने जीवन-यापन के लिए किसी व किसी मार्ग में प्रयत्नशील हैं। दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के लिए अपने जीवन-यापन का व्यवसाय करने में सफल है। एक

क्रिया से जितना है, उतना ही सही का सामान बनाना है, दूरी बचाने की है, अथवा छानो को पढ़ाना है, डॉक्टर अस्पताल में रोगियों की निर्यात करता है, कारीगर फॅक्ट्री में कार्य करता है। इन सबका कारण यही है कि उन्हें अपनी-अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करना है जिसके लिए वे विविध व्यवसाय एवं धन्य में व्यस्त हैं। यदि वे इन कार्यों में प्रयत्नशून्य न हों, तो यह निश्चय है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति सम्भव नहीं। य प्रयत्न उनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी है, 'आर्थिक क्रिया' (Economic Activities) कहलते हैं, और ऐसे प्रयत्नों के कारण, स्वभाव तथा परिणाम का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है।

अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र का विवेचनीय विषय मनुष्य ही है। वह मनुष्य से शुरू होकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहता है। वे क्रियाएँ आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक विविध क्रियाएँ में बाँटी जा सकती हैं। परन्तु ये सभी क्रियाएँ अर्थशास्त्र में सम्मिलित नहीं। अर्थशास्त्र का तो सम्बन्ध मनुष्य की वैयक्तिक आर्थिक क्रियाओं से ही है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य उन मानवीय प्रयत्नों से है जो अर्थ के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के लिए मार्ग प्रदर्शन करती हैं। इन अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की क्रियाएँ अर्थशास्त्र का विवेचनीय विषय हैं। जब मनुष्य जीवन-यापन के अतिरिक्त अर्थशास्त्रिक क्रियाओं (Uneconomic Activities) में प्रयत्न प्रसक्त होता जाता है, तो उसका जीवन 'अर्थशास्त्रिक जीवन' कहा जाता है। उदाहरणार्थ, एक पर्यटन करने वाला यात्री (Tourist) जो पर्यटन-स्थलों का भ्रमण केवल आनन्द-प्रसाद के लिए करता है, वह 'आर्थिक प्रयत्न' में संलग्न नहीं रहता जा सकता, परन्तु यदि इस यात्री की सहायता के लिए कोई पथ-प्रदर्शक (Guide) कुछ अर्थ-प्राप्ति की धारा में सहयोग देता है तो उसकी यह यात्रा आर्थिक क्रिया कहलावेगी। इन प्रकार बड़े-बड़े देश-भेदात्मक आर्थिक हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है। वे देश-भेद तथा स्वाभाविक सुन-सुने से प्रेरित होकर ही उक्त क्रियाएँ करते हैं। इसी प्रकार बालकों के खेल-कूद व व्यायाम सम्बन्धी क्रियाएँ जो मनोरंजन तथा स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए की जाती हैं, अर्थशास्त्रिक क्रियाएँ हैं, परन्तु मरवम वाला वे द्वारा इन प्रकार की गई क्रियाएँ जीवनो-



ये आर्थिक क्रियाएँ हैं।



ये आर्थिक क्रियाएँ नहीं हैं।

पार्षन के उद्देश्य से प्रेरित होने के कारण आर्थिक क्रियाएँ हैं। भ्रमः यह स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाओं का 'अर्थवृद्धि' अर्थ या धन है जो आर्थिक और अर्थव्यवस्थाओं में भेद प्रकट करता है।

संक्षेप में, केवल अर्थ-प्राप्ति एवं अर्थ-व्यय सम्बन्धी क्रियाएँ अर्थशास्त्र का विषय हैं।

(२) अर्थशास्त्र मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवधारियों का अध्ययन नहीं है—यह स्मरण रखना चाहिये कि अर्थशास्त्र केवल मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अन्य जीवधारियों की क्रियाओं का इसमें कोई विचार नहीं किया जाता, चाहे वे धनोपार्जन से सम्बन्ध रखती हों, जैसे बैलगाड़ी की खींचकर घरेलू स्तनी के लिए धन प्राप्ति करता है।

(३) अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है—अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है न कि व्यक्तिगत रूप में। इसमें उन्हीं प्रश्नों का विवेचन होता है जिनका एक मनुष्य की क्रिया का प्रभाव अपने सम्बन्धी की क्रियाओं पर पड़ता है। परिणामतः उन साधु-अंगारियों अथवा रोज़मर्रा के सामान विस्तृत सामाजिक या भौतिक कोलाहल में कहीं दूर विज्ञान निर्जन एकान्त में बड़े रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का अर्थशास्त्र में कोई स्थान नहीं।

(४) अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्य का अध्ययन है—अर्थशास्त्र केवल वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन है न कि काल्पनिक या अवास्तविक मनुष्यों का। प्राचीन अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे कि मनुष्य केवल आर्थिक लाभ और हानि की दृष्टि में रहकर कार्य करता है, उस पर दया, धर्म, नीति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा मनुष्य 'अर्थपरायण मनुष्य' (Economic Man) कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से इस प्रकार के मनुष्य का विवेचन अर्थशास्त्र का धर्म नहीं है। वे मनुष्य जैसा है, उसका विवेचन करते हैं—काल्पनिक या अर्थपरायण मनुष्य का नहीं, परन्तु वास्तव में रह तथा मान के वह जीवित मनुष्य का।

(५) अर्थशास्त्र सामाज्य और सवसाधारण मनुष्य का अध्ययन है—यह प्रसक्त (पागल), मदीमस्त (Drunkard) एवं अल्पज्ञ रूपों व्यक्तियों की क्रियाएँ सामाज्य और प्रीमन प्रकार की न होने के कारण इस विज्ञान की विषय-सामग्री हैं। इसी प्रकार एक उत्तम विसरण बुद्धि वाले अथवा दृढ्य ज्ञान वाले सहाधारण 'प' की क्रियाएँ भी अर्थशास्त्र का विषय नहीं बनती।

(६) अर्थशास्त्र का विज्ञानात्मक और कलात्मक रूप—अर्थशास्त्र के विषय में इसका विज्ञानात्मक तथा कलात्मक—दोनों ही रूप सम्मिलित हैं। यह केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, किन्तु नीति-प्रधान विज्ञान भी है, क्योंकि वर्तमान दशाओं के अध्ययन के अनुरिक्त यह आदर्शों का भी निर्णय करता है। यह अर्थशास्त्र कला के रूप में आदर्श प्राप्ति के हेतु कुछ नियमों को भी निर्धारित करता है।

उपारणार्थ किसी उद्योगशाला के अधिकारी के आर्थिक जीवन का वास्तविक अध्ययन इस शास्त्र का अथवा विज्ञान रूप सम्भन्ध चाहिए और उसका उस आदर्शों की दृष्टि में या अध्ययन किया जाता है वह इसका नीति-प्रधान विज्ञान रूप सम्भन्ध चाहिए। अधिक अर्थक अपनी वृत्ति (मजदूरी) में जैसे वृद्धि कर सकते हैं और किस

प्रकार के धर्म के मनुष्ययोग से वे अपने जीवन को सुसमय बना सकते हैं, इस प्रकार के समीप्य आदर्श बिना प्रकार प्राप्त किये जाते हैं—य सब जानें अर्थशास्त्र की बलामकता द्वारा प्रकट की जाती है ।

अर्थशास्त्र प्रश्न

इंटर माट्रिक्स परीक्षाएं

१—"अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ।" इस परिभाषा को विवेचना कीजिए ।

(उ० प्र० १९६०)

२—अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री को पूर्ण निवेचना कीजिए । (उ० प्र० १९५५)

३—"अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ।" यह परिभाषा दोषपूर्ण क्या मानी जाती है ? जो परिभाषा आप उचित समझते हैं वह लिखिए ।

(रा० बो० १९५७, जवन्पुर १९५९)

४—आपका एक चतुर मित्र जिसको विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपसे अर्थ विज्ञान का अर्थ, विषय-सामग्री तथा महत्त्व की विवेचना करने के लिए निवेदन करता है । समझाइए आप उसे किस प्रकार समुपहीत कर सकते हैं ? (रा० बो० १९५५)

५—आर्थिक त्रियास का क्या तात्पर्य है ? क्या अर्थशास्त्र में सब मनुष्यों की आर्थिक त्रियास का अध्ययन किया जाता है ? (रा० बो० १९५३)

६—"अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापार सम्बन्धी त्रियास का अध्ययन है ।" तथा "अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ।" इन दोनों में से कौन-सी परिभाषा आपको मान्य है और क्या ? (म० बो० १९५३, नागपुर १९५५)

७—"अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यावहारिक जीवन का अध्ययन है ।" इसका अर्थ समझाइए । (म० भा० १९५९)

८—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए । उसका विस्तार तथा प्रतिपाद्य विषय बताइए । (म० भा० १९५४)

९—अर्थशास्त्र को उपयुक्त परिभाषा दीजिए और उसके विषय व क्षेत्र भी चर्चा कीजिए । (रा० बो० १९५९, नागपुर १९५४)

१०—अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री की मूल्य में व्याख्या कीजिए । (नाथपुर, प्रिंसेटन आर्ट्स १९५९)

११—अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिए । अर्थशास्त्र के प्रमुख विभागों को बताना हुए उनमें पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए । (नाथपुर, प्रिंसेटन आर्ट्स १९५९)

१२—एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है ? मूल्य व अर्थशास्त्र के लाभ बताइए । (दिल्ली हा० नेरेण्डरी १९५२)

इंटर यूनीवर्सल

११—अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और उसकी विषय-सामग्री का विवेचन कीजिए । (म० बो० १९५७, रा० बो० १९५९)

अर्थशास्त्र का विज्ञानात्मक एवं कलात्मक रूप

(Science & Art of Economics)

यह निर्णय करने के पूर्व कि प्रथमात्र विज्ञान है या कला यथा दोनों ही, 'विज्ञान' तथा 'कला' शब्दों के महत्व को भी प्रकार समझ लेना चाहिए।

विज्ञान (Science)—विश्वी ज्ञान का समग्र ज्ञान-समूह, जो निरही सिद्धान्तों पर प्रबलित है। 'विज्ञान' कहना है कि हमको शक्ति प्राप्त करने हुए यह कह सकते हैं कि विज्ञान वस्तुस्थिति का मुख्यस्थिति विवरण है, यद्यपि उससे कारण (Cause) और परिणाम (Effect) के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना है।



कारण और परिणाम का सम्बन्ध

कला (Art)—विश्वी समग्र ज्ञानसमूह को जिसका उद्देश्य प्रयोगात्मक हो 'कला' कहते हैं। कला इस बात को प्रकट करती है कि किन उपायों द्वारा धन लक्ष्य प्राप्त की जा सकती है।

विज्ञान और कला में भेद

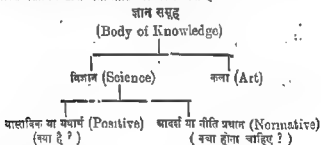
विज्ञान वस्तुस्थिति का विवरण करने हुए कारण और परिणाम में सम्बन्ध स्थापित करता है, परन्तु कला उद्देश्य प्राप्ति के साधनों का प्रयोगात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। उदाहरणार्थ, खगोलशास्त्र (Astronomy) आकाशीय वस्तुओं का विवरण करता है, अतः यह विज्ञान है, नौविद्या (Navigation) प्रयोगात्मक होने के कारण कला है। इसलिये कला का कर्म-कर्म प्रयोगात्मक विज्ञान (Practical Science) भी कहा जाता है।



अर्थशास्त्र विज्ञान है ।

नौविद्या कला है ।

विज्ञान और कला का वर्गीकरण (Classification of Science and Art)—ज्ञान-समूह विज्ञान भी हो सकता है अथवा कला भी । विज्ञान दो प्रकार का होता है—(१) वास्तविक या यथार्थ विज्ञान (Positive Science) और (२) आदर्श या नीति-प्रधान विज्ञान (Normative Science) । यह वर्गीकरण निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भली-भांति व्यक्त किया गया है :—



(१) विज्ञान के प्रकार (Kinds of Science)

(अ) **वास्तविक या यथार्थ विज्ञान (Positive Science)**—यह वर्तमान या वास्तविक दृश्यस्थिति का विवेचन करता है । यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'यह या यह क्या है ?' यह इस बात को नहीं दर्शाता कि प्रयुक्त वस्तु उचित है या अनुचित । इसका उद्देश्य तो केवल कार्यों के कारण और परिणाम को ही प्रकट करना है न कि उनकी सम्पन्नता के लिए उपाय बताना । उदाहरणार्थ, वास्तविक, वैज्ञानिक (Positive Scientist) यह नहीं बतलाएगा कि किस-किस उचित है या नहीं । वह तो यह बतलायेगा कि विषय-बान में प्रयुक्त के अतीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह किस प्रकार मूल्य को प्राप्त हो जाएगा ।

(ब) **आदर्श या नीति प्रधान विज्ञान (Normative Science)**—यह इस बात का विवेचन करता है कि प्रयुक्त आदर्श हितकर होने के कारण वाञ्छनीय है और प्रयुक्त अहितकर होने के कारण अवाञ्छनीय है । अवाञ्छनीय आदर्शों को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए और अवाञ्छनीय वस्तुओं का निषेध करना चाहिए ।

अन्य शब्दा में यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'यह या वह क्या होना चाहिए ?' पूर्व उद्धृत उदाहरण का जो हृष्ट आदर्श वैज्ञानिक (Normative Scientist) विषयान के विषय में यह कहता कि मनुष्य जीवन बहुमुख्य है, अतः इसको इस प्रकार समायोजन कर देना उचित नहीं। मनुष्य को अपना जीवन अधिक जगने के लिए दोष जीवन का आदर्श सम्मुख रखना चाहिए।

(२) कला (Art)

आदर्श और सत्य प्राप्ति के माध्याम को प्रयुक्त करने वाले ज्ञान का नाम कला है। यह ज्ञान की ओर हमारा ध्यान वृद्धि करता है कि किस प्रकार मनुष्य वास्तविक आदर्श को प्राप्त कर सके और किस प्रकार वास्तविक ज्ञान से बच सकना है। अतः यह स्पष्ट है कि कला ऐसी रीति या विधि को प्रस्तुत करती है जिससे उत्तम आदर्श की प्राप्ति और वास्तविक ज्ञान सदा हो सके। उदाहरणार्थ, विषयान के सम्बन्ध में कलाकार अर्थात् चित्र या शिल्पक यह सम्मान देता कि विषयान में अतः क्योंकि इसमें उसका शरीर में निहित उत्पन्न होना के अनिश्चित मूल्य भी हो सकते हैं।

वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान और कला में पारस्परिक सम्बन्ध

ऊपर के उदाहरण में वास्तविक वैज्ञानिक विषयान का प्रभाव ज्ञात होता है। आदर्श वैज्ञानिक विषयान को उच्च आदर्श की दृष्टि में अनुचित मानता है और कलाकार विषयान के विषय में अपनी सम्पत्ति प्रकट करता है। यही वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान और कला में भेद है। वास्तविक में कला वास्तविक विज्ञान के आदर्श विज्ञान से पहुँचने का माध्याम है। ज्ञान की उपर्युक्त तीनों शाखाओं का परस्पर भेद निम्नलिखित है। आदर्श विज्ञान वास्तविक का वास्तविक रूप प्रकट करता है और आदर्श विज्ञान वास्तविक का आदर्श रूप निर्धारित करता है तथा इन आदर्शों तक पहुँचने का माध्याम बताती है। यह सम्बन्ध निम्न रत्ना चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित है —



अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही—दोनों विभिन्न प्रकार के विज्ञानों और कला का विकसन करने के पदार्थों यह प्रश्न उत्पन्न है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही? और यदि यह विज्ञान भी है तो यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान अथवा दोनों ही?

(१) अर्थशास्त्र का विज्ञान एक रूप

(अ) अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में (Economics as a Positive Science)—वास्तविक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें वास्तविकता का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। अर्थशास्त्र भी एक वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मनुष्य के आर्थिक कार्यों का

निवेदन करते इसके प्रत्येक भाग में कार्य और कारण के सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं। उपभोग (Consumption) के क्षेत्र में अर्थशास्त्र हमको यह बतलाता है कि यदि उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने लगती है, तो प्रत्येक अगली इकाई की 'उपयोगिता' गिरती जाती है। उत्पादन (Production) के क्षेत्र में यह हमको बतलाता है कि यदि किसी भूमि पर अधिकधिक्रम और पूँजी लगाई जाय, तो किसी विशेष अवस्था में पश्चात् प्रत्येक अगली इकाई की उत्पत्ति गिरती जाती है। विनिमय (Exchange) के क्षेत्र में यह बताया जाता है किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, तो माँग घट जाती है। वितरण (Distribution) के क्षेत्र में यह बतलाता है कि यदि पूँजी की पूर्ति में स्थितता आजाती है, तो व्याज की दर में एक दम वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में अनेकों 'साधकान्तर' नियम पाये जाते हैं जो कार्य और कारण के सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अतः यह निश्चय है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है।

(१) अर्थशास्त्र आदर्श या नीति प्रधान विज्ञान के रूप में (Economics as a Normative Science) — आदर्श विज्ञान मानव व्यवहार के लिए आदर्श उपस्थित करता है। इसमें वाञ्छनीय व्यवहार और परिस्थितियों के प्रश्न पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे नीतिशास्त्र (Ethics) आदर्श विज्ञान है क्योंकि मनुष्य के व्यवहारों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसे मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दान-दुलियों की सहायता करनी चाहिए इत्यादि। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में केवल यही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि समाज में रहने वाले मनुष्य किस-किस प्रकार धनोपार्जन करते हैं और कैसे उसका उपभोग करते हैं, बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि धनोपार्जन के माध्यम मानव-जीवन की आर्थिक उन्नति के लिए उपयुक्त रूप में है या नहीं। उनमें और क्या-क्या परिवर्तन होने चाहिए जिनसे धन की उत्पत्ति में वृद्धि हो और धन का वितरण भी विधि पूर्वक हो, जिससे मानव-जीवन अधिक सुखमय हो जाय। अर्थात् समाज की आर्थिक दृष्टि में अत्यधिक समृद्धिशीली बनाने का उद्देश्य यह विज्ञान हमारे सामने रखता है। इस रूप में अर्थशास्त्र एक आदर्श या नीति-प्रधान विज्ञान है। परन्तु यह धारणा अभी सैद्धांतिक काल में ही है, व्यवहारोपयोगी नहीं बनी है।

अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने में मतभेद—इस विषय पर पर्याप्त मतभेद है कि अर्थशास्त्र को आदर्श या नीतिप्रधान विज्ञान माना जाय या नहीं। कुछ विद्वानों का विशेषतः प्रो० रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। इनका आदर्शों में कोई सम्बन्ध नहीं। किसी प्रकार की सम्मति देना अर्थशास्त्र का काम नहीं। पर अर्थशास्त्र की यह रूप देना इसका महत्त्व घटाता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के प्रतिदिन के साधारण कार्यों का अध्ययन है। यह अध्ययन उसी समय लाभप्रद सिद्ध हो सकता है जबकि अर्थशास्त्र व्यापहारिक आदर्शों पर प्रयोजित प्रयोग मात्र भवे। इसीलिए यूरोप, अमेरिका और भारतवर्ष के अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र स्वयं हमारे मनुष्य अर्थिकतम आर्थिक कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है। अतः अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना अनुचित नहीं है।

(२) अर्थशास्त्र का कलात्मक रूप

अर्थशास्त्र कला के रूप में (Economics as an Art) — वैसे कहा जाय कि अर्थशास्त्र किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम दम। अर्थशास्त्र कला के रूप में यह—

यन की अधिकतम उत्पत्ति एवं संचय करने के ऐसे उपाय बताता है कि जिनके द्वारा समाज की आर्थिक समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यह अब स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में वर्तमान परिस्थिति का यह ज्ञान कराता है और आदर्श विज्ञान के रूप में हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है और कला के रूप में आदर्श को प्राप्त करने के उपायों को प्रकट करता है।

समाज में घनेत्र आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होगी रहती है। अर्थशास्त्र इन समस्याओं को सुलभाने का मार्ग तथा साधन बताता है। उदाहरण स्वरूप, बेकारी की ही समस्या से लड़िए, अर्थशास्त्र बेकारी के कारण और परिणाम पर ही विचार नहीं करता बल्कि इस जटिल घातित से मुक्त होने का मार्ग भी बताता है। यह हमें इन व्यावहारिक साधनों से परिचित कराता है जिनके द्वारा अल्पवित्त आर्थिक समृद्धि (Economic Welfare) के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। कला का यही काम है। अस्तु अर्थशास्त्र को कला भी मान सकते हैं।

अर्थशास्त्र के कला होने पर मतभेद

अर्थशास्त्र को कला कहना या प्रतिकार है या नहीं, इस पर कोई निश्चित तथा स्थायी मत नहीं है, पर अधिकांश अर्थशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि यह कला भी है। इंग्लैंड के अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही है, कला नहीं बल्कि संसार के दूसरे देशों के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र के विद्वानों का व्यावहारिक लाभ उठाया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र में वर्तमान आर्थिक स्थिति के स्थान पर आदर्श आर्थिक स्थिति स्थापित करने के उपायों का विवेचन भी होना चाहिए। अस्तु आधुनिक अर्थशास्त्र मानव जाति की आर्थिक उत्पत्ति की वृद्धि के उपाय बनाना अपना वर्तमान समझता है।

उपयुक्त विवरण से अर्थशास्त्र का क्षेत्र भली भाँति जाना जा सकता है। इसके अन्तर्गत अर्थशास्त्र का न केवल अर्थार्थ और आदर्श विज्ञान के ही रूप में समझे हैं, अपितु एक कला के रूप में भी। अस्तु आधुनिक अर्थशास्त्र इन न केवल विज्ञान ही मानता है बल्कि एक कला भी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

- १—अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों ही क्या कहते हैं ? (दिल्ली १९३५)
- २—अर्थशास्त्र के विज्ञान एवं कला होने के प्रतिपाद्यी अधिनार पर विनयन कीजिए। (बलकला १९३८)
- ३—(अ) अर्थार्थ विज्ञान, (आ) आदर्श विज्ञान और (इ) कला के रूप में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। (बम्बई १९३९)
- ४—अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने में जो मतभेद हैं उनके दोनों पक्षों पर विवेचन कीजिए। (बलकला १९४२)

इण्टर एग्रीकल्चर

- ५—अर्थशास्त्र कला के रूप में पर टिप्पणी लिखिए। (उ० प्र० १९४३)

अर्थशास्त्र की परिभाषा और विषय आदि के सम्बन्ध में मुनिपुलि ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् अर्थशास्त्र का क्षेत्र जानने की उत्कण्ठा होती है प्रतः इस अध्याय में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में विवेचन किया जायगा ।

अर्थशास्त्र के क्षेत्र का तात्पर्य—क्या अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान अथवा दोनों ही ? यदि विज्ञान है तो कौनसा विज्ञान ? इसका युक्तिपूर्वक ज्ञान लेना अर्थशास्त्र का क्षेत्र है । इस क्षेत्र में पाठक को इसका भी ज्ञान हो जाता है कि कहीं विन आर्थिक घटनाओं का विवेचन हो सकता है ।

अर्थशास्त्र विज्ञान है (किम प्रकार का) या कला या दोनों ही—अर्थशास्त्र का क्षेत्र प्रकट करने हुए सबसे प्रथम इस बात को बतलाना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही । अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान ही है अपितु कला भी, इसका पिछले अध्याय में कुछ विचार किया गया है ।

अर्थशास्त्र एक विज्ञान है यह जानने पर उसके भेद जानने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है । इस जिज्ञासा का उत्तर सरल शब्दों में दिया जा सकता है कि यह वास्तविक तथा आदर्श दोनों प्रकार का विज्ञान है । प्रत्यक्ष उपस्थित वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हुए कार्य और कारण में अविविद्ध (घट्ट) सम्बन्ध स्थापित करना इसको वास्तविक विज्ञान की कोटि में रखता है । इसके अतिरिक्त कुछ आदर्श सामने रखकर मानवीय जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य सम्पन्न करने के कारण अर्थशास्त्रियों ने इसे कुछ समय में 'आदर्श' इस विशेषण से भी भूषित किया है, अतः यह आदर्श नीतिप्रधान शास्त्र भी समझा जाता है । इस प्रकार के उच्च आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के जो साधन चुनाये जाते हैं, उनका मासूहिव एवं अर्थशास्त्र भी कला का रूप है । उदाहरणार्थ, देश में निर्धनता व्यापक रूप में है । इसका यथार्थ विवेचन करते हुए कार्य और कारण के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना ही वास्तविक विज्ञान का कार्य है । इस सम्बन्ध में आर्थिक समुद्धि का उच्च आदर्श प्रस्तुत करना ही आदर्श विज्ञान का कार्य है । इस प्रकार के आदर्शों की पूर्ति अर्थी मानव-दानता को दूर करने के लिए क्रियात्मक उपाय बतलाना अर्थशास्त्र की कला का कार्य है ।

अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय में प्रो० मार्शल का दृष्टिकोण—प्रो० मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बात का बड़े विस्तार से विवेचन किया है । वे लिखते हैं कि अर्थशास्त्र की कला या विज्ञान अथवा दोनों ही केवल इतना ही बतलाना नहीं उचित नहीं, अपितु यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल

इस बात का ही विवेचन होना चाहिए कि इनके अन्तर्गत कौनसी घटनाएँ, किम प्रकार के मनुष्य एवं कौनसी मानव क्रियाएँ आती हैं। अर्थशास्त्र की परिधि के अन्दर समाने आता कुछ ऐसा ही संसार है।

(१) अर्थशास्त्र वास्तविक और सच्चे मनुष्य का अध्ययन है—प्रो० मार्शल ने अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि इसके अन्तर्गत चलत-फिरते हुए वास्तविक मनुष्य जो इडली मान से बना हो उसकी क्रिया का अध्ययन आता है, न कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा निमित्त वर्णित 'अर्थ-परायण मनुष्य' (Economic Man) का जो वास्तव में आज विद्यमान नहीं है।

(२) अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है—माधाररुतया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह समाज में ही रहना पसन्द करता है और समाज के अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित किए बिना उसने जीवन की आवश्यकताएँ पूरा नहीं हो सकती। उसने कार्य का प्रभाव दूसरों पर और दूसरों के कार्य का प्रभाव उस पर सदा निर्भर रहता है। अर्थशास्त्र सामाजिक व्यक्तियों के ही धन सम्बन्धी कार्यों का विवेचन है। यहाँ मानव जीवन का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में नहीं प्रत्युत सामाजिक दृष्टिकोण से होता है। वे व्यक्ति, जो समाज से अपना सम्बन्ध तोड़ चुके हैं अथवा समाज से अलग रहते हैं—जैसे माधु सत एवं रोहिमन दूसरी आदि के सहस्र ध्यक्ति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय नहीं हैं। उनके कार्यों का विवेचन अर्थशास्त्र नहीं करता है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक 'सामाजिक विद्या' माना जाता है।

(३) अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है—अर्थशास्त्र जहाँ कार्यों का विवेचन करता है जिनका सम्बन्ध धन से होता है। ऐन कार्यों को आर्थिक प्रयत्न कहते हैं। जो कार्य मनुष्य धन के लिए नहीं बल्कि दया, प्रेम, मनोरंजन, सेवा-भक्ति आदि के लिए करते हैं, उन्हें 'अनार्थिक क्रियाएँ' या प्रयत्न कहते हैं। इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, धान्यादि वस्तुओं का अन्वेषित संरक्षण एवं संप्रयोग तथा निवास स्थान का परिमार्जन (आफ सुवरा रखना) एक गृहस्थी का गृह कार्य, वर्तमानपरायण भाता की अपनी सन्तान के प्रति स्वाभाविक देन देव और खिलाड़ी का भागीद प्रमाद व स्वास्थ्य को वृद्धि के लिए जेल-भूद आदि कार्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि इन क्रियाओं का अर्थ प्राप्ति में सम्बन्ध नहीं है। ऐसी क्रियाएँ यहाँ अनार्थिक क्रियाएँ कही जाती हैं।

(४) अर्थशास्त्र नीति उपदेश नहीं देता है—यद्यपि मानव क्रियाएँ धार्मिक एवं नीति-सम्बन्धी बातों से प्रभावित होती हैं, किन्तु आर्थिक क्रियाएँ धार्मिक उपदेश एवं नैतिक नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। एक अर्थशास्त्री यह नहीं कह सकता कि अमुक कार्य उचित है और अमुक कार्य अनुचित।

(५) अर्थशास्त्र न तो किसी घटना या वस्तु की प्रशंसा करता है और न आलोचना—अर्थशास्त्र का कार्य केवल वर्तमान वस्तुस्थिति के अध्ययन तक ही सीमित है। किसी वस्तु का अन्वेषण कर उसका यथार्थ रूप प्रस्तुत करना ही इस विज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। उसकी मर्यादा अथवा उसकी आलोचना करना उसके क्षेत्र से बाहर की वस्तु है।

(६) अवध कार्य और किसी वस्तु पर अनपूर्वक अधिकार करना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है—उदाहरण के लिए, चार चारी बरके

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसारी जुए में अनेक छल-नपट करके पनाहरण करता है, राजा शत्रु पर आक्रमण कर बहुमूल्य रत्नादि चूटता है—ये क्रियाएँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती। इसी प्रकार घरोपार्जन के अनैतिक ढंग जो अर्थ को पोषित कर दिए गये हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन को चम्पु नहीं हैं।

(७) अर्थशास्त्र सामान्य स्थिति और औसत दर्जे के मनुष्य का अध्ययन है—माधारण स्थिति और औसत दर्जे के मनुष्य ही इस शास्त्र का अध्ययन-विषय है। वे मनुष्य जिनका वस्तुत्व विवृत हो गया है जैसे पागल एवं मदीमत्त पुरुष (Drunkard) या जो सन माधारण मानव की योग्यता के स्तर में ऊँचे (Genius) हैं, निविवाद रूप में अर्थशास्त्र की परिधि से बहिष्कृत हैं, क्योंकि इनके अध्ययन से अर्थशास्त्र का कोई प्रयोजन निम्न नहीं होता।

(८) आर्थिक क्रियाएँ विकासशील हैं—अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन विकासमय दृष्टि में करता है। कोई अर्थशास्त्र का सिद्धान्त सार्वकालीन सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो सिद्धान्त वर्तमान युग के लिए यथार्थ निम्न होता है वह, सम्भव है, भावी युग के लिये अव्यवहार्य सिद्ध हो। इसी प्रकार जो आर्थिक नियम एक देश के लिए लागू हों, वे दूसरे देश के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। संक्षेप में, अर्थशास्त्र गतिशील घटनाओं का अध्ययन करता है न कि स्थिर सिद्धान्तों का।

अर्थशास्त्र का स्वभाव (Nature of Economics)

अर्थशास्त्र के स्वभाव से यह तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही। बरा इतना ही जान लेना अर्थशास्त्र का स्वभाव समझना चाहिये।

अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों ही है। विज्ञानात्मक रूप से वास्तविक तथा धारणा दोनों ही रूप सम्मिलित हैं। इसका विशद विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

अर्थशास्त्र की मर्यादाएँ (Limitations of Economics)—कई अर्थशास्त्र के लेखन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी मर्यादाएँ भी प्रकट करना उचित समझते हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

(१) अर्थशास्त्र में केवल मानवीय आवश्यकताओं, प्रयत्नों और उनको पूर्ति पर ही विचार होता है।

(२) अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं है—इसने केवल अर्थ सम्बन्धी क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। अन्य प्रकार की क्रियाएँ इसकी सीमा से बाहर हैं।

(३) 'मुद्रा' अर्थशास्त्र का मापदण्ड है—अर्थशास्त्र के अन्तर्गत केवल वे दृष्टाएँ, प्रयत्न तथा क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जो मुद्रा द्वारा मापी जा सकें। अन्य क्रियाएँ जिनका मापदण्ड 'मुद्रा' सम्भव नहीं, इसकी सीमा से परे हैं।

(४) अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, वास्तविक और साधारण प्रकृति के मनुष्यों का ही विचार किया जाता है, अर्थात् एकान्तवासी, काल्पनिक और भ्रमपूर्ण प्रकृति के मनुष्यों की आवश्यकताएँ और प्रयत्न इसकी सीमा के अन्तर्गत नहीं आते।

(१) अर्थशास्त्र के विज्ञानात्मक (वास्तविक और आदर्श) तथा कलात्मक रूप अर्थशास्त्र की सीमा के जोतक है। अर्थशास्त्रियों का बहुमत इस ओर मुका है कि अर्थशास्त्र केवल वयार्थ विज्ञान ही नहीं अपितु आदर्श विज्ञान और कला भी है।

प्रो० रॉबिन्स का दृष्टिकोण—मार्शल और रॉबिन्स दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, परन्तु अन्य बातों में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रो० रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की सर्वोदाय निम्नलिखित हैं —

(१) मार्शल के विचारों के विपरीत रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक तथा प्रसामाजिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन है। इसलिए उसने अर्थशास्त्र को 'सामाजिक विज्ञान' न कहकर 'मानव विज्ञान' कहा है।

(२) रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के मानव-व्यवहार का अध्ययन किया जाता है चाहे उनका धन में सम्बन्ध हो या नहीं। मार्शल के अनुसार इनमें मानव-क्रियाओं के केवल आर्थिक पहलू का ही अध्ययन किया जाता है।

(३) रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही है। यह विचारधारा भी मार्शल में वित्कुल विपरीत है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, अपितु आदर्श विज्ञान एवं कला भी है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भर्ती-ऑन समझाइए।

(उ० प्र० १९५२, रा० बो० १९५५, ५४, ५२, म० भा० १९५४)

२—अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री की व्याख्या कीजिए।

(म० बो० १९५४)

३—समझाकर लिखिए कि अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री और क्षेत्र क्या है ?

(म० भा० १९५७)

४—अर्थशास्त्र का अर्थ समझाइए और क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

(पटना-विहार १९५२)

५—अर्थशास्त्र के क्षेत्र को स्पष्टतः समझाइए और इसके ज्ञान का महत्व भी वर्णन करें।

(पटना, १९५०)

अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध (Divisions of Economics & their Inter-relations)

अर्थशास्त्र के विभाजन का उद्देश्य—अर्थशास्त्र का विषय इतना विस्तृत है कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन बिना दस विविध विभागों में बँटि हुए सम्भव नहीं। इसके विविध विभागों में बँट जाने से इसके अध्ययन में व्यवस्थित सुविधा हो जाने के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सविस्तार तथा गहन अध्ययन किया जा सकता है। अतः, इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अर्थशास्त्र मुख्यतः चार विभागों (Departments) या शाखाओं (Branches) में विभक्त किया गया है—उपभोग (Consumption), उत्पत्ति (Production), विनिमय (Exchange) और वितरण (Distribution)। आजकल अमरबेल की भाँति बड़े वेग में बढ़ते हुए सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के विविध प्रयोजनों की निम्ति के लिए सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक कार्यों को सम्पादित करना आवश्यक हो गया है, अतः आधुनिक अर्थशास्त्र को पाँचवाँ राजस्व विभाग (Public Finance) का अध्ययन भी करना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है जितना अन्य विभागों का। संक्षेप में, अर्थशास्त्र के पाँच विभाग हैं—उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व।

अर्थशास्त्र के विभाग (Divisions of Economics)

१—उपभोग (Consumption) —उपभोग अर्थशास्त्र का नया विभाग है,



उपभोग

इसका प्रयोग सबसे प्रथम प्रो० मार्शल द्वारा किश गया। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तो इसकी उपेक्षा ही की। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है अनुप्य की आवश्यकताओं को ज्ञात करना और यह मालूम करना कि धन के प्रयोग में उनका वृद्धिकरण किन प्रकार

का होता है। अधिक स्पष्ट करने के लिये यो कहना चाहिये कि इस विभाग के मन्त्रगंड यह विचार रिया जाता है कि मनुष्य की क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं और उनकी क्या-क्या विवेकताएँ हैं। आवश्यकताओं का वर्गीकरण तथा उपभोग के नियम इसके अन्य विवेचनीय विषय हैं। इसमें इस ध्यान पर भी पूर्ण प्रकाश डाला जाता है कि किस प्रकार सीमित साधनों द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार उपभोग सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विवेचन इस विभाग का कार्य क्षेत्र है।

२—उत्पत्ति (Production)—आवश्यकताओं की पूर्ति ही धन की उत्पत्ति का मूल कारण है। यह भर्षशास्त्र का दूसरा विभाग है जिसके अन्तर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन—धन—की उत्पत्ति बँट होती है, उत्पत्ति के कौन-कौन से साधन हैं, उत्पत्ति के नियम और दंग क्या क्या हैं, आदि समस्याओं पर विचार करते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ इस ध्यान पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला जाता है कि किसी देश के उपलब्ध साधनों के द्वारा किस प्रकार अधिकतम धन उत्पन्न हो सकता है।



उत्पत्ति

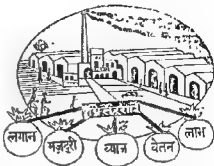
३—विनिमय (Exchange)—किस प्रकार वस्तुएँ उत्पादकों के हाथ



विनिमय

से उपभोक्तृओं के पास उपभोग के लिये आती हैं कैसे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है और कौन-कौन सी भिन्न भिन्न सस्थाओं के द्वारा इन कार्यों में सहायता मिलती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को यह विभाग सुनिश्चित करता है।

४—वितरण (Distribution)—इस विभाग के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि उत्पत्ति के साधनों का प्रतिकूल किस प्रकार और किन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित होता है। इसके अनिश्चित कुछ अन्य समस्याओं पर भी, जैसे प्राथमिक जातियों में धन के वितरण में इतनी असमानता क्यों है; और इस असमानता के क्या कारण और परिणाम हैं, भत्ती-भौति विवेचन होता है।



वितरण

५—राजस्व (Public Finance)—इसमें सरकार की आय और व्यय का विवेचन होता है। सरकार की आय के स्रोतों के साधनों पर जैसे नदी के पुल, दुर्ग, पर्वत आदि के मार्ग शुल्क ('Toll Tax') एवं विविध व्यापारिक साधनों में 'कर' सेना आदि व्यवस्थाओं पर पूर्ण प्रकाश डाला जाता है और इन बातों पर विचार किया जाता है कि सरकार (केन्द्रीय, प्रांतीय या स्थानीय) इस आय को किस मनुष्य विधि से व्यय करती है बिराष्ट्र समाज की अधिकाधिक लाभ पहुँचे।



राजस्व

विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध

अर्थशास्त्र के उपर्युक्त विभाग प्राकृतिक पदार्थों की भौति निरपेक्ष नहीं हैं। वे एक दूसरे पर प्रभावित हैं, अर्थात् इनमें पारस्परिक प्रभाव सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध की जाति का निम्नलिखित विधि में समझनी चाहिए :—

(१) उपभोग और उत्पत्ति—उपभोग उत्पत्ति का मूल कारण है, अर्थात् बिना उपभोग के उत्पत्ति सम्भव ही नहीं। उपभोग उत्पत्ति का स्वभाव निर्धारित करता है। उदाहरणार्थ, बुद्धिपूर्वक के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सपत्न अधिक है तो इनके उत्पादन में भी वृद्धि होगी, इसी प्रकार उपभोग भी उत्पत्ति पर निर्भर है, जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वेचल के ही उपभोग में लाई जा सकती हैं। वस्तुपति धी के उत्पादन किये जाने पर परिमित आय वाले गृहपति ही नहीं, सेठ साहूकार भी प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग करने लगे हैं। उत्पत्ति की मात्रा पर उपभोग की अनुपस्थिति निर्भर है। विगत विश्वव्यापी युद्ध के बाद ऊन का उत्पादन कम हो गया, धतः सर्व-साधारण ऊनी कोट, पैट नहीं पहन पाते। यदि उत्पत्ति नहीं हो तो उपभोग भी नहीं।

यह मुद्रितादादी ग्रेष्म की वीमल माहिया, जिनके निर्माण मौसम पर श्रीरवनेत्र भादशाह भी मुख्य होता था और जो प्रचुर मात्रा में राजधराने की क्षियों का मनोनेत प्रलकार वस माना जाता था, अब देखने को भी नहीं मिलती। अस्तु, उपभोग और उत्पत्ति में प्रलिय सम्बन्ध है।

(२) उपभोग और विनिमय—आनन्दक उपभोग के बिना विनिमय सम्भव नहीं। यदि मनुष्य किसी वस्तु का उपभोग करना छोड़ दे या सर्वथा स्वावलम्बी हो जाए तो विनिमय का प्रयत्न ही नहीं रहता। दूसरी ओर देखते हैं तो यह प्रकट होता है कि उपभोग स्वयं विनिमय पर अवलम्बित है। जिसान अन्न चारा, तिल, कपास आदि वस्तुएँ पैदा करता है, उलाहा आवश्यक वस्तु बनाता है, कुम्हार उपभोग के साधन मिट्टी के बर्तन, सिंघान बनाता है, वह ईंटें भी बनाता है जिससे भवन, प्राकार तथा भण्डारणार्थ बनाई जाती हैं, वैद्य विविध प्रकार की जड़ी-बूटियों का उपयोग कर चिकित्सा व्यवस्थित करता है, धन कान्हे के सिद्ध सुन्दर औषधियाँ बनाता है। अथ विद्यान, उलाहा, कुम्हार और वैद्य आदि यदि स्वात्पादित वस्तुओं पर ही निर्भर रहें तो उनके सामाजिक जीवन बन्द हो नहीं सकता। अतः सोचाना का समुचित निर्वाह करने के लिए वे परस्पर अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय करते हैं। हमारी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब यह सम्भव नहीं है कि अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करें। हम उनमें से केवल कुछ ही वस्तुओं के उत्पादन में अपना समय और शक्ति लगा सकते हैं। अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दूसरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। यह कार्य विनिमय द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अस्तु यह सिद्ध है कि वर्तमान काल में उपभोग के लिए विनिमय वितरण आवश्यक है।

(३) उपभोग और वितरण—वर्तमान धनोत्पत्ति अतिरिक्त न होकर सामूहिक रूप से होने के कारण वितरण समस्या प्रस्तुत होती है। मनुष्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने देने के पूर्व उत्पादित धन राशि का उसके मध्य वितरण होना आवश्यक है, अन्यथा उपभोग किन्तु सम्भव नहीं होता। अतः यह स्पष्ट है कि उपभोग के लिए वितरण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वितरण का स्वभाव तथा मात्रा उपभोग को निर्धारित करते हैं। जिस देश में धन का वितरण उपयुक्त रूप में है तो निःसन्देह उस देश का उपभोग भी उसमें उच्च जीवन स्तर का साधन होगा। एसी प्रकार वितरण भी उपभोग में प्रभावित है। यदि उपभोगों की मात्रा आवश्यकताओं पर्याप्त नहीं होती है तो निम्नलिखित रूप से सामूहिक उत्पन्न में भाग लेने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत वृत्तान्तों के साथ कार्य करने में समर्थ हो जाने के कारण अल्प धन उत्पत्ति करण और वितरण में भी धन अधिन प्राप्त करेंगे।

(४) उपभोग और राजस्व—सामाजिक समृद्धि या सांप्रदायिक उत्थान करने के उद्देश्य में सरकार प्रायः उपभोग के क्षेत्र में पर्याप्त हस्तक्षेप करने देखी गई है। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके उपभोग का मनुष्य की वास्तविकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार उनके उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाती है। चरम, शोका, शरीर और मद्य आदि मादक वस्तुओं पर प्रतिबन्ध उभका उद्देश्य उदाहरण है। इसीलिए इस प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं पर सरकार सखी कर आदि लगाकर उनके उपभोग को नियंत्रित करती है। दूसरी ओर उपभोग का भी राजस्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि लोग ऐसी वस्तुओं का उपभोग त्याग दें तो सरकार की आय में बड़ी क्षति

पहुँचेंगी, क्योंकि यह सरकार की भाग्य का मुख्य साधन है। भाग्य में न्यूनता हो जाने के कारण सरकार अपने उचित कार्यों का संपादन करने में असमर्थ सिद्ध होगी।

(५) उत्पत्ति और विनिमय—विनिमय के अभाव में उत्पादन अपूर्ण समझा जायगा। उत्पादित वस्तुएँ उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचनी चाहिये और यह विनिमय के द्वारा ही सम्भव है। वस्तुधा का अन्य विधाय और मन्त्रियों का अस्तित्व उत्पादन कार्य की वृद्धि करते हैं। अस्तु, उत्पत्ति विनिमय से मंच्य है। इसी प्रकार विनिमय का भी उत्पत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अर्थात् यदि वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं, तो विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) उत्पत्ति और वितरण—उत्पत्ति का अभाव वितरण पर पर्याप्त पड़ता है। यदि उत्पत्ति न हो तो वितरण भी न होगा जिससे अत्यधिक उत्पत्ति होगी, उतना ही अधिक या कम वितरण हो सकेगा। दूमरे और वितरण और उत्पत्ति में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि वितरण का ढंग उचित और ग्याय समस्त है तो उत्पत्ति में वृद्धि होता स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा होने में उत्पादकों को सम्पूर्ण वृत्ति और मन लगाकर कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु यदि वितरण का ढंग ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव उत्पत्ति पर विपरीत पड़ता जिसके कारण उत्पत्ति में न्यूनता होने लगेगी और उत्पादक संस्था की आर्थिक दशा शोचनीय अवस्था पर पहुँच जायगी।

(७) उत्पत्ति और राजस्व—उत्पत्ति का राजस्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकार की भाग्य देश निवासियों की भाग्य अथवा आर्थिक सम्पन्नता पर निर्भर है। आर्थिक सम्पन्नता यहाँ की उत्पत्ति पर निर्भर है। यदि घनोत्पादन उचित रूप में हो रहा है, तो वहाँ के निवासी धनी होंगे और इसके फल-स्वरूप उक्त देश की सरकार की भी आर्थिक परिस्थिति सुसम्पन्न होगी। इसके विपरीत घनोत्पादन कम होने पर सरकार की भाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राजस्व का भी उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में शान्ति और मुख्यवस्था है तो साधन धन का अनुपयोग करते हुए अन्धो भाग्य में अगनी पुँजी बना सकते और बड़ा उत्साह के साथ उत्पादन के काम में लगन रहते जिससे देश की उत्पत्ति में वृद्धि होगी। देश में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करना अपना दूधरे शब्दों में सोचा की सम्पत्ति और जीवन रक्षा का भार सरकार पर ही है।

(८) विनिमय और वितरण—विनिमय वितरण का गह्रायक है। आजकाल सामुद्रिक उत्पादन में मनुष्य अप्रति साधन मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है और इस मुद्रा से विविध वस्तुओं को खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विनिमय द्वारा ही सम्भव हो सकता है। विनिमय स्वयं वितरण से प्रभावित होता है। यदि वितरण की शक्ति अधिक हो तो प्रति व्यक्ति की भाग्य भी अधिक होगी, और लोग अधिक वस्तुओं का प्रयत्न करके जितते विनिमय अधिक होगा।

(९) विनिमय और राजस्व—विनिमय सम्बन्धी सभी कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन सरकार द्वारा बनाये हुए कानून और उसकी व्यवस्था पर निर्भर है। कानून एवं पत्र मुद्रा का प्रचलन, बैंकिंग प्रणाली एवं वस्तुओं की मापानुमापना तथा उनका वर्गीकरण आदि बातों की सरकार द्वारा देश-देश से देश की आर्थिक उन्नति में बड़ी सहायता मिलती है। यदि सरकार इन महत्वपूर्ण बातों की खोज करे तो विनिमय-प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह भी इस उपेक्षा में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से निश्चि प्रकार मुक्ति नहीं पा सकती।

(१०) वितरण और राजस्व—इन दोनों का भी निकट सम्बन्ध है। वितरण



का कार्य स्वयं सरकार लेकर देश में वितरण की विपन्नता को दूर कर सकती है। साम्यवादी देशों (Communist Countries) में तो वितरण की विपन्नता सुप्त भी हो गई है, क्योंकि सरकार स्वयं उत्पादित धन लोगों में बाँट देती है। अन्य देशों में सरकार अपनी नीति द्वारा इस विपन्नता को दूर करने का प्रयत्न करती है। उदाहरणार्थ, घनाक्यों के धन तथा गुप्त और बिनाश की वस्तुओं पर भारी कर लगा और धर्मियों के लिए न्यूनतम भुक्ति (Minimum Wages) निर्धारित कर तथा सामाजिक बीमा (Social Insurance) की प्रथा को लागू कर सरकार धन-वितरण की समस्या को दूर करने का प्रयत्न करती है।

ग्रन्थशास्त्र के विभिन्न विभाग

निष्कर्ष—यह स्पष्ट है कि ग्रन्थशास्त्र के अध्ययन की मुखिया के लिये ही इसे उपयुक्त विभागों में विभक्त किया गया है। ये सब भाग एक दूसरे में सम्बद्ध हैं। इनमें से कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो दूसरे से निरपेक्ष या स्वतन्त्र हो। एक भाग के अध्ययन की पूर्णता दूसरे भाग के निरतुल अध्ययन पर ही निर्भर रहेगी।

ग्रन्थशास्त्र प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—ग्रन्थशास्त्र क्या है ? इसने मुख्य विभाग कौन-से हैं और इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है ?

(सागर प्रिपरेटरी १९५९, नागपुर १९५३, सागर १९५६)

२—ग्रन्थशास्त्र को कितने भागों में बाँटा जाता है और वे एक-दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित हैं ? समझाइए।

(उ० प्र० १९६०, ५३, ५०, ७, ४०, ३४; रा० बो० १९५३, ४९, अ० बो० १९५१, म० भा० १९५१)

३—ग्रन्थशास्त्र के मुख्य विभागों की व्याख्या कीजिए (अ) उत्पत्ति और उपयोग (धा) विनियम और वितरण वा पारम्परिक सम्बन्ध समझाइए।

(उ० प्र० १९५७, ५३, अ० बो० १९५९, ४७, ४३)

४—धन के उपयोग उत्पत्ति तथा वितरण के पारम्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए। क्या अनेक धन के उचित वितरण ने देश की निर्धनता वा हज़ हाँ सकता है ?

(पंजाब, १९४९)

अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध (Relation of Economics with other Sciences)

अर्थशास्त्र पर अन्य शास्त्रों का प्रभाव

अर्थशास्त्र का अस्तित्व पृथक् होने हुए भी अन्य शास्त्रों से पूर्ण प्रभावित है। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है। समाज में मनुष्य अनेक बातों में प्रभावित होता है और आर्थिक क्रियाएँ उनमें से एक पक्ष हैं। मनुष्य सामाजिक शास्त्रों में 'मनुष्य' ही अध्ययन का लक्ष्य है, यद्यपि उससे सम्बद्ध क्रियाएँ अनेक शास्त्रों में मित्र-मित्र होती हैं। अतः सब सामाजिक शास्त्र एक-दूसरे में मित्र होने हुए भी एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में धन के वितरण पर विचार करते हुए नीतिशास्त्र का प्रभाव देखा जाना है कि देश में धन का वितरण ठीक है या नहीं। यदि ठीक नहीं, तो कैसा होना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से निरन्तर सम्बन्ध रहा है, और यह इससे विकास और उन्नति में सहायक सिद्ध हुए है। उसका भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों से अधिक परिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि इनमें भी अर्थशास्त्र की भाँति 'मनुष्य' ही अध्ययन का विषय है।

अर्थशास्त्र एक पृथक् शास्त्र है—यद्यपि अर्थशास्त्र अन्य शास्त्रों से पूर्ण प्रभावित है, तथापि यह इनसे पृथक् अपना अस्तित्व रखता है। यह सामाजिक विज्ञान होते हुए भी मनुष्य के केवल एक पक्ष का (आर्थिक क्रियाओं का ही) अध्ययन करता है। अतः इसका विषयविषय तथा क्षेत्र सर्वथा भिन्न है। फिर भी यह अन्य शास्त्रों से किसी न किसी रूप में प्रभावित एवं सम्बन्धित है।

विज्ञानों के प्रकार (Kinds of Sciences)—विज्ञानों को दो बड़े भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

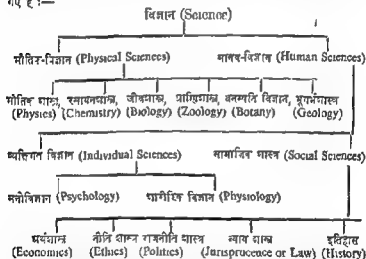
[१] भौतिक विज्ञान (Physical Sciences)—भौतिक वस्तु क्या है ? कहाँ उपलब्ध होती है ? क्या वे उत्पन्न होती हैं या व्यक्त होती हैं ? वे कितने प्रकार की होती हैं ? उनके गुण, कार्य और स्वभाव क्या हैं ? उनका स्वजाती और विजातीय वस्तुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है—आदि विषयों का अध्ययन करने वाला भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry), जीवशास्त्र (Biology), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पति विज्ञान (Botany), भूगर्भ शास्त्र (Geology), खगोल शास्त्र (Astronomy), भूगोल (Geography), गणित (Mathematics), अवज्ञास्त्र (Statistics), आदि भौतिक विज्ञान कहे जाते हैं।

[३] मानव विज्ञान (Human Sciences)—मनुष्य क्या है, शरीर, इन्द्रिय और मन क्या है ? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इनकी विविध क्रियाएँ एक-दूसरे पर क्या प्रभाव डालती हैं ? मनुष्य का व्यष्टि और समष्टि में क्या भेद है ? आदि-आदि साना का विवेचन करने वाला 'मानव-विज्ञान' है ।

(अ) व्यक्तिगत विज्ञान (Individual Sciences)—ये हैं जो मनुष्य का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में करते हैं, जैसे—मनोविज्ञान (Psychology) और शारीरिक विज्ञान (Physiology) आदि ।

(ब) सामाजिक विज्ञान (Social Sciences)—वे विज्ञान, जो मनुष्य का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में करते हैं, 'सामाजिक विज्ञान' हैं, जैसे—अर्थशास्त्र (Economics), नीतिशास्त्र (Ethics), राजनीति-शास्त्र (Politics), न्यायशास्त्र (Jurisprudence or Law) और इतिहास (History) इत्यादि ।

उपर्युक्त विज्ञानों के भेद निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भरी-भरती व्यक्त किए गए हैं :—

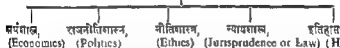


अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्र—अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से प्राथमिक भिन्नता यह है कि यह शास्त्र मानव जीवन के सामाजिक जीवन के अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्रों का अध्ययन करता है ।

अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र (Sociology) का सम्बन्ध—समाजशास्त्र वह विज्ञान है, जो मनुष्यों के सामाजिक जीवन के मन-पट्टियों का विवेचन करता है, अर्थात् समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्यों को जो कार्य करता है उन सबका समावेश समाजशास्त्र में होता है । अर्थशास्त्र में हम मनुष्यों के सामाजिक जीवन के एक विशेष पक्ष (प्राथमिक क्रियाओं) पर विचार करते हैं । हमने अतिरिक्त, दाता का लक्ष्य 'मनुष्य' है । अतः, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का एक अंग है ।

प्रो० काँंटे (Comte) कहते हैं—‘अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का जो मानव समाज और उसके सम्बन्धी का साधारण विज्ञान है एक अंग है।’ यद्यपि समस्त सामाजिक विषय परस्पर सम्बद्ध हैं, तथापि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कहना वांछनीय नहीं, क्योंकि केवल एक विज्ञान समस्त मानव जगत् के सामाजिक कार्यों का विश्लेषण पूर्वक यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। अर्थशास्त्र की एक शुद्ध ही विज्ञान मानना उत्तम है। हा यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों में कुछ सम्बन्ध अवश्य है। समाजशास्त्र मत्र सामाजिक विज्ञानों (अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि) का जनन है। इतिहास भी इसका एक अंग माना जाता है। समाजशास्त्र के ये विविध अंग निम्नांकित पटल पर समझे जा सकते हैं—

समाजशास्त्र (Sociology)



अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र (Politics)—य दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, अतः इन दोनों में पण्डित सम्बन्ध है। मनुष्य का राज्य के साथ जो सम्बन्ध रहता है उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के धनोत्पादन एवं धनोपभोग सम्बन्धी क्रियाओं का विवेचन होता है। धन का विवेचनीय विषय ‘मनुष्य’ है। केवल यही अन्तर है कि उसको राज्य सम्बन्धी शिक्षाओं का वर्णन राजनीति शास्त्र में किया जाता है और उसकी आर्थिक क्रियाओं का विवेचन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत होता है। राजनीति का अर्थशास्त्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सम्पत्ति का उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और बाणिज्य व्यवसाय आदि सभी कार्य राज्य-शासन की नीति-नीति पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। यदि उत्तम राज्य व्यवस्था के कारण राज्य में शान्ति और सुरक्षा है, तो आर्थिक जीवन की बड़ी उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति का भी शासन व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। राज्य की शक्ति और कार्य कुशलता उसकी भाय पर निर्भर है और आगम देश की आर्थिक दशा पर निर्भर है। कोई राज्य बिना प्रचुर आर्थिक बल के उन्नति नहीं कर सकता।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र (Ethics)—दो शास्त्रों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एक विस्तृत विवाद और विषमता अभी तक बनी हुई थी। कुछ लोगों का मत है—‘अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और नीति शास्त्र अन्तःकरण का विज्ञान है’, अतः शास्त्रात्मक विरोध (Natural Antipathy) है। रस्किन (Ruskin) ने तो इसे बहुत दूषित शब्दों में पुकारा है। वह कभी कहता है—‘यह अन्धकारमय अर्थशास्त्र विज्ञान है।’ (Bastard Service of Darkness)। कभी कहता है कि यह ‘अपवृत्तता का ग वि धन मज्जा है’ (Dismal science of illth rather than wealth)। यह वाग्वान् कदाचित् उग स्वाध्यायण तापन्तशाही भावना के युग में जन्मित हो प्रतीत हो, क्योंकि उस समय के शासक पूँजीपतियों के कार्यों, व्यवहारों तथा विनियोगों में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। पर १८ वीं शताब्दी से जब उद्योग विधान (Factory Law) का निर्माण हुआ, ऐसी दुर्भावनाओं का अन्त हो गया है। रस्किन का आरोप भी प्रतुलित विधि में प्राप्त धन को लक्ष्य कर ही उठता होगा। हम प्रथम ही बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र ‘धन की तुल्यता’ को अपना लक्ष्य नहीं बनाता। वह तो केवल

यही कहना है कि किस प्रकार मनुष्य घनेच्छा से प्रभावित होता है और किस प्रकार जीवन के आवश्यक साधना का समूह करने में प्रवृत्त रहता है। अर्थशास्त्र जो हम 'अचारा-नैष' (Unmoral) तो कहते हैं पर 'कदाचारात्मक' (Immoral) नहीं।

यह सत्य है कि दोनों विज्ञानों में एक समन्वय या मेली भावना देखी जाती है। अनिवार्य रूप से समाज का हितचिन्तन करने के कारण हम दोनों विज्ञानों को वृणाजुन साहचर्य की भाँति संबद्ध रखना चाहते हैं, किसी का किसी से विच्छेदन हो यह सभी अर्थशास्त्रियों का अभिप्रेत है। जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से लाभकर है, वह कालान्तर में नैतिक औचित्य है—और—जो नैतिक दृष्टि से सुस्थिर सत्य है, वह व्यवहारिक जगत् के लिए भी कालान्तर में सामकर है।¹

इस प्रकार 'मरल जीवन में प्रमुन्नाय है' (Honesty is the best policy) यह प्रादर्श जिन प्रकार व्यवहारिक जगत् के लिए मान्य है वैसे ही नैतिक जगत् के लिए भी।

इतना होने पर भी दोनों विज्ञानों को हम सर्वथा सम्बद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि नैतिक शास्त्र 'विज्ञान' और 'कला' दोनों है। इसका प्रभाव नाथ है 'नैतिक प्रावर्तों के नियमों का अनुसंधान करना और चरित्र शुद्धि की विधि व्यवस्था नियम प्रावि का निर्माण करना।' अतः यह स्पष्ट है कि नीतिविज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है।² दोनों विज्ञानों में एक अन्तर और है—अर्थशास्त्र यथार्थ विज्ञान है जो प्राथिक साधना, तबो, बाता बरणा और समस्याओं को, के जिन रूप में है, सम्भालता है, परन्तु उनके औचित्य तथा अनौचित्य का विवेक साधना नीतिशास्त्र की भूमि नहीं करता।

अर्थशास्त्र मनुष्य की धन सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है। नीतिशास्त्र हमारे मानने आदर्श प्रस्तुत करता है, यह इस बात का विवेचन करता है कि कौनसा साधन आद्यनीय है और कौनसा अव्यवनीय, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ लोगों में अचारात्मक विचार फैला हुआ है कि ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरोधी हैं। किन्तु ऐसा नहीं। यद्यपि अर्थशास्त्र में अधिकांश वास्तविक स्थिति का विचार हुआ है और नीतिशास्त्र का सम्बन्ध आदर्श व्यवहार से है, तथापि दोनों विज्ञानों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था के नैतिक पक्ष पर विचार किया जाता है और नीतिशास्त्र में आर्थिक समस्या के पक्ष पर ध्यान दिया होता है। उदाहरण के लिए—वास्तविक विज्ञान के रूप में तथान भूति (Wages), मजदूरी और मूल्य-निर्धारण आदि के नियमों का हमें विवेचन करना पड़ता है। और आदर्श विज्ञान के रूप में उचित तथान, भूति (मजदूरी), मजदूरी, मूल्य आदि आर्थिक समस्याओं को निर्धारित करने समय नीतिशास्त्र द्वारा यथायथ धाराधारी को साधने रखना पड़ता है। हमारे अतिशक्ति अर्थशास्त्र कला के रूप में आर्थिक साधन जुटाने के चार्जों को सम्भल करते हुए नैतिक आदर्शों की उपस्था नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु प्रारंभिक सरकार मजदूरी-नियम नीति को सार्वजनिक कर रही है तथा मारल सरकार न भी अपनी में उत्पादन को अत्यन्त सीमित तथा नियन्त्रित कर दिया है। वास्तव में, मनुष्य की आर्थिक स्थिति का बहुत कुछ प्रभाव उनकी आचार नीति पर पड़ता है। यह बात एक साधारण उदाहरण से समझी जा सकती है। पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों के लिये मांस मत्स्य उचित ही नहीं आवश्यक समझा जाता है।

1—Seligman—Principles of Economics P 35

2—Economics and Ethics P 10, by Sir John Marrot.

किन्तु समस्त जैसा भूमि के अधिकार निवासी, ओ सेती से नवी प्रकार जीवन निर्वाह कर सकते हैं, मांस भक्षण नीति-विषय सम्भव है ।

अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र (Jurisprudence)—अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है । न्यायशास्त्र में मनुष्य की विधान सम्बन्धी क्रियाओं पर विचार किया जाता है । न्यायशास्त्र यह बतलाता है कि मनुष्य क्या कर और क्या नहीं करे । यदि देश में कानून का पालन होना है तो अवश्य शान्ति और सुखवस्था प्रचलित होगी और देशवासीओं का आर्थिक जीवन प्रगतिशील होगा, अन्यथा इसके विपरीत परिणामित होगी । निरन्तर किसी देश के नागरिकों का वहाँ के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे इंग्लैंड में ज्वलाधिकार के कानून के फलस्वरूप बड़-बड़े शेत हैं, परन्तु इससे विपरीत भारतवर्ष में ममानाधिकार के कारण छोटे छोटे शेत (Small Holdings) हैं जो आर्थिक उत्पत्ति के अवरोधक हैं । आर्थिक परिस्थितियों का कानून पर भी प्रभाव पड़ता है । देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ देश में प्रचलित कानून में भी परिवर्तन तथा संशोधन होते रहते हैं, जैसे भारतवर्ष में औद्योगीकरण के फलस्वरूप वर्तमान फैक्ट्री में अनेक संशोधन हो गए हैं । इसी प्रकार वास्तव्य व्यवस्था की उत्पत्ति के साथ-साथ वैको में बड़ी उत्पत्ति की जिसका फल यह हुआ कि अब वैकीय कानून एक पृथक विधान बन गया है ।

अर्थशास्त्र और इतिहास (History)—अर्थशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ सम्बन्ध है । अर्थशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि समाज का विकास और उसकी व्यवस्था बहुत कुछ आर्थिक कारणों पर अवलम्बित है । इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन से भी अर्थशास्त्र के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है । कृषि, औद्योगिक, राजकीय, करों तथा पातापान सम्बन्धी समस्याओं का हल निकालने के लिए भारतीय इतिहास में परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का विवरण और पुष्टीकरण आर्थिक इतिहास द्वारा किया जाता है । कई आर्थिक सिद्धान्त केवल इसी आधार पर गढ़ कर दिए गए हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि में प्रतिकूल सिद्ध हुए हैं । इसी आधार पर मार्क्स के मतसम्बन्धी सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की गई है ।

अर्थशास्त्र वेत्ताओं ने इतिहास को इतना महत्व दिया है कि उन्होंने आर्थिक इतिहास को दो शाखाओं में विभक्त कर इनका अध्ययन करना सामकरी समझ है । वे निम्नलिखित हैं :—

(१) आर्थिक विकास का इतिहास अर्थात् आर्थिक इतिहास (२) आर्थिक विचारों का इतिहास अर्थात् आर्थिक सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव तथा विकास ।

आर्थिक इतिहास—यहाँ हमको ज्ञात होता है कि समय-समय पर देश में आर्थिक घटनाएँ किस प्रकार चला और इनका क्या परिणाम रहा । उदाहरण के लिए, देश में दुर्भिक्ष और व्यापारिक उत्तार-चढ़ाव आदि सब-कुछ और क्यों आए और उन्हें दूर करने के लिए किन उपायों को प्रयुक्त किया गया था तथा राज्य की व्यापार नीति और मुद्रा नीति क्या थी इत्यादि । यह सामग्री अर्थशास्त्र में दुर्भिक्ष, व्यापार, मुद्रा नीति आदि समस्याओं पर विवेचन करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है । इसी ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर अर्थशास्त्र में नवीन सिद्धान्तों की जन्म मिलता है तथा प्रचलित सिद्धान्तों की आलोचना, संशोधन या पुष्टि की जाती है ।

व्यापक विचारों का इतिहास—इसका भी अर्थशास्त्र में बड़ा महत्त्व है। वर्तमान प्रचलित अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को अली प्रकार समझने के लिये उनके जन्म और विकास के ज्ञान से पर्याप्त सहानुभूति प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, रगत (Rent) के सिद्धान्त का जन्मदाता डेविड रिकार्डो था, जिसने अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में लघुत्वा का सिद्धान्त प्रथम बार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् इसमें कई परिवर्तन होते रहे। यह ज्ञात हम भुवनाल की नुष्टियों से भी सर्वत्र एक सन्केष्ट करता है, और भविष्य के लिए उत्पत्ति के पथ पर आरुढ़ करता है। इसमें हमने सामेक्षिकता के सिद्धान्त का ज्ञान होना है।

सर जान सीले (Sir John Seeley) के अनुसार—

“Economics without Economic History has no root
Economic History without Economics has no fruit.”

अर्थशास्त्र का मूल है अर्थशास्त्र इतिहास।

अर्थशास्त्र फल के बिना व्यर्थ-यथ इतिहास ॥

अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत विज्ञान—अर्थशास्त्र न केवल सामाजिक शास्त्रों में ही सम्मिलित है, अपितु व्यक्तिगत मानव विज्ञान में भी। व्यक्तिगत विज्ञानों में मनोविज्ञान प्रमुख है जिसका चलन यहाँ किया जाता है—

अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान (Psychology)—मनुष्य की चरित्राधार, प्रयत्न और सहाय—ये कतिपय भौतिक तत्व दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। मानवस प्रौद्योगिक मनोविज्ञान तो इन तत्वों के अधिकांशिक सम्मीर सम्बन्ध पर आधारित होता जा रहा है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र मनुष्य की कार्य सम्बन्धी क्रियाशीलता का विवेचन है, उसी प्रकार मनोविज्ञान उसकी मानसिक व्यवस्था का अध्ययन है। अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानवीय आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति पर आधारित है और इन तत्वों का मानसिक प्रवृत्ति में समान सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये, सीमांत उपयोगिता-ह्रास-नियम, माँग का नियम, पूर्ति का नियम, व्यापार के उत्तरावकाश के नियम आदि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर अवलम्बित हैं। इसी प्रकार धर्म की बनावट विवेचना, उदासीनता, विश्वास, समीकरण की आवश्यकता आदि समस्याओं के समझने में मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है।

अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान—अर्थशास्त्र का भौतिक विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र में जो कुछ घटित तथा उद्योग सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाता है, तो भौतिक (Physics), रसायन (Chemistry), भूगर्भ (Geology), और जीवशास्त्र (Biology) आदि शास्त्रों में बड़ी सहायता मिलती है। अर्थशास्त्र के कई सिद्धान्त भौतिक रसायन एवं भूगर्भ शास्त्रों पर प्रवर्तित हैं। उदाहरणार्थ, समान उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) एवं रसायन शास्त्र में विशेष सम्बन्धित है। इसी प्रकार रसायनशास्त्र के मतानुसार पदार्थ नाशवान् नहीं है बल्कि स्थानान्तर होता रहता है। इनके आधार पर अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का उपयोगिता उत्पन्न करना और उपयोग को उपयोगिता का विनाश बहुत बड़ा परिभाषित किया है क्योंकि इस समझ में तो कोई नवीन वस्तु बच सकती है और न, नष्ट हो, मरती है, केवल उपयोगिता का परिवर्तन होता रहता है।

नासनी विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्^१ (प्राधान्य का अभी भाव नहीं होता और नियमानुसार वस्तु का अभी अभाव नहीं होता) — यही मतवर्द्धन के

इस कथन की गत्यन्ता आशय दृष्टि में भी मिट जाती है। इसी प्रकार ज्योतिष द्वारा व्यापारिक चक्रों (Trade cycles) तथा आर्थिक मन्दता पर प्रकाश डाला जा सकता है। जेवन्स का 'सूर्य के धब्बे का मिथान' जैसे सार्विक नियमों के बनाने में समीप शारन (Astronomy) से श्रुत नद्वयता प्राप्त हुई है।

इस प्रकार मक्षेप में अर्थशास्त्र और विभिन्न भौतिक शास्त्रों का सम्बन्ध जान लेने पर यह भी सम्भव लेना चाहिये कि कुछ भौतिक शास्त्रों का अर्थशास्त्र में सम्बन्ध अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अधिक पतित है, इसका विवरण किया जाना है।

अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र (Physics)—आधुनिक आर्थिकशास्त्र जैसे रैडक्ली, टैल्लिब्रिज, हार, टेलीफोन, मोटर, रेल, वायुयान, गास और तैल के एंजिन और विद्युत से चलने वाले यंत्र आदि की उत्पत्ति, विकास, उपयोगिता आदि महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना पूर्ण चर्चा भौतिकशास्त्र में होती है। इनसे नम्या का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण आर्थिक क्षेत्र में आतापीन उत्पत्ति हुई है। अतः अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध कोई रहस्यमय बात नहीं है।

अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र (Chemistry)—रसायनशास्त्र की उत्पत्ति में अनेक उद्योगों तथा व्यवसायों को उत्तम कर मानवजुल की वृद्धि की है, यह बात निर्विवाद है। प्रत्येक उद्योग-धन्धे में इसकी अनिवार्य आवश्यकता अनुभूत होती है। कपड़ा धोनी पत्थर, खर, तैल-साबुन, गोता-भास्व आदि उद्योग-धन्धे इसी के आधार पर स्थिर हैं। अतः, रसायन शास्त्र आर्थिक जीवन का एक प्रकार से आधारभूत है।

अर्थशास्त्र और जीवशास्त्र (Biology) तथा वनस्पतिशास्त्र (Botany)—जीवशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र में अर्थशास्त्र बड़ा प्रभावित है, अर्थात् मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ वनस्पति एवं पशु मसार में पूर्ण की जाती हैं। अनेक उद्योग-धन्धों को शिवाशील रखने में निष्ठ साध तथा असाध वनस्पति परम आवश्यक है। गेहूँ आदि की खेती में पौधा के रोगों की चिकित्सा तथा पशु-चिकित्सा आदि महत्वपूर्ण चर्चाएँ इसी शास्त्र में की जाती हैं।

अर्थशास्त्र और भूगोल (Geography)—अर्थशास्त्र मनुष्य के धनोपाजन तथा धनोपभोग सम्बन्धी शिवाशी का अध्ययन है। भूगोल में मनुष्य और उसके बाना-बारण का विवेकन किया जाता है। देश की स्थिति, नदी-नहर, समतल भूमि, जलवायु और वनस्पति तथा मनुष्य का आर्थिक जीवन आदि बानों पर भूगोल स्पष्ट प्रकाश डालता है। किसी देश की कलायत, समुद्र-तट, जलवायु, वनस्पति, खनिज पदार्थ और प्राकृतिक शक्तिया का वहाँ के निवासियों के आर्थिक जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय भागों में जहाँ किसी प्रकार की खेती सम्भव नहीं, श्रेष्ठ खेती पाचना ही जीविकोपाजन का मुख्य साधन होगा। यह स्पष्ट है कि किसी देश के निवासियों की मनुष्यगत आर्थिक क्रियाएँ भौगोलिक बानावरण में नियन्त्रित होती हैं। इसी कारण अतिस भूगोल अर्थशास्त्र का एक विभिन्न अङ्ग है। इसके बिना इसका अध्ययन प्रायः अपूर्ण या समझा जायगा।

अर्थशास्त्र और गणित (Mathematics)—नई नयी के विवाद के पदनाश अध्ययन में गणित की उपयोगिता स्वीकार कर ली है। जेवन्स ने तो यहां तक पोषित कर दिया था कि अर्थशास्त्र का यदि विज्ञान की नोटि में रखना है तो देश शास्त्र का गणितात्मक होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसमें उपयोग वस्तुधा के परिणाम या उनके माया-मध्यस्थी तथ्यों की विवेचना अधिक होती है। यत्रपि मानवीय इच्छाया तथा क्रियाया का व्याक्ति माप नहीं हो सकता, फिर भी आनन्द, रक्षायित्र एवं

तालिका आदि गणित सम्बन्धी नियमों तथा मूलों की सहायता से अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भली-भाँति विवेचन किया जा सकता है। 'मुद्रा मान्य सिद्धान्त' (Quantity Theory of Money) जैसे अनेकों सिद्धान्त गणित की सहायता से भली-भाँति समझे जा सकते हैं।

अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र (Statistics)—अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो किसी समस्या से सम्बन्धित धन का मूल्यांकन, वर्गीकरण सारणीकरण कर उनकी व्याख्या करता है। महाशय सेलिगमैन (Seligman) ने कहा है—'अर्थशास्त्र अथवा गणितात्मक की विविधा बड़ी बहुत और गम्भीर है। वे मनुष्य के भविष्य का भूभूतता की समस्याएँ एक पट्टी पर देखती हैं। दूसरी बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जीविक के एक ही भग की उपार्जन करता है। भारतीय उल्हासपूर्ण आभाधाएँ और आनन्दपूर्ण गणितात्मक और अर्थशास्त्र के सीमित क्षेत्र में बस जान में सीमित हो जायेंगी।'।

परन्तु बिना अर्थशास्त्र की सहायता लिए हुए अर्थशास्त्र का ठीक-एक निष्कर्ष प्राप्त माना जायगा। आर्थिक तथ्यों को पूर्णतया स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अर्थशास्त्र का प्रसबन्धन बौद्धिक है। उदाहरण के लिये, यह कहना कि भारतीय धर्मियों की भूमि बहुत कम है, यह बात महत्ता संग्रह में नहीं आती जब तक कुछ धन इस सम्बन्ध में नहीं उद्धृत कर दिया जायें। अर्थों के अनेक अध्ययन से पुराने सिद्धान्तों की व्याख्यान और नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सकता है। अर्थ विज्ञान की सहायता से अनेक आर्थिक विषयों का बड़ी सुगमता से वर्णन हो सकता है, जैसे विदेशी व्यापार, आयान-निर्वाह और बैंक के विविध व्यवहार इत्यादि। माल्यम का जनसंख्या का सिद्धान्त आर्थिक तथ्यों पर ही अवलम्बित था। समय-समय पर आर्थिक समस्याओं के लिये हानि होने वाली कमीशन और कमेटीयों अपनी योजनाएँ, आर्थिक तथ्यों के अध्ययन के पश्चात् ही, प्रस्तुत करती है। अतः यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र से पुष्ट नहीं रहता या मरता है। वास्तव में, अर्थशास्त्र का एक विभाग ऐसा है जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसको आर्थिक अर्थशास्त्र कहते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर माईस परीक्षाएँ

१—अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

(रा० वा० १९२२, उ० प्र० १९६४, ४८)

२—क्या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ? इसका दूसरे विज्ञानों से क्या सम्बन्ध है ?

(रा० वा० १९२६)

३—अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या सम्बन्ध है ? इसकी भाँति समझाइए।

(रा० वा० १९२२)

४—अर्थशास्त्र क्या है ? इसका अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।

(उ० प्र० १९२१, रा० वा० १९२०)

५—'अर्थशास्त्र' का विषय समझाइए। अर्थशास्त्र का राजनीतिशास्त्र और न्याय शास्त्र से क्या सम्बन्ध है ?

(उ० प्र० १९२२)

६—क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ? इसका सम्बन्ध राजनीतिशास्त्र से बताइए।

(माय० १९२०)

अर्थशास्त्र के नियम (Laws of Economics)

नियमों के भेद—‘नियम’ शब्द भिन्न भिन्न अर्थों तथा व्यवहारों में प्रयुक्त होता है। नियमों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :

(१) वैधानिक नियम (Statutory Laws)—वैधानिक नियम वे हैं जो देश की सरकार द्वारा बनाये जाते हैं। ये यह बताते हैं कि समूह काम वहाँ के निवासी कर सकते हैं और समूह काम नहीं। प्रत्येक देशनिवासी के लिये उनका पालन करना अनिवार्य होता है। इन नियमों के उल्लंघन करने वालों को राज्य की ओर से उचित दंड दिया जाता है। यह स्थायी नहीं होते। उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं मशोधन होते रहते हैं। कभी-कभी उनका गोप्य भी हो जाता है। ऐसे नियमों या कानूनों को राजनियम या वैधानिक नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, ‘भारतीय दंड विधान’ में यह निम्न है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी प्रकार शारीरिक कष्ट न पहुँचावे। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास या धन दंड अथवा दोनों ही दंड दिये जाते हैं। इसी प्रकार कोई मोटर ड्राइवर बिना लाइसेंस मोटर न चलावे। इस विधान का उल्लंघन करने वाला ५० रु० या इसमें भी अधिक दंड भोगता है।

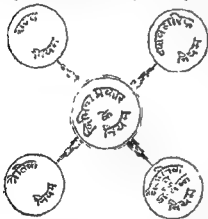
(२) नैतिक नियम (Moral Laws)—इनका सम्बन्ध नीति, धार्मिक तथा धर्म से है। ये नियम बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं जैसे—मनुष्य को मदद प्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और सतोषपूर्वक जीवन विताना चाहिए, स्वाध्याय परायणता, कर्तव्य-निष्ठा, मदालाद, पवित्रता आदि धार्मिकों का पालन करना चाहिए; दूसरों को अपने समान समझना चाहिए और आत्मा के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इन नियमों को भंग करने वाले को इस लोक और परलोक में ईश्वरीय दंड मिलता है, ऐसा नीति-परामर्श व्यक्तियों का विश्वास है।

(३) व्यावहारिक नियम (Customary Laws)—वे हैं जो किसी जाति की सामाजिक रीति अथवा परम्परागत रिवाजों और हठियों द्वारा निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिये, हिन्दू समाज में कई ऐसी रीतियाँ परम्परा में प्रचलित हैं जिन्हें लोग जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर पालन करते हैं। इन रिवाजों के पालन न करने वालों को सामाजिक दंड मिलता है, अर्थात् वे समाज की दृष्टि में नीचे गिर जाते हैं।

(४) वैधानिक नियम (Scientific Laws)—वे नियम हैं, जो कारण (Cause) और उसके परिणाम (Effect) में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इनके

द्वारा यह प्रकट होता है कि अमुक परिस्थिति में अमुक वस्तु उत्पन्न होगी और अमुक कार्य का अमुक परिणाम होगा, जैसे रसायन शास्त्र के नियम। ये नियम सर्वसोम मान्यता रखते हैं। ये नियम अपरिवर्तनशील हैं और न इनका कभी लोप होता है। इनके उल्लंघन में कोई दंड का भागी नहीं होता।

(२) अर्थशास्त्र के नियम (Laws of Economics) — प्रत्येक वैज्ञानिक नियम की भाँति अर्थशास्त्र के नियम भी कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे बताते हैं कि अमुक आर्थिक स्थिति में इन कारणों का अमुक परिणाम होगा। अर्थशास्त्र हमारे प्रतिदिन के साधारण आर्थिक कार्यों का विवेचन है। यह उन कार्यों के परस्पर कारण और परिणाम के सम्बन्ध के विषय में प्रकाश डालता है। यह हम बात का मन्वेषण करता है कि मनुष्य विशेष दशाओं में किस प्रकार बर्ताव करने है। यदि किसी विशेष आर्थिक स्थिति में एक ही प्रकार का बर्ताव या सम्बन्ध देखने में आता है तो उसे एक निश्चित रूप देकर अर्थशास्त्र का नियम कहने लगते हैं। हम यह प्रतिदिन देखते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो साधारणतया उस वस्तु की माग घट जाती है, और मूल्य कम होने पर माग बढ़ जाती है। इस प्रकार का सम्बन्ध सबन जगह पाया जाता है यदि अन्य बातों में प्रभावित



विविध प्रकार के नियम

न हो। इस प्रवृत्ति (Tendency) को अर्थशास्त्र में माँग का नियम (Law of Demand) कहते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसी प्रकार के कई नियम बनाये हैं जो आर्थिक प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं कि अमुक स्थिति में अमुक परिणाम होने की सम्भावना है। यह प्रवृत्ति सामान्य धारणाएँ (General Statements) का सूचक है। ऐसी सामान्य धारणाओं को ही आर्थिक नियम कहते हैं। सर्वप्रथम, धन सम्बन्धी मानवीय प्रवृत्तियों की सामान्य धारणाओं को ही आर्थिक नियम कहते हैं। प्रो० मार्शल ने वस्तुनिष्ठ आर्थिक नियम या आर्थिक प्रवृत्तियों के बचन में सामाजिक नियम है, जो आचरण की उन सामान्यताओं में सम्बद्ध है, जिनमें अपेक्षित प्रवृत्तियों की शक्ति मुझ मूल्य में नाशो का शक।

आर्थिक नियमों की विशेषताएँ — उपर्युक्त परिभाषा का अध्ययन करने से आर्थिक नियमों की दो मुख्य विशेषताएँ ज्ञात होती हैं, वे निम्नलिखित हैं —

(१) ये नियम सामाजिक होते हैं क्योंकि ये यह बताते हैं कि विशेष परिस्थितियों में मनुष्य सामाजिक रूप में किस प्रकार बर्ताव करेगा है।

(२) आर्थिक नियमों का सम्बन्ध मनुष्य की प्रवृत्तियों से है, जिनका शायद मुझ से सम्भव हो सके।

अर्थशास्त्र के नियम और अन्य विविध प्रकार के नियम—उपयुक्त विवरण से यह निर्विवाद स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के नियम वैज्ञानिक नियम हैं, क्योंकि वे उनकी भाँति कारण और परिणाम में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे अन्य प्रकार के नियमों में विलुप्त भिन्न हैं। जैसे—राजनियमों की भाँति आर्थिक नियम किसी राष्ट्र या सरकार द्वारा नहीं बनाये जाते और न उनमें मजबूत करने वाल किसी प्रकार के दंड के भागी होते हैं। आर्थिक नियमों का एकमात्र कार्य अर्थ सम्बन्धी विषयों में कारण और परिणाम के सम्बन्ध को स्पष्ट करना है। 'ऐसा करो' या 'ऐसा नहीं करो' इस प्रकार की वे आज्ञाएँ नहीं देते हैं। अतः यह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के नियमों के समान रहियों पर अवलम्बित नहीं है। यदि कोई गनुष्य राजनियमों की पक्षधरता करता पाया जाता है, तो उसे दण्ड सहित पकड़ा है।

क्या आर्थिक नियम प्राकृतिक नियम हैं? (Are Economic Laws, Natural Laws)

इस विषय में दो धारणाएँ प्रचलित हैं :—

(१) आर्थिक नियम प्राकृतिक नियम नहीं हैं—एक धारणा वाले अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक नियम नहीं मानते, क्योंकि इसमें भौतिक, रसायन आदि शास्त्रों की भाँति अपरिवर्तनीयता तथा सर्वव्यापी नियमों का पूर्ण प्रभाव है। अर्थशास्त्र के नियमों का सम्बन्ध 'समुच्चय' में है जो वृद्धिमान् प्राप्ति होने के लिये अपने विचारों में पूर्ण स्वतन्त्र हैं और अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन कर सकता है, अतः वे सर्वव्यापी होने में अशक्य हैं।

(२) आर्थिक नियम प्राकृतिक नियम हैं—दूसरी धारणा वालों का मत है कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियम हैं। इसके लिये वे प्राकृतिक नियमों को दो विभागों में बाँटते हैं, एक तो वे प्राकृतिक नियम जो सर्वव्यापी एवं अपरिवर्तनीय हैं और दूसरी कोटि में वे सम्मिश्रित हैं जो दी हुई परिस्थितियों में ही सर्वव्यापी सिद्ध हो सकते हैं, जैसे—किसी निश्चित तापक्रम तथा दबाव में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित परिणाम में मिलाये जायें तो वे जब में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों को वे दूसरी कोटि में सम्मिश्रित कर प्राकृतिक नियम मानते हैं, अर्थात् आर्थिक नियम किसी निश्चित परिस्थिति में सर्वव्यापी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे—यदि किसी वस्तु की माँग (Demand) बढ़ती है और पूर्ति (Supply) वैसी ही रहती है, तो निश्चित रूप में उस वस्तु का मूल्य में वृद्धि होती है। यह नियम सब जगह लागू होगा। अतः वे ऐसी परिस्थितियों में अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक नियम घोषित करने हुए तर्क भी मजबूत नहीं होने।

आर्थिक नियमों और प्राकृतिक या भौतिक नियमों की तुलना

आर्थिक और प्राकृतिक नियमों में समानता—इन दोनों प्रकार के नियमों में बड़ी समानता है, क्योंकि दोनों ही में कार्य और कारण का सम्बन्ध निश्चित निश्चित परिस्थितियों में स्थापित होगा है। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र में माँग का नियम यह प्रवृत्त करता है कि यदि किसी वस्तु की माँग बढ़ जाय, तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जायगा। इस नियम में प्रत्यक्ष सिद्ध होने में अन्य परिस्थितियों का तत्त्व भी हस्तक्षेप न होना चाहिये; अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे, माँग के साथ-साथ उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, तो फिर मूल्य में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। इसके

दिपरोत धमक वस्तु का फैलन या प्रयोग परिवर्तित हो जाने से यदि मूल्य भी गिर जाय तो उस वस्तु की माग कम रहगी।

इसी प्रकार प्राकृतिक नियमों में भी वही बात बताई जाती है। उदाहरण के तौर पर आकर्षण द्रष्टव्य नियम (Law of Gravitation) यह प्रकट करता है कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है परन्तु यह नियम भी इस बात पर दायित्व है कि अथवा कोई कारण ऐसा उपस्थित नहीं होगा जो उसके रास्ते में अवरोध पैदा कर दे। यदि बाधा जागने वाला कारण इसमें प्रतिफल प्रकटता में उपस्थित हो जाय तो इस नियम की वास्तविकता गूट हो जायेगी।

पार्थिव और प्राकृतिक नियमों में असमानता—इनमें इनकी समानता
होना ही कुछ भेद है, जो निम्नलिखित है —

प्राकृतिक या भौतिक नियम घटस और अनिवार्य होते हैं, परन्तु इनका सवया प्रभाव आर्थिक नियम से देखा जाता है। उदाहरण के लिये रसायन शास्त्र के अनुसार दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन के समीप में जब उत्पन्न हो जाता है। यह नियम घटल और सङ्ग्राही है—कोई भी बाप इसको इस लाभ में वञ्चित नहीं कर सकती। परन्तु प्रचारात्त में अन्य विनियम के नियमों में इस प्रतिपाद्यता तथा स्थिरता का संबंध प्रभाव है। उदाहरणार्थ बहुत से मनुष्य दम प्रभ में इन प्रसाधित हुए हैं कि वे विदेशी मस्ती वस्तुओं की खपत स्वदेशी मस्ती वस्तुओं का खर दना कम कर रहे हैं।

(२) प्राकृतिभ्यः आ भौतिक नियम पूर्ण होते हैं परन्तु आर्थिक नियमों का अनुमान इतना पूर्ण सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ यदि दो मान हाथमजदूर और एक भाग श्रमिकमजदूर को धन में इसी अनुपात में बढ़ाया जावे तो जल की मात्रा उसी अनुपात में बढ़नी जायगी। यदि दुग्धा दिया जावे तो जल भी दुग्धा वन जायगा और निष्ठा दिया जावे तो निष्ठा हो जायगा। परन्तु अर्थशास्त्र के पूर्व उद्घात माँग के नियम में मुख्य के भूनाधिक से उसी अनुपात में माँग तथा पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी।

(३) भौतिक नियमों को प्रयोगशाला (Laboratory) में प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर उनके व्यापकता की परीक्षा की जा सकती है परन्तु प्राथमिक नियमों में प्रयोगशाला की साध्यता का पूर्ण अभाव है।

अथदाह्य के नियमों की निश्चितता—(१) सामान्यतया दत्ता ज्ञान ता
सार प्रस्तावित न नियम अनिश्चित होता है। अथदाह्य न कुछ नियम एन भी हैं जो
प्रकृति पर शतप्रतिशत हान न कारण निश्चित है। जैसे—कमालत उपरिष्ठ हान नियम
(Law of Diminishing Return) यह एन सामान्यतया नियम है। यह प्रकृति
कृषि भी उत्तम रीतिया लगा नवीन अविवृत्त मशीन न द्वारा कुछ समय न रिष रोक
जा सकता है। परन्तु परिस्थितिया न स्थिर हा ज्ञान पर पुन इयन प्रमाण प्रारम्भ
हो जाता है।

(२) अथवा यह कि कुछ नियम तो ऐसे हैं जो स्वयं सिद्ध हैं और जिनको यथावत् सिद्ध करने में किसी विभी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। जैसे—'धृति' का मर्म तभी है मरना है जब व्यक्त म आय अधिक हो। अथवा जीवन-स्तर का नियम कुलानाश्रम की उत्पत्ति पर निर्भर है आदि नियम मन्त्र तथा सब समय एक से ही सिद्ध होते हैं।

अर्थशास्त्र के नियम]

अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित हैं; परन्तु वे भौतिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं।

अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं—यह प्रथम अघ्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। अब यह सिद्ध करना है कि अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित हैं। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य की उन इच्छाओं तथा कार्यों से है जो मुद्रा में व्यक्त हो सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति को दल भर उद्योगधाम में कार्य करने का पारिवर्त्मिक दो रूपों प्रतिदिन के हिमाय में मिलता है, तो यह उसके परिश्रम का अधिक माप है। इसी प्रकार डाक्टर को चिकित्सा में कार्य करने के फलस्वरूप यदि वेतन मिलता है, तो यह उसकी क्रियाओं का अधिक माप है। यदि वह वहाँ निरुक्त कार्य करता है, तो उसका कोई आर्थिक मार न होने के कारण आर्थिक हिमाय सम्पन्न करना नहीं कहा जा सकता। यह माप अर्थशास्त्र को ही उपलब्ध है, अन्य सामाजिक शास्त्रों में इस प्रकार के मापों का पूर्ण अभाव है, अतः उनके नियमों में अर्थशास्त्र की 'सूक्ष्म मुद्रा' (Fine Balance) से उसमें नियमों को अन्य भौतिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित बना दिया है, उसी प्रकार 'मुद्रा' (Money) के माप दृष्ट में, यद्यपि वह इतना सुनिश्चित नहीं है, फिर भी अर्थशास्त्र को अन्य विविध सामाजिक शास्त्रों की इतना सुनिश्चित नहीं है, किन्तु भी अर्थशास्त्र को अन्य विविध सामाजिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक दृढ़ एवं निश्चित बना दिया है, क्योंकि इस प्रकार के माप दृष्ट का अन्य सामाजिक विज्ञानों में पूर्ण अभाव है। अतः यह स्पष्ट हुआ कि अर्थशास्त्र के नियम अथवा सिद्धान्त नीतिशास्त्र, व्यावसायिक, राजनीति आदि शास्त्रों में अधिक दृढ़ एवं सुनिश्चित हैं।

अर्थशास्त्र के नियम भौतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि अर्थशास्त्र के नियम कारण और कार्य में सम्बन्ध स्थापित करने के कारण वैज्ञानिक नियम कहे जाते हैं, परन्तु वे प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं। वे पूर्ण रूप से इस बात को प्रकट करने में अक्षम हैं कि अमुक कारण का अमुक परिणाम अवश्य होगा। अर्थशास्त्र में माँग का नियम इस बात को स्पष्ट कर देता है। इस नियम के अनुसार मूल्य के कम हो जाने से माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ जाने से माँग कम हो जाती है। साधारणतया ऐसा ही होता है। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मूल्य के घटने से माँग ही होता है। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किसी वस्तु का माँग में कितनी वृद्धि होगी। कभी कभी ऐसा भी दृष्टिगोचर होता है कि किसी वस्तु का माँग या पलन उठ जाने से उग वस्तु के मूल्य के गिर जाने पर भी माँग में वृद्धि नहीं होती। अर्थशास्त्र ने नियम केवल इस बात को प्रकट करने में समर्थ है कि अमुक परिस्थिति में अमुक परिणाम का होना सम्भव है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे केवल प्रवृत्ति प्रथमा रूढ़ (Tendency) की ओर सूचित करते हैं, वे दृढ़ता से यह नहीं घोषित कर सकते कि अमुक परिस्थिति में अमुक परिणाम होना अनिवार्य है। इस अनिश्चितता के कई कारण हैं, जो नीचे दिये जाते हैं।

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक इच्छाओं तथा कार्यों का अध्ययन है। मनुष्य के स्वैच्छाचारों होने के कारण उसके स्वभाव को नियमबद्ध नहीं

किया जा सकता, और न यह था। ही की जा सकती है कि वह भद्व उन्नी प्रकार व्यवहार करना रहेगा । उनको इच्छाएँ निरन्तर परिवर्तनशील होने के कारण अनिश्चित हैं । अतः इन्हीं पर अवलम्बित नियमों का अनिश्चित होना भी स्वाभाविक है ।

(२) मनुष्य का आर्थिक जीवन भी धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक सम्बन्धों से प्रभावित होता रहता है, अतः अर्थशास्त्र के नियम जिनका सम्बन्ध केवल आर्थिक प्रवृत्तियों से हो है पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो पाते ।

(३) अर्थशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मनुष्य का अध्ययन करने के कारण उक्त मानव जीवन की जटिल घटनाओं का विवेचन करना पड़ता है । उसका न तो भौतिक विज्ञानों की करन घटनाओं की भाँति स्पष्ट एवं सुनिश्चित विवेचन किया जा सकता है और न उन्हीं नियमों को साधारण एवं अपरिवर्तनीय रूप ही दिया जा सकता । अतः अर्थशास्त्र के नियमों का भौतिक विज्ञानों के नियमों की प्रतीक्षा अधिक अनिश्चित होना सिद्ध हुआ ।

(४) अर्थशास्त्र में अत्यन्त प्रयोग गवेषा सम्भव नहीं, क्योंकि इसका सम्बन्ध मनुष्य या स्त्री से है जो एक जीवित तथा स्वतन्त्र प्राणी है । यह स्पष्टता में काम करना चाहता है । इसे पकड़ कर प्रयोगशाला की परिस्थिति में सीमित कर कुछ प्रयोग तो किया नहीं जा सकता, जो अर्थशास्त्र के नियमों की स्थिर कह सके । भौतिक पदार्थ तो ब्रह्म है, उनका प्रयोगशाला की वाटिन दत्ता में रखना कभी दुःसाध्य नहीं । अतः भौतिक विज्ञान के तथ्या का भाँति से कभी स्थिर नहीं होते । अतः मानव जीवन सम्बन्धी सिद्धान्त परिवर्तनशील होने के कारण नियम ब्रह्म नहीं की जा सकती ।

भौतिक नियमों की अधिक स्थिरता—भौतिक विज्ञानों के नियम पूर्णरूप से निश्चित सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा वे सर्वत्र लागू होते हैं । इसका मुख्य कारण निम्नांकित है :—

(१) भौतिक विज्ञानों का सम्बन्ध मनुष्य की प्रवृत्तियों से न हाँकर भौतिक पदार्थों से है । जो निश्चित और अपरिवर्तनीय है । अतः उनके नियमों की निश्चयता एवं दृढ़ता भी स्वाभाविक है ।

(२) भौतिक विज्ञानों का विवेचनीय विषय भौतिक पदार्थ हैं, जो स्वभाव में सरल एवं अपरिवर्तनीय हैं । सरल घटनाओं में सम्बद्ध नियमों का अध्ययन होने के कारण भौतिक नियमों का स्वतः निश्चित एवं अपरिवर्तनीय होना सिद्ध होता है ।

(३) भौतिक विज्ञानों में अत्यन्त प्रयोग पूर्ण रूप से इच्छाशुभार प्रयोगशालाओं में सम्भव होने के कारण सम्बद्ध घटनाएँ समग्रतः की जा सकती हैं । यही कारण है कि भौतिक नियम अत्यन्त स्थिर हैं ।

निरूपण—उत्पुलक विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि अर्थशास्त्र के नियम उनसे निश्चित नहीं हैं जिनसे भौतिक विज्ञानों के नियम । उनको तुलना भौतिक विज्ञानों के नियमों से नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिये, आकर्षण दानि का नियम (Law of Gravitation) स्थिर नियम है, उक्त बात को प्रकट करना है कि यदि भी कण्डु आकाश में उछाला जाय या वह पृथ्वी की आर अवसर स्थितियों । बल्ले खेल में पैदा ऊँचा उछालते हैं । उनके हाथ की दानि के समुच्च ऊँचाई तक वह पैदा जाना है—पर उक्त दानि के क्षाण ही पृथ्वी उसे अपनी धार लीकता आरम्भ कर डती है । 'पृथ्वी के पास लाने का आकर्षण अधिक जाता'—और इसी आकर्षण सिद्धान्त का सम्बन्ध है । इस नियम की मर्यादा में तनिक भी मन्दत उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उल्लंघन होगा अनिवार्यता से निश्चित है ।

मूल्य वृद्धि ता मौन पहले की अपेक्षा दुगुनी बढ़ गयी। अतः उक्त नियम को हम सभी समझेंगे जा इसके साथ दूसरा समवन नियम—“जय मांग बढेगा मूल्य भी बढेगा” काम में लाया जायगा। हम देखते हैं—एक छात्र एक डेस्क को मरकाने के लिये बम लगाता है। उसी समय दूसरा छात्र उसे रोकने की चेष्टा करता है। परिणाम क्या होता है? टेस्क वहीं रहती है। नेश मान भी इसर उषर नहीं सरकती। यदि एक ही समय में दो विरुद्ध शक्तियाँ दम्ब व मरकाने और रोकने की चेष्टा में न लगती तो बम के अनुरूप या तो यह छात्र सरका दी जाती या दूसरी और पीछे हटा दी जाती। इन परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही साथ नियमों के भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अस्तु आर्थिक नियम सिन्ही परिवर्तनशील कल्पनाओं पर आविर्भूत होने के कारण वास्तविक एवं शारीरिक समझें जाते हैं।

प्रो० मार्शल का दृष्टिकोण—प्रो० मार्शल का इस सम्बन्ध में यह कथन है कि इस प्रकार के प्रतिद्वन्द्व-मुचन अथवा भौतिक विज्ञानों के नियमों में भी देय जाते हैं, जैसे निरिष्ट तापक्रम तथा दबाव (Pressure) पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात के परिणाम में मिल जाने में अतः का रूप धारण कर लेते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी भौतिक विज्ञानों के नियम वास्तविक हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में ये धारणाएँ अधिकांश महत्त्व रखती हैं, क्योंकि इनका विवेचनीय विषय अनुपलब्ध है, जिसकी इच्छाएँ, निषाएँ आदि परिवर्तनशील हैं। परन्तु भौतिक विज्ञानों के विवेचनीय विषय जड़ पदार्थ होते हैं, जो निरिष्ट परिस्थितियों में सर्वत्र यथावत् निष्ठ होते हैं। अस्तु भौतिक विज्ञानों के नियमों को प्रयोजन की भाँति में सम्मिलित करना भारी भूल है।

अर्थशास्त्र प्रश्न

इण्टर प्राक्टिस परीक्षाएँ

१—अर्थशास्त्र में आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियमों के लक्षण बताइए।

(उ० प्र० १९५७)

२—“नियम” में आप क्या समझते हैं? “आर्थिक नियम प्रवृत्तियों का कथन है।” इस बारे में आपका क्या कहना है?

(म० भा० १९५७)

३—आर्थिक नियमों में क्या तात्पर्य है? इनका स्वभाव क्या है? आर्थिक नियमों और प्राकृतिक नियमों में क्या अन्तर है? क्या आर्थिक नियम कल्पित हैं?

(अ० बा०, रा० बा० १९४९ उ० प्र० १९५०, दिल्ली हा० से० १९५०)

४—अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना आपण्ड शक्ति व नियमों की अपेक्षा ज्वारभाटा के नियमों की जाती है। क्या?

(पटना १९४९)

५—अर्थशास्त्र के नियमों का स्वभाव तथा महत्त्व बताइए।

(पुनर १९५३)

६—आर्थिक नियमों पर टिप्पणी लिखिए।

(सागर, १९५०)

अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व (Importance of the Study of Economics)

अर्थशास्त्र का महत्व—समाज के वर्तमान समूह में अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है। प्रत्येक नागरिक के लिए अर्थशास्त्र ■ ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि मानव-जीवन अत्यन्त प्रकार से प्रभावित होता रहना है परन्तु सबसे अधिक प्रभाव उम्र पर धन का पड़ता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के अत्यन्त महत्वपूर्ण धन धन का अध्ययन करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में इस भग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उसकी आर्थिक स्थिति और वातावरण उसके विचारों पर बड़ा प्रभाव डालने है। धन की प्रचुरता अथवा न्यूनता मनुष्य और समाज दोनों पर अपना प्रभाव दिखाती है। आज का प्रत्येक राष्ट्र इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह उसे अधिक सुखी एवं समृद्धिवासी बनाये। आध्यात्मिक दृष्टि में धन चाहे सब दोषों का मूल कारण ही, परन्तु मनुष्य और उसके सामाजिक जीवन में धनोपार्जन तथा धनोपयोग का इतना महत्व है कि कोई विचारशील पुरुष तथा राष्ट्र इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्र के जीवन में आर्थिक बातों का कितना बड़ा स्थान है। इसके अध्ययन से राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता या असम्पन्नता का कारण सहज में ज्ञात हो जाता है। आजकल बहुत सी समस्याओं का हल उनके आर्थिक पहलू पर निर्भर रहता है। वेद की दृष्टि तथा तत्त्वसम्बन्धी अनेक समस्याओं का हल तो अर्थशास्त्र का अध्ययन ही निकालता है। संक्षेप में, अर्थशास्त्र सब आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण आदि का अध्ययन होने से इसका महत्व स्वयं सिद्ध है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन के उद्देश्य (Objects)—किसी भी विषय का अध्ययन दो मुख्य उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो केवल ज्ञानोपार्जन के हेतु और दूसरे व्यवहारिक जीवन के साधन के हेतु। प्रत्येक विषय के अध्ययन में ये दोनों बातें न्यूनतम मात्रा में पाई जाती हैं। किसी विषय में एक उद्देश्य का अधिक महत्व होता है और किसी में दूसरे का। उदाहरण के लिये 'दर्शनशास्त्र' (Philosophy) और 'मनो-विज्ञान' (Psychology) में ज्ञानोपार्जन ही का उद्देश्य होता है। इसके विपरीत 'विकल्पाशास्त्र' एवं 'इन्जीनियरिंग' आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें व्यावहारिक लाभ का अग्र विरोध होता है। जिन शास्त्रों का अध्ययन मुख्यतः चित्त की प्रवृत्ति एवं मानसिक विकास के हेतु ज्ञानोपार्जन एवं विकासत्मक (Light-bearing) अथवा सैद्धान्तिक (Theoretical) कहलाते हैं और जिन शास्त्रों के उद्देश्य प्रधानतया व्यावहारिक जीवन में लाभ उठाना है व फलदायक (Fruit bearing) अथवा व्यावहारिक (Practical) कहलाते हैं।

अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें उपर्युक्त दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हमारे ज्ञान-क्षेत्र को वृद्धि होकर मानसिक विकास होता है और व्यावहारिक क्षेत्र में भी

अनेक लाभ इसमें प्राप्त होते हैं। इन दृष्टि में यह दर्शन आदि शास्त्रों से अधिक उपयोगी है, क्योंकि उनमें केवल ज्ञानोपाजन ही उद्देश्य रहता है, परन्तु अर्थशास्त्र के अध्ययन से, ज्ञाना प्रकार के लाभ सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक उपलब्ध होने हैं।

प्रो० मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य प्रथम तो केवल ज्ञान के लिये ज्ञान प्राप्त करना है और द्वितीय व्यावहारिक जीवन, विशेषतः सामाजिक जीवन में मार्ग प्रदर्शन करना है।¹

नीचे इसी बात की दृष्टिकोणों से अर्थशास्त्र के महत्त्व का निरूपण किया जाता है,—

(प्र) सैद्धान्तिक महत्त्व (Theoretical Importance)

ज्ञानोपाजन की दृष्टि में अर्थशास्त्र ने अध्ययन का महत्त्व बड़ा विस्तृत है। इसमें हमें निम्नलिखित सैद्धान्तिक लाभ प्राप्त होते हैं।—

(१) यह सत्यानुसंधान का एक साधन है जिसमें हमें मनुष्य और समुदाय का व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति के लिये निगमन प्रणाली का उपयोग एक उत्तम साधन है।

(२) इसकी आगमन प्रणाली द्वारा आर्थिक घटनाओं का संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण करने के पश्चात् कार्य और कारण में सम्बन्ध स्थापित करते हुए साधारण नियम स्मर्य किए जाते हैं। इन क्रिया में सर्वत्र निरीक्षण और धर्मयुक्त विश्लेषण के लिये प्रयत्न हो जाता है। यह दृष्टिकोण गुण गिनती प्रणाली से भिन्न है।

(३) इसमें अनेक घटनाओं का अध्ययन विविध दृष्टिकोणों से होने के कारण तुलनात्मक विवेचन सम्भव है। यद्यपि इसके द्वारा मनुष्य की निम्न शक्ति पुष्ट होती है।

(४) इसका अध्ययन मनुष्य के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता हुआ उसे सदा रहने में सहायक सिद्ध होता है।

(५) इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन मानसिक कल्याण का कार्य करता है। इससे मनुष्य के अस्तित्व की सत्र प्रकार की शक्तियों को पूर्ण प्रभावित मिलता है जिससे वे चलती बसती हैं।

(६) अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान-कोष की वृद्धि होती है। यद्यपि उसकी उत्पत्ति के क्या-क्या साधन हैं, जिस प्रकार धन के उपयोग से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, धन धन का विनिमय एवं निरूपण रहता है आदि समस्याओं का विवेचन यह शास्त्र करता है, यद्यपि या कहा जाय कि समाज के आर्थिक दृष्टि का पूर्ण विवरण उपस्थित करता है। यही ही नहीं, अर्थशास्त्र मनुष्य की राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत व्यय का पूर्ण ज्ञान देता है और यह वस्तु यह है कि उनमें उन्नत का स्थान है। प्राचिनक समाज की अनेक जटिल आर्थिक समस्याओं की समझने और सुलझाने के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

1—"The aims of the study are to gain knowledge for its sake and to obtain guidance in the practical conduct of life and especially of social life"—Marshall Principles of Economics, Book I, chapter IV.

१. (७) अर्थशास्त्र उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय तथा विमरुण की आदर्श रीतियों को प्रस्तुत कर मार्ग-प्रदर्शन का कार्य भी करता है। जैसे, धनोत्पत्ति एवं उपभोग के निम्न कोनसे आदर्श सम्मुख रखना चाहिये।

अतः, यह निर्विवाद स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन ज्ञान की बुद्धि एवं मनुष्य के मस्तिष्क की शक्तियों के विकास के लिये अनुपम साधन है, इसीलिये यह एक लोकप्रिय तथा आनन्दपूर्ण विषय है।

(१) व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance)

व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक उपयोगिता की दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रगता एक विशिष्ट स्थान रखता है। अर्थशास्त्र प्रवीणों का कहना है कि अर्थशास्त्र व्यावहारिक दृष्टि से बड़ा लाभदायक एवं उपयोगी विज्ञान है जिसके अध्ययन से मनुष्य के सामाजिक जीवन की प्रत्येक आर्थिक जटिल समस्याएँ सरलता पूर्वक सुलभताई जा सकती हैं। चाहे किम दृष्टिकोण से हम देव अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक जीवन के लिये प्रत्यक्ष उपयोगी है। प्रो० पीगू तो यहाँ तक कहते हैं कि "अर्थशास्त्र का प्रमुख महत्त्व न केवल मानसिक व्यायाम है और न केवल सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, अपितु यह नीतिशास्त्र का दाता और व्यवहार का सेवक है।" अर्थशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ता या गृहस्वामी, उत्पादक, व्यापारी, पूँजीपति, मजदूर सुधारक, नागरिक आदि सभी मनुष्य लाभ उठाते हैं। अब इसका क्रमशः विवेचन करना चाहिए :—

(१) उपभोक्ता (Consumer) या गृह स्वामी (Householder) को लाभ—हम अपने घरो में ही इस शास्त्र के अध्ययन को उपयोगिता सर्व प्रथम क्यों न देखें। कुछ सतर्क दृष्टि से देखन पर ज्ञात होया कि इस शास्त्र का ज्ञान गृहस्वामी के लिये अनुपेक्षणीय लाभकर है। इसके नियमों के पालन करने से वह परिवार को सीमित आय को इस प्रकार व्यय कर सकता है कि कुटुम्ब की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होकर गृहस्थ-जीवन सुखमय बन सके। उदाहरण के लिए, वह 'सम-सीमान्त उपयोगिता नियम' (Law of Equi marginal Utility) के अनुसार अपनी सीमित आय को इस प्रकार विविध भागों पर व्यय कर सकता है जिससे प्रत्येक भाग पर व्यय की गई आय की सीमान्त उपयोगिता समान हो और समस्त उपयोगिता अधिकतम हो। इसी प्रकार पारिवारिक बजट की गहमता से वह यह ज्ञात कर सकता है कि प्रत्येक मद के व्यय का क्या अनुपात है। इससे वह अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय घटा करके आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ा सकता है। मान लीजिए, एक गृहपति गन्ने-छापूर्वक मद्य, शरीर और विश्रुत (सिनेमा) आदि में आय अर्पित करता है और ऐसा करने से उसकी अन्य आवश्यक वस्तुओं (भोजन, वस्त्र, आवास) की पूर्ति में अनुपात में सम्यक् की कमी दीगयी है तो प्रथम व्यय की रक्का अनुमति देगी कि इनमें कुछ कमी करने से उसका जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सम्पन्न और प्रसन्न बन सकेगा। जिस गृहपति ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है वह अपने उत्तरदायित्व की रक्षा दूसरों की प्रोक्षा अधिक सफलतापूर्वक कर सकता है अतः अर्थशास्त्र का अध्ययन पारिवारिक सुख और सन्तोष के लिये लाभदायक है।

1—"Economic Science is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastics nor even as a means of winning truth for its own sake, but as a handmaid of Ethics and a servant of practice" Pigou.

(२) उत्पादकों (Producers) और (Manufacturers) निर्माताओं को लाभ—घर की सीमा में बाहर निकल कर व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी दृष्टि का प्रसार कर ता ज्ञान होगा कि उत्पादकों तथा निर्माताओं को अर्थशास्त्र के ज्ञान में क्या भारी लाभ पहुँचा है। वास्तविक दृष्टि में उनका अस्तित्व इसी के आधार पर है। जैसे उत्पादक के नियम (Laws of Production) एवं प्रतिस्थापन के सिद्धान्तों (Principles of Substitution) के अध्ययन में वे उत्पादन कारकों (Factors of Production) में कार्य कुशलता ला सकते हैं। जिस कारक में कार्य कुशलता की स्थूलता रहती है उसमें स्थान पर अधिक कार्यकुशल कारक प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली बहुत ही जटिल है। मर्दों व स्त्री-बच्चों समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। इनको सुलझाने के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। यह उत्पत्ति सम्बन्धी सभी ज्ञान पर उन्नत प्रकार से प्रकाश डालता है। यह प्रमाणित है कि उत्पत्ति के क्या-क्या साधन हैं, किन-किन उत्पादों में उत्पत्ति की जा सकती है तथा इस क्षेत्र में कौनसी मुख्य कठिनाइयाँ आती रहती हैं और कैसे उनका सामना किया जा सकता है। इसी प्रकार उत्पादन-प्रसार, धर्म-वैवाचन वैज्ञानिक-ग्रन्थ, भूति (मजदूरों) प्रदान करने की रीतिरिवाज, सरकारी कर, मटिया का संगठन, व्यापारिक मार्ग और सम्बन्ध, मातापिता के साधन, बैंकों, बीमा सम्पत्तियों के संगठन का ज्ञान अर्थशास्त्र द्वारा मिल सकता है।

(३) व्यापारियों (Businessmen) को लाभ—व्यापार अर्थशास्त्र का जलात्मक रूप है। जिस प्रकार टास्टर के लिए औपधियों का ज्ञान और बकील के लिये कानून का ज्ञान आवश्यक है, उन्हीं प्रकार व्यापारी के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। व्यापारियों के लिये बाजार-भाव की गतिविधि, उत्पादन प्रणाली, वस्तुओं की घटा-बढ़ी, और माँग के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। तभी वे अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक प्रवर्धन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के विद्वानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय और विनिमय मुद्रा, ढँक आदि ज्ञान की समझना परम आवश्यक है।

(४) बैंकरो (Bankers), प्रबंधकों (Managers) तथा संचालकों (Directors) को लाभ—प्रबंधन और संचालकों तथा बैंकर्स के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान मार्ग-प्रदर्शन का काम करता है। इसके सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में ये व्यक्ति अपना कार्य विशेष दक्षता एवं कुशलता में कर सकते हैं।

(५) श्रमिकों (Labourers) को लाभ—अर्थशास्त्र का ज्ञान श्रमिकों को भी लाभकर सिद्ध होता है। इसका अध्ययन में उसे यह भी भाँति ज्ञान हो जाता है कि धनोत्पत्ति में उनका क्या स्थान है। उसे अपनी ही (न अधिक न न्यून) पारिश्रमिक का भूति क्या मिलती है, उसमें वह किस प्रकार वृद्धि कर सकता है, उन सब बातों को वह जान सकता है। इसके अध्ययन में उन्हें अपने श्रमिकों और उत्पन्नदार्थियों का पूर्ण बोध हो जाता है। उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि श्रम और पूँजी किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। वह उस अपने श्रमिकों के लिये बुद्धिमत्ता में सहायता चाहिए, वह उसे दृढ़तापूर्वक चाहिए और वह नहीं करनी चाहिए समाज का उस पर क्या अधिकार है और विविध प्रकार के संगठन में उसे क्या लाभ है आदि बातों का ज्ञान अर्थशास्त्र का अध्ययन करा देता है।

(६) राजनीतिज्ञों (Statesmen) और वित्त मन्त्रियों (Financial Ministers) को लाभ—जन साधारण व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन से लाभ उठाते हैं तो राजनीतिज्ञों और सर्व-समस्या के लिये क्या यह कम उपयोगी सिद्ध होगा ? नीटिश्य के अनुसार प्राचीन भारत में राजनीति अर्थशास्त्र का ही अंग था । सामुहिक काल में शासन की राजस्व व्यवस्था (Public Finance) अर्थशास्त्र का ही अंग है । बिना उचित कर-व्यवस्था के सरकारी व्यवस्था सम्भव नहीं । अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किम प्रकार कर यदि लगाना चाहिये और किम प्रकार उस आय को व्यय करना चाहिए जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) प्राप्त हो सके । आर्थिक औद्योगिक वीजवार्ण, पैक्टो-विषय और श्रमिकों के विषय, समान और जमींदारों के विषय, समाजवाद, प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि राजनीति के समान अर्थशास्त्र में भी विषय हैं । वास्तव में, राजनीति और सामाजिक-व्यवस्था अर्थशास्त्र का क्वालिमक रूप है ।

(७) समाज सुधारक (Social Reformer) को लाभ—अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज की आर्थिक वृद्धि का विवेचन करता है, सामाजिक समृद्धि समाज सुधारक का मुख्य लक्ष्य है । धनः अर्थशास्त्र का अध्ययन समाज सुधारक को बड़ा सहायक सिद्ध होगा है । इसके अध्ययन में ज्ञानि-व्यवस्था, संयुक्त-परिवार-व्यवस्था आदि कई सामाजिक समस्याओं और रीतियों पर आर्थिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और उसमें आवश्यक सुधार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । समाज-सुधारक बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के कई सामाजिक समस्याओं को जैसे बुझा, निर्पन्था, अल्पप्रतिफल-मन्था, यस्ता-वात-मृग्य सस्या आदि को सरल नहीं कर सकता । इन प्रकार की समस्याएँ अर्थशास्त्र और समाज-सुधारक के अध्ययन की विषय-सामग्री हैं । अस्तु अर्थशास्त्र-ज्ञान-सम्पन्न समाज सुधारक अपने सुधार के कार्यों में पर्याप्त प्रकृतिता प्राप्त कर सकता है ।

(८) समाज (Society) को लाभ—अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों के आर्थिक कल्याण की वृद्धि करता है । अनुपम सामाजिक प्राप्ति है, उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है । धनः अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी सम्पन्न हितकर है । समाज को हानि पहुँचाने वाली व्यक्तिगत समस्याओं पर विवेचन करता हुआ उनके परिणाम का उपाय सुझाता है । विनाशिता या मद्य-पान व्यक्ति को ही भ्रष्ट नहीं कर देते, वे समाज को भी विपत्ति के गर्भ में गिरा देते हैं । धनः अर्थशास्त्र इन प्रकार की हानिकारी हानिप्रद प्रवृत्तियों को सर्वप्रथम परित्याग्य वस्तु बताता है । प्रारम्भिक समस्याएँ आर्थिक कारणों से ही उत्पन्न होती हैं । सामाजिक उत्पत्ति इन्हीं समस्याओं के सफलतापूर्वक सुलझाने पर आधारित है । इन आर्थिक समस्याओं का निष्पन्न समाधान अर्थशास्त्र के ही ज्ञान से प्राप्त होता है । उदाहरण के लिये, बेकारी, निर्पन्था, धन वितरण में विषमता आदि समस्याएँ सामाजिक अशांति के प्रमुख कारण हैं । सामाजिक उत्पत्ति तथा मूल के लिए इनमें सुधार का ज्ञान अति आवश्यक है । अर्थशास्त्र इन सब समस्याओं को सुलझाने में बड़ा सहायक है । अस्तु अर्थशास्त्र का अध्ययन उत्पत्ति तथा मूल के दृष्टिकोण में सम्पन्न उपयोगी है ।

मर्मशीर सामाजिक समस्याएँ—मद्येय में, अर्थशास्त्र द्वारा निम्नांकित सभी सामाजिक समस्याओं को समाज और मूलभूत जा सकता है :—

शन दुर्लभ हो जाते हैं। एक घम एक भावना एक परिवार की रमणीयता यहा नहीं बराबर रहती है। अल्पवित्त भोजन और वस्त्र मिलने के कारण बेचारे नवयुवक शिक्षा न पठित रह जाते हैं उनकी जीवन कला उद्योग ज्ञानात्मो में निरन्तर कठिन परिश्रम करने के कारण विकसित नहीं हो पाती। ऐसी भयंकर अवस्था में यदि कदाचित् प्राप्ति भी आयई तो वस विपत्ति का द्वार खुल जाता है। इस निधनता की समस्या का क्या कुछ समाधान है या नहीं इसका उपयुक्त उत्तर अर्थशास्त्र का विचार्यो दे सकता है।

२—सामयिक दुर्भिक्ष (Periodical Famines)—भारतवर्ष की दरिद्रता में सामयिक दुर्भिक्ष से वे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। सुफानिसो में आटा गोला यह कहानन इस देश के लिये पूर्ण चरितार्थ होती है। दुर्भिक्ष को रोकने के उपायो का अर्थशास्त्र में पूर्ण विवेचन होता है इस दृष्टि में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्व पूर्ण है।

३—कृषि की अवनति—भारत एक कृषि प्रधान देश है तथापि इसकी कृषि सम्बन्धी अवस्था नोचनीय है। वह भारत जो विविध खाद्य सामग्रिया विदेशो को निर्यात करता था आज उसी के लिए वह दूसरे देशों का गुँह साक रहा है। प्राधुनिक भारत घटनकर-ग्रस्त है अत अर्थशास्त्र द्वारा निरूपित उपायो की अपनाने में इसकी विपत्तियो दूर हो सकती है।

४—उद्योग धर्मो की हीन दशा बेकारी की वृद्धि यून जीवन स्तर आदि समस्याएँ—उद्योग धर्मो की हीन अवस्था बेकारी की उत्तरोत्तर वृद्धि जन मस्या की वृद्धि निषेध अवस्था तक पहुँचना जीवन स्तर का न्यूनतम होना धन वितरण की विषमता आदि अनेक समस्याओं के हल के लिये अर्थशास्त्र की चरख लेनी चाहिए। उद्योग धर्मो में उचित रूप में उन्नति हो जाने से बेकारी और अधिक जन मस्या की समस्याओं का स्वय ही भरण हो जाता स्वाभाविक है।

५—प्रातः ध हीन व्यापार मद्य निषेध आदि नीतियो का ज्ञान—शुक्तिप्रिय व्यापार मद्य निषेध आदि नीतियो का ज्ञान तथा उद्योगो का राष्ट्रीयकरण आदि बातों के हानि-नाभ का ज्ञान अर्थशास्त्र के द्वारा हो सकता है। अत इसका अध्ययन इस दृष्टि में भी आवश्यक है।

६—धर्म में अर्थ विश्वास—भारतवासियो के जीवन में धर्म का एक विनिष्ट स्थान है। प्रत्येक बात में धार्मिकता का छुट मिला होता है। अर्थप्रतिक धन परमपण्य के कारण बर्द दिशामा में तो अर्थ विश्वास पैदा हो गया है। धार्मिक अर्थ विश्वास के कारण तथ्या की व्याख्या और आदर्शों के निर्धारण में भूल हो जाता सम्भव है। उदाहरण के लिये जन्म या मृत्यु दरिद्रता अमीरी आदि बात अधिकतर भारतवासी प्रारब्ध ही के कारण या प्रकृतितत्त अथवा ईश्वर दत्त मानने हैं परन्तु वास्तव में ये आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से उत्पन्न होनेो हैं। इस प्रकार

1—The problem of poverty weighs heavily upon the modern social conscience. Mr George Bernard Shaw one of the keenest thinkers of the present generation has put this very powerfully in his characteristic manner

के अर्थविकास को बढ़ाने और नैतिक जीवन को ऊँचा उठाने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन अभीष्ट है।

७—साम्प्रदायिक असाति—देश में साम्प्रदायिक असाति स्थापित करने में अर्थशास्त्र के अध्ययन से बड़ी सहायता मिल सकती है, क्योंकि हमारी आर्थिक चरित्राङ्का की वास्तविकता देश के विभाजन व अन्य साम्प्रदायिक धाना में हम नहीं की जा सकती।

८—आदर्शों की पूर्ति—अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम यह ज्ञान कर सकते हैं कि हमारा आर्थिक विकास आदर्शों से कितना दूर है और इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या उपाय कार्य रूप में लाने चाहिए जिसमें देश समृद्धि वाली हो सके।

जन-वितरण की विषमता को सरल करने में प्राधुनिक अर्थशास्त्र की सफलता—जन के वितरण की असौम्य विषमता अभी तक अर्थशास्त्र द्वारा हल नहीं हो सकी है। आजकल की उत्पत्ति प्रणाली में पूँजी की प्रधानता होने के कारण हमकी 'पूँजीवाद प्रणाली' (Capitalistic System) कहना प्रयुक्ति न होगा। इस प्रणाली में लाभ (Profit) की प्रधानता रहती है और अन्य उत्पादनकारक (Factors of Production) का पारिथमिक इसमें प्रत्यर्त होता है जिससे पारस्परिक प्रतिलोप रहने के कारण गमय रहता है। अधिकांश उद्योगपतियों (Industrialists) द्वारा शोषण (Exploitation) होने की प्रवृत्ति ही औद्योगिक असाति का मुख्य कारण है। प्राधुनिक उत्पत्ति प्रणाली में पूँजीपतियों का पूर्ण प्रभुत्व होता है और अधिक वर्ग उनकी तुलना में बड़ी अधिक विषमता होने के कारण उत्तरो अनुचित लाभ उठाना जाता है। यही कारण है कि पूँजीवाद के विरुद्ध समाजवाद, जैंग समाजवाद (Socialism) और साम्यवाद (Communism) आदि विविध धारा की उत्पत्ति हो गई है।

पूँजीपतियों की इस शोषण नीति के कारण सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ा और श्रमिकों के रक्षार्थ कानूनी विधान आदि कई कानून बना दिए गये हैं। श्रमिक स्वयं अपनी निवृत्तता का अनुभव करने लग गए हैं और वे अपने आपका संगठित करने लग गए हैं। अस्तु स्थान-स्थान पर व्यापार एवं श्रम संघ (Trade and Labour Unions) की स्थापना होने लगी है।

देखा जाय तो जन वितरण की विषमता का पूँजीवाद प्रणाली ही मूल कारण है जिसके द्वारा बनी अधिक गरीबी होना जा रहा है और निम्न अधिक दृष्टि-वन्तता चला जा रहा है। दूसरे शब्दों में या कहा जा सकता है कि देश का जन परिमित पन्नादेश या पूँजीपतियों के हाथों में ही सीमित है और अधिकांश जन-मध्यम मुख्यमरी का चिन्ता ही नहीं है। यह सारी विषमता देश की शासन नीति पर पूर्णतया आश्रित है, अतः यही इसको दूर करने के समुचित साधनों का निर्माण करने में समर्थ है।

ग्रन्थासार्य प्रश्न

इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

- १—अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यावहारिक लाभ क्या हैं ? इसका अध्ययन ग्रामीण जीवन के सुधार में किस प्रकार महायुक्त हो सकता है ? (उ० प्र० १९५८)
 - २—अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिए और बताइये कि प्राधुनिक काल में इस विषय के अध्ययन का क्या महत्त्व है ? (उ० प्र० १९५५)
 - ३—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिये और उसके अध्ययन से सैद्धान्तिक व व्यावहारिक लाभों का उल्लेख कीजिये । (उ० प्र० १९५३, ४०, ३६, ३२)
 - ४—अर्थशास्त्र के अध्ययन की व्यावहारिक उपयोगिता का वर्णन कीजिये । (रा० बो० १९५३)
 - ५—अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रियात्मक क्या लाभ है ? (म० बो० १९६०)
 - ६—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए और अध्ययन के अध्ययन का उद्देश्य व महत्त्व स्पष्ट कीजिए । (नागपुर १९५०)
 - ७—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए और बताइए कि व्यावहारिक समस्याओं के हल में इससे ज्ञान की क्या उपयोगिता है ? (सागर १९५०)
 - ८—अर्थशास्त्र का विषय क्या है ? यह व्यावहारिक जीवन में किस हद तक उपयोगी है ? (बनारस १९५३)
 - ९—भारतीय परिस्थितियों में अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व व्यक्त कीजिए । (म० भा० १९५२)
 - १०—अर्थशास्त्र के महत्त्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए । (उस्मानिया १९५०)
 - ११—अर्थशास्त्र का अध्ययन इतना लोक प्रिय क्या हो रहा है ? (पंजाब १९४६)
- इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षा
- १२—अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या-क्या लाभ है । (उ० प्र० १९५३)

आर्थिक जीवन का विकास (Evolution of Economic Life)

धर्मशास्त्र मनुष्य की सामाजिक दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, इस बात का विशद विवरण प्रथम अध्याय में दिया जा चुका है। आज के मनुष्य का जीवन बड़ा जटिल है। हमारी अधिकांश आवश्यकताएँ उन वस्तुओं में पूर्ण होती हैं जिनका उत्पादन या निर्माण दूसरे प्राणियों के द्वारा हुआ है या जो दूर स्थित स्थानों से आई हैं। हमारी आर्थिक क्रियाएँ दूसरों की आर्थिक क्रियाओं से सम्पन्धित हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे की आवश्यकताओं पर आश्रित है। एक देश की आवश्यकताएँ तथा वहाँ के मनुष्यों का जीवन-स्तर अन्य देशों को प्रभावित करता है। इस प्रकार का आधुनिक आर्थिक जीवन बना है कि कोई बात दूसरों को प्रभावित किए बिना स्वतन्त्र रूप में स्थिर नहीं रह सकती। यह मनुष्य का आधुनिक जटिल आर्थिक जीवन कुछ अधिक परिवर्तित करने नहीं है।

समय की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य एक जंगली तथा अशुभ का और उसकी कुछ ही परिमित आवश्यकताओं में से भोजन की आवश्यकता मुख्य थी और उसकी पूर्ति वह स्वयं जंगल में या पहाड़ों में भाँस लाकर, मछली पकड़ कर अथवा बंद मूल पर खाने पर पूर्ण करता था। जहाँ जहाँ इस अवस्था में से निकल कर मनुष्य कई अवस्थाओं में, जैसे पशु पालन, कृषि, हस्तशिल्प अवस्था में, जीवन व्यतीत करता हुआ अनेक महान् कर्षों के पश्चात् आज की अवस्था में आया है।

विभिन्न अवस्थाओं का विकास किसी विशेष क्रम में अवश्य हुआ परन्तु सभी की एक में आर्थिक अवस्थाओं को एक ही समय में होता हुआ देखा जाता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न देशों में इसकी विकास अवस्थाओं में भी कुछ अन्तर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, कई स्थानों में हस्तशिल्पकला का विकास कृषि अवस्था के साथ-साथ प्रचलित पूर्ण हो गया और अनेक स्थानों में उसके बाद। इस विकास में मनुष्य कई बातों में प्रभावित हुआ परन्तु हम यहाँ उसके केवल आर्थिक विकास का ही बल्लन करेंगे। समाज के आर्थिक विकास का अध्ययन मुख्यतः दो प्रकार में किया जा सकता है :—

१—मनुष्य की आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति करने वाली क्रियाओं का सृष्टि के प्रारम्भ में अब तक का ऐतिहासिक विकास।

२—समाज के आर्थिक संगठन का विकास।

इन दोनों तन्त्रों का क्रम में नीचे वर्णन किया जाता है :—

१—प्राथमिक क्रियाओं का विकास

(१) प्रत्यक्ष प्रयत्नों की अवस्था (Stage of Direct Efforts)—
प्राथमिक सभ्यता को प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकता, प्रयत्न और संतुष्टि में अव्यक्त पनिक एव प्रत्यक्ष सम्बन्ध था । किसी आवश्यकता की प्रेरणा होने ही प्रयत्न किया जाता था और उस प्रयत्न के फलस्वरूप संतुष्टि प्रत्यक्ष हो जाती थी । उदाहरण के लिये, किसी व्यक्ति को भूख लगती थी तो कन्द-मूल-फल और मांस मसुकी प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और इन वस्तुओं को खाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था । यदि किसी व्यक्ति को अपनी रक्षार्थ मकान जैसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, तो वृक्षों की टहनियों और पत्तों आदि से झोंपड़ो बनाना था या पर्वतों की चन्दगुफों में प्रवेश करता था । वृक्षों के पत्तों, शूल और जानवरों की खाल से अपने शरीर की रक्षा करते थे । इस प्रकार हम अवस्था में प्रत्येक मनुष्य स्वावलम्बी था और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था । अतः यह स्पष्ट हो गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने पड़ते थे और प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी । इसी कारण इसे प्रत्यक्ष 'प्रयत्नों की अवस्था' कहते हैं । इसके पदवाच यह सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होना गया ।

प्रत्यक्ष प्रयत्नों का क्रम निम्न प्रकार समझिये :—

आवश्यकताएँ → प्रयत्न → संतुष्टि
(Wants)→(Efforts)→(Satisfaction)

(२) अप्रत्यक्ष प्रयत्नों की अवस्था (Stage of Indirect Efforts)
सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और अब उसकी अपने प्रयत्नों के द्वारा उगनी गमरत आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होने लगी । उमने तुरन्त इस बात का अनुभव किया कि वह अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । यदि वह केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिये वह सर्वथा योग्य और कुशल है और अन्य आवश्यक वस्तुएँ वह दूसरों से बदल कर अपनी पूर्ति कर सकता है । प्रत्यक्ष प्रयत्न केवल उसकी सीमित आवश्यकताओं के लिये ही सुलभ थे । बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रेरणा ने अप्रत्यक्ष प्रयत्नों अर्थात् विनिमय और भ्रम-विभाजन को जन्म दिया ।

इस परिस्थिति के कारण प्रयत्नों और संतुष्टि के मध्य अन्तर पड़ गया जो बदला-बदली अर्थात् वस्तु-विनिमय (Barter) द्वारा पूरा किया जाने लगा । इस प्रकार कुछ मनुष्य कृषि का कार्य करने लग गये, कुछ कपड़े बुनने का, कुछ दवाँ का और कुछ भेड़ों का कार्य करने लग गए । इस प्रकार विभिन्न प्रकार का कार्य विभिन्न मनुष्यों द्वारा सम्पन्न होने लगा । हिन्दुओं की जाति-श्रम का प्रादुर्भाव इसी अवस्था में हुआ प्रगट होता है । वस्तु-विनिमय जैसे प्रयोग में लाया जाता था, यह इन प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कुछही को भ्रम की आवश्यकता होती थी तो वह अपने परिचित कपड़े को धन में बदल लेता था । इसी प्रकार अन्य वस्तुएँ भी एक दूसरे में आवश्यकतानुसार बदली जा सकती थी । यह जान अर्थोनिहित रीत्यादि द्वारा और भी स्पष्ट कर दी गयी है :—

वस्तु-विनिमय

(३) औद्योगिक दलबन्दी की अवस्था (Stage of Industrial Grouping)—सम्पत्ता की उत्तरोत्तर उन्नति के कारण मनुष्यों की आवश्यकताओं और जनसंख्या में भी वृद्धि होती गई जिसके कारण आवश्यकताओं, प्रयत्नों और सन्तुष्टि के सम्बन्ध में और भी जटिलता घानई, जैसा कि आन्वयल हम अनुभव करते हैं। छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी कोई यह नहीं कह सकता कि यह किसी व्यक्ति विशेष के उत्पादन का फल है। उसके उत्पादन में भी कई एक व्यक्तियों अथवा कारकों ने भाग लिया है। उदाहरणार्थ, एक कुत्ता यह नहीं कह सकता कि बपड़ा उसकी ही क्रियाओं का फल है। इसका कारण स्पष्ट है कि मजाम का उत्पादन धूपन के द्वारा हुआ। उसकी लुत्ताई और बाछ में बांधने का कार्य किसी दूसरे के हाथ हुआ। मूल कालने का कार्य भी किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न हुआ। कुत्ता में दो केवल सूत की सहायता से बपड़ा बना। इस प्रकार मजकल का आधुनिक उत्पादन कई व्यक्तियों के प्रयत्नों का परिणाम है। सहकारिता और सामूहिकता आन्वयल की उत्पादन-क्रियाओं का सार है। यह संयुक्त प्रयत्न औद्योगिक दल की आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु-विनिमय द्वारा करते हैं। फिर इस दल के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति दल की आय के वितरण द्वारा होती है। बिना वितरण के, प्रत्येक व्यक्ति जिसने संयुक्त या सहकारिता उत्पादन प्रणाली में भाग लिया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रयत्न और सन्तुष्टि के मध्य में विनिमय वाले अन्तर के अतिरिक्त वितरण का रूप में एक और अन्तर पैदा हो गया। आवश्यकताओं के बाद और प्रयत्न के पश्चात् विनिमय होता है और फिर वितरण और अन्त में सन्तुष्टि होती है। अब स्थिति निम्न प्रकार हो गई :—

वस्तु-विनिमय वितरण

आवश्यकताएँ → प्रयत्न — सन्तुष्टि — सन्तुष्टि
 (व्यक्तिगत) (दल के सदस्य (दल की) (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की)
 के रूप में)

(४) मुद्रा के प्रयोग की अवस्था (Stage of the Use of Money)—यह वह अवस्था है जिसमें हम रह रहे हैं। अब तक वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इनके द्वारा कई एक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी और बहुतों हुई मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए वस्तु-विनिमय सर्वथा अयोग्य सिद्ध होने के कारण मुद्रा-विनिमय (Money Exchange) का आविष्कार हुआ। तब है—
 "आवश्यकता आविष्कारों की जननी है।" आवकल दल द्वारा उत्पादित वस्तुएँ मुद्रा के बदले बेची जाने के कारण दल की आय होने लगी है। इस की आय दल के सदस्यों में वितरित होने के कारण दल के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत आय होती है और वह खर्चाई प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान अवस्था इससे पूर्व वाली अवस्था से भिन्न है, क्योंकि उसमें दल भी उत्पत्ति वस्तु-विनिमय द्वारा होती थी न कि मुद्रा-विनिमय द्वारा और औद्योगिक जटिलता भी बढ़ गई है।

वर्तमान प्रचलित प्रणाली की विशेषताएँ

यह कुछ निर्मालस्त्रि से परिवर्तनों के कारण विषेपता रखता है। प्रथम कोई एक वस्तु कई दलों के परिश्रम का फल है। दूसरे विनिमय-प्रणाली में परिवर्तन हुआ है।

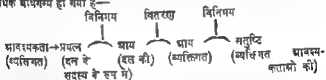
[घ] प्रथम बात का स्पष्टीकरण एवं उदाहरण देकर किया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों के निर्माण में जिसे हम पहनते हैं वही एक दला ने भाग लिया है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है —

१. मेढा को पानने वाले जो ऊन जनार कर एकत्रित करते हैं।
२. विविध दलों के लोग जो ऊन को चरागाहों में भ्रष्टियों में पहुँचाते हैं।
इसमें सब प्रकार के वातावरण, साधन भी देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सम्मिलित हैं।

३. ऊन के विविध बोटों के व्यापारी।
४. वे क्रियाएँ जहाँ ऊन की सफाई होकर बाँटा जा रूप धारण करती है।
५. ऊन के काटने वाले।
६. ऊन का बपड़ा बनाने वाले।
७. ऊनी बपड़ा के व्यापारी।
८. वर्गी।
९. बैंक और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले दल।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ऊनी वस्त्रों को जाड़ में हमारे शरीरों को शीत से बचाता है उस रूप में आने के पूर्व कई एक दलों की सेवाओं और परिश्रम का फल है। प्रत्येक उत्पादन-दल को समुक्त उत्पत्ति के विषय से श्रुत मुगलान मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है और वह दल के सदस्यों में वितरित करा दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपनी भाग से इच्छित वस्तुओं का लब्ध कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

[घ] द्वितीय परिवर्तन है विनिमय प्रणाली जो इसी युग की एक मुख्य विशेषता है। प्राज-काल विनिमय मुद्रा भ्रमण साधन से होता है। मुद्रा-विनिमय द्वारा दल का प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस प्रथा में सदस्यों को पारस्परिक अधिक अधिकृत बना दिया है और आवश्यकताओं, प्रयत्नों तथा सन्तुष्टि के सम्बन्ध को अधिक प्रयत्न एवं जटिल बना दिया है। यह सम्बन्ध नीचे दिये हुए पटल द्वारा अधिक बोधगम्य हो गया है—



२—समाज का आर्थिक संगठन

हम हमने मनुष्यों की व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से किया है। अब हम उन व्यवस्थाओं का वर्णन करेंगे जो सृष्टि के प्रारम्भ में अब तक विकसित रही, समाज के आर्थिक संगठन का विकास कहें जायें हैं।

समाज के आर्थिक संगठन का इतिहास साधारणतया निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है :—

- (१) शिकार अवस्था (Hunting Stage)
- (२) पशु-पालन अवस्था (Pastoral Stage)
- (३) कृषि अवस्था (Agricultural Stage)
- (४) हस्तशिल्प कला अवस्था (Handicraft Stage)

(५) औद्योगिक अवस्था (Industrial Stage)

(१) शिकार अवस्था (Hunting & Fishing Stage)



शिकार अवस्था

करने (Root grubbing) की अवस्था भी कहते हैं। शिकार करने के माधुनिक के समान में ऐसा करना पड़ता था। मनुष्य की आवश्यकताएँ धर्मार्थ सीमित तथा साधारण थी। आवश्यकताओं, प्रयत्नों और सन्तुष्टि में मध्यम स्तर प्रत्यक्ष था। उदाहरण के लिये, भूख की प्रणाली जानवर या मछली का शिकार करने के लिये बाध्य करती थी। शिकार द्वारा भोजन बड़ा अनिश्चित था। यदि जानवर मारा गया तो उनकी आहार मिल जाया करता था, अन्यथा भूख रहना पड़ता था। प्रारम्भिक अवस्था में जब कि हथियारों में सुधार नहीं हुआ था वह भूख मरने हुए मृतक जानवरों का शिकार भी ला लेता था। बीमार, घायल अथवा विपदग्रस्त जानवरों का मारना सरल होता है अतः उनका शिकार प्रयोग में लिया जाता था। यही नहीं वह पराजित एवं बन्दी व्यक्तियों और अस्थिर बच्चों, को भी मार कर अपना भोजन का कार्य चलाता था। रहने का तात्पर्य यह है कि उस समय 'मनुष्य मांस भक्षण' (Cannibalism) प्रचलित था।

हथियार—जड़ जोड़ने की अवस्था का शिकार अवस्था में परिणत होने पर शिकार सम्बन्धी हथियारों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारम्भिक अवस्था में शिकार करने के लिये सर्वप्रथम मूलभूत हथियार पत्थर था। वह पत्थर और लकड़ी की सहायता से चरगोश, चूहे आदि छोटे छोटे जानवरों को मार लेता था। इसीलिए इसे 'पाषाण काल' कहते हैं। उत्तर पाषाण काल में इन हथियारों में सुधार हुआ और इसमें वस्त्र उसमें धातु का प्रयोग सीखा और कई धातु के हथियार जैसे—तार, चाकू, हथोड़ा आदि शिकार करने में प्रयुक्त होने लगे। इसी कारण यह युग 'धातु काल' कहलाता है।

वस्त्र—प्रारम्भ में इस काल का मनुष्य नगनावस्था में जीवन बिताता था। समय और परिस्थितियों में उसे पेड़ों की छाल या पत्ता अथवा जानवरों की खाल से शरीर को ढकना सिखाया।

रहने की व्यवस्था तथा अग्रणी जीवन—रहने के लिए उस काल का मनुष्य स्वयं अपनी गोपनीय तैयार कर लेता था अथवा कहीं गुफा में या समतल वृक्ष के नीचे रहता था। भोजन के अभाव के कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार की खोज में भ्रमण करता था। स्थायी रूप से उसका कोई घर नहीं था। वह भ्रमण प्रवृत्त था। एक स्थान के जानवरों और वन्य-मूल फलों की न्यूनता हो जाने पर वह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अन्य स्थानों पर चला जाता करता था। शिकार

के लिए पारस्परिक सहायता बहुत होती थी। परजित व्यक्तियों के रखने के साधनों के अभाव में वे मार दिये जाते थे और उनका मांस खाने के काम में आता था। परन्तु मछलियों पर निर्वाह करी जाती जातियाँ एक स्थान पर बहुत समय तक स्थित रहती थी। उनमें इतनी पारस्परिक सहाई भी नहीं होती थी। उनका जीवन आश्वेतक जातियों की अपेक्षा अधिक मरल और सुखमय था।

जनसंख्या—इस युग की जनता भ्रमणशील एवं घिरत थी, क्योंकि जीवन निर्वाह के साधन प्राप्त न्यून, अप्राप्य और अनिश्चित थे, और भ्रमणशीलता का दूसरा कारण यह था कि जानवर शिकारी की निरन्तर आश्वेत क्रियाओं से सतर्क रहते थे और वे बहुत दूर गहरे वन में भाग जाता करते थे। अतः शिकारी भी उनके साथ घूरतक निकल जाता था। बन्द-मूल-पत्त, वनस्पति आदि प्रकृति-दत्त पदार्थ यद्यपि प्रचुर थे पर उनके खान योग्य होने में भी समय की आवश्यकता होती थी। यन्त्री यन्त्री दुमिया के कारण भी पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं होते थे। अतः जनता ने निर्वाह के के लिये इस प्रकार का वित्तुत वनों की आवश्यकता होती थी। एक शिकारी के निर्वाह के लिए न्यूनतम ५० हजार एकड़ भूमि अथवा ५० से ८० वर्ग मील भूमि की आवश्यकता होती थी। इसलिये अन्य व्यवसायों के कारण इस युग की जनसंख्या बहुत कम थी।

सामाजिक एवं आर्थिक दशा—उप समय के निवासी विन्युत जंगली और अशुभ थे। वस्तुओं के व्यक्तिगत अधिकार का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। आश्वेत और मात्स्य जीवन अवस्था में साधारण हथियारों के अनिश्चित किता की कोई विशेष वस्तु नहीं होगी थी। किसी वस्तु की जैसे ही आवश्यकता हुई, अजिा की गई और उपयुक्त हो गयी। अतः व्यक्ति अपने में पूर्ण था। बिना किसी सहायता के वह अपनी मरल आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करता था। अभी विनिमय का सूत्रपान नहीं हुआ था। पारस्परिक सहयोग तथा मेल नहीं था। मरल आपस में लड़ते रहते थे। शिकारी लोगों की अपेक्षा मछली पर जीवन निर्वाह करने वालों का जीवन अधिक आश्वेत था और वह एक स्थान पर जमकर भी रहते थे। उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति इन शिकारी लोगों की अपेक्षा अधिक थी। मछली पकड़ने के हथियार, नाने और म्यामी वर बार उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थे। मछली पकड़ने वालों की जनसंख्या शिकारी लोगों की अपेक्षा घनी थी।

(२) पशु-पालन अवस्था (Pastoral Stage)

विशेषतायें—पशु-पालन प्रगृति का प्रादुर्भाव—आश्वेत अवस्था में मनुष्य



पशु-पालन अवस्था

अपना निर्वाह जानवरों का शिकार कर और मछली मारकर करता था। यह साधन अप्रयत्ति होने के अनिश्चित अनिश्चित था। शिकार न मिलने की अवस्था में कई बार बिना आहार के दिन घाटने पड़ते थे। अतः शनं खसने इस बात का अनु-

भव करना प्रारम्भ किया कि जानवरों को मारने के स्थान पर उन्हें पालना कहीं अधिक लाभदायक है। दैसे तो इस जीवन में उसका जानवर से सम्पर्क भी बढ़ता गया जिसके कारण उनको मारने की अपेक्षा पालने की प्रवृत्ति उत्पन्न होनी लगी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के अधिक सुव्यवस्थित ढंग के अभाव का अनुभव होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने पशुपालन को अपने निर्वाह का साधन बनाया जिसके द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में निश्चित रूप में भोजन मिलने लगा। सबसे प्रथम उसने घोड़ा, बाद में कुत्ता उसके पशुपालन, बैल, भैंस, बकरी आदि जानवर पालना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में घोड़े और भैंसों को भोजन की खोज के लिये अपने साथ ले जाते थे, परन्तु कालांतर में वे अधिकार में पशुपालन से ही अपना जीवन निर्वाह करने लगे।

भोजन और वस्त्र—पाप, भैंस, भेड़-बकरी आदि पशुओं के दूध से उनकी भोजन की चिन्ता कम हुई और वस्त्रों के लिये ऊन प्राप्त होने लगी।

पशु द्वारा यातायात के साधन—अब जानवर सवारी और भार ढीने के काम भी आने लगे जिससे जाने-जाने में भी अधिक सुविधा मिलने लगी।

पर्यटनशील जीवन—(Nomadic Life)—पशुपालन के लिये चरागाहों की आवश्यकता होने लगी। मनुष्य जंगली जानवरों से बचने के लिये जलते या ठोसियाँ बनाकर रहने लगे और चरागाहों की खोज में भटकते फिरने लगे। जहाँ भी अच्छे चरागाह मिल जाते, वहाँ दिनों के लिये वहीं ठहर जाते। फिर किसी दूसरे अच्छे चरागाहों की खोज करते थे। इस प्रकार उनकी जीवन पध्दतशील था। ये घुमकूट कहलाते थे, जो अपने जानवरों के साथ इधर उधर फिरा करते थे। घालेट अवस्था में अपने भोजन के लिये इधर-उधर फिरते थे, परन्तु अब वह अपने पशुओं के भोजन अर्थात् चारे की खोज में फिरने लगे।

घासपास—पर्यटनशील होने के कारण वे एक स्थान पर मकान बनाकर स्थायी रूप से नहीं रह सकते थे। अतः वे अपने साथ तम्बू रखते थे जो अन्यकारात्मक निवास के लिए उपयोगी सिद्ध होते थे।

जनसंख्या—भोजन की प्रचुरता, निश्चितता और उसके साधनों की सुरक्षा के कारण अब घालेट अवस्था की अपेक्षा जीवन अधिक सुखमय बन गया और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी।

अब मनुष्य भोजन के लिए प्रकृति के अनिश्चित आगार का अवलम्बन छोड़ कर निजी परिश्रम पर निर्भर रहने लगा।

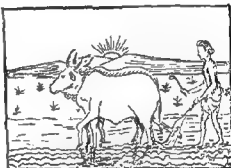
दासता (Slavery) का जन्म—बहुधा ऐसी घुमकूट जातियाँ चरागाहों की खोज में परस्पर निरन्तर लड़ाई-झगडा करती थीं। परन्तु इस समय के युद्ध में घालेट अवस्था की अपेक्षा एक विशेषता यह थी कि युद्ध बन्धियों को मारकर खा जाने के स्थान में उन्हें दासता की बेड़ी में जकड़ दिया जाता था। विजेता उन्हें अपने दास बनाकर पशुओं को रखवानी तथा अन्य लाभदायक कठिन कार्यों में नियुक्त कर दिया करता था। इस प्रकार मर भक्षण का स्थान इस अवस्था में दासता ले लिया था। दासत्व प्रथा का जन्म इसी काल में हुआ।

सामाजिक एवं अर्थिक दशा—अभी तक भूमि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार न था। केवल दास, पशु और हथियार ही व्यक्तिगत सम्पत्ति में गिने जाते थे। चरागाहों पर एक जाति केवल पास शेप रहने तक अपना अधिकार रखती थी। एक

चरागाह की पास समाप्त होने पर वे लोग अन्य धान वाले चरागाहों को खोज में चल पड़ते थे। इस प्रकार मनुष्य अब अपने लिए नहीं अपने पशुओं के लिए एक स्थान में दूसरे स्थान पर घूमने लगा। विनिमय क्रियाओं में अभी तक लोग अनभिज्ञ थे। वे अपनी आवश्यकताओं की स्वयं ही अपने प्रयत्न द्वारा पूर्ति करते थे। आवश्यकता, प्रयत्न तथा पूर्ति इन तीनों का सम्बन्ध पहले की भाँति अब भी वैसे ही प्रत्यक्ष (Direct) था।

(३) कृषि अवस्था (Agricultural Stage)

जानवरों के पालने के साथ-साथ मनुष्य ने जंगलों पीधों को भी पालना प्रारम्भ किया। जानवरों के लिए पास एकत्रित करने की प्रवृत्ति ने सम्भवतः कृषि को जन्म दिया। ज्ञान और अनुभव की दृष्टि ने फालागार में मनुष्य को अनेक लाभ दायक पीधों के उत्पादन की ओर अग्रसर किया।



भोजन और वस्त्र—
कृषि द्वारा लोगों को कई

कृषि अवस्था

प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने लगे और कपास आदि वस्तुओं की खेती ने कल की समस्या को भी हल कर दिया। अब भोजन अधिक पर्याप्त और निश्चित हो गया, धन: इनको अपने द्वारोपरि एक मात्रमिक विकासार्थ समय मिलने लगा।

आवास—अब कृषि की देल भाव के लिए मनुष्य को एक स्थान पर बसना आवश्यक हो गया। लोगों ने अपने खेतों के आस-पास स्थायी गकान बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया। वे मकान प्रारम्भिक अवस्था में कुटीर के रूप में अथवा मिट्टी के दाने हुए होने थे। इस प्रकार लोगों के भ्रमणशील जीवन का अन्त होकर स्थायी गाँवों की उत्पत्ति हो गई। धन: धन: कई एक छोटे गाँवों ने बड़े नगरों का रूप धारण कर लिया।

जनसङ्ख्या—पहले की अपेक्षा मनुष्य के अब पशुओं के भरण-पोषण के साधन अधिक पर्याप्त तथा निश्चित होने के कारण जनसङ्ख्या में गर्वांस वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार की फसलों की उपज, पशु पालन तथा अधिन: आतिमय मानव-जीवन के कारण जनसङ्ख्या में भूतपूर्व वृद्धि हुई। यह अवस्था पूर्व उल्लिखित अवस्था की अपेक्षा अधिक जन-सङ्ख्या का भरण पोषण करने में सार्थक थी।

दासत्व प्रथा की अधिक दृढता—कृषि अवस्था की दासत्व प्रथा और भी दृढ हो गई। भेती-काठी के कार्य के लिए दासों की सेवा अधिक उपयोगी सिद्ध होने लगी। इसलिए विवेका दासों को अनुत्पन्न सम्पत्ति बनाने लगे।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास—धीरे-धीरे मनुष्य परिवार बनाकर रहने लगे। भूमि पर निष्ठी व्यक्ति विशेष का अधिकार बढ्ने लगा था, किन्तु वह सारी जाति को सम्पत्ति मानो जाती थी। हाँ, मकान तथा अन्य धनक सम्पत्ति पर अलग-

ग्राम परिवारों का अवश्य अधिवार होता था। इस अवस्था में प्रत्येक परिवार अधिवार में स्वावलम्बी होता था। बाह्य समार से इसका सम्पर्क बहुत ही कम रहता था। इस प्रकार के कई कृषक परिवारों के एक समूह से गाँव का जन्म हुआ। गाँवों का जीवन विलुप्त सादा और स्वावलम्बी होता था। उसके निवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ मिल-जुल कर स्वयं बनाते थे। वे दूसरे गाँव के व्यक्तियों की प्रतीक्षा नहीं करते थे। प्रायः गाँव में लोहा और नमक इत्यादि वस्तुओं के पठिरित्त बहुत कम वस्तुएँ बाहर से आती थीं। कई स्थानों के राजनैतिक, धार्मिक, व्यापारिक व्यवसाय और किसी अन्य कारण से महत्वपूर्ण हो जाने से बड़े-बड़े नगरों की स्थापना हो गई।

गाँव में अधिकतर मनुष्य खेती करते थे। गाँव में एक थैली ऐसी होती थी जो खेती में कर अन्य घरेलू वस्तुओं के, जैसे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे पेरना, लकड़ी का काम करना, लूता बनाना इत्यादि। ऐसे लोग कारीगर कहलाते थे। कारीगरों और कृषकों को अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। ग्राम में ही बिना जाती थी। विनिमय वस्तुओं द्वारा ही होता था। मुद्रा का जन्म अभी नहीं हुआ था।

धर्मिका की भूमि (मजदूरी) भी वस्तुओं (Kind) में दी जाती थी। साधारण रूप में धर्म विभाजन का प्रारम्भ इस काल में ही हो चुका था। इस अवस्था में आवश्यकताओं, प्रयत्नों और भूमि में कुछ अशांति परीक्षा सम्बन्ध स्थापित होने लग गया था।

सामन्त (Zamindari) प्रथा का प्रादुर्भाव—इस अवस्था के प्रारम्भ काल में जो मनुष्य जितनी भूमि साफ करके उसमें कृषि कार्य कर सकता था वह उसका स्वामी बन बैठता था। ग्राम समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े कारणों से अपने समाज के मुखिया बन बैठे थे। इन लोगों ने दूसरों की भूमि छीनना प्रारम्भ किया और लोगों में अपना कृषि कार्य कराने लगे प्रथम उनका कृषि में से भाग लेने लगे। इस प्रकार तिराया (Tenants) का जन्म हुआ। यह प्रथा बढ़ने-बढ़ते इतनी बढ़ी कि कृषि युग सामन्त प्रथा में परिणत हो गया। इस सामन्त प्रथा में थोड़े से व्यक्ति सारी भूमि के स्वामी होने लगे। ये सामन्त अपने राजा के प्रति स्वामिभक्ति रखने के और अपनी अपनी भूमि को किसानों में बाँट देने के जो उसे जोतने-बोते थे और उपज का अधिकांश अपने सामन्तों को देने के।

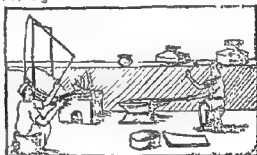
व्यापारी वर्ग की उत्पत्ति—बंटे देता जाय ता मनुष्य जीवन में बहिष्कृत भूमि का प्रादुर्भाव मित्र-मित्र स्थापना में मित्र-मित्र सहाय में हुआ। सरस प्रथम समुद्र तटीय जातियों ने व्यापार प्रारम्भ किया था। फिर जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की वृद्धि हुई, आवश्यकता ने गांधीयता में उत्पत्ति होती गई और धर्म विभाजन बढ़ता गया जैसे-जैसे व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ता गया। प्रारम्भ में व्यापार का संकीर्ण क्षेत्र था पर्यन्त एक गाँव तक ही सीमित था। धीरे-धीरे सामन्त जमींदार बग बृहत् घनी हो गया और जनस्वरूप उनकी आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगीं। उन्हें नई-नई धीरे-धीरे उत्तम विलास की वस्तुओं की इच्छा होने लगी। कारीगर भी इन श्रमीयों की इच्छाओं की पूर्ति के हेतु अच्छी-अच्छी वस्तुएँ बनाने लगे। ये वस्तुएँ ग्राम एवं स्थान से दूसरे स्थान की आवश्यकताओं के कारण जान लगीं। तब एक वर्ग और पैदा हुआ जिसका नाम व्यापारी वर्ग रखा गया। ये व्यापारी लोग एक स्थान से वस्तुएँ खरीद कर दूसरे

स्वान में देखने थे । अभी तक लोग आगों में अपनी वस्तु देकर उसके बदले में अपनी आवश्यक वस्तु ले लेते थे । रुपये-पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । परन्तु जब व्यापार में वृद्धि हुई तो व्यापारी लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय दूर-दूर तक करने लगे । अब व्यापार एक मकोरों क्षेत्र तक हो सोमिन न होकर विस्तृत हो गया और इस प्रगति के साथ मुद्रा का भी आविष्कार हुआ, यद्यपि उसका प्रारम्भिक अवस्था में एक धातुपूर्ण रूप था । इस युग के अन्त में वस्तुओं के निर्माणार्थ छोटे-छोटे कारखाने खुल गये जिनका विस्तृत उल्लेख अगली अवस्था में जो 'हस्तनिर्मित अवस्था' कहा जाता है, किया जावेगा ।

(४) हस्तशिल्प कला अवस्था (Handicraft Stage)

विशेषताएँ—कारीगरों के स्थायी वर्गों की स्थापना—समाज की प्राथमिक उत्पत्ति के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई । इनकी पूर्ति के लिए नई-नई वस्तुएँ तैयार करने के उद्योग किये जाने लगे । धीरे-धीरे स्थायित्वो

परिवारों की अवस्था का अन्त होने लगा और अलग-अलग हस्त शिल्पियों के वर्गों की स्थापना होकर सारा समाज बड़े-बड़े पेड़ों या घाँसों में विभाजित हो गया । उदाहरणार्थ, कुम्हार, बुढ़ाहे, कढ़ई, सैली, मोची आदि के



हस्तशिल्प कला अवस्था

घरे । अब वे उन वस्तुओं के बनाने में ही गारा समय और शक्ति लगाने लगे जिन्हें वे उत्तम रीति-नीति से बना सकते थे, क्योंकि इनके बदले में अन्य आवश्यक वस्तुएँ सुगमता से उपलब्ध होने लगी ।

दस्तकारी या हस्तकला युग क्यों कहा जाता है ? इस युग में वस्तुओं का निर्माण हाथ में ही होता था, अभी तक मकोरों का आविष्कार नहीं हुआ था । अतः इस अवस्था को दस्तकारी अथवा हस्तकला युग कहते हैं ।

दास प्रथा का अन्त—पूर्व प्रचलित दास प्रथा का इस समय तक पूर्ण अन्त हो गया था । मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक रहने लगे ।

विशिष्टीकरण और धर्म-विभाजन—धीरे-धीरे लोग अलग-अलग वस्तुओं के बनाने में दाता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे । फलस्वरूप धर्म-विभाजन प्रारम्भ हुआ । कोई बड़ई का काम करने लगा, कोई कुम्हार बन बैठा और कोई कपड़ा बुनने लगा । इस प्रकार लोग विविध वस्तुओं के बनाने में निपुण बनने लगे । ये लोग कारीगर अथवा कलाकार के नाम से सम्बोधित किये जाने लगे ।

मुद्रा-विनिमय प्रथा—इस कला के प्रारम्भ में वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय होने लगा । उदाहरण के लिए, कुम्हार अपने बर्तन को बुढ़ाहे के कपड़े से, किसान अपने मनुष्य को कुम्हार के औजारों से बदल-बदल करने लग । कालान्तर में वस्तु-विनिमय में नई कठिनाइयाँ और अशुविधाएँ अनुभव होने लगी । इनको दूर करने के लिये किसी

सर्वमान्य विनिमय माध्यम की खोज होने लगी, भिन्न-भिन्न स्थानों और समय पर भिन्न-भिन्न वस्तुएँ विनिमय का माध्यम बनाई गईं । अन्न वस्तुओं का विनिमय प्रायः इस से न होकर इस वस्तुओं के माध्यम द्वारा किया जाने लगा । ऐसी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का काम करती थी 'मुद्रा' कहलान लगी । धीरे-धीरे मुद्रा ने वस्तुओं के पारस्परिक प्रदत्त-उत्पन्न का स्थान न लिया जिसने कारण व्यापार में पर्याप्त उत्थिति हुई । मुद्रा का चलन इस युग की एक मुख्य विशेषता है ।

गारिवारिक प्रणाली (Domestic System)—प्रारम्भ में कारीगर स्वतन्त्र रूप में काम करने थे । वे अपने अपने छोटे-छोटे रखने थे और अपनी पूँजी में कुछ माल खादि आवश्यक वस्तुओं को खरीदते थे । तैयार हुई वस्तुओं को बिना किसी के प्रत्यक्ष करने के और जो कुछ लाभ प्राप्त होता था वह सब प्राप्त उन्हें का ही होता था । इस प्रणाली में उत्पत्ति छात्र पैमाने पर की जाती थी । कारीगर उत्पत्ति के कार्य में अधिकतर अपने कुटुम्बिका में ही मगलाना करते थे । अथवा उत्पादन-धन्दा में उत्थिति होने लगी । वस्तुओं की माँग का धेन विस्तृत होता गया । पूँजी की भी आवश्यकता बढ़ती गई । व्यापारी कारीगरों में अपने अपने माध्यम पर मजदूरी देकर माल तैयार करवाने लगे । कारीगरों को मात्र निश्चित समय पर तैयार कर पूँजीपतियों का दत्ता पड़ना था । बदले में उन्हें मजदूरी मिलती थी । इस प्रकार उत्पादन और उपभोग के बीच में मध्यस्थ का काम व्यापारी वर्ग करने लगे । उत्पत्ति की इस प्रथा को 'गारिवारिक प्रणाली' कहते थे । इस प्रकार धीरे-धीरे 'पूँजीवाद' की नींव पड़ने लगी ।

संघों की स्थापना—इस युग की एक विशेषता यह थी कि प्रत्यक्ष धन के लोभों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप था जिस कारीगर संघ (Craft Guild) कहते थे । इन संघों का कार्य वस्तुओं के मुख्य नियंत्रण करना और उनका सम्बन्ध में अपने आवश्यक नियम बनाना खादि करते थे । इन नियमों का पालन करना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के लिए अनिवार्य था । धर्म, धर्म, कारीगरों संघों का स्थान 'व्यापारी संघ' (Merchants Guild) ने न लिया जो कि व्यापार सम्बन्धी सम्बन्ध विषयों को उत्थितिपूर्ण बनाते थे पतिरिक्त राजनैतिक महत्त्व भी रखते थे ।

व्यापार में उत्थिति—विनिमय-प्रथा द्वारा अधिक मुक्तता मिलने में व्यापार में पर्याप्त उत्थिति हुई ।

यह नगरों की स्थापना—प्रौद्योगिक तथा व्यापारिक उत्थिति के माध्यम-माध्यम नगरों का बनना भी स्वाभाविक था । कारीगर उन स्थानों पर जाकर बसने लगे जहाँ पर नाम के लिए कुछ मात्र मिल गईं और तैयार माल के बेचने में सुविधा हो । इस प्रकार लोग ने प्रमुख मंडलों, नदी तथा समुद्र तट पर स्थित नगरों में बसना प्रारम्भ कर दिया ।

आवश्यकताओं, प्रयत्नों और सम्पुष्टि में अधिक परोक्षता—अब आवश्यकताओं, प्रयत्नों और कृषि के मध्य पूर्ववर्त प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहा । एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मन्त्रों वस्तुओं स्वयं उत्पन्न न करता था । वह किसी एक विशेष वस्तु बनाने में लग जाता था जिसके विनिमय द्वारा अन्य इच्छित वस्तुओं का प्राप्त कर सकता था । इस विशेषता को यों भी कहा जा सकता है कि अब विनिमय द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी ।

(५) औद्योगिक अर्थात् वर्तमान अवस्था (Industrial stage)



मनुष्य की भौतिक उत्पत्ति के फलस्वरूप उसकी आवश्यकताएँ भी उत्पन्न होती गईं। अब वस्तुओं की खोज हुई। मार्गों को हाथ द्वारा बनाई गई वस्तुएँ पुष्टि करने में समर्थ सिद्ध होने लगी। अब तो यह है कि 'आवश्यकता आविष्कारों की

जन्मी है'। मनुष्य ने औद्योगिक अवस्था के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने के परिणामस्वरूप कालान्तर में कई एक मशीनों के आविष्कार किए जिनके द्वारा आर्थिक जीवन में बहुत उपलब्धताएँ मिल गईं। उस समय के प्रारम्भिक आविष्कारों में से 'वेष्म वॉट का स्टीम इंजन'। जल के का 'फ्लाईंग शटल' और कार्टराइट का 'पावर लूम' आदि उल्लेखनीय हैं। इन आविष्कारों ने आर्थिक-जीवन को पूर्णतया व्यापक कर दिया। उत्पत्ति, व्यापार, यातायात आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। ये परिवर्तन इतने व्यापक थे कि इन्हें 'औद्योगिक क्रांति' (Industrial Revolution) में सम्मिलित करते हैं। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में १८वीं शताब्दी के अन्त और उत्तरी अमेरिका के प्रारम्भ में प्रदर्शित किया। भारतवर्ष में कुछ देर में इसका प्रभाव पड़ा।

हस्तकला का स्थान मशीनों ने ले लिया—मई-नई मशीनों के आविष्कारों ने उत्पत्ति का बीजा बिखेर दिया। अब हस्तकला का स्थान मशीनों ने ले लिया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का निर्माण कल-कारखानों के द्वारा होने लग गया है। उत्पत्ति-शील देशों में आजकल उत्पत्ति अधिकतर मशीनों द्वारा ही होती है।

कारखाना प्रणाली (Factory System) का जन्म—विभिन्न प्रकार की मशीनों के आविष्कारों ने बड़े-बड़े कारखानों का जन्म दिया, जिनमें भाप, पानी अथवा बिजली आदि की शक्ति से चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के प्रयोग ने उत्पत्ति की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई है। उत्पादन का खर्च कम हो गया है, और वस्तुएँ सस्ती हो गई हैं। हस्तकार कारखानों में जाने लग गया है।

इसके फलस्वरूप हस्तकारों के द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ कारखानों की प्रतिस्पर्धा (Competition) में नहीं टिक सकी और हस्तकारों को अपना धंधा छोड़ कर मजदूर वर्ग में सम्मिलित होना पड़ा। जो कारखाने अपने धंधे में अपनी पूँजी और बुद्धिमत्ता के साथ स्वच्छन्दता पूर्वक कार्य करते थे वे आज उद्योगपतियों के नीचे के रूप में धमिल होकर धाम चले हुए हैं। मजदूरों की समस्या में एतद्विचार होकर 'एक पूँजी जाने ब्याप्त' अथवा समस्या के लिए वस्तुएँ तैयार करते हैं।

पूँजी संचय करना, कच्चे माल की खरीदना अथवा तैयार माल की बेचना अब धर्मिका का कार्य नहीं रहता। उनका काम तो केवल माल तैयार करना है जिनके म० दि० ५

बदले सहे एक निश्चित पुष्पकार जिसे, 'वृत्ति या मजदूरी' कहते हैं, मिलता है। इस प्रकार के मनोत्पादन ढंग को 'कारखाना प्रणाली' कहते हैं।

पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में सघर्ष—आधुनिक कारखाना प्रणाली ने समाज को दो कृत्रिम घेसिया में विभक्त कर दिया है। एक तो पूँजीपति वर्ग जो कारखाने के एक प्रकार से पूर्ण स्वामी होने हैं और दूसरे श्रमिक वर्ग जो केवल केवल के लिए कारखाना में पूँजीपतिवा के अधीन काम करते हैं। पहले मानिक और मजदूर में कोई विशेष अन्तर नहीं था। दोनों एक दूसरे में मिल-जुल कर काम करते थे, मानिक मजदूर को मजदूर न समझ कर अपना एक परिवारिक व्यक्ति समझता था। दोनों में परस्पर मत-भेद और सघर्ष का कोई स्थान न था, बल्कि वे मधुवाते हवा हो गई। और इसके उत्पत्तरूप दोनों के मध्य के सम्बन्ध ने सघर्ष का रूप धारण कर लिया है और पारस्परिक बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया है। अभी मजदूर अपनी माँग की पूर्ति के हेतु हड़ताल (Strike) कर बैठते हैं और कभी पूँजीपति कारखाने को ताला लगा (Lockout) देते हैं। समाजवाद (Socialism) और साम्यवाद (Communism) की उत्पत्ति भी इसी सघर्ष का एकमात्र कारण है।

पूँजीवाद की दृढ़ता (Capitalism)—इससे पूर्व अवस्था में तो पूँजीवाद की केवल नींव ही पड़ी थी, परन्तु इस अवस्था में इसने अपना सुसंगठित रूप धारण कर लिया है। इस समय मजदूर के अधिवासा देश में समाज का आर्थिक संगठन इसी प्रकार है। सगमय सम्पूर्ण शक्ति पूँजीपतिवा के हाथ में है। आधुनिक कारखाना प्रणाली में पूँजी का महत्व बढ़ गया है क्योंकि मात्रकाल की दिवाल औद्योगिक एवं व्यापारिक व्यवस्था बिना पूँजी प्रणाली के सम्भव नहीं है। आधुनिक उत्पत्ति पर विशेष प्रभुत्व होने के कारण यह पूँजीवाद युग कहा जाता है। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिये कि समाजवाद और साम्यवाद ने भी इनसे टकरा लेने को जन्म पा लिया है। कम से तो पूँजीवाद प्रथा का अन्त कर दिया है। वहाँ समाज का आर्थिक संगठन अब साम्यवाद प्रथा के अनुसार है। अभी कुछ दिन पूर्व पूर्वी यूरोप में और एशिया में मुख्यतः चीन ने भी पूँजीवाद प्रथा का अन्त कर दिया है और साम्यवाद प्रथा को अपना लिया है।

प्रतियोगिता और व्यापारिक स्वतन्त्रता (Competition or Free Trade)—प्रतियोगिता और व्यापारिक स्वतन्त्रता इस प्रथा के दो प्रमुख किहू हैं।

शारीरिक नैतिक तथा सामाजिक पतन—कारखाना प्रणाली के अन्तर्गत शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकार उत्पन्न हो गए हैं। श्रमिक नाम पूँजीपतिवा द्वारा छड़ा जाता है और श्रमिक वर्ग को केवल जीवित रहने के लिए ही भुज (मजदूरी) मिलती है जिससे उसका शारीरिक तथा नैतिक पतन स्वाभाविक है।

प्रकृति पर आधिपत्य—मनुष्य की सहायता से मनुष्य का आधिपत्य प्रकृति पर बहुत बढ़ गया है। अनेक प्राकृतिक शक्तियाँ का प्रयोग मनोत्पादन में किया जाने लगा है जिससे कारण उत्पत्ति बड़ा परिमाण में होने लग गई है। जमीन, खलीय और आवासीय यातायात व साधन की उत्पत्ति में स्थानान्तरण कम होकर देश-देशान्तर में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर इस विश्व को एक नुदृश्य के समान बना दिया है। इस युग में नव-कारखाना, यातायात व साम्यवाद के साधन बना और दोमा कम्पनियाँ की उत्पत्ति से धन का व्यापार स्थावक अवस्था राष्ट्रीय न रह कर अन्त-

राष्ट्रीय हो गया है। कृषि में भी मशीन का प्रचुर प्रयोग होने से व्यापार के विषये ऐसी होना सम्भव हो गया है।

धातवीय एवं पत्र-मुद्रा द्वारा विनिमय—बढ़ती हुई प्राथमिक बटिलता ने मनुष्य द्वारा अधिक कुशल मुद्रा का प्राविष्टार करवा दिया है। साथ ही साथ बैंक द्वारा साध मुद्रा के प्रचार ने भी प्राथमिक जीवन का प्रगतिशील काल में कम सहायता नहीं दी है।

प्रावश्यकताओं प्रयत्नों और सन्तुष्टि में अधिक परोक्षता—यह आवश्यकता, प्रयत्न और सन्तुष्टि के मध्य बहुत ही परीण सम्बन्ध हो गया है। बिना विनिमय और विनिरण के मनुष्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष व्यक्ति यह काम करता है जिसके लिए उसमें अधिक योग्यता होती है। कार्य के बदले उसे मुद्रा में वेतन मिलता है जिसकी सहायता से वह अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। निःसन्देह आज का प्राथमिक जीवन पुराने की अपेक्षा अत्यन्त जटिल बन गया है जिसके फलस्वरूप यह सम्बन्ध प्रथम परोक्ष (Indirect) हो गया है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के प्राथमिक जीवन में देश व कालानुसार बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। इसी कारण प्रवर्धमान की एक विकास-शील (Evolutionary) विज्ञान माना गया है। अतः हमें आधुनिक प्राथमिक जीवन के वैज्ञानिक रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय-समय के इस प्रकार के परिवर्तन का अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ भी स्मरण रहे कि परिवर्तनों के मध्य कोई ऐसी दिति नहीं है जिसके कारण एक अवस्था पूर्णतया समाप्त होने के पश्चात् ही अगली अवस्था का प्रारम्भ हो तथा दो विभिन्न स्थानों में एक ही समय में अल्प अवस्थाएँ भी देखी जाती हैं। जैसे वर्तमान औद्योगिक युग में भी कृषि और घरेलू धन्य भी साध-साध प्राथमिक जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग बने हुए हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर प्रॉक्स परीक्षाएँ

- १—मनुष्य के प्राथमिक जीवन के विकास के विषय में आप क्या जानते हैं? कृषि युग तथा औद्योगिक युग में मुख्य अन्तर क्या है? (उ० प्र० १९५९)
- २—मादिराल में अब तक विभिन्न धर्मों के द्वारा प्राथमिक जीवन का जो विकास हुआ है। उसका वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक के लक्षणों को संक्षिप्त में समझाइए। (रा० धी० १९५४)
- ३—मानव समाज के प्राथमिक विकास के मुख्य सीमा चिह्न क्या हैं? (ध० बी० १९६०)
- ४—आधुनिक युग में शिकारी अवस्था से घनी और कृषि अवस्था में कम घनी आबादी क्या होती है? (ध० बा० १९४८)
- ५—प्राथमिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। एवं प्रत्येक में दूसरी अवस्था में विकास के क्या परीक्षण हैं? (पत्रा० १९५४)
- ६—प्राथमिक जीवन के विकास का मन्त्र में लिखिए।

(इन्ट्रो हा० से० १९५५, ५३)

पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान की आवश्यकता

जैसा कि प्रथम अध्याय में व्यक्त किया जा चुका है कि मध्याह्न मनुष्य के साधारण जीवन के कार्यों का अध्ययन है। अतः इसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना स्वाभाविक है। इन शब्दों का साधारण अर्थ अर्थशास्त्रीय अर्थ से दिक्कुल भिन्न होता है। जिस शब्द का अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम एक विशेष अर्थ लगाते हैं उसका साधारण बोलचाल की भाषा में अन्य अर्थ लगाया जा सकता है। इसी कारण इनके अर्थों में भ्रम उत्पन्न हो जाना सम्भव है। अतः ऐसे विविध शब्दों की व्याख्या नीचे की जाती है :—

उपयोगिता (Utility)—किसी वस्तु की आवश्यकता-पूरक शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यदि कोई वस्तु हमारे किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में उपयोगिता है। उदाहरण के लिये, भूख, भय, सुख, मदिरा आदि वस्तुएँ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। अतः उनमें उपयोगिता है।

अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द किसी नैतिक दृष्टि से प्रयुक्त नहीं होता। इसके प्रयोग से लाभ या आनन्द का भाव भी प्रगट नहीं होता है। साधारण बोलचाल में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु का उपयोगी या लाभप्रद होना है। इसके अनुसार ममल मादक वस्तुएँ उपयोगी और लाभप्रद नहीं होतीं। चाहे चाहे वस्तु नैतिक दृष्टि से बुरी हो या फटती, लाभप्रद अथवा हानिकारक, कड़वी या स्वादिष्ट, यदि वह किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता है। शराब, अफीम आदि मादक वस्तुएँ, नशीली वस्तुएँ होने में हानिकारक हैं पर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखने के कारण ये उपयोगिता-युक्त वस्तुएँ मानी जाती हैं। किसी वस्तु के उपयोग का क्या परिणाम होगा भयना वह इच्छा नहीं है, जिसकी पूर्ति की जा रही है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। उपयोगिता के लिये वस्तु का किसी के लिये समीप होना ही पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपयोगिता के कारण ही किसी वस्तु पर प्रत्येक की चाह होती है। जिस वस्तु की जितनी ही अधिक उपयोगिता प्रतीत होगी, उतनी ही अधिक उसकी चाह होगी और उनी के अनुसार अन्य वस्तु का उत्ती वदने में आदान-प्रदान होगा। इस कारण में विविध में उपयोगिता का विचार प्रधान रूप में किया जाता है।

उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता की प्रबलता या तीव्रता पर अवलम्बित है। जितनी अधिक या कम जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु की उपयोगिता होगी। यदि किसी समय बहुत तेज भूख लगी हो तो उस समय रोटी की हूपरे लिये बड़ी उपयोगिता होगी। मान लीजिये कोई व्यक्ति जोधपुर दुधामपुर की मरम्भली में यात्रा कर रहा है वह प्यास से इतना अधिक विवश हो जाय कि एक गिलास पानी बिना मर जाय। दूग दमा में पानी की उसके लिये आवश्यकता अत्यधिक है। अतः पानी की उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक है। किन्तु वही यात्री घपने विश्राम भवन में कुछ ही प्यासा हो, तो पानी की आवश्यकता पर्यावश्यक नहीं है। इसी कारण पानी की उपयोगिता उसके लिये कुछ नहीं के बराबर रहेगी।

आवश्यकताएँ देश, काल और व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्नता रखती हैं—प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएँ एक-सी नहीं होती, और न हर समय वे वही हो बनी रहती हैं। अर्थात् आवश्यकता देश, काल और व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्नता रखती हैं। उदाहरणार्थ, 'भार मरुस्थल में वानू मिट्टी की खनिज भी उपयोगिता नहीं है, परन्तु तमारे में भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिये इसको बड़ी उपयोगिता है। चीप गन्तु में लौही बल्लो की मेसमाण भी उपयोगिता नहीं होती, परन्तु शरब पानु में उसकी बड़ी उपयोगिता होती है। माँसाहारी के लिये माँस उपयोगिता रखता है, परन्तु शाकाहारी के लिये नहीं।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता के साथ जग मैनी है और आवश्यकता की तृप्ति के साथ ही अपनी बहानी समाप्त कर देती है। अस्तु उपयोगिता एक वास्तु गुण है जो कि आवश्यकता के कारण किसी वस्तु को प्राप्त होती है। उपयोगिता केवल वस्तु और अपने उपभोक्ता के मध्य सम्बन्ध प्रकट करती है।

अर्ह (Value)—अर्ह एक वस्तु के अन्दर रहने वाली एक शक्ति है, जो दूसरी वस्तुओं के साथ अपनी परिवर्तन करने में सक्षम प्रदान करती है। साधारणतः यह कि एक वस्तु की अर्ह परिवर्तनीय वस्तु से समुचित की जाती है। यदि एक सोना सोना, ६० ताका चांदी में परिवर्तित किया जाय तो सोना चांदी की अपेक्षा ६० गुना शक्ति वाला है, अथवा चांदी की शक्ति सोने की शक्ति की १/६ है।

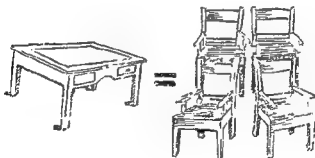
मार्शल महाशय ने कहा है 'अर्ह (Value) साधारणतया वह वस्तु है जो दूसरी वस्तुओं के परिवर्तन में साध्यम हो।' यह भाषा सरल है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अनुवर्तन करने का साध्यम है। यदि समार में एक ही वस्तु होती तो अर्ह (Value) का आदर्श कुछ न होना, क्योंकि ऐसी अवस्था में परिवर्तन सम्भव हो नहीं।

इस शब्द का उपयोग दो अर्थों में लिया जाता है :—

(१) प्रयोगार्ह (Value-in Use)—इसका अर्थ उपयोगिता में है। सामान में देया जाय तो किसी वस्तु की उपयोगिता पर उसका मूल्य निर्भर है। जब तक किसी वस्तु में उपयोगिता न होगी, तब तक कोई पदार्थ उगरे करने में कुछ भी मूल्य देने के लिय तैयार न होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक वस्तु में उपयोगिता है तो उगरे मूल्य का होना आवश्यक है। अथवा जितनी अधिक या कम उपयोगिता होगी उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु की अर्ह होगी। लक्ष्य में,

मूल्य दो चीजों पर निर्भर है—उपयोगिता (Utility) और मरुतता (Scarcity)। यदि इन दो चीजों में से एक भी अनुपस्थित हो, तो वस्तु का मूल्य नहीं होगा। यदि एक वस्तु में उपयोगिता बहुत है पर मरुतता नहीं है, अर्थात् वह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है तो उसका मूल्य नुन नहीं या बहुत कम होगा। जैय, मूषों का प्रकाश, शूद्र बाहु, जल आदि। उभी प्रकार यदि कर्टि दर्जो एक एभी कर्माज तलाना है जो किसी के घरों के लिए नमुबित नहीं बैठती ना इसके कुछ भी मूल्य नहीं है, क्योंकि इस कमीज की उपयोगिता नहीं है। प्रयोगाहा का अर्थ 'उपयोगिता' शब्द में पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होता, यद्यपि व एक दूसरे के पर्यायवाची में है, तथापि हम अहाँ शब्द को 'उपयोगिता' के अर्थ में उपयुक्त नहीं समझते।

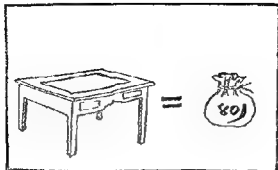
(२) विनिमय अहाँ—(Value-in-Exchange)—किसी वस्तु की अर्थ मति को विनिमय-अहाँ कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुएँ कितनी मिल सकती हैं। उदाहरण के निम्न, यदि एक भोजन वस्तु में चार बुनियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो हम कहते हैं कि एक भोजन का मूल्य चार बुनियाँ हैं और चार बुनियाँ का मूल्य एक भोजन है। विनिमय अहाँ एक सापेक्ष (Relative) शब्द है। यदि भोजन की अहाँ में वृद्धि हो जाती है, तो बुनियाँ की अहाँ अवश्य गिर जायगी। अतः भागे वस्तुओं की अहाँ में सामान्य वृद्धि (General Rise) नहीं हो सकती, क्योंकि एक की वृद्धि अन्य वस्तुओं की अहाँ की गिरावट में कारण बन जायगी।



विनिमय अहाँ (Value-in-Exchange)

सामान्य में, यह शब्द सापेक्ष होने में केवल दो प्रकार की वस्तुओं में किसी समय या स्थान विशेष पर सम्बन्ध स्थापित करता है। यह सम्बन्ध सम्प्राप्य होता है। समय और स्थान परिवर्तन में सम्बन्ध का परिवर्तन भी स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, धर्म नीति-दर्शन की अहाँ उल्लेख दाना में अधिक उच्चरक्षी है। उभी प्रकार औद्योगिक में शीतलान की अहाँ उनकी उपयोगिता अधिक है।

मूल्य (Price)—यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य धन (Money) द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे 'मूल्य' कहते हैं। जैसे एक भोजन का कीमत ८० पैसे है। या यह उसका मूल्य कहा जायगा। सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अधिकतर



मूल्य (Price)

मुद्रा में ही माँका जाता है। मारी वस्तुओं के मूल्य में साधारण वृद्धि हो सकती है, इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास हो गया है।

वस्तु (Goods)—हम चारों ओर कुछ ऐसी वस्तुओं में अपने को घिरा हुआ पाते हैं जिससे हमारी अभिलाषाएँ या आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं। हथ जिसमें खेत जोता करते हैं, चरम जिसमें दाँती लीया जाता है, पुस्तकें जिनसे चरित्र निर्माण होता है, पागड़ी, कोट, बमोजू जो शरीर रक्षा के साधन हैं और सूर्य रमणीय प्राकृतिक-दृश्य, साम्प्रदायिक जिनसे मन प्रसन्न होता है आदि—सभी हमारी आवश्यकताओं का अथवा अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। अतः ये सभी प्राकृतिक या अर्थव्यवस्थागत साधन 'वस्तु' से पुकारे जाते हैं। प्रोफेसर माजल के मत में 'वस्तु' की परिभाषा यह है : 'जो पदार्थ जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करें, 'वस्तु' है।'

साधारण बोधभाव में वस्तु का अर्थ उन पदार्थों से है जिन पर किसी समूह का अधिकार हो। परन्तु अर्थशास्त्र में यह शब्द एक विशेष अर्थ रखता है। "कोई भी पदार्थ भौतिक हो अथवा अधौतिक जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति हो, अर्थात् उपयोगिता हो, वस्तु मानी जाती है।" किसी पदार्थ को 'वस्तु' की बोटि में आने के लिये उसमें उपयोगिता होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, जल, धातु, भूतल, मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि भौतिक वस्तुएँ और प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि अधौतिक पदार्थ वस्तुओं में सम्मिलित हैं। वस्तुओं के अन्तर्गत डाक्टर, वकील, प्रोफेसर द्वारा सम्पादित सेवा और मातापिता के मापन आदि, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, सम्मिलित हैं।

कुछ लोग प्रायः 'वस्तु' शब्द को परिभाषित करने समय यह समझ बैठते हैं कि वस्तु शब्द प्राकृतिक वस्तुओं के लिये व्यवहृत होता है। किसी चीज की उपयोगिता हो उसे 'वस्तु' की बोटि में लाने के लिये पर्याप्त है। अमूर्त वस्तु वांछनीय है या अवांछनीय, इसमें कोई सम्बन्ध नहीं। उदाहरण के लिये, मदिरा अवांछनीय है किन्तु यदि यह किसी की आवश्यकता या इच्छा को पूर्ण करती है तो वह अवश्य 'वस्तु' है।

वस्तुओं का वर्गीकरण (Classification of Goods)—वस्तुएँ धनक प्रसार की होती हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार सम्भवता चाहिये :—

(१) भौतिक और अधौतिक (Material and Non-Material)

(२) हस्तान्तरणीय और अहस्तान्तरणीय (Transferable and Non-transferable)

(३) प्राकृतिक या स्वातन्त्र्यहीन और आर्थिक या स्वातन्त्र्यपूर्ण वस्तुएँ (Free and Economic Goods)

(४) उपभोग्य और उत्पादक वस्तुएँ (Consumption and Production Goods)

(५) विगस्याकी और भविष्यत्वाकी वस्तुएँ (Durable and Perishable Goods)

(६) व्यक्तिगत और सार्वजनिक वस्तुएँ (Private and Public Goods)

(१) भौतिक और अमौलिक वस्तुएँ

भौतिक वस्तुएँ (Material Goods)—ये वस्तुएँ निश्चय प्रकार, प्रकार और भार हो तथा जिन्हें कोई व्यक्ति बेच सके या छू सके, भौतिक वस्तुएँ कहलाती हैं। मटर, चना, गेहूँ, ईल कपास निच आदि कृषिज, सोहा, घोंघा, हाँवा, कोयला, पत्ता, अन्नरक आदि खनिज, उद्योगशालाओं द्वारा उत्पादित विविध भण्डित पदार्थ, मन्त्र, भवन, उपकरण, उपस्तर, (मेज कुर्सी सोफा, स्टूल, चमूच, घातपाती) और औद्योगिक पदार्थ भण्डारण में 'वस्तु' कहलाते हैं। इनमें अनिश्चित जन, बापु, जल-बापु, भूमि, अग्नि आदि सामग्र्य प्राकृतिक पदार्थ और समस्त प्रकार के प्रयोजनीय अथवा व्यवहार्य अधिकार (ग्राम, नगर, जनपद विधानसभा, उद्योगालय, कार्यालय या आधिकार्य) तथा भौतिक वस्तुओं के पट्टा, परस्मय और उपभाग में तान के स्वत्व और अधिकार (कम्पनिया के अंश (Shares), ऋण बन्ध (Debenture Bond), एक्स् अधिकार-पत्र (Patent Right), प्रतिलिप्यधिकार-पत्र (Copy-Right), विविध रचनाओं की माला करने तथा रमणीय दृश्यों से आनन्द प्राप्त करने के अधिकार, की गणना भी भौतिक वस्तुओं की क्रीडा में सम्मिलित है। ये वस्तुएँ 'वास्तु' और परिवर्तनीय अथवा हस्तान्तरणीय होती हैं।

भौतिक वस्तुओं की विशेषताएँ—भौतिक वस्तुओं की दो मुख्य विशेषताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(१) भौतिक वस्तुएँ बाह्य (External) होती हैं और उनका अस्तित्व व्यक्ति से पृथक् होता है जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है।

(२) ये हस्तान्तरणीय होती हैं अर्थात् उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिये हस्तान्तरण सम्भव है।

अमौलिक वस्तुएँ (Non-material Goods)—ये वस्तुएँ जिनका प्रकार, प्रकार या भार न हो और जिन्हें हम देख या छू भी न सकें, उन्हें 'अमौलिक वस्तुएँ' कहते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का प्रायः व्यक्तिगत रूप होने के कारण वैयक्तिक वस्तु (Personal Goods) के नाम से भी पुकारा जाता है। किसी व्यक्ति की व्यापारिक योग्यता, कार्य-कुशलता, ज्ञान, मित्रता, सुखलता, सुप्रसिद्धि आदि इतके उपर्युक्त उदाहरण हैं।

अमौलिक वस्तुओं के विभाग—अमौलिक वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं—
(अ) आन्तरिक (Internal), (ब) बाह्य (External)।

(अ) **आन्तरिक अमौलिक वस्तुओं (Internal Non-Material Goods)** में मन, मस्तिष्क, गुण, और चरित्र, आदि सम्पत्ति, श्रेष्ठ है और अमौलिक वस्तु कहलाती है, और ये गुण या शक्तियाँ जगत् पृथक् नहीं की जा सकती, जैसे-किसी व्यापारी की कार्य-कुशलता तथा किसी डाक्टर की योग्यता तथा चतुरता आदि इस श्रेणी की वस्तुएँ हैं।

विशेषता—इस प्रकार की वस्तुएँ अहस्तान्तरणीय हैं, अर्थात् एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिये, किसी डाक्टर की योग्यता तथा पातुर्प का क्रय विक्रय कदापि नहीं हो सकता। उनकी सेवाओं का लाभ रचाया जा सकता है।

(ब) बाह्य अभौतिक वस्तुएँ—(External Non-material Goods) — बाह्य अभौतिक वस्तुओं के अन्तर्गत व्यापार की ख्याति (Good will) व्यापारिक सम्बन्ध आदि इस प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं।

विशेषता—इस प्रकार की वस्तुएँ हस्तान्तरणीय होती हैं क्योंकि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये, व्यापार की ख्याति का क्रय-विक्रय हो सकता है।

(२) हस्तान्तरणीय और अहस्तान्तरणीय वस्तुएँ

(अ) हस्तान्तरणीय वस्तुएँ (Transferable Goods)—वे वस्तुएँ जिनका हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जा सके अर्थात् क्रय विक्रय हो सके, हस्तान्तरणीय वस्तुएँ कहलाती हैं। जैसे भू, वस्त्र, भोज, कुर्मी, पुस्तक, कम्पनी के भू, व्यापार की ख्याति आदि। भूमि-भवन आदि अचल सम्पत्ति भी विनिमय साध्य होने के कारण इस श्रेणी में सम्मिलित हैं, यद्यपि उनका हस्तान्तरण चल रूप में सम्भव नहीं है, फिर भी उनका स्वामित्व प्रचलित-विधान के अनुसार हस्तान्तरणीय है। विनिमय साध्यता के आवश्यक गुण

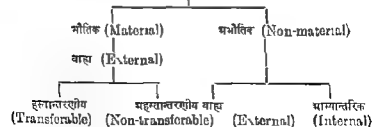
(१) वस्तु में एवं स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का गुण होना चाहिये।

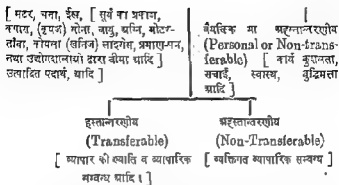
(२) केवल अधिकार-परिवर्तन का गुण भी पर्याप्त हो सकता है।

(ब) अहस्तान्तरणीय वस्तुएँ (Non-transferable Goods)—जिन वस्तुओं या उनके स्वामित्व का हस्तान्तरण सम्भव नहीं, अर्थात् जिनका क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उन्हें अहस्तान्तरणीय वस्तुएँ कहते हैं। जैसे, डाक्टर की योग्यता, वकील की कुशलता, गायक के सुरीले स्वर, अध्यापक का ज्ञान आदि। केवल इनकी सेवाओं का उपयोग दूसरा द्वारा हो सकता है।

प्रोफेसर मार्शल का 'वस्तुओं का वर्गीकरण'—प्रो० मार्शल का 'वस्तु-वर्गीकरण' निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा बनी भाँति सगोच्यता पाया है—

वस्तुएँ एवं उनका वर्गीकरण
वस्तुएँ (Goods)





(३) प्राकृतिक या स्वत्वहीन और आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ

प्राकृतिक या स्वत्वहीन वस्तुएँ (Natural or Free Goods)—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिये निःशुल्क इसी प्रकार माना में देती है कि मनुष्य को उनके लिये कोई धन खर्च नहीं करना पड़ता इसलिये इनको 'निःशुल्क वस्तुएँ' कहते हैं। इन वस्तुओं के प्रकृति-दत्त होने में इन पर किसी का स्वत्व नहीं होता है। अतः इन्हें 'स्वत्व-हीन वस्तुएँ' (Unappropriable Goods) भी कहते हैं। उदाहरण के लिये, जलवायु, मटी, घाँस, प्रारम्भिक स्थिति में प्राप्त मृत्ति आदि।

आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ (Economic Goods)—जो वस्तुएँ सीमित मात्रा में विद्यमान हैं, जो मनुष्य के प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं, जिस पर किसी का स्वत्व स्थापित हो गया है और जिनके विनिमय में अन्य वस्तुएँ या सेवाएँ प्रपक्व मुद्रा (Money) देना पड़ता हो, उन्हें 'आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ' कहते हैं। जैसे, धान, वस्त्र, भस्म, मोटर, पुस्तकें, उपस्तर (बेड-रुमी, आदि)।

(४) उपभोग और उत्पत्ति की वस्तुएँ

उपभोग की वस्तुएँ (Consumption Goods)—जो वस्तुएँ मनुष्य के काम आती हैं अर्थात् जिनमें प्रत्यक्ष और तात्कालिक रूप में आनन्दीय प्राप्तिपन्नताओं की पूर्ति होती है, उन्हें उपभोग की वस्तुएँ कहते हैं। जैसे, खाद्य सामग्री, वस्त्र, निवास-स्थान, आनन्द-जाल के साधन (साइकिन्, मोटर, वागा आदि) और पढ़ने की पुस्तकें आदि।

उत्पत्ति वस्तुएँ (Production Goods)—उपभोग-वस्तु के उत्पन्न करने में सहायता देने वाली वस्तुएँ 'उत्पत्ति वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे—मशीनरी, पच्चा माल, फैक्ट्री-भवन, औजार व बीज आदि।

(५) निरस्थायी व आचरस्थायी वस्तुएँ

निरस्थायी वस्तुएँ (Durable Goods)—वे वस्तुएँ जो दीर्घकाल-पर्यन्त या अधिक समय तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, वे 'निरस्थायी वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे—गर्जन, मशीनरी, पुस्तकें तथा उपस्तर आदि।

अचिरस्थायी वस्तुएँ (Perishable Goods)—वे वस्तुएँ जो एक ही या अल्पकाल के लिये उत्पत्ति या उपभोग के काम आती हैं वे 'अचिरस्थायी-वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे—फल, मांस, अण्डे, कोमले आदि।

(६) व्यक्तिगत और सार्वजनिक वस्तुएँ

व्यक्तिगत वस्तुएँ (Personal Goods)—वे वस्तुएँ जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो 'व्यक्तिगत वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे, भू-भवनादि, अध्यापक का ज्ञान, डाक्टर की चिकित्सा-ज्ञान आदि, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वत्व हो।

सार्वजनिक वस्तुएँ (Public Goods)—वे वस्तुएँ जिन पर समाज का सामूहिक रूप में स्वत्व हो 'सार्वजनिक वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे टाउनहाल, स्कूल, चिकित्सालय व उपवन आदि।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—कम-कमि (Value), उपयोगिता (Utility) और मूल्य (Price) में भेद दर्शाए। इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कीजिए। (रा० बो० १९५६)

२—उपयोगार्ह (Value in Use) और विनिमय अर्ह (Value in Exchange) में भेद बताइए। यह क्या कारण है कि बहुत ही उपयोगी वस्तु जैसे रोटी, एक कम उपयोगी वस्तु जैसे हीरा, से कम मूल्यवान होती है और बहुत ही अधिक उपयोगी वस्तु जैसे हवा, का कुछ भी मूल्य नहीं होता है। (रा० बो० १९५५)

३—निम्नलिखित की उचित उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। (अ) उपयोगिता (आ) अर्ह। (अ० बो० १९५४)

४—निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए :—(अ) उपयोगार्ह, (आ) विनिमय अर्ह, (इ) मूल्य, (ई) क्या किसी वस्तु में ऐसा होता है कि इसमें (१) उपयोगार्ह हो और विनिमय अर्ह नहीं हो। (ii) विनिमय अर्ह हो और उपयोगार्ह नहीं हो। (iii) क्या मूल्य में सामान्य वृद्धि हो सकती है ? (देहली हायर सेकेंडरी १९५५)

५—आर्थिक वस्तुओं की क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? क्या वे वस्तुओं के अन्तर्गत हैं—(अ) पुस्तकें, (आ) वायु, (इ) पेड़, (ई) कपड़े, (उ) भूमि। (पंजाब १९५४)

६—टिप्पणी लिखिए :—

आर्थिक वस्तुएँ तथा निष्प्रस्य वस्तुएँ।

(उ० प्र० १९६०)

धन या सम्पत्ति का साधारण अर्थ

धन शब्द के अनेक अर्थ हैं, धन अर्थशास्त्र के प्रारम्भ कर्ता जो इस शब्द के प्रयोग में समर्थ होने लगता है कि इसका वास्तविक प्रतिपाद अर्थ क्या है। साधारण भाषाशास्त्र में 'धन' शब्द से 'प्रचुरता' का आशय संते है जिसके द्वारा द्रव्य (Riches) और सम्पत्ति (Property) आदि अर्थों का बोध होता है। तदनुसार 'धन-सम्पत्ति' मनुष्य का हात्थमें उस पनाढ्य व्यक्ति में होता है जो समृद्धिवासी हो।

अर्थशास्त्रीय अर्थ--अर्थशास्त्र में धन का अर्थ बहुत व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अत्यधिक धन भी क्यों न हो वह 'निर्धन' या 'धनी' कहा जाता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से धनी मनुष्य के पास अधिक धन या सम्पत्ति होती है और निर्धन मनुष्य के पास कम। इन दोष के मध्य धन की प्रचुरता तथा न्यूनता ही इस अन्तर का प्रमुख कारण है।

धन और आर्थिक वस्तुएं (Wealth & Economic Goods)--अर्थशास्त्र में 'धन' और 'आर्थिक वस्तु' समानार्थक शब्द समझे जाते हैं। आर्थिक वस्तुएं परिमित होती हैं तथा उनका अर्थ विषय भी हो सकता है। परन्तु किसी वस्तु की केवल परिमितता (Scarcity) ही उसको 'धन' या 'अर्थ' की कोटि में सम्मिलित नहीं कर सकती। यदि वस्तु अनुपयोगी है तो कोई मूल्य देकर उसको नहीं खरीदेगा। यदि उस वस्तु को मनुष्य चाहता है और उसका उपयोग करता है तभी वह उसका 'धन' होगी। यहाँ तक कि विष, मषादि हानिकारक वस्तुओं की अर्थशास्त्र में 'धन' की श्रेणी में गणना की जाती है, क्योंकि वे भी किसी न किसी के लिये उपयोगिता रखते हैं। इसके अतिरिक्त 'धन' या 'अर्थ' बहुरूपी वस्तु का 'स्वत्व पूर्ण' होना चाहिये। इसके लिये उनका हस्तान्तरणीय होना अनिवार्य है। धन समस्त वस्तुएं 'धन' नहीं हैं। परन्तु समस्त 'धन' वस्तुएं अवश्य हैं।

सम्पत्ति का विचार करते समय आवश्यकताओं का ध्यान रखना परम आवश्यक है। एक जगदी धन मनुष्य के हाथ में पड़कर एक वृद्धि से बढ़िया पुस्तक सम्पत्ति नहीं मानी जायगी, क्योंकि उस पुस्तक का उस व्यक्ति को कुछ भी उपयोग न जान पड़ेगा। किन्तु यदि वह उसे बचल कर उसके स्थान में कुछ खाने के पदार्थों या औजारों के सामान प्राप्त कर सके तो वह पुस्तक नि मन्देह उसके लिये सम्पत्ति ठहरेगी।

धन के गुण (Attributes of Wealth)—अगर बतलाया जा चुका है कि मूल्य रखने वाली वस्तुओं को धन कहते हैं। किसी वस्तु में मूल्य होने के लिये निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है :—



(१) उपयोगिता (Utility)—वस्तु में विद्यमान मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की शक्ति का नाम 'उपयोगिता' है। अर्थशास्त्र में अनेक वस्तु कुछ न कुछ उपयोगिता रखने वाली कही जा सकती हैं, यदि वह मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में समर्थ है। इसमें किसी वस्तु के सामंशिक या हानिकारक होने का विचार नहीं किया जाता, बरकरा उसको धन दृष्टि से देखा जाता है कि वह वस्तु किसी मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करती है या नहीं? यदि इसका उत्तर 'हाँ' में पड़ता है तो तुरन्त उसको 'धन' घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शराब, भस्मीय तथा अन्य हानिकारक वस्तुएँ हानिकारक होते हुए भी 'धन' की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि वे पराधियों और भस्मीयों को आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के कारण उपयोगिता रखती हैं।

(२) परिमितता (Scarcity)—यदि कहलाने के लिये किसी वस्तु में उपयोगिता के साथ साथ 'परिमितता' या 'मर्यादा' का भी गुण होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु परिमाण में परिमित न होगी तो कोई भी व्यक्ति उसके बदले में कोई भी दूसरी वस्तु देने के लिए उत्थत न होगा। वे वस्तुएँ जो इसकी प्रचुर मात्रा में विद्यमान प्राप्त की जा सकती हैं, 'धन' नहीं बनीं जा सकती; क्योंकि उनका अपरिमित भाग में उपलब्ध होने के कारण अर्थ-विषय होना संभव नहीं। जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, जलवायु आदि। 'धन' शब्द से सापेक्षिक (Relative) धारणा का बोध होता है, जो स्थान की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता रखता है। जैसे बर्फ दिल्ली प्रान्त आसियों का धन है परन्तु हिमालय पर्वत पर रहने वालों के लिये नहीं। वायु सुने स्थान में रहने वालों के लिए धन नहीं परन्तु मनुष्यों से भरे हुए एक हॉल में जहाँ बिजली के पत्ते लगे हों, निर्दिष्ट धन होगा।

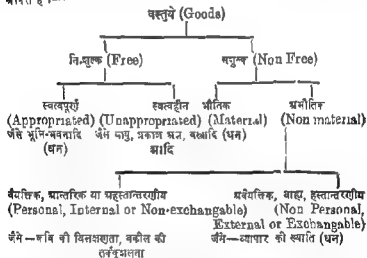
(३) हस्तान्तरणीयता या स्वत्वपूर्णता (Transferability or Appropriability)—वे वस्तुएँ धन की श्रेणी में तभी गिनी जाती हैं जब उनमें हस्तान्तरणीयता या स्वत्वपूर्णता भी हो। यह एक साधारण सम्झ की बात है कि जिस बात में एक व्यक्ति का स्वत्व नहीं रहे उसकी प्रशिक्ष के लिये न तो धन व्यय करेगा और न कुछ त्याग करेगा। दूसरे शब्दों में हस्तान्तरणीय वस्तु मूल्य वाली होने के कारण 'धन' कही जा सकती है। चन्द्रमा या सूर्य के लिये, यद्यपि उनमें उपयोगिता है, कोई व्यक्ति कुछ त्याग नहीं करता, क्योंकि वह हस्तान्तरणीय नहीं है। मनुष्य के आन्तरिक गुणों का हस्तान्तरणीय न होने के कारण 'धन' की श्रेणी में नहीं आते। किसी विविधक की दशात, गायक वा मुरीवा स्वर, मल्ला (Wrestler) का सुन्दर स्वाम्भ्य आदि अस्मान्तरिक गुणों का हस्तान्तरणीय न होने के कारण अर्थ-विषय नहीं होता,

अतः वे 'धन' क्षेत्र से बाहर की वस्तुएँ हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल भौतिक वस्तुएँ ही धन में सम्मिलित की जाती हैं। यदि कोई अमौलिक वस्तु, दस-तीन गुणों से सम्पन्न है तो वह भी अवश्य 'धन' की कोटि में अपना स्थान पा सकता है। उदाहरणार्थ 'व्यापार की स्थाति' (Goodwill) अमौलिक वस्तु होती हुई भी धन है, क्योंकि इसमें उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरणीयता तीनों गुण सम्मिलित हैं।

अतुल्य स्वयं धन नहीं है, क्योंकि वह किसी का दास (Slave) नहीं है। प्राचीन समय में दासों का ऋण-विक्रय होता था तब उसका गणना धन में होती थी।

निष्कर्षः—संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में धन से तात्पर्य उन हस्त-भौतिक और अमौलिक वस्तुओं से है जिनमें उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरणीयता के गुण विद्यमान हैं।

निम्नांकित रेखा-चित्र द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा कि कौन कौन सी वस्तुएँ धन में सम्मिलित हैं। जिन वस्तुओं की गणना धन में की जा सकती है वे (धन) शब्द से अविता है :—



धन के विषय में रस्किन (Ruskan) का दृष्टिकोण

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को अनुचित प्रधानता दी है जिसका फल यह हुआ कि रस्किन, दार्विन् आदि विद्वानों ने इसकी बड़ी आलोचना की। रस्किन ने अर्थशास्त्र के धन प्रधान स्वभाव को बड़ी आलोचना की। "अर्थशास्त्र में वे सब बांछनीय वस्तुएँ समाविष्ट हैं जिनमें अर्ह विद्यमान है।" रस्किन अर्थशास्त्र की इस धन-प्रधान परिभाषा के पूर्ण विरोधी थे। उन्ने कहते हैं "अर्थ के विषय में धन का कोई अस्तित्व ही नहीं : वह जीवन जिसमें प्रेम प्रसन्नता और गुण-प्राप्तता विद्यमान हो।" इसको अधिक स्पष्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि प्रसन्नता, प्रेम करने की शक्ति और कृतार्थ वस्तुओं की प्राप्ति करने की सामर्थ्य, ये ही वास्तविक धन हैं।

रस्किन की इस धारणा पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन गुरुओं का उन्होंने उल्लेख किया है, वे निश्चय ही वांछनीय हैं, वस्तु वे वस्तुओं की कोटि में सम्मिलित हैं। यद्यपि उनमें संप्रयोजिता है, परन्तु उनका क्रय-विक्रय न होने के कारण 'धन' या 'आर्थिक वस्तुएँ' नहीं बहो जा सकती। रस्किन का यह मत आज मृटिपूरा सिद्ध होता है।

इन सब में ऐसा अनुमान होता है कि रस्किन अर्थशास्त्र की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करना चाहता था जिसमें उक्त गुरुओं का समावेश अवश्य हो गये। पर ऐसा होना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनमें विविध गुरु 'मुद्रा' नामक अर्थशास्त्र के सुविख्यात मापदण्ड में मापे नहीं जा साने, और जो वस्तु मुद्रा (Money) में प्रकट नहीं की जा सकती, वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अधिकार नहीं रखती।

अर्थशास्त्र एक विश्वसनीय विज्ञान है अतः इसकी परिभाषा में देश-कालानुसार पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। यदि रस्किन इस बात में जोरित होने को सम्भवतः इस विज्ञान की इतनी कड़ी प्रालोचना कदापि नहीं करते।

धन के सम्बन्ध में विविध अर्थशास्त्र के विद्वानों की धारणाएँ

प्रो० मार्शल (Marshall)

प्रो० मार्शल के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति में निम्नलिखित दो प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं :—

(१) भौतिक वस्तुएँ—वे भौतिक वस्तुएँ जो सीमित, हस्तान्तरणीय तथा स्वतन्त्रपूर्ण हों। अन्य मन्त्रों में जो कहा जा सकता है कि वस्तुएँ जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार—वैधानिक या परम्परागत हो। जैसे मूलि, भवन, भूत, वस्त्र, उपस्कर (कर्त्तव्य), सम्पत्तियों के अन्तर्गत अधिकार-प्रत्येक आदि।

(२) अभौतिक वस्तुएँ—अभौतिक वस्तुओं को दो विभागों में विभक्त किया है :—

[अ] बाह्य अभौतिक वस्तुएँ—वे भौतिक वस्तुएँ जो बाह्य हा जैसे व्यापार की क्षमता (Goodwill), कवि की प्रतिभा द्वारा संप्रदत्त रचनाएँ आदि।

[ब] आन्तरिक अभौतिक वस्तुएँ—वे भौतिक वस्तुएँ जो आन्तरिक हों। जैसे दावत की दक्षता, कवि की प्राकृतिक प्रतिभा आदि व्यक्तिगत गुण और योग्यताएँ।

प्रो० मार्शल ने अनुसार सम्पत्ति या धन में सम्मिलित होने वाली वस्तुएँ भौतिक और बाह्य अभौतिक वस्तुएँ हैं। आन्तरिक अभौतिक वस्तुएँ धनोपाजन में सहायक होती हैं, परन्तु यह गुरु स्वतः सम्पत्ति में नहीं हैं। जो वस्तुएँ सम्पत्ति या धन में समाविष्ट हो सकती हैं वे सदैव बाह्य होती हैं, मनुष्य के भीतर नहीं।

प्रो० टॉसिंग (Tassig)

प्रो० टॉसिंग 'धन' या अर्थ केवल आर्थिक वस्तुओं (Economic Goods) में करते हैं। उनमें अनुसार निम्न प्राकृतिक वस्तुएँ 'धन' की कोटि में नहीं

माती । यह कहते हैं कि निःशुल्क प्राकृतिक वस्तुएँ इनकी प्रचुरता में प्राप्त होनी हैं कि मनुष्य वा उनके लिये तबिक भी पवित्र करते की आवश्यकता नहीं होती । इनके यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इनके सम्बन्ध में कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती । उदाहरण के लिये वायु, मृत्त का प्रकाश, जलवायु आदि । जब तक जन असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है तब तक तो यह प्राकृतिक प्रसाद है । जल जल आवश्यकता की अपेक्षा सीमित मात्रा में उपलब्ध हो और उसके उपयोग के लिये कुछ शुल्क देना पड़ता है (बन बगरा में पानी मूल्य में उपलब्ध होता है) तो जन आर्थिक वस्तु कहलाएगी ।

(घ) मध्य में प्रो० टॉमिन्स के अनुसार व मनुष्य धन है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मध्य है जो परिमित मात्रा में उपलब्ध है तथा जिनके लिए मनुष्य को प्रयत्न करने का आवश्यकता है ।

(ग) व मनुष्य निःशुल्क प्राकृतिक वस्तु भी धन में मन्त्रित है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो परिमित मात्रा में उपलब्ध है तथा जिनके लिये मनुष्य को परिश्रम करने की आवश्यकता है ।

प्रो० सेलिगमैन¹ (Soligman)

प्रो० सेलिगमैन व अनुसार किसी वस्तु व धन की शक्ति में धन व लिये निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता है —

(१) उपयोगिता—यदि वस्तु का धन बनने के लिये उपयोगिता रखती पाहिये । मनुष्यवासी वस्तु धन नहीं कहा जा सकती । उसे कोई व्यक्ति धन नहीं करना चाहता ।

(२) स्वरूपपूर्णता—उसका स्वरूपपूर्ण होना आवश्यक है । यदि वह स्वरूप साध्य न होगी तो धन काई न प्राप्त कर सकता ।

(३) बाह्यता—वह वस्तु मनुष्य में बाहर होना चाहिये । यदि वह बाह्य न होगी तो कोई भी व्यक्ति उस अपन में पुष्कल करके हस्तांतरण न कर सकता । बाई वस्तु है परन्तु वह धन नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह वास्तविक परिमाण में परिवर्तित न हो जाय ।

(४) परिमितता—वस्तु का परिमाण में सीमित होना भी आवश्यक है । यदि वह अनन्त लिये निःशुल्क है तो वह उसमें प्रत्यक्ष अवश्य हो जायगा परन्तु जहाँ तक मनुष्य का उस वस्तु में सम्बन्ध है उसका सम्बन्ध होना व कारण उसमें और धन प्राप्तियाँ में कोई भी अन्तर नहीं होता ।

(५) विनिमय साध्यता—आर्थिक मन्त्र वस्तुओं और अस्वित्तों में वास्तविक विनिमय (Inter change) पर आश्रित है । जलमान समय में वह प्रत्यक्ष धन जा हस्तांतरित हो जाय धन है ।

संग्रह में यदि कोई वस्तु उपयोगिता नहीं रखती तो उसका कोई मूल्य नहीं होगी यदि वह स्वरूपपूर्ण है तो उसका कोई प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह बाह्य नहीं है तो वह धन व पुष्कल नहीं हो जा सकता यदि वह मात्रा में परिमित न हो है तो उसका अर्थ में कोई कुछ भी नहीं होगा ।

प्रो० महता (Mehta)

घाफके मतानुसार 'बेवल वे ही भौतिक वस्तुएँ, जो उपयोगी तथा मीमित हों, धन या सम्पत्ति में सम्मिलित की जा सकती हैं। वे विशेषतया इस बात पर बल देते हैं कि अभौतिक वस्तुओं का अस्तित्व भौतिक वस्तुओं से पृथक् नहीं होना। प्रत्येक अभौतिक वस्तु किसी न किसी भौतिक वस्तु के शुद्ध या विशेषता में सम्मिलित होती है। भौतिक वस्तुओं की 'धन' या 'सम्पत्ति' में गणना करने के पश्चात् उनके विशिष्ट गुणों को भी इस कोटि में सम्मिलित करना एक प्रचार में पुनरावृत्ति (उन्नी वस्तु का दुबारा गिनना) बही जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि में उन्होंने प्रो० फिदर के कथन को उद्धृत करते हुए बतलाया है कि एक रेल की कम्पनी का अंश (Share) और रेल की यात्रा पृथक्-पृथक् सम्पत्ति की मर्दें नहीं हैं। बे क्रमशः सम्पत्ति, उस सम्पत्ति का स्वत्व और उस सम्पत्ति की मेवा है। साधारणतया मनुष्य स्वयं सम्पत्ति या धन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः उसकी सेवाओं को सम्पत्ति में गिना जाना चाहिये, यदि वे उपयोगी एवं परिमित हों। परन्तु जहाँ तक निर्जीव पदार्थों यथवा पशुओं का प्रश्न है, वे सम्पत्ति में सम्मिलित कर लिये जाते हैं अस्तु उनकी मेवाओं को पृथक् सम्पत्ति में गिनना भ्रम मान है, क्योंकि उनकी सराना 'द्विगुणता' दोष उत्पन्न कर देती है।

धन (Wealth) और मुद्रा (Money) में अन्तर

उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरणीयता आदि गुणों के कारण 'मुद्रा' धन की श्रेणी में आ जाती है। अस्तु समस्त मुद्रा के स्वरूप धन है, पर समस्त धन मुद्रा नहीं है। धन या सम्पत्ति के कई रूप होते हैं, उसमें मुद्रा एक रूप है।

धन (Wealth) और आय (Income) में भेद

धन से मनुष्य को सामयिक प्राप्ति होती है वह 'आय' कहलाती है। आय धन का एक प्रकार से प्रवाह (Flow) है, न कि कोप। आय के साथ समय का सम्बन्ध होता है, जैसे मासिक या वार्षिक आय। आय कम हमारा समस्त आर्थिक जीवन प्रचलित मुद्रा के आधार पर ही चलता है। इसलिये साधारणतया आय रुपये पैसे में ही प्रकट की जाती है। फिर भी यदि हमारी आय अन्य किसी रूप में प्राप्त होती है, तो उसका भी अनुमान लगाया होगा, क्योंकि आय का वास्तविक अर्थ लाभ से है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति के पास एक लाख रुपयों के मूल्य की अचल सम्पत्ति है, तो यह सम्पत्ति 'धन' हुआ और यदि उसे इस सम्पत्ति में पाँच हजार रुपये की प्राप्ति है, तो यह उसकी 'आय' हुई। इसी प्रकार अधिक की दैनिक या साप्ताहिक भृति भी 'आय' है न कि धन।

आय (Income) और पूँजी (Capital) में भेद

एक प्रकार से स्थिर वस्तु है जिसका समय में कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रायः गतिशील है और उसका समय से बड़ा सम्बन्ध है।

धन और सामाजिक कल्याण (Wealth & Welfare)

एक साधारणतया व्यक्ति और समाज का समृद्धि तथा कल्याण की वृद्धि करता है। यदि कोई व्यक्ति धनी है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपनी जीवन भली प्रकार बिताता है और दूसरा को भी सहायता पहुँचाता है। धन की नृनाधिक मात्रा में मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धनात्मक की पूर्ति में बड़ा भ्रमण पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति धनाढ्य है तो वह भली प्रकार स्वास्थ्यवर्धनात्मक की पूर्ति कर सकता है जिसमें वह अपने जीवन का एक अच्छा एक करता है। मनुष्य समाज का एक है धन समाज का प्रभाव व्यक्ति पर और व्यक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ता है। किसी व्यक्ति का जीवन का सुखी बनाना व निप सारे समाज को सुखी बनाना आवश्यक है। परन्तु प्रत्येक समाज में धनधन के नाम से भी जो दूसरों का शोषण कर निजी कल्याण चाहता है। यही कारण है कि धन समाज के चारों ओर असन्तोष और अस्थिरता फैलता है।

भौतिक समृद्धता पर स्थिर समाज में जितना धन अधिक उत्पन्न होगा उतना ही अधिक वह सुखी होगा। परन्तु इसके बिना यह आवश्यक है कि धन का वितरण इस प्रकार किया जाय कि समाज के प्रत्येक प्राणी को समान धन प्राप्त हो जिससे समाज को अधिकतम लाभ हो सके। प्राथमिक धन वितरण स्वतन्त्रता के कारण अनेक व्यक्ति निधन है और देश का अर्थव्यवस्था धन कुछ ही व्यक्ति के हाथ में है जो धनी कहलाते हैं। इस भाँति निधनता को दूर करने में ही समाज का कल्याण हो सकता है।

सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए जनसंख्या द्वारा उपनिष्ठा जनसंख्या पर विचार करना भी हितकर है। यदि समाज की आय जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में नहीं है तो समाज का दुखी रहना स्वाभाविक है। समाज की समृद्धि व निधन धन का जनसंख्या की प्रवृत्ति अधिक बढ़ता आवश्यक है।

समाज के कल्याण की वृद्धि में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला धन वाला भी है जैसे — धन की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, श्रमिकों का काम करने की प्रवृत्ति उनकी धृति तथा उनका स्वास्थ्य, मर्यादा प्रादि बाना की भी पूरी-पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी दबला आवश्यक है कि श्रमिक श्रमियों का काम प्रतिवृत्ति प्रवृत्ति में काम करना तो प्रारम्भ नहीं कर देते हैं। श्रमिक जब व कल्याण का अधिक महत्व है क्योंकि उन पर देश के उत्पादन का परिणाम स्थित है।

संक्षेप में धन कल्याण प्राप्ति का माध्यम मान है और स्वयं कल्याण प्राप्ति इसका लक्ष्य है।

धन का वर्गीकरण (Classification of Wealth)

धन का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में विभक्त की जा सकता है —

- १ व्यक्तिगत या निजी धन (Individual or Private Wealth)
- २ वैयक्तिक धन (Personal Wealth)
- ३ सामाजिक या सामूहिक धन (Social or Collective Wealth)
- ४ राष्ट्रीय धन (National Wealth)
- ५ अन्तराष्ट्रीय या साव्यवर्त्मिक धन (International or Cosmopolitan Wealth)

६. नास्ति धन (Negative Wealth)
७. प्रतिनिधि धन (Representative Wealth)

प्रो० मार्शल कृत धन का वर्गीकरण

प्रो० मार्शल न धन या सम्पत्ति को चार वर्गों में विभाजित किया है —

१. व्यक्तिगत या निजी धन,
२. सामाजिक, सामूहिक या सार्वजनिक धन
३. राष्ट्रीय धन,
४. अन्तर्राष्ट्रीय या सार्वभौम धन ।

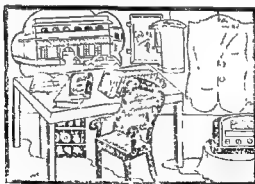
१. व्यक्तिगत या निजी धन (Individual or Private Wealth)

व्यक्तिगत सम्पत्ति में निम्निर्दिष्ट धन की गणना की जाती है —

(१) वे सब भौतिक वस्तुएँ जिन पर किसी व्यक्ति विषय का स्वत्व और अधिकार हो, जैसे भूमि, भवन, यन्त्र, वस्त्र आभूषण उपकरण (जर्नोचर), मशीनरी आदि । यदि उन व्यक्ति ने कुछ ऋण ले रखा है तो उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति में से उतना घटा पड़ा देना चाहिये । इस प्रकार उसकी सम्पत्ति का सौक-लोक अनुमान लग सकता है ।

(२) वे सब सम्भौतिक वस्तुएँ, जो बाहर हों, जैसे व्यापार की रकबा आदि ।

(३) सबकी सामूहिक सम्पत्ति में किसी व्यक्ति विशेष का भाग, जैसे सार्वजनिक सम्पत्ति तथा मर्यादा से बाहर उठाने का अधिकार, न्यायानय में न्यायाधीश द्वारा न्याय प्राप्ति, शिक्षण सम्पादन से निम्न एक या अनेक शता की विला प्राप्ति करना आदि का अधिकार ।



व्यक्तिगत या निजी धन

२. वैयक्तिक धन (Personal Wealth)

इसमें किसी व्यक्ति विषय के आम्नान्तरिण गुण सम्पत्तयें तथा वशता आदि बातें सम्मिलित होती हैं जो उनमें कर्म, पुण्यक नष्ट हो जा सकती हैं । मनुष्य की सम्भौतिक आम्नान्तरिण वस्तुएँ जिनका हस्तान्तरण नहीं हो सकता अर्थात् क्रय-विक्रय

सम्भव नहीं। परन्तु ये वस्तुएँ वास्तविक अर्थ में धन कहलाने की अधिकारी नहीं हैं। यदि इसको सम्मानित पद (Honorary Title) दिया भी तो अधिक से अधिक 'व्यक्तिगत संपत्ति' कह सकते हैं। कनिष्ठ अर्थशास्त्री उक्त वस्तुओं तथा विशेषताओं को धन या संपत्ति कह कर सम्बोधित करते हैं। वास्तव में इन प्रकार का धन अर्थशास्त्र के 'धन' की कोटि में नहीं आ सकता।

३. सामाजिक या सामूहिक धन (Social or Collective Wealth)

इस सम्पत्ति में वे सब भौतिक और धार्मिक वस्तुएँ समाविष्ट हैं, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत अर्थान्वित निजी अधिकार नहीं होता, परन्तु जिन पर प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकारों और छद्म सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का अधिकार होता है। उदाहरणार्थ—मन्दिर, बाग, स्टेट रेलवे, मन्त्रिवालय, राजाघर घर, टाउन हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, राजकीय शिक्षण-संस्थाएँ आदि।



सामाजिक या सामूहिक धन

४. राष्ट्रीय धन (National Wealth)

राष्ट्रीय सम्पत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं की गणना होनी है :—

- (१) राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ।
- (२) राष्ट्र का सामूहिक धन, जैसे—रेल, उद्यान, पुस्तकालय, मन्दिर भवन, सरकारी तथा छद्म-सरकारी भवन, हार्बर, डॉक आदि।
- (३) राष्ट्र का समस्त प्रकृतिक प्रसाद, जैसे—देश की स्थिति, नदी, पर्वत, जलवायु, वन, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक सौन्दर्य।
- (४) राष्ट्र की धर्मोपनिषद् वस्तुएँ, जैसे—राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य-प्रबन्ध, संपन्नता मुख्यवस्तु, राज्यन व्यक्तियों के उच्च आदर्श एवं आन्तरिक गुण, योग्यताएँ आदि।

पर्यासास्त्र के शाठक के मन में शका होना स्वाभाविक है कि प्राकृतिक पदार्थ (देश की जनवायु तथा भौगोलिक परिस्थिति) एवं प्रभौतिक पदार्थ (सरसिगता, भूदान् आदर्श, सुसामन आदि) किन प्रकार धन की कोटि में परिगणित हो सकते हैं। ठीक, उसकी शका उचित है। पर गृही 'सम्पत्ति' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है।

(१) यहाँ के निवागिया का सम्पूर्ण व्यक्तिगत धन भौतिक तथा प्रभौतिक—यही तक कि मनुष्य की जाति सम्बन्धी (Racial Characteristics) विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं।

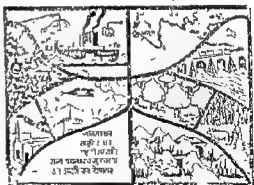
(२) सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक सम्पत्ति जैसे—सुनिस्सिपन भवन, सार्वजनिक भवन, बाग, सड़कें, पुस्तकालय आदि।

(३) उपर्युक्त दोनों प्रकार की सम्पत्तियाँ के प्रतिरित्त अन्य सब सम्पत्तियाँ जिन पर स्थानीय, प्रांतीय प्रथवा केन्द्रीय सरकारों का स्वत्व हो। जैसे, समद भवन और सन्निवास, बन्दरगाह आदि।

(४) भारत में प्राकृतिक लाभ, इसकी भौगोलिक स्थिति, जनवायु पैदावार प्राकृतिक साधन, सगा समुदा आदि शक्ति, हिमालय, विनयाचल आदि पर्वत, इसकी नई भौतिक, धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य सम्पादन के स्थान (Health Resorts) रेल, मोटर, वायुमान, समुद्री जहाज, कारण, महत् विशा संस्थाएँ, रोगी वा वैदिक जीवन, सुखयुक्त वस्त्र तथा साधन प्रसूतियाँ आदि। राजमहल भी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, क्योंकि प्रतिद्वन्द्व धनवा विदेशी शक्ति इसकी देखने के लिये धन ले रहे हैं। जो कुछ वे भारत में व्यय करते हैं, उससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है।

सम्पत्तियों की समता करते समय इसका ध्यान रखना चाहिये कि हम देश को जितना श्रेष्ठ धन्य देशों से बना है उसकी उसकी सम्पत्ति में जोड़ देना चाहिये और जितना श्रेष्ठ दूसरे देशों को देना है उसे उसकी सम्पत्ति में से निवास देना चाहिये।

५. अन्तराष्ट्रीय या सार्वभौम धन (International Cosmopolitan Wealth)



राष्ट्रीय सम्पत्ति

अन्तराष्ट्रीय धनका सार्वभौम धन में निम्नलिखित धन सम्मिलित है :—

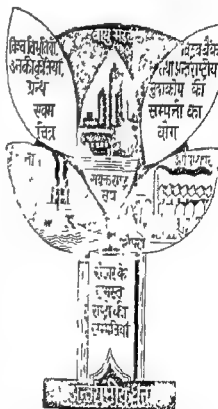
(१) सभार के समस्त राष्ट्रीय सम्पत्तियों का योग।

(२) वे सब वस्तुएँ, जिन पर किसी राज्य विशेष का अधिकार नहीं होता, उन पर सम्मत् मान्य समाज का अधिकार होता है। जैसे—सागर, महासागर आदि ।

(३) वैज्ञानिक ज्ञान तथा अनुसंधान, आविष्कार आदि इसके सम्मिलित हैं। वही भी किसी वस्तु का आविष्कार हो शोध हो उसका सभी सम्बन्धों में प्रचार हो जाता है और जो किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है ।

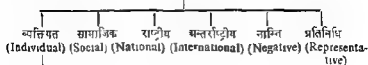
६—नास्ति धन (Negative Wealth)

इसमें किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र व समाज का घातीय सम्पत्ति चाहिए। जैसे बंध (War Bond) यह राष्ट्र का नास्ति धन है। राष्ट्र का हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ भी नास्ति धन कहलाती हैं। जैसे, फमसा का नष्ट करने वाले जंगली सुषार आदि। कुछ समय पूर्व हमारी 'सोवियत की भोली' का अपनी सोमा में से (Molasses) हटाने के लिए कुछ व्यय करना पड़ा था। उस परिस्थिति में (Molasses) नास्ति धन कहलाता था।



७—प्रतिनिधि धन (Representative)

विविध प्रकार का धन



उपभोग की वस्तुएँ उत्पत्ति की वस्तुएँ व्यापार की क्वालि वक्षता, स्वास्थ्य
 धन, वस्त्र, फर्नीचर मकानगरे, प्रोगर (Goodwill) (Personal wealth)
 आदि। आदि।

क्या व्यक्ति के आन्तरिक गुण धन की कोटि में माते हैं ?

नन्हा, किसी डाक्टर की चोरा फाड़ी करने की चतुराई, प्रोफेसर का पाठ्य, बैरिस्टर की तर्क कुशलता, महानवि की दूरदर्शनी प्रतिभा, शासन व्यवस्था की योग्यता, सामक का सधुर स्वर, पहलवान की शक्ति, किसी का सुन्दर स्वर आदि इस प्रकार के गुण व्यक्ति में सदा अविच्छिन्न रहने के कारण धन की कोटि के अन्तर्गत नहीं आते। इसमें यद्यपि उपयोगिता है, परन्तु इन अविच्छिन्न, आम्मान्तरिक वस्तुओं के प्रह्वान्तरणीय होने के कारण इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं। अतः ये धन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती। यद्यपि एक चिकित्सक अपने हस्तलापन को महत्वपूर्ण वस्तु समझ कर उस पर अभिमान करता है और इसलिये उसकी रक्षा के निमित्त वह अपने कुशल आशु और कोमल हाथ का धोषा कराता है। ऐसी वस्तुएँ यद्यपि प्रयत्नश्रिया की दृष्टि में वैयक्तिक सम्पत्ति कहाती हैं। पर गम्भीरता से परीक्षा की जाय तो ये दूषित हैं।

प्रो० मार्शल इन आम्मान्तरिक वस्तुओं को 'वैयक्तिक धन' (Personal wealth) के नाम से पुकारते हैं। प्रो० मैलिंगमैन कहते हैं कि मनुष्य के भौतिक गुण उनके धनार्जन में अनेक ही महत्वपूर्ण भिन्न होते हैं, परन्तु वे कुछ पदार्थों में 'धन' नहीं हैं। रचनापूर्वक कहन है कि 'धन' में केवल मनुष्य की बाह्य वस्तुएँ ही सम्मिलित हो सकती हैं न कि आन्तरिक।

व्यक्तिगत सेवाएँ (Personal Services)

क्या डाक्टर, वकील, अध्यापक, घरेलू नौकर आदि की सेवाएँ 'धन' की कोटि में आती हैं ? हा, इनमें आ सामान्य धन की कोटि में आती हैं। कारण स्पष्ट है। इनमें धन के सभी आवश्यक गुण समाविष्ट हैं, अर्थात् इसमें उपयोगिता, परिमितता और हानान्तरणीयता पाई जाती है। इसमें विनिमय मुद्रा में हो सकता है।

देश व प्राकृतिक सम्पत्ति (Natural resources of a country)

ये किसी व्यक्ति विशेष के परिवार की वस्तु नहीं हैं तथा उनका कोई अनिमय-मूल्य भी नहीं होना, अतः व्यक्तिगत धन व अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु ये

निनिदाव रूप से राष्ट्र की सम्पत्ति में गिन जाने है, यद्यपि उनमें धन की विशेषताओं का प्रत्यक्ष प्रभाव हो क्या न हो।

सूर्य का प्रकाश (Sun Shine)

वह प्राकृतिक प्रसाद (Free Gift of Nature) है जो निःशुल्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका कोई विनिमय मूल्य नहीं होता है। अतः साधारणतया इसे व्यवसाय की धन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं समझना चाहिये।

प्रतिलिप्यधिकार (Copy Right)

यह निश्चित रूप से धन है। यह धनोपाजन के साधन के प्रतिरूप हस्तांतरणीय होने के कारण बेचा और खरीदा जा सकता है। जो व्यक्ति यह अधिकार रखता है, वही अधिकृत वस्तु का मुद्रण और प्रकाशन कर सकता है।

बी० ए० डिग्री और एम० कॉम० डिप्लोमा (B. A. Degree & M. Com Diploma)

कतिपय अर्थशास्त्रियों के मतानुसार ये वस्तुएं 'वैयक्तिक धन' (Personal Wealth) कहला सकती हैं क्योंकि ये जीवन निवाह में सहायक मिट्ट होती हैं। वास्तव में देखा जाय तो इनका कोई विनिमय मूल्य नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अतः ये 'धन' के अन्तर्गत नहीं आती।

वह वस्तु जिसे कोई पसन्द न करे (An object which nobody likes)

सब मनुष्यों की दृष्टि में अस्वीकार्य वस्तु धन नहीं बनी जा सकती क्योंकि उनमें 'उपयोगिता' का अभाव है। इसी प्रकार 'वह चित्र जिसका कोई नहीं सराहता' (A picture which nobody appreciates) भी इसी आधार पर धन नहीं है।

डॉक्टर की सेवाएं जो रोगी को रोग से मुक्त करने में असमर्थ हो

(The services of a doctor who fails to cure the patient)

इस प्रकार की सेवाएं कोई प्रयोजन मिट नहीं करती। धन की प्राप्ति के स्थान पर अप्रिय पैदा करती हैं। उपयोगिता-रहित होने के कारण ये धन नहीं कहलाती।

व्यापार की संपत्ति (Goodwill)

वास्तव आन्तरिक वस्तु है अर्थात् इसमें उपयोगिता, हस्तान्तरणीयता और विनिमय मूल्य आदि गुण विद्यमान होने के कारण धन कहलाता है। जिस व्यापारी ने इसे बड़े परिमाण में कमाई और गुरुत्वपूर्ण मकामाई है वह व्यापार या विजय के साथ इसकी भी वैकता है और धन प्राप्त करता है अतः इसको 'धन' की श्रेणी में रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

गंगा नदी (The River Ganges)

यह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न होने के कारण 'व्यक्तिगत धन' नहीं है। यह राष्ट्र की वस्तु है, अतः 'राष्ट्रीय धन' है क्योंकि इसके जल को सिंचाई, विजय की उत्पादन आदि विविध प्रकार से मानव कल्याण के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

सड़कें (The Roads)

जो सड़कें म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा बनवाई गई हों या 'सामाजिक या सामुहिक धन' के वर्ग में आती हैं। जनकता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास आदि देश के विभिन्न भागों को मिलान वाली सड़कें 'राष्ट्रीय धन' कहलाती हैं।

एक सोने या चाँदी का सिक्का (A Gold or Silver coin)

व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो यह उमक धन का एक भाग है क्योंकि इसके वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएँ खरीद सकता है। परन्तु सामाजिक दृष्टि से यह धन नहीं है क्योंकि इसके निय तो केवल विनिमय साधन (Medium of Exchange) का ही कार्य सम्पन्न करता है। यदि देश में प्रचलित सिक्का की मर्याद दुर्गती विपुली कर दी जाय तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु और सेवा की वृद्धि भी उमा अनुपात में हो जायगी। किसी देश का धनी होना या निधन होना उस देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर है न कि सिक्का की वृद्धि पर।

जान में स्थित सोना या चाँदी (Gold or Silver in a mine)

इसका कुछ अर्थ तो 'राष्ट्रीय धन' में और कुछ अर्थ 'व्यक्तिगत धन' यथानु जान के स्वामी का अपना धन कहनाता है। यदि सोन या चाँदी की खान इतनी गहरी चली गई है कि यह धन दुष्प्राप्य हो गया हो और यदि प्राप्य भी है तो उसका व्यय उमक मूल्य में अधिक है तो ऐसी खान में यह धन नहीं कहा जा सकता।

मंगल नामक ग्रह में स्थित सोना (Gold in Planet Mars)

यह धन नहीं है क्योंकि यह धनुष्या की पहुँच में पर है। परन्तु यदि भविष्य में यह सम्भव हो जाय कि वह का भोना अपनी भूमि पर लया जा सके तो प्रथम धन की श्रेणी में आ सकेगा।

रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्वहस्त लेख (An Autograph of Rabindra Nath)

यदि कुछ ऐसा भी व्यक्ति हुआ जो रवीन्द्रनाथ के स्वहस्त-लेख की प्राप्ति के लिये यह उत्सुक हो और उसके लिय मूल्य देने को भी तैयार हो तो उसके लिय धन है भवया साधारणतया यह धन में वर्गीकृत नहीं हो सकता।

स्वास्थ्यप्रद जलवायु (A Healthful Climate)

यह 'राष्ट्रीय सावजनिक' धन है। इसका विनिमय-मूल्य न होने के कारण यह व्यक्तिगत धन नहीं हो सकता।

यह देत जिसका स्वामित्व विवादस्पद हो

(A farm the ownership of which is under dispute)

यह तब तब धन नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसमें व्यापारिक व विषय में पूरा या आंशिक निर्णय नहीं हो जाय।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

- १—धन की परिभाषा कीजिए। धन और वस्तुएँ में आ भन्नाय है उसका विवरण दीजिए। (नागपुर १९५८)
- २—धन की परिभाषा लिखिए। क्या निम्न वस्तुएँ धन कहें जा सकती हैं —
(अ) व्यक्तिगत वस्तुएँ (ब) देश की प्राकृतिक सम्पत्ति (स) यो० ए० डिग्री,
(द) कॉपीराइट। (नागपुर १९५४)
- ३—धन की परिभाषा लिखिए। क्या निम्नलिखित वस्तुएँ धन हैं —(अ) बायोराइज
(ब) यो० ए० डिग्री, (स) गवैय का कपड, (द) हिन्द महासागर।
(म० भा० १९५३)

- ४—सम्पत्ति की परिभाषा बनाएँ और निश्चित कि निम्नलिखित सम्पत्ति है या नहीं —
 (क) भूमि (ख) वन (ग) जल (घ) श्रम (ङ) प्राकृतिक सौंदर्य (च) किसी
 कारखाने का नाम (ज) धूप (अ० वा० १६१६)
- ५—धन की परिभाषा दीजिए और व्यक्तिगत धन व सामूहिक धन का अन्तर स्पष्ट
 कीजिए । (ग० वा० १६१३)
- ६—धन में क्या सम्मिलित है ? धन कहाँ से आता है ? क्या धन में बौद्धिक धन भी शामिल
 है ? (विहार-प्रश्न १६११)
- ७—धन की परिभाषा निश्चित । क्या निम्नलिखित वस्तुएँ धन की दृष्टि से धनी हैं ?
 कारखाने की मशीनें — (अ) गन्ना का प्राकृतिक सम्पत्ति, (ब) धूप, (ग) मुरोली
 'रति' (द) वा० १० निम्न (च) कारखाने । (अ० वा० १६६८)
- ८—सम्पत्ति की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार बताएँ । सम्पत्ति का क्या
 मत है ? (प्रश्न १६१८)
- ९—वस्तुओं और धन पर नोट लिखिए । (भाग १६१८)
- १०—धन में आप क्या समझते हैं ? धन का क्या वास्तविक अर्थ है ? (प्रश्न १६११)
- ११—व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्पत्ति में अन्तर क्या है ? निम्नलिखित सामान्य
 धन का मत समझिए कि किस प्रकार व्यवहार में आयेगा ? (भाग १६१०)
- १२—धन का वास्तविक अर्थ क्या है ? क्या निम्नलिखित वस्तुएँ धन हैं — (अ)
 अनाज (ब) धान (ग) बाघों व शेरों, (द) ताजमहल, (च) आनन्दमय
 वादना । (निर्णय वा० १६११)

उपभोग (CONSUMPTION)



“अर्थशास्त्र का सम्पूर्ण सिद्धान्त उपभोग के
सही सिद्धान्त पर आश्रित है।”

—जेवन्स

परिचय (Introduction)—‘मनुष्य आवश्यकताओं का पुतला है ।’ उसकी आवश्यकताएँ असीम हैं । उनकी तृप्ति के लिए वह सतत् प्रयत्नशील देखा जाता है । उनकी कुछ आवश्यकताएँ तो स्वाभाविक होती हैं, जैसे—जीवन यात्रा का निवाह करने के लिए भोजन तथा पेय पदार्थ, शरीर-रक्षा के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, आलस के लिए शस्त्र और उत्पादन के लिए उपकरण (औजार) आदि । ये प्रारम्भिक आवश्यकताएँ इतनी अनिवार्य हैं कि बिना इनके उसकी जीवन यात्रा सम्भव ही नहीं ।

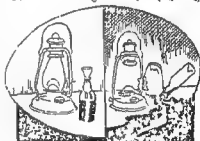
मनुष्य की आवश्यकताएँ सदैव समान नहीं होती जैसा-जैसा मनुष्य सम्यता की ओर प्रवृत्त होता जाता है या वह मनुष्य प्रगतिशील और उन्नतिशील होता जाता है । जैसे-जैसे वह इन जीवनोपयोगी आवश्यकताओं में पर पहुँचता जाता है, अर्थात् वह सुख और विज्ञान की वस्तुओं का उपभोग कर अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करने लगता है । अब वह उत्तम भोजन, वस्त्र तथा आवास आदि का उपभोग करने लगता है । मनुष्य की आवश्यकताएँ सभ्यता में, भिन्नता में और तीव्रता में बढ़ती जाती हैं, क्योंकि समाज की उन्नति और आवश्यकताओं की वृद्धि में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

साधारण बोल-चाल में उपभोग का अर्थ—उपभोग शब्द हमारी बोल-चाल के विविध अर्थों का परिचायक है । साधारण वास्तविक में उपभोग का तात्पर्य होता है ‘खा लेना’, ‘नष्ट करना’ आदि । अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ उक्त अर्थों से विभिन्न है । यहाँ उपभोग, ‘खा लेना’ या ‘नष्ट करना’ इन अर्थों की ओर बहुत अधिक व्यापक है । जब एक पदार्थ नष्ट हो जाता है वह किसी की आवश्यकता को तृप्त नहीं करता । यदि एक घड़ी, छड़ी, उपस्कर या छप्पर टूट जाय या जलकर नष्ट हो जाय तो टूटते, जलते या नष्ट होते समय मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं करते पर निरन्तर उपभोग की दशा में रहने हुए ये पदार्थ मनुष्य की विविध सामिक आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले कहे जाते हैं । इनके अतिरिक्त ‘पदार्थ का नष्ट होना’ यह कार्य भी आशेष करने योग्य है, कारण कि ‘तत्त्व या पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता’ । वस्तुओं का स्वरूप बदल जाता है । कोयला जल कर राख का रूप धारण कर लेता है जिससे कारण आग जलाने का कार्य संपादित नहीं होता । संवारे, वस्तुओं का सेवन या काम में लाया जाना जिसमें उपभोग की तात्कालिक वृद्धि अथवा क्षाया हो, उपभोग कहा जाता है ।

अन्तु यह कहता व्यावहारिक होगा कि उपभोग से वस्तु नष्ट नहीं होती बल्कि उसकी उपयोगिता नष्ट होती है।

उपभोग का अर्थशास्त्रीय अर्थ—अर्थशास्त्र में उपभोग शब्द एक विशिष्ट अर्थ रखता है। मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष और तात्कालिक पूर्ति के लिए धन के प्रयोग को 'उपभोग' कहते हैं। अन्तु स्वयं उपभोग से नष्ट नहीं होती है, बल्कि उसकी उपयोगिता मात्र ही नष्ट होती है। जैसे—यदि हम प्रकाश के लिए मोमबत्ती का उपभोग करते हैं तो मोमबत्ती का रूप परिवर्तित होकर उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, क्योंकि वह अब प्रकाश देने योग्य वस्तु नहीं रही। परन्तु वह पदार्थ जल और कार्बन डाइ-ऑक्साइड गैस (Carbon Dioxide Gas) के रूप में अब भी स्थिर है, केवल रूप में परिवर्तित हो गया है। उपभोग का तात्पर्य है किसी पदार्थ की उपयोगिता को धन में लाकर इस प्रकार नष्ट कर देना कि उस उपभोग से किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति और पूर्ति हो। एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वह मधुर सतरा अपना लैमोनेड से अपनी प्यास नाल करता है—इसके मतलब से उसे तृप्ति और मनोरंजन हुआ। यदि वह इन सत्त्वों को छील कर केक के और लैमोनेड की बोतल को धूम पर फटका कर मोड़ डाले तो किसी मनुष्य की तृप्ति या उत्तेज नहीं होता। "उपभोग को तभी समझा जायगा जब उसी उपयोग में किसी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो और उसका भ्राम्य दूर होकर उसने तृप्ति या उत्तेज प्राप्त हो।"

यह स्मरण रखना चाहिये कि उपभोग केवल वस्तुधा में ही नहीं होता है, अपितु सेवाधा में भी। यदि एक रोगी डाक्टर को अपने शरीर-निरीक्षण के निमित्त इस रुपये धुरक रूप में देता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह रुपय देकर डाक्टर की सेवा का उपभोग करता है, इसी प्रकार हम एक निश्चित शुल्क देकर गोटल बस, रेल, टाक, तार व टेलीफोन द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उपभोग करते पाए जाते हैं।



यह उपभोग है। यह उपभोग नहीं है।

मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष सन्तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता के प्रयोग को अर्थशास्त्र में 'उपभोग' कह कर पुकारते हैं।

'प्रत्यक्ष' अथवा 'अपरोक्ष' शब्द का महत्व—उपभुक्त परिभाषा में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष (Direct) शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका यहाँ महत्व प्रकट करना आवश्यक है। जैसे देखा जाय तो आवश्यकताओं की पूर्ति परोक्ष और

अपरोक्ष भयति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में होती रहती है। मूस लगने पर रोते पाना और प्यास लगने पर जल पीना आदि आवश्यकताओं की पूर्ति अपरोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में होती कही जाती है। इस प्रकार के धन के प्रत्यक्ष प्रयोग को 'उपभोग' कहते हैं। दूसरी ओर जब कारखानों में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है अथवा मशीन चलाने के लिए कोयला या बिजली प्रयोग में लाई जाती है तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं होने पाने, वरन्, यहाँ धन का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया गया है। इनके द्वारा वस्तुओं की उत्पत्ति होती है जो आगे चलकर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग की जाती है। धन का जब अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे उपभोग न कहकर 'उत्पत्ति' कहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि उपभोग धन के उस प्रयोग को कहते हैं जिससे आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप में पूर्ति होती है।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा 'उपभोग' की उपेक्षा—पुण्ये भर्गशास्त्रियों की दृष्टि में 'उपभोग' का कोई अधिक महत्व नहीं था। वे इस विभाग की उपेक्षा करते थे और अधिक महत्व 'उत्पत्ति' को देते थे। उनकी धारणा यह थी कि बिना उत्पत्ति के उपभोग सम्भव ही नहीं, चाहे वे 'उत्पत्ति के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण समझ कर उपभोग की उपेक्षा प्रथम स्थान देते थे। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने यह नहीं समझा कि उत्पत्ति और उपभोग का क्या सम्बन्ध है। उत्पत्ति बीज है और उपभोग फल। मानव समाज की आवश्यकताओं को तृप्त और मनुष्ट करने के लिए ही वस्तुओं की उत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति और उपभोग के सापेक्षिक घनिष्ठ सम्बन्ध पर भी उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। जितना अधिकारिक उपभोग बढ़ेगा उतनी ही अधिक उत्पत्ति बढ़ेगी और उतने ही अधिक श्रमिक व्यक्ति कार्यों में लगे रहेंगे। "श्रमी जनो को कार्य मलम्भता, उत्पत्ति की तीव्रता और मात्रा का प्रेरण है उपभोग न कि उत्पत्ति।"¹ अधिक वृद्धि का आरम्भ और मूल 'उपभोग' ही है, श्रौयोगिक शक्तियाँ, योग्यताएँ और सामाजिक उत्पत्ति उपभोग की बढ़ती विनिम्नता पर निर्भर है, सर जॉन मेरीवोट (Sir John Marnot) के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। उपभोग के महत्व पर आगे विस्तार से प्रकाश डाला जायगा।

आज सम्पत्ता की समुन्नत अवस्था है। अर्थशास्त्र विज्ञानशास्त्र, मनोविज्ञान और भौतिकविज्ञान की उपेक्षा करने लगा है, मानव सेवा और मानव हित के उदार विचार जीवन के प्रधान लक्ष्य माने जा रहे हैं, अतः भौतिक और अर्थव्यवस्था के उपभोग द्वारा जन समाज का अधिकारिक कल्याण किस प्रकार हो सकता है—यह समस्या आज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस विभाग के महत्व को समझा और उसे उचित स्थान दिया।

उपभोग अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में (Consumption as a Department of Economics)—उपभोग शब्द का अर्थशास्त्रीय अर्थ उपभुक्त विवेचन से पूर्ण स्पष्ट किया जा चुका है। यह उपभोग का अर्थ क्रिया के रूप (as an act) में किया गया है। परन्तु उपभोग को अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में भी जान लेना आवश्यक है। इस विभाग के अन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उनके उद्गम, उनकी विशेषताओं तथा उनकी मनुष्टि के नियम आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

उपभोग के प्रकार (Kinds of Consumption)

१—उत्पादक और अन्तिम उपभोग (Productive and Final Consumption)

कुछ प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को दो भागों में विभाजित कर दिया है—

उत्पादक और अन्तिम उपभोग ।

द्वितीय वस्तु का उपभोग विधी अथ

वस्तु का निर्माण के निमित्त किया

जाय । एम उपभोग में मनुष्य का

आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में

नहीं होती उससे उत्पन्न उपभोग

कहते हैं । जैसे—एक मशीन बनाने

के लिए मूल मशीन व विभिन्न घाटि

का प्रयोग । इस उपभोग में मनुष्य

की आवश्यकताओं की पूर्ति और तृप्ति

प्रत्यक्ष रूप में नहीं, वह अन्तिम उपभोग

कहना है । जैसे—क्षुधा की पूर्ति के लिए

अन्न और परीर की रक्षा के लिए वस्त्र

का प्रयोग अन्तिम उपभोग कहना है ।

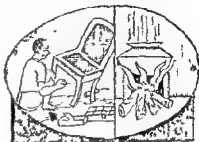
परन्तु सामुचित अर्थशास्त्रियों ने इस

वर्गीकरण का विरोध किया है । वे इनके

प्रयोग का अन्तिम उपभोग कहते हैं ।

जैसे—एक मशीन बनाने के लिए मूल

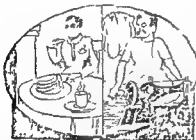
मशीन व विभिन्न घाटि का प्रयोग ।



उत्पादक उपभोग

अन्तिम उपभोग

२—मन्द और तीव्र उपभोग (Slow and Quick Consumption)



तीव्र उपभोग

मन्द उपभोग

कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपभोग

को दो भागों में विभाजित किया है और

कुछ का दर दर चर्चा करना शुरू

किया है । जैसे—जैसे जैसे वस्तु का

प्रयोग होता है, उसे तीव्र उपभोग

कहते हैं । जैसे—एक मशीन बनाने

के लिए मूल मशीन व विभिन्न घाटि

का प्रयोग । इस उपभोग में मनुष्य

की आवश्यकताओं की पूर्ति और तृप्ति

प्रत्यक्ष रूप में नहीं, वह अन्तिम उपभोग

कहना है । जैसे—क्षुधा की पूर्ति के लिए

अन्न और परीर की रक्षा के लिए वस्त्र का प्रयोग अन्तिम उपभोग कहना है ।

वास्तव में देया जाय तो उपभोग सम्पूर्ण मानवीय क्रियाप्रा का मूल मोल (Spring) है। यदि मनुष्य को आवश्यकताएँ नहीं होती तो वह वस्तुओं का उत्पादन कदापि नहीं होता। आवश्यकताएँ और तत्तत् पूर्ण की प्रेरणा से मात्र सारा भूमण्डल क्रियाशील है। प्रायः के भौतिक संसार में धनोपार्जन बना महत्त्व रखता है। क्योंकि इसके बिना मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती किन्तु सम्भव नहीं। अतः मनुष्य विविध प्राथमिक क्रियाप्रा का सम्पन्न करना हुआ अपने उपभोग में साधन को जुगल में व्यस्त देखा जाता है। इसीलिए उपभोग को सम्पूर्ण मानवीय प्राथमिक क्रियाप्रा का उत्पन्न स्थान (Starting Point) कहना अव्यक्ति नहीं होगा।

दूसरी ओर देखने में ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी गम्भीर प्राथमिक क्रियाएँ केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के हेतु सम्पन्न करता है यह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है। उत्पत्ति विनिमय और वितरण का यही एक प्रतिम सत्य है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को मनुष्य के लिए प्राथमिक क्रियाएँ सम्पन्न करना है और उनमें फलस्वरूप विविध वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन होता है जिनमें उपभोग में वह उनको पूर्ति करत में समर्थ होता है। आवश्यकताओं को पूर्ति होने ही उसके प्राथमिक प्रयत्नों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उपभोग में भी तो इसी बात का विवेचन किया जाता है। अतः उपभोग को प्राथमिक क्रियाप्रा का प्रतिम सत्य कहना अनुचित न होगा।

संक्षेप में उपभोग वह महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्रियाप्रा का सारा प्रारम्भ एवं अन्त समाहित है।

क्या उपभोग शक्ति संचय का साधन है ?

(Is Consumption a means of restoring energy ?)

उपभोग प्रदान वा उत्तर देने हुए यह कहा जा सकता है कि यह बात पूर्णतया सत्य नहीं कही जा सकती। जिन वस्तुओं का उपभोग उत्पादन कार्य के लिए होता है वे शक्ति प्रदान नहीं करती। यहाँ तक कि सम्पूर्ण वस्तुएँ जो भविष्य उपभोग के अर्हता प्राप्ति में शक्ति प्रदान के उद्देश्य को पूरा नहीं करती। उनमें से केवल आवश्यकताओं (Necessaries for life & Efficiency) ही शक्ति वा संचार करने में समर्थ है। उदाहरणार्थ पुनर्जनन भोजन वस्त्र आवास आदि मनुष्य का जीवन बना जीवन के लिए ही नहीं अपितु उनमें कार्यक्षमता तथा दृढ़ता की वृद्धि भी करते हैं। शिवाय वस्तुओं (Luxury) से उनमें उपभोग के पश्चात् क्षमता भी शक्ति वा संचार नहीं होता। इससे स्पष्ट है उनके प्रतिस्पर्ध (Luxury) में क्या शक्ति और दृढ़ता का ह्रास ही होता है अन्तर्गत की ही बात ही नहीं। अतः यह कहना कि उपभोग शक्ति के पुनः संचय में सहायक है— प्राथमिक सिद्धांत है क्योंकि इसमें उपभोग ने सम्पूर्ण चिन्तन का दिग्दर्शन नहीं होता। उपभोग में शक्ति प्रायः खर्च हो जाती है अतः शक्ति संचय का भी प्रश्न नहीं है। परन्तु मानवीय आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण समस्या है इसमें सुलझाई जाती है।

राष्ट्र की समृद्धि के लिये उपभोग का महत्त्व

राष्ट्रीय वस्त्राण बहुत कुछ देश में निवासियों के उपभोग से स्वभावतः प्रेरित होता है। अतः वस्तुएँ यदि स्थिर रहे जिनमें प्राथमिक वस्तुओं का संचय वा उपभोग होता है उतना ही राष्ट्र की समृद्धि में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत रूप से भी उपभोग संचयकारक है। यदि उपभोग की वस्तुओं का प्रयोग बुद्धिमत्ता से पुनः

कर किया जाय, तो व्यक्तिगत लाभ भी उतना ही निश्चित है जितना कि समष्टिगत । घनोपार्जन से घन का उपयोग अधिक वृद्धि है । अस्तु घन के सदुपयोग पर ही देश एवं वहाँ के निवासियों की धार्मिक सम्पत्ति अवलम्बित है ।

उपभोग के अध्ययन से व्यावहारिक लाभ

(Practical advantages of study of Consumption)

उपभोग के अध्ययन से कई व्यावहारिक लाभ प्राप्त होने हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(१) गृहस्वामियों या उपभोक्ताओं को लाभ—उपभोक्ताओं (Consumers) अथवा गृहस्वामियों (House-holders) के लिए उपभोग का ज्ञान यथा लाभदायक है, क्योंकि इससे उन सब विद्वानों का विशेषण किया जाता है जिनके प्रयोग से वे अपनी सीमित आय में अधिकतम लाभ उठा सकते हैं । उदाहरणार्थ, सम-सीमागत-उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) और वारिचार्मिक आय व्यय (Family Budgets) की सहायता से वह अपनी आय को इस प्रकार व्यय कर सकेगा, जिससे उसको न्यूनतम भाग पहुँच सके ।

(२) व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ—व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए उपभोग का अध्ययन पर्याप्त महत्त्व रखता है । वे अपनी उत्पादन श्रियाएँ मनुष्यों की आवश्यकताओं के आधार पर स्थिर रखते हैं । यदि उनका अनुमान भावी आवश्यकताओं के स्वभाव व परिणाम में सम्यक् में उचित नहीं निश्चया तो यह उनके असफलता का एक कारण बन जाता है । परन्तु उन्हें अपनी व्यापार तथा उद्योग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जन माधारण की आवश्यकताओं के स्वभाव, प्रकार एवं परिणाम आदि सम्बन्धित बातों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना पड़ता है ।

(३) राजनीतिज्ञों को लाभ—राजनीतिज्ञों तथा शासकों का यह देखना पड़ता है कि उनके देश के नागरिक अपनी आय का सदुपयोग करते हैं या नहीं । कारण यह है कि देश का उत्पादन उससे घन पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उचित उपभोग पर भी । आधुनिक सरकार इस बात का अनुभव करने लग गई है कि देश को समृद्धिदायी एवं आर्थिक मापन बनाने के लिए उसके नागरिकों की उपभोग व्यवस्था का नियन्त्रण रखना आवश्यक है । भारतीय सरकार की प्रतिषेध (Prohibition) नीति, जिसके द्वारा शराब आदि मादक वस्तुओं के उपभोग को कम करना सिनेमा आदि पर आमोद प्रमोद कर (Entertainment Tax) लगाना इसी उद्देश्य की पूर्ति के शोचक है । वास्तव में, जो राजनीतिज्ञ 'उपभोग' की उपेक्षा करता है वह कुशल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता ।

प्राचीन भारत में उपभोग के अध्ययन का महत्त्व—मनुस्मृति तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र को देखने में पता चलता है कि भारतवर्षी 'उपभोग' के महत्त्व में भली प्रकार परिचित थे । उन्होंने भोजन, वस्त्र, गृह और यज्ञादि सम्बन्धी विभिन्न ही नियम नियन्त्रण पूर्ण बना रखे हैं जिनसे वे स्वस्थ, सहृदय और समान के योग्य भगवन् बन सके । "जिन्ह प्रकार हम विद्वद् गुरु में ईश्वर की तत्ता व्याप्त है उसी प्रकार अर्थशास्त्र में उपभोग का विमल योग्य और महत्त्व भी व्याप्त है ।"

१—ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे भासते ननु ।

उपभोगो हि वस्तूनां वाञ्छनीति ननु सूते ॥

यह 'कामदेव मुनि' का वचन उपभोग की महत्ता का प्रतिपादन कर रहा है ।

एक भारतीय साधारण कृषक की उपभोग अवस्था और उसके मुद्धार के साधन

उपभोग की वर्तमान दशा—भारतीय कृषक की विध्वनित कृषिगत का रूप पारण कर चुकी है। वह अपने गीमित साधना का जो कुछ उसने अर्जित किए है गुरुभोग नहीं करता है। वह अपनी मजिद राशि को आभूषण और नाच-तमाछा में व्यय कर देता है। वह अस्वच्छ छोटे घोर अंधेरे घर में रहता है जिसमें स्वच्छ वायु के प्रयोग और अस्वच्छ वायु के निर्णित का कोई भाग नहीं होता। मदिरा आदि नशीली वस्तुओं का भी प्रयोग उनके लिए बड़ा हानिकारक मिष्ट होता है। मुकद्दमेबाजी में बड़ा प्रेम होने के कारण उनकी आय का अधिकांश भाग इनमें व्यय हो जाता है। जितना अपने खाने पीने में व्यय नहीं करता है उसमें बड़े गुना विवाह और पुत्रभोग आदि भवभोग पर व्यय कर देता है। परिणाम यह होता है कि वह निरंतर कठिन परिश्रम करने पर भी अधस्तात् और अधस्तात् रह जाता है। ऐसी गौणभोग अवस्था में उसे अपने वाय में कुशलता प्राप्त करने का अवसर कहा है। उसे जीवन याता चलाने भर के लिए आवश्यक वस्तुएँ ही उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। मिट्टी में रूढ़ पद्धत करने आता मौन तपस्वी किसान जब भरपूर भोजन पायेगा जब उसे गरीब दफने को वस्त्र मिलेगा तभी वह देश पुनः अपनी प्राचीन समृद्धि और कोई दुर्लभ लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अस्तु उसके उपभोग में कनिष्ठ मुद्धार होने परमावश्यक है।

उपभोग में आवश्यक सुधार

(१) अपने प्रथम उसकी कृषि मजदूरी और निरक्षरता दूर करनी चाहिए जिससे वह न्यय विषय में ठगा न जाय। शिक्षा का ही प्रभाव है कि वह मुकद्दमेबाजी और विवाह आदि के भवभोग में अधव्यय करता है। अतः उसकी हानिकारक आवश्यकताओं में व्यय करने की प्रवृत्ति का अवरोध करना चाहिए।

(२) उसे अपनी आय का अधिकतर भाग अपनी वायक्षयता की प्राप्ति के लिए अनिवार्य साधना में व्यय करना चाहिए।

(३) उसके पुराने तथा अनुपयुक्त कृषि सम्बन्धी उपकरण (Implements) और रीतियों में सुधार होना चाहिए।

(४) उत्तम आद उत्तम मिर्चाई उत्तम बीज और पान आदि के प्रयोग का उसे सहूलयता में स्वगत करना चाहिए।

(५) उसे अपनी समन्ताओं और आवश्यकताएँ सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) द्वारा पूर्य करनी चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इंटर मार्ट्स परीक्षाएँ

१—उपभोग के अध्ययन में (अ) एक अवगाह्य (आ) एक राजनीति तथा (इ) एक दृष्टि को क्या लाभ होता है ? (उ० प्र० १९५६)

२—उपभोग क्या है ? उपभोग व उत्पत्ति में क्या अंतर है ? उपभोग का क्या महत्व है ? (उ० प्र० १९५३ ४१)

३—उत्पादक उपभोग और अति उपभोग पर नोट लिखिए। (उ० प्र० १९३६ ३६)

४—अर्थशास्त्र में उपभोग की क्या परिभाषा दी जा सकती है ? आपके प्रदेश में रहने वाले किसानों का उपभोग किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? (उ० प्र० १९३१)

५—“आर्थिक क्रियाया का अर्थ उनको स्तुष्टि है ।” अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन के सन्दर्भ में इसका विवेचन कीजिए । (रा० बो० १९४१)

६—उपभोग की परिभाषा दीजिए । व्याख्या कीजिए “उपभोग आर्थिक विज्ञान का आदि और अन्त है ।” (सागर १९५८)

७—उपभोग और बर्बादी पर सविस्तार टिप्पणियाँ लिखिए । (अ० बो० १९५३)

८—उपभोग की परिभाषा लिखिए । उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अन्त क्या कहा जाता है ? स्पष्ट कीजिए । (नागपुर १९५४)

९—“उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाया का अन्त है”—क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? आपके मतानुसार उत्पात्ति और उपभोग में क्या सम्बन्ध है ? (पञ्जाब १९५५)

१०—उपभोग क्या है ? क्या निम्नलिखित उपभोग है ? कारण सहित उत्तर दीजिए —
(अ) सिनेमा देखना (ब) घरेलू नौकर से लेकर एक गिलास पानी पीना (स) घड़ी की ओर देखना । (दिल्ली हा० से० १९४६)

इष्टर एथीक्ल्चर परीक्षा

११—“उपभोग अर्थशास्त्र का आदि है और अन्त भी ।” स्पष्ट कीजिये ।

(उ० प्र० १९४८)

आवश्यकताएँ (Wants)

देखा जाता है कि मनुष्य वस्तुओं के उपभोग या व्यवहार में लाने से तृप्ति अनुभव करता है, यदि वे वस्तुएँ उसे प्राप्त न हों, तो उसे कष्ट होता है। किसी वस्तु के उपभोग द्वारा तृप्ति और संतोष दिलाने वाले 'भाव' का नाम आवश्यकता है।

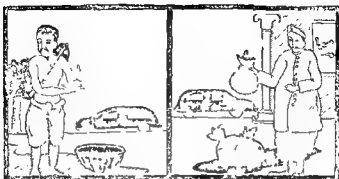
साधारणतया 'आवश्यकता' शब्द के दो अर्थ प्रचलित हैं :—

(१) आवश्यकता का साधारण अर्थ—साधारण बोलचाल की भाषा में आवश्यकता शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे इच्छा, चाह, अभिलाषा आदि। हमारे शब्दों में मनुष्य की किसी भी वस्तु की चाह या इच्छा को आवश्यकता कहा जा सकता है चाहे इच्छित वस्तु की 'चाह' के लिये शक्ति और साधन विद्यमान न हो। कहावती लोमड़ी धूम्र को चाह कर सकती है, चाहे उसके पास उन्हें पाने के लिये शक्ति या साधन न हो।

(२) आवश्यकता का अर्थशास्त्रीय अर्थ—अर्थशास्त्र में आवश्यकता एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होती है। अर्थशास्त्र में आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिये उसने पास पर्याप्त साधन और शक्ति विद्यमान हो और उस इच्छा को पूर्ण करने में मनुष्य उद्यत भी हो। उदाहरणार्थ, एक भिलारी मोटरकार खरीदना चाहता है, परन्तु उसके पास इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं है, अतः अभिलाषा करने हुए भी उसे पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्राप्त करने के साधनों का अभाव है। इसी प्रकार एक कुपण एक मोटर खरीदना चाहता है, परन्तु रुपये व्यय करना नहीं चाहता। अतः उसकी यह इच्छा भी अर्थशास्त्र की दृष्टि में आवश्यकता नहीं कहो जा सकती, क्योंकि वह साधनों को प्रयुक्त करने में उद्यत नहीं यद्यपि मोटरकार खरीदने के लिय साधन पर्याप्त है।

इच्छाओं की प्रभावोत्पादकता के साधन—इच्छाओं का प्रभावोत्पादक होने के लिये तीन मुख्य बातों का होना अनिवार्य है :—

- (१) किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की इच्छा (Desire)।
- (२) उसकी प्राप्ति के लिये साधन और शक्ति।
- (३) इन साधनों और शक्तियों का उस इच्छा को पूर्ण करने के लिये तत्परता (Willingness)।



इच्छा (केवल इच्छा)

आवश्यकता
(इच्छा + मापन + तनयता)

आवश्यकताओं का उद्गम (Origin of Wants)— आवश्यकताओं के उत्पन्न होने के मूल कारण निम्नलिखित हैं —

(१) **स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ (Natural Instincts)**— हमारा प्राग्भिक आवश्यकताएँ हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। हमारा शरीर इस प्रकार का बना हुआ है कि इसको नियमित रूप से भोजन, निद्रा, आदि और शरीर रक्षा के लिए वस्त्र आदि। इसलिए हम जीवन यात्रा को चक्रम के विषय परामर्शवद् न्यूनातिन्यून आवश्यकताओं की पूर्ति तब तक करती ही होगी।

(२) **सुख और विलासपूर्ण वस्तुओं की खानसा (Craving for better and higher things)**— आवश्यकताएँ केवल इन्हीं निमित्त उत्पन्न नहीं होती कि हम अपने शरीर सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो सके कि व सामान्यतः के लिए भी उत्पन्न होती हैं। मनुष्य की जब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वह स्वाभाविक रूप से सुख एवं विलास वस्तुओं की खानसा में लीन हो जाता है।

(३) **सौन्दर्य की रीति और परापूर्वता की प्रवृत्ति (Aesthetic Tastes and Altruistic Motives)**— इन कारणों से भी अनन्त मात्रा में आवश्यकताएँ उत्पन्न होती रहती हैं। मनुष्य का सुन्दर वस्तुओं में प्रेम होता है और अपने नैतिक जीवन को ऊँचा उठाने की इच्छा होती है। इन इन इच्छाओं की पूर्ति के लिये कई इस प्रकार की आवश्यकताएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

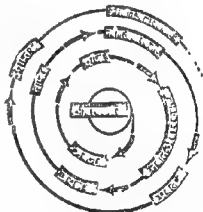
(४) **सामाजिक बंधन (Social Obligations)**— हम अपने गृह, महल और सार्वजनिक आदि बातों में सामाजिक सामर्थ्य और स्वातंत्र्य परिस्थितियों में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। हम अन्य व्यक्तियों के विचारों और सम्पत्तियों में भी प्रभावित होते हैं। अतः हमारी आवश्यकताएँ भी समग्र हमारे मायिकाओं की आवश्यकताओं जैसी हो जाती हैं।

(५) **विज्ञापन और प्रचार (Advertisement and Propaganda)**— हमारी कई आवश्यकताएँ तो उत्पादकों और निमात्राओं के विज्ञापन और प्रचार से बढ़ जाती हैं। बार-बार उन वस्तुओं के विज्ञापन देख जान से उनकी प्रशंसा में मान को बढ़ा हो जाती है। कुछ समय बाद वे प्रयुक्त होन लगती हैं।

आवश्यकता और प्रयत्न का सम्बन्ध—आवश्यकता और प्रयत्न का वास्तविक घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी आवश्यक वस्तु को प्राप्त करने के निम्न कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। अतः आवश्यकताएँ मानवीय प्रयत्न का जन्मदात्री हैं। यदि आवश्यकता समाप्त हो जाय तो वह समाप्त हो जाय कि आज क्रियाशील दृष्टिगोचर होता है किया शून्य हो जाय। देखा जाय तो यह आवश्यकता की प्रेरणा ही है जिसके कारण मनुष्य कार्य करने के लिये बाध्य हो जाता है। आवश्यकताएँ मानवीय प्रयत्न का स्रोत (spring) हैं। आवश्यकताएँ का सर्वाङ्गीत ही प्रेरित होकर वृषक कड़ी धूप और भूतनाथार वषा में सा काम करत है। आर्थिक दृष्टिवाक्याता में प्रयत्न कीना प्रयत्न है व्यापारी अपने व्यवसाय में अपने विचारों अपने विचारान्ता में दिन रात एक कर देते हैं।

अतः इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं कि समाप्त में जितने भी काम हान है वे सब आवश्यकताओं का ही कारण बने जाते हैं। जब जैम में पद का आवश्यकताय बढ़ती जाती है तब उनकी पूर्ति के निमित्त विविध प्रकार के कार्यों में मनुष्य हान लगता है। आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं। इसी कारण उन प्रयत्न का भी कोई अन्त नहीं। उनकी पूर्ति के लिये मनुष्य किंचित जान है।

आवश्यकता की प्रेरणा में प्रयत्न को किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसका सन्तुष्टि हो जाता है। एक प्रकार का आवश्यकताओं का सन्तुष्टि होना दूसरे प्रकार का समय नवान आवश्यकताएँ उत्पन्न होती है। अतः यह चक्र सतत रूप में चलता रहता है। यह समझ लिए हुए चिन्तन द्वारा अन्त मानि समझा जा सकता है।



आवश्यकता प्रयत्न और तृप्ति का सम्बन्ध
(Wants Efforts & Satisfaction)

आवश्यकताओं से प्रयत्न को प्रेरणा मिलता है और प्रयत्न से नवीन आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं। (Wants give rise to activities and activities give rise to new wants) प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकताएँ प्रयत्न करने प्रयत्न का कारण हो गई हैं। आर्थिक विकास के प्रारम्भिक काल में मनुष्य का आवश्यकताएँ साधारण और सीमित था। जब अभी उस क्षुधा सताती था तो तुरत वह भोजन की प्राप्ति में लग जाता था। यदि उस वहाँ फल प्राप्त हो जाना था तब वह खुश होकर शांत हो जाता था। अथवा किसी जगह की पानवर का मार्ग कर जंगल में अपने पेड़ पर लता था। इस प्रकार अपने खरिद की रक्षा के लिये पृथक् का छात्र के पन्त यदि प्रयोग में लाता था और रक्त के लिये अपनी धनाना का या वहाँ पर्वत की वन्द्यता में रह कर जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार उन

जित वस्तु की आवश्यकता में प्रेरित किया उसने उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बिना प्रेरणा के मनुष्य काम नहीं करता है, अपनी वस्तुएँ इच्छा की पूर्ति करने के पक्षान् अवधान में रख कर वह निरर्थक पड़ रहने से बचाता है। इस प्रकार आर्थिक-जीवन की प्राग्भिक अवस्था में आवश्यकताएँ ही प्रयत्न को प्रेरित करती हैं, यद्यपि प्रयत्न आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु ही सम्पादित किये जाते हैं।

किन्तु जब मनुष्य उत्पत्ति के पक्ष पर आरुढ़ होता है तो प्रयत्न द्वारा भी नई-नई आवश्यकताएँ उत्पन्न होने लगती हैं। जब मनुष्य प्रयत्न करता है तो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती अपितु उसने द्वारा कई अन्याय्य आवश्यकताएँ भी पैदा होने लगती हैं। मनुष्य के पुत्र में जन समाज को आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेक साधन सज्जता से उपलब्ध हो जाते हैं इसका परिणाम यह होता है कि अतः उसे पर्याप्त अवधान मिलने लगता है जिसका वह सदुपयोग करता है। अपने इस समय का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति जिस देश या समाज में पाई जाती है, वह समय और उत्तम कहता है। कुछ मनुष्य तो अपनी सभ्यता की रीतियों को आत्मस्थ में, कलह में नाश में, निश में या तन्त्रा में बिनाश में पर एक माहिरियत, गृहस्थ-कलाकार, वैज्ञानिक या व्यक्ततावी पुरुष उस अवस्था में कुछ उत्पत्ति के माग का चिन्तन करता है, उन चिन्तन को मूल रूप देता है और उसे क्रियान्वित करने में प्रयत्नशील होता है। ऐसे पुत्रों की ये प्रवृत्तियों की रीतियाँ निमग्न या आधिपत्य की रीतियाँ हैं, वह सभ्यता का निर्माण बन जाता है। समय देश के व्यक्ति अपनी अपनी रीति या प्रेरणा के अनुरूप भिन्न-भिन्न उत्पत्ति के मनो की माधना में लग जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसे अवसरों पर ही अनुमान पूर्ण आविष्कार में लगता है। आध्यात्मिक व्यक्ति परमार्थ नामों प्रपञ्च आत्मिक-विषय में इस समय का सदुपयोग करता है।

इस प्रकार की गति को किसी धनीप्राजन के उद्देश्य के लक्ष्य रूप शक्ति-विकास (Activities for their own sake) के कारण तथा प्रवृत्तियों का सदुपयोग करने के निमित्त की जाती हैं जिसमें परम्पर्यन्त वृद्धि आविष्कार होता है। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि आवश्यकता से ही प्रयत्न का जन्म नहीं होता, अपितु प्रयत्न के कारण ही नवीन आवश्यकताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह एक स्थिर नियम-सा है कि जिस समाज में उत्पत्ति और मनुष्यता का बंध होगा उसकी आवश्यकताएँ भी अधिक और तीव्र होंगी। मनुष्य और आवश्यकता की वृद्धि में परस्पर प्रतिष्ठ सम्बन्ध है। इन समय मनुष्य की प्रवृत्ति नष्ट-भङ्ग और विनाश की ओर झुकने लगती है और भोजन, भवन, भस्त्र, उपकरण (Furniture) प्रयत्न की आवश्यकता उत्पन्न होती जाती है।

उदाहरण के लिए उदाहरण के इतिहास पर ही दृष्टि डालने से यह ज्ञान होता है कि वहाँ लगभग दो सौ वर्ष पूर्व औद्योगिक-क्रान्ति (Industrial Revolution) के परम्पर्यन्त विविध प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसमें उत्पत्ति पुनः भाग में होने लगी। मशीनों के प्रयोग में जब उत्पत्ति में अधिक वृद्धि हो गई तो इस बात की आवश्यकता हुई कि वस्तुओं का गृहस्थ-स्थान में भेजा जाय जिसमें उपयोग सहे। इस आवश्यकता का पूर्ति के लिए अन्धे और अन्धे जालावाले के माधना की आवश्यकता का अनुभव हुआ। परम्पर्यन्त पत्नी मर्दानों की ओर नहीं बढ़ाई, किन्तु जब इसमें भी कार्य में चले सके तो रेल का प्रादुर्भाव हुआ। वस्तुओं गुणवत्ता और शीघ्रता में एक स्थान में दूसरे स्थान पर ध्यान देने लगे। इस प्रकार जब व्यापार और उद्योग-

धनो में उन्नति हुई तो मुद्रर स्थानो में व्यापार सम्बन्धी मन्देय भेजने व वहाँ में प्रति सन्देश प्राप्त करने और प्रेषित करने की आवश्यकता पड़ी जिसने परिसुमस्वरूप डाक, तार टेलीफोन, रेडियो आदि का आविष्कार हुआ ।

इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि मनुष्य इस उन्नत अवस्था में अपने अवस्था में कुछ न कुछ लाभप्रद कार्य करता है । वह आविष्कार करने की शक्ति व प्रवृत्ति इच्छा से प्रेरित होकर विविध वस्तुओं का आविष्कार करता है । जैसे साइकिल, मोटरगाड़ी, टेलीविजन आदि । इसमें पूर्व वह इन वस्तुओं को इस रूप में जानता हीन था, अतः इसकी उपयोगिता और अन्य गुणों के कारण साइकिल, मोटरगाड़ी, टेलीविजन आदि वस्तुओं की नई आवश्यकताएँ उत्पन्न हो जाती हैं । निस्संदेह नई आवश्यकताएँ प्रयत्नों द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं ।

इस प्रकार यह चक्र निरन्तर चलता रहता है । आवश्यकताओं के कारण मनुष्य प्रयत्नशील रहता है और मानव-प्रयत्नों द्वारा अनेक नवीन आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है । ये दोनो एक दूसरे के जन्म के कारण हैं । मानव-जानि की उत्पत्ति का यह एक प्रमुख कारण है ।

मानवीय आवश्यकताओं के ज्ञान का महत्व (Importance of the Knowledge of Human Wants) — अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं के अध्ययन का बड़ा महत्व है । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि आवश्यकताएँ मनुष्य की आर्थिक-क्रियाओं की जननी हैं । मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धनोपार्जन में प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि यह समझता है कि बिना धन के आवश्यकताओं की पूर्ति असम्भव है । देखा जाय तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, विनिमय और वितरण आदि विविध क्रियाएँ आवश्यकताओं पर ही निर्भर हैं । समस्त आर्थिक क्रियाओं का मध्य उनकी पूर्ति है । मनुष्य आवश्यकताएँ मानवीय आर्थिक-प्रयत्नों का मूल है तथा उनकी संतुष्टि ही उनका अन्तिम लक्ष्य है ।

आवश्यकताएँ मानवीय जीवन-स्तर और कार्य-कुशलता की प्रतीक हैं — आवश्यकताओं का महत्व इसलिए भी है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का जीवन-स्तर तथा कार्य-कुशलता इन्हीं पर अवलम्बित है । यह बात निर्विवाद सत्य है कि अन्य बातों के स्थिर होते हुए यदि व्यक्ति की आवश्यकताएँ अधिक मात्रा में और पूर्णतया संतुष्ट होती हैं, तो उसकी कार्य-कुशलता भी अधिक होगी । किसी देश के निवासियों की आवश्यकताओं की संख्या, मात्रा, तीव्रता और विभिन्नता अधिकतर उस देश की भौतिक समृद्धि का प्रतीक होता है ।

अतः, अर्थशास्त्र में मनुष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन बड़ा महत्व रखता है ।

आवश्यकताओं की विभिन्नता के कारण
(Factors determining wants)

प्रायः यह ऐसा जाता है कि आवश्यकताओं में देश-काल और परिस्थिति के कारण पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है । यह भिन्नता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है :—

(१) भौतिक कारण (Physical Factors)—किसी देश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु वहाँ के निवासियों को बड़ा प्रभावित करती है । जलवायु की भिन्नता मनुष्यों की आवश्यकताओं में बड़ा अन्तर पैदा कर देती है । उदाहरण के

तीन बग के सोय देखने में आने ह जम घनाप्य मध्य वर्गीय और निधन । एक निधन भारतीय कृषक या श्रमिक की आवश्यकताएँ मानी और भीमिन होती ॥ वह केवल उही आवश्यकताओं को पूरा करता है जो जीवन के नियमनित्तय ह व निराम और नितराम वस्तुओं को बना कर्मिता म प्राप्त कर सकता है । किन्तु पर मर्यादित मय मपान कृषक या श्रमिक की आवश्यकताएँ आत्मसाक्षा और अन्तर्मित हएँ । मय घनाप्य अनि एक निधन व्यक्ति की श्रमिता अत्रि आवश्यकताएँ मयना है और उन्हे पूरा करने म प्रयत्नात्त दखा जाता है ।

(३) प्रकृति हवि और फान Habi Taste and Fashion) — आवश्यकताओं म प्रकृति हवि और फान क चार मयान विनता पा जाती है । किसी अनि के लिए धूम्रपान करना की आन नान मे मितेन प्रारम्भ है पन्तु जा व्यक्ति धूम्रपान नहा करता मये निख वह आगाव मर ॥ निम वागाव का मज्जमान म प्रवर्धन है व म मज्जाम म मज्जकानि बढी जा मयनी ॥ वाधम मद्यम क निय महर क मर और मापी-मेवा अनित्तय है । पर विनताओं को कानज म प्रविष्ट म ह मूट टा म द्यपेन्ट फाउन्ट म मोटुक् की आवश्यकता मल मयना है । मितमा जमा मर उमर मिए एक पैगन होल मयता है । वातामर म य मयरा स्वभाव दन जाता है वह हमरे मिया कष्ट अनुभव करता है । जा विनताओं व परम्परागत आवश्यकताओं की पूर्ति महा कर्त व धाम आज क मज मयाज म य या मिकापुन मयतान है ।

आवश्यकताओं की विशेषताएँ (Characteristics of Wants)

मानव म आवश्यकताएँ म भीमिक मयार म तीर मति म वयना जा म ॥ इनकी प्रमुय विमताएँ निम्ननिर्माण है —

(१) आवश्यकताएँ अनन्त अपरिमित और अमय्य ह (Wants are unlimited in number) — मय या मनुष्य मीनर मयता की और मयमा होता है मयय उमकी आवश्यकताओं म वृद्धि हमा मयना ह मययता का प्रार मितर प्रवस्था म मनुष्य कवन जीवन म आवश्यकताओं म ही मृत मयना है परन्तु उनमे निश्चित मेने के व वायु म म सुय और विराम वस्तुओं का इकरा मनुभव कर उनका प्राप्ति म प्रयत्नात्त रहन मयता ह । पैम स्वभाव म आवश्यकताएँ एन क बाव दूसरा उपर मीनी रहता ह । मूरन (Moreland) मय मान का मित कन है कि किम प्रकार आवश्यकताएँ मयना हैं । उमाहरमाय मल मनुष्य की जब माये मर मी मूजी रोती पूरा रूप म मितन मग जाती है ना वह म की रोती वायन पी माक ममाळ मादि वस्तुओं की इकरा करता है और मियरी क मयना क स्थान पर मायु के वनमा के उपमाग की इकरा करन मयता है । मी प्रकार एन मया धवीन मयप्रथम मयात्रय इन या माग म जाता है परन्तु ज्या मय उमकी प्राय म वृद्धि होता है उसा म अनमार वह मयन मीनी धीन या मयी या माया मयन को मरुद करन मे और उमरे पचाड मयभवत उमर मोटरमाय क उपमाग की प्रवत इकरा हा जाती है । मूरनड म निष्प पर मयवन है कि देा उमरि की उस मयस्था को प्राप्ति मय जेद कि मयिवग माग की आवश्यकताएँ आज की अपवा अधिक मरुष्ट हान मय । यमपि अधिकता मनुष्य की आवश्यकताओं का पूर्ति हान मयनी परन्तु वह मयमया कभा मया आवेगा जब कि मपूण आवश्यकताओं की पूर्ति हा म कयाकि एक आवश्यकता की पूर्ति होने ही दूसरी आवश्यकता मयन उत्पन्न हा जाता है । इम प्रकार आवश्यकताएँ मय मयन ही रहमा ।

वास्तव में देखा जाय तो निम्ना यातायात और सवाद के माध्याम व्यापार वैज्ञानिक आविष्कारों से जो गति की वृद्धि होती है उसमें हमारा आवश्यकताएँ बढ़ती हैं। हमारी आधुनिक सभ्यता का आधारभूत आवश्यकताएँ और उनकी वृद्धि ही है। जो समाज जितना ही अधिक सम्य और उन्नत होगा उतनी अधिक सरल विभिन्नता और तीव्रता उसकी आवश्यकताओं की होगी।

(२) प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय के नियत पूर्णतया तृप्त हो सकती

है (Each want is satiable)—

यद्यपि आवश्यकताएँ अनन्त हैं तथापि प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय पूर्णतया तृप्त हो सकती है। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो इन्डियन रोस्टिवा के खाने से सभी उस समय तृप्ति हो जायगी। वही प्रकार एक व्यास व्यक्ति की व्यास इन्डियन गाथा में पानी पीने से पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाती है। जगज्ज एक व्यक्ति भोजन करता जायगा वैसे वैसे उसकी भूख की तावना कम जाती जायगी और कुछ देखा न मिलेगा तब ही जायगी यदि फिर भी भोजन करता ही जाय तो इस (पानी के)



भोजन की कोई भी उपयोगिता न होगी। इसी विषय पर उपयोगिता हानि नियम (Law of Diminishing Utility) अवलम्बित है।



(३) आवश्यकताएँ आवृत्त होती हैं (Wants are recurrent)—

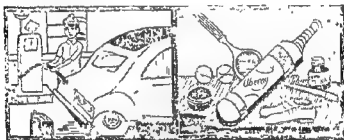
यद्यपि यह सत्य है कि प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय के नियत पूर्णतया सन्तुष्ट हो जा सकती है परन्तु कुछ समय के पश्चात् उसका अनुभव पुनः उत्पन्न होता है। जैसे दोपहर में भोजन करके सन्तुष्ट पूर्णतया शांत हो जाती है परन्तु सायंकाल का उमका पुनः अनुभव होना उचित है और फिर उसकी तृप्ति के लिये भोजन करना पड़ता है। इस प्रकार आवश्यकताएँ आवृत्त होती हैं।

(४) आवश्यकताओं में पारस्परिक स्पर्धा होती है (Wants are

Competitive)—मनुष्य अपने सीमित साधनों में अधिकतम मात्रा में वृद्धि करने में प्रयत्नमान रहता है। अतः प्रत्येक आवश्यकताएँ सर्वप्रथम मनुष्य के लिये प्रतिस्पर्धिता रखती हुई पायी जाती हैं। मान लीजिये कि कोई व्यक्ति कुछ रुपये लेकर बाजार जाता है और उसमें एक पुस्तक एवं फाउन्टेनपेन एक सूता का जोड़ा और एक सिनेमा टिकट खरीदना चाहता है। वह सब दृष्टाएँ सम्भर स्पर्धा करगी कि वह सबसे अधिक हो। यह सब करने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी

सीमित धन किम प्रकार इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यय करता है। वह उपयोगिता के अनुसार इन वस्तुओं का क्रय करता है। इस विवेकता पर अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धान्त 'सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम' (law of Equi-marginal Utility) प्राथित है।

(५) आवश्यकताएँ एक दूसरे के पूरक हैं (Wants are complementary) — मनुष्य की कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्ति अन्य वस्तुओं के द्वारा होती है। जैसे फाउन्टेनपेन के प्रयोग के लिये उसके उपयोग में स्याही की आवश्यकता होना चाहिये। इसी प्रकार बोटर-बाड़ी की इच्छा पूर्ति के लिये पेट्रोल आदि वस्तुओं का एक साथ उपलब्ध होना आवश्यक है।



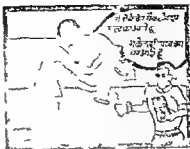
आवश्यकताएँ पूरक होती हैं।

(६) तीव्रता आवश्यकताओं का भेदक है (Wants vary in intensity) — आवश्यकताओं में पारस्परिक स्पर्धा होती है और उनकी तीव्रता में पर्याप्त अन्तर है। आवश्यकताओं की तीव्रता में व्यक्ति विशेष और समय के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक व्यापक व्यक्ति के लिये भोजन की अपेक्षा जल अधिक आवश्यक है।

(७) वर्तमान आवश्यकताएँ भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं (Present wants appear more important than future wants) — नैतिकतात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति को भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देने हैं। इसका कारण स्पष्ट है। भविष्य अनिश्चित और अन्धकार पूर्ण होता है। 'जितना सुखार्थ कर्तव्य को बहो महान है' यह सूक्ति इसी विवेकता पर आधारित है। सीमर महाशय कहते हैं कि उपभोक्ता भी गाड़ी वस्तुओं की उपयोगिता वर्तमान वस्तुओं की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। गाल ने कई नियम इसी पर अवलम्बित हैं।

(८) आवश्यकताएँ स्वभाव या प्रकृति में परिणत हो जाती हैं (Wants become a matter of habit) — अधिवास में आवश्यकताएँ

निरन्तर प्रयोग से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन हो जाती है और स्वभाव (Habit) मनुष्य का दूसरी प्रकृति कहलाना है वन यह प्रान (Acquired) और कृत्रिम (Artificial) होता है जो जन्म से प्राप्त नहीं होता है। उदाहरणार्थ कोई भी व्यक्ति बाल्यावस्था में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करने वाला नहीं होता है किन्तु इनके निरन्तर प्रयोग से इसका प्राप्ति बन जाता है। किसी वस्तु का आदर पक्ष जाने पर विना उस वस्तु के प्रयोग के उसकी गति योशना और धर्मता में अन्तर पड़ता है, समक विना उसे बन होता है। वह वस्तु उसके नियम प्रतिपाद हो जाती है। उसे परीक्षा पान करने वाला व नियम प्रकृत प्रति प्रावश्यक है, उनका प्रभाव में उनकी गतिपति पान हो जाता है।



(८) आवश्यकताएँ सामाजिक स्तर पर निर्भर हैं (Wants depend on the society in which we live)—यह आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति में निर्धारित नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के समक में होती हैं। वस्तुओं में हम पड़ते हैं भवन जिसमें हम रहते हैं वन जो हम करने हैं और आनन्द प्रमोद का साधन मिलने हम भ्रष्टाचार है सबका हमारे सामाजिक जीवन के अनुसार व्यवहार में आना प्रतिपाद है। जिस व्यक्ति का सामाजिक स्तर जितना ऊँचा या नीचा उतना या भ्रष्टाचार होता है उसकी आवश्यकताएँ भी उतनी ही ऊँची या अधोपरी होती हैं। एक उच्च पदाधिकाारी या वन सम्पन्न मनुष्य की आवश्यकताएँ एक निम्न वर्गीय व्यक्ति की प्रयोग सबका मिल जाती हैं। राजस्व राजस्व की प्राप्ति प्राप्त (Chief of Commissionary) व निम्न मोटरे भव्य भवन मनुष्यवान् वन और उच्च (पनीचर) आवश्यक है पर सब साधारण प्रजाजन के लिए ये वस्तु आवश्यक नहीं।

(९) आवश्यकताएँ परस्पर परिवर्तनीय होती हैं (Wants are interchangeable)—यह देखा जाता है कि एक वस्तु उगी प्रकार की अधिक उपयोग वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। व्यापार भौतिक उत्पत्ति होता है जो-वस्तु वन-वस्तु वन-वस्तु का निमाण या वन होता रहता है और इसमें कदाचित् वस्तु अधिक माध्यम वला प्राप्ति वस्तु का स्थान में पत्ती है। जैसे मिठाई के वन का लम्ब विल्लो के लम्ब में और साधारण छोटा बाड़ी माईपन और मोटर गाड़ी में परिवर्तित होने देखे जाते हैं।



(११) आवश्यकताएँ ज्ञान की वृद्धि के साथ बढ़ती हैं (Wants increase with the advance of knowledge)—मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि यातायन व मोटो-मोटर गाड़ी साधना में वृद्धि होती रहती है और व माध्यम



चल जा है, जो मनुष्य व उत्पादन की वृद्धि करने में सहायक है। मनुष्य नद-नई वस्तुओं के विज्ञापन आदि को देखता है और उनके उपयोग की इच्छा का पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठ जाता है और परिणामस्वरूप आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं।

(१२) आवश्यकताएँ वैकल्पिक होती हैं (Wants are alternative)—किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के कई माध्यम होते हैं जैसे चीन्हे कास में प्यास पानी व

मदिरिक मोटा, लेमोनेट, धवन प्रयत्न लगनी आदि से घान की जा सकती है और सोत कास में गर्म दूध, चाय या कॉफी आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। अल्पिष चुनोती इनके मूल्य आर उपभोक्तों के धान उपलब्ध मुद्रा पर निर्भर है।



(१३) आवश्यकताएँ समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तनशील हैं (Wants vary with time place and person)—आवश्यकताएँ सदैव एक मो नहीं रहती। इनमें समय, स्थान और व्यक्ति विषय के अनुसार पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। चीन और उत्तर प्रदेश के निवासियों की आवश्यकताओं में बड़ा भेद है। इसी प्रकार जो आवश्यकताएँ हमारे पूर्वजों की थी, वे अब हमारा नहीं हैं। अस्तु मनुष्य की आवश्यकताएँ विभिन्न हैं, और एव हा मनुष्य की आवश्यकताएँ विभिन्न समय और स्थान पर भिन्न-भिन्न होंगी।

कल्पित अवास्तविक अपवाद (Some Apparent Exceptions)—आवश्यकताओं की विवेचनाएँ, जिनका उत्पन्न और किया जा चुका है, अपवाद मूल्य नहीं हैं। उनके कल्पित अपवाद निम्नलिखित हैं—

(१) और यह उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय के लिए पूर्णतया सन्तुष्ट की जा सकती है, किन्तु कुछ आवश्यकताएँ ऐसी भी हैं जो कभी पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं की जा सकती। व आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं—

(अ) दृष्टण की मृगमृषा (Miser's love for wealth)—दृष्टण धन के लिए इतना प्रेममत्त होता है कि वह उसका सव्य सचय करने में उद्देश्य रखता है न कि उपभोग के लिए। वह निरन्तर अपने बाप में चांदी सोन के धातुपण जवाहरात और मुद्रा आदि विविध प्रकार का धन देखना रचिबर समझता है और उह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है। वह इस बात के निश्चय सदा रखता है कि धन संपत्ति कम न हो। अतः वह उसमें से पुनः पुनः धन का उपभोग करता है। एक व्यक्ति प्रमाथालु होता है। इसलिए अर्थशास्त्र इसका अध्ययन नहीं करता।

(ब) प्रदर्शन प्रियता (Love of Display)—कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने धन या संपत्ति के दिखाने की प्रवृत्ति इच्छा होती है। वे भाजन वस्त्र भवन उपस्कर आभूषण रत्नादि में अत्यधिक व्यक्तियों में अधिक सम्पन्न होना चाहते हैं और इन बातों की प्रशंसा अधिक बढ़ि कर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाओं की बढापि पूर्ति नहीं होती अस्तु वे इच्छित वस्तुओं के संग्रह में निरन्तर प्रयत्नशील देख जाते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो यह कोई अपनाद नहीं है। यह तो हमारी इच्छाओं के प्रगल्भ तथा प्रदीप्त होने के लक्षण का एक उदाहरण है। जमाही एक आवश्यकता तुल्य होती है दूसरी आवश्यकता सुरक्षित उत्पन्न हो जाती है। जैसे मनुष्य का माधारण बल निम्न से लगता है तो वह उसमें बल की दृष्टि करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार इच्छाएँ एक के बाद दूसरी बढ़ती हो जाती हैं।

(स) शक्ति प्रियता (Love for Power)—कुछ मनुष्य में शक्ति बलाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह निरन्तर अपनी शक्ति बलाने में मग्न रहते हैं। जैसे किसी राजा ने एक देश जीत लिया तो वह अपने एक देश भीतन का प्रयत्न करता है और अपने परबान् विरुद्ध विजयी होने की इच्छा को पूरा करने में उपायों को बुझाता है। मनुष्य की अपने प्रभाव, तेज वन बलादि की बलाने की इच्छा कभी तुल्य नहीं होती।

वास्तव में देखा जाय तो ऐसी इच्छाएँ साधारण मनुष्य में कम पाई जाती हैं। ऐसी इच्छाएँ प्रतापारण मनुष्यों की ही होती हैं इसीलिये इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के धर्म की कम्प नहीं है।

(द) मुद्रा प्रियता (Love of Money)—मुद्रा का आवश्यकता नभाने की तुल्य नहीं होती जिसकी अधिक मात्रा मुद्रा की तुल्य प्राप्त करने की तुल्य प्रियता उन्हीं की इच्छा बढ़ती जायगी। इस मुद्रा की सचय करने में विचार में अधिकारविशेष प्राप्त नहाने करेंगे अतः इसकी अत्यधिक मात्रा के कारण इसकी अधिकारविशेष प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

जैसे ऊपर बतानाया जा चुका है कि आवश्यकताएँ अनोचित और प्रगल्भ हैं और उनकी पूर्ति अधिकारविशेष मुद्रा में हो सकती है अतः मुद्रा का प्राप्ति करने की इच्छा मनुष्य में प्रबल रहती है। कभी पूरा नहाने मनुष्य नहाने हो पाती।

(२) आवश्यकताओं की कई एक विभाजनाओं में से उनकी अग्रगता और अपरिमितता अन्यतम लक्षण हैं परन्तु यह सबका सब नहाने है। इसका अर्थवाद निम्न प्रकार है—

साधु और सभामिया का आवश्यकताएँ—एक महापुरुष की आवश्यकताएँ विस्तृत सीमित होती हैं। उनका भाजन सात्विक तथा सामारण

होता है। सिंह या युगचर्म के अतिरिक्त विशेष वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। वे भौतिक संसार में विरक्त होकर अपने इच्छाओं और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर 'मुक्ति' (Salvation) प्राप्ति के लिये प्रसक्त देखे जाते हैं। इस बात का विवेचन प्रथम अध्याय में किया जा चुका है कि ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन में नहीं किया जाता क्योंकि उनको गलत जन-साधारण में नहीं की जानी।

आवश्यकताओं की वृद्धि (Multiplication of wants)—बहुधा यह चिन्तनीय विषय हो जाता है कि आवश्यकताओं की वृद्धि वाञ्छनीय है या नहीं। यह एक दिवादास्यद विषय है, यत्न उनकी वृद्धि वाञ्छनीय है अथवा अवाञ्छनीय यह तहसा यह दोनों उचित प्रतीत नहीं होता। इस विषय में विद्वानों की विविध धारणाएँ लीचे दी जाती हैं।

आवश्यकताओं की वृद्धि वाञ्छनीय है

(Multiplication of wants desirable)

(१) इस पक्ष के पण्डितों की यह धारणा है कि आवश्यकता की वृद्धि से कुछ संतुष्टि अवश्य हो जाती है। इसके फलस्वरूप जितनी अधिक आवश्यकताएँ हमें उत्पन्न होंगी, उतनी ही अधिक समृद्धि का परिमाण भी उत्पन्न हो अनुपात में बढ़ता जाएगा। यह धारणा भौतिक अवस्था सर्वनाशक्य दृष्टि में निरन्तर समुचित है।

(२) आधुनिक सभ्यता आवश्यकताओं की वृद्धि पर अवलम्बित है, अतः इनकी वृद्धि निरन्तर वाञ्छनीय है।

(३) यदि हम आवश्यकताओं की न्यूनता में विश्वास करने लग जायेंगे तो यह निवारण हमारी आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय-व्यक्तित्व प्राप्त करने और संसार में उन्नति के लिये अपसर होने में बाधक सिद्ध होगी।

(४) यदि हम इस भौतिक तारार की आवश्यकताओं में कमी कर देंगे तो हम आदिश-दृष्टि से इतने निर्बल हो जायेंगे कि समार का कोई भी देश हम पर विजय प्राप्त कर हमें अपने आधीन कर लेगा। यदि भारतवर्ष के निवासियों का जीवन स्तर उच्च हो जाता है, तो उसमें उन्नति की भावना भी बनी रहेगी। यह आर्थिक-उन्नति की और अपसर होने के लिये अनुपम प्रोत्साहन है।

आवश्यकताओं की वृद्धि अवाञ्छनीय है (Multiplication of wants is not desirable)—इस निवारणवाले अधिकार धारिक वृद्धि वाले व्यक्ति हैं जो मनुष्य की वास्तविक उत्पत्ति उसके 'आत्म-विकसम' में ही समझते हैं। वे इसके लिये भौतिकता में फँसना उचित नहीं समझते। इनका तर्क निम्नलिखित बातों पर निर्भर है :—

(१) वास्तविक उन्नति आत्म-कल्याण है न कि भौतिक समृद्धि।

(२) यदि कोई व्यक्ति या समाज अधिक आवश्यकताओं की वृद्धि के चक्कर में पड़ जाएगा तो आध्यात्मिक उन्नति के लिये, जो मानव जीवन का चरम सत्य है, उसे बहुत कम समय मिल सकेगा।

(३) आवश्यकताओं की संख्या बढ़ाने और फिर उनकी पूर्ति के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहने से मनुष्य का भौतिकवादी हो जाना स्वाभाविक है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिये सर्वथा लक्ष्य प्रशोध्य कर देता है।

(४) यदि आवश्यकताओं में अभीष्ट वृद्धि होत है और उन सबकी पूर्ति होन में आर्थिक क्षमताओं उपस्थित हो जानी है तो बिना आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सकें उनमें मरुत काय सदा हो जायगा । अतः वृद्धिमत्ता यही है कि मनुष्य अपना पूरनम आवश्यकताएं जैसे इसी आकार पर स्वर्गीय गांधी ने आवश्यक की बात और बसादि की पुनर्ता का सामना करने के लिए भारतवासियों को अपनी आवश्यकताओं के समर्थन की शिक्षा दी थी

उच्च दृष्टिकोण (Right View)—उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोण प्रतिपक्षी (Falsity) हैं । उचित तथ्य इन दोनों प्रतिपक्षीयों के मध्य में स्थित है । उन सीमित मरुत के आवश्यकताओं का साक्षात्त रूप भी न हानो चाहिये कि नतीजा प्राप्त न हो प्रोत्साहन ही न रहे और इनमें अधिक की गयी होगी चाहिये किमन उनकी पूर्ति में होने पर दुःख का अनुभव हमें नये ।

सारांश यह है कि हमारी आवश्यकताएं न अधिक छोटी न कम हानी चाहिये । सीमित गांधी के अनुक्रम ही उनकी वृद्धि वांछनीय है

क्या आवश्यकताएं आय का प्रयोग अधिक मात्रा के साथ उठनी हैं ?

आर्थिक मरुतों में वृद्धि में आवश्यकताओं की वृद्धि ने बड़ी भूमिका निभायी है । यही एक किन्तु मातृ की छोटी मोटी और विरक्त आर्थिक क्षमताएं । जो लोग अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हैं वे अधिक समय और उत्तम मरुतों को जानते हैं । इन दोनों में आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनकी पूर्ति के माध्यम विरक्त जाते हैं । हमारा प्रतिपाद आवश्यकताएं (Necessaries of life) और गुण व विनाम की वस्तुओं का उपभोग तब सीमित था रहा है । विभिन्न प्रकार के नवान् आर्थिकारों और विनाम की वस्तुओं में हम प्रभावित होत जा रहे हैं किमना यह है कि प्रतिदिन आवश्यकताओं में वृद्धि होनी रहती है ।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी आय एक सीमित मात्रा में होती है । वह आवश्यकताओं की पूर्ति करने में । आय में वृद्धि करना किसी व्यक्ति के लिए की बात नहीं है वह समाज की सेवा पर और सुखपर पर निर्भर है । अतः हम दोष को बराबर समझते हैं कि मनुष्य का अपने गुण और विनाम वस्तुओं में बसी किसी क्षमता । मनुष्य का कभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कभी नहीं बनना चाहिये अतः उसका जीवन नष्ट हो जायगा ।

आवश्यकताओं और आय के अनुपान करने का उपाय

(१) उत्पादन में वृद्धि आता आवश्यक है नियम प्राप्त में वृद्धि हो ।

(२) किसी देश या राज्य के आर्थिक मायता का पूरा उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

(३) जन मरुतों की वृद्धि में उचित नियन्त्रण होना चाहिये ।

भारतीय कृषक का आवश्यकताएं (Wants of an Indian farmer)

भारतीय कृषक की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ने वाले निम्नलिखित कारण हैं —

(१) रीति या व्यवहार (Custom) में निरधारित हानि वाता आवश्यकताएं — एक भारतीय कृषक का आवश्यकताएं आय वृद्धि की छोटी रीति या व्यवहार और प्रवृत्ति में अधिक प्रभावित होती है । य दो विभागा में विभक्त हो सकती

हैं—एक तो अनिवार्य आवश्यकताएँ और दूसरी रचनात्मक (जो अनिवार्य न हों) आवश्यकताएँ :—

(अ) अनिवार्य आवश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र और आवास आदि उसकी आवश्यकताएँ अधिकतर रीति या व्यवहार से निर्धारित होती हैं। उसका भोजन एक विशेष प्रकार का होना है और उसकी वेष वृषा भी उनके पूर्वजों की भाँति भगवत्पा, पगड़ों और धोती होती हैं। उसकी अनिवार्य आवश्यकताएँ बिल्कुल व्यावहारिक रीतियों से प्रभावित होती हैं।

(ब) अजीबनोपयोगी या रचनात्मक आवश्यकताएँ—कुछ ऐसी आवश्यकताएँ हैं, जो अनिवार्य नहीं हैं बल्कि वे सामाजिक व धार्मिक प्रभाव न प्रचलित हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह व गर्व आदि के अवसरों पर होने वाले व्यय इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति का उपाहरण है।

(२) प्रकृति (Habit) द्वारा निर्धारित होने वाली आवश्यकताएँ—वृषण की ऐसी आवश्यकताएँ, जो न तो अनिवार्य हैं और न रीति-व्यवहार के दृष्टिकोण से परम्परागत हैं, बल्कि स्वभाव से प्रचलित हैं, प्रकृति निर्धारित आवश्यकताएँ हैं, जैसे घूमना (चित्तम, टुक्का आदि)।

(३) बुद्धि (Reason) से निर्धारित होने वाली आवश्यकताएँ—भारतीय रूपका प्रायः अन्न और रुढ़िवादी होता है अतः बुद्धि से निर्धारित होने वाली उसकी आवश्यकताएँ बहुत कम हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग वह परम्परा में करता आ रहा है उनके वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, यद्यपि किसी वस्तु के उपयोग से हानियाँ भी क्यों न उसे बनलाई जायें। उदाहरण के लिये, उसे टोपी की अपेक्षा ढोंग की उपयोगिता बतलाई जाय तो भी वह टोपी ही पहनता समझेंगे। अतः, उसकी आवश्यकताओं में बुद्धि का हस्तक्षेप बहुत कम है।

भारतीय धर्मिक की साधारण आवश्यकताएँ
(Ordinary wants of an Indian labour)

(१) भोजन (Food)—एक भारतीय धर्मिक का भोजन अन्न रीति-रिवाज (Custom) और अन्नः प्रकृति (Habit) से निर्धारित होता है। वह बड़ी भोजन करता है जो उसके पूर्वज करते थे। यदि उसकी आय भी बढ़ जाय, तब भी वह परम्परागत खाद्य-पदार्थ ही उपयोग में लावेगा। जैसे एक हिन्दू धर्मिक घड़े सस्ते ही जाने पर भी अपना खाद्य-योग्य पदार्थ घोषित होने पर भी (यदि वह पहले इतना उपयोग नहीं करता था) कदापि प्रयोग में नहीं लावेगा।

(२) वस्त्र (Clothing)—उष्ण जलवायु और अत्यन्त निर्धनता के कारण वह प्रायः केवल अपनी नमर को ही ढँकता है। विशेष अवसरों पर प्राचीन श्रृंगी और पंशन के वस्त्र उपयोग में लाता है। इस मामले में वह अपनी बुद्धि से बाध लेता है। वह पुराने कपड़ों के कपड़ों को छोड़ कर नए कपड़े ले लेते और टिकाऊ कपड़ों को भी प्रयोग में ला सकता है, यदि उसको समुक्त प्रकार के कपड़ों की उपयोगिता में समुदाय कर दिया जाय।

(३) आवास (Housing)—इस विषय में भारतीय धर्मिक प्रकृति और रीति-रिवाज में प्रभावित है। बुद्धि और विवेक हमसे कोई स्थान नहीं रखते। एक अंगरेज धर्मिक जो कि उच्च जीवन-स्तर का अभ्यस्त है दुर्गम गन्दे, बाधुन-हिन गृह

को उल्लास कर माफ-मुहरे मकान में रहना पसन्द करेगा। परन्तु भारतीय श्रमिक मजिन और प्राणालहार (Stuffy) वातावरण में भी रहने का सम्मेलन होता है।

(४) तम्बाकू मदिरा, सिनेमा और जुया (Tobacco, Alcohol, Cinema & Gambling)—भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक व्यक्ति प्रायः इस प्रकार के दुष्टांगों में पक जाते हैं। ये व्यक्ति पारम्परिक व्यवहार और अपनी रीति से लचीली प्रेरणा पाते हैं। श्रमिक तम्बाकू और शराब इत्यादि पीता है, क्योंकि उसके समाज के अन्य व्यक्ति भी पीते हैं।

(५) औषधि द्वारा उपचार (Medicines)—भारत का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति बीमार होता है। यहाँ साधारण व्याधियाँ पारम्परिक नुस्खे प्रयोग में लाये जाते हैं। यद्यपि चिकित्सा का पूर्ण प्रभाव है, फिर भी इस विषय में नुति में काम होता है।

(६) शिक्षा (Education)—शिक्षा-सम्बन्धी विषयों में बुद्धि और विवेक से अधिक काम नहीं लिया जाता, बल्कि यह परम्परा के अनुसार जिनकी शिक्षा सन्तुष्ट है, उनकी ही से प्राप्त करते हैं।

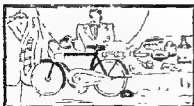
(७) सुन्दरवादी (Jugation)—सुन्दरवादी में प्रयोगशील भारतीय व्यक्ति बड़े सम्मेलन हैं।

(८) आनन्द प्रमोद, भोज आदि (Entertainments & Feasts)—शान्ति और नशीब के श्रमिकों की जाति-रिवाज के अनुसार विवाह एवं मृत्यु के अवसर पर सहभोज देते पड़ते हैं।

(९) आभाषण, विवाह, दाह-संस्कार—इन सब पर रीति-रिवाज के अनुसार व्यवस्था किया जाता है।

(१०) सजावट की वस्तुएँ (Articles of Finery)—मजाबूत या आनन्द की वस्तुओं पर कम ध्यान दिया जाता है। रीति-रिवाज के अनुसार अन्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। परन्तु ऐसी वस्तुओं की कमी पर कम ध्यान दिया जाता है।

एक कालेज के विद्यार्थी की आवश्यकताएँ—कालेज के विद्यार्थी की आवश्यकताएँ रीति-रिवाज और फैशन में निर्धारित होती हैं। जब एक छात्र ने कालेज



प्रयोग करना पड़ता है। अन्यथा वह 'बुद्ध' समझा जायगा। उस फैशन और रीति से प्रभावित होकर भ्रमपूर्ण चरित्र पड़ता है तथा अपर-तात्त्विक में निहित-हुता रहने के लिये सिगरेट-बैम भी खरीदता पड़ता है। वह चाय पीता है और अपने मित्रों को भी चाय के लिये आमन्त्रित करता है। इसी प्रकार उसे बहुसंख्य सुविधित तेल, साबुन, सैण्ड, शीम, म्मी, टूथपेस्ट और फनीयर आदि वस्तुओं पर भी ध्यान देना पड़ता है।

का विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये किसी उच्च नगर के कालेज में प्रविष्ट होता है तो उस एक क्षण अपनी कप-भूषा आदि में परिवर्तन कर देना पड़ता है। उसे अपने मात्रियों से सादर प्रार्थना करने हेतु साइकिल, फाउण्टन पेन, राय की घड़ी, मूट, टाई, बॉलर आदि का

अभ्यासार्थ प्रश्न

इन्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

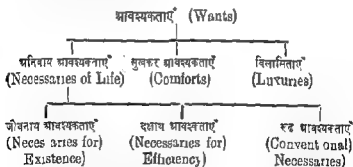
- १—'प्रावश्यकता' का मुख्य लक्षणा पर नोट लिखिए ।
(उ० प्र० १२५८, सागर १२५१ ४६)
 - २—'प्रावश्यकता' की परिभाषा दीजिए । प्रावश्यकता का निधारण पर परिस्थितियाँ का प्रभाव स्पष्ट कीजिए ।
(उ० प्र० १२५३)
 - ३—बहनी हुई प्रावश्यकताएँ बाह्यीय आदिब ध्यय उद्या है ? क्या बहनी हुई प्रावश्यकताओं और उत्पन्न से बाधकता का कोई परस्पर सम्बन्ध है ?
(प्र० या० १२६०)
 - ४—प्राप्तमान का अर्थ स्पष्ट कीजिए । एक भारतीय कृषक की प्रावश्यकताओं के निधारण पर रीति रिवाज, आदत और तब का प्रभाव व्यक्त करत हुए उनका उल्लेख कीजिए ।
(प्र० यो० १२३८)
 - ५—अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रावश्यकताओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिए ।
(उ० प्र० १२४८, ४९)
 - ६—प्रावश्यकताओं का भाव्य बर्तन वाञ्छनीय है या नहीं ?
(उ० प्र० १२४२)
(रा० यो० १२४८)
 - ७—"प्रावश्यकताएँ-प्रमाण मनुष्य ही अथ व्यवस्था का चक्र है । —वैमर्निष्ट क इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
(रा० यो० १२५०)
 - ८—'प्रावश्यकताएँ आदिन त्रियाणा का जन्म देती है और आदिन त्रियाणा प्रावश्यकताओं को जन्म देती है । —स्पष्टतया व्याख्या कीजिए । प्रावश्यकताओं का महत्त्व बर्तन विम सीमा तक वाञ्छनीय है ?
(प्र० यो० १२४३)
 - ९—प्रावश्यकताओं से क्या सम्बन्ध है ? प्रावश्यकताओं की प्रमुख विभागताओं का उल्लेख कीजिए ।
(उ० प्र० १२५५, ५३ ५२, ५५, ५६)
 - १०—मानवीय प्रावश्यकताओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए । क्या प्रावश्यकताएँ पूर्णतः मनुष्य की जा सकती हैं ?
(बनारस १२४५)
 - ११—मानवीय प्रावश्यकताओं में मुख्य लक्षणा का वर्णन कीजिए । (रा० या० १२४८-५०,
(प्र० या० १२४६, ३८, प्र० भा० १२५४ बनारस १२५३, ५१)
 - १२—प्रावश्यकताओं के क्या मुख्य लक्षण हैं ? कौन सी प्रावश्यकताएँ सीधे जानी हैं और क्यों ?
(सागर १२४८)
 - १३—प्रावश्यकताओं में क्या मुख्य लक्षण है ? क्या प्रावश्यकताओं का महत्त्व वर्धन उचित है ?
(सागर १२५८, उ० प्र० १२६२, नागपुर १२५४)
- इन्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ
- १४—मानवीय प्रावश्यकताओं के लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए । (रा० या० १२५६)
 - १५—'प्रावश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होता है । —स्पष्ट समझाइए । (उ० प्र० १२५०)
 - १६—'प्रत्येक प्रावश्यकता कोपल्लव है । —स्पष्ट कीजिए । (उ० प्र० १२६८)
 - १७—प्रावश्यकता के अर्थ बताइए और मानवीय प्रावश्यकताओं के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए ।
(प्र० या० १२५३, ५०)

आवश्यकताओं का वर्गीकरण (Classification of Wants)

आवश्यकताओं के वर्गीकरण का कारण

मनुष्य अपने साधारण जीवन में अनेक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। वे समान रूप में आवश्यक नहीं होती। उनमें से कुछ अधिक आवश्यक होती हैं और कुछ कम। हमारा कुछ आवश्यकताएँ तो ऐसी हैं जिनकी पूर्ति व बिना मनुष्य जीवन स्थिर नहीं रह सकता। उन्हें अनिवार्य आवश्यकताएँ कहते हैं। अर्थशास्त्र में तृप्ति के लिए मनुष्य वस्तु को अनिवार्यता उसे आवश्यक बनाती है। अब जो वस्तुएँ हमारी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें अनिवार्य या आवश्यक पदार्थ (Articles of Necessity) कहते हैं। ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं को 'सुख और विलास वस्तुएँ' (Articles of Comforts and Luxuries) कहते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य सब आवश्यकताओं का तृप्ति एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि आवश्यकताएँ तीव्रता (Intensity) में पर्याप्त भिन्नता रखती हैं। कुछ आवश्यकताएँ अधिक तीव्रता रखती हैं और कुछ कम। अधिक तीव्र आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए विविध उपर्युक्त साधन जुटाने में पूर्व सोचा जाना है कि तृप्ति किस व्यक्ति के लिये कितनी मात्रा में आवश्यक है। इस दृष्टि से मानव आवश्यकताएँ मुख्यतः तीन भागों में विभाजित की गई हैं—(१) अनिवार्य आवश्यकताएँ, (२) सुखकर आवश्यकताएँ और (३) विलासिताएँ। यह स्पष्ट करने के लिये नीचे चित्र दिया जाना है —



(१) अनिवार्य आवश्यकताएँ (Necessaries of Life)—मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ अनिवार्य आवश्यकताएँ कहलाती हैं। इनकी अनिवार्यता

का अनुभव इनके द्वारा किसी इच्छा की पूर्ति के अभाव में उठ खड़ी होन वाली पीड़ा में किया जा सकता है। इन इच्छाओं की पूर्ति तीन भागों में विभक्त की जाती है—जीवन रक्षा, दयना और सौभाग्य।

अतिव्याप्य आवश्यकताओं का उपविभाजन—अनिवार्य आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होन के कारण निम्नलिखित तीन विभागों में बाँटी जाती हैं—

(अ) जीवनाय आवश्यकताएँ (Necessaries for Existence)—
जिन आवश्यकताओं का पूर्ति मनुष्य ज्ञान का स्वरिखन व नियम की जाना है व जीवनाय आवश्यकताएँ कहलाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ पुनर्जनन भावन पर और पक्ष आदि चाहिए जिसमें वह अपना जीवन गति और स्वास्थ्य को स्थिर रखे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व जिना मनुष्य को स्वास्थ्य स्थिति व कारण ज्ञान का अतिव्याप्य विषय प्रस्तुत हो गचन है।

जानना ज्ञान व आवश्यकताओं देना वान और जनवायु के अनुसार पदार्थ भिन्नता रखनी है। उदाहरण के लिए पात देना व आवश्यकताओं में भोजन पद (Drink) यदि व प्रतिरिक्त पर्याप्त वस्त्र विषय प्रचार का ध्यान (Shelter) भा हाना चाहिए। परन्तु ध्यान व समझ रखना व नियम वस्त्र और आवास प्रविष्टि में व आवश्यकता नहीं। तीन बाल व समझन आधारित आवश्यकताओं और एक वस्त्र ही पदार्थ है। एम देना व जीवनाय आवश्यकताओं का मकेन कुछ धन जन की धार है व वहु व विन रखन व समय है।

जीवनाय आवश्यकता पदार्थों के उपभाग के प्रभाव—इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का निरन्तर उद्योगात्न रहता पड़ता है। धन व मनुष्य को परिश्रमी बनाता है।



(ब) दाय आवश्यकताएँ (Necessaries for Efficiency)—
जीवनाय आवश्यकताओं व अनिवार्य कुछ आवश्यकताएँ एसा हैं जिनकी पूर्ति मनुष्य का पनीपानन की गति एवं नियुक्ता बनाए रखन व लिए आवश्यक है। एसा आवश्यकताओं दाय आवश्यकताओं कहो जाता है। जब पौष्टिक भोजन स्वच्छ और उत्तम वस्त्र औपदि उपचार के मापन वस्त्र व निष्ठा-मन्व-यो मन्विष्य वृद्धावस्था व नियममन्विन प्र व और हृदयार मन्विष्य आदि।

दाय आवश्यकता पदार्थों के उपभाग का प्रभाव—एन वन्मना व उद्योग व मनुष्य को योग्यता अथवा दायता व वृद्धि होती है। व आवश्यकताओं

की पूर्ति न होने से मनुष्य की शिष्टता और धन पात्रन शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।



(घ) कुछ आवश्यकताएँ (Conventional Necessaries)—एक आवश्यकताएँ वे हैं जिनकी पूर्ति मनुष्य अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिये करता है । समाज के एक सदस्य के रूप में ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति उसे प्रत्यक्ष करना पड़ती है अथवा यह सामाजिक दृष्टि से बिराजा है और तब प्रतिष्ठा के उद्धार का ध्यान बन जाता है । इन वस्तुओं का जो प्रतिस्पर्धा आधार विचार तथा ध्यान पड़ जाने से आवश्यक बन जाने के इतिहास या एक आवश्यकताओं की वस्तुएं कहने हैं ।



मनुष्य सामाजिक प्राणी है समाज की शक्ति के कारण उस समाज के आधार विचार रीति रिवाज रखे रहने चाहिए का ध्यान करना पड़ता है । अतिविचारमय धन सुधार के लिये समाज के सामाजिक तथा धार्मिक तत्त्वों के अन्तर्गत पर प्रयोग में लाया जाता है । तब मनुष्य विचार धर्म व्यवस्था पर ध्यान देता और समाज के प्रति रिवाज के अनुसार व्यवहार कर समाज के लिये समस्त प्रयत्न पर विचार प्रचार का ध्यान करता और समाज के लिये समाज के आवश्यकताओं का ध्यान है । क्योंकि इसी दृष्टि व्यावहारिक रीति रिवाजों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । समाज के विविध व्यक्तियों मनुष्य अपनी सामाजिक मुद्राओं और प्रतिष्ठा का महत्व समझता है । मनुष्य एक स्थान पर स्थित है — बहुत से व्यक्ति केवल समाज के अन्तर्गत में अपने व निज अपनी सुवर्ण प्रतिष्ठा आवश्यकताओं की पूर्ति को एक-एक विचार, मूल्य और शक्ति धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों पर व्यय करना अपना कर्तव्य समझते हैं ।

आवश्यकताओं का वर्गीकरण]

भारतवर्ष में रुढ़ियों का प्रभाव अधिक होने से सामान्य स्थिति का मनुष्य भी अपनी जीवनाय एक दशावस्था आवश्यकताओं में नहीं कर सके आवश्यकताओं को सतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। ताह वद मो हो, वह बिनाट भोजन ग्रयवा मृत भोजन ग्रवश्य करेगा।

इनके उपभोग का प्रभाव—इनके उपभोग से मनुष्य रुढ़िवादी हो जाता है, इसका परिणाम यह देखा गया है कि उनका मानसिक विनाश मकीम हो जाता है।

अनिवार्य आवश्यकताओं में मुख्य और माथ ही मनुष्य—मनुष्य आवश्यकताओं की मान में मूल्य के अनुपात में कम परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, नमक का मूल्य अधिक गिर जाने पर भी नमक आवश्यकताओं के अनुसार ही खरीदा जायगा—

(२) सुखकर आवश्यकताएँ (Comforts) — नित्य ज़रूरतों की पूर्ति अनिवार्य आवश्यकताओं के उपरान्त जीवन की सुखी धारा प्रत्यक्ष उत्पन्न करने का काम सुखकर आवश्यकताएँ बहुवर्णीय हैं। उदाहरण के लिए स्वादिष्ट भोजन, मय भवन, चित्तवृत्ति मनोरंजन के साधन, विज्ञान का प्रयोग, स्वस्थ या मनुष्य का कृतां और एक उत्तम चिकित्सी पत्नी धोनी आवश्यकताएँ एक सुखदायक जीवन की रजारी— ये सब पदार्थ सुखकर कह जायें हैं। इनो प्रत्यक्ष एक निराशा के भिन्न एक पुरुषक अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं एक मज और सुखी उगके लिए वनस्पति आवश्यकता है, परन्तु गरीबों के लिए उनका लिए सुखकर पम्प है। सुखकर बहुधा जीवन के प्रसन्न और सुखी बनता है। एक अवस्था में मनुष्य को कुछ दुःख महसूस होता है। एक क्षमता और निपुणता में भी अवस्था रुढ़िवादी है परन्तु इन पर लिए व्यय के अनुपात में नहीं। इनके प्रभाव में मानसिक निपुणता की धनि हो नही होती प्रसन्न इसकी पूर्ति से होय या ताभा में भी अवश्य वचित रहना पड़ता है।



सुखकर एवं दानाव आवश्यकताओं में भेद—इन दोनों का अन्तर अत्यन्त सूक्ष्म है कि वे भी अलग विचारणीय दाना को एक हो पम्प समझ जायें हैं। वास्तव में दोनों में पर्याप्त अन्तर है। सुखकर पम्पों पर जितना व्यय किया जाता है उतना ही व्यय लाभ कम होता है। परन्तु दानाव पम्पों के उपभोग में स्वस्थ मार दाना में निम्नरुढ़ अधिक लाभ पहुँचता है।

सुखकर पदार्थों के उपभोग का प्रभाव—निरन्तर सुख का जीवन मनुष्य का पोषक और निरन्तर बना देता है जिसमें वह अपूर्ण जीवन के लिए अवशेष निद्रा हो सगता है।

मूल्य और भाग का सम्बन्ध—भाग और मूल्य में मूल्य की वृद्धाधिकता से समानुपात में कम परिवर्तन होने के कारण सकल लाभ प्रभाव शून्य रहता है।

(3) विनाशिता (Luxuries) — जिन आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन की अत्यधिक सुखी और विषयात्मक वस्तुओं के द्वारा की जाती है वे विनाशिता या भोग्य वस्तुएँ कहलाती हैं। इन पर जो व्यय किया जाता है वह आवश्यकताओं में कम अधिक होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जीवनभर को केवल एक-दो भोगमय वस्तुओं के द्वारा ही की जाती है। विनाशिता-वस्तुएँ अनावश्यक होती हैं। इन विनाशिताओं में मनुष्य का काम अभी प्रकार से ही करता है। इसी कारण प्रा० जीड ने इन वस्तुओं को अनावश्यक आवश्यकताएँ (Superfluous Wants) कह कर पुकारा है। प्रा० जीड ने इन वस्तुओं को अव्यय व्ययिता (Excessive Personal Consumption) भी कहा है। रुचि ने अव्यय व्ययिता (Undesired Desires) लिखा है। प्रचलित निष्ठाव्ययिता में अव्यय व्ययिता (Waste) भी मूल्य में अधिक मनोप्राप्त करने की वृद्धि लिखा है। मनुष्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं के साथ अन्य भोजन हाथ वस्तुओं में अधिक व्यय करता है। इन आवश्यकताओं का पूर्ति में अत्यधिक व्यय आवश्यक होता है पर वह व्यय होने के अतिरिक्त काय कल्याण एवं निष्ठा में मनुष्य भी रुचि नहीं करता। कम कभी तो इनका उपयोग हानिकारक सिद्ध होता है। कम ही विनाश वस्तुओं का प्रयोग हानिकारक उपयोग भी कहा जाता है। इनके अभाव में किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता।



विनाश वस्तुओं का उपयोग का प्रभाव—विनाश वस्तुओं के अतिरिक्त उपयोग से मनुष्य अपने मानवता की सीमा में बाध नहीं पाता है। परिणामतः वह अपने जीवन का व्यय जीवन में करता है। विनाश वस्तुओं का उपयोग अपने व्यय में उत्पन्न है। इनके उपयोग का हानिकारक है। इनके अतिरिक्त मनुष्य अपने जीवन की सीमा में बाध पाता है और परिणाम में वह कल्याण में बाध पाता है।

मूल्य और भाग का सम्बन्ध—कम भाग के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर ही भाग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। अतः का भाव चार आने पावे से गिर कर तीन भाग पावे हो जाता है। अतः व्ययिता का सम्बन्ध अतः के टुकड़ों पर दला जाता है। इनके अतिरिक्त यदि वस्तुओं के मूल्य में कम वृद्धि होता है तो मनुष्य को उन वस्तुओं पर व्यय करने की आवश्यकता नित्य कम हो जाती है।

व्यक्ति विशेष और उसका जीवन पर प्रभाव—वस्तुओं का वर्गीकरण व्यक्ति विशेष के साथ-साथ भिन्नता रखता है। कोई एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य दूसरे के लिए सुखकर और तीसरे के लिए विनाश-वस्तु सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए एक मोटर कार किसी व्यक्ति के लिए कार्य-वस्तु मोटर के लिए अनिवार्य वस्तु है क्योंकि वह उसकी सज्जाता से अल्प समय में वस्तु से रोडियों को देख सकता है। एक कानून के प्रोफेसर के लिए यह एक सुख वस्तु है क्योंकि इसके प्रयोग में उसे धीमे जाने के कारण बचाने पड़ा नहीं होगा और उसके कार्य में सुगमता की वृद्धि करेगा और कुछ सहायक सिद्ध होगी है। परंतु यही एक साधारण अत्यापक के लिए विनाश वस्तु सिद्ध होगी। हाथ मूलर स्थान में आनंद प्राप्त अत्यापक के लिए वह मोटर अनिवार्य हो सकती है। आनंदमान की एन एन ० वी० या बरिन्टो (Barnett law) या उच्चतम मानकदा के छान की पाकगाय (Yorkshire) में आनंदमान के लिए मोटर रखना अनिवार्य समझा जाता है। इसी प्रकार एक टेलीफोन किसी घर के सम्पादक के लिए एक अनिवार्य वस्तु है एक कानून के प्रोफेसर के लिए यह एक सुख वस्तु है और एक जमदार के लिए यह एक बिलान की वस्तु है।



सामाजिक स्थिति सामाजिक स्थिति का भिन्नता वस्तुओं के वर्गीकरण में विभिन्नता पैदा कर देता है। एक व्यक्ति के वजन रात में महसूस होता है और निम्नता के लिए विनाश वस्तु होती है और मध्य वर्गीय वर्गियों के लिए महत्वपूर्ण सुख वस्तु सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार 'व्यक्तिगत' वस्तु सामाजिक के लिए एक आवश्यकता है। सामाजिक स्थिति है। पर साधारण वर्गियों के लिए यह विनाश वस्तु है।

आर्थिक स्थिति मनुष्य के आय भी एक विविध कार्टिया का भिन्नता का कारण बन जाती है। विज्ञानी के अनुसार एक साधारण वस्तु पर एक मध्य की परीक्षा कर। यदि मध्य वर्गीय वर्गों के व्यक्ति पर्याप्त साधन सम्भव है तो यह अनिवार्य वस्तु है परन्तु वहाँ वस्तु वृद्ध के लिए सुख-वस्तु है और 'सुख आय' मान साधारण वर्गियों के लिए विनाश वस्तु है।

स्वभाव या प्रकृति—मनुष्य की प्रकृति में भी यह वर्गीकरण प्रभावित होता है। जन्म विनाश-वस्तु की प्रकृति वान व्यक्ति के लिए चाप एक अनिवार्य वस्तु हो जाती है परन्तु एक छात्र के लिए जो जीवन स्वाद के लिए चाप पान को होश

मे प्रवेश करता है, यह निस्पन्द विलाप-वस्तु है, यद्यपि यह एक उद्योगशाला के श्रमिक के लिये सुख-वस्तु है, यदि वह उम्र दिन भर कार्य करने के पश्चात् अपनी भ्रान्त को दूर करने के प्रयोजन से सेवा करता है।

विचार—मनुष्य के विचार वा भी वस्तुभाषक विभाजन में कम महत्त्व नहीं है। जो मनुष्य 'साधारण' जीवन और सन्न विचार' में विश्राम रम्य है उनके लिए साधारण भोजन, वस्त्र, आवास आदि ही अनिवार्य वस्तुएं हैं। वेप वैभव प्रदर्शन वस्तुएं उनके लिए विलास-वस्तुएं हैं।

देश—स्थान परिवर्तन के माय माय वस्तुओं के वर्गीकरण में भिन्नता पा जाती है। जो वस्तु एक स्थान पर आवश्यक मानी जाती है वही दूसरे स्थान पर सुख या विनाश वस्तु की भाँति म समिनी जाती है। कारण स्पष्ट है, भिन्न-भिन्न स्थान पर जलवायु, गेति रिवाज, पंथक शादि म पयाज भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, दुर्गलंड जैसे देश म उनी वष्य प्रसिधाय वस्तु है वपाति इनके विना अमुक घपने शरीर की रक्षा नही कइ सकता, किन्तु व ही लषा जेम देश म आवश्यक नही समझ जाते। उनी माय का धूर म काला उनी कोट पहने गुविम येन हो नहा, किन्तु ही पहानी साहू (लका क मय्य गगारिण) मो वम कनी मयादशर बाट पहने मिलते हैं। मातिर उन पवारो क सिध यदि प्रकृति न जाइ नहो दिवा, तो गया व कनी कपडा को पहनने का शाक न करे ? कितने ही मिहारी साहूवा पो उमनी जाय शीर कोतो पत इकडर भी प्रसन्न मानम होगा पर ममकना बाहिये कि लका धीर उपको रात्रपाता काकरा सुत विनाम म भारी मे सदिया माय बड माण है। भारतीय नारिया क पहन रुड आवश्यकता है, परन्तु पाश्चाय नारिया क त्रिप विनायका है।

सूत्र—जिमी वस्तु के मूल्य में व्युत्पादिकता में उभे वस्तु के श्रेणी विभाजन पर दत्ता प्रमाण पड़ता है। जैसे किसी एक कपड़ का मूल्य ७ रु० प्रति गज हो, तो वह विभाज्य वस्तु के अन्तर्गत आता है। उसका मूल्य ३ रु० गज हो जान पर मुख्य-वस्तु हो जाता है और वह बाढ़ धान गज मिलन लग जाय, तो अनिवार्य वस्तु का रूप धारण कर लेता है।

वस्तु या परिमाण—एक मापारण व्यक्ति व जिस एक जोडा ज्ञान प्रतिबोध वस्तु है दूसरा जोडा मूल-वस्तु है और तीसरा जोडा विज्ञान-वस्तु। इस प्रकार वस्तु की सख्या और मान म भा वस्तुप्रा व वर्गीकरण म धन्य हो जाता है।

समय—गमय वे हर पैर म घटून-श्री भाग्य वस्तुएं एक धंशों मे हमरी धंशों मे परिवर्तित हो जाती है। सुख वण पूव टोपें एक निलाम वस्तु मयभा जाता या पर भागकल यह भीम अन्तु म निदिवन रूप मे एक अनिवाद्य वस्तु हो गया है श्रीर गीतानन मे तो यही सुख-वस्तु समभा जाता है।

वर्गीकरण का आधार (Basis of Classification)—अब यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि क्या वस्तुभावा का वर्गीकरण किसी आधार पर सम्भवित है अथवा इन सब तथ्यों के मूल में एकता या निष्पक्षता नामक कोई तत्त्व निहित रहता है। इनको स्पष्ट स्पष्ट करने हुए यो कहा जा सकता है कि समुच्चय वस्तु को किसी विनिर्णय वाटि में रखने के लिए उन वस्तु के उपभाग का कार्य-वृत्तता अथवा क्षमता (Efficiency) पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना पड़ता है। यदि

किसी वस्तु के उपयोग से उपयोगिता की कार्य-कुशलता में अनुपस्थित वृद्धि होती है अथवा स्थिरता बनी रहती है अथवा उसका उपयोग न करके न दक्षता बहुत गिर जाती है, तो उस वस्तु का अनिवार्य वस्तु (Article of Necessary) की श्रेणी में रखेंगे। यदि उससे उपयोग से उपयोगिता की कार्य-कुशलता में वृद्धि घटने हुए अनुपात में होती है तथा उससे अभाव में आ-ह्लास अनुपात में अधिक है तो ऐसी वस्तु सुख वस्तु (Article of Comfort) की श्रेणी में रखा जावेगी। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु के उपयोग से न तो दक्षता में वृद्धि होती हो और न उसमें अभाव में ह्रास होता हो, तो उसे विन्यास वस्तु (Article of Luxury) कहेंगे।

वर्गीकरण आधार सूचक तालिका—निम्नलिखित तालिका में वस्तुओं के वर्गीकरण का आधार भली भाँति प्रकट होता है —

विभाग	उपभोग का प्रभाव	उपभोग के प्रभाव का प्रमाण
अनिवार्य वस्तुएं	कार्य-कुशलता में पर्याप्त वृद्धि	कार्य-कुशलता में पर्याप्त ह्रास
सुख वस्तुएं	कार्य-कुशलता में मामूली वृद्धि	कार्य-कुशलता में भी कुछ ह्रास
विन्यास वस्तुएं	कार्य-कुशलता में शून्य वृद्धि	कार्य-कुशलता में कोई ह्रास नहीं

उपभोग का क्रम (Order of Consumption)—वस्तुओं के उपभोग के क्रम का कोई स्थिर नियम नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य सत्रस प्रथम अनिवार्य वस्तुओं पर व्यय करे फिर सुख वस्तुओं और अन्त में विन्यास वस्तुओं पर। यह भी उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव और इच्छा पर निर्भर है कि वह किस क्रम से वस्तुओं का उपभोग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय का अधिकतम भाग अनिवार्य आवश्यकताओं पर व्यय करेगा तत्पश्चात् सुख वस्तुओं पर अन्त में विन्यास वस्तुओं पर। वह अपनी परिमित आय का अधिकतम लाभ उठाया प्रचार प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इतना दूरदर्शी नहीं होता कि वह अनिवार्य का पूरा-पूरा ध्यान रख सके। वह तो खाद्य, पीय, और मोज उद्योगों में विश्वास करने वाले हूँ है या अपनी सारी आय वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय कर देते हैं। मनुष्य अज्ञानवश या पंचन के कथोभूत हाकिम अथवा सामाजिक स्थितियों के दबाव से इस क्रम के अनुसार नहीं चले। एक अधिव्रजन उत्तम भोजन या वस्त्र की शिक्षा की अपेक्षा कर भ्रान्त प्रमोद या विवाहोत्सव तथा मूर्ख गौरव में व्यय कर देता है। जो उपयुक्त उपभोग क्रम का पालन नहीं करते वे निश्चय रूप से नृपति तथा सुख के प्रभावों का अनुभव करते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भावश्यकताओं का वर्गीकरण कीजिए। क्या विभिन्न आवश्यकताएँ सापेक्षिक होती हैं? स्पष्ट कीजिए। (उ० प्र० १९५७)
- २—'भावश्यकताएँ पारस्परिक हैं।' इस सद्धर्म में आवश्यकताओं का वर्गीकरण करते हुए आप जो जानते हैं, लिखिए। (म० भा० १९५७)
- ३—क्या एक ही वस्तु जैसे मोटर-कार या फाउन्टेन-पैन निम्न भिन्न परिस्थितियों में अनिवार्य, सुखकर अथवा विलास की वस्तु समझी जा सकती है? विस्तारपूर्वक समझाकर लिखिए। (रा० बो० १९५८, उ० प्र० १९५२)
- ४—अनिवार्यताओं, सुविधाओं और विजामिताओं का अन्तर भारत के उदाहरण देकर समझाइए। (रा० बो० १९५६, ५३, ५१)
- ५—अनिवार्य, सुखकर तथा विलास की वस्तुओं का अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या कोई एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अनिवार्य, सुखकर अथवा विलास की वस्तु हो सकती है? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करिए। वर्गीकरण का आधार भी स्पष्टतया समझाइए। (रा० बो० १९५४)
- ६—अनिवार्यताएँ, सुखकर आवश्यकताएँ तथा विलासिताओं का अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या आर्थिक दृष्टि से विनासिताओं का उपभोग करना उचित है? (प्र० बो० १९५५)
- ७—अनिवार्य सुखकर तथा विनासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं का अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या वे सापेक्षिक हैं? उदाहरणों द्वारा समझाइए। (नागपुर १९५१)
- ८—'उपभोग का अनुक्रम (Order) नियम या नियन्त्रण का विषय नहीं है। वह निजी आदतें (Person Habits), व्यक्तिगत रस (Individual Taste) तथा इच्छाओं (Desires) का विषय है।'—समझाइए। (सागर १९५४)
- ९—अनिवार्य, सुखकर व विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर टिप्पणी लिखिए। (सागर १९५१)
- १०—आवश्यकताओं के अनिवार्य, सुखकर व विलासिता सम्बन्धी भेदों की व्याख्या कीजिए। (पञ्जाब १९५३)
- ११—आवश्यकताओं का वर्गीकरण कीजिए। रुढ़ आवश्यकताओं से क्या तात्पर्य है? (उत्कल १९५१)
- १२—अनिवार्य, सुखकर व विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए और इनके अन्तर को भारतीय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। (दिल्ली हा० से० १९४८)

उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility)

उपयोगिता (Utility) — किसी वस्तु की आवश्यकता पूरक शक्ति का नाम 'उपयोगिता' है। पुस्तक, मेज, अन्न, वस्त्र आदि वस्तुएँ 'उपयोगिता' रखती हैं, क्योंकि इनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति विद्यमान है।

उपयोगिता की विभिन्नता के कारण — उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर है। जिसकी अधिक तीव्रता किसी वस्तु की आवश्यकता में होगी उतनी ही अधिक तीव्र उस वस्तु की उपयोगिता होगी। किसी एक वस्तु की उपयोगिता सभी मनुष्यों को एक सी नहीं हो सकती। मनुष्यों के स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार उनमें भिन्नता आया करती है। एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। जैसे, शिक्षित मनुष्य के लिए पुस्तक की उपयोगिता है क्योंकि इससे उसकी पूर्ति होती है किन्तु उन्मी पुस्तक को अनपढ़ के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। प्यासे मनुष्य के लिए पानी की उपयोगिता है, परन्तु उस व्यक्ति के लिए जो प्यासा नहीं है, इसकी उपयोगिता नहीं।

उपयोगिता की माप और तुलना (Measurement and Comparison of Utility) — हम अपने साधारण जीवन में अनेक वस्तुओं की माप और तुलना करते हैं, जैसे कपड़ा गज में मापा जाता है, अन्न सक्-सेर में तोला जाता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का माप करने के लिए विविध-साधन देख जाते हैं। किन्तु 'उपयोगिता' को इस प्रकार मापने के लिए कोई 'माप-इकाई' नहीं है। उपयोगिता का माप प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि उपयोगिता इच्छा की पूर्ति रूप एक भावना मात्र है जिसका सम्बन्ध मनुष्य के मन से है। अस्तु, मानसिक भावनाओं और वृत्तियों का प्रत्यक्ष रूप में माप अथवा तुलना नहीं कर सकते।

उपयोगिता माप की रीतियाँ — जो कुछ भी उपयोगिता का माप सम्भव है वह परीक्षण या अप्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है। प्रायः इस प्रकार का माप दो प्रकार से किया जाता है — (अ) मुद्रा द्वारा और (ब) बाँकड़ों द्वारा।

(अ) मुद्रा द्वारा (By Money) — जो मूल्य किसी वस्तु या सेवा का कोई व्यक्ति देना चाहता है वह उसकी उपयोगिता का माप इष्ट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य ५ रु० देने के लिए राज़ है। वह ५ रु० देने को तभी उद्यत होगा जब उसके विचार में उस वस्तु की उपयोगिता ५ रु० के बराबर

होगी। इस प्रकार हम किसी मनुष्य की उपयोगिता का अनुमान मूल्य द्वारा लगा सकते हैं।

(ग) आंकड़े द्वारा (Numerically)—उपयोगिता का अनुमान आंकड़ों से भी हो सकता है। यदि हम कल्पना कर वि हमें पुस्तक और टोप दोनों की आवश्यकता है। तब सर्वप्रथम हम यह निर्णय कर लेंगे पटथा वि पुस्तक से प्राप्त होने वाली उपयोगिता X के बराबर है। इसे निर्णय करने के उपरान्त अन्य वस्तुओं की जितनी उपयोगिता है यह हम मानूँ कर सकते हैं। अब यदि एक पुस्तक का उपयोगिता टोप की उपयोगिता की अपेक्षा दुगुनी है, तो ऐसी घनस्था में हम उनकी उपयोगिता को आंकड़ों से (२ : १) अनुपात में रखकर एकट कर सकते हैं। प्रो० मार्शल कहते हैं वि “यदि कोई व्यक्ति कुछ पैसे व्यय करते समय इस विचार में होवे वि उसे वह पैसे सिगरेट पीने में या चाय का प्याला न पीकर घर पहुँच जाने के स्थान में लाने में जाने के लिए व्यय करना चाहिये, तो हम कहेंगे वि वह इन सब वस्तुओं में समान उपयोगिता रखता है” अस्तु इन सब वस्तुओं की उपयोगिता उनके लिए समान है।

उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility)

परिचय (Introduction)—मानवीय आवश्यकताएँ अनन्त होने हुए भी एक विशिष्ट समय में पूर्णतया सन्तुष्टि की जा सकती है। इस विसिद्धता पर ‘उपयोगिता ह्रास नियम’ प्रवृत्त है। इसको ‘सन्तुष्टि-योग्य नियम’ (Law of satiable want) भी कहते हैं। ‘उपयोगिता ह्रास नियम’ के शब्द स्वयं प्रथम अर्थ प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उसके अधिकतम परिमाण में प्राप्त होने पर कम होनी आगामी और घन में परिस्थिति के अपरिवर्तित होने पर पूरी हो जायगी।

जैसे एक मनुष्य प्यास है वह पानी पीता है। पानी का पहला गिलास उसके लिए अधिक उपयोगिता रखता है, परन्तु दूसरा गिलास उसकी उपयोगिता नहीं रखता, यद्यपि उसकी प्यास की तीव्रता पहला गिलास पीने के पश्चात् कुछ कम हो गई, और तीसरे गिलास की उपयोगिता उसके लिए बहुत ही कम होगी। नभवतः उसका यह उपभोग भी न करे। अस्तु, यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी वृद्धि के साथ क्रमशः कम होती जाती है और अन्त में वह नित्य ही कम हो जाती है। अतः इसी आधार पर यह उपभोग का सिद्धान्त ‘उपयोगिता ह्रास नियम’ कहा जाता है।

नियम का सैद्धान्तिक रूप (Enunciation of law)—प्रो० मार्शल की परिभाषा—“किसी मनुष्य ने प्राप्त किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने के जो अधिकतम लाभ उसको प्राप्त होता है, वह वस्तु की मात्रा की वृद्धि के साथ-साथ घटता जाता है।”

नियम के अन्य रूप

(१) कोई वस्तु जितनी अधिक प्राप्त की जाय, उसको अधिकता को उतनी ही कम आवश्यकता प्रतीत होती जाती है।

1—The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing, diminishes with every increase in the stock that he already has
—Marshall.

(The more we have a thing, the less we want still more of that thing.)

(२) किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ उसकी अतिरिक्त वृद्धि की उपयोगिता में ह्रास होता जाता है, यदि अन्य परिस्थितियाँ समान हों।

(With every increase of his stock of that commodity the additional unit of the commodity diminishes, other things being equal.)

(३) किसी विनिर्दिष्ट समय में एक मनुष्य के पास जो वस्तु है उसकी मात्रा में वृद्धि होने पर, अतिरिक्त इकाई की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, यदि अन्य परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहें।

(At any one time, every addition to the stock of a thing a man possesses, results in a decrease of the marginal utility of the thing other things remaining the same.)

व्याख्या (Explanation)—उपर्युक्त विविध परिभाषाओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य अपनी किसी वस्तु में वृद्धि करता है त्यों-त्यों उसकी बढ़ती हुई इकाई में कम लाभ प्राप्त होता है, अर्थात् उसकी उपयोगिता घटती जाती है। यह प्रवृत्ति अर्थशास्त्र में 'उपयोगिता-ह्रास-नियम' कहलाती है। इस प्रवृत्ति का अनुभव सब प्रकार की वस्तुओं के उपयोग में देखा जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी वस्तु में वे लाभ यह प्रवृत्ति सीमा नाश हो जाती है और किसी के साथ देर न। यह नियम मानव प्रवृत्ति के विरुद्ध अनुकूल मिट्ट होना है और इसी कारणता सर्वथा देखी जाती है।

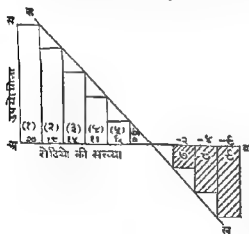
उदाहरण (Illustration)—इसे एक दुधा में घातुर व्यक्ति के उदाहरण से हम प्रकार समझेंगे। जब वह पहली रोटी खाता है, तो उस वहाँ धान्य प्राप्त होता है। उसकी तृप्ति या उपयोगिता मान लें २० है। अब, पहली रोटी की उपयोगिता अधिकतम है अर्थात् २० है। अब यदि वह दूसरी रोटी खा लेता है, तो उसकी दुधा की तीव्रता पहली रोटी की प्राप्ति की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है, अर्थात् दूसरी रोटी में उसकी तृप्ति या उपयोगिता १८ है। अब यदि वह तीसरी रोटी खा लेता है तो उसकी दुधा की तीव्रता दूसरी रोटी की प्राप्ति की अपेक्षा और भी कम हो जाती है। अब, तीसरी रोटी में १५ उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी रोटी की उपयोगिता उसके लिए दूसरी रोटी में भी कम हो जाती है। इसी प्रकार चौथी रोटी की इच्छा और भी कम हो जाती है। यदि हमने पाँचवीं और छठी रोटीयाँ और खाईं, तो उसकी उपयोगिता बहुत ही कम हो जाती है, यहाँ तक कि छठी रोटी की उपयोगिता शून्य (०) हो जाती है। पाँच रोटीयाँ तक उसकी दुधा विरुद्ध शान्त हो जाती है, अब छठी रोटी पर वह विचार करेगा कि उसे इसका उपयोग अभीष्ट है या नहीं, क्योंकि उसकी उपयोगिता उसके लिए तब तक भी नहीं है। उसे पाँचवीं रोटी के पश्चात् छठी रोटीयाँ का उपयोग बन्द कर देना चाहिए। यदि वह फिर भी रोटीयाँ खाता जारी रखता है, तो उपयोगिता के स्थान में 'अनुपयोगिता' (Disutility) प्रारम्भ हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट में कहा जा सकता है कि प्रत्येक

विवेकीय व्यक्ति का किसी वस्तु का उपभोग उसकी उपयोगिता तक ही सीमित रहता है। क्योंकि उसमें उपयोगिता का अभाव हुआ, क्योंकि वह उसके उपयोग को प्रायः समाप्त कर देता है।

नियम का सांख्यिकीकरण (Arithmetical Representation of Law)—उपयुक्त उदाहरण को निम्नलिखित सारणी में इस प्रकार समझिए :—

रोटियों की संख्या (No. of Breads)	सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)	समस्त उपयोगिता (Total Utility)
१	२०	२०
२	१५	$२० + १५ = ३५$
३	१५	$२० + १५ + १५ = ५०$
४	११	$२० + १५ + १५ + ११ = ६१$
५	६	$२० + १५ + १५ + ११ + ६ = ७०$
६	०	$२० + १५ + १५ + ११ + ६ + ० = ७०$
७	-२	-२ अनुपयोगिता (Disutility)
८	-४	$-२ - ४ = -६$
९	-६	$-२ - ४ - ६ = -१२$

नियम का रेखा-चित्रण (Graphical Representation of the Law)—उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि ज्यों-ज्यों रोटियों के उपभोग में वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों रोटियों की उपयोगिता कम होती गई है। यह तथ्य नीचे के रेखा-चित्र से भली-भांति समझाया गया है :—



उपयोगिता ह्रास नियम
(Law of Diminishing Utility)

चित्र का स्पष्टीकरण—उपरोक्त उदाहरण में भावी रेखा अथवा रोटियों की संख्या और अन्त उपयोगिता प्रकट करती है। जब धनानुर व्यक्ति पहली रोटि खाता है तो उसकी उपयोगिता अधिकतम है, क्योंकि उसकी रोटि की इच्छा प्रबल है। समझने की सुविधा की दृष्टि से यह उपयोगिता मनु २० में प्रकट की गई है। ऊपर के चित्र में भागत (१) खलता है। जब वह दूसरी रोटि लेता है, तो उसे उसकी उपयोगिता पहली

रोटी से कम प्राप्त होती है। यह अनु १८ से आयत (२) में प्रकट है। इस प्रकार भागे की सब रोटियों की उपयोगिता क्रमशः अंक १२, ११ और ९ से प्रदर्शित की गई है। दूसरी आयत (३), (४) और (५) बतते हैं। छठवीं रोटी से कोई उपयोगिता प्राप्त न होने के कारण शून्य (०) में प्रकट की गई है। सातवीं, आठवीं और नववीं रोटियों में अनुपयोगिता (Disutility) - २, -४, -६ अंकों के रूप में छायादार (Shaded) आयतों में प्रकट है। कस वक्र रेखा उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) का प्रदर्शन करती है।

उपयोगिता ह्रास नियम के अन्तर्गत मान्यताएँ

(Assumptions underlying the Law of Diminishing Utility)

अन्य वस्तुएँ समान हों अर्थात् परिस्थिति का पूर्ववत् होना (Other thing remaining the same) - ये शब्द नियम को न्यायक बनाने के लिए बड़ा महत्त्व रखते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। यदि उनमें कुछ परिवर्तन हो जाय तो इस नियम की वृथापता मिट जाने में आसानी उत्पन्न हो जाती है। ये बातें निम्नांकित हैं -

(१) वस्तु की सब इकाइयों की मात्रा और प्रकार समान होना चाहिये—उपभोग में साईं जेने वाली वस्तु की इकाई वही हो और उतनी ही होनी चाहिये जितनी कि पहले की। उदाहरणार्थ, यदि बाद की रोटीयाँ अधिक उत्तम और भारी हों तो उपभोक्ता को पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होने के कारण इन नियम की व्यापकता नष्ट हो जायगी।

(२) उपभोग के समय में अन्तर नही होना चाहिये—यदि वस्तु के उपभोग का समय लगातार नहो अर्थात् बीच में कुछ समय बीत जाय, तो यह नियम प्रभाव शून्य हो जाता है। दोनों समय पूर्वक-पूर्वक भोजन करने पर यह नियम प्रत्येक बार लागू होगा, परन्तु भोजन करते समय सब रोटियाँ एक साथ खाने में, बाद वाली रोटीयों की उपयोगिता पहले की अपेक्षा गिरती जायगी। यदि उनमें कुछ रोटीयाँ खाकर बीच में कुछ समय बिता दिया तो बाद वाली रोटीयों की उपयोगिता प्रारम्भ में घटने के स्थान पर बढ़ेगी। यदि कोई अनुप्य एवं घाम प्राप्त कान खावे, दूसरा मध्याह्न में, तीसरा सायंभान की ओर बीयां रात्रि की, तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे आभ्रान से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता पहले की अपेक्षा तीसरे में प्राप्त होने वाली उपयोगिता दूसरे से और चौथे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तीसरे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से कमदा कम हो, क्योंकि चारों भागों के खाने में इतना समय का अन्तर पड़ गया है कि 'ह्रास नियम' लागू न होगा। यह नियम एक ही सायंभान कर खाने या पीने या अन्य आवश्यकताओं को तृप्त करने में लागू होता है अन्यथा नहीं।

(३) उपभोक्ता का मानसिक दृष्टिकोण (Mental outlook) समान हो—यदि उपभोक्ता ने भाग आदि सादक वस्तु का प्रयोग किया है, तो वह उस रोटी को भी खाने की इच्छा कर सकता है जिसकी उपयोगिता शून्य है, क्योंकि सादक वस्तु से दुष्टि की सीमा का पूर्ण अनुभव नहीं होता किन्तु आवश्यकता से अधिक खाने की प्रवृत्ति हो जाती है। रात्रि में यदि भद हो जाय तो भी यह नियम (ह्रास नियम) चरितार्थ न होगा, क्योंकि इस परिवर्तन के कारण वस्तु के उपभोग से होने वाले सतोष और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता में अन्तर पड़ जायगा।

(४) यदि उपयोग का समय लम्बा हो तो फंशन, प्रकृति और आय पूर्ववत् ही रहना चाहिये—निस्संशय वस्तुओं के उपयोग में फंशन, प्रकृति और आय के परिवर्तन से नियम में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। यदि कोई विशेष प्रकार की कमीज फंशन में नहीं हो, तो उसकी उपयोगिता कम हो जायेगी। यदि वह कुछ समय बाद पुनः फंशन में आ जाय तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जायेगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की सिगरेट पीने की प्रकृति नहीं है तो उसके लिए उसकी उपयोगिता कम होगी, परन्तु यदि कभी वह उसका व्यसन हो जाता है, तो उसकी उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए बढ़ जायेगी। यदि कोई व्यक्ति सहसा धनार्थ हो जाता है, तो उत्स्विक्रित भाव भी बढ़ जायेगी। एक ही वस्तु की परचाल प्राप्त होने वाली उपयोगिताएँ ही न रह जायेंगी जो उसके धनवान् होने के पूर्व प्रतीत होती थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय १०० रु० से ३०० रु० हो जाय तो वह उन वस्तुओं को भी अधिक मात्रा में खरीद लेता है जिनका पर्याप्त स्टॉक पहले ही में उसके पास है।

(५) वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए—यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है, तो लोग उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने लग जायेंगे, यद्यपि उनके पास उस वस्तु का पर्याप्त स्टॉक हो। इस प्रकार उस वस्तु की माद की इनादों की उपयोगिता घटने के स्थान में बढ़ने लग जाती है।

उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाएँ

(Limitations of the Law Diminishing Utility)

उपयोगिता ह्रास नियम के कतिपय अणवाद हैं जो प्रवास्तविक (Apparent) और वास्तविक (Real) दो भागों में बाँटे जा सकते हैं। ये प्रवास्तविक हैं—

अप्रवास्तविक (Apparent)

(१) मुद्रा-शक्ति और प्रदर्शनप्रियता (Love of Money Power and Display)—उपयुक्त बातों में प्रभावित मनुष्य के लिए प्रत्येक प्रतिरिक्त इकाई की उपयोगिता बढ़ती जायेगी। उदाहरण के लिए, कुरल की मुद्रा की प्रत्येक प्रतिरिक्त इकाई की अधिक उपयोगिता प्रतीत होती है, क्योंकि उसका अधिक 'मुद्रा शक्ति' में ध्यानस्थ मिलता है। यही वही उन व्यक्तियों की है जो शक्ति और प्रदर्शन प्रियता में प्रेरित होकर निरन्तर सतिनयन तथा प्रदर्शनीय वस्तुओं के संग्रह में लग रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक मुद्राप्रति हो तो वह उसकी जोड़ी के दूसरे मोती का मूल्य घटने की अपेक्षा अधिक ध्यान देने को उद्यत हो जायेगा। कारण यह है कि दूसरे मोती की प्राप्ति में उसकी अधिक तृप्ति प्रतीत होती है क्योंकि समान प्रकार और कालि वस्त्र दो मुद्राप्रति देने में उसकी प्रतीति बहुत बढ़ जायेगी। यह अणवाद 'अप्रवास्तविक' (Apparent or Unreal) है, क्योंकि इन व्यक्तियों की वस्तुता जन-साधारण में नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना उचित है कि किसी वस्तु के संग्रह की प्रति भी विरक्ति का कारण बन जाती है। सुवर्ण के प्रति सुवर्ण राजा मिश्राम—इस तथ्य का सुन्दर निदर्शन है। वह स्वर्ण खनन पीछे पापन था पर उन अधिक मात्रा सुवर्ण की उने मिली, तो वह छोड़ ही दत्त का गया और उसकी उपयोगिता सुवर्ण के लिए मूल्य-ही हो गयी।

(२) विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह (Collection of curious and rare things)—यह नियम पायः विचित्र और दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति पर लागू नहीं होता, क्योंकि इन वस्तुओं के संग्रहकर्ता को अधिक आनन्द प्राप्त होता है। जैसे, पुराने टिकट और मिके के संग्रहकर्ता के लिए वाद वाली इकाइयों की अधिक उपयोगिता होती है। अतः वह निरन्तर इन्हीं के संग्रह में प्रयत्नशील रहता है। यह अपवाद अवास्तविक प्रतीत होता है। यदि कोई वस्तु दो-तीन वस्तुओं से मिलकर बनती है, तो सब वस्तुएँ उसी का ही अंग मानी जानी चाहिए। जैसे एक अण्डा में दो मोती हैं और वे दोनों मिलकर एक ही वस्तु में प्रतीक हैं। यदि एक ही वस्तु के कई अंग हों और एक को उपयोगिता दूसरे की अपेक्षा अधिक हो, तो इससे नियम की सत्यता में तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता।

(३) इकाइयों की अति-लघुता (Very small units)—यदि उपयोग्य वस्तु कम माना में ली जाय तो निस्संदेह अनिश्चित इकाइयों में अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, यदि एक प्याले व्यक्ति को कुछ देर तक पीने-पूँद पानी दिया जाय, तो प्रत्येक अनिश्चित पानी की बूँद की इच्छा अधिक प्रबल रहेगी जिसके फलस्वरूप उसकी उपयोगिता भी बढ़नी जायगी।

(४) प्रतिकूल मानसिक अवस्था के व्यक्ति (Persons in abnormal state of mind)—ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रत्येक अनिश्चित इकाई की अधिक उपयोगिता होती है। उदाहरणार्थ, एक मदिरा-व्यसनी व्यक्ति एक बोतल मदिरा की बूकने के पश्चात् दूसरी बोतल की इच्छा करता है क्योंकि दूसरी बोतल पहली बोतल की अपेक्षा उसके लिए अधिक उपयोगिता रखती है। यह अपवाद भी कारणों में अपवाद समझा गया है : प्रथम तो ऐसे मदीमत्त व्यक्ति अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र की सामग्री नहीं है। दूसरे अन्ततोगत्वा (Ultimately) यह नियम लागू हो जाता है, क्योंकि वह एक के पश्चात् दूसरी बोतल लेने में असमर्थ हो जाता है।

(५) सुविधाओं का विस्तार (Extension of Facilities)—जिनसे सम्बन्धों तथा यातायात और संचार के साधन की वृद्धि में उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुँचता है जिनके फलस्वरूप इन वस्तुओं की जितनी अधिक विस्तार होगा उतनी अधिक उपयोगिता बढ़ेगी। जैसे मगर में पहलू की अपेक्षा अब टेलीफोन सम्बन्धों में वृद्धि हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए, जिसके पास पहले से ही टेलीफोन है, अधिक उपयोगिता हो जायगी, क्योंकि वह अब पहले की अपेक्षा कई एक व्यक्तियों से टेलीफोन पर वार्तालाप कर सकता है। 'उपयोगिता ह्रास नियम' इस बात पर बल देता है कि वस्तुओं की वृद्धि उसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए न कि दूसरे-दूसरे व्यक्तियों के पास। इस उदाहरण में अनिश्चित इकाई का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि टेलीफोन का विस्तार कई व्यक्तियों में हुआ है। अतः यह अपवाद भी अतत्त्व सिद्ध होता है। परन्तु यदि एक ही व्यक्ति अपने घर या दुकान में एक से अधिक टेलीफोन लेता है तो निश्चय रूप से अनिश्चित सम्बन्धों की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम हो जाती है।

निष्कर्ष—इन अनेक सीमाओं के होने भी यह नियम लक्ष्मण व्यापकता रखता है। प्रो० टॉसिंग के अनुसार "उपयोगिता ह्रास नियम की प्रवृत्ति इनमें कम अपवादों में साथ इसकी निस्तृत प्रतीत होती है कि इसे 'सार्वदेशिक' कहने में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं।"

वास्तविक अपवाद (Real Exceptions)

(१) रसीली कविता या मधुर गायन—प्रो० टासिग कहते हैं कि 'किंगी रसीली कविता के दुबारा और विवाग पठने या किसी मधुर गायन के दुबारा या विवाग सुनने से पहली बार की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। दैनिक जीवन में इस प्रकार के अनुभव अत्यन्त ही होते रहते हैं। अस्तु यह एक वास्तविक अपवाद माना जाता है। परन्तु इस अपवाद में भी सीमा या देग में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब कि बार-बार कविता पठने या गायन-श्रवण से आनन्द प्राप्त नहीं होता अर्थात् उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है क्योंकि श्रवण उक्ति के सीमित होने से उत्तम प्रकार का हो जाना स्वाभाविक है और जिसकी पुनः प्राप्ति में पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

(२) तृप्ति की अधिकतम अवस्था (Point of optimum satisfaction)—कतिपय अर्थशास्त्रियों का विचार है कि किसी वस्तु के उपभोग की प्रारम्भिक प्रवृत्ति में तो प्रत्येक क्रमानुगत (Successive) इकाई में अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। केवल उपभोग किसी विशेष अवस्था पर पहुँचने के पश्चात् ही अर्थात् तृप्ति की अधिकतम अवस्था (Point of optimum Satisfaction) के प्राप्त हो जाने पर उपयोगिता में ह्रास होगा प्रारम्भ होगा। असीमित वस्तु के निकट आ जाने से मुक्त भावगमन भी जाग्रत हो जाती है। इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को प्यास की वेदना नहीं है। किन्तु मधुर नारंगी की एक फाक मुँह में रखने की तो बात क्या किमी गतिबद्ध व्यक्ति के उभे घूमने पर सहसा मुँह में पानी आ जाता है और नारंगी खाने की इच्छा हो उठती है। यदि इसी प्रकार नारंगी की एक फाक क्रमानुगत इकाइयाँ में ली जाय तो प्रारम्भ की इकाइयाँ की उपयोगिता में वृद्धि होगी, और यह एक 'मादरा अधिकतम तृप्ति अवस्था तक पहुँचने की ओर इसके पश्चात् उपयोगिता में ह्रास होना प्रारम्भ होगा। यदि इस मनोवैज्ञानिक मान्यता को यथाथ माना जाय, तो इसे भी वास्तविक अपवाद मानते हैं कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस तक के बंध में यथाथ प्रमाण न होने से इस कथन की सत्यता निश्चय पूर्वक घोषित नहीं की जा सकती।

उपपुक्त अपवादों का निराकरण करने के लिए उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा को निम्न प्रकार संशोधित किया जा सकता है —

“उपभोग को विशेष अवस्था पर पहुँचने के पश्चात्—अन्य वस्तुओं के समान रहने पर किसी वस्तु के उपभोग की क्रमानुगत इकाइयाँ में उपयोगिता का ह्रास होता जाता है।”

(After a certain stage in consumption is reached each successive unit gives diminishing utility, other things remaining the same)

सीमान्त और समस्त उपयोगिता (Marginal and Total utility)

सीमान्त उपयोगिता (Marginal utility)—किसी वस्तु के क्रमानुगत तथा निरन्तर उपभोग के कारण उसकी अन्तिम इकाई की उपयोगिता को 'सीमान्त उपयोगिता' कहते हैं। अन्य शब्दों में यह वह उपयोगिता है जो किसी वस्तु की उस इकाई में प्राप्त होती है जिसे उपभोक्ता उपभोग से लाने के लिए आकृष्ट होता है।

प्रो० मार्शल के अनुसार "किसी वस्तु का वह भाग जिसको खरीदने के लिए उपभोक्ता दाय्य है, वह 'सीमान्त द्रव्य' (Marginal Purchase) कहलाता है, क्योंकि वह उसकी उपयोगिता न्यूनतम हो जाने के कारण इस दृष्टि में पड़ जाता है कि उसे प्रय खरीदने के लिये व्यय करना उचित है या नहीं।" इस 'सीमान्त प्रय' की उपयोगिता को 'सीमान्त उपयोगिता' (Marginal Utility) कहते हैं।

प्रो० बेनहम (Benham)—'सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम' (Law of Diminishing Marginal Utility) के नाम से सम्बंधित करते हैं। यह नियम सीमान्त उपयोगिता की दृष्टि से निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है— "किसी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता उस वस्तु की मात्रा को वृद्धि के साथ घटती जाती है।" सीमान्त उपयोगिता का भाव केवल एक ही वस्तु के उपभोग से प्रकट नहीं होता। जब एक वस्तु अधिकधिक मात्रा में प्रयुक्त की जाती है तब अन्तिम वस्तु की उपयोगिता से ही इसका यथार्थ धर्म प्रकट होता है।

उदाहरण—मान लीजिये कि कोई व्यक्ति कुछ सेब (Apples) खरीदता है। उनकी उपयोगिता भी-से-से हुई तालिका में दिखाई गई है :—

सेब	सीमान्त उपयोगिता (इकाई)
१	१०
२	८
३	६
४	४
५	२
६	१
७	०
८	-२

अनुवृत्त सीमान्त उपयोगिता
 (Positive Utility)
 "शून्य उपयोगिता (Zero Utility)
 "प्रतिवृत्त उपयोगिता (Negative Utility)

ऊपर के उदाहरण में ज्यों-ज्यों सेब की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों सीमान्त उपयोगिता में ह्रास देखा जाता है। वह अधिक ग अधिक पाच सेब खरीदेगा। छठे सेब की उपयोगिता शून्य होने में वह उसे खरीदना उचित नहीं समझता। पाँचवें सेब के पश्चात् वह इस क्षण में ठूलने लगता है कि छठा सेब खरीदा जाय या नहीं। यदि वह वृद्धि में काम लेता है, तो पाँचवें सेब के बाद ही उसको खरीदना बन्द कर देना चाहिये। पाँचवें सेब की उपयोगिता 'सीमान्त उपयोगिता' कहलायेगी।

मूल्य और सीमान्त उपयोगिता (Price and Marginal Utility)

हमारा उपर्युक्त उपभोक्ता वहीं ठहरेगा, यह सेब के मूल्य पर निर्भर है। यदि प्रति सेब का मूल्य ४ आना है, तो वह चौथी सेब के पश्चात् ही रुक जावेगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता उतनी ही है जितना कि मूल्य (सीमान्त उपयोगिता की मात्रा की इकाई) में मान दिया गया है। यदि प्रति सेब का मूल्य १ आना है तो वह छठे

सेव तक खरीद कर सनेगा । यदि वे नि शुल्क उपेक्षण्य हैं तो वह आठो सेवो को उपभोग में ला सकेगा । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग उस बिन्दु तक जारी रखता है जहाँ मूल्य और उपयोगिता समान होती है ।

उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदते समय भी सीमान्त-उपयोगिता से सहामन्य प्राप्त करता है । यदि सब सेव सब प्रकार से समान हैं, तो वह पहले सेव के १० आने, दूसरे के ३ आने, तीसरे के ६ आने, चौथे के ४ आने और पाँचवें के २ आने नहीं देगा । वह प्रतिम सेव की उपयोगिता के बराबर सब सेवों का मूल्य देगा, अर्थात् इन सब सेवों का मूल्य १ आने के हिसाब से देगा । कारण स्पष्ट है कि यह सब सेव आकार, प्रकार, स्वाद तथा रस प्रादि बातों में समानता रखते हैं । अतः इनके मूल्य में इस प्रकार भिन्नता नहीं हो सकती । अस्तु, यह निष्कर्ष निकलता कि किसी वस्तु की प्रतिम इकाई की उपयोगिता ही उपभोक्ता को उस वस्तु का मूल्य देने में मार्ग प्रदर्शन करती है । वह हमसे अधिक कदापि नहीं देगा, क्योंकि उसने अधिक इकाई की उसके लिए कोई उपयोगिता ही नहीं होती ।

रुपये की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility of Money)—भाय की वृद्धि से उपयोगिता में ह्रास होता तथा भाय में ह्रास होने से सीमान्त उपयोगिता में वृद्धि होता, यह भी एक स्थान में रखने योग्य बात है । किसी व्यक्ति के पास जैसे जैसे सम्पत्ति बढ़ती जाती है उसे-उसके सीमान्त उपयोगिता कम होती जायगी । यदि किसी मनुष्य की भाय ७० ६० मासिक से १५० ६० मासिक हो जाय तो उसके लिए इस वित्त-वृद्धि के पूर्व प्रतिम रुपये की जो उपयोगिता थी उस उसकी अपेक्षा उस उपयोगिता में ह्रास या न्यूनता दिखाई देने लगेगी । इस तथ्य की प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात से मिल जायगा कि ७० ६० मासिक भाय में वह अनिवार्य आवश्यकताओं और विवासाया (पाव, सुगरी, रेशमी वस्त्र, रेडियो आदि) में जो व्यय करता था अब १५० ६० प्राप्त करने पर बंद जायगा । वह उसी मूल्य में उन वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदने लगेगा । अतः निश्चय है कि भाय बढ़ने पर व्यक्ति के लिए रुपये की सीमान्त उपयोगिता कम हो जाती है । इसके विपरीत भाय में न्यूनता हो जाने पर रुपये की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है यदि किसी को १५० ६० के स्थान में ७० ६० मासिक मिलने लगे, तो वह उपभोग की अनेक वस्तुओं में बर्बाद कर देगा ।

अनुकूल, शून्य और प्रतिकूल सीमान्त उपयोगिताएँ (Positive-Zero and Negative Marginal Utility)—यदि सीमान्त इकाई के उपभोग से ह्रास या सतोष प्राप्त होता है तो वह सीमान्त उपयोगिता अनुकूल (Positive) होती है । जैसे ऊपर की तालिका में १ से ६ तक की सब की सीमान्त उपयोगिता अनुकूल है । यदि सीमान्त उपयोगिता के उपभोग में न तो गन्तीय प्राप्त होता हो और न ह्रासलोप ही, तो सीमान्त उपयोगिता शून्य (Zero) होती है । जैसे ऊपर की तालिका में ७ वें सेव की उपयोगिता शून्य है । जब उपभोग इस सीमा पर पहुँच जाय कि सीमान्त उपयोगिता शून्य हो, तो इस सीमा को 'पूर्ण-वृत्ति' (Satety) को मोटा कहते हैं । यदि सीमान्त उपयोगिता के उपभोग में असतोष या अनुपयोगिता (Disability) होती है, तो सीमान्त उपयोगिता प्रतिकूल (Negative) समझी जायगी । ऊपर के उदाहरण में ८ वें सेव इस अवस्था का सूचक है ।

साधारणतया ऐसी अवस्था बहुत ही कम पाई जाती है कि मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपनी मरणा के करीब नि 'मृत्यु' हो जाय, और मरने तक कि अनुपयोगिता में परिणत हो जाय, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने मृत्यु को किसी एक वस्तु पर अपना ही ध्यान करेगा जिससे उसकी उपयोगिता होगी। यदि कोई वस्तु नि शुल्क प्राप्त होती है, तो वह सीमान्त उपयोगिता होने पर भी उपयोग करता रहेगा और यदि स्वास्थ का विचार न करे तो सम्भवतः, इसके पश्चात् भी उपयोग करे जिसे उपयोगिता न करके हम अनुपयोगिता कहेंगे।

समस्त उपयोगिता (Total Utility)

किसी वस्तु का सारा दशावस्था की सीमान्त उपयोगिता (या के योग) को 'समस्त उपयोगिता' कहते हैं। कोई व्यक्ति १ दर्जन वस्तुओं को खरीदता है उसकी कारखाना वस्तुओं में जो उपयोगिता उस व्यक्ति को मिलती उसे हम 'समस्त उपयोगिता' कहेंगे।

ऊपर के उदाहरण का लक्ष्य यह है कि हम समस्त उपयोगिता का मापन करना चाहें, ता किन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिये :—

मैप (Apples)	सीमान्त उपयोगिता (इकाइयाँ)	समस्त उपयोगिता (इकाइयाँ)
१	१०	१०
२	८	१० + ८ = १८
३	६	१० + ८ + ६ = २४
४	४	१० + ८ + ६ + ४ = ३०
५	२	१० + ८ + ६ + ४ + २ = ३०
६	१	१० + ८ + ६ + ४ + २ + १ = ३१
७	०	१० + ८ + ६ + ४ + २ + १ + ० = ३१
८	-२	१० + ८ + ६ + ४ + २ + १ + ० - २ = २९

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जैम-जैम वस्तु के परिमाण में वृद्धि होती जाती है, पूर्ण तृप्ति की सीमा तक—मृत्यु-उपयोगिता पहुँचने तक—समस्त उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। परन्तु यह समस्त उपयोगिता की वृद्धि क्रमागत रूप से होती है, दूसरे शब्दों में पञ्चान्न प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की इकाइयों अनुपात से कम होती जाती हैं। इसका कारण यह है कि पूर्ण तृप्ति के पश्चात् भी इकाई नेत्रण की जायगी उसमें मरणा के स्थान में वेदना, हानि या अन्याय होगा, जो पूर्णतः तृप्ति में से वृद्ध ले लेता। जब यह होता है कि पूर्ण तृप्ति के बाद भी इकाइयों नेत्रण की जायगी उसका कारण सीमान्त उपयोगिता ऋण (-) में विभाजित जायेगी, और समस्त उपयोगिता बढ़ने के स्थान में घटती ही जायेगी। ऊपर के उदाहरण में यह स्पष्ट है कि जब सीमान्त उपयोगिता शून्य है, तो समस्त उपयोगिता ३१ है। इसके उपरान्त समस्त उपयोगिता में ह्रास होता है, अर्थात् साठवें मैप पर समस्त उपयोगिता नेत्रण २९ हो रह जाती है। अतः पूर्ण तृप्ति बिन्दु के पश्चात् उपयोगिता गिरती जाती है। सारांश—सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, और समस्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस प्रकार जब सीमान्त उपयोगिता अधिकतम या शून्य हो, तो समस्त उपयोगिता अधिकतम हो जाती है।

सीमान्त और समस्त उपयोगिता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है ?

व्यावहारिक जीवन में समस्त उपयोगिता की अपेक्षा सीमान्त उपयोगिता अधिक महत्व रखती है। समस्त उपयोगिता की तो उपेक्षा की जा सकती है पर सीमान्त उपयोगिता के बिना कुछ भी काम नहीं चलता। सीमान्त उपयोगिता मूल्य निर्धारण में मार्ग प्रदर्शन करती है। समस्त उपयोगिता में मूल्य का कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह सीमान्त उपयोगिता ही है जो मूल्य का मापदण्ड है। यदि ऐसा न हो तो जल का मूल्य सोन के मूल्य से बही अधिक होना।

उपयोगिता द्वारा नियम का व्यावहारिक महत्व

(Practical Importance of the Law of Diminishing Utility)

(१) माँग का नियम (Law of Demand)—पराश या अवरोध रूप में यह नियम हम पर निर्भर है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो हम उसका अधिक मात्रा में खरीदने के लिए तैयार होते हैं।

(२) सीमित साधनों का उपयोग (Utilization of scarce means)—हम अपना सीमित प्राय का सर्व प्रथम उन वस्तुओं के लिये देने में तैयार रहते हैं जिनकी उपयोगिता हमारे लिये अधिकतम है। जैसे अनिवार्य आवश्यकताएँ (Necessaries) सर्व प्रथम समुष्ट की जायेंगी उसके बाद सुखकर आवश्यकताएँ (Comforts) और तदनन्तर विलासिताएँ (Luxuries)। मान लिया जाय कि एक साधारण व्यक्ति को ११ रु० अन्न, वस्त्र, घी, फल, दुध, वेप, पदार्थ आदि में व्यय करने हैं। वह सर्वप्रथम प्रत्येक आवश्यकता की सीमान्त उपयोगिता तथा समस्त उपयोगिता की तुलना परस्पर तीर पर करेगा तत्पश्चात् वह उन्हें अनुपात से उनका खपता लगावेगा।

(३) प्रतिस्थापन नियम (Principle of substitution)—यह नियम भी इससे बड़ी सहायता प्राप्त करता है। हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः नूतन उपयोगी वस्तुओं को अधिक उपयोगी वस्तुओं से बदलते हैं। जितना रोबन या उपयोग प्रयत्न वस्तु से कम उपयोगिता प्राप्त होगी उतने स्थान पर ऐसे लेवत, उपयोग या वस्तु का प्रयोग हो, जिसकी अधिक उपयोगिता हो।

(४) कर नियम व व्यवहार का आधार (Basis of Principle and Practice of Taxation)—प्रगतिशील वर प्रणाली (Progressive System of Taxation) का नियम इसी आधार पर आधारित है। उदाहरणार्थ, धनी व्यक्तियों पर उनकी आय के अनुपात में आय-कर लगा कर उन पर अधिक वर भार रखना इस नियम का व्यावहारिक प्रयोग है।

(५) मुद्रा पर नियम का प्रभाव (Money and the Law)—उपयोगिता द्वारा नियम अन्य वस्तुओं की भाँति मुद्रा पर भी लागू होता है। यदि एक धनी व्यक्ति को आय में से १०० रु० ले लिये जायें तो वेदना कुछ विलासिताओं का ही उपयोग कम होवेगा, परन्तु एक निर्धन व्यक्ति को आय में से १ रु० भी निवाहना बड़ा भारी होगा, क्योंकि इससे कुछ अनिवार्य वस्तुओं का खर्च हो जावेगा।

(६) आय का उत्तम वितरण (Better Distribution of Income)—आय के उत्तम वितरण की दृष्टि से भी यह नियम लाभदायक सिद्ध

होता है। उपयोगिता ह्याम नियम के अनुसार अमुक मुद्रा आय एक अमीर के लिये तनिक उपयोगिता रखती है। पर वही आय एक गरीब के लिए पर्याप्त उपयोगिता रखती है। अमीर १ रु० से सिनेमा देखेगा, परन्तु एक गरीब उससे साध सामग्री खरीदेगा। अस्तु, आय का उत्तम वितरण अमीरों से गरीबों को देश की समस्त आय में तो वृद्धि नहीं करेगा, परन्तु समस्त समृद्धि (Total welfare) में अवश्य वृद्धि करेगा; क्योंकि उससे गरीब अमीरों की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त करेंगे और वे अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकेंगे।

अभ्यासाय प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—'जब सीमान्त उपयोगिता धून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है।'

इस वचन को समझाइए तथा बोप्टक धोर चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए।

(उ० प्र० १९६०)

२—समान्त उपयोगिता ह्याम नियम लिखिए और इसकी पूर्णतया व्याख्या कीजिए।

सीमान्त उपयोगिता का अन्तर बताइए। (सागर १९१७; उ० प्र० १९५५)

३—किसी वस्तु की प्रारम्भिक, सीमान्त और समस्त उपयोगिता में भेद बताइए।

(अ० बो० १९२३)

४—समान्त उपयोगिता ह्याम नियम समझाइए और इसकी सीमाएँ बताइए।

(प्र० बो० १९१९)

५—उपयोगिता का अभिप्राय समझाइए। सीमान्त उपयोगिता के सम्यक् घटने के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 'अन्य बातें समान रहने पर' (Other things being equal) वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? वे बातें कौनसी हैं? (उ० प्र० १९४९)

६—उपयोगिता ह्याम नियम की व्याख्या कीजिए। इसकी मर्यादाएँ क्या हैं?

(सागर १९१०; रा० बो० १९५२; पटना १९४९)

७—उपयोगिता ह्याम नियम की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। इसके अपवादों पर विचार कीजिए। (रा० बो० १९४९, पटना १९४५, नागपुर १९५२, ५०)

८—'हमें किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्राएँ प्राप्त होनी जाती हैं, उसकी प्रतिरिक्त मात्राएँ प्राप्त करने की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है।'—इस वचन को स्पष्ट कीजिए। (म० गा० १९५६, अ० बो० १९३५)

९—उपयोगिता-ह्याम-नियम की व्याख्या कीजिए। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए इसका व्यवहारिक महत्त्व क्या है?

(रा० बो० १९५८)

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility)

परिचय (Introduction)

इस सतार मे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाओं को इस प्रकार नियमित करने का प्रयत्न करता है जिससे उसे न्यूनतम वेदना, असुविधा और व्यय के साथ अधिकतम हतोप प्राप्त हो। उसकी एक मान इच्छा यह रहती है कि किस प्रकार उसे अधिकतम प्रसन्नता होवे। यूनानी लोग इसे अधिकतम आनन्द का सिद्धान्त (Hedonic Principle) कहते हैं।

संतुष्टि की मात्रा सीमित होती है और उसकी आवश्यकताएँ श्रमक्ष्य होती हैं। अतः उसकी मात्रा कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होती है। उसकी समस्त आवश्यकताएँ उस सीमित मात्रा से पूर्ण नहीं होती। अस्तु वह स्वाभाविक रूप से इस बात में प्रवृत्त होता है कि किस प्रकार वह उसे व्यय करे जिससे उसे अधिकतम तृप्ति हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वह वस्तुओं को उपयोगिता की दृष्टि से जमाकर अपनी मात्रा को व्यय करता है, अर्थात् सबसे प्रथम अनिवार्य वस्तुओं पर व्यय करता है, तत्पश्चात् सुख और विलास वस्तुओं पर। यदि वह इस श्रम से अपनी मात्रा को व्यय करता है, तो अन्त में वह इस बात का अनुभव करता है कि मुद्रा की अन्तिम इकाई की उपयोगिता सब वस्तुओं पर लगभग समान है। इस व्यवस्था को सम-सीमान्त उपयोगिता (Law of Equi-marginal Utility) कहते हैं।

नियम का सौदन्तिक रूप (Enunciation of the Law)—सम सीमांत नियम निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: "दी हुई राशि में अधिकतम तृप्ति की जा सकती है यदि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई राशि की अन्तिम इकाई की उपयोगिता लगभग समान हो।"

(Maximum satisfaction out of expenditure of a given sum can be obtained, if the utility derived from the last unit of money spent on each object of expenditure is more or less the same)

व्याख्या (Explanation)—उपर्युक्त नियम इस बात की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार हम अपनी मात्रा को विविध वस्तुओं पर व्यय करें जिससे प्रत्येक व्यय की हुई मुद्रा की इकाई से अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसकी यों भी कहा जा सकता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किस प्रकार अपनी व्यय-राशि को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसकी विविध व्यय की इकाइयों की सीमान्त उपयोगिता समान रहे, अर्थात् मात्रा को प्रत्येक बार व्यय करने में अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो।

प्रो० मार्शल की परिभाषा—मार्शल इस नियम को इस प्रकार परिभाषित करते हैं “यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई वस्तु है जिसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है तो उसके उपयोग को इस प्रकार बाँटेगा कि सब दशाओं में सीमान्त उपयोगिता समान हो रहे।”

(If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it between these uses in such a way that it has the same marginal utility in all.)

यदि किसी एक उपयोग में उसकी सीमान्त उपयोगिता अधिक है, तो वह उसमें से कुछ लेकर अन्य उपयोग में लगा देगा, जबतक इस प्रकार वह मुद्रा की प्रत्येक इकाई से अधिकतम तृप्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास केवल एक रम्या है, यदि उसे चाय बनाने और सतरो पर धूप करना है तो हम प्रथमता या प्रथमता में प्रत्येक वस्तु की अन्य वस्तु की अपेक्षा उपयोगिता नापने और अपनी रायों इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि रम्या की प्रथम इकाई की सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक वस्तु पर समान रहे।

नियम के विविध नाम—सब सीमान्त उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution), अधिकतम तृप्ति का नियम (Law of Maximum Satisfaction) सबका उदासीनता नियम (Law of Indifference) भी कहते हैं। इसे ‘प्रतिस्थापन नियम’ इसलिए कहते हैं कि कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान में अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रयोग कर देते हैं। प्रत्येक मुद्रिमान व्यक्ति अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करना चाहता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस कारण इसे ‘अधिकतम तृप्ति का नियम’ भी कहते हैं। इसे ‘उदासीनता नियम’ इसलिए कहते हैं कि वस्तु या मुद्रा के विभिन्न उपयोगों से समान उपयोगिता प्राप्त होने के कारण उपयोगिता वस्तु या उपयोग के चुनने में उदासीन रहता है और अंततः यह पड़ जाता है कि वह किस वस्तु या उपयोग को स्वीकार करे।

उदाहरण (Illustration)—यह नियम निम्न उदाहरण से भली प्रकार समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास ₹२ धान हैं। और वह उन्हें घाटा, चावल और दाल खरीदने में व्यय करना चाहता है। वह इन विविध वस्तुओं पर ₹ आने की इकाई में व्यय करता है। ‘उपयोगिता ज्ञान नियम’ के अनुसार प्रत्येक क्रमानुगत वस्तु की इकाई की उपयोगिता गिरती जाती है जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है।—

वस्तु का नाम	वस्तु की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता					
धान	२०	१७	१४	१२	१०	६
चावल	१६	१४	११	१०	४	१
दाल	१५	१३	१०	७	४	२

१ आने का ४ छटांक भाटा, ३ छटांक चावल और ३ छटांक दाल उपलब्ध होता है। प्रत्येक क्रमानुगत एक आने को विविध वस्तुओं पर व्यय करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वह ऊपर की तालिका में स्पष्ट है।

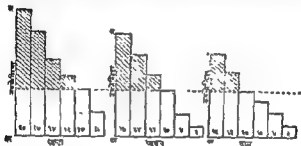
ऊपर के उदाहरण से यह ज्ञात है कि भाटे की प्रथम इकाई की उपयोगिता अधिकतम होने से सबसे प्रथम एक आना इस पर व्यय किया जायगा। जब प्रथम दूसरा आना व्यय करेगा तो विविध वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना कर पुनः इसी को भाटा खरीदने में व्यय करेगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता ही अभी अधिकतम है। जब तीसरा आना व्यय किया जायगा तब भी वह सब वस्तुओं की तुलना करेगा। हमें ज्ञात है कि भाटे की तीसरी इकाई की उपयोगिता १४, चावल की पहली इकाई की उपयोगिता १६ और दाल की पहली इकाई की उपयोगिता १५ है। अतः यह स्वभाविक है कि तीसरा आना चावल की पहली इकाई पर खर्च किया जायगा। अन्य आने भी इसी प्रकार व्यय किए जायेंगे। नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें विविध वस्तुओं पर १२ आने व्यय करने का क्रम बतनाया गया है :—

एक आने की इकाइयाँ	वस्तु का नाम	उपयोगिता
१	भाटा	२०
२	भाटा	१७
३	चावल	१६
४	दाल	१५
५	चावल	१४
६	भाटा	१४
७	दाल	१३
८	भाटा	१२
९	चावल	११
१०	भाटा	१०
११	चावल	१०
१२	दाल	१०
१२ आने	५ भाटे की इकाइयाँ ४ चावल की इकाइयाँ ३ दाल की इकाइयाँ	१६२

ऊपर की तालिका से यह विदित होता है कि प्रत्येक वस्तु के अन्तिम आने की उपयोगिता समान है। प्रत्येक दशा में समान्तर उपयोगिता १० है जो तालिका में निर्दिष्ट चिन्ह द्वारा प्रकट की गई है। वह अपने व्यय की इस प्रकार जमावेष्टा कि ५ आने दो भाटा खरीदने में, ४ आने चावल में और ३ आने दाल खरीदने में व्यय करेगा। यहाँ समस्त उपयोगिता (Total Utility) १६२ इकाइयाँ हैं। इन क्रम से व्यय करने पर ही अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। परन्तु यदि हम क्रम में कुछ हेर फेर हुआ तो समस्त उपयोगिता गिर जायेगी। क्योंकि भाटे की ५, चावल की ४ और दाल की तीन इकाइयाँ क्रय करने के स्थान में भाटे की ४, चावल की ४ और दाल

की ४ इकाइयाँ अथवा ये अन्य परिमाण में खरीदी जायें तो समस्त उपयोगिता में न्यूनता होना स्वाभाविक होगा।

नियम का रेखा चित्रण (Diagrammatic Illustration)—उपर्युक्त उदाहरण रेखा-चित्र द्वारा निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है (१) छाटा, चायन और शाल की निम्नलिखित इकाइयों की उपयोगिताएँ नीचे के तीन चित्रों में बतलाई गई हैं :—



सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility)

चित्र का स्पष्टीकरण—ऊपर के चित्रों में अन्व-रेखाओं पर दून् विविध वस्तुओं की इकाइयाँ नापी गई हैं और अन्व रेखाओं पर इनके प्राप्त प्रतिबोधिताएँ बतलाई गई हैं। एक रेखा उन् आयतों (Rectangles) को जिनकी उपयोगिता प्रत्येक वस्तु में १० इकाइयाँ हैं मिलाती हुई खींची गई है। चित्रने प्रायत इस रेखा द्वारा स्पर्श किए गए हैं वे सब इस बात को बतलाते हैं कि प्रत्येक वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदी गईं, अथवा प्रत्येक के लिए कितने खाने व्यय किये गये। ऊपर के रेखाचित्रों द्वारा यह स्पष्ट है कि चाटे की ५, चायन की ४ और शाल की ३ इकाइयाँ खरीदी गई हैं, अर्थात् ५ खाने भाटे के लिए, ४ खाने चायन के लिए और ३ खाने शाल के लिए व्यय किये गये हैं। (१ इकाई १ खाने के बराबर मानी गई है)

उपयोगिता क्षेत्र (Scope of the Law)

इस नियम की उपयोगिता का अनुभव हमको अपने दैनिक जीवन में निरन्तर होता रहता है। इसकी यथार्थता प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार की सभी शाखाओं में प्रकट होती है :—

उपभोग (Consumption)—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम केवल मुद्रा व्यय पर ही नहीं अपितु उन सब वस्तुओं पर भी लागू होता है जिनका प्रयोग अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास दस पत्र बचता है और यदि वह एक कमीज, पायजामा भूतल और अनिश्चित बसना चाहता है, तो उसे इन विविध प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बाँटना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार के प्रयोग की प्रतिफल इकाई की सीमान्त उपयोगिता समान रहे। इस प्रकार यह अधिकतम प्रतिफल प्राप्त कर सकेगा। एक और उदाहरण देना इस विषय की अविवेक स्पष्ट कर देगा। माना कि किसी मरम्मत में जल की एक बड़ी बाटली उपलब्ध हुई, इस परिमित जल को भोजन बनाने, पीने, नहाने, बपड़े धोने आदि कार्यों के लिए इस प्रकार बाँटा जाय कि इन सबकी प्रतिफल इकाई की उपयोगिता समान रहे और समस्त उपयोगिता अधिकतम हो।

वर्तमान और भविष्य के उपयोगों की तुलना—इस नियम का उपयोग केवल यही जानने के लिए नहीं होता है किमी वस्तु या मुद्रा के विविध उपयोगों में किम प्रकार बाँटा जाय, अपितु उपयोग किमी वस्तु या मुद्रा के वर्तमान और भविष्य के उपयोगों को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे प्रत्येक मनुष्य इस बात की तुलना करता है कि अधिक वस्तु को इतनी मात्रा लेने से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगी है, उगी प्रकार उसे इस बात की भी तुलना करनी चाहिए कि वर्तमान समय के किये जाने वाले उपयोग के व्यय से उत्पन्न होने वाली समस्त उपयोगिता से भविष्य में किये जान जाने उपयोगों में व्यय में प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कितना अन्तर है। दोनों उपयोगिताओं में से किन्हीं पलड़ा अधिक भारी है। प्रत्येक मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाना ही पटना है मत, मनुष्य को अपनी भाष का कितना भाग वर्तमान में व्यय करना चाहिए और कितना भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

प्रो० मार्शल इस सम्बन्ध में यह कहते हैं, “एक विचारशील पुरुष अपने साधनों को विविध प्रयोगों में—वर्तमान या भविष्य—इस प्रकार वितरण करेगा कि प्रत्येक दशा में वही सौमान्य उपयोगिता प्राप्त हो। परन्तु दूर के साधनों के उपयोगों की वर्तमान में सौमान्य उपयोगिता या अनुमान लगाने समय अनिश्चितता और भविष्य की उपयोगिता की तुलना का ध्यान रखना चाहिए।”

उत्पत्ति (Production)—सम सौमान्य उपयोगिता नियम की उपयोगिता केवल उपयोग तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत उत्पत्ति, विनिमय और वितरण में भी यह ‘प्रतिस्थापन नियम’ के रूप में देखा जाता है। उत्पत्ति के क्षेत्र में इसका बहुत अधिक महत्व देखा जाता है। प्रत्येक व्यापारी या उत्पादक निरन्तर अपने साधनों को विविध उत्पादन-कारक (Factors of Production) में इस प्रकार वितरण करता रहता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यह निरन्तर अपने मस्तिष्क में प्रत्येक कारक की ‘सौमान्य उत्पादकता’ (Marginal Productivity) का माप तान करता रहता है और उनकी उपयोगिता में अनुसार अपने साधनों का विनियोग करता रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी मनुष्य का उत्पादन अधिक द्वारा उत्पन्न किया जाने की अपेक्षा मशीन द्वारा अधिक उत्तम और मज्जा सम्बन्ध है, तो वह अधिक के स्वार्थ में मशीन का उपयोग करेगा। कम यही ‘प्रतिस्थापन नियम’ का महत्व है। इसी प्रकार कृषक भी अपने मस्तिष्क में यह गौणता रहता है कि वह अपने समुद्र क्षेत्र में गेहूँ बोये या जी प्रयत्न करे। यह प्रत्येक की सौमान्य उत्पादन-उपयोगिता का तुलनात्मक दृष्टि से जान कर वही श्रेष्ठ उत्पन्न करता है जिसमें न्यूनतम व्यय से अधिकतम लाभ हो।

विनिमय (Exchange)—विनिमय क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। जैसे उपयोग समान मूल्य वाले पदार्थों में सबसे पहल उन वस्तुओं का खरीदना है जिनकी उपयोगिता अधिक हो। समान मूल्य वाली कई वस्तुओं में से उन वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करता है जिसमें वह अधिकतम तृप्ति कर सक।

वितरण (Distribution)—वितरण क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता कम दृष्टिकोण पर नहीं होगी। एक उत्पादक अपने साधन को कई एक उत्पादन-कारकों पर इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक कारक की सौमान्य उत्पादकता (Marginal Productivity) समान रहे। प्रत्येक कारक की सौमान्य उत्पादन शक्ति की सहायता से ही प्रत्येक कारक का पारित्यमिक (Remuneration) निर्धारित किया जाता

है। प्रावृत्त अधिवसन सामाजिक नाम का हटि म इस नियम को ध्यान में रख कर विभिन्न उपायान्तर करके का यह सवान् विनियम को प्राप्त करता है।

राजस्व (Public Finance)—इस नियम की सहायता में सरकार द्वारा सावजनिक व्यय का इस प्रकार संचालित किया जाता है कि उच्च अधिवसन सामाजिक नाम (Maximum Social Advantage) प्राप्त हो।

नियम की बाधाएँ व्यवसाय मर्यादाएँ

(Hindrances or Limitations of the Law)

न्याय मनुष्य स्वभावतः अपनी श्रुति में अधिवसन नाम का इच्छा करता है और इसीलिए वह यह नियम का अनुसरण करता है तथापि व्यावहारिक जीवन में होता जाता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो इस नियम की पूर्ण प्राप्ति में बाधा बन जाती हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(१) अधिचारित व्यय—कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जितना साधन उनके अपने इच्छा को व्यय करने पर है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यय की सीमांत उपयोगिता का हिमाय नमाना बचाने समय का दुर्पयोग है।

(२) दूसरा व निमित्त व्यय—यह भी कहा जाता है कि भय प्रायः अपने लिए बस्तुएँ नहीं खरीदते। उदाहरण के लिए जब कभी निम्न उनके माना बिना व्यवसाय प्रविभाजन वस्तुएँ खरीदते हैं। वे बस्तुएँ दूसरा के उपयोग के लिए खरीदी जायेंगी उनका उपयोगिता का अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है।

(३) जनसाधु-परिवर्तन स्वास्थ्य का दान तथा वस्त्रादि के विनाश का प्रभाव—उपभोक्ता स्वयं मनुष्य सामान्य उपयोगिता नियम द्वारा अपने व्यय का समाधान नहीं करता है। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य कभी-कभी कम उपयोगिता वाली वस्तुएँ खरीदता है। रेल का टिकट इसका सरल उदाहरण है। यमराजी पुरुष अपनी प्राणीयता के लिए अपने दैनिक जीवन में रेल का टिकट को मुक्त का अनिवार्य मानते नहीं समझते इसी कारण वे उस उतार भरतक भी नहीं खरीदते परन्तु उनका धन के परिवर्तन के निमित्त इस प्रकार के भय में व्यय उस करना पड़ता है। इसी प्रकार कभी-कभी मनुष्य को स्वास्थ्य ग्राह्य जिन कठ कष्टों को प्रोत्साहित नहीं करता के पार्य मान पड़ता है। उनमें उनकी मनुष्य सामान्य उपयोगिता नहीं दाना जाती। इनमें अनिश्चित जिन सीमा तक बस्तुएँ विनाशित की गई हैं उनमें भी उक्त व्यय में घटाने माना स्वाभाविक है।

(४) पूर्व निर्दिष्ट व्यय—उपभोक्ता की प्रायः का कुछ मात्रा किन्हीं निश्चित व्यय के लिए पड़ने में ही निश्चित होता है। मनुष्य इस प्रकार के व्यय का समाधान इस नियम द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिन मकान का किराया कर प्राप्ति पूर्व निर्दिष्ट होता है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(५) मूल परिवर्तन—प्रायः मूल के परिवर्तन में मनुष्य सामान्य उपयोगिता नियम पर प्राप्ति अनुमानित गणना (Calculation) इस नियम की उपयोगिता प्रकट करने में असमर्थ हो जाती है। मान लीजिए कि धातु का मूल बढ़ जाय और चाकरी व धातु का मूल घट जाय तो धातु पर व्यय जितना था उस धातु की उपयोगिता पूर्व अनुमानित उपयोगिता में कम हो जायगी।

(-६) असमीमित साधन—श्रुति-दत्त निःशुल्क वस्तुओं की भांति यदि साधन असमीमित हो, तो इस नियम का कोई महत्त्व नहीं रह जाता ।

(-७) अयोग्य या अपट व्यवस्थापक—यदि व्यवस्थापक में योग्यता या कुशलता का अभाव है, तो वह विविध उत्पादन-कारकों के समायोजन से अधिकतम लाभ नहीं उठा सकेगा ।

रीति-रिवाज अथवा फैशन का प्रभाव

(Effects of Custom or Fashion on the Law)

रीति रिवाज कभी-कभी निर्भीक वस्तु की उपयोगिता को अनिवार्य बना देता है । उदाहरणार्थ घोंटी और पायजामा दोनों वस्तुएँ एक ही प्रयोजन मिट्ट करने के कारण एक के स्थान में दूसरे प्रयुक्त की जा सकती हैं, परन्तु रीति-रिवाज की श्रृंखला में बँधे हुए होने के कारण ब्राह्मण कभी पायजामा प्रयुक्त नहीं करेगा, चाहे वह घोंटी की अपेक्षा अधिक मन्ता क्यों न पड़े । एक उदाहरण और दे देना इस विषय का अधिक स्पष्ट कर सकेगा । हिन्दू द्विज का बालक यज्ञोपवीत मस्कार के समय दण्ड, मेखला, कमण्डल, शामन, भीमी धारण करता है । इसका धारण करना वैदिक रीति के आधार पर अनिवार्य है । इन वस्तुओं की उपयोगिता से यद्यपि उमको 'शून्य' मताप प्राप्त होता है पर रीति-रिवाज की विवशता में उसे उनका उपयोग करना पड़ता है । सम-भोमान्त उपयोगिता नियम के आधार पर वह इन वस्तुओं के स्थान पर ऐसी वस्तुओं का उपयोग चाहेगा जिनसे उसे इनकी उपयोगिता की अपेक्षा अधिक सन्तोष उपलब्ध हो ।

इसी प्रकार फैशन की दासता भी कई बार मनुष्य को अमुक वस्तु के उपयोग के लिए बाध्य कर देती है । उदाहरण के लिए, फैशन का दास एक कॉलेज का विद्यार्थी मङ्गलन खरीदने के स्थान में टाई खरीदना पसन्द करेगा, यद्यपि उसी मूल्य में भस्मन जैसी लाभदायक वस्तु खरीदी जा सकती है । यह फैशन के प्रभाव में अपनी मुद्रा उन वस्तुओं पर ही जिनकी उपयोगिता कम है, व्यय करेगा । यह सम-भोमान्त उपयोगिता नियम के विरुद्ध है ।

- ६—प्राय को व्यय करने में प्रतिस्थापन किस प्रकार नाम आता है ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए । (पन्ना १६१० ४५)
- ७—सम-मीमांसा उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए । दैनिक जीवन में इसका महत्त्व बताइए । (म० भा० १६५२ अ० वा० १६५४ ४८)
- ८—उपभोग में ताम्र हान क्षय प्रतिस्थापन नियम की व्याख्या कीजिए और यह भी बताइए कि रीति रिवाज और पैंगल से इसमें क्या परिवर्तन होता है ? भारतीय उदाहरण दीजिए । (म० भा० १८४४)
- ९—यदि आपको अनुपाय ही हो तो नाम रखें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ वस्तु अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए आप किस सिद्धान्त का ध्यान में रखेंगे ? मुख्य मुख्य मद्दा का उल्लेख कीजिए जिन पर कि आप यह रचना व्यय करना चाहेंगे और उन मद्दा का आप क्या सापेक्षिक महत्त्व देंगे ? (पञ्चाव १६४८)
- १०—सम-मीमांसा उपयोगिता नियम पर टिप्पणी कीजिए । इस प्रतिस्थापन का सिद्धान्त अथवा अनुसोमना नियम क्या कहते हैं ? (पञ्चाव १६५२)
- ११—सम-मीमांसा उपयोगिता नियम में आप क्या समझते हैं ? एक उपभोक्ता के पास गेहूँ दूध चाय व चीनी पर खर्च करने के लिए ₹५०० है तथा प्रत्येक की मीमांसा उपयोगिता निम्न प्रकार है —
- | | | | | |
|-------|----|----|----|----|
| गेहूँ | २८ | २६ | २० | १६ |
| दूध | २८ | २० | १६ | १० |
| चाय | २२ | १८ | ६ | २ |
| चीनी | २० | १७ | १६ | ६ |
- (रा० दा० १६५७)
- १२—अधिकतम सन्तुष्टि (Maximum Satisfaction) प्राप्त करने के लिए कौन-सी व्यय प्रणाली व्यय जिन नियमों के पालन में की जाये और श्रृंखला (Fashion) का प्रभाव कहाँ तक जायक होता है ? (नागपुर १६५४)
- १३—सम-मीमांसा उपयोगिता नियम का जिन-से उदाहरण सहित अच्छा प्रकार में समझाइए । (मागूर १८५८ ५६ १०)

उपभोक्ता की वृत्त (Consumer's Surplus)

उपभोक्ता की वृत्त का अर्थ (Meaning)—उपभोक्ता की वृत्त के सिद्धान्त का 'उपयोगिता हानि नियम' में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सिद्धान्त इस बात को स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता का जो वस्तुएँ कि वे खरीदते हैं उनमें प्रतिरिक्त मनुष्य (Surplus Satisfaction) प्राप्त होती है। यह प्रतिरिक्त मनुष्य कुछ वस्तुओं में अधिक और कुछ में कम प्राप्त होती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, तब हम उस वस्तु का मूल्य जो हम वास्तव में देते हैं उसमें कहीं अधिक देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस मूल्य में कुछ मुद्रा बचाकर घर लौट आते हैं। यह बची हुई मुद्रा अन्य वस्तुओं के लिये मूल्य की जा सकती है जिनसे हमें 'प्रतिरिक्त मनुष्य' प्राप्त होती है। इस प्रतिरिक्त मनुष्य का अर्थान्त में 'उपभोक्ता की वृत्त' के नाम से संबोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि पास्ट कार्ड मरलता में अमीर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों की पोस्ट कार्ड लिखने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वे बाजार में कम मिलाकर एक बार पास्ट कार्ड लिखने के लिए पास्ट कार्ड के पच्चीस नये पैसे तक देने को तैयार हो सकते हैं, परन्तु वास्तव में पोस्टकार्ड पाँच नये पैसे में मिलते हैं। उनसे आसानी से खरीदे जा सकते हैं। अतः, एक पोस्टकार्ड खरीदने में बीस नये पैसे की वृत्त रहती है। यह बची हुई मुद्रा अन्य आवश्यक वस्तुओं में व्यय की जा सकती है जिसमें उन्हें प्रतिरिक्त मनुष्य प्राप्त हो सकेगी। यही प्रतिरिक्त मनुष्य 'उपभोक्ता की वृत्त' है।

उपभोक्ता की वृत्त की उत्पत्ति के कारण (How does Consumer's Surplus arise?)—उपभोक्ता की वृत्त इसलिए होती है कि जो मुद्रा मूल्य के रूप में किसी वस्तु को खरीदने के लिए व्यय की जाती है उसकी उपयोगिता उस से प्राप्त सम्पूर्ण उपयोगिता में कम होती है। 'उपयोगिता हानि नियम' के अनुसार जैसे-जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ता है उसकी उपयोगिता कम होती जाती है—प्रत्येक वस्तु की पहली इकाई को उपयोगिता की अपेक्षा बाद वाली इकाई की उपयोगिता गिरती जाती है, यहाँ तक कि अन्त में उपभोक्ता को किसी एक इकाई पर अपना उपभोग समाप्त कर देने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस इकाई की उपयोगिता शून्य की जाने वाली मुद्रा (मूल्य) की उपयोगिता के समान है। यह इकाई सीमान्त इकाई (Marginal Unity) और इसमें प्राप्त उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) कहलाती है। सीमान्त इकाई से अधिक इकाई खरीदना मुद्रा का दुष्प्रयोग माना होगा। अतः उसे वस्तु का उपयोग वहीं समाप्त कर देना पड़ेगा। उस वस्तु की सब इकाईएँ एक समान हानि के कारण वस्तु की

विषय इकाई का मुख्य सामान स्टाई का उपयोगिता अर्थान् मुख्य व अन्तर्गत दिया जायगा। परन्तु सीमान्त इकाई से उपर वाली इकाई का उपयोगिता उससे अधिक होने के कारण उन इकाई का उपभोग का मुख्य की उपयोगिता में अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यम वही नाम उपभोक्ता की वस्तु है। दूसरे शब्दों में या कहा जा सकता है कि मुख्य के रूप में मिलनी उपयोगिता का उस वस्तु के लिए हमको त्याग करना पड़ता है वह समस्त उपयोगिता में कम होती है। इस प्रकार त्याग की गई उपयोगिता और प्राप्त उपयोगिता का अंतर ही उपभोक्ता की वस्तु है। हमको उपभोक्ता की वस्तु इमान्तिव कहते हैं कि उस वस्तु को संतोष में उस व्यक्ति का उत्तम उपयोगिता का नाम हा जाता है। अस्तु यहाँ यह बात भाव्यान् दन योग्य है कि उपभोक्ता का वचन का सम्बन्ध उपयोगिता में है न कि मूल्य में। हा यह भाव अनुप्रा की भांति स्पष्ट ब्याने पाई म नापी जा सकती है।

संक्षेप में उपभोक्ता का यह नाम निम्न कारणों में उपर्युक्त होता है —

- (१) उपयोगिता हानि नियम का लागू होना।
- (२) वास्तव में वस्तु का एक ही समय एक ही मुख्य विद्यमान होना।
- (३) उत्पत्ति की वनामक उत्पत्ति व कारण वस्तुश्रम का सत्ता उपर्युक्त होना।
- (४) एक ही वस्तु के लिए अमीर गरीब और मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं का होना।

उपभोक्ता का वचन का सैद्धान्तिक रूप (Statement of the law)

जैसे हम प्रकार के नाम का अनुमान हम अपने जीवन में कई वस्तुओं के सम्बन्ध में करते रहते हैं परन्तु इसका सैद्धान्तिक रूप में परिचय हमें प्रथम प्रो. मार्शल ने दिया। उन्होंने इस विचार धारा की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य मनुष्य वास्तव में होता है वह उस मुख्य में जिस वह व्यक्ति वस्तु में वचन रहने को तैयार हो जायगा, संवदा कम होता है। और सामान्य ही वस्तु उसके वरिष्ठ होता है। अतः उसके वचन के जो उस मनुष्य में मिलता है वह साधारणतया उस मनुष्य में अधिक होती है जिस वह उस मुख्य के रूप में देता है और इस प्रकार उसके वचन में अनिश्चित मनुष्य प्राप्त होती है। जो मुख्य किसी वस्तु से वचन रहने की अपेक्षा मनुष्य देने का तैयार हो जायगा और जो मुख्य वास्तव में देता है, उन दोनों मुख्यों का अंतर ही उपभोक्ता की वस्तु का आर्थिक माप है। अतः इस सम्बन्ध में योग्य सिद्ध है कि हमें वचन को हम अवसरों (Opportunities) या वातावरण (Environment) में प्राप्त होने वाला नाम भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक उत्पत्ति के साथ साथ उपभोक्ता का वचन में वृद्धि होती रहता है। उदाहरण के लिए जो दान भौतिक सम्पत्ति की दृष्टि में अधिक प्रमत्तिगीन है वह निम्न अर्थ प्रदान दान देना की अपेक्षा सम्पत्ति का नाम मनुष्य को अधिक उपर्युक्त होता है।

1— The excess of the price which he would be willing to pay rather go without the thing over which he actually does pay is the economic measure of the surplus satisfaction
—Marshall

• प्रो० टॉसिग के मतानुसार समस्त उपयोगिता और समस्त विनिमय-मूल्य को नापने वाली राशियों का अन्तर ही उपभोक्ता की वचन है ।^१

प्रो० जे० के० मेहता इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं—किमी वस्तु से मनुष्य जो उपभोक्ता की वचन प्राप्त करता है, वह उस वस्तु से मिलने वाली सन्तुष्टि और वस्तु को पाने के लिए त्याग करने वाली सन्तुष्टि का अन्तर होता है ।^२

संक्षेप में, उपभोक्ता की वचन = जो हम दे सक्ते हैं

—जुन जो हम वास्तव में देते हैं ।

In short, (Consumer's Surplus) — What we are prepared to pay minus what we actually pay

उपभोक्ता की वचन का गणितात्मक रूप

(Mathematical Expression of Consumer's Surplus)

उपभोक्ता की वचन का गणितात्मक रूप निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है —
उपभोक्ता की वचन = समस्त उपयोगिता — (सीमान्त उपयोगिता × खरीदी जाने वाली इकाइयों की संख्या)

Consumer's Surplus = Total Utility — (Marginal Utility × No of units purchased)

उ० व० = $\Sigma U - (MU \times N)$

C.S. = $\Sigma U - (MU \times N)$

अर्थात् उ० व० का अर्थ है उपभोक्ता की वचन

स० उ० " कुल उपयोगिता

स० " " खरीदी जाने वाली इकाइयों की संख्या

उदाहरण (Illustration) — मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है । भूख शांत करने के लिए वह बाजार में जाकर रोटी खरीदता है । प्रत्येक रोटी की उपयोगिता नुसार वह निम्नान्वित सारणी में अंकित मूल्य देने को तैयार हो जाता है । मान लीजिए बाजार में प्रति रोटी का मूल्य एक आना है ।

यह कुल ५ रोटियाँ खरीदेगा । पाँचवी रोटी की उपयोगिता और मूल्य दोनों बराबर हैं । यदि छठी रोटी खरीदना है तो उसको मूल्य में कम तृप्ति प्राप्त होगी ।

1—According to Taussig, Consumer's Surplus is the "Difference between the sum which measures total utility and that which measures total exchange value "

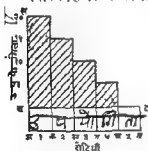
2—J K Mehta in his Groundwork of Economics defines it as follows "Consumer's Surplus obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction which he derives from it and that which he forgoes in order to procure that commodity"

अतः वह पाँचवीं रोटी के बदलाव और कोई रोटी न मरी देगा। वह पाँच रोटियों के लिए तीन रुपये भोज खाने तक देने का तैयार हो सकता है, किन्तु बाजार भाव एक घाना होने के कारण उसे पाँच रोटियाँ के लिए कुल पाँच घाने देने पड़ने हैं। ऐसी स्थिति में उसे दो रुपये की हानि खाने की वचन होगी।

रोटी की संख्या	सूर्य या वह देने को तैयार हो सकता है	बाजार भाव	उपभोक्ता की वचन
पहली	२० घाने	१ घाने	$(20 - 1) = 19$ घाने
दूसरी	१५ "	१ "	$(15 - 1) = 14$ "
तीसरी	१० "	१ "	$(10 - 1) = 9$ "
चौथी	५ "	१ "	$(5 - 1) = 4$ "
पाँचवीं	१ "	१ "	$(1 - 1) = 0$ "
कुल ५ रोटियाँ	५१ घाने	५ घाने	$= ४६$ घाने

रेखा चित्रण (Diagrammatic Representation)

रेखा-चित्रण का स्पष्टीकरण—ऊपर के चित्र में प्रत्येक रेखा पर रोटियों की



संख्या और प्रत्येक रेखा पर उपभोक्ता की इकाइयाँ नापी गई हैं। प्रत्येक रेखा एक, एक, एक, एक, एक और एक म विभाजित है। इनमें से प्रत्येक एक विभाजित क्रम में एक रोटी का प्रयोग है। जहाँ आयत (Rectangle) उनमें प्रत्येक भाग पर बना हुआ है वह प्रत्येक रोटी की उपयोगिता दर्शाता है। प्रत्येक रोटी का सूर्य खाने वाली रेखा है। आयतों का समुदाय भाग उपभोक्ता की वचन का प्रतिनिधित्व करता है। हम देखते हैं कि सीमान्त उपयोगिता में उपभोक्ता-वचन शून्य है।

उपभोक्ता की वचन (Consumer's Surplus)

दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण (Examples from daily life)—इन प्रकार की वचन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में करने रहते हैं। भिन्न-भिन्न वस्तुओं में तुष्टि की वचन भिन्न-भिन्न होती है। साधारणतया आवश्यक वस्तुओं में उपभोक्ता की वचन अधिक प्राप्त होती है और सुख तथा विनाश की वस्तुओं में कम। दैनिक जीवन में वाम आने वाली साधारण वस्तुओं में अधिक तुष्टि की वचन होती है, जैसे दियामलाई, मिट्टी का तेल, लवण, दूध, गुमाचार-पत्र, पोस्टकार्ड, लिफाफे आदि। उपभोक्ता तथा अन्य ग्राहक बुलबुले, बसें तथा दामगादियाँ, भोजन खाने तथा निराला वस्तु में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं आदि अन्य उन्नी प्रकार के उदाहरण हैं।

उपभोक्ता की वचन के माप में कठिनाइयाँ

(Difficulties of measuring Consumer's Surplus)

उपभोक्ता की वचन का वयार्थ माप एक कठिन साध्य कार्य है। उसका मपे, माने, पाई में ठीक-ठीक माप करने मसब हमें कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं :—

(१) उपभोक्ता की वचन वस्तुओं के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक वातावरण पर निर्भर है—आर्थिक मध्य और प्रगतिशील देशों में जीवनोपयोगी वस्तुओं अधिक मात्रा में तथा मन्ने दामों में उपलब्ध होने के कारण वहाँ के निवासियों को विच्छेद हुए दमों की अपेक्षा अधिक उपभोक्ता की वचन प्राप्त होती है।

(२) भिन्न-भिन्न वस्तुओं में भिन्न-भिन्न उपभोक्ता की वचन होना—मनुष्य कई एक वस्तुओं का उपभोग एक साथ करता है—योंही उनको सीमान्त तथा समस्त उप-प्रतिनाओं में पर्याप्त भिन्नता होती है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मय वस्तुओं में प्राप्त समस्त वचन की मापना यदा कठिन हो जाता है।

(३) बाजार में उपभोक्ता की वचन का वयार्थ माप कठिन है—बाजार में प्रत्येक उपभोक्ता की वचन की मापना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक की मय, पसंदी और स्वाद में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

(४) उपभोक्ता की वचन की धारणा काल्पनिक एवं अमूर्त है—यह कहना कि १०० रु० मय करने में १००० रु० की गुनि प्राप्त होती है कोई मय नहीं मयना क्योंकि वास्तव में तो भी की वचन का अनुभव नहीं होता।

(५) प्रतिनियार्थ पदार्थों में भी यह मिथ्यात्व पूर्णतया लागू नहीं होता—प्रतिनियार्थ पदार्थों की समस्त उपयोगिता की मापना यदा कठिन है, क्योंकि वस्तुओं में उपभोक्ता की वचन समीक्षित होती है जो ठीक-ठीक मापे नहीं जा सकती है। प्रो० टॉमिग के मतानुसार यह मिथ्यात्व केवल प्रतिनियार्थ आवश्यकताओं में ही नहीं बल्कि मय आवश्यकताओं में भी ठीक तरह लागू नहीं होता।

(६) प्रतिनियार्थ वस्तुओं के लिए यह मिथ्यात्व लागू नहीं होता—जो वस्तुएँ पद-प्रदर्शन तथा मान या प्रतिष्ठा के लिए रागीदी जाती हैं उनमें यह धारणा प्रभावहीन होती जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता, जब तक कि वे अधिक मूल्यवान हैं, प्रतीत होती है। उनके मन्ता होने ही प्रतिनियार्थ मूल्य भी मापव हो जाता है। अस्तु ऐसी अवस्था में यह वचन की धारणा उचित ही हो जाती है।

(७) मुद्रा मय लोगों के लिए समान उपयोगिता नहीं रहती—एक मय की एक घनवान रूप के लिए जो उपयोगिता है, उसमें नहीं अधिक उमकी उपयोगिता एक मरीय आदमी के लिए है। अतः उनके वस्तु-मय के दृष्टिकोणों में भी पर्याप्त भिन्नता होना स्वाभाविक है। अस्तु इन विषमता के कारण हमारा ठीक मापन सम्भव नहीं है।

(८) मांग-मूल्य सूचिका पूर्ण अवस्था में उपलब्ध न होना—यह अनुमान लगाना कठिन है कि कोई मनुष्य किसी वस्तु के लिए कयाय उमका त्याग करने के क्या मूल्य देने के लिए तैयार हो जावेगा। यह ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाना ही उपभोक्ता की वचन के मापन में बाधा उपस्थित करता है।

(६) प्रतिष्ठापित एवं स्थापित वस्तुओं का मापन कठिन है—उदाहरण के लिए चाय और कढ़वा प्रतियोगिता (Rival) एवं स्थापित (Substitute) वस्तु है। यदि चाय उपलब्ध न हो जाता है तो चाय कढ़वा पीना प्रारम्भ कर देगा। परन्तु यदि चाय और कढ़वा दोनों में मिलावट होती है तो प्रतिष्ठापित वस्तु होगी। अतः चाय और कढ़वा दोनों को समस्त उपयोगिता एक दूसरे के समान मचाय और कढ़वा को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपयोगिता के योग में बहुत अधिक है। इन दोनों की उपयोगिता का योग इस पर भी उनमें प्राप्त समस्त उपयोगिता के बराबर होगा।

(१०) प्रारम्भिक इनाइया की उपयोगिता मित्रता आता है—या चाय समस्त वस्तुओं के साथ मिलावट करता जाता है—इसका उपयोग प्रारम्भिक चाय के साथ की आवश्यकता होती जाती है। अतः उनकी उपयोगिता बिर जाती है। इस कारण ही उपभोक्ता की वस्तु का जीवन-जीव माप कठिन हो जाता है।

उपभोक्ता की उन्नति के सिद्धान्त का महत्व—(Importance of the doctrine of Consumers Surplus) उपभोक्ता का वचन का महत्त्व निम्नलिखित प्रश्न—आवृत्ति के हिसाब से बड़ा महत्व है—

(१) उपयोगिता और भू-प्राप्ति—सबसे प्रथम यह सिद्धान्त हमारा हमें और ध्यान आकृष्ट करता है कि किसी वस्तु का भू-प्राप्ति सर्वत्र समान प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः प्राप्ति में भी कुछ भेद है कि किसी वस्तु की प्राप्ति किसे उपयोगिता का यथावत योग्य उपयोग मिले वार भू-प्राप्ति में प्रत्यक्ष भेद होता है।

(२) वातावरण अथवा अवसरों का प्राप्ति होना—इस धारणा के अन्तर्गत में हम अपने वातावरण अथवा अवसरों में प्राप्त होने वाले लाभों का अनुमान लगा सकते हैं।

(३) विभिन्न स्थानों और समयों के आधिकारिक जीवन का तुलना—उपभोक्ता की वचन के सिद्धांत द्वारा विभिन्न स्थानों और समयों के समस्त वस्तुओं के आधिकारिक जीवन को तुलनात्मक रूप में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ प्राप्ति में २०० रु० मासिक वसति वातावरण अथवा जल-उपयोग वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। या किसी गाँव में दूर स्थित स्थान में रहने वाले व्यक्ति का ३०० रु० मासिक प्राप्ति पर भी उपलब्ध नहीं हो सकती है।

(४) राजस्व विभाग में महत्व—यह सिद्धान्त का महत्व राजस्व विभाग में भी प्राप्त होता है। किसी राज्य के अर्थ-मन्त्री का नयन उपभोक्ता के दृष्टि पर रहता है कि योग्य वस्तु नयन को नैतिक है और नयन द्वारा जो भू-प्राप्ति होगी उन्नत वस्तु। एक प्रभावित राज्य जिसमें यह अधिक उपभोक्ता का वचन होगा वहाँ नयन वस्तुता में प्रभावित जा सकते हैं।

(५) एकाधिकार मूल्य निर्धारण में महत्व—यह सिद्धान्त एकाधिकार (Monopoly) मूल्य निर्धारण में महत्व प्राप्त है। एकाधिकार (Monopoly) उन वस्तुओं के मूल्य में महत्त्व का वृद्धि कर सकता है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के वचन हैं। किन्तु वह मूल्य अधिक वस्तु के वचन समान कर देता जहाँ वस्तुता में प्रभावित जा सकता है।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होने वाले लाभ का मापन सम्भव—
इस पारणा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे किसी देश में कमी वस्तुओं का आयात (Import) किया जाय जा उस देश की वस्तुओं में भी अधिक मन्नी किन्, तो निम्नदेह लेम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उपभोक्ताओं का लाभ होगा।

अभ्यासाय प्रश्न

कृष्णर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—उपभोक्ता की वचन (Consumer's Surplus) में क्या क्या सम्मिलित हैं। यह किस प्रकार मापी जा सकती है ? उदाहरण सहित समझाएँ और रेखाचित्र भी खींचिए। (उ० प्र० १६/७)
- २—उपभोक्ता की वचन का आशय समझाएँ। इसके अध्ययन की क्या उपयोगिता है ? (उ० प्र० १६/१०)
- ३—उपभोक्ता की वचन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या उपभोक्ता जा सकता है ? किंवा ? (पटना १६४, भाग १६४६)
- ४—उपभोक्ता की वचन का आशय क्या है ? चित्र की सहायता से समझाएँ। (ग० वी० १६५३, ५२, ५१, प्र० वा० १६/३)
- ५—उपभोक्ता की वचन का अर्थ समझाएँ और उदाहरण तथा उपयोग के इनका समझाएँ स्पष्ट कीजिए। (प्र० वा० १६४८)
- ६—उपभोक्ता की वचन, चित्र की सहायता से समझाएँ। इसकी क्या महत्ता है ? (ग० वी० १६/६)
- ७—उपभोक्ता की वचन निम्न कहते हैं ? इसका उद्देश्य कैसे जाना है और इसका कैसे मापा जा सकता है ? (भाग १६/१, ६६, प्र० वा० १६५५, ८३)
- ८—उपभोक्ता-हानि-निवृत्ति तथा उपभोक्ता की वचन में पारस्परिक सम्बन्ध पर नोट लिखिए। (भाग १६/७)
- ९—उपभोक्ता की परिभाषा लिखिए। इस मुद्रा में कैसे मापा जा सकता है ? उदाहरण दीजिए। (भाग १६५०)
- १०—उपभोक्ता की वचन का क्या आशय है ? इसका उद्देश्य किस प्रकार होता है ? (भाग १६५२)
- ११—‘उपभोक्ता की मनुष्य की वचन’ विचार धारा का प्रतिपादन कीजिए। क्या आप इसे माप सकते हैं ? (पटना १६८८)
- १२—‘उपभोक्ता की वचन’ पर सविस्तर टिप्पणी लिखिए। (उ० प्र० १६/३, ११, ८०, ४६, १६, ग० वी० १६८६, प्र० वी० १६/१, ८६, ४३, भाग १६५६, २०, प्र० भा० १६८८, ४३, ४४, पत्रिका १६४६)

जीवन स्तर का अर्थ (Meaning)—मनुष्य अपने दैनिक-जीवन में कई एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब वह अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त समय तक करता रहता है, तो वह उस आवश्यकता की तृप्ति का आदी बन जाता है। धीरे-धीरे इस प्रकार की आवश्यकताओं उस व्यक्ति की आदतों में परिवर्तित हो जाती है। आदत पड़ जाने के कारण वह उन आवश्यकताओं को सामान्य में नहीं छोड़ पाता। वे उसके प्रति दिन के साधारण जीवन का एक आवश्यक घटक बन जाती हैं। जीवन-स्तर का आशय मनुष्य की इसी आवश्यकताओं में है जिनकी तृप्ति का वह आदी हो गया है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर में अभिप्राय उन वस्तुओं में है जिनके उपभोग का वह आदी बन चुका है।

इसमें यह स्पष्ट है कि जीवन-स्तर आदतों पर निर्भर होता है, अतः इसमें घीघ्रता या सुगमता से परिवर्तन होना सम्भव नहीं। यह स्वभाव या आदत की भाँति लगभग स्थिर ही रहता है।

जीवन-स्तर एक सापेक्षिक शब्द है—अधिकतर यह शब्द सापेक्षिक रूप में प्रयुक्त होता है। जब हम यह कहते हैं कि अश्वेतों का जीवन स्तर भारतवासियों के ऊँचा है, तो हम जीवन-स्तर को तुलनात्मक दृष्टि में देखने दृष्ट पाय करते हैं। यही इसका सापेक्षिक रूप है।

जीवन-स्तर में भिन्नता—सभी जीवन-स्तर धराया रहन महन का दर्जा एक समान नहीं पाया जाता। प्रत्येक बाल, देश और व्यक्ति का दर्जा भिन्न-भिन्न होता है। अमेरिका के रहने वालों का जीवन-स्तर भारतवासियों के जीवन-स्तर की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। जो जीवन-स्तर अमेरिका में भी वर्षों पूर्व या वह बशों के वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना में वही नीचा है। इसी प्रकार एक ही समय और देश में भिन्न भिन्न श्रेणी वाले लोगों का जीवन-स्तर अलग अलग होता है।

जीवन-स्तर को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors governing the Standard of Living)

जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं :—

(१) आय—जीवन-स्तर का आन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक समीर आदमी अधिक आवश्यकताओं की तृप्ति करने के कारण ऊँचा जीवन-स्तर रखता है। जिस आदमी की आय कम होती है उसका जीवन-स्तर नीचा होता है। साधारण आय वाले व्यक्तियों का जीवन-स्तर साधारण ही होता है।

(२) विवेकपूर्ण आय का व्यय—किसी पदार्थ या अपर्याप्त आय से ही किसी व्यक्ति का जीवन स्तर निर्धारित नहीं हो सकता । यह भी देगना आवश्यक है कि वह अपनी आय का व्यय किस प्रकार करता है । आय पर्याप्त होने के साथ साथ उसका विवेकपूर्ण व्यय भी उन्ने जीवन-स्तर की एक शक्ति है । मान लीजिए कि दो व्यक्तियों की समान आय है, परन्तु उनमें से यदि एक व्यक्ति अपनी आय का व्यय प्रतिक मुद्रिमानि में करता है तो निरसदेह उत्तम जीवन स्तर हमारे की अपेक्षा प्रधिन ऊँचा होगा । यह कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वोत्तम (1 y) (08315e) रहन महन का दर्जा ही ऊँचा जीवन स्तर होता है ।

(३) मुद्रा की क्रय शक्ति—मुद्रा की क्रय शक्ति प्रत्येक देश या समय में समान नहीं होने के कारण विभिन्न देश या समया के निवासियों के जीवन स्तर को तुलनात्मक दृष्टि में देखते समय मुद्रा की क्रय शक्ति को ध्यान में रखना परम आवश्यक है । अस्तु जीवन-स्तर को निर्धारित करने में मुद्रा की क्रय शक्ति का बड़ा महत्व है ।

(४) व्यक्तिगत स्वास्थ्य—कई लोग व्याधियाँ से ग्रस्त होने के कारण अनुभव पुरि धीर धत होते हुए भी कई वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते । उदाहरणार्थ मधुमेह से ग्रस्त रोगी मिष्ठान्न का आनंद नहीं उठा सकता । अस्तु ऐसे व्यक्ति का जीवन स्तर एक स्वास्थ्य मनुष्य की अपेक्षा नीचा होगा ।

ऊँचा और नीचा जीवन स्तर

(High and Low Standard of Living)

ऊँचे और नीचे जीवन-स्तर में यहाँ भेद है कि पहलें प्रकार के जीवन-स्तर में मनुष्य को अधिक आर्थिक कल्याण प्राप्त होता है और उसमें अधिक कार्य-कुशलता तथा प्रगतिता का संचार होता है । नीचा जीवन-स्तर मनुष्य के विकास में बाधा उपस्थित कर उसकी आय कुशलता में मूलता पैदा करता है ।

खर्चीला और सस्ता जीवन-स्तर

(Expensive and Cheap Standard of Living)

यह धारणा गलत है कि अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने बात या जीवन स्तर सदैव ऊँचा होता है और कम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले का नीचा । एक पिछल खन जीवन वास्तव में खर्चीला जीवन है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह ऊँचा जीवन स्तर ही हो । इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि एक गतिव्ययी जीवन नीचा जीवन-स्तर ही हो ।



















भारतवर्ष में जीवन-स्तर (Standard of Living in India)—भारतवर्ष समार के सबसे निचन देशों में से है और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बहुत ही नीचा और असन्तोषजनक है । यहाँ की निचनता का कुछ अनुमान वार्षिक व्यक्तिगत औसत आय में किया जा सकता है । भारतवर्ष और कुछ अन्य देशों के निवासियों की व्यक्तिगत औसत आय के अर्थ तुलना के लिए नीचे दिये गए हैं —

विभिन्न दशा का प्रेति व्यक्ति तुलनामय आय

दरा	प्रति धानि प्राप	दरा	प्रति धानि प्राप
सकुन गल भ्रमगिया	७२६४	जापान	५००
बगदा	८६४०	भारतवष	३८१
सुदीन	४२८०	पाकिस्तान	२११
दुगद	३८६१	उरुगा	१८०
रुम	११८०	स्याम	१८०

भारतनामिया की औषध आय का अनुमान

वर्ष	अनुमान क्या	व्ययिगन श्रीमन् भाय
		४०
१८३०	दादाभाइ नोगानी	२०-०-०
१८००	गान् वजन	३०-०-०
१८००	मि० दिगडा	१०-१-०
१८११	मर गा० पन० गमा	१०-०-०
१८१३-१४	वाल्मिा श्री० जाना	८४-१-६
१८१३-१४	वकील श्री० मुखन	१८-०-०
१८२०-२१	गान् श्री० पभाट	३४-०-०
१८२१	विन्ना निगत	१०३-०-०
१८२१-२६	वी० व० धाग० मी० गव	७६-०-०
१८३१-३२		६२-०-०
१८३३-३८	मर अम्म विग	१६-०-०
१८६८-६९	नाजग्न टनवन वमशी	२१०-०-०
१८५१-५२	मन्ना टननामिन्	२१०-०-०
१८१६	आनिम वमशीग	२८१-०-०

उपयुक्त आवश्यकताओं में यह बात होता है कि भारतवर्ष में इस आय कितनी कम है। इससे तो जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि सम्पूर्ण आय को केवल भोजन सम्बंधी पर ही खर्च कर दिया जाय तो भी रागा को भर पेट भोजन नहीं मिल सकता। जब जीवन रक्षक पदार्थ ही समाप्त माना में उपलब्ध नहीं है तो निपुणता दायक पदार्थों की खाना करना ही निश्चयक है। भोजन में जो दूध जैसे पोषक पदार्थों का उपभोग बहुत कम है। अच्छा भोजन केवल त्योंहारा और उत्तमता पर ही प्राप्त होता है। अतः वे अनुसार कपड़ा बहुत ही कम अनुप्या का उपलब्ध होता है। अधिकतर मनुष्य भना और मोटा कपड़ा पहनते हैं। नगरों में मकानों का पूर्ण अभाव है। औद्योगिक नगरों में स्थानाभाव के कारण एक मकान में १०-१५ मनुष्य रहते हैं या सड़क के किनारे पड़ रहते हैं। धर्मिक वगैरहों में कौठरिया में बड़ा प्रकाश और शुद्ध वायु का सर्वथा अभाव होता है निर्वाह करना है। गावाँ का दूध और भी खोचनीय है। यदि कबल गावें वाला ही ही आसत निवासों जाय तो मुश्किल से २५ या ३०-४० वार्षिक आय होगा। इतनी कम आय से उनका जीवन स्तर क्या हो सकता है। इसकी कल्पना आसानी में की जा सकती है। गावाँ में प्रायः कच्चे छोटे घड़े और घड़े मकान पाये जाते हैं बिना रहकर मनुष्य वही स्वस्थ जीवन-धनीत नहीं कर सकता। वहाँ प्रायः एक ही मकान में मनुष्य और पशु दोनों ही निर्वाह करते हैं और ग्रामपास कूड़ा करवट राख और गोबर आदि का डर लगा रहता है जिससे लोग सदैव बीमारियों के निवार करने रहते हैं। चिकित्सा का कोई उपयुक्त प्रबंध न होने के कारण भारतवर्ष में रोकें जाने वाले रोगों में प्रतिवर्ष ६० लाख मृत्यु होता है। ऐसे जीवन-स्तर में शिक्षा की तो आशा ही नहीं की जा सकती। सारांशतः भारतवर्ष में जीवन-स्तर इतना बिगड़ चुका है कि महा अधिकांश लोग भूख और अधनान रहते हैं। इस सम्बंध में प्रो० मूरसड ने लिखा है एक बड़ा संख्या में मनुष्य शिक्षा या चिकित्सा का प्रबंध नहीं कर पाते और स्वास्थ्यकारी निवासों में मुक्त नगरों में बहुत कम होते हैं। कारीगरों मजदूरों और छोटे छोटे किसानों को भी बाढ़ में वर्षात बमन उपलब्ध नहीं होते, और देश के अनेक भागों में मजदूरों का भोजन उहूँ पूरे दिन परियम करने के लिए बरफ नहीं होता।

नीचे जीवन स्तर के कारण

(Causes of Low Standard of Living)

भारतवासियों के शब्द जीवन-स्तर के निम्नलिखित कारण हैं —

(१) निर्धनता (Poverty) — भारतवासियों के जीवन-स्तर का मुख्य कारण उनकी निर्धनता है। मनुष्य इतने निर्धन है कि उहूँ पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। यह जान कर आश्चर्य होगा कि एक भारतवासी की औसत मासिक आय लगभग पांच रुपया है। धनोपाजन के साधनों का अभाव और धन वितरण की असमानता ही इस निर्धनता का मुख्य कारण है।

(२) अनिज्ञा (Illiteracy) — भारतवर्ष में अनिज्ञता का अर्थ अनिज्ञता है। असमानता के कारण उनका दृष्टिकोण सुकुचित रहता है और उनकी आवश्यकताएँ भी सीमित होती हैं। वे असमानता के अंधकार में डूबे रहने के कारण अपनी सीमित आय का सदुपयोग नहीं कर सकते। अतः उनकी आय का अधिकतर भाग मूर्खता

यात्रा मण्डपान आदि क्लृप्तसत्त्वों की मदा और जय मृत्यु विवाह आदि रीति रिवाजों पर खच होता पाया जाता है।

(३) रूढ़ि-ग्रस्तता (Customs)—योग सामाजिक रूढ़ि रिवाजों और रूढ़ियों व कथना में इस प्रकार जकड़ हुए हैं कि उन्हें प्रतिपादित आचरणों में को कम कर अपना धन सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्बन्ध बनाए रखने में तथा सामाजिक रीति रिवाजों पर खच करना पड़ता है। सामाजिक रूढ़ियों की वास्तविकता का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि क्षिणित सोमा को भी कभी कभी इन पदा पर विवश होकर खच करना पड़ता है।

(४) धार्मिक और नैतिक आदर्श (Religious and Social Ideals)—सादा जीवन और उच्च विचार (Simple living and high thinking) का आदर्श हम देश की संस्कृति का मुख्य अंग है। यह आदर्श हम देश की भौतिक सम्पन्नता और सुख में बाधक सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि आज हम इङ्ग्लैंड और अमेरिका आदि देशों से भौतिक सम्पत्ति और उत्पत्ति में पिछड़े हुए हैं।

(५) भौतिक कारण (Physical Factors)—प्रकृति के कारणों का भी प्रभाव हमारे देश के जीवन स्तर पर पड़ चुका नहीं है। भारतवर्ष एक गम प्रधान देश होने के कारण यहां मौसम जल में अधिक कष्टों की आवश्यकता नहीं होती और शरीर श्रुति में प्राप्त की गर्मी सर्दी को भगाने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार बड़ भगवान का भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राप्ति जल में भीतर का शोक और नाश का संशय पूर्ण सुख देने वाला है और शरीर का शरीर और शरीर में रहना बुरा प्रतीत नहीं होता।

(६) पर्याप्त तथा कुशल यातायात व संचार के साधनों का अभाव (Absence of adequate and efficient means of transport and communication)—पिछड़े और उत्पत्तिशील देशों में पारस्परिक सम्बन्ध में हानि भी पिछड़े हुए देशों में नीचे जीवन स्तर का कारण है।

नीचे जीवन स्तर के परिणाम

(Effects of Low Standard of Living)

भारतवर्ष में अनुप्या का जीवन स्तर बहुत नाबाल है जिससे कारण अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं --

(१) अति जनसंख्या (Over population)—भारतवर्ष में जमीन का जीवन बहुत नीचा है और कारण आवादी बहुत बढ़ती जा रहा है यद्यपि अधिक जनसंख्या का पट भर भोजन भी नहीं मिलता।

(२) कमजोर शारीरिक रचना (Weak Constitution)—अनुप्या का पर्याप्त जल पीने और पहनने का न मिलने के कारण शारीरिक रचना बड़ा कमजोर होती है।

(३) दुर्बल प्लेन (Weak Generation)—एक दुर्बल व्यक्ति का प्लेन का कमजोर होना स्वाभाविक है। यह प्लेन अनेक चीजें कर अक्षम

नागरिक मिट हो सकती है क्योंकि इनका शारीरिक एवं मानसिक विनाश ठीक प्रकार नहीं हो पाता ।

(४) अक्षयता और निबन्धता (Inefficiency and Poverty) नीचा जीवन स्तर मनुष्य की कार्य-कुशलता में हानि कर उसकी समान की प्रति का गिरा देता है जिसमें वह दुर्नतम पारिवर्त्मिक ही प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार वह सदैव दरिद्रता के चपटल में फसा रहता है ।

(५) विविध राधा का शिकार (Victims to various diseases) कर्मज और शरीर बाधा मनुष्य बीमारियाँ को रोकने में अपने आपका प्रयोग पाता है और इसके फलस्वरूप वह सदैव अनेक प्रकार के रोगों में घुल रहा है जिसमें उसका भवितव्य श्रमिकों में बाधा पहुँचती है ।

जीवन स्तर का ऊँचा करने का उपाय

(Methods of raising the Standard of Living)

निम्नांकित उपाय भारतवर्ष में जीवन स्तर को ऊँचा करने में बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं —

(१) अल्प जनसंख्या पर नियंत्रण—जायन स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार की जनसंख्या का अधिकार न बढ़ने दिया जाए । अधिक प्राप्ति में विवाह करों द्वारा निग्रह तथा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिवारों की जनसंख्या का प्रत्यक्ष वर्धन में रोकना चाहिए जिसमें उपभोग के लिए पदार्थ अधिक परिमाण में उपलब्ध हो सकें ।

(२) शिक्षा का प्रसार—निम्न मनुष्य का सम्भवतः एक दूरदर्शी बनता है । अल्प शिक्षित मनुष्य अधिक मजदूरी वृद्धि पर नियंत्रण कर अपने जीवन-स्तर का ऊँचा उठा सकता है । शिक्षा मनुष्य की कार्य-कुशलता का बढ़ती है जिसमें उसकी आय में वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त वह अपनी सीमित आय का उपयोग कर उसमें अधिकतम गुणित कर सकता है । अल्प प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने के अनिवार्य रूप से शिक्षा और व्यापार शिक्षा की व्यवस्था भी आवश्यक है ।

(३) लान स्वास्थ्य आन्दोलन—सरकार की ओर से लान स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रचार होना चाहिए जिसमें लोग आगे-पीछे व स्वच्छता में रहने का महत्त्व का समीक्षा मिल सकती है । स्वास्थ्य रक्षा व चिकित्सा को सम्मान व अनिवार्य स्थान स्थान पर चिकित्सा व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध होना चाहिए ।

(४) राष्ट्रीय आर्थिक योजना का अधीन कार्यन्वित करना देश का अधिक उन्नति होना व वहाँ के निवासियों की आय बढ़ना स्वाभाविक है । योजना का अनुसरण कर उपयोग तथा आर्थिक विकास की उन्नति होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होगी जिसमें लोग व रहने-गहने का स्तर ऊँचा उठ सकता है ।

(५) कृषि की उन्नति—भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जहाँ ८० प्रतिशत में अधिक लोग कृषि में अपना निर्वाह करते हैं । अतः यह आवश्यक है कि विपन्नता गरीबी को उन्नत किया जाए । अधिक व अधिक निचोड़ गरीबी कृषि व्यवस्था को सुविधा विमानों को मिलनी चाहिए । यदि हम चाहें कि हमारा कृषि मीठा उन्नत हो, तो यह आवश्यक है कि हमारे कृषकों को साधन और न भारत में मुक्त कर उन्नत

निग माय का उचित प्रबंध किया जाय। यह समस्या ठीक मुक्तक कानून तथा महकरी साम्य समितियों द्वारा सामान्यी म हन की जा सकती है।

(६) यातायात के साधनों में वृद्धि हो—यातायात के साधन रत मन्त्र माटर जहाँ की वृद्धि हो जिससे दग म अनर वस्त्र आदि उपभाग की वस्तुएँ बढ़ती। यानों में मनुष्य बाहर का अनुभव प्राप्त करता है और अच्छे वस्तुओं का उपयोग करने योग्य है।

(७) प्रवास—प्रवास का भी जीवन-स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी जगह एक ही पग के बादमा अधिक हो और उनकी घाय कम हो तो उनके बहा में बाहर आय प्रकृष्ट स्थान में जाकर रहने में उनकी आय में वृद्धि होगी और उसमें जीवन स्तर ऊँचा होगा।

(८) सम्पत्ति के वितरण में विषमता कम होनी चाहिए—यार दवायिका का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि दग कम सम्पत्ति का वितरण समान हो। यह उचित नहीं कि कुछ लोग तोष विनाशिताया का उपयोग कर और अधिक जनमया को पद भर भोजन भी न मिले।

(९) जमींदारी प्रथा का अन्त हो—किमाना की प्राप्ति दगा का उन्नति के लिए जमींदारी प्रथा का अन्त होना आवश्यक है।

(१०) मिल मानिवा का अत्यधिक मुनाफा कम हो—मिल मानिवा की तोषण प्रवृत्ति में आरंभ श्रमिक वर्ग की दगा गतनीय है। अस्तु किन्हीं मानिवा का मुनाफा कम कर मजदूरों की आय बढ़ानी चाहिए।

(११) गराय आदि हानिकारक वस्तुओं का उपयोग बंद हो—गराय प्रसल य जा तम्बाकू आदि नगीनी वस्तुओं का उपयोग बंद होना चाहिए जिससे प्रभावशालक सब कम होकर स्वास्थ्य अरुण हो सके।

(१२) सामाजिक राति रिवाजों पर अंधविश्वास व अनावश्यक खच बंद हो—सामाजिक नीति रिवाजों पर मनुष्य को के तन्मा अनावश्यक खच करना पड़ता है—जहाँ तक कि कई मानों की कमाई एक ही दो दिन में सम्पन्न कर दो जाती है। ऐसा करना जीवन-स्तर का गिराना है। अस्तु सामाजिक सुधार और गि रा प्रयोग में ही यह प्रवृत्ति दूर किया जा सकता है।

(१३) मुद्रास्फीति का घाय कम किया जाय—आगतवष में मुद्रास्फीति में अत्यंत धन राति गट्ट होनी जाती है। जिससे जमादार बाधाओं सभी मुद्रास्फीति में अपना धन खूबता है। पारस्परिक महिष्णुता के अभाव में सभी-वर्गों में दंड भय प्रसारण कर देता है।

उच्च जीवन स्तर का महत्व

(Importance of High Standard of Living)

इस भौतिक सम्पत्ति के युग में उच्च जीवन स्तर का बड़ा महत्व है। व्यक्ति तथा समाज भी म ही अपनी उन्नति निमित्त दखत है। अस्तु वस्त्रों के ब्यापक प्रयोग करने रहते हैं। बर्ष प्रकार का साज अनमयान तथा विकास का पातनाएँ बनाने में मग्न रहता इसके महत्व का प्रकट करता है। वास्तव में उच्च जीवन का भौतिक उन्नति का और नीचा जीवन-स्तर भौतिक अवनति का चालक न गया है।

महत्त्व व्यक्ति विचार तथा समाज दाना के लिए आवश्यक है।

व्यक्तिगत महत्त्व—जिस व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा होगा है उसको शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता अधिक होती है और वह अधिक उत्पादन कर अधिक आय प्राप्त कर सकता है। उपभोग ने क्षेत्र में भी उच्च जीवन-स्तर वाला व्यक्ति नीचे जीवन स्तर वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आयस्वपनताया की पूर्ति करने के कारण अधिक मजदूरी, तृप्ति और सुख प्राप्त कर सकता है। उच्च जीवन स्तर रखने वाला सुविश्रित तथा सम्यक् होने के कारण सन्तान प्रावश्यकता से अधिक बड़ने नहीं देता है।

सामाजिक महत्त्व—उच्च जीवन-स्तर पर सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक उत्तरी प्रवृत्ति है। उच्च जीवन स्तर वाले समाज की कार्यक्षमता तथा उत्पादन-शक्ति बढ़ी हुई होती है। ऊँचे रहने-महने वाला समाज सम्पत्ति और सुख में परिपूर्ण होता है। ऐसे समाज में मदस्य बड़ा उत्तरीयोन होने है, उच्च वैज्ञानिक प्रगतिमान तथा मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक विचारों के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

उच्च जीवन स्तर का आध्यात्मिक दृष्टि से विचार—बुद्ध महाशय भौतिक उत्तरी की अपेक्षा आध्यात्मिक उत्तरी पर अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार आत्मा और मस्तिष्क की उत्तरी ही जीवन का तथा साधन है। ऐसे मनुज उच्च भौतिक जीवन स्तर के यज्ञाय 'सादा जीवन और उच्च विचार' की महत्त्व बताते हैं। गांधी और टागोर जैसे बड़े-बड़े महापुरुषों ने इसी साधन का प्रचार किया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आलोचना करने हुए यह कहा जा सकता है कि यह केवल आदर्शों की ही वस्तु है। इससे द्वारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक उत्तरी नहीं हो सकती, यस्तु यह सब आध्यात्मिकता को मान्य नहीं। इन भौतिक युग में जहाँ गंगा के सम्य देव अपनी अधिपत्य भौतिक उत्तरी की ओर प्रसर है हम इन नैदानिक आदर्शों के महारे विम प्रकार उनके पीछे में भौतिक उत्तरी में अपना निर ऊँचा रख सकते हैं। यस्तु, भारतीय नवयुवक गांधीजी के इन आदर्शों से पूर्णतया महमत नहीं।

क्या भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ रहा है ?—बुद्ध विद्वानों का मत है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर पतन की अपेक्षा ऊँचा हो रहा है। वे कहते हैं कि हम सुख और विनाश वस्तुओं का बाहर में आयात कर बड़ी मात्रा में उपभोग कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, शहरी में सूती, ऊनी, कुनिम रेसम के वस्त्र, साइकिल, मोटर, अष्ट्रे मरान, तेल, साबुन, पाउडर, मेकअपरेजर, व्हेडम आदि का उपभोग प्रचुर मात्रा में देखा जाता है, यहाँ तक कि धूम्रक भी चाय, सोडावाटर, बर्फ, बीडी मिश्रण मिनेमा आदि में पानी आदि को व्यय करता दृष्टा पाया जाता है। गाँवों में भी प्राधुनिक फैशन के कोट, कमीज, कूट, नैल साबुन, कपा गाइनिंग आदि वस्तुओं का प्रचार बढ़ रहा है। विदेशी आयात, सुख और विनाश की वस्तुओं तथा अष्ट्रे यन्त्रों आदि का उपभोग उत्तरी इस तर्क का आधारभूत है।

इस तर्क का खण्डन करने हुए यह कहा जा सकता है कि विदेशी वस्तुओं का ही आयात बढ़ रहा है कि भीम भारतवासियों के समस्त उपभोग का। इसके प्रतिरुति सुख और विनाश की वस्तुओं का उपभोग केवल घनाश्रय लागू दान हो किया जाता है जो गमस्त जन नर्या का पोडासा हिस्सा है। उन पोडा मस्तिष्क के आधार पर यह देता कि भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ रहा है न्याय-योग्य नहीं है।

हमारे मन वागों का बहना है कि भाग्यवानियों का जीवन-स्तर पहले की अपेक्षा गिर रहा है। सबसे प्रथम कारण यह है कि आजीवन भुगतने समय जैसे पौष्टिक और शुद्ध आशु-मार्ग उपलब्ध हो नहीं होने जिसके कारण आजीवनियों की ओर ध्यान बढ़ने लगा है। भुगतने समय अपने रहने के लिए बड़े-बड़े भवन बना या खरीद लिया करने से, परन्तु आज इन भवनों का प्रयोग-उत्तर भी नहीं है। आज के अनुपात में भवन अपने प्रथम ही भवन हैं कि कोई बचन नहीं है। नतीजा यह है कि भुगतने के बाद बचाव आजीवन आदि बना दिया करने से। आजीवन के निम्नलिखित का अर्थार्थ माला देना पड़ता है और व्यक्ति व निम्नलिखित लोगों ही उनके अर्थार्थ है कि आज का ऊँची दर के कारण अपने जीवन-काल में भुगतने के लिए नहीं होने पाए। ऐसी दशा में क्या जीवन-स्तर कायम रह सकता है ?

निष्कर्ष—दोनों ओर की तरफों का जीवन-स्तर जीवन के प्रथम निष्कर्ष रूप में गरीब रहा जा सकता है कि पहले में तो प्रथम जीवन-स्तर में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि आजीवन मोटरवाहन, विद्युत्, अच्छे भवन आदि एक जीवन रहने। मनुष्य के उपभोग में सम्मिलित है। फिर भी औद्योगिक नगरों की बात बर्णियों के नहीं है। माला, भवन और भवन एक निम्नलिखित रूप में उनके जीवन-स्तर को गिरा रहा है। गाँवों में लोगों की ओर भी औद्योगिक दशा है। छोटे-बच्चे अपने भवन, भवन भवन, मोटे व मनुष्य भवन, प्रथमिष्ट रहने, मनुष्य, विद्युत् व मनुष्य भवन आदि वगैरे जीवन-स्तर को गिराने वाला बन्धुएँ इतिहास होनी हैं। कारण यह है कि मनुष्य व प्रथमिष्ट जन-मनुष्य का तो जीवन-स्तर वर्तमान समय में प्रथम बढ़ा है, परन्तु ६० प्रतिशत मनुष्यों का जीवन-स्तर बर्णों में गिरा हुआ है।

युद्धोत्तर जीवन-स्तर (Post-war Standard of Living) - युद्ध के समाप्त होने पर भी मनुष्यों के भुक्तानों में नहीं रही हुई। जैसे भुक्तानों में व्यापारियों, उद्योगपतियों, उद्योगों आदि को युद्धकाल में और भवन को बचाने का काम पड़े रहा है। उनका पहले ही जीवन-स्तर ऊँचा था, अब भी ऊँचा है। यही है। परन्तु मध्य श्रेणी के मनुष्यों और व्यक्ति को बर्णों की बर्णों में गरीब पड़ना ही का मायना करता पड़ रहा है। मनुष्यों का भवन निम्नलिखित प्रथम है, परन्तु वह मनुष्यों के बर्णों में मनुष्यों से बहुत कम है। मनुष्य, उनका रहने-सहने का पड़ा पहले की अपेक्षा और भी गिर गया है। विमानों की अवस्था प्रथम ही कुछ सुधरे गई है, क्योंकि खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ गया है। परन्तु फिर भी उनके जीवन-स्तर में बड़ी परिवर्तन नहीं हुआ, केवल निम्नलिखित बढ़ गया है। वे लोग विमान के अभाव में मनुष्य-भोजन, विद्युत्, मनुष्य आदि पर पहले की अपेक्षा अधिक व्यय कर रहे हैं। जीवन-स्तर को ऊँचा करने के उद्देश्य से परिपूर्ण बर्णों के अधिक कीमतों देना में उन चुकी है जिनमें से जन-भोजन, गाँवों और बर्णों के योजनाओं के साथ सम्बन्धित हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्त पर है। योजना बनाने में अधिक महत्वपूर्ण स्तरों का सम्बन्धित करना है। इन दशा में भी कार्य प्रारम्भ करना निम्नलिखित आवश्यक है।

अर्थशास्त्र प्रश्न

डाक्टर आई.म.प.प.प.

१—भारतवासियों के रहने-सहने के स्तर के नीचा होने के क्या कारण हैं ? इसे किस प्रकार ऊँचा किया जा सकता है ?

(७० प्र० १९६०)

२—रहन-सहन के स्तर से आप क्या समझते हैं ? यह किन किन बातों पर निर्भर है ?
(उ० प्र० १६५८)

३—जीवन मान से आप क्या समझाया जा सकता है ? क्या आवश्यकताओं की बहुलता सदा जीवन-मान में वृद्धि उत्पन्न करती है ? अपने मत का समर्थन कीजिए ।
(प्र० बों० १६५९)

४—भारतवासियों के शैक्षणिक मीचे रहन-सहन के दर्जे के क्या कारण हैं ? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण जनसांख्यिक है ? कारण सहित उत्तर दीजिए ।
(अ० बों० १६५४)

५—रहन-सहन के दर्जे में क्या आशय है ? एक भारतीय कृषक या श्रमिक के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं ? (अ० बों० १६५२)

६—भारतीय कारखाने में काम करने वालों श्रमिक के जीवन-स्तर पर सशक्त नोट लिखिए ।
(म० भा० १६५६)

७—रहन-सहन के दर्जे में क्या आशय है ? यह किन-किन बातों पर निर्भर है ?
(उ० प्र० १६५८, सागर १६५०)

८—किसी व्यक्ति के रहन-सहन के दर्जे को निर्धारित करने वाली बात कौन-कौन सी है ? क्या आप 'मादा जीवन उच्च विचार' के आदर्श में विद्वान रहते हैं ? क्या ऊँचे रहन-सहन के दर्जे से सदा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । सकारण उत्तर दीजिए ।
(रा० बों० १६५३)

९—भारत के निर्धन व्यक्तियों के रहन-सहन का दर्जा किस प्रकार स्थायी रूप से ऊँचा किया जा सकता है ?
(नागपुर १६४६)

१०—रहन-सहन के दर्जे से क्या आशय है ? यह किन-किन बातों पर निर्भर है ? भारत में रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने का क्या महत्व है ? (सागर १६५०)

११—आवश्यकताओं और रहन-सहन के दर्जे में क्या सम्बन्ध है ? क्या आवश्यकताओं की संख्या में वृद्धि सर्वत्र सामंजस्यपूर्ण होती है ?
(पनाम १६४६)

१२—एक विदेशी पत्रकार का मत है कि 'भारत में निर्धनता नहीं है।' उसकी दलीलें निम्नलिखित हैं :-

(अ) भारत में राजा, महाराजाओं के विशाल सहाय और सहाय पजाने हैं ।

(आ) प्रतिदिन सिनेमा में अपार भीड़ रहती है । क्या आप इस मत से सहमत हैं ।
(बिल्सी हा० मे० १६४०)

१३—रहन-सहन के स्तर पर टिप्पणी लिखिए ।

(सागर १६५५, नागपुर १६५१, उ० प्र० १६४०, अ० बों० १६५१, ४३, ४०)

इण्टर एप्रोक्वियर परीक्षाएँ

१४—रहन-सहन के दर्जे का क्या आशय है ? क्या भारत में रहन-सहन का दर्जा नीचा है ? इसमें किस प्रकार सुधार हो सकता है ?
(उ० प्र० १६५१, ४८)

१५—जीवन-स्तर से क्या समझते हैं ? देहाती में यह नीचा क्यों है ? यह किस प्रकार ऊँचा किया जा सकता है ?
(अ० बों० १६५५)

आय (Income)

ज्या जहाँ भौतिक सम्पत्ता का विकास होता गया तथा तब तब मनुष्य की आवश्यकताओं की तुलना अपेक्षित रूप में होती जाती है। इस सम्पत्ता के प्रारम्भिक काल में आवश्यकताओं की तुलना प्रत्यक्ष रूप में होती थी। उदाहरणार्थ भूमि लगाता जगत् में पत्तों काटकर या पत्तों की मार कर अपनी दुष्टता को दूर करने परन्तु आज का जगत् हमें विपरीत दृष्टि देता है। आज मनुष्य कोई भी उद्योग करे उस पारिस्थितिक मुद्रा (Money) के रूप में निर्यात। यह उस मुद्रा में दृष्टिगत वस्तुओं की खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही आवश्यकताओं की पूर्ति का अपेक्षित रूप है। अब भी सोचा में आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतर प्रत्यक्ष रूप में होती है तथाकिन्तु वही का क्षत्रपण और यहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं सम्मिलित है। मनुष्य की आवश्यकताओं सीमित है। अथवा अनामित इस उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न प्रवृत्त करता पड़ता है। जिन प्रयत्नों में धन का उत्पादन होता है आर्थिक प्रयत्न कहलाता है। आर्थिक प्रयत्न के फलस्वरूप जो धन प्राप्त होता है उस हम आय कहते हैं। मनुष्य अपनी आय का उन वस्तुओं के खरीदने में खर्च करता है जिनके प्रयोग में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। आय के उस प्रयोग का जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण की जाती है, अर्थशास्त्र में व्यय कहते हैं। प्रो० डा० एस० पन्मन ने प्रयत्न, आय और तुलना को निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा समझाया है —



प्रयत्न, आय और तुलना
(Efforts, Income & Satisfaction)

आय का उपयोग
(Disposal of Income)

मनुष्य आय अपनी आय का उपयोग दो प्रकार में करता है—
व्यक्तिगत दृष्टि में और सामाजिक दृष्टि में, जगत् के नीचे स्पष्ट किया गया है।

(१) व्यक्तिगत दृष्टि में उपयोग—(क) खर्च (Spending),
(ख) बचत (Saving)

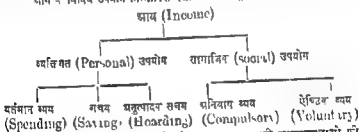
आय, व्यय और बचत]

- (स) अनुत्पादक संचय (Hoarding)
(गाढ़ता या निरर्थक षडा रचना) ।
(२) सामाजिक दृष्टि से उपयोग—(घ) अनिवार्य (Compulsory) व्यय,
(व) ऐच्छिक (Voluntary) व्यय ।

(१) व्यक्तिगत दृष्टि से उपयोग—मनुष्य अपनी आय का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में तीन प्रकार से कर सकता है—(अ) वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति से उत्पन्न की गई आय को उगता 'व्यय' या 'व्यय' (Spending) कहते हैं । (ब) उनकी भारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय का जो भाग रखा जाता है उसे उगती बचत या 'संचय' (Saving) कहते हैं । इस प्रकार की संचित आय वंश प्रादि की उधार देकर, कृषि उद्योग भण्डो, अस्पादक उत्पादक (Productive) कार्यों में लगाकर रमा जाती है । (स) जो संचित आय जमीन में गाढ़ कर निजोरी में प्रयत्न जेवर प्रादि में रूप में रखी जाती है उसे 'अनुत्पादक संचय' या 'व्यय' (Hoarding) कहते हैं । इस प्रकार की व्यय किसी भी उपयोग में नहीं आती, बल्कि निरर्थक पड़ी रहती है । अस्तु इसका अनुत्पादक (Unproductive) संचय या बचत कहा जाता है ।

(२) सामाजिक दृष्टि से उपयोग—सामाजिक दृष्टि से व्यय होने वाली आय को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—(घ) एक भाग वह है जिसमें हमें विविध प्रकार (Types) के रूप में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों तथा नगरपालिका व जिन्ना बोर्ड जैसी स्थानीय संस्थाओं को अनिवार्य रूप में देना पड़ता है । (व) दूसरा भाग वह है जो हम अपनी दृष्टानुसार दात प्रादि में व्यय करते हैं ।

आय के विविध उपयोग निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा पूर्य स्पष्ट हो जाते हैं —



व्यय आय का वह प्रयोग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करता है ।

व्यय (Spending)

बहुत से मनुष्य यह कह सकते हैं कि व्यय करना कोई बर्तन कार्य नहीं है खर्च करना तो सभी जानते हैं । वास्तव में ऐसा जान तो यह व्यय धारणा है । यह कहता किन्तु ठीक होगा कि व्यय करना एवं बचना है जिसका पर्याप्त ज्ञान सब को नहीं होता । बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें यह नहीं मायूम कि धन का पत्र और निम प्रकार खर्च करना चाहिए जिससे अधिकतम सुख प्राप्त हो सके । सभी सा के रूप से हो बैठते हैं और सभी अपव्ययी होकर द्रव्य का निरर्थक नामा में उड़ाने लग जाते हैं । यही कारण है कि वे अपने धन या आय से अधिकतम सुख नहीं प्राप्त कर पाते ।

व्यय का आर्थिक पहलू (Economic Aspect of Spending)

व्यय के सिद्धान्त (Principles of Spending)—मनुष्य को जो वृत्ति अपनी आय के व्यय से प्राप्त होती है वह दो बातों पर निर्भर है—(अ) व्यय के ढंग, और (आ) वस्तुओं का मूल्य ।

(अ) व्यय के ढंग (Methods of Spending)—हम बहुधा यह सुनते हैं कि समुद्र व्यक्ति व्यय करने में निपुण है और समुद्र नहीं इसका तात्पर्य यह है कि व्यय करने में निपुण व्यक्ति कुछ व्यय के सिद्धान्तों को समझते हैं और अन्य नहीं ।

व्यय की सफलता निम्नलिखित सिद्धान्तों पर निर्भर है—

१—आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान—सर्व प्रथम एक सफल जीता को अपनी आवश्यकताओं का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए । उसे विजेता के यद्दानों में भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष लोगों की देखा देती में वस्तुएँ नहीं खरीद लेनी चाहिए । उसे कोई वस्तु केवल इसलिए कि वह सस्ती या सुन्दर है नहीं खरीदनी चाहिए ।

२—वस्तुओं के गुणों का विशेष ज्ञान—बहुधा यह देखा जाता है कि एक ही प्रयोजन के लिये कई एक वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध होती हैं । ऐसी अवस्था में जीता को चाहिए कि वह उनके गुणों का निरूपण करे और उन वस्तुओं को खरीदे जो वास्तविक रूप में प्रयोक्त प्रयोजन सिद्ध कर सकें । बाहरी दिखावट या रंग रूप में आकर्षित होकर नहीं खरीद लेना चाहिए बल्कि टिकाऊपन का भी ध्यान रखना चाहिए ।

३—सौदा करने में कुशलता—कुछ व्यक्तियों में यह गुण देखा जाता है कि वे दूसरों की प्रेषण कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीद लेते हैं । वे लोग सामारगताया विक्रिता जो मूल्य मंगी नहीं देते बल्कि आवश्यक (Higgly) के पक्षान् देते हैं । साथ ही में यह भी आवश्यक है कि 'निश्चित मूल्य' (Fixed Rate) वाली दुकानों पर आवश्यकता में अर्ध समय नष्ट नहीं करना चाहिए ।

४—उत्तम वय ध्यान की जानकारी—सफल जीता को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किस स्थान पर अच्छी और सस्ती वस्तुएँ मिलती हैं । वहाँ तक जाने का कष्ट उठाने के लिए उसे सदैव तैयार रहना चाहिए ।

५—उचित क्रय समय का ज्ञान—अपेक्षित वस्तु उचित समय पर खरीदी जानी चाहिए । जैसे ईंधन वर्षा ऋतु से पहले, गेहूँ फसल के तैयार होने ही खरीद लेना चाहिए ।

६—वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की तुलना—कुछ व्यक्ति वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच तुलना करने में बड़े कुशल होते हैं । वे तुलनात्मक दृष्टि से इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाय, वर्षान् व्यय करने समय का पूरा पूरा ध्यान रहता है ।

(आ) वस्तुओं का मूल्य—उपरोक्त बातों ने अनिश्चित मनुष्य को जो वृत्ति अपनी आय के व्यय से प्राप्त होगी है वह काफी अरा तथा उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर निर्भर है जिन पर वह अपनी आय को खर्च करता है । यदि वस्तुएँ सस्ती मिलती हैं तो मनुष्य अपनी आय में अधिक वस्तुएँ खरीद कर अधिक वृत्ति प्राप्त कर सकता है । यदि वस्तुएँ महँगी हैं, तो वह अपनी आय में कम वस्तुएँ खरीद लेगा । जगत वृत्ति भी कम होगी ।

व्यय स्थान (Places of Spending)

साधारणतया ग्राहक बिना दुकान पर जाकर अपनी खरीद वस्तुओं के द्वारा देना न कर वस्तुओं की खरीद करता है। परन्तु ऐसा भी देखा जाता है कि ग्राहक दुकानदार के पास न जाकर दुकानदार ग्राहक की पास पहुँच जाता है। चाहे हम सब प्रकार के व्यय स्थानों का वर्णन करें —

(१) फेरीवाले (Hawkers)—ये लोग ग्राहकों के पास पहुँचने वाले व्यापारी होते हैं। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ किसी ठोस टोकरी या गाँठ में बाँध कर बिक्री वाली माहौल में गाँव गाँव में जाकर बेचने देते हैं। साधारणतया इस देश में बिना दुकानों पर सामान खरीदने बड़ा जाता है। अक्सर फेरीवाले लोगों द्वारा विज्ञापन देने की वस्तुएँ चूड़ियों गोंग बिनारी बपड़ा बदन आदि पर बाँधे खरीद लेती हैं। इस प्रकार ऐसे छोटे गाँवों में व्यापारी दुकान न होकर फेरीवाले प्रामोदयोगी वस्तुएँ ले जाकर बेचते हैं।

(२) पैठ—(Periodical Markets) पठ उन बाजारों को कहते हैं जो स्थान स्थान पर मासिक अर्द्ध मासिक या पारिवारिक मर्यादित मर्यादित दिनांक समय पर लगते हैं जिनमें लोग अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का खरीद-विक्री करते हैं। यह प्रथा कर्नाट और मद्रास में भी प्रचलित है। पठ के दिन गाँव वाले अपने घरों का छुड़ा रख कर वस्तुओं की खरीदने में व्यस्त रहते हैं।

(३) मेले (Fairs)—बाजार भी इस देश में समय-समय पर लगते हैं जो विविध धार्मिक होते हैं। इन मेलों में दूर-दूर से यात्री आकर भाग लेते हैं। बहुत से दुकानदार भी अपना अपना सामान बेचने के लिए लाते हैं। वहाँ मनुष्य का अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदने की अधिक सुविधा मिल जाती है। गुजरात में मुम्बई और पुणे के मेल इस मीटिंग में आते हैं।

(४) दुकानें (Shops)—जिस प्रकार फेरीवाले पठ और मेले में गाँव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं उसी प्रकार नगरों में स्थायी दुकानें देखी जाती हैं। इस प्रतिष्ठापना शुरुआत में दुकान ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा गली हुई होती है। कई दुकानदार तो साधारण उपयोग की वस्तु ही वस्तुएँ रखते हैं और कई बेचने विविध प्रकार की वस्तुएँ ही रखते हैं। तब भी प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिलने के कारण वे विविध प्रकार या मर्यादा बढाती हैं जैसे धातु मर्तल मर्तल बपड़ा बाजार मर्तल बाजार आदि। नगरों में ऐसा भी देखा जाता है कि एक बड़ा दुकान की कई विभागों में विभक्त कर दिया जाता है जिसमें छाती में गहरा वस्तुएँ तक एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकती है। ऐसा दुकानों को बहु विभागीय भण्डार (Departmental Store) कहते हैं।

(५) प्रदर्शनी (Exhibition)—प्रदर्शनी या नुमायश कला और विज्ञान के माध्यम से स्थापित करने का सुप्रसिद्ध प्रदान करती है। प्रदर्शनी में दूर-दूर से उत्पादक विपणन एवं व्यापारी अपनी अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं जिसमें दर्शकों की अपनी आवश्यकताओं की मर्यादा का खरीदने के प्रतिरूप यह भी जानकारी हो जाता है कि अधिक वस्तु कहाँ अच्छी बिकती है। प्रदर्शनी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कई कारोबारों की वस्तुओं का विज्ञापन होता है जिसमें इन वस्तुओं की माँग में वृद्धि होकर उनका उत्पादन बढ़ता है। दर्शन प्रतिरूप शरीर की वृद्धि की वस्तुओं में अपनी वस्तुओं का मुकाबला कर कमियाँ

को मान्य कर लेने का अवसर मिल जाता है जिससे माल की किरप घटती हो सकती है।

व्यय का सामाजिक पहलू (Social Aspect of Spending)

यद्यपि हमने व्यय के आर्थिक पहलू पर विचार किया। अब इसके सामाजिक पहलू पर विचार किया जायगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका समाज में व्यय कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य उन चीजों का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता जब तक समाज के अन्य सदस्य भी उनमें प्रभावित होते हैं। मनुष्य की अन्य श्रियाओं की भाँति उसके व्यय करने की क्रिया का भी प्रभाव समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य स्वास्थ्य-संरक्षक और उत्तम पदार्थों पर अपनी आय व्यय कर, अपनी कार्य-क्षमता में वृद्धि कर सकता है, समाज के घनी होने में सहयोग दे सकता है, और अन्य सदस्यों के लिए धारण स्थापित कर सकता है। इसके विपरीत, वह मादक तथा हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग में अपनी कार्य-क्षमता में हानि कर समाज की निर्धन बना सकता है और अन्य समस्या को अग्रव्यय करने के लिए गलत रास्ता बता सकता है। इस प्रकार मनुष्य के प्रत्येक चयन या बुरे कार्य का प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ सकता है। संक्षेप में, समाज की उत्पत्ति काफी दूर तक लोगों के व्यय करने के ढंग पर निर्भर है। यदि व्यय का ढंग अच्छा है, तो समाज भी उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं।

व्यक्तिगत व्यय का समाज पर प्रभाव दो प्रकार से देखा जा सकता है :—

(अ) उत्पत्ति पर प्रभाव, (आ) उपभोग पर प्रभाव।

(अ) व्यय का उत्पत्ति पर प्रभाव (Effects on Production)

(१) यह तो सभी जानते हैं कि उत्पत्ति माँग पर निर्भर है। जिस वस्तुओं की माँग होगी उसकी उत्पत्ति की जाती है। जिस वस्तु पर हम व्यय करते हैं उसकी माँग पैदा हो जाती है और उसकी उत्पत्ति के लिए साधन जुटाने लग जाते हैं। धीरे धीरे उस वस्तु की उत्पत्ति की जाने लगती है।

(२) वह वस्तु जिसकी माँग बढ़ती है यदि श्रिताम-वस्तु है, तो उपभोक्ता की कार्यक्षमता में वृद्धि आती जिसका फल बेहतर उम उपभोक्ता की ही नहीं बल्कि सारे समाज की भुगतना पड़ेगा। कारण, जब उस वस्तु की माँग है, तो उसकी उत्पत्ति आवश्यक होगी। देश की पूँजी और श्रम का एक भाग हम और श्रित प्रायोगों जिसका प्रयोग अन्य आवश्यक और लाभदायक उद्योग-व्यवसायों में किया जा सकता है। इसका यह परिणाम होगा कि आवश्यक और वस्तुनिष्ठ पदार्थों की उत्पत्ति बढ़ जायेगी।

(३) यदि कोई मनुष्य अपनी आय को सौव-सामग्री कर स्वास्थ्य-वर्धक भोजन, वस्त्र तथा मनोरंजन आदि पर व्यय करता है, तो उसकी कार्य-क्षमता और उत्पादन शक्ति में अग्रव्यय वृद्धि होती है।

(४) व्यक्तिगत व्यय के फलस्वरूप यदि श्रमिकों को ऐसे कारखानों में काम करना पड़ता है जहाँ आरोग्यवर्धक जलवायु और अनुकूल वातावरण का पूर्ण अभाव हो, तो समाज को बड़ी हानि पहुँचती है।

(५) यदि उद्योग ऐसे होने दें जिनमें उत्पत्ति बड़े पैमाने पर की जाती है जिसके कारण जिन इकाई उत्पत्ति-व्यय कम हो जाता है। यदि लोग इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर व्यय करते हैं, तो समाज को लाभ होता है। इसके अलावा, उन उद्योगों की बनी हुई वस्तुओं पर जिनका उत्पत्ति न्यून अधिक है, व्यय करने में समाज को हानि है।

(अ) व्यय का उपभोग पर प्रभाव (Effect on Consumption)

(१) धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा बुद्धि विनाश वस्तुओं का अत्यधिक उपभोग से मांग बढ़ जाने के कारण उच्च मूल्य में इनकी वृद्धि हो जायगी जिससे सामान्य श्रमिकों के लोग उन वस्तुओं के उपभोग उपयुक्त मात्रा में नहीं कर सकेंगे। यथा कनकमय उतारे स्त्रोत्रों के लोभ उन्माद और बाय काननो में निविन्ता होना जायगी। इतना भविष्य में उत्पत्ति और भी कम हो जायगी जिससे समाज का हानि होगी।

(२) मनुष्य दूसरा का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति द्वारा ही प्रायः सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आती है। यदि एक व्यक्ति दूसरे को मजदूरान् प्रेरित करता है तो उच्च मूल्य में रहना बाधक धारण करने के लक्षण बनने के और फिर उन लोगों के प्रभाव में इनका प्रचार फैलता जाता है जिससे कनकमय समाज की बड़ी हानि पहुँचती है। इस प्रकार मनुष्य का प्रभाव दूसरे उपभोग का दूसरा पर प्रभाव पड़ता है।

व्यय में राज्य द्वारा हस्तक्षेप (State Intervention in Expenditure)

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यदि लोग व्यय मान सम्भल कर अपने व्यय को उचित ढंग से व्यय नहीं करने तो समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्पत्ति कम हो जाती है उपभोग की मांग बुजबुजती है सभी धन लगती है और धीरे धीरे समाज का जीवन चक्र गिरने लगता है। अतएव सामाजिक दृष्टि से यह देवता आवश्यक है कि लोग अपने व्यय को जिस प्रकार व्यय करते हैं।

विविध विचारधाराएँ—इस विषय पर कि राज्य द्वारा व्यय में हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं या विचारधाराएँ प्रचलित हैं। जो व्यक्ति हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं उनका कहना है कि सरकार का यह कृतव्यय नहीं है कि वह किसी व्यक्तिगत व्यय में हस्तक्षेप करे। प्रत्येक व्यक्ति की आय उसके परिधर्म का फल है अतः उसने उपभोग में सरकार द्वारा हस्तक्षेप होना उचित नहीं। सरकार का कृतव्यय तो यही होता है कि वह देश की रक्षा का प्रयत्न करे और देश में भीतर शांति व विधि स्थापित करे। जो व्यक्ति हस्तक्षेप के पक्ष में हैं उनका कहना है कि राज्य को सामाजिक दृष्टि से रगते हुए व्यय का नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत व्यय के अनुचित ढंग का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत मूल्य स्वतन्त्रता समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उचित धारणा इन दोनों मतों के मध्य है। आदर्शन अधिकांश लोगों का यह मत है कि सामाजिकता प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आय के उपभोग में स्वतन्त्रता होती चाहिए किन्तु यदि उसके उपभोग में स्वयं का धनवा समाज का अनिष्ट दिखोकर होता हो तो राज्य द्वारा अवश्य हस्तक्षेप होना चाहिए।

व्यय में राज्य द्वारा हस्तक्षेप के ढंग—व्यय में राज्य द्वारा निम्न हस्तक्षेप किया जाता है—

(१) विधि द्वारा (By Law)—कानून द्वारा किसी वस्तु विनाश का उपभोग बंद किया जा सकता है यद्यपि उसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्राचीन समय में मृत्यु के कई देवों में प्रचलित विनाश वस्तुओं के उपभोग विषय कानून (Sumptuary Law) इसके उदाहरण हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में स्पेन में विनाश वस्तुओं के बन्द होने के लिए उनके निर्माण

विषय तथा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इसी प्रकार इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय ने शासन काल में ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये एक कानून बना जिसके द्वारा मृतक शरीर को भी ऊनी कफन में लपेट कर गाड़ना अनिवार्य था।

भारतवर्ष में हस्तक्षेप—भारतवर्ष में इस प्रकार का राज्य नियंत्रण प्राचीन काल से ही प्रचलित है। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य शासनकाल में अनुचित वस्तुओं के उपभोग को रोकने के लिए इस प्रकार के कई कानून प्रचलित थे। उनके अनुसार चार नौने मदिरा भी सरकारी खाजा बिना केवल उस व्यक्ति को ही जाय जिसके ज्ञान-चलन के बारे में पूर्ण जानकारी हो और मदिरापान माघारणतया मदिरालय में ही किया जाय। इसके अतिरिक्त मदिरानियों में सरकारी गुप्तचरों की व्यवस्था भी कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वारा पाई जाती है।

प्राधुनिक काल में भी भारतवर्ष में इस प्रकार के अनेक कानून देखे जाते हैं। जैसे मदिरा, फल्लेम, गाँजा, कोकीन, तिजाय, विष आदि वस्तुओं के रखने, दिखाने तथा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इनके विक्रेता को राज्य में लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है तथा राज्य द्वारा इनके विषय म्यान और मध्य भी निश्चित किये जाते हैं। आशक्त की मरनिषेध (Prohibition) नीति इसी नियम की प्रतीक है। धी, दूध आदि पात्र-पदार्थों के अशुद्ध मिश्रण (Adulteration) को रोकने के लिए भी सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं।

युद्धकाल में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण रग हो जाने के कारण उनके मन्थन में न मिलने के भय से लोग अपने उपभोग में अधिक मात्रा में वस्तुओं का निश्चक संग्रह करना प्रारम्भ कर देने हैं जिससे जन साधारण का उपभोग कम हो जाता है। अन्तु रार्शासिग तथा मूल्य-नियन्त्रण द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं की वितरण व्यवस्था की जाती है। युद्धोत्तर काल में सर्वात् आशक्त भी उसी विषय परिस्थिति के कारण रार्शासिग और मूल्य-नियन्त्रण व्यवस्था राज्य द्वारा प्रचलित है। फल्लेम आदि स्वाध्म-वादाक वस्तुओं का भी रार्शासिग प्रारम्भ हो रहा है जिससे कुछ समय पश्चात् लोग इस व्यवस्था से मुक्त हो सकें।

(२) मूल्य-निर्धारण द्वारा (By Fixing Prices) - कई वस्तुओं का अधिकतर, न्यूनतम या कोई उचित मूल्य निश्चिन कर दिया जाता है, जैसे—गुड़, चक्र, गेहूँ, पपड़ा आदि का। इसी प्रकार किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए कई प्राती में ईंट के न्यूनतम भाव निश्चित कर दिये गये हैं। यह मूल्य को प्रभावित करने का प्रत्यक्ष रूप है।

(३) कर द्वारा (By Taxes) - राज्य द्वारा किसी वस्तु का उपभोग कम करना चाहे तो उस पर कर लगा दिया जाता है। जैसे मदिरा, खोशे, मिगरेट आदि पर भारी कर लगाकर इनके उपभोग को कम किया जा सकता है। इस रीति द्वारा मूल्य अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित हो जाते हैं। यदि विदेशों में जाने आने वस्तुओं का उपभोग रोकना चाहें, तो भारी आयात कर दिया जाता है।

(४) आर्थिक सहायता द्वारा (By Subsidy) - यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु की उत्पात्ति या उपभोग में वृद्धि अभीष्ट है तो उसके उत्पादकों का आर्थिक या धन्य रूप में सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

संचय (Saving)—भाषारण्यभा हम अपने भाय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय नहीं कर देते । वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हम भावी आवश्यकताओं या भी ध्यान रखते हैं । इसलिए हम अपने भाय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाने हैं जिससे भागे चलकर आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े । इन धनी हुई स्वरूप को कुछ लोग तो जमीन में गाड़ देते हैं अथवा तिजोरी में बन्द कर रखे रहते हैं और कुछ उत्पादक कार्यों में लगाते हैं । संचित द्रव्य का वह भाग जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी उत्पादक (Productive) रूप में रखा जाता है, संचय (Savings) कहलाता है ।

अनुत्पादक संचय (Hoarding)—संचित द्रव्य का वह भाग जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अनुत्पादक रूप में रखा जाय अनुत्पादक संचय (Hoarding) कहलाता है ।

संचय और अनुत्पादक संचय में अन्तर

(Difference between Saving and Hoarding)

वेना ही भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचय किया द्रव्य है परन्तु जो भाग उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है वह 'संचय' कहलाता है और जो भाग अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाता है, वह 'अनुत्पादक संचय' है । इसको एक उदाहरण से इस प्रकार समझिए । किसी व्यक्ति के पास तीन हजार रुपये संचित हैं । इसमें से यदि वह एक हजार रुपये बैंक में व्याज पर जमा कर देता है या किसी व्यवसाय में लगा देता है, और शेष दो हजार की तिजोरी में बन्द कर रखता है या जमीन में गाड़ देता है, तो एक हजार रुपये तो उसका 'संचय' (Saving) है, और शेष दो हजार रुपये 'अनुत्पादक संचय' (Hoarding) है ।

संचय और अनुत्पादक संचय तुलनात्मक दृष्टि से—संचित द्रव्य संचय करने वाला तथा देश दोनों की ही लाभदायक है । बैंक में रुपये जमा कराने वाला अपने रुपये को आवश्यकता के समय काम में तो ला सकता है, परन्तु नाम ही साथ जब तक बैंक में जमा रहता है, व्याज और मिलता है । यह रुपये बैंक द्वारा उद्योग-पटिया, व्यापारियों, कुपकों आदि को उपार दिया जाता है जिससे देश की आर्थिक उत्थिति होती है । इसके विपरीत अनुत्पादक संचय उसके स्वामी और देश के लिए एक बड़ी हानि है । निरर्थक रूपसे बड़ी पड़ा या पड़ा रहने से चलन की माशा में कमी होती जाती है । जिससे विनिमय-मन्चालन में कठिनाइयाँ तथा असुविधाएँ उपस्थित हो जाती हैं । यह द्रव्य कार्य में नहीं आने के कारण इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, अस्तु देश के आर्थिक विकास में कोई सहायता नहीं मिलती है । अतः संचय ही देश की उत्थिति व समृद्धि का मूल तत्त्व है ।

संचय के उद्देश्य (Objects of Saving)—मुख्य निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित होकर संचय करता है :—(१) व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए (२) वृद्धावस्था के लिए साधन उपस्थित करके के लिए, (३) अपने धर्म और आश्रितों के लिए साधन उपस्थित करने के लिए, व (४) सामाजिक प्रतिष्ठा व स्याति प्राप्त करने के लिए ।

सचय निर्णय कैसे किया जाय ? सभ सीमान्त उपयोगिता के प्रसिद्ध नियम द्वारा मनुष्य को अपने धन्य के समायोजन में बड़ी सहायता मिलती है। इससे द्वारा एक विवेकशील मनुष्य अपनी आय की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार समायोजन करता है कि आय का कुछ भाग भविष्य के लिए भी बचा लिया जाता है।

व्यय और सचय का सम्बन्ध

(Relation between Spending & Saving)

व्यय और सचय का सम्बन्ध अग्रजी ग्रयगात्री प्रो० वमन दास भा. भा. नि. समझाया गया है। व्यय और सचय में एक बात समान है। दोनों में इन्धन व गुश्ता और सेवाओं के साथ निमित्त होता है किन्तु अंतर यह है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग समान नहीं होता है। व्यय में वस्तुएँ और सेवाएँ आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रथम रूप में प्रयुक्त की जाती हैं मन्वय में वे वस्तुएँ और सेवाएँ अनिवार्यता के लिए प्रयुक्त की जाती हैं और इच्छित प्रयोजन रूप में नहीं। अर्थात् अग्रज्य रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उदाहरणार्थ यदि कोई मनुष्य जो १०० बीघा अनिश्चित पत्तीचर (उपस्कर) पर व्यय करने को या अपना विचार बन कर इस पत्ती से नवीन आधिपकार और बन खरीदता है जिसकी सहायता से वह उतने ही समय में अधिक काम कर सकेगा तो वह स्वयं के वदन सचय को स्वाभाविक करगा दोनों बर्णों में खरीद ही होती किन्तु खरीदी हुई वस्तु को उपभोग व स्थान पर उत्पादन काम में लिया गया है।

इस प्रकार बात होता है कि व्यय और सचय दोनों हमारे प्रतिदिन व प्रतिवर्ष जीवन के आवश्यक अंग हैं। इन की उत्पत्ति भेदों से उत्पन्न होता है कि इनके उपयोग की इच्छा विद्यमान है। किन्तु क्योंकि पूँजी जो सचय का परिणाम है इन का उत्पत्ति का मुख्य साधन है इसलिए इन को वर्तमान उपयोग व रिक्त ही नहीं करन भविष्य के उपयोग के लिए भी उत्पन्न किया जाता है।¹

सामाजिक दृष्टि से व्यय अधिक महत्वशाली है या सचय ?

व्यय और सचय इन को प्रयोग करने के दो ढंग हैं। दोनों का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अंतर केवल इतना ही है कि व्यय वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सचय से भावी आवश्यकताओं की। व्यय और सचय दोनों ही आर्थिक उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं।

व्यय (Spending)—कुछ लोगों का कहना है कि अधिक व्यय करने में ही समाज की उत्पत्ति हो सकती है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वे इस प्रकार तर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि लोग अधिक व्यय करेंगे तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। इससे उत्पत्ति बढेगी और जब उत्पत्ति में वृद्धि होगी तो पूँजी और श्रम को अधिक काम मिलने लगेगा। इसके फलस्वरूप बेकारों की समस्या हल हो जायेगी और मजदूरों की मजदूरी बढ जायेगी। व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अधिक लाभ होने लगेगा। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त उत्पत्ति होगी। लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो जायेगा और देश की आर्थिक दशा सुधर जायेगी। यह बात बड़ा तर्क

येक है यही हम देना है। उत्पत्ति बढ़ाने के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी की मांग सभी बड़ गन्ती है जब कि सोय चांगी आय का प्रसार भाग देगा। यदि लोग अपनी पूरी आय वर्तमान आवश्यकताओं की ही पूर्ति में लगा देंगे तो फिर सबकुछ बढ़ा में हो सकेगा। सचय या सचय न होने से भविष्य में पूँजी बढ़ा स पायगी। देश की उन्नति एक जायगी और तरह तरह के आर्थिक कष्टों का सामना हम करना पड़ेगा। अस्तु यह भोचना मूल है कि अधिक व्यय करने में समाज की भलाई है।

सचय या वचन (Savag)

इस विपरीत बुद्धि लोग का यह विश्वास है कि अधिक सचय करने में व्यक्ति और समाज दोनों की ही उन्नति होगी। अधिक सचय करने पर ही पूँजी की मांग बढ़ेगी। हमारी सहायता में उत्पत्ति यह पैमाने पर की जाने लगेगी। इस प्रकार उन्नति का चक्र चलता रहेगा। किन्तु प्रश्न यह है कि उत्पादित वस्तुओं को खरीदने कौन? जब लोग व्यय कम करेंगे तो वस्तुओं की मांग कहीं से होगी? कैसे उनका रूप विक्रम होगा? आहों की सभी होने के कारण वस्तुएँ गोदामों में पड़ी पड़ी सड़न लगनी। उत्पादकों को बड़ी क्षति पहुँचनी जिसके फलस्वरूप में उत्पत्ति का कम कर देगा। उत्पत्ति का घटाने में लोग बकाय हो जायेंगे। उनके आर्थिक जीवन को एक गहरा घटा लगना। समाज की भी उन्नति रुक जायगी। अनेक आर्थिक समस्याओं का कारण समाज का बना घुटने लगेगा।

निष्कर्ष (Conclusion) - इससे यह सिद्ध होता है कि व्यय और सचय



दोनों ही आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। जिस प्रकार दो पैर मनुष्य को चलने के लिये और दो पक्ष पक्षी को उड़ान के लिये आवश्यक हैं उसी प्रकार आर्थिक जीवन के लिये व्यय और सचय दोनों का ही होना परम आवश्यक है। व्यय कम होने में वस्तुओं की मांग कम हो जायगी और इससे बकारी बढ़ेगी। इससे विपरीत सचय कम होने से पूँजी की वृद्धि में स्थूलता होगी जिससे उपयोगिता और व्यवसाय की उन्नति में रुकावट पहुँचेगी। अस्तु व्यय और सचय दोनों ही सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

श्रद्धासाध्य प्रश्न

इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

१- व्यय और वचन का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये। किसी व्यक्ति के अपव्यय (Extra-vagance) का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार इस अपव्यय को किम प्रकार रोक सकती है? (उ० प्र० १९५६)

२- क्या समाज के लिये यह बात महत्व की है कि कोई व्यक्ति अपनी आय को किस प्रकार व्यय करता है? क्या समाज का व्यक्ति की व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप आवश्यक है? (उ० प्र० १९४०, ३७, ३४, २८)

- ३—सचय और अनुत्पादक सचय पर टिप्पणी लिखिए । (अ० बो० १९५४)
- ४—वचत (Sachat), व्यय और अनुत्पादक सचय में क्या अन्तर है ? बिना किसी सच-विचार के व्यय करने का क्या सामाजिक प्रभाव है ? पूर्णतया स्पष्ट कीजिए । (अ० बो० १९५१)
- ५—‘सामाजिक दृष्टि से वचत व्यय से श्रेष्ठ है ।’ क्या आप इन कथन से सहमत हैं ? स्पष्टतया व्याख्या कीजिए । (अ० बो० १९५४)
- ६—सचय, व्यय और अनुत्पादक सचय में भेद दर्शाइये । विवेकहीन व्यय के क्या सामाजिक परिणाम होते हैं ? (रा० बो० १९५२)
- ७—‘आर्थिक उन्नति के लिये सचयन तथा व्यय दोनों समान आवश्यक हैं ।’—समझा कीजिए । प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय वचत योजनाओं के दार में आप क्या जानते हैं ? (सागर १९५५)
- ८—वचत को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है ? वचत का आर्थिक प्रभाव बताइए । (सागर १९५१)
- ९—वचत, व्यय और सचय का अन्तर समझाइये । असावधानी में व्यय करने के क्या सामाजिक प्रभाव होते हैं ? स्पष्ट कीजिए । (म० भा० १९५१)
- १०—‘सचय’ की आदत से क्या समझने है ? इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं ? (पत्राव १९५१)
- ११—‘वचत’, ‘व्यय’ और ‘सचय’ का अन्तर स्पष्ट कीजिए । (रा० बो० १९५२, म० भा० १९५५)
- १२—नक्षिन् टिप्पणियाँ लिखिए—वच और वचत । (उ० प्र० १९५४, ४८, ४९, म० भा० १९५५, ५३, दिल्ली हा० से० १९५०)

परिभाषा (Definition)—विलासिताएँ वे वस्तुएँ हैं जिनका उपभोग मनुष्य जीवन के लिए न तो आवश्यक है और न उनमें कार्य-कुशलता में कोई वृद्धि होती है। प्रो० जोड ने विलासिताओं का व्यय की आवश्यकताओं की तुलना यह कर परिभाषित किया है। प्रो० एली ने इसे अधिक उपभोग वर्णित किया है। विलासिताओं के उपभोग के लिए मनुष्य जीवन में कोई अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती। प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं से जीवनार्थ, रुढ़ तथा दत्तार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं के प्रतिरिक्त सुख-वस्तुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। विलासिताएँ इनमें सम्मिलित नहीं होने के कारण अनावश्यक वस्तुएँ सिद्ध होती हैं। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए जो कहा जा सकता है कि विलासिताएँ वे वस्तुएँ हैं, जिनके उपभोग से अत्यधिक आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु उनमें कार्य-कुशलता नहीं बढ़ती, जबकि उनके उपभोग के अभाव में न तो कार्य-कुशलता गिरती है और न कोई वेदना ही होती है।

विलासिता एक सापेक्षिक (Relative) शब्द है—विलासिता एक सापेक्षिक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ देश, काल, स्वभाव और मनुष्य के जीवन-स्तर से पर्याप्त भिन्नता रहता है। उदाहरण के लिये, चाय का प्रयोग भारतवर्ष में लगभग ५० वर्ष पूर्व मध्य योशी के मनुष्यों के लिए भी विलासिता समझी जाती थी। परन्तु आज वही वस्तु उनके लिए आवश्यक हो गई है, यद्यपि दूर-स्थित ग्राम में रहने वाले निर्धन किसानों के लिए अब भी वह विलासिता ही है। लेकिन इंग्लैंड में शीत ऋतुवायु के कारण चाय अनेक किसानों के लिए अनिवार्य है, जबकि वही वस्तु भारतीय किसानों के लिए विलासिता है। इस प्रकार नई आविष्कृत वस्तुएँ प्रारम्भ में विलासिताओं की कोटि में आती हैं, परन्तु धीरे-धीरे जब लोग उनके उपभोग के आदी हो जाते हैं, तब वे ही अनिवार्य वस्तुएँ हो जाती हैं, जैसे मोटरकार, साईकिल, ग्रामोफोन इत्यादि।

विलासिताओं की समस्या (The Problem of Luxuries)—यद्यपि हम इस दान पर विचार करेंगे कि सामाजिक दृष्टि से विलासिताओं पर किया गया व्यय लाभप्रद है तथा हानिकारक है। यह एक टेढ़ी समस्या है। इस पर भिन्न-भिन्न राय प्रकट की जाती हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि जीवन में विलास-वस्तुओं का उपभोग भी होना चाहिए, अन्यथा जीवन में कोई परिवर्तन या आनन्द नहीं होगा और मनुष्य बोका होने वाले पशु का भाँति हो जावेगा। विलास-वस्तुओं के उपभोग से

मनुष्य भौतिक सम्पत्ति में अग्रसर होता जाता है जिसमें समाज की उन्नति होती है। दूसरे पक्ष वाले इसमें विलुप्त विपरीत ही कहते हैं। उनके मतानुसार विलास वस्तुओं पर किया गया व्यय निन्दनीय है। इससे मनुष्य विलासी और धासो हो जाते हैं और उनकी कार्य-कुशलता गिर जाती है। इस कारण समाज की भी अवनति हो जाती है। इससे पूर्व कि इन विषय पर निष्पक्ष राय प्रवृत्त की जाय, यह जान लेना आवश्यक है कि विलासिताओं के पक्ष और विपक्ष में कौन-कौन सी तर्क प्रस्तुत की जाती हैं।

विलासिताओं के पक्ष में तर्क

लाभ (Advantages)

(१) मानव समाज की उन्नति और सम्पत्ति के लिये आवश्यक है—विनाशिताओं की वृद्धि मानव समाज की उन्नति और सम्पत्ति के लिए आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत भी विलासिताएँ नहीं होंगी तो हमारा जीवन भी बीमार होत-वाले मनुष्यों के समान बीमार और बंजर हो जायगा। मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ने के साथ-साथ सम्पत्ति का भी विकास होता है।

(२) कर्मशील बनने का प्रोत्साहन मिलता है—जब मनुष्य दूसरा को विनाश वस्तुओं का उपयोग करने दृष्ट देखता है, तो वह भी उनकी प्राप्ति में लग जाता है और अपने प्रयत्नों से आतिरिक्त अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो ही जाता है। साथ ही यदि मनुष्य कठिन में कठिन परिश्रम करता है तो वह दम्भी अभिलाषाओं की पूर्ति से प्रेरित होकर करता है।

(३) कला की उन्नति होती है—विलास वस्तुएँ उत्तम और कलापूर्ण होती हैं। उनके बनाने में अनुप्रास, दक्षता तथा कलात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अस्तु उनके उपयोग से उत्तम श्रेणी की शरीरगरी का प्रोत्साहन मिलता है।

(४) रोजगार वृद्धि और बेकारी कम होती है—विनाश-वस्तुओं पर व्यय करने से उन वस्तुओं की माँग बढ़ती है जिसमें उद्योग-धन्धा और वाणिज्य व्यवसाय में उन्नति होती है। इससे परिणामस्वरूप राजगार में उन्नति होती है जिसमें बेकारी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है।

(५) जीवन-स्तर ऊँचा होकर जनसंख्या में कमी हो जाती है—इन वस्तुओं के प्रयोग से मनुष्य के जीवन-स्तर में उन्नति होती है और जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं होन पाती, क्योंकि लाभ प्रपणे जीवन-स्तर की ऊँचा बनाय रखने की दृष्टि में जन्म निराश्रक उपाय काम में लाते हैं।

(६) मानव जीवन अधिक सुखमय और समृद्धिशाली हो जाता है—विलास वस्तुओं का उपयोग भौतिक उन्नति व सम्पन्नता का चिह्न है। इसमें वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है जिससे कारण उसका जीवन अधिक सुखी और समृद्धिशाली हो जाता है।

(७) आविष्कारों का प्रोत्साहन मिलता है—विनाशिताओं की आवश्यकता बड़ी आविष्कारों की जननी है। उनके द्वारा आविष्कारों की और प्रवृत्ति होने में हमारे प्राकृतिक और धन्य साधनों का उचित दब में काम में लाया जा सकता है।

(८) धन-वितरण की असमानता कम हो जाती है—इससे धन-वितरण की असमानता कम हो जाती है। विनास-वस्तुओं पर व्यय करने से धनवानों के द्रव्य का कुछ भाग गरीबों के पास पहुँच जाता है। निधन उग धन को अधिक आवश्यक कार्यों में ला सकते हैं।

(९) विलासिताएँ योग्यता का कार्य करती हैं—विलासिताओं को प्रबल इच्छा से बहुमूल्य वस्तुएँ, उत्तम फर्नीचर, सोना-चांदी और रत्नादि का संग्रह हो जाता है जो आर्थिक संकट में रक्षा कर सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय नारियाँ जेवर आदि की बड़ा महत्व देती हैं।

(१०) विलासिताएँ मनोरंजन के साधन हैं—विनास-वस्तुओं से मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं जिनसे जीवन की नीरमता और एकरमता दूर होकर नवीन स्फूर्ति और कार्यक्षमता प्राप्त होती है।

विलासिताओं के विपक्ष में तर्क

हानियाँ (Disadvantages)

(१) उद्योग धंधों और व्यापार में वान्छितक उत्पत्ति नहीं होती—यह सोचना भूल है कि विनासिताओं पर व्यय करने से व्यापार और उद्योग धंधों में उत्पत्ति होती है। अपव्यय से पूँजी की वृद्धि कम हो जाती है जिससे उत्पत्ति के कार्य में हानि अथवा घाति पहुँचती है। यदि पूँजी और अन्य उत्पत्ति के साधन विनास वस्तुओं की उत्पत्ति के स्थान में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लक्ष्ये जायें तो रोजगार की अधिक उत्पत्ति होगी।

(२) कर्मशीलता के लिए अधिक प्रेरणा नहीं मिलती—मनुष्य को जितनी प्रेरणा विनास-वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए होती है उससे कहीं अधिक प्रेरणा जीवनार्थ वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए होती है, क्योंकि इनके बिना उसका जीवन संभव ही नहीं। विनासिताएँ अनावश्यक हैं, अतः उनके लिए प्रयत्न करना इतना जल्दगी नहीं।

(३) कला की उत्पत्ति की धारणा अधिक प्रबल नहीं है—विलास-वस्तुओं से कला की उत्पत्ति तो अवश्य होती है पर यह समझना भूल है कि अनिवार्य तथा सुलभ वस्तुएँ कला की उत्पत्ति में कम सहायक होती हैं। कभी-कभी विलास वस्तुओं के बनाने में केवल साधारण श्रम की ही आवश्यकता पड़ती है। सांस्कृतिक अधिकतर विलास-वस्तुएँ कारखानों में मशीनों से बनाई जाती हैं और उनके बनाने में व्यक्तिगत चतुराई की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल थोड़ी-सी हाथ से बनाई जाने वाली विलास-वस्तुओं के आधार पर ही उनके द्वारा कलात्मक उत्पत्ति मान लिया भूल है।

(४) विलासिताओं से देश में असंतोष, अशांति और क्रांति उत्पन्न हो जाती है—कुछ ही घण्टी व्यक्तियों द्वारा विनासिताओं का उपयोग मध्यवर्गीय तथा गरीब आदिमियों के असंतोष और अशांति का कारण बन जाता है जिससे वातावरण क्रांतिकारी बन जाता है। देश जाय तो आधुनिक समय में जो समाजवाद और गाम्भवाद की उत्पत्ति हुई है वह इन्हीं के कारण हुई है।

(५) अनुत्पादक धन-संचय (Hoarding) से देश को हानि है—विलास-वस्तुओं के उपभोग से अनुत्पादक धन-संचय को प्रोत्साहन मिलता है जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक बड़ा भाग बेकार पड़ा रहता है।

(६) विलासिताओं पर व्यय न्यायमुक्त नहीं है—जिग देश में अधिकांश लोगों को भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता वहाँ पर विलासिताओं पर किया गया व्यय किस प्रकार न्यायपूर्ण हो सकता है। यह कहीं तक ठीक माना जा सकता है कि एक और तो सोप झूठ के भारे मौन के चिन्कार बन रहे हों और दूसरे और मोड़े से लोग विलासिताओं के साथ खुलकर उछा रहे हों। ऐसा होने से देश में अर्थशक्ति का जाल फैल जाता है और अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं—जिनमें आसानी से सुधार नहीं किया जाता।

(७) धन-वितरण की असमानता दूर नहीं होती—यह कहना कि विलासिताओं के कारण धन धनी से निर्धन को पहुँच जाता है, निरुद्ध ठीक नहीं है। जो भी राशि धनी विलास वस्तुओं के लिए निर्धन को देता है, वह निर्धन में पुनः धनी के पास पहुँच जाती है, यद्यपि निर्धन विलास वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा मांस और मूल्यवान् औजार धनी से ही खरीदता है। यस्तु धनी से निर्धन के पास धन का परिवर्तन भ्रम मात्र है।

(८) विलासिताओं के उपभोग का दुष्परिणाम—कभी-कभी निर्धन को भी विलास-वस्तुएँ उपभोग के लिए मिल जाती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे अपनी विभिन्न आध को आनन्द के वस्तुओं के स्थान पर विलासिताओं पर खर्च कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी कार्य-कुशलता में ह्रास हो जाता है। मनुष्य इसका एक उदाहरण है।

(९) जीवन-स्तर ऊँचा होने और जन-संख्या कम होने का वास्तविक कारण विलासी जीवन नहीं है—लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होने पर जन-संख्या कम होने का मुख्य कारण उनका विलासी जीवन नहीं है बल्कि उनकी निशा, सृष्टि और मनुष्य निर्ग्रह के दृष्टि सामर्थ्य की क्षमता की क्षमता है।

(१०) विलासिताओं के उपभोग से मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और चरित्र गिर जाता है—बड़े विलास वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके उपभोग से मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है, चरित्र बिगड़ जाता है और कार्य-कुशलता में ह्रास हो जाता है।

- - (११) विलासिताओं से जीवन में अर्थमयता और निष्कर्षावन प्राप्त होता है—विलासिता के कारण शक्ति, क्षमता, उत्साह का ह्रास होता है और जीवन प्रभावशाली नहीं और निष्कर्षा हो जाता है।

निष्कर्ष—इस प्रकार की अनेक बातें विलासिताओं के पक्ष और विपक्ष में कही जाती हैं। दोनों पक्ष की बातें कुछ अर्थ तक ठीक हो सकती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ विलास वस्तुएँ ऐसी हैं जो नैतिक या सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होतीं। उनके उपभोग में मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, चरित्र बिगड़ जाता है और कार्य-कुशलता में ह्रास हो जाता है। इन वस्तुओं पर विशेष रूप ध्यान देने की भी दृष्टि-वाण से न्यायमय नहीं बताया जा सकता। किन्तु इससे यह परिणाम निकलना

उन्निती न होयों कि सभी विनाश-वस्तुएँ निकट हैं और उनका उपभोग बन्द कर देना चाहिए। ऐसा करने से उत्पत्ति का मार्ग बन्द हो जायगा। मात्र जो विलास वस्तु मानी जाती है, वत वही आवश्यक वस्तु की कोटि में आ सकती है। अतएव प्रत्येक प्रकार की विलासिता को बन्द कर देना युक्तिमानी नहीं होगी। कुछ विनाश वस्तुएँ हानि रहित हैं, अस्तु उनके उपभोग को प्रोत्साहन मिलने में व्यक्तिगत प्रवृत्ति सामाजिक दृष्टि से कोई आपत्ति न होगी, अपितु लाभ ही होगा। इस सम्बन्ध में प्रो० पेन्मन कहते हैं, "विलासिता स्वतः कोई बुरी वस्तु नहीं है, यद्यपि इसके कई रूप व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हानिकारक और सामाजिक दृष्टि में अवाञ्छनीय हैं।"

अपव्यय (Waste)

प्रायः लोग अपनी धन्य को अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हुए देखे जाते हैं। उन वस्तुओं से व्यय के अनुरूप तृप्ति प्राप्त नहीं होने पर भी वे व्यय करने जाते हैं। यह उनकी धन्य का अपव्यय है। अस्तु, बिना बराबर लाभ या तृप्ति प्राप्त किए सुदृढ़ के व्यय को 'अपव्यय' कहते हैं। यदि कोई वस्तु बिना उसकी उपयोगिता के अनुरूप तृप्ति दिये नष्ट हो जाती है, तो यह उसका 'अपव्ययित उपभोग' (Wasteful Consumption) होगा।

अग्नि, बाढ़ और भूकम्प आदि प्राकृतिक सम्पत्ति का विनाश 'अपव्यय' (Wastage) कहा जाता है। जो सम्पत्ति इस प्रकार नष्ट होती है वह व्यक्तिगत हानि के अनिवार्य सामाजिक हानि भी है। सभी लोगों द्वारा सह-सा रूप्य बड़े-बड़े पोलो मैदानों को कायम रखने, आतिथ्यवाजी, मदिरागार, जुग आदि में खर्च किया जाता है। वे इसे अपव्यय नहीं समझते, क्योंकि इनकी वस्तुओं के उपयोग में वे अपने स्वयं की उपयोगिता के बराबर तृप्ति देखते हैं। परन्तु सामाजिक दृष्टि से यह खर्च अपव्यय है, क्योंकि आतिथ्यवाजी, मदिरा आदि अनावश्यक वस्तुओं के स्थान में यदि धर्म और पूँजी जीवनावयोगी अनिवार्य वस्तुओं में लगाये जाते, तो अधिक लाभदायक मिष्ट होने। एक बड़े भू-भाग में बजाय लेनी करने के यदि पोलो खेली जाय, तो क्या यह सामाजिक अपव्यय नहीं है ?

एक दूसरा उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा कि कोई व्यय व्यक्तिगत अपव्यय तो है, परन्तु सामाजिक अपव्यय नहीं। एक धनी पुण्य राज्य द्वारा पदवी प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी सार्वजनिक शिक्षणशाळा में दान देना है। इस व्यय के करने पर भी उसकी प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं होती अतः यह अपव्यय ही रहता है। अस्तु व्यक्तिगत दृष्टि से तो अपव्यय हुआ, परन्तु सामाजिक दृष्टि में नहीं। समाज को तो इस व्यय से लाभ हुआ। कई एक व्यय ऐसे हैं जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों में अपव्यय हैं, जैसे फलों का सड़ जाना, बाँधी में भूख छोड़ देना या कोई काम अनुरूप ही छोड़ देना आदि।

सम्पत्ति का विनाश और रोजगार

(Destruction and Employment)

अकस्मात् या जानबूझ कर होने वाली सम्पत्ति के विनाश में कुछ भी तृप्ति प्राप्त नहीं होती, अतः इसकी मरणा अपव्यय में की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि विनाश से रोजगार मिलता है, क्योंकि नष्ट हुई वस्तुओं के पुनर्निर्माण में काम-धंधे फिर से चालू हो जाते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगता है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि सम्पत्ति को जान-बूझकर नष्ट कर देना चाहिए। यह तर्क अम पदा

करता है। किसी वस्तु को नष्ट कर उसका पुनः निर्माण करने के बजाय तो किसी अन्य आवश्यक वस्तु के निर्माण में पूँजी व श्रम लगाना अधिक लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी अपनी पुस्तक को फाड़ कर पुनः दूसरी खरीद लेता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक दूसरी खरीदने के बजाय उसी मूल्य में एक पाठ्यपुस्तक खरीदना अधिक लाभदायक होगा। यह स्मरण रहे कि विना विनाश के भी राजगार के साधन निकल सकते हैं। काम की उत्पत्ति व्यय पर निर्भर होती है। नई नई वस्तुओं की माँग पैदा होने से नये-नये कारखाने खुलते हैं जिससे देश में रोजगार चेतना है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—विलासिताएँ क्या हैं? कुछ व्यक्ति विलासिताओं के पक्ष में नहीं हैं। क्या उनका मत उचित है? समाज में विलासिताओं के लाभ व हानियाँ बताइए।
(उ० प्र० १२४३)
- २—अपव्यय वर्गों की वर्वादी (Waste) तथा सम्पत्ति का विनाश (Destruction) पर टिप्पणी लिखिए।
(उ० प्र० १२४७, ४४, ३८)
- ३—क्या विलासिताओं का उपभोग आर्थिक दृष्टि से उचित है?
(अ० बो० १२५५)
- ४—उपभोग और वर्वादी पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
(अ० बो० १२५३)

पारिवारिक बजट (आयव्ययक) (Family Budgets)

पारिवारिक बजट का अर्थ (Meaning)—पारिवारिक बजट में किसी कुटुम्ब के जीवन स्तर का भली भाँति पता चल सकता है, क्योंकि इसमें उनके आय-व्यय का विस्तृत व्यौरा दिया रहता है। यह मासिक व्यय वार्षिक बनाया जाता है। अतः हम पारिवारिक बजट को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं—किसी परिवार की निश्चित अवधि में प्राप्त आय और होने वाली आय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट या आयव्ययक कहते हैं।

पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य (Objects)—पारिवारिक बजट से निम्नलिखित प्रयोजन सिद्ध होते हैं :—

- (१) पारिवारिक बजट से किसी परिवार के जीवन-स्तर का पता चल सकता है।
- (२) इससे यह पता चल सकता है कि प्रत्येक परिवार में कितने प्राप्ती हैं।
- (३) परिवार की कितनी आय है और वह किन साधनों से प्राप्त होती है।
- (४) आय किन पदार्थों या सेवाओं पर व्यय की जाती है।
- (५) परिवार के सदस्यों की क्या-क्या और कितनी अनिवार्य, सुख और विलास-वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं।
- (६) परिवार में कुछ बचत होती है या नहीं, ऋण-ग्रस्त है या नहीं।
- (७) किसी परिवार की एक निश्चित अवधि की आयव्यय का एक स्थान पर ही पता लग सकता है।
- (८) विभिन्न देशों के पारिवारिक बजटों की तुलना से अनेक मूल्यवान् निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
- (९) पारिवारिक बजट से किसी परिवार या कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। वह सुखी है या कठिनाई से जीवन निर्वाह करता है।
- (१०) निर्देशाङ्क (Index Numbers) बनाने के लिए पारिवारिक बजटों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सकती है।
- (११) समाज के विभिन्न वर्गों की करदान क्षमता (Taxable Capacity) मापने की जा सकती है।

पारिवारिक बजट का स्वरूप (Form)—पारिवारिक बजट एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है। सबसे प्रथम परिवार के सदस्यों की संख्या और अवधि (मास या वर्ष) तथा आय से जानी है। तत्पश्चात् वर्गीकृत रूप में व्यय के मद और उनके समूह दिये जाते हैं। प्रत्येक वस्तु के उपभोग की मात्रा, प्रति इकाई मूल्य,

समस्त धन्य, प्रत्येक व्यय को राशि का समस्त आय से प्रतिशत अनुपात और विशेष विवरण आदि बातें दी हुई होती हैं। इसका साधारण रूप नीचे दिया जाता है :—

पारिवारिक बजट

कुटुम्ब के मुखिया का नाम व पता

पेशा

सदस्यों की संख्या

(पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या तथा आयु दोनों ही लिखना चाहिए)

आय (मासिक या वार्षिक)

अवधि

व्यय के मद	उपभोग की मात्रा		व्यय राशि		व्यय का समस्त आय से प्रतिशत के रूप में अनुपात	विशेष विवरण
	मात्रा	एक सप्ताह के समय की उपभोग की गई समस्त मात्रा	प्रति इकाई मूल्य	व्यय की समस्त राशि		

पारिवारिक बजट के मुख्य अंग (Component Parts)—निम्नलिखित मद एक पारिवारिक बजट के मुख्य अंग गिने जाते हैं :—

मद (Items)	पुद्रा (Money)
(अ) परिवार की आय (ब) परिवार का व्यय	
१—अनिवार्य-वस्तुयें	
(क) भोजन	
(ख) वस्त्र	
(ग) किराया	
(घ) ईंधन ॥ प्रकाश	
२—सुख वस्तुयें	
(क) शिक्षा	
(ख) स्वास्थ्य	
(ग) सौकर	
(घ) मनोरंजन	
३—विलास-वस्तुयें	
(क) _____	
(ख) _____	
४—मंचय	

पारिवारिक बजट का महत्त्व (Importance)—पारिवारिक बजट की उपयोगिता केवल धर्मशास्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गृहस्वामियों, सुधारकों और राजनीतिज्ञों के लिए भी अत्यधिक है। प्रत्येक नी उपयोगिता नीचे दी जाती है —

गृहस्वामियों (Householders) के लिए—पारिवारिक बजट द्वारा गृहस्वामी प्रत्येक व्यय के मद को तुलनात्मक दृष्टि में देखकर यह ज्ञात कर सकता है कि क्या वह अधिक मद पर अधिक व्यय कर रहा है या ठीक, और क्या किसी मद के व्यय को कम करना चाहनीय है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि पारिवारिक बजट गृहस्वामी को 'सम सीमान्त उपयोगिता नियम' पालन कराने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। पारिवारिक बजट के अभाव में वह अपनी आय बड़ी लापरवाही से खर्च कर सकता है। पारिवारिक बजट ही सीमित आय से अधिकतम सुविधा करने का एक मात्र साधन है।

अर्थशास्त्रियों (Economists) के लिए—(१) पारिवारिक बजटों द्वारा किसी देश के निवासियों के जीवन-स्तर का अध्ययन हो सकता है तथा उनकी आय देशों के पारिवारिक बजटों से तुलना कर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे इङ्ग्लैंड और भारत के श्रमिकों की अवस्था की तुलना करने पर आय का कार्य-सहायता और समृद्धि से क्या सम्बन्ध है, इस बात का समुचित ज्ञान हो जाता है।

(२) धर्मशास्त्री पारिवारिक बजटों से यह ज्ञान कर लेते हैं कि किस मद पर कितना व्यय व्यय किया जा रहा है तथा आय का विवेकपूर्ण व्यय हो रहा है या नहीं।

(३) पारिवारिक बजटों के आधार पर रहन सहन की लागत के निर्देशांक (Cost of Living Index Numbers) तैयार किये जा सकते हैं जिससे रहन-सहन की लागत की भूलाभिता का ज्ञान हो जाता है और न्यूनतम मृत्ति (Minimum Wage) तय करने में बड़ी सहायता मिलती है। इसके परिणाम-स्वरूप हड़ताल आदि से होने वाली हानि को रोका जा सकता है।

(४) पारिवारिक बजटों द्वारा देश के मनुष्यों के विभिन्न वर्गों की करदात क्षमता (Taxable Capacity) का भी ठीक-ठीक ज्ञान हो जाने में करो की उचित दर निर्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती है।

(५) कुछ ऐजेंसिज जैसे आर्थिक नियम इन्हीं पारिवारिक बजटों पर अवलम्बित होने के कारण इनका महत्त्व और भी अधिक है।

समाज सुधारकों (Social Reformers) के लिए—पारिवारिक बजटों के अध्ययन से समाज सुधारक यह ज्ञान सकते हैं कि लोग अपनी आय का सदुपयोग कर रहे हैं या अव्यवस्थित व्यस्तता पर अवलम्बित कर रहे हैं। यदि उनकी दृष्टि में लोग अपनी आय का अधिकतम लाभ मदिरा आदि नशीली वस्तुओं के उपभोग में खर्च कर रहे हैं, तो वे ऐसी आदतों के विरुद्ध प्रचार करना प्रारम्भ करते हैं और राज्य पर निषेध कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं। इसी प्रकार उन्हें जब यह मालूम होता है कि लोग विवाह, मृत-भोज, जन्मोत्सव, शांतिश्रमानी आदि अनुत्पादक मदों पर अत्यधिक व्यय कर रहे हैं, तो वे प्रचार द्वारा इन व्ययों को कम करने की शिक्षा देते हैं।

राजनीतिज्ञों (Statesmen) के लिए—पारिवारिक बजटों से विभिन्न वर्गों के मनुष्यों की करदात क्षमता मालूम कर लेते हैं और उसी आधार पर अपनी कर नीति अवलम्बित करते हैं। यदि समाज के किसी भी वर्ग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि लोगों की पूरा पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, तो ऐसे मनुष्यों

को केवल कर से मुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उत्तरी आय वर्गों के उपायों को भी वर्ग स्व में लाया जाता है।

ऐंग्लिस का नियम (Engle's Law)

पारिवारिक वज्रो की इतनी उपयोगिता है कि समार के भोजन देता में इसकी महत्वपूर्ण खोज हो चुकी है। पारिवारिक वज्रो के इस नियम को सर्व प्रथम मान्य करने का श्रेय डाक्टर ऐंग्लिस का है। डा० ऐंग्लिस Prussian Statistical Bureau के अध्यक्ष थे। इन्होंने सन् १८५७ ई० में जर्मनी के संघमानी प्रांत में रहने वालों की तीन वर्गों—पथिक, मध्यम श्रेणी के लोग और श्रमिकों में विभक्त कर पारिवारिक वज्रो तैयार किये थे। व्यय के मुख्य मद निम्नांकित समूहों में विभाजित किये गये—(१) भोजन, (२) वस्त्र, (३) मकान किराया, (४) ईंधन और प्रकाश, (५) शिक्षा, (६) कानूनी सरक्षण, (७) स्वास्थ्य, (८) मुक्त व मनोरंजन और (९) कर। डा० ऐंग्लिस ने इन विभिन्न पारिवारिक वज्रो का अध्ययन कर जो उनमें निम्नलिखित निकाले वे आज भी ऐंग्लिस के नियम के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

- (१) यदि आय कम है, तो भोजन पर व्यय प्रतिशत अधिक होगा।
- (२) करों पर व्यय का प्रतिशत लगभग बराबर रहता है।
- (३) आय कुछ भी हो, ईंधन, प्रकाश और मकान-किराये पर व्यय प्रतिशत अनुपात लगभग स्थिर रहता है।
- (४) यदि आय अधिक होगी तो व्यय का प्रतिशत अनुपात शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कर आदि पर अधिक होता है।

सारांश में, मनुष्य की जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे भोजन पर व्यय का प्रतिशत अनुपात घटता जाता है, वस्त्र, किराया, ईंधन और प्रकाश पर व्यय का प्रतिशत अनुपात स्थिर रहता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि व्यय का प्रतिशत अनुपात बढ़ता जाता है।

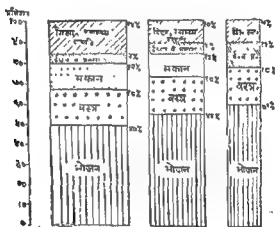
नीचे दी हुई तालिका में ऐंग्लिस का नियम स्पष्ट-भाषा में समझा जा सकता है :—

व्यय के मद	परिवार की आय का बिंबध व्यय का महा पर किये गये व्यय में प्रतिशत अनुपात।		
	पथिक वर्ग (निचला)	मध्यम वर्ग के धनी वर्ग के परिवार का व्यय	श्रमिक वर्ग के परिवार का व्यय
१—भोजन	६२	५४	५०
२—वस्त्र	१६	१८	१८
३—मकान किराया	१२	१२	१२
४—ईंधन व प्रकाश	५	५	५
५—शिक्षा	२	२.५	५.५
६—कानूनी सरक्षण	१	२	३
७—स्वास्थ्य	१	२	३
८—मुक्त-वस्तुएं मनोरंजन और कर आदि	१	२.५	३.५
	१००%	१००%	१००%

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि निर्धन परिवार की आय वा १५ प्रतिशत भाग हो केवल जीवनार्थ आवश्यकताओं पर ही पूरा हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुख-वस्तुएँ आदि भद्रों पर केवल ५ प्रतिशत ही व्यय किया जाता है। मध्यम वर्ग के परिवार का यह अनुपात १० से १० प्रतिशत का है और धनी परिवार का ८५ से १५ प्रतिशत है।

रेखाचित्रण का स्पष्टीकरण—निम्नांकित चित्रों में आयनों (Rectangles) की लम्बाई आय के व्यय का प्रतिशत प्रदर्शित करती है और चौड़ाई पाथ का परिमाण। अतएव सबसे अधिक चौड़ा आयत धनी परिवार का और सबसे कम चौड़ा निर्धन परिवार की आय-व्यय के प्रतीक है। बीच वाला न अधिक चौड़ा है और न ज्यादा तग, अतः यह मध्यम वर्ग के परिवार की आय-व्यय का प्रतिशत कराना है।

ऐंजिल्स के नियम का रेखाचित्रण



भारतवर्ष में पारिवारिक बजटों का अध्ययन—दूसरे देशों की भांति भारतवर्ष में भी पारिवारिक बजटों का कुछ अध्ययन हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रार्थ-शास्त्रियों, संस्थाओं, थम-समितियों तथा राज्य-अंग-विभाग द्वारा सहस्रवर्षीय कार्य हुआ है। इनमें से मेजर जैक, फिन्डले विलरज, पंजाब आर्थिक-अनुसन्धान समिति, कानपुर और बम्बई के थम विभाग और २० प्र० थम समिति के कार्य प्रशंसनीय हैं। मेजर जैक (Major Jack) ने अपना कार्य बंगाल प्रांत के फरीदपुर जिले के निवासियों के पारिवारिक बजटों की अध्ययन करने में ही सीमित रखा। यद्यपि यह प्रारम्भिक कार्य था, फिर भी भारतीय अर्थशास्त्र में इसका बड़ा महत्व है।

ऐंजिल्स का नियम और विविध वर्गों के पारिवारिक बजट

भारतीय श्रमिक का पारिवारिक बजट—भारतीय श्रमिक की अवस्था बड़ी दयनीय है। उसकी आय इतनी कम है कि उसे पूरा पेट भर भोजन तक नहीं

मिलता। उसकी आय का अधिकतम भाग भोजन पर ही व्यय होता है। ऐंजिल के नियम का पहला भाग कि ज्यो-ज्यो परिवार की आय बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो भोजन पर व्यय कम होता जाता है—एक भारतीय श्रमिक के लिए पूर्णतया लागू नहीं होता। वे कुछ समय तक बढ़ी हुई आय को भोजन पर ही व्यय करते हुए पाये जाने हैं, क्योंकि पहले से ही उनको घणघात भोजन मिल रहा था। नियम का दूसरा भाग कि वरत्रपरव्यय पूर्ववत् ही रहता है, बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि आय बढ़ने से इस मद पर व्यय सामूनी बढ़ता है। नियम का तीसरा भाग कि मकान-किराया, ईंधन और प्रकाश पर व्यय समान ही रहता है, भारतीय श्रमिक के बजट पर लागू नहीं होता, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर इन मदों पर होने वाले व्ययों में थोड़ा परिवर्तन अवश्य होता है। इसी प्रकार नियम का चौथा भाग कि आय की वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व मूल-वस्तुओं पर व्यय बढ़ता है पूर्णतया लागू नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी आय में वृद्धि होती है वह मुख्य व विलास-वस्तुओं की अपेक्षा अनिवार्य वस्तुओं पर खर्च कर दी जाती है, क्योंकि वह वस्तुएँ पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी।

इस सम्बन्ध में पिन्डले शिराज का अध्ययन बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने सन् १९२१-२२ ई० में वर्म्बई नगर के सभी जातिगो और कारखानों के श्रमिकों के पारिवारिक बजटों का मकलन किया। इनके अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ३० ०० प्रति मास से कम आय वाले श्रमिक भोजन पर आय का ६० प्रतिशत खर्च करते हैं, और ८० से ९० ०० मासिक आय वाले श्रमिक लगभग ५३ प्रतिशत खर्च करते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आय की वृद्धि के साथ-साथ भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत अनुपात भी घटने लगता है। यह निष्कर्ष ऐंजिल के नियम की पुष्टि करता है।

भारतीय कृषक का पारिवारिक बजट—भारतीय कृषकों के बजट का अध्ययन भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि श्रमिकों का। इस सम्बन्ध में पंजाब आर्थिक-अनुसंधान-समिति का कार्य उल्लेखनीय है। इसने छत्तीस प्रतिनिधि कृषक परिवारों के बजटों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि ज्यो-ज्यो जीवन-स्तर बढ़ता है, भोजन पर किये जाने वाले व्यय का अनुपात गिरता जाता है। इससे 'ऐंजिल के नियम' की पुष्टि होती है।

पारिवारिक बजट तैयार करने की विधि

सम्बन्धित व्यक्तियों के आय-व्यय के बारे में पूछ-ताछ करने के पूर्व निम्नांकित बातों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए :—

१—सबसे प्रथम पूछ-ताछ करने वाले को उसके इस कार्य का उद्देश्य स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए क्योंकि वह यह पूछ-ताछ किस प्रयोजन के लिए करना चाहता है।

२—इसरी बात जो ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि जिस व्यक्ति को पूछ-ताछ के लिए चुना है, वह उस समुदाय का उपयुक्त और वास्तविक प्रतिनिधि है। उदाहरण के लिए, हम एक किसान की आय-व्यय के बारे में पूछ-ताछ करना चाहते हैं, तो पहले यह जानना आवश्यक होगा कि किसान की परिभाषा क्या है, अर्थात् कौन व्यक्ति किसान कहलाता है, यदि बालों का पहले निर्णय होना चाहिए।

३—पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। किसान तथा अग्रजिवा भारतीय जनता अशिक्षित है, अतएव प्रश्न इस प्रकार सरल तथा क्रम में हों कि किसान या श्रमिक सामानों से समझ सके।

४—पूछ-ताछ करने वाले को सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यह उसकी वेप-भूषा, बोल-चाल के ढंग व चातुर्यता पर निर्भर है। उसे पूछ-ताछ करने की कोई उत्सुकता प्रकट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे लोग उसके इस कार्य को मदेहात्मक दृष्टि से देखते लगेंगे। किमान के सामने ही लिखने व बैठ जाना चाहिए नयोंकि इससे उसका सदेह और भी दृढ हो जायगा और प्रश्नों का उत्तर देना बन्द कर देगा।

५—यदि पूछ-ताछ शिक्षित लोगों से की जा रही है, तो एक प्रश्नावली (Questionnaire) बना कर उसके लिखित में उत्तर मगवा लेना अधिकांश विभाजनक होगा।

पारिवारिक वज्रट का स्वरूप तैयार करना—जब सब आवश्यक सूचनाएँ इकट्ठी हो जायँ, तो प्रामाणिक स्वरूप में वज्रट बनाना आरम्भ कर देना चाहिए। वज्रट का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें अभीष्ट समस्त बातों का समावेश हो सके। आवश्यक गणना भी यथा स्थान पर प्रकृत होना चाहिए। प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली राशि की प्रतिशत गणना स्पष्ट रूप से पृथक् लिख देने से एक ही दृष्टि में होने वाले व्यय के अनुपात का पता लग सकता है।

पारिवारिक वज्रटों का रेखाचित्रण—वज्रटों को रेखाचित्र द्वारा भी प्रकट दिया जा सकता है। खड़े लम्बे आयत (Rectangle) को कई भागों से विभक्त कर विविध मदों पर होने वाले व्यय को प्रकट किया जा सकता है। रंग, रेखाओं या बिन्दुओं द्वारा प्रत्येक-प्रत्येक भाग को चिह्नित किया जाता है। समान सम्बाँध वाले परन्तु विभिन्न चौड़ाई के एक से अधिक आयतों द्वारा विविध वर्गों के परिवारों के आय-व्यय का तुलनात्मक दृष्टि से रेखाचित्रण किया जा सकता है। रेखाचित्र के उदाहरण इसी अध्याय में देखिए।

विविध वर्गों के पारिवारिक वज्रटों के उदाहरण

[१]

एक कारखाने के श्रमिक (निर्धन) का पारिवारिक वज्रट

नाम व पता—फिसल, नई कस्बा, कागपुर

पेशा—श्रमिक

परिवार के सदस्यों की संख्या—१ पुरुष, एक स्त्री, ४ बच्चे = ६ लोग

मासिक आय—६० रु०

अवधि—१ मास (जनवरी, १९२८)

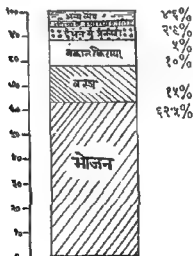
व्यय के मद	मात्रा	दर	व्यय की राशि	विवरण
१—भोजन			रु० न० प०	
(अ) अनाज और दाल				
गेहूँ	३२॥ सेर	१ रु० २१॥	१३ ००	
चावल	८ " "	" " २	५ ००	
ज्वार, बाजरा आदि	१८ " "	" " ३	६ ००	
चना	६ " "	" " ३	३ ५०	
दाल	७ " "	" " २	३ ००	
(आ) शाक और फल	—	—	१ ००	
(इ) अन्य वस्तुएँ				
अन्नसति पी	१०॥ छ०	३२० प्रति सेर	३ ५०	
बड़वा तेल	१॥ सेर	१५० " "	२ ५५	
गुड़	२ सेर	०५० " "	१ ००	
नमक	२ सेर	०२५ " "	० ५०	
मसाला	—	—	० ७५	
योग			३७ ५०	
२—दस्त्र				
बमोज	१	—	३ ००	
पाजामा	१	—	२ ५०	
बन्दो के बण्डे	२	—	३ ००	
अपोछा	१	—	० ५०	
योग ..			९ ००	
३—मकान किराया	—	—	६ ००	
४—ईंधन और प्रकाश				
लकड़ी	११ मन	२ रु० प्रति मन	२ ५०	
मिट्टी का तेल	२ बोतल	० २५, बोतल	० ५०	
योग —			३ ००	
५—शिला और स्वास्थ्य				
स्कूल फीस	—	—	० ५०	
स्टेशनरी	—	—	० ५०	
औषधि सब्बार	—	—	० ७५	
योग			१ ७५	
६—अन्य व्यय				
नाई	—	—	३ ८	
घोषो	—	—	१ २५	
पान-तम्बाकू	—	—	१ १२	
योग —			२ ७५	
७—वचन और विनियोग	—	—	—	

मुख्य मदों पर व्यय की गई राशि

(समस्त आय का प्रतिशत अनुपात)

व्यय के मद	व्यय की गई राशि	समस्त आय का प्रतिशत अनुपात
भोजन	₹ ३७ ५०	६२.५%
वस्त्र	₹ १० ००	१५%
मकान का किराया	₹ ६ ००	१०%
ईंधन और प्रकाश	₹ ३ ००	५%
शिक्षा और स्वास्थ्य	₹ १ ७५	२.९%
अन्य व्यय	₹ २ ७५	४.६%
बचत और निविशेष	—	—
	₹ ६० ००	१००.०%

ऊपर दिये गये बजट का रेखा चित्र



[२]

एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति का पारिवारिक वजत

नाम व पता—दीनदयाल, नया बाजार, मजमेर

पेशा—हैट बनकर

परिवार के सदस्यों की संख्या—२ पुरुष, २ स्त्रियाँ, ३ बच्चे—योग ७

मासिक आय—२०० रु०

अवधि—१ मास (नवम्बर, १९५७)

व्यय के मद	मात्रा	दर	व्यय की राशि	विवरण
१—भोजन				
(अ) अनाज और दाल			रु० न० पै०	
गेहूँ	३५ सेर	१ रु० का २॥	३५ ००	
बाजल	१६ "	" " " २	८ ००	
ज्वार, बाजरा	६ "	" " " ३	२ ००	
अना	६ "	" " " ३	३ ००	
दाल	१० "	" " " २	५ ००	
(आ) शाक और फल				
शाक	—	—	१० ००	
फल	—	—	५ ००	
(इ) अन्य वस्तुएँ				
दूध	३६ सेर	०.५० रु.प्र.से.	१८ ००	
घी	४॥ "	५.०० प्रतिसेर	२२ ५०	
तेल	१ "	२.०० " "	२ ००	
बीनी	६ "	१.०० " "	६ ००	
माय	६ "	३.०० " पीठ	१ ५०	
नमक	४ "	०.२५ " सेर	१ ००	
सत्ताले	१ "	२.०० " "	२ ००	
योग			१०० ००	
२—दख				
कमीज	१	—	४ ००	
धोती	२	—	१५ ००	
ब्लाउज	१	—	२ ००	
दर्रों के कपड़े	३	—	४ ००	
होसिये	२	—	२ ५०	
सणम जोती	१	—	४ ५०	
योग			३२ ००	

व्यय के मद	मात्रा	दर	व्यय की राशि	विवरण
३-मकान किराया योग			१ ००	
४-ई धन और प्रवास				
सोफा कोक	१ मन	२१० रु प्र म	२ १०	
लकड़ा का कोयना	२० मर	८ ००	४ ००	
विजली	—	—	३ ५०	
योग			१० ००	
५-शिक्षा और स्वास्थ्य				
१ स्कूल फीस	—	—	२ ००	
१ स्नेहानरी पुस्तकें	—	—	३ ००	
आदि	—	—	४ ००	
आपधि उपचार	—	—	१२ ००	
योग				
६-ग्रन्थ व्यय				
(अ) सामाजिक				
(बायत) प्रादि			२ ००	
(आ) मनोरंजन				
(मिनेमा)			४ ००	
(इ) सेवाएँ				
नाई	—	—	१ ००	
धोवो	—	—	५ ७५	
भंगी	—	—	१ २५	
(ई) विविध				
पान सम्बाहू	—	—	२ ००	
पत्र व्यवहार	—	—	१ ००	
(उ) कर	—	—	१ ००	
योग			१८ ००	
७-वर्ष और विनियोग	—	—	१२ ००	

मुख्य मदों पर व्यय की गई राशि

[समस्त आय का प्रतिशत अनुपात]

क्रम सं०	व्यय का मद	व्यय की गई राशि	समस्त आय का प्रतिशत अनुपात
		र० न० पैसे	
१—	भोजन	१०० ००	५०%
२—	वस्त्र	३२ ००	१६%
३—	मकान किराया	१६ ००	८%
४—	ईंधन और प्रकाश	१० ००	५%
५—	शिक्षा और स्वास्थ्य	१२ ००	६%
६—	अन्य व्यय	१८ ००	९%
७—	वचन और विनियोग	१२ ००	६%
		२०० ००	१००%

[३]

एक सम्पन्न व्यक्ति का पारिवारिक वजट

नाम व पता—दिग्विजयसिंह, सिविल लाइन्स आगरा

पेशा—सरकारी अफसर

परिवार के सदस्यों की संख्या—२ पुरुष २, स्त्रियाँ ४, बच्चे = ८ योग

मासिक आय—२००० रु०

अवधि—१ मास (अक्टूबर, १९५७)

व्यय के मद	प्रतिशत अनुपात	व्यय की गई राशि
१—भोजन		२० न० ५०
गहूँ		५० ००
चावल		१५ ००
दालें	...	१० ००
मांस		३० ००
नमक और मसाले		६ ००
ठूट		५० ००
तेल		७ ००
दूध		४० ००
भात घड़े		४० ००
चीनी		१० ००
फल		३० ००
चाय, मखन आदि		१७ ००
	१५%	३०० ००
२—वस्त्र	२०%	४०० ००
३—मकान (पगला)	८%	१६० ००
किराया		
४—गर्मी और प्रकाश	४%	८०० ००
५—शिक्षा	४%	८०० ००
६—स्वास्थ्य	४%	८०० ००
७—विलासिताएँ	२२.५%	४५० ००
८—कर	३%	६० ००
९—पुटकर व्यय	६%	१२० ००
१०—बचत और निवियोग	७.५%	१५० ००
ग्राम	१००%	२००० ००

नोट—यह बजट संक्षेप में बनाया गया है। यह भी बजट सख्या १ और २ की भाँति विस्तार पूर्वक बनाया जा सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—पारिवारिक वज्रट किम कहने है ? उसक विभिन्न मदा को व्याख्या कीजिए । एक ६० २० मामिक पाने वाल वलदार (MaoJ) का वज्रट वनाइए ।

(उ० प्र० १९५८)

२—पारिवारिक वज्रट क्या है ? किमी किमान मयवा कारखान के थमजोशो का वलित मामिक वज्रट तयार कीजिए ।

(उ० प्र० १९५०)

३—पारिवारिक वज्रट मे क्या ममभने हैं ? य क्या और कँस वनाये जाते हैं ? गृहस्वामी, अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ तथा ममाज सुधारक को इनमे क्या लाभ हैं ?

(उ० प्र० १९४६, ४७, रा० थो० १९५३)

४—पारिवारिक वज्रट किमे कहते है ? फिमी (अ) वृषक और (अ) दापकार के पारिवारिक वज्रट का ममूना वनाइए ।

(अ० थो० १९५५)

५—एक व्यक्ति की जिननी अधिक छाय होमी है उतना ही वह अनिवार्यतामा (विशेषकर म जन) पर कम प्रनिदान दश्य करता है । यह कथन कहाँ तक म्यायोचित है ?

(अ० थो० १९५०)

६—परिवार क व्यय क मम्बुन म प्रनिशानि एजिन के नियम का स्पन्गेकरण कीजिए । यह भारतीय परिस्थितिया म किम मीमा तक लागू होता है ?

(अ० थो० १९४६)

७—पारिवारिक वज्रट किम कहते है ? एन वृषक और दूसरा दापक के पारिवारिक वज्रट वनाइए । विभिन्न व्यय के मदा को दृष्टि म इनकी तुलना कीजिए ।

(म० भा० १९५२)

८—एजिन के उपभोग नियम को स्पष्ट कीजिए । यह नियम भारत म कहाँ तक लागू होता है ?

(सागर १९५६)

९—निम्नलिखित पर स्पष्टिपथा लिखिए —

पारिवारिक वज्रट

(उ० प्र० १९४६, रा० थो० १९५०)

एजिन का उपभोग का नियम (सागर १९५७, ५८, ५९, म० भा० १९५६,

५३, उ० प्र० १९५६, ५९, नागपुर १९५९)

उत्पत्ति PRODUCTION



"आर्थिक उपयोगिताओं का सृजन
ही उत्पत्ति है।"

—निकल्सन

उत्पत्ति का अर्थ (Meaning of Production)—मायारण बोल-
चाल में उत्पत्ति का अतिशय भौतिक (Material) वस्तुओं के उत्पादन से है।
विमान, यई, कुम्हार आदि को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि उनके उद्योगों से
भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जैसे—घर, कुर्सी, बर्तन आदि। डाक्टर, वकील,
अध्यापक, धरतू नौकर आदि साधारणतया उत्पादक नहीं कहलाते, क्योंकि उनके
उद्योगों का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति से नहीं होता। अब यह प्रश्न उठता
है कि उत्पत्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? वह कौनसा कार्य है जिसके करने से मनुष्य
को उत्पादक कहा जा सकता है। यह तो सभी को मालूम है कि मनुष्य कोई भी ऐसा
नया पदार्थ नहीं बना सकता जो किसी न किसी रूप में पहले से ही विद्यमान न हो और
न उसे ढूंढ हो कर सकता है। प्रकृति का जितना स्वरूप सत्ता में है वन उतना ही
रहेगा। मनुष्य तो केवल विद्यमान पदार्थों में ही कुछ परिवर्तन करके उन्हें पहले से
अधिक उपयोगी या मूल्यवान बना सकता है। इनके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर
सकता। कुछ पदार्थ अपनी प्राकृतिक अवस्था में विशेष उपयोगी नहीं होते। यदि
मानव प्रयत्न द्वारा उन्हें एक नया रूप दे दिया जाय, तो उनकी उपयोगिता बहुत बढ़
जाती है। उदाहरण के लिए, यई लकड़ी को स्वयं उत्पन्न नहीं करता। लकड़ी तो उसे
प्रकृति की ओर से प्राप्त होती है। वह अपने औजारों से काट-छाट कर कुर्सी और मेज
आदि बनाता है। इन लकड़ी के लकड़ी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा अधिक हो
जाती है। इसी प्रकार दर्जों कोई सर्वथा नया पदार्थ नहीं बनाता। वह लकड़ी को काट
कर एक विशेष माप या मोट या कमीज बना देता है जिससे उसकी उपयोगिता बढ़
जाती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि मनुष्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना सकता
जो सर्वथा नया हो। यह वन विद्यमान पदार्थों की उपयोगिता ही बढ़ा सकता है।
इसी उपयोगिता वृद्धि को अर्थशास्त्र में 'उत्पत्ति' कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी
रूप में उपयोगिता बढ़ाता है उसे उत्पादक कहते हैं। विज्ञान, यई, व्यापारी, वकील,
बान्धव, मुनी सभी उत्पादक कहलाने के पायदायी हैं, क्योंकि इनके उद्योगों द्वारा
उपयोगिता की वृद्धि होती है।

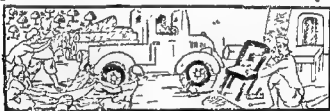
उपयोगिता वृद्धि—अगर कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र में 'उत्पत्ति' का अर्थ
उपयोगिता-वृद्धि है। अब हम यहां पर इस बात पर विचार करेंगे कि वस्तुओं
की उपयोगिता-वृद्धि किन प्रकार होती है। उपयोगिता-वृद्धि के मुख्य दस
विधन विधिन हैं :—

(१) रूप-परिवर्तन (Form Utility) —जब किसी वस्तु के रूप में आवश्यक परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता बढ़ा दी जाती है तो उसे 'रूप परिवर्तन उपयोगिता' कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इस नए रूप में मिट्टी की उपयोगिता पहलू को बराबर अधिक हो जाती है। इसी प्रकार बर्तन खरटा में कुर्सी, सज, सावभारी आदि तैयार करता है, यद्यत् रूप-परिवर्तन से इन वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है।



रूप-परिवर्तन उपयोगिता

(२) स्थान-परिवर्तन (Place Utility) —किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना से जो उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे 'स्थान परिवर्तन उपयोगिता' कहते हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ में 'लकड़ी काट कर बाजार में बेची जाय या सोहा, कोयला पत्थर आदि खान से निकाल कर दूसरे स्थान को भेज दिए जाय, ता इन वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। लाने व दाने की उपयोगिता खान के पास बहुत कम



स्थान-परिवर्तन उपयोगिता

होती है। जब इन वस्तुओं को गाड़ी या वाहन द्वारा बाजार में लाया जाता है, ता उसका स्थान परिवर्तन होने में इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार घघ, दाक और फल सेतों या दगोबा से मण्डों ले जान पर उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती है।

(३) समय-परिवर्तन (Time Utility) —वस्तुओं के सचय या संरक्षण में भी उपयोगिता बढ़ती है। घघ अपने फसल के अवसर पर अधिक परिमाण में होने में उनका उपयोगिता नहीं होता कि बाद



समय-परिवर्तन उपयोगिता

मे जबकि उसका परिमाण कम हो जाता है। अतएव दुकानदार मात्र को सतियों मे सचय करने हे और उस समय दसको निकालते है जब इसकी माग अधिक होती है। गृह, चावल, अन्न आदि पदार्थ पुराने होने पर अधिक उपयोगो होते है।



अधिकार परिवर्तन उपयोगिता

अधिकार परिवर्तन मे गाने की उपयोगिता बढ जाती है। इसी प्रकार पुस्तक की उपयोगिता पुस्तक खजाना को अपना पुस्तक खाना को अधिक है।



सेवा उपयोगिता

(४) सेवा उपयोगिता (Service Utility) — भौतिक वस्तुमा क रंग, स्थान समय या अधिकार परिवर्तन मे ही नही बल्कि सेवाया से भी उपयोगिता वृद्धि होती है। बाघने गाने बाने तथा तमाशा दिलाने वाले अपनी कला मे दसको और आनन्द को प्रदान करके उनकी आवश्यकतामा की पूर्ति करते हैं अत ये भी आर्थिक दृष्टि से उत्पादक हैं। इसी प्रकार डाक्टर वेषाज पुस्तकालय, शस्त्रागार, वकील भाई (हज्जाम) घरेलू नौकर आदि अपने सेवा क य मे उत्पत्ति मे सहायक होते है।

(५) ज्ञान उपयोगिता (Knowledge Utility) — जो उपयोगिता किसी वस्तु की जानकारी मे पैदा होती है वह ज्ञान उपयोगिता कहलाती है। सूचना रखने वाला विज्ञापन दसका एक उत्तम उदाहरण है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रमुख पुस्तक के गुण न मान्य हो तो उसे उसकी कुछ भी उपयोगिता नही होगी किन्तु यदि कोई विज्ञापन उसे उस पुस्तक के लाभ बताये तो उसे यह बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगेगी। इस प्रकार इसकी उपयोगिता विज्ञापन द्वारा पैदा हो जाती है।



ज्ञान उपयोगिता

उत्पत्ति का महत्त्व (Importance of Production)

उत्पत्ति का महत्त्व व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है —
व्यक्तिगत महत्त्व — मनुष्य वस्तुमा के उपयोग मे अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। किन्तु यह पूर्ति तभी सम्भव है जब वस्तुएं उत्पत्ति की जा चुका हों।

मनुष्य को वित्तीय वृद्धि प्राप्त हो सकती है यह उत्पत्ति के परिमाण पर निर्भर है। उत्पत्ति द्वारा ही मनुष्य का जीवन स्तर निर्धारित होता है। मारतवासियों का जीवन-स्तर बहुत निम्न है। इसका मुख्य कारण धनोत्पत्ति की कमी है। जीवन-स्तर तभी ऊँचा हो सकता है जबकि उत्पत्ति में वृद्धि हो। अतएव इस बात को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है कि उत्पत्ति किन-किन साधनों द्वारा होती है और किम प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

सामाजिक दृष्टि से महत्व—सामाजिक दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएँ जो प्राथमिक समाज की दुरी तरह से घेरे हुए हैं, वे अर्थिक उत्पत्ति की कमी तथा होना के कारण ही होती हैं। समाज को इन समस्याओं से मुक्त करने के लिए हम उत्पत्ति-नियम पर ध्यान देने से ध्यान देना होगा। निर्धनता की समस्या का ही उदाहरण लीजिए। इसको हल करने के लिये धन-वितरण की समस्या को दूर करने का सुझाव दिया जाता है, परन्तु केवल यही पर्याप्त उपाय नहीं है। यदि देश में यथेष्ट उत्पत्ति नहीं होगी तो लोग निर्धन ही बने रहेंगे, चाहे जिस ढङ्ग में वितरण क्यों न किया जाए। अस्तु सामाजिक समृद्धि और उत्पत्ति के लिये उत्पत्ति का यथेष्ट रूप से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है।

उत्पत्ति के साधन (Factors of Production)

धनोत्पत्ति में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना उनकी सहायता के उत्पत्ति असम्भव है। मुख्यतः चारों का उदाहरण लीजिए। हमें पूर्व कि किमान कुछ धन पैदा कर लें उसके पास भूमि, श्रम, पूँजी, साधन, हस्त, बैल आदि का होना आवश्यक है। इनके बिना वह किसी प्रकार का धन पैदा नहीं कर सकता। उत्पत्ति के अन्य क्षेत्रों के लिए भी वही बात लागू है। उन वस्तुओं को जो उत्पत्ति के कार्य में सहायक होती हैं उत्पत्ति के साधन कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए उत्पत्ति के साधनों को पाँच भागों में विभक्त कर दिया जाता है—भूमि, धन, पूँजी, प्रबन्ध और साहम।

(१) भूमि (Land)—साधारणतया भूमि में अधिप्राप्त वृद्धिमान से होता है, किन्तु अनेकान्तर में इनके अन्तर्गत वे सब उपयोगी पदार्थ और शक्तियाँ सम्मिलित हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और धनोत्पत्ति में प्रयोग की जाती हैं। जैसे वृक्षों, तेल, पहाड़, जल, नदी, वायु, वर्षा, गर्मी, जलवायु आदि अन्य पदार्थ और शक्तियाँ जो वृद्धिमान के ऊपर और नीचे पाई जाती हैं।

(२) धन (Labour)—धन का अर्थ मनुष्य के उन मानविक तथा शारीरिक प्रयत्नों से है जो फलित के लिये किया जाते हैं। मनोरञ्जन के लिये किया गया प्रयत्न अर्थशास्त्र में धन की वाटि में नहीं आये। अर्थशास्त्र में धन के अन्तर्गत वे ही प्रयत्न आते हैं जिनका प्रयोजन धनोत्पत्ति में होता है।

(३) पूँजी (Capital)—धन का वह भाग जो आर्थिक धन पैदा करने में सहायक होता है, वह पूँजी कहलाता है। पूँजी के अन्तर्गत विविध वस्तुएँ सम्मिलित हैं, जैसे—बच्चा भात, आहार, मशीन, वाहन, अनाज का बीज, मछलियाँ आदि।

(४) संगठन (Organisation)—उत्पत्ति के विविध साधनों का यथेष्ट रूप में प्रबन्ध, निरीक्षण अथवा व्यवस्था करने के कार्य को संगठन कहा जाता है।

प्राधुनिक उत्पत्ति प्राणाली में 'प्रत्यक्ष' का डगना अत्यधिक महत्त्व है कि बिना कुशल प्रवर्धन के कारखाना में उत्पादित का काय धन ही नहीं सकता ।

(१) साहम (Enterprise) —बनोत्पत्ति में जास्तिम उठान व काय को साहम कहते हैं । साहम वल की उत्पादन प्रणाली में जसकि उत्पादन एक बड पैमान पर किया जाता है, जास्तिम उठान का काय एक बडा महत्त्व रखता है । अस्तु, यह धनापत्ति का एक प्रथम साधन माना जाता है ।



उत्पत्ति के साधन

उत्पत्ति के साधनों का उपयोग—अत्यन्त व्यवसाय या उद्योग में इन साधनों का बिना न किमी धाना न अवश्य उपयोग किया जाता है । यह ही गदना है कि किमी में कोई साधन अथवा परिमाण में प्रयुक्त होता है और किमी में कम । हम नाव के उदाहरणों में यह देखते हैं कि बिना बिना व्यवसायों में किमी प्रकार इन साधनों का उपयोग किया जाता है ।

(२) ग्रामीण बुनाहा (Village Weaver)—एक ग्रामीण बुनाहा व लिए अथवा प्राचीन प्रमाद (Free Gut of Nature) की आवश्यकता नहीं होती । जवन भूमि का एक छाया या टुकड़ा स्वयं बैंगन और करवा रखावित करने के लिए चाहिए । वह मित्रों का प्रयोग नहीं करता है अपितु ही म जल शक्ति का प्रयोग योर्क सा माना में प्रारम्भ हो गया है । उन बाहर व यमिका की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । आवश्यकता पड़ने पर प्रायः बुद्धिमान मध्य ही काय कर

सेते है। अतः उसको किसी भी प्रकार की श्रम समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे मूल आदि खरीदने के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है सो वह किसी ग्रामीण साहूकार से उधार ले लेता है। ग्रामीण साहूकार की व्याज दर इतनी अधिक होती है कि वह सदैव उसका भिन्न बन रहा है तथा हर प्रकार उसका शोषण (Exploitation) होता रहता है। इस कार्य में कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल जोखिम उभ समय होती है जबकि उसका बना हुआ माल न बिके या लागत क्षमों में भी कम से बिके।

(द) बर्तन बनाने का व्यवसाय (Brass Industry)—बर्तन बनाने का व्यवसाय करने वाला को एक जुलाह की अपेक्षा अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। कारखाना बनाने के लिए भूमि के अतिरिक्त खनिज पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जुलाहे की अपेक्षा अधिक परन्तु एक बड़े कारखाने की भांति कम धमिकों की आवश्यकता होती है। सब आवश्यक धमिक मजदूरी पर ही रहे जाते हैं। पूँजी भी जुलाहे की अपेक्षा अधिक चाहिये। अधिक धमिका और अधिक पूँजी लगाने के कारण मजदूर या प्रबन्ध के कार्य में अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। कारीगरों में काम बँटन, उनकी नियमों के अतिरिक्त कच्चा माल खरीदने और बने हुए माल की बिक्री का प्रबन्ध करना पड़ता है। जुलाहे की प्रशिक्षण कार्य एक बड़े पैमाने पर होने के कारण जोखिम का महत्ता भी स्वाभाविक है।

(म) सूती कपड़े की मिल—एक सूती कपड़े की मिल में जुलाह और बर्तन के कारखाने की अपेक्षा प्राकृतिक प्रसाद अधिक परिमाण में प्रयुक्त होता है। मिल स्थापित करने के लिए एक मज्बे कीड़े मैदान के अतिरिक्त रई, कोयला या बिजुल और एक निम्न प्रकार की जलवायु अर्थात् नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ये सब वस्तुएँ भूमि के अन्तर्गत आती हैं। मिल में काम करने के लिए हजारों धमिकों की आवश्यकता होती है। एक कपड़े की मिल में भवन निर्माण के लिए इन्ड्रिन और मशीनें खरीदने, रई खरीदने और बने हुए माल को मजदूर रखने के लिए पूँजी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यह पूँजी बैंकों में या जगता में जमा के रूप में उधार ली जाती है। प्रत्येक वस्तु अधिक परिमाण में प्रयुक्त होने के कारण मजदूर या प्रबन्ध की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अन्तः शोषण एवं कुशल प्रबन्ध की निपुणता बर्तनीय हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने, मशीनों के विस्तृत हो जाने और भाग में परिवर्तन होते रहने के कारण लाभ हानि के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हो जाती है। प्रत्युत जोखिम भेलने वाले साहू मूल रूपों की आवश्यकता इसकी प्रथम आवश्यकता है।

उत्पत्ति के साधनों का सापेक्षिक महत्त्व

(Relative Importance of the Factors of Production)

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि उत्पादन में सभी साधनों की तुलनात्मक मात्रा में आवश्यकता होती है। परन्तु यह निश्चय करना बर्तन है कि कौन-सा साधन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम, क्योंकि प्रत्येक साधन का स्वामी अपने साधन को अधिक महत्वपूर्ण समझता है।

देना आज तो भूमि (Land) और श्रम (Labour) उत्पादन के दो साधन हैं। मनुष्य बिना इन्ड्रिन या भूमि की सहायता के उत्पादन का कार्य भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, किसान मनी या नाम तभी कर सकता है जबकि

उसके लिए भूमि, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक वस्तुएँ पहले से ही विद्यमान हो। इसी प्रकार मछली पकड़ने वाला अपना काम तभी कर सकता है जबकि प्रकृति की ओर से नदियों और तालाबों में मछलियाँ हो। इन प्रकृतिदत्त वस्तुओं को ही भूमि कहा जाता है। मनु, उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम भूमि का होता अनिवार्य है। यद्यपि प्रकृति मनुष्य के लिए बहुत सी वस्तुएँ स्वयं प्रदान करती है, फिर भी बिना मनुष्य के परिश्रम के उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। चाहे बिना उत्तम प्राकृतिक साधन क्यों न हो, किन्तु जब तक मनुष्य परिश्रम नहीं करता, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि भूमि और श्रम उत्पत्ति के प्रमुख साधन (Primary Factors of Production) माने जाते हैं।

मनुष्य केवल भूमि और श्रम के ही सहारे भाग्य नहीं बढ़ सकता। उसे भूमि के अतिरिक्त कई और वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्राचीन निवासों का निर्माण करने के लिए धनुष-बाण का प्रयोग करते थे, मछली पकड़ने के लिए जाल और कटि को काम में लाते थे। आज मनुष्य अनेक प्रकार की मशीनों तथा औजारों का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्र में ये सब वस्तुएँ पूँजी के अन्तर्गत आती हैं। आधुनिक उत्पत्ति काफ़ी अंश तक पूँजी पर ही अवलम्बित है। पूँजी की सहायता से मनुष्य की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। मनु, उत्पत्ति में पूँजी (Capital) का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

आयकक्ष अधिकतर उत्पत्ति कल-कारखानों द्वारा की जाती है जहाँ कि सहस्रो श्रमिक एक साथ काम करते हैं। इन कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है जो विजनी शक्ति की शक्ति से चलाई जाती हैं। कारखानों में निरीक्षण अपना प्रबन्ध करने वाले की बहुत आवश्यकता होती है। उसे यह विचारना पड़ता है कि कौनसा काम किस प्रकार किया जाय, नहीं से आवश्यक साधन सँभाले और अच्छे मिल सकने हैं, कार्य का विभाजन श्रमिकों में किस प्रकार किया जाय। उत्पादित वस्तुओं को कितने मंडियों में बेचा जाय, जैसे उन्हें उन स्थानों तक ले जाया जाय, किस ढंग से उन वस्तुओं को विक्रयित किया जाय, आदि बातों पर भी उसे विचार करना पड़ता है। इन सब बातों की व्यवस्था ही तो संगठन (Organisation) कहलाती है। इस कार्य का माउन्टन इसना अधिक महत्व है कि यह एक श्रमक साधन माना जाता है।

आधुनिक उत्पत्ति भविष्य के लिए की जाती है। भविष्य में किसी वस्तु की माँग का अनुमान लगा कर ही उसका उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है। भविष्य अनिश्चित होने के कारण यह अनुमान भी सदैव ठीक नहीं उतर सकता। अतः ऐसे धनियों के समूह की आवश्यकता है जो हानि-लाभ के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले सकें। उनका यह कार्य अर्थशास्त्र में साहस (Enterprise) या जोखिम उठाना (Risk-taking) कहलाता है। जब तक इस प्रकार के व्यक्ति कार्य को न सवालसे तब तक आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली का सफलतापूर्वक चलना सम्भव नहीं है।

पूँजी, संगठन और साहस भूमि और श्रम के सहायक होने के कारण ये धनोत्पत्ति के गौण साधन (Secondary Factors of Production) कहे जाते हैं। भूमि या प्रकृति और श्रम या मनुष्य में ही प्रकृति निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय। अतः, श्रम अर्थात् मनुष्य ही धनोत्पत्ति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन कहा जाता है। इस सम्बन्ध में प्रो० पेन्सन का कथन अधिक मान्य है। ये कहते हैं कि

“धनोत्पत्ति का प्रत्येक साधन आवश्यक है, किन्तु निम्न-निम्न समूह में और श्रौयोगिक विचारों की भिन्न-भिन्न अवस्थायों में, भिन्न-भिन्न साधनों का अधिक महत्व रहा है।”

उत्पत्ति के साधक (Agents of Production)

उत्पत्ति के साधनों के स्वामी, अर्थात् उनकी पूर्ति करने वाले व्यक्ति ‘उत्पत्ति के साधक’ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, भूमि का स्वामी भू-स्वामी (Landlord), श्रम करने वाला श्रमिक (Labourer), पूँजी वाला पूँजीपति (Capitalist), प्रवन्ध करने वाला प्रवन्धक या संगठनकर्ता (Organiser), और उत्पन्न करने वाला या जोषिम उठाने वाला साहसी (Enterpriser or Entrepreneur) कहलाता है।

धनोत्पत्ति के प्रत्येक कार्य में चाहे वह बड़े पैमाने पर हो या छोटे पर, उपयुक्त साधन और साधक आवश्यक हैं। परन्तु प्रत्येक कार्य में इन सब साधनों तथा साधकों का पुरक-पुरक विद्यमान होना आवश्यक नहीं। कभी तो प्रवेश सामन के लिए पुरक-पूरक साधक स्वतन्त्र रूप से होता है और कभी दो, तीन, चार या पाँचों साधनों के लिए एक ही साधक होता है। अतएव साधनों के बीच रहने हुए भी साधक केवल दो या तीन हो सकते हैं या कभी एक ही साधक सारे साधनों की पूर्ति कर देता है।

उत्पत्ति की कार्य-क्षमता

(Efficiency of Production)

कार्य-क्षमता का अर्थ—प्रति माल या श्रेष्ठतर माल सबसे अधिक मात्रा में श्रेष्ठतर माल की निश्चित अवधि में बनाने या पैदा करने के सामर्थ्य की उत्पत्ति की कार्य-क्षमता या कुशलता कहते हैं। उदाहरणार्थ, दो मयान मूनी कपड़े की मिलों में यदि एक मिल की वार्षिक उत्पत्ति दूसरी मिल से मात्रा और श्रेष्ठता में ब्याप्री हो, तो एक की उत्पत्ति की कार्य-क्षमता दूसरी की अपेक्षा अधिक कहलायेगी।

उत्पत्ति की कार्य-क्षमता—उत्पत्ति की कार्य-क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर है :—

(१) भीतरी परिस्थितियाँ, और (२) बाहरी परिस्थितियाँ।

(१) भीतरी परिस्थितियाँ (Internal Circumstances)—वे हैं जो किसी व्यवसाय के भीतर ही विद्यमान हैं। उनका सम्बन्ध कार्य करने की रीतिमा से है। ये दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं—

(अ) प्रत्येक साधन की व्यक्तिगत कार्य-कुशलता—धनोत्पत्ति के प्रत्येक साधन को अपने कार्य में कुशल होना चाहिये, अर्थात् जिस कार्य के लिए किसी साधन को प्रयुक्त किया जाय वह उस कार्य के लिए उपयुक्त हो। जितनी प्रत्येक साधन की कार्य-कुशलता अधिक होगी, उतनी ही समस्त उत्पत्ति की क्षमता में वृद्धि होगी। इसको यों कहा जा सकता है कि समस्त उत्पत्ति की क्षमता उसमें समाविष्ट साधनों की व्यक्तिगत कार्य-कुशलता पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, एक अच्छे डग में बना हुआ मिशान भवन एक हाथ से कपड़े बुनने वाले कारखाने की अपेक्षा एक आधुनिक सूती कपड़े की मिल के लिए अधिक उपयुक्त है, अतः उसकी क्षमता दूसरी दशा में पढ़ने की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक है।

(आ) साधनों का उपयुक्त मात्रा में संयोग—उत्पत्ति की क्षमता के लिये विविध साधनों का उपयुक्त मात्रा में संयोग बड़ा आवश्यक है। जिस ध्वन्याय में कौन-से साधन किस मात्रा में प्रयुक्त होने चाहिए, यह एक कठिन समस्या है। परन्तु इन बात का ठीक ठीक ज्ञान दीर्घकालीन अनुभव द्वारा विद्यमान हो सकता है। उत्पत्ति के साधनों के उद्देश्य संबंध में ही अधिकतम उत्पत्ति और लाभ सम्भव हो सकता है।

(२) बाहरी परिस्थितियाँ (External Circumstances)—बाहरी परिस्थितियाँ ध्वन्याय या उद्योगों में बाहर विद्यमान होती हैं जो वे प्रायः निर्दिष्ट मात्रा के मूल्य को प्रभावित कर विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के पारिश्रमिक को प्रभावित करती हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

- (क) उद्योग का रसायनिककरण और मशीनें में निरूपण।
- (ख) मशीनें में प्रचलित मूल्य।
- (ग) अन्य उत्पादकों की स्पर्धा।
- (घ) वातावरण के साधनों की सुविधा।
- (ङ) वैज्ञानिक सुविधाएँ।
- (च) अन्य सम्बन्धित भौतिकीय बलों की कुशलता।
- (छ) सरकार की आर्थिक नीति।

अभ्यासायें प्रश्न

इण्टर प्रार्ट में परीक्षाएँ

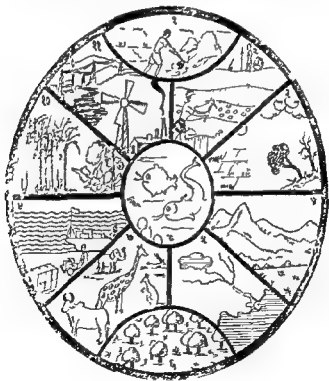
- १—उत्पादन के किन्हीं साधन की कार्यक्षमता में क्या तात्पर्य है ? भूमि तथा पूँजी की कार्यक्षमता किन बातों पर निर्भर है। (उ० प्र० १९५७)
- २—उत्पत्ति के कौन-कौन से साधन होते हैं ? उनके तुलनात्मक महत्व का वर्णन कीजिए। (उ० प्र० १९५५, ५४, ५०)
- ३—उत्पादन का प्रथम समझाकर लिखिए। क्या नीचे लिखे मुख्य उत्पादक हैं :—
(क) आपके धर्मशास्त्र ज्ञान के परीक्षक, (ख) किसान, (ग) घरेलू नौकर और (घ) व्यापारी। (उ० प्र० १९५१)
- ४—'उत्पत्ति' में आप क्या समझते हैं ? क्या निम्नलिखित उत्पादक हैं :— (अ) किसान, (आ) कवि का विद्यार्थी, (इ) प्रोफ़ेसर और (ई) माता-पिता। (उ० प्र० १९५२)
- ५—सन्तत उत्पादन के साधन प्रकृति तथा धन हैं। पूँजी और प्रयत्न को उत्पादन के अन्य साधन मानने का क्या अर्थ है ? (विहार-पटना १९५२)
- ६—'उत्पादन उपयोगिताओं का सृजन है'। 'उपभोग में उपयोगिता का विनाश होता है।' समझाइए। (सागर १९५४)

इण्टर एप्रीकल्चर परीक्षाएँ

- ७—उत्पत्ति का अर्थ बताइए। स्व, स्वामि तथा समन की उपयोगिता की स्पष्ट कीजिए। (अ० बो० १९५७)
- ८—धर्मशास्त्र में 'उत्पत्ति' का क्या अर्थ है ? उत्पत्ति और उपभोग के सम्बन्ध को विवेचना कीजिए। (अ० बो० १९५४)
- ९—'उत्पत्ति' में आप क्या समझते हैं ? उत्पत्ति के साधनों का संक्षेप में विवरण दीजिए और उनके पारस्परिक सम्बन्ध के महत्व को समझाइए। (अ० बो० १९५६)

भूमि का अर्थ (Meaning)—सामान्य भाषा में पृथ्वीतल (Surface of the Earth) का भूमि कहते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। अर्थशास्त्र में भूमि से अभिप्राय उन समस्त वस्तुओं और शक्तियों से है जो प्रकृति द्वारा निर्गुण धर्मोत्पत्ति के लिए मनुष्य को पृथ्वीतल पर प्रयत्न करने में सक्षम कर देती है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएँ समाविष्ट हैं —

(१) भूमि और उसके पोषण तत्व (२) मनुष्य शक्तियों का समूह जिससे भूमि को भूमि में परिवर्तित है (३) वायु जल तथा सूर्य और जलवायु (४) धरातल



की ऊँचाई-निचाई अर्थात् पहाड़, मैदान आदि, (२) नदी भ्रूल और समुद्र, (६) जलन, (७) विविध प्रकार का पशु-जीवन, (८) मछलियाँ, (९) समुद्र-तट व प्राकृतिक बन्दरगाह, (१०) कच्चा मात और (११) प्रेरक शक्तियाँ, जैसे वायुशक्ति, जलशक्ति आदि ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र में प्रकृति का वही भाग 'भूमि' में सम्मिलित किया जाता है जो धनोत्पत्ति में मनुष्य का सहायक होता है । प्रकृति का ऐसा भाग भूमि नहीं कहनाता । अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ वही प्राकृतिक प्रसाद (Free Gifts of Nature) में है । चूँकि इन सबमें भूमि ही प्रधान है, अतः ये सब प्रायः भूमि के ही नाम से सम्मोहित किये जाते हैं । दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि भूमि, प्राकृतिक प्रसाद और प्राकृतिक साधन एक त्वाँरे के पर्यायवाची शब्द हैं ।

भूमि की विशेषताएँ (Characteristics of Land)

भूमि में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं जो इससे और अन्य उत्पत्ति के साधनों के मध्य भिन्नता प्रकट करती हैं :—

(१) भूमि परिमाण में परिमित है—भूमि की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह परिमाण में परिमित है । यदि हम चाहे कि हमारे देश में रौना प्रपात कोबले की पालें जितनी प्रकृति ने दी है उससे अधिक हो जायें, तो यह असम्भव है । उत्पत्ति के अन्य साधनों की मिलने पर घटाया-बढ़ाया जा सकता है परन्तु भूमि का जितना परिमाण है उनका ही रहना । यदि भूमि का मूल्य जब जाय तो कहीं से नहीं भूमि पैदा नहीं की जा सकती । वह उसी ही रखी चाहे भूमि की माँग घटे या बढ़े ।

(२) भूमि उत्पत्ति का प्रमुख साधन है—भूमि उत्पत्ति का प्रमुख साधन है । इसके बिना उत्पत्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । धनोत्पत्ति के लिए प्राकृतिक साधन विद्यमान होने चाहिए । हमें भूमि की आवश्यकता उठने बैठने चलने फिरने, कारवायें बनाने, कच्चा मात पैदा करने व निकालने आदि कार्यों के लिए अत्यधिक है ।

(३) भूमि एक प्राकृतिक प्रसाद है—भूमि प्रकृति की देन है । यह मनुष्य की उत्पत्ति की हुई वस्तु नहीं है । मानव समाज को भूमि प्रकृति की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती है । परन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से भूमि का मूल्य हाता है । जब पूँजी और मानव-प्रयत्न द्वारा भूमि की उपयोगिता बढ़ा दी जाती है, तो इसकी खरीदने के लिए मनुष्य को पर्याप्त मूल्य देना पड़ता है ।

(४) भूमि स्थिर है—भूमि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकते । भूमि का जो भाग जहाँ पर स्थिर है, वह वहीं पर रहेगा ।

(५) भूमि उत्पत्ति का एक निष्किण साधन है—भूमि स्वयं उत्पत्ति नहीं कर सकती । प्राकृतिक साधन जिन अवस्था में रहे हैं, वैसे ही रहते हैं । उत्पत्ति के लिए अन्य साधनों की सहायता निरन्तर आवश्यक है । अनाज, कपास व अन्य वस्तुएँ भूमि पर प्रयत्न मात्र नहीं पैदा होती बल्कि मनुष्य को पूँजी आदि की सहायता से पूर्ण प्रयत्न करना पड़ता है ।

(६) भूमि अमर एवं अक्षय है—मनुष्य भूमि को नष्ट नहीं कर सकता । हाँ, यह बात अवश्य है कि प्राकृतिक कारणों से जैसे बाढ़ या भूकम्प आदि से जल

के स्थान में थल धीरे थल के स्थान में जल हो जाता है। पर भूमि का कुल परिमाण उतना ही रहता है जितना पहले था। उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परन्तु भूमि का उपजाऊपन अवश्य संभव है।

(७) भूमि उपजाऊपन की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता रखती है—सब जमीनें एक-सी नहीं होती—कोई बज्र और कोई रेतीली।

(८) भूमि का मूल्य उसकी स्थिति पर निर्भर है—जिन्ही जमीन के टुकड़े का मूल्य वादी वस्तु तक उसकी स्थिति पर निर्भर होता है। जो जमीन वस्त्र या नगर के समीप स्थित होती है उसका दूर स्थित जमीन की अपेक्षा अधिक लगान या किराया माता है। भूमि (मजदूरी) और व्यापार भी दूरी में अवश्य प्रभावित होने हैं पर इतने नहीं जितनी कि जमीन होती है।

धनोत्पत्ति में भूमि का कार्य एवं महत्त्व (Importance & Function of Land in Production)—भूमि धनोत्पत्ति का आधारभूत माधन है। इसके बिना किसी प्रकार की धनोत्पत्ति नहीं की जा सकती। भूमि में हमें जल, वायु, प्रकाश आदि प्राप्त होता है जिनके बिना हम एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। ससार में जितने काम होने हैं उन सब के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। भूमि पर ही मनुष्य रहने के लिए घर और धनी-पत्ति के लिए कारखाने बनाता है। इसी पर पैती होती है जिनके मनुष्य को नाना प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ मिलते हैं। इसी में अनेक उद्योग धन्य को बनाने वाले विविध प्रकार के कच्चे माल प्राप्त होते हैं। लोहा, कोयला, चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों की उत्पत्ति इसी में निहित है। जगत् में अनेक प्रकार की खनिजों तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, और समुद्र, नदियों तथा भीनों में मछलियाँ आदि पदार्थ निम्न हैं। नदियों के पानी में विद्युत्-शक्ति पैदा की जाती है जिसमें केवल प्रकाश ही नहीं मिलता बल्कि कारखाने भी चलाये जाते हैं। भूमि का एक महत्त्वपूर्ण उपमा यह है कि इस पर हम अपनी तथा व्यापार की सुविधा के लिए रेल, सड़कें, नहरें आदि बनाते हैं। अस्तु भूमि एक प्रकार का भण्डार है जहाँ में हमें ग्राह्य पदार्थ, वस्त्रा माल, वायु, जल, बहुमूल्य खनिज पदार्थ आदि मिलते हैं।

किसी देश की आर्थिक उन्नति बहुत अथ तक वहाँ के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है। यदि किसी देश की भूमि उपजाऊ है, भौतिक स्थिति उत्तम है, नदी पहाड़, जल तथा खनिज उचित परिमाण में विद्यमान हैं, वहाँ की जनबाहु अच्छी है और वर्षा नियमित समय पर पर्याप्त मात्रा में होती है, तो वह देश जिससे वह उन वस्तुओं का भण्डार रखने वाले अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है। उदाहरण के लिए, आज जो अमेरिका और इंग्लैंड की आर्थिक उन्नति की पुराना गमन सार में कहना रहते हैं, वह वहाँ के प्राकृतिक साधनों तथा उनके मनुष्यो का फल है। भारतवर्ष भी प्राकृतिक साधनों की दृष्टि में पूर्ण सम्पन्न है परन्तु हमें इस बात की है कि इनका उचित ढंग में प्रयोग नहीं किया जाता। हम यही मुख्य कारण है कि आज यह देश आर्थिक उन्नति की बुद्धि में अन्य देशों में नहीं निर्यात होता है।

भूमि की कार्य-क्षमता (Efficiency of Land)

भूमि की क्षमता का अर्थ है भूमि पर न्यूनतम परिश्रम और व्यय में अधिकतम तथा श्रेष्ठतर पैदावार करना। भूमि की क्षमता से उसकी उत्पादन शक्ति (Produce Capacity) का तात्पर्य होता है। भूमि की कार्य-कुशलता अथवा उत्पादन शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है।

(१) प्राकृतिक दशाएँ (Natural Conditions) — जिस अवस्था में प्राकृतिक साधन प्राप्त होते हैं उसका उत्पत्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनमें से मिट्टी जलवायु भीतरी नदी आदि का पैदावार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि मिट्टी उपजाऊ है तो पैदावार भी अधिक होगी। इसी प्रकार बहुत गरम या ठंडा जलवायु काम में बाधा डाल सकता है।

(२) सामाजिक दशाएँ (Social Conditions) — भूमि की स्थिति अर्थात् उसका आबादी या मण्डो से निकट होना और यातायात व सम्वाद के साधनों का उपलब्ध होना आदि बातें सामाजिक दशाओं में अंतर्गत आती हैं। इन दशाओं में परिवर्तन होने से भूमि की कार्य-क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे, एक दूर स्थित भूमि में निकट में रेलवे लाइन चला जायगी तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जायगी है।

(३) आर्थिक दशाएँ (Economic Conditions) — भूमि की कार्य-कुशलता आर्थिक दशाओं पर भी निर्भर है। जैसे उस पर जितनी पूँजी और धन लगाया जायगा उसकी उपज उतनी ही प्रभावित होती जायगी।

(४) मानव प्रयत्न (Human Efforts) — उपर्युक्त सब बातों के होने हुए भी भूमि की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए मानव प्रयत्न की आवश्यकता है। परिश्रमी और उद्योगी मनुष्य प्राकृतिक सुलभाओं को कुछ अंश तक दूर कर सकता है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य जलवायु को बदल कर अपने अनुकूल बना सकता है। यह पमान पर वृक्षों को लगान से जलवायु में अन्तर आ जाता है। इसी प्रकार उचित ढंग की खाद डालने से प्रदूषण वृक्ष परिवर्तन आदि से भूमि की उपज बढ़ाई जा सकती है। मनुष्य अपनी बुद्धिबल से यड़ी-बड़ी नदियाँ के बाँध बना कर नहरें निकाल सकता है। इसी प्रकार यातायात के साधनों में उत्तरी करने प्राकृतिक साधनों की स्थिति सुधार सकता है।

खेती करने की विविध रीतियाँ

(Various Methods of Cultivation)

खेती की पैदावार दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। एक तो नये रोना को जोत कर और दूसरे पुराने खेतों में ही अधिक पूँजी और परिश्रम लगाकर, अर्थात् खेती करने की दो मुख्य रीतियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं —

(१) विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) — नये देशों में खेती के यह-वह टुकड़ा पर अल्प पूँजी और धन में खेती करना विस्तृत खेती कहलाता है। जिन देशों में जनसंख्या कम होती है और भूमि की अधिकता होती है, वहाँ उपज बढ़ाने के लिए विस्तृत खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती आस्ट्रेलिया ब्रिटेन और अमेरिका जैसे नये देशों में प्रायः देखी जाती है जहाँ वृषभ एक ही भू-भाग से अधिकतम पैदावार का प्रयत्न नहीं करते।

विस्तृत खेती की विशेषताएँ (Characteristics)—विस्तृत खेती की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

१. इस प्रकार की खेती नये देशों में, जहाँ भूमि की अधिकता है तथा जहाँ जन-संख्या कम है, की जाती है।
२. खेती का औसत आकार बड़ा होता है।
३. अल्प पूँजी और थम लगाया जाता है।
४. इस प्रणाली में भूमि का उपयोग सापेक्षाही से किया जाता है।
५. इस कृषि प्रणाली में प्रायः खेद परिवर्तन (Rotation of Fields) का प्रयोग किया जाता है। सारी भूमि कई भागों में विभाजित कर कई खेन बना लिए जाते हैं जिन पर बारी-बारी से खेती की जाती है।

(२) गहरी खेती (Intensive Cultivation)—युएने देशों में छोटे-छोटे खेतों के टुकड़ों पर अधिक पूँजी और थम लगा कर खेती करने का 'गहरी खेती' कहते हैं। यूरान देशों में जहाँ पानी आवाही के कारण बैक्टीरिया हुई नई भूमि उपलब्ध नहीं होती वहाँ उपज की मात्रा बढ़ने पर युएने खेती में हों और अधिक पूँजी व थम लगाकर पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक किसान घरने खेती का उपज बढ़ाने करने प्रयत्न बुद्धि करने के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रयत्नशील रहता है। इस सम्बन्ध में उन्हें कृषि-विज्ञान में बड़ी सहायता मिलती है। इस प्रणाली का अनुकरण इङ्ग्लैंड, डेनमार्क, हॉलैण्ड आदि देशों में किया जाता है जहाँ की जनसंख्या अधिक भूमि की कमीसे ग्रस्त है। इन देशों में वैज्ञानिक मापनों द्वारा युएने खेती से ही उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। मारनार्थ एवं कृषि-प्रयत्न देश होते हुए भी इस क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत पीछे है।

गहरी खेती की विशेषताएँ (Characteristics)

१. इस प्रणाली का उपयोग युएने देशों में जहाँ जनसंख्या की अधिकता के कारण नई भूमि उपलब्ध नहीं होती, किया जाता है।
२. खेती का आकार छोटा होता है।
३. खेती में लगाना गहराई तक हल चला कर खेती की जाती है।
४. फल-परिवर्तन (Rotation of Crops) की युक्ति प्रयोग में लाई जाती है।
५. खेन के प्रयोग इष्ट पर खेती बड़ी सावधानी से की जाती है।
६. मिट्टी के तत्वों का अनुसंधान किया जाता है और जो बर्तियाँ होती हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों से पूरी की जाती हैं।
७. कृषि-सम्बन्धी प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएँ तथा थर्म (गैस) स्थापित किये जाते हैं जिनसे उत्तम प्रकार के बीजों, खादों और खेती के ढाँचे के परिणामों की जाँच की जाती है।
८. उत्तम प्रकार के हल और अन्य उपकरण (Implements) प्रयुक्त किये जाते हैं जिससे सारी कृषि-क्रिया वैज्ञानिक हो जाती है।
९. इस प्रकार खेती उन देशों में की जाती है जहाँ थम और पूँजी की प्रचुरता हो, परन्तु भूमि के प्रयोग में मितव्ययता बाँझीय हो।
- इन दोनों प्रकार के ढाँचों में कृषक का यही उद्देश्य रहता है कि उत्पाद के मापनों को बढ़ा कर उपज बढ़ाई जाय। विस्तृत खेती में तो भूमि अन्य मापनों की

प्रपेक्षा अधिक मात्रा में बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि नया देश होने और सावादी कम होने के कारण भूमि अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। परन्तु भेती में भूमि की कमी होने के कारण अन्य साधन अर्थात् यम और पूँजी ही बढ़ाये जाने हैं। माराध यह है कि परिस्थिति के अनुसार कृषक वही दंग प्रयोग में लाता है जो उसे कम लागत में अधिक उपज दे सके।

भारतवर्ष में गहरी भेती (Intensive Cultivation in India)

भारतवर्ष एक बहुत प्राचीन देश है जहाँ जन-संख्या की अधिकता और सहायक धन्यों के नष्ट हो जाने से भूमि पर भार अधिक हो गया है, अर्थात् यहाँ की अधिकांश जन-संख्या भूमि पर ही जीवन निर्वाह करती है। कुछ पड़न भूमि प्रयत्न है पर वह अधिकांश बेती योग्य नहीं है। मस्तु, यहाँ गहरी भेती होती है। भेती इस प्रकार गहराई में हो रही है कि गिट्टी की उत्पादन शक्ति प्रायः नष्ट हो चुकी है और अब उपज इतनी कम हो रही है कि बिना बाहर से मनाज रंगामे काम नहीं चल सकता है। यहाँ गहरी भेती होने का एक यह भी कारण है कि यातायात के साधनों में उन्नति होने के कारण उपज यही-यही मडियों तक सुगमता से पहुँचा दी जाती है जिसमें उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। इससे गहरी भेती करने की योजना बहुत प्रोत्साहन मिल जाता है। फिर भी भारतवर्ष में भेती की दशा ठीक नहीं है, इसमें कई कठिनाइयाँ हैं जो नीचे दी जाती हैं।

भारतवर्ष में गहरी भेती को अपनाने में कठिनाइयाँ

(Difficulties in the adoption of Intensive Cultivation)

(१) भारतीय कृषकों की मनभिरता और रुढ़िवादिता (Ignorance and Conservatism of Indian Cultivators)—भारतीय किसानों की अज्ञानता और लकीर का फकीर होना ही इस मार्ग में बड़ी घड़मन पैदा करता है। वे इसलिए इस प्रणाली को नहीं अपनाते क्योंकि उनसे पूर्वज इसको नहीं करने थे।

(२) कृषकों की निर्धनता (Poverty of Tillers)—कृषक वर्ष निर्धन होने से यांत्रिक उपकरणों द्वारा भेती नहीं कर सकते। अन्नकल की ऊँची दरो और सहकारिता के कारण उनकी दशा में अवस्थ सुधार हो गया है।

(३) साख की सुविधाओं का अभाव (Lack of Credit Facilities)—जो कुछ साख सुविधाएँ कृषकों को उपलब्ध हैं वे अपर्याप्त एवं बड़ी महँगी हैं। अतः किसान लोग भेती में नये सुधार करने के लिये इन महँगी सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकते।

(४) सिंचाई की सुविधाओं का अभाव (Lack of Irrigation Facilities)—भारत के सभी भागों में सिंचाई के साधन नहीं मिलते। यद्यपि राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में बहुत कुछ हुआ है, परन्तु अब भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया जा सकता है।

(५) अच्छे चरागाहों का अभाव (Lack of Good Pastures)—उत्तम चरागाहों की कमी होने के कारण यहाँ भेती कराने वाले अच्छे पशुओं का अभाव है।

(६) भेतों का छोटा-छोटा और यत्न-तन्त्र स्थित होना (Small and Scattered Holdings)—भेत छोटे छोटे टुकड़ों में बँटे होने और इसर उधर दूर-दूर हैं—१४

दूर स्थित होने के कारण उत्तम ढंगा और मशीनरी द्वारा सुधार होना सम्भव नहीं है।

किस प्रकार राज्य द्वारा कृषि की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सकती है ?

विस्तृत मैदान—राज्य द्वारा छोटे छोटे खेतों को मिठाकर बड़े खेत बनाने, सामूहिक और सहकारी मैदान बनाने और अशुद्ध (Uncultivated) भूमि पर मैदान बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

गहरी सिंचनी—राज्य द्वारा कृषकों को भूमि पर स्थायी सुधार करने की सहायता मिलनी चाहिये। इससे अनिश्चित कृषकों को बीज, खाद और लवणों के खर्च की सुविधाएँ प्राप्त हानी चाहिये।

भूमि की गतिशीलता (Mobility of Land)

बुद्ध प्राकृतिक साधन एवं शक्तियाँ गतिशील हैं—अर्थशास्त्र में भूमि शब्द एक व्यापक शब्द में प्रयुक्त होने के कारण इनमें प्राकृतिक साधन एवं शक्तियाँ सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ साधन व शक्तियाँ गतिशील हैं और अन्य नहीं। उदाहरण के लिए, मिट्टी का स्थानांतरण हो सकता है नदियों के साथ भाड़ जा सकता है, जब विद्युत शक्ति और खनिज पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानान्तरित किया जा सकता है।

भूमि स्वयं गतिशील नहीं है—भूमि की गतिशील कहना भ्रान्तिजनक है। इसकी उदाहरण एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना एक अत्यन्तव्य कार्य है।

भूमि किस माध्यम से गतिशील है—भूमि इस माध्यम से गतिशील है कि धन और पूँजी के ग्लोबल विनिर्माण से किसी क्षेत्र की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सकती है और किसी की घटाई जा सकती है।

भूमि वस्तुवाचन सिद्ध करने की सामान्य रचना के कारण इनमें गतिशीलता का प्रामाण्य अनुभव करने हैं। एक ही भूभाग पर धान खेताब या एक पैदा किया जा सकते हैं। हमारे देश में प्रायः पदार्थों की सबीर्णता होने के कारण बहुत सारी कूट और रई पैदा करने वाली भूमि श्रमदा खाल और बर्फ की पैदावार में लवा दी गई है। महा मठ दान स्मरण रखना चाहिये कि हम प्रकार का प्रयोग परिवर्तन भी कई दशकों में जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और पूँजी के विनिर्माण की सुविधा पर निर्भर होता है। जैसे कूट पैदा करने वाली मिट्टी बड़े पैदा करने में श्रममय है और निम्न जलवायु में बड़े पैदा होता है उसमें कूट पैदा होता बढित है।

विशिष्ट प्रयोजन वाली भूमि प्रयोग की दृष्टि से भी प्रचलन या स्थिर होती है—कुछ भूमि ऐसी होती है जो किसी विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध करने के अनिश्चित अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, खेती के उत्तरी भाग की भूमि में खेती जगह हो सकती है। वहाँ की भूमि उत्तरी उपजाऊ नहीं है कि फसलें पैदा करने के लिए जगह साफ करने का बर्त व व्यर्थ किया जाय।

बुद्ध अचल या स्थिर प्राकृतिक साधन—बुद्ध प्राकृतिक साधन ऐसे हैं जो पुरानेसा निर्मित हैं, जैसे—जलवायु, सूर्य का प्रकाश, नदियाँ, पहाड़ आदि। ये प्राकृतिक साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण एवं प्रदेश में दूसरे प्रदेश को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

भारतवर्ष के प्राकृतिक साधन (Natural Resources of India)

अब हम यहाँ भारतवर्ष के प्राकृतिक साधनों का अध्ययन करेंगे। प्रकृति ने भारत को जो उपहार भेंट किये हैं उनका हमारी आर्थिक व्यवस्था में बड़ा महत्व है। बिना इनका अध्ययन किये हम अपनी आर्थिक समस्याओं को ही नहीं कर सकेंगे। हमारी कोई भी आर्थिक योजना बिना इसके ज्ञान के सफल नहीं हो सकती। अस्तु हमें अपने देश के प्राकृतिक साधनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। १५ अगस्त १९४७ ई० को भारत स्वतन्त्र हुआ परन्तु यह दो भागों में विभाजित कर दिया गया—भारत और पाकिस्तान। हम पुस्तक में केवल भारतवर्ष का ही जल्लोचन किया गया है।

भारतवर्ष की स्थिति, सीमा और क्षेत्रफल (Situation, Boundary and Area of India)

भारतवर्ष भूमध्य रेखा के उत्तर में ८° से ३७° अक्षांश और ६८° से ९७° पूर्वी देशान्तरों के भीतर फैला हुआ है। भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल जम्मु व काश्मीर राज्य सहित १२,५६,७६७ वर्ग मील है। देश की उत्तर में दक्षिण में अधिक से अधिक लम्बाई २,००० मील है और पूर्व में पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। यह क्षेत्रफल रूस को छोड़कर समस्त यूरोप के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है और इङ्ग्लैण्ड का तेरह गुना, जापान का छः गुना, कनाडा का ३ और सोवियत रूस का ३ है। ससार की जन-संख्या का ३ भाग भारत में पाया जाता है।

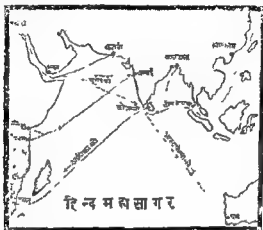
भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो ससार में सबसे ऊँचा है और सर्वत्र बर्फ में ढके रहते हैं। देश के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की ओर भी पहाड़ों की श्रेणियाँ हैं जिनमें कुछ दर्रे हैं। इन दर्रे के द्वारा वायव्यमन होता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर स्थित है। भारतवर्ष की स्थलीय सीमा ६,४२५ मील लम्बी है और इसका समुद्र तट ३,५३५ मील लम्बा है।

भारतवर्ष की स्थिति का महत्व

(१) भारतवर्ष पूर्वी गोलार्द्ध के लगभग मध्य में स्थित है जिसके कारण यह प्राचीन काल में ही विषय विख्यात रहा है। इसकी स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ से जल-मार्ग द्वारा ससार के सभी देशों को जहाज जाते हैं। वायु-मार्ग की दृष्टि से भी हमारे देश की स्थिति बड़ी उत्तम है। यूरोप तथा आस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित होने के कारण इन महाद्वीपों के बड़े-बड़े वायुयान भारत होकर जाते हैं। इस प्रकार भारत में संसार के समस्त देशों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं। अब स्वतन्त्र भारत को अपना स्वयं का जहाजी बेड़ा रखकर इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठा लेना चाहिए।

(२) भारतवर्ष की स्थिति का दूसरा महत्व यह है कि उनके उत्तर में हिमालय पर्वत उत्तरी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है तथा इस प्रकार होने वाले विदेशियों के आक्रमणों से इस देश की पूर्ण रक्षा करता है।

(३) भारतवर्ष की स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ चार प्रकार का जलवायु मिलता है जिनमें गर्म और ठंडे देशों की सभी संभावनाएँ यहाँ मिली हैं।



भारतवर्ष की स्थिति

भारतवर्ष का समुद्रतट (Coast line)

भारत का समुद्रतट लगभग ३,५३५ मील लम्बा है। परन्तु यह प्रतिक बन्दरगाहों का भीषण है जिनका कारण यहाँ उत्तम बन्दरगाहों का अभाव है। केवल बम्बई, मद्रास, हावर विदेशी जहाजों और जलयानों की अच्छे बन्दरगाह हैं।

भारतवर्ष के प्राकृतिक या भौतिक विभाग

(Natural or Geographical Regions of India)

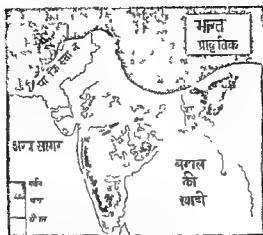
प्राकृतिक या भौतिक दृष्टि से भारत निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है —

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (१) उत्तरी पहाड़ी प्रदेश | (२) उत्तरी विन्ध्य मंडल |
| (३) दक्षिणी पठार | (४) समुद्रतटीय मैदान |

(१) उत्तरी पहाड़ी प्रदेश — भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है जो पूर्व में आसाम से पश्चिम में काश्मीर तक तीन सिरदारों से मिलता है १,५०० मील लम्बा है। इसकी औसत चौड़ाई २०० मील है। इसे समग्र में सबसे ऊँचा पर्वत माना जाता है।

हिमालय द्रोण होने वाले आर्थिक लाभ — भारत की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में हिमालय पर्वत का बड़ा महत्व है —

(१) यह उत्तर में आसाम से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है जिससे देश की पैदावार आदि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।



(२) हिन्द महासागर में मान घासी जल में भारी हवासा को रोक कर देश में वर्षा काला है जिससे कृषि में बड़ी उपजति होगी ।

(३) पश्चिमी भाग के ठाना पर वन है जिसकी लकड़ी से कई प्रकार के कारखाने चलान हैं ।

(४) पहाड़ी भागों की निम्नी भूमि में चाराघाट है जहाँ पशुपालन और उमम सम्बद्ध करने चलन है ।

(५) हिमालय पर्वत में अनेक बड़ी-बुटियाँ प्राप्त होती हैं जिससे शीतल व्यवसाय का पर्याप्त प्रालाहन मिलता है ।

(६) भारत की २० प्रतिशत चाय यहाँ ही उत्पन्न होती है ।

(७) पहाड़ी भाग के वना में जंगली पशुधा का शिकार किया जाता है और उनका चमड़ा और हड्डियाँ काम में लाई जाती है ।

(८) हमने हमारे देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा होती है जिससे हम गान्तिपूर्वक अपने आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सकते हैं ।

(९) पहाड़ी भाग में बहने वाली नदिया से जल विद्युत उत्पन्न कर अनेक व्यवसाय चलाये जाते हैं ।

(१०) हिमालय पर्वत में अनेक नदियाँ निकलती हैं जिनसे मैदान में सिंचाई होती है ।

(११) हिमालय प्रदेश का जनवायु स्वास्थ्यकर होने के कारण वहाँ सहस्र। मनुष्य अपने स्वास्थ्य सम्पादन के लिये जाते हैं । वहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य रमणीय होने के कारण मित्रों यात्रे एक बड़ी मर्या में प्रतिवर्ष जाते हैं जिससे भारत को बड़ी आय होती है ।

(१२) उत्तरी विशाल मैदान—यह मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है । यह लगभग २००० मील लम्बा और १५० मील चौड़ा है । यहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा सिंचाई के साधन विद्यमान होने के कारण यहाँ कृषि मुख्य उद्योग है । कृषि की प्रगति का दूसरा

कारण यह है कि इस भाग में खनिज पदार्थों का पूर्ण अभाव है। इस मैदान में कभी जन संख्या है तथा कई व्यापारिक मण्डल रखने वाले नगर भी स्थित हैं।

(३) दक्षिणी पठार—इस भाग के उत्तर में विन्ध्याचल और सतपुठा पहाड़, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित हैं। यह सम्पूर्ण भाग पथरीला और ढूँढ़ा-फूटा है। पठार की औसत ऊँचाई समुद्र-तल से २००० फीट है। इसमें होकर बहने वाले मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। जिनका आर्थिक विकास उत्तरी मैदान का हुआ है उनका दक्षिणी पठार का नहीं हुआ। पठारी मार्ग होने के कारण यहाँ कुछ कठिनाईयाँ अवश्य हैं—कृषि के निम्न अधिक भूमि नहीं है, वर्षा भी कम होती है और घातघात के साधनों में भी बाधा है, परन्तु मनुष्य के निरंतर प्रयत्न द्वारा ये सब समस्याएँ हल हो सकती हैं।

(४) समुद्रतटीय मैदान—दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिम में तटों पर समुद्र तट हैं। इस तट के दो विभाग विद्ये जा सकते हैं—(अ) पश्चिम समुद्र तट और (ब) पूर्वी समुद्र तट। अरब सागर के उठने वाली जलधरी हवाएँ पश्चिम तट पर झण्डो खपाँ करती हैं। यहाँ मैदान की कमी के कारण अधिक खेती भी नहीं हो सकती परन्तु बनों की लकड़ी का सतुपयोग किया जा सकता है। जहाँ समतल मैदान है वहाँ चावल, गन्नें मसाला तथा तारियल की अच्छी पैदावार होती है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तट पर वर्षा कम होने पर भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी आदि नदियों में बिचाई हो जाने के कारण यहाँ खेती अच्छी होती है। यहाँ की मुख्य उपज चावल और गन्ना है। समुद्र तट कटा-फटा हुआ नहीं होने के कारण इस पर प्राकृतिक बन्दरगाहों का अभाव है।

भारतवर्ष की भूमि (Soils of India)

भारतवर्ष की भूमि गोटे रूप में निम्नरितित श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है :—

(१) टमट भूमि (Alluvial Soils)—यह भूमि नदियों में साईं हुई मिट्टी से बनती है, इसलिए बड़ा उपजाऊ होती है। यह भूमि अधिकतर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आन्ध्र, गोदावरी, कृष्णा, पश्चिमी घोर पूर्वी समुद्र-तटीय मैदानों में फैली हुई है। यह भूमि लगभग ३ लाख वर्गमील के क्षेत्रफल को घेर रही है और बहुत गहरी तथा उपजाऊ है।

विशेषताएँ—नर जगह इस भूमि की रचना तथा गुण समान हटिगोबर नहीं होते। भारत के उत्तर-पश्चिम में यह भूमि छिन्नक (Porus) और शुष्क है और इसी प्रकार के कई स्थानों में यह रेतीली है, उत्तर प्रदेश बिहार और उड़ीसा में यह लोम (Loams) के रूप में मिलती है और बंगाल में यह भूमि अधिक टोम (Compact) और नर (Moist) हुआ गई है। यह भूमि लगभग सभी रसायनिक तत्वों में परिपूर्ण होने के कारण बड़ी उपजाऊ है। इसमें नात्रे (Nitrate) की कमी अवश्य है, परन्तु वह सावर की माषाग्न लाट में गुनी की जा सकती है। यह बिचाई की मुविधाओं में अग्रज होने पर खेती और खरीप की सभी फसलें उत्पन्न कर सकती है।

(२) काली भूमि (Black Soils)—यह भूमि ज्वालामुखी पदार्थों के पट्टने में जा राख बाहर निकलती है उनके उड़ होकर जमीन में बनती है। इसे 'लाय' भूमि भी कहते हैं। यह भूमि मध्य प्रदेश के मलवा भाग में, काठियावाड़ नगर

पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य भारत क्षेत्र, मध्य प्रदेश राज्य के बैलारी, कुरवूल, कोयंबटूर और दिनेवेली जिलों में फैली हुई है। इस प्रकार इसके द्वारा लगभग २ लाख वर्गमीन भूमि घिरी हुई है।

विशेषताएँ—इस भूमि में समिन्न पदार्थों सन्निहित होने के कारण इसका रंग काला होता है। इस भूमि की एक विशेषता यह है कि वर्षा ऋतु में पड़ने वाले पानी को अपने अन्दर सोख नहीं ले और नुष्क ऋतु में पौधों को पानी पहुँचाती रहती है। इस प्रकार इस भूमि में दीर्घ बाल तक नमी नहीं रहती है। यह भूमि प्रायः रबी की फसलों के लिये बड़ी उपयुक्त है, परन्तु खरीफ की फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं।

(३) लाल भूमि (Red Soils)—इस प्रकार की भूमि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, बंगाल का दक्षिणी भाग, बड़ोदा और घरावली, राजस्थान व आन्ध्र प्रदेश में पाई जाती है।

विशेषताएँ—लाल भूमि की रचना, गहरी और उपजाऊपन में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। नुष्क पठारों पर यह कम गहरी कम उपजाऊ, ककरीली, रेमीली या पथरीली और हल्के रंग की है जिसमें केवल बाजरा आदि की साधारण फसल हो सकती है। परन्तु नीचे के मैदानों में उपजाऊ, गहरी, चपकीले लाल रंग की, गहरे भूरे रंग की या काले रंग की है जिसमें मिर्चाई की गन्नायता में विविध उत्तम फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें नाइट्रोजन (Nitrogen), फॉस्फोरस वा अम्ल (Phosphoric Acid) और नमी (Humus) का अभाव होता है, परन्तु पोटैश (Potash) और चूना (Lime) पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं।

(४) हल्के लाल रंग की भूमि (Laterite Soils)—यह भूमि भी लाल रंग की होती है जो उष्ण कटिबंध की गहरी जल सृष्टि के कारण लाल रंग की चट्टानों के पुलने में बनती है। यह ईंट सहस्र भूमि दक्षिणी पठार की ऊँची चोटियों, मध्य प्रदेश, पूर्वी पाट का अधिकांश भाग, उड़ीसा तथा बम्बई के दक्षिणी भाग, मलाबार तट पर पाई जाती है। आन्ध्र प्रदेश के पठारी भाग में कुछ स्थानों में भी यह मिट्टी मिलती है।

विशेषताएँ—यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। इसमें पाटाश, चूना,

फॉस्फोरस और मैग्नेशिया की कमी रहती है। ऊँचे भागों में यह मिट्टी बहुत कम गहरी होती है और ककरीली होती है। परन्तु नदियों की घाटियों और नीची भूमि में यह प्रायः मिट्टियों के मिश्रण में तथा गहरी के कारण उच्च पोष्य बन गई है। इस मिट्टी में विशेषतया चावल को पैदावार दी जाती है।



भूमि की उर्वरा-शक्ति को निर्धारित करने वाले तथ्य

(Factors that govern the fertility of the soil)

(१) प्रकृति (Nature) — भूमि की प्राकृतिक रचना की भिन्नता के साथ साथ भूमि के उपजाऊन में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे दुमट भूमि अन्य प्रकार की भूमि से अधिक उपजाऊ होती है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तुलना भारतीय कृषक को अधिक प्राकृतिक लाभ पहुँचते हैं।

(२) खाद (Manuring) — भूमि का उपजाऊन खाद पर भी निर्भर है। भूमि की प्राकृतिक वसिया की कृत्रिम हलों अर्थात् खाद, कमल परिवर्तन प्रववा मिश्रित पसल द्वारा पूरा किया जा सकता है। यह बात नहीं है कि भारतीय कृषक खाद के महत्त्व को नहीं समझता। उनकी अज्ञानता, रुढ़िवादिता और सुस्ती ही इन दलों को न अपनाने का मुख्य कारण है।

(३) जल (Water) — किसी भूमि की उर्वरा-शक्ति पानी पर भी निर्भर है। भारतभर में जल-वृष्टि अनिश्चित व अनियमित रूप में होती है। प्रचुर पानी की कमी नुषों, तानाबा और नहरों से सिंचाई कर पूरी की जाती है। फिर भी बहुत-सारी भूमि बिना सिंचाई की सुविधाओं के बेकार पड़ी हुई है। अस्तु, सिंचाई के साधना विशेषतया नहरा—के प्रसार के लिए अभी यहाँ पर्याप्त क्षमता है।

(४) वैज्ञानिक ढंग और उपकरण (Scientific Methods and Implements) — प्राधुनिक वैज्ञानिक ढंगों तथा उपकरणों (मशीनों) द्वारा भूमि की उपज बढ़ाई जा सकती है। परन्तु भारतीय कृषक विधेन होने के कारण इन सब का प्रयोग करने में असमर्थ है।

भूमि की समस्याएँ (Problems of the Soil)

भूमि सम्बन्धी दो मुख्य समस्याएँ हैं—भूमि का बटाव और भूमि-शक्ति।

(१) भूमि का बटाव (Soil Erosion)

अर्थ—वृष्टि के जल प्रववा वायु से भूमि के उत्तम बरणा के बह जाने या उड़ कर बने जाने को 'भूमि का बटाव' कहते हैं। भूमि का बटाव वृषि-जलन की विध्व-भ्यापी समस्या है। पृथ्वी पर यह बटाव कहीं मन्द गति से घोर कहीं वेग में होता पा रहा है। कृषि प्रयोग क्षेत्र भिमुरी (अमरिका) में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भूमि के २% ढाल पर ४० टन उपजाऊ मिट्टी प्रति एकड़ बट जाती है। अमेरिका के चिक्ना वुड मिट्टी के ३% ढाल पर जहाँ २३-५" वर्षा होती है ४० टन मिट्टी प्रति एकड़ का ह्रास होता है। चेम्बरलिन का कथन है कि १ फुट मोटी मिट्टी बनाने में दस हजार वर्ष से भी अधिक समय लगता है।

भूमि के बटाव के प्रकार (Kinds) — भूमि का बटाव मुख्यतः दो प्रकार से होता है —

(१) सतह बटाव (Sheet Erosion) — जब भूमि की सतह के मुलायम तम बासीक नए पानी के साथ बह जाने है प्रववा हवा के साथ उड़ जाने है, तब भूमि के ऐसे बटाव को 'सतह बटाव' कहते हैं।

(२) गहरा या गालोदार बटाव (Gully Erosion) — जब वर्षा का पल भूमि पर तीव्र गति में बहता है तो भूमि पर गहरे छद्मे तथा गालियाँ बन जाती

है। इसे 'गहरा या गालीदार कटाव' कहते हैं। यह कटाव बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इन गाली के द्वारा अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी बहती रहती है। जिससे भूमि विलुप्त कृषि योग्य नहीं रहती।

भूमि के कटाव के कारण—भूमि के कटाव को प्रोत्साहन देने वाली कई बातें हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

- (१) भूमि पर वनस्पति का अनुपस्थिति । (२) मानसून की मात्रा ।
(३) भूमि की स्थिति । (४) भूमि का ढाल । (५) भूमि पर वायु की गति ।

भूमि के कटाव के साधन (Agencies of Soil Erosion)—भूमि का कटाव दो साधनों में होता है—(१) जल-वृष्टि (Rainfall), और (२) हवा (Wind)।

भूमि के कटाव से हानियाँ—(१) उपजाऊ मिट्टी के हटने से यह स्थान खेती के लिए निरस हो जाता है। (२) बहाई हुई मिट्टी उस स्थान को हानि पहुँचा सकती है जहाँ पर वह इकट्ठी हो। (३) कहीं कुएँ या छोटी नदियाँ सूख जाती हैं तो कहीं नदियों में बाढ़ आती है।

उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, झाँसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, लुधियानपुर, जौनपुर आदि जिलों में भूमि का कटाव अधिक योग्य पर है। राजस्थान का मरुस्थल लगभग ३२,००० एकड़ प्रति वर्ष भयंकर गति से उत्तर-प्रदेश में ढल रहा है। उत्तर-प्रदेश में लगभग ४६ लाख एकड़ भूमि कटाव के कारण कृषि के अयोग्य हो चुकी है।

भूमि के कटाव को रोकने के उपाय

(१) पर्वत पर जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ वृक्ष लगा देने चाहिये। ऐसा करने से नदी के प्रवाह में रुकावट होकर पानी की बंद गति हो जायगी।

(२) नदी के ऊपरी भाग में कई स्थानों पर बाँध बना देने चाहिये। ऐसा करने से भी पानी का प्रवाह धीमा पड़ जायगा। इन बाँधों का पानी फिर कई प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है।

(३) पहाड़ी ढालों पर जहाँ से पानी बहता हो, ब्यारियाँ ली बना लेनी चाहिये। ऐसा करने में पानी तेजी से न बहकर धीरे-धीरे बहेगा जिससे मिट्टी बहकर नहीं जा सकेगी।

(४) खुनी भूमि पर पेड़ लगाये जाने चाहिये, चाहे उनसे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ न हो।

(५) भूमि का ढाल जिस दिशा में हो, ठीक समाने विपरीत दिशा में फसल की कटाव होनी चाहिये। परन्तु घनी फसलों को ढाल की भूमि में कतार में नहीं बोना चाहिए।

(६) चरागाहों पर पशुओं को स्वतन्त्र छोड़ने की प्रथा बन्द कर देनी चाहिये ताकि घास उगी रहेगी जिससे पानी भूमि में नसा जायगा। पानी द्वारा कटाव कम हो जायगा और घास भी अधिक प्राप्त होगी।



ढाल के विरुद्ध फसल की कतार

(७) घास के चारों ओर के बगीचों की भूमि क्षति भूमि पर चूने (Terraces) और बहाव की नालियाँ (Drains) बना कर खेती करनी चाहिए जिसमें ऊँचाई में आने वाला पानी रुकता हुआ आता है और वह अधिक भूमि नहीं काट पाता। फसल को पानी की भाँति अधिक रूप में प्राप्त होता है।



टिरेसिंग विधि द्वारा खेती

(८) जब खेत का ढाल १ मीटर में १० से १५ फीट तक हो तो वहाँ मेंटों का प्रयोग किया जाता है। खेत के चारों ओर मजबूत मेंट होनी चाहिए। माथा रखतवा मेंट की चौड़ाई ४ फीट और ऊँचाई २ फीट होनी चाहिए। ताकि पानी का बहाव चारों ओर से हो सके। पानी निकलने के लिये नाली (Drain) का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये जिसमें खेत का पानी बिना मिट्टी बहाव निकल जाय।



खेत की मजबूती

(९) बहुत ही ढाल वाली भूमि में यह बड़ा प्रतिकूल होता है क्योंकि इसमें मुरझाव प्रचलित होता है। खाद देने पर यह भूमि अधिक विपत्ति हो जाती है। विपत्तिवाहक बड़ जाने से नाशपूर्ण पानी और पानी की गति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(१०) जहाँ गहरे बड़ाव के कारण दरार पड़ गई हो वहाँ उनके मुँह पर मिट्टी के ढाँ लगा देने चाहिए जिससे बालांतर में वही हुई मिट्टी के पुनः जमा हो जाने में देर नहीं लगने का भय रहे।

केन्द्रीय भूमि रक्षा मंडल (Central Soil Conservation Board)

योजना आयोग के परामर्श पर ही केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर मई १९५३ में इस मंडल की स्थापना की। इस मंडल का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के बड़ाव व बहाव से होने वाली हानियों के कारणों पर विचार करके उनकी रोक के उपायों पर सरकार की परामर्श देना है। इसी मंडल के अध्यक्षता में गवर्नर के अध्यक्ष की पूर्ण को और प्राग्विक से रोकने के लिए राजस्व व उद्योग प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में वन लगाने का मुझा दिया गया है। मध्यम निष्पत्ति के विषय में अनुसंधान करने के लिए जोधपुर में 'मरुस्थल वन अनुसंधानशाला' स्थापित की जा चुकी है।

योजना और भूमि संरक्षण—दूसरी योजना में भूमि संरक्षण के लिए २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एक व्यापक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसमें २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र, पट्टा बाढ़ क्षेत्र, बेवार पड़ी भूमि और पहाड़ी क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वयं भूमि-संरक्षण का कार्य कर रही है।

(२) भूमि थान्ति (Soil Exhaustion)

भूमि पर निरन्तर अत्यधिक फसलें पैदा करने में जब उसकी उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है तो हम उसे 'भूमि थान्ति' कहते हैं। बिना विश्राम तथा खाद दिये निरन्तर बेती करने रहने में भूमि झिल्लुन थक जाती है।

भूमि-थान्ति के कारण—(१) निरन्तर फसलें पैदा करने के कारण भूमि को आराम करने का अवसर नहीं मिल पाता। (२) फसल के रोटेशन (Rotation) में नहीं खेता। (३) रसायनिक खादों का अभाव। (४) भांगर की जन-गत्या का लगातार बढ़ना और भूमि के क्षेत्र का सीमित होना। सीमित क्षेत्र में अधिकाधिक भांगर उत्पन्न करना।

भूमि-थान्ति से बचने के उपाय—(१) फसल का हेर फेर (Rotation of Crops)। (२) खेतों को मारी-बागी से जोड़ना। (३) दो-तीन बप के बाद भूमि को एक फसल के लिये पलती छोड़ना। (४) गोबर का उपयोग केवल खाद के लिये ही करना। ईंधन के लिये लकड़ी का प्रयोग करना। (५) हरी खाद (Green Manure) के लिये मूँद, डेडा, घूँग, मरहम, रातजम आदि की फसलें खेता। (६) रासायनिक खादों का उपयोग करना। (७) महापशु फसलों आदि में भूमि पर स्थित जन-मकान का दमन बम करना।

भारतवर्ष का जलवायु (Climate of India)

भारतवर्ष एक विचाल देश है जो 8° से 37° उत्तरी अक्षांशों तक फैला हुआ है। बर्फ रेखा इसकी लगभग दो भागों में विभक्त करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। मनु कि की इसने विभिन्न भागों के जलवायु में बड़ा अन्तर है। जैसे पश्चिम में गर्मी और गर्मी दोनों ही अधिक पड़ती है। मनु उष्ण ज्यों पूर्व की ओर जाने है तापक्रम का अन्तर कम होता जाता है और बर्षा में आसाम में तो सर्दी और गर्मी दोनों ही कम हो जाती है। इसी प्रकार राजस्थान और पश्चिम में जलवायु शुष्क है, किन्तु बर्षा और आसाम में यही नमी लिए हुए है। उत्तरी भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में शरद ऋतु में बड़ी गर्मी और ग्रीष्म ऋतु में स्वाम्भयप्रद सर्दी पड़ती है। समुद्रतटा पर समशीतोष्ण जलवायु मिलता है। इस प्रकार भारत का जलवायु अर्द्ध उष्ण (Semi-Tropical) कहा जा सकता है।

भारतवर्ष के जलवायु का आर्थिक प्रभाव

(Economic Effects of Climate of India)

(१) भारतवर्ष में कई प्रकार का जलवायु मिलने के कारण यहाँ गन्धक के साथ पदार्थ एवं अच्छा मात पैदा किया जा सकता है। इन प्रकार भारत आर्थिक समस्याओं के लिये स्वावलम्बी हो सकता है।

(२) जलवायु की भिन्नता के साथ-साथ वनस्पति और जीव-जन्तुओं में भी भिन्नता पाई जाती है। वही घने जंगल घेर-चीना आदि पशुओं में परिपूर्ण मिलता है वही पास के मैदानों में हिरन, गाय, बैल आदि जानवर हटिगोचर होने हैं और मत्स्यजाल में छोटी-छोटी भाड़ियों को खाने वाले ऊँट, भेड़ बकरी पाये जाते हैं।

(३) जलवायु का मनुष्यों की कार्यक्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु में रहने वाले प्रायः निर्जल और आन्तरी रहने हैं जबकि ठंडे देशों के लोग मजदूर और परियमी होते हैं।

(४) जलवायु मस्तिष्क को प्रभावित करती है। गर्म जलवायु में रहने वाले निरन्तर मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकते। अन्वेषण में यह ज्ञात हुआ है कि ६०° फा० का तापक्रम शारीरिक कार्य के लिये आवश्यक है और ३०° फा० का तापक्रम मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्य के लिये।

(५) जलवायु से मनुष्यों के वेशे निर्धारित होते हैं। जिस देश का जलवायु गर्म और तर होता है, वहाँ सेनी अधिक होने के कारण वहाँ ने निवासियों का मृदुन घग्घा लेनी ही होगी। भारत में कृषि प्रधान होने का यही मुख्य कारण है।

(६) जलवायु से मनुष्यों की वेषभूषा निर्धारित होती है। ठंडे देशों के लोग ऊनी और गरम वस्त्र पहनने हैं और गर्म देशों में सूती और ठीले वस्त्र प्रचलित किये जाते हैं।

(७) मकानों की बनावट, नगरों की बनावट और सड़कों आदि की योजनाएँ जलवायु में पूर्ण प्रभावित होती हैं। ठंडे जलवायु के प्रदेशों में मकानों में आगन आवश्यक नहीं, परन्तु गर्म जलवायु के प्रदेशों में मकानों में आगन का होना आवश्यक है।

(८) गर्म जलवायु में अहाँ धूप तेज पड़ती है, चमकीले रंग प्रसन्न किये जाते हैं, किन्तु ठंडे एवं चनाच्छादित प्रदेशों में हल्के और सादे रंग अच्छे लगते हैं। भारत में इस प्रकार के रंग इसीलिये 'इ गलिख कलर' कहे जाते हैं।

जलवृष्टि (Rainfall)

जलवृष्टि जलवायु का प्रमुख अंग है। बिना तापक्रम और जलवृष्टि में जलवायु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। भारतवर्ष में जलवृष्टि अधिकतर मानसून हवाओं से होती है, इसीलिये भारत ने जलवायु को 'मानसून जलवायु' कहे हैं।

मानसून का अर्थ—यह शब्द अरबी भाषा के 'मौसिम' शब्द से निकला है, परन्तु अरब इसमें तात्पर्य पानी बरसाने वाली मौसमी हवाओं से है। भारत में ये हवाएँ गर्मी और सर्मी दोनों मौसमों में चलती हैं और पानी बरसती हैं। गर्मी में ये हवाएँ दक्षिण पश्चिम से चलने के कारण इन्हे दक्षिण पश्चिमी मानसून (South-West Monsoon) कहते हैं। इसी प्रकार शीतकालीन हवाएँ उत्तर पूर्व की ओर से चलने के कारण उत्तर-पूर्वी मानसून (North-East Monsoon) कहलाती हैं।

मानसून हवाओं के उत्पन्न होने के कारण—भारत में अधिकतर जलवृष्टि ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। गर्मी के दिनों में जबकि सूर्य बर्फ रेखा पर होता है, तब भारत का पूरा भाग (उत्तरी भारत) जल की अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाता है और बड़ी की हवाएँ गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं जिससे वायु भार कम (Low Pressure) हो जाता है। सूर्य से दूर स्थिर तबुद्ध पर इस समय भूमि की अस्थिरता कम गर्म होने के कारण वायु-भार अधिक (High Pressure) होगा। घट. हवाएँ उच्च वायु भार से कम वायु भार की ओर अर्थात् तबुद्ध से भूमि की ओर चलती हैं। ये हवाएँ तबुद्ध पर से हजारों मील की यात्रा करती हुई आने के कारण जल से परिपूर्ण होती हैं। जब ये हवाएँ मार्ग में स्थित जियो पहाड़ों को पार करने के लिये ऊपर चढ़ती हैं तो ठण्डी होकर वर्षा के रूप में गिर आती हैं। ये हवाएँ ग्रीष्म ऋतु में (जून में मितम्बर तक) चलती हैं, इस कारण इन्हे गर्मी का मानसून और दक्षिण-पश्चिम की ओर से चलने के कारण दक्षिण-पश्चिमी मानसून (South-West Monsoon) कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग ८० प्रतिशत वर्षा इन्हीं हवाओं से होती है, अतः उनका यहाँ बड़ा महत्व है।

शीतकाल में सूर्य की मकर रेखा पर आ जाने के कारण वायु भार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात् भूमि पर उच्च वायु भार और समुद्र पर कम वायु भार रहता है। अतः हवाएँ शीतकाल में भूमि की ओर से समुद्र की ओर चलती हैं। भूमि की ओर से चलने वाली हवाएँ शुष्क होती हैं परन्तु जब ये हवाएँ बंगाल की खाड़ी में से होकर आगे बढ़ती हैं, तो अपने मांस पानी ले लेती हैं। दक्षिणी भारत का दक्षिणी-पूर्वी भाग और लका का पूर्वी भाग इन हवाओं के मार्ग में पड़ने के कारण मदास में इन हवाओं में शीतकाल में अच्छी वर्षा होती है। ये हवाएँ शीतकाल में अक्टूबर से जनवरी तक चलती हैं, इसीसे इन्हें शीतकालीन मानसून और उत्तर-पूर्व की ओर से चलने के कारण उत्तरी-पूर्वी मानसून (North East Monsoon) कहते हैं।

जलवृष्टि का वितरण (Distribution of Rainfall)

ग्रीष्म कालीन मानसून (The Summer Monsoon)—इसकी मुख्य दो शाखाएँ हैं—अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा।

अरब सागर की शाखा (The Arabian Sea Branch)—ग्रीष्म काल में जो हवाएँ अरब सागर में उठती हैं वे उत्तरपश्चिम की ओर से आती हैं और पश्चिमी घाट में टकराती हैं जिससे वहाँ अधिक जलवृष्टि होती है। पश्चिमी घाटीय मैदान में इन हवाओं से औसत ८० इंच वर्षा होती है। ये हवाएँ उत्तर की ओर भी जाती हैं और देश के कुछ अन्य भागों (राजस्थान मध्यप्रदेश) में भी वर्षा करती हैं।

बंगाल की खाड़ी की शाखा (The Bay of Bengal Branch)—

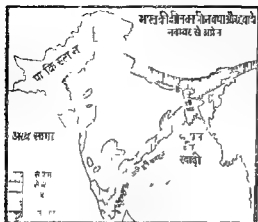
जो जल में परिपूर्ण हवाएँ बंगाल की खाड़ी से उठती हैं वे आसाम की कुछ पहाड़ियों से सीधी टकराती हैं। जिसके फलस्वरूप वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। अमेले बिरापूर्जी में सन् १८६१ में ८०० इंच से भी अधिक वर्षा हुई पाई जाती है, वैसे औसत ४६० इंच का है। ये हवाएँ हिमालय पर्वत के कारण सीधी उत्तर की ओर निकल जाने के बजाय वाई भार



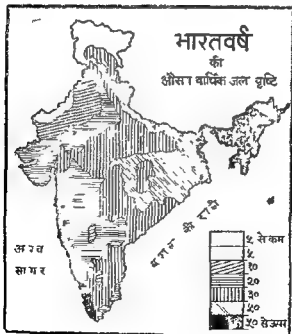
मुद्र जाती हैं। ज्यों ज्यों पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं त्यों-त्यों वर्षा में कमी होती जाती है यहाँ तक कि सिन्ध में वर्षा २ या ३ इंच ही होती है।

शीतकालीन मानसून (The Winter Monsoon) — शीतकाल में

हवाएँ स्थल भाग से
जल भाग की ओर
चलती हैं घट के
गुण होती हैं। जब
बंगाल की खाड़ी पर
से होकर जाती हैं तो
ग्रसन में पानी न
लेती हैं और मग्न में
स्थित मद्रास के उत्तर
और दक्षिण के जिलों
और पूर्वी तथा म
पश्चिम बंगाल होती हैं।
इन्हें प्रतिदिन शीत
वात में कुछ वर्षा
पड़ाव लगने में मध्य
प्रदेश और माला में
भी होती है।



नीचे दिया गया मानचित्र भारत में जलवृष्टि के वितरण को दर्शाता है —



भारतीय मानसून की विशेषताएँ

(Peculiarities of Indian Monsoon)

- (१) देश की लगभग ६० प्रतिशत वर्षा मानसून द्वारा होती है ।
 - (२) अधिकांश वर्षा गाल भर न होकर कुछ ही महीनों में होती है । गर्मी का मानसून जून से सितम्बर और सर्दी का अक्टूबर से जनवरी तक सीमित है । गर्मी के मानसून से अधिक वर्षा होती है ।
 - (३) मानसून कभी-कभी नियत समय पर न आकर प्रायेः-भीड़े आता है ।
 - (४) मानसून कभी-कभी तो बिल्कुल हँ नहँ आता जिससे बरफ़ण टपि को भयानक हानि पहुँचती है ।
 - (५) यह भी कहा जाता है कि पाँच वर्षों के नामचक्र में एक उत्तम, एक निरुद्ध और तीन वर्ष उदासीन होते हैं ।
 - (६) मानसून से मूसलाधार वर्षा हल्की है । पानी तभी में बहता है जिससे भूमि के उपजाऊ मत्स्य को बहा कर ले जाता है ।
 - (७) वर्षा के वार्षिक औसत में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के मध्य पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है । जैसे चेरापूजी में ४६०" औसत है तो छिन्ध के उत्तरी भाग में केवल २" या ३" ही है ।
 - (८) जो भाग मानसून के मार्ग में आता है वहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ अधिक वर्षा होती है ।
 - (९) मानसून उठते समय समुद्र से बड़े तूफान आते हैं जिससे समुद्रतटीय प्रदेशों में जल ब धन की बड़ी क्षति होती है ।
 - (१०) सर्दी के मानसून से बहुत कम वर्षा होती है और वह भी देश के कुछ ही भागों में । अधिकतर वर्षा लगभग सर्दी प्रान्तों में गर्मी के मानसून में होती है ।
 - (११) गर्मी और सर्दी के मानसूनों के कारण भारतवर्ष में केवल दो ही पन्ने—रबी और खरीफ होती हैं ।
 - (१२) जलवृष्टि साल भर न होकर केवल कुछ ही महीनों में सीमित होने के कारण भारतवर्ष में अच्छे खेतावाहों का अभाव है । इसके फलस्वरूप पशुओं को सूखी बड़बी पर रखा जाता है जिससे वे अधिक बलिष्ठ नहीं हो पाते ।
 - (१३) ग्रीष्म ऋतु की सूख गर्मी के पड़पाव वर्षा होने के कारण भारतवर्ष में अनेक बीमारियों के जन्मदाता कीड़े-मकोड़े पैदा हो जाते हैं । जैसे मलेरिया (Malaria), आमतिहार (Dysentery) आदि । अनेक बीमारियों के बीजाणु उत्पन्न होकर वर्षा ऋतु में धीरे-धीरे पड़पाव अनेक भारतवासियों को बीमार कर निर्बल कर देने हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।
 - (१४) भारतवर्ष के गर्म क्षेत्र जलवायु ने भारतवासियों की कार्यकुशलता कम कर उनकी सुस्त एक आरामतलब बना दिया है ।
- मानसून का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Monsoon)—मानसून भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है । भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ सभी सिन्हाई के साधन पर्याप्त मात्रा में स्थित नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों का साध आर्थिक जीवन मानसून पर ही अवलम्बित है ।

(२) मानसून की कमी या उमका निलुप्त न होना केवल कृषक के लिये ही नहीं, अपितु निर्माणाद्या व्यापारियाँ एवं उपभोक्ताओं के लिये भी अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होता है।

(३) मानसून की 'बूनता' से माधाराख क्षय गति ग्रिस्त जाती है जिससे उत्पादन की कमी होकर व्यवसायिक शक्ति की मर्यादों की माँग कम हो जाती है।

(४) देश की प्रायः सभी 'बूनता' से जाता है क्योंकि अनापूर्ति के कारण व्यापार एवं लोगों के आवागमन में कमी हो जाती है।

(५) राज्य की आय (Revenue) में ह्रास हो जाता है और दमिस्त सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने में व्यय में वृद्धि हो जाती है।

(६) लोक काम (Public Works) में कमी हो जाती है जिससे विकास रुक जाता है।

(७) मानसून के न आने में पयन नष्ट हो जाती है और पहने का अपना निर्माण कम हो जाने में भारत का व्यापार गन्तव्य भी प्रतिकूल (Unfavourable Balance of Trade) हो जाता है।

(८) मानसून की असफलता से विभिन्न सम्बन्धी कठिनाइयाँ (Exchange Difficulties) उत्पन्न हो जाती हैं।

(९) मनुष्य के चरित्र निर्माण पर मानसून का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देश के जिन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है (जैसे बंगाल-यमुना का मैदान) वहाँ के लोग में आत्मनिर्भरता (Self sufficiency) रूढ़वादिता (Conservatism) और घर पर रहने की (Staying at home) की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। यों तो अधिक परिश्रमी न होकर आरामतन्त्र होते हैं। आजीविका के सुख में आनन्द उपलब्ध होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकता का समय अपनी आध्यात्मिक धार्मिक एवं साहित्यिक उत्पत्ति के लिये लगाता है।

(१०) इसके विपरीत देश के जिन भागों में जनवृष्टि का प्रभाव होता है वहाँ के मनुष्य परिश्रमी होते हैं क्योंकि उन्हें उदरपूर्ति के माध्यम उठाने के लिये अत्यन्त प्रयत्न करना पड़ता है। उदरपूर्ति के माध्यम उत्पत्ति में निरन्तर सब रहने के कारण उन्हें अपनी आध्यात्मिक एवं साहित्यिक उत्पत्ति के लिये विन्युत अवकाश नहीं मिलता।

(११) जनसंख्या का घनत्व भी इस देश में वर्षा की मात्रा के अनुसार पाया जाता है। घनत्व अनुषंग में माना जाता है कि देश में अधिक वर्षा वाले भागों में अधिक जनसंख्या है।

भारत की आपत्ति व्यवस्था में मानसून का निम्नलिखित प्रभाव है यह ऊपर के विवरण में प्रस्तुत किया गया है। अतः मानसून की मात्रा का भारत का भाग्य निर्धारण करना कोई अनिवार्य नहीं होगा। यही कारण है कि भारत का देश मानसून का जुआ (Gamble of Monsoon) कहा जाता है क्योंकि भारताव बजट अधिकांश में मानसून पर ही निर्भर है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारत के आर्थिक जीवन में वर्षा के महत्व को दिखाइए तथा भारत में मानसून में मार्ग का गक्षण में बहाने कोजिए । (घ० बो० १८५६ ५६)
- २—भारत को कृषि में बाम आने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ का वर्गीकरण कीजिये और उनकी मुख्य जगह का नाम लिखिये । (घ० बो० पू० १८५६)
- ३—भारत में भूमि की मुख्य समस्या क्या है ? उत्तर प्रदेश की सरकार उनको हल करने के लिये क्या कर रही है ? (उ० प्र० १८५४)
- ४—भारत की भूमि और जलवायु का विवरण काजिये । देश की आर्थिक समस्या पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ? (उ० प्र० १८३३)
- ५—भारतवासियों का मानसून किम प्रकार प्रभावित करते हैं यह पूछानमा समझिये । (रा० बो० १८५५)
- ६—किमा देश के आर्थिक विकास पर बहा की जलवायु तथा प्राकृतिक दशाभा के पठन का प्रभाव की व्याख्या कीजिये । (घ० बो० १८५४, ५०)
- ७—निम्नलिखित पर नोट लिखिए —
भारत में मिट्टी का कटाव (रा० बो० १८६०), वन महोत्सव (उ० प्र० १८५४),
हिमालय क्षेत्र (रा० बो० १८६०)

भारतवर्ष में वनों की भी एक अमूल्य सम्पत्ति है जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। भारतीय सप की कुल भूमि का २२ प्रतिशत अर्थात् २,८०,३४८ वर्गमील क्षेत्रफल वनाच्छादित है। ससार के कई अन्य देशों की तुलना में यह क्षेत्रफल कम है। भव राज्या में वन विनरए समन नहीं है जैसा कि नीचे की सारणी से स्पष्ट है :—

राज्य	वनाच्छादिन क्षेत्रफल का प्रतिशत
मध्य प्रदेश	४७.७%
छात्ताम	३६.०%
मद्रास	२७.०%
उत्तर प्रदेश	१६.०%
पश्चिमी बंगाल	१५.०%
झारखंड	१४.०%
बिहार	१४.०%
उड़ीसा	१३.७%
पंजाब	११.०%

भारतीय वनों के प्रकार (Kinds of Indian Forests)

भारतीय सप एक उपमहादीप होने के कारण इसमें जलवायु, प्राकृतिन दशा एव भूमि की रचना की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसी के अनुसार भारतीय वनों में भी भिन्नता होता स्वाभाविक है। मुख्य प्रकार के भारतीय वन नीचे दिये जाने हैं :—

१. सदावह्वार वन (Evergreen Forests) :—य वन देश के उन भागों में पाये जाते हैं जहाँ बि वर्षा का औसत न्यमम सी इंच या अधिक हो। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, हिमालय प्रदेश के पूर्वी भाग में पांच हजार फीट की ऊँचाई तक और आसाम में पाये जाते हैं। वहाँ के वन घने हैं और वृक्ष भी कई प्रकार के हैं। इन वनों में बाम, वैन, ताड़ और रवड के पेड़ मुख्य हैं।

२ पतझड़ या मानसून वन (Deciduous or Monsoon Forests)—यह के कुछ समय विप्रेष्यता प्रीप्स बाल के प्रारम्भ म इन वना के वृक्षा के पत्ते गड़ जान है। इसी कारण इहे पतझड़ के वन कहते हैं। इन वनों को मानसून के वन भी कहा ह। ये वन भारत के कई भागो मे मिलन हैं परन्तु हिमालय का निम्नता प्रदेश और द्वाग नागपुर का पठार इनके लिये प्रसिद्ध है। इन वना के मुख्य पड़ सागवान सान चंदन शोगन और आदि हैं इनकी लकड़ी बड़ा मुख्यवान होती है और फर्नाचर प्रावि न धान म खाती है।

३ कोणारो या पर्वतीय वन (Coniferous or Mountain Forests)—य वन हिमालय के दक्षिणी ढालो पर सोन हजार म नौ हजार फीट की ऊँचाई म बांच म मिलन हैं। यहाँ के वृक्षा म ऊँचाई प्रीप्स जनवापु की भिन्नता के अनुसार वर्ग बिम्मे ह। इन वना म कपूर चीड़ इबदार आदि के वृक्ष मिलन हैं जिनकी लकड़ा बड़ा लाभदायक होती है।

४ अल्पाइन वन (Alpine Forests)—हिमालय पर्वत पर नौ हजार फीट स अधिक ऊँचाई पर अधिन ठण्ड पड़ने क कारण छोटे वृक्ष और चौड़े पाय जान ह। इन वना म खेत समोवर लक्ष आदि के वृक्ष मुख्य ह। अधिन ऊँचाई के कारण इन वृक्षा का उपयोग बड़ा हो सकता।

५ समुद्रतटीय या डेल्टा के वन (Tidal or Littoral Forests)—इन प्रकार के वन समुद्रतट के दलदली भाग तथा नदिया के उन शेट्टा म जो कुछ बाल क लिए नमकीन पानी म डूबे रहते हैं पाय जाते हैं। इनमें मैनग्रोव नामक वृक्ष मिलन के कारण इहे मैनग्रोव वन और समुद्र का ज्वार बढ घाल के कारण उदार वन भी कहन हैं। गया के डेल्टा म सुंदरी वृक्षा की प्रधानता के कारण ये सुंदर वन कहलान हैं। वनी प्रकार महानदी गोदावरी कृष्णा आदि नदिया के डेल्टा म भी ऐसे वन पाय जान ह। इन वृक्षा की लकड़ी का जनाने क अतिरिक्त कोर उपयोग बड़ी है।

६ शुष्क या मरुस्थली वन (Arid or Scrub Forests)—

भारत क जिन भागो म जलवृष्टि बहुत कम होता है वहा वृक्ष कम होन ह। एम वृक्षा की न लम्बी होती है और पत्ते धाट निरुग कम पानी होन पर भी पतन करे। इनके प्रतिरुति यहाँ कई प्रकार की बाटेदार झाड़ियाँ आ मिलन है। ये निम्न राज सान पत्ती पत्राच म पाय जान है। इन वना मे कोकर वगून और खेजडा के वृक्ष मुख्य हैं। इन वृक्षा का जवन स्थानीय गहूहन हो है।



वनो का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Forests)

विनी देश की आर्थिक व्यवस्था में वनों का बड़ा महत्त्व है। भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में तो वन का अत्यधिक महत्त्व है। इनके द्वारा प्राप्त लाभ दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—(अ) प्रत्यक्ष लाभ, और (आ) परोक्ष लाभ।

वनो के प्रत्यक्ष लाभ (Direct Advantages of Forests)—वन के प्रत्यक्ष लाभ उनके द्वारा मिलने वाले वस्तुओं के कारण होते हैं। ये निम्नांकित हैं—

(१) वना से इमारती लकड़ी (Timber) और जलाने की लकड़ी (Fire-wood) प्राप्त होती है। यही वनों की मुख्य पैदावार (Major Products of Forests) है जिससे सागवान, सास, कटु, चीड़, देवदार, शीशम, चन्दन, गुलाब, जारोण रॉय, मुल्गरी, भारतीय सहोमनी आदि लकड़ियाँ सम्पन्नित हैं। ये लकड़ियाँ भवन निर्माण, रेलों के डिब्बे, पटरियों के स्लीपरों, नावों, फर्नीचर, तेल का समान और कृषि-उपकरण बनाने के लिये प्रयुक्त की जाती हैं। कठून, धोंकड़ा, खैरड़ा आदि साधारण लकड़ियाँ जलाने के काम में लाई जाती हैं।

(२) वनों में कई उद्योगों तथा व्यवसायों को क्या माल (Raw Materials) मिलता है। इनकी वनों की अल्प पैदावार (Minor Products of Forests) कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं :—

(क) वामन वना के व्यवसाय के लिये वान की भुगदी, भवाई और भारर नाम वनों में ही प्राप्त होती है।

(ख) दबून व कीकर आदि वृक्षा की छाल से चमड़े रबने के व्यवसायों (Tanning Industries) को सहायता मिलती है।

(ग) चीड़ या देवदार के वृक्षों से राल और तारपीन का तेल प्राप्त होने से रंग व रोगन, तेल, माबुन, मोमबत्ता, ग्रामोफोन के रिकार्ड व बुडिया बनाने के व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण है कि उत्तरप्रदेश और पंजाब में इस प्रकार के कई कारखाने दृष्टिगोचर होते हैं।

(घ) वनों की लकड़ी से सुगन्धित तेल प्राप्त होता है, जैसे चन्दन आदि का तेल।

(ङ) रबड़, लास, मोद आदि पदार्थ वनों से ही प्राप्त होते हैं जिनमें रबड़, लास, चपड़ी, बार्निश व पॉलिश आदि के व्यवसाय चलाये जाते हैं।

(च) दियासलाई के व्यवसाय में सीकें वना की लकड़ी से ही प्राप्त होती हैं।

(छ) रेशमी बरत का व्यवसाय भी वनों पर ही निर्भर है, क्योंकि रेशमी कीड़े महतून के वृक्ष के पत्तों पर रखे जाते हैं।

(ज) वनों में कई जड़ी-बूटियाँ तथा फल-फूल प्राप्त होते हैं जिसके कारण औषधि वना और मुरब्बे आदि के व्यवसाय का विकास होता है।

(झ) गह्व का व्यवसाय भी वना पर निर्भर है।

(३) वनों में लकड़ी काटने व चीरने तथा अन्य सम्बन्धित कारखानों के स्थापित होने में कई मनुष्यों को रोजगार मिलता है।

(४) वनों और चरागाहों में घास प्राप्त होती है। जैसे हिमालय में तराई प्रदेश में दूध देने वाले पशु बड़ी तादाद में रखे जाते हैं जिससे दूध, दही, मक्खन और घी का व्यवसाय होता है।

(५) वृक्षों के पत्तों में 'सबुज साद' (Green Manure) तैयार किया जाता है।

(६) वनों में कई जगहों पर घूमने फिरते हैं जिनका निवारण कर उनका खमड़ा, घाल आदि काम में लाने जाते हैं।

(७) वनों में राज्य सरकारों का घास होनी है।

वनो के पर्यन्त लाभ (Indirect Advantages of Forests)

(१) वनों के वृक्षा में नगरी रहने के कारण आस पान का जनबाध समशीतोष्ण रहता है।

(२) वनों में वर्षा होती है। पानी में परिपूर्ण हवाएँ जब वनों के वृक्षों में से होकर जाती है तो ठंडी होकर नदी प्राय-याग वर्षा कर देती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।

(३) पहाड़ी ढालों पर वृक्ष होने के कारण वर्षा के जल प्रवाह में रुकावट हो जाती है जिससे बाढ़ नहीं आती और भूमि में कटाव (Soil Erosion) नहीं होने पाता।

(४) वन हवाओं के तीव्र बल को रोक कर बड़ी-बड़ी आंधियों और तूफानों द्वारा मराने व फसलों को नष्ट होने से बचाते हैं।

(५) मरुभूमि में वृक्ष लगा देने से मिट्टी उज्जने से बचती है।

(६) वन देश में सौन्दर्य और स्वास्थ्य-सम्पादन के केन्द्र बन गए हैं, जैसे गिरमा, मैनीताव, बार्जिलिय और नीलगिरी आदि।

(७) वन बाहरी आक्रमणों को रोकते हैं जिसमें देश में शान्ति और सुरक्षा स्थापित होकर आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

(८) वृक्षों के पत्तों भूमि पर बिरे मिट्टी में मिलकर उत्तम खाद का काम देते हैं।

वनो के इस प्रकार के अनेक लाभों के कारण प्रत्येक देश में वनों का बड़ा महत्त्व समझा जाता है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में विशेष तो इनका और भी अधिक महत्त्व है। इंग्लैंड में वनों की श्रव 'कृषि की दासी' (Handmaid of Agriculture) में कहकर इन्हे इसका आवश्यक सहयोगी समझना चाहिए। वास्तव में, वनों की राष्ट्रीय मर्यादा कहना बिल्कुल उचित है।

वनो की शासन व्यवस्था (Forest Administration) - भारत में वनों का सरदार बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। सन् १८६४ ई० में बड़े-बड़े प्रांतों में 'वन विभाग' (Forest Departments) स्थापित किये गये। सन् १८६४ ई० में

1—Forestry Should no longer be regarded as a handmaid to agriculture but a necessary complement to it.

—Planting Commissioner Report.

भारत सरकार द्वारा परिपत्र (Circular) जारी किया गया जिसके आधार पर वन सम्बन्धी नीति निश्चित की गई। इस नीति के मुख्य चार सिद्धान्त थे - (१) जलवायु और प्राकृतिक कारकों में वनाच्छादित पर्वत क्षेत्रफल संरक्षित रखना प्राथमिक आवश्यकता है, (२) लोगों की सान्धारण गणुद्धि के लिये वनों के सुरक्षित रखने की आवश्यकता द्वितीयक है, (३) वानिकी (Forestry) में वृष्टि अधिक आवश्यक है, परन्तु स्थूलतम भूमि पर वनों का रहना भी आवश्यक है, (४) वनों की शाय की गया सम्भव पूर्ण रूप से बसूनी होनी चाहिये। वास्तव में शाय में भी सरकारी नीति प्रत्येक तक प्रभावित रही है।

राज्य नियन्त्रण की दृष्टि से भारत के वन तीन भागों में विभाजित किये गये हैं :—

(१) सुरक्षित वन (Reserved Forests)—ये वन हैं जिनकी रक्षा करना जलवायु की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। ये वृक्ष सरकार के कठोर नियन्त्रण में होते हैं। इनके वृक्ष नहीं काटे जाते और न वहाँ पशु चराने की ही प्राज्ञा होती है।

(२) रक्षित वन (Protected Forests)—इन वनों पर भी राज्य की देख-रेख रहती है। प्रावश्यकतानुसार इनकी लकड़ी भी काटी जाती है और इनमें प्राज्ञा प्राप्त कर पशु भी चराये जा सकते हैं।

(३) स्वतन्त्र वन (Unclassed Forests)—इनमें लकड़ी काटने एवं पशु चराने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु उसके बदले में सरकार को निश्चित शुल्क देना पड़ता है।

वर्गीकरण	क्षेत्रफल
सुरक्षित वन २,६०० वर्ग मील
रक्षित वन ६,८०० " "
स्वतन्त्र वन " "	... १८,५०० " "
योग—	<u>२८,२०० " "</u>

सरकार की ओर से सन् १९०६ ई० में बेहराटून में 'वन सम्शोधनशाला' (Research Institute of Forests) स्थापित किया गया जिसमें वन सम्बन्धी वानों का वैज्ञानिक शोधपूर्ण किया जाता है। इस प्रकार की कई सम्शोधनशालाओं की आवश्यकता है।

भारतीय वन-उद्योगों की हीन दशा के कारण

(Causes of Backwardness of Indian Forests)

पारवत्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में वन-उद्योगों की अत्यन्त पतित दशा है इस बात का प्रमाण हमें भारतवर्ष और जर्मनी के वनों की वार्षिक मात्र की तुलना में मिल सकता है। भारतवर्ष की सरकार की वनों में केवल पाँच करोड़ रुपये की ही वार्षिक आय होती है, जबकि जर्मनी में जो भारतवर्ष के पूरे प्रान्त के बराबर है, वनों में २ करोड़ रुपये वार्षिक आय होती है। इस हीन दशा के कई कारण हैं जिनका नीचे उल्लेख किया जाता है :—

१—विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के मुख्य, गुण्य और उपयोगिता की अनभिज्ञता।

२—भारतीय सरकार का अब तक वन जोषण की अपेक्षा वन-रक्षा की ओर अधिक ध्यान रहा है।

३—वन-विज्ञान और वन-रक्षण विद्या का प्रभाव।

४—वन-अन्वेषणान्तरो का प्रभाव।

५—वन-विभाग और वृषि-विभाग में निकट सम्पर्क का पूर्ण प्रभाव।

६—प्रशिक्षण वन मानायात के साधनों में वर्णित है।

७—लगभग निहाई वन निजी सम्पत्ति हैं और वे साधारणतया बिना विचार वृष्ट किये जाते हैं।

८—वन विभाग में कार्य करने के लिये उपयुक्त वेतन, ग्रेड आदि प्रलोभन का प्रभाव।

वनो की उन्नति के उपाय—भारतवर्ष में वनों की उन्नति निम्नलिखित उपायों द्वारा की जा सकती है,—

१—भारतवर्ष में वन रक्षण तथा वन-प्रसार योजनाओं की शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। 'अधिक वृक्ष लगाना' आदि इस प्रकार के आन्दोलन बड़े सार्थक सिद्ध हो सकते हैं।

२—वन-रक्षण तथा वृक्ष लगाने के कार्य में वैज्ञानिक ढंगों का आश्रय लेना चाहिये।

३—वन-उपजों के अन्वेषण तथा प्रयोगों द्वारा वन-उद्योगों का विकास करना चाहिए।

४—साक्षरता के साधनों का विकास होना आवश्यक है।

५—वनो के क्षेत्रफल में दस प्रकार वृद्धि होनी चाहिये कि पशुओं के लिये उद्योग करवाणों की भी समुचित व्यवस्था हो जाय और ईंधन व व्यापारिक प्रयोजन वाली सब्जो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। जवानों की लकड़ी प्राप्त होने पर गोबर का मोद नष्ट होने में बच सकेगा।

६—वृषि रक्षित कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक प्रान्त में 'वन-उपयोग प्रशिक्षार्थी' (Forest Utilization Officers) नियुक्त किये जायें चाहिये और जहाँ के उचित शोषण का उद्देश्यविधि उन्हीं पर होना चाहिये।

७—राज्य वनीकरण को सिफारिश के अनुसार बन दो भागों में विभाजित हो जाना चाहिये—मुश्क वन और छोट-मोटे वन। मुश्क वन में होने चाहिये जो व्यापारिक वन हों और छोट-मोटे वन में होने चाहिये जो ईंधन और साधारण लकड़ी की पूर्ति करने हैं। छोट-मोटे वन पचासवों में सुपूर्द कर देने चाहिये।

८—वृषि-विभाग और वन-विभाग के मध्य निकट सम्पर्क बर्धनीय है।

९—वृषि कर्मियों और स्कुलो में वन-सम्बन्धी अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिये जिसमें वन-विभाग के लिये मुख्य कर्मचारियों तैयार किये जा सकें।

१०—प्रचार द्वारा वन उपजों और उन पर बर्धनमयित उद्योगों के महत्त्व को जनता में सम्मुख करना चाहिये।

११—वन विभाग में मुख्य कर्मचारियों को साष्टक करने के लिये उत्तम वेतन व ग्रेड होना चाहिये। सरकारों छात्र-वृत्ति द्वारा वन-विद्या के लिये अधिक-अधिक संख्या में छात्र भेजे जान चाहिये।

• सरकार की वर्तमान वन-नीति—योजना बमीयान की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने १२ मई १९१२ को अपनी नवीन वन-नीति की घोषणा की जिसके अनुसार भारत सरकार ने एक 'वनो का केन्द्रीय बोर्ड' (Central Board of Forests) की स्थापना की। यह बोर्ड केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वन-नीति का ध्यान रखता है। यह केन्द्रीय सरकार के ऊपर निगरानी रखता है कि वह 'नवीन वन नीति' का पालन करती है। इसके अतिरिक्त वनों के विकास के लिये एक 'वन प्रेमो-सर्ग' स्थापित किया गया है जिसके प्रधान सरक्षक भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद हैं। इस सर्ग का कार्य वन विज्ञान का प्रचार करना है। वन-महोत्सव समारोह इसी सर्ग द्वारा संचालित होता है।

वन महोत्सव समारोह—इस उत्सव का श्रीगणेश सबसे प्रथम मई १९५० में उत्तर प्रदेश के राम्भाय थी वें० एम० मुखी जो उस समय केन्द्रीय सरकार के लघु मंत्री थे, द्वारा हुआ था। तब से यह प्रति वर्ष जुलाई मास में मनाया जाता है। स्थान-स्थान पर सरकारी व गैर सरकारी अधिकारी तथा अन्य प्रतिष्ठित व साधारण व्यक्ति वृक्षारोपण करते हैं। इसके फलस्वरूप लोगों में पेड़ लगाने की प्रेरणा जाग्रत होती है तथा लाखों पेड़ प्रति वर्ष इसी महाने लगाये जाते हैं।

योजना तथा वन—हमारी योजना में इमारती लकड़ी, विद्यालयाई की लकड़ी, वाटन, लुगदी तथा गोद का उत्पादन बढ़ाने और जंगल क्षेत्रों का भरपूर उपयोग और उपलब्ध जंगलान के साधनों का अधिकतर उपयोग करने का कार्यक्रम बनाया गया है। वन सम्बन्धी योजना में जिसके लिये २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ६ लाख एकड़ भूमि में जंगलों को विकसित करने और ३ लाख एकड़ भूमि में नये जंगल बनाने और ५० हजार एकड़ भूमि में चरागाह बनाने का प्रयत्न किया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएं

- १—भारतवर्ष की आर्थिक दशा पर उसके वनों का महत्त्व बताइए। उनकी उत्पत्ति करने के लिये क्या कार्य किया गया है ? (१० वी० १९६०)
- २—'वन महोत्सव' के आर्थिक महत्त्व पर टिप्पणी लिखिये। (उ० प्र० १९५४)
- ३—भारतीय वनों का आर्थिक महत्त्व समझाइये और इस सम्बन्ध में सरकारी नीति भी बताइये। (५० भा० १९५३, ५२)
- ४—हमारी अर्थ व्यवस्था में जंगलों के महत्त्व को स्पष्टतया समझाइये। आप भारत में जंगलों के विनाश के लिये क्या सुझाव रखेंगे ? (५० वी० १९५३, ३९, ४० वी० १९५०, ८५, पन्ना १९४८, दिल्ली १९५४)

भारतवर्ष की कृषि सम्पत्ति (Agricultural Wealth of India)

भारत में कृषि का महत्त्व

भारत में कृषि का बड़ा महत्त्व है। यहाँ के लगभग ७० प्रतिशत लोग का धन्यता सेनी करना है। देश की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये अन्न उत्पन्न करने में ही इसका महत्त्व नहीं है, बल्कि अनेक उद्योग धन्यता की चलाने के लिये बच्चा नाल भी कृषि से मिलता है। अस्तु भारतीय आर्थिक व्यवस्था में कृषि का एक मुख्य स्थान है।

भारतीय कृषि की दशा

“भारत में हम पिछड़ी हुई जानियाँ रखते हैं हम पिछड़े हुए उद्योग भी रखते हैं और कृषि दुर्भाग्यवश उनमें से एक है।”
—डा० क्लॉउड्सटन

भारतवर्ष में कृषि का इतना महत्त्व होने हुए भी यह एक धक्की दशा में नहीं है। “भारत एक धनाढ्य देश है जिसमें दरिद्र निवास करते हैं।” यह कहावत यहाँ लागू होती है। भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है और जनबाध में कृषि के लिए अनुदान है, परन्तु फिर भी यहाँ भूतों की दशा शोचनीय है। अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति एकड़ पैदावार बहुत ही कम है जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है :—

(पाँट में)

देश	गहूँ	चावल	गन्ना	मकई	बपास	तम्बाकू
अमेरिका	८१२	२,१८५	४७,५३४	१,५७६	२६६	८८२
जर्मनी	२,०१७	—	७०,३०२	२,८२८	—	२,१२७
इटली	१,३८३	४,५६८	—	२,०५६	१७२	१,१४६
सिंह	१,६१८	२,६६८	—	१,८६१	२२५	—
जावा	—	—	४३,२७०	—	—	—
जापान	१,७१३	३,४४४	—	१,३२६	१५६	१,६६५
चीन	६८६	२,४३३	१६,६७०	१,२८४	२०४	१,२८८
भारत	६६०	२,२४०	१४,५८८	८०३	८६	६०७

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि गेहूँ की प्रति एकड़ पैदावार भारत में मिश्र की ३ और हॉलैंड तथा जर्मनी की ६ है। चावल की प्रति एकड़ उपज इटली की ३, नेपाल में मिश्र की ३, चीन में जावा की ३ और मकाई में यू.सी.ई.डी. की ३ है।

भारतीय कृषि के घरेलू निष्कर्ष

(Causes of Backwardness of Indian Agriculture)

भारत में कृषि का अत्यधिक महत्व होने हुए भी यह एक अच्छी दशा में नहीं है। इसके अनेक कारण हैं जो ग्रामीण में नीचे दिये जाते हैं :-

(१) कृषक की नियंत्रिता, (२) कृषक की अधिज्ञा, (३) कृषकों की सामूहिक एवं सामाजिक स्थिति, (४) उत्तम व गन्ने खाद का अभाव, (५) पानी के पशुओं की दुर्बलता, (६) मृदा की अभाव, (७) उत्तम बीजों का अभाव, (८) कृषक की गड़बड़ करने वाले अनेक पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े आदि का होना, (९) प्राचुर्य पानी के बीजों का अभाव, (१०) भूमि का कटाव तथा बाढ़ के जाने में भूमि का नष्ट होना, (११) जनशक्ति की अनियमितता, (१२) घरेलू उद्योगों का नष्ट होना और भूमि-भार का नष्ट जाना, (१३) पानी में बैक्टीरिया इत्यादि का अभाव, (१४) भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, (१५) अल्पज्ञा और मरणा अर्थ-प्रवृत्ति, (१६) कृषकों द्वारा सामाजिक नीति विचारों पर फिक्कन गर्व, (१७) पानी की उपज की अमान्यता व विपणन (Marketing) व्यवस्था, (१८) कृषक की स्थितिदिता।

कृषि उन्नति के उपाय—भारतीय कृषि की उन्नति उपर्युक्त कठिनाई व बाधाओं को दूर करने में ही मिलती है। मनु-राष्ट्र मंडल (U.N.O.) के कृषि और खाद्य-निर्माण (F. A. O.) व हाइड्रॉपेट्री की १० सी० साइ में भारत की कृषि उन्नति के विषय निम्न सुझाव दिये हैं :-

(१) जंगलों को वाहन की प्रणाली पर बड़ा निरन्तरण कर मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण दिया जाय।

(२) नव-युवा द्वारा मिनाई क्षेत्रों में वृद्धि करना।

(३) कृषि (खाद्यनिर्माण) खाद के उपयोग में वृद्धि करने की अपेक्षा दाज वाली (Clover Crops) कृषक का अधिक उपयोग किया जाय जिससे उनका द्वारा सादृशान मजदूर करने तथा पानी को अधिक समय भूमि में रहने की प्रणाली का विकास हो।

(४) कृषि में मजान का प्रयोग करना व नव दूरका नष्ट हो सीमित कर देना।

पानी की कमी के कारण कृषि प्रणाली (Dry Farming) को अपेक्षा कर दूर कर सकना है। इस प्रणाली द्वारा पानी करने में न मिश्र औषधों वर्ष में ही उपजति की जा सकती है, यदि सूखे वर्षों में भी कुछ-कुछ पैदा किया जा सकता है।

१०० अनाज व अनुमान यदि बहुत भक्षण आदि क्षेत्र बनाने खाद तथा को बनावट दृष्टि में उत्तम व साइड की वृद्धि की जाय ता जोर की खाद में १०० प्रतिशत सादृशान मिल सकता है। जिससे खाद्यान्न में १०० लाख टन की वृद्धि की जा सकती है। इसका अभाव निम्न खाद की वर्षा अन्न में और पशुधन का बाढ़ में भी प्रोत्साहन वृद्धि में वृद्धि (Coma) बना कर, स्वयं खाद का उत्पादन कर पानी कर सकते हैं। कृषक का अनिश्चित, निश्चित की खाद भी लाभ में खाद जा सकती है। अगर खाद्यान्न तथा मृदा की खाद देना, बनावट, बीज, साधन-सामान आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

कृषि के लिए पम्पला की उन्नत जातियों को अपनाया चाहिए। उदाहरण के लिये, अमेरिका में अब तक यहाँ की ५० नई जातियाँ निकल गई हैं जो बीमारियाँ गन्धुआ अनापूर्ति अथवा सर्दी व कोहरा में मुक्त है। दीर्घक आदि कोटो को रोक्ने के लिये वेना में फसला को हेर फेर (Rotation) के साथ जोया जाय अथवा गहरा हल चलाकर अय्य की धाम-फूस को खेती में निकाल दिया जाय।

कृषि साध व्यवस्था के लिये सहकारिता का विकास नितांत आवश्यक है। यह न केवल साध के क्षेत्र में ही लाभदायक सिद्ध होगी परन्तु कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी जैसे लाभ, बीज, भोजन प्राप्ति, बिक्री व्यवस्था आदि।

भारतवर्ष में फसलें—भारतवर्ष में मुख्यतः दो फसल पैदा होती हैं—(१) खरीफ की फसल और (२) रबी की फसल।

(१) खरीफ की फसल—इसकी पुष्पाई जून से अक्टूबर तक अर्थात् गर्मी व मानसून प्रारम्भ होने से पूर्व ही होती है। अच्छी वर्षा होने से सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस फसल की मुख्य पैदावार गन्ना, ज्वार-धानरा चावल, पाट, मक्का, मूँग, मूँग और तिलहन (तिल और भूँसफली) है।

(२) रबी की फसल—यह शरद ऋतु के प्रारम्भ में बोई जाती है और शीत ऋतु में काट ली जाती है। सर्दी के मानसून में वर्षा बहुत कम होने से और वह भी केवल गन्ना में ही होती है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। इन फसल की मुख्य पैदावार गन्ना, जौ, चना, मूँग, अलसी और राई है।

इन फसलों का विस्तृत विवरण आगे दिया जाता है

(१) खाद्य पदार्थ (Food Crops)

चावल (Rice)—चावल गर्म और तप्त जलवायु में पैदा होता है। पानी की न्यूनता की पूर्ति सिंचाई द्वारा की जाती है। चावल की फसल के लिये उन्नत भूमि आवश्यक है। यही कारण है कि चावल अधिकतर नदियों के डेल्टा तथा उनकी पाटियों और मैदानों में उत्पन्न किये जाते हैं। वैसे भीशा बहुत चावल भारत में सभी जगह पैदा होता है, परन्तु बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उ० प्र०, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और पूर्वी पञ्जाब इसके मुख्य पैदा करने वाले हैं। यह देश की कृषि योग्य भूमि के ३०% पर बोया जाता है। चावल की पैदावार में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत की समस्त उपज का २१ प्रतिशत चावल भारतवर्ष में उत्पन्न होता है, परन्तु ज्ञान मर्यादा इनकी अधिक है कि इसे विदेशों से चावल मँगाना पड़ता है। भारत में १९५८-५९ में उपज ८ करोड़ १६ लाख एकड़ भूमि पर चावल की खेती हुई और २ करोड़ ९७ लाख टन चावल पैदा हुआ। चावल को प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए अग्रणी पद्धति को भी अपनाया जा रहा है।



चावल (Rice)

गेहूँ (Wheat) अनाजा में गेहूँ सब में अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य की जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग गेहूँ ही खाता है और गेहूँ अत्यन्त प्राचीन काल में उत्पन्न किया जाता है। यही कारण है कि गेहूँ की बहुत प्रकार के जनसामु में उन्नत करने



मधुवास्त्र

का प्रयत्न किया गया है। गहू मटियार भूमि में खूब उत्पन्न होता है परन्तु अधिक कठोर भूमि बोये के लिए हाजिरास्त्र मिश्र होती है। इस धान के बोने में समय मई और जून होना आवश्यक है। परन्तु फसल पकने के समय तेज धूप लगना ही आवश्यक है। यम्मु भारत में गहू धक्कूर व नवम्बर में बोया जाता है और अग्रत व मई में बाटा जाता है।

भारतवर्ष में गहू रबी की मुख्य फसल है। देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें यह धान-वट्टक पैदा न होता हो किन्तु पूर्वी पञ्जाब उत्तर प्रान्त मध्य प्रदेश त्रिहार और बम्बई में इसकी पैदावार विशेष रूप से होती है। भारत में गहू की कुल उपज का ६५% उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। जोती जने वाली भूमि के १० प्रतिशत भाग में गहू की खेती होती है अर्थात् लगभग २२ करोड़ एकड़ भूमि गहू की पैदावार के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ प्रति एकड़ पैदावार कम होती है और यहाँ का बढ़ता हुआ जन-संख्या की खिलाने के लिए गहू बाहर से बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। भारत में १९५८/५९ में तीन करोड़ एकड़ भूमि पर लगभग १७ लाख टन गहू उत्पन्न किया गया। इस देश की विचार जन संख्या के लिए यह पैदावार बहुत कम है। अस्तु अमरीका आदि देशों से बड़ी मात्रा में गहू आयात किया जाता है। सन् १९५९ में गहू और आना मिलाकर ३५ लाख टन आयात किया गया।

जौ (Barley) — जो गेहूँ की ही जाति का धान है किन्तु यह और धान की म अधिक कठोर होता है। जौ मई और मई खर सहन कर सकता है। साधारण भूमि पर भी जौ का अच्छी फसल उत्पन्न हो सकती है। भारतवर्ष में लगभग ६२ लाख एकड़ भूमि में जौ पैदा होता है और लगभग २० लाख टन पैदा होता है। जौ उत्पन्न करने वाले मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश त्रिहार और पूर्वी पञ्जाब हैं। भारत की समस्त पैदावार का जो निहाई भाग अनेक उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जौ विद्युत प्रयोग का मुख्य भोज्य पदार्थ है। इस देश में अधिकतर जौ का उपयोग पान के लिए ही होता है न कि मटियार बनाने में। भारत में बहुत कम जौ विदेशों का भेजा जाता है। सन् १९५८/५९ में लगभग ८१६ लाख एकड़ भूमि पर जौ बोया गया और २६४ लाख टन पैदावार हुई।



मधुवास्त्र

मक्का (Maize) — मक्का की खेती मक्का भी गम और मर जनवरी में पैदा होती है। मक्का की अच्छी पैदावार के लिए रेत मिट्टी हुई मटियार भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में मक्का उत्पन्न करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मद्रास हैन्नावार और बम्बई हैं। मक्का की सारी पैदावार यही उपयोग में आ जाती है। सन् १९५८/५९ में लगभग ११ करोड़ एकड़ भूमि पर मक्का की खेती की और २६८ लाख टन पैदावार हुई।

ज्वार-बाजरा (Miller)—भारतवर्ष के उन भागों में जहाँ वर्षा कम होती है, ज्वार-बाजरे की मुख्य फसल होती है। भारत के अत्यन्त शुष्क प्रदेशों में बाजरा मुख्य आधार है। बाजरे के लिए ऐसीसी भूमि चाहिए। ज्वार-बाजरे की फसल के लिए मिर्चाई की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार-बाजरा भारत के सभी भागों में होता है, परन्तु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात इनकी पैदावार के लिए मुख्य है। भारतवर्ष में यह लगभग ६६ लाख एकड़ भूमि में उत्पन्न किया जाता है। समस्त पैदावार का तीन-चौथाई भाग तो इसी देश में बाम खा जाता है और दोष भाग निर्यात कर दिया जाता है। सन् १९५८-५९ में भारत में ज्वार-बाजरा १२ करोड़ एक्ड में बोया गया था जिसमें २०.८८ लाख टन पैदावार हुई।



दालें (Pulses)—भोज्य पदार्थों में दालों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में दाल भोजन का एक आवश्यक अंग है, भरहर, चना, मटर, मसूर, मूँग तथा उड़द मुख्य दालें अधिकतर उष्ण कटिबंध तथा ज़ोतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होती हैं। दालों का पैदा करने से किसानों की मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि दालों में बीघे में नाइट्रोजन जमा कर देते हैं। अधिक ताप में पैदा करने वाले मुख्य राज्य पंजाब, मध्य-प्रदेश, बंगाल और बम्बई हैं। समस्त पैदावार यहाँ खप जाती है। सन् १९५८-५९ में दालों का उत्पादन १२ करोड़ टन है।

शाक-तरकारी (Vegetables)—शाक भोजन का मुख्य अंग है। प्रत्येक भारतीय के घर में शाक-तरकारी किसी-न-किसी रूप में प्रतिदिन उपभोग में लाई जाती है। तरकारियाँ उत्पन्न करने के सिधे बहुत ज़रूरी भूमि, यथेष्ट खाद और जल की आवश्यकता होती है। किन्तु तरकारियों के बीघे खराब हो जाने के कारण शहर तथा समीपवर्ती कस्बों के लिए ही तरकारियाँ उत्पन्न की जाती हैं। सब भासा की जाती है कि यातायात के बीघे सामनों की उत्पत्ति और रक्षितार (Cold Storage) के आविष्कार से तरकारी तथा फलों की ऐसी की बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।



फल (Fruits)—फलों के उत्पन्न करने का धन्दा भारतवर्ष में यहाँ उत्पन्न दशा में नहीं है, क्योंकि यहाँ फलों का उपभोग बहुत कम है। यहाँ लगभग सब प्रकार का जलवायु मिलने से सब प्रकार के फल उत्पन्न किये जा सकते हैं। यहाँ होने

धाने कुछ प्रसिद्ध फल थे हैं—आम, अमरुद, अनार, जामुन, नारंगी व सखरे, नेले पपीता लोन्ही, तरबूज, खरबूजा आदि। वर्तमान समय में कला के उपयोग में वृद्धि पाई जाती है और कुछ फल जैसे आम आदि का निर्यात भी होने लगा है, फलों की किस्म और उनके धर्मों के द्वारा वे पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

मसाले (Spices)—भारतवर्ष में मसालों का उपयोग बड़ी मात्रा में होता है। हल्दी, धनियाँ लाल मिर्च की पैदावार तो प्रायः सभी जगह देखी जाती है। काली मिर्च, दाउचीली, लोण अदरक, इलायची आदि को गर्म जलवायु की आवश्यकता होने से इनकी पैदावार दक्षिणी भारत में मसाला और द्रावणकोर के तट पर होती है।

गन्ना या ईख (Sugar-cane)—भारत गन्ने का जन्म-स्थान है और सारा



का सयने अधिकांश गन्ना पैदा होता है। इन पाकों गर्मी और वर्षा की आवश्यकता है। जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ सिंचाई करनी पड़ती है। गन्ना मार्च-अप्रैल में बोया जाता है और फरवरी में काट लिया जाता है। गन्ना उत्पन्न करने वाले मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब है। इनके अनिश्चित बंगाल, मध्य प्रदेश, और पश्चिम में भी सयने भी खेती होती है। गन्ने की उपज में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है क्योंकि यहाँ भारत का ६०% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। सन् १९३२ ई० में जब विदेशों से घाने वाली शक्कर पर सरक्षण-पर लग गया तब से भारतवर्ष में शक्कर के कारखाने खुल गये और गन्ने की पैदावार में भी वृद्धि हो गई। सन् १९५५-५६ में गन्ने का उत्पादन ७ करोड़ टन था।

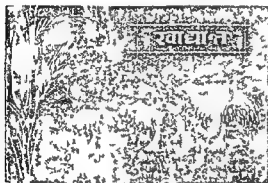
भारत की खाद्य समस्या (India's Food Problem)

गत शताब्दी में भारत धान के उत्पादन में स्वावलम्बी था और यहाँ में धान पर्याप्त मात्रा में विदेशों का निर्यात किया जाता था। धीरे-धीरे इसकी खाद्य-स्थिति बिगड़ती गई और यहाँ तब कि गत महायुद्ध में तो बहुत बड़ी भयंकर हो गई। अब भी खाद्य मजदूत इस देश पर मढ़ा रहा है। इस प्रकार की खाद्य स्थिति होने के अनेक कारण हैं, परन्तु उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) जनसंख्या में वृद्धि, (२) भूमि के उपजाऊपन में कमी हो जाना (३) प्रकृति का प्रकोप अवाह, बाढ़ आदि के रूप में, (४) खेती के लिए सिंचाई और उत्तम वाद का अभाव, (५) आधुनिक खेती के औजारों का अभाव, (६) पशुओं परिवर्तन आदि सभी के वैज्ञानिक ढंगों की अनभिज्ञता, (७) बिना मोच-मगने दूधों को वाटना बिना के पकवस्था भूमि का कटना और उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाना

तथा वर्षा का कम होना (८) खली व लिये निबन्ध पशु और उनके लिये चारे व घास की कमी (९) भारतीय कृषक की श्रद्धा तथा प्रशानता (१०) भोजन का अपव्यय (११) का महापुद्गल व बारण किसान खेतों का काम छोड़ कर मैना में भर्ती हो गये (१२) खाद्य पदार्थों का दोषपूर्ण वितरण (१३) ब्रह्मा का भारत में (१९३ ई०) प्रचलित होना जिससे चावल की कमी हो जाना (१४) देश के विभाजन का प्रभाव—बहु और चावल उत्पन्न करने वाले भाग अधिकतर पाकिस्तान में चले गये (१५) खालात्रा के स्थान पर अधिक पैसा देने वाली फसल—जैसे बज्राम गन्ना जूट आदि बोना (१६) देश में दूध तथा फल की कमी होना (१७) यातायात के साधनों की कमी ।

इही कारणों से हमारे खाद्य स्थिति अत्यन्त मन्दतम हो गई है । अनाज की



कमी को दूर करने के लिये बरोडा योजना का अनाज हमारी सरकार को विशेषा में समर्पण पड़ता है । सन् १९५६ में ३६ लाख टन गन्ना पावन खाद्य खाद्यान्न आयात किया है जब तक हम अन्न के लिये हमारे देश का मुँह ताकते रहेंगे ? सन् १९५०-५१ में ५ करोड़ टन और सन् १९५५

५६ में ६ करोड़ टन खाद्यान्न पड़ा निम्न । इसी योजना के अन्तर्गत वर्षान्तर १९६०-६१ तक ५ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का नया यत्न रखा गया है ।

खाद्य सामग्री में वृद्धि करने के उपाय

(१) पड़त भूमि में खली करना (२) सामूहिक खेतों () रासायनिक खाद्य का उपयोग (४) निषाई के साधनों में वृद्धि करना (५) अन्न व अनिश्चित अन्न पोषण पदार्थों की उपलब्धि करना जैसे दूध फल सब्जियाँ तथा मछली का प्रयोग (६) उत्तम खाद्य एवं बीज की व्यवस्था करना (७) भूमि की कृषि योग्य बनाना (८) गहरी खेती करना (९) खेती की उपज बढ़ाने के लिये अपेक्षित एवं प्रयोग करना (१०) आधुनिक औद्योगिक के खली कृषक के परामर्श करना (११) छोटे छोटे गार व मलिया को बांध कर अपवाहों को नियंत्रण बनाना (१२) दोषपूर्ण गन्ना प्रयोजन वाली योजनाओं को काय रूप में लाना (१३) छोटे छोटे खेतों का एकीकरण करना (१४) खेती के औजारों तथा अन्न वस्तुओं की यातायात सुविधा (Priority) प्रदान करना (१५) खाद्य भंडार के विवरण की समुचित व्यवस्था करना (१६) प्रविष्ट अन्न उपजाओ तथा वृद्ध नमामो आदालत को सकल बनाना ।

(२) पेय पदार्थ एवं मादक वस्तुएँ (Beverages & Drugs)



चाय (Tea)—चाय एक प्रकार की झाड़ी की सूखी पत्ती है। चाय का वृक्ष उष्ण कटिबंध में ही उत्पन्न हो सकता है। इसकी पैदावार के लिये गर्मी और जल की बहुत आवश्यकता है, परन्तु यदि जल वृक्ष की जड़ के पास देर तक रहे तो वृक्ष की हानि पहुँच जाती है। इसी कारण चाय बहुधा पहाड़ के ढालों पर उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि पानी बह जाय। चाय की भाँड़ी लगभग पाँच वर्षों में चाय उत्पन्न करने योग्य हो जाती है और ३० वर्ष पर्यंत पत्तियाँ देती रहती हैं।

भारत में बांग्लादेश और बर्मा सबसे अधिक चाय उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। बांग्लादेश में भारत की उपज की ५३% चाय उत्पन्न की जाती है और बर्मा की दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर २८% चाय पैदा की जाती है। इनके अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और केरल में भी पैदा होती है। भारत में चाय उत्पन्न करने वाली कुल भूमि ७८ लाख एकड़ है जिनमें १२।८ लाख धूम्रक काम करने के लिए, और कुल वापिक पैदावार १८ करोड़ पौंड है। यह भारत की मुख्य व्यापारिक फसल है। पैदावार का तीन-चौथाई भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है।

सन् १९५८-५९ में ६८ करोड़ पौंड चाय उत्पन्न की गई जिसमें से १३६ करोड़ रुपये के मूल्य की चाय निर्यात की गई। देश में 'चाय बोर्ड' द्वारा चाय के उपभोग का प्रचार-निर्वाह जाता है जिसके फलस्वरूप भारत में पहले की अपेक्षा चाय अधिक खपने लग गई है।



कहवा का पौधा

कहवा (Coffee)—कहवा भी चाय की भाँति पेय पदार्थ है। कहवे का वृक्ष चाय की तरह गर्मी और पानी चाहता है, किन्तु कहवे का पौधा जबकि बह छोटो होता है मूल्य की तेज धूँ को सहन नहीं कर सकता। कहवे के लिये बहुत उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है। दक्षिण के नीलगिरि पहाड़ी प्रदेश में कहवा ध्रुव पैदा होता है। मैसूर, कुर्ग, मद्रास, और केरल में मुख्यतया यह उत्पन्न होता है। भारत की सम्पूर्ण उपज का १०% कहवा मैसूर राज्य से और २५% मद्रास राज्य में प्राप्त होता है।

सन् १९५८-५९ में भारत में २४ लाख एकड़ भूमि में ८८ करोड़ पौंड कहवे की पैदावार की गई। भारत में इसका उपभोग बहुत कम होता है, परंतु पैदावार का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। सन् १९५८-५९ में भारत में २४ लाख एकड़ भूमि में ८८ करोड़ पौंड कहवे की पैदावार की गई। भारत में इसका उपभोग बहुत कम होता है, परंतु पैदावार का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। सरकार ने एक पञ्चवर्षीय योजना को स्वीकार कर लिया है। इस योजना पर लगभग २ करोड़ ६५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।



तम्बाकू (Tobacco)—भारतवर्ष में तम्बाकू का प्रचार अधिक है। तम्बाकू का उपयोग पीने खाने और सूखने में होता है। तम्बाकू उष्ण कटिबंध की पैदावार है परन्तु वह बहुत प्रकार के जलवायु में उपजती होती है। तम्बाकू की पैदावार के लिये भूमि उपजाऊ होनी चाहिये। तम्बाकू की फसल के लिए साद और सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। इसे भारतवर्ष में तम्बाकू उगभग सभी जगह पैदा होती है परन्तु बंगाल उड़ीसा मद्रास बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अधिक मात्रा में पैदा की जाती है। भारत में तम्बाकू मन् १९५८ ५९ में ६ लाख एकड़ भूमि प्रयुक्त की गई जिस पर २६ लाख टन पैदावार की गई।

भारतीय तम्बाकू मोटी तेज और गहरे रंग की होने के कारण सिगरेट बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है। भारत में इसका उपयोग अधिकतर बोझो बनाने और हुका पीने में होता है। अधिकांश पैदावार यही उपयोग में आ जाने के कारण केवल २० प्रतिशत ही निर्यात की जाती है। खरार के तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है।

(३) कच्चे मान की या व्यापारिक फसलें (Raw Materials or Cash Crops)



कपास (Cotton)—एक भाड़ी का फूल है जिसके रंग में सूत तैयार होता है। कपास उष्ण कटिबंध की पैदावार है। कपास की पैदावार के लिये गर्मी और धूप की बहुत आवश्यकता होती है। परन्तु अधिक गर्मी उसके लिए हानिकारक है। गर्मी के दिनों में साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है। किन्तु अधिक वर्षा पैदावार कम करती है। पारा कपास को मष्ट कर देता है। कपास के लिये हल्की मज्जिमर भूमि जिसमें नूना हो उपयुक्त है। भारतवर्ष में नावा या बरार प्रान्त की काली भूमि इसके लिए अत्यन्त उपयुक्त है। पानी की कमी सिंचाई द्वारा पूरी की जाती है। भारत में कपास उत्पन्न करने वाले प्रान्तों में बरार खानदेश मध्य भारत मध्य प्रदेश गुजरात तथा बम्बई का उत्तर पश्चिमी भारत मध्य प्रदेश गुजरात तथा बम्बई का उत्तर पश्चिमी भाग मुख्य है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कपास पैदा होता है। भारतवर्ष में १ करोड़ २९ लाख एकड़ भूमि पर कपास उत्पन्न की जाती है।

भारत की कपास अच्छी जाति की नहीं होती। फूल बहुत छोटा होता है जिसमें घारीय सूत तैयार नही हो सकता। भारत के विभाजन के पश्चात्पश्चात् पंजाब का पश्चिमी भाग तथा मध्य पश्चिम में चला गया। इस दृष्टि में आगनाय बिना के नूना रंग वाली कपास की हानि हो गई। परन्तु भारत सरकार इस बात का ध्यान कर रही है

कि सन्धे रेंगे वाली कपास भी ग्रेड माना में भारतवर्ष में ही उत्पन्न हो जितने भारत कपास के लिये बाहरी देशों पर निर्भर न रहे। इस सम्बन्ध में 'इन्डियन कौटन कमेटी' ने कपास की किस्म बायम रखन के लिये कई कानून बना कर सराहनीय कार्य किया है। भू० साधमश्री धा के० एम० मुन्शी ने १६ नवम्बर १९५० का संसद में यह प्रकट किया था कि भारत कपास की 'पूर्वी भारतीय किस्म' (East Indian Varieties) में सन् १९५१-५२ तक स्वावलम्बी हो जायगा। छोट रेंगे वाली रूई देश की आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त विदेशों का विशेषतया इंग्लैण्ड और जापान को निर्यात की जानी है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व कपास का उत्पादन २६५ लाख गॉटों था। सन् १९५४-५५ में यह उत्पादन ८२.६८ लाख गॉटों तक पहुँच गया, प्रथम उत्पादन में ४२% वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह सलग प्रथम योजना के उत्पादन से ३१% अधिक रखा गया। सन् १९५८-५९ में ४७ लाख गॉटों की उत्पत्ति हुई।

जूट (Jute)—एक प्रकार का लम्बे पीये का द्विवेक होना है। इस रेशेदार द्विवेक का कातकर सूत तैयार किया जाता है और इसी में टाट आदि बुने जाते हैं। देश के विभाजन के पूर्व भारत समस्त भारत में सबसे अधिक जूट पैदा करता था। जूट की खेती के लिये अधिक गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है। जूट की खेती से माला ही भूमि के पाए गए ताल गढ़ हो जाते हैं, अतः उस भूमि पर प्रतिवर्ष नदियाँ से पानी हवाई मिट्टी बिछ जानी चाहिये। बंगाल में यथा की बात में मैदान पर नहीं मिट्टी बिछ जाती है। यही कारण है कि भारतवर्ष का ६० प्रतिशत जूट बंगाल में ही पैदा होता है और १० प्रतिशत बिहार उड़ीसा आदि में पैदा होता है। देश के विभाजन के कारण जूट की मिल तो भारत में रहे गई हैं और जूट की पैदावार अधिकांश पाकिस्तान में होती है। परस्पर मल नहीं हान के कारण हमका जूट की खेती पड़ रही है। विदेशों में भी अन्य दुर्लभ म्यानाएज मनुष्यों के प्रयोग में जूट की खपत को कम कर दिया है।



जूट (जूट) का पौधा

भारतवर्ष में जूट की पैदावार की बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सन् १९५० में जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिये विविध सरकारी को महत्वाका और ऋण के रूप में १३ लाख रुपय केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गये थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व जूट का उत्पादन ३३ लाख गॉटों था, परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में यह उत्पादन ४० लाख गॉटों तक पहुँच गया था। दूसरी योजना का उत्पादन-तत्त्व प्रथम योजना की अपेक्षा २४% अधिक रखा गया। सन् १९५८-५९ में जूट का उत्पादन ५२ लाख गॉटों का रहा।

रबड़ (Rubber) - भारतवर्ष समस्त की उत्पत्ति का २ प्रतिशत रबड़ उत्पन्न करता है। इसका गन्ने व तर जलवायु की आवश्यकता है। रबड़ एशिया भारत में विशेषतया मद्रास, गुर्ग, मैसूर, केरल में उत्पन्न होता है। केरल सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न करता

है। १ लाख ४१ हजार एबड भूमि रजड की पैदावार ने दिव प्रयुक्त की जाती है और



कुन पैदावार ३ करोड ६० लाख पोड का लगभग हाती है। भारत में उत्पन्न होने वाली रजड कोचीन कन्दमूल द्वारा इंगलंड तथा हालट स्ट मैट्रिमैन्ट आदि को भेजी जाती है। द्वितीय महायुद्ध के कालमें भारत में रजड की उत्पत्ति बहुत बढ़ गई है। सन् १९१८-१९ में १८८ लाख एबड भूमि पर ४९ लाख पांड रजड उत्पन्न की गई।

तिलहन (Oilseeds)—भारतवर्ष में तिलहन उत्पन्न करने का देश में मुख्य है और प्रविषण कराडा रणया का तिलहन विदेशों को मुख्यतः काम का भेजा जाता है। तिलहन की मुख्य वस्तु निम्नलिखित हैं—सरसो, राई, सन का

बीज बिनोडा तिल छोटी और मूँगफली। इनके अनिरिक्त कारियन और मन्दा का पना में भी वन तैयार होता है।



तिलहन



अंडी (रडी)



राज्य

सरसो और राई (Rape and Mustard)—उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल और आसाम।

अण्डी (Linsced)—मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बम्बई और मद्रास।

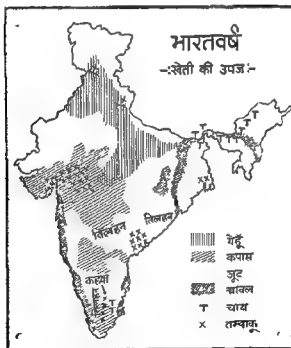
अंडी (Castor seed)—मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश।

तिल (Sesamum)—मद्रास, मध्य प्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आंध्र।

मूँगफली (Groundnut)—गुजरात, बम्बई, मध्य प्रदेश, -छत्तीसगढ़ और
आंध्रप्रदेश

जिन्नीला (Cotton seeds)—बम्बई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब,
उत्तर प्रदेश

सन् १९५५-५६ में मूँगफली की खेती का क्षेत्रफल १ करोड़ ४४ लाख एकड़ और उत्पादन (छिलके सहित) ४५ लाख १६ हजार टन था। सन् १९५५-५६ में रेड्डी की उपज १ लाख १३ हजार टन और क्षेत्रफल १२ लाख एकड़ था। प्रथम योजना के अन्त में तिलहन का उत्पादन ५५ लाख टन था जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह लगभग ७० लाख टन निर्धारित किया है।



भारतवर्ष की कृषि सम्पत्ति

योजना और कृषि-उत्पादन—योजना काल में कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में मुख्य तमय निम्न तानिका में दिये गये हैं :-

वर्ष	इकाई	१९२५-२६ में अनुमानित उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य	१९६०-६१ तक अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत वृद्धि
लोचात्र	साल टन में	६५०	१००५	७५०	१५.४
तिनहन	" "	२५	१५	७०	२७.३
गन्ना (गुड)	" "	४६	१३	७१	२७.६
रई	माख गौडे	४२	१३	५५	३१.०
हूट	" "	४०	१०	५०	२५.०

कफसलों का विवरण कुछ इस प्रकार है :—

	माख टन
चावल	४०-५०
गेहूँ	१५-२०
अन्य अनाज	२०-२५
दाले	१५-१५

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्द'स परीक्षाएँ

- १—भारतीय कृषि में मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? उनको हल करने के सुझाव दीजिए ।
(अ० बी० १९६०)
- २—भारत की वर्धमानकृषि में कृषि का महत्त्व समझाइए । हमारी कृषि की उन्नति के उपायों का वर्णन कीजिए ।
(रा० बी० १९६०)
- ३—भारत में कृषि को पिछड़ी हुई दशा के क्या कारण हैं ? हम दशा की उन्नति के लिये हाल में क्या-क्या उपाय काम में लाये गये हैं ?
(अ० बी० १९५६, ५८, नागपुर १९५०)
- ४—भारत की कृषि उपज क्या-क्या है ? इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या तरीके काम में लाये गये ? उनका विवरण कारण सहित लिखिए । (अ० बी० १९५२, ४०)
- ५—खाद्य उपजों और व्यापारिक उपजों पर टिप्पणी लिखिए । (नागपुर १९४७)
- ६—अन्य देशों की तुलना में भारत की कृषि की कम उपज के कारणों की व्याख्या कीजिए ।
(नागपुर १९४५)
- ७—भारत की कृषि में मन्त्रों के प्रयोग के लाभों और हानियों का विवेचन कीजिए ।
(अ० बी० १९५६ पू०)
- ८—भारत की प्रमुख फसलों का व्यापारिक महत्त्व और वितरण लिखिए ।
(पटना १९५२)
- ९—कृषि के दोषों का उत्प्रेषण कीजिए और उनको दूर करने के उपाय बताइए ।
(पटना १९ २)
- १०—भारतीय कृषि प्रणाली क्या है ? इसमें क्या दोष हैं ? क्या ये दूर किये जा सकते हैं ?
(दिल्ली हमर सेनेटरी १९४७)
- इष्टर एपीकलनर
- ११—कृषि भव्यताओं की विशेष समस्याएँ क्या हैं ? उनको घाय किस प्रकार हल करेंगे ?
(अ० बी० १९५६)

भारतवर्ष में सिंचाई (Irrigation in India)

सिंचाई का अर्थ एवं महत्व (Meaning and Importance of Irrigation)—भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी तीन-चौथाई से भी अधिक जनसंख्या परोक्ष या अपरोक्ष रूप में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि की सफलता के लिये निर्यामिन रूप में पर्याप्त मात्रा में जल मिलना नितान्त आवश्यक है। यही कारण है कि भारत की कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था में वर्षा का अंश महत्व है। ऐसी अवस्था में वर्षा को भारत की माप्य विधाता कहना कोई अति-वायोक्ति नहीं होगी। हमें आचार्य पर वुल्फ (Wolff) ने ठीक ही कहा है “भारतीय अर्धवर्षा का लुप्ता है। यदि वर्षा नहीं आती है, तो कृषि व्यवसाय स्थगित हो जाता है।”

यदि वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो इसकी पूर्ति के साधन जुटाना आवश्यक हो जाता है। मनु खेतों को कृत्रिम ढंगों से पानी देने को सिंचाई कहते हैं। वर्षा द्वारा जमीन को जल मिलना एक प्राकृतिक उपाय है, परन्तु सिंचाई द्वारा पानी मिलने का अप्राकृतिक या कृत्रिम ढंग कहते हैं।

भारतवर्ष में सिंचाई की आवश्यकता (Necessity of Irrigation in India)

निम्नांकित कारणों भारत में सिंचाई की आवश्यकता प्रकट रहती है --

१. भारत में वर्षा समय और स्थान की दृष्टि से अनिश्चित है। कभी वर्षा अधिक हो जाती है तो कभी कम। तीन वर्ष के चक्र में एक वर्ष उत्तम, दूसरा निम्न और तीसरा उष्णित होता है। अतः वर्षा की कमी की पूर्ति सिंचाई में की जाती है।

२. देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। बंगाल, आसाम, पश्चिमी बंगाल आदि स्थानों पर वर्षा अधिक होती है, अतः वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु अन्य भागों में, जहाँ वर्षा साधारण होती है जमीन को देने के लिए सिंचाई पर आश्रित रहना पड़ता है।

३. हमारे देश में कुछ भागों में वर्षा नहीं के बराबर होती है जैसे राजस्थान का अधिकांश भाग, पश्चिमी पंजाब आदि। यहाँ सिंचाई न की जाय, तो पैदावार बिल्कुल नहीं हो सकती।

४. भारत में ६० प्रतिशत वर्षा गर्मियों में मानसून में होती है और सर्दियों में वर्षा बहुत कम होती है, अर्थात् जमीन के बराबर होती है, अतः सर्दियों की फसलों के लिये सिंचाई नितान्त आवश्यक है।

५. भारतवर्ष में कुछ पसलों ऐसी हैं जो किता अधिक और नियमित पानी की पूर्ति के बिना नहीं हो सकती। जैसे—चावल, गन्ना, जूट आदि।

६. देश में कुछ भागों की मिट्टी ऐसी है जो अधिक समय तक पानी को धरने में नहीं रख सकती, जैसे बालू, रेत। इस प्रकार की मिट्टी को गोली रखने के बिना उसे निरन्तर पानी देने की आवश्यकता है।

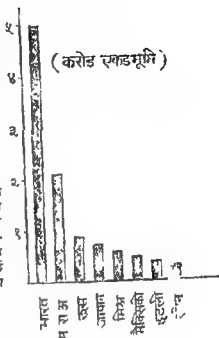
७. भारत की बहुतों हुई जनसंख्या की विलक्षण के लिये केवल वर्षों की वर्षा में होने वाली पसलों ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नदों की पसला की भी आवश्यकता होती है। परन्तु नदों में वर्षा नहीं होने के कारण सिंचाई के साधनों का उपयोग करना पड़ता है।

भारतवर्ष में सिंचाई के साधन (Means of Irrigation in India)

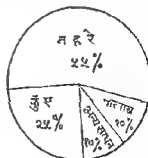
भारतीय प्रजातन्त्र में सिंचाई के एक साधन में लगभग ५ करोड़ एकड़ भूमि सीधी जाती है जो समस्त दुवि माध्य भूमि का लगभग १७ प्रतिशत है। ऊपर के रेखाचित्र में यह स्पष्ट है कि गन्ना में सब से अधिक सिंचाई भारतवर्ष में होती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के कारण पन्नाय और मिन्य के अधिकार सिंचाई के साधन पर अधिकार के अधिकार में बने गये हैं।

भारतवर्ष में मुख्य सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं—

१. कुएँ (Wells)
२. तालाब (Tanks)
३. नहर (Canals)

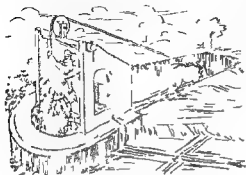


भारत में सबसे अधिक भूमि सीधी जाती है



सिंचाई के साधनों का वितरण

१. कुएँ (Wells)—कृषा द्वारा सिंचाई भारत का अत्यन्त प्राचीन ढंग है। भारत में जितनी भूमि में सिंचाई होती है उसका लगभग चौथाई भाग अर्थात् १



करोड़ २० लाख एकड़ भूमि कुआँ द्वारा सींची जाती है। भारत में लगभग २२ लाख कुएँ हैं जिनमें बनने में १०० करोड़ रुपये व्यय हुआ है। कुआँ द्वारा सिंचाई करने के ढंग में भारतीय किसान भलीभाँति परिचित हैं और ये कुएँ भी अनेक प्रकार बना सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व एवं कृषा कुआँ

कुएँ द्वारा सिंचाई लगभग ५० ८० म मैपार हो जाया करता था। वैसे कुआँ द्वारा सिंचाई प्रायः सभी राज्या में होती है परन्तु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब बम्बई, मद्रास बिहार और ब्रिगो-पूर्वी राजस्थान में अधिकता से होती है।

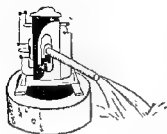
कुआँ द्वारा सिंचाई करने में भी कई ढंग प्रचलित हैं जिनमें परम ऊँची आदि। रह (Persian Well) में कुछ व्यय अधिक होता है। इस ढंग का उपयोग मलाबार राजस्थान काठियावाड़ पंजाब और बम्बई में अधिक होता है। चरस (Leather Bag) उत्तर प्रदेश मद्रास मध्य प्रदेश और बिहार में प्रचलित है।



कुआँ द्वारा सिंचाई के विविध ढंग

उत्तर प्रदेश के ट्यूब-वेल अर्थात् टिजनी के कुएँ (Tube-wells in U. P.)

कुआँ द्वारा सिंचाई में भी बिजली का प्रयोग बड़ा लाभदायक मिष्ट हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने १३ करोड़ रुपये व्यय करके १६१० ट्यूब-



नलकूप (थ्यूब व्हील)

सींचो जा सकती है । जैसे-जैसे विजली का प्रसार अल्प जिला में होता जायगा, वैसे-वैसे वहाँ भी थ्यूब-व्हील की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी ।

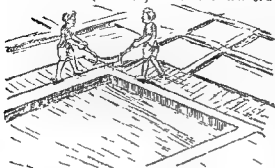
इन विजली के कुँआ से उत्तर प्रदेश को उपज बढ़ गई है और बेकार पड़न भूमि ऊपि योग्य बन गई है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग १५०० थ्यूब व्हील बनाने की योजना और तैयार की है जिससे निकट भविष्य में इस राज्य के पश्चिमी शुष्क भाग में गेहूँ कपास, गन्ना आदि की पैदावार बढ़ जायगी । भविष्य में थ्यूब-व्हील उत्तर प्रदेश में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन बन जावेगा ।

गंगा-नहर जल-विद्युत् ग्रिड योजना (Ganges Hydro-Electric Grid System)—उत्तर प्रदेश में गंगा की नहर के प्रवाह को कम करने के लिए लगभग दस-दस फीट की ऊँचाई के कुछ प्रपात (Falls) बनाये गये हैं जिनके द्वारा जल-विद्युत् तैयार की गई है । धीरे-धीरे अलग-अलग प्रपातों के दस्ति-घर (Power Houses) विजली के तारों द्वारा एक दूसरे से मिला दिए गये हैं । इसको मिला देना से जो विजली की योजना तैयार हुई है उसको गंगा-नहर जल-विद्युत् ग्रिड योजना कहते हैं ।

कुएँ द्वारा सिंचाई का भविष्य (Future of Well Irrigation)—कुएँ द्वारा सिंचाई के लिए हम देश में अब भी बड़ा क्षेत्र है । कुएँ सुगमता से कम व्यय में बनाये जा सकते हैं, अतः इस साधन का भविष्य अधिक उज्ज्वल प्रतीत होता है । सस्ती विजली से थ्यूब-व्हील का प्रसार अत्यधिक हो सकता है । उत्तर प्रदेश की भूमि अल्प राज्या में भी सरकार द्वारा थ्यूब-व्हील योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं । इसी से अल्प समय में हमारी खास समस्या बहुत-कुछ सरल हो सकती है ।

योजनाएँ और नलकूप—साधारण सिंचाई के लिए नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं । सन् १९५१ में पहले भारत में लगभग २५ हजार नलकूप थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पेश्वर और जम्मुई में लगभग ४,४०० नलकूप और तैयार हुए । इन नलकूपों से लगभग २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । आगू योजना में ३५०० नलकूप और लगाये जायेंगे ।

२ तालाब (Tanks) — तालाब तथा बांध द्वारा मिर्चाई भारतवर्ष

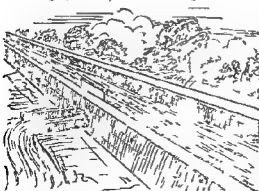


तालाब द्वारा मिर्चाई

तालाब इतिहासी भारत में है। इनकी संख्या लगभग ७५ हजार है। सबसे महान् राज्य में ३५ हजार तालाब हैं जिनमें ३८ लाख एकड़ भूमि सिंचा जाया है। महान् राज्य में परिवार बांध (Pernar Porject) घरेलू पानी एकत्र भूमि की सिंचता है। बंगाल में ३ लाख और बिहार में १६ लाख एकड़ भूमि तालाबों द्वारा सिंचा जाता है। सम्पूर्ण भारतीय प्रजासत्तय राज्य में ६० लाख एकड़ भूमि सिंचाई १२ प्रतिशत भूमि तालाबों द्वारा सिंचा जाती है। महान् व बांध या प्रजासत्तय में अधिक तालाब है। उच्च तालाब राजस्थान व दक्षिणी-पूर्वी पहाड़ भाग द्वारा मध्य भारत में भी है।

में प्राचीन समय में चली आ रही है। भारत के जिन भागों में भूमि पर्वतीय है प्रत्येक भूमि व तांचे का पानी (Sub soil Water) बहुत गहरा है वहाँ तालाबों और बांधों से मिर्चाई का पानी है। अतिवर्ष

३ नहर (Canals) — भारतवर्ष में नहरों द्वारा मिर्चाई एक प्रमुख साधन



नहरों द्वारा मिर्चाई

होने के कारण इन्हें सरकार स्वयं बनवाता है। अधिभाजित भारत में जिनका मिर्चाई नहरों में जाती थी उसकी १४ प्रतिशत व्यक्तिगत मालिकता द्वारा होती है।

है। देश में जिनका भूमि का मिर्चाई होता है उसका सबसे अधिक भाग नहरों द्वारा ही सिंचा जाता है। भारत में कुल नहरों का दम्बा ७६,००० मील है। इतना बड़ा नहरों का जाल बनाने के बिना प्रत्येक क्षेत्र में पानी मिर्चाई नहरों के बिना संभव नहीं है।

नहरों के प्रकार (Kinds of Canals)—भारत में मुख्य तीन प्रकार की नहरें पाई जाती हैं —

१. वरमाती या बाढ़ की नहरें (Inundation of Flood Canals) — ये नहर नदी में सीधे जिन बाँध के निकाली जाती हैं । मुख्यतः नहर बाढ़ रोकने के लिए बनाई जाती है । जब नदी में बाढ़ का पानी बम हटा जाता है तो इन नहरों में भी पानी बन्द हो जाता है । इन नहरों का केवल वर्षा ऋतु में ही उपयोग होने के कारण ये 'वरमाती' नहरें कहलाती हैं । वर्षा ऋतु के बाढ़ मिचाई के लिए कुओं का ही साध्य लेना पड़ता है । पञ्जाब और सिन्ध में पहले इस प्रकार की नहर थी, परन्तु अब इन नहरों का स्थायी या निर्या बहने वाली नहरों में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । मकर बांध इसी का एक उदाहरण है ।

२. स्थायी नहर (Perennial Canals) — इन नहरों के बनाव में बाँध का प्रयोग किया जाता है । नदी के आरवार बाँध डालने में नदी के पानी की दृष्टि से राह ऊँची हो जाती है जिससे नहरों में बग़ार पानी पहुँचना रहता है । इसीलिए ये स्थायी नहरें कहलाती हैं । इस प्रकार की नहरें उत्तर प्रदेश, पञ्जाब और मद्रास में पाई जाती हैं । निम्न नदी के आरवार बाँध बना कर वरमाती नहरों का स्थायी नहरों में परिवर्तित कर दिया गया है ।

३. गोदामी नहर (Storage Canals) — ये नहर उन स्थानों में बनाई जाती हैं जहाँ मरदा बहने वाली नदियों का पूर्ण प्रसार होता है । वरमाती पानी का एकत्रित करने के लिए बाँधों के आरवार बाँध बना दिया जाता है और फिर नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती हैं । इस प्रकार की नहरें बङ्गाली भारत, मध्य प्रदेश, बुन्देलखण्ड और मद्रास में पाई जाती हैं ।

भारतवर्ष में नहरों का वितरण

(Distribution of Canals in India)

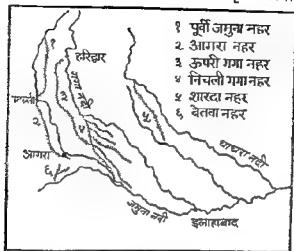
भारतवर्ष में अधिकांश नहरें उत्तर प्रदेश और पूर्वी पञ्जाब में पाई जाती हैं । इसमें निम्नलिखित कारण हैं — (१) मरदा बहने वाली नदियों का वितरण होना, (२) नदियों उत्तम गति में बँधी हुई हैं, (३) भूमि का समतल होना और (४) भूमि में उपजाऊ होने के कारण नहरों में अधिक लाभ पहुँचना ।

उत्तर प्रदेश की नहरें (Canals of U. P.)

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नहरें हैं — (१) ऊपर-गंगा-नहर (Upper Ganges Canal), (२) निचली-गंगा नहर (Lower Ganges Canal) । ये दोनों नहर बाघाज के जिला का सीक्ती हैं । (३) पूर्वी यमुना-नहर (Eastern Yamuna Canal), और (४) घागरा नहर (Agra Canal) । ये दोनों नहर यमुना में निकाली गई हैं और यमुना में पूर्वी और पश्चिमी तट के जिलों का सीक्ती हैं ।

(५) शारदा नहर (Sharda Canal) — यह नहर सन् १९२० ई० में उत्तर प्रदेश में बँधी थी । इस नहर का विभाजन-कार्य नहर-उपनिषद् का एक प्रमुख समुदाय के समुदाय प्रयुक्त किया है । इस नहर का निर्माण में लगभग १० करोड़ रुपये व्यय हुआ है । इसके द्वारा मध्य और बुन्देलखण्ड की लगभग ६० लाख एकड़ भूमि सीक्ती जाती है और इस भूमि पर अधिकतर गन्ने की खेती होता है ।

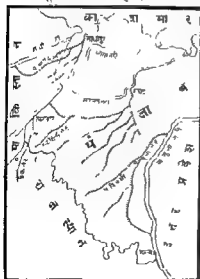
(६) बेतवा नहर (Betwa Canal) — बेतवा नदी यमुना की ही शाखा है । इसी में १२ मील दूर पच्छिम नामक स्थान पर नदी में एक नहर निकाली



उत्तर प्रदेश का नहर

गर्त है जो उत्तर प्रदेश के भागी जागीन और हमीरपुर जिला की प्राय २ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई करती है।

पूर्वी पंजाब की नहर (Canals of East Punjab)



पूर्वी पंजाब की नहर

भारत के विभाजन से पूर्व पंजाब में एक उत्तम नहर प्रणाली स्थित थी परन्तु विभाजन के पक्ष स्वरूप अब पूर्वी पंजाब में केवल चार नहर बच रह गई हैं —

१ पश्चिमी यमुना नहर (Western Yamuna Canal) — यह नहर पुरानी है जो सन् १८०० ई० में बनकर तैयार हो गई थी। इसमें द्वारा दक्षिणी पंजाब को पानी मिलता है जिससे लगभग २ लाख एकड़ भूमि सिंचा जाती है।

२ ऊपरी बारी दोआब नहर (Upper Bari Doab Canal) — यह नहर सन् १८६० में बनकर तैयार हो गई थी। यह रावी नदी से बनानी गई है और इसमें अमृतसर आदि जिला में लगभग १० लाख एकड़ भूमि को पानी मिलता है।

३ सर हिन्द नहर (Sirhind Canal)—यह सतलज नदी में निकाला गई है और सन् १८८८ ई० में बनकर तैयार हो गई था। इस नहर की कुल लम्बाई साक्षात्मा महित ३८०० मील है और इसके द्वारा सुधियाना फिरोजपुर हिसार पणियाला नामा जोड़ पादि में कुल मिलाकर लगभग १८ लाख एकड़ भूमि का सिंचाई होती है।

४ सतलज घाटी की योजना (Sutlej Valley Project)—इस योजना में अन्ततः कुल ११ नहर निकाली गई है। इस सम्पूर्ण कार्य में २१ करोड़ रुपये व्यय होकर सन् १९३३ ई० में यह योजना पूर्ण हो गई थी। यह पंजाब की फिरोजपुर जिले की नहरों को छोड़कर सारी नहरें पाकिस्तान में हैं। इन नहरों में बोकाराने की लगभग ३३ लाख एकड़ भूमि सिंचाई द्वारा हरी भरी हो गई है।

दक्षिण की नहरें (Canals of Deccan)

यह तो पहले ही बना दिया जा चुका है कि दक्षिण में नहरों में सिंचाई नही होगी। केवल महानदी, गोदावरी कृष्णा और कावेरी के क्षेत्र में नहरों का उपयोग होता है।



कावेरी मैट्टूर योजना (Kaveri Mettur Project)

—कावेरी नदी क डेल्टा में नहरों द्वारा लगभग दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी या परन्तु नहरों में पानी भेजने का कोई प्रयत्न नही या अग्न मैट्टूर (Mettur) नामक स्थान पर कावेरी नदी पर एक बाध द्वारा ८० हजार स्क्वियर फीट पानी रोक कर ८८ मीटर लम्बी एक नहर निकाली गई है जो अपनी साक्षात्मा द्वारा १० लाख एकड़ भूमि का सिंचकर कृषि-योग्य बनाता है। यह योजना सन् १९३४ ई० में बनकर तैयार हो गई था।

पेरियार योजना (Pennisar Project)—यह दक्षिण में सबसे पुरानी योजना है। पेरियार नदी वारडेमम पहाड़ियों में निकल कर भरत सागर में गिरती थी, परन्तु नदी के पश्चिमी तट पर कोई इन्फ्रा उपयोग नही था क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसके विपरीत वारडेमम पहाड़ियों के पूर्व में स्थिति निम्नवर्ती और मधुरा जिला के निचले मैदान पानी बिना प्यासे थे क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। इन दुर्लभ जिलों को



पाना पिलाने के लिए महाड की जह में एक मुख्य खादी गई जिसके कारण परियार नदी भरव नागर से मुहकर इन मुख्य जिला में बहने लगी। इसके द्वारा लगभग १० लाख एकड़ भूमि में खेती होती है।

यम्बई राज्य के बांध

यम्बई राज्य में दो महत्वपूर्ण बांध हैं—भंडारदरा बांध और लॉयड बांध।

भंडारदरा (Bhandardar Dam)—यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह गोदावरी की एक महायक नदी में पानी लेकर प्रवाह नहर के लिए पानी प्राप्त करता है। इससे द्वारा ग्रहमदनगर जिले में ८० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होकर कुछ गन्ने की फसलों पैदा होती है। यात्रना सन् १९२५ में बन कर तैयार हो गई थी।

लॉयड बांध (Lloyd Dam)—यह हुन्गा नदी की एक महायक नदी पर बना है और इसमें सीरा नहर का पानी मिलता है, जिसमें पुनः और सोलापुर जिलों में ३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

मुन्देनखण्ड में प्रभुन बांध

उत्तर प्रदेश का हुमनापुर जिले में १०२ करोड़ रुपय की लागत में प्रभुन बांध बनाई जाती थी। यह बनकर नैयार हुमा है। मुन्देनखण्ड की समृद्धि और विकास के लिए प्रभुन बांध का महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रभुन बांध ७४ फुट ऊँचा, २० फुट चौड़ा और २३ मील लम्बा है। इसके निर्माण में ३ वर्ष लग्य हैं। इन बाँध के जलाशय में १६६,७० लाख घनफुट पानी संग्रहीत हो पाता है जिसमें २६,६७२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इन सिंचाई की व्यवस्था के फलस्वरूप पन्ना/वाहन में ७,५०० टन की वृद्धि होगी। परन्तु यह वृद्धि रबी की फसल में ही होगी।

बिहार की नहरें (Canals of Bihar)

बिहार में तीन मुख्य नहरें हैं—पूर्वी सोन नहर (Eastern Son Canal) पश्चिमी सोन नहर (Western Son Canal) और त्रिवेणी नहर (Triveni Canal)।

मध्य प्रदेश की नहर (Canal of M. P.)

मध्य प्रदेश की मुख्य नहरें हैं—महानदी (Mahanadi Canal) नर्मदा नहर (Narmada Canal) और तन्डुला नहर (Tandula Canal)।

दासादर नदी से एक नहर निकाली है जिसका नाम दासादर नहर (Dasaoder Canal) है। इस नहर के द्वारा बगल के बरदवाल और हुजली जिलों में सिंचाई होगी है।

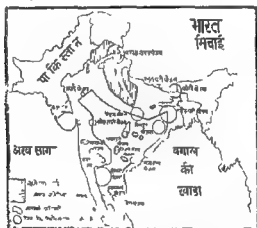
राजस्थान नहर—राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी शैलीय भाग में जल का प्रभाव का दूर करने के लिए ३० मार्च १९५६ का कानूनी मुद्दा सभी द्वारा राजस्थान नहर का संग्रहण किया गया। इसके निर्माण में ६१ करोड़ रुपय से भी अधिक का अनुमान है। इसका कार्य क्षमता विचार है कि इस नहर पर २० हजार मनुष्य प्रतिदिन के हिसाब से बराबर १० वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। इस नहर के बन जाने पर लगभग ३२६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। यह सतलज नदी पर ध्यास के समय में एक नीच निर्मित हरी के बांध में निकाली जायगी।

मिचार्ट के कुछ नवान् योजनाएँ (New Irrigation Works)

स्वतन्त्र भारत में केंद्राध्य तथा राज्य सरकारों ने बहुत सी बहुप्रयोजन योजनाएँ (Multipurpose Projects) प्रारम्भ कियी हैं जिनमें न केवल जल विद्युत ही उत्पन्न होगी बल्कि साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होगी। इन योजनाओं में के मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) दामोदर घाटी योजना (२) ब्राह्मणी नगर योजना (३) त्रिशूल बांध योजना (४) तुंगभद्रा योजना (५) हीराकुण्ड बांध योजना (६) रामगढ़ नगर योजना, (७) कोसी योजना (८) जवाड़ योजना (९) बम्बैन घाटी योजना (१०) नागावुड बांध योजना (११) मयूरगिरी योजना (१२) कावेरी योजना (१३) कृष्णा मन्त्रालय योजना (१४) नन्दन योजना (१५) नाथर योजना (१६) नवदा नाली योजना (१७) काकरापारा योजना (१८) मन्त्रकुण्ड योजना (१९) मज्जमता योजना (२०) गंधी नगर बांध योजना।

इनका विस्तृत विवरण आगे अध्याय २० में दिया गया है।



सिंचाई के साधनों का सरकारी वर्गीकरण

(Government Classification of Irrigation Works)

महर्षि देव में मिचार्ट का प्रमुख साधन है। ये राष्ट्रीय सम्पत्ति है। आद्य की ही में महर्षि के साधन निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं—

१ उत्पादक साधन (Productive Works)—ये कहना है जो निम्नलिखित कार्य पूरे होने के पश्चात् हमें वर्ष में भीतर अपनी नयी हुई पूँजी पर ध्यान तथा धन खर्च देने योग्य बन जाते हैं। ये साधन तो हुई पूँजी से बनाये जाते हैं।

२ उत्पादक साधन (Productive Works)—ये हैं निम्नलिखित निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं होना है बल्कि उत्पादक होना है। जैसे किन्हीं साधनों को प्रदान

से बचाने के लिए इस प्रकार के साधन प्रस्तुत किये जाते हैं। चानू भ्राय में से कुछ प्रतिशत बकाय सहायता और बीमा कोष में सहायता के रूप में प्रदान की जाती है जिसका उपयोग इस प्रकार के साधना के निर्माण में किया जाता है।

३. क्षुद्र साधन (Minor Works)— इसमें छोटे-छोटे विविध प्रकार के सभी साधन सम्मिलित होते हैं। ये सरकारी चानू भ्राय में से बनाये जाते हैं।

सन् १९२१ ई० से उपर्युक्त वर्गीकरण बदल गया है। अब ये कोष (Fund) की उपेक्षा रखते हुए केवल उत्पादन और रक्षात्मक साधनों में ही वर्गीकृत होते हैं।

सहरो और रेलों का मापेक्षिक महत्त्व

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और जलवायु भी अनुकूल है। परन्तु जलवृष्टि इतनी अनुकूल नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। भारतीय मापेक्ष समृद्धि जलवृष्टि पर बहुत कुछ निर्भर होने के कारण इसकी प्राथमिक व्यवस्था में हमका बड़ा महत्त्व है। परन्तु भारत में जलवृष्टि अनिश्चित, अनियमित एवं असमान होने के कारण कृषि साधना द्वारा ऐसी ही सिंचाई निताप्त आवश्यक है। सिंचाई से शुष्क प्रदेशों में भी ऐसी सम्भव हो जाती है। इस प्रकार सिंचाई द्वारा कृषि पैदावार में वृद्धि हो जाती है। निर्माण व्यवसाय को भी अपने कच्चे माल के लिए अधिकतर खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होकर देश में व्यापार में वृद्धि होती है।

कृषि की उत्पत्ति के लिए केवल सिंचाई ही आवश्यक नहीं है, बल्कि साप ही साप रेल जैसे सीमा यातायात के साधना के बिना ही भी आवश्यकता है। यदि देश में यातायात के साधनों का अभाव है, तो खेती की बड़ी हुई पैदावार को दूरा स्थान पर पहुँचाना कठिन हो जायगा। खेती के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं के वितरण के लिए उपर्युक्त मण्डियों और बाजारों को बँटना आवश्यक है और यह कार्य यातायात के साधनों द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। रेलें स्वयं खेती पर आश्रित हैं क्योंकि बिना खेती के यातायात की वस्तुभावा पूर्ण अभाव रहेगा और खेती स्वयं सिंचाई पर निर्भर है। मल्टी, नहर और रेलें बनाना दोनों ही समान महत्त्व की वस्तुएँ हैं।

सिंचाई के लाभ (Advantages)

सिंचाई के साधना से हमारे देश को निम्नलिखित लाभ हैं —

१. सिंचाई द्वारा मानसून की अनिश्चितता से सुरक्षित रहा जा सकता है।
२. अकाल से बचने का एक अनुपम साधन है।
३. सिंचाई के कारण भूमि की प्रति एकरूप उपज बढ़ जाती है।
४. सिंचाई द्वारा शुष्क भागों में भी खेती सम्भव हो सकती है।
५. सिंचाई के कारण खेत या बंजर भूमि कृषि योग्य बन सकती है।
६. सिंचाई के कारण भूमि के भीतर का पानी ऊपर आ जाता है जिससे खेती में बड़ी सहायता मिलती है।

७. सिंचाई में वर्ष भर निरन्तर खेती का व्यवसाय चलता रहता है और बड़े प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं।

८. सिंचाई द्वारा सहरी खेती सम्भव होती है जिससे कृषि की उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होती है।

६. सिंचाई द्वारा सावन, शरा जैसी फसलें पैदा हो सकती हैं ।

१०. सिंचाई द्वारा केवल मात्रा में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि निस्म (Quality) में भी सुधार होता है ।

११. सिंचाई द्वारा सरकार की भी आम अच्छी होती है ।

सिंचाई से हानियाँ (Disadvantages)

१. अधिक सिंचाई के कारण भूमि पर क्षार (Alkaline) फैल जाता है और भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है ।

२. नहरों के बनने से कभी-कभी भूमि में पानी की अधिकता (Water logging) होकर कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होने लगती हैं जिससे कारण भूमि बेकार हो जाती है ।

३. नहरों के आन पास की भूमि में बिखरा हुआ पानी इकट्ठा होकर दमदम या कीचड़ का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण बीमारी फैलाने वाले जीव जन्तु व कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं । इस प्रकार ये स्थान मत्तियाँ व अन्य मलमल बीमारियों के जन्म-स्थान होकर मीका मनुष्यों को मौत के घाट उतार देते हैं ।

४. खेतों में पानी देने समय बहुत मात्रा पानी बेकार गट्ट हो जाता है ।

५. नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी मेंता पर सिंचने के बजाय नहरों में जमा हो जाती है, जिससे कारण उसका कोई उपयोग नहीं होता ।

६. नहरों द्वारा सभी खेतों को पानी एक साथ नहीं मिलने के कारण खेती में बड़ी हानि होने की सम्भावना हो सकती है ।

७. कभी-कभी नहरों और नालावा के टूट जाने से जन धन की बड़ी क्षति होती है ।

- योजना और सिंचाई—दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिए ४५८ करोड़ रुपये खर्चा किया गया है जबकि प्रथम योजना में इस मद पर ३६५ करोड़ रुपये व्यय किया गया । पहली योजना की अवधि में यही और मध्यम प्रकार की योजनाओं में ७० लाख एक्ड़ की सिंचाई होने लगेगी । दूसरी योजना में यह क्षेत्र बढ़ कर १ करोड़ २० लाख एक्ड़ हो जाने की आशा है । सिंचाई की १८८ मई योजनाओं में १३६ पर १ करोड़ रुपये में कम व्यय होगा, ३४ पर १ करोड़ व ५ करोड़ तक व्यय होगा, ८ पर ५ करोड़ में १० करोड़ रुपये तक व्यय होगा, ६ पर १० करोड़ में ३० करोड़ रुपये तक व्यय होगा और केवल एक पर ३० करोड़ रुपये में अधिक व्यय होगा ।

बाढ़ नियन्त्रण—'केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण मण्डल' के प्रतिष्ठित १२ राज्यों में भी बाढ़ नियन्त्रण मण्डल है जिसको अनाहकार, ममितायाँ प्राविधिक समस्या में सहजता देनी है । 'केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग' में एक बाढ़ विभाग और सम्मिलित कर दिया गया है । विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में भी ५०६ योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० लाख रुपये में कम व्यय विये जाने का अनुमान लगाया गया है ।

१२ ४५ करोड़ ६० का अनुमानित सागन की २४६ अन्य योजनाएँ विचाराधीन हैं। उत्तर प्रदेश के बाढ़प्राही क्षेत्रों में ४,२०० से अधिक गाँवों की सतह ऊँची कर दी है और बाढ़ नियंत्रण कार्य वृत्त आरम्भ होने के समय से अब तक कई राज्यों में कुल मिलाकर २,४४३ मील लम्बे तट बचाव का निर्माण किया जा चुका है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—उत्तर प्रदेश में सिचार्ड मुविषा के विकास की सल्लस व्याख्या कीजिए।

(उ० प्र० १९५५)

२—भारतवर्ष के विभिन्न भागों में सिचार्ड के क्या-क्या साधन काम में लाये जाते हैं।

राजस्थान में सिचार्ड की मुविषाओं के प्रसार के तरीकों के लिए सुझाव दीजिए।

(रा० प्र० १९५२)

३—भारत के विभिन्न भागों में सिचार्ड की कौन-कौन सी मुविषाएँ हैं ? उत्पादक और

अनुत्पादक सिचार्ड के साधनों में भेद दर्शाइए। सिचार्ड के लाभ हानि भी बताइए।

(अ० वी० १९५६, ५२, ४४, ४१, उ० प्र० १९४२)

(उ० प्र० १९५३)

४—भारत में सिचार्ड का क्या महत्व है ? यहाँ क सिचार्ड के विभिन्न साधनों का

विवरण दीजिए।

(उ० प्र० १९५५, ५७, ४५ पृष्ठ १९५२,

अ० वी० १९५४, ५२, सागर १९५२, ४९, पत्र १९५१)

५—भारतवर्ष में सिचार्ड के साधनों के लाभों का वर्णन कीजिए और प्रायः इनके प्रसार

की सुझाव बताइये।

(वनारम १९४९)

६—स्पष्टीकरण लिखिए।

दामोदर घाटी योजना।

(उ० प्र० १९५३)

राजस्थान नहर।

(रा० वी० १९६०)

क्षेत्र-विभाजन एवं अपखण्डन

(Sub-Division & Fragmentation of Holdings)

पोपणक्षम क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Economic Holding)—
पोपणक्षम क्षेत्र से उस खेत का अर्थ है जो न तो इतना बड़ा हो कि कृषक द्वारा वह न गहमे और इतना छोटा भी न हो कि उसके परिवार के लिए उस पर खेती करना लाभदायक सिद्ध न हो। कीटिंग्स (Keatings) महाशय इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं, "वह क्षेत्र जो किसी कुटुम्ब को वर्ष-वर्षान्त धन्य में ध्यस्त रखे और उनमें उसका जीवितोपाजन हो।"

ऊपर की परिभाषा उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि पोपणक्षम क्षेत्र का अनुमान एकाड़ों में ठीक प्रकार चढ़ी लगाया जा सकता है। एक कम उपजाऊ ५० एकड़ भूमि का टुकड़ा सारे कुटुम्ब को कार्य व्यस्त रख सकता है, तो उसी कुटुम्ब के लिए १० में १५ एकड़ भूमि का उपजाऊ टुकड़ा पर्याप्त हो सकता है। अतः, पोपणक्षम क्षेत्र का मापन एकाड़ों में ठीक प्रकार नहीं हो सकता है।

भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में खेतों के प्रकार निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	औसत खेती का क्षेत्रफल	राज्य	औसत खेती का क्षेत्रफल
महाराष्ट्र	१०२	मद्रास	४६
पंजाब	६२	बिहार और उड़ीसा	३१
म० प्र० और वरार	८५	गुजरात	३०
बंगाल	५१	उत्तर प्रदेश	२५

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में कम से कम २½ या ३ एकड़ भूमि पर खेती होती है जो कृषक के कुटुम्ब के निर्वाह के लिए बिल्कुल अपूर्ण है। ऐसी अवस्था में जो रहन-सहन का स्तर भारतीय किसान रख सकता है, उसकी भली-भाँति कल्पना की जा सकती है।

क्षेत्रों की विशेषताएँ— भारत में खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में ही विभाजित नहीं होते, बल्कि वे यत्र-तत्र (Scattered) भी स्थित होते हैं। छोटे टुकड़ों पर खेती करना वैसे ही लाभहीन व्यवसाय है, परन्तु जब वे झुपड़-तुपड़ एक दूसरे में दूर स्थित हों, तो और भी कार्यक्षमता में ग्लानता या जाना स्वाभाविक है। प्रत्येक खेत के टुकड़े पर जो यत्र-तत्र स्थित है खेती करने के लिए पहुँचने में समय और शक्ति का दुरुपयोग होता

है तथा भारतीय दूधन वस्त्रों को निरक्षर मध्य-उत्तर जाने में बाधित हो जाता है। हमारे अतिरिक्त विमानों को खरीदने वाली सभी वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को न जाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सब सगो की एक साथ देव रेखा भाग्य हो जाती है। प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग चारा और आठ नवाने का ध्येय भी बढ़ जाता है।

जन विभाजन एवं अपसंख्यन के कारण (Causes)

मैना के छोटे घोर दूर दूर होने व मुख्य कारण निम्नलिखित हैं —

१ **उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance)**—इसके अनुसार उत्तराधिकार नियम के अनुसार सार ज्येष्ठ पुत्र ही पिता को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है अन्य भगम्पत्ति का विभाजन नहीं होता। परन्तु भारतीय म इसके विपरीत नियम प्रचलित है। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी सम्पत्ति का उसके सब पुत्रों में समान विभाजन हो जाता है। अतः इस प्रकार विभाजन और उपविभाजन होता रहता है।



मृत का विभाजन

२ **भूमि पर जन सघनता का भार (Pressure of Population)**—भारत में बड़ी जन-संख्या के कारण और सहायक यथा क अभाव में अधिकांश जन संख्या को पितृ होकर मैना में ही जीवन निवास करना पड़ता है। अतः इससे भूमि विभाजन की प्रतीति मिलती है।

३ **कुटीर व्यवसायों का लोप (Disappearance of Cottage Industries)**—औद्योगिक क्रांति ने मशीन द्वारा बनी हुई वस्तुएँ उत्पन्न कर पुरेसे यथा की लागत कम कर दिया है। अतः सबसे निम्न मूल्य की एकमात्र सामान रह जाता है।

४ **हिंदू संयुक्त परिवार प्रथा की समाप्ति और व्यक्तिवाद का विकास (Break up of Joint Hindu Family System & the Rise of Individualistic Spirit)**—हिंदू संयुक्त परिवार प्रथा में लोग एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। परन्तु व्यक्तिवाद के आनुवंशिक के साथ-साथ जन विभाजन तथा अपसंख्यन प्रारम्भ होता है क्योंकि कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति स्वतंत्र म न अपना भाग अलग ले सकता है।

जन अपसंख्यन के लाभ (Advantages)

१ **कृषक स्वामित्व (Peasant Proprietorship)**—मैना के दुर्गम छोटे ही क्यों न हो परन्तु कृषक उस दुर्गम का स्वामी हो रहता है। इस प्रकार जन

विभाजन से भू सम्पत्ति का विवरण ठीक होकर एक मूस्वामि या ना वग स्थापित हो जाता है ।

२ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता (Social & Economic Stability)—इस प्रकार का स्वामित्व रखने वाला कृषक बस देण में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता रखने में सहायक होता है इस कारण में अधिकांश जाति का विश्वास है ।

३ वर्ष-पर्यन्त घड़ा (Employment all the year round)—जब किसी कृषक के पास भूमि के कई टुकड़े हों और वे अलग अलग प्रकार के हों तो उनके लिए वर्ष भर बेरोज़गारी का कुछ-न-कुछ काम बचता ही रहता है ।

४ मानसून की अनिश्चितता से रक्षा (Insurance against vagaries of Monsoon)—जब सन कई टुकड़ा में विभाजित हो और वे अलग अलग भूमि-क्षेत्र (Soil Areas) में स्थित हों तो एक वर्ष पर फसल नष्ट होने पर दूसरे वर्ष की पैदावार से उसको पूरि हो सकती है ।

क्षेत्र अपखण्डन से होनेवाला अर्थान् इसका दुप्रभाव

(Disadvantages or Trial Effects of Fragmentation)

१ भूमि का नष्ट होना (Wastage of Land)—भूमि के विभाजन के कारण उप-विभाजन से भूमि का बहुत साग भाग प्रायः नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रत्येक खेत या सीमा स्थिर करने में कुछ भू-भाग छोड़ना आवश्यक हो जाता है । इसके परिणित एक यह क्षेत्र पर खेती नलायत की जा सकती है परन्तु उन्ही खेत के छोट छोट टुकड़ा पर वह सम्भव नहीं ।

२ जमीन की उन्नति रुक जाती है (Unprogressive Agriculture)—छोट छोट खेतों में तो कोई मशीन प्रयुक्त की जा सकती है और न आधुनिक वैज्ञानिक सुपाक का ही प्रयोग हो सकता है । अन्तु ऐसी अवस्था में खेत एक उन्नत देश में नहीं रह सकता ।

३ सिंचाई में कठिनाई (Difficulties of Irrigation)—छोट छोटे खेतों में अलग अलग कुएँ नहा बनाए जा सकने बजाकि प्रथम तो सन का क्षयफल घटता होता है और द्वितीय लागत भी अधिक बैठती है । अन्ततः स्थित खेतों में पानी पहुँचाना उठना ही कठिन है बजाकि दोब में दूसरा के सेन घा जात है । सब बहुत सार इस प्रकार में विभाजित सन बिना विचार के ही रह जात है ।

४ खेतों की सीमा सम्बन्धी झगड़े (Boundary Dispute)—सबसे कम नामा सम्बन्धी सब से झगड़े प्रायः खेतों में घटते हैं । इस प्रकार के मुद्दामयानी में सन का बड़ा दुष्प्रयोग होता है । यह सन बेतरी के उन्नति करने में बाधानी से लगाया जा सकता है ।



खेतों की सीमा सम्बन्धी झगड़ा

५. श्रम व पूँजी का दुष्प्रयोग (Waste of Labour & Capital) जब एक मैन से दूसरे मैन को स्वयं कृषक या धर्मिक जाने है उसी मैन के उपयोग व दैन्य प्रादि को ले जाने है, ता समय और शक्ति का बड़ा हानि होना है।

६. मार्केटिंग कठिनाइयाँ (Marketing Difficulties) — छोटे सेतो की पैदावार बहुत कम होने के कारण उसका मही तक ले जाना बड़ा मुश्किल पड़ता है।

७. पैदावार में न्यूनता (Low Yield) — जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि छोटे आँठ और दूर-दूर स्थित सेतो में आनुवंशिक सावधानियों में लाभ नहीं उठाना जा सकता तथा खाद, मिर्चाई आदि की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पैदावार प्रति एकड़ कम होना स्वाभाविक है।

८. माहम नष्ट करना है (Destroys Enterprise) — यदि किसान एक अव्यवस्थित सेतो में कोई प्रयोग नहीं करना के कारण माहम का प्रभाव देना गया है। यही कारण है कि छोटे सेतो की उत्पत्ति में एक ग्रावट भी आ गई है।

उपाय (Remedies)

(१) ज्येष्ठता के नियम में संशोधन (Amendment in the Laws of Inheritance) — इस प्रकृति का रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हमारे प्रचलित उत्तराधिकार के नियमों में संशोधन कर उत्पत्ति की शक्ति ज्येष्ठता का नियम लागू करने में क्षैत्र अव्यवस्थित रोका जा सकता है।

(२) संश्लेषण (Consolidation of Holdings) — बिचरे दूर सेतो का एकिकरण अव्यवस्थित द्वारा सुगमता में हो सकता है।

बिचरे हुए समान भूख पान सेतो की आरम्भिक समझौते में मिश्र कर एक सेत बनने की क्रिया को संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कई अलग छोटे-छोटे सेतो के बदले में एक बड़ा सेत प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। संश्लेषण का कार्य जो महबारी समितियों द्वारा पत्राव उत्तर प्रदान आदि गति में हुआ है वह वास्तव में प्रगतिशील है।



संश्लेषण

(३) सहकारी कृषि (Cooperative Farming) — सहकारी सेतो में भी यह समस्या हो सकती है। बिना में सेती करने के उद्देश्य में कई तक सेत मिश्रित किए जाते हैं। जो सेती करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें सेती का कार्य भी दिया जाता है। पैदावार में से उनसे मिलने वाली कट कर यह अनुमानों का उनकी भूमि के अनुपात में बाँट दी जाती है। इस प्रकार की कई सहकारी समितियाँ पूर्वी पत्राव और उत्तर प्रदेश में संस्थापित द्वारा चलाई जा रही हैं। इनके प्रतिष्ठित मद्रास, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि, बिहार, ओरिस्सा आदि राज्यों में चलाने की चलाने जा रही है।

(४) राज्य द्वारा पोषणक्षम क्षेत्र स्थिर होना (Economic Holdings fixed by the Govt.) — सरकार द्वारा पोषणक्षम सेत का क्षेत्रफल स्थिर हो जाना चाहिए और उसके बाद उपरिमान व अव्यवस्थित निवेशों द्वारा बदल दिया जाय।

(५) जिला अधिकारियों को अधिकार (Powers for District Authorities)—यदि पोपणक्षम क्षेत्र की स्थिरता समान रूप में करना संभव नहीं हो, तो जिला अधिकारियों को वह अधिकार दे दिए जायें कि वे श्रमुक्त अधिकार से नीचे जाने भू-विभाजन को मान्यता न दें और न उसकी रजिस्ट्री करें ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

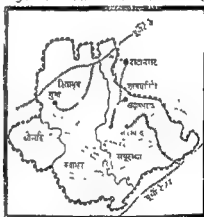
इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—कृषि क्षेत्र विभाजन एवं अपसृष्टन से क्या समझते हैं ? इसमें होने वाली हानियों को प्रकट कीजिए और उपाय बताइए । (उ० प्र० १९४१)
- २—भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र के अपसृष्टन के कारण और नष्ट होने वाले उपाय बताइए । (नागपुर १९४१, दिल्ली १९४०, कलकत्ता १९४३)
- ३—भारत में खेतों के उपविभाजन और अपसृष्टन के कारणों और परिणामों की समीक्षा कीजिये । (पंजाब १९४२, ४६, दिल्ली १९४४)
- ४—चक्रवर्ती और सहकारी कृषि में क्या तत्पर्य है ? उसके द्वारा भारत में खेतों के उपविभाजन और अपसृष्टन की समस्या कैसे हल की जा सकती है ?
- ५—पोपणक्षम क्षेत्र शब्द की व्याख्या कीजिए और इसका भाग्यीय कृषि में क्या महत्त्व है, समझाइय ।
- ६—टिप्पणी लिखिए : -
भारत में कृषि खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना । (प्र० को० १९६०)

भारत की खनिज सम्पत्ति (Mineral Wealth of India)

भारतवर्ष खनिज सम्पत्ति में न तो अधिक धनी है और न अधिक निर्धन। इस देश में समस्त खनिज पदार्थों का वार्षिक औसत उत्पादन लगभग ४० करोड़ रुपये का है। जैसे कि लोगों की धारणा है कि भारतवर्ष में समीप खनिज सम्पत्ति है, यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि खनिज उद्योग यहाँ अभी वंशव अवस्था में ही है। अतः हम यहाँ भारत की खनिज सम्पत्ति का यथार्थ चित्रण करेंगे। भारतवर्ष में निम्नलिखित मुख्य खनिज पदार्थ मिलते हैं।

लोहा (Iron & Ores)—समुक्त राज्य अमेरिका और जापान के पश्चात् भारत में सारा का सबसे अधिक लोहे का सचय है। भारतवर्ष में लोहे का अधिक सचय बिहार और उड़ीसा में है अर्थात् सिंहभूम का जिला, मयूरभञ्ज, बोकारो और बघोभर की रियासतें लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और महाराष्ट्र में भी लोहा अच्छी विराम का निश्चयता है, परन्तु उनके समीप कोयला और चूना न मिलने से अभी उनका अधिक विकास नहीं हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष में ३ अरब टन लोहा विद्यमान है। वर्तमान में भारतीय लोहे का उपयोग करने वाले मुख्य कारखाने ये हैं। Tata Iron and Steel Co Ltd., Jamshedpur, Bengal Iron Co. Ltd., Kulti और Indam Iron and Steel Co Ltd Asansol.



लोहा खनिज-क्षेत्र

सम्पूर्ण भारत के लोहे का वार्षिक उत्पादन ३० लाख टन है। यह हमारे सीमावर्ष की बात है कि बिहार में लोहे और कोयले की खानें एक दूसरे के समीप मिलती हैं। अतः उत्पत्ति की लागत में काफी कमी हो जाती है। सारी लोहे की खानें भारतवर्ष में ही स्थित हैं, पाकिस्तान में कोई लोहे की खान नहीं है। भारत में जनवरी १९६० में ८,१६,००० मीट्रिक टन खनिज लोहा निर्यात गया। सबसे अधिक लोहा उड़ीसा में

निष्काया गया। यहाँ ३ २३ ००० मीट्रिक टन साहो निकला। इसके बाद बिहार का नम्बर आता है जहाँ २ ३४ ००० मीट्रिक टन निष्काया गया मसूर में १ १० ००० मी० टन मध्य प्रदेश में ६० ००० मी० टन और महाराष्ट्र राज्य में २१ ००० मी० टन रोहो निकाला गया।

कोयला (Coal)—यह आधारभूत खनिज पदार्थ है जिस पर भारतीय प्रयोगीकरण निर्भर है। भारतवर्ष में कोयले की स्थिति सन्तोषजनक है। सस्तर में कायला उपलब्ध करने वाले देशों में इसका सातवाँ स्थान है। यहाँ कायल का उपयोग जलाने मात्र के लिए और रेल चलाने के लिए होता है। भारतीय कायल की विश्व अधिक में उल्लेख है। माया का दृष्टि में भी यह सीमित है। कोयले के उपयोग की वनमान गति में सम्पूर्ण मध्य हो मो वष में अधिक नहीं रह सकेगा। हमारे यहाँ पट्टी को यहाँ कमी है अतः कमि पट्टी कोयल हाग बनाया जा सकता है। जब कोयल द्वारा पेट्रोल वनत संगेता तो सम्पूर्ण मध्य इयने भी कम मध्य में गपात हो जायगा। परन्तु हम अपने कायले के उपयोग में पूर्ण विनियमिता करने की चाहित।

भारतवर्ष में कोयल का वितरण असमान है। कोयल का खान मुख्यतः बंगाल बिहार और उडुसा में स्थित है—खानों के प्रतिशत वनत रानोमन और अश्रित है। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश आसाम और हैदराबाद में भी कोयल की खान है। राजस्थान में विनोपनया सीरनेश में भी थोड़ा कोयला मिलता है। मद्रास और पूर्वी बंगाल में को ला विनोपन नहीं है। भारतवर्ष में सम्पूर्ण कोयल के सचय का अनुमान ८ अरब टन गगाया गया है और वाषिक विकास का ३ करोड़ टन।

जनवरी १८६० में गग म गग माना स कुल ४३ ८ ८४६ टन कायला निकाला गया। राष्ट्रीय कोयला विभाग निमन की गई खानों के वनत के प्रपन्ता में यह आशा वपना है कि सन् १९६१ में प्रारम्भ में उल्लेख हो कोयला निकालन मयोगा निमन का दूसरी योजना में लय रवा गया है।

पेट्रोल (Petroleum)—भारतवर्ष में पेट्रोल वनत ही वन निकलता है। अर्थात् के वनत हागे और देश व विमानत स भारत में पेट्रोल की निमन और भी नावनीय हो गी। वेष आसाम में कुछ वनत मिलता है जिनमें भारत की केवल ४ प्रतिशत आवपनता की पूर्ण होती है। आसाम में पेट्रोल के मुख्य क्षेत्र जिमबाई कप्याग और हमाग है। भारत म मय को आविरकार कोष में मने गुण निमन (Synthetic) पेट्रोल पर ही निर्भर रहना पडता। इमनी कमी की पूर्ण के लिए चीनी व बांग्लाता में वन गीने में पाजर अमकोहल वनत की प्रो साहल दिया जा रहा है।

मैंगनीज (Manganese)—यह भूरे रंग की एक पातु है। यह बहुत बड़ी होती है और बड़ी वनितार्थ व निवतनी है। मैंगनीज का प्रयोग सारे और कोलाद की कडा बनान में होता है। निर्वन पाउडर और कुण्ड में डारने का लाल रवा (L'ossure Permanganate) बनाने तथा जिन्की और बान के कारखाना में भी इमना प्रयोग होता है। इमने प्रयोग से बाँच का पोलापन दूर हो जाता है।

रम के परबल भारत ही सस्तर में सबसे अधिक मैंगनीज उपलब्ध करता है। भारत में मैंगनीज मुख्यतः मध्यप्रदेश बम्बई मसूर मद्रास बिहार और उडीसा में निकाला जाता है। पाकिस्तान में मैंगनीज का सचय विनोपन नहीं है। भारतम साह

के कारखानों में मैंगनीज की उत्पत्ति निरन्तर बढ़ रही है, परन्तु फिर भी मैंगनीज विदेशों को भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में बच जाता है। हमारे देश का मैंगनीज मुख्यतः ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम और जर्मनी की निर्यात किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इस व्यवसाय को बड़ी महत्त्वता मिल रही है। सन् १९५४ में मैंगनीज का उत्पादन १,८१ लाख टन था जिसे बढ़ाकर दूसरी योजना में सन् २० लाख टन उत्पादन करने का संकल्प है। इस समय इस उद्योग में ८५ हजार व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

अभ्रक (Mica)—अभ्रक का प्रयोग रिजिनी के कपड़ों और रॉपों के सामान में होता है। वनार के तार, समुद्री विमान और माटर व्यवसाय में अभ्रक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब, इनकी माँग निरन्तर बढ़ रही है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक विमानता है, प्रयोग सवार के संचय का तीन-चौथाई भाग यहीं मिलता है। भारत में अभ्रक मुख्यतया बिहार, मद्रास, राजस्थान और अजमेर में मिलता है। केवल बिहार में भारत का ८० प्रतिशत अभ्रक निर्यात है। भारत में इसकी सीढ़ी उत्पादन लगभग ४ लाख ६० हजार हेक्टर है और यहाँ विदेशों के व्यवसाय का अभाव होने में अधिकतम मात्रा निर्यात की जाती है। अरबों रिहाय में इस उद्योग में लगभग ६० हजार व्यक्ति मग्न हैं।

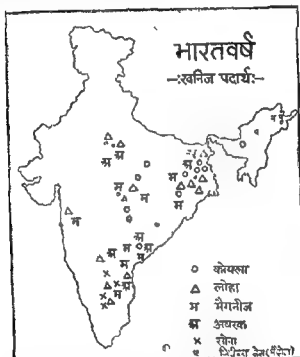
गोला (Gold)—गोला एक बहुमूल्य धातु है जिसका प्रयोग अधिकतर आभूषण और सिक्के धनाने में होता है। भारत में सवार का कुल २०% गोला मिलता है। भारत का लगभग ६६ प्रतिशत गोला असम की दार्जिलिंग जिला में प्राप्त होता है। बांग्लादेश में असम के दार्जिलिंग और हैदराबाद में हैदराबाद की खानों में भी प्राप्त होता है। यह नदियों की किनारे में भी मिलता जाता है। भारत में गोला का वार्षिक उत्पादन लगभग १,३०,००० किलो है। यह मात्रा भारत की आवश्यकता में कम है, अब हम बाहर से आभूषण करना पड़ता है। सन् १९५१ में भारत में २०६,००० किलो गोला निर्यात गया।

चादी (Silver)—यह मैंगनीज का कोयला खानों में बहुत थोड़ी मात्रा में बचाई जाती है। प्रति वर्ष चादी एक बड़ी मात्रा में विदेशों में आयात की जाती है।

ताँबा (Copper)—निर्यात व तार, समुद्री तार और रिजिनी के अन्य पदार्थों में ताँबा बहुत प्रयुक्त होता है। इसमें जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है, दिन मिलाव में चाँदी और निचले मिलाव में जर्मेन-मिलवर्ग बनता है। ताँबा शुद्ध रूप में बहुत कम मिलता है। सवार में ताँबा विकास के दो देशों में भारत का आठवाँ स्थान है। भारत में ताँबा बिहार, मद्रास, अजमेर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में निकाला जाता है। अभी तक हमारे देश में इसका प्रयोग पीतल व जर्मेन बनाने में ही होता है। अब आशा की जाती है कि रिजिनी के व्यवसाय की उन्नति के साथ इस व्यवसाय को भी उन्नति होगी। भारतीय स्थान कार्यालय द्वारा प्रकाशित किये गये आकड़ा में अनुसार जनवरी १९६० में २०,५८८ मीट्रिक टन लौह का उत्पादन हुआ। सारा लौह राजस्थान बिहार राज्य व मिहसूम जिले में पाया जाता है।

सीसा (Lead)—आमतौर पर सीसे की कुछ खानें बिहार मद्रास, राजस्थान, अजमेर और हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, परन्तु उनका उत्पादन बहुत ही कम है। जनवरी १९६० में १३,८१८ मीट्रिक टन सीसा और जस्ता निर्यात किया।

शोरा (Salt peter)—शोरा बहुत उपयोगी वस्तु है। इसका मुख्य प्रयोग खाद बनाने में होता है। इसमें वास्तु, शोरे का तेजाब, काँच आदि भी बनाये जाते हैं। शोरा अधिकतर बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। लगभग सारा शोरा विदेशों को भेज दिया जाता है।



भारतवर्ष की खनिज सम्पत्ति

नमक (Salt)—भारत में नमक समुद्रों, कुँधों और झीलों के तटों पर पानी से बनाया जाता है। नमक चट्टानों में भी प्राप्त होता है। भारत में नमक महारष्ट्र व भद्राक्ष में समुद्र के पानी को सुखा कर और राजस्थान में मीठर झील के तटों पर पानी को सुखा कर बनाया जाता है। चट्टानों (गंधा) नमक पाकिस्तान में बनाया जाता है। सरकारी अनुमान के अनुसार १९५७ में नमक का उत्पादन ६६३ लाख मन् हुआ जो १९५६ में ८८६ लाख मन् तथा १९५५ में ८११ लाख मन् था।

कुछ प्रमुख केन्द्रों में अनुमानित उत्पादन (लाख मन् में) हम प्रस्तुत होगा :—
राजस्थान २०५, मम्बई २६४०६, गोवा २३०५४, बम्बई ६३७१, भद्राक्ष १५००६ तथा भाद्र ५६०५।

सम्भवतः इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ ।

इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में गेनखरी (Gypsum), चूना (Lime Stone), बाक्साइट (Bauxite), क्रोमाइट (Chromite), मोनाजाइट (Monazite), मैग्नेसाइट (Magnetite), इलमेनाइट (Ilmenite), वूल्फ्रम (Wolfram), टिन (Tin) और सीमेन्ट व्यवसाय की सामग्री आदि खानज पदार्थ मिलते हैं ।

खनिज पदार्थों के संचय की आवश्यकता

(Necessity of Conserving the Mineral Wealth)

किसी देश के आर्थिक उत्थान में खनिज पदार्थों का बड़ा महत्त्व है । यह सौभाग्य की बात है कि देश के विभाजन से हमारे खनिज पदार्थों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा जो कुछ भी खनिज पदार्थ हमारे देश में विद्यमान हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए । सेत में एक वर्ष फसल नष्ट हो जाने पर निराशा होने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे वर्ष अच्छी पैदावार हो सकती है । परन्तु खनिज पदार्थ एक बार निक्कल जाने पर वे भूमि में से पुनः प्राप्त नहीं किये जा सकते । इसलिये खनिज पदार्थों के संचय की रक्षा निम्नान्त आवश्यक है । यही नहीं बल्कि उनका विकास तथा सदुपयोग हमसे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि देश को आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति इन्हीं के सदुपयोग पर आश्रित है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इन्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—भारत की खनिज सम्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । इनका भारत की भावी आर्थिक उन्नति के लिए क्या महत्त्व है ?

(प्र० बो० १९५७, ५४, ५०, उ० प्र० १९५६)

२—भारत की खनिज सम्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (उ० प्र० १९५०, ४७)

३—"भारत में प्रकृति के साधन प्रचुर मात्रा में हैं, आवश्यकता इस बात की है कि इनका उचित उपयोग व विकास किया जाय तथा इनको सुरक्षित रखा जाय ।" इस कथन को जंगल और खानों के सम्बन्ध में समझाइए ।

(प्र० बो० १९५१, उ० प्र० १९४०)

४—भारत के औद्योगीकरण के लिए देश की खनिज सम्पत्ति कहाँ तक पर्याप्त है ?

(वनारम १९३१)

५—भारत की खनिज सम्पत्ति का उल्लेख राजस्थान में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों के विषये विवरण सहित कीजिए ।

(रा० बो० १९६०)

भारतवर्ष में शक्ति के साधन (Power Resources in India)

औद्योगिक उन्नति के लिए शक्ति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि कृषि की उन्नति के लिए मिचार्ड। अस्तु, शक्ति ही औद्योगिक उन्नति का आधारभूत है। 'शक्ति' एक व्यापक शब्द है परन्तु यहाँ पर 'प्रेरक शक्ति' (Motive Power) से ही इसका तात्पर्य है। वस्तुओं को चलाने वाली या क्रियाशील रखने वाली शक्ति को प्रेरक-शक्ति कहते हैं। यह प्रेरक शक्ति मनुष्यों, पशुओं, हवा आदि से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु आधुनिक उन्नत देशों में यह कोयले, तेल व बिजली से प्राप्त की जाती है। जन-विद्युत को छोड़ कर अन्य साधनों में कोयला एक सबसे सस्ता शक्ति का साधन है। अब हमें यह देखना है कि भारतवर्ष में कौन-कौन से शक्ति के साधन विद्यमान हैं और उनका उपयोग कहाँ तक सम्भव है।

भारतवर्ष में शक्ति के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं :—

(१) मनुष्य, (२) पशु, (३) वायु, (४) ईंधन, (५) कोयला, (६) तेल और, (७) जल।

(१) मनुष्य (Man)—मानव शक्ति धनोत्पत्ति का एक आवश्यक साधन है, क्योंकि बिना मनुष्य की सहायता के धनोत्पत्ति का कोई कार्य सम्भव नहीं। परन्तु आधुनिक समय में मनुष्य का अधिकार कार्य प्रशान ने ले लिया है, इसीलिए इसको 'मशीन युग' कहते हैं। फिर भी मनुष्य का महत्व कम नहीं है। भारतवर्ष की विधात मानव शक्ति में यदि कोई न्यूनता है तो उसकी कार्य प्रशमता। अस्तु, भारतीय मानव शक्ति को यदि अधिक कार्य-कुशल बनाना अभीष्ट है तो विध्वनता को दूर कर भारतीयों के जीवन-स्तर को उच्च करना चाहिए, इसी में देश का हित एवं कल्याण निहित है।

(२) पशु (Animal)—मानव शक्ति के पश्चात् पशु-शक्ति का महत्व है। भारत में पशु-शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। यहाँ की खेती तो बिल्कुल इसी पर आश्रित है। बैल, भैंसे, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊँट आदि पशु खेती में सहायक होने के अतिरिक्त बोझा ढोने, सवारियाँ ले जाने के कार्य को भी सम्पन्न करते हैं। चारे की कमी, पशु चिकित्सा का अभाव और नस्ल बिगड़ जाने से इस देश के पशुओं की निपुणता में ह्रास हो जाना स्वाभाविक है। अस्तु, हमें पशुओं की केवल सख्या में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उनकी निपुणता एवं कार्यक्षमता को भी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(३) वायु (Wind)—वायु भी शक्ति का एक प्रबल साधन है। पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ वायु का वेग रुकने नहीं पाता, वहाँ घाटा पीछने और पानी उठाने के लिए पवन चक्कियों का उपयोग होता है। मैदानों में वायु द्वारा प्रायः अनाज में सूना

अन्य किया जाता है। हानर म वायु के निरंतर एक हा दिना म चने रहने को सुविधा न वही वायु गति को उपयुक्तता को अगति बना दिया है। परन्तु भारत में व्यापारिक प्रयोजना व लिय वायुगति का अधिक प्रयोग नहीं होता है।

(४) ईंधन (Wood fuel) — लकड़ी जला कर भी गति पैदा की जा सकती है। लकड़ी जलाकर भाप उत्पन्न करने में क्षति का अधिक हान्य होता है। भारत में एक घोर कठिनाई है। यहाँ अधिकांश वन पहाड़ों पर स्थित हैं यद्यपि मातामान की सुविधा बिना लकड़ा प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ लकड़ा का प्रयास करके बहुत कामों में ईंधन के प्रयोजन तक ही सीमित है। कुछ समय पहिने जब पत्तों की कमी हो गई थी तो मोटर गाड़ियाँ घोर घसा में लकड़ा का बोझ जलाकर प्रत्येक गति का मंचार दिया गया था। घट्टा भा मयूर व लोह व कारखाना जीवन व अभाव में लकड़ी जलाकर प्रत्येक क्षति उत्पन्न की जाती है।

(५) वायुता (Coal) — वायुता अब भी भाप और बिजली उत्पन्न करने का एक बहुमूल्य साधन है परन्तु भारत में वायुता का बहुत सीमा है। (अ) देश के विस्तार को देखते हुए यहाँ वायुता की मात्रा बहुत कम है। यहाँ मात्रा में २ करोड़ २० लाख टन वायुता विद्यमान है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ४५ करोड़ ६ लाख टन विद्यमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में कुल वायुता का संचय (Deposit) ४ करोड़ १६ करोड़ टन है। (ब) भारत का वायुता घटिया होता है। इसका कारण कम रहता है परन्तु राज्य सरकारों और जन अंग अधिक रहता है। (ग) यहाँ पर कोयले का वितरण एकमात्र नहीं है। देश का ६० प्रतिशत कोयला बिहार के गाड़वाला क्षेत्र में स्थित है यहाँ से बम्बई मद्रास और पंजाब आदि स्थानों को वायुता का जाल मध्यस्थ अतिरिक्त लगा है। परन्तु यहाँ के कोयले का उपयोग कम व्यय में और सुविधा व गाड़ केवल अभाव और बिहार के उपयोग द्वारा ही हो सकता है। (द) जिन स्थानों में वायुता की कमी है यहाँ आबादी बहुत कम है जब छोट्टा नागपुर का पठार। यहाँ वायुता के निम्न मजदूर नहीं मिलते अधिकांश मजदूर दूर से आते हैं इससे मजदूरों में गहरी कटौती है।

वायुता का जीवन बहुत थोड़ा है अतः इसका सदुपयोग करना चाहिए। भारत में अधिकांश कोयला को लोहे व कारखानों व निम्न सुरक्षित रखना चाहिये क्योंकि वह बहुत कम है। उसको रेत व इस्पात में भाग बनाने में प्रयोग नहीं करना चाहिये। पश्चिम कोयला हमारे देश में बहुत है। अभाव हान ही में मद्रास के दक्षिणी अर्ध और कूड़ागीर जिना से विन्हाइट कोयला पाया गया है। इस कोयले से बिजली और इतने तैयार जा सकता है। वायुता के सदुपयोग का अर्थ यह है कि खान खोदने के वर्तमान दशा में सुधार किया जाय और इनके द्वारा उत्पादित गति का कोई भी अंग व्यर्थ न जावे।

(६) तेल (Oil) — पट्टन का अधिकतर प्रयास मोटर-कार कम और हवाई जहाजों के चलाने में किया जाता है। परन्तु भारत में अधिक पट्टन उत्पन्न नहीं होता है। भारत में पट्टन केवल अस्पात में डिग्वार्ड व पास मिलता है जो सवार के उत्पादन व १ प्रतिशत का बचाव होता है। अब भारत का पट्टन एक बड़ी मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका इरान ईराक ब्रह्मा आदि देशों से मगाना पड़ता है। निस्संदेह भारत में तेल की समस्या अति निम्नताजनक है। अतः कालान्तर स्थिति में तेल भारत का एक महत्वपूर्ण गति का साधन नहीं हो सकता।

भारत में कृत्रिम तेल (Synthetic Oil) प्राप्ति में बनाया जा सकता है। (ख) यद्यपि पटिया कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसका उपयोग तेल बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार का तेल ब्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में अधिक तैयार किया जाता है। (ग) भारत में चीनी के कारखानों में जो चीरा नष्ट होता है उसमें २ करोड़ टन मद्यसार (Alcohol) बनाई जा सकती है। इसको पेट्रोल के साथ किसी अनुपात में मिला कर बड़े प्रकार की इंजनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जर्मनी, फ्रांस, चीन आदि देशों में चुन्दर की जड़ों का प्रयोग मद्यसार बनाने के लिये किया जाता है। (घ) यह बात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान द्वारा सिद्ध कर दी गई है कि लकड़ी के धुरादे तथा व्यर्थ नष्ट होने वाले पत्तों और फटा में भी तेल बनाया जा सकता है।

(७) जल (Water) — जल शक्ति का एक बड़ा सामर्थ्यशाली साधन है जिससे विद्युत् प्रदीप की जा सकती है। इसे जल-विद्युत् (Hydroelectricity) या श्वेत कोयला (White Coal) कहते हैं। सबसे बड़ी मुविधा इसमें यह है कि यह बहुत दूर तक सुगमता से भेजा जा सकता है और इसका प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। भारत में जल शक्ति कोयले और तेल का पूर्ण भण्डार है, जल-शक्ति ही हमारे लिये एक गान मान्य रह जाना है। अतः भारत में इसका पूर्णतया विकास होना नितांत आवश्यक है।

यदि प्रकृति ने भारत को कोयला और तेल प्रदान करने में कुछ कसौटी की है तो जल-शक्ति के प्रदान करने में अपनी उदारता का परिचय दे दिया है। भारत में जल शक्ति के विकास के लिये एक बड़ा भारी क्षेत्र है यद्यपि वर्तमान दशा में इसका विकास बहुत कम हुआ है। सन् १९१६ ई० में भारतवर्ष के हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर्वे (Hydroelectric Survey) से पता चलता है कि हिमालय पर्वत से जल के प्रत्यक्ष १००० फीट नीचे गिरने से ३० लाख किलोवाट जल विद्युत् शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर भारत के पास सबसे अधिक जल शक्ति है अर्थात् २७० लाख किलोवाट। यदि इस महान् शक्ति को उचित ढंग में प्रयोग किया जाय, तो देश का प्रत्येक गाँव औद्योगिक केन्द्र बनाया जा सकता है। परन्तु हम इस शक्ति का केवल पचासवाँ भाग ही प्रयोग में लाते हैं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जापान तिहाई जल-शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं और स्विट्जरलैंड तो अपनी जल शक्ति का तीन चौथाई भाग प्रयोग कर लेता है। इस शक्ति के विकासार्थ भारत सरकार ने सेंट्रल टेक्निकल बोर्ड (Central Technical Board) की नियुक्ति की है।

जल विद्युत् के विशेष गुण — जल-शक्ति के अनेक गुण हैं जो निम्नलिखित हैं —

(१) यह सस्ती शक्ति होती है। कोयले, ईंधन या तेल की अपेक्षा इसकी लागत ७५ प्रतिशत कम होती है।

(२) निरन्तर उत्पन्न होने के कारण जल शक्ति के काम में यथा शक्यता है।

(३) नारों द्वारा बिजली दूर-दूर तक सुगमता से और सस्ती दर पर पहुँचाई जा सकती है।

(४) बिजली में कोयले आदि की भाँति न तो धुआँ ही होता है और न धावाज ही।

विजली के आर्थिक लाभ (Economic benefits of Electricity)

विजली का घरेलू उपयोग—विजली के रूप में आधुनिक समाज को एक उपहार प्राप्त हुआ है। इसे आधुनिक सभ्यता का चिन्ह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके घरो के दैनिक परिचय कम हो गये हैं। इसके द्वारा घरों में उतम, सरता और बड़ी सुविधा देने वाला प्रवास प्राप्त होता है। आजकन अनेक घरेलू कार्य विजली द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

उद्योगपति को लाभ—विजली के द्वारा उद्योगपति को मशीन और धातुसम्पत्ता-नुसार प्रेरित शक्ति प्राप्त होती है। बिजली पैदा करने का व्यय कोयले, तैल और ईंधन की तुलना में बेवज एक चौथाई है। प्रेरक शक्ति प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ मौलिक शिक्षा के लिए इसका प्रयोग निराला आवश्यक है, जैसे वाटरवाइट से एन्जिनियरिंग बनाने में विजली का प्रयोग अनिवार्य है। जब बिजलु तारों द्वारा २५० मील की दूरी पर पहुँचाई जा सकती है, इसलिए घरेलू बसे हुए और गर्मियों मौसमिक पैदा की दूर ले जाया जा सकता है। मर्दों में गर्मी और गर्मी में मर्दों उपर कर धम की कार्य-कुशलता में सुधार किया जा सकता है।

कुटीर एवं छोटे व्यवसायों को लाभ—कुटीर एवं छोटे-छोटे दस्तकारों को इसमें बहुत लाभ है। जापान और स्विट्जरलैंड में छोटे कारखानों में इसका प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। भारतवर्ष में छोटे कारखानों में विजली का प्रयोग लाभदायक निम्न हो सकता है। मूल में भी विजली के द्वारा ५ हजार रुपये बचते हैं।

यातायात के क्षेत्र में विजली का उपयोग—वातायान के क्षेत्र में भी विजली का उपयोग घाँसनीय है। इस समय भारतीय रेलों द्वारा लगभग ७० लाख टन कायला खनित होता है। विजली के द्वारा कोयले का उपयोग कम हो सकता है। दम्भई में बल्गाएँ तक विजली की रेलगाटियाँ कितनी सुविधाजनक कार्य कर रही हैं। यह सबको धिदित ही है। भारत की समस्त रेलों के लिए केवल बिहार की कोमी योजना ही विजली की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

कृषि में विजली का उपयोग—मेनी में भी विजली का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए भैंस जोतने, बोने, घास व फसल काटने, अनाज में भूसा घाला करने आदि क्रियाओं में विजली का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। भारतवर्ष में खेती छोटे-छोटे खेतों में होती है। तथा भारतीय कृषि निर्धन होने में विजली का उपयोग नहीं कर सकता।

सिंचाई—जल विद्युत का प्रयोग सिंचाई में निम्न प्रकार हो सकता है —

(१) विजली द्वारा पानी कुँआ में निकाला जा सकता है और खेतों का समय पर भींचा जा सकता है। इसमें खेतों की शक्ति बचकर मेनी के अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो सकती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास के कुछ गाँवों में इन कार्य के लिए विजली प्रयुक्त की जाती है।

(२) विजली द्वारा सिंचाई होने में पानी निरर्थक बह नहीं होने पाता।

(३) बहुप्रयोजन योजनाओं में विजली उत्पन्न करने के पश्चात् नाला जल अर्थात् Tail water सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

(४) नदियाँ पर बाँध बनाने और Pumping Stations स्थापित करने में विजली बड़ी सहायक है।

(५) बिजली द्वारा राख गया जैसी नीची छतह रखने वाली नदी में भी सिंचाई हो सकती है ।

(६) बिजली सिंचाई की सुविधाएँ प्रस्तुत कर खेती को पैदावार में वृद्धि करती है ।

(७) बिजली द्वारा सिंचाई में गरीब और सम्पन्न फसलों की पैती होना सम्भव है ।

(८) बिजली द्वारा सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ने से मनाल का आक्रमण प्रभाव घूम हो जाता है ।

(९) बिजली के प्रयोग से सिंचाई का निरन्तर साधन उपलब्ध होने से वर्ष भर में कई फसलें पैदा की जा सकती है ।

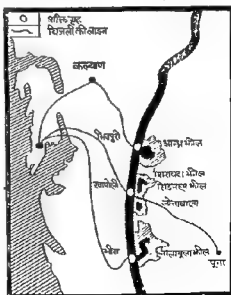
ग्राम्य व्यवसायों को लिए बिजली का उपयोग—जल-विद्युत का विकास गांधी के दशम धर्मों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । इससे गांधी के उद्योग-धर्मों का पुन उत्थान हो सकता है । जिन श्रियाओं को बार बार करना पड़ता है वे बिजली से चलन वाली मशीनों में भली प्रकार सम्पन्न की जा सकती हैं । बिजली के प्रयोग से पुराने ढंग के घोड़ा-गाड़ी में भी परिवर्तन हो सकता है ।

भारत सरकार की प्रसिद्ध जल-विद्युत योजनाएँ

बम्बई महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य

भारत में जल-विद्युत के सबसे बड़े कारखाने बम्बई राज्य में हैं । इन सबको स्थापित करने का श्रेय टाटा को है । इनमें बम्बई, कल्याण, पूना और वागा नगरों को बिजली दी जाती है । इन्हीं में बम्बई की सूती कपड़े की मिलें शक्ति प्राप्त करती हैं और पश्चिमी तथा जी० घाई० पी० रेल भी इसी बिजली का प्रयोग करती हैं । इस राज्य के बिजली के मुख्य कारखाने निम्नलिखित हैं :—

टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाय कंपनी लि० (The Tata Hydro-electric Power Supply Co., Ltd.)—यह कारखाना बम्बई में ४३ मील की दूरी पर स्थित है और इतना उत्पादन सन् १९१५ में हुआ था । औरपाट के ऊपर लोनावाला-बालवान और शिरावटा भीनों में तीन विशाल बांध बनाकर एक विशाल जलाशय बना दिया गया है । यह पानी बड़े-बड़े नलों द्वारा लगभग ७० हजार फीट की ऊँचाई से रापोसी के शक्ति-



बम्बई राज्य की जल-विद्युत योजनाएँ

घृह (Power House) में छोड़ा जाता है। इस ऊँचाई से बिरने के कारण जल के प्रत्येक गन ६३३ म पांच गन का दबाव हो जाता है। इस शक्ति से पहिय चलते हैं जिनसे ६० हजार किलोवाट विद्युत् उत्पन्न होती है।

(२) आन्ध्र वैली पावर सप्लाई कम्पनी लि० (The Andhra Valley Power Supply Co., Ltd.)—इस कम्पनी ने अपना कार्य सन् १९१५ ई० में प्रारम्भ किया था। यह शक्ति-गृह भिवपुरी पर स्थित है जहाँ आन्ध्र नदी पर बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया गया है। इससे ७२ हजार किलोवाट विजली पैदा की जाती है।

(३) टाटा पावर कम्पनी लि० (The Tata Power Co. Ltd.)—यह कारखाना सन् १९१७ ई० में प्रारम्भ हुआ। बम्बई में ८० मीटर दक्षिण-पूर्व में भीरा नामक स्थान पर सोलापूर नदी में बांध बनाया गया है जिससे ६६ हजार किलोवाट विजली उत्पन्न कर बम्बई को पहुँचाई जाती है।

बम्बई राज्य की अन्य मुख्य विचाराधीन योजनाएँ

(१) उत्तरी-गुजरात योजना—श्री महमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी का विस्तार करनी।

(२) दक्षिणी गुजरात ग्रिड योजना—जिसके द्वारा सूरत में नया शक्ति-गृह स्थापित होगा।

(३) कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट—यह नावना नदी पर बांध बनाकर तंबार की जायगी।

(४) परोन्हापुर योजना—जिसकी विजली रोन्हापुर की सीमा को ब नगर को प्राप्त होगी।

मद्रास राज्य

मद्रास राज्य में निम्नलिखित मुख्य योजनाएँ हैं—

(१) पैकारा जल विद्युत् योजना (The Pykara Hydro-electric Scheme)—यह योजना सन् १९२९ ई० में प्रारम्भ की गई थी। मद्रास के नीलगिरी जिले में पैकारा नदी पर बांध बनाया गया है जहाँ विजली उत्पन्न कर कोयंबटूर, इरोड, त्रिचनापली, मदुरा आदि नगरों में पहुँचाई जाती है। यह योजना दक्षिणी भारत की औद्योगिक उन्नति में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई है। इसने पूर्ण विकास के पश्चात् योजना ४० हजार किलोवाट विजली उत्पन्न कर सकेगी।

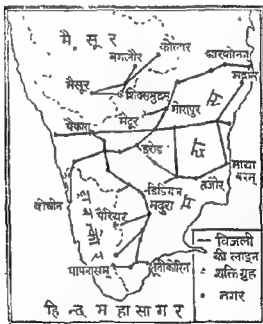
(२) मेट्टूर जल-विद्युत् योजना (The Mettur Hydro-electric Scheme)—सन् १९३४ ई० में कावेरी नदी पर सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध बनाया गया जो सुचारु में सबसे बड़ा बांध है। यह १७६ फीट ऊँचा है और द्रष्टा १०,००० करोड़ पन फुट जल समा सकता है। पहले यह बांध सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था, परन्तु अब इसकी महत्त्वता से जल-विद्युत् उत्पन्न की जाती है। इस योजना द्वारा ४ हजार किलोवाट विजली उत्पन्न की जा सकती है जो सस्ते, त्रिचनापली, तंजौर, मद्रास, चित्तूर और चिन्नलीपुट जिलों को शक्ति देती है। यह इरोड स्थान पर पैकारा योजना से मिला दी गई है।

(३) पापनासम योजना (The Papanasam Hydro-electric Scheme)—वायप्रणो नदी पर पापनासम के पास सन् १९४४ ई० में एक विद्युत्

वांछ बनाया गया। इससे जो बिजली पैदा होती है उससे टेनेबनी, तून्नेकोरिन और मदुरा आदि जिलों को बड़ा लाभ पहुँचता है।

केरल राज्य पल्लीवासल जल-विद्युत् योजना (The Pallivasal Hydro-electric Scheme)—इस योजना का प्रादुर्भाव इस राज्य में सन् १९४० ई० में हुआ। इस योजना में मुद्रपूजा नदी के पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है। कोयंबी की सम्पूर्ण बिजली की माँग इस योजना द्वारा पूर्ण की जाती है। इसके द्वारा अनुवाय के एल्यूमिनियम के कारखानों को प्रेरक शक्ति मिलती है। ऐसा अनुमान दिया जाता है कि यह योजना दस वर्ष पश्चात् ३० हजार किलोवाट बिजली पैदा कर सकेगी।

हमारे अनिरुक्त Neriyaangalam और Singatam योजनाएँ विचाराधीन हैं।



दक्षिणी भारत की जल विद्युत् योजनाएँ

मैसूर राज्य—शिवसमुद्रम जल विद्युत् योजना (The Shivasamudram Hydro-electric Scheme)—मैसूर राज्य में भारत की सर्व प्रथम जल-विद्युत् योजना सन् १९०२ ई० में कावेरी नदी पर स्थित। शिवसमुद्र भील पर ६२ मील दूर स्थित कोयंबी की मोने की खानों की शक्ति पहुँचाने के लक्ष्य से बनाई गई। इस योजना में मैसूर राज्य के २०० नगरों को बिजली मिलती है जिसमें बंगलूर मुख्य है। वर्तमान में इस योजना से ४२ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है।

इसके अलावा मंसूर राज्य में शिमशा (Shimsba) और जोग (Jog) प्रपातों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करने वाले दो योजनाएँ जिनमें एक सन् १९४० ई० में पूर्ण होगई जिनमें लगभग १८ हजार किन्नीवाट बिजली उत्पन्न होगी है। जोग योजना मन् १९४० ई० में पूर्ण हो गई और इनमें ४८ हजार किन्नीवाट बिजली उत्पन्न होगी है।

उत्तर प्रदेश

गगानहर जल विद्युत ग्रिड योजना (The Ganges Canal Hydro-electric Grid Scheme) — इस योजना के अन्तर्गत मान शक्ति ग्रह — बहादुराबाद, मोहम्मदपुर, चित्तौरा, खानवा, सोना, पासरा, और मुंजरा — में स्थित हैं। ये माता यन्त्रि-ग्रह बिजली के द्वारा द्वारा एक दूसरे के साथ मिला दिये गये हैं। यही ग्रिड योजना कहलाती है। इस योजना द्वारा प्रान्त के पश्चिम में १४ जिलों में ६३ कम्पार्स को और दिल्ली प्रान्त में बहादुरा को धरेलू, वृषि और उद्योग-धर्मों को बिजली मिलती है। जहाँ नहर द्वारा पानी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर कुएँ खोद कर इस बिजली से पानी उत्पन्न उठाया जाता है और खेती की सिंचाई की जाती है। यही Ganges Valley State Well scheme है। इसके अन्तर्गत जितने कुएँ खोदे गए हैं वे बिजली के कुएँ अर्थात् ट्यूब-वेल (Tube Well) कहलाते हैं। ट्यूब वेल (नल बूज) द्वारा मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूँ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ जिलों में लगभग १० लाख एकड़ भूमि सिंचे जाये है।

उत्तर प्रदेश की ग्राम्य विद्याराधोम योजनाएँ

(१) शारदा नहर योजना (Sarda Canal Scheme) — इसमें ५० हजार किन्नीवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

(२) नैयर योजना (Nayer Scheme) — इस योजना में गंगा नदी की सहायक नदी नैयर पर गडबान जिले में नरोरा नामक स्थान में एक बाँध बनाया जायगा।

(३) जमुना हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना (The Jamuna Hydro Electric Scheme) — यह योजना देहरादून से ३० मील दूर नदी पर बाँध बनाकर नैयर की आपत्ती। इस योजना में १७ करोड़ रुपया व्यय होगा।

(४) रिहन्द योजना (Rihand Scheme) — इस योजना में सोन की सहायक नदी रिहन्द पर बाँध बनाया जायगा जिससे डेढ़ लाख किन्नीवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

(५) टोंस गिरि योजना (Tons Gira Scheme) — इस योजना के अनुसार जमुना नदी पर दो बाँध बाँधे जायेंगे। यह योजना उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार द्वारा सम्पन्न होगी।

पंजाब प्रदेश

मण्डी जल-विद्युत योजना (The Mandi Hydro-electric Scheme) — पंजाब प्रदेश के मण्डी राज्य में व्यास नदी की एक सहायक उहल नदी के प्रपात से बिजली उत्पन्न की जाती है। इसका शक्ति-ग्रह जोगन्दनगर में स्थित है। इस योजना में १ लाख १८ हजार किन्नीवाट बिजली उत्पन्न होगी है जिसमें पंजाब और दिल्ली की वर्तमान सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसकी १५,००० फीट लम्बी झमाती सुरंग इजीनियरिंग निपुणता का एक अद्भुत नमूना

प्रस्तुत करती है। इससे जमना, शम्भाना करनाल और फिरोजपुर को बहुत मस्ती बिजली मिलती है। भविष्य में सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली आदि नगरों का भा बिजली दी जा सकेगी।

अन्य विचाराधीन योजनाएँ—रमूल योजना, मियावाला योजना आदि।
काठमोर राज्य

बारामूला जल विद्युत योजना (The Baranulla Hydro electric Scheme) —थीनगर से ३४ मील उत्तर पश्चिम में बुनियाद के समीप जो बारामूला से १४ मील है मेखम नदी के पानी में बिजली उत्पन्न की गई है जो बागमूला और थीनगर को पहुँचाई जाती है। यह भारत की द्वितीय जल विद्युत योजना है जिसमें २६,००० घोड़ों का शक्ति को बिजली उत्पन्न की जाता है।

भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएँ (Multi purpose schemes of India)

भारत में कई बहुउद्देशीय योजनायाँ का निर्माण हो रही हैं तथा बहुत सी विचाराधीन भी हैं। इसमें बिजली भी पैदा होती है और साथ ही साथ सिंचाई का कार्य भी सम्पन्न होता है। उनमें से मुख्य योजनाएँ निम्नलिखित हैं —

दामोदर घाटी योजना (Damodar Valley Project) —दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल कर बिहार के कई जिलों में होनी हुई पश्चिमी बंगाल की बनी गई है। यह एक भयंकर नदी है जिसमें प्रायः बाढ़ आती रहती है। यह बहुत तेज बहती है जिसके कारण भूमि का कटाव बहुत होता है। इस नदी का बड़ा महत्व है क्योंकि यह बिहार राज्य के खनिज पदार्थ के भण्डार के पास



में होकर बहती है। इसलिए भारत सरकार ने दामोदर घाटी निधम की स्थापना मई १९४८ में की। इसके अन्तर्गत दामोदर व उसकी सहायक नदियों पर ८ बांध तथा दुर्गापुर व ऐण्डरसन पर कुण्ड (Barrage) बनाने की योजना है। दुर्गापुर कुण्ड बन चुका है। तिसमें बाँध तथा दोहरे बिजली का केन्द्र तैयार हो गया है। इस योजना पर अब प्रथम ५१ करोड़ रुपए लागत का अनुमान था, परन्तु अब लगभग ६३ करोड़ रुपए हो गया है। इस योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में २२ करोड़ पाउंड कूए लिया गया है।

६१ फीट घोर नम्माई ६५५ फीट है। इसमें तीस-तीस फीट चौड़ी २६ जल-अणुजिकाई हैं। यदि ये सब जलमार्ग खुले हों तो उनमें से ३ लाख ५० हजार 'क्यूबिक' जल प्रवाहित हो सकता है (क्यूबिक प्रवाह का माप है एक मैकबड में एक घन फुट जल बट गया तो एक 'क्यूबिक' हुआ)। तैंगल बाँध को बनाने में तीन लाख घन घन कंक्रीट २००० टन फौनाद घोर ६० हजार टन गोमेट लवर् हुआ है। और १२ लाख ३० हजार घन गज खुदाई करके इसकी बाँध रखी गई है इस पर लगभग ४ करोड़ रुपया लागत आई है।

लाभ :—(१) ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो जा सकेगी। (२) पंजाब में प्रति वर्ष ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। (३) बार लाख किलोवाट जल-विद्युत उत्पादन की जायेगी। सिंचाई के परिणामस्वरूप अनुमान में ११ लाख टन तांबा, ८ लाख गॉड कई, ५ लाख टन गन्ना, १५ लाख टन काग और एक लाख टन धातु घोर जिलहन की उपज देना में बढ जायेगी। (४) इस योजना के कारण अनुमानतः २५ लाख व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सकेगा। (५) लगभग १३० नगरों की बिजली मिलेगी। (६) एक हजार के लगभग 'टयूब वेल्' लगाये जायेंगे जिनमें सिंचाई का खेत घोर बढ जायेगा। (७) कृषिपट्ट के निहाल जिनमें गेहूँ बसाने का कारखाना बनाया जा सकेगा। (८) विविध मशीनरन के मापन मुक्त हो गयेगे।

सारा की दृष्टि में यह नगर का सबसे उपयोगी बाँध होगा।

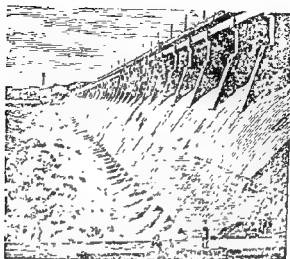
हीराकुड बाँध योजना (Hirakud Dam Project)—इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्मन्धुर जिले में महानदी पर २ मील लम्बा बाँध

बनाया गया है जो संसार में सबसे लम्बा बाँध है। इसके धनाश नदी के दोनों किनारी पर १३ मील लम्बा मिट्टी के पुल बने गये हैं। बिजलीघर के पास बाँध की ऊँचाई २०० फीट है। बाँध में जो जमाव बना है उनका विस्तार २८८ वर्ग मील है। इसमें १०६ लाख एकड़ फुट पानी भरा रहेगा जिनमें १८ लाख ८०



हजार एकड़ छोटे पानी बिजली पैदा करने के लिए घोर बाँधी ४७ लाख २० हजार एकड़ फुट पानी सिंचाई तथा बिजली आदि के लिए मुक्ति रहेगा। इस योजना पर ६४ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। हीराकुड जमाव में बरख नहर में सबसे पहले ७ मिस्टर १८५५ फीट सिंचाई के लिए पानी दिया गया।

लाभ—(१) इस योजना के पूर्ण हो जाने पर १८ लाख एकड़ भूमि भोजी जा सकेगी। (२) इस पर दो बड़े पावर हाउस (Power House) बनाये जायेंगे जिनमें १२३ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। ये बिजली ग्वाज पर जर्मन विदेशियों को माराना में बनाये जा रहे हैं। (३) नोडा व इलाहाबाद के कारखानों की यहाँ से बिजली प्रदान की जायेगी। इसके धनिक अन्य नवीन उपयोग-धन्यो की बिजली दो



हिराकुड योजना

जावेगी। (४) इस प्रकार सम्मेलनपुर में सघन एक औद्योगिक नगर बसा जायगा। (५) इस योजना से महाबदी की बाढ़ों पर भी नियन्त्रण हो गयेगा।

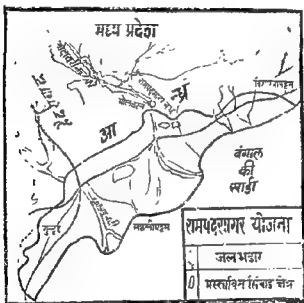
कोसी योजना (Kosi Project)—कोसी नदी हिमालय में निकल कर मुँगेर जिले में गया नदी से मिल गई है। बाढ़, फसलों की खाति तथा मत्तोरिया की बीमारी इसकी देन है। इनमें मुक्ति पाने के लिए कोसी योजना का जन्म मिला। कोसी नदी पर पहाड़ी भाग में बाराह क्षेत्र मन्दिर में ऊपर की ओर एक ७८३ फुट ऊँचा बाँध बनाया जायगा जो बसंसार में सबसे ऊँचा बाँध होगा। इसी योजना का दूसरा बाँध नेपाल विहार सीमा पर बनाया जायगा। इसका अनुमानित व्यय ₹७७ करोड़ है।

लाभ :—(१) इससे नहरों निकालकर बिहार राज्य में ९० लाख एकड़ भूमि पर, नेपाल देश में १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। (२) इसमें लगभग १८ लाख किलोवाट बिजली बनेगी जिससे कारखाने चल सकें। (३) इससे बाढ़ों का



नियन्त्रण किया जा सकेगा । (४) वन लगाकर भूमि का कटाव रोका जा सकेगा । (५) मलेरिया की रोकथाम का जा सकेगा । (६) मनोरंजन के साधन सुव्यवस्थित जा सकेगा ।

रामगढ़ सागर योजना (Ramgadh Sagar Project)—प्रायः राज्य



में गोदावरी नदी पर बीजापुर में स्थित पर १४८ फुट ऊँचा बांध बनाया जा रहा है । इस योजना पर १३० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है । यह मुख्यतः एक सिंचाई योजना है ।

साम—

(१) इसमें दो नहरें बनाकर विमानवाहन नया मन्तूर विधानसभा क्षेत्र में २० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जावेगी ।

(२) इसमें १३ लाख विधानसभा क्षेत्रों उत्पन्न की जावेगी ।

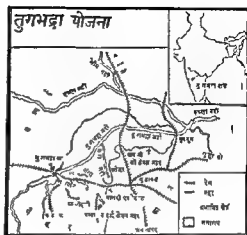
तुंगभद्रा योजना (Tungabhadra Project)—दृष्ट्या नदी की

सहायक नदी तुगभद्रा पर लगभग १९० फुट ऊँचा तथा १ १/२ मील लम्बा बांध बनाने की योजना है। इस योजना का अनुमानित व्यय १० करोड़ रुपये है।

साध—

(१) इससे घाघर और हैबराबाद में लगभग २० लाख एकड़ भूमि पर सिनाई हो सकेगी।

(२) वही जमीन १८ हजार बिजलीघट बिजली भी मिल जायेगी।



तुगभद्रा बांध योजना

रिहन्द योजना (Rihand Project)— रिहन्द नदी विन्ध्यप्रदेश के पठार में निक्षेप कर उत्तर प्रदेश में बहती हुई सोन नदी में गिरी है। इस नदी पर विपरी नामक स्थान के समीप २८० फुट ऊँचा एक बांध बनाया जा रहा है। इसका अनुमानित व्यय लगभग ३६३ करोड़ रुपये है।

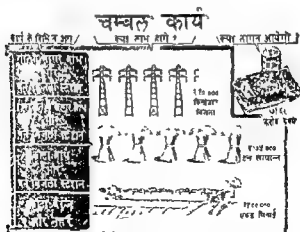
लाभ—(१) इससे निकासी गई नहरों में उत्तर प्रदेश और विद्यप्रदेश में सिंचाई होगी। अनुमान है कि लगभग २४ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी। (२) इस योजना में ४ हजार नलकूप बनाये जायेंगे। (३) इससे बनाई गई बिजली बिहार तक प्रयोग की जा सकती है। इसमें १० हजार ३६२ किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी। (४) इस योजना से बाढ़-नियंत्रण, मछली-पालन, नौका-चालन व मनोरंजन की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

चम्बल घाटी योजना (Chambal Valley Project)—इस योजना के प्रस्तावित चम्बल नदी पर श्रीरामगढ़ के समीप २०० फुट ऊँचा बांध तैयार किया जा रहा है। इस योजना पर लगभग ७१ करोड़ रुपया व्यय होगा। इसके प्रस्तावित गांधी नगर बांध, राना प्रताप सागर बांध, कोटा बांध और कोयल बैरेज बनाये जायेंगे। प्रस्ता १९६० में चम्बल योजना के बिजलीघर में बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी और १९६० की खरीफ की फसल की सिंचाई भी हो सकेगी।

लाभ—(१) इसके द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग १८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी।

(२) ४½ लाख टन वायुमल वार्षिक पैदा होगा।

(३) इसमें २१ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। जिसके कारण नगर व कस्बों की बिजली मिलने के अतिरिक्त अनेक कम-कारखाने चमकेंगे।



नाम—(१) इस योजना से आठ तथा हैदराबाद राज्या में ३१८३ लाख एकड़ भूमि की विचार्य होगी। (२) इसमें ७१ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। (३) इसमें आठवीं की पैदावार में १२ लाख टन की वृद्धि होगी। (४) इस योजना के पूर्ण हो जाने पर हैदराबाद के नलगावा और परभस क्षेत्र में आठ व कृष्णा नगर एवं सुल्तान क्षेत्र में अनाज के हमरा को निपट किया जा सकेगा।

जवाई योजना (Jawai Project)—राजस्थान में घरावती की बहाडिया में तीन करोड़ रुपय की लागत की योजना मई १९४६ में प्रारम्भ हुई और इस वर्ष के



जवाई बांध योजना

समय तक पूर्ण हो जाने का आशा है। इस योजना का मुख्य बांध ११४ फुट ऊँचा और ३०३० फुट लम्बा जिसकी ७ लाख वर्ग फुट पानी की क्षमता है असाय भरन से जा पानी पैदा बहु करीब १२ मील के धरे में बसा सकेगा।

नाम—(१) इसमें औसतन करीब १० हजार एकड़ भूमि की सुविधा होगी और इस एक लाख दस हजार एकड़ भूमि प्रभावित होगी। (२) इस योजना से लगभग ३०४ लाख मील में होत बाँधी बसा व पानी में १ लाख १० हजार एकड़ अतिरिक्त अनुपजाऊ भूमि का उत्पादन होगा, गहुँ वन आदि और खाद का उत्पादन करने योग्य बनाया जाएगा। (३) इसमें ४५ हजार बिजली बिजली उत्पन्न हो सकेगी। (४) इस विचार्य की सुविधा से १५ हजार टन अनाज उत्पन्न किया जा सकेगा।

अन्य बहुउद्देशीय योजनाएँ

मयूरक्षी योजना (Mayurakshi Project)—यह १५ करोड़ का लागत की योजना पच्छिमी बंगाल की सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इससे



मधुराक्षी योजना

अमलगत ११३ फुट उँचा और २०६७ फुट लम्बा बाँध नैवार हागा जिसमें पाँच लाख एकड़ पानी समा सगा। इसमें ६ लाख एकड़ भूमि को पानी मिलगा। यह निम्नपतया सिंचाई की योजना है परन्तु फिर भी इसमें ४ हजार किनोबॉट बिजली उत्पन्न होगी।

कोयना योजना—यह बम्बई राज्य की ६० करोड़ रुपये की योजना है। जिसमें लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि सीपी जायगी और २८ लाख बिजली बिजली उत्पन्न होगी।

कृष्णा मिनार योजना—यह धाम और हैदराबाद की ८० करोड़ की लागत की योजना है जिसमें तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १२ लाख बिजली बिजली उत्पन्न होगी।

गोदावरी घाटी योजना—यह धाम राज्य में ६८ करोड़ रुपये की लागत की योजना बनाई जा रही है। इसमें लगभग ३२ करोड़ एकड़ भूमि को पानी मिलगा और और २८ लाख बिजली बिजली उत्पन्न होगी।

गंडक योजना—इस २५ करोड़ रुपये की लागत की योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की लगभग २३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यह मुख्यतया सिंचाई की योजना है, परन्तु इसमें २ हजार किनोबॉट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की नायर योजना, बम्बई की नर्वदा-नासी योजना, मद्रास की लोमर भवानी योजना, बम्बई की काकरापारा योजना, धाम और उड़ीसा की भयूष भयूषकुण्ड योजना, बड़ोदा की साबरमती योजना, भोपाल की किन्नर नदी योजना, और मध्य प्रदेश की गांधी सागर बाँध योजना, उल्लेखनीय है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारतवर्ष में जल-विद्युत्-शक्ति से किन प्रकार उन्नति हुई है ? इस समय कौन-सो प्रमुख योजनाएँ इस ओर कार्य कर रही हैं ? (उ० प्र० १९५७)
- २—भारतवर्ष में शक्ति के प्रमुख साधन क्या हैं ? जल शक्ति का अधिक महत्त्व तथा इसके भावी विकास की सम्भावनाओं पर तर्क सहित विचार कीजिए । (रा० बो० १९५७)
- ३—शक्ति के मुख्य साधन क्या हैं ? संक्षेप में बताइये कि भारतवर्ष में जल-विद्युत्-योजनाओं में कितनी उन्नति की गई है ? (प्र० भा० १९५७)
- ४—भारत में बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजनाओं की आवश्यकता तथा उनके महत्त्व का विवेचन कीजिए । (प्र० बो० १९५६)
- ५—बहु-उद्देशीय योजनाओं के उद्देश्यों को समझाइए । भारत की कुछ मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए और प्रत्येक के उक्त उद्देश्य या उद्देश्यों का भी वर्णन कीजिये जिनके कारण उक्त योजना का निर्माण किया जा रहा है । (प्र० बो० १९५५)
- ६—भारत में शक्ति के प्रमुख साधन क्या हैं ? उनका पूर्ण विवेचन कीजिये ।
(उ० प्र० १९५५, ५३, ५२, ५१, ४८, ४६ ; प्र० भा० १९५५, ५४, ५१ ;
प्र० बो० १९५३, ४६, ४२, रा० बो० १९५२, २०, ४५)
- ७—नोट लिखिए :—
भारत में शक्ति के साधन (प्र० बो० १९५६)
भारत में शक्ति-उत्पादन की योजनाएँ (सागर १९५४)
भारतीय नदी-घाटी योजनाएँ (नागपुर १९५५)

* श्रम उत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है (Labour is an indispensable factor of production) — श्रम उत्पत्ति का एक प्रमुख साधन है। इसकी सहायता के कारण उत्पत्ति के साधनों में इसका बड़ा महत्व है। प्रकृति के साधन निरक्षर है, इसे उपयोग बनाने के लिए मनुष्य द्वारा प्रयत्न प्रवाह श्रम की आवश्यकता है। अस्तु, भूमि की भाँति श्रम भी उत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है।

श्रम का अर्थ (Meaning of Labour) — माधुरा भाषा में किसी भी काम करने के प्रयत्न को 'श्रम' कहते हैं। उदाहरण के लिए, माता का बीमार

पुत्र के पास राखि भर बैठे रहना, खिलाना का मंच में 'जी-ज्ञान' में खेलना, प्रोफेसर का किसी अन्य कालेज में निमन्त्रण पाकर व्याख्यान देना आदि। परन्तु अर्थशास्त्र में श्रम का अर्थ इतना व्यापक नहीं है। अर्थशास्त्रीय अर्थ के अनुसार मनुष्य के सभी मानसिक एवं शारीरिक प्रयत्न जो मनोरंजन के



लिए न करके धनोपार्जन के उद्देश्य में किये जायें 'श्रम' कहलाते हैं। ऊपर के उदाहरणों में माता, खिलाना और प्रोफेसर के कार्यों का धनोपार्जन में कोई सम्बन्ध नहीं होने के कारण उनके प्रयत्न अर्थशास्त्र की दृष्टि में श्रम नहीं बहे जा सकते। परन्तु यदि माता के बच्चाप वेतन पर रखी हुई नर्स कार्य सम्पन्न करती है, खिलाना प्राप्त के लिए जी-ज्ञान में खेलता है, प्रोफेसर अपने ही कॉलेज में जहाँ सौकर है व्याख्यान देता है, तो निमन्त्रण उनके प्रयत्न अर्थशास्त्र की दृष्टि में 'श्रम' कहलाने योग्य है, क्योंकि उन मदका सम्बन्ध धन बनाने में हैं न कि मनोरंजन में। इसी प्रकार धनोपार्जन के उद्देश्य में प्रभावित अध्यापक, डाक्टर, वकील, राज्य-मन्त्री, बडई, लुहार, किसान, मजदूर आदि सभी प्रकार के प्रयत्न चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक—छोटे मनुष्यों के ही अथवा बड़ों के, अर्थशास्त्रीय श्रम के अन्तर्गत आते हैं।

प्रो० जेवन्स (Jevons) की दी हुई धम की परिभाषा अध्ययन-योग्य है। उनके अनुसार धम वह मानसिक अथवा शारीरिक प्रयत्न है जो अन्न या पूर्णतः कार्य में प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त होने के अतिरिक्त अन्य लाभ को दृष्टि में लिया जाय।¹ प्रो० मार्शल भी इस परिभाषा में पूर्ण सहमत है और उन्होंने अपने पुस्तक *Principles of Economics* में भी उद्धृत किया है।

अर्थशास्त्रीय धम की मारभूत बातें—घाटिक दृष्टि में 'धम' में निम्नांकित बातें समाविष्ट हैं—

(१) धम के अन्तर्गत केवल मानवीय प्रयत्न ही समाविष्ट हैं। प्ररतु, प्रहति, पशुओं या मशीनों द्वारा सम्पन्न कार्य धम नहीं कह जाते हैं। यद्यपि घोड़ों, बैलों मत्स्य आदि बौद्धिक दान वाले पशुओं के परिश्रम में घनत्वार्जन होता है, परन्तु फिर भी वह अर्थशास्त्रीय धम में सम्मिलित नहीं किया जाना है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल मनुष्यों के प्रयत्न का ही अध्ययन है।

(२) धम के अन्तर्गत मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं। जैसे अध्यापक, चकील, यहाँ, मजदूर आदि के कार्य।

(३) मनुष्य के वे ही मानसिक एवं शारीरिक कार्य जो मनोवार्जन की दृष्टि में किए जायें, धम कहना ही योग्य होते हैं। जो कार्य केवल आनन्द-प्रसोद, मनुष्य या कृत्रिम पालन की दृष्टि से सम्पन्न किए जायें, वे धम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उदाहरणार्थ, मनोरंजन एवं आनन्द-प्रसोद के लिए किसी गायक द्वारा गीत बजा का प्रदर्शन करना, निष्कार द्वारा निष्क बनाना, अध्यापक द्वारा निष्क शिक्षाप्रदाय करना, कर्मचारी पालन की दृष्टि में कृत्रिमता द्वारा घर में कार्य सम्पन्न करना, स्नेहवश भाता द्वारा बच्चा का पालन-पोषण करना आदि।

धम की विशेषताएँ (Peculiarities of Labour)

उत्पत्ति के साधन के रूप में धम की कुछ विशेषताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) धम उत्पत्ति के लिए अनिवार्य है (Labour is indispensable for production)—उत्पत्ति का कार्य भी कार्य बिना धम की सहायता के सम्भव नहीं है। चाहे जितने प्रहति व सामन एवं पूँजी सम्पन्न बसा न हो, बिना मानवीय प्रयत्न (धम) द्वारा भक्ष्यवृत्ति कदापि सम्भव नहीं हो सकती।

(२) धम नाशवान है (Labour is perishable)—मनुष्य के शरीर के साथ ही समय धम भी खर्च होकर नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी कार्य न करे, तो उसका उस दिन का धम नष्ट हो जाता है और वह उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता।

(३) धम न केवल उत्पत्ति का साधन ही है अपितु इसका साध्य भी है (Labour is not only a means of production-but is also its end)—धमिक जन केवल उत्पत्ति में सह्यक ही नहीं है बल्कि वे उत्पत्ति के साध्य

1—"An exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work"

भी है, क्योंकि ममत्त उत्पत्ति का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अस्तु, श्रम का उत्पत्ति साधन एवं माध्य होना सिद्ध होता है।

(२) श्रम विनियोग योग्य है (Money can be invested in Labour)—जिस प्रकार कारखानों, मशीनों आदि के क्रय में पूँजी लगाने में धन्य होती है, उसी प्रकार मनुष्य की शिक्षा, कार्य-कुशलता आदि बातों की प्राप्ति के लिए व्यय करने से भी धन्य होनी है। दोनों धन्य प्राप्ति की दृष्टि से पूँजी लगाने में समानता रखते हैं। इसलिए श्रम को कभी-कभी 'मानवीय पूँजी' (Human Capital) भी कहते हैं।

(३) श्रम का श्रमिक से पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है (Labour is inseparable from labourer)—श्रम साधारण क्रय-विक्रय की भाँति पृथक्ता नहीं रखता। यदि कोई श्रमिक अपना श्रम देना चाहे तो उसे स्वयं निर्दिष्ट स्थान पर जाकर श्रम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रमिक अपने घर बैठे और उसके श्रम द्वारा उत्पत्ति कारखाने में होती रहे। श्रम के साथ श्रमिक की उपस्थिति आवश्यक है। श्रमिक का कार्य-क्षेत्र उसके अनुकूल होना चाहिए, वहाँ उसके सुख व रक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

(४) श्रमिक केवल अपना श्रम ही बेचता है न कि अपने आपको (The labourer sells his labour only but retains property in himself) —जब कोई व्यापारी वस्तु बेचता है तो वह वस्तु दूसरे की सम्पत्ति बन जाती है। परन्तु श्रमिक अपना श्रम बेचने पर भी अपना स्वामित्व कायम रखता है। उत्पादक जितना अधिक व्यय लगा कर वस्तु उत्तम बनायेगा उतनी ही वस्तु अच्छे भाव मिलेगी। परन्तु यह बात श्रम के सम्बन्ध में यथार्थ मिश्र नहीं होती। जो व्यक्ति मनुष्य को शिक्षित करते हैं या उनके पालन-पोषण पर धन व्यय करते हैं, उन्हें श्रम के भूषण में कुछ नहीं मिलता। श्रमिक के योग्य बनने में उसके माता-पिता या संरक्षक की धार्मिक स्थिति, दूरवसिता, विचार, स्वभाव, योग्यता आदि बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता या संरक्षक शिक्षित, सम्पन्न और दूरदर्शी हैं, तो वे अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाकर योग्य और कुशल बना सकते हैं। इस योग्यता और श्रम का लाभ बँटे को मिलता है। माता-पिता को अपने बेटे को शिक्षित बनाने में किये गये व्यय के बदले में कोई व्याज या अन्य लाभ नहीं मिलता। बतव्यपरायण पुत्र माता-पिता को सेवा प्रदत्त करते हैं, परन्तु स्वामी पुत्र से तो इतना भी नहीं होता।

(५) श्रम की पूर्ति बहुत धीरे-धीरे घटती-बढ़ती है (Slow increase or decrease of supply of Labour) —अन्य वस्तुओं की माँग के घटने बढ़ने पर उनकी पूर्ति भी सीधे घटाई-बढ़ाई जा सकती है। परन्तु श्रम की पूर्ति बढ़ाने या घटाने में लम्बी समय लागता है। श्रम की पूर्ति जनसंख्या और कार्य-कुशलता पर निर्भर है और इन दोनों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है। किसी व्यक्ति के किसी विशेष धर्म के लिए योग्य बनने के लिए लम्बी समय की आवश्यकता है। इसी प्रकार सम्पादन, डाक्टर, वकील, इंजीनियर आदि की मर्यादा में कई वर्षों की शिक्षा के परानु ही वृद्धि हो सकती है।

(६) श्रम गतिशील है (Labour is mobile)—उत्पत्ति के साधनों में केवल धन ही गतिशील है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यवसाय में दूसरे व्यवसाय को और एक देश में दूसरे देशों को आ-जा सकता है।

भूमि और श्रम में अन्तर

(Difference between Land & Labour)

यद्यपि भूमि और श्रम दोनों ही उत्पात्ति के अनिवार्य साधन हैं, परन्तु दोनों में कुछ अन्तर अवश्य है।

✓ (१) भूमि उत्पत्ति का एक निष्क्रिय (Passive) साधन है जो बिना मनुष्य और मशीनरी की सहायता के उत्पत्ति में सहायक भिन्न नहीं हो सकता। यन्त्र उत्पत्ति का एक सक्रिय (Active) साधन है जिसके द्वारा सारी उत्पत्ति के कार्य का संचालन होता है।

(२) भूमि का परिमाण निश्चित और परिमित है, अतः इसमें घृणादिक्ता होना संभव नहीं। परन्तु श्रम की पूर्ति में पड़ावकी हो सकती है।

(३) भूमि अविनाशी, अनन्त और अमर है परन्तु श्रम नाशवान् है।

(४) भूमि स्थिर है—उसकी स्थिति या स्थान में परिवर्तन असम्भव है, परन्तु श्रम गतिशील है।

(५) भूमि स्वस्वामी में अलग हो जा सकती है, परन्तु श्रम धर्मिक में अलग नहीं हो सकता।

पूँजी और श्रम में अन्तर (Difference between Capital & Labour)—पूँजी और श्रम में घनिष्ठ सम्बन्ध है। पूँजी भी एक प्रकार से 'घनी-सूत श्रम' (Crystallised Labour) है, क्योंकि पूँजी श्रम द्वारा उत्पन्न किया हुआ धन का वह भाग है जो धन उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु दोनों में कुछ तात्त्विक अन्तर अवश्य है।

(१) यद्यपि पूँजी और श्रम दोनों ही नाशवान् हैं, फिर भी पूँजी की अपेक्षा श्रम की पुनर्प्राप्ति सीधे और सुगमता से हो सकती है।

(२) श्रम पूँजी की अपेक्षा सीधे नष्ट होता है। श्रम का यदि हम उपयोग भी न करें तब भी नष्ट हो जाएगा।

(३) श्रम की अपेक्षा पूँजी अधिक गतिशील है क्योंकि पूँजी का स्थानांतरण अधिक सुगमता से हो सकता है।

(४) पूँजी पूँजीपति से पूँचक हो सकती है। यदि पूँजीपति चाहें तो अपनी पूँजी को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। परन्तु श्रम धर्मिक में पूँचक नहीं हो सकता।

(५) कारखाने और मशीनों में लगाई हुई पूँजी उनकी विपरीत द्वारा वापस निवाली जा सकती है, किन्तु किसी धर्मिक की शिक्षा या कुशलता प्रशिक्षण में लगाई हुई पूँजी इसी सुगमता में नहीं निवाली जा सकती है।

उत्पत्ति में श्रम का महत्व

✓ (Importance of Labour in Production)

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है श्रम उत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है। बिना इसके साधारण से साधारण उत्पत्ति का कार्य भी सम्भव नहीं हो सकता। प्राकृतिक साधन चाहे जितनी प्रचुर मात्रा में विद्यमान क्यों न हों, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न-कुछ प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। जहाँ

प्रकृतितत्त्व पदार्थों में न्यूनता तथा जलवायु में प्रतिकूलता होती है, वहाँ मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी आधार पर धम का महत्व भी बढ़ता जाता है।

मथ हो यह है कि धम की अनिवार्यता में आधुनिक सभ्यता का जन्म निहित है। मनुष्य स्वभाव से ही न्यूनतम परिश्रम करना चाहता है। अतः परिश्रम में बढ़ते के सहोदय में कालान्तर में वह बड़े बड़े आविष्कारों की ओर प्रयत्न करता हुआ जिसमें उत्पादन क्षेत्र में प्रभूतपूर्व उन्नति हुई। कम से कम परिश्रम करने की प्रवृत्ति को न्यूनतम प्रयत्न का नियम (Law of Least Efforts) कहते हैं। यही नियम भौतिक सभ्यता का आधार माना जाता है।

धम के भेद (Kinds of Labour)

धम के अलग-अलग आधार पर अलग-अलग भेद किए गये हैं जो नीचे दिये जाते हैं :—

०१. उत्पादक और अनुत्पादक धम (Productive and Unproductive Labour)—उत्पत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता वृद्धि में। अतः जिन धम से किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है वह उत्पादक धम कहलाता है और जिनमें उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती है वह अनुत्पादक धम कहलाता है। जैसे नदी पर पुल बनाना आरम्भ किया गया। यदि वह पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है और उसका उपयोग होने लगता है तो ऐसा धम उत्पादक धम कहलाता है। परन्तु यदि पुल अपूर्ण ही छोड़ दिया जाय जिसमें उसका कोई उपयोग न हो सके, तो उसमें लगा हुआ धम अनुत्पादक धम कहलाता है।

कोन-सा धम उत्पादक है और कोन ना अनुत्पादक, इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में पूर्ण मतभेद रहा है। आरम्भिक कालों में अर्थशास्त्री वैभव कृषक के धम को ही उत्पादक कहते थे, शेष सबको अनुत्पादक। बाद में एडम स्मिथ ने वैभव भौतिक वस्तुओं उत्पादन करने वाले धम को ही उत्पादक धम कहा। उनके मतानुसार कुम्हार का धम उत्पादक है परन्तु गधे का नहीं। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात पर एक मत है कि उत्पादक धम वह है जिसमें उपयोगिता में वृद्धि होती है, चाहे वह उपयोगिता भौतिक पदार्थ में निहित हो या न हो। जैसे कृषक, वडई, व्यापारी, अध्यापक, डाक्टर आदि का कार्य।

०२. निपुण और अनिपुण धम (Skilled and Unskilled Labour) निपुण धम वह है जिसमें सम्पन्न करने में किसी विशेष अनुसृत अथवा शिक्षा की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे—मास्टर ड्राइवर, चित्रकार, गायक, कृषक आदि का कार्य। जो धम बिना किसी अनुसृत या विशेष शिक्षा के सम्पन्न किया जा सकता है वह अनिपुण धम कहलाता है, जैसे चपरासी धरेल नौकर, कुली आदि का कार्य।

निपुणता एक मार्पेटिक शब्द है जो देन-काल के अनुसार पर्याप्त भिन्नता रखता है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में निखने पड़ने की योग्यता को कुशलता कहेंगे परन्तु अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं, क्योंकि वहाँ अधिकांश मनुष्य लिखना-पढ़ना जानते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष में मोटर चालाना एक निपुण धम है, परन्तु यही कार्य अमेरिका आदि प्रगतिशील देशों में अनिपुण कार्य समझा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों, स्वयंचालित यंत्रों के प्रयोग और साधारण ज्ञान के बढ़ते हुए प्रसार ने धम अन्तर को कम कर दिया है।

३. **शारीरिक और मानसिक श्रम (Manual and Mental Labour)**—जिस कार्य के सम्पन्न करने में शरीर की प्रधानता होती है वह शारीरिक श्रम कहलाता है, जैसे—बर्डी, लुहार ॥ हमाल आदि का कार्य । जिस कार्य के करने में मस्तिष्क की प्रधानता होगी है वह मानसिक श्रम कहलाता है, जैसे—अध्यापक, वकील, न्यायाधीश आदि का कार्य ।

यह स्मरण रखने की बात है कि कोई भी कार्य केवल शारीरिक या मानसिक नहीं हो सकता । मुख्य से मुख्य शारीरिक कार्य में भी मस्तिष्क की आवश्यकता होती है और उच्च से उच्च मानसिक कार्य में भी शरीर का उपयोग हुए बिना नहीं रह सकता । अतः अर्थ-शास्त्र में दोनों प्रकार के कार्य श्रम के अन्तर्गत आते हैं ।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)

किसी देश में श्रम की पूर्ति दो बातों पर निर्भर है :—

(१) श्रम की मात्रा अर्थात् धर्मिकों की संख्या (Population)

(२) श्रम की कार्य-कुशलता (Efficiency of Labour)

यदि दो देशों की जनसंख्या समान है तो श्रम की पूर्ति उस देश में अधिक होगी जहाँ के श्रमिक अधिक कुशल हैं । इसी प्रकार यदि दोनों देशों के धर्मिकों की कार्य-कुशलता समान है, तो श्रम की पूर्ति अधिक जनसंख्या वाले देश में अधिक होगी । हम अगले दो-तीन अध्यायों में इन बातों का विवेचन करेंगे ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—श्रम की क्या विशेषताएँ हैं जो उसे अन्य किसी वस्तु में भिन्न बनाती हैं ? इस भेद का क्या महत्व है ? (प्र० को० १९६०)

२—‘श्रम’ शब्द की परिभाषा तथा व्याख्या कीजिए । श्रम की क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? श्रम और भूमि तथा श्रम और पूँजी में भेद दर्शाइये । (उ० प्र० १९५१)

३—निम्नलिखित पर मल्लि टिप्पणियाँ लिखिए :—

उत्पादक और अनुत्पादक श्रम

(उ० प्र० १९४४; म० भा० १९४५, ४६; रा० को० १९४४, म० को० १९४५)

कुशल और अनुकुशल श्रम

(उ० प्र० १९४५, ३६, ३४)

४—श्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए ।

(म० को० १९४६)

५—श्रम की परिभाषा दीजिये । क्या निम्न कार्य श्रम में शामिल हैं ? कारण भी बताइए :—

(अ) क्रिकेट का मैच खेलना । (ब) मेकनीक में छपाने की कविता बनाना ।

(स) किसी व्यवस्थित में भाग लेने के लिए रेल यात्रा करना । (नवम्बर १९४०)

किसी देश की जनसंख्या मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होती है :—

१. प्राकृतिक बात अर्थात् जन्म-मृत्यु ।
२. दृष्टिम बात अर्थात् आवास-प्रवास ।

१. प्राकृतिक घाते (Natural Factors)

जनसंख्या जन्म द्वारा बढ़ती है और मृत्यु द्वारा घटती है। अतः, किसी देश की जनसंख्या (अ) जन्म-संख्या (Birth Rate) और (आ) मृत्यु-संख्या (Death Rate) पर निर्भर होती है। जनसंख्या का शुरुआती-मंदाव में अधिक होना (इ) प्रति-जीवन-संख्या (Survival Rate) कहलाती है। यही जनसंख्या की वृद्धि का मापदण्ड है। अतः जनसंख्या के प्राकृतिक कारकों में इनकी बातों का विवेचन किया जायगा।

(अ) जन्म-संख्या (Birth Rate)—जन्म-संख्या का अर्थ यह है कि किसी देश में निश्चित अवधि में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं। जैसे यदि किसी देश में किसी वर्ष ४० जन्म-संख्या है, तो इसका अर्थ यह है कि उस वर्ष उस देश में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ ४० बच्चों ने जन्म लिया। अन्य बातों के समान रहने पर किसी देश में जितनी ही अधिक जन्म-संख्या होगी वहाँ की जनसंख्या में उतनी ही अधिक दर से वृद्धि होगी।

जन्म-संख्या के कारण (Causes of Birth Rate)—किसी देश की जन्म-संख्या निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है :—

(१) जलवायु—ठंडे देशों की अपेक्षा गर्म देशों में स्त्री-पुरुष दोनों ही जीवन प्राप्त कर विवाह-शायी बन जाते हैं। अतः वहाँ विवाह छोटी आयु में होना अनिवार्य हो जाता है जिसके फलस्वरूप सन्तान छोटी आयु में ही होने लगती है। यही कारण है कि भारतवर्ष जैसे गर्म देश में ठंडे देशों की अपेक्षा अधिक जन्म-संख्या है।

(२) धार्मिक रीति-रिवाज—भारतवर्ष में धार्मिक रीति-रिवाज जन्म-संख्या की वृद्धि में सहायक है। यहाँ हिन्दुओं में विवाह एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार है। धार्मिक दृष्टि से पुत्रोत्पत्ति स्वर्गस्थ पूर्वजों की आत्माओं की शान्ति मिलने का साधन समझा जाने के कारण एक हिन्दू पुरुष का विवाह आवश्यक माना गया है। इस प्रकार हमारे देश में धर्मशास्त्रानुसार कन्या का परिणयग्रहण संस्कार जीवन-शान्ति के

पूर्व ही हो जाना चाहिए, अन्यथा उसके माना बिना नरकबामी होने हैं। दण्डका परिणाम यह होता है कि छाती धातु से सन्तान हानि लगती है और उसके जीवनकाल में उसके द्वारा बहुत स बच्चा का जन्म मिल जाता है।

(३) सामाजिक रीति रिवाज—जन्म-मरणा बहुत कुछ सामाजिक अवस्था पर भी निर्भर है। जिस समाज में बड़े परिवार का सम्मान व गर्व होता है, मृत्युनाम्पति ईश्वर की दत्त मानी जाती है और इस पर नियन्त्रण करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर समझा जाता है तथा एक भ अधिक स्त्रियाँ स विवाह करने की प्रथा प्रचलित है, वहाँ जन्म-मरणा का अधिक होना स्वाभाविक है। संपुक्त-परिवार प्रणाली में भी दाल-विवाह की प्रथा को प्राप्ताह्न मिलता है क्योंकि कुटुम्ब के प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए स्वाधनम्भी होना आवश्यक नहीं है। उक्त मय बाँटें आरक्षण में पाई जाती हैं। अतः इस दल में जन्म-मरणा भी अधिक पाई जाती है। किन्तु अब हमारे देश में निश्चित व्यक्तियों के हृत्किरण में परिवर्तन आता जा रहा है।

हमारे विपरीत पाश्चात्य देशों में विवाह बड़ी धातु में होना, एक स अधिक स्त्रियाँ में विवाह नहीं कर सकत तथा अनेक स्थानों में एक पति व अनेक पुत्रों में स केवल एक ही होना को विवाह करने की सजा होन श्रादि कारणा न बड़ा जन्म-मरणा कम रहता है।

(४) राजनैतिक अवस्था—जन्म-मरणा की स्थितिबन्ता देश की सरकार की नीति पर भी निर्भर है। उदाहरणार्थ जर्मनी और स्वीडन आदि वैदिक देशों में जन्म मरणा क्षान के त्रिषे छप्पार छाग अधिक मलान उत्पन्न करक वान माना पिनामा को प्रोत्साहन, दावर और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। प्रजातन्त्र राज्यों में भी बध्म मताधिकार में जन्म-मरणा की वृद्धि का प्राप्ताह्न मिलता है।

(५) आर्थिक अवस्था—आर्थिक अवस्था का जन्म-मरणा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उच्च जीवन-स्तर वान अपना जीवन-स्तर बनाए रखन के लिए बड़ी धातु में विवाह करना है जिसके फलस्वरूप गलतान कम होती है। परन्तु नीचा जीवन-स्तर रखन वान मनुष्यों में निधनता और अग्निता के कारण दूरदायिता का अभाव होता है जिसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी जनसंख्या पर बड़ी निबन्धन नहीं होता। यही नहीं, बल्कि थोड़ा बड़ा ही काम पर लगा दिव्य जान है जिसमें माना-पितामा को धाय में बुद्धि होती है। इसलिए नीचे जीवन-स्तर वान बड़े धातु विवाह कर नत है। अस्तु, निम्न स्तर में यह कहा जा सकता है कि अल्प धातु व समान होन पर, समाज का जीवन-स्तर अतिनी हो नीचा होता है, जन्म-मरणा उनकी ही अधिक होती है।

भारतवर्ष में जन्म-मरणा—भारतवर्ष में उपर्युक्त सभी जन्म-मरणा दलान वान कारण उत्पन्नित हैं। भारतवर्ष एक गर्म देश है जहाँ ठंडे देशों की अपेक्षा स्त्री-पुरुष कम धातु में हो। युवा अवस्था प्राप्त कर नत हैं जिसके कारण शीघ्र विवाह कर लिया जाता है। यहाँ सामान्य प्रविवाहित रहन की प्रथा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि न उचित नहीं समझी जान के कारण हिन्दूधर्म में विवाह एक अनिवार्य सा मन्त्रार हो गया है। हिन्दू धर्म के अनुसार यदि किसी दम्पति व कोई पुत्र उत्पन्न न हो, तो पिण्ड, श्राद्ध आदि क्रियाएँ नहीं हो सकने के कारण पत्नीव में उसकी आत्माओं को पालन नहीं मिलती।^१ मुसलमानों में विवाह को अपनी अनिवार्यता नहा समझी

जाती, परन्तु फिर भी उनमें पुनर्विवाह आदि प्रथाएँ जन्म-मृत्यु को बढ़ाये रखने में सहायक हैं ।

हमारे देश की आर्थिक अवस्था भी ऐसी है जिससे जन्म-मृत्यु की वृद्धि को प्रोत्साहित मिलता है । यहाँ के अधिकतर लोग निर्धन हैं, उनका जीवन स्तर नीचा है तथा वे अशिक्षित हैं । ऐसी दशा में उनका विवेकहीन एवं भाव्यवादी होना स्वाभाविक है । अस्तु, भारत में जन्म-मृत्यु की वृद्धि वही प्रवृत्ति है ।

भारतवर्ष में प्रति हजार लगभग ३५ बच्चे पैदा होते हैं जिसके कारण जन्म-मृत्यु ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब में बढ़ रही है । इस प्रयत्न के ने भारतवर्ष की समस्या का दूसरा घना बसा हुआ देश बना दिया है जबकि पहला देश चीन है ।

(घा) मृत्यु-संख्या (Death Rate)—इसका अर्थ यह है कि किसी देश में किसी निश्चित अवधि में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ जितने मनुष्य मरते हैं । उदाहरणार्थ, यदि किसी देश में किसी वर्ष में मृत्यु-संख्या २० है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वर्ष उस देश में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ २० मनुष्यों की मृत्यु हुई । अन्य बातों के समान रहने पर जिस देश में मृत्यु-संख्या जितनी अधिक होगी, वही की जनसंख्या में वृद्धि उतनी ही कम दर से होगी ।

मृत्यु-संख्या के कारण (Causes of Death Rate)—मृत्यु-संख्या निम्न-लिखित कारणों से निर्धारित होती है ।

(१) सामान्य उन्नति की अवस्था—प्रगतिशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के कारण लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों में भी कराते हैं । वे स्वास्थ्य-वर्धक भोजन, स्वच्छ वस्त्र, सुते हवादार मकान, बीमारियों से बचने के उपाय आदि बातों पर पूर्ण ध्यान देते हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे दीर्घायु प्राप्त हैं । अस्तु, उन्नत देशों में मृत्यु-संख्या कम होती है ।

(२) विवाह की आयु—थोड़ी आयु में विवाह होने से दुर्बल मन्दाग उत्पन्न होता स्वाभाविक है । दुर्बल मन्दाग दीर्घमूल तक जीवित नहीं रह सकने के कारण मृत्यु-संख्या को बढ़ाती है । परिणत अवस्था में विवाह होने से ही दीर्घायु एवं हृष्ट पुष्ट मन्दाग हाती है ।

(३) आर्थिक अवस्था निर्धनता जीवन-स्तर को नीचे गिराती है । जिन लोगों का जीवन-स्तर नीचा होता है, वे प्रायः अशिक्षित भी रहते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का पालन करने करने में अपने-आपको प्रभावित पाते हैं । इसके परिणामस्वरूप निर्धनता के कारण उन्हें पीष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं होता तथा बीमारियाँ से बचने के उपायों के सामने वे बेबखिर रहते हैं । अस्तु, ऐसे लोगों का दीर्घायु होना सम्भव नहीं है ।

(४) प्राकृतिक प्रकोप—दुर्गम, बाढ़, भूकम्प, सूख को बीमारियाँ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भी मृत्यु-संख्या में वृद्धि हो जाती है ।

भारतवर्ष में मृत्यु-संख्या—भारत में मृत्यु-संख्या भी बढ़ी हुई है । प्रभावशाली हमारे देश में अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित, निर्धन और पिछड़े हुए अवस्था में हैं । उनका जीवन-स्तर नीचा है और वे सामाजिक उन्नति के बंधन में जकड़े हुए हैं । उनकी अज्ञानता स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की अवहेलना कराती है और उनकी

निधनता उह जीवन रखत वदावों म बचिन रखनी है । धार्मिक साध विभाग के कारण ही भारतवर्ष म आज भी अधिकांश जनसंख्या म वान विवाह प्रथा प्रचलित है जिनके कारण मृत्यु संख्या को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है । इस दृष्टि म प्रकृति का भी बड़ा प्रकोप है । यहाँ समय समय पर भूकम्प और बाढ़ आने है तथा बुधिया तो यहाँ की एक मायाय विषयता हो गई है । योष्टिक भोजनानि व श्राव म मनुष्य सामारिया का भुवाधिका करन म अपन धातका निवस पाता है अत वह सदैव सामारिया का निवार बना रहता है । एवम हैका आनि महामार्या म मर्या मनुष्य मान व बाढ उनारे जान है ।

(इ) प्रति-जीवन दर (Survival Rate)—मृत्यु संख्या से जन्म दर का धार्मिक का प्रति-जीवन दर कहन है । प्राकृतिक कारणों द्वारा होने वाला जन मर्या हसा पर ही निर्भर है ।

जब किसी देश की जन संख्या और मृत्यु संख्या समान होती है अर्थात् प्रति-जीवन दर समान होती है तो ऐसा जन संख्या स्थिर (Stable) जनसंख्या कहलाती है । जब जन्म संख्या और मृत्यु-संख्या म अन्तर होने व कारण जनसंख्या म युवाधिका होती है तो ऐसा जनसंख्या प्रवर्धित (Dynamic) जनसंख्या कहलाती है । जब जनसंख्या मृत्यु संख्या म अधिक होती है तब जनसंख्या का प्रवर्धित घटकर घनत्व (Positive) कहा जाती है और जब जनसंख्या मृत्यु संख्या म कम होता है तब वह घटकर ऋणात्मक (Negative) कहलाती है ।

२. स्थानिक वातावरण प्रवास (Immigration & Migration)

मनुष्य का एक देश से दूसरे देश को आगमन का आवास प्रवास कहन है । जब मनुष्य एक देश छोड़कर दूसरे देश का जात है तो उस प्रवास (Migration) कहत है और जब व दूसरे देश म आत है तो उस आवास (Immigration) कहा है । किसी देश की जनसंख्या पर आवास प्रवास का बड़ा प्रभाव पड़ता है । आवास से जन संख्या बढ़ता है और प्रवास म घटती है । जब आवास प्रवास म अधिक होता है तो वह अधिक आवास प्रवास की वास्तविक दर (Net Rate of Migration) कहलाती है । अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया नए देश कहलाते हैं क्योंकि उनकी सीमाएँ बड़े आसानी अधिक समय नए देश हैं फिर भी इन देशों में पर्वत जनसंख्या है । यह देशों की बड़ी हुई जनसंख्या मुख्य आवास प्रवास के कारण ही है । इनकी सीमा के पड़ोसी कई यूरोपवासी नए जा कर बस गये । इसी प्रकार आयरलैंड की जनसंख्या प्रवास में काफी कम हो गई है । परन्तु हमारे देश में आवास प्रवास का कोई महत्व नहीं है । हा अधिकांश राज्य म कुछ स्थानिकवासी नीति व व्यापार के लिए आकर अवश्य बस गये थे परन्तु उनकी संख्या नगण्य थी । विन्हा म भारतवासियों का साथ दुर्व्यवहार होने और रण मद की नीति व कारण प्रवास भी अब बहुत कम हो रहा है ।

१—अष्ट वर्षीय भवद्वारी नववर्षी च रोहिणी ।

दावर्षी भव कया तत् ऊव रजस्वता ॥ १० वा ५६—वागीदाय

माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population)

परिचय (Introduction)—उत्पत्ति के अथवा साधना की तुलना माल्थस का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की मात्रा अधिकतर श्रम के परिमाण पर निर्भर है। अतएव जनसंख्या की समस्या का भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। प्राधुनिक काल में जनसंख्या के प्रश्न पर भाषित दृष्टि में विचार करने वाला से सन प्रथम स्थान डब्लड ने पादरी माल्थस (१७६६-१८३४) का है। माल्थस का पिता बड़ा आलावादी था परन्तु माल्थस एक निरन्तावादी मध्यमवर्ग था जिसे सम्यता का मरिष्य व्यवहारमय प्रतीत होता था। बहुत प्रथम और अनुसंधान के पश्चात् माल्थस ने सन १७९८ ई० में जनसंख्या के सिद्धान्त पर निबन्ध नामक पुस्तक की रचना की जिसमें उसने निम्नलिखित बातों को स्थापना की। इन्हीं बातों के विवेचन को माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त कहते हैं।

माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की सारभूत बात

(१) किसी देश की जनसंख्या में साध सामग्री की सीमा को पार करके अधिक वेमसे प्राप्ति बढ़ने की प्रवृत्ति होती है—किन्तु प्रवार की बाधा न होने पर जनसंख्या साध पदार्थ की उत्पत्ति का प्रवेशा नहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि (Geometric Progression) के अनुसार बढ़ती है जसे २ ४ ८ १६ ३२ ६४ आदि और साध सामग्री समांतर वृद्धि (Arithmetic Progression) के हिसाब से बढ़ती है जसे १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ आदि। इस प्रकार जनसंख्या लगभग २५ वर्षों में दुगुनी हो जाती है किन्तु साध सामग्री (Food Supply) प्रवृत्ति निर्वाह साधना (Means of Subsistence) के लिए यह बात लागू नहीं है। साध सामग्री इस अनुपात में नहीं बढ़ती। अतः जनसंख्या में साध सामग्री की सीमा को पार करके प्राप्ति बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। पूर्वकाल में ऐसा हुआ है और भविष्य में भी ऐसा होने की सम्भावना है।

(२) जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति दो उपायों से रक्त सकती है—एक तो जनसंख्या के कम होने से और दूसरे मृत्यु संख्या में बढ़ने से। सधम ब्रह्मचर्य पालन बड़ी आयु में विवाह करना आदि साधनों से जनसंख्या कम हो सकती है। पतमान समय के सतति नियंत्रण (Birth Control) आदि दृष्टि साधन भी इसी प्रकार के प्राप्ति हैं। इस प्रकार के उपायों को माल्थस ने निवारक या कृत्रिम अवरोध (Preventive Checks) कह कर पुकारा है। मृत्यु संख्या की वृद्धि अनेक कारणों द्वारा हो सकती है जैसे युद्ध दुर्घति भूकम्प बाढ़ महामारी आदि। इन्हें उगने प्राकृतिक अवरोध (Positive Checks) कहा है।

(३) माल्थस का निष्कर्ष—माल्थस ने इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्यों को चाहिए कि वे जनसंख्या को समित न बढ़ने दें। उनका यह कहना था कि यदि लोग समय ब्रह्मचर्य आदि निवारक या कृत्रिम उपायों को काम में न लायें तो भविष्य में उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़गा यह तब कि उह पर्याप्त भोजन भी न मिल सकेगा। लोग भूखे रहेंगे तरह तरह के

बीमारियाँ फैलेंगी और इस कारण मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ने लगेगी। जनसंख्या का अधिक भाग इस प्रकार के प्राकृतिक उपायों से नष्ट हो जायगा। निवारक या कृत्रिम अवरोध (Preventive Checks) के अभाव में प्राकृतिक अवरोध (Positive Checks) द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या का रकना स्वाभाविक है। यतः स्वयं मनुष्य को इस विषय में सतक रहना चाहिए।

माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना

(Criticism of Malthusian Theory)

(१) माल्थस का सिद्धान्त पूर्णतया ठीक नहीं है—माल्थस के विचारों पर इङ्ग्लैंड, आयरलैंड आदि देशों में वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ा और उससे उन्हीं के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उस समय जनसंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। कृषि में उत्पत्ति ह्रास-प्रवृत्ति का प्रदर्शन प्रारम्भ हो चुका था। खाद्य सामग्री की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उचित उपाय लोगों को ज्ञान न थे। वास्तविक जीवन में प्रभोत्वपूर्ण उत्पत्ति नहीं पाई थी। यथायात के माध्यम से पुराने ढंग के जेजिमे के पतनस्वरूप खाद्य-सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों से मुक्तपूर्वक आयात नहीं की जा सकती थी। जनसंख्या के आधार पर माल्थस ने इस उपर्युक्त सिद्धान्त की स्थापना की थी। औद्योगिक क्रान्ति ने आर्थिक-जीवन का पूरापरा रूप बदल दिया है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक आविष्कार हो गये हैं जिनसे उत्पत्ति की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है। यथायात के माध्यम से वर्तमान उत्पत्ति होने में अब एक देश दूसरे देशों से खाद्य-सामग्री भेगा सक्ता है। एक सार वैज्ञानिक उपायों से जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और दूसरी ओर जोमा में सन्तान-निग्रह के कृत्रिम उपायों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इससे जनसंख्या कई देशों में काफी घट गई है। अतः माल्थस ने जो भावी जनसंख्या के विषय में भ्रान्त और अंधविश्वासपूर्ण चित्र पेशा था, वह वर्तमान समय में यथार्थ भिन्न नहीं है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण माल्थस के सिद्धान्त में जो पूर्ववत् सत्यता नहीं रही और न वह सब देना और सब कालों के लिए ठीक ही है।

(२) माल्थस ने जो जनसंख्या और खाद्य सामग्री की वृद्धि का अनुपात बताया है वह ठीक नहीं है—यह सिद्ध करना कठिन है कि जनसंख्या गुणोत्तर-वृद्धि और खाद्य सामग्री समान्तर-वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। इतिहास पर दृष्टि डालने से यह ज्ञान होता है कि खाद्य सामग्री में समान्तर अनुपात में नहीं अधिक वृद्धि हुई है। मानव वृद्धि वन द्वारा उत्पत्ति के अनेक नये उपायों द्वारा मासूम हो गये हैं जिनसे जनसंख्या की वृद्धि से भी अधिक होने लगी है। दूसरी ओर मनुष्यता तथा जीवन-स्तर के बढ़ने के साथ-साथ निवारक या कृत्रिम उपायों का महत्त्व भी बढ़ता जा रहा है। जीवन-स्तर ऊँचा होने से लम्बा में सन्तान कम पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे भावी सन्तान का जीवन स्तर नीचे न गिरे।

माल्थस के सिद्धांत विद्वत्-विज्ञान के प्रथम प्रयोगों का एक बहिष्कृत विशेषण था। यतः उसे इस प्रकार के गणितीय सम्बन्धों सूत्रों (Formulas) के प्रयोग का बड़ा शौक था।

(३) माल्थस की यह धारणा कि जनसंख्या लगभग २५ वर्षों में दुगुनी हो जाती है उचित प्रतीत नहीं होती है—संगार के किसी भी देश में अब तक जनसंख्या २५ वर्षों में दुगुनी नहीं हुई है। जनसंख्या को दुगुना होने में लगभग १८० वर्ष लगते हैं। अतः इस धारणा की पुष्टि इतिहास द्वारा नहीं होती है।

(४) सम्यता के विचार के साथ-साथ सतानीत्पत्ति भी कम हो जाती है—प्राचीन शास्त्र का नियम है कि ज्यो-ज्यो मनुष्य सम्यता की ओर अग्रसर होता जाता है, त्यों-त्यों उसकी सतानीत्पत्ति की शक्ति में ह्रास होता जाता है। मानसिक और नैतिक उन्नति के साथ-साथ मनुष्य की सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा कम होती जाती है। विदोपकर शिक्षित स्त्रियाँ कभी अधिक बच्चों की माता बनना पसन्द नहीं करती हैं। यदि एक शिक्षित एष सम्य दम्पति को एक कार (Car) बचवा बच्चे (Baby) में से कोई एक वस्तु पसन्द करने के लिए कहा जाय, तो वे निस्सन्देह 'कार' ही पसन्द करेंगे। माल्थस ने इस प्रवृत्ति पर कोई विचार नहीं किया। अस्तु, भविष्य में माल्थस ने जो अति-जनसंख्या होने का भय प्रकट किया वह निराधार है।

(५) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन होने से भी जनसंख्या घटती जा रही है—पुराने समय की भाँति अब बड़े परिवारों का होना इतनी गौरव की बात नहीं समझी जाती है। पैंक्री एक्ट और विवाह प्रचार से निर्धन मनुष्यों में जन्म-संख्या कम होने लगी है क्योंकि बच्चों का छोटी छाय में कारखानों में काम करना अब एक नाजूकी रूपावट हो गई है। अतः परिवार की छाय को बढ़ाने के लिए सतानीत्पत्ति की प्रवृत्ति मद्ध होती जा रही है। उच्च श्रेणी और मध्यम श्रेणी के लोगों में भी अपने जीवन म्तर को बनाये रखने की दृष्टि से अधिक संस्थान की प्रमिताया नहीं रहनी है। अतः वे भी यैन कैम प्रकार से जन्म-संख्या कम से कम रखने का प्रयत्न करते हैं।

(६) माल्थस ने उत्पत्ति-ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) के बारे में ठीक नहीं समझा—उसने इस नियम को सार्वदेशिक समझ कर भूल की। कृषि बला और लेडी के ढंगों में सुधार कर इस प्रवृत्ति को रोक जा सकता है तथा कारखानों की उत्पत्ति-वृद्धि एवं भाव-भामशी के आभाव से यह प्रवृत्ति निवृत्ति की जा सकती है।

(७) जनसंख्या में वृद्धि होने से श्रम की भी संख्या घटती है—जब मनुष्य मसार में आता है, तो वह केवल मुँह और उदर ही लेकर नहीं आता, बल्कि काम करने के लिए हाथ और बुद्धि वन भी लेकर आता है। अस्तु, यह सोचना भूल है कि जनसंख्या में वृद्धि सामा सामर्थियों को घुसाना है। कुछ हद तक जनसंख्या की वृद्धि साथ-साथ ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है, ऐसा प्रो० कैन का मत है।

(८) जनसंख्या की समस्या पर विचार करते समय देश की समस्त धनीत्पत्ति (Total Wealth) को ध्यान में रखना चाहिए न कि केवल छाव सामग्री की उत्पत्ति की ही—माल्थस ने इस सम्बन्ध में केवल साम-भामशो का ही विचार किया है। सम्भव है किसी देश में खाद्य-पदार्थों की कमी हो पर वह देश अपनी औद्योगिक वस्तुओं के बदले में कृषि-प्रधान देशों से खाद्य-भामशो मगा सकता है। इंग्लैंड के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। वहाँ मुद्रिकत से १६ प्रतिशत

जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न होने हैं। परन्तु वहाँ कारखानों में इतना माल तैयार होना है कि बड़ी मुश्किल में अन्य देशों से उम माल के बदले में खाद्य-सामग्रियों मेंगाई जा सकती है। अस्तु, खाद्य-पदार्थों की इतनी कम उत्पत्ति होने हुए भी वहाँ खाद्य-सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, और वहाँ के अनुप्या का जीवन स्तर भी तुलनात्मक दृष्टि से वही जैसा है।

माल्थस के सिद्धान्त में सत्यता के अद्य

(Elements of Truth in the Malthusian Theory)

इस प्रकार के दोष माल्थस के सिद्धान्त पर लगाए जाते हैं, और वे बहुत कुछ ठीक भी हैं। पर इतना यह साधन नहीं कि माल्थस का सिद्धान्त विस्तृत नहीं है। यह मन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण माल्थस के सिद्धान्त में अब पूर्ववत् मर्यादा न रही फिर भी उममें सत्यता का अद्य है। भारतवर्ष, चीन आदि देशों में माल्थस का सिद्धान्त पूरा रूप में लागू है। परन्तु यूरोप और अमेरिका आदि उन्नत देशों में यह सिद्धान्त विस्तृत प्रभावशाल्य हो गया है।

भारतवर्ष और माल्थस का सिद्धान्त—भारतवर्ष में माल्थस का सिद्धान्त पूर्णतया लागू है। भारतवर्ष में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शत ५० वर्षों में वहाँ जनसंख्या में लगभग ११ करोड़ की वृद्धि हो गई है। श्रमिता और निर्धनता के प्रतिरिक्त यहाँ की सामाजिक रीतियों और धार्मिक विश्वासों में जनसंख्या की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल रही है। विवाह करना अनिवार्य कार्य बन गया है। पुत्र प्राप्ति धार्मिक कृत्य समझा जाता है। सर्व साधारण में यह विचार प्रचलित है कि बिना पुत्र के पुरुषों में गति नहीं होती है। उष्ण जनजातों ने नगरों छोड़ी घातु में विवाह हो जाता है और नई धर्म-ग्रन्थ कन्या को दम वर्ग की घातु में विवाह कर देने का आदेश भी देते हैं। इन सब कारणों में यहाँ की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। किन्तु भारतवर्ष में विविध कारणों से कृषि तथा व्यवसाय ग्रन्थों की उत्पत्ति बहुत कम है। अतः इस देश में अति-जनसंख्या (Over-Population) की समस्या विद्यमान है। लोगों का जीवन स्तर मिरा हुआ है। मृत्यु-संख्या ग्रन्थों से बड़ी अधिक है। निवारक या दृष्टि अवरोधों का पूर्ण अभाव है। जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए कुमिल, महाभारी आदि प्राकृतिक उपायों का अथक प्रयोग मदैव बना रहता है। अस्तु, माल्थस का सिद्धान्त भारतवर्ष जैसे देशों में अद्य भी लागू है।

प्रो० टॉसिग (Taussig) के अनुसार “कैची जन्य-संख्या, कैची मृत्यु-संख्या, विध्वंसी हुई औद्योगिक दशाएँ, न्यून भूति, यह सब बातें माथ-साथ नत्ती हैं।”

यूरोप व अमेरिका और माल्थस का सिद्धान्त—ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, मध्य एशिया-अमेरिका आदि धनी और प्रगतिशील देशों में सम्पत्ति की वृद्धि जनसंख्या के अनुपात से अधिक हुई है, अतः वहाँ अति-जनसंख्या की समस्या विद्यमान नहीं है। साथ ही इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि रोकने में प्राकृतिक अवरोधों जैसे मृदु महाभारी आदि निवारक या दृष्टि अवरोधों जैसा देर से विवाह करना, समय, वृद्धाचर्य-पालन, मतनि-निग्रह आदि का पूर्ण हाथ रहा है। माल्थस के मथनानुसार सम्यता की उन्नति के माथ-साथ निवारक या दृष्टि अवरोधों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इन्हीं कारणों से इन देशों में माल्थस का सिद्धान्त असत्य सिद्ध हो रहा है।

सर्वोत्तम (आदर्श) जनसंख्या का सिद्धान्त (Theory of Optimum Population)

'सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त' जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धान्त माना जाता है। सबसे प्रथम प्रो० कॅनन (Cannan) ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया और प्रो० कार सौण्डर्स (Carr Saunders) का नाम भी इसके विकास के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है।

सिद्धान्त की परिभाषा

प्रो० कार सौण्डर्स इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं — "प्राथमिक दृष्टि में किसी देश में किसी विशेष समय और परिस्थिति में वही जनसंख्या का घनत्व सर्वोत्तम समझा जायगा जिसमें प्रति व्यक्ति की आय या धनोत्पत्ति अधिकतम हो और जनसंख्या के ह्रास की चटने या बढ़ने में प्रति व्यक्ति की श्रमिक आय या धनोत्पत्ति में न्यूनताधिकता हो जाय।"

अधिकतम जनसंख्या का सिद्धान्त यह बतलाना है कि किसी देश में किसी समय प्राथमिक साधनों की सम्पन्नता इतनी हो कि वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या रह सके और उसके प्रति व्यक्ति की श्रमिक आय अधिकतम हो। साधारण बोल-चाल की भाषा में इसे यों भी कह सकते हैं कि जनसंख्या भी अधिक हो और बसाने व खान पीने की भी खूब हो।

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि जनसंख्या और प्राथमिक साधनों के विकास की समरसि की सर्वोत्तम जनसंख्या कहने हैं। परन्तु यदि जनसंख्या इतनी अधिक हो कि प्राथमिक साधन पीछे रह जायें और वे उस सीमा तक जनसंख्या का भ्रंश-प्रकार निर्वाह करने में असमर्थ हो जायें, तो ऐसी जनसंख्या को अति-जनसंख्या (Over-Population) कहेंगे। निर्धनता, गिरा हुआ जीवन स्तर, भुखमरी, कार्य-कुशलता में ह्रास आदि अति जनसंख्या के कुछ भयंकर दुष्परिणाम हैं जिनका इलाज अति-जनसंख्या को उचित सीमा पर लाने पर ही हो सकता है। इसी प्रकार न्यून जनसंख्या की समस्या भी पाई जाती है। किसी देश की जनसंख्या इतनी कम हो कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधन प्राथमिक साधनों में पूरा सामन उठाया जा सके तो जनसंख्या की ऐसी घटबुट को न्यून-जनसंख्या (Under Population) कहेंगे। इसके भी वही दुष्परिणाम होंगे जो अति-जनसंख्या के। अतः हमारा उद्देश्य अति-जनसंख्या और न्यून जनसंख्या के परे सर्वोत्तम जनसंख्या का होना चाहिए।

माल्थस के सिद्धान्त और सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त की तुलना

(१) सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त में जनसंख्या और प्राथमिक साधनों द्वारा उत्पादन शक्ति में सम्बन्ध स्थापित किया गया है, जबकि माल्थस के सिद्धान्त में केवल जनसंख्या और साधन सामग्री के ही मध्य सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

(२) सर्वोत्तम जनसंख्या की सीमा स्थायी नहीं है। यह द्रव्यसि के साथ-साथ बदलती रहती है। अतः किसी देश में जनसंख्या की बढ़ने की कोई शैक्षणिक सीमा नहीं हो सकती।

(३) माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि का अमानक चित्र खींचकर तत्प्रावधान दुष्परिणामों से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। परन्तु किन्हीं परिस्थितियों में जनसंख्या की वृद्धि सामंजस्यकारी होती है। अतः सर्वोत्तम जनसंख्या में केवल इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि वांछनीय है अथवा नहीं।

(४) सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त की भाँति समय, वृद्धावस्था पालन आदि नैतिक उपदेशों से युक्त है। इसमें इस प्रकार की बात नहीं मिलती।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिये।
(रा० बो० १९५७)
- २—माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त हमारे देश में कहाँ तक लागू है ?
(म० बो० १९५६ पू०)
- ३—माल्थस (Malthus) के सिद्धान्त की समझाइय तथा उसकी आलोचना कीजिये।
(उ० प्र० १९५६)
- ४—माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिये।
सर्वोत्तम जनसंख्या का क्या सिद्धान्त है ?
(रा० बो० १९५४)
- ५—माल्थस के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये। क्या यह भारत पर लागू होता है ?
(रा० बो० १९५९)
- ६—जनसंख्या का आधुनिक सिद्धान्त क्या है ? माल्थस के सिद्धान्त से इसमें क्या अन्तर है ?
(रा० बो० १९५९)
- ७—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —
प्राकृतिक अवरोध और कृत्रिम अवरोध (उ० प्र० १९५०, ४९, ४७, ४८)
सर्वोत्तम जनसंख्या (रा० बो० १९४१ ४९)
नैसर्गिक तथा प्रतिबंधक निरोध (उ० प्र० १९६०, ५०)
प्रतिबंधक रोक (म० भा० १९५७)

‘एक राष्ट्र की सच्ची सम्पत्ति न उसकी भूमियो और न नदियो मे न उसके वना और राना मे न उगने पशुयो मे न उसके झोंरा मे निहित है, बल्कि उसके स्वास्थ्य और सुखी आत्मा और श्रम और बचा मे निहित होती है।’ —जी० सी० हिल्स

भारतवर्ष की जनसंख्या का आकार - सन् १९५१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ३५,६०,२८४०० है। इस प्रकार १० वर्षों में १०६ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। इसमें से पुरुषों की संख्या १८,३३,०५६५४ है और स्त्रियों की १७,२५,३०८३१ है। इस तरह १००० पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियों की औसत आती है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत संसार में चीन की छोड़कर अधिक आबादी वाला देश है। भारत की जनसंख्या सोवियत संघ (११ करोड़), उत्तरी अमेरिका (१२ करोड़), अफ्रीका (२० करोड़), दक्षिणी अमेरिका (११ करोड़) में अधिक है और सोवियत संघ को निकालकर यूरोप (३६६ करोड़) की आबादी से कुछ कम है। भारतवर्ष में संसार की कुल जनसंख्या का लगभग १५ प्रतिशत अर्थात् ३ मनुष्य निवास करते हैं।



संसार की जनसंख्या में भारत का स्थान

भारत के पुनर्गठित राज्य

‘राज्य पुनर्गठन विधेयक’ के अनुसार भारत में १४ राज्य और ६ केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश बनाये गये जिसकी स्थापना १ नवम्बर १९५६ को की गई। १ मई १९६० को तत्कालीन बम्बई राज्य का विभाजन करने दो नये राज्या—महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना का गई है। इस प्रकार इस समय भारत में १५ राज्य व ६ केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश हैं। नागलैण्ड की स्थापना हो जाने पर १६ राज्य हो जायेंगे।

१५ राज्यों के नाम इस प्रकार हैं—आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, मेसूर, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जम्मू व कश्मीर।

केन्द्र द्वारा शासित ६ प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं—देहली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान, एवं निकोबार द्वीप समूह, नवदीव एवं अमिनदीव द्वीप समूह।

राज्या और केन्द्र द्वारा प्रवासित श्रेश्ठा की कुल जनसंख्या भी एक दूसरे में भिन्न है। उत्तर प्रदेश, बम्बई, विहार और आंध्र की जनसंख्या जेप सभी इकाइयों की कुल जनसंख्या के बराबर है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। इसकी जनसंख्या जम्मु-कश्मीर, आसाम, केरल, उज्जाना और भैरूर की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। आंध्र में राजस्थान और पंजाब से अधिक है। बम्बई की जनसंख्या मध्य प्रदेश और मैसूर से भी अधिक है। दिल्ली की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दोनो द्वीप समूहों से भी अधिक है।

गाँवों और ग्रहों की जनसंख्या—भारत को ८२८ प्रतिशत जनसंख्या बेहाला में रहती है। बेहाला की जनसंख्या २६,५०,०४,२७१ और ग्रहों की ६,१८,२५,२१८ है।

जनसंख्या का पेशेवार विभाजन—सन् १९५१ की जन गणना की रिपोर्टों की नवीनता यह है कि इसमें समूहों आबादी को पेशे के अनुसार विभक्त किया गया है। समूहों आबादी को कृषिजीवी और अकृषिजीवी दो श्रेणियों में बाँटा गया है।

(अ) कृषिजीवियों की जनसंख्या

श्रेणी	आधितो रहित जनसंख्या
१—भूस्वामी	१६,७३,००,०००
२—जो भूस्वामी नहीं हैं	३,१५,००,०००
३—कृषि मजदूर	४,४७,००,०००
४—कैबल लगान जमान करने वाले भूस्वामी	५२,००,०००
(घ) अकृषिजीवियों की जनसंख्या	
१—कृषि के अनिर्दिष्ट अन्य उत्पादन काय करने वाले	३,७६,००,०००
२—व्यापारी	२,१२,००,०००
३—नौकरी आदि कार्य करने वाले	४,२८,००,०००
४—मानावात जीवी	५६,००,०००

जनसंख्या की वृद्धि (Growth of Population)

(१८६१-१९५१)

(लाक्षा में)

जनसंख्या वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि (+) या कमी (-) जन दशक में
१८६१	२,३५६	
१९०१	७,३५५	-४
१९११	९,४६०	+१२५
१९२१	२,४८१	-६
१९३१	२,७५५	+२७४
१९४१	३,१२८	+३७३
१९५१	३,५६६	+४४१

भारतवर्ष में सबसे पहले अनुष्य गणना सन् १८७२ ई० में हुई थी। तब से प्रत्येक दसवें वर्ष गणना होती है। कुछ वर्षों के जन गणना के एक ऊपर तात्विका में दिखे गये हैं। इन वर्षों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या की वृद्धि में बड़ी अनियमितता (Irregularity) रहती है। समय-समय पर मरुत और मृत्युमारियों के प्रकोप ही इस अनियमितता के मुख्य कारण हैं। सन् १९२१ में तीस वर्षों के भीतर लगभग ११ करोड़ आसानी बढ़ी। सन् १९२१ के पहले और बाद की वृद्धि में पर्याप्त अन्तर रहा है। सन् १९२१ के पूर्व जनसंख्या घटान, महाप्राणी प्रादि में कम होती रही तथा साधारण जनसंख्या में अधिक उत्पन्न होता रहा, परन्तु बाद के वर्षों में छायाज का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि में पीछे रह गया। सन् १९८१ में १९५१ के भीतर जनसंख्या में ४५ करोड़ की वृद्धि हुई जो १२५ प्रतिशत होती है।

भारतीय जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात—औद्योगिक देश में एक हजार पुरुषों के पीछे २४७ स्त्रियाँ हैं। भारत के सभी राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है, परन्तु उड़ीसा, मनीपुर, मद्रास, मॉगल्टु केंद्र में स्त्रियाँ की संख्या पुरुषों से अधिक है जो क्रमशः प्रति हजार पुरुषों के पीछे १००२ १००६, १००८ और १०७६ है। पुरुषों की प्रवेशा स्त्रियों की संख्या मरने कम अद्यतन निवासों में है यहाँ एक हजार पुरुषों के पीछे ९२१ स्त्रियाँ हैं। स्त्रियों में भी स्त्रियों की संख्या कम है क्योंकि एक हजार पुरुषों के पीछे ७६८ है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, गुजरात और केन्द्र राज्य में भी स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरुषों के पीछे ९०० से कम है।

भारतीय जनसंख्या की विशेषताएँ—भारतीय जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) भारत की जनसंख्या चीन की छोड़कर समस्त में सबसे अधिक है। समस्त के अनुष्य यही निष्कर्ष करने हैं।

(२) यहाँ की जनसंख्या में दुर्बल या महाप्राणियों के कारण बड़ी अनियमितता रही है। फिर भी यह पचास वर्षों में अविभाजित भारत में १६ करोड़ की वृद्धि हुई।

(३) भारत के समस्त भाग में जनसंख्या की वृद्धि समान नहीं रही है। जैसे दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग की जनसंख्या अधिक बनी।

(४) भारतीय जनसंख्या देश के आर्थिक माधन के विकास की प्रथम अधिक तेजी से बढ़ रही है।

(५) भारत में आर्थिक जनसंख्या ३४.३ और मृत्युसंख्या २४.२ प्रति हजार है जो समस्त में सबसे अधिक है। इसी प्रकार अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षा भारत में औसत जीवन का समय बहुत कम है अर्थात् २७ वर्ष है।

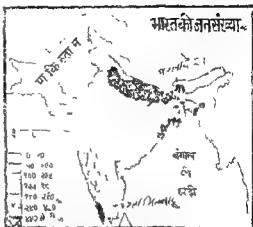
(६) जनसंख्या के घनत्व में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, जैसे मरुभूमि भाग में १ वर्ग मील में केवल १० अनुष्य ही रहते हैं जबकि बंगाल जैसे घनत्व में एक राज्य में ८०० अनुष्य प्रति वर्ग मील रहते हैं।

(७) अनुष्यों के बने के बटवारे में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणार्थ ७० प्रतिशत में भी अधिक जनसंख्या खेती पर निर्वाह करती है।

(८) पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात में भी अन्तर पाया जाता है। साधारणतया देश में एक हजार पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। पंजाब में स्त्रियों की संख्या ८४७ है और मद्रास में १००८ है।

जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)—किमी स्थान

पर औसतन प्रति वर्ग मील जितने व्यक्ति रहते हैं उसे उस स्थान की जनसंख्या का 'घनत्व' कहते हैं। यदि पंजाब की जन-गणना का घनत्व ८०० है, तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ प्रति वर्ग मील आठ सौ अनुषंग रहते हैं। गणस्त भारत का औसत घनत्व ३१२ है, परन्तु घनत्व का औसत भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। एक और तो दिल्ली राज्य में घनत्व ३०१७ और केरल में १०१५ और दूसरी ओर अडमन व निकोबार द्वीप में यह १० और मीरापूर में ३८ ही है। निम्नांकित तालिका द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का औसत घनत्व दिखाया गया है:—



जनसंख्या के घनत्व के अनुसार राज्यों का क्रम

क्रम संख्या	राज्य	घनत्व	क्रम संख्या	राज्य	घनत्व
१.	केरल	९०७.८	१२.	राजस्थान	१२०.९
२.	पंजाब	७८७.२	१३.	आंध्रप्रदेश	१०५.९
३.	मद्रास	५९९.९	१४.	जम्मू व काश्मीर	४७.५
४.	बिहार	५७३.५	केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र		
५.	उत्तर प्रदेश	५५७.३	१.	दिल्ली	३०१०.३
६.	पंजाब	३४३.२	२.	चिपूर	११५.७
७.	मध्य	२९२.०	३.	हिमाचल प्रदेश	९३.७
८.	संयुक्त	२६०.४	४.	मणिपुर	९९.९
९.	बम्बई	२५३.९	५.	लक्षद्वीप व मन्नार	०.१
१०.	उड़ीसा	२४२.७	६.	अडमन व निकोबार	०.८
११.	मध्य प्रदेश	१५२.५			

जनसंख्या के घनत्व के अनुसार ससार के कुछ देश

देश	घनत्व	देश	घनत्व
१. हंगेरी (ओदरलैण्ड)	८२५.३	७. भारत	३१२
२. येलनिशम	७३४.४	८. स्विट्जरलैंड	२८८
३. जपान	५७५.४	९. फ्रांस	१६२
४. इङ्ग्लैंड	५३७.८	१०. अमेरिका	४६
५. जर्मनी (पश्चिमी)	४०२.७	११. आस्ट्रेलिया	३
६. इटली	४०४.६	१२. ननाडा	३

जनसंख्या के घनत्व की विभिन्नता के कारण—जनसंख्या के वसाध का समशी घना उनके घनत्व में मलता है। कुछ राज्यों की तो जनसंख्या बहुत ही घनी है, जवनि दूसरे राज्यों की जनसंख्या बहुत ही कम है। घनत्व की इस विभिन्नता के कई कारण हैं, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :—

१. भूमि का घरातल (Configuration)—समतल भूमि पर भूमि प्रचार खेती होने के कारण वहां घनी जनसंख्या का निर्वाह हो सकता है, जैसे बंगाल, बिहार आदि। पहाड़ी भूमि में खेती में बाधनाई होने के कारण जनसंख्या का घनत्व भी गिर जाता है। यही कारण है कि दक्षिणी पठार की आबादी कम है।

२. मिट्टी (Soil)—उपजाऊ भूमि में अधिक जनसंख्या का निर्वाह हो सकता है, जैसे—मिथाना सलाई हुई दुग्ध मिट्टी।

३. वर्षा (Rainfall)—भारत में जनसंख्या का घनत्व अधिक वर्षा के साथ-साथ चलता है। भारतवर्ष में उत्तम जनसंख्या के घनत्व के लिए लगभग ४०" वर्षा पर्याप्त है। इस औसत वर्षा में कृषि और जल के कारण जनसंख्या के घनत्व का वितरण भी घट जाता है। मरुस्थली भागों में जनसंख्या का घनत्व इसी कारण कम होता है।

४. सिंचाई (Irrigation)—जहाँ वर्षा की कमी को पूरा करने के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ जनसंख्या के घनत्व पर बड़ी प्रभाव पड़ता है जो उत्तम वर्षा का पड़ता है।

५. जलवायु (Climate)—जनसंख्या के घनत्व पर जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भूमि के उपजाऊ तथा अधिक वर्षा होने पर भी यदि वहाँ का जलवायु अस्वास्थ्यकर है, तो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होगा। यही कारण है कि आसाम में अस्वास्थ्यकर जलवायु होने के कारण जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है।

६. सुरक्षा (Security)—जिन स्थानों में जन-धन सुरक्षित होता है वहाँ आबादी का घनत्व अधिक होता है। आजकल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जन-धन की सुरक्षा के अभाव में जनसंख्या का घनत्व भी कम है।

७. यातायात (Transport)—सस्ते व शीघ्र यातायात के साधनों के कारण मार्केटिंग तथा व्यापारिक व्यवस्थाओं में सुधार हो जाने के कारण जनसंख्या का घनत्व भी घटित हो जाता है। यातायात के साधनों की कमी के कारण मध्य प्रदेश और आसाम में जनसंख्या का घनत्व कम है।

८. आर्थिक साधन (Economic Resources)—जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ आदि जैसे आर्थिक साधन विद्यमान होने हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जैसे—पंजाब और बिहार में खनिज स्थानों की अपेक्षा कोयला और ताँबा की खानों के निम्न जनसंख्या अधिक है।

९. आवास-प्रवास (Immigration & Migration)—प्रायः नये जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है और प्रवास से कम होता है।

१०. औद्योगिक विकास (Industrial Development)—वृष्टि विकास की अपेक्षा औद्योगिक विकास में अधिक जनसंख्या का निर्वाह हो सकने के कारण औद्योगिक उपग्रह वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। बम्बई, जमशेदपुर, कोलकाता और कलकत्ता आदि इसी बात की पुष्टि करने हैं।

स्वास्थ्य और जन्म-मरण के आँकड़े

स्वास्थ्य (Health)—किसी देश की आर्थिक दशा वहाँ के निवासियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर होती है। भारतवर्षी प्रायः दुर्बल होते हैं। उनका स्वास्थ्य अन्य उन्नत देशों के मनुष्यों की अपेक्षा गिरा हुआ है। निर्धनता, प्रदूषण, अविज्ञान इसके प्रधान कारण हैं। प्रदूषण भारतवासियों का जीवन-मरण नीचा है। गुल व चिल्ला वस्तुओं का तो प्रश्न ही नहीं, उन्हें भर-पेट भोजन तथा शरीर रक्षा के लिए पर्याप्त वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होने। रहने के विषये कच्चे, गन्दे, अपेक्षे और सरसकट घरों का भरा। ऐसी प्रवृत्ति में उनके अच्छा स्वास्थ्य बनाय रखना और भयंकर बीमारियों का सामना करने की आशा दूरक्षा मान ली है। भारतवर्ष में प्रायः इन बीमारियों का प्रकीर्ण विशेष पाया जाता है—ऐन्जा, प्लेग, मलेरिया, बेचन, मोतीमर, कालाज्वर, टुबरकुलस, क्षयरोग आदि।

प्रसिद्ध भारतीय मेडिकल रिसर्च कांफ्रेंस का यह निष्कर्ष है कि रोजी जा सकने वाली बीमारियों से औसतन ५० में ६० लाख मनुष्यों की मृत्यु प्रतिवर्ष भारत में होती है, और इसी कारण औसतन प्रति व्यक्ति के वर्ष में दो या तीन मास मर जाते हैं। इसमें औसतन प्रति व्यक्ति की कार्य कुशलता में २० प्रतिशत ह्रास होना बताया गया है। भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से केवल २० प्रतिशत ही बच्चे-बानों की आयु तक पहुँच पाते हैं।

भारतवासियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निर्धनता निर्मूल नर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा माय-हीमाय शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। प्रचार द्वारा जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों का ज्ञान कराना भी स्वास्थ्य सम्पादन के लिए आवश्यक एवं आवश्यक वस्तु सभी जानते हैं। स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने वाले योग्य व्यक्तियों और सुसज्जित संस्थाओं का पूर्ण प्रभाव है। प्रभु, स्वास्थ्य-सम्बन्धी अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान कर भारतवासियों के स्वास्थ्य सुधारन की योजनाओं को राज्य द्वारा प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

जन्म मरण के आँकड़े (Vital Statistics)—जन्म मरण सम्बन्धी सभी बातों के आँकड़ों को धर्मशास्त्र में वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। भारतवर्ष में जन्म मरण सम्बन्धी सम्पूर्ण म गवने अधिक है, इस बात का फल निम्नलिखित तालिका में चलता है —

देश	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
भारत	२३	२२
इटली	२७	१७
जापान	२३	६
फ्रांस	१८	१६
युनाइटेड किंगडम	१७	१०
जर्मनी	१७	११

भारत में अधिक जन्म-मरण के कारण—भारत में अधिक जन्म-मरण होने के कारण निम्नलिखित हैं —

(१) विवाह की अनिवार्यता (Universality of Marriage)—भारतवर्ष में, विधवाया हिन्दुवा स्त्री, विवाह कर पुनः प्राप्त करवा कर पवित्र धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। क्योंकि इसमें बड़े विदेशों में प्रचलित है कि बिना पुनः के परलोक में मुक्ति नहीं होती। अतः, विवाह की अनिवार्यता जन्म-मरण की वृद्धि में सहायक है।

(२) लघु विवाह करने की प्रथा (Early Marriage)—प्रचलित प्रथा के अनुसार देश के लगभग ६० प्रतिशत विवाह अल्प आयु में ही हो जाते हैं जिससे मनुष्यसंख्या में वृद्धि हो जाती है।

(३) निवारक या कृत्रिम उपायों का अभाव (Absence of Preventive Checks of Birth-Control)—पारम्परिक देश में धार्मिक मूल्यों निहित हैं जिनसे जन्म-मरण में वृद्धि हो जाती है जिससे जनसंख्या बढ़ती है। परन्तु भारत में विधवा, अविवाहिता और धार्मिक विचारों के कारण कृत्रिम उपायों का प्रयोग नहीं किया जाता। पूर्वजों का स्मरण होकर मार्ग धर्मानुसंगिक प्रथाओं का भी कोई सहज नहीं समझते।

(४) निर्धनता (Poverty)—देश में निर्धनता के मोक्ष जीवन-स्तर के कारण मनुष्यों में आध्यात्मिक और दूरदर्शिता का अभाव हो गया है। दूरदर्शिता का अभाव में उन्हें अधिक मनुष्यों के जीवन-पापों में शिथिलता की कोई विचार नहीं रहता। इससे अनिश्चित निर्धनता का कारण अल्प आयु में ही मनुष्य समाप्त हो जाता है, अतएव निर्धनता और अधिक जन्म-मरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(५) अशिक्षा और पिछड़ी हुई देश (Illiteracy and Backwardness)—अशिक्षा और पिछड़ी हुई देश में जन्म-मरण का अधिक होना

स्वाभाविक है। शिक्षा मनुष्य को कर्त्तव्य पगल्लु बनाती है, अनिष्टा मनुष्य को विपरीत पाठ पठाती है। अन्तु, जन्म-संख्या बढ़ाकर अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करना अनिष्टा का ही कार्य है।

(६) गर्म जलवायु (Warm Climate)—देश की गर्म जलवायु के कारण लड़कियों का शीघ्र विवाह कर दिया जाता है।

भारत में अधिक मृत्यु-संख्या के कारण—भारतवर्ष में मृत्यु-संख्या के अत्यधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं :-

(१) स्थायक निर्धनता (Chronic Poverty)—निर्वनता के कारण खाने-पीने की सचछी कन्तुएँ उपलब्ध नहीं होती जिनके कारण मनुष्यों में बीमारियों का सामना कर पिकस प्राप्ति करने की सामर्थ्य नहीं रहती।

(२) महामारियों का प्रकोप (Prevalence of Epidemics)—मलेरिया, प्लेग, इन्फ्लूएन्जा, क्षय रोग आदि भयंकर बीमारियाँ द्वारा प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या में भारतवासियों की मौत के घाट उतारे गये हैं।

(३) अशिक्षिता (Illiteracy)—इसके कारण लोग स्वस्थ और दीर्घायु सम्बन्धी विषयों से अनभिज्ञ रहते हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव (Lack of Medical Facilities)—चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं का, विशेषतया गाँवों में, पूर्ण अभाव होने के कारण मृत्यु-संख्या अधिक होना स्वाभाविक है।

मृत्यु-संख्या की दो मुख्य विशेषताएँ—भारतवर्ष में मृत्यु-संख्या की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—एक तो क्रिया की अत्यधिक मृत्यु संख्या और दूसरी जैसी बाल-मृत्यु-संख्या।

भारत में स्त्री-मृत्यु—भारत में स्त्रियों की मृत्यु-संख्या बहुत अधिक है। उनकी मृत्यु विशेषतया प्रसवोत्पत्ति के समय १५ से ४० वर्ष की आयु के बीच में अधिक होती है, इसके अतिरिक्त शारीरिक निम्नलिखित हैं :-

(१) सामाजिक कुप्रथाएँ—पर्व प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों को मराने की चाहतदारियों में बन्द रहना पड़ता है जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वच्छ वायु, सूर्य का प्रकाश तथा उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होता। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वे अल्प आयु में ही बाल का शम हो जाती हैं।

(२) संस्था स्त्री जीवन—बहुत वर्षों के संगोम जीवन पड़ा संस्था समझा जाता है प्रत्यः उनके स्वास्थ्य के बारे में उचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसी कारण निम्न-बाल में भी बालिकाओं के पावन-पोषण की उपेक्षा की जाती है।

(३) अल्प आयु में विवाह होना—बाल विवाह की कुरीतियों के कारण लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता है। उनका अर्पणिकर प्रवृत्ति में विवाह होता उन्हें निर्वन और रोग-ग्रस्त बना देता है। स्वायत्त-तुल्यता, राज-प्रभुता और अन्य अनेक प्रकार के रोग युवावस्था ही में उनके जीवन को समाप्त कर देते हैं।

(४) अशिक्षित दाइयाँ—प्रसव-काल में अशिक्षित दाइयाँ अपने गहन और क्षतिकारी उपायों के प्रयोग में कई एक स्त्रियों के जीवन को नष्ट करने में काम देती हैं।

भारत में स्त्री और बाल मृत्यु संख्या को कम करने के उपाय (Remedies)

(१) विवाह सम्बन्धी शरद्विषयों में काम में सतत और विवाह को प्रायु बढ़ाना अति आवश्यक है ।

(२) प्रसूति द्रव्यों की स्वच्छता और विशुद्ध दवाओं की सेवाएँ तथा माधुर्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ सर्व माधुर्य को उपलब्ध होनी चाहिए ।

(३) स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों, अतानर्निग्रह के दुर्निमित्तों और निम्न पारम पोषण के नियमों की जानकारी जन साधारण को कराना लाभदायक सिद्ध होगा ।

(४) बच्चों के लिए अफीम आदि मादक द्रव्यों के प्रयोग का निषेध होना चाहिए ।

(५) लकड़ों और औद्योगिक केन्द्रों में मशीन व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । गाँवों में भी स्वच्छ पीने के जल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(६) कुर्बान आदि प्रौढियों या निम्न वितरण और अनिवार्य टीका लगाने को धनसहायता देनी चाहिए ।

(७) स्त्री के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहिए ।

(८) दरिद्रता को दूर करने वाले समस्त उपायों का सरकार द्वारा प्रयोग निश्चित आवश्यक है ।

भारत में औसत जीवन काल (Average Life in India) — उपर्युक्त प्रतिफल दशांश में भारतीयों का औसत आयु होना स्वाभाविक है । औसत आयु देश की आर्थिक अवस्था का एक मुख्य कारण है । भारतवर्ष में मृत्यु का औसत जीवन-काल केवल २७ वर्ष का ही है जबकि न्यूजीलैंड के मनुष्यों का ७० वर्ष, गणतन्त्र अमेरिका

देश	औसत जीवन काल
न्यूजीलैंड	७० वर्ष
म. रा. अमेरिका	६५ "
ब्रिटेन	६२ "
जर्मनी	६२ "
फ्रांस	५७ "
जापान	५७ "
भारत	२७ "

का ६५ और इंग्लैंड का ६२ वर्ष है । तुलनात्मक दृष्टि में औसत जीवन काल का अध्ययन नीचे दिये गये चित्र द्वारा भली-भाँति हो सकता है । जीवन-काल का विषय हमारे लिये बड़ा महत्व रखता है । यदि हमारी औसत आयु बढ़ जाय तो हम अधिक कार्य एवं जीवित रह कर काम कर सकेगे जिससे देश का अधिक भव्य हो सकेगा —

(२) यूरोप के देना की अपेक्षा भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व (Density) बहुत कम है, इसलिए यहाँ प्रति जनसंख्या होना नहीं कहा जा सकता। परन्तु इतनी कम जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ की धार्मिक पिछड़ी हुई अवस्था में भार स्वल्प है।

(३) प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना प्रति जनसंख्या की समस्या को घुट नहीं करता है। लेकिन जो कुछ आय में वृद्धि हुई है वह नहीं के बराबर है।

प्रति-जनसंख्या के पक्ष की बातें

(१) मान्यता का जनसंख्या का निम्नलिखित भारतवर्ष में पूर्णतया लागू होता है। यहाँ विवाह की प्रतिबाधना, मलिन-निग्रह के निवारक या वृद्धिमत्त उपारों का प्रभाव उत्पत्ति-ज्ञान नियम की रोकने की सम्मर्पण रुझान, दूधपन आदि का प्रयोग औद्योगिक पिछड़ी हुई अवस्था के कारण मान्यता का निम्नलिखित निम्नलिखित निम्न हो रहा है। अतः इस आधार पर भारत में प्रति जनसंख्या बढ़ना अनुचित नहीं होगा।

(२) सर्वोच्च उन्मुखता के निम्नलिखितानुसार भी प्रति-जनसंख्या का होना निम्न होता है। जनसंख्या देश के धार्मिक गणनों के विकास में वही अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है।

(३) उपरोक्त होने वाली जाति नामों द्वारा भी प्रति-जनसंख्या निम्न होती है। श्री १० के ० वाटन के अनुसार जनसंख्या १ प्रतिगण बढ़ी है जबकि साठ पचासों के उत्पादन में केवल ०-६१ प्रतिगण ही वृद्धि हुई है। देश के विकास के कारण जाति पचासों में और भी स्थानांतरण आ गई है। अतः, बड़े मात्रा में विदेशों में साठ पचासों में स्थानांतरण पटना है।

(४) सेवा का छोटे-छाट टुकड़ों में बँटा हुआ होता, मलिन-निग्रह धर्मियों की संख्या की वृद्धि आदि के ऐसे अप्रत्यक्ष प्रभावों भारत में प्रति-जनसंख्या का होना निम्न करने हैं।

प्रति-जनसंख्या की समस्या को सरल करने के उपाय

(१) बालन द्वारा सामाजिक रीति-रिवाजों में सुधार कर विवाह की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक है।

(२) मलिन-निग्रह के वृद्धिमत्त उपारों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। परिवार योजना (Family Planning) का प्रचार किया जाय।

(३) शिक्षा का प्रसार प्रति आवश्यक है।

(४) धार्मिक नामों का विकास—वृद्धि, उद्योगधर्म और सामाजिक व नववाद के नामों की उत्पत्ति होना परम आवश्यक है। यही दृष्टिगत-भारत के विकास कोष है।

(५) धनी आवासीय जाने लोग कम आवासीय वाले भाग में जाकर बन सकते हैं।

(६) भारत में जिन वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता में अधिक है (जैसे चाय, मसूर आदि), उन्हें विदेशों को निर्यात कर उनके बदले में रुपया न लेकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाय।

(७) चरकवन्दी धर्मों को छोटे-छोटे सेवा की बिनाबर बड़े सेवक बनाने की बात नामों की प्रोत्साहन देने में वृद्धि की उत्पत्ति हो सकती है।

(८) नुटीर व्यवसायों का पुनरुत्थान भी एक आवश्यक आर्थिक मुद्दा है। विशेषतया देहली में उपर्युक्त नुटीर व्यवसायों की स्थापना होनी चाहिये।

(९) प्रान्तीयता एवं जातीयता को भावना को मखून नष्ट किया जाय।

(१०) नगरों की प्रशिक्षण, याता की उन्नति का पूरा ध्यान रखा जाय।

जनसंख्या और योजना—द्वितीय योजना में परिवार नियोजन (Family Planning) के निम्ने रत्ने मये ४-६७ करोड़ रुपये य मे ४ करोड़ रुपये केन्द्र के नियम तथा ६७ लाख रुपये राज्यों के नियम निर्धारित किये गये हैं। इसी योजना काय में २,००० उपचारालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोल जायेंगे। सन् १९५६ में १९६० तक ३१३ ग्रामीण तथा ६६५ ग्रामीण उपचारालय स्थापित किये जा चुके हैं। परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के निम्ने केन्द्र में एक 'उच्चाधिकार परिवार नियोजन मण्डल' स्थापित किया गया है। जनता को प्रवृत्तिकाओं, प्रदर्शिनियों तथा चलचित्रों की सहायता से परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों से अवगत कराया जा रहा है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर मीडियम परीक्षाएँ

- १—जनसंख्या के घनत्व का अर्थ समझाइए। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में यह भिन्न भिन्न क्या है? कारण लिखिये। (प्र० वा० १९५७ ५५, उ० प्र० १९५५ ५२)
- २—भारत की वर्तमान जनसंख्या क्या है? क्या भारत में जनसंख्या का आधिक्य है? कारण सहित लिखिये। (सागर १९५६)
- ३—भारतीय जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के निम्ने किन उपायों की निवारणें करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में आधिक्य को मुक्त करने की कितनी श्रम कर सकते हैं?
- ४—भारत में बहुत अधिक और बहुत कम घनी आबाधिका के उदाहरण पाये जाते हैं। जनसंख्या के घनत्व के ऐसे बड़े अंतरों के कारणों को समझाइये। क्या आपका इस विचार से आप सहमत हैं कि भारत में जनसंख्या अत्यधिक है? अपने उत्तर के प्रमाण भी दीजिये। (प्र० वा० १९५६)
- ५—भारत के विभिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व भिन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं? देश के विभाजन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। (उ० प्र० १९५४)
- ६—भारत में विशेषतया औद्योगिक क्षेत्रों में बाल श्रम के क्या कारण हैं? इस कोष को कम करने के उपाय क्या-क्या हैं? (उ० प्र० १९५४)
- ७—जनसंख्या का घनत्व से आप क्या समझते हैं? वे क्या तथ्य हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रभावित होता है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। (प्र० वा० १९५५, ५३, ५६, ५१)
- ८—विभिन्न देशों में जनसंख्या में वृद्धि के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए। (रा० वा० १९५३)
- ९—भारतीय जनसंख्या के घनत्व सम्बन्धी प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। क्या आप इन सामान्य मत से सहमत हैं कि भारत में अनावधिक्य है? स्पष्ट कीजिए। (दिल्ली हा० में १९५१)

श्रम की कार्यकुशलता का अर्थ

श्रम की कार्यकुशलता का अर्थ उसकी उत्पादन-शक्ति में है। कार्यकुशलता का सम्बन्ध श्रमजीवी के उद्योग से है जिससे द्वारा वह एक निश्चित अवधि के भीतर अधिक कार्य भली प्रकार सम्पन्न कर सकता है। किसी भी श्रमजीवी की कार्यकुशलता की परीक्षा इन दो बातों से की जा सकती है—(क) उत्पादन की मात्रा व किस्म, और (ख) उत्पादन का समय। श्रम की कार्यकुशलता एक सापेक्षिक पद (Relative Term) है और इसका प्रयोग तुलनात्मक अर्थ में ही होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक घण्टा में निश्चित समय में अधिक उत्पादन करे या दूसरा में पढ़ने कार्य समाप्त कर देने प्रभवा उसका उत्पादन अधिकतर हो, तो वह दूसरा की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल कहा जाता है। दो श्रमजीवियों की कार्यकुशलता की तुलना के लिए यह आवश्यक है कि उन दोनों के पास एक-दूसरे सामग्री, एक-दूसरे यन्त्र और एक-दूसरे कार्य-अवस्था हो। अन्य बातें समान हान पर, श्रमजीवियों की कार्यकुशलता का निर्णय उस अन्तर में कर सकते हैं जो एक निश्चित समय में और उनकी उत्पादन की मात्रा और किस्म में पाया जाता है।

यह तो उम्मीद है कि सब श्रमजीवियों की कार्यकुशलता समान नहीं होती—किसी में कम और किसी में अधिक। एक ही काम में एक-दूसरे दशा में काम करने वाला में वे प्रत्येक का उत्पादन भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण यही है कि श्रमजीवियों की उत्पादन-शक्ति भिन्न भिन्न है। किसी भी देश के उत्पादन के परिमाण और किस्म पर वहाँ के श्रमजीवियों की कार्यकुशलता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतएव यहाँ हम कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाली चीजों का अध्ययन करेंगे।

कार्यकुशलता निर्णय करने वाली बातें

(Factors Determining Efficiency)

दो बातें श्रमजीवियों की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालने वाली अनेक चीजें हैं, परन्तु अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से उन्हें निम्नलिखित में बाँटा जा सकता है—

- (प्र) श्रमिकों की कार्य करने की योग्यता और इच्छा को प्रभावित करने वाली बातें।
- (प्र) व्यवस्थापक की व्यवस्था करने की योग्यता को प्रभावित करने वाली बातें।

(ग) धर्मिकों की कार्य करने की योग्यता और दृष्टि

धर्म की दृष्टता धर्मिका को कार्य करने की योग्यता और दृष्टि पर निर्भर है। यदि किसी व्यक्ति में काम करने की योग्यता तो हो पर दृष्टि न हो यथवा दृष्टि तो हो पर योग्यता न हो तो वह व्यक्ति कार्यकुशल नहीं हो सकता। अस्तु, हम नीचे उन्हीं माना का वर्णन करेंगे जो इन दोनों को प्रभावित करता है।

१. जातीय एवं वैश्व गुण (Racial & Hereditary Characteristics)—धर्मिक अपने माता पिता और अपने जाति से कुछ गुणों को प्राप्त करता है। इन गुणों का उसकी कार्यक्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ कारण है कि इंग्लैंड और नॉर्वे के मत्स्यह स्विट्जरलैंड के घड़ी बनाने वाले और इटली के कलाकार आज तक भी समार में प्रसिद्ध हैं। भारत में जाति प्रथा द्वारा इन जातीय एवं वैश्व गुणों का रखा होतो है। जैसे—ब्राह्मण का मानोपायन से अधिक देसी जाती है, क्षत्रिय से बड़ प्रशस्ति प्राप्त होती है वैश्य प्राय व्यापार में सलग्न रह कर अपनी परम्परा को कायम रखता है। इसी प्रकार पञ्जाब धर्मिक अगामी धर्मिक से भेदभाव होता है।

२. प्राकृतिक दशाएँ तथा जलवायु (Physical Conditions & Climate)—प्राकृतिक दशाया और जलवायु का कार्य-क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत ठण्ड और बहुत गर्म जलवायु में अधिक देर तक कार्य नहीं हो सकता है। सम-शीतोष्ण जलवायु कार्यक्षमता को बढ़ाती है। यही कारण है कि इंग्लैंड या धर्मिक भारतीय धर्मिक की प्रेरणा अधिप कार्य-निष्पन्न होता है। इसी प्रकार हमारे देश में भी पञ्जाब धर्मिक अगामी धर्मिक में अधिक कार्यक्षमता रखता है। सराई प्रेरणा में अगामी प्रमाण जलवायु होने से वहाँ के धर्मिकों में दृष्टि का प्रभाव दला जाता है।

३. जीवन स्तर (Standard of Living)—एक धर्मिक का सभी प्रकार काम करने से लिय उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद भोजन, उचित वस्त्र, हवादार और स्वच्छ मकान, चिकित्सा और विद्याय सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होना आवश्यक है। इन वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना ही उच्च जीवन-स्तर कहलाता है। उच्च जीवन-स्तर कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। इससे विपरीत इन वस्तुओं का अभाव में जीवन स्तर गिर जाता है जिसके फलस्वरूप मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य रखने में असमर्थ हो जाता है और जीवन-यात्रा सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ या विन्नायाँ में पड़ता होकर अपनी कार्यक्षमता को खोता है।

४. सामान्य बुद्धि (General Intelligence)—सामान्य बुद्धि वैश्व भी होती है तथा प्रात भी। वैश्व बुद्धि माता पिता और जाति पर निर्भर होती है। प्रात-बुद्धि शिक्षा तथा माता पिता का प्रभाव का परिणाम है। एक अमेरिकन धर्मिक का एक ओमान् भारतीय धर्मिक के विचार में अधिक स्पष्ट और निश्चय में अधिक दृढ़ होता साधारण बुद्धि के महत्त्व को सिद्ध करता है।

५. शिक्षा (Education)—शिक्षा में मनुष्य को मानसिक शक्तियाँ का विकसित होता है, जिसमें अपने विचारों को व्यक्त करने और लेखन-रूप में प्रस्तुत करने, प्रशिक्षित धर्मिक की प्रेरणा शिक्षित धर्मिक अपने कृत्या और उत्तरदायित्व का भली प्रकार समझ सकता है। यह तो हम साधारण शिक्षा (General Education)

का कार्य। हमने प्रतिरिक्त कार्यक्षमता के लिये बोडी-यूटन प्रोवाविह या ताक्कि शिक्षा (Technical Education) भी आवश्यक है। ताक्कि शिक्षा क हांग काई हुनग या क्ला सोयो जानी है। इस शिक्षा में संशान्ति और व्यावहारिक रूप में निम्नी कार्य को सम्पन्न करने का ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह कार्य भत्तो प्रकार कम से कम समय और तापन में किया जा सके। अस्तु कार्यक्षमता के लिये ताक्कि शिक्षा भी आवश्यक है। इसीलिए कई प्रगतिशील देशों में प्राथमिक शिक्षा में गुप्त और प्रतिपाद्य बना दी गई है और प्रोवाविह शिक्षा के लिये कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अस्तु प्रभावात्त वसा ह्वात दंग में जाना हो जाना का प्रभाव है।

६. नैतिक गुण (Moral Qualities)—कार्यक्षमता पर श्रमिक के नैतिक गुणों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बलवन्तियुक्त तथा ईमानदार श्रमिक अपना कार्य सचाई, परिश्रम तथा हृदय में रखेगा चाहे उसका कार्य की दायरे में कम निरोधक उपस्थित हो या न हो। अस्तु इससे निपटने एक कामकाज श्रमिक हर समय काम में ली कुशल और समय में कुशलपण करने का प्रयत्न करेगा। चरित्रहीन अनुपुन में कार्य कुशलता प्रपश्य कम होगी।

७. कार्य करने की स्वतन्त्रता (Freedom)—कार्य करने की स्वतन्त्रता में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। किन्ती न कोई कार्य उपपूर्वक प्रपथा का निरोधक म बनाम जान में कार्यक्षमता में ह्रास होता स्वाभाविक है। मनुष्य स्वाभाव में स्वतन्त्रता-प्रिय है, अस्तु दासतापूर्वक कार्य केदावि कार्यकुशलता नहीं बसा सकेगा।

८. आशा और परिश्रम (Hopefulness & Change)—जिस कार्य में भविष्य में उन्नति की आशा नहीं होती है वह प्रत्येक निष्कर्ष पूर्ण हो किया जाता है। काम में विपरीत रूप बसा करने के लिये कार्य लोको आशापुत्र बान हो जिसमें श्रमिक कार्य में कुशलतापूर्वक लगन रह सके। सुखरी, पुन, वाम विभाजन (Profit-sharing) आदि योजनाएँ इस अस्तु की आवश्यकता की पुष्टि करती हैं। इससे प्रतिरिक्त कार्य में परिश्रम होता आ प्रति आदर्श है। आसक की निरन्तर लय हो प्रकार का कार्य करने रहने में उस कार्य में प्रगति होना स्वाभाविक है। अस्तु कार्य में उपयुक्त रोनि न बन्नी-बन्नी सुवपूर्ण परिश्रम कर देने में कीरमता कर होकर कार्यक्षमता में वृद्धि हो जानी है।

९. पारिश्रमिक की पर्याप्तता, समीपता और प्रत्यक्षता (Sufficiency, Nearness and Directness of Reward)—श्रमिक को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलना चाहिये जिससे वह उच्च जीवन स्तर रखकर अपने बाधकपथा बसा सके। इसके प्रतिरिक्त श्रमिक का पारितोषिक प्रत्यक्ष रूप में निवेष्ट भविष्य में मिलने में कार्यक्षमता बनी रहनी है।

१०. काम करने की दशाय (Working Condition)—जिस स्थल पर श्रमिक काम करता है वहाँ के वातावरण का उसकी कार्यकुशलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कारखानों में स्वच्छ वायु, जल, प्रकाश आदि स्वास्थ्यवर्धक बातों का उचित प्रत्यक्ष है, तो श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रपश्य बड़ी हुई होगी। स्वास्थ्य-जनक सुविधाएँ श्रमिक की योग्यता पर उतना प्रभाव डालती हैं।

११. कार्य अवधि (Duration of Work)—यह अनुभव-विद बात है कि काम करने के घण्टा की कुछ सीमा तक बढ़ा देने से श्रमिक की कार्यक्षमता

बढ़ जाती है। अत्यधिक समय तक काम करने का श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे उसकी कार्य-शक्ति कम हो जाती है। उचित समय विभाग से भी कार्य-धमना बढ़ती है। यदि काम करने के माय-माय चोड़ा समय विश्राम तथा घाने-पीने के लिये मिल जाय तो श्रमिक की शक्ति बढ होकर पुनः काम करने के लिय नवीन उत्साह और शक्ति का संचार हो जाता है।

१२ सामाजिक एवं राजनैतिक दशावस्था (Social & Political Conditions) — देश की सामाजिक एवं राजनैतिक दशावस्था का श्रमिक की दक्षता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस देश में अज्ञान, वातावरण है, जहाँ जन-जन की सुरक्षा का अभाव है अथवा जहाँ के पूँजीपतियों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष चल रहा हो, वहाँ के श्रमिकों का कार्य-क्षमता परों हुई मितना स्वाभाविक होगा।

१३ सामाजिक प्रथाएँ (Social Customs) — देश की सामाजिक प्रथाएँ भी कार्य-क्षमता पर प्रभाव डाले बिना नही रहता। हमारे देश में ब्रह्म धर्मव्यवस्था के कारण मनुष्य अधिकतर अपना कार्य शक्ति के अनुसार नही चुन सकता। शक्ति हो या नही उस शक्ति को ही अपनाकर अपने काम के अनुकूल हो कार्य करना पड़ता है। जिसमें कार्य-क्षमता में ह्रास होता है स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त यहाँ मनुष्य-परिहार प्रणाली के प्रचलन से कार्य-क्षमता को कोई प्राणात्मक नहीं मिलता। परन्तु प्रसन्नता की बात तो यह है कि अब ये दोनों ही व्यवस्थाएँ निश्चित होती जा रही है।

१४ सामग्री की उत्कृष्टता (Best Material & Equipment) — श्रमिक का कार्य-क्षमता कुछ अक्ष तक इस बात पर भी निर्भर है कि वह किस ढंग की मशीनों और कच्चे माल की सहायता से कार्य करता है। जिनकी उत्तम काम करने की सामग्री उस मिलगी, उनको अधिक उसका कार्य-क्षमता में वृद्धि होगी।

१५ श्रमिकों का संगठन (Labour Organisation) — श्रमिक नम (Trade Union) जैसी श्रमिकों की संगठित संस्थाओं द्वारा उच्च उचित परिस्थितिक शिक्षा दीक्षा और सुधारजन की सज्जिधायें प्राप्त हो जाती हैं जिससे उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे देश में कई कारणों से अभी इस प्रकार की संस्थाएँ पूर्ण रूप से सुसंगठित नही हो पाई हैं।

(अ) व्यवस्थापकों की व्यवस्था करने की योग्यता को प्रभावित करनेवाली बात श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ाने वाली सभी बात उपस्थित होने पर भी बिना एक योग्य व्यवस्थापक के उसकी कार्य-क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती। यदि कार्य का नियमपूर्वक विभाजन किया जाय प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाय और उपयुक्त मशीनों का उपयोग किया जाय तो कार्य-क्षमता में वृद्धि होना निश्चित है। एक योग्य व क्षम श्रमिक व्यवस्थापक यह है जो श्रमिकों को सफुट रूपसे उनमें विश्वास और कार्य करने की लक्ष्मी लयन पैदा कर सके।

भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता

(Efficiency of Indian Labour)

साधारणतया यही कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक अक्ष एवं अनुकूल *। इससे यदि देश का श्रमिकों की कार्य-क्षमता की तुलना भारतवर्ष के श्रमिकों से करने के लिये ही प्रयत्न किया गया है। कहा जाता है कि एक जापानी श्रमिक २४० नकलियाँ (Spindles) को देख रख करता है अङ्गरेज श्रमिक १४० म ६०० की,

(८) अनुत्कृष्ट व्यवस्था (Inferior Organisation)—भारतीय कारखानों का मुख्य और व्यवस्था भी गरीबजनक नहीं है, इस में मुख्य व्यवस्थापकों का प्रभाव होने के कारण धर्म-वृत्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें भारत की नवयुवका का विदेश में इस कार्य की शिक्षा के लिए भेजना चाहिए।

(९) गर्म जलवायु (Hot Climate)—इस देश के गर्म जलवायु का धर्मिक के अस्तित्व और गरीब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु में अधिक समय तक कार्य कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। जिसकी वजह से यहाँ और भी अधिक गर्मी (Humidities) सर्वाधिक मात्रा में फैलती है। इससे धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाती है।

(१०) काम के घंटे (Working Hours)—यह जलवायु में यही देश तक काम करने रहने में कुशलता में ह्रास होना स्वाभाविक है। भारतीय कारखानों में कानूनों द्वारा काम करने के घंटे प्रत्येक कम कर दिये गये हैं किन्तु ऐसे गर्म जलवायु की शर्तों में यह भी और भी कम होने चाहिए। वर्तमान समय में सर्वेक्षणों के अनुसार कारखानों में ४८ घंटों का सप्ताह और सोमवार कारखानों में ४४ घंटों का है। परन्तु यह कानून कई छोटे कारखानों में लागू नहीं होता है।

(११) स्वतन्त्रता और आशा का अभाव (Lack of Freedom & Hopefulness)—प्रगतिशीलता का भी कार्यक्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बड़े निरोधक और आशा के अभाव में धर्मिक की कार्यक्षमता में कमी होना स्वाभाविक है।

(१२) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव (Lack of Educational Facilities)—भारतवर्ष में माध्यम एवं प्रौद्योगिक शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है। अन्य प्रगतिशील देशों की भाँति यहाँ पर भी केवल कम प्राथमिक शिक्षा ही प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक शिक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिक अथवा तकनीक (Technical) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ आवश्यक हैं। माध्यम शिक्षा धर्मिक की मानसिक-विकास करने के लिए आवश्यक है। प्रौद्योगिक शिक्षा में व्यावहारिक अज्ञानता दूर होकर कार्य-विधान क्षमता की वृद्धि होती है।

(१३) पर्याप्तशीलता (Migratory Character)—भारतीय धर्मिक केवल कारखानों पर ही निर्भर नहीं रहते। वे कारखानों में नयी काम करने मानते हैं जो वेतनों पर कोई काम नहीं होता और जब वेतन पर काम होता है तब वे कारखानों का काम छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अतः उनका कारखानों में सम्बन्धी सम्बन्ध होता है। ऐसी प्रवृत्ति में उनकी उत्पादकता में न्यूनता आती स्वाभाविक है। प्रौद्योगिक केन्द्रों में धर्मिकों को नियमित रूप में रहने का प्रोत्साहन देने के लिए, सहरी जीवन में सुधार पर उसे आवश्यक बनाना चाहिए।

(१४) ऋण-अवस्था (Indebtedness)—अधिकांश भारतीय धर्मिक ऋण-अवस्था में हैं। अतः कुशलता वृद्धि के प्रयत्न के लिये वे प्रायः उदासीन हो रहते हैं। ऋण प्रगति में बाधक सिद्ध होता है। अतः धर्मिकों को दीर्घातिशायन ऋण-मुक्त किया जाना और गृहकार्य आन्दोलन द्वारा उन्हें पिढीपिता का पाठ पढ़ाया जाय।

(आ) शिल्पकारों की अकुशलता के कारण (Causes of Inefficiency of Artisans)

(१) उचित व्यवस्था का अभाव (Lack of Proper Organisation)

(२) पुराने ढंग (Old Methods of Production)

(३) आधुनिक यन्त्रों व उपकरणों का अभाव (Lack of Up-to-date Machinery & Tools)

(४) सस्ती प्रेरक शक्ति का अभाव (Lack of Cheap Motive Power)

(५) सस्ती पूँजी की कमी और ऋण-ग्रस्तता (Unavailability of Cheap Capital & Indebtedness)

(६) निरक्षरता, अनाविज्ञता और अनिर्वादिता (Illiteracy, Ignorance, Conservatism)

(७) मार्केटिंग सुविधाओं का अभाव (Lack of Marketing Facilities)

उपाय (Remedies)—शिल्पकारों के व्यवसाय की सुव्यवस्था, उत्पादन के आधुनिक ढंग को अपनाया आधुनिक यन्त्रों का उपयोग, सस्ती प्रेरक शक्ति की व्यवस्था, साधारण और हाथिक शिक्षा का प्रवर्धन, सस्ती पूँजी व लिये सहकारी साख्त समितियाँ (Cooperative Credit Societies) का प्रसार और मार्केटिंग व्यवस्था के लिये सहकारी ख़रीद-विक्रय समितियाँ (Cooperative Purchase & Sale Societies) की व्यवस्था द्वारा ही शिल्पकारों की कार्य-क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

(इ) कृषि श्रमिकों की अकुशलता के कारण (Causes of Inefficiency of Agricultural Labour)—यह ज़रूरत बड़ा व ज़रूर होना है कि भारतीय कृषि श्रमिकों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(१) खेतों का उप विभाजन (Fragmentation of Holdings)

(२) कृषकों की ऋण-ग्रस्तता (Indebtedness of Cultivators)

(३) कुटीर व्यवसायों का पतन (Decline of Cottage Industries)

(४) अत्यधिक भू-भार (Ever Increasing Pressure on Land)

(५) कृषि श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा (Competition among Agricultural Labourers)

(६) निरक्षरता (Illiteracy)

(७) आशा, परिवर्तन और हस का अभाव (No Hopefulness, Change & Cheer)

(८) लम्बे घंटे का काम (Long Hours of work)

उपाय (Remedies)—परवर्ती अवधि में धीरे-धीरे खेतों को मिलाकर बड़ा खेत बनाना (Consolidation of Holdings), सहकारी आधार पर कृषि श्रमिकों का संगठन (Organisation of Agricultural Labourers on Cooperative Basis), प्रवास (Emigration), शिक्षा प्रसार आदि।

पञ्जाबी श्रमिक और उत्तर प्रदेशीय श्रमिक की कार्य-कुशलता की तुलना

१. पञ्जाबी श्रमिक साधन ज्ञान का है और उत्तर प्रदेशीय श्रमिक साधनशास्त्रिक ज्ञान का। यस्तु पञ्जाबी श्रमिक उत्तर प्रदेशीय श्रमिक को आसानी से शिक्षित करिष्ठ, तथा और बढिसे परिचय करवा लाता है। ज्ञानीय गुण के कारण पञ्जाबी श्रमिक उत्तर प्रदेशीय श्रमिक से अधिक कुशल है।

२. उनसे जलवायु के कारण पञ्जाबी श्रमिक उत्तर प्रदेशीय श्रमिक से अधिक कुशल है।

३. पञ्जाबी श्रमिक अपनी साधन का अधिकतम भाग शरीरशक्तियों का उपयोग करने पर व्यय करता है और उत्तर प्रदेशीय श्रमिक अधिकतम साधन का उपयोग करने पर व्यय करता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टतम आदर्श परीक्षाएँ

१—श्रम की क्षमता का क्या अर्थ है ? श्रम में श्रम की क्षमता ज्ञान के लिए या कार्य करने की क्षमता उत्तरा विवेचन कीजिये। (उ० प्र० १९४४)

२—श्रमजीविता की कुशलता किस-किस कारणों पर निर्भर है ? समझाइये।

(उ० प्र० १९४२, ४०)

३—'भारतीय कार्यक्षमता या श्रमिक क्षमता के कारणों के श्रमिक से कम कार्य-कुशलता है।' क्या आप इसमें सहमत हैं ? यदि है तो कारण दीजिये।

(उ० प्र० १९४०)

४—'श्रम की कार्यक्षमता अधिक उत्पत्ति का विषय कारण है।' भारतीय श्रमिक का कम कार्यक्षमता के कारण से क्या कहा जाता है ?

(म० भा० १९४३)

५—श्रम की कार्य-कुशलता पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है ? क्या भारतीय मजदूर कार्यक्षम है।

(म० भा० १९४४)

६—श्रम की कार्यक्षमता का प्रभावित करने वाली बातों को समझाइये। भारतीय श्रमिक क्षमता के महर्ष में उत्तर दीजिये। (म० भा० १९४३, प्र० प्र० १९४६)

७—श्रम की कार्यक्षमता में क्या क्या समझते हैं ? किन बातों पर श्रम की कुशलता निर्भर होती है ? (रा० बी० १९६० ; म० बी० १९४१, ४६)

८—उन सब दशाओं का ध्यानपूर्वक विवेचन कीजिये जिनसे श्रम की कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में ये दशाएँ कहाँ तक पाई जाती हैं ?

(रा० बी० १९४३, ४६)

९—भारतीय श्रम में क्षमता की क्या कमी है ? इसकी वृद्धि के गुणांक दीजिये।

(मासिक १९४६)

१०—एक लेनिन मजदूर को कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाली कौनसी बात है ? उन दशाओं का परीक्षण कीजिये कार्यक्षमता बढ़ाने वाली है।

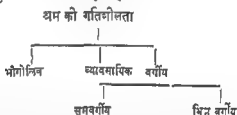
(म० बी० १९४१)

श्रम की गतिशीलता (Mobility of Labour)

श्रम की गतिशीलता का अर्थ (Meaning)—किसी श्रम की एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को और एक वर्ग (Grade) से दूसरे वर्ग को जाने की योग्यता और तत्परता को श्रम की गतिशीलता कहते हैं।

उत्पत्ति के समस्त माधनों में श्रम सम्बन्धन, सबसे अधिक प्रगतिशील है, क्योंकि श्रमिक अपने कार्य और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन बड़ी कठिनाई से करता है। श्रम श्रमिक का एक दम है जो उससे पृथक् नहीं किया जा सकता। अस्तु, आदम स्मिथ ने ठीक ही कहा है “सब प्रकार के सामानों में से मनुष्य का स्थानान्तरण प्रति दुष्कर है।”¹

श्रम की गतिशीलता के भेद (Kinds of Mobility of Labour)—
श्रम की गतिशीलता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है :—



१ **भौगोलिक गतिशीलता (Geographical Mobility)**—श्रमिक का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ‘भौगोलिक श्रम या स्थान गतिशीलता’ कहलाता है। इस प्रकार की गतिशीलता प्रायः संसार में सभी जगह पाई जाती है। भारतवर्ष में भी शिक्षा-प्रसार, यातायात व सम्वाद के साधनों की उत्पत्ति, सामाजिक रीति-रिवाजों की विविधता और समस्त देश में हिन्दी भाषा के प्रचार ने भौगोलिक गतिशीलता को सुगम बना दिया है।

भौगोलिक गतिशीलता के प्रकार—भौगोलिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है—

(क) **अस्थायी गतिशीलता (Temporary Mobility)**—श्रम का अल्पकालीन स्थानान्तरण अस्थायी गतिशीलता कहलाता है। हमारे देश में ग्रामिण भौगोलिक गतिशीलता इसी प्रकार की होती है। देशान्तर में जब सेना पर काम नहीं होगा है तब किसान मजदूर व औद्योगिक नगरों में मजदूरी के लिये चले जाते हैं, और जब

1.—“Of all sorts of traffic man is the most difficult to be transported”

— Adam Smith.

वर्षा होने पर खेत पर काम करने के दिन आते हैं तब ये वापस गाँव चोट जाते हैं। गहरा म काम करने के समय में भी मध्यम समय पर गाँव में जात रहते हैं क्योंकि उनके मुटुमध्य मध्यम यंत्र रहते हैं। ग्रामीण लोग बेचल बारखाना में ही काम करने नहीं जानें बल्कि दल्लर में चपरासी और घरा में नौकरा का भी काम करने के लिए जाते हैं। निम्नो सरकारी आश्रम का स्थानान्तरण होना भी सम्भावनी गतिशीलता है।

(घ) स्थायी गतिशीलता (Permanent Mobility)—जब लोग अपने प्रांत या देश की छाड़कर स्थायी रूप में दूसरे स्थान में जा सकते हैं तो उनका स्थानान्तरण स्थायी गतिशीलता कहलाता है। इस देश में इसका अधिक महत्त्व नहीं है क्योंकि जब लोग स्थान का छोड़कर अन्य स्थान की बात है तो अपने प्रांत या देश प्रग में प्रतिक्रिया नौकरागिरि वापस चोट जाते हैं।

भौगोलिक गतिशीलता के कारण—भौगोलिक गतिशीलता वह कारणों से प्रेरित होता है जिसमें अधिक सामाजिक और राजनितिक प्रधान है।

(२) व्यावसायिक गतिशीलता (Occupational Mobility)—जब अधिक किसी कारणवश एक उद्योग या धंधे का छाड़कर दूसरे में प्रवेश करता है तो उनकी प्रिया व्यावसायिक गतिशीलता नहीं जाना है।

व्यावसायिक गतिशीलता के कारण व्यावसायिक गतिशीलता के कई कारण हैं जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

(१) अधिक पारिश्रमिक—जब अधिक जान ममान हो तो अधिक अधिक पारिश्रमिक मिलने जाना है या प्रयत्न करने की ओर आकर्षित होते हैं।

(२) काम के अनुबन्धना—काम का अनुबन्धना के कारण अधिक एक देश में दूसरे देश की ओर आकर्षित होते हैं।

(३) काम सम्पन्न उ मुगमता व सुविधा—अधिक रूप प्रायः उन काम की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें शीघ्र में प्रविष्टि योग्यता की सुविधा हो।

(४) नौकरों का स्थायित्व—अधिक प्रायः स्थायी काम की ओर अधिक प्रवृत्त है। सम्भावना या बाढ़ दिना तक चलने जान काम को कम प्रवृत्त करने है।

(५) नौकरा के सुरक्ष—जब नौकरों या धंधे में सुरक्षता का अभाव होता है वह अधिक डर का काम प्रवृत्त किया जाना है।

(६) लक्ष्य और ईमानदारी वाले कार्य—जब कार्य में लक्ष्य और ईमानदारी की आवश्यकता होती है उसमें प्रविष्टि पारिश्रमिक मिलता है। जिस मनुष्यो की अपने काम में लक्ष्य व ईमानदारी अभाव है वे लोग ही काम करने प्रवृत्त करने है। इस छिद्र द्वारा जान करने की अपेक्षा व बँटा रहना प्रवृत्त करने है।

(७) कार्य की कुशलता अथवा अनुबन्धना—जब कार्य के करने में अधिक कुशलता तथा विशेष निष्ठा सेवा की आवश्यकता होती है उसमें श्रम की गतिशीलता अधिक होती है और अनुबन्धन श्रम वाले व्यवसाय में कम होती है।

निम्न प्रकार के कारणों आदि की वृद्धि से कुशल काम वाले व्यवसायों और धंधों में गतिशीलता कम जान पड़ रही है और अल्प तथा अनुबन्धन श्रम का अन्तर भी कम होता जा रहा है। मालवप में व्यावसायिक गतिशीलता कम होने के मुख्य कारण निरक्षरता अज्ञानता जाति प्रथा और सामुदायिक यात्रादि का अभाव। भीष्म में

शिक्षा-प्रसार में वृद्धि होनी जा रही है जिससे कारण रुढ़िवादित और जाति-प्राति के बन्धन भी शिथिल होने जा रहे हैं।

३. वर्गीय गतिशीलता (Grade Mobility)—एक वर्ग में दूसरे वर्ग में जान का वर्गीय गतिशीलता कहलाता है।

वर्गीय गतिशीलता के प्रकार (Kinds of Grade Mobility)—वर्गीय गतिशीलता दो प्रकार का होनी है —

(१) सम-वर्गीय, और (२) भिन्न-वर्गीय।

(१) सम-वर्गीय गतिशीलता (Horizontal Mobility)—एक व्यवसाय या कारखाने को छोड़कर दूसरे कारखाने या कारखाने में जाकर उसी वर्ग में काम करना 'सम-वर्गीय गतिशीलता' कहलाता है। जैसे मुन्नी कपड़े को मिल में कपड़े पर काम करने वाला श्रमिक उसे छोड़कर बूट मिल में जाकर वही काम कर प्रथम एर बैन का लेखापाल (Accountant) दूसरे वेंक में जाकर वही कार्य कर, तो यह समवर्गीय गतिशीलता का उदाहरण होगा।

सम-वर्गीय गतिशीलता



सम्बन्ध मुन्नी कपड़े
की मिल का श्रमिक

कलकत्ता की
बूट मिल में

(२) भिन्न वर्गीय गतिशीलता (Vertical Mobility)—यदि कोई श्रमिक नीचे वर्ग में ऊँचे वर्ग में कार्य करने लग जाय प्रथम ऊँचे में नीचे वर्ग में उतार दिया जाय, तो इसे 'भिन्न-वर्गीय गतिशीलता' कहेंगे। उदाहरण के रम्य कथन में हैट क्लर्क बनना प्रथम हैट क्लर्क से पुनः क्लर्क बनना आदि।



क्लर्क

हैडक्लर्क

नीचे वग स ऊँ वग म जान वे वारण—(१) यमिन भगवत पार
निभा द्वारा योग्यता दशाक्षर नीचे वग स ऊँ वग म जा सता है (२) निभा
वारणवग ऊँ वग म स्थान रिक्त जा जान पर नात्र वग वाता का ठ न वग वा भा म
मिक्त जाता है ।

ऊँच वगैरे नीचे वगैरे में ध्यान व चरणा—(१) किन्ना धमिरा का कथन मना
म शरीर होता। (२) धमिरा का चरणावाली धमिरा का धमिरा का धमिरा
की धमिरा में धमिरा होता।

यह स्मरण करो कि वन में जंगलवा मरत है परन्तु ऊँच वन का प्राप्ति करना
शक्ति है।

भारत में धर्म का गणिशास्त्रना में बाधना

(Mindrange & the Mobility of Labour in India)

हमारे देश में धर्म की गणितीना में निम्नलिखित बातों द्वारा काम
पहननी —

१. **आर्थिक दबाव का प्रभाव (Absence of Economic Pressure)**—भूमि पर आर्थिक दबाव का भाग धीरे धीरे का उप विभाजन हानि रूप में आर्थिक दबाव का आर्थिक दबाव इसी कारण नहीं है कि वह प्रत्यक्ष रूप से दबाव का विषय नहीं है। केवल भूमि मूल्य में धीरे धीरे दबाव का विषय है।

२ भाग्यवादिना (Fateists) — भाग्यसेय सामान्य मनुष्यो कोर भाग्यवादी है। कहा जा जाता जा भाग्य में लिखा है वही विरण — दूसरे व अधिवि विराम करत है। प्रत्यक्ष व अविविधावाज्जने के त्रिध अपन गाँवा में हा रहना पसन्द करत है।

३. नीचा जीवन-स्तर (Low Standard of Living)—भारतीय सामान्यतः एक निम्न जीवन-स्तर का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि उनके जीवन-स्तर में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है।

४ पारिवारिक स्नेह (Family Affection)—अपन परिवार व सख्तया—को जान रक्षा आदि के साथ स्नेह इतना प्रबल होता है कि वह उनका छोड़कर कहीं अघटन जाना पसन्द नहीं करता।

५ घर के स्थान का प्रेम (Love of Home and Locals) १- जिस गाँव या जिन में अधिक पैदा हुआ है तथा जहाँ अपना पानन पोषण हुआ है वह प्रायः वही रह कर जीवनोपायन करना पसंद करता है। यद्यपि अथवा उस अधिन पारिश्रमिक क्या नहीं मिलता है। भारतीय अधिकांश यह प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है - घर का पानी काह्न की मीठा। अर्थात् स्थान वसति के लिए घर छोड़ कर जान की प्रतीति घर पर रहने के लिये मूल ही पैदा करना उचित है।

६ जाति प्रथा और समुक्त परिवार प्रणाली (Caste System and Joint Family System)—शायद लोग अपनी जाति के अनुसार ही भाषा प्रयोग करते हैं। दूसरे भाषा में रुचि होना हूए भी सामाजिक निंदा से डरने के कारण उस प्रयोग नहीं कर पाते। जाति बंधन के ही कारण बड़-बड़ होनाकार नवप्रवृत्त उच्च शिक्षा दीक्षा के लिए विदेशों में नज़र आते हैं। समुक्त परिवार के सदस्यों के स्वयं में बड़

अपग वेनारा की उचित देख रेख करनी पड़ती है। यत वह उन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह जीवन निर्वाह के लिये नहीं जा सकता। इस प्रकार औद्योगिक गतिशीलता में बाधा पड़ती है। इसके अनिश्चित मनुष्य परिवार प्रथा में मनुष्य की प्रायः उनके काम में बहुत पात में नहीं होने के कारण उनकी उन्नति करने की इच्छा प्रतीति प्रबल नहीं रहती। यस्तु यह व्यावसायिक एवं व्यापक गतिशीलता में बाधक सिद्ध होता है।

७. कृषि-कार्य का स्थिर स्वभाव (The Stable Nature of Agricultural Operations) — कृषि कार्य सम्पन्न करने के लिए एक स्थान पर स्थायी निवास की आवश्यकता है। एक गिल्फार्ड अपने जीवधारियों के जीवन को लेकर सुगमता पूर्वक स्थान परिवर्तन कर सकता है परन्तु एक कृषक के लिये यह कार्य कठिन है। वह भूमि अपने साथ नहीं ले जा सकता है। जहाँ कहीं भी जायगा वहीं भूमि प्राप्त करनी पड़ेगी। नई भूमि प्राप्त करना कोई सुगम कार्य नहीं है। फिर उस नई मिट्टी का अध्ययन कर नये वातावरण में पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। यह कठिन है। यह स्थान-परिवर्तन कभी नहीं चाहता है।

८. शारीरिक दुर्बलता एवं साहस का अभाव (Poor Physique and Lack of Enterprise) — अफ्रीका का शारीरिक दुर्बलता और उसमें साहस का अभाव उनकी गतिशीलता में बाधक सिद्ध होता है।

९. निरक्षरता और अज्ञानता (Illiteracy & Ignorance) — भारतीय धर्म की अग्रगण्यता व यही दो आधारभूत कारण हैं जिनसे यह कहा जाना है कि वे कहा जाय और क्या कर। वर्तमान समय में हमारे देश में अज्ञानता के कारण (Employment Exchange) में इस समय व में अज्ञान कुछ काम हो रहा है।

१०. औद्योगिक केन्द्रों का प्रतिकूल वातावरण (Uncongenial Atmosphere of Industrial Centre) — लार्डी हव्स में रहने वाले प्रयोगों के लिये यह कपरा की गयी शक्ति में स्थित अनेक बोटिंग प्रतिकूल सिद्ध होता है। कहीं कहीं जीवन और कहीं गरीब जीवन। यत किसी कारणवश बाध्य होकर भले ही वह गहर में चला जाय परन्तु साधारणतया वह अपने गांव का छोड़कर कहीं नहीं जाता।

११. उपयुक्त यातायात व संचार की सुविधाओं का अभाव (Lack of Adequate Facilities for Transport and Communication) — यद्यपि रेल और सड़क द्वारा यह कठिनाई बहुत कम तक हो गई है। फिर भी भारतीय भाग में कुछ गांव आधुनिक यातायात के साधनों की सुविधाओं से वंचित हैं। वर्षों से तो वे अच्छी सड़कों के अभाव में बस्ती और नगरों में विच्छिन्न हो चुके हैं।

१२. जलवायु की भिन्नता (Variation in Climate) — भारतवर्ष में एक राज्य में दूसरे राज्य को जाने में जलवायु की भिन्नता प्रबल होन लगता है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जब बनारस में जाता है तो वह बनारस से चिंतित हो जाता है। यही प्रकार मम्बई में व्यक्ति के लिये कानपुर का जलवायु बड़ा भयानक सिद्ध होता है।

१३. भाषाओं और धर्म की भिन्नता (Variety of Languages and Religion) — भारतवर्ष में अनेक अनेक भाषा में अनेक अनेक भाषा प्रचलित हो

के कारण धर्म की गतिशीलता को बड़ी बाधा पहुँचती है। जब राजस्थान का श्रमिक इस कठिनाई से ही मुक्ति नहीं जा सकता और मद्रास का श्रमिक को नहीं जा सकता। इसी प्रकार धार्मिक आधार विचार में भी बड़ी भिन्नता मिलती है जिनके कारण धर्म की गतिशीलता की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है।

१४. कृषि की प्रधानता (Predominance of Agriculture)—भारतवर्ष में अधिकांश लोगो का मुख्य पेशा कृषि है, अतः वे अपने मुख्य पेशे को छोड़कर अन्य पेशा के लिये जाना पसन्द नहीं करता।

१५. जन साधारण की निर्धनता (Poverty of the Masses)—भारतवर्ष में अधिकांश लोग निर्धन हैं। वे अपना निर्वाह बड़ी कठिनाई में करते हैं। अतः उनके पास इधर-उधर जाने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं।

१६. महत्वाकांक्षा का अभाव (Lack of Ambition)—भारतीय श्रमिक भाव्यवादी गन्तव्य और साध्यात्मिक शक्ति व होन के कारण उनमें भीतर दृष्टि में प्राप्त करने की अभिलाषा का पूर्ण अभाव होता है। अतः वे वही पौर उन्मी स्थिति में रहना पसन्द करते हैं।

१७. निवास स्थानों की कठिनाइयाँ (Housing Difficulties)—गाँव के लोग शहरों में इकट्ठा भी नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें स्वच्छ हवादार भूकान नहीं मिलते। अतः विवश होकर उन्हें बड़ी बान पोटियाँ में रहना पड़ता है।

भारतीय श्रमिक की गतिशीलता (Mobility of the Indian Cultivator) भारतीय श्रमिक की गतिशीलता बड़ी मन्द है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो उसे अपने पत्नी के लिये साधन को इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई होती है। नये स्थान में नई भूमि प्राप्त करना बड़ा कठिन है। नये स्थान की मिट्टी जलवायु, फसलों आदि का अध्ययन बड़ा आवश्यक है। इनके साथ-साथ निरक्षरता, अज्ञानता, कठिनाइयाँ, जाति प्रथा, मनुष्य परिवार प्रणाली, कीट-पतंगों के स्नेह आदि कारण भी उसकी एक ही स्थान और एक पेशा में सीमित रहने में बाधक करते हैं।

भारतीय श्रमिक की गतिशीलता (Mobility of the Indian Labourer)—भारतीय श्रमिक की अपेक्षा भारतीय श्रमिक अधिक गतिशील है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है और उसकी जानकारी शहरों में भी प्राप्त कर सकती है। जब वह औद्योगिक शहर में पहुँचता है तो कारखाने की कार्यप्रणाली से हिचक जाता है। परन्तु जब मजदूरी के दबाव और परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के कारण वह अधिक गतिशील हो गया है। स्थिति धर्मिक अपने पेशे में परिवर्तन बड़ी कठिनाई से करता है।

भारतीय शिल्पकार की गतिशीलता (Mobility of the Indian Artisan)—भारतीय शिल्पकार भारतीय श्रमिक और श्रमिक से अधिक गतिशील है, क्योंकि वह अपने कुछ औजारों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से जा सकता है और बिना अधिक कठिनाई के अपना कार्य आरम्भ कर सकता है। यह तो है उसकी भौतिक या स्थान गतिशीलता। उसमें श्रमिक या श्रमिक से अधिक अनुसृतता व अनुसृतता होने के कारण वर्गीय गतिशीलता भी पाई जाती है। कुटीर व्यवसायों के नष्ट होने से उसे बाध्य होकर अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ा है।

जाति प्रथा का श्रम की गतिशीलता पर प्रभाव (Influence of Caste System on Mobility of Labour)—जाति-श्रम का श्रम की भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। जाति प्रथा की मर्यादा में अबाध हुए मनुष्य के खिये अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना पडा बैठिन है। जाति द्वारा निर्धारित आचार विचार का कारण हा एवं उ० प्र० का आह्वान पजाव या दवान म नही रह सकता। बढ बढ होनहार नवयुवक इसी वारण विदेश में जाकर उच्च शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने में वचिन रह जात है।

इसी प्रकार जाति प्रथा व्यावसायिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति के अनुसार अपना पगा ग्रहण करता है। उसको उनमें रुचि नहीं हान पर भी वह अन्य बाय नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एक नुहार कुम्हार का बाय नहा कर सकता कुम्हार जुनाहे का घोर जुनाहा लाती का काम नहीं कर सकता।

गतिशीलता और कार्य कुशलता (Mobility & Efficiency)—गतिशीलता में बाध-कुशलता में वृद्धि होती है क्योंकि व्यवसाय स्वतन्त्रतापूर्वक चुनकर ग्रहण किया जा सकता है। फिर प्रतियोगिता का कारण उसे अपने साधिया के मध्य एक कुशल अधिक होकर हा रहना पडता है अन्यथा उसका जीवन निर्वाह होना कठिन हा जाता है। गतिशीलता श्रमिक को अपना रुचि के अनुसार मन्दा ग्रहण करवाती है जिससे पत्तस्वरूप उनकी कामक्षमता बढ़ती है।

श्रम की गतिशीलता और भृति (मजदूरी) (Mobility of Labour & Wages)—श्रम की गतिशीलता बढ दिया है जिसका द्वारा श्रम एक स्थान पते या श्रेणी में जहाँ श्रम अधिक है उस स्थान, पते या श्रेणी में पहुँचता है जहाँ इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इससे श्रम की माग और पूर्ति का समायोजन (Adjustment) हा जाता है। जिससे पत्तस्वरूप भृति में समानता (Equalisation of Wages) आकर मधु जगह भृति की दर एक-सी हो जाती है। श्रम की गतिशीलता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक भृति की दर में समानता आती जायगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—श्रम की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है ? भारतीय श्रमिका की गतिशीलता कम हान के क्या कारण हैं ? (रा० बा० १९६०)
- २—श्रम की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है ? भारतीय श्रमिका की गतिशीलता पर सामाजिक रीति का क्या बड़ा उप प्रभाव पडता है ? सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। (म० बा० १९५२, उ० प्र० १९५१)
- ३—भारत में श्रम की गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। इसका भृति (मजदूरी) पर क्या प्रभाव पडता है ? (उ० प्र० १९४०)
- ४—श्रम की गतिशीलता पर सविज्ञापित टिप्पणी लिखिए। (रा० बा० १९५२, सागर १९४८, नागपुर १९४७, उ० प्र० १९२०, ४६)

पूँजी की परिभाषा (Definition)—मनुष्य या धन उत्पन्न करना है उसका उपयोग वह निम्ननिर्णयित प्रयाजना के नियमों के अनुसार करना है —

- (१) वह उसको कृतमान आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा सकता है।
- (२) वह उसे भावों आवश्यकताओं के लिये रख सकता है।
- (३) वह उसे दान में दे सकता है।
- (४) वह उसका धन देने में उपयोग कर सकता है।
- (५) वह उसको अनुरोधित मजदूरी (Hoardings) के रूप में रख सकता है।
- (६) वह उसका और अधिक उत्पादन के लिये लगा सकता है।

अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि धन के इन उपयोगों में से कौनसा उपयोग पूँजी कहलाता है? धन का जेबत वह दो भाग पूँजी है जिसका कि उपयोग और अधिक धन उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। अस्तु, यह स्पष्ट हुआ पूँजी धन का केवल एक भाग है। समस्त पूँजी एक धन है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि समस्त धन पूँजी हो। पूँजी की कौटि में धन का वह भाग जो दो गत आवश्यक है—प्रथम तो यह मानव-प्रयत्न का फल होता चाहिए और द्वितीय उसमें धनोत्पत्ति में सहायता निम्नो चाहिए। अतः हम पूँजी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं पूँजी भूमि को छोड़कर, धन का वह भाग है जिसका उपयोग अधिक धन-उत्पादन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिये, कारखाना में मशीन, कच्चा, मूल आदि धनोत्पत्ति के कार्य में प्रयुक्त होने के कारण पूँजी कहलायेंगे। इसी प्रकार हम किसान के बीज, हल, बीज आदि का भी पूँजी कहेंगे। हमारी पूँजी की इस परिभाषा में भूमि सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भूमि मानव प्रयत्न का फल नहीं है बल्कि यह प्रकृतिदत्त वस्तु है।

धन और पूँजी के अन्तर का स्पष्टीकरण—उपयुक्त परिभाषा से धन और पूँजी के अन्तर को स्पष्टता से समझा जा सकता है। धन उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। परन्तु जो धन प्राथमिक धन की उत्पत्ति में लगाया जाय, उसे पूँजी कहेंगे। अस्तु, धन एक वस्तु पूँजी है या नहीं, यह उसके प्रयोग पर निर्भर है। उदाहरणार्थ धन जब रहने के लिये मिला जाता है तो वह केवल धन ही है, किन्तु यदि उसका उपयोग कारखानों के लिये होने लगे, तो वह पूँजी हो जावेगा। कोयला जब भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तब केवल धन रहता है, परन्तु जब मशीनों में डाला जाता है, तब पूँजी हो जाता है।

इसी प्रकार जब वेहूँ लाख पदावध रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब केवल धन कहलाता है पर-जब बीज के काम में आता है, तब वही पूँजी का रूप धारण कर लेता है। यस्तु प्रमाण से ही यह पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु केवल धन है या पूँजी। क्या निम्नलिखित वस्तुएँ पूँजी की श्रेणी में आती हैं ?

① बीज का अन्न (Seed Corn)—इसका प्रयोग फलोत्पत्ति के लिये होने के कारण स्वयत्तया पूँजी है।

② अनुत्पादक संचित रुपये (Hoarded Rupees)—इनका किसी उत्पादन कार्य में उपयोग नही होने से पूँजी नहीं है।

③ व्यापार की ख्याति (The Goodwill of a Business)—खलिगत व्यापार/इसमें ख्याति प्राप्ति को मापा करता है इसलिये यह उसकी पूँजी है। इसकी प्रभौतिक पूँजी (Immaterial Capital) कहना उचित होगा।

④ किसी सर्जन या गायक की दक्षता (The Skill of a Surgeon or a Musician)—पत्रों द्वारा व्यक्ति विशेष को अच्छी मालूम हो जाती है, परन्तु स्वयं इसमें कोई भाग नही होती है धन यह पूँजी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं की जा सकती। प्रो० मासल इसे व्यक्तिगत धन (Personal Wealth) कह कर पुकारता है। इसी आधार पर किसी अध्यापक की ज्ञान शक्ति (The Intellect of a teacher) भी पूँजी नहीं कही जा सकती।

⑤ कृपण का धन (The Miser's Wealth)—यह पूँजी नहीं है, क्योंकि कृपण के धन का उपयोग फलोत्पादन के लिये नहीं होता है। उसका धन केवल अनुत्पादक संचय मात्र ही है।

⑥ एतद्व्यवहार अधिकार (Patent Right)—यह व्यक्तिगत पूँजी है, क्योंकि इसमें उसको प्राय होती है।

⑦ चल मुद्रा (Money in Circulation)—यह तबल विनिमय-माध्यम हो होने के कारण किसी एक की पूँजी नहीं हो सकती। हस्तस्थ मुद्रा किसी व्यक्ति विशेष को वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार प्रदान करती है, अतः यह चल पूँजी (Floating Capital) भी नहीं जानी है।

⑧ बैंक में स्थित संचित राशि (Accumulated Savings in the Bank) बैंक में जमा कराने वाले व्यक्ति की संचय के रूप में धारण होने से यह उसकी व्यक्तिगत पूँजी है। यदि बैंक संचित राशि को फलोत्पादन में लगाता है तो यह सामाजिक दृष्टि से भी पूँजी है।

पूँजी और मुद्रा (Capital & Money)—साधारणतया यह विद्वान्स किया जाता है कि पूँजी और मुद्रा एक ही वस्तु है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह निस्संदेह सच है कि हमारा वचन का अधिकार भाग मुद्रा के रूप में होता है और लक्ष्य सभी पूँजी वाले मामलों की मुद्रा की ही सहायता से प्राप्त किया जाता है। किन्तु सब मुद्रा पूँजी नहीं हैं। मुद्रा तभी पूँजी कहलायगी जब उसका उपयोग फलोत्पादन के लिये किया जाय। यदि उसे खान, कपड़ा आदि अन्य उपयोग की वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, तो वह पूँजी नहीं है। इसी प्रकार जो मुद्रा संचित कर गाढ़ की जाती है वह भी पूँजी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि समस्त पूँजी मुद्रा के रूप में नहीं रहती। धन, मशीन, कच्चा माल आदि भी पूँजी हैं परन्तु उनमें से

कोई मुद्रा नहीं है। अस्तु यह सिद्ध हुआ कि अर्थशास्त्र की दृष्टि में मुद्रा और पूँजी दोनों एक नहीं हैं। नव मुद्रा धन अवश्य है, निन्तु नव मुद्रा पूँजा नहीं है।

पूँजा और भूमि (Capital & Land)—पूँजी और भूमि में निम्नलिखित भेद है—

(१) पूँजी मानव प्रयत्न का फल है जबकि भूमि प्राकृतिक प्रसाद (Gift of Nature) है।

(२) पूँजी नाशवान होती है। विम जाव के बाद पूँजी को नव निरे में लगाना पड़ता है। परन्तु भूमि अणव योग्य अविवर्तनी है।

(३) पूँजी माँग का समाप्तिमा व अनुसार बदली रहता है परन्तु भूमि का परिमाण परिवर्तित है।

(४) व्यक्तिगत दृष्टि में भूमि का द्रव्य विग्रह्य होना है परन्तु सामाजिक दृष्टि में भूमि एक प्राकृतिक प्रसाद है। ननिन पूँजी के लिये गण्य और व्यक्ति दाना का ही मानन गवाना पड़ती है।

(५) महत्ता की प्रगति में माध धन्य वस्तु सन्नी होनी जाती है परन्तु जनसंख्या की वृद्धि में भूमि महत्ता हानी जाती है।

(६) पूँजी गुन्व के आधार पर मापी जाती है परन्तु भूमि का मापन धरातल के क्षेत्र के आधार पर होता है।

(७) भूमि का स्थान स्थिर होता है। परन्तु अविवर्तन पूँजी परिवर्तनशील होती है। केवल कुछ ही भूमि स्थिर होती है।

क्या भूमि पूँजी है? (Is Land Capital)—युट लेवका का मत है कि भूमि भी एक प्रकार की पूँजी है उसे पूँजी की गुणों में सम्मिलित करना आभोद प्रसाद की मोटर यात्रियाँ को दोन वाली मोटर



धन

पूँजी

वाहिन। भूमि धन है और उत्पादन में बहुत सहायक है। मशीन और कच्चे माल की भाँति जब कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो उसे कुछ मूल्य देना पड़ता है। अतः भण्य प्रसार की पूँजी का भाति भूमि भी व्यक्तिगत दृष्टि में पूँजी है। इसके अतिरिक्त भूमि का वह भाग जो मानव प्रयोग में लाया जाता है अधिकतर अनुप्रा द्वारा ऐसा बन सका है। दृष्टी नारणा में यह कहा जाता है कि भूमि को पूँजी माना जाय। इस दृष्टि में बहुत सत्यता है। निन्तु भूमि और पूँजी का वन्य भ्रमण वस्तु है। इन दोनों में महत्वपूर्ण भेद है। उदाहरण के लिये, भूमि प्राकृतिक प्रसाद है और पूँजी मानव

प्रयत्न का फल है। सम्राज का भूमि के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता है, यद्यपि व्यक्तिगत भूतन्त्र का उसके नियंत्रण अधिकार अक्षय्य होता है। भूमि का यह अन्तर तथा अन्य अन्तर जितना उन्मुख ऊपर किया जा सकता है, स्पष्ट करने हैं कि भूमि और पूँजी दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं। उन्मुख एक मानना अर्थात् भूमि को पूँजी की क्रांति में छाना उचित नहीं है।

पूँजी की विशेषताएँ (Characteristics of Capital)—पूँजी की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

१ पूँजी उत्पत्ति का एक अनिवार्य माध्यम है क्योंकि इसके द्वारा उत्पत्ति सम्भव नहीं है। बड़ा परमाणु की उत्पत्ति के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक माध्यम है।

२ पूँजी उपयोग के या समय बीतने के साथ-साथ घिसती जाती है और उसका प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है—उदाहरण के लिए, कोई एक मशीन १० वर्ष कुशलतापूर्वक काम कर सकती है और उसका मूल्य १०,००० रुपये है, तो प्रतिवर्ष उसका मूल्य का दमना भाग घिसाट (Depreciation) के कारण कम होता जायगा यहाँ तक कि ६५५ वर्ष बाद वह मशीन निरर्थक होकर मूल्य शून्य की हो जायगी। प्रतिवर्ष का घिसाट का मूल्य यद्यपि १,००० रूपये मात्र है मगर निरन्तर कर प्रतिस्थापन (Replacement) के लिए यह आवश्यक है कि १० वर्ष पश्चात् मशीन के प्रतिस्थापन के लिए उक्त राशि का व्यवस्था हो जायगा।

३ पूँजी बचत का परिणाम है जिसे वैयक्तिकता (Waiting) कहते हैं—यह पूँजी उधार लेने वाले या पूँजीपति का धन के रूप में कुछ वृत्तिकार देना आवश्यक हो जाता है।

पूँजी का महत्व (Importance of Capital) आर्थिक जीवन

(१) पूँजी उत्पत्ति का एक अनिवार्य माध्यम है—वस्तुतः मनुष्य पूँजी का सर्वप्रथम स्थान है। यदि हम मानव समाज के विकास की प्राथमिक अवस्था पर भी नज़र डालें तो ज्ञात होगा कि पूँजी का किसी न किसी रूप में उपयोग आवश्यक था। मनुष्य के विकास और ज्ञान की वृद्धि के माध्यम से पूँजी का महत्व बढ़ता गया, यहाँ तक कि पूँजी की प्रचलना के कारण वस्तुमान प्रथम का 'पूँजी-युग' कह कर पुकारा जाता है। यह स्पष्ट है कि भूमि और श्रम की क्रांति से पूँजी नहीं आती, किन्तु उत्पादन के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मनुष्य जीवन बिना इसमें नहीं चल सकता।

(२) पूँजी के बिना न तो मनुष्य की शक्ति का ही पूर्ण रूप से उपयोग हो पाता है और न प्रकृति-दत्त वस्तुओं का ही सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है—पूँजी के अभाव में न तो प्रकृति की शक्तियों का उचित उपयोग हो सकता है और बिना उन्मुख न हमें काम को कुछ कर सकते हैं।

(३) पूँजी महोत्सव उत्पन्न करती रहती है और जो लोग इस क्षेत्र में मग्न हैं उनका ध्यान भ्रमण होता है—सांख्यिक उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से रखा (Roundabout) और जटिल (Complex) है। वस्तुतः के उत्पादन में प्रचलन समय लगता है। उत्पत्ति के पश्चात् उत्पत्ति में नैतिकता आती है और उत्पत्ति

अप्य-विरुद्ध होता है। मगर वही जाकर उत्पादकों की अपनी वस्तुओं का मूल्य मिल जाता है। उस समय तक उत्पादक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूँजी पर ही निर्भर रहने है।

(४) पूँजी से धनोत्पत्ति की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा सकती है—धनोत्पत्ति में भूतल, मशीनें, योजन, कच्चे माल, ईंधन आदि का आवश्यकता पड़ती है। इन सब वस्तुओं की पूर्ति पूँजी द्वारा ही की जा सकती है।

(५) पूँजी की सहायता से ही विस्तृत और निश्चित रूप में उत्पादन सम्भव है—धन विभाग की ओर पूँजी के ही उपयोग का कल है। पूँजी के उपयोग से उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और लागत बहुत घट गई है।

अतः से आदि से अतः तक धनोत्पत्ति में पूँजी की सहायता लेनी पड़ती है। उत्पादन की कोई भी शाखा या व्यवस्था हो उसमें पूँजी का उपयोग अनिवार्य होता है। पूँजी के महत्व और उसके बहुपयोगिता की समाजवाद (Socialism) के जनसंघर्ष मार्क्स ने भी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। वही नहीं, कम जैसे मार्क्सवादी (Communist) देशों में भी पूँजी का उपयोग बड़ परिमाण में किया जाता है।

पूँजी के कार्य (Functions of Capital)- पूँजी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

१. आजीविका का साधन (Provision of Livelihood)—प्राथमिक उत्पादन प्रणाली टूटी और बर्बाद है। असु, उत्पत्ति के प्रारम्भ में माल की दिक्रा तक पर्याप्त मजदूरी मिलती है। इन अवधि में उत्पादन मालिकों का पैसा बचता, वह आदि आवश्यक वस्तुओं, प्रधान करने का कार्य पूँजी द्वारा सम्पन्न होता है।

२. उत्पादन सामग्री का साधन (Provision of Appliances)—पूँजी द्वारा कारखाना, भवन, यन्त्र, उपकरण आदि अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। प्राथमिक उत्पादन रीतियों प्रति आधुनिक और विस्तृत होने के कारण बहुत धन की आवश्यकता होती है।

३. कच्चे माल का साधन (Provision of Raw Material)—पूँजी द्वारा जो कारखानों के लिये कच्चा और बड़े विविध माल प्राप्त किया जाता है।

पूँजी के भेद (Types of Capital)

मिश्र-मिश्र लेवका ने पूँजी का व्यवस्था-व्यय वर्गकरण किया है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) चल और अचल मजदूरी या स्थायी और स्थायी (Fixed & Circulating Capital)—चल या अस्थायी पूँजी उसे कहते हैं जो उत्पादन कार्य में खर्च हो एक ही बार के उपयोग करने में लाने जाती है। जैसे कच्चा माल, कारखाना बाजार आदि। अचल या स्थायी पूँजी उस कहते हैं जिसका प्रयोग उत्पादन के लिये बार-बार किया जा सकता है। जैसे भवन, मशीनें, यन्त्र, इन्जिन आदि। प्राथमिक माल में अचल या स्थायी पूँजी में बहुत की परती है और बच-बच कारखाना में इनका विशेष महत्व है।

(२) उत्पात्ति-प्रधान (या व्यापार) और उपभोग-प्रधान पूँजी (Production (or Trade) & Consumption Capital)—जिन वस्तुओं में अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति होती है वे उत्पत्ति प्रधान पूँजी कहो जाते हैं, जैसे, कच्चा माल, भवन, मशीनें, योजनार आदि। उपभोग-प्रधान पूँजी ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिनसे प्रत्यक्ष उपभोग से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जैसे थमिकों को दिये हुए भोजन, वस्त्र, निवास स्थान आदि।

(३) निम्न और चर पूँजी (Sunk & Floating Capital)—निम्न पूँजी वह पूँजी है जो केवल किसी विशिष्ट कार्य में लगाई गई हो और उसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं हो सकता हो। उदाहरणार्थ, रेल के इंजिन या पुल बनाने में लगी हुई पूँजी। निम्न पूँजी का किसी एक विशिष्ट कार्य में लगे रहने के कारण इसे एकमयी या विशिष्ट पूँजी (Specialised Capital) भी कहते हैं। चर पूँजी उन पूँजी को कहते हैं जो उत्पात्ति के एक कार्य में हटा कर दूसरे कार्य में लगाई जा सकें, जैसे मुद्रा, कच्चा माल आदि। इसको बहुमयी या प्रविष्ट (Unspecialised Capital) भी कहते हैं।

(४) भौतिक और वैयक्तिक पूँजी (Material & Personal Capital)—भौतिक पूँजी वह है जिसमें दृश्यमान भौतिक पदार्थ निहित हो और जिसका व्यव-पिप्रय या हस्तांतरण हो सकता हो, जैसे—पुंजान, मशीनें, कच्चा माल, आदि। किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जग, स्वभाव और कार्य-क्षमता को आधार-भूत धारणाओं और उत्तर प्रश्न नहीं की जा सकती वैयक्तिक पूँजी कहलाती है, जैसे—किसी राजन की दक्षता, सम्भावक की ज्ञान शक्ति आदि।

(५) वेतन और सहायक पूँजी (Remuneratory & Auxiliary Capital)—जो पूँजी धमिकों को उनके श्रम के प्रतिफल स्वरूप दी जाय वह वेतन पूँजी कहलाती है और जो पूँजी उत्पात्ति के कार्य में सहायता पहुँचाती है उसे सहायक पूँजी कहते हैं, जैसे मशीनें, योजनार आदि।

(६) देशी और विदेशी पूँजी (Indigenous & Foreign Capital)—जिस पूँजी पर एक ही देश के नागरिकों का स्वत्वित या सामूहिक रूप में अधिकार हो उसे देशी पूँजी कहते हैं। जो पूँजी अन्य देशों की होती है अथवा जिस पर विदेशियों का अधिकार होता है वह विदेशी पूँजी कहलाती है।

एक भारतीय कृषक की पूँजी—एक भारतीय कृषक पूँजी का उपयोग कई रूप में करता है जिसका वर्गीकरण चल या अस्थायी और अचल या स्थायी पूँजी में किया जा सकता है। हथ, बैल जोड़ा, रस्सियाँ, गाढ़े, पावड़ा, कुल्हाड़े, डलियाँ या टोशरियाँ—ये सब उसकी अचल या स्थायी (Fixed Capital) में सम्मिलित हैं। उसकी चल या अस्थायी पूँजी (Circulating Capital) में सम्मिलित वस्तुएँ बीज, मजदूरी, भ्रम और चारा आदि हैं। खाद का वर्गीकरण दोनों प्रकार की पूँजी में किया जा सकता है।

एक भारतीय वटई की पूँजी—उसकी अचल या स्थायी पूँजी—सारे काम करने के योजनार, और चल या अस्थायी पूँजी—कच्चा माल अर्थात् लकड़ी के लट्टे व लकड़ें, मजदूरी की मजदूरी, यदि कोई ॥

पूँजी की कार्यक्षमता (Efficiency of Capital)—पूँजी की कार्यक्षमता मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर होती है—(१) उपयुक्तता, (२) सदुपयोग और (३) परिणाम तथा सफलता ।

(१) **उपयुक्तता (Suitability)**—जिस प्रयोजन के लिए पूँजी का उपयोग होता है उसके लिये वह उपयुक्त होना चाहिये । उदाहरण के लिये, एक तेज और महंगा सस्तरा नाई के लिए ठीक है पर उसी वस्तु का उपयोग धातु आदि के लिये अनुपयुक्त है, क्योंकि यह कार्य तो एक सस्ते व गाधारण चाकू से भी प्रकार मध्यम किया जा सकता है ।

(२) **सदुपयोग (Proper Use)**—पूँजी के प्रयोग करने की रीति पर भी उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है । जैसे, किसी अनुष्ठान थमिक को किसी मशीन पर बिना बिना जाय, तो वह उसका प्रयोज्य उपयोग नहीं कर सकेगा जिसके फलस्वरूप मशीन की कार्यक्षमता में कमी हो जायगी ।

(३) **परिमाण तथा संगठन (Quantity & Organisation)**—जब व्यवसाय को उत्पन्न के साथ-साथ पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है, तो पूँजी की उत्पादन शक्ति भी बढ़ती जाती है । परन्तु यह स्मरण रहे कि पूँजी व्यवसाय में अधिक मात्रा में उन देशों में लगाई जाती है जहाँ अधिक मात्रा में अनिश्चितता, सुरक्षा और व्याप प्रभावित हो और जहाँ के लोग औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से सुसज्जित हों ।

पूँजी की वृद्धि (Growth & Accumulation of Capital)—संचय या बचत (Savings) से पूँजी की वृद्धि होती है । संचय द्वारा ही धन की पूँजी का रूप दिया जाता है । पूँजी की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपनी समस्त आय को व्यय न करके उसका कुछ भाग बचाए । जिससे अधिक धन की आवश्यकता होती हो अधिक भविष्य में पूँजी में वृद्धि होगी । अतः, पूँजी का परिमाण संचय या बचत से परिमाण पर निर्भर है ।

पूँजी की वृद्धि मुख्यतः दो बातों पर निर्भर है—(क) संचय करने की शक्ति और (घ) संचय करने की इच्छा । ये विभिन्न कारणों द्वारा प्रती-प्रकार व्यक्त की गई हैं :

पूँजी की वृद्धि निर्भर है—		
(क) संचय करने की शक्ति	(घ) संचय करने की इच्छा	
इंग्लिश का उपयोग	निजी या व्यक्तिगत बातें	बाहरी बातें
	१. शिक्षणीयता या दूरदर्शिता	१. जल व माल की संस्था
	२. पारिवारिक स्नेह	२. पूँजी के निवेशों की सुविधाएँ
	३. सामाजिक एवं राज-नैतिक प्रतिपादनाएँ	३. सुयोग्य व्यापारी एवं उद्योगपति
	४. आर्थिक प्रेरणाएँ	४. व्यापार को ऊँची दर
	५. स्वभाव	५. मुद्रा का स्थान-साधन के रूप में प्रसिद्ध

(अ) सचय करने की शक्ति (Power or Ability to Save)—सचय की शक्ति उपभोग की अपेक्षा उत्पत्ति के अधिक होने पर निर्भर है। उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने से सचय शक्ति में वृद्धि होगी। यदि किसी देश में उत्पत्ति का परिमाण अधिक है और उपभोग का कम है तो उस देश में बचने की शक्ति अधिक होगी। व्यक्तिगत दृष्टि में भी वन्य तभी सम्भव है जब कि व्यय की अपेक्षा आय अधिक हो। किसी देश की उत्पात्ति अथवा वहाँ के निवासियों की आय का अधिपत्य निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता है —

१ किसी देश के प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता (Rich Natural Resources of a Country)—उत्तम समुद्र तट बंदरगाह तथा जलवायु, उपजाऊ भूमि (प्रतिवर्ष पदार्थों की प्रचुरता) आतायात के साधन, जन शक्ति और जहाज चलाने योग्य नदियाँ आदि।

२ अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम भौगोलिक स्थिति (Good Geographical position in relation to other countries)

३ कृषि, व्यापार और उद्योगों का तत्पर विकास (Efficient Development of Agriculture Trade Commerce & Industry)

४ भूमि धन और पूँजी का संगठन (Organisation of Land & Labour & Capital)

५ बैंक और सार्वजनिक मुद्रास्वाध्याय का सुव्यवस्था (Efficient Organisation of Banking & Credit Facilities)

६ आधुनिक मशीनों और रीतियों का उपयोग (Use of up to date Plants Machinery and Processes)

७ वैज्ञानिक कृषि (Scientific Agriculture)

(आ) सचय करने की इच्छा (Will to Save)—बचने से सचय शक्ति में ही पूँजी की वृद्धि नहीं हो जाती। इसके लिए सचय करने की इच्छा भी होनी चाहिए। सचय करने की इच्छा पर भ्रमणवाद दो बातों का प्रभाव पड़ता है —

१ निजी या व्यक्तिगत बात और २ बाहरी बातें। अब इन दोनों पर संक्षेप में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विचार किया जायगा।

१ निजी या व्यक्तिगत बात (Subjective Considerations)—इस शीर्षक में प्रत्यक्ष उन बातों का विवेचन किया जायगा जो मनुष्य का एक सचय में विशेष प्रेरित करती हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(१) विवेकशीलता या दूरदर्शिता (Prudence or Foresight)—दूरदर्शी और विवेकशील पुरुष भविष्य की श्रमक प्रापति तथा बचने के लिए आय का कुछ भाग बचाने में निर्णय प्रयत्नशील देखे जाते हैं। ये प्रापति या योग्यता, पसारी, आलस्य, व्ययता आदि के कारण ही मजबूत हैं। फिर बुद्धिमत्ता में काम करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। अतः उस अवस्था में काम में जाने के लिए बाध पड़ सचय करने में।

(२) पारिवारिक स्नेह (Family Affection)—पारिवारिक स्नेह से सचय की सबसे बड़ी प्रेरण शक्ति है। काम अपना सन्तान की शिक्षा दीक्षा व विवाह आदि के

निय धन की आवश्यकता और मनुष्य के पश्चात् अपने आश्रितों के लिये कुछ छोड़ जान का इच्छा में प्रेरित होकर धन संचय कर ले है ।

(३) सामाजिक एवं राजनैतिक अभिलाषाएँ (Social & Political Considerations) — सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्ति के लिये धन की विविध आवश्यकता पड़ती है । आजकल धन के द्वारा मनुष्य सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपने आप का ऊपर उठा सकता है धन इसमें धन मनुष्य प्रवृत्ति का वही प्रात्याह्वन मिलता है ।

(४) आर्थिक प्रेरणाएँ (Economic Considerations) — मनुष्य अपना आर्थिक स्थिति का सुधारन के लिये धन मनुष्य में सबसे रहता है । व्यापारियों की प्रेरणा में भी धन संचय प्रवृत्ति का प्रधान प्रात्याह्वन मिलता है । धन के द्वारा मनुष्य के लिये धन के जिससे काम पूरा होनी है वही व्यापार और व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है । व्याज प्राप्ति को इच्छा में भी मनुष्य का लक्ष्य धन संचय की ओर इशारा हो जाता है । जितनी अधिक व्याज की दर होना, उतनी अधिक धन संचय का प्रयत्न इच्छा होगी ।

(५) स्वभाव (Temperament) धन संचय करना कुछ मनुष्यों की स्वभाव की बात है । उनकी आय चाहें जितना हो वे उसमें से कुछ न कुछ संचय करवा लेते हैं । बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका प्रवृत्ति बचाना का बही होता है बचि जाना पाना और चयन रहना — यह उनका प्रिय होता है ।

२ बाहरी जान (Outer Considerations) — धन संचय करने का इच्छा का प्रेरणा करने बिना व्यक्ति का निजी जाना से ही नहीं बल्कि देश में स्थित बाहरी दशा से भी मिलती है । ये दशा मनुष्य में निम्नलिखित है —

(१) जान व माल की सुरक्षा (Security of Life & Property) — धन संचय इच्छा को प्रेरणा देने के लिये देश में जान व माल की रक्षा का साधन उपस्थित होना अनिवार्य है । यदि माला को यह विश्वास है कि उनकी पूँजी सुरक्षित न रहेगा उस कारण डर उठा ले जायगा या सरकार द्वारा धन लेना कर के तब तक नहीं करेगा और अपनी सारा धन की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय करेगा । परन्तु धन संचय तब सम्भव है जब देश में शांति और सुव्यवस्था हो ।

(२) पूँजी के विनियोग का सुविधाएँ (Facilities for Investment) — लोगो में संचय प्रवृत्ति को प्रबल करने के लिये यह आवश्यक है कि देश में पूँजी के विनियोग का सुविधाएँ अधिकतम मात्रा में उपलब्ध हो । जहाँ जहाँ उद्योगों में धन में रुचि होती जायगी, वहाँ वहाँ पूँजी की लगाने का आवश्यकता धन में भी रुचि होती जायगी । वेदा और बीमा कंपनियों में पूँजी जमा करने में पर्याप्त सहायता मिलती है । भारतवर्ष में इन साधनों का अभाव होता है ।

(३) मुद्राया व्यापारी एवं उद्योगपति (Capable Businessmen & Industrialists) — देश में सर्वाधिक मुद्राया व्यापारी एवं उद्योगपति का होना ही पूँजी संचय का बड़ा प्रात्याह्वन मिलता है । जहाँ उनकी कृपावश में सचाई पर विश्वास कर अपना पूँजी का कुछ व्यापार व उद्योगों में भी लगाया जा सके है जिसमें पूँजी में वृद्धि होती स्वाभाविक है । इस देश में मुद्राया व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की अभाव नहीं है ।

(४) व्याज की ऊँची दर (High Rate of Interest)—यदि देश में व्याज की ऊँची दर प्रचलित है तो लोग दूसरे काम उद्योगों के लिए पूँजी-मध्य की ओर भूक जाते हैं। भारतवर्ष में व्याज की दर काफी ऊँची है परन्तु इसका लाभ केवल कुछ ही लोगों तक सीमित है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या निर्धन है।

(५) मुद्रा का मध्य-मापन के रूप में अस्तित्व (Existence of Money as a Store of Value)—लोगों को वस्तुओं का रूप में धन-समृद्ध करना पड़ता है। इसमें अनेक श्रमविषाएँ तथा कठिनाइयाँ होने के कारण लोग वस्तु रूप धन-मध्य नहीं करते। मुद्रा मूल्य का भण्डार है। इसमें स्थानिक या पूर्ण होता है। मुद्रा का भौग वरावर बनी रहती है। यह सीधे नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है और न इसके मूल्य में उतार-चढ़ाव हो जाता है। यही मुद्रा के रूप में धन-मध्य के अन्तर्गत लोगों ने इस प्रकृति का बड़ी प्रेरणा मिली है। हमारे देश में यह मूल्य विद्यमान है।

भारतवर्ष में पूँजी का विकास—मध्य शक्ति भारतवर्ष में पूँजी की बड़ी कमी है। इसमें देश का प्राथमिक उद्योग में बड़े-बड़े उद्योग हैं। पूँजी के अभाव में प्राकृतिक सौभाग्य का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ का उद्योग-व्यवसाय प्राचीन दृष्टि अवस्था में है जबकि अन्य देशों में औद्योगिक व्यवस्थाएँ तथा उद्योग में कृषि में पर्याप्त उन्नति हो रही है। उद्योग धन की भी पर्याप्त कमी है। इन सब कारणों से देश का उद्योग कम है तथा यहाँ के अधिकांश निवासियों की आय इतनी कम है कि वे बचत कर ही नहीं पाते।

मध्य-उच्छेद (मिनी बाने)—यहाँ पूँजी-मध्य की उच्छेद को प्रभावित करने वाली निम्न बातों का भी अभाव नहीं है। हम में पारिवारिक स्तर है और अपन नियमों का पालन पालन व्यवस्था के लिये कुछ न कुछ मध्य करने की भी इच्छा है। निम्न धनवानों को छाड़कर मध्य साधारण लोग मध्य में ही समाहित व राजनैतिक सम्मान प्राप्ति की इच्छा है और न उनमें पर्याप्त दूरदर्शिता ही है। इसका मुख्य कारण भारतीयों की दूरदर्शिता है। पर वास्तविक कारण जिनका साथ धन-मध्य नहीं कर पाते वचना की निर्णयता है। अधिकांश भारतीयों को मध्य भावों पर्याप्त धन और मकान प्राप्ति तक उपलब्ध नहीं होने, तो अन्तः प्रभाव कि मध्य-मध्य धन वचना कर सकते हैं। निम्न लोग में कुछ वचना की शक्ति है उनमें सर्वोच्च कुटुंबियाँ पर नियम हैं। यह अगिला, अन्तः-विश्व और दुर्गो सामाजिक गति-विचारों का फल है।

मध्य शक्ति (वाली बाने)—पूँजी के विकास की मध्य शक्ति का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर पूँजी के निवेश (Investment) के सुरक्षित और लाभप्रद साधनों का अभाव है। नये व्यावहारिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उपयोग व्यवहार भी बढ़ रहा है, परन्तु अन्य देशों की अनेक यह वचना का कम है। बेरोजगारी का दर भी देश के आकार के अनुसार नहीं है। इन कारणों से कई बँकों के फल होने में पूँजी मध्य कार्य में बड़ी बाधा पड़ती है। इसके अनिश्चितता का मध्य धन को भी प्रकृति है। यदि धन में पूँजी वृद्धि नहीं होती। इस देश में वचना के विविध प्रकार में पर्याप्त धन वचना के अवसर में दिया जाता है। निम्न ही राज, महागंगा आदि धन धन का मनमाना उपयोग कर रहे हैं। सब ना यह है कि लोग मध्य-मध्य देश करने न नियम, निष्ठा, शांतियाँ आदि जैसे धन व योग्य दक्षताओं और व्यावहारिकों की अधिक संख्या में देश देश का आवश्यकता है।

पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Capital)

पूँजी की गतिशीलता का अर्थ—पूँजी के स्थान या उपयोग में दूसरे स्थान या उपयोग में प्रयुक्त होने की योग्यता और तत्परता को 'पूँजी की गतिशीलता' कहते हैं। उत्पाद के समान मापनों में पूँजी अधिक गतिशील है। पूँजी पूँजीपति से पृथक् की जा सकती है, अतः धन की भाँति पारिवारिक स्नेह, घर का प्रेम, वाना-वरण की अनुकूलता आदि व्यक्तिगत वानों का उसकी गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके प्रतिरिक्त धन और पूँजी की स्थानान्तरण दशाओं में बड़ा भिन्न है। पूँजी सुगमता और कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती है पर धन के साथ ऐसा नहीं है।

पूँजी की गतिशीलता के कारण

(Factors leading to the Mobility of Capital)

१. सुरक्षा (Security)—पूँजी की सुरक्षा पूँजीपति का सबसे पहला ध्येय होता है। पूँजी का विनियोग किसी भी व्यवसाय या व्यापार में हो प्रत्येक वृत्ति पर हो, पूँजी की सुरक्षा पर नज़र भी साफ नहीं मानी चाहिए। सुरक्षा के कारण से पूँजी का विनियोग सम्भव नहीं है।

२. लाभदायकता (Profitability)—दूसरा ध्यान पूँजीपति का व्याज की दर पर होता है। यदि विनियोग सुरक्षित हो, तो पूँजी उच्च में लगाने जायगी जिसमें व्याज की दर अधिक है।

३. विनियोग के मनोपजनक और विभिन्न मार्ग (Satisfactory & Diverse channels of investment)—देख में क्या-क्या और किस प्रकार के विनियोग-मार्ग विद्यमान हैं, यह देख की अविवेक उत्पत्ति पर निर्भर है।

४. तीव्र संचार और पूँजी भेजने के साधन (Rapid Means of Communication and Transmission of Capital)—बिना तीव्र संचार और पूँजी भेजने के साधनों के पूँजी का एक स्थान में दूसरे स्थान की सौझना व कम लागत में भेजना सम्भव नहीं है।

५. विनियोग-क्षेत्र की राजनैतिक स्थिरता (Political Stability of the Region of Investment)—जिस क्षेत्र में पूँजी लगाई जाना चाहें, राजनैतिक स्थिरता में सुदृढ़ होना चाहिए, अन्यथा उसके प्रति विविधांगक के दिल में विश्वास जगता नहीं होगा।

६. आर्थिक व्यवस्था का विकास (Development of Financial Mechanism)—पूँजी की गतिशीलता में बैंक व्यवस्था उच्च महत्त्व है। अतः उसका विस्तार होना आवश्यक है।

पूँजी की गतिशीलता में भिन्नता (Variation in the Mobility of Capital)—पूँजी की गतिशीलता इन बातों पर भी निर्भर होती है कि पूँजी तरल (Liquid) है या स्थिर (Fixed)। तरल पूँजी अति गतिशील होती है। जैसे गन्धक गैस और विपण्य प्रतिवृत्तियाँ (Marketable Securities) आदि वस्तुएँ जिसका सौदा गति में परिवर्तन सौझना और सुगमता में हो सके। स्थिर पूँजी इसकी गतिशीलता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, गन्धक, लौह, मरुनादि में लगी हुई पूँजी बड़ी कठिनाई में बाध

निकासो जा सकती है। इन वस्तुओं के विपणन में अधिक भयंकर सुगता है तथा क्षति भी पहुँचती है।

भारत में पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Capital in India) भारतीय पूँजी अर्थिक गतिशीलता नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) आर्थिक विकास का सौंझ काल (Infancy of Economic Development)—भारत का आर्थिक विकास का नियत नई औद्योगिक योजनाएँ बन रही हैं तथा उनमें कई क्रियाशील भी हो रही हैं परन्तु उनको सुरक्षा व प्रति अभी काया व पूर्णतः व विश्वास नहीं हुआ है। अतः लम्बी दशा में पूँजी का गतिशीलता अधिक नहीं हो सकती।

(२) हमारा आर्थिक ढाँचा आर्थिक मुख्यव्यवस्थित नहीं है (Our Financial Mechanism is not well Developed)—वर्तमान बैंक देश का आवश्यकता में बहुत कम है। देशाना में तो इनका पूर्ण अभाव है। इनके प्रतिरिक्त बका की विम्व भी बहुत कम है। इसमें पूँजी की गतिशीलता में बाधा पहुँचती है।

(३) साहस का अभाव (Lack of Enterprise) सरकारीकरण में साहस का अभाव है। उनमें जोखिम उठाने की भावना अभी पूर्ण रूप से अज्ञात नहीं हुई है। अस्तु विनिर्माण मात्र भाव कम है।

(४) बेईमानी (Dishonesty) कभी-कभी अर्थशास्त्रिक गणितियाँ व प्रसिद्धि का भूँटा प्रचार कर तथा उनके नाम के अति अनेको साधारण विचार जनता से पूँजी हट्टी करती जाती है। जब वास्तविकता प्रकाश में आती है तो लोगों का विश्वास विफल पड़ा जाता है। इससे दुश्भाव में अनेक कम्पनियाँ को भी हाथ पहुँचती है।

(५) जन साधारण की अत्यधिक निधनता (Extreme Poverty of the People)—आरक्षण में अर्थशास्त्र लोग इन निधन हैं कि उन्हीं वसात आरक्षण वस्त्र प्राप्ति तक उपलब्ध नहीं होते। ऐसी दशा में उनमें वस्त्र की मात्रा अत्यन्त मंद है। देशाना में श्रमीत्या की वृद्धि कम आय होने से वहा पूँजी की वृद्धि और भी कम है।

(६) दृढिदादिता और लागू की अनुत्पादक मध्य की प्रकृति (Conservatism & Hoarding Habit of the People)—अर्थशास्त्र भाग्यशाली प्रयत्न प्रवृत्ति का पथ में विचलित नहीं होना चाहते हैं। प्राचीन समय में लोग अल्पता पूँजी गृह्य साधन में निवेशित हैं अथवा उसे जमीन में गाँवर रखते हैं। इसमें उत्पादक कार्य के लिए पूँजी का अभाव हो जाता है।

(७) सहायक व्यवसायों और धन्दा का अभाव (Lack of Subsidiary Industries and Occupations)—सहायक व्यवसायों और धन्दा का अभाव में पूँजी जनता में अल्प मात्रा में आ जाती है जिसमें पूँजी की पूर्ति और उम्मा गतिशीलता हो जाता है।

(८) विश्वसनीय सूचनालय का अभाव (Lack of reliable Information Bureaus)—आरक्षण में ऐसी सराफ़ा का पूर्ण अभाव है जिससे उद्यम साधारण पूँजी के सुविधान व लाभदायक विनिर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

(९) विश्वासमान और अनुभवी उद्योगपति और व्यापारियों का अभाव (Lack of Reliable and Experienced Industrial Magnates & Businessmen)—जन साधारण में अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का भावना अभी दूर ही

सकती है जबकि देश में अधिकाधिक मक्या में निर्यातमान और अनुभवहीन उद्योगपति व व्यापारी हैं।

(१०) सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of the Government)—ब्रिटिश राज्य काल में सरकार की औद्योगिक नीति भारतीय उद्योगधर्मा के विपरीत रही। परन्तु अब भा भारत सरकार की नीति विपरीत स्पष्ट नहीं है सरकार ने १० वर्ष पूर्व उद्योगों में राष्ट्रीयकरण की बात जा दश व सामने प्रस्तुत की है उसमें पूँजीपतियों के सम्मिलित में योजना पैदा कर दी है।

भारत में पूँजी की अनिच्छितता की वाधामा का दूर करने के उपाय

१. निर्यात बैंक और अन्य सहायक मक्यामा की स्थापना (Establishment of Investment Bank & Other Financial Bodies)—इसमें पूँजी व निर्यात व सम्बन्ध में ठीक और निर्यात करन माय्य सहाय मिल सकती है।

२. वैयक्तिक मकल होने वाली मक्याएँ हा चालू की जाय (Partially only concerns having the effect of success)—राज्य व औद्योगिक विकास व रक्षण काल में पत्र होने वाली मक्यामा की आरम्भ करना बरा आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें लोग की पूँजी लगाने में बड़ी हिचक पैदा हो सकती है।

३. प्रांतीय औद्योगिक निर्यातकाल की स्थापना (Establishment of Provincial Industrial Corporation)—भारत में प्रत्येक प्रांत में बनिंग इण्डस्ट्री बमटी व सभाजन व अनुभाग औद्योगिक निर्यातकाल की स्थापना हानी चाहिए जिसमें उद्योगों का दोषनापीन काल मिल सके और जल साधारण में निर्यात सम्बन्धी विद्यमान पैदा हो सके।

४. आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास और सहकार आन्दोलन का प्रसार (Development of Modern Banking and Expansion of Cooperative Movement)—इसमें अनुवादक बापों व सभा हुई पूँजी निर्यात कर उपादक बापों के नियम उपलब्ध हो सकेगी।

५. सरकार की अनुवृत्त नीति (Sympathetic Attitude of the Government)—भारत सरकार की नीति में निम्न उद्योगों के नियम अधिक महानुवृत्ति साधारण है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

- १—पूँजी किसे कहते हैं ? उपादक में उसका क्या स्थान है ? (५० बा० १९५८)
- २—पूँजी का मूल्य किन किन बातों पर निर्भर है ? भारत की पूँजी मक्या की बलवान स्थिति में उदाहरण दीजिए। (५० बा० १९५६)
- ३—पूँजी की मायमायमा किन बातों पर निर्भर है ? व्यवस्थापक द्वारा पूँजी अधिन निर्यातकाल किस प्रकार बनाई जा सकती है ? (३० प्र० १९५६)
- ४—अन्य और अलग पूँजी में भेद बताइए। पूँजी का सफल हो जाना किन किन बातों पर निर्भर है। (३० प्र० १९५८ ३० प्र० १९५३)

५—पूँजी की परिभाषा दीजिए । भारत में पूँजी की सचय की मद भनि व कारण दीजिए । (ग्र० बो० १९५५)

६—पूँजी शब्द से ग्राम क्या अर्थ समझने है ? व कौन सी दशाएँ हैं जो इसकी पूर्ति निर्धारित करती हैं ? यह भी बताइए कि ये दशाएँ भारतीय गाँवों में कहीं तक पाई जाती हैं ? (रा० बो० १९५३)

७—भारतीय सदन में बताइए कि व कौन सी दशाएँ हैं जो धन व सचय में सहायक होती हैं ? व दान कृपक पर कहाँ तक लागू है ? (रा० बो० १९५१)

८—देश में पूँजी के वृद्धि के बाग़ानों को स्पष्ट कीजिए । क्या भारत में पूँजी की कमी है ? (म० भा० १९५५)

९—पूँजी की परिभाषा कीजिए । उसके निर्माण की प्रक्रिया समझाइए । देश में पूँजी का सचय किन कारणों पर निर्भर रहता है वह सभ्य में बताइए । (नागपुर १९५८)

१०—नोट लिखिए —

चन और अचन पूँजी (उ० प्र० १९५७ पृ० ४८) म० भा० १९५५,
नागपुर १९५७ मार्ग १९५५)

इन्टर एग्जामिनेशन

११—पूँजी शब्द की परिभाषा कीजिए तथा चन अचन पूँजी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए । (रा० बो० १९५६, ग्र० बो० १९५७, पृ०)

मशीनों का उपयोग (The Use of Machinery)

मशीनों का प्रादुर्भाव एवं महत्त्व—पूँजी के कार्य रूप है जिसमें मशीन उसका सबसे महत्वपूर्ण रूप है। औद्योगिक क्रांति के कसबस्वर्ण मशीनों के आविष्कार हुये जिनके कारण उत्पादन-क्षेत्र में आश्चर्यानीत उन्नति हुई। मशीनों के प्रयोग में मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की और आधुनिक सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। कृषि, उद्योग, यातायात और व्यापार में मशीनों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मशीनों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इस युग को हम मशीन युग (Machine Age) बहे बिना नहीं रह सकते।

अब हम यह देखेंगे कि मशीनों के प्रयोग में मनुष्य को क्या लाभ और हानियाँ हैं।

मशीनों में लाभ (Uses or Advantages of Machinery)

मशीनों में बहुत से लाभ हैं, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१. प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार बढ़ गया है—मशीनों द्वारा आज मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम कर दिखाये हैं। जैसे, बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल व बांध बना दिये गये हैं, हवाई और समुद्री जहाज, रेलें, बिजली आदि अनेक आविष्कारों में उसने आज प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और करता हो जा रहा है।

२. मनुष्य भारी और निरम काम करने में मुक्त हो गया है—मशीनों के आविष्कारों के पूर्व मनुष्य को भारी से-भारी काम अपने आप करना पड़ता था जिससे उसकी शारीरिक शक्ति में ह्रास होकर वह शीघ्र ही मृत्यु का शिकार हो जाता था। अब मशीन द्वारा भारी-भारी वस्तु उठा कर इच्छित स्थान पर आसानी से पहुँचाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त मशीन के अभाव में एक ही प्रकार का काम मनुष्य को बार-बार करना पड़ता था। परन्तु अब यह कार्य मशीन द्वारा सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है जिसमें कार्य में नीरसता नहीं रहती है। जैसे, वागजों का मोड़ना आदि।

३. मशीन में श्रमिक की योग्यता में वृद्धि होती है—मशीनों में विशेषकर छोटी मशीनों के निर्माण और प्रयोग में बड़ी चतुराई की आवश्यकता होने में वह निपुण, सावधान तथा होशियार हो जाता है जिसके कारण उसकी योग्यता में वृद्धि होती है।

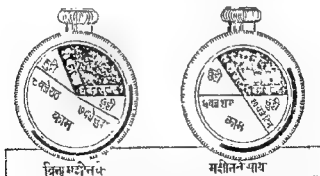
४ मशीनों से श्रम की गतिशीलता घटती है—मशीनों के प्रयोग से श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है। एक कारखाने में काम करने के बाद दूसरे कारखाने में भी काम आसानी से किया जा सकता है क्योंकि कुछ उद्योगों में मशीन लगभग एक ही होती है।

५ मशीन द्वारा काम अधिक नियमितता, निश्चिन्ता और शांति से होता है—मशीन द्वारा जो काम किया जाता है वह मनुष्य की मर्यादा अधिक नियमित, निश्चित और शीघ्र होता है। यदि हाथ से कारीगर दस दिन में एक मशीन बनाता है तो मशीन में दस मिनटों में एक दिन में बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त मशीन द्वारा बनी हुई मशीन "बालू" एक-दो हों परन्तु हाथ से बनी हुई एक ही प्रकार की बस्तुओं में मित्रता पाई जाती है।

६ मशीन द्वारा अधिक बस्तुएँ कम लागत में बनाई जा सकती हैं—मशीन द्वारा बहुत अधिक परिमाण में बनाई जाने के कारण सस्ती पड़ती है। जो बस्तुएँ पहले बेचने में लागत अधिक थी वह अब मशीन द्वारा बनने से उन साधारण के प्रतिदिन के उपयोग की बस्तुएँ हो गई हैं।

७ मशीनों पर अनुकूल श्रमिक भी कार्य कर सकते हैं—साधारण योग्यता वाले श्रमिक भी अब मशीन द्वारा वह काम कर सकते हैं जो पहले निपुण श्रमिकों द्वारा ही सम्पन्न हो सकता था। अब सब दक्षता का कार्य मशीन करती है अधिक से तो केवल मशीन संचालन की ही देख रेख करनी पड़ती है।

८ मशीनों में समय संचयन होती है और अधिक अवकाश मिलता है—मशीनों के प्रयोग में संचयन होने में अवकाश अधिक मिलने लग गया है। इस अवकाश का अब मनोरंजन और मनो-आध्यात्मिक विकास तथा अन्य लाभदायक कार्यों द्वारा सदुपयोग हो सकता है।



९ मशीनों से दूरी और समय की समस्या बहुत कुछ हट हो गई है—

मशीन द्वारा अब माल एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता, गतिशीलता और कम खर्च से भेज सकते हैं। मशीनों का काम दिना और घंटा में होने लग गया है। सड़क के विभिन्न भागों के मनुष्य अब दूर के मशीनों से आया है। अब सारा सड़क मनुष्य के हाथों से बन गया है।

१० मशीन के प्रयोग से मनुष्य की बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास होता है—मशीन पर काम करने के नियम प्रायः ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती हैं जो बुद्धि और उत्तरदायित्व से काम कर सकें। इसीसे मशीन पर काम करने वाले व्यक्तियों की बुद्धि और उत्तरदायित्व में विसम होना स्वाभाविक है।

११ मशीन से राजस्व मिल जाता है—मशीन के प्रयोग में उत्पादन में पर्याप्त विचाम हो रहा है जिससे कमसेकम बहुत मनुष्यों को काम-धन्य मिल जाता है।

१२ मशीन से मजदूरी में उछल होकर जीवन स्तर में सुधार हो सकता है—कामगारों में मजदूरी बढ़ती है जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

मशीनों से हानियाँ

(Abuses or Disadvantages of Machinery)

मशीनों के प्रयोग से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं—

१ मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों की शक्ति कम होती है—मशीनों की गतिबल से एक ही श्रमिक बहुत से श्रमिकों का काम कर सकता है। इससे श्रमिकों की शक्ति कम हो जाती है। परन्तु मनुष्यों के मजदूरी में उछल होकर शक्ति बढ़ जाती है और श्रमिकों में कुछ और व्यक्तियों की भी काम मिल जाता है।

२ मशीनों के प्रयोग से श्रम की नीरसता बढ़ती है—मशीनों पर काम करते समय श्रमिकों का ध्यान एक ही मशीन की गति का देखना ही काम करना पड़ता है, इससे उनका काम नीरस हो जाता है। परन्तु इसके साथ साथ यह भी बात है कि काम के पेटे कम हो गये हैं जिससे श्रमिकों को अधिक मिलने लग गया है। इस अवस्था का श्रमिक मनुष्यों को कर सकता है।

३ मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ता है—मशीनों के आकारों के पूर्ण श्रमिकों को धरती के ऊपर उठाना से स्वस्थतापूर्वक श्रमों के अनुसार गति में काम करते थे जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने नहीं पाता था। लेकिन अब उन्हें परतल हाथों किसी के निर्देशन में नियत समय पर ही निरंतर कार्य में लगना पड़ता है जिससे उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त मशीनों की आवाज और ध्वनि श्रमिकों की शक्ति को बर्बाद करने में जाता है।

४ मशीनों से उत्पादन होना सम्भव है—मशीनों के द्वारा माल की मात्रा में वृद्धि होना है। उत्पादन (Over Production) में वृद्धि में मान के माल की शक्ति पूर्ण बढ़ जाती है जिससे कमसेकम मनुष्य घटने लगता है। उत्पत्ति कम होने लगती है और धार्मिक संकट आ जाता है। श्रमिकों को मजदूरी में घटती और मजदूरी में कम होने लगती है।

५ मशीनों से श्रमिकों की शक्ति कम होती है—मशीनों से बने हुए माल की प्रतियोगिता में श्रम का बर्बाद होना नहीं ठहर सकता क्योंकि श्रम का बर्बाद होना मान में होता है और मनुष्य उसे श्रमिकों में नहीं खरीद सकता। इससे स्वस्थ श्रमिकों का निर्वाह बढ़ने लगता है।

६. मशीन श्रमिकों के शारीरिक एवं नैतिक पतन का प्रमुख कारण वन चुकी है—कारखाना प्रणाली के अन्तर्गत सहस्र मनुष्यों का औद्योगिक केन्द्रों में बंधना पड़ता है जिनसे आवादी में अत्यधिक वृद्धि होकर अस्वास्थ्यकर वातावरण पैदा हो जाता है। रहने के लिए म्यूचल मकानों के अभाव में श्रमिकों को गन्दे बानों कोडरियों में रहना पड़ता है। ऐसे वातावरण में मजदूरी, अत्यधिक भाग दिलावट व अत्य शारीरिक एवं नैतिक पतन करने वाले अनेक दोषों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

७. मशीन से बनी वस्तुएँ इतनी सुन्दर और कलात्मक नहीं होती जितनी कि हाथ से बनी वस्तुएँ होती हैं—मन भी प्रविष्टा कलात्मक वस्तुएँ हाथ से ही बनाई जाती हैं, जैसे कसादे का काम, रेशमी साड़ियाँ आदि।

८. मशीनों के प्रयोग में स्वामियों और श्रमिकों के मध्य सघर्ष चलता रहता है—श्रमिकों को पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है उसमें वे शायः असन्तुष्ट रहते हैं और स्वामियों ने अत्यधिक लाभ को अनुचित बनाने हैं। इसके अनैतिक के और कई मुद्दों का भी माँग करने हैं जिन्हें मिल मालिक देने में आना-कानी करते हैं, इन कारणों से उनमें आपस में सघर्ष चलता रहता है जिनके फलस्वरूप हड़तालें, तालाबंदियाँ आदि भयानक घातक प्रवृत्तियाँ को प्रेरणा मिलता है।

९. मशीन बुद्धिमान श्रमिकों को केवल मशीन चलाने वाले ही बना देती है—मशीन के प्रयोग में श्रमिकों को अपनी कार्यबुद्धि दिखाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सब कार्यबारी का काम मशीन द्वारा ही सम्पन्न होता है। श्रमिक चाहे जितना बुद्धिमान क्यों न हो उसे केवल छोटे भड़े मशीन के चलने की गति को ही देखना पड़ता है।

१०. आधुनिक औद्योगीकरण के दोषों की जन्मदाता मशीने ही है—औद्योगिकवाद से पूँजीवाद की उत्पत्ति हुई है और इसने स्त्री व बच्चा तथा उपनोत्पादों का शोषण होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—वास्तव में, मशीनों से लाभ और हानियाँ दोनों ही हैं। परन्तु वर्तमान समय में मशीनों का प्रयोग इतना बड़ बड़ा है कि उनके बिना हमारा सामाजिक जीवन चलना फटित है। अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ तक हो सके मशीनों के प्रयोग में होने वाली हानियाँ पर विचार किया जाए और उन्हें दूर करने के उपाय सोचे जायें।

मशीनों का उत्पत्ति पर प्रभाव (Effects of Machinery on Production)—मशीनों के प्रयोग में उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि सब यही है और उत्पत्ति को विविध प्रकार में प्रभावित कर दिया है। उत्पत्ति पर मशीन के कुछ प्रभाव भक्ष्य में नीचे दिये जाते हैं :—

१. बड़े परिमाण में उत्पत्ति (Mass Production)
२. वस्तुओं का प्रमाणिकरण (Standardisation of Goods)
३. शुद्धता और यथार्थता (Accuracy and Exactness)
४. उत्पत्ति की कारखाना प्रणाली (Factory System of Production)
५. उत्पत्ति में श्रम-विभाजन (Division of Labour in Production)

६. उत्पत्ति की लागत का अत्यधिक कम होना (Enormous Decrease in the Cost of Production)

मशीनों का श्रम पर प्रभाव (Effects of Machinery on Labour)—
मशीनों के प्रयोग से श्रम पर अच्छे से प्रभाव पड़ने है और बुरे भी । ये दोनों ही प्रकार के प्रभाव नीचे दिये जाते हैं :—

(अ) मशीनों पर श्रम से उत्तम प्रभाव (Good Effects of Machinery on Labour)—

१. मशीनों से श्रमिकों को योग्यता, बुद्धि और विचारशीलता में वृद्धि होती है ।
२. मशीनों के उपयोग से श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है ।
३. मशीनों से श्रम की गतिशीलता में सहायता मिलती है ।
४. मशीन पर प्रकुशल श्रमिक भी यथाविधि काम कर सकता है ।

(आ) मशीनों का श्रम पर बुरा प्रभाव (Bad Effects of Machinery on Labour)—

१. मशीनों के प्रयोग से वेकारी बढ़ती है ।
२. मशीनों से काम में गोरमता आ जाती है ।
३. श्रमिक मजदूरी पर काम करते हैं इसलिए उत्पत्ति-कार्य में उनकी कोई वृद्धि नहीं होती ।

४. श्रमिक मशीन पर बनाई जाने वाली वस्तु के केवल एक ही अंग को देखता रहता है, इसलिए सम्पूर्ण वस्तु के निर्माण होने पर जो प्रसन्नता किसी को होती है इससे वह वंचित रहता है ।

५. मशीन का प्रयोग अपने सुविधानुसार नहीं हो सकता । श्रमिक को तो काम करने के लिये कारखाने में जाना ही पड़ेगा ।

६. मशीन प्रयोग से कुशल श्रमिक केवल मशीन-चालक बन जाता है ।

कृषि में केवल मशीनों का प्रयोग (Use of Machinery in Agriculture)

मशीनों के प्रयोग में तेजी से बड़ी उत्पत्ति हुई है इसका प्रमाण हमें अमेरिका और इंग्लैंड के उदाहरणों से मिल सकता है । खेत की जुलाई से लेकर फसल के घर जाने तक की समस्त क्रियाओं में मशीनों का प्रयोग बड़ा साधनमय सिद्ध हुआ है । उदाहरण के लिये भारतवर्ष में देशी ढंगों और औजारों में होती होती है और इंग्लैंड में आधुनिक मशीनों द्वारा । भारतवर्ष में एक एकड़ भूमि की फसल को एक दिन में काटकर खलियान में ले जाने में २ पुरुष और कुछ स्त्रियों की आवश्यकता होती है, परन्तु इंग्लैंड में मशीनों के प्रयोग से एक आदमी एक दिन में ६ एकर भूमि की फसल को काटकर तथा बाँधकर खलियान में पहुँचा देता है ।

मशीन और भारतीय कृषि (Machinery & Indian Agriculture)

अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में बड़े बड़े खेतों के होने से तथा अन्य कई कारणों से मशीनों का उपयोग किया जाता है परन्तु भारतवर्ष में मशीनों के प्रयोग के लिये अनुकूल परिस्थितियों का अभाव है । अस्तु भारतवर्ष में निम्नलिखित कारणों से खेती में मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता :—

(१) भारतवर्ष छोटे छोटे और वन-वन स्थित लता का देश है जहाँ मगाना द्वारा खेतों लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती ।

(२) भारतवर्ष की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है । मगीना द्वारा बड़े पमाने पर खेतों करने में एवं वनी सस्या में किसानों को बदलत करना पड़गा जिसमें एक दम बेकारी बर जायगी । इस बेकारी की समस्या को हल करना कठिन होगा क्योंकि किसानों के नियमित खेती के अनिश्चित जीवन निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं है ।

(३) जिस देश में धर्म का अभाव हो वहाँ मगाना का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है । परन्तु भारत जहाँ धर्म का देश है जहाँ धर्म की प्रचुरता है मगीना का प्रयोग हानिकारक सिद्ध होगा क्योंकि धर्म के बंधन बंधन रहेंगे ।

(४) भारतीय कृषक नियमित और अनुसृत हैं । अतः वे आधुनिक मगाना को न तो खरीद सकते हैं और न उनका रखन का खर्चा ही सहन कर सकते हैं ।

अतः मगाना का भारतीय कृषि मगाना के प्रयोग के नियम अनुपयुक्त है । मगर ही बड़े बड़े जमींदार वर्ग आदि की खेती के नियमों का मनाब प्रयुक्त कर सकते हैं ।

अभ्यासाथ प्रश्न

इष्टर आदि म पंग गाए

१—मगीना के लाभ तथा हानियाँ की विवेचना कीजिए । (उ० प्र० १८४१)

२—उपनिषद् में मगीना के प्रयोग के लाभ और हानियाँ बताइए ।

(ग० बा० १६५१ ४३ म० भा० १८५५)

३—क्या मगीन देश का धन वृद्धि में काम आया करता है ? क्या आप इसका प्रमाण अपने देश में अधिक पमाने पर करने के पास हैं ? (म० भा० १८५३)

४—उत्पादन में धन के गुण दोषों का वर्णन कीजिए । (म० भा० १८५४)

५—उद्योग के लिए मगीन विभिन्न वस्तुएँ हैं । स्पष्ट व्याख्या कीजिए ।

मगठन (Organisation)

मगठन का अर्थ (Meaning)—अब तर हमन उत्पत्ति के तीन साधना भूमि धन प्रोर पूँजी—का अध्ययन किया है। इन सबका अपना अपना महत्व है और य तीनो उत्पत्ति के नियम अनिवार्य हैं। परन्तु व्यक्तिगत रूप में इनका कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व और उनकी आवश्यकता उनके पारस्परिक मेलों और सहयोग पर ही निर्भर है। अन्तु ठीक प्रकार का उत्पत्ति के नियम इनका उचित मेल और सहयोग नितान्त आवश्यक है। इन सबका एक साथ जुटा कर इनका सम्मिलित रूप में संचालन करने के लिये काय का व्यवस्था में मगठन या व्यवस्था रहता है। उत्पत्ति का विविध साधना का सर्वोत्तम मेल और सहकारिता तथा उनकी मुख्यवस्था को मगठन कहते हैं। जो व्यक्ति मगठन करने का भाव अपने ऊपर रखता है वह मगठनकर्ता या व्यवस्थापक (Organiser) कहलाता है।

मगठन का महत्त्व (Importance)—मगठन या व्यवस्था धनोपत्ति का प्रमुख साधन है। हमने बिना किसी भी प्रयोग या धर्म में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास को प्रारम्भिक अवस्था में भी उत्पत्ति में किसी न किसी प्रकार का मगठन अवश्य पाया जाता था। किन्तु बिना का औद्योगिक व्यवस्था इनका माबारम्भ अब सरल हानी भी नि मगठन या व्यवस्था का कोई अधिक महत्त्व नहीं था। परन्तु जैसे जैसे समाज की उत्पत्ति होती गई वैसे वैसे मगठन का महत्व भी बढ़ता गया। आज कल की आर्थिक व्यवस्था में मगठन अनिवार्य बन गया है। उत्पत्ति के विभिन्न साधना के स्वामी अलग अलग होते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इन साधना को उत्पादन-काय के लिये एकत्रित करे। उत्पत्ति की वृद्धि के साधन-साधन मशीनों का प्रयोग मशीनों का विकास श्रम विभाजन आदि के कारण आधुनिक व्यवसाय या उद्योग का प्रबंध बन ही जटिल और जटिली हो गया है। जो लोग प्रबंध के काम में निपुण तथा विपुल होते हैं वे ही इस काम को हाथ में ले सकते हैं। अन्तु आजकल की उत्पत्ति में मगठनकर्ता का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

मगठनकर्ता के काय (Functions of an Organiser)—आधुनिक उत्पादन में मगठनकर्ता अनेक माभदायक और महत्वपूर्ण काय सम्पन्न करता है। व्यवसाय का सम्पूर्ण भाग उसी पर निर्भर होता है। उसकी नीति और उसके कार्यों का उपान्त के अन्य साधना की उत्पादन शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मनुष्य की काय शक्ति पर बुद्धि का विजय या पराजय निर्भर होती है उसी प्रकार मगठनकर्ता

पर व्यापार की सफलता और असफलता निर्भर होती है। एक चतुर सेनापति को भीति उसको मानसिक तथा बाह्य अनुशासन रखना पड़ता है। वह उपति के समस्त माधना का नियंत्रण करता है उन्हें मंचालित करता है और उचित आज्ञा देता है। हमीनिय उसे उद्योग का कप्तान या सेनापति (Captain of Industry) कहते हैं। सगठनकर्ता के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं —

(१) कार्य की सुव्यवस्थित योजना बनाना—सबसे पहले सगठनकर्ता सम्पूर्ण कार्य की प्रारम्भ में यह तक सुव्यवस्थित योजना बनाता है। वह यह निर्णय करता है कि किन वस्तुओं की उपति की जायगी? उत्पत्ति का परिणाम क्या होगा? उत्पादन के लिये कौन-कौन से ढंग समय में लाये जायें और व्यवसाय का पूरा स्थान कहाँ रहेगा।

(२) उपति के विविध माधना का यथेष्ट मात्रा में जुटाना तात्पर्य नीति का निर्णय करने के पश्चात् उपति के आवश्यक माधना का वह खरोटना है और उनकी इस प्रकार व्यवस्था करता है कि उत्पत्ति अधिकाधिक हो और व्यय कम से कम। इसलिये वह सबसे उपति के अष्टांग उपायों की धार में समर्थ रहता है। उसे यह देखना होता है कि प्रत्येक माधन वह कार्य कर रहा है या नहीं जो उस वर्ग के लिये दिया गया है और कोई गति बेकार तो नहीं जा रही है। वह उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है।

(३) श्रमिकों का सङ्गठन—समस्त श्रमिकों को उनकी बुद्धि तथा शक्ति और इच्छा आदि के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजन कर प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यतानुसार काम देना उनके काम के पूरा निश्चित करना तथा काम की देख रैख करना भी सगठनकर्ता का काम है। वह मासिकता का अनुशासन लाता है और परिश्रमियों का उत्साह बढ़ाता है। सारांश यह है कि वह श्रमिकों में श्रमिकों में श्रमिकों का प्रयत्न करता है।

(४) आवश्यक मशीनों तथा औजारों की व्यवस्था करना—वह श्रमिकों के लिये उत्तम औजारों और यन्त्रों की व्यवस्था करता है जिसमें उनकी कार्यक्षमता घनी रहें। नवीनतम यन्त्रों से उन जानकारी रखनी पड़ता है और उनका वह उपयोग भी करता है। वह यह भी देखता है कि सब मशीनों का उपयोग यथावधि हो रहा है या नहीं। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन खरीद कर उनकी दायरे में और मरम्मत का काम पूरा ध्यान रखना पड़ता है।

(५) श्रमिकों का प्रबंध करना—उन आवश्यक श्रमिकों को उचित मात्रा में उचित स्थान से और अनुरूप समय पर श्रमिकों को लाने का भी प्रबंध करना पड़ता है।

(६) उत्पत्ति की मात्रा एवं विष्म का निधारण—उद्योग या व्यवसाय की सफलता के लिये उत्पत्ति का उचित परिमाण और विष्म का होना आवश्यक है। यदि मात्रा माग में अधिक बना है या उसका विष्म प्रचलित पत्रों के अनुसार नहीं है तो हानि होता स्वाभाविक है। इसलिये सगठनकर्ता को वाजार में मासिकता में मासिकता प्रति आवश्यक है।

(७) माल की बिक्री का व्यवस्था करना—उत्पत्ति की वित्त की व्यवस्था करना भी उनका ही आवश्यक कार्य है जिनके कि अन्य कार्य। सगठनकर्ता को यह देखना होगा कि उसके माल को कहाँ कहाँ खपत हो सकेगी उस माल का निर

प्रकार विभाजन किया जाय जिसमें माग में वृद्धि हो तथा तबहार मान को किन् किन् साधना द्वारा मढ़िया तक पहुँचाया जाय। किसी भी व्यवसाय की सफलता अधिक प्रशस्त इन बातों पर निर्भर है।

(८) अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उत्पत्ति के नये सूत्र और उत्तम ढंगों की खोज संगठनकर्ता अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उत्पत्ति के नये सूत्रों और उत्तम ढंगों को मान्य करने का प्रवर्धन करता है।

(९) साहस और जोशम उठाने का कार्य—जब संगठन और साहस का कार्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष न होकर एक ही व्यक्ति के जिम्मे होता है तब संगठनकर्ता का संगठन कार्य में प्रतिरिक्त साहस (Enterprise) का कार्य अर्थात् लाभ हानि उत्पत्ति का प्रोत्साहन भी सहजो पड़ती है।

(१०) विविध कार्य—उपयुक्त कार्यों के प्रतिरिक्त उसे प्रत्यक्ष विविध कार्यों का सम्पन्न करना पड़ता है। वह विभिन्न उत्पत्ति के साधनों का प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) के अनुसार सर्वोत्तम अनुपात में विनाशर उत्पत्ति वृद्धि नियम का क्रियान्वित रहने का प्रयत्न करता है।

संगठन की कार्यक्षमता (Efficiency of Organization)—संगठन का कार्यक्षमता का अर्थ उत्पत्ति का अधिकतम मिल-व्ययना के साथ प्रयत्न करने की योग्यता से है। व्यवसाय की सफलता भिन्न व्यक्तियों के उत्पत्ति पर निर्भर होती है और भिन्न व्यक्तियों संगठनकर्ता की कार्यक्षमता पर निर्भर रहती है। अस्तु संगठनकर्ता का व्यवसाय का सुदीर्घ होना आवश्यक है। एक कुशल और स्वयंसेवक व्यवस्थापक या संगठनकर्ता निम्नलिखित गुण होने चाहिए—

१. दूरदर्शिता (Foresight)—व्यवस्थापक या भावी माग का सत्यापन और गुणवत्ता अनुमान लगाने की सामर्थ्य होती चाहिए और उस माग का परिचलन करने वाली राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था जनवाणी संबंधी सभी प्रकार की बाधा का ज्ञान होना चाहिए। उसमें प्रत्यक्ष उत्पत्ति के साधनों की स्थापना के आधार पर भविष्य माग की मागत का अनुमान लगाने की भी योग्यता होती चाहिए।

२. संगठन शक्ति (Organizing Capacity)—एक योग्य संगठनकर्ता वह है जो उत्पत्ति के समस्त साधनों को सर्वोत्तम अनुपात में विनाशर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

३. अथ संगठन की विशेष योग्यता (Special Ability to organize labour)—समस्त उत्पत्ति के साधनों में से अथ एक सक्रिय साधन है एवं इसका संगठन के लिये विशेष योग्यता और क्षमता की आवश्यकता है। उसे व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। योग्यता के साथ उसकी महानुभूति होनी चाहिए। संगठनकर्ता का व्यक्ति पत्र चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रमिकों का उसके प्रति विश्वास हो सके और वे उसे आदर की दृष्टि से देखें। श्रमिकों को उत्तम मार्ग पर उभार उठाना चाहिए, श्रमिक कुशल मजदूर अधिक काम करता है। जयम इतनी योग्यता होनी चाहिए जिसमें परिचर्यों और कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन मिले और प्रोत्साहन को योग्यता से दृष्टि भोगना पड़े।

४. उच्च शिक्षा (Higher Education)—उच्च शिक्षा द्वारा संगठनकर्ता की मान और निष्ठा शक्ति बढ़ती है। उसके बुद्धि विकास के लिये श्रमिकों का श्रमिकों का श्रमिकों का उच्च शिक्षा प्रदान है।

१. **विशिष्ट ज्ञान (Technical Knowledge)**—एक कुशल सगठन कृता के लिए विशिष्ट ज्ञान भी आवश्यक है। उस कच्चे सामान की जिसका और मूँपा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। व्यापार संचालन और मार्केटिंग व्यवस्था से बिना ज्ञान के प्रतिस्पर्धित मगाना खार और जालान न गम्ब व म भी उन पूरी ज्ञानकारी हानी चाहिए।

६. **अनुभव (Experience)**—अनुभवी सगठनकृता अधिक कृता मिद हो सकता है क्योंकि बहुत सी बात अनुभव द्वारा सीखी जा सकती है।

७. **विश्वास ज्ञान का योग्यता (Ability to inspire Confidence)**—प्राथमिक व्यापार का उच्च प्रतिक्रिया उद्योग पर स्थिर है। उद्योग यति तथा मित्र सक्ता है जबकि पूजापतिया का व्यवस्थापन पर पूरा विवात है। अतः विश्वास ज्ञान बात सवाई स्थानकारी प्रति शुभ व्यवस्थापक म प्रत्यक्ष होने चाहिए।

भारत म सगठन (Organisation in India)

कृषि और कुशल व्यवसाय (Agriculture and Cottage Industries)—भारतवासी म समय और कुशल व्यवसाय का पूरा समझ है। कृषि और कृषि व्यवसाय की ज्ञान तो सभी ना ग्राहनीय है हमारे किसान और कारीगर जा स्वयं अपने अपने व्यवसाय का सगठन करत हैं। एतन समय और कुशल मिला है जिसके कारण शोका व्यवसाय पतिन व्यवस्था म है। एतनी और कृषि व्यवसाय का उत्पादन एतन कम है और उनका संचालन जीवन निवाह के लिए भा पर्याप्त नहीं है। अस्तु देश का प्राथमिक उद्योग कि स्थिति म यह आवश्यक है कि औद्योगिकीय व्यवसाय का सुसगठन किया जाय क्योंकि ज पर अविज्ञान भारतवासियों का मुख्य निभर है।

उद्योग प्रबंध (Industries)—भारत म कुशल उद्योग और श्रुती कृपा के कारण ज्ञान का य सुचरम्भित है। एतन सगठनी सुसगठित करत का अर्थ विज्ञानी विपणन पूजापतिन सगठनकृता का है जिसका अर्थपूर्ण सेवाया म औद्योगिक धन म एतनी उद्योगिता है। एतनी है। एतनी यो करत भी विपणन करत हाता कि विज्ञानी व्यवस्थापक का अद्यतन भारतवासी के लिए उद्योग मगना पडता है। क्योंकि उद्योग बहुत ऊँचा कतन गेता पडता है। एतन देश का जनवाय मम हान के कारण उनको काय रिता स्वयं कम हो जानी है। एतन मम के अभाव म काम म उनकी स्थिति एतनी नहीं हातो तथा उनका माय कर्म कर्मों के नीचे ममको प्रसक्ति हान म उजा। एतन नद निवात नहीं जा सकत एतन म प्राय अपन कत व्या की जेता कर बडत है।

एतन कारणों म हमारे उद्योगपतियों म भारतीय विद्यापिषा का विज्ञान म सगठन ममता पि म दीक्षा और अनुभव के लिए यजना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय शिक्षित कर्मगत एतन उद्योग का संरक्षण (Protection) प्रदान करता है जो भारतीयकरण म सिद्धान्त की अपनान है। एतन भारतीय कृपासना उद्योग के पद पर है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर ग्राट म परीक्षाएँ

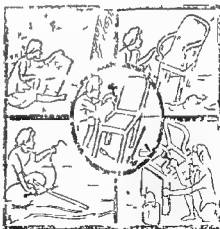
१—सगठन का क्या अर्थ है? यदि प्राथमिक हाथ के कते कृपा के उद्योग का सगठन करने के लिए कहा जाय ता आप कते करत? (उ० प्र० १८४४)

२—उद्योग के कप्तान (Captain of Industry) पर टिप्पणी लिखिए।

श्रम विभाजन का अर्थ (Meaning)—बिसी कार्य के बड़े भाग और उपविभाग करना और उन्हें श्रमिका के मध्य उनकी रुचि और योग्यतानुसार बाँटना अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को कार्य का वही भाग दिया जाता है जिसमें उसकी विशेष रुचि होती है। वह उसी कार्य को निरन्तर करने रहने में उस कार्य में दक्ष हो जाता है। श्रम विभाजन में सब कुछ एक-दूसरे भागों पर एक साथ मिल कर काम करता है। और सभी के सहयोग में अभीष्ट वस्तु तैयार होती है।

श्रम विभाजन का विकास (Growth of Division of Labour)—मानव-जीवन के प्रारम्भिक काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत ही

बम और सरल थी, प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने परिश्रम से ही कर लेता था। परन्तु कालांतर में सम्पत्ति के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गईं। उसे अपनी बनाई हुई वस्तुओं में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असुविधा होने लगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को अलग-अलग वस्तुओं के उत्पन्न करने में लगाने लगा। कोई विमान बन बैठा, कोई खुलाहा और कोई कुम्हार आदि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी



यह श्रम विभाजन नहीं है।



यह श्रम विभाजन है।

बूने बनाने के कारखाने में बूने बनाने का काम कई विभागों में विभाजित है। कुछ मनुष्य चमड़ा राने = कुछ उमर टुकड़ करने = कुछ कूता के तर बनाने हैं और कुछ उनका अप्रयोग बनाने हैं।

श्रम विभाजन का महत्व (Importance)—श्रम विभाजन आधुनिक सभ्यता का आधार है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जीवन सुचारु रूप में नहीं चल सकता था। श्रम विभाजन ने मनुष्य की आधुनिक सभ्यता की और अग्रसर होने में बड़ी सहायता प्रदान की है। उन्नति के विभिन्न मापकों की आवश्यकता की वृद्धि का मुख्य कारण श्रम विभाजन है। बिना श्रम विभाजन के मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर सकता जिसके फलस्वरूप उसका जीवन स्तर नीचे गिर जायगा। श्रम विभाजन के कारण ही उत्पादन में अधिक प्रगति हुई है। मशीन में स्थानित एक माशिनरिस्ट द्वारा बहुतों की आवश्यकताओं में श्रम विभाजन एक आवश्यक वस्तु है।

श्रम विभाजन के विषय आवश्यक शर्तें (Conditions of Division of Labour)—श्रम विभाजन के लिये निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं—

१. **श्रमियों का समूह (Group of Labourers)**—जब तक कि अधिक एक माशिनरिस्ट काम नहीं करेगा तब तक श्रम विभाजन सम्भव नहीं होगा। अतः अधिक से अधिक श्रम विभाजन हो सकता है।

२. **विनिमय प्रणाली (Exchange System)**—श्रम विभाजन के फलस्वरूप अधिक जल्द एक माशिनरिस्ट दूसरे को बस्तुएँ देकर अपने काम में प्रयोज्य वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा न हो तो श्रम विभाजन के फल नहीं होंगे। अतः श्रम विभाजन के लिये विनिमय प्रणाली का होना भी आवश्यक है।

३. **विस्तृत बाजार (Wide Market)**—जब तक बस्तुओं की खपत के विषय विस्तृत बाजार नहीं हो ता बड़ा माना में उत्पादन नहीं हो सकता। जब बस्तु मांग में उत्पादन नहीं है तो श्रम विभाजन करने सम्भव नहीं हो सकता है।

शक्ति और योग्यतानुसार पुरुष-पुरुष काम करने लग गया। पारस्परिक वस्तुओं का विनिमय होने के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ी सुविधा हो गई। मुद्रा विनिमय से श्रम विभाजन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक विनाम और यन्त्रादि के आविष्कारों की उन्नति ने प्रत्येक कार्य के बहुतों में विभाग और उपविभाग सम्भव कर दिए हैं। प्रत्येक विभाग का काम एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का भाग दिया जाता है। उदाहरणार्थ

४. निरन्तर उत्पादन (Continuous Production)—श्रम-विभाजन के बिना निरन्तर उत्पादन होना आवश्यक है। बिना इसके मितव्ययता यदि श्रम-विभाजन से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो सकते।

श्रम विभाजन के रूप

(Forms of Division of Labour)

श्रम-विभाजन के विविध रूप निम्नलिखित हैं —

१. व्यावसायिक श्रम विभाजन (Occupational Division of Labour) श्रम विभाजन के इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति का काम करने के लिये अपना अपनी रुचि और योग्यतानुसार किसी एक विशेष व्यवसाय में बंधा होता है। उस पेशे या धन्दे को वह व्यक्ति से धन तक करता है। उदाहरणार्थ, कोई कृषि कार्य करता है, कोई कपड़ा तैयार करता है, कोई बर्तनों का काम करता है और कोई मुहार का। ये लोग विभिन्न द्वारा अपनी पैदा की हुई या बनाई हुई वस्तुओं को दूसरा की वस्तुओं से बदल कर अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यावसायिक श्रम विभाजन का प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ, यर्धान् हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था में ही इसे जन्म दिया। कालान्तर में ये पेशे जातिनुसार पैदा हो गये—मुहार का बड़का मुहार, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का ही काम करने लगा।

२. पूर्ण क्रियाओं का श्रम विभाजन (Division of Labour into Complete Process)—बढ़ती हुई मानव-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पत्ति में वृद्धि आवश्यक समझी गई और उनके कमस्वरूप कालान्तर में प्रत्येक व्यवसाय या पेशा कई विभागों में विभक्त हो गया तथा काम करने वालों के भी उतने ही उप-विभाग बन गये। इन व्यवस्था के पूर्व एक ही कार्य की सम्पूर्ण क्रियाएँ एक ही व्यक्ति द्वारा सम्पन्न की जाती थी—जैसे कपड़ा बनाने वाला स्वयं ही कपास ओढ़ने, रई धुनने, कातन और बुनने की व्यवस्था करता था। परन्तु बाद में एक काम कई विभागों में बाँट दिया गया और प्रत्येक विभाग की क्रिया गुप्त व्यक्ति-समूह द्वारा सम्पन्न की जाने लगी। जैसे कपड़ा तैयार करने के लिये एक व्यक्ति समूह केवल कपास पेशा करता है, दूसरा कपास की मुद्राई करता है, तीसरा धुनता है, चौथा सूत काता है और पाँचवाँ कले हुए सूत का कपड़ा बुनता है। इस प्रकार के श्रम-विभाजन के चलते-चलते व्यक्ति समूह का प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य की केवल एक ही क्रिया सम्पन्न करता है, परन्तु फिर भी वह क्रिया स्वतः पूर्ण है। इसलिये इसे पूर्ण क्रियाओं का श्रम विभाजन कहते हैं। प्रत्येक समूह से निकली हुई वस्तु अर्द्ध-निर्मित होती है और वह श्रम में अपने समूह का वेतन दी जाती है जब तक कि वह अपना अनिमित्त रूप धारण न करे।

३. अपूर्ण क्रियाओं का श्रम-विभाजन (Division of Labour into Incomplete Process)—मौलिक सम्पत्ता व विकास के साधन-साधनाना प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ जिसने कमस्वरूप एक पूर्ण क्रिया या कई उप-क्रियाओं में बाँट दिया गया और प्रत्येक उप-क्रिया मशीन द्वारा सम्पन्न होने लगी। इस प्रकार कई मशीनों द्वारा एक पूर्ण क्रिया सम्पन्न होने लगी। उदाहरणार्थ, कपड़े के मित में कपड़ा कई उप-क्रियाओं द्वारा बनकर तैयार होता है। आदम स्मिथ नामक कार्यशास्त्र वेत्ता के अनुसार पिन बनाने का कार्य लगभग १८ विभागों में विभक्त होता है। एक मनुष्य तार खींचता है, दूसरा उसे मोटा करता है, तीसरा उसे बाँटता है, चौथा मुनीला बनाता है, पाँचवाँ उसके सिरे का चपड़ा करता है, आदि। इस प्रकार

के श्रम-विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक क्रिया धूर्ण होती है और समस्त उप-क्रियाओं के सहयोग से एक पूर्ण क्रिया सम्पन्न होता है। इसी कारण इसे 'धूर्ण क्रियाओं का श्रम-विभाजन' कहते हैं।

४. प्रादेशिक या भौगोलिक श्रम विभाजन (Territorial or Geographical Division of Labour)—जब कोई उद्योग या व्यवसाय निम्नी विशिष्ट कारखानों, जैसे जलवायु, कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम की क्षमता आदि में किसी प्रमुख स्थान या देश में केन्द्रित हो जाता है, तो उसे 'प्रादेशिक या भौगोलिक श्रम-विभाजन' कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में जूट के कारखाने बंगाल में, लोहे के विहार में, कपड़े की मिलें बिजौवनवा कम्बई और ग्रहमदाबाद में और सूती का व्यवसाय फिरोजाबाद में केन्द्रित है।

५. सरल और जटिल श्रम-विभाजन (Simple & Complex Division of Labour)—श्रम विभाजन सरल और जटिल भी है। जब नाई कार्य किसी एक व्यक्ति के लिये कठिन भारी और श्रमोन्मुख हो और उसे कई व्यक्ति प्राथम में मिलकर सम्पन्न करें तो उसे सरल श्रम विभाजन (Simple Division of Labour) कहते हैं। जैसे, विमां बट लेन को हँकना या जोड़ना, किसी दूध दही की दूधान का काम तथा भारी बोझ उठाना आदि। व्यावसायिक श्रम-विभाजन भी इसी का उदाहरण है। जब कई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह वस्तु-निर्माण का केवल एक विशेष भाग सम्पन्न करते हुए परस्पर सहयोग में कार्य करने हैं तो वह जटिल श्रम-विभाजन (Complex Division of Labour) कहलाता है। उदाहरणार्थ, कृता के कारखाने में कृता का निर्माण कई विभागों की कार्य-सम्पन्नता पर निर्भर है। इसी प्रकार सूती कपड़े की मिल में बाल-निर्माण के लिये कनाई, तुनाई, रवाई आदि विभागों के कार्यों का सहयोग नितान्त आवश्यक है। धूर्ण क्रियाओं का श्रम-विभाजन भी इसी का उदाहरण है।

श्रम-विभाजन के लाभ (Advantages of Division Labour)

उत्पत्ति के लिए (For Production as a whole)

१. उत्पत्ति में वृद्धि (Increased Output)—श्रम-विभाजन का यह मुख्य लाभ है। इसके द्वारा उत्पत्ति में वृद्धि होती है। प्राथम स्थिति कहते हैं कि यदि एक आदमी मवेशी पिन बनाये, तो वह २० पिन में अधिक एक दिन में नहीं बना सकता। परन्तु जब १० आदमी प्राप्त में मिल कर श्रम विभाजन के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करें तो वे एक दिन में ४००० पिन बना सकते हैं। श्रम-विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रवि और शोखना के अनुसार काम मिलने में यह अधिक उत्पत्ति कर सकता है।

२. उत्पत्ति की श्रेष्ठता (Superior Product)—श्रम विभाजन के अन्तर्गत एक व्यक्ति उत्पत्ति की एक ही क्रिया को निरन्तर करता रहता है, अतः उसके द्वारा तैयार की गई वस्तु का श्रेष्ठ होना स्वाभाविक है।

३. लागत में कमी (Decreased Cost of Production)—जब मनुष्य किसी काम को करते-करते उसमें निपुण हो जाता है, तो वह थोड़े समय में अधिक उत्पादन करने लग जाता है जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है।

४. मशीनों का अधिक उपयोग (Increased Use of Machinery)—एक कार्य को बहुत से उपक्रियाओं में विभक्त कर देने से अधिक उपविभाग

म की जान बानी क्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। ऐसा होने से मशीनों का उपयोग सहज हो जाता है।

५. आविष्कारों में उन्नति (Progress in Inventions)—धन विभाजन से आविष्कारों की भी उन्नति होती है। जब मनुष्य लगातार एक ही काम में लगा रहता है तो उसमें यह सोचने का प्रयास अक्सर मिल जाता है कि उस काम के करने की विधि में किस प्रकार और अधिक उन्नति की जा सकती है। इस प्रकार नये नये आविष्कारों में वृद्धि होती जाती है।

६. समय का वचन (Economy of Time)—जब मनुष्य को भिन्न भिन्न काम करने पड़ते हैं तो उनका बहुत सा समय काम के अन्दर रहने में और भिन्न भिन्न चीज़ों के उठाने धरने में नष्ट हो जाता है। धन विभाजन से मनुष्य का समय एक ही क्रिया करने में पड़ती है अतः उसका समय इधर उधर के कामों में नष्ट नहीं हो पाता।

७. औज़ारों में मितव्ययता (Economy of Tools)—जब एक व्यक्ति दो तीन काम साथ करता है तो उन प्रत्येक काम के लिए पृथक् पृथक् औज़ार रखने पड़ते हैं। परन्तु इन सबका वह एक साथ प्रयोग नहीं कर सकता। अतः जब वह एक औज़ार को प्रयुक्त करता है तो अन्य औज़ारों के रखरखाव करता है। धन विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही क्रिया करने होती है। अतः उस उसी काम के लिए औज़ारों की आवश्यकता होती है और उनका वह निरन्तर प्रयोग करता रहता है। इस प्रकार धन विभाजन द्वारा औज़ारों में बहुत वचन होती है। इससे अनिश्चित काम औज़ारों के होने पर प्रत्येक व्यक्ति उनसे भयभीत नहीं होकर काम करता है जिससे फलस्वरूप औज़ारों की जीवन अवधि बढ़ जाती है।

८. कच्चे मान में वचन (Economy of Raw Material)—धन विभाजन में कच्चे मान के प्रयोग में भी पर्याप्त मितव्ययता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में निपटता होने के कारण वह कच्चे मान को उचित रीति में प्रयुक्त कर सकता है।

९. व्यवसायों का विस्तृत एवं विभिन्न होना (Extension & Diversification of Occupations)—प्रतियोगिता की आविष्कारों और प्रयोगों से जाति-पातों का अनेक माध्यम खुल जाते हैं जिससे कुछ घास तब बेकारी की समस्या हल हो जाती है।

१०. संगठन योग्यता का विस्तृत मात (Extensive Demand for Organizational Ability)—धन विभाजन और कार्य-संचालन में उन्नति का परिणाम होता जाता है। इससे निम्न सुयोग्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुयोग्य संगठनकर्ताओं की उन्नति में वृद्धि होती है जिससे फलस्वरूप उद्योग व्यवसायों में उन्नति होती है।

अधिकांश के लिए (For the Labourers)

११. कार्य-क्षमता में वृद्धि (Increase in Efficiency)—धन विभाजन के फलस्वरूप एक व्यक्ति सम्पूर्ण क्रिया का कार्य एक ही समय निरन्तर करता रहता है जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। निरन्तर प्रयत्न से उसकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाता है तथा वह अपने काम में विचारण होता जाता है।

१२ रसि तथा योग्यतानुसार कार्य (Work according to Taste and Ability)—धन विभाजन म सम्पूर्ण कार्य नई विभागा म विभक्त हो जाता है जिसस प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रसि धोर योग्यतानुसार काम मिल जाता है ।

१३ शारीरिक परिश्रम म कमी (Diminution of Strain)—सम्पूर्ण रिया का उप विभाग मशीन द्वारा सम्पन्न हो जाने मे मनुष्य भारी काम करने मे मुक्त हो जाता है । उत्पात्ति का सारा कार्य मशीन द्वारा होता है । उस ती केवल मशीन की देखभाल ही करने पड़ती है ।

१४ धन की गतिशीलता म वृद्धि (Increase in the Mobility of Labour)—धन विभाजन मे मशीन का प्रयोग होता है जिनमे श्रमिक कहीं भी किसी भी वागस्थान मे वासाली मे काम कर सकता है क्योंकि मशीन का मवाजन लगभग एक-सा होता है ।

१५ आविष्कार करने की योग्यता मे वृद्धि (Increase in Inventive Ability)—धमिक निरन्तर एक ही प्रकार की मशीन पर काम करते रहने के कारण मशीन म कई प्रकार के सुधार साध सकता है तथा अधिक सुविधाजनक और लाभदायक नई मशीन का आविष्कार भी करने म समर्थ हो सकता है ।

१६ बुद्धि का विकास (Development of Intelligence)—मशीन पर काम करने से धमिक अधिक बढिमान हो जाता है क्योंकि उस मशीन सम्बन्धी कई बातों पर निरन्तर सोचना पड़ता है । यही कारण है कि कृषि धमिक की प्रगति कारणाने म काम करने वाला धमिक अधिक बढिमान होता है ।

१७ काम सीखने म समय परिश्रम और धन की बचत (Saving in Time, Efforts and Wealth)—धन विभाजन म एक काम क कई उपविभाग कर दिने जाते है और प्रत्येक धमिक को केवल एक ही उपविभाग का काम माया जाता है जो मरलतापूर्वक यात्रा हा समर्थ म सीखा जा सकता है । फलतः काम सीखने म समय परिश्रम और धन का बचत होती है ।

१८ ऊँची मजदूरी (भृति) (Higher Wages)—किसी स्थान क काम किसी विनिष्पत्त्यवसाय का कार्य म अग्रगण्य हो जाते हैं जिससे परिणामस्वरूप उह ऊँची मजदूरी मिलने लगती है ।

१९ सहकारिता की उत्पत्ति (Development of Co-operation)—धन विभाजन के कारण बढ बढ कारणाने खुद जान है जहाँ पर बहुत म धन जावो । क साथ मिल जुल कर काम करते है । एक साथ काम करने और रहने म धन की विद्या म संगठन और एकता का भाव जाग्रत हो जाता है जिससे पसस्वरूप के अपनी दया म पचास सुधार कर सकते हैं ।

धन विभाजन की हानियाँ (Disadvantages of Division of Labour) धन विभाजन की हानिया दो वर्गों म बाँटी जा सकती है—

(अ) प्रथम हानियाँ और (आ) अग्रगण्य हानिया ।

(घ) प्रत्यक्ष हानियाँ (Direct Disadvantages)

१. कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व का हान (Loss of Efficiency and Responsibility)—सम्पूर्ण काम का केवल एक ही धनु करन में थमिक का दृष्टिकोण मर्यादित होता है और उसका ज्ञान विस्तृत सीमित रहता है। यदि सम्पूर्ण काम एक ही मनुष्य करे तो उस काम की गल्टी-भुलाई उसके ऊपर डाली जा सकती है। परन्तु जब बहुत से मनुष्य मिलकर एक ही कार्य सम्पन्न करें तो यह निश्चित करना बहुत कठिन है कि कार्य किन्हीं द्वारा खराब हुआ है। इस प्रकार उत्तरदायित्व का अभाव में थमिक अपना कार्य मावधानी में नहीं करते।

२. काम की नीरसता (Monotony of Work)—उत्पत्ति की एक ही छद्म श्रिया को लगातार करने रहने में वह काम नीरस हो जाता है। इस नीरसता का सबसे मन, यदि और उत्पादन शक्ति पर दुरा प्रभाव पड़ता है।

३. आनन्द का नाश (Loss of Interest)—जब कोई व्यक्ति एक सम्पूर्ण वस्तु को खदे-सा ही बनाता है तो उसे उसके बनाने में बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। परन्तु जब वह किसी बाख्ताने में दूसरे के साथ काम करता है, तो उस काम में आनन्द नहीं आता। बाख्ताने में उसका ध्येय-स्थिति नहीं होता और न सम्पूर्ण वस्तु का निमाण उसी के ही प्रयत्न का फल होता है।

४. श्रमिक मशीन-गुल्य हो जाता है (Labourer is reduced to Machine level)—काम के एक उप विभाग की बिलम्बर करने रहने में मनुष्य मशीन-गुल्य हो जाता है। उत्पत्ति की एक निगम श्रिया के प्रतिरिच उस श्रमिक का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। कम्यन्थ उसकी बुद्धि का विकास एक जाता है और उसकी कार्यक्षमता में ग्लानता आ जाती है।

५. थम की गतिशीलता का हान (Loss of Mobility of Labour)—मनुष्य जब यदा एक ही काम करता रहता है तो आसम्भ्यता पड़ने पर वह किसी अन्य काम के लिए योग्य नहीं रहता। श्रम बायी के विषय में उस कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए यदि उसका नियोजित कार्य छूट जाय तो उसे अन्यत्र काम मिलना कठिन हो जाता है।

६. स्त्रियों और बच्चों का शोषण (Exploitation of Women and Children)—थम विभाजन के कारण उत्पत्ति की प्रत्यक्ष श्रिया इतनी मरल हो जाती है कि स्त्रियाँ और बच्चों को उस श्रिया को कर देने हैं। अतएव मिल-मालिक पुरपा के स्वान पर स्त्रियाँ और बच्चा को काम में लगाते हैं। शोषक व अधिक मस्ते पड़ते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनके चरित्र और आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नमजोर स्त्रियाँ नमचार बच्चों को जन्म देती हैं। कमजोर होने के कारण वे आगे चलकर जीवन भार उठान में अपने आपको असम्यक्त होते हैं। ऐसी अवस्था में उनके गमान को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता।

७. कुशल श्रमिकों के लिये सीमित कार्य-क्षेत्र (Limited Scope for Skilled Labour)—प्रत्येक कार्य के कई उप विभाग कर देने में काम बहुत सरल हो जाता है। उसको करने के लिये विशेष निपुणता की आवश्यकता नहीं होती। शोषारण थम में हो काम सरल होता है। अतः कुशल श्रमिकों का कार्य-क्षेत्र कम हो जाता है।

(आ) अप्रत्यक्ष हानियाँ (Indirect Disadvantages)

८. अधिकारी और मिल मालिकों के मध्य सम्पर्क का अभाव (Loss of Personal Contact between Employers and Employees)—अम-विभाजन के प्रत्यक्ष मन्त्र्या अधिकारी एक ही कारखाने में एक साथ काम करते हैं। अधिकारी की सहाय्य अधिक होने के कारण उनमें और मिल मालिकों में सम्पर्क कम हो जाता है जिसमें पारस्परिक मनोबोध बढ़ता है। कभी मजदूर हड़ताल करते हैं ता कभी मिल मालिक कारखाना के दरवाजा के तार लगाने हैं। इसका परिणाम केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि सम्पूर्ण समाज को भी गोलिया पड़ता है।

९. अत्यधिक जनसङ्ख्या का एक ही स्थान पर संचित होना (Overcrowdedness)—कारखाना प्रणाली के प्रत्यक्ष मन्त्र्या मनुष्य एक ही कारखाने में काम करते हैं। जब किसी औद्योगिक प्रदेश में बड़ी कारखाने हों तो मजूरा भी सरप्रास में अधिकारी का एक ही स्थान पर रहना स्वाभाविक हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि रहने के लिए स्वच्छ हवादार मकान नहीं मिल पाते और शरीर अमशोषिता को विना हावर गर्मी काल-बोडरियाँ रहना पड़ता है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनमें अनेक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

१०. पराश्रितता (Interdependence)—अम-विभाजन में अधिक सामूहिक रूप में काम करना है। अतः एक अधिकारी की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण कार्य स्थगित हो जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—अम-विभाजन के लाभ उसकी हानियाँ में कहीं अधिक हैं। यही कारण है कि अम-विभाजन में बराबर उन्नति होती जा रही है। यही नहीं प्रगतिशील सभ्यताओं द्वारा इन दोषों को कम से कम करने के प्रयत्न प्रचलित जा रहे हैं। काम के घट कर अधिकारी का धनिक प्रवर्धन देना, कल्याण-कार्य (Welfare Work) जैसे—विद्यालय, भोजनकक्ष, नानालय, खेल-कूद और मनोरंजन के माध्यम से अनेक वस्तुओं सह माधेदारी (Co-Partnership) नाम-विभाजन (Profit-sharing) आदि योजनाओं द्वारा इन दोषों का दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अम-विभाजन की सीमाएँ (Limitations of Division of Labour)—अम-विभाजन निम्नलिखित बातों से परिमित है —

१. व्यवसाय का स्वभाव (Nature of Occupation)—अम-विभाजन उन व्यवसायों में सम्भव है जिनमें उत्पत्ति की क्रियाएँ और उप-क्रियाएँ साध-साध भक्त संचालित हैं। उदाहरणार्थ, गन्नी मशीन की मिल में सूत कातने के बुनने का काम साध-साध चलता है। परन्तु कृषि व्यवसाय में ऐसा नहीं है—सब क्रियाएँ एक के बाद दूसरी होती हैं। इस चलाने के पश्चात् बीज बोया जाता है और उसके बाद फसल काटी जाती है।

२. बाजार की सीमा (Extent of Market)—अम-विभाजन बाजार में बिक्री की सीमा पर भी निर्भर है। यदि बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो अम-विभाजन भी काफी दूर तक फैला जा सकता है। अधिक स्पष्ट करने हेतु यह कहा जा सकता है कि अम-विभाजन केवल उन्हीं वस्तुओं की उत्पादन में लाभदायक

सिद्ध हो सकता है जिनकी माग बहुत अधिक हो तथा जिनका उत्पादन बड़े परिमाण में होता हो ।

३. उत्पात्ति का परिमाण (Scale of Production)—श्रम विभाजन और बंट परिमाण में उत्पात्ति का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रम-विभाजन अधिकतर उन्हीं व्यवसायों में सम्भव है जिनमें उत्पत्ति बड़ पैमाने पर होती है । जैसे कपड़ों, लोहे और चमड़े आदि के कारखाने । छोटे व्यवसायों में इनका योगित क्षेत्र होता है, जैसे घरेलू मन्थे आदि ।

४. पूँजी की मात्रा (Amount of Capital)—श्रम विभाजन और उत्पात्ति का परिमाण साथ-साथ चलते हैं । ये दोनों ही पूँजी की मात्रा पर निर्भर हैं । बिना पर्याप्त पूँजी के बड़ पैमाने पर उत्पात्ति नहीं हो सकती और बिना बड़ पैमाने पर उत्पात्ति हुए श्रम विभाजन सम्भव नहीं हो सकता । अस्तु, पूँजी की कमी से श्रम विभाजन परिमित हो जाता है ।

५. व्यापार-संचालन की सुविधाएँ (Mechanery of Commerce)—कुशल व्यापार-संचालन के लिये मोट्टर, मर्याद और यातायात के साधन, बैंकिंग प्रणाली आदि सुविधाएँ आवश्यक हैं । इन सुविधाओं के कारण ही दूर देशों से व्यापार हो सकता है । इनके अभाव में न तो वस्तुओं की माग अधिक होगी और न उत्पादन ही बड़ परिमाण में होगा । अस्तु श्रम विभाजन व्यापार-संचालन की सुविधाओं पर भी निर्भर है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—श्रम-विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिये । इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण देकर अपना उत्तर स्पष्ट कीजिये । (उ० प्र० १९६०)
- २—श्रम-विभाजन का क्या अर्थ है ? इसके लाभ हानियों का विवेचन कीजिये । (पटना १९५२, अ० भा० १९५५, ५३ मार्च १९५२, दिल्ली हा० से० १९४९)
- ३—श्रम विभाजन और महानुपाय उत्पादन के सम्बन्ध को कारण सहित समझाइये । (मार्च १९५६)
- ४—“बाजार के क्षेत्र से श्रम विभाजन सीमित है ।” प्रत्यक्षता समझाइये । श्रम विभाजन और किन किन बाधाओं पर सीमित है ? (अ० बी० १९५६, पञ्जाब १९४३)
- ५—यह बताइये कि श्रम विभाजन और मशीनरी हमारे मध्य क्या स्थित है ? उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है । (रा० बी० १९५६)
- ६—पूर्ण और अपूर्ण जियादा के श्रम विभाजन में आप क्या समझते हैं ? श्रम विभाजन के लाभ बताइये । (उ० प्र० १९४४)
- ७—श्रम-विभाजन किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न रूप उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये । (रा० बी० १९५०)
- ८—श्रम विभाजन की सीमा किन बाधाओं पर निर्भर है ? इससे क्या लाभ व हानियाँ हैं ? (उ० प्र० १९४९)

उद्योगों का स्थानीयकरण (Localisation of Industries)

स्थानीयकरण का अर्थ (Meaning)—उद्योगों के किसी उपयुक्त तथा लाभदायक क्षेत्र में स्थापित होकर उत्पत्ति करने का प्रवृत्ति का उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। जिस प्रकार थम विभाजन में कुछ व्यक्ति किसी विषय व्यवसाय या उनके किसी विशेष भाग को करने का नौ जानते उसी प्रकार कुछ स्थान किसी एक उद्योग या व्यवसाय के केन्द्र बन जाते हैं उद्योगों का प्रचाराय के इस प्रकार केन्द्रित होने का प्रवृत्ति को अध्ययन में उद्योगों का स्थानीयकरण या केन्द्रायकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में लोहा का कारखाना अधिकतर बिहार राज्य के जमशेदपुर में केन्द्रित हैं। लूट के कारखाने बनारस नगर के पास धान के धाना में केन्द्रित हो गए हैं बम्बई और अहमदाबाद में सूती कपड़ा के कारखाने चीनी के उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी का उद्योग फिरोजाबाद और ताता का धनीय में केन्द्रित हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड में तकियापर और मनेचेस्टर सूती कपड़ा की मिला के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रवृत्ति को प्रादेशिक थम विभाजन (Territorial Division of Labour) भी कहते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण एक प्रकार में थम विभाजन का विस्तृत रूप है जिसमें केवल सम्पूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व भी सम्मिलित होता है।

स्थानीयकरण के कारण (Causes of Localisation)—उद्योगों के स्थानीयकरण के बहुत से कारण होते हैं सम्बन्धवर्ती को जहाँ सुविधाएँ मिलती हैं वहाँ वह अपने कारखाने के लिए स्थान चुनता है। ये कारण निम्नलिखित हैं —
प्राकृतिक कारण (Natural or Physical Causes)

(१) कच्चे माल की प्राप्ति—उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिन स्थानों में किमा व्यवसाय के लिए कच्चा माल सस्ता और सफेद मात्रा में उपलब्ध है ता वही पर वह व्यवसाय केन्द्रित हो जाता है। उदाहरणार्थ वेगान में लूट अधिक पैदा होने के कारण लूट के कारखाने वेगान में और उत्तर प्रदेश के बिहार में गन्ने की खेती अधिक होने से इन राज्यों में गन्ना के कारखाने केन्द्रित हैं।

शक्ति के साधन—कारखानों को चालू करने की शक्ति की सुविधा के कारण कुछ कारखाने उन क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं जहाँ प्रबल या गामक शक्ति (Motive

Power) समीचीन गुणवत्ता में प्राप्त हो सकती है। आज-कल प्रेरक शक्ति अधिकतर बोझों और जल से प्राप्त की जाती है। जैसे जमशेदपुर के लोहे के कारखानों की समीपवर्ती बोझों की स्थानों में प्राप्त बोझों प्रेरक शक्ति प्रदान करता है और अगदीर में हुआई जहाज बनाने के कारखानों के लिए जल-विद्युत मुख्य-प्रेरक शक्ति का साधन है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में घड़ी के कारखानों के लिये जल-शक्ति ही प्रधान है।

(३) प्राकृतिक सुविधाएँ—प्राकृतिक सुविधाओं से गार्मय है भूमि की वनायट, मिट्टी का स्वभाव, समुद्र-तट की वनायट, उत्तम बंदरगाह, जहाज चलाने योग्य नदियाँ आदि। जिन उद्योगों के लिए इन प्राकृतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है वे उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं जहाँ उनकी अपनी आवश्यकतानुसार सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे जहाज निर्माण उद्योग के लिए उत्तम बंदरगाह का होना आवश्यक है। अतः भारतवर्ष में बिजगापट्टम बंदरगाह इस उद्योग का केन्द्र हो गया है।

(४) जनवायु—पुछ उद्योग-धंधों के लिए एक विशेष प्रकार की जनवायु की आवश्यकता होती है। वह जनवायु हर एक जगह नहीं मिलती है। अतः ऐसे उद्योग-धंधे उन स्थानों में केन्द्रित हो जाते हैं जहाँ उस प्रकार की जनवायु मिलती है। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में बम्बई और इज्जना में लकड़कारों की जनवायु सूती कपड़ों के कारखानों के लिए विशेष उपयुक्त है, क्योंकि इन स्थानों के वायुमण्डल में नमी होती है जिसके कारण सूती का तार शीघ्र नहीं टूटता और भस्मृत तथा मुत्तायम भी रहता है। इस कारण से इन स्थानों में सूती कपड़े के बहुत से कारखाने पाये जाते हैं।

■ दिक कारण (Economic Cause)

(५) मंडियों और बाजारों की निकटता—निश्चित मान की जहाँ खसत प्राप्त होती है वहाँ तक प्रामः कारणों स्थापित हो जाते हैं। कारखानों के समीपवर्ती स्थानों में जनकथा घनी होती चाहिए अथवा वहाँ से घनी जनकथा वाले स्थानों की मात्र शीघ्र व सस्ते मातायाग के साधनों द्वारा भेजा जा सके। इसका लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल में सूती कपड़ों भावि के अनेक कारखाने खोले जा रहे हैं।

(६) यातायात की सुविधाएँ—यातायात के साधनों का उद्योग-धंधों के केन्द्रीयकरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन स्थानों में रेल, जहाज आदि के यातायात की सुविधा होती है, वहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा स्थानीयकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। बम्बई, कलकत्ता आदि नगरों की विशेषता बहुत कुछ इसी कारण है।

(७) श्रम का उपलब्ध होना—योग्य और सस्ते श्रमियों का बड़े-बड़े मात्रा में मिलना भी स्थानीयकरण का कारण होता है। जैसे, भारतवर्ष में चूरी का व्यवसाय फिरोजाबाद, रणई-खोई फर्रुखाबाद और बूट का व्यवसाय बंगाल में केन्द्रित है क्योंकि वहाँ पर उचित ढंग का श्रम समृद्धता से मिल जाता है।

(८) पूँजी सम्पत्ती सुविधाएँ—उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति वहाँ भी देखी जाती है जहाँ पूँजी सस्ती और बड़े-बड़े मात्रा में समृद्धता से उपलब्ध हो सकती है। वे नगर जो पार्षिक केन्द्र हैं तथा जहाँ अधिकाधिक मात्रा में वैनिङ्ग और निविदाग (Investment) सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे प्रामः उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योग-पतियों के ध्यान को शीघ्र ही आकर्षित कर लेते हैं।

राजनैतिक कारण (Political Causes)

(६) राज्य द्वारा संरक्षण तथा प्रोत्साहन—सरकार द्वारा संरक्षण तथा सहायता भी स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्राचीन काल में हिन्दू और मुसलमान राजाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन से अनेक व्यवसाय राजधानियों के निकट स्थापित हो गये थे, जैसा टाटा की मजदूर और मुजिदाबाद का रेजिम का व्यवसाय आदि।

अन्य कारण (Other Causes)

(१०) वीघ्र प्रारम्भ का लाभ—कभी-कभी किसी क्षेत्र में कोई उद्योग या व्यवसाय बहुत पहले से चला आता है और वह विशिष्ट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया है तथा वहाँ व्यवसाय-सम्बन्धी सभी सुविधाएँ प्राप्तानी में उपलब्ध हो जाती हैं तो उसी प्रकार के अनेक कारखानों का वहाँ स्थापित होना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार वह स्थान या क्षेत्र उद्योगों का केन्द्र हो जाता है।

(११) सहायक उद्योग धन्यों से लाभ प्राप्ति—किसी स्थान या क्षेत्र में जब कोई उद्योग श्रम निकलता है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक सहायक उद्योग धन्यो स्थापित हो जाते हैं जिसके कारण मुख्य व्यवसाय को अनेक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। इस कारण उस प्रकार के कई कारखाने उसी क्षेत्र में स्थापित होकर लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणार्थ, कलकत्ता के वस्त्र-निर्माण उद्योगों में लाभार्थ रंगाई-छपाई, इस्त्रीनिर्धारण, मशीनें व यंत्रों बनाने आदि के कई कारखाने स्थापित हो गये हैं जिससे वस्त्रोद्योगों (Textile Industries) को वहाँ स्थापित होने में अनेक लाभ उपलब्ध हो सके हैं।

(१२) प्रौद्योगिक संस्थाएँ (Technical Institutes), अनुसंधानालयों और प्रयोगालयों की सुविधाओं से लाभ—किसी विशिष्ट प्रौद्योगिक केन्द्र में प्रौद्योगिक संस्थाएँ, अनुसंधानालय तथा प्रयोगालयों की सुविधाओं से लाभ उठाने के लिए कारखाने वहाँ स्थापित हो जाते हैं। इससे अनिश्चित प्रौद्योगिक पत्रिकाएँ (Technical Journals) भी उस केन्द्र में प्रकाशित होती हैं जिनमें उस उद्योग-सम्बन्धी सभी प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है।

(१३) सस्ती भूमि, जल की प्रचुरता आदि कारण—कारखानों के लिये सस्ती भूमि, पानी की प्रचुरता आदि मुख्य कारण ऐसे हैं जिनसे स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे दूध की मछाने और धोने आदि क्रियाओं के लिये बंगाल में जल पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

स्थानीयकरण के लाभ (Advantages of Localisation of Industries)—स्थानीयकरण के कई लाभ हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

१. प्रसिद्धि व संपत्ति (Reputation and Goodwill)—स्थानीयकरण द्वारा उस विशिष्ट स्थान की बनी हुई वस्तुएँ उतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं कि वे दूर-दूर स्थानों में अच्छे दामों में बिकने लगती हैं। जैसे, काश्मीर के घाल दुपट्टे, अमृतसर के चाले, मेरठ की कैंचियाँ, शिवटूरलैंड की बनी हुई पड़ियाँ आदि।

२. वंशिक दक्षता (Hereditary Skill)—केन्द्रीयकरण के स्थान के रहने वालों की विशिष्ट दक्षता का पिता से पुत्र को हस्तान्तरण होता रहता है, अतः वह एक प्रकार से वंशिक दक्षता हो जाते हैं जो अन्य स्थानों में उपलब्ध नहीं हो सकती।

उदाहरण के लिये, जूट व्यवसाय की विशिष्ट दक्षता (Skilled Labour) बंगाल तक ही सीमित है।

३. सहायक उद्योगों का विकास (Development of Subsidiary Industries)—उद्योग के प्रवर्धित पदार्थ (Waste Product) का उपयोग करने के हेतु कई महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बड़ी स्थापित हो जाते हैं। जैसे शकर के कारखाने के छोटे में शराब और एल्कोहल (Spirits and Alcohol) तैयार करने के कारखाने, सूती कपड़ों के प्रवर्धित मूल के उपयोगार्थ डोरी, रस्सियाँ आदि के कारखाने और मोहरे तथा इस्पात के कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ काम में लाने के लिये टुकड़ा आदि के कारखाने स्थापित हो जाते हैं।

४. पूरक उद्योग धन्यों की स्थापना (Establishment of Supplementary Industries)—उद्योग धन्यों के स्थानीयकरण में धन्य कई पूरक धन्यों की स्थापना हो जाती है। जैसे मोहरे और इस्पात के कारखानों के समीप कोयले, पेष, पत्तियाँ आदि और मशीनों बनाने तथा सुधारने के कारखाने स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार भारी उद्योगों के केन्द्र गांधारगुलिया मिट्टा आदि व्यवसाय के भी केन्द्र होते हैं, क्योंकि वहाँ विषयों और वस्तुओं का धर्म मस्ती दर पर प्राप्त हो जाता है। इसके अनिश्चित भारी कारखानों में काम करने वाले पुरुष अधिक मजदूरी नहीं माँग सकते हैं।

५. दक्षता का स्थानीय बाजार (Local Market for Skill)—केन्द्रीयकरण का स्थान दक्षता का स्थानीय बाजार बन जाता है, क्योंकि उस प्रमुख धन्य या व्यवसाय में जानकारी रखने वाले, समस्त धर्मिक उस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जिसमें उद्योगपतियों को यहाँ अपना उद्योग स्थापित करने में दक्ष धर्म की पूर्ण सहज हो जाती है।

६. विशिष्ट मशीनों का प्रयोग (Use of Specialised Machinery)—केन्द्रीयकरण वाले क्षेत्र में एक ही प्रकार के कई कारखाने होते हैं जिसमें एक दूसरे से धर्म बढ़ने के लिये पारस्परिक प्रतियोगिता (Competition) पाई जाती है। इस स्वास्पर्धक प्रतियोगिता के कारण ही वे विशिष्ट एवं आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं।

७. उन्नति के लिये सामूहिक प्रयत्न (Collective Efforts for Improvement)—एक ही प्रकार के सारे उद्योग एक ही स्थान पर केन्द्रित होने के कारण उस उद्योग की उन्नति के लिये सामूहिक प्रयत्न किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, धर्मिकों की शिक्षा-दीक्षा के लिये प्रौद्योगिक संस्थाएँ (Technical Institutes), अनुसंधानालय (Research Institutes), प्रयोगालय (Laboratories), विशेष पत्रिकाएँ (Technical Journals) आदि बातों का उपयोग सामूहिक रूप में होता है लिया जा सकता है।

८. व्यापार सम्बन्धी सुविधाएँ (Commercial Facilities)—किसी प्रौद्योगिक केन्द्र में कई कारखाने एक स्थान में स्थापित होने के कारण विशिष्ट (Specialised) ग्राहक के साधन, बैंक, डेयर-बाजार, निर्बन्धित गोदाम (Bonded Warehouse), बीमा कम्पनियाँ आदि वहाँ स्वतः ही स्थापित हो जाती हैं जिसमें उद्योग-धर्मियों का बड़ा आर्थिक लाभ पहुँचना है।

स्थानीयकरण की हानियाँ

(Disadvantages of Localisation)

उद्योगों के स्थानीयकरण में हानियाँ भी होती हैं। मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं—

१. मदी का सिकट (Risk in Depression)—उद्योगों का स्थानीयकरण किसी स्थान को अधिक हार्ड से एक ही उद्योग पर निर्भर कर देता है। यह परिस्थिति मतापजनक नहीं कही जा सकती क्योंकि उस व्यवसाय में मदी आने में सम्पूर्ण क्षेत्र सिकट पड़ता हो जाता है। इनका फलस्वरूप कारखाने बंद हो जाते हैं और माले क्षेत्र में बेकारी फैल जाती है।

२. मानव-बुद्धि का संकीर्ण विवर्धन (Narrow Development of Human Skill) उद्योगों के स्थानीयकरण में किसी एक विशेष प्रकार की बुद्धिमानता की आवश्यकता होने से अधिकतर विशिष्ट बुद्धिमानता प्राप्त श्रमिक ही प्रकार बनते हैं। उनका अग्रणी बुद्धि व अन्य पहलुओं का विकास का अवसर व समय नहीं मिलता जिसके कारण उनकी कार्य-बुद्धिमानता का एकांगी विकास हो रहता है।

३. अव्यवस्थित श्रम की बेकारी (Unemployment of Unemployed labour)—केंद्रीयकरण के क्षेत्र में विशिष्ट सामान्यता का श्रमिकों का कारखाना में काम करना मिल जाता है। परन्तु उस क्षेत्र के अव्यवस्थित श्रमिकों को काम पाना नहीं मिलता व वे बेकार रहते हैं—जैसे स्त्रियाँ, बच्चे आदि। अतएव उद्योगों के केंद्रन में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है।

४. केंद्रीयकरण के दोष (Evils of Centralisation) स्थापित करण व अन्तर्गत एक छोटी संख्या में कारखानों एक ही स्थान में स्थापित हो जाने में संख्या श्रमिकों का उसी क्षेत्र में बसना अनिवार्य हो जाता है जिसमें कारण कई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व नैतिक दोष पैदा उत्पन्न हो जाते हैं। जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण मजदूरी का बर्बाद हो जाता है और स्वच्छता का भी प्रभाव रहता है। इनके अतिरिक्त मजदूरी, व्यभिचार, मादकपदार्थों का सेवन आदि भी व्यापक हो जाते हैं।

५. श्रम की गतिशीलता में बाधा (Mobility of Labour hampered)—स्थानीयकरण द्वारा श्रम की गतिशीलता भी कम हो जाती है। नतीजा कारखानों व केंद्रों व श्रमिकों का मिलान पर श्रम औद्योगिक केंद्रों का नहीं हो सकता क्योंकि वे बसने वाले केंद्रों व कारखानों के पास ही नियुक्त हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)—स्थानीयकरण का लाभ हानियों की दृष्टि से अधिक है। जो कुछ दोष हैं वे भी उत्तरदायी हैं। यदि एक केंद्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित कर दिए जायें तो मानव बुद्धिमानता का एकांगी विकास और मदी द्वारा होने वाले आर्थिक सिकट का भय दूर हो सकता है। अव्यवस्थित श्रमिकों की बेकारी महामय उद्योग-विकास द्वारा दूर हो जाना सम्भावित है। श्रमिकों में कारखानों में मन लगाने का प्रभावित न कर देता तो स्थापित करने में केंद्रीयकरण का दोष दूर हो सकता है। अतः केन्द्र में जन वित्त, दानि और शीघ्र व समान यातायात व सम्वाद के माध्यमों द्वारा अतिरिक्त स्थानों में कारखानों स्थापित करना सम्भव है।

उद्योगों का विवेन्दीयकरण (Decentralisation of Industries)

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुख्य बात ऐसी है जिनके द्वारा उद्योगों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति में स्वावट पैदा हो जाती है। ये विवेन्दीयकरण अर्थात् उद्योगों के यत्र तत्र स्थापित किये जाने में सहायक होती हैं। एक ही प्रकार के उद्योगों के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थापित होने की प्रवृत्ति को उद्योगों का विवेन्दीयकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में, पहले सूती कपड़ों के कारखाने अम्बई और महमदाबाद में ही थे, परन्तु अब कई स्थानों में स्थापित हो गये हैं और होने जा रहे हैं। इसके कारण मुख्यतया निम्नलिखित हैं —

(१) जल विद्युत शक्ति का विकास—जल विद्युत शक्ति का विकास के पूर्व कारखाने प्रायः कोयलों की खानों के आस-पास ही स्थापित होते थे। परन्तु जल विद्युत शक्ति के विकास से आज कारखाने दूर-दूर स्थानों में स्थापित हो सकते हैं क्योंकि जल-विद्युत शक्ति नारों द्वारा सुगमता से और कम लागत में दूर के स्थानों में ले जाई जा सकती है।

(२) यातायात के साधनों की उन्नति—यातायात के साधनों में उन्नति होने से बड़ा माल भेजने तथा तैयार माल भेजने में पर्याप्त सुविधा हो जाने के कारण केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति निमित्त हो गई है।

(३) औद्योगिक नगरों में भूमि के मूल्य और भवनों के किराये में वृद्धि—बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में जनसंख्या की वृद्धि के कारण नए कारखाने स्थापित करने के लिये पर्याप्त भूमि बड़ी कठिनाई में और बहुत ऊँचे मूल्य पर मिलती है। इससे प्रतिरिक्त हमारे देश का किराया भी बहुत देरा पड़ता है और कर-भार भी वहाँ बहुत होता है। जिनके कारण बड़ा हुआ सागत खर्च नये कारखानों के लिये प्रमत्त हो जाता है। कच्चा और देहानों के कारखानों के स्थापित करने में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएं

- १—उद्योगों का स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं? उन कारणों का विवेचन कीजिये जिनसे यह उत्पन्न होता है? (७० प्र० १९५३)
- २—उद्योग-धन्धा के स्थानीयकरण के कारण बताइयें। बम्बई में सूती धन्धा के मदम में अपना उत्तर लिखिये। (२० वी० १९५१)
- ३—उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण बताइयें और इससे मुख्य लाभ-हानि का वर्णन कीजिये। (२० वी० १९५२, ४६)
- ४—‘उद्योगों के स्थानीयकरण’ से आप क्या समझते हैं? इसके क्या कारण हैं? इसके प्रमुख लाभ भी बताइयें।
- ५—उद्योग-धन्धा के स्थानीयकरणों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये। (५० भा० १९५२)

उत्पत्ति के परिमाण का अर्थ

उत्पादन छोटे और बड़े दोनों परिमाण में होता है। जब उत्पादन अधिक कच्चे माल, थम और पूँजी आदि से किया जाता है, तो उसे बड़े परिमाण की उत्पत्ति (Large-Scale Production) कहते हैं। बड़े परिमाण की उत्पत्ति के अन्तर्गत उद्योगों का संगठन इस प्रकार का होता है कि उनमें अधिक मात्रा में कच्चा माल, पूँजी, आधुनिक एवं विशिष्ट मशीनों का प्रयोग और विस्तृत श्रम-विभाजन के अतिरिक्त सहस्रो श्रमिक काम करते हैं तथा जिनकी उत्पत्ति केवल देश तक ही सीमित न रहकर दूर देशों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। कपड़े, चीनी की बड़ी बड़ी मिलें, लोहे और इस्पात के कारखाने ऐसे-ऐसे कम्पनियाँ आदि उत्पत्ति के बड़े परिमाण के कुछ उदाहरण हैं। इससे विपरीत छोटे से कच्चे माल, थम और पूँजी से कम मात्रा में माल तैयार करने का छोटे परिमाण की उत्पत्ति (Small-Scale Production) कहते हैं। उदाहरणार्थ, जुलाहा, कुम्हारों, मुनारों, सुहारों आदि के काम। कुछ व्यवसायों में उत्पत्ति का परिमाण बड़ा होता है और कुछ में छोटा। कभी-कभी एक ही व्यवसाय में बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के उत्पादन सामान्य चलते हैं। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् उत्पादन के परिमाण में बहुत वृद्धि हो गई है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस आदि सभी मज्दूरीय बड़े परिमाण की उत्पत्ति के उद्योगों को अपनाते जा रहे हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि छोटे परिमाण वाले उद्योग का विलुप्त हो गया है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो छोटे पैमाने पर ही चलाये जा सकते हैं। जिन उद्योग-पंथों में उत्पादक के व्यक्तिगत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। या जिनमें व्यक्तिगत रूचियों और कौशल के अनुसार काम करना पड़ता है, उनमें बड़े परिमाण पर उत्पत्ति मफ़्त नहीं हो सकती। दोनों दोनों में कुछ अलग-अलग विशेषताएँ हैं जिनके कारणों से प्राप्त एक माप चाखू है हम यहाँ अब से प्रथम बड़े परिमाण की उत्पत्ति पर विचार करेंगे और अन्तर्धान छोटे परिमाण की उत्पत्ति पर।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति

(Large scale Production)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति के लाभ

(Advantages of Large-Scale Production in Manufacture)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति के कई लाभ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रो० मार्शल के मतानुसार ये लाभ दो भागों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं—

(१) बाह्य वचन (External Economies) और (२) आन्तरिक वचन (Internal Economies) ।

(१) बाह्य वचन (External Economies)—यह वचन है जो किसी उद्योग पधो की मांगरण उत्पत्ति व कारण होती है। यह विधा विवेक उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होत के कारण गहा होता बनि मण्युय व्यवसाय के माधारण विकास के कारण उत्पन्न होती है। उम व्यवसाय में मरदन मन्त्रा वाग्यमान इस प्रकार का लाभ उठा सकते है। अधिक स्पष्ट करने हुये गी कहा जा सकता है कि उद्योग धन्दा के स्थानीयकरण से जा लाभ होत है उरु बाह्य वचन कहते है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र की मिला की मन्त्रा में वृद्धि होत के माध माध उम प्रयुक्त होतें बार्मी मनीना के उत्पादन में वृद्धि हावर उनकी लागत कम हा चार में वडी भागी वचन हानी है। इसी प्रकार जब कोई व्यवसाय किसी विशिष्ट स्थान पर केन्द्रीय हो जाता है ता उम व्यवसाय के समस्त कारखाना को यातायात बिज्ञापन, बीमा, बरु, सहायक धन्दा, राज्य सहायता अनुमदान तथा प्रौद्योगिक मन्त्राशा आदि की सुविधा विवेक रूप में उपलब्ध होत के कारण पयात वचन होती है। इस प्रकार के समस्त लाभ बाह्य वचन के नाम में सम्बोधित विय जाते है।

(२) आन्तरिक वचन (Internal Economies)—यह वचन है जा किसी एक कारखाने के आन्तरिक व्यवस्था तथा प्रबंध की उरुगता के कारण होती है। इसका बाहरी प्रबन्धना में बाड सम्बन्ध नही है। आन्तरिक वचन वाग्यमान के मण्डन की उत्तमता पर निर्भर होती है। सुयोग्य व्यवसाय विस्तार उत बात का शोध में लगा रहता है जिनसे आन्तरिक वचन में वृद्धि हा। बड परिमाण के उत्पादन में जो मुख्य आन्तरिक लाभ होत है वे निम्नांकित है —

१. श्रम विभाजन के समस्त लाभ (All the Advantages of Division of Labour)—उत्पादन बड परिमाण में हात के कारण श्रम विभाजन में दूर पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

२. मशीन के प्रयोग के समस्त लाभ (All the Advantages of Use of Machinery)—बड परिमाण में उत्पत्ति और मशीन का प्रयोग एक प्रकार में साथ साथ चलते है। अस्तु मशीन के प्रयोग के लाभ व परिमाण की उत्पत्ति में लाभ बड जात है।

३. मूल्य में कमी (Low Prices)—जब किसी वस्तु का उत्पादन बड पैमान पर होता है तो उम वस्तु के लागत दाम भी कम हा जात है जिससे वह वस्तु बाजार में मन्त्री मिलन लगती है और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचना है।

४. श्रम की मितव्ययता (Economy of Labour)—बड कारखाना में कोई एक काम पाठ में श्रमिका द्वारा मन्त्र किया जाता है जबकि छोट कारखाना में उता काम के लिए अधिक श्रमिका ना लगाना पडता है।

५. विवेक की नियुक्ति (Employment of Technical Experts)—बडी मात्रा में उत्पादन होत में श्रम विभाजन में उत्पत्ति होता है स्वाति यह बड वाग्यमान में बडी मायना वात विगपन नियुक्त विय जा सकता है। जा उरु परिमाण के उत्पादन में सम्भव नही है।

६ आधुनिक एवं विशिष्ट मशीनों का प्रयोग (Use of Up to date and Specialised Machinery) — बड़े परिमाण में उत्पादन करने वाला आधुनिक एवं विशिष्ट मशीनों का प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ा सकता है।

७ ब्रय में मितव्ययता (Economy in Buying) — बड़े कारखाने वास्तव में अधिक मात्रा में खरीदते हैं। अतः उन्हें इन वस्तुओं में खरीदने में ब्रय दर लड़ाई हुआई आदि में पर्याप्त मितव्ययता होती है।

८ विक्रय में मितव्ययता (Economy in Selling) — अधिक मात्रा में मात्र बचन में ब्रेक लागू आदि वस्तुओं में पर्याप्त बचन होती है।

९ अवशिष्ट पदार्थों का सदुपयोग (Utilization of Bye Products) — बड़े कारखाने में उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों का सदुपयोग हो सकता है। उदाहरणार्थ खाद्य की मिठाई में गीर (Molasses) से अथवा शक्ति (Power Alcohol) तैयार की जाती है।

१० बड़े परिमाण में विज्ञान सम्पन्न (Large Scale Adversing) — छोटे कारखाने बड़े वैज्ञानिक विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः केवल बड़े कारखाने वाले ही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

११ बड़े निर्माता का व्यापार सम्बन्धी व्यापक नीति निर्धारित करने का पर्याप्त अवसर मिल सकता है (A large Manufacturer can devote himself entirely to broad questions of policy) — बड़ा निर्माता अपना दैनिक सामान सम्बन्धी कार्य प्रबंधन आदि कमनायिका के मजदूर कर वह अन्य व्यापार के नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर सकता है।

१२ बाजार की घटा-बढ़ती से अल्प प्रभावित नहीं होना (Not much affected by Market Fluctuations) — बड़ा व्यापारी या उत्पादक अपने स्वयं के अनुभव तथा विशेषज्ञ (Experts) का समर्थन में भावी बाजार का ज्ञान प्राप्त कर अनुमान लगाकर उत्पादन प्रारम्भ करता है। अतः, वह बाजार की घटा-बढ़ती से प्रभावित नहीं होता रहता है। यदि कदाचित् उसका अनुमान ठीक न पड़े तो भी वह अपनी विकल्प योजना के माध्यम से बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

१३ प्रयोगशाला में प्रयोग और अनुसन्धान किया जा सकता है (Experiments and Researches can be carried out in Laboratories) — एक बड़ा निम्नलिखित अपने स्वयं के प्रयोगशाला एवं अनुसन्धान के लिए स्थापित कर बड़े-बड़े विज्ञान का उपयोग कर अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। छोटे निर्माता या उत्पादक इन लाभ से वंचित रहते हैं।

१४ स्थान की मितव्ययता (Economy of Space) — बड़े निर्माता अतः उत्पादन के लिए बड़े-बड़े कारखाने के बड़े छोटे छोटे कारखाने हैं या अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।

१५ पूँजी की मितव्ययता (Economy of Capital) — बड़ा निर्माता या उत्पादक पूँजी का उपयोग बड़ी मात्रा में करता है। अतः वह पूँजी कम व्याज पर प्राप्त कर सकता है।

१६ मान्यता में वृद्धि होती है (Credit is enhanced) — छोटे निर्माता या उत्पादक की अपेक्षा बड़े निर्माता या उत्पादक का अधिक लाभ जानने

संग जाते हैं जिसमें जमाकर रखा है वहन दूर दूर तक पहुँच जातो है। यह स्याति मांस का विशाल यशस्व म महात्मक सिद्ध होता है। पूँज भी आवश्यकानुसार और कम-अधिक पर एक प्रादि से मिल जाता है।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति का हानिया

(Disadvantages of Large Scale Production)

१ मान व माग का अनुमान अन्यथा मित्र हान पर हानि का सम्भावना—यदि निमाता या उत्पादक का भाव माग का अनुमान ग्राह्य मित्र न हान पर मान का प्रविष्टीत स्टॉक अधिक रह जायता तो उस हानि उठाने पड़ी।

२ उद्योगपतिया और श्रमजीविया व मध्य निवृत्त सम्पर्क का प्रभाव—बड़ा माग की उत्पत्ति के सम्बन्धित कारणता से मध्य श्रमजीवियों काय रहते हैं। मध्य मिल मालिकों और श्रमजीवियों व मध्य निवृत्त सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता। इसीलिए कभी श्रमिकों की शक्ति में हड़ताल और बन्धन-योगपतियों का शक्ति में मानवलो होता है।

३ श्रमतोषजनक वितरण व्यवस्था वितरण में श्रमिकों को कम भाग मिलने में व लोग मरवा प्रमुख रहते हैं। यह वितरण में लोगों व मध्य मनी मानिय रहता है और उनमें परस्पर मध्य घनता रहता है जो व्यवस्था और राज्य का उत्पत्ति व विधे प्राप्त मित्र हो सकता है।

४ ट्रस्ट कार्टेल आदि सभा का उत्पत्ति—यह निमाता या उत्पादक परस्पर मिलकर एकाधिकार (Monopoly) स्थापित कर ट्रस्ट (Trust) कार्टेल (Cartel) आदि मध्य बनाते हैं। ये मध्य मान वेचते हैं और उनमें मध्य अधिक लाभ लेते हैं।

५ दूर और कुटीर व्यवसायों का घनन—यह निमाता या उत्पादक का घनक प्रकार की घनन हान व कारण मान करता व्यव मरते हैं। उनमें मानने शक्ति विमान और विस्तृत हान है कि यह निमाता या उत्पादक उनका प्रतिपादितता (Control) में मरवा रहते हैं। घनन गति ट्रस्टों का घनन का लाभान्वित व मध्यकर स्थिति या मध्यकर रहते हैं।

६ घन वितरण में श्रममानता—उद्योग व राष्ट्रवर्धन व भाव में यह उद्योग मध्य श्रमजीवियों व राज्य में आ जाते हैं जिसमें कारण मध्य व अधिकार घन वृद्धि में मध्य भर उद्योगपतियों व अधिकार में आ जाते हैं और उनका का एक घन भाग निधन हो जाता है।

७ श्रमिकों के स्वाभ्यन्तर और बाह्य व कुप्रभाव—यह माग व उत्पादन व घनन कारणता में मध्य श्रमिकों का एक मान रहता तथा लाभ करता पड़ता है। मध्य श्रमिकों के बड़ा व नम्रता अधिक है। जान व श्रमिकों का वितरण मध्यमवर्ग हो जाते हैं। ऐसे मध्यमवर्ग बाजारवर्ग में उनका श्रमिक मध्य मध्यमिक घनन कारण हो जाता है।

८ प्रकारों की घनता—बड़ा माग में उत्पत्ति व विधे मागता या प्रभाव निमाता कारणता है। मागता व प्रभाव में प्रभाव वरती है मध्य वृद्धि मध्य व माग मध्यमिक मान कर जाता है।

६. उत्तरदायित्व व नीरसता का अभाव और दक्षता का एकाङ्गी विकास—बड़े परिमाण में उत्पात्ति में मनुष्य-विभाजन होता है और अम-विभाजन द्वारा उत्पन्न होने वाली हानियाँ होती हैं, जैसे उत्तरदायित्व व नीरसता का अभाव और दक्षता का एकाङ्गी विकास आदि ।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति की सीमाएँ

(Limitations of Large-Scale Production)

— बड़े परिमाण की उत्पत्ति के एकल लाभ हैं । मनु, इन लाभों को अधिकतम मात्रा में प्राप्त करने के हेतु उत्पत्ति में वृद्धि करना स्वाभाविक है । परन्तु उत्पत्ति की वृद्धि असीमित प्रवृत्ति तक नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं । ये सीमाएँ निम्नलिखित हैं —

(१) उद्योग-धन्यो का स्वभाव—कुछ उद्योग स्वभावतः भारी होते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर ही चलाया जाता है जैसे चैन के इजन बनाना बिजली उत्पादन करना मोटर व जहाज आदि के उद्योग । जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत ध्यान, शक्ति और दक्षता की आवश्यकता होती है उनमें बड़े परिमाण में उत्पत्ति लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ, रेशमी परत बुनना, बसंदा काटना, चित्र बनाना, बीड़ी बनाना, दर्जी, स्वर्णकार और जवाहराज आदि का काम ।

(२) उत्पत्ति का स्वभाव—यदि निमित्त बहुत छोटा पदार्थ होने वाली है प्रकृति प्रवाहनीय है, तो उसका उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है । इसके विपरीत, यदि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से नहीं जा सकती है तथा जिसके द्वारा धनी मनुष्य से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है ।

(३) बाजार का विस्तार—बड़े परिमाण में उत्पादन तभी सम्भव हो सकता है जबकि मांग भी उतनी के लिये बाजार विस्तृत एवं स्थायी हो । जिन वस्तुओं की मांग कम होती है वेबल के ही बरतुएँ बड़ा पैमाने में उत्पादन की जा सकती हैं, जैसे कपड़ा, चीनी, कागज आदि ।

(४) उत्कृष्ट व्यवसाय एवं प्रवृत्ति की कठिनाई—मनुष्य की मरदन शक्ति सीमित होती है । वह कार्य का देश रख किसी एक सीमा तक ही भली प्रकार कर सकता है । उसके उपरान्त विभिन्न विभागों का निरीक्षण, निवर्तण और सामंजस्य उसके लिये कठिन हो जाता है । उसके कार्यकुशलता घट जाती है और काम में अनेक त्रुटियाँ होने लगती हैं । इस प्रकार किसी एक सीमा के पश्चात् उत्पादन-प्रसार लाभदायक नहीं होता ।

(५) अम-विभाजन और मशीनों की मितव्ययताओं की सीमा—अम-विभाजन और मशीनों के प्रयोग से जो उचित होती है वह निरन्तर नहीं रह सकती । उनका भी निर्माण एक सीमा के पश्चात् घटने लगता है, कारणों से होता है, क्योंकि उस सीमा के बाद अम-विभाजन और मशीनों के प्रयोग से वृद्धि करना कठिन हो जाता है ।

(६) पूँजी आदि उत्पत्ति के साधनों की परिमितता—उत्पत्ति के परिमाण का जितना अधिक बढ़ाया जायगा, उतनी ही अधिक आवश्यकता पूँजी और अन्य साधनों की पड़ेगी । ये साधन सर्वत्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते । अतएव इस कारण भी उत्पत्ति की मात्रा सीमित हो जाती है ।

(७) मनुष्यों का चरित्र :—उत्पादन का परिमाण देश के मनुष्यों के चरित्र पर हो निर्भर है। यदि लोग माहसी हैं और नवीन योजनाओं सम्बन्धी जोखिम उठाने के लिये तैयार हैं, तो निरन्तर उपादन बड़े पैमाने पर होगा।

प्रो० चैपमैन^१ (Prof. Chapman) के अनुसार बड़े परिमाण की अन्तिम सीमाएँ (Final Limits) निम्नलिखित हैं :—

- (१) मगदन की प्राभ्यान्तरिक (Internal) कठिनाइयाँ।
- (२) निर्मित वस्तुओं के गुणों का महत्त्व।
- (३) उपयोग में आने वाली मशीनों की लागत।
- (४) बाह्य (External) कठिनाइयाँ जो बाजार के स्वभाव से सम्बद्ध हैं।
- (५) वस्तु की माँग में स्थिरता।
- (६) उद्योग की उत्पत्ति-विधि सम्बन्धी निश्चयता।
- (७) बड़े पैमाने की उत्पत्ति में व्यय का परिमाण।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति और यातायात के साधन

(Large-Scale Production & Means of Transportation)

सस्ते और छोटे यातायात के साधन बड़े परिमाण की उत्पत्ति में बड़ा सहायक हैं। (१) इनके द्वारा दूर स्थित स्थानों में वस्तु मान प्राप्त किया जा सकता है। (२) इनमें धम की गतिशीलता बढ़ती है। (३) मान को उपर के लिये बाजार और मंडियों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति और कृषि व्यवसाय

(Large-Scale Production & Agricultural Industry)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति का प्रयोग निर्माण व यातायात व्यवसायों में मशीनीकरण हो सकता है। परन्तु कृषि व्यवसाय इनके लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं है। इसके कई कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१. कृषि में विशिष्ट (Specialised) मशीनों और धम-विभाजन का बहुत कम क्षेत्र है।

२. कृषि में उत्पत्ति-ह्रास-नियम (Law of Diminishing Return) होने के कारण बड़े परिमाण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

३. कृषि जलवायु आदि प्राकृतिक कारणों पर विशेष निर्भर होने के कारण बड़े परिमाण की उत्पत्ति के उपयुक्त नहीं है।

४. निर्माण व्यवसाय की ओर आशा कृषि व्यवसाय एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला होने के कारण निरीक्षण एवं प्रबन्ध कठिन हो जाता है। इस कारण कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति और भारतवर्ष (Large Scale Production and India)—बड़े परिमाण की उत्पत्ति आजकल समार के सभी मुख्य देशों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतवर्ष में भी इस ओर पर्याप्त प्रयत्न

दृष्टिगावर होती है परन्तु कुछ वाग्म्य यह। अब जो अवरोधक मित्र होते हैं वे निम्न निम्नित हैं —

१ अनविज्ञता (Ignorance) २ साहस का अभाव (Lack of Enterprising Spirit) ३ संकीर्ण विचार (Narrow Outlook) ४ भाग्यवादिता (Fatalism) और ५ विदेशी प्रतियोगिता (Foreign Competition)

छोटे पारिमाण की उत्पत्ति

(Small Scale Production)

जो कारण हैं कायम (Causes of Persistence of Small Scale Production) वे परिमाण की उत्पत्ति व अनेक कारण हैं और इस भाग लोना का भुक्तान बढता जा रहा है पर इसका कारण यह नहीं है कि छोटे परिमाण की उत्पत्ति का अन्त आ गया है। छोटे कारखाने वर्तमान समय में भी अपनी विशेष शक्ति का लाभ कायम कर रहे हैं। उन्हें अधिक धन नहीं मिल सकता। इससे निम्नलिखित कारण हैं —

१ व्यक्तिगत देख रेख और लक्ष्य देने व्यवसाय—जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत अभ्यास, लक्ष्य और देख रेख की आवश्यकता होती है। व छोटे पैमाने पर ही सुचारु रूप में चलाये जा सकते हैं। जैसे दर्जा, हथवाड़ी, स्वामिकार, खेती आदि का व्यवसाय

२ बनावट-बौद्धिक की वस्तुएँ—जिन वस्तुओं के तैयार करने में विभिन्न बनावट और नान की आवश्यकता होती है उनका निर्माण व्यवसाय छोटे पैमाने पर होना निश्चित है।

३ सीमित तथा अस्थायी मांग—कुछ वस्तुएँ ऐसा होती हैं जिनकी मांग न तो अधिक होती है और न स्थायी रहती है जैसे पान, मजबूत आदि की वस्तुओं का व्यवसाय प्रायः छोटे पैमाने पर ही होता है।

४ व्यवसाय का स्वभाव कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें विभिन्न विभाग नहीं किए जा सकते और जो स्वभावन छोटे पैमाने पर ही चलाये जा सकते हैं जैसे धूप आदि।

५ उद्योग की प्रागम्भिक अवस्था—प्रायः सभी उद्योग शुरू में छोटे पैमाने पर ही प्रारम्भ किए जाते हैं।

६ स्वतन्त्रताप्रिय शिल्पकार—जो शिल्पकार स्वतन्त्र रह कर ही जोरदार काम करना चाहते हैं वे प्रायः अपने व्यवसाय को छोटे पैमाने पर ही चलाना पसन्द करते हैं।

छोटे परिमाण की उत्पत्ति के लाभ

(Advantages of Small Scale Production)

(१) व्यक्तिगत निरीक्षण—छोटा निम्नता या उत्पादक अपने काम की देख रेख स्वयं कर सकता है। अतएव वह अधिकारी की निश्चिन्ता और अवधान पर अनुग्रह रख सकता है। वह उनमें वांछितानुसार काम कर सकता है उसकी गूँथियाँ निकाल सकता है और उन्हें प्रामाण्य दे सकता है।

(२) म्वाभी और सेवको के मध्य निकट सम्पर्क—छोटे कारखाने में म्वाभी और श्रमिकों के मध्य सीधा एवं निकट सम्पर्क स्थापित रह सकता है जिससे पारस्परिक सहय नहीं रहता ।

(३) ग्राहकों से अधिक सम्पर्क—छोटे निर्माता या उत्पादक अपने ग्राहकों के अधिक सम्पर्क में रहते हैं । वे उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुएँ तैयार करते हैं जिसमें अधिकृत स्टॉक रहने की बहुत कम सम्भावना होती है ।

(४) धन का समान वितरण—छोटे परिमाण की उत्पत्ति में अन्तर्गत धन-वितरण स्वयंसे सम्मान ही होता है । इससे सामाजिक अशांति और असम्यक् काम हो जाता है ।

(५) स्वतन्त्रतापूर्वक एवं सुविधानुसार कार्य—छोटे परिमाण की उत्पत्ति में शिल्पकार एक अधिक घर बैठे स्वतन्त्रतापूर्वक तथा अपनी सुविधानुसार काम कर सकते हैं । उन्हें किसी की आधीनता में नहीं रहना पड़ता है ।

(६) बड़े परिमाण की उत्पत्ति के दोषों का प्रतिहार—जिस देश में छोटे परिमाण की उत्पत्ति की प्रधानता होती है वहाँ के निवासी सूक्ष्म विभाजन मशीनों के प्रयोग आदि सीधोगोकरण की हानियों में बचे रह सकते हैं ।

(७) व्यक्तिगत गुणों के विकास का अवसर—छोटे परिमाण के उत्पादन में आत्मनिष्ठता, उत्तरदायित्व, सफाई आदि व्यक्तिगत गुणों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है ।

(८) औद्योगिक नगरों के दोषों से मुक्ति—छोटे परिमाण की उत्पत्ति में अस्वस्थकर घायात, मृन्दगी, मरुपान, बेइजागमन, जुम्रा आदि दोष नहीं पाये जाते । वहाँ का वातावरण मशीनों की गड़गड़ाहट और धमकी के गुण से दूषित नहीं होता ।

(९) पूँजीवाद के दोषों का अभाव—छोटी मात्रा की उत्पत्ति में स्त्री व बच्चों का शोषण, असमान धन-वितरण आदि पूँजीवाद के दोष नहीं पाये जाते ।

छोटे परिमाण की उत्पत्ति की हानियाँ

(Disadvantages of Small-Scale Production)

छोटे परिमाण की उत्पत्ति में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :—

(१) बड़े परिमाण में उत्पत्ति की विविध वचत्ता का सर्वथा अभाव—छोटे पैमाने के उत्पादन में बड़े परिमाण की उत्पत्ति में होने वाली विविध वचत्ता का सर्वथा अभाव देखा जाता है । उदाहरण के लिए, नवीनतम मशीनों के प्रयोग में वचत्त, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग, सूक्ष्म अन्त-विभाजन में वचत्त, कारखाने, पैकिंग विभाग और वातावरण की वचत्त, बच्चा माल व मशीनों आदि के खराब होने में वचत्त, विज्ञापन, प्रभु संधान और प्रयोग आदि सुविधाएँ छोटे उत्पादकों को उपलब्ध नहीं होती ।

(२) प्रति इकाई अधिक उत्पादन व्यय—बड़े परिमाण की उत्पत्ति की विविध वचत्ता के अभाव में छोटे परिमाण में प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है जिससे छोटे उत्पादक बड़े उत्पादकों की प्रतियोगिता में नहीं उठ सकते ।

(३) कुछ उद्योग धन्य स्वभावतः बड़े परिमाण में चलाये जा सकते हैं—
कुछ व्यवसाय ऐम हैं जिनमें अधिक पूँजी की आवश्यकता होने से केवल अधिक पूँजी
बाध ही कर सकते हैं। जैसे खान खादना यातायात सम्बन्धी उद्योग, शोक व्यापार, बीमा
और बैंक कार्य आदि।

(४) मामूली साधनों से सबट निवारण नहीं हो सकता—छोटे उत्पादन के
पाम सीमित साधन होने से निर्पत्ति का मामला ठीक प्रकार नहीं किया जा सकता।

(५) सम्पूर्ण साख सम्पन्न नहीं हो सकती—छोटे उत्पादक का उत्पादन-कार्य
छोटे पैमाने पर होने से वह सस्ती ग्राहक का लाभ नहीं उठ सकता।

छोटे परिमाण की उत्पत्ति के बाधों को दूर करने के साधन

१- (१) मशीनों का प्रयोग (Use of Machinery)—आजकल मशीनों
के आविष्कारों की उत्पत्ति के फलस्वरूप अनेक प्रकार की मशीनें छाड़ी और मीथना में
काम करने वाली मशीनें उपलब्ध होती हैं जो अधिकतर जल विद्युत द्वारा चलाई जाती
हैं इनके प्रयोग में छोटे उत्पादकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने के अनिवार्य उसे अनेक
लाभ प्राप्त होते हैं।

(२) सहकारिता का विकास (Development of Co-operation)—सहकारिता का उत्पत्ति के फलस्वरूप छोटे उत्पादकों को बहुत सी व सुविधाएँ प्राप्त हो
गई हैं जो पहा व फल व उत्पादकों को ही उपलब्ध थीं, जैसे अनेक विभिन्न पूँजी प्राप्ति में
सफल।

(३) व्यापारिक ज्ञान का प्रसार (Diffusion of Trade Know-
ledge)—वर्तमान समय में व्यापारिक ज्ञान केवल बड़े उत्पादकों तक ही सीमित नहीं
है बल्कि छोटे उत्पादकों भी समाचार-पत्रों व्यापारिक-संस्थाओं व सम्मेलनों आदि द्वारा
व्यापारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

(४) विज्ञान की उत्पत्ति (Progress of Science)—विज्ञान की उत्पत्ति
में भी छोटे उत्पादकों को बड़ी सहायता मिलती है। मशीनों का आविष्कार शक्ति के
सम्बन्ध में, सम्बाद व यातायात के साधनों की उत्पत्ति औद्योगिक ज्ञान का विकास,
अनुसंधान और प्रयोग के लाभदायक परिणाम आज छोटे और बड़े सभी उत्पादकों को
उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)—आज भी मनुष्य-राज्य अमेरिका ब्रिटिश,
जर्मनी इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड बेल्जियम, जापान आदि देशों में छोटे व्यवसाय बड़े
पैमाने वाले व्यवसायों के साथ साथ मिलते हैं और उनसे सफलतापूर्वक टक्कर ल रहते हैं।
भारतवर्ष में छोटे पैमाने के व्यवसायों के विकास के लिए पर्याप्त धन है। अब भी
भारत में लाखों मनुष्य अपनी आजीविका के लिए परेशान व्यवसायों पर निर्भर हैं। भारत
एक कृषि-प्रधान देश है और यहाँ के कृषक वर्ग मशीनों तक बेकार बैठे रहते हैं।
ऐन्सोर्ट्स इनके लिए छोटे व्यवसायों का विकास बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। इन
सम्बन्ध में अखिल भारतवर्षीय ग्रामोद्योग मण्डल (All India Village Industries
Association), भारतीय नवविम, केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों का कार्य
सहाय्यी है।

बड़े पैमाने पर खेती (Large-Scale Farming)

जिमी भूमि के बड़े भाग पर थमिया की सहायता से मशीन द्वारा खेती करने को बड़े पैमाने की खेती कहते हैं। बड़े पैमाने की खेती के अन्तर्गत खेत सितना बड़ा होना चाहिए इस विषय में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणार्थ मारनबर्ग में लगभग २५-३० बीघे का खेत बड़े पैमाने की खेती योग्य समझा जाता है, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में १०० बीघे का खेत एक मध्यम आकार का खेत माना जाता है। कुछ भी हो, बड़े पैमाने की खेती के अन्तर्गत मशीनों का विस्तृत प्रयोग, उत्तम बीजा का उपयोग, प्राधुनिक सिंचाई के साधन और मार्केटिंग सुविधाएँ आदि बात सम्मिलित हैं। बड़े परिमाण की खेती में लाभ

(Advantages of Large-Scale Farming)

१. प्राधुनिक मशीनों और औजारों का प्रयोग सम्भव—बड़े पैमाने की खेती में प्राधुनिक और मूल्यवान मशीन और औजार प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होकर लागत कम हो जाती है।

२. श्रम-विभाजन से लाभ—यद्यपि निश्चित अवसरों की भांति श्रम विभाजन इतनी सूक्ष्म प्रणाली तक नहीं जाया जा सकता, परन्तु फिर भी छोटे पैमाने की खेती की प्रणाली बड़े पैमाने की खेती में श्रम विभाजन अधिक विस्तृत रूप में सम्भव है। अतः, श्रम-विभाजन व अनेक लाभ बड़े पैमाने की खेती को उपलब्ध हो सकते हैं।

३. दक्षता में वृद्धि—दक्षता में वृद्धि नहीं हो सकती है जब तक व्यक्ति वही काम करता है जिसमें वह दक्ष हो। यह तभी हो सकता है जबकि थमिक निरन्तर वही कार्य करे। बड़े पैमाने की खेती में ही यह सम्भव है कि थमिक निरन्तर एक ही काम करता रहे।

४. मूल्य-विक्रय में वृद्धि—बड़े पैमाने का वस्तु का मूल्य-विक्रय में भी वृद्धि पायी जाती है। वस्तु में बड़े मात्रा में लगी जाने वाली लागत है जिसमें उत्पन्न कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

५. बड़ा फल पर्याप्त पूँजी से सुसज्जित होता है—बड़े पैमाने की खेती की पर्याप्त पूँजी सरलता से कम समय पर उपलब्ध हो सकती है। यह अपनी पूँजी को उत्तम मूल्य, रिबाई, भाँसे-नाशियों आदि का निधि प्रयुक्त कर सकता है। यह सुविधा छोटे पैमाने की खेती में नहीं हो सकती।

६. वैज्ञानिक ढंगों में लाभ—बड़े पैमाने की खेती में फसल-परिवर्तन (Rotation of Crops), रासायनिक खाद का प्रयोग तथा खेती के अन्य वैज्ञानिक ढंगों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना सहज है।

७. अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग—बड़े पैमाने पर अवशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होने के कारण लाभ उपयोग में लाए जा सकते हैं।

८. मध्यमजनों का तोप—बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले अपने पैदावार सीधे उपभोक्ताओं से बेच सकते हैं जिनमें मध्यमजनों (Middlemen) का तोप होता उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को ही लाभ हो जाता है।

६ गृह्यक उद्योग धन्धा की स्थापना—बड़ पैमाने पर कई गृह्यक उद्योग यों स्थापित किये जा सकते हैं। जैसे—गन्ध के फाग पर डरी चीनी की मिम गुड़ और शराब आदि के बारमान खुन सकते हैं।

बड़े परिमाण की खेती से हानियाँ

(Disadvantages of Large Scale Farming)

१ कृषि निरीक्षण एवं प्रबन्ध में कठिनाई—बड़ पैमाने की खेती में उत्पत्ति नाय दूर तक फैल जाने के कारण फसल का निरीक्षण एवं प्रबंध कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता तथा इसके लिये समय तक फैल रहने के कारण निरीक्षण सम्बन्धी व्यय भी अधिक होता है।

२ श्रम विभाजन अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता—निर्माण व्यवसाय की धेनी में श्रम विभाजन करना लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कई सीमाएँ हैं।

३ समय और शक्ति का दुरुपयोग—बड़ पैमाने की खेती में बड़-बड़ मत्त होते हैं जिनके एक भाग में दूसरे भाग का जाल घाने में श्रमिका व समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है।

४ खेती का अधिकतर मौसम पर निर्भर होना—खेती में प्राधुनिक मशीना और वैज्ञानिक ढंगा का प्रयोग होने से भी मौसम प्रभाव नहीं हटता और जलवृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना उपयुक्त जलवायु व इतनी कम विस्तृत सम्भव नहीं।

५ मशीनों के प्रयोग से अधिक व्यय सम्भव नहीं—खेती में विभिन्न मशीनों का प्रयोग कम होने में व्यय कम होता है।

६ कृषकों की व्यक्तिवादिता—खेती व श्रमिक प्रायः समुदाय में कार्य करना पसन्द नहीं करत। वे स्वतन्त्रताप्रिय होते हैं उन्हे अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता। अस्तु उन्हें मजदूर बनना एक बड़ा पछि काय हो जाता है।

७ फल फल आदि की खेती में कठिनाई—फल फूल आदि की खेती में देख देख की अधिक आवश्यकता होने व बारम्बार बड़ पैमाने के उत्पादन में कठिनाई हो पाता है।

८ भूमिरहित श्रमिका की समस्या में वृद्धि—बड़ पैमाने की प्रतिस्थापिता में छोटा काम बान नही रहता बनने। अतः छोटे काम वाला का प्रवेश पधा छोड़ कर अन्य काम करना पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे भूमिरहित श्रमिका की समस्या में वृद्धि होती जाती है।

९ जमींदारी प्रथा की हानियाँ—बड़ परिमाण की खेती में धन वितरण में असमानता हो जाती है। एक जमींदार का सारा धन एक ही हाथ में रहता है और दूसरा कृषक का। जमींदार प्रथा नाथ अथवा बमचारिया व मुकुद का गहरा व विनाश आघात व्यक्त करने लगत है। जमींदार और किसानों में मध्यम वर्ग प्रथा विनाश का कारण प्रावि सामाजिक दोष उत्पन्न हो जात है।

बड़े परिमाण की खेती और भारतवर्ष—दृग्ग कोई सन्देह नहीं है कि छोटे परिमाण की खेती की अपेक्षा बड़े परिमाण की खेती में अन्न लाभ है। परन्तु

भारतवर्ष की परिस्थिति इस प्रकार की है कि बड़े पैमाने की खेती में लाभ के स्थान में हानि होना सम्भव है। ऐसी दशा में भारतवर्ष में बड़े पैमाने की खेती को अपनाने के बजाय छोटे खेतों में ही विविध प्रकार के सुधारों द्वारा पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न करना उचित है।

भारतवर्ष में बड़े परिमाण को खेतों में बाधाएँ

(Hindrances to Large-Scale Farming in India)

भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर खेती निम्नलिखित कारणों में नहीं की जा सकती :—

१. खेती का छोटा और दूर-दूर स्थित होना
२. भागीय किसानों की निर्धनता
३. उनकी शिक्षा की अभाव
४. उनकी भाग्यवादिता
५. सरकार के प्रदर्शन फार्मों (Demonstration Farms) की अमफलता
६. भारतवर्ष में समानाधिकार कानून का अभाव होता
७. भारतीय कृषि का प्राकृतिक एवं जनसांख्यिक सम्बन्धी कारणों पर पूर्णतया अधिभार होना
८. छोटे पैमाने की खेती के अपेक्षित लाभ
९. भारतीय कृषि व्यापार के लिए नहीं अपितु उदर पूर्ति के लिए की जाती है
१०. कृषि सम्बन्धी प्रयोगों के लिए अपर्याप्त फार्म

छोटे पैमाने की खेती के लाभ

(Advantages of Small-Scale Farming)

१. फसलों का व्यक्तिगत निरीक्षण—छोटे फार्म का तात्पर्य किसान खेतों की विभिन्न विभागों की देख-रेख स्वयं कर अपने लाभ को अधिकतम सीमा पर ले जा सकता है।

२. श्रमिकों के मजदूरी का पूर्णतया अभाव—छोटे पैमाने की खेती में मजदूरों पर रूखे जाने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम होता है। यतः स्वामी और श्रमिक के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

३. फल, फल आदि की खेती के लिये अधिक उपयुक्त—फल, फूल और वे फसलें जिनमें अधिक देख-रेख की आवश्यकता होती है छोटे परिमाण में ही उत्तम की जा सकती हैं।

४. महत्वागता में लाभ—महत्वागता में छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुँच सकता है। भारत के कई देशों में महत्वागता न किसानों की स्थिति में धूर्त काया पसन्द कर दी है।

५. सामाजिक समानता—छोटे पैमाने की खेती के अन्तर्गत सारे भूमि छोटे छोटे भूस्वामियों में बँट जाती है। जिससे ऊँच-नीच का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होने पाता। धन-विनयता की समानता के कारण सभी छोटे-छोटे किसान समृद्ध रहते हैं।

६. राजनैतिक लाभ—सू-स्वामिधा का अधिक सख्या में होना एक बड़ी राजनैतिक शक्ति कही जाती है। सरकार जिस प्रकार चाहे उनका उपयोग कर सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion)—सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से छोटे फार्म अधिक लाभदायक हैं। प्राचीन विद्वानों का मन भी छोटे खेती के पक्ष में ही है। प्लिनी (Pliny) का मन है कि खेत छोटे होने चाहिये। वे कहते थे कि अधिक बोन की अपेक्षा अधिक जलसा लाभप्रद है। पलादीन के अनुसार भी छोटे फार्म को भली प्रकार जोतना और बोना बड़ा फार्म पर बेगार करने की अपेक्षा कही भ्रष्टा है। बड़े पैमाने की खेती अधिक सकल नहीं हो सकती। अमेरिका में भी बहुत बड़े-बड़े फार्मों को छोटा करना पड़ा। निर्माण उद्योग धंधों की अपेक्षा खेती में स्वभावतः बड़े परिमाण की उत्पात्ति का सीमित क्षेत्र है। भारतवर्ष की परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि यहाँ छोटे पैमाने की खेती ही लाभदायक निरूपित हो सकती है। इन परिस्थितियों का उत्तेल उपर किया जा चुका है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर चार्ट्स परीक्षाएँ

१—बड़ी और छोटी मात्रा की उत्पात्ति में क्या अन्तर है ? इन दोनों में, आपसे अनुमान में, कौनसी मात्रावर्ष के लिये उचित है ? (प्र० भा० १९५६)

२—बड़ी मात्रा की उत्पात्ति के लाभ-हानि समझाइय। बड़ी मात्रा की उत्पात्ति किस सीमा तक बढ़ाई जा सकती है ?

३—आंतरिक तथा आम्पातरिक बचत पर नोट लिखिये।

(प्र० भा० १९५३, अ० बो० १९५२, ५०)

४—कहा और क्यों थोड़ा परिमाण का उत्पादन बड़े परिमाण के उत्पादन में लाभदायक है ? भारत में कुछ लघु उद्योगों के जीवित रहने में क्या कारण हैं ?

(प्र० बो० १९५५)

५—बड़ा पैमाने की उत्पात्ति में क्या लाभ हैं ? इन लाभों के उपसर्ग होने पर भी छोटे पैमाने की उत्पात्ति क्यों साथ-साथ चलती रहती है ?

(रा० बो० १९५४)

६—आंतरिक और बाह्य मितव्ययताओं पर टिप्पणी लिखिये।

(प्र० भा० १९५३)

इण्टर एप्रोक्लर परीक्षाएँ

७—बड़े पैमाने के साथ तथा सीमाया का विवेचन कीजिये। (अ० बो० १९५७)

८—बड़े पैमाने के उत्पादन से एक लाभ यह होता है कि प्रति टकाई मूल्य में कमी हो जाती है। इस कथन की व्याख्या करिये।

व्यवसाय संगठन के रूप (Forms of Business Organisation)

पहले यह बतनाया जा चुका है कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में संगठन या व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम यहां पर संगठन के विविध रूपों का निरूपण करते हैं। आजकल व्यवसाय संगठन के कई रूप दृष्टिगोचर होते हैं। जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं —

१. व्यक्तिगत साहस प्रणाली (Single Entrepreneur System)
२. साझेदारी (Partnership)
३. संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियां (Joint Stock Companies)
४. एकाधिकार (Monopolies)
५. गवोग (Combinations)
६. सहकारिता (Co-operation)
७. लाभ विभाजन (Profit Sharing)
८. सरकार द्वारा उत्पादन (State Enterprise)

१. व्यक्तिगत साहस प्रणाली

(Single Entrepreneur System)

इस प्रणाली में अलग-अलग व्यापार या उद्योग का स्वामी और सञ्चालकता एक ही व्यक्ति होता है। अधिक स्पष्ट करते हुए या कहें तो यह माना जाता है कि व्यवसाय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर होता है। वही कच्चा माल खरीदता है, पूंजी का प्रबंध करता है तथा माल की बिक्री की व्यवस्था करता है। इसे व्यक्तिगत स्वामित्व (Individual Proprietorship) अथवा एकल उपाधिक प्रणाली भी कहते हैं। प्रो० हैने (Hance)^१ ने अनुसार व्यक्तिगत साहस प्रणाली व्यावसायिक संगठन का वह रूप है जिसमें प्रत्येक वेजल एक ही व्यक्ति होता है जिस पर सारा उत्तरदायित्व होता है। व्यापार का संचालन करता है और जो व्यापार के अंशक हो जाने की जाति में भी होता है। फुटकर व्यापार, दूरी, डाक्टर, वकील व कुटुम्बोय कर्मों का व्यवसाय, कवि आदि व्यक्तिगत साहस प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं।

^१—Business Organisation and Combination—L. H. Hance, P. 47.



नाम (Advance)

(१) इस प्रणाली में अत्यन्त व्यवसाय सरलता और आश्रयपूर्वक स्थापित किया जा सकता है।

(२) इस प्रणाली में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर होने के कारण यह व्यक्ति तून जो लगा कर कुशलनापूर्वक काम करता है।

(३) एकाकी उत्पादक अपने व्यवसाय का सर्वेसर्वा होता है। अस्तु उसके भाग में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। वह कितना भी बाल का व्यवसाय शोध निगम करके आवश्यक काम कर सकता है।

(४) उत्पत्ति छोट परिमाण में होने में माल अच्छा नकार होता है।

(५) उत्पादन अधिकतर निकटवर्ती उपभोक्ताओं के लिए होता है। अस्तु उत्पादक को उपभोक्ताओं की रुचि आदि जानने का सुविधा होने में अतिरिक्त भाग में भी ठाव अनुमान लगाना जा सकता है जिससे उत्पादक उत्पादन में बाध होने वाली हानियाँ नष्ट होने पाती।

(६) एकाकी उत्पादन व्यवसाय के भेदों (Business Secret) का गुप्त रह सकता है।

(७) इस प्रणाली में हिमाय विभिन्न अधिकतम उत्पादन होता है। अस्तु मुनीय एकाकी व्यवसायों के व्यवसाय में ध्यात करने हो पाती है।

हानियाँ (Disadvantages)

(१) इस प्रकार के व्यवसाय में एकाकी व्यवसाय में अत्यन्त अधिक भाग में प्रतियोगिता में टकराने पड़ने जा सकता है।

(२) एकाकी उत्पादक का अत्यन्त उत्पत्ति अधिक (Unit Cost) होता है। अस्तु सर्वोत्तम व्यवसाय है। यह माहुरा की योग्यता अन्त का प्रवर्धन हो सकता है।

(३) एकाकी उत्पादक को संगठन गति सीमित होता है। वह अपने व्यवसाय में अत्यन्त अधिक अस्थिरता तक बढ़ने नहीं कर सकता।

(४) कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो एकाकी उत्पादक प्रणाली के अनुसार अर्थात् छोटे पैमाने पर सलाह नहीं चलाये जा सकते। जैसे रेल, तार, नहराज आदि के व्यवसाय।

(५) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के लिए यह प्रणाली सबसे अनुपयुक्त है।

२ साझेदारी

(Partnership)

व्यावसायिक मान्यता का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामूहिक तया व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से प्रविष्ट होकर बिना व्यवसाय का संचालन करते हैं। भारतीय साझेदारी विधान सन् १९२० के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है जो किसी व्यापार को मेल मिलकर चलाया उसके ध्यान पर एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित करने के लिये नया लाभ विभाजन के लिये सहमत होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार साझेदारी के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है—(१) साझेदारी एक से अधिक व्यक्तियों के बिना नहीं हो सकती। (२) सम्बन्धित व्यक्तियों का संयोजन व्यापार संचालन के लिए होना चाहिये। (३) उक्त लाभ विभाजन के लिये सहमत होना चाहिये। (४) व्यापार या गोद मेल मिलकर कर अथवा उत्तम से कुछ मूल्य लिये हुए (५) साधारण व्यवसाय में साझेदारी की संख्या २० से अधिक नहीं होना चाहिए और बिना व्यवसाय में वह संख्या १० से अधिक नहीं हो सकती है।

साझेदारी के पारम्परिक सम्बन्ध परिवार वस्तुस्थिति अथवा साझेदार द्वारा प्राप्त ज्ञान आदि वृत्ति तथा लाभ प्राप्ति पर अनुपात प्राप्ति वाले साझेदारी के सम्बन्धों (Partnership Agreement) में निम्नलिखित बातें हैं। यह सम्बन्धों नीतिगत अथवा निम्नलिखित में भी हो सकता है। अधिकतर साझेदारी अनिश्चित दायित्व (Unlimited Liability) के अनुसार ही संचालित होती है। अर्थात् दायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक साझेदार अपना धन के अलावा अपने पसीमिन (Sweat) भी अर्थात् साझेदारी में लगाए गए धन के अतिरिक्त अपनी निजी संपत्ति का कुछ खर्चान में लाई जा सकती है।



1—Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all
—Sec 4 of the Indian Partnership Act 1932

विधान यह नहीं कहता है कि प्रत्येक फर्म को रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से हो। परन्तु रजिस्टर्ड फर्मों का अनिवार्य सामंसेदारी विधान के अनुसार कुछ ऐसे लाभ उपलब्ध होने हैं कि कोई भी फर्म बिना रजिस्टर्ड हुए नहीं रहती।

नाम (Advantages)

(१) मरुक्त पूँजी वाली कम्पनिया की घोषणा सामंसेदारी फर्म का निर्माण कानूनी दृष्टि से अधिक सुगम एवं सरल है।

(२) प्रत्येक सामंसेदार का असंमित दायित्व होने के कारण गृहकी उत्पादक की अपेक्षा सामंसेदारी व्यवसाय का अधिक पूँजी उपलब्ध हो सकता है।

(३) एक से अधिक व्यक्तियों के मालिक द्वारा कार्य सम्पन्न होने के कारण अधिक कार्य कुशलता पाई जाना स्वभाविक है।

(४) मरुक्त पूँजी वाली कम्पनिया के शेयरधारियों (Shareholders) को अपना लाभधारा का नया साझा होने के कारण वे बड़े उत्पादक और बाह्य में काम करते हैं।

(५) सामंसेदारी में कार्य विभाजन एवं विनिष्ठीकरण सम्भव है। व्यवसाय के विभिन्न भाग विभिन्न सामंसेदारों के सुपुर्ण कर व्यवसाय सुचारु रूप से चलाया जा सकता है।

(६) असंमित दायित्व के कारण पूँजी जाखमी व्यवसायों में नहीं लगाई जा सकता। अल्प अधिक साधनो से काम लिया जाता है।

(७) सामंसेदारी में कर्मचारियों और ग्राहकों से निवृत्त संपर्क रखा जाना के कारण व्यापार में वृद्धि होती है।

(८) सामंसेदारी में पर्याप्त शक्ति और लोच (Elasticity) मालिहित है। बहुत ही व्यवसाय तो बिना इसके चलाय ही नहीं जा सकते। प्रा० भार्गव के कथना अनुसार एक विरल हुए व्यवसाय का पुनरुद्धार करने का सबसे सरल उपाय है कि सबसे बड़े कर्मचारियों को सामंसेदार बना लिया जाय।

हानियाँ (Disadvantages)

(१) सामंसेदारी का अस्तित्व अनिश्चित है। यदि किसी कारण से सामंसेदार में भागाद उत्पन्न हो जाय या किसी सामंसेदार की मृत्यु हो जाय या वह पागल हो जाय अथवा दिवाला निकल दे, तो सामंसेदारी टूट जाता है।

(२) असंमित दायित्व के कारण एक साधारण भूल से व्यवसाय का भारी क्षति पहुँच सकती है।

(३) बहुत से व्यक्ति प्रकृत्य व साहस में साथ न लेकर केवल पूँजी ही लगाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिये सामंसेदारी उपयुक्त नहीं है।

(४) सामंसेदारी में बहुमत की प्रधानता होने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के विषय में तुरन्त निर्णय नहीं किया जा सकता।

(4) कोई भी साभदार बिना अग साभदारी की सब सम्पत्ति के अपन हिस्से का हस्तान्तरण नही कर सकता । अस्तु पूजा एंव ही व्यवसाय मे एकी रहत ह ।

(5) यह पमान पर उत्पादन करने के लिय पूजी की कमी रहता ह । मस्त साभदारी बड़े पमाने का उत्पत्ति व वचता से वर्धित रहती है ।

(6) प्रमोमित दायित्व व कारण बहुत से व्यक्ति इसको पसन्द नही करते इस प्रकार इसकी लोकप्रियता सीमित हो जाती है ।

३. गयुक्त पूजी वाली कम्पनिया

(Joint Stock Companies)

यह परिभाषा की उत्पत्ति के निचे साभदारी म ओ अधिक संख्या म व्यक्तिया का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता न सयुक्त पूजी वाली कम्पनिया की जन्म दिया साभदारी साभदार संगठन का यह रूप सबसे अधिक प्रचलित है । क्वाकि इमम साभदारीया (Shareholders) का दायित्व सीमित होता है । सबसे पहल सयुक्त पूजी वाली कम्पनिया का प्रादुर्भाव इंगलंड तथा अन्य यूरोपीय देशो मे हुआ । प्रा० हने (Haney) का अनुसार सयुक्त पूजा वाला कम्पनी साभाजन का दृष्टि से निर्माण की गई व्यक्तिया का एक गणिद्धन संस्था है जिसकी पूजी हस्तांतरणीय अर्था म विभक्त होती है । एय स्वामित्व के लिये सदस्यता आवश्यक है । अधिक स्पष्ट परत हुए सयुक्त पूजी वाली कम्पनी व्यक्तिया का एक समूह है जो साभाजन का दृष्टि म बनाई जाती है और उसकी पूजी इन व्यक्तिया द्वारा गणन अर्था म गणित की जाती है तथा प्रत्येक व्यक्ति एक या अधिक अग या हिस्से (Shares) धरीत सकता है । जो हस्तांतरणीय (Transferable) होते हैं प्रत्येक के किसी व्यक्ति को देप जा सकते है ।

सयुक्त पूजी वाली कम्पनिया की विशेषताएँ

(Characteristics of Joint Stock Companies)

(1) साधुनिन सयोग संस्था म पूजी की आवश्यकता अधिक माना म होती है । एवाकी या साभदारी व्यवस्था म इसकी पूर्ति नही हो सकती है । परम्प कम्पनिया अपन अग या हिस्सा को वचदार सभाोट पूजी प्राप्त कर सकती है । सब कम्पनी के हिस्से धरीतन नाम हिस्सा के मूल्य तक कम्पनी के स्वामी या मालिक समभोजन ह । इस प्रकार कम्पनी एक या दो व्यक्तिया की संस्था न होकर अनन्य व्यक्तिया की संस्था होता है । इसी कारण यह सयुक्त पूजी वाली कम्पनिया कहत ह ।

(2) कम्पनी के प्रत्येक साभदारी या हिस्सेदार (Shareholder) का सीमित दायित्व (Limited Liability) होता है अर्थात् कम्पनी के प्रति उसका दायित्व विनन उमा पाग अग है उनके मूल मूल्य (Face Value) म ही सीमित होता है । यह अग या साभ मूल्य उसने चुना लिया है ना उग पर किसी प्रकार का दायित्व नही रहता है । उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति न किसी कम्पनी पूजी या 10 पना व सो भी अपने व चार अग धरीत अग कम्पनी न प्रत्येक का अग साभा मूल्य हा वसूत किया है ना उसका दायित्व बचत दा भी अपना लव हा सीमित होगा । यदि कम्पनी न चारा अग का कुल मूल्य अर्थात् चारों अग का समूल पर

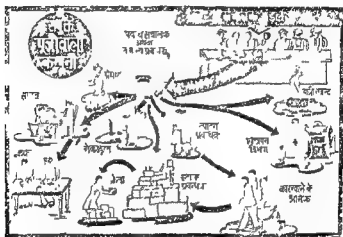
निया है तो उसका दायित्व कम्पनी के प्रति कुछ भी नहीं होगा। सीमित दायित्व के कारण ही यह व्यवस्था अधिक प्रचलित एवं सार्वव्यापी है।

(३) कम्पनियाँ केवल हस्तांतरणीय होने के कारण उनका मूल विषय मरना तथा सुगमता में ही अवता है।

(४) कम्पनी का संचालन लोकतान्त्रिक (Democratic) होता है।

(५) सीमित दायित्व वाला कम्पनी के नाम के अन्त में सीमित या लिमिटेड शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

(६) संयुक्त पूजा वाली कम्पनी की पूजा छाने छाने लिंगा या धरा में विभक्त होने के कारण गोपनीय आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति भी यदि चाहें तो वह 'परी' सकता है।



संयुक्त पूजा वाली कम्पनी का निर्माण—एक संयुक्त पूजा वाली कम्पनी का प्रकार बना जाना है। सबसे पहले साहस (Enterpriser) के व्यक्ति में व्यवसाय या व्यापार का साधना जानी है। ऐसे पचास बत ६ पाय व्यक्तियों का सम्मेलन प्राप्त कर कुछ ७ व्यक्तियों से (या कम) जिस आवश्यक मूलभूत धन है। यह भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के पास की व्यवस्था करता है। यह कम्पनी का स्मारक-पत्र (Memorandum of Association) बनाते हैं जिसमें कम्पनी का नाम उसका प्रधान कार्यालय तथा कम्पनी की अधिकृत पूजा (Authorized Capital) और उसका धरा (Shares) में विभाजित आर्थिक दायित्व की घोषणा पादि बातों का उल्लेख होता है। स्मारक-पत्र के साथ-साथ कम्पनी के अन्तर्नियम (Articles of Association) भी जिसमें कम्पनी के भीतर शासन चालित करने में सम्बन्धित नियम होते हैं पारित किया जाता है। जब रजिस्ट्रार यह देखता है कि कम्पनीक हित से सब आवश्यक पूर्ण हो गया है तो वह एक समागमन-पत्र (Certificate of Incorporation) प्रदान कर देता है। जिसके द्वारा कम्पनी स्थापित हो जाती है।

निये विवरण-पत्रिका (Prospectus) निकालना पड़ता है। जब तक न्यूनतम पूँजी एकत्रित न हो जाय तब तक ये प्रयोजन व्यापार आरम्भ नहीं कर सकती।

अलोक-सीमित कम्पनियाँ (Private Limited Companies)—
इस प्रकार की कम्पनियाँ पर विवरण-पत्रिका आदि प्रेषण का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। ये विवरण-पत्रिका नहीं निकाल सकती। इनके अध्यापारियों की अधिकतम संख्या ५० से अधिक नहीं हो सकती।

समुक्त पूँजी वाली कम्पनी और साझेदारी की पारस्परिक तुलना

१. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अध्यापारियों (Shareholders) की संख्या ७ और अधिकतम संख्या प्रयोजित होती है। साझेदारी में न्यूनतम संख्या २ और अधिकतम २० है परन्तु वस्तु-व्यवस्था में यह १० तक ही सीमित है।

२. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अध्यापारी सारे देण्डों में और कभी-कभी समार में भी हिस्सा हूँते हैं। अर्थात्, उनमें मध्य निष्पत्ति सम्भव नहीं होता। इसके विपरीत साझेदारी में साझेदारों की संख्या साधारण होती है अतः उनके बीच में सम्बन्ध घनिष्ठ एवं अविविच्छिन्न रहना स्वाभाविक है।

३. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी के आर्थिक साधन प्रसीमित होते हैं, परन्तु साझेदारी में ये परिमित होते हैं।

४. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अध्यापारियों का दायित्व सीमित होता है, परन्तु साझेदारी में यह प्रसीमित होता है।

५. समुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ में व्यवसाय का पैमाना बड़ा होता है परन्तु साझेदारी में व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है।

६. साझेदारी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह रजिस्टर्ड हो, परन्तु समुक्त पूँजी वाली कम्पनी में स्थिर रजिस्टर्ड होना परमावश्यक है।

७. समुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ में वेतनभोगी प्रबन्धक (Salaried Manager) रखा जाता है, परन्तु साझेदारी में यह आवश्यक नहीं है।

८. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी अस्तित्व में होता है। अर्थात् वह अभिभाग बना सकता है तथा इस पर भी अभिभाग बनाया जा सकता है। परन्तु साझेदारी में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार का अस्तित्व बड़ा होने के कारण वह न तो किसी पर अभिभाग बना सकती है और न ही दूसरा इस पर बना सकता है, अर्थात् साझेदार व्यक्तिगत रूप में अभिभाग बना सकता है तथा इस पर भी इसी हेतु मध्यम बन सकता है कि पर्याप्त काम में।

९. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी का अस्तित्व स्थायी होता है, परन्तु साझेदारी का अस्तित्व अस्थायी एवं अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस साझेदार की मृत्यु होना पर अथवा उसके पामन या दिवंगति का होना पर साझेदारी समाप्त हो जाती है।

१०. साझेदारी में प्रत्येक साझेदार व्यवसाय या व्यापार का वास्तविक स्वामी होता है परन्तु एक समुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अध्यापारी केवल नाममात्र का स्वामी होता है क्योंकि वास्तव में सारा कार्य संचालन करने हैं।

११. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अध्यापारी अपने अपने सुगमता में हस्तान्तरित कर सकते हैं, परन्तु साझेदारी में बिना साझेदार के अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता।

१२. साभेदारों ने धार्मिक अधिकार आपन की अनुमति पर निर्भर होते हैं, परन्तु एक समुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अधिकार बिना कम्पनी की स्वीकृति के नहीं बदले जा सकते ।

१३. समुक्त पूँजी वाली कम्पनी ने हिमाव-विचार की जायिज जान (Audit) बिनी राज्य प्रमाणित ऑडिटर द्वारा होना अनिवार्य है, परन्तु साभेदारी में यह आवश्यक नहीं है ।

समुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के लाभ (Advantages)

(१) समुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ ने द्वारा ही व्यवसाय बड़े पैमाने पर सम्भव है । इनमें श्रम-विभारत्र, विशिष्टीकरण एवं मशीनों के उपयोग के प्रोत्साहन मिलने के अनिरिक्त विशेषज्ञों की सेवाये भी सरलता में प्राप्त हो जाती हैं ।

(२) कम्पनी की पूँजी बड़ा में विभक्त हो जाने में तथा सीमित दायित्व के निदान के कारण बहुत बड़ी पूँजी वाले व्यक्ति आ कम्पनी पूँजी इन कम्पनियों में लगा देने हैं । इस प्रकार बहुत रुपया एकत्रित हो जाता है और सक्षम-श्रुति को पदात प्रोत्साहन मिलता है ।

(३) इनके माली (Shares) का सरलता में श्रव-विक्रय हो सकता है, क्योंकि ये हस्तांतरणीय होते हैं ।

(४) सीमित दायित्व (Limited Liability) होने के कारण पूँजी की कोई कठिनाई नहीं होती ।

(५) कम्पनी साभेदारी और एकाकी उत्पादक प्रणाली को प्रपेक्षा अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसका अपना पृथक् कानूनी अस्तित्व होता है ।

(६) बहुत में बड़े व्यवसाय जैसे रेल, जहाज निर्माण आदि बिना समुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के सफल नहीं हो सकते ।

(७) व्यवसाय बड़े पैमाने पर होने के कारण बड़े पैमाने की उत्पाति के समस्त लाभ कम्पनी को उपलब्ध होते हैं ।

(८) कम्पनी की नामन-व्यवस्था में पराप्त वचन होती है क्योंकि मालिकों को वेतन नहीं दिया जाता है । उन्हें केवल अधिकेशन की उपस्थिति की फीस ही प्रति दिवस के हिसाब में मिलती है ।

(९) कम्पनियों का शासन लोकन्यायिक होता है, क्योंकि मालिकों या चुनाव साधारण अधिकेशन में अधधारियों द्वारा होता है । मालिकों का कार्य अमरतोप जनक होने पर अधधारियों द्वारा ये हटाये भी जा सकते हैं ।

(१०) कम्पनियों के कार्य-रावानन पर सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण होने के कारण अधधारियों के हित सुरक्षित रहते हैं ।

(११) विविध कम्पनियों के माल सरीद कर निविगमन (Investor) अपनी नातिम का एक स्थान पर सीमित न रखकर फैला देता है ।

(१२) इस प्रणाली के अन्तर्गत पूँजीपति और सहस्रो श्रम-असम हो जाने से उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है ।

(१३) सीमित दायित्व के कारण कम्पनी नवनये औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य आरम्भ कर सकती है । इस प्रकार देश का औद्योगिक विकास हो सनता है ।

हानियाँ (Disadvantages)

(१) सीमित दायित्व के कारण हम ऐसे योजनाएँ अपना ही जानी हैं जिनमें लाभ की प्रतीक्षा नहीं हो सकती है।

(२) हमारे जहाँ-जहाँ के कारण हमारी कम्पनी के काम में बाधा पड़ती है।

(३) कई बार हमारे कार्यालयों के कारण कम्पनी की व्यवस्था और निर्माण में बाधा पड़ती है।

(४) हमारे कार्यालयों के कारण कम्पनी के प्रारम्भ में संचालन में बाधा पड़ती है और बाद में भी अधिक मालिकों की प्रतीक्षा (proxies) प्राप्त कर संचालन में बाधा पड़ती है।

(५) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों का निर्माण होता है।

(६) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

(७) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

(८) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

(९) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

(१०) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

(११) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

(१२) हमारे कार्यालयों के कारण हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

कम्पनियों के निर्माण—संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों में हानियाँ पड़ती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था व्यवस्था बनाने में बाधा पड़ती है। न केवल हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है, बल्कि हमारे कार्यालयों के संचालन में बाधा पड़ती है।

८ एकाधिकार

(Monopolies)

साधारणतया एकाधिकार का अर्थ है प्रतियोगिता (Competition) का अभाव। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का अधिकार हो जाता है तो उसका यह अधिकार एकाधिकार कहलाता है। उदाहरण

के नियम, दालघर सम्बन्धी सेवा सेवाया का एकाधिकार केन्द्रीय सरकार का है। इसी प्रकार जल पूर्ति (Water Supply) का एकाधिकार प्रायः नगर की म्यूनिसिपैलिटी को ही होता है। किसी निम्नतर स्तर पर जैसे बिजली नाम आदि जनसाधारण उपयोगिता सम्बन्धी कार्यों का एकाधिकार या सेवा किसी एक व्यक्ति या दिया जाता है। भारत में ये नियम आधिकारिक रूप से लागू नहीं किये जाते हैं।

एकाधिकारों के प्रकार—एकाधिकार मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं।

(१) कानूनी एकाधिकार (Legal Monopoly)—जब एक एकाधिकार है जो कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। जैसे दालघर, स्टेट गैस आदि।

(२) प्राकृतिक एकाधिकार (Natural Monopoly)—जब एकाधिकार किसी प्राकृतिक वस्तु के एक स्थान पर प्राप्त होने या उचित रूप में काम चलाने के कारण स्थापित हो जाता है। जैसे ही दालघर में बालों का एकाधिकार।

(३) सामाजिक एकाधिकार (Social Monopoly)—जिस एकाधिकार की उत्पत्ति सामाजिक हितों में आती है उसे सामाजिक एकाधिकार कहते हैं। जैसे—विद्युत, पानी आदि का एकाधिकार।

(४) एकाधिकार एकाधिकार (Natural Monopoly)—जब एक व्यवसाय में मजदूर हो या हो न अद्वितीय प्रत्येक व्यक्ति एक एकाधिकार प्राप्त करता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। यद्यपि यह दालघर और मजदूरों के दालघर को उदाहरण है। भारत की American Chemical Company (A.C.C.) भी इसी के अन्तर्गत है।

(५) स्थानीय एकाधिकार (Local Monopoly)—जब एकाधिकार एक स्थान पर ही सीमित हो तो उसे स्थानीय एकाधिकार कहते हैं। जैसे किसी स्थानीय बोर्डिंग में बालों का एकाधिकार प्राप्त हो।

(६) राष्ट्रीय एकाधिकार (National Monopoly)—जब एकाधिकार किसी देश तक ही सीमित हो तो उसे राष्ट्रीय एकाधिकार कहते हैं। यदि एक देश में एक ही देश में लागू है तो उसे राष्ट्रीय एकाधिकार कहते हैं।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार (International Monopoly)—जब एकाधिकार का क्षेत्र कई देशों में फैला हुआ हो, तो वह अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार कहता है। जैसे दालघर की स्टैंडर्ड आइज कंपनी।

दो प्रकार के दालघर एकाधिकार (Public and Private Monopoly) और अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार (Quasi Public Monopoly) भी होते हैं।

एकाधिकार के लाभ (Advantages of Monopoly)

(१) एकाधिकार में उत्पादन मात्र (Demand) के अनुसार होने से अत्यधिक उत्पादन का भय नहीं रहता है।

(२) एकाधिकार में प्रतियोगिता के अभाव के कारण लाभ निश्चित रहता है।

(३) एकाधिकार बड़े परिमाण की उत्पत्ति द्वारा होने वाली सब प्रकार की बचतों का लाभ उठाता है।

विविध वस्तुओं बनाकर भिन्न भिन्न गण्टिया में बिक्री के लिये भेज दी जाती है। अमेरिका की United States Steel Corporation भी इसी प्रकार की है।

(२) क्षैतिज संयोग (Horizontal Combination)—जब एक ही व्यवसाय में सलग्न कई कम्पनियाँ परस्पर मिलकर गण स्थापित कर लेती है, तो वह क्षैतिज संयोग कहा जाता है। अमेरिका की Standard Oil Company और Sugar Refining Company इसी कोटि में आती है।

क्षैतिज संयोग के भेद—क्षैतिज संयोग के कई तरह के भेद हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

(अ) ट्रस्ट (Trusts)—इसमें सम्मिलित कम्पनियाँ के व्यक्तिगत प्रतिस्व का प्रस्त होकर एक नवीन कम्पनी की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार एकीकरण (Amalgamation) के द्वारा घनेबना के स्थान पर गठना स्थापित हो जाती है। इस प्रकार का एकीकरण मनुष्य राज्य अमेरिका में अधिक प्रचलित है। जैसे स्टैंडर्ड ओइल ट्रस्ट, स्टील ट्रस्ट इत्यादि।

(आ) कार्टेल (Cartel)—इस प्रकार की संघबद्धी ट्रस्ट में निबल होती है। इनमें सम्मिलित कम्पनियाँ के व्यक्तिगत प्रतिस्व का अन्त नहीं होता। इसका सघ में सम्मिलित होने का उद्देश्य केवल मुख्य और उत्पादन तक ही सीमित रहता है। कार्टेल को सिण्डिकेट (Syndicate) भी कहते हैं। इसका प्रकार विशेषतया जर्मनी में पाया जाता है।

(इ) धारणी कम्पनी (Holding Company)—जब एक कम्पनी दूसरी को अपने नियन्त्रण में लाने के उद्देश्य में उसके अधिकांश अंश खरीद लेती है, तो वह धारणी कम्पनी कहलाती है। नियन्त्रित (Controlled) कम्पनियाँ सहायक (Subsidiary) कम्पनियाँ कहलाती हैं। एक धारणी कम्पनी कई सहायक कम्पनियों की नीति (Policy) और उत्पादन (Production) का नियन्त्रण कर सकती है।

अन्य प्रकार के अस्थायी संघ—कभी कभी उत्पादक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य को गिरने में बचाने के लिये अस्थायी संगठन स्थापित कर लेते हैं जो कोप (Pool), संयोजन (Monger), वलय या रिंग (Ring), वार्नर (Corner) और भले आदमियों का समझौता (Gentleman's Agreement) इत्यादि कहलाते हैं।

संयोग के लाभ (Advantages of Combinations)

(१) इन संगठनों द्वारा बड़े परिमाण की उत्पात्ति के समस्त लाभ उपलब्ध होने से उत्पत्ति-व्यय में कमी का आ सकता है।

(२) इनमें निरन्तर उत्पादन (Continuous Production) अधिक निश्चित है।

(३) वे मन्त्रों की कठिनाइयाँ का सरलता से सामना कर सकते हैं।

(४) प्रतिस्पर्धा का अभाव होने से विज्ञापन आदि पर होने वाले व्यय में पर्याप्त बचत हो जाती है।

(५) इन संघों द्वारा प्रयोग (Experiments) और अन्वेषण (Research) आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

लिपेता और निर्वेता में भाग स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास, वचन तथा विनियोग के तत्त्वों का प्रसार होना है ।

सहकारिता के मुख्य रूप (forms of Co operation)—सहकारिता के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं—

- (१) उत्पादकता का सहकारिता (Producers Co operation)
- (२) वितरण या उपभोक्ताओं का सहकारिता (Distributive or Consumers Co operation)
- (३) ऋण सहकारिता (Credit Co operation)
- (४) उत्पादकता की सहकारिता (Producers Co-operation) — इसमें प्रत्यक्ष उत्पादक सहकारी समितियाँ (Producers Co-operative Societies) स्थापित की जाती हैं । ये समितियाँ सदस्यों के विश्व उद्दिष्ट मूल्य पर आवास्यता तथा मान आजाद तथा पूजा का प्रदर्शन करती हैं । उत्पादित वस्तुओं का बर्गोदरता का उच्च प्रदर्शन तथा परीक्षा और न केवल मूल्य का बर्ग दिया जाता है । इस प्रकार का समितियाँ ज्ञान तथा समारंभ में अधिक प्रचारित हैं ।

नाम । (Advantages) — (१) अधिक स्वयं ही अपने व्यवसाय के स्वामी बनते हैं । अपने में अधिक विश्वास तथा लक्ष्य में काम करते हैं । निराले उत्पादन का क्षमता में वृद्धि होती है । (२) उत्पादकता में साधनात्मक संघर्ष का प्रभाव नहीं होता रहता । यदि सभी वस्तुओं की मूल्य में भी प्रचार की जाती है । (३) प्रोत्साहन परीक्षात्मकता प्रायः जीवित या अधिकता के कारण प्रत्यक्ष अधिकृत होता है । (४) समिति सदस्य अधिक एक स्वामी बना हुआ है । यह उन्हें प्रेरित करता है ।

घटिनाइयाँ (Difficulties) — अधिकतर ये समस्याएँ प्रसरण रही हैं । इनके कारण हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं —

- (१) प्रोत्साहन परीक्षात्मकता के कारण कुछ प्रयत्न बढ़ा रहे हैं । (२) अधिक निराशा का तथा प्रवृत्ति का रूप में अनुचित हस्तक्षेप करने हैं । (३) अधिकता में अनुमानित तथा उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है । (४) परस्पर भयानकता का कारण होता है ।

उपाय (Remedies) — इसमें सन्देह नहीं कि उत्पादकता की सहकारिता प्रामाण्य तथा परीक्षात्मकता नहीं है, परन्तु निम्न प्रकार शक्ति का साधना मशीन का विकास मशीनों की बलवान् भावना प्रायः निम्न उपायों के द्वारा इनमें परीक्षात्मकता का प्रसारण है ।

- (१) वितरण या उपभोक्ताओं की सहकारिता (Distributive or Consumers Co operation) — इसमें अल्पतरु उपभोक्ताओं द्वारा सहकारिता समितियाँ अथवा मण्डल (Consumers Co-operative Societies or Stores) स्थापित किए जाते हैं । इन मण्डलों के स्वामी तथा उपभोक्ताओं के ही व्यक्ति होते हैं । ये मण्डल उपभोक्ताओं की दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बेचते हैं और आसानी से वह सदस्यों में उनसे क्रय के अनुपात में बांट दिया जाता है । एसी कई समितियाँ मिलकर एक बड़ा सहकारी समिति (Wholesale Co-operative

की व्यवस्थाया में उत्पत्ति काय प्राद्वेष्ट न्यक्तिया तथा कम्पनियों के हाथ में होता है । परन्तु तीसरी व्यवस्था में समस्त उत्पत्ति कार्य केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय सरकार के हाथ में होता है । उदाहरण के लिये, भारतवर्ष में शक्, तार, रेल, सिनार्ड जल-विद्युत् आदि की व्यवस्था स्वयं सरकार करती है । इनके अतिरिक्त गैर, निजसी, पानी, ट्राम आदि की व्यवस्था कई जगह म्युनिमिपल बोर्डों द्वारा की जाती है ।

समाजवादी (Socialists) चाहते हैं कि देश का समस्त उत्पादन-कार्य सरकार द्वारा ही हो जिससे मारत लाभ मुद्धी भर लोगो के हाथ में आकर सारी जनता में बँट सके । इसीलिये आन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Industries) की भाषाज उपर उठो हुई है । आनवल कई पूँजीवादी देशों में भी यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि कम से कम आघारोद्योगों (Key Industries) पर तो राज्य का स्वामित्व एव सभासन होना चाहिये और अन्य उद्योगों पर भी सरकार का उचित नियन्त्रण होना चाहिये । इङ्गलैंड में थम सरकार पर्याप्त सेक्टर गवर्नमेण्ट के क्षामन काल में राज्य का स्वामित्व एव नियन्त्रण सनिज, यातायात, बैंकिंग आदि प्रवसाथों पर विस्तृत किया गया ।

लाभ (Advantages) (१) समान की यज्ञ लाभ है, क्योंकि लाभ सरकार द्वारा जनता में बँट जाता है । (२) वस्तुओं की किस्म की गारण्टी रहती है । (३) सरकार के पास पूँजी आदि साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं । (४) सभी सरकारी मीसरी चाहते हैं अत उत्तम में उत्तम कार्य प्रवीण एव कुशल कर्मचारी व थमिक रहे जा सकते हैं । (५) सरकारी उत्पादन प्रथि नोन-नियन्त्रण योग्य है । (६) सरकार लाभ प्राप्ति के लिये पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा कर सकती है, परन्तु प्राद्वेष्ट उत्पादक नहीं कर सकते हैं । (७) उपभोक्ताओं के हितों को उचित रूप में रक्षा की जा सकती है ।

हानियाँ (Disadvantages) — (१) मीकरणही एव कठोर शासन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सारी वागडोर सरकारी कर्मचारियों के हाथों में होती है । कभी-कभी छोटे कर्मचारी सम्य नागरिकों के साथ अशिष्टता का व्यवहार कर बैठते हैं । (२) सरकारी कर्मचारी उत्पत्ति एव लाभ वृद्धि में अधिक रसि नहीं रखते क्योंकि उनकी तत्काली तो पद और मीकरी के कार्य कास (Seniority) के अनुसार होती रहती है । उन्हें हानि-लाभ से क्या सम्बन्ध ? (३) अपभय और अनुसलता पर बहुत कम नियन्त्रण होता है । (४) सरकारी कर्मचारियों का शीघ्र स्थानान्तरण (Transfer) सपसता में बाधक सिद्ध होते हैं । (५) सरकारी काम एव प्रकार से रीत्यक (Routine) के रूप में होगा है, इसमें मीलिकता का प्रभाव होता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों पर नोट लिखिये ।

२—सहकारी उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।

३—सामिदारी पर टिप्पणी लिखिये ।

४—व्यवसाय संगठन के मुख्य-मुख्य स्वरूपों का वर्णन कीजिये । इनके गुण-दोषों को संक्षेप में वर्णन कीजिये ।

(सागर १९४९)

५—सीमित दायित्व वाली कम्पनी पर टिप्पणी लिखिये ।

(म० आ० १९४१, म० बी० १९४१, ४८)

साहस का अर्थ (Meaning)

औद्योगिक विराम के प्रारम्भिक काल में उत्पादन प्रणाली सरल एवं आधारणीय थी। उपनि के पमाना छोटा था और आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतर प्रत्यक्ष रूप में ही होती थी। कालान्तर में समाज की उन्नति के साथ-साथ उत्पादन प्रणाली जटिल होती गई। उत्पत्ति के पैमाने में वृद्धि हुई व्यवसाय का आकार प्रकार बढ़ा। धन विभाजन व मशीन का प्रयोग अधिकारिध्वं मात्रा में होने लगा और दानापान व सम्वाद के साधना में प्राणातीत उन्नति हुई। इन सबके फलस्वरूप प्रवच की कठिनाइयाँ उत्पन्न बनीं कि उत्पत्ति काय संगठनकर्ता की शक्ति के बाहर हो गया। व्यापार की जातिम अथवा अति चतना में वृद्धि हुई जिसको सहन किये बिना उत्पत्ति सम्भव हो गई। इस प्रकार साहस के रूप उत्पत्ति के पञ्चव साधन का प्रादुर्भाव हुआ। अध्याय में इन जातिम अथवा अतिचिन्तना को साहस कहते हैं और जो व्यवसाय की जातिम उठाता है वह साहसा (Entrepreneur) कहनाता है।

साहस की आवश्यकता तथा महत्व (Necessity & Importance) — प्राकृतिक उत्पत्ति प्रणाली घड़ी जटिल है। वचन स्थानीय व स्थान पटनामा में ही रहा वरिष्ठ कई अनगणनीय वाना में भी यह प्रभावित वाली रहनी है। आजकल उत्पादन वचन स्थानीय माँग का पूर्ति के लिये ही नहीं किया जाता है बरिष्ठ दूर गंगा की आवश्यकतामा का पूर्ति के लिये भी प्राकृतिक औद्योगिक प्रणाली के अनमार पहन वस्तु की माँग का अनमान लगाया जाता है और उमक आधार पर उत्पादन काय प्रारम्भ किया जाता है। इन प्रकार निर्माता वस्तु बनाकर बाजार में लाने के लिये पयात् समय से नता है। इस बीच में सम्भव है कि उपभातामा की रुचि में परिवर्तन हो जाय पैमाने बदल जाय अथवा उपभाता की माय में अनर या जाय जिस फलस्वरूप वस्तु के श्रावक न मित। यह भी सम्भव है कि वस्तु जब बाजार में लाय जाय तो उपभाता का पसन्द न आय और माय का अनमान ठीक न मितन पर अधिक उत्पादन (Over production) हो जाय। इन सब दशामा में निर्माता का लाभ के स्थान में हानि होना स्वाभाविक है। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पत्ति के साधना में में कौनसा साधन इस जातिम को उठान के लिये तैयार है। भूमि, धन पूँजी और व्यवस्था तो अपना अपना पारिधमिक करर अदय हो जाने हैं, इन्हें व्यवसाय की हानि में कोई सम्बन्ध नहीं। अब रहा साहस जो निर्माण योजना करना है उत्पत्ति काय का संचालन करता है उत्पत्ति के साधना का यथैव मयों में एकत्रित करना है और उत्पत्ति में सम्बद्ध सभी

जोसिम को यपन सबब कथा पर रखता है। इन सब जोसिमो को उठाना साहसी का काम है बिना इसके उत्पादन बिल्कुल सम्भव नहीं है। अस्तु, आधुनिक उत्पादन-प्रणाली में इसका अत्यधिक महत्व है। यह भावश्यक नहीं है कि साहसी मदैव ही कोई पृथक् व्यक्ति हो। ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही व्यक्ति स्वयं पूँजीपति प्रबन्धक तथा साहसी भी होता है। ऐसा प्रायः छोटे व्यवसायों में होता है।

प्रो० कारवर (Carver) के मतानुसार साहसी की सेवाएँ ऐसी नहीं हैं कि एक बेतनभोगी प्रबन्धक सम्पन्न कर सके। औद्योगिक संगठन में इसका महत्त्व उतना ही बड़ा है जितना कि सेवा में सनापति का अथवा मनिमन्डल में प्रधान मंत्री का। कुछ नैसर्ग साहसी की तनवा एक युद्ध-अग्नी से करने = जिसको बाहर के शत्रु का सामना करने की अवस्था के अनिश्चित छुड़रता का भयान रचना पड़ता है। साहसी पर उत्पत्ति की धमना ही नहीं बरन् देश का सम्पूर्ण औद्योगिक विकास भी निर्भर होता है। अस्तु किनो देश में जितने अधिक बचन साहसी हूँ उतना ही उन्नयन उस देश का प्राथम्य भविष्य होगा।

संगठनकर्त्ता या प्रबन्धक और साहसी (Organizer & Entrepreneur)—एक साहसी और प्रबन्धक में मुख्य भन्तर यह है कि प्रबन्धक या संगठनकर्त्ता तो उत्पादन के नियम विधि उत्पत्ति के माधना को यष्टेष्ट माया में एकपित करता है, परन्तु साहसी व्यवसाय की ओलिम अथवा अनिश्चितता से सङ्गन करता है। व्यवसाय के हानि लाभ का उत्तरदायित्व साहसी पर होता है और वही व्यवसाय की मोति संचालन करता है। संगठन या प्रबन्धक सम्बन्धी प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने का काम प्रबन्धक या संगठनकर्त्ता का है। संगठनकर्त्ता या प्रबन्धक को निश्चित वेतन मिलता है। परन्तु साहसी का पारिभ्रमिक पर्याप्त लाभ होगा पर निर्भर होता है। हानि होने की अवस्था में वह उसमें भी बचित रहता है, परन्तु वेतन भोगी प्रबन्धक इस जोलिम में मुक्त रहता है। जोलिम उठाने का कार्य एक व्यक्ति के स्थान में व्यक्तियों के समूह या समुदाय द्वारा भी हो सकता है। उदाहरणार्थ सहकारी उत्पादन प्रणाली में जोलिम सहकारी समिति द्वारा उठाना जाता है। यह भावश्यक नहीं है कि प्रबन्धक और साहसी पृथक्-पृथक् हों। दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं। यह व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर है।

पूँजीपति और साहसी (Capitalist and Entrepreneur)—साहसी और पूँजीपति य उत्पत्ति के दो पृथक् पृथक् साधन हैं। यह हो सकता है कि कभी कभी पूँजीपति साहसी का तथा अन्य कार्य भी करने लग जाता है। जैने, एक भूपक बहुधा श्रमिक पूँजीपति प्रबन्धक एवं साहसी स्वयं ही होता है। इनका यह प्रप नहीं है कि इन दोनों में कोई अन्तर ही नहीं है। पूँजीपति मदैव ध्याज के लिये पूँजी उधार देता है। इसकी ध्याज की दर निश्चित होती है। इनका व्यवसाय के हानि-लाभ में कोई सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु साहसी का कोई निश्चित पारिभ्रमिक (Remuneration) नहीं होता है। यदि उसको माँग का अनुमान ठीक निकलता है, तो उसे लाभ होता है और उसके गनत निष्ठ होने पर उसे हानि उठानी पड़ती है। मसार के प्रगतिशाल देशों में यह होगा बाप धिअर अन्तिम अन्तिमों द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे ?

उत्पत्ति के अन्य साधन और साहसी

(Other factors of Production & Entrepreneur)

उत्पत्ति के अन्य साधन और साहसी में एक महत्वपूर्ण भन्तर है। पूँजीपति, श्रमिक, पूँजीपति और प्रबन्धक का परिभ्रमिक निश्चित होता है, परन्तु साहसी का कोई

निश्चित पारिथमिक नही होता। उसको नाम भी हो सकता है अथवा हानि भी। उसका पारिथमिक प्रायः उसका व्यापारिक दक्षता एवं दैवी कारुण्य पर अवलम्बित होता है।

साहसी के कर्तव्य (Functions of Entrepreneur)

साहसी व कार्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है —

१. शासनात्मक कार्य (Administrative Functions)
२. वितरणात्मक कार्य (Distributive Functions)
३. जातिम उठाने का कार्य (Risk taking Functions)
४. शासनात्मक कार्य (Administrative Functions) —

(१) व्यवसाय की योजना बनाना—साहसी व्यवसाय विवेक की योजना बनाता है। वह इस बात का विचार करता है कि कौन सा वस्तु कहाँ किस प्रकार बिक्री होना चाहिए और क्यों।

(२) उत्पत्ति की इकाई का आकार निर्धारित करना—साहसी यह भी विचार करता है कि उत्पत्ति का पैमाना क्या होना चाहिए।

(३) श्रमिक बचचे मान आदि के बारे में निर्णय करना—साहसी को इस बात का भी विचार करना पड़ता है कि किस किस प्रकार के श्रमिक नयाय आवश्यक होंगे तथा किस प्रकार का बचचे मान और मजदूरी प्रदान की जाएगी।

(४) प्रतिस्थापन नियम का उपयोग करना—यह प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) व अनुसार उत्पत्ति के विविध माध्यमों को ऐसी सर्वाधिक अनुपात में विभाजन का प्रयत्न करता है जिससे उसे 'युक्ततम' योगदान में अधिकतम लाभ हो सके।

(५) समूह व्यवस्था—युक्त वय एवं संगठन का कार्य भी साहसी स्वयं ही सम्पन्न करता है। परन्तु अब अत्युक्त पूँजी प्रणाली (Joint Stock System) के प्रचार में संगठन कार्य संगठनीय (Salaried) व्यवस्था द्वारा सम्पन्न होना लगा है।

(६) निर्मित वस्तुओं के विक्रय का प्रयत्न करना—यद्यपि यह कार्य व्यवस्था के क्षेत्र में सम्पन्न होता है परन्तु इस सम्बन्ध में साहसी का भी उत्तम हो उत्तमदायक माना जाता है।

(७) उत्पत्ति के तरीके ढूँढना की आज्ञा करना—साहसी उत्पत्ति के तरीके ढूँढना की आज्ञा करता रहता है तथा आवरण-कार्य कर उत्पत्ति के क्षेत्र में योगदान का कार्य करता है।

(८) विभाजन की व्यवस्था करना—निर्मित वस्तुओं के उत्पत्ति गति में विभाजन करने की व्यवस्था करना साहसी का कार्य है क्योंकि इसमें वस्तुओं की विपरीत में बड़ा महापता मिलती है।

(९) राज्य तथा जनता के प्रति उपयुक्त नाति का निर्णय करना—साहसी का बस उपमानावस्था व्यवस्थाओं में ही सम्पन्न होना पड़ता है कि वह उन सरकार एवं जनता से भी सम्पन्न होना चाहता है अन्य उत्तम सम्पन्न में भी नीति का निर्णय करना होता है।

(१०) प्रतिद्वन्द्विया के प्रति नीति निर्धारित करना—प्रतिद्वन्द्विया (Rivals) के प्रति धपनाई जाने वाली नीति का निर्धारित करना भी साहसी का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है क्योंकि इस पर व्यवसाय की बहुत कुछ मफलता अवलम्बित होता है।

(११) व्यवसाय पर नियन्त्रण रखना यद्यपि यह कार्य उभय महायक अथवा प्रवचक द्वारा सम्पन्न किया जाता है, परन्तु अनिम नियन्त्रण साहसी के हाथ में होता है।

२ वितरणात्मक कार्य (Distributive Functions)—चाहे व्यवसाय में हानि हो अथवा लाभ उत्पत्ति के साधना को पारिथमिकता निश्चिन्त रूप से मिलता ही है। इनका नाम हानि या कोई सम्पत्ति नहीं होना। अस्तु उत्पत्ति के साधना को पारिथमिक वितरण करना साहसी का एक मुख्य कार्य है।

३ जोखिम उठाने का कार्य (Risk taking Function) साहसी के जोखिम उठाने का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है। व्यवसाय में एक प्रकार की अनिश्चितता विद्यमान होती है बिना अनुमान ठीक प्रकार तयारा नहीं जा सकता। अस्तु इस अनिश्चितता को सहन करना साहसी का कार्य है।

प्रो० बेंनहम (Benham) के अनुसार एक साहसी का निम्नलिखित प्रश्नों पर नियंत्रण करना चाहिये—

(१) उसको किस उद्योग में प्रवेश करना है?—इस प्रश्न का सम्बन्ध वस्तु समूह से है जैसे वस्त्र वस्त्र या मशीनरी आदि।

(२) वह किस प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उत्पत्ति करेगा?—इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रत्येक समूह के अन्तर्गत प्रात यात्री विविष्ट वस्तुओं से है जैसा कि मध्यम भी किस प्रकार का वस्त्र तैयार किया जायगा।

(३) उसकी उत्पत्ति की इकाई (Plant) का क्या आकार होगा?—इसके अन्तर्गत कारखाना घेत दुकान आदि आते हैं।

(४) उसकी फर्म का क्या आकार होगा?—इस प्रश्न का सम्बन्ध उपरि की मात्रा से है।

(५) वह उत्पत्ति के कौन से उपाय काम में लायगा?—इसके अर्थ शक्ति में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह उत्पत्ति के विविध साधना का उपयोग किस अनुपात में करेगा।

(६) उसकी उत्पत्ति की इकाई किस या किन किन स्थानों पर स्थापित की जायगी?—इस सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों का ज्ञान आवश्यक होता है।

एक आदर्श साहसी के गुण (Qualities of an ideal Entrepreneur) एक आदर्श साहसी में निम्नलिखित गुणों का समावेश आवश्यक है—

१. एक आदर्श साहसी में स्पष्ट दूरदर्शिता होना चाहिए (An Ideal Entrepreneur must have clear foresight)।—एक आदर्श

माहसी के लिये यह आवश्यक है कि वह वस्तु की भावी माँग, किस्म तथा बाजार के उतार-चढ़ावों का ठीक-ठीक अनुमान लगा सके, अन्यथा उसे अत्युत्पादन (Over production) से हानि हो सकती है।

२. उसे मानव मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान होना चाहिए तथा उपभोक्ताओं की रुचियों एवं आदशों से पूर्ण जानकारी होनी चाहिए (He should have a deep insight into Human Psychology and must know the tastes and habits of Consumers)—एक उत्तम साहसी के लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्यों के स्वभाव, रुचियाँ तथा आदतों से पूर्ण परिचित हो। उनकी व्यावसायिक सफलता इस गुण में सन्निहित है।

३. उसे मनुष्यों का नेता होना चाहिए। (He must be a Leader of men)—उसे मनुष्यों का नेता होने के लिये सबसे अच्छे आदर्शों का धुनना चाहिये और मनुष्यों के स्वभाव आदि बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये।

४. उसमें अवलोकन तथा विवेचना शक्ति होनी चाहिए (He should possess the power of observation and discrimination) एक सफल एवं कुशल साहसी में घटनाओं का ध्यान पूर्वक मनन कर उसका ठीक विवेचन करने की शक्ति होनी चाहिए।

५. उसे विनिष्ट ज्ञान से सुसज्जित होना चाहिए (He should possess Technical Knowledge)—एक कुशल साहसी के लिये यह आवश्यक है कि उसे उत्पादन प्रणाली, मशीनों, उनकी वनावट और परिचालन, नये-नये आविष्कारों, कच्चे मान के स्रोतों, तैयार मान के बाजारों और भाषा से पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिये।

६. उसमें विपत्ति को सहने का साहस होना चाहिए। (He must have courage to face hard times)—सफल साहसी वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी न डरता, साहस व धैर्य न छोड़े, निश्चित न हो और निराशा को अपने पास पटकने भी न दे। सफलता उसी के ही पैर चूपती है जो विचारशील, शम्भीर, चतुर, माहसी उल्लाहपूर्ण एवं सहनशील होता है।

७. उसे सतर्क तथा निडरतापूर्वक निर्णय करने वाला होना चाहिए (He should be cautious and still take bold decisions) सफल साहसी सतर्क रहते हुए भी अपना निर्णय निडरतापूर्वक करता है। यह ठीक समय पर सही निर्णय करके धैर्य विदबास के साथ आगे बढ़ता है।

८. उसमें व्यावहारिक साधारण ज्ञान होना चाहिए (He should be gifted with practical Common sense)—सफल एवं आदर्श साहसी को देश, काल और परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होने के अतिरिक्त व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।

भारतवर्ष में साहसी—य गुण प्रायः स्वभाविक अथवा जन्म सिद्ध होते हैं। इसलिये टाटा, बिड़ला, जामिया, मिश्रादिया, आदी, बापू जैसे नाम्य साहसी भारतवर्ष में बहुत कम हैं। अमेरिका के हैबरी हार्ड, रॉबेसोन और न्यूफील्ड के नाम भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। परन्तु उपयुक्त शिक्षा, अवसर और अनुभव द्वारा इन गुणों का विनाश किया जा सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्द्स परीक्षाएँ

१—आदर्श साहसी के क्या आवश्यक गुण हैं ? भारत और मध्य गन्ध दमेरिका के कुछ साहसियों के नाम बताइए । (१९४६)

२—'व्यवसाय के बसान' पर टिप्पणी लिखिए ।

३—धन के उत्पादन में प्रबन्ध और साहस का क्या महत्व है ?

(ग० बो० १९५५)

४—प्राधुनिक व्यापारिक संयुक्त में साहसी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का बताइए । ये उद्योग के कितने क्या हैं ? (प्र० बो० १९५०)

५—प्राधुनिक उद्योग में साहसी के क्या कार्य हैं ? भारतीय शरीर शिपी इन कार्यों को किसे प्रकार करता है ?

(ग० बो० १९५१, १९५८)

६—साहस और प्रबन्ध में क्या संबंध है ? प्राधुनिक उद्योग प्रणाली में साहस क्यों एक आवश्यक साधन माना जाता है ? भारत में साहस के क्षेत्र का बताइए ।

(प्र० बो० १९५४)

७—भारत में प्राधुनिक व्यवसाय संयुक्त में साहसी के कार्य स्पष्ट कीजिए ।

(सागर १९५०)

८—साहसी किसे कहते हैं ? उसके कार्य क्या-क्या हैं ?

(सागर १९५१, ५०, ४६)

९—संयुक्त के साहसी (उपक्रम) के काम का स्पष्टीकरण कीजिए । प्राधुनिक उत्पादन में इन कार्यों का विशेष महत्त्व क्या है ? सूती कपड़ा के उद्योग का उदाहरण लेकर समझाइए ।

(नागपुर १९५७)

१०—उपक्रमी (Entrepreneur) किसे कहते हैं ? उसके आवश्यक गुण क्या हैं ? वह किस से कार्य करता है ? किन्हीं दो मण्डल अधिन भारतीय कीर्ति के उपक्रमियों के नाम लिखिए ।

(नागपुर १९५५)

भारतवर्ष में लघु एवं कुटीर उद्योग (Small scale & Cottage Industries in India)

“प्रौद्योगिक मण्डल हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसमें बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों की समुचित योजना होनी चाहिए। आधारभूत उद्योगों में छोटे-छोटी इकाइयों के निम्ने कम स्थान है, परन्तु उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में उनकी उपयोगिता एवं महत्त्व अधिक है।” —ब्रम्हर्षी योजना

परिभाषा व्यापक धर्म में कुटीर व्यवसाय से उन उद्योग धर्मों का तात्पर्य है जो छोटे पैमाने पर चलाये जाते हैं तथा जो बड़े पैमाने के उद्योगों में विलुप्त भिन्न होते हैं। नीचे कुछ परिभाषाएँ दी जाती हैं —

उ० प्र० प्रौद्योगिक वित्त समिति (१९३५) के अनुसार “कुटीर-धर्मों के होते हैं जिन्हें ग्रामीण अपने ही लेंचे-जोले पर अपने घरों में तथा कर चलाते हैं।”

ये उद्योग-धर्मों जिनमें शक्ति प्रयुक्त नहीं होती है तथा उत्पादन कार्य साधारणतया कारीगर स्वयं के घर पर और कभी-कभी छोटे कारखानों में जहाँ ६ से अधिक श्रमिक काम नहीं करते, चलाये जाते हैं, कुटीर-व्यवसाय कहलाते हैं।^१ इन परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि कुटीर-व्यवसाय में तात्पर्य है उन उद्योग धर्मों में जिन्हें कारीगर अपने घरों में अपने हाथों तथा परिवार के सदस्यों की सहायता में चलाते हैं। कच्चा माल, औज़ार आदि उसी के होने हैं। बड़ी मात्रा तैयार करता है और वहीं बाजार में बेचता है। इस प्रकार का माल उत्तरदायित्व उसी के ऊपर रहता है। ये कारीगर प्राथमिक मशीनों की सहायता के बिना ही कार्य करते हैं। इनमें कार्य-कुशलता पैतृक होती है। इन-धर्मों में विज्ञानों की सहायता भी ली जा सकती है। कुटीर-व्यवसाय नगरी और गाँवों दोनों स्थानों में चलाये जा सकते हैं। गाँवों में जो कुटीर-व्यवसाय स्थित होते हैं उन्हें ‘नेश्रिय बैंकिंग ऑफ कमेटी’ के ग्रामीण या घरेलू उद्योग कहकर पुकारा है। इन उद्योगों में करपे से कपड़ा बुनना, रेशम बनाना, सोने व चाँदी के तार बनाना, धातु के बर्तन बनाना, बोझी-सिगरेट बनाना, चट्टाईयाँ बनाना, गुड़ बनाना, धान से चावल निकालना, पी-दूध का काम करना, तेल पेरना आदि-आदि सम्मिलित हैं।

कुटीर और लघु उद्योगों में अन्तर—योजना समीक्षण ने इन दोनों का अन्तर स्पष्ट कर दिया है : “कुटीर-उद्योग उन धर्मों को कहेंगे जो गाँवों में स्थित हैं, जो कृषि के सहायक धर्मों हैं तथा जिनमें अधिकतर कार्य हाथ से कुटुम्बीय सदस्यों की सहायता में किया जाता है। इनके द्वारा तैयार किया हुआ माल प्रायः पड़ोस के बाजार में लिये जाता है। लघु उद्योग उन उद्योग-धर्मों को कहेंगे जो नगरों में स्थित हैं तथा जिनमें आशिक रूप में अपना पूर्णतया धर्मों के प्रयोग के साथ-साथ बाहर के श्रमिक भी रखे जाते हैं। सहरी कुटीर धर्मों के द्वारा बहुत-सा ऐसा सामान बनाया जाता है जो बहुत दूर-दूर भी भेजा जाता है।”^२

1—The Bombay Economics and Industrial Survey Committee.

2—First Five year Plan

कुटीर उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण (Classifications)—कुटीर व्यवसाय जो इस समय भारतवर्ष में विद्यमान है, निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं :—

(घ) १. वे उद्योग जो कृषकों के लिये सहायक हैं तथा जिनसे उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे—टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, मधुमक्खी पालना इत्यादि।

२. वे उद्योग जिनसे गांवों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे—गुम्हार, कुहार, सुनार और दर्जी आदि के धन्धे।

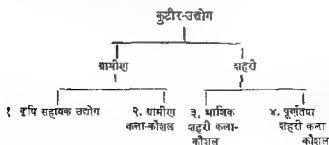
३. वे उद्योग जिनका सम्बन्ध कलापूर्ण वस्तुएं बनाने से है। जैसे—कालीन बनाना, कसीदा निकालना, हाथी-दांत की वस्तुएं बनाना, जवाहरात, चित्रकारी, मोनाकारी का काम आदि।

(घा) भारतवर्ष में कुटीर उद्योग मुख्यतः दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—कलापूर्ण धन्धे और बिना कलापूर्ण धन्धे। नक्काशी, मोनाकारी, बरतों पर सुतहरी पोलिश बढाना, कसीदा, निवालना, लकड़ी और मिट्टी का कलापूर्ण कार्य, जवाहरात का काम, चाँदी-सोने के आभूषण बनाना आदि प्रथम श्रेणी में आते हैं। करघों द्वारा वस्त्र निर्माण आदि कार्य दूसरी श्रेणी में आते हैं।

(इ) इस वर्गीकरण के अनुसार कुटीर-व्यवसाय दो प्रकार के हो सकते हैं :—

ग्रामीण और शहरी व कस्बों में कारखानों के रूप में चलाये जाने वाले उद्योग—प्रथम प्रकार के उद्योग सहायक धन्धों के रूप में अवकाश के समय किसानों द्वारा चलाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, कुक्काला सम्बन्धी कार्य, फल उत्पन्न करना कुवकुट पालना, रेशम के कीड़े पालना, लाख पैदा करना, मधु-मक्खी पालना बढाई बनाना, बाँस और बेंत का काम, जुलाहे और कुम्हार का काम, बीड़ी बनाना, तेल पेलना, घुड़ बनाना इत्यादि। दूसरे प्रकार के धन्धे वे हैं जो कारीगरों द्वारा कारखानों में पूरे वर्ष भर चलाये जाते हैं। जैसे—करघों में सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र बनाना, गोटा-बिनारी बनाना, पीतल के बर्तन बनाना आदि।

(ई) मद्र १९५० ई० के राजकोषीय प्रायोग* (Fiscal Commission) द्वारा दिया गया वर्गीकरण निम्न रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया गया है :—



१. **घृदि महायय उद्योग**—इस भाग के कुटीर-उद्योगों में वे सब उद्योग सम्मिलित हैं जो वृषको द्वारा मृदायक धत्तों के रूप में किये जा सकने हैं। जैसे बरघों पर बुनाई, कीटाकुमि (रेडम के कीट) पालना, टलियाँ या टाकरियाँ बनाने का उद्योग, खाटा पीसने का उद्योग, बीड़ी बनाने का उद्योग आदि।

२. **ग्रामीण कच्चा कौशल**—इसके अन्तर्गत विवेकपूर्वक ग्रामीण हस्त-कौशल आते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, तुहार व मुनार के कर्म, कोनू द्वारा तेल निकालना, सीध के बुनाई द्वारा कपड़ा बुनाई का उद्योग, चर्म तस्करणी उद्योग, गाड़ियाँ बनाने का उद्योग, नावें बनाने का उद्योग आदि जो ग्रामीण प्रय-व्यवस्था में सम्मिश्रित हैं।

३. **और ८ शहरी उद्योग**—इन भागों के अन्तर्गत वे सारे कुटीर उद्योग आते हैं जो शहरी में रहने वाले कारीगरों को पूरा दिन का काम देने हैं। उदाहरणार्थ—बाँदी-सोने व तार का व्यवसाय लकड़ी तथा हाथी-दाँत का बुनाई का उद्योग पीतल तथा प्रस्य धातुका सम्बन्धी उद्योग खिलौने बनाने का उद्योग, रंगम ठगु निर्माण उद्योग बगैरि व छपाई उद्योग आदि।

भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन के कारण (Causes of decline of Cottage Industries)—भारत में औद्योगिक क्षेत्र में जो स्वयंभूत स्थिति बना ली थी वह सर्वत्र के लिये स्थिर रहने वाली नहीं थी। इसका इस गर्वपूर्ण औद्योगिक स्थिति का विपक्षी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की स्थापना में प्रारम्भ हुआ था और प्रवेश के शासन काल के अन्त तक यह चरम सीमा तक पहुँच चुका था। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं—

(१) पुराने भारतीय न्यायालयों का प्रन्त भारतीय उद्योग देनी न्यायालयों की देख-रेख में फूटने पड़ने थे। ब्रिटिश मता के लोकोचरण और केन्द्रीकरण ने उनका नाश हो गया। यह स्वाभाविक ही था कि जब उनके सरलता का ही नाश हो गया, तो वे उद्योग बँसे जावित रह सकते थे।

(२) विपरीत परिचर्मा प्रभाव—पश्चिम देश पर विहित हुआ नया सिष्ट समाज पुरातन भारतीय जीवन का पूर्णतया स्थापना था। प्रवेशी शासन की स्थापना के साथ-साथ पाश्चात्य सम्प्रदाय का प्रभाव अग्रजस्य में अनुभव होने लगा जिसके परिणामस्वरूप देशवासियों के जीवन स्तर, जीवन और कविता आदि में बड़ा परिवर्तन हो गया। वे स्वदेशी ह्रास में बनी हुई वस्तुओं के स्थान में इंग्लैंड पारि देशों की मशीन से बनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा लग गये जिसके कारण भारतीय उद्योग-धर्म इन पतित अवस्था का पहुँच गये।

(३) भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति—पहले लिये उद्योगों को उन्नत करने और उन्हें विदेशी प्रतियोगिता में सुरक्षित रखने का उद्देश्य ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय वस्त्र पर प्रायः प्रतिरोधी कर लगा दिए थे। यद् १७०० और १८०६ के मध्य रमीन छोटें प्रमाणोंवा रोऊ दो गई थी और कनिष्ठ धन्य विस्मो पर ३० से ८० प्रतिशत कर देना हुला था। प्रो० हॉरेस विल्मन लिखते हैं, 'धर्म' इस प्रकार के प्रतिरोधी कर और वन्दन विद्यमान न होने तो पैसले और पैन्नेटर की मिलो का जन्म में हो गया थुट जात और ऊँचे भाप की सक्ति से भी चनाया कटित हो सकता था।' ब्रिटिश-शासन-का ने प्रवेशी वस्तुओं के भारत में सले दानो

में भोक्तने का प्रत्येक यत्न किया गया और भारतीय निर्माताओं को निम्नसाह करने और दबाने की पूर्ण चेष्टा की गई ।

(४) मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता—हाथ में बनी हुई वस्तुएँ मशीन द्वारा बनी हुई वस्तुओं की प्रतियोगिता में नहीं उठर सकती, क्योंकि वे अधिक मँहवी पड़ती हैं तथा उनके तैयार होने में अगाधश्रम तथा समय लगता है ।

(५) भारतीय सरकार की निर्धार्य नीति—शासन की बागडोर इंग्लैंड की मशीनरी से भारत सरकार के हाथों में आने पर भी मरते हुए उद्योगों को महारा नहीं मिला । उस समय की भारतीय अजबों सरकार ने निर्धार्य (Tariff) नीति अर्थात् प्रतिबन्ध रहित व्यापार की नीति को अग्राया और भारतीय उद्योगों के संरक्षण के बारे में सन् १९२१ तक कुछ भी नहीं सोचा गया । फिर भी संरक्षण नीति में हादिकता का अभाव था ।

भारतीय कुटीर-उद्योगों के जीवित रहने के कारण—कुटीर-उद्योगों को मरने करने वाले इतने शक्तिशाली कारणों के होते हुए भी ये अब तक जीवित रह सके हैं, इसके अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

१. जाति-प्रथा के कारण बुढ़ाई, कुम्हार आदि अपने पूर्वजों के ही काम करते हैं । स्थान-परिवर्तन अथवा आजीविका के नये साधन प्राप्त करने में इन्हें बहुत सामाजिक पार्श्वभूमि सहन करना पड़ता है ।

२. बहुतों मनुष्यों की स्वच्छन्दानुसार काम करने की आदत पड़ी हुई है । अस्तु, वे कारखानों में निश्चित घण्टे काम करना अथवा अन्य कानून-कायदा का बन्धन पसन्द नहीं करते ।

३. पद-प्रथा के कारण अनेक औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, उनके लिये परैष धन ही हितकर है ।

४. कारखानों में मिलने वाली मजदूरी इतनी अधिक नहीं होती कि गाँव में लोग सहसा नगर में रहने की अनुविधाएँ और व्यय सहन करने लगे । वे भूख में विशेष पीड़ित तथा अशुचि होकर रहने पर ही निवृत्त होकर घर या कुटुम्ब का मोह छोड़ते हैं ।

५. अपने ही घर में अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के मध्य स्वारभ्यकर बातचरम में अपनी इच्छानुसार कार्य करने का आकर्षण कुटीर व्यवसायों को जीवित रखे रहने में बड़ा सहायक है ।

६. हमारी जनसंख्या के ७० प्रतिशत में भी अधिक लोग कृषि व्यवसाय में रतन्त हैं । कृषि एक मौसमी व्यवसाय होने के कारण १-६ मास के लिये किसानों को बेकार रहना पड़ता है । अनेक सहायक कर्षे ऐसे हैं जो कृषि के साथ सुगमता से चलाये जा सकते हैं ।

७. अब भी भारत में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो कलापूर्ण कार्य के लिये मूल्य देने की तैयार हैं और उनके शौहक हैं । उनके संरक्षण में अनेक पुरानी शिल्पकलाओं को मरने में रूका लिया है ।

८. कठिण ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी माँग स्थानीय, स्थल्य एवं सीमित होने के कारण उनका मशीन द्वारा बड़े परिमाण में उत्पादन नहीं किया जा सकता है ।

६. कुटीर व्यवसायों में तुलनात्मक दृष्टि में माल अधिक मरता बनाया जा सकता है। यही कारण है कि ये आज तक जीवित हैं।

१०. वैवर्णिक धन्यता का अभाव तथा घर न छोड़ने की आदत के कारण पट्टन धन्यता को आसानी से छोड़ना पसन्द नहीं करते।

११. यातायात आदि साधनों के अभाव के कारण अब भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जो दूर व अन्य भाग से विन्तुल कटे हुए हैं तथा जहाँ पर मधीन निमित्त वस्तुएँ पहुँचने नहीं पाती, वहाँ परेनू धन्य ही चलाये जाते हैं।

१२. वे धन्ये जिनमें व्यक्तिगत ध्यान एवं देख देख की आवश्यकता है, छोटे परिमाण में ही चलाये जा सकते हैं।

१३. कुटीर व्यवसाय ही ऐसे धन्ये हैं जिनमें आहुता की शक्तियों के अनुकूल ही उत्पादन किया जा सकता है।

१४. कुछ सिन्धुनारा ने अपने आपको कई अवस्थाओं के अनुकूल बना लिया है और उन्होंने अपने गिल्ह-कला को नये चौजारों व विज्ञानों आदि के प्रयोग में सुरक्षित कर दिया है।

१५. स्वदेशी आन्दोलन तथा समय समय पर औद्योगिक प्रदर्शनों होने रहने में भारत की प्राचीन कला-विज्ञान को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है।

१६. केन्द्रीय सरकार के उदार अनुदान, अखिल भारतवर्षीय स्निहर्षण मण्डल और भारतीय कांग्रेस के धन्य प्रयत्नों ने कई भारतीय सिन्धु कलाओं को नष्ट होने में रोक रखा है। महात्मा गाँधी के दलपूर्वक समर्थन ने भी इन्हें जीवन-दान दिया है।

प्राधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में लघु एवं कुटीर-उद्योगों का महत्व—यह धारण कि लघु एवं कुटीर व्यवसायों का प्राधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है केवल अल्प तथ्य पुस्तक ज्ञान का शोषण है। प्रिंसिपल क्रोपोत्किन (Prince Kropotkin) का कहना है कि “लघु व्यवसाय कभी नष्ट नहीं हुआ है और न हो सके है प्रोटेंस (Protens) अर्थात् सामुद्रिक देवता के समान वे अपना रूप बदलते रहते हैं।”

प्राधुनिक समय में समीचीन विज्ञान की शक्ति, अती लोभा में बलापूर्णा एवं विलास वस्तुओं के उपयोग की अधिक रक्ति, महंगी आन्दोलन तथा औद्योगिक (Technical) ज्ञान के विलुप्त प्रकार आदि अनुकूल भाग में लघु एवं कुटीर-व्यवसायों को बच प्रोत्साहन मिला है और इसी कारण वे आज भी बृहत् उद्योगों के साथ-साथ स्थित हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। वे सहायक तथा पूरक धन्ये हैं न कि बराबरी या स्पर्धा करने वाले। देखा जाय तो वास्तव में कई बृहत् उद्योग स्वयं सहायक एवं लघु व्यवसायों के जन्मदाता हैं। उदाहरणार्थ वाईमिकनों का निर्माण तो बड़े कारखानों में होता ही है, परन्तु उनको ठीक अवस्था में रखने तथा उनके बीलोंद्वारा वे लिये नगर की कनी-कनी और कोने-कोने में इस प्रकार का कार्य करने में लिये छोटी-छोटी इमारतें प्रायः देखी जाती हैं। यही बात मोटर-कारों के व्यवसाय पर भी लागू हो सकती है। इसी प्रकार मृत्त कपड़े के मिल के साथ साथ फीने, दरियाँ, निवार आदि बनाने के व्यवसाय स्थापित हो जाते हैं।

यहाँ तक कि विश्व के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस में ६९% औद्योगिक संस्थाओं में से प्रत्येक में १०० में कम मनुष्य काम करते हैं। जर्मनी में १२.६% मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिये कुटीर व्यवसायों पर आश्रित हैं। दरमिद्धम जैसे आधुनिक औद्योगिक नगर में भी प्राचीन औद्योगिक संस्थाएँ छोटे पैमाने पर काम करती हैं और प्रत्येक से ५० मनुष्य में भी कम काम करते हैं। हान्सड और वेल्जियम में भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ छोटे कारखानों में ही तैयार होती हैं। स्विट्जरलैंड का घड़ी बनाने का कुटीर व्यवसाय तो जयन्त-प्रसिद्ध ही है। जापान में औद्योगिक जनसंख्या के ५२% मनुष्य सब भी अपनी प्राचीन कुटीर व्यवसायों में ही प्रान्त करते हैं। चीन में सहकारी प्रणाली के अन्तर्गत कुटीर व्यवसायों ने बड़ी उन्नति की है। सोवियत रूस में भी औद्योगिक व्यवसाय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत-वर्ष में अनेक योजना बनाने वालों ने भी कुटीर व्यवसायों के पुनर्मज्जुन पर बड़ा धन दिया है। हाल ही के भारतीय राजकोषीय आयोग अर्थात् किम्बल कमीशन ने अनुमान लगाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार का ६२.५% भाग छोटे परिमाण में होता है जिनमें देश के ४५% मनुष्य बाय सम्पन्न हैं तथा जिनके द्वारा ३४, व्यापार संचालित होता है।

भारतवर्ष में कुटीर उद्योगों का महत्व—भारतवर्ष में कुटीर उद्योगों का महत्व और भी अधिक है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है यहाँ के लियानी निर्धन हैं तथा अधिकांश जनता का जीवन-स्तर नीचा है। हमारे कृषकों को पूरे वर्ष भर काम नहीं करना पड़ता है। कृषि के शाही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “भागीय कृषि की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पर काम करने वाले कृषकों को हमारे वर्ष भर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में कम से कम बार महीने वह बिलकुल खाली रहता है। ऐसे खाली समय में उसको तथा उसके परिवार को कोई काम देने के लिये लघु एवं कुटीर व्यवसायों की आवश्यकता है।” “भारतीय बैंकिंग जाँच समिती” का भी मत है कि “कृषकों को तथा उसके परिवार को उनके खाली समय में काम देने के लिये कुटीर व्यवसाय स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह अपनी आय बढ़ा सकता है।” डा० राधाकृष्णन मुकुनी ने खोज करके पता लगाया है कि उत्तर भारत के बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ वे कृषक वर्ष भर में लगभग २०० दिन बेकार रहते हैं। उनका कहना है कि कहीं-कहीं तो जहाँ सिंचाई के उत्तम साधन प्राप्त हैं, इससे भी अधिक समय तक बेकार रहते हैं। जिस कृषक के पास कम भूमि है उसके ता मारे परिवार की भी उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। अस्तु, उन लोगों को ऐसा काम देने की आवश्यकता है जहाँ वे काम करके अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ भी बना सकें तथा अपनी आय की वृद्धि भी कर सकें। राष्ट्रीय योजना समिति (१९३६) का मत था कि “आमोण भारत की अधिकांश जनता अपने शैक्षिक कल्याण के लिये अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त कर पाती। अतः उनके लिये कुटीर-धंधों को स्थापित करना बहुत आवश्यक है।” और हम अपनी कृषि को वैज्ञानिक एवं यांत्रिक करना चाहते हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार जो लोग वे रोजगार ही जायेंगे उन्हें काम देने के लिये छोटे घरेलू धंधों को प्रोत्साहित किया जाय। इसी प्रकार योजना कमीशन ने पंचवर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन व्यवसायों के विकास के लिये व्यय करना निश्चय किया है। कमीशन का कहना है कि “सरकार को चाहिए कि

बटोर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के पथों के सम्बन्ध में बैसा ही उत्तरदायित्व ग्रहण करे जाता कि उसने नेतृ के विकास के सम्बन्ध में ग्रहण किया है।

भारतवर्ष में कृषि वर्षा पर निर्भर है और वर्षा स्वयं परिमाण्य एवं समय की दृष्टि में अनिश्चित है। अस्तु, ग्रामीण उद्योग-वन्धों के विकास में यह भाग्यितता कम होकर अकाल की ओपस्थता कम हो सकती है। इस प्रकार ग्रामीण उद्योग-वन्धे 'धनुष की बूमरी रस्ती' की भाँति कृषि के लिये उपयोगी मित्र हो सकते हैं।

कुटीर व्यवसाय हमारे देशवासियों की प्राकृतिक प्रतिभा और गह्वीय परम्परा के अनन्त है। कई पीढ़ियों के अनुभव ने हमारे कारीगरों ने इन कामों में विशेष दक्षता प्राप्त कर ली है। इन उद्योग-वन्धों के लिए जो बच्चा माल चाहिए वह हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है। इनमें बहुत कम पूँजी की आवश्यकता होती है जोकि हमारे कारीगर स्वयं तथा बहुत ही अथवा सुश्रमता में प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सरल और साधारण औजारों की आवश्यकता होती है जो हमारे देश में तैयार होत हैं। इनके तैयार माल की सरीसृप के लिये हमारे यहाँ बहुत सख्या में स्थानीय उपभोक्ता होते हैं जिनकी भिन्न भिन्न रुचि और स्वाभाव में स्थानीय कारीगर सुपरिचित होते हैं। इन प्रकार कारीगर कुशलता और सुन्दरतापूर्वक इनकी आवश्यकताओं का पूर्ण करके पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं।

हमारे देश का श्रम शक्ती अतिशय एवं अनिपुण है, अतः इस प्रकार के श्रम से बड़ा कारखाना की अपेक्षा छोटे कारखानों का विकास अधिक सुश्रमतापूर्वक हो सकता है। इनके अतिरिक्त हमारे पूँजी के अभाव स्वल्प होने के कारण बड़े कारखानों की अपेक्षा छोटे कारखाने अधिक सुश्रमता में चलाने जा सकते हैं। धूम पर जन-संख्या का आर्थिक बचान तथा भूमि-अपव्ययन व जन-तल स्थित होना व काष्ण भागवत् वर्ष में प्रम कृषि एक लाभदायक उद्योग नहीं रहा है। अस्तु कृषकों का अपनी अपव्ययन एवं प्रत्य प्राय का पूरा करन के लिए महीयक धंधे चलाया आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखानों में महीयों और पेचीदा मशीनों के प्रयोग में श्रम-संचय का लाभ प्राप्त होता है। अतः कम प्रावर्दी वाले देशों में जहाँ श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इनमें अधिक लाभ पहुँच सकता है। परन्तु भारत में श्रम-संचय जनसंख्या वाले देश में बड़ा कारखानों का विकास एक सीमित अवस्था तक ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परन्तु भागवत् वर्ष की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये जीवनोपाय व माधन उपस्थित करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग-वन्धों का विकास नितान्त वाञ्छनीय है।

देश के विभाजन ने एक नई समस्या और उपस्थित हो गई। यह है पुनर्वास समस्या। पाकिस्तान में प्रायः दूध लोगों को बसाना और काम-कामे देश एक नई समस्या है। इसका बहुत-बहुत हल कुटीर एवं लघु व्यवसायों के विकास में सन्निहित है।

महात्मा गांधी ने देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में कुटीर व्यवसायों के महत्व पर सदैव बल दिया। ये कारखानों में बड़े परिमाण्य की उत्पात्ति की अपेक्षा परों में ही वृद्ध उत्पादन चाहते थे। उनकी अभिप्रायों में यहाँ तक थी कि प्रत्येक गाँव में बिजली हो जाए और गाँव वाले अपने औजार आदि बिजली में चलाने लग जायें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत का उद्धार गाँवों के पुनरुत्थान में सन्निहित था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये महात्मा गांधी की प्रेरणा से अखिल

भारतवर्षीय ग्रामोद्योग एतामिवेश्वर तथा अखिल भारतवर्षीय स्विनम एसोसियेशन को स्थापना हुई। ये दोनों गृहार्थ भारतीय वृद्ध उद्योगों विवेकता शहर उद्योगों को जीवित रखने में बड़ी सहायक भिन्न हुई हैं।

प्राचार विनोबा भावे^१ ने भी बनारस में अपनी ११ अगस्त १९१२ की प्रापना सभा में कुटीर उद्योगों को के विकास पर बड़ा ध्यान दिया और बताया कि इनमें कृषकों को धन में वृद्धि होगी जिससे उनकी अन्य शक्ति बढ़ेगी।

लघु एवं कुटीर व्यवसायों से लाभ (Advantage)—लघु एवं कुटीर व्यवसायों के विकास में देश को निम्नलिखित लाभ हैं।

(१) आर्थिक लाभ—भारतवर्ष में किसानों का धन में नुकसान ५६ करोड़ों के बराबर है। प्रत्येक वर्ष के इस प्रकार नुकसान में अनेक कुटीर व्यवसायों का बना कर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बना सकते हैं। शहरों में भी हजारों व्यक्ति इन व्यवसायों में अपना जीवनयापन कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्ष में लगभग ४० प्रतिशत श्रमिक धन में कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। अतः सहायक धन द्वारा वे अपनी इस बेकारी को दूर कर सकते हैं।

(२) श्रमिकों से सुरक्षा—सन् १८८० ई० के भारतीय प्रवाल कमीशन ने यह बताया कि भारत में श्रमिकों का प्रवाल प्राप्ति में सुरक्षित रहने के लिये कुटीर उद्योगों का विकास अति आवश्यक है।

(३) कारखाना प्रणाली के दोषों में मुक्ति—कुटीर व्यवसायों द्वारा कारखाना प्रणाली के दोष दूर हो सकते हैं क्योंकि इसमें उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो जाता है जिसमें गृहों में अपनी आवासों नहीं हैं। अतः अपनी और अपने अपने आर्थिक एवं मानसिक पतन में बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हड़ताल और तानाशाही तथा धोखाधड़ी का जो हितकुल ही भय नहीं रहता।

(४) नैतिक लाभ—नैतिक दृष्टि में भी कुटीर व्यवसायों का उत्कर्षात्मक वास्तविक है। इनमें निरंतर अपना आत्मनिर्भर रह सकते हैं। कारखानों में अपने घर के स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने का काम कर सकते हैं तथा उन्हें शारीरिक परिश्रम भी कम करना पड़ता है।

(५) बेकारी की समस्या दूर हो सकती है—दुष्कालावन कृत्रिम पानन उद्योगों का वृद्ध की सबसे पानना आदि धन कुटीर व्यवसायों में लोग की बेकारी की समस्या भी कुछ घट सकती है।

(६) भारतीय शिल्पकला का प्राचीन गौरव कायम रखा जा सकता है—भारतवर्ष प्राचीन काल में ही अपनी शिल्पकला के लिये सुप्रसिद्ध है। प्रत्येक कुटीर व्यवसायों के विकास में यह प्रसिद्धि गौरव एवं परम्परा कायम रखी जा सकती है।

(७) धन वितरण की असमानता दूर हो सकती है—बढ़ परिणाम की उत्पत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अधिकांश धन कुछ ही पूँजीपतियों के हाथों में है और श्रमिकों को केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिये धन प्राप्त होता है। इसमें

ग्रामन्तोष की भावनाएँ उत्पन्न होकर पारस्परिक संघर्ष खड़ा हो जाता है। लघु एवं कुटीर व्यवसाय इस असमानता एवं असन्तोष को दूर करने का दावा रखते हैं।

(८) देश का आर्थिक सन्तुलन सुदृढ़ बन जायगा—कुटीर तथा लघु उद्योग उद्योग-धन्यो के विकास में देश की प्रतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा हिनयो और बालका को भी उनकी शक्ति और योग्यतानुसार काम मिलने लगेगा। ग्रामीण लोगों को अपनी आय बढ़ाने के साधन मिलेंगे जिनसे व अपनी जीवन स्तर ऊँचा बना सकेंगे। इनमें बहुत-से पढ़े-लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा तथा देश का आर्थिक बलबल सन्तुलित होकर सुदृढ़ बन जायगा।

(९) भूमि पर जनसंख्या का भार कम हो जायगा—लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में देश में अनेक धन्ये मुक्त जायेंगे और जनसंख्या का एक बड़ा भाग इनमें जीवनयापन कर सकेंगा जिसमें भूमि का भार कम हो जायगा। इन समय कुटीर उद्योगों के अभाव में मजदूरी को अपनी आजीविका के लिये भूमि की पार ही बेचना पड़ता है।

(१०) कला-कौशल की उन्नति होगी—कुटीर उद्योग धन्यो का कला की दृष्टि में भी बड़ा महत्व है। कारीगरों की पलाई यस्तुएँ सुन्दर और कलापूर्ण होती हैं।

(११) कुटीर-उद्योग कृषि उद्योग के सहायक सिद्ध होंगे—बड़ी कुटीर-उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कृषि को प्रत्यक्ष रूप में सहायता मिलती है। जैसे, दुग्धघाला सम्बन्धी उद्योग में न केवल उसे एक उनके कुटुम्ब के सदस्यों के ही स्वास्थ्य को दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में उपयोग में लाभ पहुँचाना, बल्कि उसे कृषि के लिये उत्तम पशु भी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार तेज घेरने के कार्य में सती व साव पशुओं के लिये सलाख प्रयुक्त की जा सकती है।

लघु एवं कुटीर उद्योग की वर्तमान अवस्था—भारतभर में सभी लघु एवं कुटीर उद्योग समान अवस्था में नहीं हैं। मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता के अनुसार उनकी अवस्था में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिये ढाका की मनमल का तो नाम-निगान ही नहीं रहा। कुछ धन्य ऐसे हैं जो मृतप्राय अवस्था में हैं।

भारतभर में अब भी एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुटीर एवं लघु उद्योगों में अपनी आजीविका प्राप्त करता है। निम्नलिखित सब प्रकार का कुटीर व्यापार छोटे पैमाने पर ही होता है। कृषि-कार्य एवं लघु स्तर पर ही होता है। इसके प्रतिरिक्त, असंख्य औद्योगिक कलाएँ और हस्तकारियाँ हैं जो देश में लाखों लोगों का रोजगार देती हैं—इस विषय में डा० राधाकमल मुकुर्जी का अनुमान है कि यह संख्या १ करोड़ ४० लाख से कम नहीं। इस समय के अनुमान के अनुसार देश में कुटीर उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं जिनमें से ३० लाख व्यक्ति हाथ करपा उद्योग में ही काम करते हैं।^१ डा० राधाकमल मुकुर्जी ने यह उद्योगों की बहुत लम्बी सूची दी है जो अब भी देश के विभिन्न भागों में प्रचलित हैं।^२ उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं। बाखरवी, इलाहाबाद, जौनपुर के जिलों में कई गाँवाँ व थोकरी

1—*Economics Problems of Modern India* 1941, Pages 20 & 25

2—*Economics Problems of Modern India*, 1941, pp 14-21

बनाना, मनावार और दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल में रस्से बनाना, चटार्ई बनाना, पक्षियाँ बनाना, ग्रासाम में रेघम के कीड़े का पालना; मेरठ, बदायूँ, मिर्जापुर (उ० प्र०), मोलपुर (बंगाल), चेन्नापाटन (मैसूर) और कोटापल्ली (मद्रास) में खास और सिचौने बनाना, धनूतमर, मिर्जापुर, भागना और वाराणसी में दरियाँ व कानौन बनाना मुशिदाबाद, मातवा, मधुय और भागनपुर में रेशम बुनना, मिर्जापुर (उ० प्र०) और नदिया (बंगाल) में कलापूर्ण मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, निजेवल्ली (मद्रास) में सुँगियाँ और माडियाँ बनाना, फतहपुर और फिरोजाबाद (उ० प्र०) में काँच की चूड़ियों का काम । डा० मुकुर्जी लिखते हैं, “प्रत्येक जिले के एक या अधिक गाँवों में सूती कपड़ा व रेशम की बुनाई होती है, लकड़ी का काम होता है, चीने, चाँदी, ताँबे, डिघानु, बाँस, घेत और चमड़े का उष्मकटि का कलापूर्ण काम होता है । समस्त देश में कपड़ों पर कटार्ई और बुनाई का काम होता है । साधुनसाजी का भी बहुत विस्तार पूर्वक काम किया जाता है ।”

भारतीय कुटीर-उद्योगों की स्थिति का विश्लेषण करने में पता चलता है कि मशीन निर्मित वस्तुओं ने कई बृह-उद्योगों को रमावल में पहुँचा दिया है । जिन उद्योगों ने प्रतियोगिता का सामना किया है वे इस समय में शोचनीय अवस्था में हैं और कारीगर अपनी विवशता और जड़ता के कारण उनमें बिपटे हुये हैं । कुछ लघु उद्योग ऐसे भी हैं जो प्राथिक दृष्टि से अच्छे अवस्था में हैं । यह विश्व-महायुद्ध के कारण भारत में मागत में कमी हो गई जिसके कारण कई भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला तथा अनेक नये कारखाने भी स्थापित हो गये । बहुत बगानी में कुटीर मिल्पकारों ने अपने-आपको जीवित रखने के लिये परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार हस्त लिया है और अपने उत्पादन माधनों में उचित परिवर्तन कर दिये हैं । औद्योगिक धामीशान के शब्दों में “जुनाही ने मिल का मूल, रंगरेजों ने रासायनिक रंगों, लुहारी ने कारखाने के ताँहे का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है । वर्गी मशीनों और कारीगर मशीनों से घने औजारों को काम में लाने लगे हैं ।” इस प्रकार कुटीर-उद्योग अपने-वैशि में कारखाना उद्योग का पूरक हो गया है ।

भारतवर्ष के प्रमुख कुटीर एवं लघु उद्योग—हमारे देश में वैसे तो अनेक उद्योग-धन्धे कुटीर प्रणाली पर चलाने जाते हैं परन्तु उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

देहन दण्डसाय—यह व्यवसाय भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है तथा भारतीय कुटीर उद्योगों में इसका सर्वोच्च स्थान है । प्रायः इस उद्योग के दो भाग किये जाते हैं :—

(प्र) मूल कानना और (भा) मूल से कपड़ा बुनना ।

(अ) मूल कानना—उन धेधों में जहाँ कपास उत्पन्न होता है, किमान कुछ कपास लेकर साफ करके और उसमें से जिनोले अनय निकाल कर अपने परिवार के सदस्य, जैसे स्त्री, बृद्ध माता, बच्चों आदि की सहायता से प्रयत्न के समय मूल कानना है । कता हुआ मूल गाँव के जुनाहे को लेकर अपने कुटुम्ब के लिये कपड़ा तैयार करा लिया जाता है । हाथ से मूल कानने का काम पहले बहुत होता था, परन्तु मशीनों के प्रयोग ने इसे कम कर दिया है । अखिल भारतवर्षीय चत्तोग्रिध राष्ट्रीय, कावेत और राज्य सरकारें इस काम को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

(ग्रा) हाथ से कपड़ा बुनने का व्यवसाय-अर्थात् हाथ-करघा उद्योग (Handloom Industry) - भारत अपने वस्त्र-उद्योग के लिये प्राचीनकाल में विद्व-विख्यात था। अब भी भारतीय कुटीर-उद्योगों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यवसाय देश की चौथाई मांस की पूर्ति करता है। सन् १९३२ के भारतीय प्रयुक्त मण्डन (Tariff Board) के अनुसार हाथ-करघा उद्योग में लगभग १ करोड़ व्यक्तियों का भरण-पोषण होता है। उन्हीं ने करघों की मरम्मत का अनुमान २५ लाख के लगभग लगाया था। सत्य-शोध समिति के अनुसार भारत में आज २० लाख घर हैं जो ६० लाख व्यक्तियों की आजीविका का साधन हैं। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन १०० लाख गज आका गया है जो संगठित उद्योगों के उत्पादन का ३ से अधिक है।

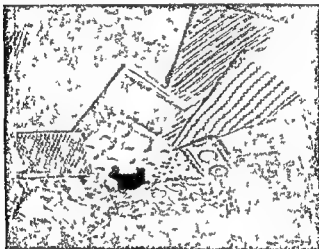
हाथ-करघा उद्योग के मुख्य केन्द्र—हाथ-करघा उद्योग के मुख्य केन्द्र निम्न-निम्न हैं—मद्रास, कडप्पा, कोयम्बटूर, काशीकट (मद्रास), पूणा, कर्नाटक (बम्बई); इटावा, अलीगढ़, गारावली, ब्रह्मपुर, समरौहा, गोरखपुर, पाराणसी, आगरा, बरेली, कानपुर, मिर्जापुर, मुम्बई-नगर (उत्तर प्रदेश); भागलपुर, पटना, गया, हुगलीबाग, दम्भगा, राँची (बिहार), शान्तिपुर (बंगाल), नागपुर, पन्डरी, ग्वाल्दर (मध्य प्रदेश), बगलोर (मैसूर), धर्मपुर, अम्बाला, रोहतक, लुधियाना, (पंजाब), धौलपुर (राजस्थान), जयपुर, बीकानेर (राजस्थान)। उपर्युक्त केन्द्रों में खादी, मनमज, बरिदी, शाल-बुधाने, कालोन, कम्बल आदि बनते हैं। १९५०-५५ में १०-१५ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हुआ तथा ७-७२ करोड़ ६० की सारी बिकी।

केन्द्रीय सरकार के प्रयत्न—केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग के लिये सन् १९४६ में एक स्थायी 'हाथ-करघा बोर्ड' (Handloom Board) की स्थापना की जिसमें राज्यो के प्रतिनिधि, गैरसरकारी, युवक, ~~युवक~~ हाथ-करघा उद्योग के प्रतिनिधि हैं। इस बोर्ड ने हाथ-करघा उद्योग की उन्नति के लिये कुछ सिफारिशों की हैं जैसे बुनकरों की भावश्यकता के अनुसार मूल की पूर्ति बढ़ाई जाय, अथवा मूल के भागत में वृद्धि हो, बुनकर सहकारी समितियों में वृद्धि हो, मूल व रण का वितरण ठीक ढंग में हो, बुनने की बिक्री के लिये उचित व्यवस्था हो, फारीसों को सामयिक शिक्षा देने के लिये शिक्षण एवं अनुष्ठान संस्थाओं की स्थापना हो, आदि। भारत सरकार ने १९४५-४६ में लगभग ४ वर्षों में खादी के विकास के लिये १२ करोड़ ५६ लाख ६० की सहायता स्वीकार की थी। इसमें से योजना बनाने वाली संस्थाओं ने लगभग १२ करोड़ ३२ लाख रुपये खर्च किया था। सन् १९४६-४७ में भारत सरकार ने खादी उद्योग के लिये ६ करोड़ ३५ लाख ६० का अनुदान और लगभग ४ करोड़ ५२ लाख ६० का ऋण देना स्वीकार किया। इसमें अम्बर खादी भी शामिल है। रिजर्व बैंक सूत खरीदने के लिये बड़ी सहकारी समितियों को ऋण देता है।

केन्द्रीय सरकार निम्न उपायों द्वारा हाथ-करघा उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है :—

(१) युवकों के लिये सुत-प्राप्ति के हेतु मद्रास और उज्जैना में दो सुत बानने वाली मिल खोल रही है। (२) कुछ विशेष प्रकार की वस्त्रों की किन्म हाथ-करघा उद्योग के लिये सुरक्षित कर दी गई है। (३) मिल के बने कपड़ों पर २ नया पैसा प्रति गज उपकर (Cess) लगाने से जो बर्बाद होती है वह हाथ-करघा उद्योग की उत्पत्ति में लगाई जा रही है। (४) औद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जा रही हैं जिनमें शिल्पकार हिस्सेदार होंगे। (५) केन्द्रीय सरकार पर्याप्त भाषिक

सहायता दे रही है। (६) विद्युत् को बढ़ावा देने के लिये प्रति रुपया ५ से ६ नये पैसे तक छूट दी जाता है। ब्राम्प पिछा मगडब मद्रास में खान्दा मया है जिसकी शाखाएँ मद्रास बाबई कनकता बाराणसा तथा खान्दा ॥ है। (७) ग्रामाण क्षत्रा में हाथ करके व वन बपडा व प्रचार क लिय ४० मोटर गाडिया का व्यवस्था की रबोहति दो गई है। (८) हाथ करके व वन कपडा के भण्डार कोलम्बा घटन मिनापुर में खोन मय है। (९) हाथ करके के वन बपडा व निर्यात पर कोई शुल्क नहा लिया जाना। (१०) हाम ही म भारत सरकार ने सहकारी समितिया के बुनकरा के लिय बहिनया धनाने व रिने महायता धन व एण योजना स्वीकृत व है।



बगाल के हाथ करपा की साडियाँ

ग्रजिल भारतवर्षीय चर्मा सघ—इत तस्वा ने भी इस उद्योग के बडाने में प्रगतनीय काय किया है। देश भर में स्थान-स्थान पर कताईगरा घोर बुनकरों को महायता दकर लादी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है।

ग्रादी उद्योग का मया आघार अम्बर चर्मा—नघु एष प्रामोश्री १९५५ पर नियुक्त कव समिति न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के घटगत घटिरित लादी उत्पादन के लिये अम्बर चर्मा के प्रयोग की सिफारिश की है। अम्बर चर्मा वह चर्मा है जिसमें ४ तकनिमी होती है जिनके द्वारा कताईगरा घाठ घट दिल्य काम कर सुत व ६ सपडे (Hanks) कान सकता है। भारत सरकार ने सन् १९५७ ५८ में ७५ हजार अम्बर चर्मे चानू करन की स्वीकृति दी। सन् १९५७ ५८ में अम्बर चर्मे के सुत से १ करोड ११ लाख ५० हजार वग गज बपडा तैयार हुवा। १९५७ ५८ में अम्बर चर्मा कार्यक्रम के अन्तगत ११० १५३ व्यक्तिया को रोजगार मिला। द्वितीय योजना में कपडा का उत्पादन १ अरब ७० करोड गज बढ़ाया जायगा जिसमें से ३ करोड गज बपडा अम्बर गूत से बना होया।

हाथ करघा उद्योग और योजनाएँ—प्रथम पंचवर्षीय योजना में हाथ-करघा उद्योग में लिये ११.१ करोड़ और सादी उद्योग में लिये ८.४ करोड़ रुपये खर्च किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रमशः १६.५ करोड़ और १६.७ करोड़ रुपये खर्च किये गये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में गिजर्व बैंक ने द्वारा उन्हें ऋण दिया जायगा और यह एक विवेकता होगी। भारत सरकार हाथ करघा उद्योग को सहकारिता के आधार पर चलाने का सिद्धान्त स्वीकार कर उन्हें वार्षिक सहायता तथा मूल ऋण देने और हाट व्यवस्था में भी सहायता दे रही है।

रेशम का उद्योग—भारत प्राचीन काल में अपने रेशमी वस्त्रों के लिये देश-देशान्तरी में विख्यात था। विदेशों में जहाँ भारतीय रेशमी वस्त्र निर्यात किया जाता था, चीन, जापान और फ्रांस मुख्य थे। सन् १८८६ ई० में लगभग ११ लाख रुपये का रेशमी वस्त्र निर्यात किया गया था, परन्तु धीरे-धीरे यह निर्यात कम हो गया। यूनिफ रेशम का प्रादुर्भाव इस क्षेत्र में लिये प्राप्त मिट्टी द्वारा। मानक भी भारत में रेशम का व्यवसाय बुटीर व्यवसाय ही है। रेशम का बीड़ा बंगाल, मद्रास, माल, केर, अरु, गुजरात प्रादि प्रदेशों की पत्तियाँ खिजाकर चला जाता है। रेशम भारत के निम्नलिखित भागों में पैदा होता है—

(१) काश्मीर, जम्मू तथा पंजाब का मिला हुआ भाग। (२) बंगाल में मुर्शिदाबाद मालदाह, राजगाही और बीरभूमि के जिले तथा बंगाल का पश्चिमी भाग। (३) दक्षिणी मैसूर का पटार तथा कोयम्बटूर का जिला। सन् १९५७ में ३१.७० लाख पींड वस्त्र रेशम का उत्पादन हुआ जिसमें से लगभग आधे का उत्पादन मैसूर राज्य में ही हुआ। मैसूर के बाद इसके महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों में असम, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिमी बंगाल तथा मद्रास के राज्य आते हैं। अगस्त १९५८ में पुनर्संयुक्त 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' रेशम उद्योग तथा रेशम बीड़ा-पालन के विज्ञान को देखभाल करता है। द्वितीय योजना में इस क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' की ओर से मैसूर में एक अखिल भारतीय रेशम-बीड़ा-पालन प्रशिक्षण कक्षा तथा श्रीनगर में एक 'केन्द्रीय रेशम बीड़ा (विदेशी) पालन केंद्र' स्थापित किया गया है।

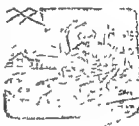
ऊनी वस्त्र का उद्योग—ऊनी वस्त्र उद्योग भारतवर्ष में प्राचीनकाल में प्रचलित है। मुगल काल में काशी, दूरी व शाल का धन्धा बहुत उन्नति पर था, परन्तु विदेशी वस्त्र के आगमन से ऊनी वस्त्र का धन्धा चोपट हो गया। ऊन में जो वस्तुएँ तैयार होती हैं उनमें शाल दुधाले, बम्बल, काशीन एवं पहने के लिये वस्त्र मुख्य हैं। भारतीय ऊन बहुत पटिया होता है, अतः अच्छा ऊन वपडा बनाने के काम में नहीं आ सकता। फिर भी काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पारस, उत्तर प्रदेश, खान्तिर, बगनौर में यह धन्धा किया जाता है। काश्मीर के शाल-दुधाले बहुत प्रसिद्ध हैं। दरिया के किनारे मिर्जापुर, एलोर, अमृतसर और आगरा प्रसिद्ध हैं। बम्बल का पधा देश के कई भागों में प्रगतिशील प्रवृत्ति में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त हाजिरी अर्थार्थ स्वेटर, मात्र, मफलर आदि बनाने का उद्योग भी दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। बंगाल और उत्तर प्रदेश हाजिरी के मुख्य केन्द्र हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग ६० लाख रुपये का मान प्रति वर्ष बनाया जाता है।

लनड़ी सम्बन्धी उद्योग—आधा में कई इस उद्योग को सहायक धरे के रूप में करते हैं। वे अपने घर-बाग के समय हल, बेलगाड़ी, चूल्हे, गड़े, चावर, भवान बनाने के लिये आवश्यक लकड़ी का सामान प्रादि वस्तुएँ बनाने हैं। बड़े बाग और कच्चा में

वे इसे स्वतन्त्र कुटीर-उद्योग के रूप में करते हैं। बाहरा में बड़े-बड़े तांग कर्मीयों और मकान निर्माण सम्बन्धी लकड़ों का सामान तैयार करते हैं। लकड़ों के खिलौने प्रगति वाले कारीगर भी पाये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में लकड़ी की कारीगरी का प्रचलन काम होता है। राहागपुर इस काम के लिये प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में पुराने और अमेरिका का मान निर्यात भी किया जाता है। लखनऊ, देहरादून, बरेली, मीरठ, बाराणसी आदि नगरों में लकड़ी के खिलौने तथा लकड़ी का अन्य सामान बनाया जाता है। पन्ना में त्रिबेट, टैनिंग आदि वास्तव्य घर के भेनों का सामान बनाया जाता है। अमृत में चन्दन को लकड़ों की धनी हुई वस्तुओं पर आरोक कलाओं से सुन्दर का काम बहुत ही सुन्दर होता है।

धातु सम्बन्धी उद्योग—प्राचीन समय में राजा, महाशत्रु तथा नगरों का राज्य शासक में युद्ध का सामान, जैसे नखवार, दान, छुरा, भाले, अस्त्रों आदि तुरीया द्वारा ही बनाई जाती थी। आजकल भी देशों के श्रोत्रार्थ, जैसे—हथका, फाल, पावडा, कुल्हाड़ी, कुदाला, सुर्पा, बमूला, हँसिया, हथौड़ा, बैलगाड़ी में लगे बाला और गकान के काम आने वाला मोहक का सामान आदि गांधी में रहने वाले लुहार ही तैयार करते हैं। बाहरा में लोह का सामान बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होता है। झेलम में लोह का पात्र, ताले, सौरी मच्छे बनते हैं।



लोहार

ताँबा, पीतल आदि धातुओं के वर्तन कर्मियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तन बनाने का मुख्य केन्द्र है। बाराणसी, मिर्जापुर, फतेहगढ़, हाथरस, प्रयाग, फतेहपुर, हरदोई, लखनऊ, मेरठ, आगरा मुरादाबाद आदि नगरों में वर्तन बनाने का मुख्य काम होता है। मुरादाबाद कर्मियों के वर्तन के लिये प्रसिद्ध है और वहाँ वर्तनों पर सुलाई का काम प्रचलन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपये का मान बनता है। इन वर्तनों का आनंदिक मूल्य व खिलौने वस्तुओं जैसे—पानदान, मिर्चदान, फूलदान, पीकदान, मिर्चदान-बेल, पण्डित, दे, आदि वस्तुएँ बड़े ही कलापूर्ण ढंग से बनाई जाती हैं जिनकी माँग विदेशों में भी रहती है। कुँआला सर्माजी की रिपोर्ट का अनुसार इस उद्योग में गाँव द्वारा स्थिति समान है जिनके द्वारा बनी हुई वस्तुओं का बाणिज्य मुख्यतः लगभग ३० लाख रुपये होता है।

देग की जनता का रहने पहनने की बड़ी रचि है। चांदो भावा, पीतल, ताँबा आदि के रहने गाँव की स्थितियों में ही पाये जा सकते हैं। पहने की रचियाँ भी मोन तथा चांदो के प्राधुनिक ढंग के फैशनदार रहने पहनती हैं। मनुष्य का माँस बाणिज्य, हाथ की उँगलियों में अंगूठियाँ और सोने में बटिया पहनते हैं। ये वस्तुएँ सुनारों द्वारा बनाई जाती हैं। इस उद्योग में लाखों व्यक्तियों का भरण-पोषण होता है।

धर्म सम्बन्धी उद्योग—हमारे देश में धर्म-धन बहुत है। समाज में गांधी और भेमाँ का जिनकी मर्यादा पाई जाती है, उसका १५ ५० भाग हमारे देश में है। इसी प्रकार समाज के १६-१७% मेड-वर्ग की दशा में पाये जाते हैं। इन धर्मों के मरने पर जो बगडा निवसता है वह बच्चे माल के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ग्रामीण लोग, समाज, मोक्ष आदि इसी बच्चे माल से जूझते, मरने, चरम

यादि चमड़े का भागान भंडार करते हैं। इनके प्रतिरिक्त घोड़े, ऊँट आदि पशुओं की मशरौरी के लिये काटरी नगाण, आदि वस्तुएँ भी बगई जाती हैं। यहाँ से भी इन लोगों द्वारा देशों को लूटे चम्पस चमड़ के बरत आदि बनाए जाते हैं। इन लोगों की कार्य-प्रणाली प्राचीन है। अधिकतर बच्चा मात्र शिक्षा को भेजा जाता है। मात्र भी इस उद्योग के द्वारा लाखों व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में लगभग १ लाख व्यक्ति इस उद्योग में मग्न हैं। चामड़ाओं के चमड़ा को बसाने व रंगने के काम में मुधार करने के लिए प्रदक्षीय सरकार ने ज. व. की है और उसी प्रशिक्षण (Training) सम्बन्धी व्यवस्था की है। हम वर्ष चमड़ा उद्योग के लिये १४२ चलने-फिरने केन्द्र स्थापित कर रहे हैं।

काँच की खूडी का उद्योग—काँच की खूडी बनाने के मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश, मद्रास और पूना हैं। इस उद्योग में लगभग ५०,००० मनुष्य कार्य-मग्न हैं। गन् महाबुद्ध के पूर्व मुद्रियों की ८० प्रतिशत मात्र की पूर्ति उत्तर प्रदेश के अकेले नगर किरौआबाद में होती थी, मात्र का ११ प्रतिशत विदेश में आयात होता था और १ प्रतिशत भारत के अन्य प्रांतों में। काँच के मात्र के दाने भारतवर्ष में कई एक स्थानों पर बनाये जाते हैं। इसका प्रधान आह्ला बम्बई में बनता है।

तेल पेरने का उद्योग—अत्यंत बड़ा एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। यह व्यवसाय संचालित किया जाता है। ये मात्र लकड़ी के कोष्ठ की सहायता में गन् पेरते हैं। निराल में ग तेल निकालने के पदचान को खली रह जाती है वह पशुओं का निमान और मात्र के काम में प्रयुक्त की जाती है। गन् कुछ वर्षों में इस उद्योग को भी मात्र द्वारा विकसित हुए तेल की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है जिससे उद्योग को कुछ हानि भी हो रही है। इस उद्योग की उत्पत्ति करने में लिये प्रचलित भारतीयों के प्राम उद्योग मध्य तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग की अग्र में प्रयत्न किया जा रहा है। इस कार्य में लिये ४५ आदर्श उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और वे हजारों में भी अधिक मुषों के निमान की आनिता में उत्पादन शुरू किया गया है। गाँवों में तैयार तेल के लिये १५० विक्री एजेंसियाँ खोली गई हैं।

गुड़ बनाने का उद्योग—गुड़ बनाना किसानों का सीमधी सहायक व्यवसाय है। जहाँ गन् की खेती की जाती है वहाँ किसान लोग मक्खनी या लोहे की बरतों की



गुड़ का गुड़ उद्योग

सहायता में गर्म का रंग निकाल कर भट्टी पर कड़ाहों में रंग पका कर गुड़ में गार कर लेते हैं। गुड़ बनाने का कार्य परिष्कृत-साध्य होने के कारण बहुत से किसान तो मग्रा काट कर शक्कर बनाने वाले कारखानों को बेच देते हैं। अनुसंधान द्वारा यह निश्चित हो चुका है कि शक्कर की अपेक्षा गुड़ में अधिक पोष्टिक तत्व है। अस्तु, अखिल भारत-वर्षीय ग्राम्य-उद्योग संघ द्वारा गुड़ के बच्चे का अधिक प्रचार करने तथा गुड़ का उपयोग अधिक बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार गुड़ बनाने के मुख्य केन्द्र हैं।

अन्य विविध प्रकार के उद्योग—यहाँ देश के समस्त कुटीर व्यवसायों का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता। अस्तु, उपर्युक्त उद्योग-धंधों के प्रतिरिक्त जो अन्य उद्योग-धन्धे देश के विभिन्न राज्यों में प्रचलित हैं उनकी सूची नीचे दी जाती है :—गोदा बनाना, सलवे-मिचारे का काम, माथुन बनाना, स्याही बनाना, मुद्रस्थित तैल व इन बनाना, कागज बनाना, पीछी बनाना, कुचड़ पानन, दुग्धधाना भण्डव्ही व्यवसाय, रस्सियाँ बनाना, चटाईयाँ तथा टोकरियाँ बनाना, बेंग की महायता से मेज-कुर्सी, डलियाँ और सगकड़ा में गूँडे बनाना, सहद इकट्ठा करना, शाकशाकी पैदा करना पावत कूटना, चादि आदि।

कुटीर उद्योगों की समस्याएँ एवं उपाय

देश के श्रमिकों का लगभग ८५% भाग कुटीर उद्योग-धन्धों में व्यस्त है, अतः यह स्पष्ट है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में इन उद्योग-धन्धों का कितना भारी महत्त्व है। समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री निरन्तर इनकी उन्नति का चिन्तन कर रहे हैं और केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहते हैं। भारत में कुटीर उद्योगों के विकास के मार्ग में घनेको बाधाएँ हैं। इस विषय पर दृग्दर्शकों की औद्योगिक एवं आर्थिक भूमिति, राजकीयोंय आयोग (पिम्कल कमीशन) ने अपनी विमल विवेचना दी है। इन सबसे मतानुसार इन उद्योग-धन्धों की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्नलिखित हैं :—

१. आवश्यक पूँजी की कमी—कुटीर उद्योग को चलाने वाले शिल्पकारों के लक्ष्य धष्ट मात्रा में पूँजी का नहीं मिलना सबसे प्रथम समस्या है। यद्यपि उन्हें थोड़ी ही पूँजी की आवश्यकता होती है, परन्तु यह भी उन्हें सुबसता में उपलब्ध नहीं हो पाती। विश्वास में उन्हें बहुत ऊँची ध्याज-दर पर मंजूरियों से स्पर्धा उभार लेना पड़ता है। इतना ही नहीं कुछ साहूकार तो कारीगरों से ऊँचा मूल्य लेकर उन्हें बच्चा भात देने हैं और कम मूल्य में कारीगरों द्वारा बना हुआ भात लेते हैं।

इस समस्या को हल करने के लिये 'केन्द्रीय वॉलिंग जॉइंट कमिटी' ने दृढ़ मन प्रकट किया कि कारीगरों को अपनी सहकारी समितियाँ स्थापित करने चाहिए। प्रांतीय औद्योगिक अर्थ-प्रवर्धक मण्डलों की स्थापना इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इन दिशा में थोड़ा कार्य अवश्य हुआ है, जहाँ इस प्रकार का प्रांतीय मण्डल स्थापित हो चुका है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में उद्योगों को सरकारी सहायता देने के सम्बन्ध में ध्याननिवम बनाये गये हैं।

२. उचित प्रकार के माल का अभाव—हमारे कारीगरों को पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर अच्छी किस्म का वच्चा भात भी साधारणतया नहीं मिल

पाता। विरोधकर, युद्धकाल और युद्धोपरान्त वच्चं माल के प्राप्त होने की कठिनाइयाँ बड़ गर्व है।

कच्चे माल की समस्या को सहकारी समितियों द्वारा सुगमता में हल किया जा सकता है। यह समितियाँ थोक भाव पर मान सरीस कर अपने सदस्यों को कम मूल्य पर दे सकती हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय कुटीर उद्योग उप-समिति की सिफारिश मराठनीय है। उसके अनुसार ऐसी मिल्की की सस्या में वृद्धि की जाय जो केवल मूल तैयार करके हाथ से बचका बुनने वालों की भाँग की पूर्ति करे तथा जो मिल्में बिलमाल है व अपना तैयार किया हुआ सूत का कुछ भाग कारीगरों को भी देवे।

३. कुटीर उद्योगों के अनुकूल मशीनों एवं औजारों का अभाव—वैसे तो कुटीर उद्योगों में मशीनों और औजारों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, परन्तु कारीगर लोग हमने निश्चय है कि योंसे से औजार भी उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ यह आवश्यक है कि उचित मूल्य में तथा अच्छे विस्म के औजार उन्हें गरीबों का अवसर दिया जावे।

यह कार्य सहकारी समितियाँ द्वारा व्यवस्थित सम्पन्न किया जा सकता है। यदि वे चाहें तो अपने सदस्यों को औजार ग्रन्थ विप्रेय (Hire-Purchase) पद्धति पर देव सकती है। इसके अतिरिक्त हम जान की भी आवश्यकता है कि देश में ही छोटी कुटीर उद्योगों के अनुकूल छोटी-छोटी मशीनों और औजारों का निर्माण प्रारम्भ किया जाय। बिजली का विकास एवं प्रसार इस दिशा में बड़ा लाभदायक मित्र होगा।

४. साठित बाजारों की अनुपस्थिति—बहु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था ठीक नहीं है। विप्रेय-संगठन के अभाव में उन्हें अपने वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिलता।

बिक्री का कार्य सरकारी अथवा सहकारी विप्रेय समितियाँ द्वारा साप्ताहिक रूप में एकलनापूर्वक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कुटीर-उद्योग समिति ने १९३७ में केन्द्रीय विप्रेय (मार्केटिंग) संगठन स्थापित करने की प्रमुख गम्पनि की। प्रत्येक प्रान्त में विप्रेय मण्डल बनाने पर उनकी साक्षात् प्रत्येक गाँव में खोना आवश्यक है। घाट एण्ड लाफ्ट एम्पोरियम लखनऊ, स्वदेशी स्टोर बम्बई तथा कॉमिंग्सल म्यूजियम कलकत्ता जैसी संस्थाओं का कार्य इस दिशा में अनुकरणीय है।

५. कुटीर कारीगरों में संगठन का अभाव—मुख्यतः सभी का अभाव हमारे वर्तमान कुटीर-उद्योगों की भारी कमजोरी है। बिना सुगमठित मध्यों के वे अपनी कठिनाइयों का उचित अधिकारियों के सम्मुख नहीं रख सकते और न अपना मुद्धार ही कर सकते हैं। अस्तु कुटीर कारीगरों को 'विन्ड्स' के रूप में सुगमठित किया जाय। इस प्रकार के सब अर्थात् गिल्ड्स काशीर में स्थापित हो चुके हैं। अन्य राज्या में भी इनका अनुकरण वाछनीय है।

६. विदेशी वस्तुओं के आयात और देश में वृद्ध उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता—इस समय कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को विदेशों में आयात की हुई वस्तुओं और देश में बड़े-पड़े कारखानों द्वारा निर्मित वस्तुओं से सामना करना पड़ता है। हमने गिने सबसे अच्छा सुभाव यह है कि आयात वस्तुओं की सूची को जाँच की जाय और उन वस्तुओं का आयात रोक कर दिया

जाय जो यही कुटीर उद्योग में प्राप्त हो सकती है तथा जिनके निर्माण के लिये देश में ही कुटीर उद्योगों का विकास हो सकता है। जिसमें हमारे कुटीर उद्योग साधारण की हुई वस्तुओं की प्रतियोगिता में निर्भय हो जायें। जहाँ तक देश के ही बृहत् उद्योगों की प्रतियोगिता का प्रश्न है उत्पादन-कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि कुछ उपभोग की वस्तुएँ केवल कुटीर-उद्योगों द्वारा ही बनाई जायें और किसी विनोद वस्तु के उत्पादन को प्रारम्भ करने के लिये कुटीर उद्योगों को ही अवसर दिया जाय। इसमें अतिरिक्त, किसी वस्तु के विभिन्न भागों को कुटीर उद्योगों द्वारा बनाय जायें और उनमें संयोजन का कार्य बड़े कारखानों द्वारा कराया जाय।

७. उत्पादन स्तर एक मान के किस्म की समस्या—कुटीर उत्पादन के स्तर एक मान को किस्म में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये हमें उत्पादन का प्रमाणीकरण, नवीन कार्य प्रणाली, उत्तम मशीनों का प्रयोग, लालच में सुधार आदि बातों को अपनाना चाहिये। उत्पादन रत्ना एवं डिजाइन्स में अनुसंधान द्वारा सुधार करना इन उद्योगों में भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बड़े कारखानों में। इस कार्य के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ तथा अनुसंधानशालाएँ बड़ी सहायता प्रदान कर सकती हैं।

८. कुटीर उत्पादन के विज्ञापन का अभाव—कुटीर उत्पादकों के माध्यम इन सीमित हैं कि वे अपनी वस्तुओं को विज्ञापित नहीं कर सकते जिसमें उन्हें अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इस दृष्टिकोण से उनको सरकार द्वारा सहायता चाहनीय है। सरकार को चाहिये कि कुटीर कारीगरों की वस्तुओं का उचित रीति में विज्ञापन हो। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिये विविध प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाय और औद्योगिक प्रदर्शनीया में तथा मेन्सों में कुटीर वस्तुओं का पर्याप्त प्रचार किया जाय।

९. कुटीर कारीगरों में शिक्षा का अभाव—अधिकांश कारीगर साधारण लिपि पढ़ना भी नहीं जानते। इस कारण उनमें नये तथा आकर्षक ढंग से काम करने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। अतः, इस बात की आवश्यकता है कि कम-से-कम प्राथमरी शिक्षा ही अनिवार्य करदी जाय। अधिक से अधिक औद्योगिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की जाय। यह वर्ष भारतवर्ष के जापान के कुछ दिग्गजों की सामर्थ्य किया था जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों में काम में काम जाने वाली विभिन्न प्रकार की ५० मशीनों का उपयोग भारतीयों की सिखाया था।

१०. प्रदर्शन-कार्य एवं अनुसंधानशालाओं का अभाव—न तो औद्योगिक और डिजाइन्स आदि का प्रकार प्रदर्शन द्वारा अपनी भाति हो सकता है। अनुसंधान-शालाओं के स्थापित होने से लोगों को इन वस्तुओं के उचित प्रयोग का परिचय कराया जा सकता है। औद्योगिक आयोग के सिफारिशों की वि कारीगरों को व्यवसायिक शिक्षा देने के हेतु राज्य द्वारा प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किये जायें। जिनका भी और सुधार महत्त्व में भी औद्योगिक शिक्षण के सिफारिश जाय जिससे कि बंदी जेल से छूटने पर कारीगर अपने बंद अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

११. कुटीर कारीगरों की निर-रता, अज्ञानता एवं रहिवादिता—निरक्षरता, अज्ञानता एवं रहिवादिता आयाय्य मान्यता का दोष है। सामान्य जन-मता-वीरता सम्पत्ती शिक्षा के प्रकार से अज्ञानता एवं मनीषिता दूर की जा सकती है।

१२ सगठन एवं सहाय्य का अभाव—वर्तमान समय में कुटीर उद्योग अमर्यादित अवस्था में है। इसी विषय उद्देश्य तथा विदेशीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। सगठन एवं सहाय्य का अभाव के कारण कुटीर उद्योग में ही नहीं है अपितु नरु एवं कुटीर व्यवसायों और वृहत् व्यवसायों के मध्य भी है। प्रस्तुत यह आवश्यक है कि नरु उद्योगों के लिए कच्चा माल गावां में कुटीर एवं मध्यम प्रकार के व्यवसायों में तैयार होकर वृहत् उद्योगों में अंतिम निर्माण के लिये आना चाहिये। इस प्रकार कुटीर एवं वृहत् उद्योगों के मध्य गाम्भीर्य स्थापित किया जा सकता है।

१३ उत्पादन के हानिकारक एवं स्पर्धी ढंग—उत्पत्ति के मदक्ष एवं हानि कारक ढंग और उनके परिणाम स्वल्प उत्पात्ति की ऊँची लागत भारतीय कुटीर उद्योगों की एक दुमरी समस्या है। सस्ती विजली के प्रयोग तथा शिल्पकारों के प्रतिभामय यह समस्या हल की जा सकती है। भारतवर्ष में विद्युत् शक्ति के प्राकृतिक भावन बहुत हैं। इसलिये यदि गावां में भी छोटे-छोटे कुटीर उद्योग विद्युत् मयिन से चलने लगें, तो कुटीर उद्योगों की वस्तुएँ सस्ती और अल्प परिश्रम से बन सकती हैं। साथ ही साथ बाजारों को उत्पादन के प्राकृतिक ढंगों में परिचित किया जाना चाहिये। प्रधान तथा म उत्पादन व्यय की रकम करने के प्रयत्न लिये जाने चाहिये।

१४ सरकार द्वारा सहाय्य एवं प्रोत्साहन का अभाव—भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने तक ब्रिटिश शासन भारतीय कुटीर धंधा के प्रति उदासीन ही रहा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों की दुर्दशा हो गई। भयंकरता में सरकार द्वारा कुटीर व्यवसायों की उन्नति के लिए निम्न तीन नियम आन लिए जाते हैं। सामान्यतया हानि, जापान वगैरहों और बेनिजियम इनमें कुछ उदाहरण हैं। जापान सरकार ने इस प्रकार नई नई सहाय्य देती रही है। और भारत सरकार द्वारा भी इस आशय से कुछ उपाय जा रहे हैं।

कुटीर उद्योग एवं सरकार—छात्र वर्गों के उद्योगों का सगठन करने का अधिक प्रयत्न राज्य सरकारों पर है। उनकी सहाय्य के बिना केंद्रीय सरकार ने निम्न सगठन स्थापित किये हैं अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीणीय मण्डल, पञ्च उद्योग मण्डल, तारिखत जल मण्डल तथा केंद्रीय गैस मण्डल। सन् १९५७-५८ में छात्र वर्गों के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिये ३२० करोड़ रु० के ऋण तथा ११० करोड़ रु० के अनुदान का स्वीकृति दी गई है। प्रत्यक्ष ७० औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें मई १९५८ तक ५७ औद्योगिक संस्थाओं के लिए योजना में निर्वाचित छान १० करोड़ रु० में बाँटकर १५ करोड़ रु० बँट गई है। केंद्रीय सरकार ने औद्योगिक विस्तार मंत्रालय के द्वारा उद्योगों को प्राविधिक सहाय्य देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में मुद्रा कटन तथा अन्य विषयों की व्यवस्था के लिए १९५२ में स्थापित अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल ने देश तथा विदेश दोनों देशों में विविध रूप में ध्यान दिया है। इस मण्डल के निर्वाण प्रोत्साहन स्वरूपी कुछ कार्यो के लिए भारतीय दस्तकारी विभाग निगम स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में दस्तकारी नग्राह बनाये जाते हैं। प्रतिवर्ष १ अरब रुपय के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रतिवर्ष १ अरब रु० के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

फोर्ड फाउण्डेशन—कुटीर उद्योगों की आर्थिक एवं शिल्पिक दशा को सुधारने के लिये फोर्ड फाउण्डेशन के नेतृत्व में एक शिल्पिक समिति बुलाई गई थी जिसकी सिफारिशों के अनुसार शिल्पिक सुविधाओं का कार्यक्रम नैऋत्य सरकार ने बनाया है। इस कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय इन्स्टीट्यूटों की स्थापना क्रमशः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में की गई है। इनकी चार शाखाएँ होगी जिनमें से एक शाला की स्थापना त्रिवेन्द्रम में की गई है। इन शाखाओं में शिल्पिक सुविधाएँ देने के लिये विदेशी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम (National Small-Scale Corporation)—भारत सरकार ने फरवरी १९४५ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की है जिसका उद्देश्य लघु-उद्योगों की उत्पत्ति करना, उनका संरक्षण, आर्थिक सहायता तथा अन्य सहायता देना है। निगम की पूँजी १० लाख रुपये है जो १०,००० शेरो में विभाजित है। यह निगम केवल ऐसे लघु-उद्योगों की सहायता देगा जो शक्ति का प्रयोग करते हों, परन्तु उनमें १०० से अधिक व्यक्ति काम न करते हों तथा उनकी पूँजी ५ लाख ६० से अधिक न हो। इस निगम के चार प्रमुख विभाग हैं—(१) सरकारी खरीद विभाग, (२) निर्यात द्वारा खरीद विभाग, (३) हाट-मार्केट विभाग और (४) औद्योगिक बस्ती विभाग। हाट-मार्केट विभाग की ओर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में निम्नलिखित बस्तियाँ चलाई जा रही हैं। ये बस्तियाँ निश्चित मार्गों पर चलती हैं और इनमें लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई ३०० से अधिक चीज़ें होती हैं। राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार सहायक निगम जौल गये हैं।

पञ्चवर्षीय योजनाएँ और कुटीर उद्योग—द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास के लिये २०० करोड़ रु० का आयोजन है जबकि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में १५ करोड़ रु० का आयोजन प्रारम्भ में किया गया था यद्यपि वास्तव में ३१२ करोड़ रु० लग् १९४१-४६ तक खर्च किये गये।

राय सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मेलन नई दिल्ली में १ जुलाई, १९४२ ई० में हुआ जिसमें यह निर्णय किया गया कि यह प्रतिनिधि सम्मेलन आर्थनायिक हुआ करे जिसमें कुटीर एवं लघु व्यवसायों के विकास के विविध पहलुओं पर विचार किया जाए और कुटीर उद्योग बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कार्य की प्रगति पर दृष्टि डाली जाय।

भारतवर्ष में फैक्टरी उद्योग अथवा कुटीर उद्योग (Factory Versue Cottage Industries in India)—आधुनिक उत्पादन-व्यवस्था द्वारा होने वाले विविध लाभों से कभी-कभी यह भ्रम हो जाता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इतने मुकाबले में किश प्रकार स्थिर रह सकते हैं। भारतवर्ष में गांधी-विचार-धारा वाले इनमें अविश्वास प्रकट करते हैं। दूसरी ओर वर्तमान विचारधारा वाले केवल गहरे औद्योगीकरण में ही विश्वास रखते हैं।

इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है कि कुछ उद्योग-धन्धे ऐसे हैं जो छोटे पैमाने पर ही सत्ताम चलाने जा सकते हैं और जिनके लिये मशीनों का प्रयोग अनुपयुक्त है।

उदाहरणार्थ

(१) वे उद्योग-धन्धे जिनमें मशीनों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। जैसे बीड़ी बाँधने का धंधा आदि।

(२) वे उद्योग धन्ये जिनमें उच्च श्रेणी की कला की आवश्यकता होती है। जैसे जरी, बेस वूटे व कढ़ाई का काम, चित्रकारी आदि।

(३) वे उद्योग-धन्ये जिनमें व्यक्तिगत इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिये, दर्जों का घना, मोवाकारों का काम आदि।

(४) वे उद्योग धन्ये जो प्रयोगात्मक अवस्था (Experimental Stage) में हैं। उदाहरणार्थ, अमरिका में फोर्ट मोटर का कारखाना प्रारम्भ में छोटे पैमाने पर ही स्थापित हुआ था।

(५) वे उद्योग-धन्ये जिनमें व्यक्तिगत देख-रेख की आवश्यकता होती है, जैसे दर्जों व हुताबाह का काम।

(६) वे उद्योग धन्ये जिनके द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं की माँग बहुत सीमित या अनिश्चित हो, जैसे जवाहरात का काम।

(७) वे उद्योग धन्ये जो बड़े कारखानों के साथ-साथ सहायक धन्यो के रूप में आवश्यक होते हैं, जैसे मशीनों की मरम्मत का काम।

(८) वे उद्योग धन्ये जिनमें कारीगर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अनुकूल वित्तव्यवस्था में काम करना चाहते हैं।

इसके विपरीत कई उद्योग-धन्ये ऐसे हैं जो बड़े पैमाने की उत्पाति और मशीनों के प्रयोग के लिये ढाबुल है और जिनका छोटे पैमाने पर गन्व रहित चलाना असम्भव या हानिकारक होता है।

उदाहरणार्थ

(१) रेल, माटर, जहाज आदि बनाने के कारखाने।

(२) जन-विद्युत् उत्पन्न करने के कारखाने।

(३) लोहा और इस्पात आदि के आपारभूत कारखाने।

(४) देश रक्षा के आवश्यक उद्योग धन्ये, जैसे गोला, बारूद, ध्वज बनाने के कारखाने।

(५) यातायात उद्योग, जैसे रेल चलाने का कार्य।

(६) वे उद्योग-धन्ये जिनके द्वारा निमित्त वस्तुओं की माँग विस्तृत हो, जैसे वस्त्र उद्योग आदि।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि बहुत एव कुटीर व्यवसायों का हमारे देश की आर्थिक-व्यवस्था में एक विधित स्थान है और रहेगा। इनके द्वारा लाखों अनुभवा का जीवन-निर्वाह होता है। बड़े कारखानों के चलाने के लिये पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है, परन्तु हमारे देश में इसका पूर्ण अभाव है। अस्तु, योड़ी-योड़ी पूँजी की आवश्यकता वान छोटे कारखानों ही परिमित्वि के अनुकूल लाभदायक मिष्ट हो सकते हैं। हमारे गरीब जनसंख्या अत्यधिक है और निर्बलता सर्वव्यापी है, अतः मनुष्यों को काम-धन्ये देने के लिये विविध कुटीर उद्योगों की स्थापना वांछनीय है। आर्थिक उत्पत्ति के अन्तर्गत जो अमी बेकार हमारे कुटीर उद्योग-धन्ये में समाये जा सकेंगे। इन सबके उपरान्त, बड़े परिमाणों की उत्पत्ति की कुछ सीमाएँ (Limitations) हैं जिनसे कारण उत्पादन के परिमाण में किसी असीमित अवस्था तक वृद्धि होता सम्भव नहीं है। मद्योप में, लघु एव वृहत् उद्योगों का अपना दृष्ट-क्षेत्र है। वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर सहाय्यी एव पूरक हैं। अस्तु, हमारे देश में दाना का एक साम विकास निम्नलिखित आवश्यक है। इन्धन, सधुक्त-उद्योग-अमरिका, फास, जर्सी, आपान आदि

भौद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में जो इन उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है वह इस बात को और भी स्पष्ट एवं पुष्ट कर देता है ।

निष्कर्ष—हमारे देश में जनसंख्या अत्यधिक है तथा वहाँ पूँजी और भौद्योगिक मशीनों एवं विशेषज्ञों का अभाव है । यहाँ के कारीगरों में सैकड़ों वर्षों की जीवित कला-परम्परा भी है । इसलिये भारत में कुटीर उद्योगों का विकास प्रत्यन्त आवश्यक है तथा उपयोगी सिद्ध होगा । कारीगरों के व्यक्तित्व के विकास तथा स्वास्थ्य के लिये भी गृह-उद्योग हितकर है अतएव राज्य तथा जनता के परस्पर सहयोग में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीयीय योजना बनाई जाकर कार्यान्वित होनी चाहिये जिससे हमारे देश के मूलभूत गृह-उद्योग पुनः जी उठें और लाखों बेकार कारीगरों का भरण-पोषण हो सके । साथ ही चीन की भाँति 'इण्डुस्को' (Indusco) भौद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जायें जिससे हमारे कुटीर उद्योगों की कई समस्याएँ हल हो सकेंगी ।

अभ्यासाथ प्रश्न

इण्टर आर्टस् परीक्षाएँ

- १—उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग-धन्यों पर एक टिप्पणी लिखिये । उनकी उन्नति के लिये प्रदेश सरकार क्या-क्या प्रयत्न कर रही है ? (१९५७)
- २—हमारे देश के प्राथमिक जीवन में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? उनके विकास तथा उन्नति के लिये आप क्या सुझाव पेश करेंगे ? (रा० बो० १९६०, ५७)
- ३—बड़े उद्योगों के होड़ करने पर भी भारतीय कुटीर उद्योग क्यों तथा कैसे जीवित रहे ? प्रकाश ढालिये । (प्र० बो० १९५७)
- ४—भारत में कुटीर उद्योगों को जीवित रखने की क्या सम्भावनाएँ और कठिनाइयाँ हैं ? (पटना १९५२, प्र० बो० १९५२)
- ५—भारत में कुटीर उद्योगों की अवनाति के कारण बताइये और उनके सुधार के सुझाव दीजिए । (म० भा० १९५२)
- ६—क्या आप भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के और अधिक विकास के पक्ष में हैं ? कुटीर उद्योगों और व्यावसायिक श्रम पर इसके क्या प्रभाव होंगे ? (दिल्ली हा० से० १९४९)

‘उद्योग व्यापार की आत्मा है और समृद्धि की आधार शिला है।’

—रॉबर्ट ब्लेक

ऐतिहासिक परिचय—हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि प्राचीन समय में भारत अपनी औद्योगिक उन्नति के लिये प्रसिद्ध था। परन्तु यूरोप की औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के फलस्वरूप मशीना स बहुत सस्ता माल बनने लगा जिसके कारण भारतीय गृह-उद्योग पर बड़ा आघात पहुँचा। अब भारत को पश्चात्तय ढंग पर बड़ बड़ कल-कारखाने स्थापित करने पड़े। मगज़ के लिये भारत कच्चा माल खरीदने और अंग्रेज़ी कारखाना का तैयार भास बेचने के लिये प्रच्छा बाज़ार था। इसलिए वह भारत में औद्योगीकरण के विरुद्ध रहे जिसके कारण इन उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारतीय उद्योगों को प्रथम व द्वितीय विश्व महायुद्ध में अधिक प्रोत्साहन मिला जिसके कारण आज कुछ उन्नति दृष्टिगोचर होती है। इस समय भारत में सूती वस्त्र, जूट शकर लोहे व फोसाद, सीमेन्ट आदि के बड़े बड़े कारखाने हैं जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं लाभ (Need and Benefits of Industrialization)—जनसंख्या का दृष्टि पर अत्यधिक अवलम्बन भारतीय प्रायिक जीवन को बड़ी भारी कमी है। यहाँ उद्योगों का अभाव है। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था संतुलित एवं स्थिर नहीं है। अस्तु, अभीष्ट सन्तुलन की प्राप्ति के लिए देश में शीघ्र औद्योगिक विकास अत्यावश्यक है। देश की दरिद्रता दूर करने तथा देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिये भी यह कम आवश्यक नहीं है। देश की नव प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये उद्योगों का विकास और भी आवश्यक है।

औद्योगिक आयोग (१९१६-१८) के शब्दा में औद्योगीकरण के लाभ सन्निहित हैं। “औद्योगिक विकास देश के लिये बड़ा हितकर मिट्ट होना, क्योंकि इससे धन के नवीन साधन प्रस्तुत होंगे, पूँजी के संचय में वृद्धि होगी, राज्य की आय बढ़ेगी, धन की अधिक लाभदायक काम मिलना दृष्टि के अस्थिर नाशा पर देश का अत्यधिक अवलम्बन कम हो जायगा और अन्त में राष्ट्रीय जीवन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राष्ट्रीय चरित्र का विकास होगा।”

भारतीय औद्योगिक अवनति के कारण (Causes of Industrial Backwardness of India)—भारतवर्ष में राष्ट्रीयीय दरिद्रता, न्यूनतम जीवन-स्तर, अत्यधिक जनसंख्या आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अस्तित्व हमारे औद्योगिक

अवतति मे सन्निहित है। यहाँ हम भारतीय औद्योगिक अवतति के कुछ कारणों पर दृष्टिपात करेंगे :—

१. प्रेरक शक्ति के अग्र्याप्ति साधन—यद्यपि भारतवर्ष प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न है, परन्तु कोयले और तेल की दृष्टि में स्थिति असन्तोषजनक है। जल शक्ति का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है।

२. उत्कृष्ट कच्चे माल का अभाव—कई कारखानों का चलाने के लिये उच्च कोटि का कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। जैसे, वस्त्र उद्योग के लिये मश्वरे किस्म की रई उपलब्ध नहीं होती। चीनी के उद्योग के मार्ग में कच्चे की प्रति एकड़ कम उपज और किस्म की कुरावों वगैरे अवरोधक है।

३. अज्ञिपुर्ण मानव शक्ति—अन्य उन्नत देशों की भाँसा हमारे यहाँ की मानव शक्ति (Man Power) कम विपुल है। इसका कारण पाषाण एवं विशिष्ट ज्ञान का अभाव है।

४. पूँजी के अग्र्याप्य साधन—भारतवर्ष में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करने के लिये पर्याप्त पूँजा उपलब्ध नहीं है। विदेशी पूँजी से औद्योगीकरण खनने से सावधानी है।

५. धोरण संगठनकर्त्ताओं और साहसियों का अभाव—श्री गिर्लाई के अनुसार “देश को समीचीन प्रावश्यकता प्रवर्धन, मार्गदर्शक और साहसियों की है।” प्रो० मारशल ने बहुत समय पूर्व लिखा था कि “यदि भारतवर्ष में डाटा जैसा एक या दो बड़ी व्यक्ति और जापानियों जैसे कुछ हजार उत्साही मनुष्य हों, तो यह शीघ्र ही एक बड़ा राष्ट्र बन जायगा।”

६. घातक निर्वाप नीति—सन् १९२३ तक ब्रिटिश सामन की निर्वाप नीति (Laissez Faire Policy) भारतीय औद्योगिक विकास के लिये हानिकारक सिद्ध हुई। इसके परचाय उनका संरक्षण की नीति भी असन्तोषजनक हो रही।

७. दूषित रेल भाडा नीति—घरेलू के राज्य तक हमारी रेलों की किराया नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक हो रही। इससे विदेशी माल को प्रोत्साहन मिलता रहा।

८. सुव्यवस्थित बाजारों का अभाव—माल की बिक्री के लिये सुव्यवस्थित बाजारों का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था से औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

९. विज्ञापन के दूषित ढंग—वास्तव में देखा जाय तो भारतवर्ष में विज्ञापन कला में सुविशित व्यक्तियों का अभाव है। आधुनिक व्यापार एवं औद्योगिक विकास इस ही पर स्थिर है।

१०. आधारभूत उद्योगों का अभाव—हमारे यहाँ अधिकतर उपभोक्ताओं की वस्तुओं के निर्माण करने वाले कारखानों का ही विकास होना है। आधारभूत उद्योगों (Key Industries) में केवल लोहे और फौलाद व सीमेन्ट के उद्योगों ने बड़ी उन्नति की है। रसायन, विजली का सामान, औजार, हवाई जहाज, मोटर आदि के कारखानों का पूर्ण अभाव है।

११. विदेशों पर आश्रितता—हमें मशीनों, रसायन, औजारों आदि वस्तुओं के लिये विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। यह परिस्थिति अवाञ्छनीय है।

१२ योजना-रहित उद्योगों का विकास—हमारे यहां के उद्योग देश में ठीक प्रकार नहीं चले हुए हैं। अधिकतर कारखाने बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि में ही केन्द्रित हैं।

१३ सहायक उद्योगों का अभाव—उप-उत्पत्ति (By-Product) के सदुपयोग के लिये सहायक व्यवस्था आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, ये संबन्धी श्रमिकों के जीवन यापन के साधन हो सकते हैं।

औद्योगिक विकास के उपाय (Measures for Industrial Development) — औद्योगिक व्यवस्था के कारणों को दूर कर विकास की धार में जाने वाले कुछ उपाय नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं।—

(१) सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा, (२) औद्योगिक विकास को योजना (Plan) तैयार कर कार्यान्वित करना, (३) आधारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना, (४) साधारण एवं तकनीक (Technic!) शिक्षा की व्यवस्था करना, (५) औद्योगिक अर्थ-प्रवर्धन (Industrial Finance) का समुचित प्रबंध करना, (६) विभेदक सुरक्षण (Discriminating Protection) नीति को अपनाना, (७) रेल आळा नीति में उचित परिवर्तन करना, (८) जल विद्युत् साधना का पर्यटन विकास करना, (९) सरकार की स्टोर-जब नीति में सुधार करना, (१०) औद्योगिक प्रशिक्षणियों की व्यवस्था करना, (११) बैंक व्यवस्था सुविधाओं का अधिक प्रचार करना, (१२) राज्य द्वारा औद्योगिक अनुसन्धान एवं प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन तथा प्राथमिक सहायता मिलाना, (१३) औद्योगिक श्रम की दशा में सुधार करना, (१४) प्रवायु समिष्टपुंज प्रणाली (Managing Agency System) में आवश्यक सुधार करना।

भारत के प्रमुख वृहद उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry) — यह भारत का सबसे प्रमुख उद्योग है। सन् १८१८ ई० में सबसे पहले कलकत्ते के समीप फोर्ट ग्लोस्टर (Fort Gloster) में एक सूती कपड़े की मिल चालू की गई। पर कलकत्ता सूती कपड़े के लिये उपयुक्त स्थान न था। इस कारण बम्बई में सूती कपड़े की मिल सन् १८५४ ई० में चालू हुई। शीघ्र ही यह उद्योग पूंजी और वातावरण की सुविधाओं के कारण बम्बई प्रांत में केन्द्रित हो गया। सन् १८७७ ई० के पश्चात् नागपुर, घट्टमदाबाद और बालापुर के कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में भी कपड़ा मिल उद्योग विकसित होने लगा। बाद में स्वदेशी आन्दोलन ने इसे और प्रांतों में बढ़ने में सहायता दी। शीघ्र ही मद्रास, बड़ौदा, जमशेद, इन्दौर, भागल, दिल्ली, मद्रास, कोयम्बटूर, मडुरा आदि नगर कपड़ा मिल उद्योग के केन्द्र बन गये। इस उद्योग की सन् १८१५ में ११-०९ तक प्लेग, अमेरिकन हर्ड के मूल्य में वृद्धि होना तथा चीन के आक्रामक में घटवृद्ध हो जाने के कारण कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। सन् १९०७ के पश्चात् सामान्यतया यह उद्योग उत्पत्ति की ओर अग्रसर रहा और प्रथम महायुद्ध के समय में तो इस उद्योग में बड़ी उत्पत्ति थी। सन् १९२५ के पश्चात् सावर्भौम मन्त्री, भीषण जापानी प्रतिस्पर्धिता और ऊँचे स्तानीय करों के कारण इस उद्योग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सन् १९२७ ई० में इसे सुरक्षण (Protection) दिया गया और सन् १९३१ ई० में इस विरोधकर जापानी कपड़े के लिये और बड़ा

दिया। द्वितीय महायुद्ध ने पुनः कपड़ा मिल उद्योग को विस्तार का स्वर्ण अवसर प्रदान किया।

सन् १९३६ के आरम्भ में ४८२ सूती वस्त्र मिलें (१८८ सूत बनाने वाली और २९४ निधित) जिनमें १३४१ लाख तंतुओं और २०१ लाख करघा पर काम हो रहा था, जनवरी १९५६ में मिला की मर्यादा घट कर ४७६ (१८७+२८९) हो गई। इनमें लगभग १२२ करोड़ रु० का निवेश हुआ है तथा लगभग ८६ लाख मजदूर काम कर रहे हैं। सन् १९५६ में १०७२ लाख पीठ सूत तथा ४ लाख ६२ लाख ७० हजार वस्त्र उत्पन्न हुआ।

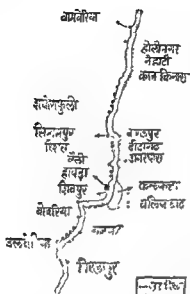
भारत इस समय विश्व के प्रमुख वस्त्र बनाने वाले देशों में से है। रुई की सपट के अनुसार इसका चौथा स्थान है। फिर भी हमारे औद्योगिक प्रति व्यक्ति कपड़े की सपट केवल १२ यज है जोकि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

सूत एवं सूती वस्त्र का उत्पादन

वर्ष	सूत (लाख पीठ)	सूती वस्त्र (लाख पीठ)
१९४७	१२,६६०	३७,६२०
१९५०	११,७५०	३९,६७०
१९५५	१६,३०८	५०,६४०
१९५६	१६,७१२	५३,०६६
१९५७	१७,८०१	५३,१७४
१९५८	१६,८५४	४६,२७०
१९५९	१७,१८८	५०,६४०

योजना और मिल-वस्त्र उद्योग—प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५२,००० लाख गज कपड़ा और १६,००० लाख पीठ सूत का उत्पादन हुआ जबकि दूसरी योजना में १६,५०० लाख पीठ सूत और ८२,००० लाख गज (१८ यज प्रति व्यक्ति) कपड़ों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है।

जूट उद्योग (Jute Industry)—भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग जूट का है। मसूर का अधिकांश जूट पूर्वी बंगाल में होता है। सतएव जूट की मिलें सब कलकत्ते में या बनबत्ते के समीप हुगली नदी के किनारे पर ४० मील के घेरे में स्थित हैं।



होली नदी के किनारे जूट मिल

प्रारम्भ में जूट उद्योग पर यूरोपियन पूँजीपतियों का पचावसत्य था परन्तु मान्य स्वतन्त्र होने के पश्चात् जूट मिलों भारतवाधियों के हाथ में आगई है। देश का विभाजन में इस उद्योग को बड़ा धक्का पहुँचा है। हमारे जूट का दो तिहाई उत्पादन क्षत्र पाकिस्तान में जाता गया, जबकि जूट के सारे कारखाने भारतवर्ष में थे। भारतीय रुपये के अयमूल्य (Devaluation) और पाकिस्तान के घपते रुपये की दर त धड़ाने से भीषण गतिमय उत्पन्न हो गया था १६ महीने तक जारी रहा। वर्षा १९५१ में भारत और पाकिस्तान के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों का हानि से क्षत्र पाकिस्तान में जूट का आयात प्रारम्भ हो गया है।

भारत में जूट का उद्योग सत्रम अधिक सघटित है। इण्डियन जूट मिनिम एसीनियेशन (I. J. M. A.) इस उद्योग की उत्पत्ति के निम्न प्रत्यक्षीत है। भारत में इस समय ११२ जूट मिल हैं जिनमें १०१ मिल कलकत्ता में होली नदी के तट पर स्थित हैं शेष ११ भारतीय वनात व अन्य राज्यों में हैं। सन् १९२६ के आंकड़ों के अनुसार इसमें ५३.३ करोड़ रुपये की पूँजी लगने हुई है। इस उद्योग में सत्रम ३ लाख व्यक्ति कार्य-सम्पन्न हैं। सन् १९५०-५१ में लगभग १२० करोड़ रुपये का जूट निर्यात को भेजा गया। जूट मिला का वार्षिक उत्पादन १७० करोड़ ६० है।

जूट उद्योग का अविष्य बड़ा अनिश्चित है। भारतीय जूट मिलों अधिकतर कच्चे माल के लिये आधिकारिक पर निर्भर हैं। अस्तु, भारत में अधिकधिक जूट उत्पादन का प्रयत्न होता चाहिए। सन् १९५० में जूट का उत्पादन = लाख ३६ हजार टन था। हाल ही में सरकार ने गन्धमी बगान, आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में जूट की खेती में विन्मार् के लिये २६ लाख रुपये की राशि स्वीकृति की है।

सन् १८५५ ई० में सीरामपुर के निकट रिशरा में एक घरेलू में पहला जूट का कारखाना (Jute Spinning Mill) स्थापित किया। चार वर्ष पश्चात् अर्थात् सन् १८५९ ई० में सबसे प्रथम शक्ति द्वारा प्रेरित करघों (Power Looms) का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। पहले तीस वर्षों में इस उद्योग की गवर्गि रही, परन्तु प्रथम विश्व महायुद्ध में इसकी बड़ा प्रोत्साहन मिला। सन् १९२६-३० की मही में इसे खदेड़ दिया, परन्तु सन् १९३४-३६ में इसकी स्थिति में कुछ सुधार हो गया। द्वितीय विश्व महायुद्ध में पुनः इसे अनुपम लाभ प्रदान किया। इस उद्योग ने बिना सरक्षण के उत्पत्ति की।

जूट द्वारा निर्मित माल का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
१९४७	१,०५२
१९४०	७३६
१९४५	१,०२७
१९४६	१,०६३
१९४७	१,०३०
१९४८	१,०६२
१९४९	१,०५२

पुरानी एन प्रिंसी हुई मशीनें इस उद्योग की भारी कमजोरी है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) के द्वारा इस उद्योग के मयकारण के लिये ४५६ करोड़ रु० का प्रण देना निश्चित किया है।

जूट उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में जूट की वस्तुओं का उत्पादन १० लाख टन रहा जबकि दूसरी योजना में १२ लाख टन जूट की वस्तुओं का लक्ष्य रखा गया है।

लोहे और इस्पात का उद्योग (Iron & Steel Industry)—

लोहे और इस्पात का उद्योग सभी उद्योगों का आधार स्तम्भ है। भारतवर्ष का यह एक पुराना उद्योग है। दिल्ली के पास का लोहे का स्तम्भ १६०० वर्ष पुराना बताया जाता है। यह स्तम्भ इस बात का प्रमाण है कि प्रचीन काल में भारतवासियों ने लोहे और फौलाद के उद्योग में बहुत दक्षता प्राप्त कर ली थी। हमारे देश में लोहे का मशीन उद्योग बहुत देर में प्रारम्भ हुआ क्योंकि अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि इंग्लैंड के जमीन तोड़े की वस्तुओं के लिये भारत में स्थान रहे। सन् १८७४ ई० में सर्वप्रथम अरिया की बाँसा की खानों के राष्ट्रीय कारखाने, बर्गल (Bargal Iron Steel Co.)



ने औद्योगिक दम से लोहा बनाना प्रारम्भ किया था। सन् १८८६ में इस कारखाने को बंगाल प्रायद्वीप स्टील (Bengal Iron Steel Co.) में ले लिया। सन् १९०० ई० में इसने द्वारा ३५ हजार टन कच्चा लोहा (Pig-iron) तैयार हुआ, परन्तु इस इस्पात भर्षाई फौलाद (Steel) के बनाने में सफलता नहीं मिली। सन् १९०७ में

स्वर्गीय जमशेदजी टाटा ने, बिहार के सिपशूब जिले के साक्ची (Sakchi) नामक स्थान में, जो बाद में जमशेदपुर (Jamshedpur) के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क (Tata Iron & Steel Works) की स्थापना की।

देश की वकूती हुई माँग में प्रेरित एवं टाटा कम्पनी की सफलता में प्रोत्साहित होकर अन्य कम्पनियों ने भी लोहे के कारखाने खोले। इस समय भारत में निम्नलिखित मुख्य लोहे व फौवाद के कारखाने हैं —

(१) टाटा आयरन एण्ड स्टील क०, जमशेदपुर (Tata Iron & Steel Co. Jamshedpur) (TISCO)

(२) बंगाल आयरन कम्पनी लि०, हीरापुर (Bengal Iron Co. Ltd., Hirapur)

(३) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील क० लि०, बसुपुर (आसनसोल के निकट) (Indian Iron & Steel Co. Ltd., Basupur Near Asansol) (IISCO)

(४) युनाइटेड स्टील कॉर्पोरेशन, मनोहरपुर (United Steel Corporation Manoharpur)

(५) मैसूर स्टील आयरन वर्क, भद्रावती (Mysore Iron & Steel Co., Bhadravati) (MISCO)

इनके अतिरिक्त बंगाल के भास-पाम कुछ और छोटे-छोटे साह के कारखाने हैं।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् प्रतियोगिता के कारण मशीन का माँगा आया जिसके कारण सरक्षण के लिये प्राचीन वनना पड़ा। सन् १९२४ ई० में ३ वर्ष के लिये इस उद्योग को सरक्षण दिया गया। फिर सन् १९२७ ई० में ७ वर्ष के लिये सरक्षण बढ़ा दिया गया, परन्तु अब आर्थिक सहायता न देकर विदेशी मान पर आयात-कर लगा दिया गया है। द्वितीय महायुद्ध से इसे और भी प्रोत्साहन मिला। विदेशों के बड़-बड़ आर्टीलेरी ने लोहे और इस्पात के उद्योग का मूल बढ़ाया। देश में आर्जिनल फैक्टरियाँ और इंजीनियरिंग के कारखानों के मुल्यन से भारतीय साह और इस्पात की माँग और भी बढ़ गई। सन् १९५०-५१ में लोहे और इस्पात का उत्पादन ३५,८५,१३५ टन था।

टाटा का लोहे व फौवाद का कारखाना एतिया में सर्वप्रथम है। इसमें रस की पट्टरी, नक्काश के लिये लोहे के गड्ढे आदि बड़ी-बड़ी वस्तुएँ बनती हैं। हान ही में टाटा के सहिते, एचमिल आदि बनाने के लिये नई मशीनें लगाई हैं। स्टील कार्पोरेशन ऑफ बंगाल (SCOB) ने जिनकी स्थापना सन् १९२७ में हुई थी, अपने कारखाना का मूल विस्तार किया है।

इस उद्योग में २५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है, ६ लाख व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी बनाते हैं तथा सरकार का कर आदि के रूप में इसमें ८ लाख रुपया प्राप्त होता है। यहाँ यह दुहराना आवश्यक न होगा कि लोह व इस्पात का उद्योग सबसे बड़ा आयात-भूत भया है। देश की आर्थिक उन्नति इसी पर अवलम्बित है। इसमें थोड़ा ही समय में इतनी आश्चर्यजनक उन्नति करली। फिर भी इस उद्योग के विस्तार को बहुत आवश्यकता है। बड़ी-बड़ी मशीनें, औजार तथा बहिया इस्पात का सामान हम आज भी बाहर से मँगाना पड़ता है। इनका हो नहो, हमारा देश का

उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम था नहीं के बराबर है। संयुक्त-राज्य अमेरिका में इस समय १० करोड़ टन तथा ब्रिटेन में ६ करोड़ ५० लाख टन फोसफोरस तैयार होता है जबकि भारत में केवल ६ लाख टन ही होता है। भारत में इस उद्योग के जनने की बड़ी सुविधाएँ हैं। विनोदचन्द्र की राय है कि भारतीय भूगर्भ में ३० परसेंट टन सोडा भरा पड़ा है। प्राकृतिक साधनों की ध्यान में रखते हुए हमारे सोदे के विकास की बड़ी संभावना है।

इस्पात का उत्पादन

(हजार टनों में)

वर्ष	बच्चा सोडा	इस्पात
१९४७	१,३२०	८६३
१९४०	१,४६२	१,००४
१९४५	१,७५७	१,२६०
१९४६	१,८०७	१,३३६
१९४७	१,७८६	१,३४६
१९४८	२,०३०	१,३००
१९४९	—	१,७११

इस्पात के उत्पादन में सप्ताह के देशों में भारत का स्थान
(बस लाख टन)

संयुक्त राज्य अमेरिका	१००
रूस	४०
ब्रिटेन	१८
जर्मनी	१७
फ्रांस	१०
बेल्जियम	५
जापान	५
संयुक्त अधिराज्य	३
सार	३
भारत	१.२६

इस्पात उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस्पात का उत्पादन कम रहा। दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीन नये कारखाने

खीनकर तथा वर्तमान कारखानों के उत्पादन को बढ़ाकर इन कच्ची को पूरा किया जा रहा है। दूसरी योजना के अनुसार १९६०-६१ तक मैंग्रू आयरन और स्टील कम्पनी में इस्पात का उत्पादन १ लाख टन बढ़ जाने की प्राप्ति है। योजना के अन्त तक निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन-मूल्य १२० करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँच जायेगा। इसके अनिश्चित सरकारी क्षेत्र में तीन इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये हैं— (१) मरकेला (उड़ीसा) में १२० करोड़ रु० की लागत का “हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी” नामक कारखाना जर्मनी के वार्षिक व तांत्रिक सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका वार्षिक उत्पादन ७२० हजार टन होगा। (२) दूसरा कारखाना दिल्ली (मध्य प्रदेश) में हम के सहयोग में ११० करोड़ रु० की लागत का स्थापित किया गया है। इसका वार्षिक उत्पादन ७७० हजार टन होगा जो निर्यात कर दिया जायगा। (३) तीसरा कारखाना ११५ करोड़ रु० की लागत का दुर्गापुर (बंगाल) में स्थापित किया गया है। यहाँ साधारण और मध्यम श्रेणी के इस्पात का उत्पादन ७६० हजार टन हुआ करेगा।

दूसरी योजना के अन्त तक (१९६०-६१) ६० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें में ३० लाख टन निजी कारखानों के विनाम द्वारा और ३० लाख टन सरकारी कारखानों में प्राप्त किया जायगा। योजना काल में निजी कारखानों के विकास पर ११५ करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे।

चीनी का उद्योग (Sugar Industry)—सम्राट के इतिहास में गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अर्धवेद में मिलता है जिसका रचना काल ईसा के लगभग १,००० वर्ष पूर्व माना गया है। शकरी का उल्लेख बौद्ध-ग्रन्थों के ग्रन्थ ‘प्रतिमोक्ष’ में मिलता है जिसका रचना-काल ईसा के ६०० वर्ष पूर्व माना जाता है। बाणभट्ट के अर्धशास्त्र में भी शकरी के सम्बन्ध में कई स्थान पर उल्लेख है। ईसा के ३०० वर्ष पूर्व यूनानी यात्री मैगस्थनीज के यात्रा विवरण में भी गन्ना और शकरी का उल्लेख मिलता है। मध्यप्रदेशीय भाग में शकरी का नाचो व्यापार होता था जिसका उल्लेख सन् १२६० में मार्कोपोलो ने अपनी यात्रा-विवरण में किया था। सन् १४६८ में वास्कोडिगामा जब भारत आया, तो उसने यहाँ बाजार में ढेरों शकरी देखी थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी (१६००) के जमाने में भी शकरी भारत और मध्यपूर्व के देशों को भेजी जाती थी। अब तक शकरी का उत्पादन कुटीर उद्योग के रूप में होता था। धीरे-धीरे विदेशियों का ध्यान इस और आकर्षित हुआ। सन् १६०३-१६०५ में चीनी दलाने के कारखाने उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए जिनमें से कई अब तक चालू हैं। सन् १६३१ के पूर्व प्रति वर्ष लगभग १५ करोड़ रुपये की चीनी हमारे यहाँ आता से जाती थी। सन् १६३२ में इस उद्योग को सरकारी सरकार प्राप्ति हुआ जिसके परिणामस्वरूप हमने आधुनिक उन्नति की। सन् १६३० में यहाँ केवल ३२ चीनी के कारखाने थे सन् १६३६ में उनकी संख्या १४४ हो गई।

आज चीनी उद्योग की स्थिति यह है कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला स्थान सूती वस्त्र उद्योग का है। आज देश में सफेद चीनी के १६० आधुनिक कारखाने हैं। इनका वार्षिक उत्पादन १६ लाख टन है जिसकी कीमत लगभग १२० करोड़ रुपये है। इस उद्योग में आज १ लाख ४० हजार दस कर्मचारी तथा विद्वद्विद्वानों में शिक्षा प्राप्त ३५०० व्यक्ति काम करते हैं इसके अलावा समस्या आदमी इस उद्योग से सम्बन्धित अन्य कार्यों में परीक्ष रूप में रोजी पाते हैं। चीनी का उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ही केन्द्रित है। सन् १९२४-२५ में चीनी

की मिलों का विवरण इस प्रकार था—उत्तर प्रदेश ७२, बिहार ३०, मद्रास १६, बम्बई १५, मध्यभारत ६, बंगाल ४, हैदराबाद ३, राजस्थान २, उड़ीसा २, पेंडु २, ग वंग के राज्य २, पंजाब १, कश्मीर १, मंधूर १, मौराष्ट्र १, विध्य प्रदेश १, ड्रावदकोर १ = १६०। सन् १९५९ में चीनी का उत्पादन २०.८४ लाख टन था।

चीनी-उद्योग और योजना—इस उद्योग की महत्ता देखने हुए अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका और भी विस्तार किया जा रहा है। २५ लाख टन वार्षिक उत्पादन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने ४० नये कारखाने खोलने तथा ४२ वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की अनुमति दे दी है। आज चीनी उद्योग दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

कागज निर्माण उद्योग (Paper Industry)—कागज बनाने का काम सम्भवतः सबसे पहले चीन में आरम्भ हुआ। उस समय कागज हाथ में बनाया जाता था। चीन के सम्पर्क से ही कई मधियों पूर्व भारत की भी हाथ से कागज बनाने की प्रेरणा मिली। आज भी भारत के अनेक भागों में हाथ से कागज बनाया जाता है। भारत में मगध द्वारा प्राच्युरिक ढंग से कागज बनाने की शिल्प परम्परा एक क्षताब्दी पूर्व सबसे पहले डा० बर्टे ने हुगली नदी के किनारे सीगमपुर में स्थापित की थी। वास्तविक प्रारम्भ सन् १८६७ ई० में ही सम्भना बाहिए जबकि रॉयल पेपर मिल (Royal Paper Mills) की स्थापना बैली (Bally) में हुई। इसके पश्चात् कई मिलें स्थापित की गईं जिनमें से मुख्य में हैं—अपर इंडिया वुपर मिल, लखनऊ (Upper India Cooper Mills, Lucknow), टीटागढ़ पेपर मिल कलकत्ता के समीप (Titagarh Paper Mills near Calcutta), डकन पेपर मिल, पूना (Deccan Paper Mills, Poona) और श्री गोपाल वुपर मिल, जगधरी (Shri Gopal Paper Mills, Jagadhari) सन् १९०० तक कागज के ३ कारखाने स्थापित हो गये जिनमें १६,००० टन कागज बनता था। इसके बाद इसे सस्ते विदेशी कागज से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। सन् १९२५ ई० में सरकार ने मिलों के कारण इन उद्योग में आनातनी उत्पत्ति हुई।

इस समय देश में कागज बनाने की २० मिलें हैं जिनकी जातिव उत्पन्न-क्षमता १,११,६०० टन है। इनमें में बार मिलें बंगाल में, दो दो मिलें उत्तर प्रदेश और मंधूर में तथा उड़ीसा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र, महाराष्ट्र और केरल में एक-एक मिल हैं। बम्बई में बार मिल हैं। सात नये कारखाने स्थापित करने के लक्ष्यसे दिये जा चुके हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता ५५,१०० टन होगी। इनमें से तीन मिल बम्बई में और आसाम, बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र में एक-एक मिल होगी। वर्तमान कारखानों में से ८ कारखानों का पर्याप्त विस्तार किया जायगा जिनमें १,०६,५०० टन कागज और बनाने की उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी। इन विस्तार योजनाओं के क्रियान्वित होने तथा नये कारखानों के स्थापित हो जाने पर देश की कागज की उत्पादन-क्षमता कुल ३,५०,८०० टन वार्षिक की हो जायेगी। सन् १९५९ में कागज का उत्पादन २.९१ लाख टन था। व्यक्ति वार्षिक भोग्य वपन १६ पाउंड ही है। यदि हम ससार के अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो ज्ञान होगा कि हम इस दिशा में सबसे पिछड़े हुए हैं। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :—

देश	उपभोग
सं० रा० अमेरिका	२५० पीट
इंग्लैंड	१७५ "
कनाडा	१५० "
जर्मनी	७५ "
नियु	४ "
भारत	१३ "

भारत में गन्ता बनाने का उद्योग अधिक पुराना नहीं है। दूसरे महायुद्ध से पहले इसका बहुत थोड़ा उत्पादन होता था किन्तु युद्ध-काल और युद्ध के बाद गन्ता बनाने का अनेक छोटे-छोटे कारखाने स्थापित हुए जिनमें से अधिकांश में भारत में बनी मशीन ही लगाई हैं। पतल गत्ते तथा पैकिंग करने की अन्य सामग्रियों के चलन के कारण गत्ते की माँग कम है। गन्ता उद्योग का उत्पादन गत तीन वर्षों से ३०,००० टन वार्षिक हो चल रहा है और निकट भविष्य में इस उद्योग के विशेष विकास की परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतीत नहीं होती हैं।

देश में जितना भी अलवारी कागज काम में जाता है, इस समय लगभग सारा-का-सारा विदेहा में आयात किया जाता है। देश में अलवारी कागज का एक मान कारखाना मध्यप्रदेश में न्यूजग्रिट एंड पेपर मिल लि० (नेपा मिल) है जो इस समय सफेद अलवारी कागज प्रति दिन बना रहा है।

कागज उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन् १९५१-५६ के लिए कागज के उत्पादन का लक्ष्य दो लाख टन रखा था और ११ करोड़ रुपये की व्ययस्था की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कागज का उत्पादन लगभग ६ लाख टन रखा गया है और ४४ करोड़ रुपये खर्च का प्रायोजन किया गया है।

सीमेंट उद्योग (Cement Industry)—सीमेंट उद्योग का प्राथमिक समय में दड़ा गहरा है। एशिया के देशों में सीमेंट-उत्पादन में भारत का सीमांत स्थान है। पहला स्थान जापान का और दूसरा चीन का है। भारत में प्राथमिक ढंग में पहली बार सीमेंट तैयार करने का श्रेय मद्रास की है जहाँ सन् १९०४ में साउथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से सीमेंट बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया जिसमें समुद्री सीपिया ने सीमेंट बनाया जाता था। इसके बाद सन् १९१३ में पोरबन्दर (सीरापूर) में इण्डियन सीमेंट कम्पनी लि० नाम से सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। फिर राजस्थान में बूंदी के निजट लाखेरी में और मध्यप्रदेश में बटनी में एक-एक सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। सन् १९३६ तक देश में सीमेंट के १३ कारखाने थे जो आपस में कुल प्रतिस्पर्धा करते थे। इस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये सन् १९३६ में एग्रीसिमेंटेड सीमेंट कम्पनी (A.C.C.) गठित बनाया गया जिसमें सोन बेली सीमेंट कम्पनी के अतिरिक्त शेष १२ कम्पनियाँ इसकी सदस्य थीं। सन् १९३८ में ५ सीमेंट कम्पनियों की स्थापना से दानिया

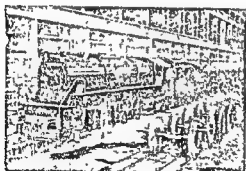
गुप को जन्म मिला जो ए० सी० सी० (एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी) गुप के साथ प्रतिस्पर्द्धा करता था । सन् १९४० में दोनों गुपों में समझौता हो गया और सीमेन्ट को बिक्री के लिये सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी का निर्माण किया गया । सन् १९४० से टानमिया की पाँचों कम्पनियाँ अलग हो गई । द्वितीय युद्धकाल में सीमेन्ट के चार अन्य कारखाने स्थापित हुए ।

इस समय भारत में सीमेन्ट उद्योग के ३२ कारखाने हैं जिनमें ४५ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है और लगभग ३५,००० कर्मचारी काम करते हैं । इनकी उत्पादन-शक्ति ८२५ लाख टन प्रतिवर्ष है । इनमें से दो उत्तरप्रदेश और मैसूर सरकार में हैं और शेष कारखाने निजी हैं । इनमें से ७ ज़िहार में, ४ उम्बई में, ३ मद्रास में, २-२ मैसूर, आंध्र, मध्यप्रदेश राजस्थान और पंजाब में तथा १-१ उड़ीसा और केरल में हैं । आशा है कि सन् १९६१ तक देश भर में ६४ कारखाने हो जायेंगे । अनेक वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की योजना के अलावा भारत सरकार ने ३१ नये कारखाने खोलने की योजना भी स्वीकार करली है । उद्योग का विस्तार होने पर ५०-६० करोड़ रु० की पूँजी लगेगी और ३०-४५ हजार और लोगों को काम मिलेगा ।

सीमेन्ट उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख टन रखा गया था, परन्तु यह पूरा नहीं किया जा सका । इसके निम्न प्रमुख पहलू यह थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ टन का प्रतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य रखा गया है । अन्तु दूसरी योजना के अन्त तक यानी सन् १९६१ तक सीमेन्ट का कुल उत्पादन १ करोड़ ६० लाख टन हो जायगा ।

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योग

रेल के इंजन तथा डिब्बे बनाने का उद्योग—केन्द्रीय सरकार ने २६ जनवरी १९५० को एक कारखाना पश्चिमी बंगाल में धारानगोल

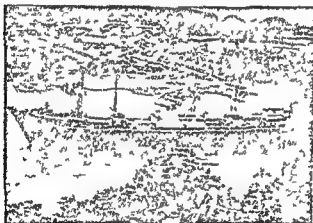


के समीप वितारजन स्थान पर १४ करोड़ रु० लगाकर स्थापित किया । इन कारखानों में अगस्त १९५१ तक ४०० इंजन तैयार हुए । इस कारखाने की उत्पादन क्षमता सन् १९५४ में ६ इंजन प्रति मास थी । अब यह कारखाना १६ इंजन प्रति मास तक बना रहा है । इन इंजनों में ७० प्रतिशत पुर्के देखी हैं और शेष विदेशों से मंगाये जाते हैं । सन् १९५६ तक पूर्णतया देशी इंजन बनने की आशा है । दूसरी योजना काल में देश की इंजनों की माँग को पूरा किया जा सकेगा और सन् १९६१ तक हम इंजनों के लिए आत्म-निर्भर हो जायेंगे, तथा कुछ इंजन बाहर भी भेज सकेंगे ।

रेल क इन्जन बनाने के अतिरिक्त सरकार ने डिब्बे बनाने का एक कारखाना मद्रास के निकट वेरावलूर नामक स्थान में खोला है। इस कारखाने में सवारों तथा माल गाड़ी के डिब्बे बनाए जायेंगे। इस अतिरिक्त हिंदुस्तान ऐयरक्राफ्ट लि० बंगलौर के कारखाने में भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं।

हवाई जहाज निर्माण उद्योग—द्वितीय महायुद्ध में पहल भारत में हवाई जहाज बनाने का कोई कारखाना न था। युद्ध काल में सन् १९३८ में सर्वथा बालनर होराचन्द ने मैसूर सरकार के माफ़े में बंगलौर में हिंदुस्तान ऐयरक्राफ्ट कम्पनी लि० स्थापित की। कुछ ही वर्ष बाद भारत सरकार ने इसे खरीद लिया। उसमें प्रबल नये हवाई जहाज बनाए जाते हैं। बंगलौर के इस कारखाने में ८५०० आदमी काम करते हैं। वहाँ हवाई जहाज के अलावा रान के डिब्बे भी बनाए जाते हैं।

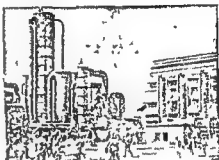
जल-जहाज निर्माण उद्योग—भारतवर्ष में आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व भी जल जहाज बनाने का धंधा बहुत उत्तम दशा में था। मार्कोपोलो का कहना है कि उसने महासागर में भारत से विगत जल जहाज को देखा। डिगबोई के अनुसार



विगासापट्टम में जल जहाज का निर्माण काम

बम्बई व मागील जहाज व जहाज इंग्लैंड का आकर बम्बई के जहाजों से बड़ा अधिक अच्छे थे। स्टील युग के आरम्भ होने पर भारत का यह धन्दा उद्योग नष्ट हो गया। बीसवां शताब्दी के मध्य में पुनः भारत में जल जहाज निर्माण प्रारम्भ हुआ। द्वितीय महायुद्ध काल में सन् १९४१ ई० में सर्वप्रथम नये देश का कारखाना मित्रिया म्याम नवीगान कम्पनी ने विगासापट्टम में खोला। अब तक वहाँ जल-जहाज, जल-जवाहर, जल-क्रान्त आदि १५ विमान जहाज बनाए जा चुके हैं जिनमें से १२ जहाज भारत में चलने वाले और तीन डाक जहाज में से चले हैं। इस कारखाने का नाम हिन्दुस्तान शिपवायर्ड है। इसमें ७३७ हिम्म भारत सरकार के हैं। इसमें कुल पूँजी ४३ करोड़ रुपये अभी २५ है और इसमें ५ हजार आदमी काम करते हैं।

कृत्रिम खाद का कारखाना—देश में अन्न की कमी के सकट का सामना करने की योजना के अंग स्वरूप सिंदरी में खाद के कारखाने की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने दिसम्बर १९५१ में अमोनियम सल्फेट बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कारखाना बिहार राज्य के सिंदरी स्थान पर स्थापित किया। इस कारखाने का पूरा नाम सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (Sindri Fertilizers & Chemicals Ltd.) है। यह कृत्रिम खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। इसमें २३ करोड़ ०० की पूंजी लगी है। सन् १९५५ में ६ लाख टन अमोनियम सल्फेट देश भर में प्रेषित हुआ। इन दिनों में इसकी दैनिक उत्पादन-शक्ति ६५० टन है जबकि सन् १९५६ का प्रक्षेपित दैनिक उत्पादन ६०६ टन रहा।



पेन्सिलीन का कारखाना—पूना में ६ मील की दूरी पर २०० एकड़ भूमि में फैला हुआ सिम्परी नामक स्थान पर भारत सरकार ने प्रति वर्ष ६०-६० लाख मणा यूनिट पेन्सिलीन का उत्पादन करने के ध्येय से २ करोड़ रुपये की लागत का कारखाना स्थापित किया है।



भारत सरकार का पेन्सिलिन कारखाना सिम्परी (पूना के समीप)

जिनका नाम हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड है। मुख्य अधिक प्रयत्न करने पर यह कारखाना १॥ करोड़ में सकर २ करोड़ तक प्रतिवर्ष मणा यूनिट पेन्सिलीन का उत्पादन कर सकेगा। इस कारखाने में उत्पादन के उच्च विनोदना प्राप्त तरीके प्रयोग में लाने जाते हैं। यहाँ की नयी पेन्सिलीन की परीक्षा अमेरिका और ब्रिटेन की मशहूर प्रयोगशालाओं में की जा चुकी है और यह हर प्रकार से वांछित साबित हुई है।

१ अगस्त १९५५ में कारखाने में उत्पादन नियमित रूप में हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्ट्रेप्टोमाइसीन, वाइसिलीन और डिपेन्सिलीन जैसी पाँच एंटीबायोटिक्स औषधियाँ का भी उत्पादन किया गया है।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of the Government of India)

१९ अगस्त १९४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। ६ अग्रेल १९४८ से सरकार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

१. भारतीय उद्योग धन्धों में काम करने वाले अधिकों की दृष्टा सुधारने का प्रयत्न करना।

२. सरकार न सारे उद्योगों को चार भागों में विभाजित किया है—

(प्र) वे उद्योग जिन पर पूर्ण रूप से सरकार का एकाधिकार है, जैसे द्रव्य-मन्त्रों का निर्माण, रेलवे यातायात तथा अणु-शक्ति की उत्पत्ति तथा नियन्त्रण आदि। इनके प्रतिरिक्त सरकार किसी भी उस उद्योग को ले सकती है जो राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक है।

(घ) निम्नलिखित उद्योगों को केन्द्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय सरकार स्वयं चलायेगी। परन्तु यदि आवश्यक होगा तो सरकार पूँजीपतियों से भी सहायता ले सकती है—

(१) शोयला, (२) मोहरा तथा पौलाय, (३) बाघुपान, (४) जलपान, (५) टेलीफोन, तार तथा वैतार का तार आदि का निर्माण, (६) मिट्टी का तेल।

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन उद्योगों में से कोई भी लेते, परन्तु इन उद्योगों में सगी हुई निजी सम्पत्ति को १० वर्ष तक स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने का अधिकार होगा। दस वर्ष के पश्चात् सरकार इन उद्योगों को धत्ति-पूर्ति देकर ले लेगी।

(स) इनके प्रतिरिक्त जो उद्योग होंगे उन्में बंद-सरकारी पूँजी व्यक्तिगत रूप से अथवा सहकारी रूप से लगवाई जा सकती है। परन्तु इन उद्योगों को भी सरकार घोर-धीरे ले लेगी। सरकार इन उद्योगों में उस समय भी हस्तक्षेप कर सकती है जबकि उन का कार्य सुचारु रूप से न चल रहा हो।

(द) इनके प्रतिरिक्त सरकार यह समझती है कि निम्न लिखित १८ उद्योगों की योजना तथा नियन्त्रण का कार्य भी राष्ट्रीय हित में सरकार के पास ही रहना चाहिये। ये उद्योग निम्नलिखित हैं :—

(१) नमक, (२) मोटर तथा ट्रैक्टर, (३) प्रारम्भिक मशीनों, (४) विजली सन्तन्धी यन्त्रालय, (५) अन्य भारी मशीनों, (६) मशीनों के गुर्दों, (७) लोह, इस्पात आदि, (८) रिजली-उत्पादनिक उद्योग, (९) लोह के प्रतिरिक्त धन धातु, (१०) ग्वड का उद्योग, (११) लकड़ मचमार, (१२) मृत्तों तथा उन्नी कपड का उद्योग, (१३) मोमेंट, (१४) चीनी, (१५) सागरण तथा समुद्राचार पत्र का कागज, (१६) वायु तथा समुद्री यातायात, (१७) धातुएँ (१८) रसा सम्बन्धी उद्योग।

बड़े उद्योगों के प्रतिरिक्त, सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी बहुत अधिक बल दिया है। सरकार इन उद्योगों की उत्पत्ति के लिय अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेगी।

सरकार समझती है कि अधिक-से अधिक उत्पत्ति तभी हो सकती है जबकि पूँजी तथा धन में मेल-जोल हो। इसी कारण सरकार ने प्रबन्ध किया कि काम का ठीक

प्रकार वितरण हो। श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले। पूँजीपतियों को अपनी पूँजी पर उचित लाभ मिले।

सरकार श्रम तथा पूँजी के बीच होने वाले संघर्ष का निपटारा करने के लिये उचित प्रकार के साधन जुटावेगी। श्रमिकों के मकानों को उन्नत करने तथा नये मकान बनवाने के लिये सरकार एक 'हाउसिंग बोर्ड' भी स्थापित करेगी। यह बोर्ड दस वर्ष में दस लाख श्रमिकों के लिये मकान बनवायेगा। यह मकान सरकार तथा पूँजीपतियों द्वारा बनवाये जायेंगे। श्रमिकों का भाग उनसे उचित किराये के रूप में लिया जायगा।

भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा (१९४६)

प्रमुख उद्योगों का संचालन सरकार के आधीन रहेगा—निजी क्षेत्रों को विकास की पर्याप्त सुविधा—प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने तारीख ३० मई १९४६ को लोक सभा में भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुये बताया कि भारत सरकार देश में नये उद्योगों की स्थापना और मातायात सुविधाओं के विकास का उत्तरदायित्व धीरे-धीरे स्वयं अपने आधीन कर लेगी और इन कामों की सीधी और अधिकतर जिम्मेदारी सम्हाल लेगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी सरकार अधिक हिस्सा लेगी, परन्तु साथ ही निजी क्षेत्र को भी विकास और विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। निजी क्षेत्र के कार्य में सहकारिता के विकास पर बल दिया गया है।

इस औद्योगिक नीति को तीन वर्गों में बाँटा गया है—(१) वे उद्योग, जिनमें जिनका विकास केवल सरकार के आधीन रहेगा। (२) वे उद्योग जो धीरे-धीरे सरकार के आधीन आयेँगे और जिनके आधीन सरकार नये कारखाने भी स्थापित करेगी, परन्तु साथ ही सरकार के इस प्रवास में निजी क्षेत्र का सहयोग भी प्राप्त किया जायगा, और (३) वे ऐसी सभी उद्योग जिनका भावी विकास निजी क्षेत्र के बल पर होना जायगा।

पहले वर्ग में शस्त्रास्त्र तथा प्रतिकक्षा से सम्बन्धित उद्योग शामिल हैं जैसे मरु-शक्ति, लोहा-इस्पात और मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये भारी मशीनी कारखाने, कोयला और लिग्नाइट, वज्र लोहा आदि निकालने का कार्य, गंधक, मोने और हीरे की खानें तथा ताँबे, सीसे, टिन आदि की सफाई, हवाई व मधुद्री जहाजों का निर्माण, टेन्के-फोन और तार, व धेतरा का साधान (इसमें रेडियो रिसेविंग सेट सम्मिलित नहीं) तथा बिजली उत्पादन और वितरण।

दूसरे वर्ग में एल्युमिनियम तथा अन्य लोहेतर धातु, मशीन टूल, पैरो-एलाय, टूस-स्टील, रासायनिक उद्योगों के लिये आवश्यक पदार्थ, ओपियर, कुनिम रबड, लाद, सड़न-मातायात और समुद्री मातायात आदि।

इस नीति में औद्योगिक सहकारिता के विकास और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में कुटीर और अमोद्योगों के महत्व पर बल दिया गया है।

भारत सरकार की यह औद्योगिक नीति सन् १९४८ की औद्योगिक नीति से बहुत भिन्न नहीं है। इतना अवश्य है कि हमने भारत को विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सरकारी उद्योगों के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएं

१—भारतवर्ष में सोमेट उद्योग की प्रगति पर टिप्पणी लिखिये । (४० प्र० १९६०)

२—भारत का एक मानचित्र बनाकर उसमें प्रमुख उद्योगों के केन्द्र दिखाइये ।
(४० प्र० १९४०)

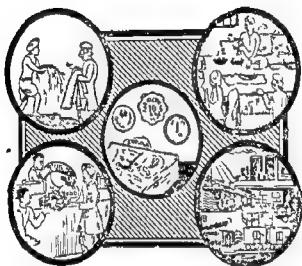
३—बिहार के किन्हीं दो उद्योगों की वर्तमान दशा का वर्णन कीजिये ।
(पटना १९५०)

४—निम्नलिखित किन्हीं दो वृहद् उद्योगों के विकास का वर्णन कीजिये :—
(अ) लोहा और इस्पात, (आ) मृत्तौ बपड़ा, (इ) जूट, (ई) सोमेट, (उ) कागज ।

५—सन् १९४८ की भारत सरकार की औद्योगिक नीति की मुख्य बातें बताइये ।

६—भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति (१९५६) को विवेचना कीजिये ।

विनिमय (EXCHANGE)



"हम वास्तव में मानव समाज को बिना विनिमय के भी कल्पना कर सकते हैं। परन्तु ऐसा समाज, यदि समाज कहा जा सकता है, न तो वैज्ञानिक अन्वेषण के योग्य है और न उसको इसकी आवश्यकता ही है।"

—सोनियर

विनिमय—अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में (Exchange—as a Department of Economics)—यह अध्याय में हम अर्थशास्त्र के प्रथम दो विभागों अर्थात् उपभोग और उत्पत्ति का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके तीसरे विभाग अर्थात् 'विनिमय' का अध्ययन करेंगे। विनिमय अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि कैसे और क्यों-कर वस्तुओं का विनिमय होता है, कैसे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किन समस्याओं द्वारा विनिमय-क्षेत्र में विरोध सहायता मिलती है, इत्यादि। अन्य बातों में जो कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में विनिमय के अन्तर्गत हम प्रथम तो उस व्यवस्था का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादकों और उपभोक्तियों के मध्य हस्तान्तरण अथवा स्थानान्तरण होता है, और द्वितीय उन शक्तियों का अध्ययन किया जाता है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है।

क्या विनिमय अर्थशास्त्र का एक पृथक् विभाग है? (Is Exchange a separate Department of Economics)—कुछ लोगों का मत है कि विनिमय का अध्ययन उत्पत्ति के ही अन्तर्गत होना चाहिये क्योंकि इनके द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता (utility) में वृद्धि होती है जिसके कारण यह एक उत्पादन-क्रिया नहीं जा सकती है। यह तर्क उचित तो अत्यन्त प्रतीत होता है, परन्तु विनिमय के अन्तर्गत हम अनेक ऐसी बातों का अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति के क्षेत्र से बाहर हैं। अतः, उनके विस्तृत अध्ययन के लिये विनिमय को अर्थशास्त्र का एक पृथक् ही विभाग मानना आवश्यक है।

विनिमय—एक आर्थिक-क्रिया के रूप में (Exchange—as an Economic act)—अब तक हमने विनिमय का अर्थ अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में पाया। अर्थशास्त्र की आर्थिक-क्रिया विनिमय का दूसरा रूप है। यह रूप हमारा ध्यान हमारे अर्थशास्त्रीय अर्थ की ओर आकृष्ट करता है। जब कोई मनुष्य अपने वस्तुओं और सेवाओं को देकर उनके बदले में अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएँ प्राप्त करता है, तो वह एक आर्थिक-क्रिया सम्पन्न करता हुआ कहा जाता है। उसकी यह आर्थिक-क्रिया 'विनिमय' कहलाती है। अतः दो पक्षों के मध्य में होने वाले वैधानिक (Legal), ऐच्छिक (Voluntary) और पारस्परिक

(Mutual) धन के हस्तान्तरण (Transfer) को विनिमय कहते हैं। यदि एक वृषभ अनाज देकर एक कुत्ता से बचक लेता है, तो यह विनिमय का एक उदाहरण है। किन्तु यदि एक घोर उम किमान के भवान भ बुझ कर अनाज चुरा लेता है, तो यह विनिमय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह हस्तान्तरण न वैधानिक है, न ऐच्छिक है और न पारस्परिक है। यदि वृषभ राज्य को 'कर' के रूप में अनाज या मुद्रा देता है, तो यह क्रिया भी विनिमय की दृष्टि में नहीं आती, भवपि यह वैधानिक है, तथापि यह ऐच्छिक और पारस्परिक नहीं है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति राज्य को दण्ड के रूप में कुछ राशि दे, तो धन का यह हस्तान्तरण वैधानिक होने पर भी विनिमय नहीं कहा जायेगा, क्योंकि यह अनिवार्य और प्रतिफल-रहित है। एक और उदाहरण हम स्पष्ट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र को कोई वस्तु भेंट के रूप में देता है प्रथम किसी भित्तारी को धन देना है, तो ये ज़िपाएँ भी विनिमय नहीं कही जा सकती। यद्यपि भेंट तथा दान वैधानिक एवं ऐच्छिक हैं, परन्तु इनमें पारस्परिकता या अभाव है अर्थात् एक पक्षीय है, क्योंकि भेंट या दान के बदले में कोई धन या संपत्ति नहीं मिलती।

अन्तु हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में विनिमय के लिये धन का हस्तान्तरण वैधानिक (Legal), ऐच्छिक (Voluntary) और पारस्परिक (Mutual) होना चाहिये। अर्थशास्त्र में विनिमय की यही तीन मुख्य विशेषताएँ (Characteristics) हैं जिनके आधार पर यह सहज कहा जा सकता है कि प्रभु धन या सेवा का हस्तान्तरण विनिमय है या नहीं।

विनिमय की आवश्यकता तथा विकास (Necessity & Growth of Exchange)—प्राचीन काल में मनुष्य स्वावलम्बी था। अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वह स्वयं तैयार करता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह किसी दूसरे पर निर्भर न था। उत्पत्ति और उपभोग के मध्य सीधा सम्बन्ध था। अतएव उस समय विनिमय की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अथ उत्पत्ति का मार्ग ढाँचा बदल गया है। आजकल धन-विभाजन और मशीनों की गहनता से अन्न पैमाने पर उत्पत्ति होती है। हमारी आवश्यकताएँ भी पहले की प्रकृति बहुत बढ़ गई हैं। अतः अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं ही उत्पन्न करना सम्भव नहीं है। आधुनिक उत्पत्ति व्यक्तिगत उपभोग के लिये नहीं बल्कि मशीन मध्य-विवरण के लिये की जाती है। यह विशिष्टीकरण (Specialisation) का युग है। जो जिन वस्तु के जनन में दक्ष होता है, वह वही वस्तु तैयार करता है चाहे उस वस्तु का आवश्यकता हो या नहीं। ऐसी दशा में अब तक उत्पन्न की हुई वस्तुओं का उपभोक्ता तब न पहुँचाया जायगा तब तब उत्पत्ति अधूर्ण रहती और उस समय तब उपभोग का कार्य स्थगित रहेगा। अस्तु यह निरान्त आवश्यक है कि उत्पत्ति और उपभोग में निरन्तर सम्बन्ध स्थापित किया जाय। यह कार्य विनिमय द्वारा ही सम्भव है, यद्यपि उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिये विनिमय की ज़रूरत आवश्यक है। विनिमय से उत्पत्ति को पूर्ण रहती है और उपभोग सम्भव होता है। अन्तु, आधुनिक प्राथमिक व्यवस्था में विनिमय का एक विशिष्ट स्थान है। मानव जाति को उन्नति में विनिमय बड़ा महापुरुष मित्र दुष्टा है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में विनिमय का अथवा रूप से अध्ययन किया जाता है।

विनिमय का सिद्धान्त (Theory of Exchange)—प्रत्येक विनिमय-क्रिया में निम्नलिखित तीन बातें होनी चाहिये :—

(१) विनिमय-क्रिया की सम्पन्नता के लिये कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। इनमें से एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्राप्त वस्तुओं के बदले में अपनी वस्तुएँ देने को तैयार होना चाहिये और इसी प्रकार दूसरा पहले पक्ष में प्राप्त वस्तुओं के बदले में अपनी वस्तुएँ देने को उत्तम होना चाहिये।

(२) विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिये—विनिमय में दोनों पक्षों को लाभ पहुँचता है, इसीलिये वे अपनी वस्तुओं की दूसरी वस्तुओं में बदलते हैं। दो जामें वाली वस्तु में जाने वाली वस्तु की अधिक उपयोगिता होने के कारण मनुष्य अपनी कम उपयोगिता वाली वस्तु को देकर दूसरे से अधिक उपयोगिता वाली वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(३) जब विनिमय द्वारा किसी भी पक्ष को हानि होने लगती है, तभी व्यवहार अथवा सौदा (Transaction) समाप्त हो जाता है—जब मनुष्य इस बात का अनुभव करता है कि बदले में जाने वाली वस्तु की उपयोगिता जाने वाली वस्तु की अपेक्षा कम है तो वह तुरन्त व्यवहार समाप्त कर देता है और अन्य वस्तु के बदले की सोचता है जिसकी उपयोगिता उसकी वस्तु से अधिक हो।

बिस प्रकार विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है (How both parties gain in utility by Exchange)—विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके प्रत्येक पक्ष को उपयोगिता का लाभ होता है। अन्य शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है कि विनिमय केवल उसी दशा में होगा जबकि दोनों को लाभ होगा। कुछ लोगों की धारणा यह है कि विनिमय से एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। किन्तु यह धारणा निर्बल एवं भ्रमात्मक है। विनिमय पूर्णतया स्वैच्छानुसार होता है। अस्तु जब तक दोनों पक्षों को लाभ प्रतीत न होगा तब तक विनिमय नहीं किया जायगा। विनिमय के लिये यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष वाले विनिमय के लिये इच्छुक हों। यह इच्छा उनमें तभी उत्पन्न होगी जब उन्हें यह विश्वास होगा कि विनिमय क्रिया में उन्हें लाभ होगा। यह सम्भारण बुद्धि की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में दूसरे को कम मूल्य वाली वस्तु क्यों भी स्वीकार नहीं करेगा। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि राम के पास पुस्तक है और कृष्ण के पास फाउन्टेन पेन और दोनों ही विनिमय करना चाहते हैं। यह तभी सम्भव है जबकि राम के लिये फाउन्टेन पेन की उपयोगिता पुस्तक से अधिक हो और कृष्ण के लिये पुस्तक की उपयोगिता फाउन्टेन पेन से अधिक हो। दोनों पक्षों को यह विश्वास होना चाहिये कि विनिमय द्वारा प्राप्त वस्तु की उपयोगिता दी हुई वस्तु की उपयोगिता से अधिक है। अतः जब दोनों पक्षों को विनिमय से लाभ दिखाई देना है तभी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है, अन्यथा नहीं। न्योही विनिमय द्वारा किसी भी पक्ष को हानि होती है, न्योही विनिमय समाप्त हो जाता है। विनिमय वा अस्तित्व लाभ के साथ साथ है ॥ कि हानि के साथ।

उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति अ और व को लीजिये। अ गेहूँ उपजाना है और व चावल। हमें यह भी मान लेना चाहिये कि वे दोनों इतना अधिक गेहूँ और चावल उत्पन्न करते हैं कि वे स्वयं उनका उपभोग नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि अ नितना गेहूँ उत्पन्न करता है उतना यह उपभोग नहीं कर सकता और व

न व ही गव चावल का उपयोग कर सकता है। जब अ अपने आवश्यकता के अनुसार गेहूँ से मना है, ता गेहूँ गेहूँ उतारे लिये बेकार हो जाता है। इसी प्रकार व के लिये भी आवश्यकता में अधिक बना हुआ चावल बेकार है। इस प्रकार अ और व दोनों के पास व वस्तुओं के जिनकी उपयोगिता बढन कम है या कुछ भी नहीं है। यदि विनिमय न हो, तो अ कम गेहूँ का ही उपयोग कर सकता है और व केवल चावल का ही। अ के विनिमय के साथ का अकी प्रकार समझ सकते हैं। अ और व अपने गेहूँ व चावल की बदला बदली कर लेते हैं अब जो गेहूँ अ के लिये व्यर्थ था वह व के लिये अधिक उपयोगी है और जो चावल व के लिये व्यर्थ था वह अ के लिये अधिक उपयोगी है। इस प्रकार विनिमय द्वारा दोनों को लाभ हुआ।

यह निम्नांकित उदाहरण द्वारा और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है :—

इकाइयाँ (Units)	सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)	
	गेहूँ (Wheat) का	चावल (Rice) का
१	२०	२२
२	१४	१६
३	८	१०
४	४	६
५	२	४

उदाहरण का स्पष्टीकरण—इस उदाहरण में यह मान लिया गया है कि अ के पास ५ इकाई गेहूँ के और व के पास ५ इकाई चावल है, और दोनों व्यक्तियों का स्वभाव एक सा है जिसके कारण दोनों के लिये गेहूँ और चावल की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता समान है। उपर्युक्त सारणी (Table) में 'उपयोगिता ह्रास-नियम' (Law of Diminishing Utility) के अनुसार अ और व की वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) उनके उपयोग की इकाइयों के घटते-घटते अनुपात में घटती जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि उपयोग की इकाइयों की वृद्धि के साथ-साथ वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता कम होती गई है, यहाँ तक कि पाँचवीं इकाई की उपयोगिता दोनों के बहुत कम है। अतः यह स्वाभाविक है कि विनिमय सर्वत्र कम उपयोगिता रखने वाली इकाई में प्रारम्भ होगा। प्रथम सौदे में अ गेहूँ की ५ वीं इकाई देगा जिसकी उपयोगिता २ है, और उसे चावल की पहली इकाई प्राप्त होगी जिसकी उपयोगिता २२ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ $(२२ - २) = २०$ हुआ। इसी प्रकार व चावल की पाँचवीं इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ४ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ $(२० - ४) = १६$ हुआ। इस प्रकार पहले सौदे में अ और व दोनों की ही उपयोगिता का लाभ होगा। दूसरे सौदे में अ गेहूँ की चौथी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ४ है, और उसे चावल की दूसरी इकाई मिलेगी जिसकी उपयोगिता १६ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ $(१६ - ४) = १२$ हुआ। इसी प्रकार व चावल की चौथी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ६ है, और उसे

बदले में उसे गेहूँ की दूसरी इकाई मिलेगी जिसकी उपयोगिता १४ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ $(14 - 6) = 8$ हुआ। इस प्रकार दूसरे सोदे से भी उन दोनों की उपयोगिता का लाभ होगा। तीसरे सोदे में अब गेहूँ की तीसरी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ८ है और उसके बदले में उसे चावल की तीसरी इकाई मिलेगी जिसकी उपयोगिता १० है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ $(10 - 6) = 4$ हुआ। इसी प्रकार च चावल की तीसरी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता १० है, और उसके बदले में उसे गेहूँ की तीसरी इकाई प्राप्त होगी जिसकी उपयोगिता ८ है। अतः उसकी उपयोगिता के लाभ के स्थान में $(8 - 10) = -2$ की हानि हुई। इस प्रकार तीसरे सोदे में अब भी लाभ और हानि का हानि होगी। यद्यपि अब लाभ है और वह यह सोदा करना भी चाहेंगे। तथापि यह सोदा पूर्ण नहीं हो सकता, इस सोदे से हानि की हानि है।

निष्कर्ष—निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विनिमय द्वारा जब तक दोनों पक्षों को लाभ होता है दोनों पक्ष राजा मन्दी और खुशी से सोदा करत जायेंगे। जब विनिमय से किसी एक पक्ष को हानि की सम्भावना हो तो वह पक्ष सोदे के लिये इत्थार कर देगा। इसी प्रकार विनिमय उसी सीमा तक होगा जब तक दोनों पक्षों को लाभ रहे और जब किसी भी एक पक्ष को हानि होने लगेगी उस दशा में विनिमय समाप्त हो जायगा।

क्या इसी प्रकार दो राष्ट्रों को भी विदेशी व्यापार से लाभ होता है ?
(Do both nations gain likewise by foreign trade ?)

साधुनिक विदेशी व्यापार अतु विनिमय का ही एक विस्तृत रूप है। इसके अन्तर्गत एक देश अपनी अतिरिक्त वस्तुओं को निर्यात कर विदेशों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त करता है। इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय व्यापार अर्थात् विनिमय में वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि होती है। अब यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि क्या अतिरिक्त पक्षों की भाँति विदेशी व्यापार में भी दो विभिन्न राष्ट्रों को उपयोगिता का लाभ होता है। इसमें शक्ति भी संदेह नहीं है कि जब दो स्वतन्त्र देश अपनी राजा मन्दी और खुशी से बिना किसी दबाव के पारस्परिक व्यापार करते हैं, तो निश्चय ही दोनों देशों की उपयोगिता का लाभ होता है। अन्तराष्ट्रीय व्यापार में उपयोगिता का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित बात आवश्यक है :—

(१) दोनों देश आर्थिक विकास की दृष्टि से समान हों। यदि एक देश आर्थिक विकास की दृष्टि में अधिक बढ़ा हुआ है और दूसरा कम, तो पहला देश को लाभ होगा और दूसरे को हानि। जैसे अमेरिका व इङ्ग्लैंड आदि आर्थिक अग्रलिखित देशों और एशिया व अफ्रीका आदि पिछड़े हुए देशों के मध्य का विदेशी व्यापार।

(२) दोनों देश राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हों। जब अन्तराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले राष्ट्र स्वतन्त्र हों, तो दोनों देशों को लाभ हो सकता है अन्यथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे का शोषण (Exploitation) होता स्वाभाविक है। जैसे, भारत के स्वतन्त्र होने तक इङ्ग्लैंड द्वारा उस देश का शोषण हुआ।

(३) विदेशी व्यापार करने वाले देश अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के स्वतन्त्रता पूर्वक अपना निर्यात कर सके। यदि एक देश को अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव से किसी अन्य देश से व्यापार करने को बाध्य किया जाये, तो इस प्रकार के व्यापार से उस देश को हानि होगी।

(४) केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात (Import) होना चाहिये जिनका उत्पादन उस देश में न हो सके। यदि किसी देश का आयात केवल उन्हीं वस्तुओं में होता है जो उत्पादन उस देश में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, तो निश्चय ही उस देश को विदेशी व्यापार से लाभ होगा।

(५) केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात (Export) होना चाहिये जो निर्यात करने वाले देश में अतिरिक्त मात्रा में उत्पन्न हो अथवा वहाँ उनका उत्पादन आयात करने वाले देश की अपेक्षा अधिक लाभ से किया जा सकता हो।

विनिमय का महत्व (Importance of Exchange)

प्राथमिक जीवन में विनिमय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन का कोई भी ऐसा भ्रम नहीं है जिस पर विनिमय का प्रभाव न पड़ता हो। धन या सम्पत्ति की उत्पत्ति, वितरण तथा उपभोग की आर्थिक क्रियाएँ विनिमय पर आधारित हैं। विनिमय का हमारे जीवन में इतना निकट सम्बन्ध हो गया है कि यदि विनिमय क्रिया समाप्त हो जाय, तो हमारी भौतिक सम्पत्ति का ढाँचा नष्ट हो जायगा और मनुष्य सम्पत्ति न उत्पत्ति के रूप में बहुत सीने गिर जायगा। यद्यपि विनिमय स्वतः शून्य नहीं है फिर भी हमारी बसती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये यह निश्चित आवश्यक है।

विनिमय के लाभ (Advantages of Exchange)

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि विनिमय द्वारा लोगों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है। इसके अतिरिक्त विनिमय के और भी अनेक लाभ हैं जिनसे विनिमय का महत्व प्रकट होता है। उसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

१. विनिमय की सहायता से मनुष्य और प्रकृति की शक्तियों का यथेष्ट रूप से प्रयोग किया जा सकता है—विनिमय की सहायता से देश के प्राकृतिक साधनों को उचित ढंग से उन स्थानों अथवा कामों में प्रयुक्त किया जा सकता है जिनके लिये वे उपयुक्त हैं। विनिमय के अभाव में देश की मानव एवं प्राकृतिक शक्ति के साधनों का विकास सम्भव नहीं है।

२. विनिमय के कारण श्रम-विभाजन (Division of Labour), विशिष्टीकरण (Specialisation), बड़े परिमाण की उत्पत्ति (Large-scale Production) आदि सम्भव हैं—विनिमय के न होने पर प्रत्येक व्यक्ति या देश को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वयं की तैयार करनी पड़ेंगी, चाहे उगाने उत्पादन की उसमें योग्यता हो या नहीं। विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार न किया जाकर योग्यतानुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धान्त का उत्पादन-क्षेत्र में अनेक प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। जिसके फलस्वरूप बड़े परिमाण की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है। श्रम-विभाजन, बड़े परिमाण की उत्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के लाभ विनिमय प्रथा में प्रतिफलित हैं।

३. विनिमय द्वारा देश की अतिरिक्त उत्पत्ति का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग हो सकता है—विनिमय से विदेशी व्यापार सम्भव है और विदेशी व्यापार द्वारा कोई भी देश अपनी अतिरिक्त (Surplus) उत्पत्ति को अन्य देशों में प्रच्छेद

मृत्यु पर धन कर नाश उठा सकता है। जैसे भारतवर्ष में मल्लिकार्जुन पाकिस्तान ॥ तू
और आस्ट्रेलिया में उन बावन्धवना ॥ अविष पैदा होनी है मन दृष्ट उन देशों में जहाँ
इन्वेंच घमाव है निर्यात कर नाश उठाया जा सकता है।

४ विनिमय द्वारा हम ऐसी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जो हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते—विनिमय द्वारा हम वस्तुओं में ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें उत्पादन देना सम्भव नहीं है। जैसे आमतौर पर रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोटर कार आदि का उपयोग।

५. विनिमय द्वारा सम्पत्ति वस्तुओं का उपयोग सम्भव है—विनिमय द्वारा मणियाँ का धान विनिर्मित होना है तथा उपयोग परिमाण में वृद्धि होता है जिससे पतनस्वल्प प्रणि द्वारा जागृत नाम धन्य धन्य मस्ती उपयोग होना सम्भव हो जाता है।

६ विनिमय द्वारा ज्ञान सम्पत्ता तथा संस्कृति का विनाश होता है—
विनिमय ग विज्ञानी व्यापार को प्रायःहृदय मितता है जिगा परिणामस्वरूप एक राष्ट्र
दूसरे राष्ट्र के सम्पत्ति में भ्रान्त है और एक दूसरे की कला ज्ञान विज्ञान के सीखने का
दोना का प्रयत्न प्राप्त होता है ।

७ विनिमय द्वारा औद्योगिक उन्नति में एक दूसरे की सहायता प्राप्त हो सकती है—एक देश की पूँजी अनुभव और शक्ति दूसरे देश की भेज जा सकती है जिसमें औद्योगिक उन्नति में एक दूसरे की सहायता प्राप्त हो सकती है। भाग्य अपनी औद्योगिक उन्नति के लिये अमेरिका में पूँजी के अनुभवों पुष्पा का श्रावण का लाभ उठा सकता है।

५. आधुनिक असीमिन् आवश्यकताया की पूर्ति विनिमय द्वारा ही सम्भव हो सकती है—आधुनिक समय में मनुष्य की आवश्यकताएं अनन्त हैं। यह उन सबकी पूर्ति के लिए स्वयं उत्पादन बड़ा कर सकता है। दूसरी ओर उत्पादित वस्तुओं की मर्यादा से उपरान्त हो जाने से आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो सकती है।

६ विनिमय द्वारा उत्पादन शक्ति गिराने का जो गकनी है—उपासक शक्ति का क्षय। रत्न का धीरे धीरे क्षय हो जाता है। विनिमय का ही कारण है। आज यदि सातवियर में मैंने धीरे धीरे सारा धन खर्च कर दिया तो शायद तो कहा जाय कि मैं इस उपासक में न लगे व्यक्ति हूँ। छान्दक प्रत्येक उपासक में लग जाय कि विनिमय परिलक्ष्यमस्वस्व सदैव कि नियम उनकी उत्पादन शक्ति नष्ट हो जायगी।

१० विनिमय राष्ट्रा म मनी भाव उत्पन्न कर देता है—विनिमय द्वारा विदेशी व्यापार म उत्पत्ति होती है जिससे फलस्वरूप राष्ट्रा व मध्य महानुभूति एवं मित्रता के भाव उत्पन्न हो जात है। जिसम जनन नाशदायक प्रयोजन निन्द्य हो सकत है।

११ सत्र के समय सहायता प्राप्त हो सक्ती है—यसका सूचक गुण तथा अन्य राष्ट्रीय अन्तर्गत म ह्य विनिमय द्वारा अर्थ देना म सहायता प्राप्त कर सकत हैं। यदि हम विज्ञा म सत्र आदि की सहायता नहीं मिलती तो हमारा साथ-सबद प्रीर भी गम्भीर हो सकत था।

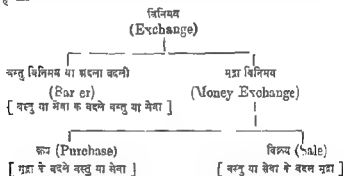
विनिमय के रूप (Forms of Exchange)

विनिमय के दो मुख्य रूप हैं—(१) धन्य विनिमय यर्वाग्न मरुता-मरुता (Barter) और (२) मुद्रा विनिमय (Money Exchange) यर्वाग्न मरुता मरुता ।

(१) वस्तु विनिमय अर्थात् बदला बदली (Barter)—जब एक वस्तु या सेवा का बदला सीधा बिना अन्य वस्तु या सेवा के किया जाय तो उसे 'वस्तु विनिमय' या बदला बदली कहते हैं। यदि एक कृषक भन्ना भनाज देकर किसी दुगाने से फलदा लेता है तो यह वस्तु विनिमय अर्थात् बदला बदली का उदाहरण है। वस्तु विनिमय का एक विषया यह है कि इसमें मुद्रा (Money) का प्रयोग किन्तुल नहीं होता है।

(२) मुद्रा विनिमय (Money Exchange) अर्थात् क्रय विक्रय (Purchase & Sale)—जब वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम द्वारा हो तो वह मुद्रा विनिमय कहलाता है। वह क्रय अथ विक्रय द्वारा सम्पन्न होती है। किसी वस्तु या सेवा को मुद्रा के बदले में प्राप्त करना क्रय या खरीद (Purchase) कहलाता है और किसी वस्तु का मुद्रा के बदल में देना विक्री या विक्रय (Sale) कहलाता है। जैसे रूपा रूकर भनाज लेना और रूपा लेकर भनाज देना आदि।

विनिमय के विविध रूप निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भली प्रकार व्यक्त किये गये हैं —



वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ या असुविधाएँ (Difficulties or Inconveniences of Barter)—आर्थिक विकास का प्रारम्भिक अवस्था में वस्तु विनिमय प्रथा ही सबसे प्रचलित थी। धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति की और उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती गईं। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी मनुष्य ने वस्तु उत्पादन के नये नये साधन भी खोज निकाले जिसके फलस्वरूप आधुनिक आर्थिक भाग बनना विस्तृत और जटिल बन गया है कि वस्तु विनिमय प्रथा में अनेक कठिनाइयाँ और असुविधाएँ अनुभव होना लगीं। वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयाँ या असुविधाएँ निम्नलिखित हैं —

१. आवश्यकताओं के दुहरे संयोग का अभाव (Lack of Double Coincidence of Wants)—वस्तु विनिमय की सबसे पहली कठिनाई या असुविधा आवश्यकताओं के दुहरे संयोग का अभाव है। वस्तु विनिमय तभी सम्भव है जबकि एक मनुष्य दूसरे ऐसे मनुष्य की खोज करे जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और जो उसकी वस्तु को लेने के लिये भी तत्पर हो। अन्य शब्दों में कहा जा

सकता है कि एक मनुष्य की आवश्यकता दूसरे मनुष्य की आवश्यकता के समुन्म होनी चाहिए। यद्यपि वस्तु विनिमय सम्भव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये कृष्ण के पास एक गाय है और वह गाय के बदले वस्त्र चाहता है। तो उसको एक ऐसी मनुष्य की सौजता पड़ना जिसके पास न केवल वस्त्र ही हो अपितु वह गाय भी चाहता हो। मान लीजिए गाय के बदले न वह केवल वस्त्र ही ले सकता है। तब कृष्ण को एक ऐसी मनुष्य बुझना पड़ना जो गेहूँ चाहता हो और इसी प्रकार उरी मय मनुष्यों की भी सौज बरनी पड़गी जब तक उसकी अपनी आवश्यकता की वस्तु नहीं प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वस्तु विनिमय बहुत अनुविधानजनक एक कष्टसाध्य होता है।^१

यद्यपि मुद्रा के चलन से यह कठिनाई दूर हो गई है। प्रत्येक मनुष्य अब अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बाजार में बेच सकता है और प्राप्त मुद्रा के बदले में कोई भी वस्तु बाजार में खरीद सकता है।

२. सर्वमान्य मूल्य मापदण्ड का अभाव (Lack of Common Measure of Value)—विनिमय की दूसरी कठिनाई यह है कि उसमें वस्तुओं के मूल्य की आकृति का कोई आधार नहीं है। मान लीजिए, एक मनुष्य के पास गेहूँ है और दूसरे के पास कपड़ा है। दोनों आपस में अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हैं। परन्तु यह कैसे निश्चय किया जाय कि कितने गेहूँ के बदले में एक गज कपड़ा मिले या एक सेर गेहूँ के बदले में कितना कपड़ा मिले। तथापि ये वस्तु विनिमय व्यवस्था में नाग और पूति के मध्य कोई उचित सम्बन्ध नहीं है।

मुद्रा के द्वारा यह कठिनाई दूर हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में आंक सकता है जिससे वस्तुओं का आपस के मूल्य निश्चित विधि में आसके है।

३. विभाजन की कठिनाई (Lack of Divisibility)—कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका विभाग और उपविभाग नहीं हो सकता जैसे चाय पौड़ा मेज नाव आदि। विभाग करने से उनका मूल्य बहुत घट जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। यदि

१—यदि विचार करें, देगे में अब भी वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित है। कुछ गाँवियों ने जिन्हें ऐसे देगे में यात्रा करने का अवसर मिला है, वस्तु विनिमय की अनुविधाया तथा कठिनाइयों का रोचक वर्णन किया है। उनमें से लीजिनेट कैमरन (Lt. Cameron) का वर्णन उल्लेखनीय है। लीजिनेट कैमरन को काफी का मयात्रा करते समय एक नाव की आवश्यकता पड़ी जिसको प्राप्त करने में उन्हें ब्रित अनुविधाया का सामना करना पड़ा उनका वर्णन उन्होंने All Cross (Africa) में इस प्रकार किया है। रोचक का एजेंट हाजीदात में भुवधान जानता था जो कि मेरे पास नहीं था। किन्तु मुझे मालूम हुआ कि मुहम्मद इब्न साहब के पास हाजीदात थे उन्हें वस्त्र की आवश्यकता थी। पर मेरे पास वस्त्र भी नहीं था और इसी मेरी समस्या हल नहीं हुई। फिर मैंने सुना कि मुहम्मद इब्न गरीब के पास वस्त्र था परन्तु उन्हें तार की आवश्यकता थी। सामयिक तार मेरे पास था। अतः मैंने तार इब्न गरीब को दिया उन्होंने मुझे जो वस्त्र दिया वह मैंने इब्न साहब को दिया उन्होंने जो हाजीदात दिया वह मैंने रोचक के एजेंट को दिया तब वही जाकर मुझे नाव प्राप्त हुई। ।

एक प्रकार की रोचक कहानियाँ डब्लू० एस० जेरोन्स (W S Jerons) ने अपनी Money and the Mechanism of Exchange नामक पुस्तक में दी है।

सब वस्तुओं का एक भंडार मूल्य हो, ता इस प्रकार के विनिमय में कोई कठिनाई नहीं होगा। पर वास्तव में वस्तुओं का मूल्य भिन्न भिन्न होता है। एसी स्थिति में किन प्रकार भिन्न भिन्न मूल्य वाली वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप में बदला-बदली हो सकती है? वस्तुओं का कठ भागों में बांट कर मूल्य बराबर करता हर समय सम्भव नहीं है।

उदाहरण के त्रिय भान 'बीजों' कि एक किसान के पास एक घोंग फाउन् है जिसके बदन में वह कुछ बपड़ा कुछ नमक कुछ खतन और एक फलबड़ा रना चाहता है। यदि वह मर वस्तुएँ एक ही मनुष्य के पास हा और उस घोंग की आवश्यकता हो, तो वह विनिमय सुगमता में हो सकता है। यदि वे सब वस्तुएँ प्रथम प्रथम मनुष्य के पास हा तो घोंग के बसय घनक टुकड़ कर उट प्राप्त नही किया जा सकता। इस प्रकार यह कठिनाई वस्तु विनिमय में घटचन पैदा करती है।

मुद्रा के द्वारा यह कठिनाई सरलता में दूर की जा सकती है। बाड बाता मनुष्य घोंग की बाजार में बच देगा और प्राप्त मुद्रा से अपनी आवश्यकता की भूमा वस्तुओं को खरीदेगा।

४ अर्थ-मन्चय का अभाव (Absence of Store of Value)—वस्तु विनिमय में अविष्य के उपयोग के त्रिये अर्थ मन्चय का पूण अभाव है क्वाकि वस्तुओं के साधन लब्ध हो जान में उनका संचय सम्भव नहीं है।

मुद्रा में अर्थ मन्चय लब्ध है अतः यह अविष्य के उपयोग के त्रिये सुरक्षित रखी जा सकता है।

अन्य कठिनाइयाँ (Other Difficulties)—इनके प्रतिरित वस्तु विनिमय के प्रीर भा कठिनाइयाँ हैं जैम वेतन वितरण का कठिनाई यातायात की सुवाधा के विनिमय की कठिनाई आदि। यातायात की सुवाधा के बदल में कोई वस्तु भरा हो जा सकती। इस प्रकार वर्तमान अर्थ व्यवस्था में वस्तु विनिमय की इतनी अविष्य कठिनाइयाँ हैं कि वह एक दिन के त्रिय भी सम्भव नहीं हो सकती।

वस्तु विनिमय का सम्भव बनाने वाली दशाएँ (Conditions Making Barter Possible) धातकन जबकि अर्थ विभाजन मूल्य अवस्था तक पहुँच गया है तथा आवश्यकताएँ अत्यधिक बड़ गई हैं एवं वस्तुओं का उत्पादन वर पैमान पर होता है एसा अवस्था में कोई भी समाज मुद्रा का उपयोग त्रिये बिना सीमित नहीं रह सकता। वस्तु विनिमय केवल निम्नलिखित दशाओं में ही सम्भव हो सकता है—

(१) सीमित आवश्यकताएँ (Limited Wants)—वस्तु विनिमय के त्रिये एन दो व्यक्तियों की आवश्यकता होता है जिनके जन-देन का वस्तुएँ एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुकूल हा। यह नती सम्भव हो सकता है जबकि समाज में सदस्या की आवश्यकताएँ किन्तु सीमित हा। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ और उनकी विरुध वदना जानी हैं तैम-तैम ही वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ उपस्थित होती जाना हैं वस्तु विनिमय हमारे गावा में सुगमता में हो सकता है क्वाकि ग्रामागा का आवश्यकताएँ नाथारण और सीमित हन्ते हैं। उदाहरणाय यदि एक किसान अपना गेहूँ देकर चावल सना-चाह तो यह सम्भव है कि उस कोई दूसरा एसा व्यक्ति मिल जाय जो अपना चावल देकर गेहूँ लना चाहता हा। परन्तु एक उमर निवासा एन घड़ी देकर फाउल्लन पैर लना चाहता है तो उसे एम व्यक्ति को ढूँढन में बड़ी कठिनाई होगा जो उच्छर यज्ञ के बदल में फाउल्लन पैर देने का तैयार हा। इसका कारण यह है

कि गहूँ और चावल की आवश्यकता माधारणतया गाँव में गाँवों का रहती है। अतः गाँव में अनुसूचन आवश्यकता चाँने व्यक्तियों का पना समाना इतना बढित नहीं है जितना कि एक नगर में पेटा और फाउन्टेन पैन व विनिमय के लिये। यहाँ और फाउन्टेन पैन की आधारभारण आवश्यकता हान व अनिरिक्त उनमें कई प्रकार की किस्म हाता ह जिनके कारण बदला बदली के लिये उपयुक्त व्यक्तिया का मिलना दुर्लभ हो जाता है।

(२) विनिमय का सीमित क्षेत्र (Limited Field of Exchange) वस्तु विनिमय तभी सम्भव है जबकि विनिमय का क्षेत्र संकुचित हो। यदि विनिमय का क्षेत्र गुरुचित नहीं है तो वस्तु विनिमय व निम्न उपयुक्त गुरुत्वा का साधन में अव्यक्तिक समय लगाना और एक दूसरे को आवश्यकताओं से परिचित हान का कोई अवसर नहीं मिलता जहाँ वस्तु विनिमय के लिये अव्यक्त आवश्यक है।

(३) समाज का सामान्य पिछड़ापन (General Backwardness of Society) — वस्तु विनिमय एक ऐसे समाज में सम्भव है जहाँ अत्यंत पिछड़ा हुआ तथा असम्पन्न हो और जितना एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करने के अनिरिक्त विनिमय का अर्थ साधन हो न हो। आजकल भा पिछड़ा तथा असम्पन्न देश में वस्तु विनिमय की प्रथा पाई जाती है। उन भारतीय ग्रामों में जो कि नगरों में बहुत दूर स्थित हैं समाज भी इसी प्रकार की वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित है।

निष्कर्ष (Conclusion) — वस्तु विनिमय का सम्भव बनाने वाला जिन अवस्थाओं का वर्णन ऊपर किया गया है वे वास्तविक की अपेक्षा काल्पनिक प्रतीत होती हैं। इन युग में कोई भी सम्पन्न समाज मुद्रा के प्रयोग की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रा० कासीन (Cassell) ने इस सम्बन्ध में उक्ति की निम्न है कि 'मानवीय इतिहास में कभी ऐसे समाज का अस्तित्व नहीं रहा जिसमें सामान्यतया तथा पूर्णतया मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तुओं का विनिमय चलता रहा हो। आज भी ग्रामीण भारत में जिन प्रकार का वस्तु विनिमय प्रचलित है वह पूर्णतया वस्तु विनिमय न होकर एक प्रकार का मिश्रण है। अस्तु वस्तु विनिमय की पूर्ण अवस्थाओं का प्रतिपादन करना कल्पना-मात्र है।

वर्तमान समय में भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वस्तु विनिमय का महत्त्व (Importance of Barter in the Rural Economy of India at the Present Time)

आज के युग में भी भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में वस्तु विनिमय (Barter) का बड़ा महत्त्व है। जैसे देखा जाय तो ग्रामों का दैनिक जीवन आद्य भी वस्तु विनिमय द्वारा गन्तव्य होता है। गाँवों में ग्रामों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग कुछ ही अवसरों पर होता है जैसे ग्रामीणों का सरकारी लगान देना हो, महानगरों को फल-सुरमा हो, ग्रामों में कपड़ा, चाँद, खरीदना हो, ग्रामों में जहाँ ता बदला बदला में हो काम चलता है। नमक, तेल, धी, मिर्च-मसाला, साग, चाँद दैनिक आवश्यकताएँ सब वस्तु विनिमय से ही पूर्ण की जाती हैं। एसी अवस्थाओं में लोग ग्रामों में लाभ उठाते हैं कि उसमें वे बदला बदली की जान चाँने वस्तुओं का मूल्य जान पत है। उदाहरणार्थ र३ १ २० की २ मर आती है और मिठाई १ २० की एक सेर आती है तो एक सेर र३ देकर आधा मर मिठाई ली जा सकती है।

भारतीय ग्रामों में अब भी वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित होने के कारण— अब प्रत्येक ग्राम में प्रचलित होता है कि ग्रामीण भारत में अब भी वस्तु विनिमय प्रथा का

प्रचलित है ? इसका सरल जवाब में उत्तर देने हूँ या कहा जा सकता है कि भारतीय श्रमोद्योग की आवश्यकताओं का धारण एवं मोमिन है जिसके कारण वस्तुओं की अदला-बदली मही उनका काम सुगमतापूर्वक चल सकता है । उनके जीवन में इस प्रकार की कोई कठिनाई उपस्थित हो नहीं होती । दानों अतिरिक्त उनके बाँवों का क्षेत्र जहाँ वस्तु-विनिमय होता है मोमिन होता है जिससे वे एक दूसरे की आवश्यकताओं में भरी प्रकार परिचित रहते हैं । जहाँ उपभुक्त व्यक्तियों की सेवा करने में अधिक समय नहीं लगता है । उनका सामान्य पिछड़ रूप हुआ वस्तु विनिमय प्रथा के प्रचलन का एक मुख्य कारण है । उनका गिरा हुआ जीवन-स्तर, अविद्या, अज्ञातता, अविवादिता, यातायात व सम्बाधक साधना की कमी, वैविध्य सुविधाओं का अभाव आदि कई ऐसी बातें हैं जो उनके सामान्य विकास में अवरोधक सिद्ध होती हैं । नगरों में बहुत दूर स्थित गाँवों में दवा और की शोधनीय है । परन्तु नगरों के निकटवर्ती गाँवों में सब भुद्धा का वटना हुआ प्रचार होता जाता है ।

वस्तु विनिमय अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा मुद्रा विनिमय अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता (Superiority of Money Economy to Barter Economy)

मुद्रा-विनिमय अर्थात् वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा वस्तु-विनिमय की समस्या कठिनाईपूर्ण एवं अमुविशेष रूप होकर आधुनिक परिस्थितियों में आ गुच्छा रूप में कार्य संचालित हो रहा है वह मुद्रा विनिमय की कुशलता का ही प्रतीक है । आधुनिक समस्त प्रायिक क्रियाओं अर्थात् उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व में वस्तु विनिमय बिल्कुल अयोग्य सिद्ध हुआ है । अब यह देखा है कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में किस प्रकार वस्तु-विनिमय का स्थान मुद्रा विनिमय में ग्रहण किया है ।

उपभोग—प्राचीन समय में जबकि मनुष्य की आवश्यकताओं का धारण एवं मोमिन थी, तब वस्तु-विनिमय की प्रचलना थी । परन्तु आज जबकि मनुष्य की आवश्यकताओं में केवल सभ्यता में ही वस्तु विनिमय में भी बहुत बड़ा बदलाव है, वस्तु-विनिमय इनकी पूर्ति के लिये अयोग्य सिद्ध हो चुका है । मुद्रा के प्रयोग में मनुष्य के लिये नाना प्रकार की वस्तुओं का उपभोग सम्भव कर दिया है ।

उत्पत्ति—आजकल उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होती है । आधुनिक मशीनकारों को क्या मास बड़ा परिमाण में क्षरीयता पड़ता है, उसे विदेशों से मशीनों मँगाने पड़ती हैं, कारखाने में काम करने वाले द्वारा श्रमिकों को समय पर मजदूरी वितरण करने पड़ती है तथा अपनी वस्तुओं की खपत की आवश्यकता देख विदेशों में करनी पड़ती है । ये सब बिना मुद्रा के प्रयोग के बिल्कुल सम्भव नहीं हो सकता । उधार लेने और देने की व्यवस्था की पूर्णतया मुद्रा विनिमय पर ही निर्भर है । आधुनिक उत्पत्ति का सम्पूर्ण ढाँचा वस्तु-विनिमय के अलगवस्तु तो स्वयं तुल्य है परन्तु यही मुद्रा विनिमय में साक्ष्यकार है ।

विनिमय—मुद्रा ने न केवल वस्तु-विनिमय को कठिनाईपूर्ण को ही दूर किया है बल्कि विनिमय को सुगम बनाने वाले साधन, वैयक्तिक आदि के लाभ भी उपरब्ध करा दिये हैं । वास्तव में, आधुनिक विनिमय मुद्रा विनिमय ही है ।

वितरण—मुद्रा ने आधुनिक उत्पादक का वितरण-कार्य बड़ा सुगम बना दिया है । मुद्रा के कारण ही आज मनुष्य उत्पादन प्रणाली सम्भव है । इस प्रणाली के द्वारा जो वस्तुएँ बनती हैं वे बाजार या मंडी में बेच दी जाती हैं और जो मुद्रा प्राप्त होती है वह नियमानुसार विविध उत्पादन साधनों अर्थात् मूल्यवान्, श्रमिक,

पूर्वोपार्जित, सञ्चयनवर्ती और माहुरी में बाँट दी जाती है। यह वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत वित्तकुल सम्भव नहीं है, क्योंकि जबकी उत्पादन वस्तुओं में सुगठान करना पड़ेगा तबमें प्रत्येक उत्पादन साधक की अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने में कठिनाई या नामना करना पड़ेगा।

राजस्व—जब उत्त प्रवस्था की कल्पना कीजिये तबमें विविध प्रकार की सरकारी आय वस्तुओं में होने लगेगी और सरकारी कर्मचारियों को वेतन आदि भी वस्तुओं में दिया जाता होगा ऐसी व्यवस्था में किन प्रकार अनुविधा होगी उसका भी भली-भाँति अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक सरकार को प्रत्येक ऐसे कार्य करने पड़ने है जो मुद्रा द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। यह मुद्रा का ही प्रभाव है कि प्रायः सरकार देश में सुख, शांति और न्याय स्थापित कर सकती है।

इसमें यह स्पष्ट है कि वस्तु-विनिमय आधुनिक धर्म-व्यवस्था में विघ्नित अनुपयुक्त सिद्ध होता है और इसी कारण मुद्रा-विनिमय ने इसका स्थान ग्रहण कर आधुनिक धर्म-व्यवस्था की गुच्यारूप से संचालित करने का योग प्राप्त किया है।

विनिमय के साधन (Instruments of Exchange)

आधुनिक विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुएँ उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता के पास सीधी न पहुँच कर कई साधनों द्वारा पहुँचती हैं। नीचे कुछ इन्हीं साधनों का उल्लेख किया जाता है :—

(१) व्यापारी वर्ग (Merchants & Traders)—इनके द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य सम्पर्क स्थापित होता है। ये लोग वस्तुओं को दूर के स्थानों में लाकर उपभोक्ताओं के पास पहुँचा देते हैं। व्यापार करने के उद्योगों के अनुसार इनमें पर्याप्त निरता पाई जाती है—कई लोग व्यापारी होता हैं और कोई कुदकर।

(२) यातायात व संचार के साधन (Means of Transport & Communication)—सड़क, समुद्री बहाव, वायुमार्ग, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि में वस्तुओं के अन्तर्विषय में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इनसे विनिमय की प्रत्याह्वान मिलकर व्यापार में वृद्धि होती है।

(३) मुद्रा (Money)—वर्तमान समय में विनिमय का साधक मुद्रा है। इसके द्वारा वस्तु-विनिमय की समस्त कठिनाईयाँ दूर होकर विनिमय-व्यवस्था बड़ी सुगम हो गई है।

(४) मण्डी या बाजार (Markets)—वस्तुओं के अन्तर्विषय के विभिन्न मण्डियों या बाजारों की भी आवश्यकता है।

(५) साख-पत्र और साख-संस्थाएँ (Credit Instruments & Credit Institutions)—मुद्रा-विनिमय का कार्य लाख पत्रों (चेक, दिन ऑफ़ एक्सेचेंज व प्रीमियरी नोट) और लाख संस्थाओं (बैंक आदि) द्वारा कुशलता पूर्वक सम्पन्न किया जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—विनिमय का अर्थ स्पष्ट कीजिए । विनिमय में दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होता है ? उदाहरण देकर समझाइए ।

२—वस्तु विनिमय किसे कहते हैं ? इनमें क्या अनुविधाएँ हैं ? यह किन परिस्थितियों में सम्भव है ? (रा० बो० १९६०)

३—वस्तु विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय के लाभ तथा हानियाँ बताइए ।

(प्र० बो० १९५९)

४—वस्तु विनिमय की क्या कठिनाईयाँ होती हैं ? क्या यह कहना सत्य है कि वस्तु-विनिमय में यदि एक पक्ष का लाभ होता है तो दूसरे का हानि ? इसके कारण मावधानी से बताइए । (म० भा० १९५६)

५—भदल बदल (Barter) की हानियाँ क्या हैं ? सिका के प्रचसन द्वारा ये कहाँ तक दूर हुई हैं ?

६—विनिमय' के अर्थ का स्पष्ट अर्थ समझाइये । विनिमय से उपयोगिता में दोनों पक्षों को किन प्रकार लाभ होता है ?

७—विनिमय किसे कहते हैं ? इसे स्पष्ट कीजिये कि विनिमय की क्रिया में दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होता है ? (म० भा० १९४४)

८—आप वस्तु विनिमय में क्या अर्थ समझते हैं ? वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाईयों को समझाइए । (प्र० बो० १९४५)

९—विनिमय की क्या शक्तें हैं ? एक उदाहरण सहित बताइये कि विनिमय से दोनों पक्षों को उपयोगिता का किस प्रकार लाभ होता है ? (प्र० बो० १९५२)

१०—मुद्रा द्वारा बिक्री (Sale for Money) व वस्तु-विनिमय का स्थान क्या ले लिया ? समझाइये । (रा० बो० १९४५)

११—भदल-बदल की प्रमुख अनुविधायाँ का उल्लेख करिये । वर्तमान काल में प्राचीण अर्थ-व्यवस्था में भदल-बदल के महत्व का वर्णन किये । (देहली हा० सै० १९४८)

इण्टर एसीकल्चर परीक्षाएँ

१२—विनिमय का उद्देश्य कौनसा होता है ? बताइये कि आप बिक्रय बाटल की अपेक्षा श्रेष्ठ क्या होता है ? (प्र० बो० १९४७)

भदल-बदली की अनुविधायाँ पर नोट लिखिए ।

(रा० बो० १९५१, ४९; प्र० बो० १९५०, ४९, उ० प्र० १९५०, ४८)

मंडी अथवा बाजार (निपणि)

(Market)

मंडी अथवा बाजार (विपणि) का अर्थ (Meaning of Market)

साधारण बोल चाल की भाषा में हम उस स्थान को मंडी अथवा बाजार कहते हैं जहाँ क्रैता और विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं का मोदा करने के लिये एकत्रित होने हैं। कभी-कभी मंडी अथवा बाजार किसी ग्रहण या बट्ट मकान में भी होता है। धान मंडी, सब्जी मंडी, कपड़ा बाजार, स्टेशनरी मार्ट, जेवर मार्केट आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक वस्तु किसी विशिष्ट स्थान पर बेची जाती है तो वह स्थान उस वस्तु के लिये मंडी है। वस्तु जितनी वस्तुएँ एक स्थान पर बिकती हैं उतनी ही मंडियाँ उस स्थान में मानी जायगी। दूसरे शब्दों में मंडी अथवा बाजार शब्द का प्रयोग साधारणतया किसी स्थान-विशेष के लिये होता है जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें या मोदाम बने हुए हों, जहाँ बड़ी बड़ी वस्तुएँ रखी जाती हों तथा क्रैता और विक्रेता मोदा करने के लिये एकत्रित होते हों। किन्तु अर्थशास्त्र में मंडी अथवा बाजार शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट एवं विस्तृत अर्थ में होता है। अर्थशास्त्र में मंडी अथवा बाजार से हमारा अर्थ किसी विशिष्ट स्थान में नहीं होता जहाँ वस्तुएँ बेची और खरीदी जाती हों बल्कि उस मोदे क्षेत्र से होता है जिसमें क्रैता और विक्रेता आपस में इस प्रकार प्रतियोगिता करें कि सारे क्षेत्र में वस्तु का मूल्य समान हो जाय। यद्यपि यह स्पष्ट है कि व्यापिक मंडी अथवा बाजार का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष में नहीं होता बल्कि वस्तु-विशेष के क्रैता और विक्रेताओं में है जो आपस में सम्पर्क स्थापित कर प्रतियोगिता करते हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप सारे क्षेत्र में एक ही मूल्य प्रचलित हो जाता है। वस्तु यदि एक ही क्षेत्र में एक ही वस्तु के क्रैता और विक्रेताओं के अनेक समूह हों तो उस क्षेत्र में एक से अधिक बाजार हो सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष में नहीं होता, बल्कि परस्पर प्रतियोगिता में सलग्न किसी वस्तु के क्रैताओं और विक्रेताओं के समूहों से होता है। स्थानीयता का कोई बन्धन नहीं है। जैसे गेहूँ, रुई, चाँदी, सोना आदि का बाजार मसाला-व्यापारी है। इसी प्रकार एक ही क्षेत्र में एक ही वस्तु के विभिन्न बाजार अथवा मंडियाँ हो सकती हैं, जैसे थोक बाजार और फुटकर बाजार, क्योंकि थोक व फुटकर क्रैता और विक्रेताओं के समूह भिन्न भिन्न होते हैं और उनके मूल्यों में भी पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

कुछ समय पूर्व जबकि यातायात व सम्वाद के साधनों का विकास नहीं हुआ था किसी स्थान विशेष को मंडी या बाजार कहना उचित ही था, क्योंकि वस्तु के क्रैता और विक्रेता उन्हीं स्थान के लोग होते थे। किन्तु अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। भारतीय चाय केवल भारत में ही नहीं बिकती है बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका

आदि दूर स्थित दशा में भी विक्री होती है। अतः इसका बाजार विश्व व्यापी है। वह समस्त क्षेत्र जहाँ उसके क्रय और विक्री उपस्थित हैं चाय के बाजार के अनुरूप है।

कुछ प्रामाणिक परिभाषाएँ (Some Standard Definitions)

(१) प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कूर्नो (Cournot) ने बड़ी अर्थवा बाजार को इस प्रकार परिभाषित किया है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार शब्द का आशय ऐसा स्थान से नहीं जहाँ कि वस्तु का क्रय विक्रय होता है बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रय और विक्री के मध्य ऐसी स्वतंत्र प्रतियोगिता हो कि किसी वस्तु का मूल्य सुगमता और क्षीयता से समानता की ओर प्रवृत्ति प्रदर्शित करे।^१

(२) इंग्लैंड के एक बड़े अर्थशास्त्री जेवन्स (Jevons) ने इस निम्न प्रकार परिभाषित किया है प्रारम्भ में बाजार किसी करव का वह सार्वजनिक स्थान होता था जहाँ विक्री के लिए सारा एव अर्थ पदार्थ रखे जाते थे परन्तु यह शब्द अब एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसका आशय उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिनके मध्य में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो और जो किसी वस्तु में बहुत से छोटे करें।^२

(३) हॉबसन (Hobson) का परिभाषा

अनेक प्रत्यक्ष रूप में प्रतियोगिता करने वाले व्यापार का नाम बड़ी अर्थवा बाजार है।^३

1— Economists understand by the term market not any particular place in which things are bought and sold but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly
—Cournot

Quoted by Marshall in Principles of Economics P 324

2— Originally a market was a public place in a town where provisions and other objects were exposed for sales but the word has been generalised so as to mean any body of persons who are in intimate business relations and carry extensive transactions in any commodity
—Jevons

Theory of Political Economy P 84—85

3— Market is the name given to a number of directly competing businesses
—Hobson

(४) वॉकर (Walker) की परिभाषा :

राजनीति अर्थशास्त्र में बाजार (विनिमय) शब्द का सकेत प्रथम तो वस्तुओं की और द्वितीय विनिमय करने वालों के समूह की ओर होता चाहिये • • जितने विनिमय करने वालों के समूह होंगे उतने ही वहाँ बाजार होंगे ।⁴

(५) चैपमैन (Chapman) की परिभाषा .

यह आवश्यक नहीं है कि बाजार शब्द से स्थान का ही बोध हो परन्तु इससे सदैव वस्तु या वस्तुओं और उनके कर्ताओं व विक्रेताओं का बोध होता है जो एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप में प्रतियोगिता कर रहे हों ।⁵

(६) बेंहम (Benham) की परिभाषा

मंडी वह क्षेत्र है जहाँ कर्ताओं और विक्रेताओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षों के द्वारा इतना निकट सम्बन्ध हो कि मंडी के एक भाग में प्रचलित मूल्यों का अन्य भागों में दिये जाने वाले मूल्य पर प्रभाव पड़ता हो ।⁶

(७) ऐली (Ely) की परिभाषा

बाजार वह सामान्य क्षेत्र है जिसमें किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ क्रियाशील हों

उपरोक्त विविध परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र में मंडी अथवा बाजार किसी स्थान विशेष को नहीं कहते हैं,

4—"The term market in Political Economy should have reference to a species of commodity, secondly to a group of exchangers, there are as many markets as there are groups of exchangers "

—Walker

5—"The term refers not necessarily to a place but always to a commodity or commodities and the buyers and sellers of the same who are in direct competition with one another "

—Chapman

6—"We must therefore define a market as any area over which buyers and sellers are in such close touch with one another, either directly or through dealers, that the prices obtainable in one part of the market effect the prices paid in other parts "

—Benham

Economics—Benham Ch II P 20

7—"In the words of Prof Ely, market means "the General field within which the forces determining the prices of a particular commodity operates "

वस्तु इस शब्द से उस सारे क्षेत्र (Area) या प्रदेश (Region) का अर्थ होता है जिसमें ब्रेता और विक्रेता फँसे हुये हैं और वे आपस में इस प्रकार प्रतियोगिता करें कि वस्तु का मूल्य सर्वत्र समान हो जाय उदाहरणार्थ, यदि एक वस्तु का मूल्य दो स्थानों में प्रतियोगिता न होने के कारण भिन्न-भिन्न है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उस वस्तु के दो बाजार हुये चाहें वे दो मील की दूरी पर ही क्यों न हों, परन्तु यदि एक वस्तु का मूल्य प्रतियोगिता होने के कारण दो स्थानों पर एक ही है, तो वह एक ही बाजार कहना चाहें वे दो स्थान पर्याप्त दूरी पर स्थित क्यों न हों। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक मंडी (Economic Market) में न वस्तुओं की भौतिक उपस्थिति (Physical Presence) की आवश्यकता होती है और न क्रेताओं और विक्रेताओं का किसी विशिष्ट स्थान पर एकत्र होना ही आवश्यक है। अतः वे, विनिमय करने वालों का वह समूह जो एक दूसरे के साथ क्रय-विक्रय में प्रतियोगिता कर रहा हो आर्थिक मंडी अथवा बाजार कहलाता है।

आर्थिक मंडी अथवा बाजार की विशेषताएँ

(Characteristics of an Economic Market)

आर्थिक मंडी अथवा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएँ होती चाहियें :

१. वस्तु विनियमन न कि स्थान विशेष—आर्थिक मंडी की एक विशेषता यह है कि उसका सम्बन्ध किसी वस्तु विशेष के साथ होता है, न कि स्थान के साथ।

२. विनिमय करने वाले दलों का अस्तित्व आर्थिक मंडी की दूसरी विशेषता यह है कि वस्तु विनिमय के लिये ज़रूरी और विक्रेताओं के दोनों दलों का होना आवश्यक है। ये बाजार के विभिन्न भाग हैं। इनके बिना किसी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता।

३. विनिमय करने वाले दलों में पारस्परिक प्रतियोगिता—प्रतियोगिता आर्थिक मंडी का मुख्य बल माना जाता है। परन्तु प्रतियोगिता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वेदने वाले और खरीदने वाले एक ही स्थान पर हों। वे भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हुये भी रेल, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि की सहायता से आपस में अचूकी तरह में प्रतियोगिता कर सकते हैं।

४. मंडी की परिस्थितियों का ज्ञान—क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतियोगिता तभी सम्भव है जबकि इनके मंडी की परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो।

५. एक वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य होना—प्रतियोगिता के प्रभाव में किसी वस्तु का मूल्य सम्पूर्ण क्षेत्र में एक समय में एक ही होगा। यदि किसी वस्तु के बेचने और खरीदने वालों में पूर्ण प्रतियोगिता है और उन्हें इस बात की स्वतंत्रता है कि जब और कहाँ चाहें बेचें और खरीदें सकते हैं तो उन दशा में उस वस्तु का मूल्य मंडी के प्रत्येक भाग में समान होगा। उदाहरण के लिये, कोई बिजनेस किसी वस्तु की खरीद की अपेक्षा कम मूल्य पर बेचने को तैयार है, तो ऐसी दशा में वह याहूँ उगली और बिचें बायेंगे। अतः वेप बिजनेसों को वह वस्तु बेचना असोष्ट है तो उन्हें भी वही मूल्य स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई आहूँ मूल्यों की अपेक्षा अधिक मूल्य देने को तैयार है, तो सभी बिजनेस अपने माल को

उसी के हाथ बेचना चाहेंगे। अन्य बाहरी को वह वस्तु न मिल सकेगी जब तक कि वे भी उतना ही मूल्य देने को तैयार न हो जायें। इस प्रकार प्रतियोगिता के प्रभाव में किसी एक वस्तु का मूल्य मदी या बाजार के भिन्न भिन्न भागों में यातायात के लागत-व्यय को छोड़कर एक समान रहना स्वाभाविक है।

पूर्ण और अपूर्ण बाजार (Perfect & Imperfect Market)

एडम स्मिथ (Adam Smith) तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने विनिमय के क्षेत्र में पूर्ण बाजार की कल्पना की है। जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition) प्रचलित हो उसे अर्थशास्त्र में पूर्ण बाजार कहते हैं। जिस बाजार में प्रतियोगिता अपूर्ण (Imperfect) हो, वह अपूर्ण बाजार कहलायेगा। पूर्ण प्रतियोगिता होने की वृत्ता में सम्पूर्ण बाजार में एक ही मूल्य (Single Price) प्रचलित होगा। अर्थात्, एक ही प्रतियोगितामूलक मूल्य (Competitive Price) पूर्ण बाजार का लक्षण एवं परीक्षा है। यदि बाजार में एक ही प्रकार की वस्तु के पृथक् पृथक् मूल्य प्रचलित हों तो सभी कृता उन विक्रेताओं में खरीदने जो कम मूल्य पर बेच रहे हों और सभी विनिर्माता उन क्रयों को देंगे जो उच्च मूल्य पर मरीद रहे हों। इस प्रकार मूल्यों का अन्तर बिलीन होकर मदा एक ही मूल्य स्थापित हो जाता है। यदि बाजार या मदी विस्तृत हों, तो यातायात-व्यय के कारण मूल्यों में अन्तर छोटे होने से समानता का बोध हो सकता है।

पूर्ण बाजार के लिये आवश्यक बात (Necessary Conditions for Perfect Market) — पूर्ण बाजार तभी सम्भव है, जबकि —

- (१) खेता और विक्रेता बड़ी संख्या में हों,
- (२) उनके मध्य परस्पर पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता हो
- (३) खेताओं और विक्रेताओं की क्रय विषय सम्बन्धी बातों का ज्ञान हो
- (४) वस्तु को बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का हानिम प्रसिद्ध न हो,
- (५) वस्तु की किस्म आदि में कोई अन्तर न हो,
- (६) व्यापारियों के कार्य में किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो,
- (७) वस्ते एवं कुशल यातायात के साधन हों, और
- (८) बाजार विस्तृत हो।

निम्नांकित दशाओं में पूर्ण बाजार है या अपूर्ण ? —

(अ) पुरानी पुस्तक एवं वस्त्र (Second-hand Books and Clothes) — पुरानी पुस्तकों और वस्त्रों का बाजार अपूर्ण होता है, क्योंकि उनका कोई प्रमाणित मूल्य (Standard Price) नहीं होता है।

(आ) ऋण राशि (Loan of Money) — ऋण की जोयम और मर्याद ने अनुसार ब्याज-दर में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। पाश्चाय देय में जहाँ बैंकिंग प्रणाली सुव्यवस्थित है, यदि ऋण की अन्य दशाएँ समान हों, तो ब्याज दर में भिन्नता नहीं हो सकती। परन्तु भारतवर्ष में मुद्रा-बाजार अपूर्ण है, क्योंकि पाश्चात्य लोग ऋणियों की अनभिज्ञता (Ignorance) का अनुचित लाभ उठाने के लिए दर में ब्याज कम कर लेते हैं।

(इ) विदेशी चलान्य (Foreign Currency)—विदेशी चलान्य का प्रायः पूरा बाजार होता है क्योंकि व्यवहार वर्तक (Dealers) इतने निपुण होते हैं कि तनिय भी परिवर्तन नया न हो वे उसको नोट परते हैं और लाभ उठाते हैं।

(ई) वास्तविक सम्पत्ति (Real Estate)—वास्तविक सम्पत्ति का बाजार माधारगुण्य पूरा होता है। इसका व्यापार विविध ज्ञान वाले प्रतिवर्तक (Agents) के द्वारा होता है और प्रत्येक अपनी रायि इसमें लगाने के पूर्व पर्याप्त ज्ञान योजन करते हैं।

(उ) उपभोक्ताव्यय की वस्तुएँ (Consumers Goods)—उपभोक्ताव्यय की वस्तुओं का बाजार अपूर्ण होता है क्योंकि पुनर्र मूल्यों में दुकान दुकान और स्थान स्थान के बीच पचान भिन्नता पाई जाती है।

(ऊ) धर्म-सेवाएँ (Labour Services)—धर्म-सेवाओं का बाजार अपूर्ण होता है क्योंकि धर्म की गतिशीलता कम होने में ऊँची मूल्य (मजदूरी) का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसके अनिश्चित धर्मिक नीति करने में कमजोरी होती है और प्रायः वह यह नहीं जानता कि वहाँ अधिक मूल्य (wages) मिल सकता है।

(ए) नाशवान वस्तुएँ (Perishable Goods)—शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार प्रायः अपूर्ण होता है क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोग एक जल विषय स्थान पर होता है। जितना अधिक बाजार विस्तृत होगा उतनी ही अधिक पूर्णता उसमें होगी।

(ऐ) फुटकर व्यापार की वस्तुएँ (Retail Goods)—फुटकर व्यापार की वस्तुओं का बाजार अपूर्ण होता है क्योंकि उनकी स्थानीय मांग होती है और फुटकर व्यापारियों के ढङ्गा में तथा उपभोक्ताओं की गतिविधि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

क्या पूर्ण बाजार का अस्तित्व वास्तविक है ?

पूरा बाजार का अस्तित्व संशयामक है क्योंकि इसकी व्यापारपूर्ण गति—'पूर्ण प्रतियोगिता' स्वयं वास्तविक है। पूर्ण प्रतियोगिता का अस्तित्व वास्तविक स्तर पर भन ही देखा जा सकता है परन्तु व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का अस्तित्व असम्भव सिद्ध होता है। इसका कारण स्पष्ट है। बाह्य की मिला इन बात का पूर्ण ज्ञान होता है और न उह जानने के नियम। मध्य है कि प्रमुख वस्तु न्यूनतम मूल्य में वहाँ मिलती है। इसका अनिश्चित साक्षात्कार व्यय अनुविधा और प्रालम्भ के कारण वे दूर स्थित सभी दुकानों में खरीदने के बजाय पास के सही दुकानों में ही वस्तु खरीद लेते हैं। यही नहीं दुकानदार के व्यवहार और उनके द्वारा या जान वाली सुविधाओं में पर्याप्त भिन्नता पाई जाने के कारण जब ही वस्तु विभिन्न मूल्यों पर विक्री हुई देनी जाती है। यही सब कारणों से फुटकर व्यापार में प्रतियोगिता बहुत ही अपूर्ण होती है। यों ही और सारा बाजार के सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता को सम्पन्न बहुत भय में चरितार्थ होती है।

मानव एक और प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता की धारण मिटती है। एक वस्तु बाह्य से पर्यटन से विभिन्न नाम और रूप धारण कर विभिन्न वस्तुओं के नाम से विक्रय करती है। विभिन्न ब्रांड, पैकेजिंग विज्ञापन आदि अनेक ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा बाह्य का अपनी ओर आकर्षित किया जाता है।

इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक सिद्ध होती है। हाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ वस्तुओं का बाजार अन्य वस्तुओं के बाजार को अपेक्षा अधिक पूर्ण है। अस्तु, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान में केवल अधिक और कम प्रतियोगिता ही सम्भव हो सकती है।

एक आदर्श अथवा उत्तम बाजार के गुण

(Qualities of an Ideal or Good Market)

एक आदर्श अथवा उत्तम बाजार के निम्नलिखित गुण होने चाहिये :—

(१) प्रतियोगिता—क्र्रेताओं और विक्रेताओं में पर्याप्त प्रतियोगिता होने चाहिये जिसके कारण वस्तु का मूल्य सम्पूर्ण बाजार में एक-सा रह सके।

(२) बाजार की परिस्थितियों का ज्ञान—क्र्रेताओं और विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता दोनों पक्षों को दृग् बान के निम्ने बाध्य करनी है कि वे एक दूसरे के कार्यों में तथा वस्तु सम्बन्धी माँग व पूर्ति की दशाओं से अनौ-आनि अवगत रहे ताकि वे बाजार में सलाह कार्य कर सकें।

(३) मूल्य की समानता—जिस बाजार में समस्त भागों में एक-सा मूल्य प्रचलित होता है वह एक आदर्श बाजार माना जाता है। क्र्रेताओं और विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है।

(४) भले तथा विज्ञ विचरानी—विचरानी भले तथा जातकार आदमी होने चाहिये जो वस्तुओं का मूल्य स्थिर करने में क्र्रेताओं और विक्रेताओं की सहायता कर सकें।

(५) पर्याप्त एवं शीघ्र यातायात व सम्वाद के साधन—यातायात व सम्वाद के साधन पर्याप्त, सुगम तथा शीघ्र होने चाहिये जिनसे वस्तुओं का मूल्य सम्पूर्ण मंडी अथवा बाजार में समान रह सके।

(६) मंडी अथवा बाजार की विस्तृति—बाजार जितना ही अधिक विस्तृत होना है उतना ही वह आदर्श या उत्तम बाजार बन जाता है।

(७) बाहरी हस्तक्षेप का अभाव—जिस मंडी या बाजार में क्र्रेता और विक्रेताओं की अपनी-अपनी कामें स्वतन्त्रतापूर्वक कर रहे हों, उसे उत्तम मंडी या बाजार कहेंगे। लडाई के समय की कंट्रोल-व्यवस्था इसी का एक उदाहरण है।

(८) प्रतिव्ययहीन वस्तु-स्थानान्तरण—बाजार में वस्तु-स्थानान्तरण में किसी प्रकार का शुल्क प्रतिकल्प नहीं होना चाहिये। लडाई के समय में शीर अथवा भी कई वस्तुओं के स्थानान्तरण में प्रांतीय प्रतिकल्प लगे हुये हैं। इस प्रकार के प्रतिकल्प उत्तम बाजार के स्तर में गिराने वाले होने हैं।

बाजार का नियम (Law of Market)—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि यदि बाजार में विज्ञ क्र्रेता और विक्रेता एक बड़ी मध्यम से पूर्ण रूप में प्रतियोगिता कर रहे हों, वस्तु का प्रकार एक-सा हो और वस्तु के स्थानान्तरण में कोई प्रतिव्यय न हो, तो उस वस्तु का एक ही समय में सर्वत्र एक ही मूल्य रहेगा। यह नहीं हो सकता है कि एक स्थान पर वस्तु उतनी हो और दूसरे स्थान पर महँगी। यदि किसी विक्रेता ने अपना मूल्य बढ़ा दिया, तो उसके अहक सुनते उसे छोड़कर अन्य सन्ने विक्रेताओं से वस्तु खरीदना प्रारम्भ कर देगे। अतः उन व्यापारी को भी अपना मूल्य उसी स्तर पर स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि स्वतन्त्र प्रतियोगिता में सस्ते मूल्य के मुकाबले में ग्राह्य की

दृष्टि में व्यापारी की निष्पत्ति एवं शब्दबद्धाद कोई महत्त्व नहीं रखता । इसी प्रकार यदि कोई क्रेता कम मूल्य देना चाहे, तो कोई विक्रेता उसे वस्तु नहीं देनेगा, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता को यह मान्य है कि उस मूल्य पर उसे बहुत-से ब्रोता मिल जायेंगे । अतः क्रेता को धिक्का होकर वही मूल्य देना पड़ेगा जो धन्य क्रेतावर्ग दे रहे हैं । इस प्रकार बाजार में एक ही समय में एक वस्तु का मूल्य एक ही होता है । अस्तु, एक ही समय में एक वस्तु का मूल्य प्रचलित होने की प्रवृत्ति को बाजार का नियम (Law of Market) कहते हैं ।

यह स्मरण रखने योग्य बात है कि बाजार में पूर्ण प्रतिযোগिता आदि दशाओं में एक ही समय एक ही वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता स्वाभाविक है । मूल्य में कोई अन्तर है तो वह केवल यातायात-व्यय (Cost of Transport) जिसमें भाषा-वीणा व्यय, इनामी, बैंक-न्योदान, चुगी-कर आदि सम्मिलित होते हैं, सीमित होता है । अस्तु, यदि बाजार विस्तृत हो, तो यातायात-व्यय के कारण मूल्यों में अन्तर सीमा देना चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि बनपुर और आगरा के बीच गेहूँ का याता-यात व्यय ₹ ६० मन है, तो दोनों के बीच में गेहूँ के मूल्य में एक रुपये तक का ही अन्तर मिलेगा । यदि इसे निकाल दिया जाय, तो दोनों स्थावा का मूल्य एक-सा हो जायगा ।

उदासीनता का नियम (Law of Indifference) — यदि प्रतियोगिता पूर्ण एवं स्वतन्त्र हो और वस्तु एक ही प्रकार की हो, तो एक ही समय में उससे प्रत्येक भाग का एक ही मूल्य होगा, और उनका कोई भी भाग उसके किसी दूसरे भाग में जिसे उदासीनतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है । इनका कारण यह है कि जब वस्तुएँ समान होने से क्रेता विक्रेता विशेष की भाँति से उदासीन (Indifferent) रहता है । जहाँ वस्तु सस्ती मिलती है वह वही में खरीद लेता है । किसी द्वारा उस वस्तु की पूर्ति की गई, वह तनिक भी जानने की इच्छा नहीं करता । इसी प्रकार विक्रेता भी क्रेता-विशेष की भाँति से उदासीन रहता है । जो उसे अधिक मूल्य दे उसे ही वस्तु देव देता है । उस वस्तु की सब इकाइयाँ समान होने तथा क्रेता और विक्रेता की पारस्परिक उदासीनता के कारण ही मूल्य एक रहता है । अतः इस प्रवृत्ति को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेक्स (Jexons) ने उदासीनता का नियम (Law of Indifference) कह कर पुकारा है । यदि ऐसा न हो और क्रेता किसी विशिष्ट विक्रेता अर्थात् दुकानदार से वस्तु खरीदे अथवा दुकानदार किसी विशिष्ट क्रेता अर्थात् ग्राहक की ही वस्तु बेचे, तो बाजार में मूल्य का अन्तर हो सकता है । इस नियम के अनुसार एक ही बाजार में एक ही समय में एक ही वस्तु का एक ही मूल्य होना चाहिये । यदि वह नियम लाघ होता है, तो बाजार पूर्ण नहलायेगा अथवा अपूर्ण ।

बाजारों का विकास

(Evolution of Markets)

समय बड़ा परिवर्तनशील है । धार्मिक जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य की बहुत कम आवश्यकताएँ थी । वह अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करता था । अस्तु, उस समय में विनिमय की कोई आवश्यकता थी और न मंडी अथवा बाजार का ही कोई अस्तित्व था । धीरे-धीरे मनुष्य सम्पत्ति की ओर ध्यान देता और बालागुर में उगने भौतिक सम्पत्ति में बड़ी उन्नति की । पहले घटना-वृत्ता के

रूप में विनिमय प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप स्थानीय बाजारों का प्रादुर्भाव हुआ । तदनन्तर विनिमय क्षेत्र में विकास और यातायात व सम्बाध के साधनों की उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों ने जन्म लिया और बाजार सामान्यता से विभिन्नोकरण की ओर सुगमजि होने लगे ।

अतः, बाजारों के विकास का अध्ययन हम दो दृष्टिकोणों में कर सकते हैं—

(१) भौगोलिक दृष्टिकोण से, और (२) क्रियात्मक दृष्टिकोण से ।

(१) भौगोलिक विकास (Geographical Evolution)—भौगोलिक दृष्टि से बाजार तीन प्रकार के होते हैं ।

(अ) स्थानीय बाजार (Local Market)—जब किसी वस्तु के क्र्रेताओं और विक्रेताओं की व्यापारिक क्रियाएँ किसी विशिष्ट स्थान पर ही सीमित हों तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय कहा जायेगा । उदाहरणार्थ, धान, मक्की, मूँगी, सोया, सरसिका, प्लॉय मॉर्नेट, स्टेशनरी माटें आदि । शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ जैसे—दूध, दही, मक्खन, घड़े, माँग, हथ शाक, ताजा फल-फूल आदि और भारी व सस्ती वस्तुएँ जैसे—ईंट, इमारती पत्थर, बानू-रेत आदि का क्रय-विक्रय भी इसी के अन्तर्गत आता है । परन्तु अब 'शीतगार' (Cold Storage) के द्वारा ताजवान् वस्तुओं शीघ्र नष्ट होने वाली (Perishable) वस्तुओं को कई दिनों तक ताजा रखा जा सकता है । अतः जहाँ शीघ्र एवं सभ्य यातायात के साधनों के साथ-साथ 'शीतगार' की सुविधा प्राप्त है, वहाँ ऐसी वस्तुओं का बाजार अब अधिक विस्तृत हो गया है ।—

स्थानीय बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of a Local Market)—स्थानीय बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :—

(१) स्थानीय बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय किसी प्रयुक्त स्थान पर ही, जहाँ कि वह उत्पन्न भवना तैयार की जाती है, सीमित होता है ।

(२) क्र्रेता और विक्रेता प्रायः उसी स्थान के होते हैं ।

(३) यह किमी गाँव, कस्बे अथवा नगर तथा उसमें १०-१२ मील की दूरी तक ही सीमित होता है ।

(४) जो व्यापार थोड़ी मात्रा में होता है वह स्थानीय मधी तब ही सीमित रहता है, जैसे फुटकर व्यापार ।

(५) ताजवान् वस्तुओं का बाजार स्थानीय होता है, जैसे दूध, मक्खन, घड़े, माँस, मछली, हथ शाक, ताजा फल-फूल इत्यादि ।

(६) भारी एवं सस्ती वस्तुओं का बाजार स्थानीय होता है, जैसे ईंट, इमारती पत्थर, बानू-रेत, पीछी मिट्टी इत्यादि ।

(७) जहाँ वस्तु-विनिमय (Barter) प्रथा प्रचलित है वहाँ केवल स्थानीय बाजार ही होता है ।

(८) जिन वस्तुओं के क्रय-विक्रय में व्यक्तिगत रुचियों की प्रवृत्ति होती है, उनका स्थानीय बाजार होता है ।

(आ) प्रांतीय बाजार (Provincial Market)—जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय केवल किसी प्रान्त तक ही सीमित हो, तो उस वस्तु का बाजार

प्रान्तीय बाजार कहलायेगा। जैसे, मईसी व इलाहाबाद की बीस और चैन की टाकरियाँ प्रायः उ० प्र० में ही विक्रयी हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद के टुक, बरेली का फर्नीचर और अगरे ने मुड़े प्रान्तीय बाजार के कुछ अन्य उदाहरण हैं।

प्रान्तीय बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of a Provincial Market) प्रान्तीय बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) वस्तु के प्रेता और विप्रेता का किसी निश्चित स्थान अर्थात् गाँव, बस्ते या नगर तथा उसने प्राप्त प्राप्त के धन तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण जिले या प्रान्त में फैले हुए होते हैं।

(२) वस्तु घीघ्र नष्ट होने वाली नहीं है। प्रान्तीय बाजार में केवल टिकाऊ वस्तुओं का प्रत्येक विक्रय होता है।

(३) केवल प्रान्तीय महत्व एवं प्रसिद्धि की ही वस्तुएँ इसमें संचालित होती हैं।

(४) वस्तुओं का प्रत्येक विक्रय प्रायः प्रान्त की सीमा तक ही सीमित रहता है।

(५) **राष्ट्रीय बाजार (National Market)**—जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय देशव्यापी हो, अर्थात् उसके खेता और विक्रेता सारे देश में फैले हुए हों, तो उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय अर्थात् राष्ट्र या देश व्यापी बाजार कहलायेगा। उदाहरणार्थ, धोतियाँ, साड़ियाँ, चूड़ियाँ, भारतीय टोपी, पगड़ी व माफा, भारतीय स्वयं व नोट, हुका, भारतीय कम्पनियाँ और बैंकों के सेंटर रिजर्व बैंक के सेंटर माफ-यंत्र, सगमरमर का पर्यर आदि वस्तुओं का प्रत्येक विक्रय तथा चलन बसत भारतवर्ष में ही सीमित है, अतः इनका बाजार राष्ट्रीय व्यापी है। इसी प्रकार खाद्यान्न, रई, वस्त्र, चादी, सोना, मसाला आदि वस्तुओं का भी राष्ट्रीय बाजार है। जो वस्तुएँ टिकाऊ और मूल्यवान हैं उनका बाजार प्रायः राष्ट्रीय व्यापी होता है।

राष्ट्रीय बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of a National Market)—राष्ट्रीय बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं —

(१) राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं का प्रत्येक विक्रय तथा चलन किसी देश की सीमा तक ही सीमित होता है। जैसे भारतीय पगड़ी, टोपी, स्वयं व नोट, साड़ियाँ, धोतियाँ, चूड़ियाँ आदि।

(२) जो वस्तुएँ टिकाऊ तथा मूल्यवान हैं उनका बाजार राष्ट्रीय व्यापी होता है। जैसे—रई, चादी, सोना इत्यादि।

(३) जिन वस्तुओं के नमूने निकाले जा सकते हैं तथा जिनका क्रय-विक्रय, प्रसं वषण (Grading) एवं विवरण द्वारा हो सकता है, तो उन वस्तुओं का राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे—वस्त्र, खाद्यान्न आदि।

(४) राष्ट्रीय बाजार का महत्व किसी एक राष्ट्र या देश तक ही सीमित होता है।

(५) जिन वस्तुओं की माँग व पूर्ति राष्ट्रव्यापी होती है, तो उनका बाजार भी राष्ट्रीय व्यापी होता है।

(ई) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (International or World Market)

जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय संसार के सभी भागों में होता हो, अर्थात् उसके क्रेता और विक्रेता सम्मत् संसार में फैले हों, तो उस वस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी बाजार कहलायेगा। उदाहरणार्थ, गेहूँ, रुई, ऊन, चमड़ा, जूट, चाय, चाँदी, निम्बू, चाँदी, सोना तांबा, मोहरा व इत्यादि, पेट्रोल, रेशमी वस्त्र, स्वेज नहर के देशों में मांस पर, पूँजी (Capital) आदि। सोनागार एवं यानवाहन के मापनों की सुविधा के कारण जूट, धान, गेहूँ आदि की भी मंडी होने वाली वस्तुओं का भी बाजार अत्यन्त विश्वव्यापी होता जा रहा है। आस्ट्रेलिया का माँस आरु सोनागार के कारण हो। इंग्लैंड के निवासियों की लक्ष्मियों की अपनी ताजा हालत में मुनोमिन कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रथवा विश्वव्यापी बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of World or International Market)—एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथवा विश्वव्यापी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं।

(१) जिन वस्तुओं के इतना ही और बिजनेसों की पारम्परिक प्रतियोगिता विश्वव्यापी हो, तो उन वस्तुओं का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय होगा। जैसे—गेहूँ, रुई, चाँदी, सोना, स्वेज नहर के देशों इत्यादि।

(२) जिन वस्तुओं की माग और पूर्ति संसार के अनेक विश्वव्यापी हो तो उन वस्तुओं का राष्ट्रीय बाजार होगा। जैसे—गेहूँ, रुई, चाय, तांबा, चाँदी, सोना, ताँहा इत्यादि।

(३) जिन वस्तुओं का प्रत्येक नमूना (Samples of Patterns), जन-वर्णन (Grading) तथा विवरण (Description) द्वारा हा सजता है, तो उनका बाजार विश्वव्यापी होगा। जैसे—बरत, रुई, ऊन, चाय, गेहूँ इत्यादि।

(४) जिन वस्तुओं में अल्प भार में अधिक मूल्य ले जान की शक्ति है, उनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे—चाँदी, सोना इत्यादि।

(५) जो वस्तुएँ टिकाऊ हैं तथा जिनकी लम्बे समय में है, उनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे—गेहूँ, रुई, मोहरा आदि।

(२) क्रियात्मक विकास (Functional Evolution)—क्रियात्मक दृष्टि से बाजार निम्न प्रकार के होते हैं :—

(अ) सामान्य या मिश्रित बाजार (General or Mixed Market)—जिम बाजार में मनुष्य की आवश्यकता की अनेक वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता हो तो वह सामान्य या मिश्रित बाजार कहलायेगा। पुराने समय में अपने देश में बाजार सामान्य एवं मिश्रित हुआ करते थे, अर्थात् एक ही बाजार में मनुष्य की आवश्यकता की अनेक वस्तुएँ मिल जाती थी। अविश्व बाजार गाँवों में इसी प्रकार के होते हैं, परन्तु अब कुछ विशिष्टीकरण (Specialization) होने लगा है, अर्थात् भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बाजार पृथक्-पृथक् होने लगे हैं। यहों में यह प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है।

(आ) विविष्ट बाजार (Specialised Market)—बाजारों के क्रियात्मक विकास की दूसरी श्रेणी विविष्ट बाजार है। भौतिक विकास के साथ साथ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा और उनकी सख्या तथा विभागों में भी वृद्धि हुई। इनके साथ-साथ श्रम विभाजन का विकास हुआ और उपयोग के क्षेत्र में अमानवीय उत्पत्ति हुई जिसने परिणामस्वरूप बाजारों का विविष्टीकरण होने लगा अर्थात् एक ही प्रकार की कुछ वस्तुओं की एक ही स्थान में बिक्री होने लगी। उदाहरणार्थ, बड़े-बड़े नगरों में सोन-चांदी का बाजार अलग होता है जिसे सराफा कहते हैं। इसी प्रकार तरकारी बाजार पृथक् होता है जिसे मर्चें मंडी कहते हैं। घान मंडी, धी मंडी, लाहा मंडी, बनाव मार्केट, स्टेशनरी मार्केट आदि इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अस्तु, विविष्ट बाजार वह स्थान है जहाँ पर केवल एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का खय-विक्रय होता है। जैसे—मर्चों में केवल चाँदी-गहना की वस्तुओं का ही खय विविष्ट होता है, घान मंडी में विभिन्न प्रकार के अनाज खरीदे व बेचे जाते हैं।

(इ) नमूने द्वारा बिक्री (Marketing by Sample)—जब मान बड़ी मात्रा में तथा अनेक किस्मों में तैयार होने लगे, तो बिक्री के लिये मान चिन्ना कर बिक्री करने में कठिनाई होने लगी। तब नमूने द्वारा बिक्री का प्राचुर्य हुआ। अब दुकानदार अनेक नमूने लिये ही अपनी दुकान में रक्खे हैं या भेष मान स्टॉक गोशाला में रखते हैं। नमूने के आधार पर खेता और बिक्री के मध्य सीधा सम्पर्क हो जाता है। नमूने द्वारा सामानों से बाहर भेज जा सकते हैं। व्यापारिक एजेंट केवल नमूनों की महायत्ना में ही बाजार प्राप्त कर पाते हैं। खाद्यान्न, रुई, गरम मसाले, चाय, कपड़ा, दवाइयाँ आदि वस्तुओं का खय विविष्ट नमूनों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। हमारे पास व्यापार में अधिकतर यही रीति काम में लायी जाती है। अस्तु, नमूने द्वारा बिक्री करने का वह ढंग है जिसमें नमूने द्वारा व्यापारियों के मध्य सीधा सम्पर्क किया जाता है।

(ई) ग्रेड द्वारा बिक्री (Marketing by Grade)—ग्रेड द्वारा बिक्री की पद्धति के नमूने स्थान की आवश्यकता का भी प्रमाण कर दिया। इस पद्धति के अन्तर्गत एक ही वस्तु के अनेकों विभागों के अनुसार विभिन्न ग्रेड अर्थात् वर्ग निर्दिष्ट कर दिये जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग का एक पृथक् नाम या चिन्ह (Trade Mark) निश्चित कर दिया जाता है। तब उन्हीं वर्गों अर्थात् ग्रेडों के आधार पर वस्तुओं का खय विक्रय होता रहता है। उदाहरणार्थ, गन्ने के बड़े ग्रेड हैं, जैसे पूमा न० १२, आर्मेनिया न० २ आदि, चाय भी बड़े ग्रेडों में विभक्त है जैसे अरिज पोकाव न० १, निपटन चाय आदि, रुई को मंडोच, बगान, ऊमरा आदि अनेक ग्रेडों में बाँट रखते हैं। इसी प्रकार नोटून, पहरपात, तीन हाथी आदि प्रसिद्ध लट्टे (एच कपड़ा विशेष) की किस्म हैं। ये ग्रेड अपने प्रसिद्ध और गुणवर्तिन होने के कारण बिना देख के खय नाम में ही खोले जाते हैं। इस पद्धति के कारण केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि विश्व-व्यापी हो जाता है। अस्तु, ग्रेड द्वारा बिक्री करने का वह ढंग है जिसमें एक ही वस्तु किस्मों के अनुसार बड़े ग्रेडों अर्थात् वर्गों में विभक्त कर दी जाती है और उनके अलग-अलग नाम या चिन्ह नियत कर दिये जाते हैं जिनके आधार पर खय-विक्रय होता रहता है।

बाजारों के भेद

(Types of Markets)

बाजारों का विभाजन मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है—

क्षेत्रानुसार और कालानुसार ।

१. क्षेत्रानुसार बाजार (Space Markets)—क्षेत्र की दृष्टि से बाजारों को हम स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विभक्त कर सकते हैं। इनका विस्तार विवेचन ऊपर किया जा चुका है अतः इन्हें यहाँ दोहराना विटरेपण मान है।

२. कालानुसार बाजार (Time Markets)—समय के आधार पर बाजारों को हम दैनिक, अल्पकालीन और दीर्घकालीन बाजारों में विभक्त कर सकते हैं। यह विभाजन वस्तु की माँग (Demand) और पूर्ति (Supply) के समतुल्य (Equilibrium) अर्थात् समानता के लिये जितना समय या अवधि आवश्यक होती है उस पर निर्भर रहता है। यह बात नीचे के विवरण में स्पष्ट हो जाती है :

(अ) दैनिक बाजार (Daily Market)—इसे दैनिक बाजार इसलिए कहते हैं कि यह कुछ ही घंटों समया एक या दो दिन तक ही रहता है। इसीलिये इसे अति अल्पकालीन बाजार (Very Short Period Market) भी कहते हैं। इसमें किसी वस्तु की पूर्ति (Supply) विस्तृत निश्चित एवं सीमित होती है और तुरन्त घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, किन्तु उसकी माँग में घटा-बढ़ी हो सकती है। इसमें समय इतना कम होता है कि किसी वस्तु की माँग बढ़ाने पर उस वस्तु का स्टॉक जो उस समय उपलब्ध है बढ़ाना नहीं जा सकता, क्योंकि इतने अल्प समय में वह वस्तु न तो उत्पन्न या तैयार की जा सकती है और न बाहर से ही भेगाई जा सकती है। अतः, माँग बढ़ने पर उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार माँग घट जाने पर मूल्य भी कम हो जाता है। अतः, ऐसे बाजार में मूल्य निर्धारण में माँग (Demand) का मुख्य हाथ होता है। प्रायः शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार दैनिक अथवा अति अल्पकालीन होता है, जैसे—दूध, मक्खन, मांस, पछनी, घड़े, ताजी तरकारियाँ, फल-फूल, बर्फ इत्यादि। अतः, दैनिक अथवा अति अल्पकालीन बाजार वह है जो बहुत ही छोटे समय अर्थात् कुछ ही घण्टों या दिनों तक रहता है और जिसमें वस्तु की माँग की मूल्य-निर्धारण में पूर्ण प्रधानता होती है।

दैनिक बाजार की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) यह बाजार अति अल्पकालीन होता है, अर्थात् कुछ घण्टों या एक-दो दिन तक ही रहता है।

(२) इस प्रकार के बाजार की प्रधानता यह है कि वस्तु-विशेष की पूर्ति (Supply) अर्थात् स्टॉक जो उस समय उपलब्ध है निश्चित होता है, उसमें न्यूनाधिकता करना विस्तृत सम्भव नहीं है, क्योंकि समय बहुत छोटा होता है।

(३) दैनिक बाजार में किसी वस्तु के मूल्य-निर्धारण में माँग की प्रधानता होती है, अर्थात् माँग की न्यूनाधिकता से ही मूल्य प्रभावित होता रहता है।

(४) दैनिक बाजार में बेचने योग्य वस्तुओं का ही अप्रचलित होता है। उदाहरणार्थ, दूध, मक्खन, ताजा तरकारियाँ, फल फूल, धाँसे, माँस, मछली, बर्क इत्यादि।

(५) इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं का मूल्य माँग की अनुरूपता के प्रभाव में जल्दी-जल्दी बदलता रहता है। उदाहरण के लिये, तेल घूप में दफों की माँग बढ़ जाने पर इसका मूल्य भी घटित हो जाती है, परन्तु एकदम बर्बाद हो जाने पर इसकी माँग में कमी हो जायगी और उसका मूल्य भी कम हो जायगा।

(६) दैनिक बाजार में प्रचलित मूल्य जिसमें घटा धीरे शून्य-राश में होती रहती है, बाजार मूल्य (Market price) कहलाता है।

(भा) अल्पकालीन बाजार (Short Period Market)—इस प्रकार के बाजार का समय दैनिक अथवा अल्पकालीन बाजार के समय की अपेक्षा अधिक लम्बा होता है, परन्तु यह कुछ महीनों तक या वर्ष-वर्षान्त रहता है। दैनिक अपेक्षा अल्पकालीन बाजार में तो वस्तु की पूर्ति (Supply) निश्चित (Fixed) होती है, उसमें एक बड़ी तहकी की जा सकती, परन्तु अल्पकालीन बाजार में पूर्ति कुछ अल्प तक बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस कार्य के लिये कुछ समय मिल जाता है। जिसमें वह वस्तु बाहर से मँगाई जा सकती है तथा वर्तमान माँगों का और अधिक प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिये, पारदन्तु में मछली की माँग बढ़ जाने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। थोड़े हुए मूल्य का लाभ उठाने के लिये अब मछुए अपने आला आदि में अधिक समय तक काम करके प्रतिदिन अधिक मछलियाँ पकड़ना प्रारम्भ कर देंगे। इसी प्रकार पूर्ति घटाई भी जा सकती है। यदि पारदन्तु समाप्त हो गई है और मछली की माँग में कमी आ गई है, तो कुछ मछुए अपने जाना का उठा कर रख देंगे और काम करने के समय में भी कमी कर देंगे। परिणामतः माँग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के अनुसार हो जायेंगे और मूल्य बहुत कुछ लागत (Cost of production) के लगभग ही रहगा। यद्यपि इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण में माँग और पूर्ति दोनों का ही हाथ रहता है, फिर भी पूर्ति की अपेक्षा माँग का अधिक महत्व होता है। अल्पकालीन बाजार यह है जो कुछ महीनों तक अथवा वर्ष-वर्षान्त रहता है तथा जिसमें माँग और पूर्ति के समतुल्य के लिये समय मिल जाने पर भी मूल्य निर्धारण में माँग का कुछ अधिक महत्व रहता है।

अल्पकालीन बाजार की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) इसमें समय दैनिक बाजार की अपेक्षा अधिक होता है, परन्तु यह बाजार कुछ महीनों या वर्ष भर तक ही रहता है।

(२) इसमें इतना समय मिलता है कि माँग के अनुसार पूर्ति का समन्वय हो सकता है।

(३) यद्यपि इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण में माँग और पूर्ति दोनों का ही हाथ रहता है, फिर भी पूर्ति की अपेक्षा माँग का अधिक महत्व होता है।

(४) इसमें मूल्य लागत के लगभग रहता है, पूर्ण रूप से लागत में निर्धारित नहीं होता है।

(५) इस प्रकार के बाजार में प्रचलित मूल्य अल्पकालीन (Short-Period) अथवा 'अध-सामान्य' (Sub normal) मूल्य कहलाता है।

(६) दीर्घकालीन बाजार (Long Period Market)—यह बाजार कितने ही महीनों और कभी-कभी वर्षों तक चलता रहता है । इसमें पूर्ति (Supply) का मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है । इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में पूर्ति के साधन माँग के अनुसार सीधेता से बढ़-बढ़ सकते हैं । माँग में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी निम्नलिखित साधनों द्वारा वृद्धि की जा सकती है :—

(१) उत्पात्ति के परिमाण में वृद्धि करने से, (२) उत्पादन-क्रिया में उत्पत्ति करने से, (३) अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम को इस ओर लगा कर, (४) अन्य उत्पादन कार्यों में से पूँजी हटाकर इस ओर लगाकर, और (५) उत्पादन-यन्त्रों में परिवर्तन कर ।

इसी प्रकार यदि माँग में कमी हो जाती है, तो पूर्ति भी उपयुक्त वृद्धि के साधनों के विपरीत कार्य करने में धटाई जा सकती है । उदाहरणार्थ, इस कार्य में लगी हुई पूँजी और श्रम हटा कर अन्य कार्यों में लगाये जा सकते, हैं आदि । ममय पूर्ति की मृताधिकता के लिये पर्याप्त होता है, अतः मूल्य बढ़ना स्वाभाविक रहता है । कभी-कभी यह भी सम्भव है कि यह छीक लागन के बराबर ही हो जाय । इस प्रकार दीर्घकालीन बाजार में मूल्य-निर्धारण में पूर्ति (Supply) का पूर्ण हाथ रहता है । उदाहरणार्थ, यदि मछली की माँग में वृद्धि स्वाभाविक है, तो जालों, तावा आदि मछली पकड़ने के साधनों में वृद्धि करके अतिरिक्त अधिक मछुल इस काम में लवाये जायेंगे और काम करने में समय में भी वृद्धि कर दी जायगी । इसी प्रकार माँग की कमी होने पर समय, मनुष्य और साधनों में कमी कर दी जायगी । विश्व-गहायुद्ध आदि असाधारण परिस्थितियों में जब किसी वस्तु का मूल्य एक समये समय तक बहुत ऊँचा स्वाभाविक रूप में स्थिर हो जाता है, तो उस वस्तु के अनेक नये कारखाने खुल जाते हैं और पुराने कारखानों में सुधार एवं विस्तार हो जाता है । अस्तु, दीर्घकालीन बाजार वह है जो कई महीनों तथा वर्षों तक रहता है और जिसमें पूर्ति की माँग के अनुसार बदलने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है तथा मूल्य निर्धारण में पूर्ति का विशेष महत्व होता है ।

दीर्घकालीन बाजार की विशेषताये (Characteristics)

(१) इसमें ममय अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अर्थात् यह बाजार कई महीनों तक और कभी-कभी वर्षों तक चलता रहता है ।

(२) इसमें इतना पर्याप्त समय मिलता है कि माँग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है ।

(३) इस प्रकार के बाजार में मूल्य-निर्धारण में पूर्ति का पूर्ण हाथ होता है ।

(४) यदि मूल्य स्वाभाविक रूप से एक समये समय तक लागत (Cost of Production) से नहीं अधिक रहता है, तो उत्पादन-साधनों में वृद्धि कर उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है और यदि मूल्य लागत में कहीं अधिक नीचा स्थिर हो जाय तो उत्पादन-साधनों को कम कर उत्पत्ति में कमी की जा सकती है ।

(५) दीर्घकालीन बाजार मूल्य 'सामान्य मूल्य' (Normal Price) कहलाता है ।

(ई) अति दीर्घकालीन बाजार (*Secular or Very Long Period Market*)—यह बाजार बहुत लम्बे समय अर्थात् ५० वर्ष अथवा अधिक समय तक रहता है । इस प्रकार के लम्बे समय में केवल माँग और पूर्ति में संतुलन हो नहीं हो जाता बल्कि उनमें अनेक परिवर्तन होने के पश्चात् भी समन्वय हो जाता है । उदाहरणार्थ, सोने की उत्पत्ति-परिवर्तन, जन-संख्या की वृद्धि, रुबि और पैंशन के परिवर्तन आदि बातें हैं जो माँग में परिवर्तन हो जाता है उसका दूरा अत्यधिक लम्बे समय में पूर्ति के परिवर्तन में, जो विज्ञान की उन्नति, मशीनों के आविष्कार, यातायात के विकास, उत्पत्ति के सुधार और खनिज पदार्थों के अनुपयोग से होता है पूर्ण समन्वय हो जाता है । अतः, अति दीर्घकालीन बाजार वह है जो बहुत लम्बे समय अर्थात् ५० वर्ष अथवा अधिक समय तक प्रचलित रहता है और जिसमें केवल माँग और पूर्ति के संतुलन के लिये ही पर्याप्त समय नहीं मिलता बल्कि इसमें अनेक परिवर्तन होने के पश्चात् भी संतुलन हो जाता है ।

अति दीर्घकालीन बाजार की विशेषताएँ (*Characteristics*)

(१) इसमें समय कई वर्षों का होता है—यह कभी कभी तो सैदियों तक रहता है ।

(२) इसमें समय इतना पर्याप्त होता है कि केवल माँग और पूर्ति में संतुलन ही नहीं हो जाता बल्कि इन दोनों में अनेक परिवर्तन होने के पश्चात् भी संतुलन होना सम्भव हो जाता है ।

(३) इस प्रकार के बाजार में प्रचलित मूल्य (जो 'अति दीर्घकालीन मूल्य' (*Secular Price*) कहते हैं ।

चोर बाजार (*Black Market*)—जब वस्तुओं का लब्ध-विक्रय खुले बाजार में न होकर चुपचाप राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य से ऊँचे मूल्य पर होता है, तो इसे चोर बाजार कहते हैं । यह काला बाजार, ब्लैक मार्केट या अश्वैय बाजार आदि नामों से भी पुकारा जाता है । जब विशेष परिस्थिति बरा वस्तुओं की पूर्ति माँग की अपेक्षा कम हो जाती है, तो चोर बाजार जन्म पा लेता है । गत युद्धकालीन समय में चोर बाजार का पर्याप्त खोर रहा और अब भी बहुत सी वस्तुएँ चोर बाजार से ही प्राप्त हो सकती हैं । जब माँग की तुलना में आवश्यक पदार्थों की कीमते कम हो जाती है, तो उनके दाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं । तब जनता की भलाई के लिये सरकार उनका उचित मूल्य निर्धारित कर देती है जिसे मूल्य नियन्त्रण (*Price-Control*) कहते हैं । प्रायः मूल्य-नियन्त्रण के साथ-साथ राशनिय (*Rationing*) भी (अर्थात् एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितनी मात्रा ले सकता है) प्रचलित कर दिया जाता है । उदाहरणार्थ खाद्यान्न, कपड़ा, चीनी, कागज, दवा, तेल व पेट्रोल, सोपे, मोझे का सामान आदि वस्तुएँ बत महायुद्ध और उसके पश्चात् भी पर्याप्त समय तक सरकारों नियन्त्रण में रही और उनके वितरण के लिये राशनिय व्यवस्था प्रचलित थी ।

बहुधा उत्पादक और व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं को नियन्त्रित मूल्य पर बेचना पसन्द नहीं करते, इसलिये वे लोग इन्हें खिपा (Hoarding) कर रख लेते हैं जिससे उनकी पूंति और भी कम हो जाती है। जनता आवश्यक वस्तु के प्रभाव में परेशान होकर ज्यों तौर से अधिक मूल्य पर खरीदने के लिये तत्पर हो जाती है और इस प्रकार चोर बाजार का निर्वात चक्र चरता रहता है। राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचना अवैध (Illegal) होता है, वस्तु ऐसे विहता पर खुराना किया जा सकता है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। किन्तु ऐसा होना पर भा चोर बाजार पनप रहा है, क्योंकि अत्यधिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित होकर व्यापारी लोग कानून का उल्लंघन करने को तैयार हो जाते हैं। संशय में चोर बाजार आवश्यक वस्तुओं की कमी, उनकी माँग की अधिकता, मूल्य-नियन्त्रण, जनता के पारा अधिक रूप का होना (मुद्रा स्थिति), वस्तु वितरण की दूषित प्रणाली, सरकारी नियन्त्रण की अपूर्णता आदि कारणां ये बढ़ता है। चोर बाजारी से मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, गरीब जनता आवश्यक वस्तुओं के लिये वंचित रहती है, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैल जाता है और देश में सर्वत्र अशांति छा जाती है। अस्तु, इन बुराइयों को दूर करने के लिये प्रबल सरकारी नियन्त्रण आवश्यक है।

चोर बाजार सम्बन्धी बुराइयों को दूर करने के उपाय—निम्नलिखित उपायों द्वारा चोर बाजार का अन्त हो सकता है : -

(१) सबसे प्रथम तो कण्ट्रोल तथा राशन उन्हीं वस्तुओं का होना चाहिये जिनकी वास्तव में कमी हो, और जिनके उत्पादन तथा वितरण पर सरकार कठोर नियन्त्रण रख सकती हो।

(२) नियन्त्रित मूल्य ऐसा होना चाहिये जिसमें लाभ की काफी छुजावश रहे जिसमें उत्पादक और व्यापारी लोग चोर बाजार से वस्तुएँ बेचने में लिये प्रोत्साहित न हो।

(३) वस्तु-वितरण में सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। उक्त तो यही है कि वितरण सरकार स्वयं सहायरी समितियों द्वारा किया करे।

(४) इस कार्य की देख-भाल करने वाले सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी ईमानदार तथा कर्तव्यपरामर्श होने चाहिये।

(५) कानून तोड़ने वालों की कड़ा दण्ड मिलना चाहिये।

(६) जनता का सहयोग भी आवश्यक है। अस्तु जनता को जहाँ तक हो सके चोर बाजार से वस्तु न खरीदने का प्रण करना चाहिये।

(७) मूल्य-नियन्त्रण और राशनबन्ध व्यवस्था को सफल बनाने के लिये सरकार द्वारा नियन्त्रित वस्तुओं को आयात आदि माधमों से अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

भारत सरकार का कार्य—भारत सरकार में चोर बाजार आदि भ्रष्टाचारों को रोकने के लिये कई कानून बनाये। 'फूड ग्रैन्स कण्ट्रोल आर्डर' के द्वारा राशन-पदार्थों की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। वनत खाने प्राणी में कमी वाले प्राणी में खाद्यान्नों की वृद्धिशील किया। भोज आदि पर प्रतिबन्ध लगाया गया। सम्पूर्ण देश में समुचित वस्तु वितरण व्यवस्था के लिये टैक्सटाइल कमिशनर की नियुक्ति की गई जिसके द्वारा विविध प्रांतों के लिये उनकी आवश्यकता के अनुसार कपडे

का बोट (Quota) निश्चित किया गया और कई टेक्सटाइल सम्बन्धी कानून बनाये गये। लायाना की कमी को पूरा करने के लिये विदेशों से भारी आयात की व्यवस्था की गई।

निष्कर्ष—भारत में अब ऐसी अवस्था घाबई है कि राशन तथा वस्तुओं तोड़ दिया जाय तो कुछ दिनों में ब्लैक मार्केट अर्थात् चोर बाजार घपने-भाप समाप्त हो जायगा। स्वर्गीय महात्मा गांधी तो कच्चेले आदि व्यवस्था से सहमत नहीं थे। उनके मतानुसार वस्तुओं में वस्तुओं की कृत्रिम क्लृप्ति (Artificial Scarcity) उत्पन्न हो जाती है। सामंजस्य में क्या जाय ता वस्तुओं और राशनिंग की सकलता जनता के कार्रवाई पर निर्भर है। उमरा नैतिक स्तर ऊँचा होना चाहिए। उनमें देश-प्रेम और कर्तव्य-परायणता के साथ बूट-बूट कर लगे होने चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो उन देशों में तो जहाँ शांति बाल में भी वस्तुओं के स्थायी अभाव के कारण सदैव राशनिंग प्रचलित होता है, काम चलना ही कठिन हो जाय। समाजवादियों (Socialists) का विश्वास है कि हमारा अर्थ-व्यवस्था में समय समय पर जा सकट उत्पन्न होने हैं, जगता एक बड़ा कारण वस्तुओं का मूल्य में अचानक उतार-चढ़ाव है। धन, किसी भी मनुष्यिक अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य का स्थिर रहना आवश्यक है।

बैध या उत्तम बाजार (Legal or Fair Market)—जब बाजार में वस्तुओं नियमित मूल्य पर बेची जायें, तो वह वैध या उत्तम बाजार कहलाता है। इस प्रकार के बाजार की नियमित बाजार (Controlled Market) भी कहते हैं।

खुला बाजार (Open Market)—जब बाजार में वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण न हो तथा मांग और पूर्ति के अनुसार अर्थात् स्पर्धा और विक्रेताओं को पारस्परिक प्रतियोगिता के फलस्वरूप जो मूल्य प्रचलित हो उनके अनुसार वस्तुओं का क्रय-विक्रय हो, तो ऐसे बाजार की हम खुला बाजार कहेंगे। सरकारण अवस्था में जब वस्तुओं के क्रय विक्रय पर विनी प्रकार का नियंत्रण अवस्था प्रविष्ट न हो, तब ऐसे बाजारों का अस्तित्व देखा जा सकता है।

बाजार का विस्तार (Extent of Market)

बाजार के विस्तार से यह भाग्य है कि किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं के संसार के किन-किन भागों में प्रतियोगिता होती है। यदि प्रतियोगिता का क्षेत्र बड़ा है तो बाजार का विस्तार भी विस्तृत होगा, अन्यथा बाजार का विस्तार सङ्कुचित कहा जायगा। वस्तुओं के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालने वाली बातें निम्नलिखित हैं।

(अ) देश की आन्तरिक अवस्था, और

(ब) वस्तु का गुण।

(अ) देश की आन्तरिक अवस्था (Conditions within the Country)—बाजार की सीमाओं का प्रभावित करने वाली आन्तरिक दशाएँ निम्नलिखित हैं —

(१) शांति, सुरक्षा, न्याय और सचाई (Peace, Security, Justice & Honesty)—बाजार का सीमाओं पर देश में व्याप्त शांति, सुरक्षा, न्याय और सचाई का गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यापारी लोग अपना मान निर्भीक होकर

सुदूर स्थानों को तब ही भेजने जबकि उन्हें इस बात का विश्वास होना कि उनका सामान सुरक्षित पहुँच जायगा और उनके सामान का मूल्य उन्हें मिल जायगा। यदि किसी बाजार में सामान के पहुँचने की अवधि में कोई गड़बड़ हो जाय, तो सरकार उनकी सहायता करेगी। व्यापारियों में निष्ठा और भ्रष्टाचार में न्याय होने की दशा में व्यापारी लोग देश के किसी भाग में भ्रष्टाचार भेजने में नहीं हिचकेंगे। यही तो सुशासन व्यवस्था का परिणाम है।

व्यापार के दिन भर में अनेक मोदे मौलिक रूप में तब होने रहने हैं और प्रत्येक के लिये कानूनी इकरारनाम होना बड़ा कठिन है। अतः व्यापारिक नैतिकता (Business Morality) का उच्च स्तर भी बाजार के विस्तार के लिये आवश्यक है।

(२) यातायात और मर्याद के उत्तम, सस्ते और तीव्र साधन (Efficient Cheap and Quick Means of Transport & Communication) :—बाजारों के विस्तार में यातायात और मर्याद के उत्तम, सस्ते और तीव्र साधनों का बड़ा हाथ है। अच्छी गड़कों, मोटर, रेल, समुद्री जहाज और वायुयानों के कारण ही आज विभिन्न देशों के बीच व्यापार सम्भव हो गया है। डाक, तार, टेलीफोन, सेलार के तार आदि द्वारा दूर-देशों के व्यापारियों में सम्पर्क स्थापित हो गया है। इनके द्वारा व्यापारी लोग आज बड़े बड़े हो मोदे तय कर लेते हैं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। यातायात व मर्याद के विविध साधन केवल बाजारों का ही विस्तार नहीं करने, बल्कि इनमें वस्तुओं के मूल्य के एकीकरण में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय इनकी ही है।

(३) मुद्रा प्रणाली साधन एवं बैंकिंग प्रणाली—(Efficient Currency, Credit & Banking System) :—बाजारों के विकास के लिये मुद्रा के प्राथमिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता (Stability) निम्नलिखित आवश्यक है। यदि मुद्रा का मूल्य बहुत जल्दी-जल्दी घटता या बढ़ता है, तो व्यापारियों का अधिक लाभ-हानि हो सकती है। इसी प्रकार बाजार के विस्तार के लिये एक उत्तम बैंकिंग प्रणाली का होना आवश्यक है। अच्छे बैंकों के होने में उचित धन पर ऋण मिल सकता है। मान की विविधता के द्वारा पैसाई जा सकती है और धन का मूल्य हुंडी, बिल, चेक आदि साधनों द्वारा चुकाया जा सकता है। धन के बाजारों के विस्तार का बहुत कुछ श्रेय चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सेप्शन, हुंडी आदि साधनों को है। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा दूरस्थ व्यापारियों की आर्थिक स्थिति और मर्चाई के विषयों में विशिष्ट मूल्यांकन प्राप्त हो सकती है। इससे व्यापारियों का दूरस्थ प्रदेशों में व्यापार करने में प्रोत्साहन मिलता है और बाजारों का क्षेत्र विस्तृत होता है।

(४) व्यापार के वैज्ञानिक ढंग (Scientific Methods of Business) :—व्यापार करने के ढंगों का भी बाजार के विस्तार पर पूरा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान-ज्ञान, विज्ञान, प्रदर्शनी, मिनेम आदि आधुनिक व्यापारिक ढंगों में बाजारों की सीमाओं को विस्तृत करने में बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। नवीन वस्तुओं के निर्माण एवं उनके उपयोग का दूर देशों में विज्ञान, वाइडरिन्ग, छपाई, यांत्रिक एजेंट आदि साधनों द्वारा असीमांसी किया जा सकता है। मनुष्य वस्तुएँ तब ही खरीदेंगे जबकि उन्हें उनके बारे में जानकारी हो। वस्तुओं की जानकारी विविध प्रकार के विज्ञानों द्वारा असीमांसी प्रकार हो सकती है। आज अनेक विदेशी वस्तुएँ इस प्रकार के

प्रकार के आधार पर ही भारतवर्ष में मिलती हैं। इसी प्रकार भारतीय चाय का आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार हो गया है।

(५) पैकिंग दण और डीतागार प्रणाली (Packing Method & Cold Storage)—उत्तम पैकिंग दण और डीतागार प्रणाली में भी बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता पाया जाता है। उदाहरण के लिये चाय, मांस, ताजा फल-फूल, तरकारीयाँ का बाजार पहले बस सबीण एव सीमित होता था, परन्तु पैकिंग के आधुनिक एवं वैज्ञानिक दणों और डीतागार प्रणाली द्वारा आज इन ताजवान् वस्तुओं को दूर के स्थानों पर उछी हालत में न जाना सम्भव हो गया है। अतः अतः इनका बाजार व्यापक न होकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है।

(६) श्रम विभाजन के प्रयोग की सीमा (Degree of Division of Labour)—यदि श्रम विभाजन का प्रयोग बड़ा पैमाने पर होता है, तो उपजति भी बड़ा पैमाने पर होगी। बड़ा पैमाने पर उपजति होने के कारण साम कम हो जायेंगे जिससे वस्तुएँ सस्ती होंगी, जब कोई उपयोगी वस्तु सस्ती मिलेगी, तो उस वस्तु का बाजार भी विस्तृत होगा।

(७) राज्य की नीति (Policy of the State)—व्यवस्था और राष्ट्रीय की वास्तविक मर्यादाओं को राजनैतिक एवं आर्थिक सम्मेलन पर भी बहुत कुछ बाजार का विस्तार निर्भर है। उदाहरणार्थ का राष्ट्रीय के मध्य विस्तृत बाजार तब ही सम्भव है जबकि उनमें न मर्यादक राष्ट्र पञ्चाय व्यापार (Free Trade) नीति को अपनाते। यदि व्यापार में किसी प्रकार का प्रतिबंध हो, तो बाजार सीमित होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीयता (Nationalism) स्वावलम्बन (Self sufficiency), प्रत्युत्तर (Tariffs), सुरक्षा (Protection), निषेध (Prohibition), प्रतिबंधित आयात-निर्यात, क्वाटा प्रणाली (Quota System) आदि नीतियों पर भी बाजार की सीमाओं का विस्तार निर्भर होता है।

(८) वस्तु के गुण (Qualities of a Commodity)—बाजार का विस्तृत होना बकरा दूध की आंतरिक समस्या पर ही निर्भर नहीं है बल्कि वस्तु विषय के गुणों पर ही निर्भर है। साधारणतया निम्नलिखित गुणों वाली वस्तु का बाजार विस्तृत होता है —

(१) सार्वदेशिक माँग (Universality of Demand)—सार्वदेशिक माँग वाली वस्तुओं का बाजार बहुत बड़ा होता है। जिसकी अधिक किमी वस्तु का माँग होगी, उतना ही विस्तृत उस वस्तु का बाजार होगा। उदाहरणार्थ माता, चाँदी, पैट्रोल, लोहा, कपड़ा, चाय, गेहूँ, रई, जूट, मिलन आदि वस्तुओं की माँग का क्षेत्र विश्वव्यापी है क्योंकि सभी देशों में इन वस्तुओं की माँग रहती है। शेयर (Shares) आदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ (Securities) का भी बाजार विश्वव्यापी होता है। इसी प्रकार मत्स्योपर जैसे विषयविशेष पर विषय और लक्ष्य की रचनाओं को सभी देशों के विभिन्न लोग पढ़ते हैं, इसलिये उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं का प्रयोग तथा चयन किसी स्थान विशेष तक ही सीमित है, तो उनका बाजार विस्तृत नहीं होता। उदाहरण के लिये, अफगानी चप्पन, माडियाँ, घाँसियाँ, टाँसियाँ, पगडा आदि वस्तुओं की माँग अधिकतर भारतवर्ष तक ही सीमित है, इसलिये इनका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय न होकर बस राष्ट्रीय है।

(२) टिकाऊपन (Durability)—बहुल मात्रा में यथा गौध नष्ट होने वाली वस्तुओं को सुदूर भविष्य पर नहीं भेजा जा सकता। परिमाणगत उनका बाजार मरुचित होता है। फल तत्कारिणों द्वारा मक्खन अथवा मांस मशीनों आदि वस्तु इन्हीं श्रेणी में आती हैं। गोना चांदी बग़ाछ आदि वस्तुएँ टिकाऊ हैं इनमें गिरने पड़ना नष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता अब इनका अंतराष्ट्रीय बाजार होता है। ताज़ाभार (Cold Storage) तथा गौध भालापान के पायना के कारण वाणिज्य और मात्रा वस्तुओं का भी बाजार संश्लेषित विस्तृत होता पा रहा है। इसी कारण आज का भारतवर्ष में दुग्धचक्र को चला कर निर्यात सम्भव हो गया है और धार्मिकता का मांस व हड्डियाँ प्रति व्यक्तिगत बाजार की आवश्यकताओं से पूर्ति करने में ।

(३) ग्रहणायता (Portability) — विस्तृत मशीन न नियम प्रावधान है कि वस्तु का मूल्य उतना भार की क्षमता अधिक होना चाहिए। जिन वस्तुओं का पतन व क्षम होता है और मूल्य अधिक होता है उनका बाजार विस्तृत होता है जैसे—तेल, चाँदी, हीरा पन्ना, रेशम, पड़ियाँ, पाउडर, पैन आदि। इनके विपरीत जो वस्तुएं धुन नारी हैं और जिनके मूल्य की तुलना में उनका वातापान ब्यय बहुत अधिक पतना है, जैसे ईंट, इमारतों का पत्थर, घास आदि उनका बाजार स्थानीय होता है। औद्योगिक कच्चे माल और धातुओं आदि के विषय में ऐसा नहीं है, यहाँ उनसे बाजार विस्तृत होता है।

(४) गोप्रे प्रोच या नमूना निकालने व ब्रह्म वर्धन का उपयुक्तता (Commerciality of Substitute for Samhita) (विनिर्देश)—जिन वस्तुओं का संग्रहित हो जाना या परिष्कार का मतलब है अथवा जिनके नमून धामनी में नियत जा सकते हैं या जिनका एक चरण (Crude) पत्रता से हो सकता है तो उनका बाजार व्यवसाय विस्तृत होता है। ये चीज़ें गन्ना, चाय, धानि, मसूरियाँ, आदि हो सकती हैं। तथा उनके नमूने निकाले जा सकते हैं। दूरस्थ व्यापारी खदम नमूना या फ्राई के आधार पर ही चीज़ें तय कर सकते हैं। सभी प्रकार प्राप्तिगत रूप से आधार के पुर्वों के निर्माण में गोष्ट गाठिका और अन्य प्रकार की मनोना का निम्न तापा बाजार बना दिया है। भारत सरकार द्वारा बड़े एगमाक (EXHIBITS) या का बाजार अब पर्याप्त विस्तृत हो गया है।

(५) पूर्ति की पर्याप्तता (Adequacy of Supply)—यह वस्तु जिसकी पूर्ति बढ़ती है, परिमित है अर्थात् जिसकी पूर्ति मात्रा व अनुसार नहीं बढ़ाई जा सकती। उदाहरण के लिए, जल, धातु, खनिज, पत्थर, लकड़ी, आदि का बाजार बहुत सीमित होता है। यद्यपि इनकी पूर्ति बढ़ती है, परन्तु विशुद्ध बाजार के नियमों के अभाव में यह पूर्ति पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, जल की पूर्ति बढ़ती है, परन्तु जल की पूर्ति पर्याप्त नहीं होती। यद्यपि इनकी पूर्ति बढ़ती है, परन्तु विशुद्ध बाजार के नियमों के अभाव में यह पूर्ति पर्याप्त नहीं होती।

(६) ग्यानापन्न वस्तु की उपलब्धता (Availability of Substitute)—
 बिना वस्तु के बाजार का लाभ इस बात पर भी निर्भर होता है कि उस स्थान में प्रयुक्त
 की जाने वाली अन्य वित्तीय वस्तुएँ उपलब्ध हैं। यदि एक वस्तु के स्थान में बाजार की
 अन्य वस्तु प्रयास में आई जा सकती है तो उस वस्तु के बाजार का मूल मजबूत
 होगा। उदाहरण के लिये यम्बई मिन व बपडा का बाजार अधिक त्रिभूत तथा है
 क्योंकि जापान और यूएस के देशों में तैयार की जाने वाली वस्तुओं का मूल प्रतिस्पर्धा करने

है। इसी प्रकार मोटर-बस की रन स प्रतिपादिता होने में इनका बाजार सकीर्ण है। काफी घोर चाय एक-दूसरे के स्थापनापत्र है। अस्तु यदि काफी का चलन न हो तो चाय का बाजार घोर भी विस्तृत हो जाय।

(३) पूरक वस्तु की उपलब्धता (Availability of Complementary Products)—वस्तुएं एक-दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं परंतु अधिकांश में वे एक-दूसरे की पूरक भी होती हैं। जैसे फूटपाथ की मांग मोटर गाड़ी के उपयोग पर निर्भर है। इसी प्रकार जूता के पैरों की मांग जूतों की मांग के साथ सम्बद्ध है। अस्तु एक की मांग दूसरे की मांग को बढ़ाती है। यदि पूरक वस्तु उपलब्ध है तो उस वस्तु का बाजार प्रचण्ड विस्तृत होगा।

(८) वस्तु की मांग की पूर्ति की नियमितता (Regularity of future supply of a commodity)—उस वस्तु का बाजार बड़ा होगा जिसके लिये लोग को यह विश्वास हो कि भविष्य में वह वस्तु नियमित रूप में मिलती रहेगी। उदाहरण के लिये कोयला यदि भवन-संरचना में विद्यमान न हो तब तक उसको बड़ा विचार नहीं हो जाय कि भविष्य में किसी उद्योग के लिये आवश्यक मिलती रहेगी।

(९) वस्तु का फैशन में आना (A Commodity Coming into Fashion)—किसी वस्तु का बाजार उसके फैशन में आने ही विस्तृत हो जायगा। यदि उसका निरन्तर प्रयोग में लोग उस वस्तु के उपयोग के लिये आगे हा गए हैं तो उस वस्तु का बाजार घोर भी विस्तृत हो जायगा। उदाहरण के लिये चाय घोर काफी का भारस्वरूप में सीमित बाजार है। परंतु लोगों के आदी होने में इनका बाजार-क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार किसी वस्तु के फैशन में आने से उसकी मांग कम हो जाती है और फलतः उसका बाजार भी सीमित हो जाता है। भारतवर्ष में माजकन टाइल का फैशन उठता जा रहा है। इसलिये इनका बाजार भी संवर्धित होता जा रहा है।

(१०) किसी वस्तु विशेष का प्रयोग (Use of a Particular Commodity)—किसी वस्तु विशेष का बाजार क्षेत्र उसके प्रयोग पर भी निर्भर होता है। उदाहरण के लिये यदि टेलीफोन का विस्तृत रूप में प्रयोग होता है तो उसका बाजार भी विस्तृत होगा। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब फोन की सहायता कम होता है तो मांग फोन लगाना न हो चान्च क्योंकि उसकी उपयोगिता कम होगी। अधिक व्यक्तियों में वातचीत न हो कर संभव। परंतु यदि फोन रखने वालों की काफी संख्या है तो अधिक लोग फोन लगवाना चाहेंगे। जिसके फलस्वरूप फोन की मांग बढ़ेगी और उसका बाजार भी विस्तृत होगा।

(११) आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि (Increase in Economic Prosperity)—मांग एक सांख्यिक घटना है। इसका सम्बन्ध मूल्य और मात्रा दोनों में है। हम यह भी प्रति जानते हैं कि धन वृद्धि के साथ-साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। धन में सम्पन्न हो कि एक घनाश्रय व्यक्ति की मांग एक निपट व्यक्ति की मांग से बड़ा प्रमाण होगी। यदि किसी वस्तु का उपयोग गरीबों में बरत है और प्रयोग में तो वस्तु की मांग अधिक होगी जिसके फलस्वरूप उसका पूर्ति में अधिक होगा। इस प्रकार जब उस वस्तु का मांग एवं पूर्ति दोनों ही अधिक है तो उसका बाजार भी विस्तृत होता साधारण है। अस्तु आर्थिक सम्पन्नता की वृद्धि के साथ-साथ बड़ी वस्तुओं का बाजार का विस्तार जा बढ़ता है।

(१२) किसी वस्तु विशेष के लिये राज्य की नीति (State Policy for a Particular Commodity)—किसी वस्तु का बाजार राज्य की नीति पर भी निर्भर होता है । उदाहरण के लिये, ईस्ट इण्डिया कंपनी ने इंग्लैंड के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय मूलों व रेशमों वगैरह उद्योग को गढ़ करने का नीति का प्रस्ताव था । मुगल साम्राज्य ने रेशमों वस्त्रों के प्रतिरिक्त अनेक वलात्मक वस्तुओं का प्रोत्साहन देकर उनकी माँग को विस्तृत करने में पर्याप्त महायत्न प्रदान की थी । भारत सरकार भारतीय कुटीर उत्पत्ति के बाजार को विस्तृत करने के लिये देश में तथा विदेश में प्रचार कर रही है । अस्तु, किसी वस्तु का बाजार क्षेत्र विस्तृत करने में राज्य की सहायता, सुरक्षा आदि का बड़ा हाथ होता है । निम्नलिखित वस्तुओं के बाजार किस प्रकार के हैं ?

ई ट (Brooks)—इनका बाजार बड़ा सीमित है क्योंकि इनमें बहनीयता (Portability) के गुण का अभाव है ।

ताजा तरकारियाँ व फल (Fresh Vegetables & Fruits)—फल का बाजार बड़ा सीमित होता है, क्योंकि ये नाशवान् (Perishable) वस्तु हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं । परन्तु आकस्मिक शीतगार (Cold Storage) के बड़े हुए प्रचार ने इन वस्तुओं के बाजार को पर्याप्त विस्तृत कर दिया है ।

मूल्यवान् धातु (Precious Metals)—मूल्यवान् धातु जैसे सोना, चाँदी आदि का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है क्योंकि उनमें खूब भार में अधिक मूल्य रखने की सामर्थ्य होने के प्रतिरिक्त इनकी माँग सार्वदेशिक है ।

वालू रेत (Good)—वालू-रेत का बाजार बहनीयता नहीं होने के कारण सीमित एवं स्थानीय होता है ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के शेयर (Shares of the Reserve Bank of India)—बहनीयता के गुण के प्रतिरिक्त ये सब एक श्रेणी के हैं तथा इनका अत्यन्त अधिकतर भारत तक ही सीमित है । धातु इनका राष्ट्रीय बाजार है ।

स्वेज नहर के शेयर (Suez Canal Shares)—इनका अत्यधिक अल्प मात्र में विभिन्न देशों द्वारा होता है अस्तु, इनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है ।

एक पूर्वजों की घड़ी (An Ancestral Watch)—पूर्वजों की घड़ी का महत्व एक वस्तु तक ही सीमित है, अस्तु इसका कोई बाजार नहीं हो सकता है ।

चाय (Tea)—चाय की माँग सार्वभौम है तथा इसका अत्यधिक भार भी भारी भाँति हो सकता है । इसमें बहनीयता का भी गुण है । धातु इनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है ।

आम और नारंगिया (Mangoes & Oranges)—आम व नारंगियाँ जमीन पर ही सीमित नष्ट होने वाली हैं अतः इनका प्रायः स्थानीय बाजार होता है । परन्तु कुछ प्रसिद्ध आमा और नारंगियाँ—जैसे लखनऊ का खजूर, बनारस का लखड़ा, नागपुर के मंगरा आदि का बाजार अत्यधिक विस्तृत है क्योंकि सीमित आयात के माध्याम द्वारा ये फल देश में दूर-दूर भेजे जा सकते हैं । शीतगार की सुविधा के कारण कुछ भारतीय प्रसिद्ध आमा का विदेशों को निर्यात सम्भव हो गया है ।

फर्नीचर (Furniture)—इनकी आयात की अनुविधा व होने वाले टूट-फूट के कारण इनका बाजार प्रायः स्थानीय होता है, परन्तु आयात की सुविधाओं में

सुधार हो जाने से इनका प्राचीन बाजार हो गया है। उदाहरणार्थ बरेली का वना हुआ फलावर अधिकतर रु० प्र० में ही खरीदा व बेचा जाता है।

साइड्स (Sides)—साइडो में बहुनीयता रिवाजमय आदि गुण होते हुए भी वनरा यात्रा विश्व यापी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी मात्र सावदेशिक मात्र है। उनका महत्व भारतवर्ष तक ही सीमित है अथवा मात्र इनका चलन नहीं है अपन इनका स्वयं राष्ट्रीय बाजार ही है।

ताजा दूध (Fresh Milk)—माधारणतया ताजा दूध का श्रेय विश्व तथा नीय होता है क्योंकि यह दोषों रागरा होने वाली वस्तु है। गीतागर की सुविधा से कारण इसका राजा अधिक बिकत होता जा रहा है।

सोना और चांदी (Gold & Silver)—इसका बाजार केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय है क्योंकि इनमें बहुनीयता का स्वयं बड़ा गुण विद्यमान है।

कॉटन (Cotton)—कॉटन की मांग सावदेशिक है तथा यह भी दोष रहने वाली वस्तु नहीं है। यह नमूना और जनक (प्रतिग) के लिये बड़ा उपयोग है। इसका बाजार विश्व यापी है।

ग्रन्थासत्र प्रश्न

हुण्टर घाट से परीक्षाएँ

१—किसा पक्ष व बाजार (Market) का विस्तार किन कारणों पर निर्भर है ? विस्तृत बाजार को पाने के लिये किसे पक्ष को किन गुणों की प्राप्ति करना होती है ? (स० बो० १९४६)

२—बाजार गठ की परिभाषा दीजिये। स्पष्ट करके बताइय कि निम्नलिखित वस्तुओं के बाजार का धन कसा है —

(अ) नमूना आम (ब) जूट का सामान (स) कपड़े का कपड़ा (द) कुम्हार के बर्तन।

३—नारिमापिक गठ बाजार से प्राप्त क्या सम्झते हैं ? व कारण क्या क्या है जो किसी वस्तु के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालते हैं ?

(स० बो० १९४४ ५२)

४—पूर्ण और अपूर्ण बाजार में भेद बताइये। कारण सहित बताइये कि क्या निम्न लिखित वस्तुओं तथा मत्तानाक बाजार पूर्ण होता है ? (अ) Real Estates (ब) Loans of money (स) धन सेवाएँ (द) उपयोग की वस्तुएँ।

(स० बो० १९४१)

५—बाजार किरा कहते हैं ? अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय बाजार में भेद बताइये। उन में कारणों को भी स्पष्ट कीजिये जो किसी वस्तु के बाजार पर प्रभाव डालते हैं। (स० बो० १९४०)

६—बाजार का धन समझाइये और विस्तृत बाजार की निर्धारित करन धन तथा को समझाइय। विस्तृत बाजार और सीमा बाजार वाली तान तीन वस्तुओं के नाम दीजिये। (स० बो० १९४७)

७—जुट और अन्य बाजार में क्या अंतर है ? अन्य बाजार व क्या-क्या धन इसका कारण है ? (स० बो० १९४६)

८—विषय क्या है ? वह कौन से कारण हैं जो विषय के बाजार का निर्धारण करते हैं ? उदाहरण दीजिये। (सावर १९४६)

१—माँग (Demand)

माँग का अर्थ (Meaning of Demand)—मनुष्य को किसी वस्तु के लिये कोई इच्छा (Desire) माँग नहीं कहा जा सकती। इच्छा को माँग में परिणत होने के लिये उसकी प्रभावपूर्ण (Effective) होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि कौन सी इच्छा प्रभावपूर्ण कहलाती है। प्रभावपूर्ण इच्छा (Effective desire) वह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन (Means) उपलब्ध हैं और उन साधनों को प्रयुक्त करने की तत्परता (Willingness) भी है। उदाहरण के लिये, यदि कोई भिक्षावे मोटर-कार की इच्छा रखता है तो उसकी यह इच्छा हवा में महम बनाने के समान है क्योंकि मोटर-कार खरीदने के लिये उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। इसी प्रकार यदि एक कृषक अपनी मोटर-कार तो खरीदना चाहता है परन्तु वह उसके लिये रुपया खर्च करना नहीं चाहता है, तो उसकी यह इच्छा प्रभावपूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके पास मोटर-कार खरीदने के लिये पर्याप्त धन नहीं है निम्न धन के साथ उसकी इतनी खालसा है कि वह उसे खर्च करने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है। इन दोनों उदाहरणों में इच्छा केवल इच्छा ही है, प्रभावपूर्ण नहीं है। अतः ऐसी इच्छा जो प्रभावपूर्णता के गुण से रहित हो, अर्थशास्त्र में माँग नहीं कही जा सकती। मनु, अर्थशास्त्र में माँग (Demand) शब्द से केवल प्रभावपूर्ण इच्छा से ही तात्पर्य होता है। अन्य शब्दों में माँग के लिये निम्नलिखित तीन बातें आवश्यक हैं :—

- (१) किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा (Desire),
- (२) उस इच्छा को पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन (Means), और
- (३) उन साधनों के द्वारा इच्छा-पूर्ति की तत्परता, (Willingness)।

प्रश्न: अब हम यह कह सकते हैं कि माँग किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और उन साधनों द्वारा उस इच्छा को पूर्ति करने के लिये उत्तरदाता भी हो।

माँग, मूल्य और समय (Demand, Price & Time)—माँग और मूल्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना मूल्य के माँग का कोई अस्तित्व नहीं है। मूल्य के अनुसार ही हम वस्तु को माँग करते हैं। वस्तु का मूल्य कम होने पर हम उसे अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं और बड़ा जाने पर खरीद की मात्रा कम कर देते हैं। अतः माँग में किसी आवश्यक वस्तु को उस मात्रा का बोध होता है जिसे कोई किसी

अमुक मूल्य पर खरीदने को तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति दस सेर चीनी चाहे माने मेर की दर में खरीदने को तैयार हो, तो दस मेर चीनी उसकी मांग होगी। यदि केवल यही कहा जाय कि अमुक व्यक्ति की मांग दस मेर चीनी है, तो यह अर्थशास्त्रीय अर्थ में मांग नहीं हो सकती। अस्तु मांग के साथ एक निश्चित मूल्य का रहना आवश्यक है। कोई भी मांग बिना किसी निश्चित मूल्य के कोई भी अर्थ नहीं रखती। प्रत्येक मांग के साथ एक निश्चित मूल्य लगा रहता है। प्रो० पैन्सन (Penson) लिखते हैं “किसी वस्तु की मांग मदैव किसी ग्राहक या आधी ग्राहक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसी वस्तु की मांग का उसका मूल्य में परिचित सम्बन्ध होता है। वस्तु यही माना तक वस्तुओं की किसी वस्तु के खरीदने की उत्तरदाता इस बात पर निर्भर होती है कि उन्हें उनका मूल्य क्या मूल्य देना पड़ेगा। इंग्लिश मूल्य में प्रत्येक मांग के साथ कोई वस्तु नहीं है।”^१ इसके अनिश्चित मांग और समय में भी सम्बन्ध बाधा जाता है। किसी वस्तु की अमुक मात्रा अमुक मूल्य पर किसी अमुक समय पर ही उपलब्ध हो सकती है। दूसरे समय पर मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में अनुपादिकता स्वाभाविक है। वस्तु मांग मध्य समय की इकाई के साथ वनगाई जाती है, जैसे प्रति वष, प्रति मास, प्रति सप्ताह या प्रति दिन। प्रत्येक मांग एक निश्चित समय में ही प्रभावपूर्ण मानी जायगी। अतः अर्थशास्त्रीय अर्थ में मांग के लिय निम्नाविन बातें आवश्यक हैं :-

(१) प्रभावपूर्ण इच्छा (Effective Desire),

(२) निश्चित मूल्य (Fixed Price), और

(३) निश्चित समय (Fixed Time)।

यदि उपर्युक्त बातों के आधार पर मांग को इस प्रकार परिभाषित कर सका है मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिस कोई व्यक्ति किसी निश्चित मूल्य पर किसी निश्चित समय में खरीदने के लिय तैयार हो।

प्रो० बेंनहम (Benham) के शब्दों में किसी दिने हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो अमुक समय में उस मूल्य पर खरीदी जाय।

प्रो० जे० एस० मिल (J. S. Mill) लिखते हैं कि मांग में हमारा आशय मांगी जाने वाली मात्रा में होता है और स्वरूप रखने में वह मात्रा स्थायी मात्रा नहीं होती बल्कि यह मूल्य के अनुसार सामान्यतया बदलती रहती है।^२

१—“Demand is always made by a buyer or would be buyer, for a certain article. The demand for a commodity is closely related to its price. The willingness of people to buy a thing depends, to a considerable extent, upon what they have to pay for it. Therefore, there is no such thing as demand apart from price.”

Penson. *Everyday Economics*, Pt. I, p. 107.

२—“The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price.”

Benham *Economics*, p. 36.

३—“We must mean by the word demand, the quantity demanded and remember that this is not a fixed quantity, but in general varies according to the value.”

J. S. Mill *Principles of Political Economy*, III, II, 4.

माँग और पूर्ति]

माँग का मूल्य (Demand Price)—माँग का मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई श्रेता किसी वस्तु का निश्चित मात्रा किसी विनिष्ट धनराशि में खरीदने के लिये तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति १ आने प्रति दर्जन के हिस्से से दो दर्जन मसुरे खरीदने को तैयार है, तो १ आना प्रति दर्जन मसुरे उसकी माँग का मूल्य हुआ।

माँग का नियम (Law of Demand)—माँग और मूल्य के सम्बन्ध के विवरण का माँग का नियम कहने है। माँग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) पर अवलम्बित है। इस नियम के अनुसार जितनी अधिक हम शीर्ष वस्तु मिलते हैं उसनी ही उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। उपयोगिता घट जाने से हम उस वस्तु को कम मूल्य पर ही खरीदने को तैयार होते हैं। किन्तु वस्तु के अधिक खरीदे जाने के लिये उसका मूल्य कम होना चाहिये। इसका ही भी कह सकते हैं कि जितना किसी वस्तु का मूल्य कम होगा उतनी ही उस वस्तु की माँग अधिक होगी, इसके विपरीत मूल्य बढ़ने पर वस्तु की माँग घटती होगी। माँग घटने पर माँग कम हो जाती है। यह प्रवृत्ति माँग का नियम (Law of Demand) के नाम से प्रसिद्ध है।

माँग का नियम यह वक्तव्य है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने से वस्तु की माँग बढ़ जाती है और किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उस वस्तु की माँग घट जाती है, यदि अन्य बात समान रहें। इसकी अधिक स्पष्ट करते हुए या बताना यह कहना है कि किसी वस्तु के मूल्य और माँग में निम्नलिखित सम्बन्ध (Inverse) सम्बन्ध है, क्योंकि मूल्य में घटने से माँग बढ़ जाती है और मूल्य में बढ़ जाने से माँग घट जाती है। इसी तुलना बच्चों के डेकुल (See-Saw) नामक खेल में घनी-आलि की जा सकती है। इस खेल में जब एक सिरे पर बेटा हुआ बच्चा नीचे आता है, तो दूसरे सिरे पर बेटा हुआ बच्चा ऊपर उठ जाता है और जब दूसरा नीचे आता है, तो पहला ऊपर उठ जाता है। ठीक वही स्थिति माँग के नियम के अनुसार मूल्य और माँग की रहती है, अर्थात् किसी वस्तु के मूल्य के कम हो जाने पर उसकी माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ जाने से माँग कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब मेव का मूल्य दो आना प्रति मेव है, तो किसी व्यक्ति की माँग ५ मेव प्रति दिन की है। यदि मेव का मूल्य बढ़ कर तीन आने प्रति मेव हो जाय तो उस व्यक्ति की माँग घट कर ४ मेव प्रतिदिन रह जाती है। यदि मेव के दाम घट कर एक आना प्रति मेव हो जाय, तो उस व्यक्ति की माँग बढ़ कर सम्भवतः ६ मेव प्रतिदिन हो जायेगी।

माँग के नियम के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट कर देना उचित है। अर्थात् माँग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी माँग में सम्बन्ध स्थापित करता है तथापि माँग और मूल्य में कोई अनुपातिक (Proportionate) सम्बन्ध नहीं बनता। अर्थात् माँग और मूल्य का सम्बन्ध विनिश्चित नहीं है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपातिक हो। उदाहरण के लिये, यदि किसी वस्तु का मूल्य आधा रह जाय, तो यह आवश्यक नहीं है कि माँग ठीक दुगुनी हो जाय, या नववाँ चौथी चौथी, पचगुनी हो जाय। इसी प्रकार मूल्य के दुगुने होने पर माँग ठीक आधी न रह कर निहाई, पौनी भी हो सकती है। वस्तु यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य १०० अनुपात में घटे या बढ़े, माँग भी उन्नी अनुपात में बढ़े या घटे।

प्रो० मार्शल (Marshall) के अनुसार मुख्य वाले सुमान होने पर, किसी वस्तु का मुख्य घटने से उस वस्तु की माँग बढ़ती है और मुख्य के बढ़ने से माँग घटती है ।

प्रो० टॉमस (Thomas) नाम के नियम का इस प्रकार परिभाषित करते हैं—जिसी वस्तु कुछ समय में किसी वस्तु या सेवा की माँग बढ़े हों मुख्य की अपेक्षा प्रयोजित मुख्य पर अधिक होगी और घटे हुये मुख्य की अपेक्षा कम होगी ।

‘मुख्य बात भयानक है अथवा किसी वस्तु कुछ समय में’ यदि इस प्रकार के शब्द बड़े व्यापक हैं । इसका तात्पर्य यह है कि फँसान, रूचि, रिवाज, मोमम, प्रतस्पर्धा आदि में परिवर्तन होने से बिना मुख्य में परिवर्तन हुए भी माँग में परिवर्तन होना सम्भव है । वस्तु माँग का नियम यह है कि माँग होता जबकि अन्य बात भयानक है अथवा उत्तम बाई परिवर्तन में है । ✓

माँग के नियम के अपवाद (Exceptions to the Law of Demand) पूर्ण प्रतिपक्षिता का व्यवस्थापना की कल्पना के अनिश्चित, माँग के नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

माँग का नियम निम्नलिखित चित्र द्वारा भरी प्रकार व्यक्त किया गया है —



बहुत कम वेतनागत ✓

अत्यधिक वेतनागत ✓

(१) निरन्तर मूल्य का बढ़ना — (Continuous Rise in Prices)—यदि कुछ समय तक मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही हो ना उधरता

{—In the words of Prof. Marshall “Other things being equal, with a fall in the price, the demand for the commodity is extended, and with a rise in the price the demand is contracted”

Marshall *Principles of Economics*, p 99

२—“At any given time, the demand for a commodity or service at the prevailing price is greater than it would be at a higher price and less than it would be at a lower price”

—Thomas

परास्पर भिन्न मूल्य वृद्धि से वजन व नियम अधिक खरीद कर जमा कर उठा है। गत निम्न महापुट्ट का अनुभव इस अपवाद का पूर्ण रूप में पुट्ट करता है।

(२) उपमात्ता की वस्तु की विषय की अनविज्ञता (Ignorance of Consumer about the Quality of a Commodity)—उपमात्ता की वस्तु का किस्म की अनविज्ञता के कारण वह उस वस्तु का मूल्य या उपयोगिता का अनुमान उदरगत (Quoted) मूल्य में लगाता है। बहुत से लोग कम मूल्य वाली वस्तुओं को निम्न मूल्य मान कर नहीं खरीदते और उन्हें मूल्य वाली वस्तुओं का उच्च मूल्य मान कर खरीदते हैं। इस प्रकार उपादय मूल्य कम मूल्य का था। इसे मूल्य पर वस्तुओं की अधिक देखभाल प्रदान करने है।

३) ऊँचा मूल्य और सृष्टि प्रदत्त (High Price & Disposal of Wealth)—कभी कभी लोग समुद्र वस्तु इकट्ठि खरीदते हैं कि उमड़ा मूल्य ऊँचा है और उमड़ा वे अपनी सम्पत्ति का उचित प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाना से उगे जनसाधारण भी खरीदने लग जाय तो वे उस महा खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर खादिकता का अधिक मूल्य या और जो साधारण ने खरीदने की वस्तु नहीं थी वह समुद्र लोग खरीदने लगे। लेकिन अब उमड़ा मूल्य गिर जाना से जनसाधारण के उपयोग की वस्तु हो गई है और समुद्र लोग अपनी गान रखने के लिये उच्च महा खरीदते हैं।

(४) आय में वृद्धि (Rise in Income)—मूल्य के बढ़ने के साथ साथ यदि मनुष्यों की आय में वृद्धि हो जाय तो वस्तुओं की माँग इसमें भी बढ़ती है। गत महापुट्ट में मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने पर भी वस्तुओं की माँग इसमें भी बढ़ती है। इसका कारण यह था कि मनुष्यों की आय भी साथ ही साथ बढ़ गई थी। युद्धकालीन कारणों से माँग प्रसार के विविध कार्यों के कारण रोजगार का क्षय बढ़ गया था। पसारी भाव का भी नहीं रहने था। लोगों ने व्यापार तथा कल कारखानों में पलायन गुनाहा समाया और विमानों को भी मूल्य के बढ़ने में बड़ा लाभ हुआ। यह प्रकार कुछ नौकरी लोग के मनुष्यों का खर्च करने पर जनता की आय में गवाह वृद्धि हो गई जिसे उनकी पहचान का अर्थ है अर्थ गति बढ़ गई।

माँग का सूची (Demand Schedule)

माँग का नियम यह कहना है कि जब उनके मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसका माँग पर भी अभाव पड़ता है। अर्थात् विभिन्न मूल्यों पर माँग की विभिन्न मात्राएँ खरीदी जायगी। यदि एक माँग का विभिन्न मात्राओं का जो विभिन्न मूल्य पर माँगो जायगा एकत्रित कर एक स्थान पर रखा जा तो सूची इस प्रकार बनेगी उस इस माँग को सूची बन्गी। इसकी स्पष्ट दृष्टि होगी या कहा जा सकता है कि माँग की सूची सारणी (Table) के रूप में एक निरूपण है जिसमें दिए हुए समय में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं का उन विभिन्न मूल्यों के साथ संबंध प्रकटनाया जाता है। अतः माँग की सूची यह सारणी है जिसमें विभिन्न विभिन्न स्थान और समय पर विभिन्न मूल्यों पर माँग की विभिन्न मात्राएँ दिखाई गई हों। माँग की सूची बनाने समय केवल मूल्य द्वारा ही बात पर्याप्त नहीं पर ही विचार किया जाता है। मूल्य के अनिश्चित माँग में परिवर्तन करने वालों अथवा बाजार का कोई विचार नहीं किया जाता जब पैनल यदि स्थान पर माँग में परिवर्तन वास्तविक माँग में बढ़ता है।

मांग की सूची के भेद (Kinds of Demand Schedule)—मांग की सूची दो प्रकार की होती है (१) व्यक्तिगत मांग-सूची (Individual Demand Schedule) और (२) बाजार की मांग सूची (Market Demand Schedule)

(१) व्यक्तिगत मांग सूची (Individual Demand Schedule)—वह सारणी है जिसमें किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग विभिन्न मूल्यों पर दिखाई जाती है। किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य के प्रतिरूप उसकी आय, रुचि स्वभाव आदि अनेक बातों पर भी निर्भर रहती है। अतः मांग की सूची बनाने समय यह कल्पना करनी जाती है कि मध्य बातें पूर्ववत् हैं, केवल उस वस्तु के मूल्य ही में परिवर्तन होता है। व्यक्तिगत मांग सूची में किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की मांग की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, परन्तु कठिनाई यह है कि इस प्रकार की पूर्ण मांग सूची मुद्रण में तैयार नहीं की जा सकती।

(२) बाजार मांग सूची (Market Demand Schedule)—वह सारणी है जिसमें समस्त बाजार की मांग विभिन्न मूल्यों के साथ दिखाई जाती है। बाजार की मांग सूची कई व्यक्तियों की एक साथ होने से इसे सामूहिक (Collective) अथवा सामाजिक (Social) मांग सूची भी कहते हैं। बाजार मांग सूची मूल्य के सामने सम्पूर्ण बाजार में किसी वस्तु की बेची जाने वाली समस्त मात्राएँ एक कर पलाई जा सकती है। बाजार की मांग सूची तैयार करत समय एक कठिनाई उपस्थित होती है। यह यह है कि बाजार में भाग लेने वाले क्रोषाओं की रुचि, स्वभाव, आय, धर्म आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण मूल्य का वस्तु की मांग पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। अतः अनुपमा की मांग की एक मांग सूची बनाने समय इन व्यक्तिगत अन्तरों पर कोई विचार नहीं रखा जाता है।

व्यक्तिगत मांग-सूची और बाजार मांग-सूची को निम्नांकित उदाहरणों द्वारा भली प्रकार समझाया गया है —

✓ सेवा की मांग मूचियाँ
(Demand Schedules for Apples)

व्यक्तिगत मांग सूची बाजार मांग सूची
(Individual Demand Schedule) (Market Demand Schedule)

मूल्य प्रति दर्जन ₹०	मांग की मात्रा प्रति दर्जन	अ	ब	स	मांग (मांग की मात्रा प्रति दर्जन)
७	१	३	१	०	४
६	२	४	२	१	७
५	३ ✓	५	३	२	११
४	४	६	४	४	१४
३	६	७	६	५	१८
२	८	८	८	६	२०
१	१०	११	१०	८	२९

गारखी का स्पर्जीकरण—उपयुक्त सारणी में बाजार मांग सूची के अन्तर्गत मैं ने घंटी वगैरे में मध्य और म. स. अथवा वगैरे व. अनुष्ठा की (मांग वगैरे गड़ है। अर्थात् मूल्य ७ ६० प्रति दजन है तो कुल चार दजन सेव बाजार में बचा जायगा ६० प्रति दजन मूल्य पर ७ सेव १ ६० मूल्य पर ११ सेव और इसी प्रकार मांग ४ ६० ३ ६० २ ६० और १ ६० पर क्रमशः १४ ६० २२ और २८ सेव बच जायेंगे। यह सारणी मांग के नियम का चरित्राण करती है। जैसे ही जन मूल्य कम होता जाता है वम ही-वम मांग बढ़ती जाती है और इसी प्रकार वम कम पूर्य बढ़ता बढ़ता है वैसे-वैसे मांग घटती जाती है।

मांग-सूची के सम्बन्ध में कुछ ज्ञानिय बातें

१. मांग-सूचियों ज्यों कि ऊपर दी हुई हैं, पूर्ण नहों हैं। "नवा यह केवल प्राणिक रूप ही है। पूर्य सूची तब चल सकती है जबकि सूच्य और वस्तु का मायाभा की एक विन्धुन सूची तयार की जाय। यह काम बड़ा कठिन है।

२. मांग-सूची काल्पनिक होती है, क्योंकि हम काल्पनिक मांग सूचा बना सकते हैं। हम केवल किसी समुक्त समय पर प्रचलित मूल्य पर माया जाने वाली वस्तु का माया का ही ज्ञान नकन है। अथ सूच्य और वस्तुएं हम अपनी कल्पना में ही दिख सकते हैं। इनके नियम विगत रेखा भी महायक पिछ नहों हो सकती क्योंकि विभिन्न समय की अवस्थाओं में भिन्नता पाई जाती है।

३. काल्पनिक मांग सूची का निर्माण धनि दुष्कर है। कोई भी व्यक्ति स्वयंसेवा में यह नहीं कह सकता कि किम मूल्य पर वह किमा वस्तु का किन्ना माया करान्या। मांग-सूची कोई निरलेख (Absolute) वस्तु नहों है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता एक-दूसरे पर प्राप्रित होती है।

४. मांग-सूची में केवल परिवर्तन प्रवृत्ति का ही ज्ञान हो सकता है। वम केवल यही जान हो सकता है कि समुक्त मूल्य का माया वस्तु का मांग में समुक्त परिवर्तन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति निश्चय रूप में यह नहीं कह सकता है कि समुक्त परिवर्तन अवश्य ही होगा।

मांग-सूचिया का उपयोगिता (Utility of Demand Schedule)—यद्यपि विवरण मांग-सूचियों के निर्माण में अनेक कठिनायों के परन्तु फिर भी अभी कि वह है कि प्रसार में लाभदायक है। इनमें निम्नलिखित प्रयोजन निहित हैं—

(१) वित्त मंत्री (Finance Minister) का यह अनुमान लगाना पड़ता है कि कशा व लगान में जो वस्तुओं व मूल्य में वृद्धि होगी उसमें उन्ना करों का पान होना वस्तुओं का मायाभा में किन्ना वमी हो जायगी। इस प्रकार की गणना पाना वस्तु तयार नियम नहों की जा सकता।

(२) इनकी उपयोगिता उपायों और निमाणाओं व नियम वम तय है। विभिन्न वस्तुओं की मांग-सूचिया का अध्ययन करके व वस्तुओं का व वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करन है। इन सूचियों द्वारा उपभोक्ताओं की वषय का पान हो सकता है।

(३) एकाधिकार (Monopolist) का भी अनेक लाभ व अधिकतम वन व नियम मूल्य परिवर्तन द्वारा हानि वाना उपभोक्ताओं का प्रति प्रियाओं का प्यान व रखना पड़ता है।

(४) इनमें मांग का नियम वम प्राणि समझा जा सकता है।

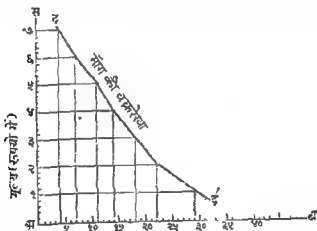
(५) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से माँग की सीमा का अन्त्य ज्ञान हो सकता है।

(६) इनमें व्यापारी वर्ग बाजार की प्रवृत्ति (Tendency) का सुगमता से अनुमान लगा लेते हैं।

(७) इन साक्ष्यों से निवेदाओं को भिन्न-भिन्न मूल्य पर निम्नी विविध समय और स्थान पर माँग की विभिन्न मात्राओं का पता चल जाता है।

✓ **माँग की वक्ररेखा (Demand Curve)**—माँग सूची के प्रयोग द्वारा रेखाचित्र बनाने में जो वक्ररेखा बनती है वह माँग की वक्ररेखा कहलाती है। माँग की वक्ररेखा एक प्रकार से माँग-सूची का रेखिक चित्रण है। इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि वे एक-दूसरे पर आधारित हैं। माँग की वक्र रेखा सूची के आधार पर ही बनाई जाती है। दोनों में केवल यही अन्तर है कि माँग-सूची एक सारणी के रूप में होती है और माँग वक्ररेखा एक रेखिक चित्र के रूप में होती है, अथवा दोनों एक ही वस्तु के विभिन्न प्रतीक हैं। हमारे सामने ये, या भी कहें जा सकते हैं कि दोनों ही माँग के नियम की प्रामाणिकता का एक ही दृष्टि में प्रदर्शित करने की दो युक्तियाँ हैं।

ऊपर माँग की सूचियों के अन्तर्गत दिये हुए प्रयोगों से निम्नांकित रेखाचित्र बनता है निम्नो मूल्य और माँग का सम्बन्ध एक वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है :—



माँग की मात्रा (दर्जनों में)

माँग की वक्ररेखा (Demand Curve)

अब रेखा पर सेव की माँग दर्जनों में और अक्ष रेखा पर तबों का मूल्य रूपों में दिखाया गया है। ऊपर की तालिकानुसार निम्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राएँ खड़ी और घटती रेखाओं से प्रकट की गई हैं। छोटे प्रत्युदा का गिलास देने में माँग की वक्र रेखा द द बन जाती है जा महरो वाली स्पाही से दिखाई गई है।

मांग का चक्र रखा नीचे की ओर क्या झुकती जाती है ? (Why does demand curve slope downwards ?)—प्रायः हम यह देखते हैं कि जब मांग की वक्र रेखाएँ मर्देव वार्ड से दायें तरफ नीचे की ओर झुकती जाती हैं। इसका कारण स्पष्ट है उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) के अनुसार यदि किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि की जाय, तो प्रत्येक इकाई की मार्गमार्ग उपयोगिता (Marginal Utility) कम होती जाती है जिससे फलस्वरूप मूल्य में भी गिरावट आ जाती है। अस्तु किसी वस्तु के घटते हुए मूल्य पर उम वस्तु की प्रतिक इकाई की संख्या में वृद्धि के कारण देखा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य कम होने में उसकी मांग बढ़ती है। उपयोगिता ह्रास नियम की मर्यादा पर निर्भर है और यदि मांग बात गलत नहीं तो उपयोगिता ह्रास नियम की मर्यादा में कदापि भ्रम नहीं आ सकता। इस नियम मांग की वक्ररेखा मर्देव नीचे की ओर झुकती है।

कब मांग की वक्ररेखा नीचे की ओर नहीं झुकती ? (When does the Demand Curve not slope downwards)—जबकि प्रभावित बाजार पर हो संभव है कि प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक इकाई से मांग में वृद्धि हो या वस्तु का उपयोग प्रतिक्रिया हो संभव है कि प्रभावित वस्तु से प्रभावित हो या जीवनाप आदि वस्तुओं के मूल्य में अचानक वृद्धि हो गई हो तो वक्ररेखा नीचे की ओर झुकने में रुक जायगी।

मांग में परिवर्तन

(Changes in Demand)

मांग में परिवर्तन कई प्रकार से होता है और प्रत्येक प्रकार की विवेचनाएँ निम्नलिखित हैं। अस्तु नीचे मांग के परिवर्तन के विभिन्न रूपों का निरूपण करने हुए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—

मांग का विस्तार एवं संकुचन (Extension & Contraction of Demand)—मांग के नियमानुसार किसी वस्तु के मूल्य का परिवर्तन उसकी मांग में विपरीत परिवर्तन उत्पन्न करता है अर्थात् जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है।

मूल्य के घटने से जो मांग में वृद्धि होती है उसे मांग का विस्तार (Extension of Demand) कहते हैं और मूल्य के बढ़ने से मांग की कमी का मांग का संकुचन (Contraction of Demand) कहते हैं। मांग का विस्तार और संकुचन का सम्बन्ध मूल्य के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन में है न कि अन्य कारणों से होने वाले परिवर्तन में।

मांग की वृद्धि एवं ह्रास (Increase and Decrease of Demand)—मांग में परिवर्तन मूल्य के अनिश्चित कारणों से भी होता है जैसे मुद्रा के माध्यम से वास्तविक मांग में वृद्धि होना व रजि व्यापार का स्थिति आदि में परिवर्तन। उदाहरण के लिये नया मुद्रास्फीयता (Inflation of Money) के कारण वस्तुओं के मूल्य में अचानक वृद्धि हो गई हो और जिस प्रकार मांग में उत्तरी मांग में भी कमी हो गई हो। इसी प्रकार बाजार में नए वस्तुओं के आने से मांग में वृद्धि हो जाती है और मर्यादा के लिये या छुट्टी के दिनों में मांग में वृद्धि हो जाती है और मर्यादा के लिये या छुट्टी के दिनों में मांग में वृद्धि हो जाती है।

के कारण 'हेयर पिन' (Hair Pins) और 'हेयर नेट' (Hair Nets) की मांग में परिवर्तन हो जाता है। अस्तु मूल्य के अतिरिक्त अन्य कारणों से मांग के बढ़ जाने को मांग की वृद्धि (Increase of Demand) कहेंगे और कम हो जाने को मांग की ह्रास (Decrease of Demand) कहेंगे।

मांग में परिवर्तन करने वाले कारण

(Factors Causing Changes in Demand)

मूल्य के अतिरिक्त मांग में जिन कारणों से परिवर्तन होता है वे निम्नलिखित हैं :—

(१) रुचि और फैशन में परिवर्तन (Changes in Tastes & Fashion)—दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुओं की मांग में रुचि और फैशन के कारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे भारतवर्ष में चाय की बोर लोगों का अधिक प्रभाव होने से इसकी मांग बढ़ रही है। और 'टार्' का फैशन कम होने से इसकी मांग घट रही है।

(२) मौसम में परिवर्तन (Changes in Climate or Weather)—सर्दी में गर्म कपड़ा की मांग और गर्मी में बिजली के पत्ती और ठण्डे पेय-पदार्थों (Cold Drinks) की मांग बढ़ जाती है।

(३) जन-संख्या में परिवर्तन (Changes in Population)—यदि बाहर से अधिक लोग आकर बस जायें तो उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ जायेगी। यदि, लड़ाई में नवयुवक एक बड़ी संख्या में मारे जायें तो शादियों में बनी हुई जायगी और इसके परिणाम स्वरूप शादियों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की भी मांग कम हो जायेगी।

(४) मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन (Changes in the Amount of Money)—मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा-संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन हो जाने से उनकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे गत विश्व महायुद्ध के पूर्व भारतवर्ष में १७६ करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलित थी और युद्ध काल में वर्षोत् अग्रेल तक १६४५ ई० में १२०० करोड़ हो गई जिसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई।

(५) वास्तविक आय में परिवर्तन (Changes in Real Income)—केवल मुद्रा की मात्रा से मांग में परिवर्तन नहीं होता बल्कि लोगों की वास्तविक आय के परिवर्तन में भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ, प्रौद्योगिक निपुणता, ज्ञान वृद्धि, नये आविष्कारों तथा उत्पत्ति के नवीन ढंगों के कारण वस्तुओं का लागत मूल्य (Cost of Production) गिर जाता है जिसके कारण वस्तुएँ सस्ती उपलब्ध होने लगती हैं। अतः वस्तुओं का मूल्य गिर जाने से उनकी मांग बढ़ जाती है।

(६) धन-वितरण में परिवर्तन (Changes in Distribution of Wealth)—धन वितरण के परिवर्तन से भी वस्तुओं की मांग में अन्तर आ जाता है। उदाहरण के लिये, यदि धन-वितरण गरीबों के पक्ष में है, तो अनिवार्य आवश्यक पदार्थों की मांग बढ़ जायेगी और धनी लोगों के पक्ष में है, तो भित्ता-वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जायेगी।

(३) व्यापार की स्थिति में परिवर्तन (Changes in Conditions of Trade)—व्यापार वृद्धि (Boom) के समय में मूल्य का बढ़े हुए होने पर भी वस्तुओं की माँग प्रायः अधिक और मंदी (Depression) के समय में कम हो जाती है।

(८) स्थापान वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन (Changes in Prices of Substitutes)—यदि किसी वस्तु के बदले में अब वस्तु प्रयुक्त की जा सकती है तो एक की माँग की वृद्धि दूसरे की माँग को कम कर देती है। जैसे रेडियो के मूल्य में कमी हो जाने में घासोफोन का माँग में भी कमी हो जायगा क्योंकि अब लोग घासोफोन के स्थान में रेडियो कायम लावेंगे।

विभिन्न प्रकार की माँग (Different kinds of Demand)

संयुक्त माँग (Joint Demand)—कई वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये एक साथ होता है जैसे मोटर और पेट्रोल, कलम और इन्क, बुता और पालिश आदि। अतः जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की माँग एक साथ की जाय तो उसे संयुक्त माँग कहेंगे।

(८) सम्मिश्रित माँग (Composite Demand)—कई वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक कामों के लिये होता है जैसे लकड़ी की माँग कारों के फायर वुड, दरवाजों, रेलवे रैंगन, जहाजों के सामान आदि बनाने में होता है। इसी प्रकार मृत्ति का उपयोग बना भवन निर्माणों के अलावा सिमेंट के अंश में माँग बगोचा आदि के लिये होता है। अतः जब किसी वस्तु की माँग दो या दो से अधिक प्रयोगों के लिये की जाय तो उसे सम्मिश्रित माँग कहेंगे।

(९) प्रत्यक्ष एवं प्राप्त माँग (Direct & Derived Demand)—संयुक्त माँग में एक से अधिक वस्तुएँ एक साथ माँगी जाती हैं। इसलिए संयुक्त माँग में आधारभूत वस्तु की माँग अथवा अंतिम उत्पत्ति की वस्तु की माँग को प्रत्यक्ष माँग कहेंगे और पूरक वस्तु या वस्तुओं की माँग को प्राप्त माँग कहेंगे। उदाहरण के लिये मोटर कार का माँग स पेट्रोल की माँग उत्पन्न होती है। अतः मोटर कार की माँग तो प्रत्यक्ष माँग है और पेट्रोल की माँग प्राप्त माँग है।

माँग की लोच

(Elasticity of Wants)

माँग की लोच का अर्थ (Meaning of Elasticity of Demand)—ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वस्तु का मात्रा में मूल्य के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। माँग के नियमानुसार यदि मूल्य बान समान रहे तो मूल्य के कम होने से माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ने से माँग कम हो जाता है। यह परिवर्तन कभी कम होता है और कभी अधिक। अतः मूल्य में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप जो माँग में परिवर्तन होता है, उसे माँग की लोच (Elasticity of Demand) कहते हैं। लोच माँग का एक स्वाभाविक गुण है। अतः मूल्य में घटने व बढ़ने से माँग में

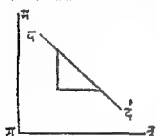
परिवर्तन विभाग हा जाना सम्भव है। माग न उमा परिवर्तन का अर्थशास्त्र म माग को नाच कहा है।

यह व्यापारिक जीवन का निर अनुभव है कि कुछ वस्तुएँ ऐसा हैं जिनके मूल्य में तनिक परिवर्तन होने से उनका माग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ जाता है। जैसे रस्निया का मूल्य कम हो जाने पर उसका माग में वृद्धि हो जाता है और मूल्य अधिक हो जाने पर उसका माग घट जाता है। यह कुछ वस्तुएँ ऐसा हैं जिनकी माग पर मूल्य की न्यूनारिक्ता का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे लकड़, खाद्यान्न आदि आवश्यक वस्तुएँ। अन्त में यहाँ माग में परिवर्तन से माग में अत्यन्त परिवर्तन हो जाने का माग की अधिक नाच कहेंगे और मूल्य का न्यूनारिक्ता में माग में बहुत ही कम परिवर्तन होने का माग की कम नाच कहेंगे।

प्रो० मार्शल (Marshall) ने माग में माग का नाच अधिक या कम मूल्य का उन्नयन का अनुपात माग की वृद्धि और वस्तु के प्रत्यक्ष होने है।

माग का नाच का विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत माग हो सकता है। किन्तु वस्तु का माग (१) नाचदार (२) अत्यधिक नाचदार (३) पूर्णतया नाचदार (४) सामान्यतया नाचदार या अल्पतया (५) पूर्णतया नाचदार हो सकता है। इनके विस्तृत विवरण नाच दिया गया है —

(१) नाचदार माग (Elastic Demand) यदि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव में ठीक उमा अनुपात में माग में परिवर्तन होता है तो ऐसा माग में माग नाचदार कहना पड़ेगा। उदाहरण के लिये बिना वस्तु का मूल्य गटना हो जाये तो उसका माग घट कर आधी रह जायगा और यदि उसका मूल्य घट कर आधा हो जाये तो उसका माग गूना हो जायगा। प्रायः जमा मूल्य की वस्तुएँ (Articles of Comforts) में देखा जाता है।



माग नाचदार (Elastic Demand)

वस्तुओं (Articles of Comforts) में देखा जाता है। जब प्रत्यक्ष की वस्तु का माग का नाच का इतना बड़ा हो जाय कि मूल्य में तनिक परिवर्तन से माग में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाय (Semi Poritonal) या अत्यधिक (Semi Vertical) है।

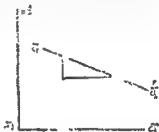
(२) उच्च नाचदार माग (Highly Elastic Demand)—यदि माग में

परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन से अधिक अनुपात में होता है तो

ऐसा माग में माग अधिक नाचदार कहना पड़ेगा। कुछ वस्तुएँ जिनके मूल्य

1— The elasticity of demand in the market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price
Marshall Principles of Economics p. 100

थोड़ा कम होने पर उनकी माँग बहुत बढ़ जाती है, और मुख्य जस्त बढ़ जाने से उनकी माँग काफी कम हो जाती है। रेडियो, मोटर-कार, वादयंत्र, प्रतीक (Refrigerator), रेसमो यन्त्र, मोफा सैट, टाइपा आदि विनास वस्तुओं (Articles of Luxury) की माँग प्रायः इस प्रकार की होती है। उदाहरण के लिये, यदि रेसमो कपड़े या टाई के मूल्य में २५ प्रतिशत कमी हो जाती है, तो माँग में वृद्धि ५० प्रतिशत या इतने भी अधिक हो जाती है, अर्थात् माँग में वृद्धि अनुपात में अधिक हो जाती है। इसी प्रकार रेसमो कपड़े का मूल्य थोड़ा सा भी बढ़ जाय, तो माँग बहुत कम हो जायगी अर्थात् माँग अनुपात से अधिक गिर जायगी। इस प्रकार की माँग की लाइन का टुकड़ा से अधिक चट्टे है। दिए हुए चित्र के अध्ययन में यह सात होता है कि इस प्रकार की माँग (Highly Elastic Demand) की वक्र रेखा लंबी हुई (Horizontal) या क्षैपटी (Flat) होती है, अर्थात् इसकी प्रवृत्ति आधार रेखा (Base Line) के समानान्तर (Parallel) होने की होती है।



बहुत लोचदार माँग

(३) पूर्णतया लोचदार माँग (Perfectly Elastic Demand)

मूल्य में परिवर्तन होने पर भी माँग में पर्याप्त घटा बढ़ी हो जाने को दशा में माँग की पूर्णतया लोचदार कहेंगे। ऐसी वस्तुयों जिनकी माँग में बिना



बहुत लोचदार माँग

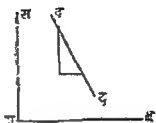
(Perfectly Elastic Demand)

मूल्य के परिवर्तन द्वारा ही अधिक घटा बढ़ी हो जाय, वास्तविक जीवन में दृष्टिकोण पर नहीं होता। अतः ऐसी दशा में वास्तविक जीवन से परे होने के कारण काल्पनिक कहो या कहनी है। माँग की इस अवस्था में वक्र रेखा आधार रेखा के क्षैपृत समानान्तर होती है अर्थात् बिना में शिथिलता पायी है।

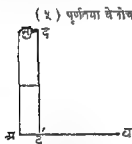
(४) सामान्यतया लोचदार अथवा मेलोच माँग (Moderately Elastic or Inelastic Demand) - यदि

किसी वस्तु की माँग में मूल्य के अनुपात से कम परिवर्तन हो, तो ऐसी दशा में माँग को सामान्यतया लोचदार अथवा मेलोच कहेंगे। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु के मूल्य में २५ प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की माँग में वृद्धि केवल १० या १५ प्रतिशत और मूल्य में २५ प्रतिशत वृद्धि होने पर वस्तु की माँग में केवल १० या १५ प्रतिशत कमी हो, तो ऐसा वस्तु की माँग को सामान्यतया लोचदार, कम लोचदार या मेलोच कहेंगे। इस वस्तु की माँग को इकाई में कम कहेंगे। इस प्रकार की माँग प्रायः

जीवनाय आवश्यक वस्तुओं (Articles of Necessity) में पाई जाती है। नमक इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। नमक का मूल्य एक आन सेर दो आने सेर स हो जाने पर भी नमक की मांग सम्भवतः बहुत चाड़ी कम हो। इसी प्रकार यदि नमक का मूल्य एक आने में घट कर दो पैसे हो जाय तब भी नमक की मांग में मूल्य के अनुपात में वृद्धि नहीं होगी। दिव्य द्रव्य चित्र में यह स्पष्ट है कि सामान्यतया लोचदार या बेलाच मांग की वक्र रेखा की प्रवृत्ति खड़ी होने (Vertical) की ओर होती है।



सामान्यतया लोचदार या बेलाच मांग
(Moderately Elastic or Inelastic Demand)



पूर्णतया बेलाच मांग
(Perfectly Inelastic Demand)

(५) पूर्णतया बेलाच मांग (Perfectly Inelastic Demand) — मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन न होने की दशा में मांग की बेलाचदार वक्र है। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि मूल्य चाहे कुछ भी हो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्णतया लोचदार मांग की भाँति इसका भी अस्तित्व वास्तविक है। पूर्णतया बेलाच मांग की वक्र रेखा बिल्कुल खड़ी (Vertical) होती है। जमा कि चित्र में स्पष्ट है।

निष्कर्ष—साधारणतया जीवन के नियम आवश्यक वस्तुओं की मांग कम लोचदार (Inelastic) होती है क्योंकि जो वस्तु जीवन के नियम आवश्यक हैं उनको तो बिना भी मूल्य पर खरीदना ही पड़ता है और एक बार आवश्यकता अनुसार मात्रा में कुछ खराब तब के पचात फिर पाठे मूल्य में भारी कमी क्या न हो पाय। उन वस्तुओं को अधिक मात्रा में नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी ओर बिना वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार (Highly Elastic) होती है क्योंकि वे वस्तुएँ जीवन के नियम आवश्यक नहीं होती अतः जहाँ तब बचत करता रहा। हाँ जाना बड़ा तक इनका प्रयोग अधिक नहीं किया जाता। जब वे सस्ता होती हैं तो इनको बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है और यदि इनका मूल्य फिर से बढ़ जाता है तो इनका प्रयोग स्थगित कर दिया जाता है जिससे उनकी मांग में भारी कमी आ जाती है।

इस प्रकार कई मूल्य वस्तुओं में भी अनुपात से अधिक वृद्धि होने के कारण उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। सामान्यतया मूल्य वस्तुओं की मांग में केवल अनुपातिक परिवर्तन होने से उनकी मांग लोचदार (Elastic) होती है।

निम्नांकित वस्तुओं की मांग किस प्रकार की है लोचदार अथवा लोचदार या कम लोचदार है ?

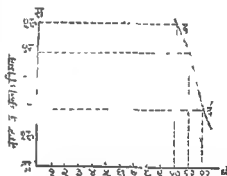
✓ नमक (Salt)—नमक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसकी मांस मूल्य की न्यूनताधिकता में अधिक प्रभावित नहीं होती। आवश्यक मात्रा में तो इसे प्राप्त करना हो पड़ता है, चाहे मूल्य अधिक हो या कम। अस्तु, नमक की मांस सामान्यता लाचदार (Moderately Elastic) यववा बेलाच (Inelastic) होती है।

मान लीजिये कि नमक की मांस सूची निम्न प्रकार है :—

नमक का मूल्य प्रतिमन	नमक की मांस
५ २०	१० मन
४ २०	११ "
२ २०	१२ "

उपरोक्त सूची में दिये हुये अंकों की सहायता से निम्नांकित रेखा चित्र बनाया गया है —

इसमें हम यह रेखा नमक की मांस की प्रवृत्ति करती है और हम उस रेखा नमक के मूल्य का प्रवृत्ति करती हैं। दाएँ नमक की मात्रा रखा है। उक्त बातें रेखा यह प्रवृत्ति करती है कि जब नमक का मूल्य ५ २० मन है तो मांस १० मन है। जब नमक का मूल्य ४ २० मन हो जाता है तो नमक का मांस बढ़कर ११ मन हो जाती है।



नमक की मांस की माप (मनो में) मांस की माप में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन की प्रतीति कम है, क्योंकि मूल्य में कमी तो २० प्रतिशत हुई है पर मांस में वृद्धि १० प्रतिशत हुई है। फिर नमक का मूल्य २ २० हो जाता है, तो नमक की मांस १२ मन होनी है, यद्यपि जब मूल्य में ६० प्रतिशत कमी हुनी है, तो मांस की मात्रा में, केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि होती है। इस निष्कर्ष में यह रेखा जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं की प्रतीति है और इसकी प्रवृत्ति गरीब होने (Vertical) की ओर होती है।

दिमागसाई और ईंधन (Mind Box & Fuel)—दिमागसाई और ईंधन जीवनार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएँ हैं। इनकी मांस पर मूल्य की घटा-बढ़ी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इनकी मांस बेलाचदार (Inelastic) है।

हीरे (Diamonds)—हीरे केवल शोध विज्ञान की वस्तु है, धन, मूल्य की घटा-बढ़ी का इनकी मांस पर अल्पप्रति प्रभाव पड़ता है। इसलिये इनकी मांस बहुत

लोचदार (Highly Elastic) है।

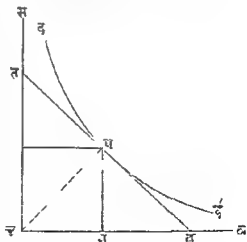
रेडियो सेट मोटरकार व प्रशीतक (Radio Sets Motor Cars & Refrigerators)—ये भोव विवास की वस्तुएँ हैं। इनके मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाने पर माग में बर्धमान घटा कभी हो जाता है। इसलिये इनको माग बहुत लोचदार (Highly Elastic) है।

कोयला और चाय (Coal & Tea)—प्रायः उन वस्तुओं की माग अधिक लोचदार होती है जिनके स्थान में अन्य वस्तुएँ प्रयुक्त की जा सकती हैं क्योंकि एक वस्तु का मूल्य कम जाने पर उसके स्थान में अन्य वस्तु का उपयोग प्रारम्भ हो जाता है। कोयला और चाय की माग अत्यधिक लोचदार (Highly Elastic) है क्योंकि कोयला के सहेले होने पर लकड़ी बनाई जा सकती है और सस्ता होने पर लकड़ी के बजाय कोयला अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार चाय के सहेले होने पर चाय का प्रयोग किया जा सकता है और सस्ता होने पर चाय का प्रयोग किया जाने लगता है।

माग की वक्र रेखा की लोच—(Elasticity of Demand Curve)—
माग की वक्र रेखा पर किसी बिन्दु पर उसके समुच्चय (Slope) को माग का वक्र रेखा की लोच कहते हैं। प्रस्तुत माग का वक्र रेखा की लोच रेखागणित द्वारा सुविधायित्व से नापी जा सकती है जमा कि लोच चित्र में दर्शाया गया है।

विशेष लोच चित्र में दाद माग की वक्र रेखा है जिसमें प की कोई एक बिन्दु है।

एक लोच रेखा जो प बिन्दु पर दाद की रेखा रेखा (Tangent) है खाकी यदि है जो अ व रेखा में प बिन्दु पर गिनता है और अ स रेखा त त बिन्दु पर गिनती है। अ व माग की वक्र रेखा की लोच प बिन्दु पर प थ और प त का अनुपात (Ratio) है। यदि प थ और प त बराबर हैं तो लोच इकाई (Unity) के बराबर है। यदि प थ प त ना दुगुना है तो लोच भी दुगुना है और आधा है तो लोच भी आधी है इत्यादि गणित का दूसरे ढंग से \angle थ प म और



माग का वक्र रेखा की लोच

(Curve)

\angle म प अ न अनुपात में प्रकट कर सकते हैं। यदि दादा नाख बराबर है तो लोच इकाई के बराबर है। यदि \angle थ प म \angle म प अ म बराबर है तो लोच था अनुपातिक

दृष्टि में बढ़ी है। यदि \angle थ प म \angle म प अ के अनुपात से बढ़ता है तो लोच भी उसी अनुपात से बढ़ेगा।

/// माँग की लोच और उत्पत्ति-ह्रास नियम (Elasticity of Demand & Law of Diminishing Returns)—माँग की लोच और उत्पत्ति ह्रास-नियम में घनिष्ठ सम्बन्ध है। उत्पत्ति-ह्रास नियम के अनुसार ज्यों-ज्यों वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है, त्यों-त्यों उसकी प्रत्येक इकाई की उपयोगिता घिरती जाती है। उपयोगिता का घर्ष यहाँ प्रत्येक इकाई की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) में है। यह उपयोगिता का ह्रास एक-सा (Uniform) नहीं होता है। कुछ दशाओं में यह ह्रास सीधे-सा में होता है, जैसे जमक आदि जीवनापयोगी वस्तुएँ। जब तक का मूल्य गिरता है, तो हम तुरन्त उसे अपना संपूर्ण मायस्यकता के अनुसार खरीद लेंगे और यदि फिर मूल्य घिरे तो हम उसे बिन्दुल नहीं खरीदेंगे। इस दशा में उपयोगिता का ह्रास बड़ी चोशता में होता है। ऐसी वस्तुओं की माँग बेलाच होती है। कुछ दशाओं में सीमान्त उपयोगिता में ह्रास धीरे-धीरे होता है, जैसे रेजमी कपड़ा, मोटरकार, रेडियो, वाइसिकल आदि सुख एवं विलास वस्तुएँ। इनकी माँग लाचदार या अत्यधिक लोचदार होती है। संक्षेप में, जब सीमान्त उपयोगिता में ह्रास शीघ्रता से होता है तो माँग कम लोचदार या बेलाच होती है और जब यह धीरे-धीरे होता है तो माँग लोचदार या अत्यधिक लोचदार होती है।

माँग की लोच और उपभोक्ता की वचन (Elasticity of Demand & Consumer's Surplus)—माँग के स्वभाव का उपभोक्ता की वचन पर भी बड़ी प्रभाव पड़ता है। जीवनार्थ और हठ प्रावश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की माँग प्रायः कम लोचदार होती है। वे प्रायः अमूर्त भी होती हैं। जीवन रक्षक वस्तुओं की अत्यधिक उपयोगिता होने के कारण उपभोक्ता जो मूल्य दे रहा है उसमें भी कहीं अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो जाता है। परन्तु शान्ति में वह कम मूल्य दे रहा है क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बड़े परिमाण में होने में वे सस्ती उपलब्ध होती हैं। इसलिये कम लोचदार या बेलाच माँग वाली वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता की वचन अधिक होती है। शुभ और विलास-वस्तुओं की माँग लोचदार या अत्यधिक लाचदार होती है। उपभोक्तागण उनका अधिक मूल्य देने की तैयार नहीं हैं क्योंकि वे पहले से ही उनका ऊँचा मूल्य दे रहे हैं। अस्तु, ऐसी दशा में 'उपभोक्ता की वचन' कम होगी। इस प्रकार जब किसी वस्तु की माँग कम लोचदार या बेलाच हो, तो उपभोक्ता की वचन अधिक होती है, और जब उसकी माँग लोचदार या अत्यधिक लोचदार हो तो उपभोक्ता की वचन कम होती है।

/// माँग की लोच का माप (Measurement of Elasticity of Demand)—बसत यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की माँग लोचदार है या बेलाचदार। व्यापारों तथा और अर्थ-मन्त्रियों का जानने के लिये और भी अधिक गहराई तक पहुँच है अर्थात् वे लोच की ठीक अंश में मापने की भी चेष्टा करते हैं। अस्तु, हमें लाच-मापन की विविध रीतियों का भी अध्ययन करना चाहिए।

माँग की लोच को मापने की प्रायः दो रीतियाँ अन्विष्ट हैं जिनका विस्तृत वर्णन नीचे दिया जाता है :—

(१) इकाई रीति (Unity Method)—प्रो० मासन ने भी इस रीति की सिफारिश की है। इस रीति के अनुसार माँग और मूल्य के समानुपात परिवर्तन से लोच की इकाई (Unity) स्थिर की जाती है और माँग में अनुपात से अधिक वृद्धि होने पर लोच का इकाई में अधिक होता तथा अनुपात से कम वृद्धि होने पर इकाई में कम होना कहा जाता है।

(प्र) इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि जब किसी वस्तु की माँग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन हो जिस अनुपात में कि उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो उस वस्तु की माँग की लोच इकाई (Unity) के बराबर बनी जाती है। उदाहरणार्थ किसी वस्तु का मूल्य दुगुना हो जाय तो माँग आधी हो जाती है। ऐसी अवस्था में जितना रुपया उस वस्तु के खरीदने में व्यय किया जाता है। (प्रति इकाई मूल्य \times खरीदी जाने वाली इकाइयों की मात्रा) वह सबदा समान रहता है चाहे वस्तु के मूल्य में कितनी भी बढ़ो-बढ़ी न हो प्रायः सुख वस्तुओं (Articles of Comfort) के साथ ऐसा ही होता है। इनकी माँग लोचदार (Elastic) होती है। इसका मापन गणित लो = १ (Elasticity is equal to Unity) होता है।

/// (पा) यदि माँग में होने वाला परिवर्तन के अनुपात से अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की माँग की लोच इकाई से अधिक बनी जाती है। उदाहरणार्थ मूल्य में २० प्रतिशत कमी होने पर माँग में ५० प्रतिशत वृद्धि हो जाय अथवा मूल्य में २० प्रतिशत वृद्धि होने पर माँग में ५० प्रतिशत कमी हो जाय। ऐसी अवस्था में उस वस्तु के खरीदने में जितना रुपया व्यय किया जाता है वह मूल्य के बढ़ने पर कम हो जाता है और मूल्य में घटने पर बढ़ जाता है। प्रायः विलास-वस्तुओं के साथ ऐसा होता है। इनकी माँग बहुत लोचदार (Highly Elastic) होती है। इस प्रकार की लोच का मापन गणित लो > १ (Elasticity is greater than Unity) होता है।

/// (इ) यदि माँग में होने वाला परिवर्तन के अनुपात से कम परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की माँग की लोच की इकाई से कम बनी जाता है। उदाहरणार्थ मूल्य में २० प्रतिशत कमी होने पर भी माँग में केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि हो अथवा मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर भी माँग में केवल २० प्रतिशत ही कमी होती हो। ऐसी अवस्था में वस्तु के खरीदने में जो रुपया व्यय किया जाता है वह मूल्य के बढ़ने पर बढ़ जाता है और मूल्य में घटने पर घट जाता है। प्रायः जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं (Articles of Necessity) के साथ ऐसा ही होता है। इन वस्तुओं की माँग नम लोचदार या वेलास (Inelastic) होता है। इसका मापन गणित लो < १ (Elasticity is less than Unity) होता है।

निम्नांकित सारणी इसे और भी स्पष्ट कर देती है :—

मूल्य (Price)	माँग (Demand)	कुल व्यय-राशि (Total Money Outlay)
₹ ५.०० प्रति मन	१००० मन	₹ ५०००
" ४.५० " "	१००० " "	" ४५००
" ४.२५ " "	४००० " "	" ४०००
" ४.०० " "	१००० " "	" ४०००
" ३.५० " "	३००० " "	" ७५००
" ३.२५ " "	४००० " "	" ७५००
" ३.०० " "	१००० " "	" ३०००
" २.५० " "	१५०० " "	" ३०००
" २.२५ " "	२००० " "	" २२००

निष्कर्ष—जब मूल्य के गिरने से कुल व्यय-राशि घटती रहती है, तो माँग की लोच इकाई के बराबर होती है, जब व्यय-राशि बढ़ती है, तो माँग की लोच इकाई से अधिक होती है और जब यह कम होती है, तो लोच इकाई से कम होती है।

माँग की लोच-माप की व्याख्या नीचे की सारिका में और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है :—

क्र० सं०	माँग के परिवर्तन का प्रमाणिक माप	लोच का मापन-मन्त्र	प्रत्यक्ष अर्थों में माने वाली वस्तुएं	लोच में धन
(म)	अनुपात के बराबर	लो १.००	सुरत वस्तुएं	लोचदार
(भा)	अनुपात में अधिक	लो > १.००	विनाश वस्तुएं	अधिक लोचदार
(इ)	अनुपात में कम	लो < १.००	जीवनार्थ याच- इतर वस्तुएं	गानागत या लोचदार या बेलाच

(२) प्रतिशत-परिवर्तन तुलना-रीति (Percentage Change Com-
parison Method) — इस रीति में अनुसार माँग की लोच, मूल्य और माप के
प्रतिशत-परिवर्तन की पारस्परिक तुलना द्वारा ज्ञात की जाती है। मान लीजिये कि
मूल्य में १० प्रतिशत वृद्धि होती है। यदि माँग में कमी ५० प्रतिशत हो जाती है, तो माँग
की लोच इकाई के बराबर होगी, यदि माँग में कमी ५० प्रतिशत में अधिक होती है, तो
माँग की लोच इकाई से अधिक होगी और यदि माँग में कमी ५० प्रतिशत में कम होती
है, तो लोच इकाई से कम बनी जायेगी। इस रीति द्वारा माँग की लोच मापने का सूत्र
(Formula) निम्न प्रकार है :—

$$\text{माँग की लोच} = \frac{\text{माँग में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन}}$$

माँग की लोच की भिन्नता के कारण (Causes of Variation in Elasticity of Demand)

अर्थात्

माँग की लोच को निर्धारित करने वाले तथ्य (Factors determining Elasticity of Demand)

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कुछ वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है और कुछ वस्तुओं की कम लोचदार। इसका कारण यह है कि माँग की लोच प्रत्येक वस्तु पर निर्भर होती है और यह जाने प्रत्येक वस्तु में भिन्न भिन्न पाई जाती है। अतः, माँग की लोच को निर्धारित करने वाली बातें निम्नलिखित हैं :—

१. वस्तुओं का स्वभाव (Nature of Commodities) साधारणतया जीवनार्थ अनिवार्य वस्तुओं की माँग कम लोचदार (Moderately Elastic) अथवा बेलोच (Inelastic) होती है, सुख वस्तुओं की माँग लोचदार (Elastic) और विलास वस्तुओं की लोच बहुत लोचदार (Highly Elastic) होती है।

(अ) जीवनार्थ अनिवार्य वस्तुएँ—जैसे नमक, दियामलाई, जल, आदि की माँग बहुत कम लोचदार या बेलोच होती है, क्योंकि इनका प्रयोग बिना नहीं रहा जा सकता। इनका मूल्य चाहे जितना क्यों न बढ़ जाय उन्हें आवश्यक भाषा में तो खरीदना ही पड़ता है। इनके मूल्य में कभी हो जाने पर भी माँग अधिक नहीं घटती, क्योंकि वे पक्ष में ही पर्याप्त भाषा में खरीदी जाती हैं। परन्तु यदि किसी देश का स्थानीय व्यक्ति इनमें निर्भर है कि वे जीवनार्थ अनिवार्य वस्तुओं की भी पर्याप्त भाषा में नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिये इन वस्तुओं की माँग भी लोचदार होगी। इसलिए भारतवर्ष जैसा निर्भर देश में इस प्रकार की वस्तुओं की माँग कुछ लोचदार है। गेहूँ के मूल्य में परिवर्तन होने में ऊँच और मध्यम वर्ग के मनुष्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु निम्न वर्ग के मनुष्यों में मुख्य तौर पर गेहूँ का उपयोग अवश्य बढ़ जाएगा। कुछ आवश्यकताओं (Conventional Necessaries) की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की माँग भी कम लोचदार या बेलोच होती है। जैसे, भारतवर्ष में मृत्यु-भाज देना कई शिल्प परिवारों में सामाजिक अनिवार्यता समझी जाती है। चाहे चाय पशियों का मूल्य कुछ भी हो।

(आ) सुख वस्तुएँ—ये वस्तुएँ आवश्यकता नहीं होती कि इनके बिना काम चल ही नहीं सकेगा हा, परन्तु उनका उपयोग दक्षता-वर्धक होता है। अतः इनका माँग लोचदार होती है।

(इ) विलास वस्तुएँ—इनकी माँग बहुत लोचदार होती है, क्योंकि इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं है। इसलिए यदि मूल्य बहुत बढ़ जाता है, तो इनका उपयोग कम कर दिया जाता है और मूल्य में कम होने पर उपयोग बढ़ जाता है। परन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि विलास वस्तुओं की माँग प्रती लोगों में हो अवश्य लोचदार है, परन्तु मध्यम या निर्धन लोगों में वह बेलोचदार हो गयी, क्योंकि उन वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे होते हैं कि वे उन्हें खरीद ही नहीं सकते। जैसे रेडियो, मोटर कार इत्यादि।

२. **स्थानापन्न वस्तुएँ (Substitutes)**—यदि किसी वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु प्रयोग में लाई जा सकती है, तो उस वस्तु की माँग लोचदार होती है, और यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो उसकी माँग बेलोचदार होती है। उदाहरण के लिये चाय और काफी, बिजली और तेल, गन्ध और साबुन या अन्य साबुन, चीनी और गुड़ एक दूसरे के स्थान में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मनुष्य उसकी स्थानापन्न दूसरी वस्तु का प्रयोग प्रारम्भ कर देगा। जैसे चाय के दाम बढ़ने में उसकी माँग कम हो जायगी और काफी की माँग बढ़ जायगी। जिस वस्तु का कोई उपयुक्त स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है उस वस्तु की माँग की मोड़ पर मूल्य का घटा-बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि उसकी माँग बलाघ होती है, जैसे नमक।

(३. **प्रयोगों की अनेकता (Variety of Uses)**—यदि किसी वस्तु का प्रयोग अनेक कार्यों के लिये किया जा सकता है, तो उसकी माँग उदा वस्तु की अपेक्षा जिसका प्रयोग बहुत कम कार्यों के लिये होता है, अधिक लोचदार होती है। उदाहरणार्थ बिजली (Electricity) का प्रति इकाई मूल्य कम हो जाने पर इसका प्रयोग अनेक प्रकार में होने लग जायगा जैसे प्रकाश भोजन बनाने पढ़ाई व रेडियो चलाने बमों के छेड़ने या गर्म करने पकड़ा पत्र इत्यादि करने मशीन चलाने बुझाये पानी निकालने आदि। यदि इसका मूल्य बढ़ा दिया जाय तो इसका प्रयोग केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेगा अनावश्यक कार्यों में हटा लिया जावेगा। इसी प्रकार जल, दूध, बीजना तोहा आदि अनेक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की माँग भी लोचदार होगी।

(४. **मूल्य का प्रभाव (Influence of Price)**—माँग की मोड़ मूल्य स्तर (Price Level) पर भी निर्भर होती है। बहुत ऊँचे और बहुत नीचे मूल्यों वाली वस्तुओं की माँग की लोच अधिक होती है। इसका कारण यह है कि बहुत ऊँचे मूल्य वाली वस्तुओं का उपयोग तो केवल धनी नाथ तक ही सीमित होता है यद्यपि उनमें लिये मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाना कोई भ्रम नहीं रहता। बहुत कम मूल्य वाली वस्तुओं को सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार खरीद लेते हैं, यद्यपि उनमें मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर माँग में थोड़ा बढाई अधिक नहीं होती। मध्यम मूल्य वाली वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है क्योंकि इनका उपयोग सभी व्यक्तियों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोग भी करते हैं। यदि इनके मूल्य में कमी या वृद्धि होती है, तो मध्य वर्ग के लोग इनका उपयोग करने लग जाते हैं जिनके पलम्बरूप इनकी माँग में वृद्धि हो जाती है, और यदि मूल्य बढ़ जाता है, तो इनका उपयोग स्थगित कर देने में निम्न वर्ग इनकी माँग कम हो जाती है।

यह स्मरण रखने की बात है कि उपर्युक्त विवेचन समस्त समाज की माँग की दृष्टि से किया गया है। यदि किसी समाज के एक वर्ग की माँग का वर्णन किया जाय, तो यह कहा जा सकता है कि "ऊँचे मूल्य पर माँग की लोच अधिक होगी, और मध्यम मूल्य पर माँग की लोच अधिक नहीं होगी" यद्यपि वस्तु-वस्तु मूल्य कम होता जाय तो जैसे जैसे लोच भी कम होती जाती है, और यदि मूल्य इतना

बन हो जाय कि उस खेती के सभी व्यक्तियों की पूर्ण तृप्ति हो जाय, तो माँग की ताव धीरे धीरे शून्य हो जाती है।" यह कथन प्रो० मार्शल के अनुसार है।

५. व्यय किये जाने वाली आय का अनुपात (Proportion of Income Spent)—यदि किसी वस्तु पर मनुष्य की आय का अधिक भाग व्यय होता है, तो उसकी माँग अधिक लोचदार होगी, और यदि आय का बहुत ही कम भाग व्यय होता है, तो उसकी माँग बेलोच होगी। उदाहरण के लिये, मनुष्य पर मनुष्य की आय का बहुत ही कम भाग खर्च होता है, यस्तु उसकी माँग बेलोच होगी है। इस प्रकार सुई-डोरे घान गुपारी घाबि वस्तुघा के उदाहरण दिये जा सकत है। इस प्रकार की वस्तुघो पर मनुष्य की आय का बहुत छोटा भाग व्यय होता है इसलिए इनके लस्ते या अहस हाने पर इनके खन पर कमी या वृद्धि नहीं की जायगी।

६. रचि अरचि एव प्रकृति (Taste, Distaste and Habit)—यदि किसी वस्तु के पक्ष या विपक्ष में रचि या अरचि बन जाती है तथा उसके उपभाग की यादत पड़ जाती है तो उसकी माँग की लोच कम होती है। उदाहरण के लिये जिस व्यक्ति की रचि चाय पीने की होती है वह कच्चा का प्रयोग भाष कम हान पर नहीं करेगा। इसी प्रकार हिन्दुओं में घाय धीरे मुसलमाना में मूधर व मोय व विरद प्रवल यावता होती है, इसलिए इनका मूय कम हो जाने पर भी इनकी माँग नहीं बढ़ती है। यही यात किसी वस्तु के प्रयोग की प्राप्ति पर लागू होती है। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु के उपयोग का प्राप्ति हो जाता है, तो उस वस्तु का भाव घट जाने पर भी वह उस वस्तु का उपभाग कम नहीं करता। जैसे सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीनेवाले हान पर भी सिगरेट पीने में कमी नहीं कर पात।

७. धन वितरण (Distribution of Wealth)—प्रो० टॉमिंग (Taussig) के मतानुसार साधारणतया धन के समान वितरण से माँग की लोच बढ़ जाती है। और धन-वितरण की असमानता से माँग कम लोचदार या बलोच हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है जब समाज के सब भाग के माधन लगभग समान हाने, तो मूय के परिवर्तन का प्रभाव सारे समाज पर लगभग एक-सा होता तिनके परिणाम-स्वरूप समाज की माँग अधिक लोचदार होगी जायगी। धन-वितरण की असमानता के कारण समाज के कुछ-कुछ वर्गों में विभक्त हो जायँगे और उनकी क्रय शक्ति में भी बड़ा अन्तर हो जायगा। वस्तु के मूय में परिवर्तन होने में विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़गा जिसके कारण लोच में पर्याप्त भिन्नता हो जायगी। यदि किसी वर्ग की किसी वस्तु की माँग अधिक लोचदार है तो दूसरे वर्ग के

I—"Elasticity of demand is great for high prices, and great or at least considerable for medium prices, but it declines as the price falls, and gradually fades away if the fall goes so far that satiety level is reached"

लिये उसकी माँग कम लाचदार हो सकती है और सम्भव है किन्हीं अन्य वस्तु के लिये उसकी माँग बेलोचदार हो जाय ।

८ प्रयोगानुसार एक ही वस्तु की विभिन्न प्रकार की लोच (The same commodity may have different kinds of Elasticity)—एक ही वस्तु की माँग एक प्रयोग के लिये बेलोच है तो दूसरे के लिये लोचदार हो जाती है । उदाहरण के लिये, गहने की माँग गन्तव्य के लिये मायाज के रूप में बेलोच है परन्तु गणुषा की विनाश के लिये इसकी माँग लाचदार हो जाती है ।

९ जिन वस्तुओं का उपयोग स्थगित किया जा सकता है उनकी माँग प्रायः लोचदार होती है (Demand for those commodities whose consumption can be postponed is usually elastic)—जिन वस्तुओं का उपयोग स्थगित किया जा सकता है उनकी माँग प्रायः लोचदार होती है । उदाहरणार्थ जब भ्रमण निर्माण सम्पन्धी वस्तुएँ मँदेकी हो जाती हैं तो भ्रमण निर्माण कार्य स्थगित हो जाते हैं जिससे पाम्बन्ध उन वस्तुओं की माँग कम हो जाती है । इसी प्रकार उनके सस्ते होने पर पुनः निर्माण कार्य चलने लगते हैं और उन वस्तुओं की माँग भी बढ़ जाती है ।

१० वस्तुओं की समुक्त माँग (Joint Demand)—जब किसी वस्तु का उपयोग अन्य वस्तुओं के साथ समुक्त रूप में होता है तो उस वस्तु की माँग को लोच भ्रमण साथ वाली वस्तुओं की माँग की लोच पर निर्भर रहती है । यदि साथ वाली वस्तुओं की माँग अधिक है तो उस वस्तु की माँग भी अधिक होगी और उसकी माँग कम होने पर उस वस्तु की माँग भी कम हो जायगी । जैसे मोटर कार और पेट्रोल फायरिंगेन और स्लाडो जैसे और वाणिज्य वस्तुओं की माँग समुक्त रूप में होती है । इसी प्रकार चूना ईंट पत्थर गीमट लकड़ी लोहा, शीशा बारीकर और इन्जीनियर आदि की मजदूरी की भ्रमण निर्माण कार्य में एक साथ चलता है ।

११ लोच की समय के साथ भिन्नता (Elasticity varies with obange in time)—एक ही वस्तु की एक समय में माँग का नाच कुछ और होती है और दूसरे समय में कुछ और । किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की शुरुआत उसकी माँग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि कुछ समय व्यतीत हो जाने पर पड़ता है क्योंकि मूल्य में परिवर्तन का बोझ का पता चलने में समय लागता है । इसलिये जो माँग की लाच कम समय में होती है वह अधिक समय के व्यतीत हो जाने पर अन्य रूप धारण कर लेती है । वस्तु समय के परिवर्तन से भी माँग की नाच में परिवर्तन हो जाता है ।

निष्कर्ष—उपयुक्त तथ्य मायाजनुसार माँग की नाच की भिन्नता के कारण प्रकट करते हैं । परन्तु माँग की लोच का निर्धारित करने वाले निश्चित एक मध्यम नियम में नहीं चले जा सकते और न इस प्रकार के नियम बनाना सम्भव ही है । इसका कारण यह है कि माँग की नाच परिस्थितियों पर निर्भर होती है और उनमें परिवर्तन

के मांग-माप इसमें भी परिवर्तन होगा सम्भव है। यदि हम यह ज्ञात करना चाहें कि समुक्त मांग लोचदार है या बेलोच, तो हमें उस वर्ग के मनुष्यों का भी ध्यान करना पड़ेगा जिनके लिये हम मांग की लोच का मानना चाहते हैं।

मांग की लोच का महत्त्व (Importance of Elasticity of Demand)—मांग की लोच के अध्ययन का महत्त्व निम्न प्रकार है।

(१) सबसे प्रथम तो इसका अध्ययन मूल्य-निर्धारण और कार-निर्णय के सिद्धान्तों के लिये बड़ा उपयोगी है। इसके द्वारा हम यह ज्ञान भवने हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने में उस वस्तु के, उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हम यह भी बता सकते हैं कि यदि समुक्त वस्तु की पूर्ति थोड़ी घटा या बड़ा दी जाय तो उसका मूल्य कितना बढ़ या घट सनता है।

(२) एकाधिकारी (Monopolist) के लिये मांग की लोच का व्यावहारिक महत्त्व है। इसके द्वारा उसे मूल्य-निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। यदि उसको एकाधिकार की वस्तु जो बनाव में आवश्यक वस्तु है और उसकी कोई अन्य स्थानापन्न वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु की मांग बेलोच होगी और एकाधिकारी उसको मूल्य में वृद्धि कर अपना लाभ बड़ा सकता है, क्योंकि उसकी मांग कम होगी या कोई बच नहीं रहता है। परन्तु यदि वस्तु की मांग लोचदार है, तो उसे मूल्य में वृद्धि करने के पूर्व सोचना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य वृद्धि में उस वस्तु की मांग घट जायगी जिससे उसके लाभ में हानि पहुँचना स्वाभाविक है। अस्तु, बेलोच मांग वाली वस्तुओं का ऊँचा मूल्य और लोचदार मांग वाली वस्तु का कम मूल्य उसे अधिकतम लाभ-प्राप्ति की ओर संकेत करता है।

(३) व्यापारी (Businessmen)—की भी लोच के अध्ययन में वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने में बड़ी सहायता मिलती है। यदि वस्तुओं की मांग लोचदार है, तो वह मूल्य घटा कर अपनी बिक्री को लाभप्रद बना सकता है। परन्तु यदि मांग बेलोच है तो वह वस्तुओं का अधिक मूल्य वसूल कर सकता है। यदि वह मानव सहानुभूति से अधिक प्रेरित नहीं है, क्योंकि बेलोच वाली वस्तुएँ अधिकतर जीवनार्थ आवश्यक वस्तुएँ होती हैं और उनका उपयोग अधिकतर निर्धन मनुष्यों द्वारा ही होता है।

(४) वित्त मंत्री (Finance Minister)—के लिये इसका व्यावहारिक महत्त्व कम नहीं है। वित्त मंत्री को भी किसी वस्तु पर लम्बा कर लगाते समय या पुराने कर में वृद्धि करने समय उस वस्तु की मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि लोचदार मांग वाली वस्तु पर कर लगाया जायगा, तो उसका मूल्य बड़ा जायगा जिसमें उसकी मांग घट जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि सरकारी आय (Revenue) कम हो जायगी। यदि कर बेलोच मांग वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो उसमें सरकारी आय अधिक हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं का कर से भाव बढ़ कर मांग कम होने का भय नहीं रहता है। परन्तु बेलोच मांग प्रायः जीवन रक्षक पदार्थों की होती है, अतः मान्यता की दृष्टि के कारण सम्भव है कि सरकार ऐसी वस्तुओं पर विलुप्त कर ही न लगावे या कम लगावे।

(५) समुक्त उत्पत्ति की दशा में मांग की लोच का प्रयोग (Application of concept of elasticity of demand in case of Joint

Products)—मयुक्त उत्पत्ति की दशा में जबकि पृथक्-पृथक् वाण्यत निरन्तर महा की जा सक्ता हो तब माग की राब की पारणा के प्रयोग का उपयोगिता देखा जाता है । उत्पादक मूल्य निर्धारित करत समय माग के स्वभाव में ही अपना पय प्रवर्तन प्राप्त करता है अथ पदों में या कहा जा सक्ता है कि वह मुख्य स्थिर करत गमन इस निर्दालन का पालन करता है Charge what the traffic will bear अथान् जिन वस्तुया के मूल्य वृद्धि से माग घटने का भय नहा है उनका ही ऊँचा मूल्य स्थिर किया जाय ।

२ पूर्ति (Supply)

पूर्ति का अर्थ (Meaning)—साधारण भावना की भाषा में पूर्ति शब्द एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है । परन्तु अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग एक विनिष्ट अर्थशास्त्र में होता है । अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का आशय विना वस्तु की उम माना से हुआ किता विनिष्ट मूल्य पर विना विनिष्ट समय में किता व निर्य प्रस्तुत का जाय ।

वस्तु या पूर्ति और उमक अंक (स्क्वन्ड) में अन्तर (Difference between Supply and Demand) जिस प्रकार विना वस्तु की माग (Demand) और उमकी इच्छा (Desire) में अन्तर होता है वसा कि ऊपर बताया जा चुका है उसा प्रकार विना वस्तु की पूर्ति (Supply) और उमके (Stool) में भी अन्तर प्रकट किया जा सक्ता है । किती वस्तु के अंक से उम वस्तु की कुल मद्या या सम्पूर्ण माना से हाता हुआ मण्डी में रिक्की व निर्य मगहिन होने के और पूर्ति स्त्राव का यह भाग है जिसे विक्रता किसी विनिष्ट मूल्य पर किसी विनिष्ट समय में बचने के लिय तयार है । आकर की यह (1st Basin) व गणना में अंक उम माना का अर्थ है जो बाजार में उपयुक्त मूल्य प्रवर्तित हान पर पचा जा सक्ता है और पूर्ति उस मात्रा का अर्थ है जो विक्रता किसी विनिष्ट मूल्य पर बचने का तयार है । उदाहरण के लिय किता व्यापारी व पास ५०० मन गेहूँ है और वह हम माना में किता विनिष्ट समय में बचने २०० मन गेहूँ ही १५ १० प्रति मन के हिसाब में बचने का प्रयत्न करता है तो ५०० मन तो उमका अंक तथा २०० मन उसका पूर्ति हूँ । यह अंतर अन्तर की बात है कि मात्र नष्ट होने वाली वस्तुया के अंक और पूर्ति में बाध अन्तर नहा हाता है क्योकि एगी वस्तुया का पयात समय तक बचने नहा विना जा सक्ता । परन्तु स्थायी व टिकाऊ वस्तुया के अंक और उमकी पूर्ति में अर्थशास्त्र अन्तर होता है । वस्तुानुसार अंक का मित भिन्न भाव बचने व निर्य निश्चया जा सक्ता है ।

पूर्ति मूल्य और समय (Supply Price and time)—माग की भांति पूर्ति और मूल्य में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है । विना मूल्य के पूर्ति का का अर्थ नहा है । किसी समय में एक वस्तु का किता पूर्ति हांको यह मूल्य पर निर्भर है । बिना मित मूल्य पर वस्तु का पूर्ति मित भिन्न हांको है । मूल्य में वृद्धि हान में पूर्ति वस्तु है और मूल्य के घटने से पूर्ति घटने है । अन्त पूर्ति का विना मूल्य व का अर्थ नहा

नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ति और समय में भी सम्बन्ध पाया जाता है। मूल्य के परिमाण से अलग-अलग समय में अलग-अलग पूर्ति होना स्वाभाविक है। अस्तु, पूर्ति भी मरदा किसी विशिष्ट समय के लिये होती है, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास या प्रति वर्ष आदि।

पूर्ति का मूल्य (Supply Price)—पूर्ति का मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई विक्रेता अपनी वस्तु की निश्चित मात्रा किसी विशिष्ट समय में बेचने के लिये तैयार हो। उदाहरण के लिये, यदि कोई दूकानदार ३० २० प्रति मन के हिसाब से १५० मन चाँदी किंगो विशिष्ट समय में बेचने के लिये तैयार है, तो ३० २० प्रति मन उसकी पूर्ति का मूल्य है।

पूर्ति का नियम (Law of Supply)—पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ जाती है और मूल्य में घटने से पूर्ति घट जाती है। इसमें स्पष्ट है कि पूर्ति और मूल्य में सीधा (Direct) सम्बन्ध है, यानी जैसे परिवर्तन मूल्य में होता है वैसे ही पूर्ति में हो जाता है। इसका कारण यह है कि मूल्य बढ़ जाने पर अधिक उत्पादन और विक्रेता माल की पूर्ति बढ़ा कर लाभ उत्पन्न का प्रयत्न करेंगे। इससे अधिक स्पष्ट करने के लिये यह कहा जा सकता है कि जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उन उत्पादकों के लिये जो जिनकी लागत (Cost of Production) अधिक होगी है, अब माल उत्पन्न करना और बेचना लाभप्रद हो जाता है। वे उत्पादन जिनकी लागत पटन में ही कम है, जैसे मूल्य में अधिक लाभ प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर अधिक माल उत्पन्न कर बेचने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार कुल उत्पादन में वृद्धि होकर माल की पूर्ति बढ़ जाती है। मूल्य वृद्धि कुल उत्पादन का प्रतिक्रियात्मक उत्तर का एक अनुपात है। इसके विपरीत जब मूल्य कम हो जाता है, तो उत्पादन और विक्रेता माल की उत्पत्ति और विक्रय में कमी कर देते हैं। वे उत्पादन जिनकी लागत अधिक होगी है, अपना उत्पादन-कार्य स्वयंभू कर देते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि माल की कुल उत्पत्ति में ह्रास हो जाता है जिससे माल की पूर्ति में कमी हो जाती है। यह स्वाभाविक ही है कि विक्रेता माल बेचने का अधिक-तम अधिक मूल्य प्राप्त करने हैं, इसलिए जब माल के लिये अधिक-तम मूल्य मिले तो वे माल बेचने के लिये अधिक-तम-अधिक मात्रा में प्रस्तुत करने हैं और माल कम हो जाने पर प्रस्तुत मात्रा में कमी कर देते हैं।

माँग और पूर्ति के नियमों में अन्तर है—माँग और पूर्ति के नियमों का अन्तर ऊपर के विवरण में स्पष्ट हो गया होगा परन्तु फिर भी यहाँ स्पष्ट में दिया जाता है। माँग के नियम में मूल्य और माँग में विलोम अथवा उल्टा (Inverse) सम्बन्ध होता है, क्योंकि जब मूल्य बढ़ता है तो माँग घटती है और मूल्य घटता है तो माँग बढ़ती है। परन्तु पूर्ति के नियम में मूल्य और पूर्ति में सीधा (Direct) सम्बन्ध होता है, क्योंकि जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और मूल्य घटता है तो पूर्ति भी कम हो जाती है।

पूर्ति की सूची (Supply Schedule)—माँग सूची की भाँति पूर्ति की सूची भी तैयार की जा सकती है। इसमें विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने वाली विभिन्न पूर्ति की मात्राओं का सम्बन्ध प्रकट किया जा सकता है। अस्तु, पूर्ति की सूची वह सारणी है जिसमें किसी विशिष्ट स्थान और समय पर विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने

बालों पूर्ति की विभिन्न मात्राये दिखाई जाती है। इसको उदाहरण से इस प्रकार समझिये :—

चाय का मूल्य	चाय की पूर्ति
४ रु० प्रति पाउंड	१००० पाउंड
४ " " "	८०० "
३ " " "	६०० "
२ " " "	३०० "
१ " " "	१०० "

उपरोक्त सारणी पूर्ति के नियम को जटिल करने का प्रयास करती है इसमें यह स्पष्ट है कि मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति का मात्रा घटता जाता है और मूल्य के घटने पर पूर्ति का मात्रा घटती जाती है।

पूर्ति की सूची के भेद (Kinds of Supply Schedule)—माँग की सूची की भाँति पूर्ति की सूची भी दो प्रकार की होती है—(१) व्यक्तिगत पूर्ति सूची, और (२) बाजार की पूर्ति-सूची।

(१) व्यक्तिगत पूर्ति सूची (Individual Supply Schedule)—वह सारणी है जिसमें किसी व्यक्ति-विशेष की भिन्न-भिन्न मूल्यों पर वस्तु-विशेष की पूर्ति का परिवर्तन दिखाया जाता है।

(२) बाजार पूर्ति-सूची (Market Supply Schedule)—वह सारणी है जिसमें अनेक-अनेक मूल्यों पर अनेक बाजार और अनेक समय में समस्त उत्पादकों या विक्रेताओं की पूर्ति का परिवर्तन दिखाया जाता है।

पूर्ति की सूची की उपयोगिता (Utility of Supply Schedule)—पूर्ति की सूची में निम्नलिखित लाभ है :—

(१) इन सूचियों में व्यापारी वर्ष बाजार की प्रवृत्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता है।

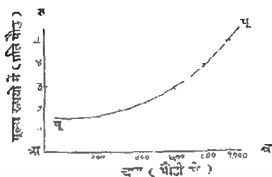
(२) इन सारणियों में क्रेताओं को भिन्न-भिन्न मूल्यों पर किसी विशिष्ट समय और स्थान पर पूर्ति की विभिन्न मात्राओं का पता चल जाता है।

(३) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने में पूर्ति की लोच का अच्छा ज्ञान हो सकता है।

(४) इन सारणियों में पूर्ति के नियम को भली प्रकार समझा जा सकता है।

पूर्ति की वक्र-रेखा (Supply Curve)—यदि किसी वस्तु की पूर्ति-सूची के अक्षों को रेखा-चित्र पर प्रदर्शित किया जाय, तो इस प्रकार प्राप्त बिन्दुओं को मिलाने से जो वक्र-रेखा बनती है उसे पूर्ति की वक्र-रेखा कहते हैं।

नीचे दिये हुए चित्र में अ व रेखा पर चाय की पूर्ति पाउंडों में और अ स रेखा पर चाय का मूल्य रुपये में (प्रति पाउंड) दिखाया गया है। ऊपर दी हुई सूची के



पूरि की वक्र रेखा (Supply Curve)

अनुसार विभिन्न मूल्य पर बची जाने वाला वस्तु की मात्रा वृद्धिमान रूप से प्रदर्शित की गयी है। इस प्रकार समस्त प्राप्त विवेचना का चित्रा दत्त व पूरि की वक्र रेखा पू पू' प्रतीती है जो बचने वाला मूल्यो व विवेका गट है।

मांग और पूरि की चक्र रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study of Demand and Supply Curves)—मांग की वक्र रेखा

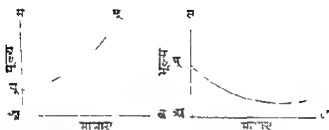


मंदिर बाई घोर व बा' घोर नीच का लक्षण सुझाता है। यह सुझाव (slope) उप-योगिता ह्रास नियम का प्रतीक है। घोर इस बात का सूचक है कि जहाँ जहाँ वस्तु व मूल्य में बचने हुआ जाती है, वहाँ जहाँ उसका मांग बढ़ती जाती है। यह नियम प्रत्यक्ष वस्तु पर लागू होता है। अतः प्रत्यक्ष वस्तु की मांग की वक्र रेखा मंदिर मुड़ी रहती है, जैसा कि मांग वक्र चित्र में स्पष्ट है।

अतः पूरि की वक्र रेखा में उन्नी विवेका पाई जाती है, अर्थात् पूरि का वक्र

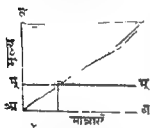
रेखा प्रत्यक्ष वस्तु व मूल्य व मांग में मांग नहीं रहती है। अतः कारण यह है कि पूरि की

मांग की वक्र रेखा वस्तु व मूल्य व मांग में मांग नहीं रहती है। अतः कारण यह है कि पूरि की वक्र रेखा का मुख्य उद्देश्य है नियम व अनुसार बदला रहता है। अतः ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) व अनुसार उद्देश्य वस्तु हुआ जाती है जिसमें वस्तुत्व लागू लागू लागू जाता है। अतः प्रत्यक्ष व मांग की वक्र रेखा मांग व मांग का मांग, उन्नी हो लागू वस्तु मांगी और पूरि की वक्र रेखा (पूरि) बाई घोर उन्नी होती जायगी। दक्षिण निच दिव दृष्टि चित्र में (१) में। अतः विवेका उद्देश्य वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) व अनुसार उद्देश्य व वृद्धि हुआ जाती है जिसमें वस्तुत्व लागू लागू लागू जाता है। अतः प्रत्यक्ष व मांग की वक्र रेखा मांग व मांग का मांग, उन्नी हो लागू वस्तु मांगी और पूरि की वक्र रेखा (पूरि) बाई घोर उन्नी जायगी। दक्षिण निच



(१)
उत्पत्ति-हारा-नियम की अवस्था
में पूर्ति की वक्ररेखा

(२)
उत्पत्ति वृद्धि-नियम की अवस्था
में पूर्ति की वक्ररेखा



(३)

उत्पत्ति स्थिर-नियम की अवस्था
में पूर्ति की वक्ररेखा

चित्र म० (३) में। उत्पत्ति स्थिर नियम (Law of Constant Returns) की अवस्था में लागत समान रहनी चाहे उत्पत्ति की मात्रा कितनी ही हो। अर्थात्, पूर्ति की वक्ररेखा (प्र.प्र.) अ.व. आधार रेखा के समानान्तर होगी। देखिये सामने के चित्र म० (३) में। इस प्रकार ये पूर्ति की वक्ररेखा के विभिन्न स्वरूप हैं।

विभिन्न प्रकार की पूर्ति (Different Kinds of Supply)

संयुक्त पूर्ति (Joint Supply)—यदि दो या अधिक वस्तुएँ किसी एक उत्पादन-क्रिया में उत्पन्न की जायें तो ये संयुक्त पूर्ति की वस्तुएँ कहलाती हैं। जैसे, पेट्रोल के बनाने में मिट्टी का तेल, बैसलीन, गैलीलीन और नैफथेलीन प्रादि वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। गेहूँ के साथ जूना, कपास के साथ बिनोले और कोल रैन में कोर साथ साथ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार उड़ी के बिलोने में मक्खन और मटु साथ साथ उत्पन्न होते हैं। संयुक्त पूर्ति की वस्तुओं में से एक को जित पर कि उत्पत्ति भाग्य मुद्रपतमा केन्द्रित होता है मुख्य उत्पत्ति (Main Product) और शेष को उप-उत्पत्ति (By-Product) कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यदि मुख्य उत्पत्ति की पूर्ति बढ़ेगी तो उप-उत्पत्ति की पूर्ति भी बढ़ेगी, और यदि मुख्य उत्पत्ति की पूर्ति घटेगी तो उप-उत्पत्ति की पूर्ति भी घटेगी। संयुक्त उत्पत्ति की अवस्था में, इनमें से किसी एक वस्तु के उत्पन्न करने का जो व्यय होता है वही इन समस्त वस्तुओं के उत्पन्न करने का व्यय समझा जाता है। अर्थात्, संयुक्त पूर्ति में दो या दो से अधिक वस्तुओं की पूर्ति साथ ही साथ किसी एक मूल्य पर होती है।

सम्मिश्रित पूर्ति—(Composite Supply)—किसी एक ही माँग की पूर्ति के लिये यदि वस्तुएँ विभिन्न स्रोतों से आव, तो इसे सम्मिश्रित पूर्ति कहेंगे। जो वस्तुएँ एक दूसरे की स्थानापन्न हैं सयुक्त पूर्ति के उत्तम उदाहरण हैं। जिस प्रकार गेहूँ और चावल भोजन की माँग की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार चाय, काफी और कोको आदि गम पेय पदार्थ भी एक ही प्रकार की माँग की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार कागज व्यवसाय में लकड़ी, नास, चीपटे और रद्दी कागज लुगदी (Pulp) बनाने में प्रयुक्त किये जाते हैं। सम्मिश्रित पूर्ति की दिशामा में विभिन्न स्रोतों (Sources) से आने वाली वस्तुएँ एक-दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती हैं, इसलिये एक वस्तु का अत्यधिक उपभोग दूसरी प्रतिस्पर्धी वस्तु के उपभोग को कम कर देता है। उदाहरण के लिये भवन निर्माण कार्य के लिये ईंटों का अधिक प्रचार हो जाने से इमारतों परपर छोड़ने का कार्य सिमित हो जाता है। इसी प्रकार मशीनों के प्रयोग से श्रमिक बेकार हो जाते हैं।

पूर्ति की लोच (Elasticity of Demand)

पूर्ति की लोच का अर्थ (Meaning)—मूल्य में परिवर्तन होने के साथ साथ पूर्ति में घटा बढ़ी होनी रहती है। वस्तु, मूल्य के साथ पूर्ति के बदलने की शक्ति या गुण को पूर्ति की लोच कहते हैं।

पूर्ति की लोच के अंश (Degrees of Elasticity Supply)—साधारणतया मूल्य बढ़ने में पूर्ति बढ़ जाती है और मूल्य के घटने से पूर्ति घट जाती है। परन्तु जब किसी वस्तु की पूर्ति में ठीक मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की पूर्ति को लोचदार (Elastic) कहेंगे। जैसे मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर पूर्ति में भी ५० प्रतिशत वृद्धि होकर। जब पूर्ति में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन से अधिक अनुपात में हो, तो वह पूर्ति अधिक लोचदार (Highly Elastic) कही जायगी। जैसे मूल्य में २० प्रतिशत वृद्धि होने पर पूर्ति में ५० प्रतिशत वृद्धि होना। जब पूर्ति में परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन से कम अनुपात में होता है, तो उस पूर्ति को बेलोच (Inelastic) कहेंगे। उदाहरणार्थ, किसी वस्तु के मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि हो, तो वह बेलोच पूर्ति होगी। इसी प्रकार लोच का अंशात्मक माप मूल्य के घटने के उदाहरणों द्वारा चरितार्थ किया जा सकता है।

पूर्ति की लोच के विभिन्नता के कारण (Causes of variation in Elasticity of Supply)—सब वस्तुओं की लोच समान नहीं होती और न मध्य परिस्थितियों में किसी वस्तु की पूर्ति का लोच एक ही रहती है। कुछ वस्तुओं की पूर्ति की लोच अधिक होती है और कुछ की कम, इसके कई कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१)—वस्तुओं का स्वभाव (Nature of Commodities)—पूर्ति की लोच अंशतः वस्तुओं के स्वभाव पर भी निर्भर होती है, अर्थात् वस्तु नाशवान् (Perishable) है अथवा टिकाऊ (Durable)। नाशवान् अर्थात् शीघ्र नष्ट होने

वानो वस्तुएं जैसे दूध, मछली, ताजी शक्जियाँ आदि अधिक समय तक संचित नहीं रखी जा सकती और न इनकी पूर्ति में मूल्य के अनुसार परिवर्तन ही किया जा सकता है। इसलिये इनकी पूर्ति बेलाच (Inelastic) होती है। वास्तव में, इनके स्टॉक और पूर्ति में कोई भ्रन्तर नहीं होता। परन्तु टिकाऊ वस्तुओं (गेहूँ, सोना, कीयला आदि) में ऐसा नहीं है। ये अधिक समय तक संचित रखी जा सकती हैं तथा मूल्य के अनुसार इनकी पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मूल्य बढ़ता है, तो पूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है और मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटाई जा सकती है। इसलिये इनकी पूर्ति लोचदार (Elastic) होगी है। अस्तु, स्थायी या टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचदार और नाशवान वस्तुओं की पूर्ति बेलाच होती है।

(२)—उत्पादन-व्यय (Cost of Production)—किसी वस्तु के उत्पादन व्यय का उसकी पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में सीमान्त लागत-व्यय (Marginal Cost of Production) पहले की प्रती भा बढ़ जाता है, तो उस वस्तु की पूर्ति कम सांचवार होगी। ऐसी शक्स्था में यदि मूल्य में थोड़ी वृद्धि होती है तो वह बढ़ते हुए लागत-व्यय के लिये पर्याप्त होने में पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती। यदि उत्पादन-वृद्धि के साथ-साथ लागत-व्यय कम हो जाता है, तो मूल्य के थोड़े से बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। ऐसी दशा में पूर्ति सांचदार होती है। सबसे में, जब सीमान्त लागत व्यय वेग में बढ़ता है, तब पूर्ति में लोच कम होगी, जब सीमान्त लागत-व्यय में धीरे-धीरे वृद्धि होती है तब लोच अधिक होगी, और जब सीमान्त लागत-व्यय घटता जाता है, तो उस समय पूर्ति में अधिक लोच होगी।

(३)—उत्पादन-प्रणाली (System of Production)—पूर्ति की लोच कुछ अत तक उत्पत्ति की प्रायोगिक (Technical) दशा पर भी निर्भर होती है। यदि किसी वस्तु की उत्पादन-प्रणाली बहुत जटिल या विशिष्ट प्रकार की है, तो पूर्ति बेलाच होगी, क्योंकि ऐसी दशा में पूर्ति में गुणानुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यदि उत्पादन-प्रणाली सीधी व सरल है तथा निम्ने स्थिर पूँजी (Fixed Capital) का अधिक उपयोग नहीं हो तो पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि पूर्ति में मूल्यानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अस्तु, जटिल एवं विशिष्ट उत्पादन प्रणाली में पूर्ति बेलाच होती है और सीधी व सरल उत्पादन-प्रणाली में पूर्ति लोचदार होती है।

(४)—भावी मूल्य का अनुमान (Estimation of Future Price)—पूर्ति की सांच विक्रता के भावी मूल्य के अनुमान से भी प्रभावित होती है। यदि उसका अनुमान है कि मूल्य और अधिक बढ़ेगा, तो वह स्टॉक को रोक कर बाद में बेचने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार यदि भविष्य में अधिक मूल्य मिलने या थोड़ा मूल्य बढ़ने का अनुमान लगाया जाय, तो पूर्ति की लोच अधिक होगी।

उत्पादन व्यय (Cost of Production)—किसी वस्तु के उत्पादन में अनेक माधन और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादक को ये सेवाएँ नि मुक्त उपलब्ध नहीं होती बल्कि उसे उनसे बदले में कुछ देना पड़ता है। यत्न, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ न कुछ लागत लगती है। उदाहरण के लिये, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिये उत्पादक का आवश्यक उत्पादन-माधन को निश्चित पारिश्रमिक पर रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है और वह स्वयं सारी जोखिम भेजता है तथा प्रत्येक चिन्ताओं और कठिनाइयों के साथ कार्य में मग्न रहता है। इस प्रकार की सब सेवाओं तथा त्याग का अर्थशास्त्र में उत्पादन-व्यय (Cost of Production) कहते हैं। उत्पादन-व्यय में दो घटक अन्तर्हित हैं। जब उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने वाले सम्पूर्ण उत्पत्ति के साधनों के परिश्रम, त्याग एवं सेवाओं के रूप में अनुमान लगाया जाता है, तो हम इसे वास्तविक उत्पादन-व्यय (Real Cost of Production) कहते हैं, जब उत्पादन-व्यय को मुद्रा में नापा जाता है, तो उसे मुद्रा-उत्पादन व्यय (Money Cost of Production or Expenses of Production) कहते हैं।

प्रमुख और पूरक लागत

(Prime Cost & Supplementary Cost)

कुल उत्पादन-व्यय के दो भाग किये जा सकते हैं—(१) प्रमुख लागत और (२) पूरक लागत।

प्रमुख लागत (Prime Cost)—प्रमुख लागत में आन्तरिक उत्पादन व्यय के उन भागों का है जिनका उत्पत्ति में मीमांसा सम्बन्ध होता है तथा जिनमें उत्पत्ति के माधन-साधन पश्चित होना पड़ता है। कच्चे माल का मूल्य, साधारण श्रमिकों की मजदूरी (भूति), प्रेरक शक्ति का व्यय आदि इसके अन्तर्गत हैं। जैसे-जैसे उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे प्रमुख लागत में वृद्धि होती जाती है। उत्पत्ति की मात्रा में कमी होने में प्रमुख लागत भी कम हो जाती है। यदि कुछ समय के लिये उत्पादन स्थगित कर दिया जाय, तो प्रमुख लागत कुछ भी नहीं होगी।

पूरक लागत (Supplementary Cost)—उत्पादन व्यय के वे सम्पूर्ण स्थायी एवं अस्थायी व्यय जो उत्पत्ति के साथ परिवर्तन नहीं होता है, पूरक लागत कहलाते हैं। कारखाने का निरासा, मशीनों का खर्च, प्रबंधन का वेतन आदि इसमें सम्मिलित हैं। कारखाने में चाहे पूरे समय तक काम हो अथवा बाधित समय तक, पूरक लागत में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिये, मान लीजिये, किन्तु कारखाने का कारखाना एक मकान के लिये बन्द हो जाता है। काम बन्द रहने की हलाक में कच्चे माल, प्रेरक शक्ति पर कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। किन्तु मकान-भूतिका का कारखाने का निरासा, मशीनों का वेतन पाने वाले अर्थशास्त्रियों और प्रबंधकों का वेतन आदि तो हर हालत में देना ही पड़ेगा, चाहे काम चालू हो या नहीं। अतः, उत्पादन कार्य स्थगित हो जाने पर प्रमुख व्यय तो बन्द हो जायगा परन्तु पूरक व्यय जारी रहेगा।

प्रमुख और पूरक लागत का अन्तर—प्रमुख और पूरक लागत का अन्तर नात करना बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इनकी व्यावहारिक उपयोगिता मुख्य के सिद्धान्त में प्रत्यक्ष है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि प्रमुख और पूरक लागत के योगफल को कुल लागत (Total Cost) कहते हैं। दीर्घकाल (Long Period) में वस्तु का मूल्य कुल लागत के बराबर होना चाहिए मगर उस वस्तु का उत्पादन जारी नहीं रह सकेगा। यदि अल्पकाल (Short Period) में मांग में कमी होने के कारण मूल्य कुल लागत से भी नीचे गिर जाय तो ऐसी अवस्था में उत्पादक क्या करे ? यह पहले बताया जा चुका है कि अल्प समय में पूरक लागत स्थायी होती है अतः उत्पत्ति को मात्रा में कम करने में पूरक लागत में कोई कमी नहीं होती मगर मुख्य (चर) समय में कम से कम इतना होना चाहिए जिसमें प्रमुख लागत तो निकल सके। यदि ऐसा नहीं है तो उत्पादक उत्पत्ति को और अधिक घटा कर प्रमुख लागत को कम करने का प्रयत्न करेगा। यह प्रयत्न उस समय तक जारी रहेगा जब तक मूल्य प्रमुख लागत की सीमा न छू ल। किन्तु दीर्घकाल में मुख्य प्रमुख लागत और पूरक लागत के बराबर होना चाहिए मगर व्यापार स्वयंसे हो जाएगा। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में सब प्रकार की लागत परिवर्तनीय हो जाती है और उत्पत्ति के साधन वहाँ लगाय जायेंगे जहाँ वे अधिक लाभदायक सिद्ध हो सके हैं।

सीमांत और औसत लागत (Marginal and Average Cost)—अंतिम इकाई के उत्पादन व्यय को सीमांत लागत (Marginal Cost) कहते हैं। मान लीजिए जब किसी एक वस्तु की १० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं तो कुल लागत ४०० रुपया है और जब ११ इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं तो कुल लागत ४५१ रुपया हो जाती है। इन दोनों उदाहरणों में ११ वीं इकाई सीमांत इकाई है और दोना कुल लागत का अंतर अर्थात् ५१ रुपया इसकी लागत हुई। इसे सीमांत लागत कहेंगे। प्रत्येक उत्पादक उत्पत्ति को उस समय तक बढ़ाता जाएगा जब तक सीमांत-लागत मूल्य में कम है। जब सीमांत लागत और मूल्य दोनों बराबर हो जायेंगे तब उत्पादन स्थिति बार दिया जाता है। यदि उत्पादक इस सीमा को उल्लंघन करते हुए उत्पादन घाटू रखता है तो सीमान्त लागत मूल्य में अधिक हो जाएगी जिससे उसको हानि होगी।

कुल लागत को उत्पन्न की गई इकाइयाँ की संख्या से भाग देने में औसत लागत का पता चल जाता है। ऊपर के उदाहरण में जब १० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं तब औसत लागत ४० रुपया है और जब ११ इकाइयाँ का उत्पादन होता है तो औसत लागत ४१ रुपया है। उत्पत्ति में वृद्धि होने पर औसत लागत बढ़ सकती कम हो सकती या स्थिर रह सकती है। जब सीमांत लागत औसत लागत में कम होती है तो उत्पत्ति के बढ़ने पर औसत लागत गिर जायगी और जब सीमांत लागत औसत लागत में अधिक है तो उत्पत्ति के बढ़ने पर औसत लागत में वृद्धि हो जाएगी।

मूल्य निर्धारण में सीमान्त लागत का अधिक महत्व है क्योंकि साधारणतया मूल्य सीमान्त लागत के बराबर होता है। जब यह आवश्यक नहीं है कि सीमान्त लागत और औसत लागत दोनों बराबर ही हों तो मूल्य भी औसत लागत से कम अधिक हो सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएं

- १—माँग और पूर्ति की सारणियों (Schedules) तथा रेखाओं (Curves) की परिभाषा कीजिये, मममाइये तथा उन्हें चित्रित कीजिये ।
- २—माँग की लोच का अर्थ समझाइये । कुछ वस्तुओं की माँग की लोच प्रत्यक्ष वस्तुओं की माँग की लोच से अधिक क्यों होती है ? जिन वस्तुओं की माँग की लोच अधिक होती है उनके पाँच उदाहरण दीजिये ।
- ३—पूर्ति की लोच से क्या तात्पर्य है ? पूर्ति की लोच का आधार किन किन बातों पर निर्भर है ? (घ० बो० १९५७)
- ४—माँग की लोच से क्या तात्पर्य है ? माँग के विस्तार और वृद्धि में भेद बनाइये । (घ० बो० १९५६ पू०)
- ५—माँग की लोच का क्या अर्थ है ? किन-किन बातों पर यह लोच निर्भर होती है, उदाहरण दीजिये । (घ० बो० १९५३)
- ६—माँग का सारणी तथा वक्र रेखा किसे कहते हैं ? प्रायः घपने नगर के तीन वर्ग—धनी, मध्यम तथा निर्धन की सतरा की सम्मिलित माँग की सारणी २४ आने, २० आने, १६ आने तथा ६ आने प्रति दजन मावा पर बनाइये । विभिन्न मूल्यों पर तीन वर्गों द्वारा खरीदे जाने वाले सतरों की संख्या को जोड़िये । प्रायः कागज पर माँग की वक्र रेखाएँ अंकित करिये और बताइये कि प्रायः इन वक्र रेखाओं से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ? (रा० वा० १९५५)
- ७—माँग की लोच का क्या तात्पर्य है ? माँग की लोच को प्रभावित करने वाली बातों को संक्षेप में लिखिये । (म० भा० १९५४)
- ८—माँग की लोच में क्या अभिप्राय है ? कुछ वस्तुओं की माँग दूसरी वस्तुओं की माँग से अधिक लोचदार क्यों होती है ? (सागर १९५२, १९५०)
- ९—माँग के नियम की व्याख्या करिये । माँग में प्रत्यक्ष के प्रभाव को बताइये । (दिल्ली हा० से० १९५१)
- १०—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये—
 माँग की लोच (नागपुर १९४५)
 माँग की पूर्ति की सारणी (उ० प्र० १९५७, ५१, ५७)
 पूर्ति की लोच (म० भा० १९५४)
 माँग और पूर्ति की वक्र रेखा (बनारस १९४६)
 पूर्ति अनुसूची (घ० बो० इ० एग्जीक्यूटिव, १९५६)

मूल्य शब्द का अर्थ (Meaning)

इस पुस्तक के प्रथम भाग के दसवें अध्याय में ग्रह (Value) और मूल्य (Price) का विचार विवेचन किया जा चुका है । यहाँ केवल इतना दुहरा देना ही पर्याप्त है कि किसी वस्तु की विनिमय शक्ति अर्थात् बदले में अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति को विनिमय ग्रह (Value-in-Exchange) कहते हैं । जैसे यदि किसी एक मेज के बदले में चार कुर्सियाँ प्राप्त की जा सकती हैं तो उस मेज की ग्रह चार कुर्सियाँ हुई । परन्तु जब किसी वस्तु की विनिमय ग्रह को मुद्रा में प्रकट किया जाय, तो वह उस वस्तु का मूल्य (Price) कहलायेगा । उदाहरण के लिये, यदि उस मेज को खरीदने में ४० रुपया व्यय करना पड़ता है तो यह राशि उसका मूल्य हुआ । प्राथमिक अर्थ-शास्त्र में मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सब चीज़ें मुद्रा द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं । अतः मुद्रा मूल्य की जन्मदाता कही जा सकती है । भारत में, देखा जाय तो अर्थशास्त्र का विज्ञान मूल्य के सिद्धान्त पर ही अवलम्बित है । अस्तु, मूल्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में बड़ा महत्त्व रखता है । इस प्रकार वस्तुओं की विनिमय ग्रहों के निर्धारण की समस्या वास्तव में वस्तुओं के 'मूल्य-निर्धारण' की ही समस्या है ।

प्रायः हम यह देखते हैं कि बाजार में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ क्रय-विक्रय के लिये प्रस्तुत की जाती हैं उन सबका मूल्य एक-समान नहीं होता है । हमें प्रतिरिक्त, मात्र जो एक वस्तु का मूल्य है वह सर्वत्र उतना ही नहीं बना रहता । उसमें प्रायः उतार-चढ़ाव होता रहता है । इस सम्बन्ध में कई प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक है, जैसे—किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ? वस्तुओं के मूल्य में भिन्नता क्यों पाई जाती है ? मूल्य में प्रायः परिवर्तन क्यों होता है ? इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जायगा ।

किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ?

(How is price of a commodity determined)

अर्थात्

मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त

(Theory of Determination of Price)

परिचय (Introduction)—वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में समय समय पर कई सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये परन्तु वे एकपक्षीय, अपूर्ण एवं दूषित होन के कारण अस्वीकार किये गये। उदाहरणार्थ, मूल्य का श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) जिसे प्रारम्भ में आदम स्मिथ (Adam Smith) तथा रिकार्डो (Ricardo) नामक मर्यादात्मिकों ने स्वीकार किया था तथा बाद में जर्मन विद्वान कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने इस पर विरोध विवेचना की थी, यह बतलाना है कि वस्तुओं का मूल्य श्रम के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। मान लीजिये कि दो वस्तुएँ उत्पन्न की जाती हैं। यदि उनमें से एक वस्तु को उत्पन्न करने में चार दिन का श्रम लगता है और दूसरी को उत्पन्न करने में केवल दो दिन का ही श्रम लगता है तो पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य की अपेक्षा दुगुना होगा। यह सिद्धान्त माँग पक्ष (Demand Side) की अपेक्षा करता है और पूर्ति पक्ष (Supply Side) का केवल अपूर्ण विवेचन करता है। अतः इसकी बड़ी भालोचना हुई और यह मर्यादा अपेक्षात्मिक घोषित किया गया। इन प्रकार का दूसरा सिद्धान्त मूल्य का उत्पादन व्यय सिद्धान्त (Cost of Production Theory of Value) है। इसमें श्रम के अनिश्चित अन्य उत्पादन-व्यय भी सम्मिलित किये गये हैं। परन्तु फिर भी यह एकपक्षीय ही है, क्योंकि श्रम सिद्धान्त की भाँति इससे द्वारा भी माँग पक्ष की अपेक्षा की गई है, अर्थात् यह केवल पूर्ति पक्ष का ही प्रतिपादन करता है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए जेक्स (Jevons) ने इसनेट में, मैंगरन ने आदिष्टा में और वायरस ने म्बिन्डरनेट में मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility Theory of Value) को प्रचलित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी माँग तथा उपभोक्ता के लिये उसकी उपयोगिता के अनुसार ही निर्धारित होता है। यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उसने मिलने वाली उपयोगिता से अधिक हो जाता है, तो उपभोक्ता उसे लेना बन्द कर देंगे। यह सिद्धान्त भी एकपक्षीय है, क्योंकि इसने द्वारा मूल्य की समस्या का अध्ययन पूर्ति-पक्ष की अपेक्षा करते हुए केवल माँग-पक्ष के दृष्टिकोण से ही किया जाता है।

प्रो० मार्शल ने इन सिद्धान्तों के पारस्परिक विरोध को मिटाने का प्रयत्न किया। उनके मतानुसार न तो केवल उत्पादन व्यय और न केवल उपयोगिता ही परन्तु दोनों मिल कर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करत हैं। मूल्य माँग तथा पूर्ति दोनों पर निर्भर है। माँग पर सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है और पूर्ति पर उत्पादन व्यय का। इस प्रकार प्रो० मार्शल के मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में माँग और पूर्ति का समान महत्त्व प्राप्त है। इसलिये इसे मूल्य का माँग और पूर्ति का सिद्धान्त (Demand & Supply Theory of Value) कहते हैं। इस सिद्धान्त के द्वारा मूल्य-निर्धारण की समस्या पर माँग और पूर्ति दोनों दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। अतः यह सिद्धान्त प्राक्कल वैज्ञानिक, पूर्ण एवं सर्वमान्य समझा जाता है। अब हम इसी सिद्धान्त का विवेचन करेंगे।

मूल्य का आधुनिक सिद्धांत (Modern Theory of Value)— प्रो० मार्शल द्वारा प्रतिपादित माँग और पूर्ति का सिद्धान्त मूल्य का आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति साम्य का गणिता के पारस्परिक प्रभाव (Interaction) द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में जिस बिन्दु पर माँग और पूर्ति में सन्तुलन होता है वही पर मूल्य निर्धारित होता है। यह किस प्रकार होता है ? माँग और पूर्ति के सन्तुलन द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है ? इसकी समझने के लिये सप्लाई माँग और पूर्ति सम्बन्धी कुछ बातों का विवेचन करना आवश्यक है।

माँग-पक्ष (Demand Side)— माँग पक्ष का विस्तारण न हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मिलता है —

- (१) किसी वस्तु की माँग क्या होती है ?
- (२) किसी वस्तु का मूल्य क्या दिया जाता है ?
- (३) किसी वस्तु का मूल्य किस सीमा तक दिया जा सकता है ?

किसी वस्तु की माँग हम वारण कहते हैं क्योंकि उसमें उपयोगिता है। यदि उपयोगिता या आवश्यकतापूर्वक शक्ति किसी वस्तु में नहीं है तो कोई भी उस वस्तु की माँग प्रस्तुत न करेगा और न कुछ मूल्य देने का तैयार होगा। वस्तु उपयोगिता माँग का आधार है। किसी वस्तु की माँग प्रायः उसमें अताप्रा द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कोई अता किसी वस्तु का मूल्य इसलिये देता है कि वह वस्तु उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो कुछ मूल्य कोई अता किसी वस्तु के बदले देने के लिये मया रखता है उसे 'माँग मूल्य' कहते हैं। यह मूल्य आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होता है। जितनी अधिक प्रबल आवश्यकता की वृद्धि होती वस्तु करती है उतना ही अधिक मूल्य उसने लिये अता देने की तैयार होगा है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अनाज खाता हो तो वह सम्भवतः पानी में एक मिलाव के लिये एक रुपया देने की तैयार हो सकता है। जब उसकी प्यास बहुत गंभीर हो जाए और अगर बिना पानी की आवश्यकता कुछ भी न रहे तो वह पानी का एक मिलाव के लिये एक पाना भी देने की तैयार न होगा। इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अता किसी वस्तु की पहली इकाई के लिये अधिकतम मूल्य देने की तैयार रहता है क्योंकि इससे उसकी श्रम्य न तीव्र आवश्यकता की पूर्ति होती है। उपयोगिता द्वारा नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु की इकाईयाँ के उपयोग में वृद्धि की जाय तो उसकी प्रायः पानी इकाईयाँ की सीमागत उपयोगिता घटता जायगी। इस कारण प्रायः प्रायः प्रायः इकाईयाँ का माँग मूल्य भी घटता जायगा। यदि उस वस्तु का श्रम्य जाना गया जाय तो प्रायः एक ऐसी अवस्था प्रायः जबकि जो मूल्य वस्तु की श्रम्य इकाई के लिये देना पड़गा वह उस इकाई की उपयोगिता के बराबर होगा। वह इस इकाई पर अपना श्रम्य व्यय कर देगा। इसी कारण इस श्रम्य की अन्तिम इकाई बढ़ेगी। जब मूल्य किसी वस्तु की अन्तिम इकाई के लिये दिया जाता है वह उस वस्तु की सीमागत उपयोगिता (Marginal Utility) का माप होता है। जब शरीर जाने वाली वस्तु का शरीर इकाईयाँ सब प्रवाह में समान है तो कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि अता पहली इकाई (जिनको कि उपयोगिता उसने लिये श्रम्य है) का मूल्य अधिक है और बाद वाली इकाईयाँ का मूल्य कम है। वह सारी इकाईयाँ का मूल्य एक ही दर से

अर्थात् अपने स्वयं की अन्तिम इकाई की उपयोगिता के बराबर वाले मूल्य के हिमाज में देगा। अस्तु, जो मूल्य कौता किसी वस्तु के लिये देने को तैयार होता है वह उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है। यदि मूल्य सीमान्त उपयोगिता में अधिक है, तो वह उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। वैसे तो कौता कम से कम मूल्य पर वस्तु को खरीदना चाहेगा परन्तु अधिक से अधिक मूल्य जो वह देने को तैयार हो सकता है, वह वस्तु की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होगा। मध्य में, माँग की ओर से सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) बाजार-मूल्य के लिये अधिकतम सीमा (Maximum Upper Limit) निर्धारित करती है। यह कौता का अधिकतम मूल्य (Maximum Price) है जिससे अधिक वह नहीं देगा।

इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि केवल उपयोगिता द्वारा ही मूल्य निर्धारित होता है। एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न होती है। अतः उसका मूल्य भी प्रत्येक के लिये भिन्न-भिन्न होता चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि बाजार में एक वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य प्रदर्शित होता है, यद्यपि उसकी उपयोगिता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न है। इसी प्रकार यदि उपयोगिता ही मूल्य का आधार है, तो जिन वस्तुओं में उपयोगिता अधिक है उनका मूल्य अधिक होना चाहिये, और जिनकी उपयोगिता कम है उनका मूल्य कम होना चाहिये। खाद्य सामग्री, जल, धातु आदि की उपयोगिता हीरे आदि में कहीं अधिक है। फिर भी हीरे का मूल्य उन सबमें अधिक होता है। इसी प्रकार लोहे की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक है, परन्तु इसका मूल्य सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल आदि धातुओं में बहुत कम होता है। अस्तु इसमें, यह पता चलता है कि मूल्य निर्धारण में केवल उपयोगिता का होना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे प्रतिरिक् किसी अन्य शक्ति की भी आवश्यकता है। वह है पूर्ति (Supply)।

पूर्ति-पक्ष (Supply Side)—पूर्ति-पक्ष का विस्तृत रूप निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रकाश डालता है—

- (१) किसी वस्तु की पूर्ति का प्रश्न कब और क्यों उठता है ?
- (२) किसी वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है ?
- (३) किसी वस्तु का मूल्य किस सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है ?

जब तक किसी वस्तु की माँगा पर्याप्त नहीं है तब तक उसकी पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो उसे बेचने के लिये बाजार में ले जाने का कौन क्या करेगा। वस्तु, बाजार में किसी के लिये उन्हीं वस्तुओं की लोपा जाता है जिनकी माँगा पर्याप्त होती है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में प्राप्त करने में कुछ-कुछ लाभ आवश्यक लगती है। इसलिये विज्ञेता उन वस्तुओं के लिए कुछ मूल्य माँगी है। यदि मूल्य उत्पादन व्यय में कम है, तो विज्ञेता उस वस्तु को नहीं बेचेगा। कम से कम मूल्य जो कि किसी वस्तु की एक विशेष इकाई के लिये स्वीकार कर सकते हैं वह उसकी सीमान्त उत्पादन-व्यय (Marginal Cost of Production) के बराबर है। यदि मूल्य सीमान्त उत्पादन-व्यय से कम है, तो वे

उस इकाई का उत्पादन स्थगित कर देंगे। यह सम्भव है कि किसी दिन मूल्य उतत व्यय में कम हो जाय, पर यह सदैव के लिये नहीं हो सकता। जिस मूल्य पर विक्रेता किसी वस्तु की बेचने के लिये तैयार रहते हैं उसे 'पूँजि-मूल्य' कहते हैं। यह उत्पादन-व्यय पर निर्भर होता है। जैसे तो विक्रेता अपनी वस्तु की अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करेगा परन्तु कम से कम मूल्य जो वह उस वस्तु के लिये स्वीकार कर सकता है, वह वस्तु के सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होगा, संक्षेप में, पूर्ति की ओर से सीमान्त उत्पादन-व्यय (Marginal Cost of Production) बाजार-मूल्य के लिये न्यूनतम सीमा (Minimum or Lower Limit) निर्धारित करता है। यह विक्रेता का न्यूनतम मूल्य (Minimum Price) है जिसके नीचे वह उसका मूल्य कमो स्वीकार नहीं करेगा।

इसमें यह सही समझ लेना चाहिये कि मूल्य केवल उत्पादन-व्यय द्वारा ही निर्धारित होता है। चाहे जितना अधिक किसी वस्तु का उत्पादन-व्यय क्यों न हो, पर जब तक उसमें उपयोगिता न होगी तब तक उसका कुछ भी मूल्य न होगा। जैसे किसी मशीन के धराने में पर्याप्त लागत लगी है, परन्तु उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है क्योंकि उससे ऐसी तेज कहीं छेदी आवाज उत्पन्न होती है कि उसको कोई भी खरीदना पसन्द नहीं करता। अतः, लागत होते हुये भी उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल्य में प्रायः परिवर्तन होता रहता है, परन्तु वस्तु का निर्माण समाप्त हो जाने पर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह उतना ही रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल उत्पादन-व्यय में ही मूल्य निर्धारण की समस्या हल नहीं की जा सकती। इसके लिये माँग (सीमान्त उपयोगिता) और पूर्ति (सीमान्त उत्पादन-व्यय) का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है।

माँग और पूर्ति का पारस्परिक प्रभाव (Interaction of Demand & Supply)—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति की दो शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव में निर्धारित होता है। माँग अर्थात् सीमान्त उपयोगिता क्रेता की ओर से मूल्य की अधिकतम सीमा नियत करती है। वह हमसे अधिक मूल्य नहीं देता और बेध्या इस बात की करता है कि जहाँ तक हो सके उसे कम से कम मूल्य देना पड़े। इसी प्रकार पूर्ति अर्थात् सीमान्त उत्पादन व्यय-विक्रेता की ओर से मूल्य की न्यूनतम सीमा नियत करता है। वह इससे कम मूल्य स्वीकार नहीं करेगा जबकि इससे अधिक मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इन्हीं दो सीमाओं के बीच में मूल्य निर्धारित होता है। अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि इन दो सीमाओं के अन्तर किसी वस्तु का ठीक मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? इस प्रश्न का सरल जवाब में उत्तर देते हुए यो कहा जा सकता है कि इन दो सीमाओं के बीच में किसी वस्तु का मूल्य (अ) क्रेताओं और विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता, (ब) माँग व पूर्ति की सापेक्षिक आवश्यकता (Relative Urgency) और (स) क्रेताओं व विक्रेताओं की सीढ़ा करने (Bargaining) तथा भाव-ताव (Higgling) करने की कुशलता द्वारा निर्धारित होता है। इनसे उम्बो में, यदि माँग का प्रभाव अधिक है, प्रयत्न प्रेमाओं की खरीदने की आवश्यकता अधिक तीव्र नहीं है तथा वे गोदा व भाव-ताव करने में

अधिक बुझने है, तो मूल्य विक्रेता की न्यूनतम सीमा (सीमान्त उत्पादन-व्यय) के निकट होगा यानी बेताया \therefore अनुकूल होगा । यदि पूर्ति का प्रभाव अधिक है अर्थात् विक्रेताओं की माग बेचने की इच्छा तीव्र नहीं है तथा वे मोटा व भाव-भाव करने में अधिक निपुण है तो मूल्य क्रेता की अधिकतम सीमा (सीमान्त उपयोगिता) के निकट होगा यानी विक्रेताओं के अनुकूल होगा ।

इस प्रकार प्रो० मार्शल के कथनानुसार "मूल्य इन दो सीमाओं के बीच में बैडमिंटन की चिड़िया (शटल कॉक) की भाँति घूमता रहता है ।" जर क्रेता पक्ष या प्राहक तब बचने को अधिक उत्सुक होता है तो मूल्य ऊपर की मताह (Upper Limit) तक चढ़ जाता है और जब विक्रेता मान की जखत या पूर्ति बढ़ाने के लिये लाजायित हो उठता है तो मूल्य सिसक कर नीचे की सतह (Lower Limit) पर आ जाता है । परन्तु मूल्य का उतार-चढ़ाव अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता । जैसे जैम समय बीतता जाता है, यह निश्चयात्मक रूप में वस्तु की उपयोगिता प्रमाण माँग और उत्पादन सागत-व्यय प्रमाण पूर्ति के समय के केन्द्र पर जाकर स्थिर हो जाता है । इस प्रकार इन दो सीमाओं के बीच में वास्तविक मूल्य उस बिन्दु पर निश्चित होता है जहाँ पर माँग और पूर्ति दोनों हो बराबर हों । माँग और पूर्ति के इस प्रकार बराबर होने को माँग और पूर्ति का सन्तुलन (Equilibrium of Demand & Supply) कहते हैं । जिस स्थान पर माँग और पूर्ति बराबर होता है उसे सन्तुलन बिन्दु (Equilibrium Point) कहते हैं और इस मूल्य को सन्तुलन मूल्य (Equilibrium Price) कहते हैं । मार्शल इसे 'स्थायी सन्तुलन मूल्य' (Temporary Equilibrium Price) कहता है और मिल (Mill) ने इस 'साम्य मूल्य' (Equation Price) कह कर पुकारा है । यदि मूल्य बढ़ता है, तो बेताया की माँग कम हो जाती है और उधर विक्रेता अधिक माना में बेचने के लिये तैयार हो जाते हैं जिससे पक्कड़प उबल प्रतिभागिता होती है और पूर्ति में वृद्धि होकर मूल्य घट जाता है । इसके विपरीत यदि मूल्य घटता है, तो माँग बढ़ जाती है पर पूर्ति घट जाती है, बेताया में प्रतिभागिता होती है जिससे पक्कड़प मूल्य बढ़ जाता है और अन्त में सन्तुलन-बिन्दु पर रुक जाता है । मिल ने माँग, पूर्ति और मूल्य के इस सम्बन्ध को निम्न शब्दा में स्पष्ट किया है :
 "माँग, पूर्ति और मूल्य एक यन्त्र रचना के तीन अंगों के समान हैं जिसमें, गैर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया



1—"The price may be tossed hither and thither like a shuttle cock as one side or the other gets the better in the higgling and bargaining of the market"
 —Marshall.

प्रभाव पड़ता है और दोनों की प्रवृत्ति मनुष्य की ओर होती है।”^१ अर्थात् यह अन्त-निर्भरता एक पक्ष में पड़े तीन पक्षों की भाँति है, और हम नहीं कह सकते कि कौन किसके सहारे खड़ा है।

सिल्वरमैन (Silverman) के शब्दों में “माँग की ओर से एक विन्दु का मूल्य सीमान्त उत्पादन व्यय अथवा सीमान्त औद्योगिक पथ द्वारा अनुमानित व्यय के समान रहता है। इस प्रकार के सीमान्त व्यय और सीमान्त उपयोगिता के मनुष्य की मुद्रा माँगों के बीच पर ‘मूल्य’ कहा जाता है।

उदाहरण (Illustration)—इस सिद्धान्त को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा भली प्रकार समझाया जा सकता है :—

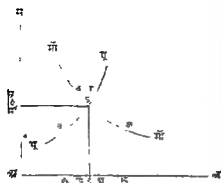
कम्य माना (माँग)	चाय का मूल्य (प्रति पाँड)	विक्रय माना (पूर्ति)
२०० पाँड	५ ७० प्रति पाँड	१००० पाँड
४०० „	४ „ „ „	८०० „
६०० „	३ „ „ „	६०० „
८०० „	२ „ „ „	३०० „
११०० „	१ „ „ „	१०० „

उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि ३ २० प्रति पाँड दर से चाय की माँग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, अर्थात् श्रेष्ठा ६०० पाँड चाय खरीदना चाहेंगे और विक्रेता भी उतनी ही चाय बेचना चाहेंगे। यतः यही विन्दु माँग और पूर्ति के मनुष्य को प्रकट करता है। अब मान लीजिए कि मूल्य ४ २० प्रति पाँड पर दिया जावे, तो माहक ४०० पाँड चाय खरीदना चाहेंगे जबकि विक्रेता ८०० पाँड चाय बेचना चाहेंगे। इसी प्रकार अन्य मूल्यों पर भी माँग और पूर्ति का समुतन स्थापित न हो सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि मूल्य पुनः ३ २० प्रति पाँड पर स्थिर हो जावेगा।

सिद्धान्त का रेखा-चित्रण (Diagrammatic Representation)—मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त को रेखा-चित्र द्वारा भी निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है :—

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण—इस चित्र में अक्ष रेखा माँग और पूर्ति की मात्रा को प्रकट करती है और अक्ष रेखा मूल्य प्रकट करती है। माँ माँ माँग-ग्राह्य

१) —“Demand, Supply and Price are like the three sections of a mechanism which always act and react upon each other and always tend to a state of equilibrium.” —Mill



मांग और पूर्ति की माप

निर्दिष्ट होता है, ता इस माप की सहायता से जान होया कि प्रत्येक मात्रा मांगी जायगी और प्रत्येक मात्रा किसने द्वारा देखी जायगी। मांग में पूर्ति अधिक होने के कारण मूल्य गिरेगा। मान लीजिए मूल्य ८ में भी नीचे फिर जाता है और वह छ पर स्थिर हो जाता है। इस मूल्य पर मांग की मात्रा ३५ है और पूर्ति की मात्रा ३८। मांग पूर्ति से अधिक है, अतः मूल्य बढ़ेगा। इस पर स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य ८ में कम या ज्यादा होना पर मांग और पूर्ति की मात्राओं में भी असंतुलन हो जाता है और मूल्य वापस हाकर ८ पर आकर स्थिर हो जाता है जहाँ मांग और पूर्ति की मात्राएँ समान होती हैं।

निष्कर्ष—उपरोक्त वर्णन से यह पुष्ट हो जाता है कि मूल्य-निर्धारण में मांग और पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाजार में एक वस्तु का अत्यधिक होना मूल्य मांग और पूर्ति का असंतुलन प्रभाव डालता है और बाजार-मूल्य इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का ही फल होता है। तीन प्रकार एक वस्तु के बनने के विषय में पहचान की आवश्यकता होती है, उन्ना प्रकार मूल्य-निर्धारण के विषय मांग और पूर्ति की आवश्यकता होती है। इन बातों का प्राप्ति मार्ग में बहुत स्पष्ट कर दिया है। उनके अनुसार मूल्य एक महत्वपूर्ण वस्तु के समान दो किताबों के मध्य लटका होता है। जिसकी एक ओर मांग होती है और दूसरी ओर पूर्ति। यही नहीं, श्री ० मार्शल ने मूल्य-निर्धारण की तुलना खोले के दो पत्तों के पर देने और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। "जिस प्रकार हम इन बातों पर अवगत करने हैं कि खोले के दो पत्तों में से ऊपर का पद बाजार काटता है अथवा नीचे का, वैसे ही मूल्य की उपरोक्ता निर्धारण करती है अथवा



1—"Price rests balanced like the Keystone of an arch—the one side of which is demand and the other supply".

—Marshall.

उत्पादन-व्यय ।^१ जिस प्रकार कागज काटने के बिने दोनों पत्तों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार मूल्य-निर्धारण के लिए माँग और पूर्ति दोनों आवश्यक



है। यह ठीक है कि कंचों के दोनों छत्तों को क्रियाएँ नवा एक-सो गहो होंगी। कभी एक में अधिक काम किया जाता है और कभी दूसरे में। उदाहरणार्थ, एक साधारण व्यक्ति दोनों पत्तों को साथ-साथ चलाता है, जिससे नीचे वाले पत्त को चलाती है और दूसरी नीचे के पत्त का रोज पर जमा कर ऊपर वाले पत्त को चलाती है। यही बात माँग और पूर्ति के भी साथ समझ है। कभी माँग का प्रभाव अधिक होता है और कभी पूर्ति का पर दोनों का होना आवश्यक है।

मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में समय का महत्व (Importance of Time Element in the theory of Value)—रिकाडों तथा अन्य सम-कामीन विद्वानों ने मूल्य-निर्धारण में उत्पादित एवं माँग के ही प्रभाव को स्वीकार किया। उन्होंने समय के महत्व पर विचार नहीं किया। परन्तु सर्वप्रथम मार्शाल ने मूल्य-निर्धारण में समय के महत्व को स्वीकार किया। उनका यह निश्चित मत था और यह सत्य भी है कि जितना अधिक समय होगा उतना ही अधिक मूल्य पर पूर्ति का प्रभाव पड़ेगा। तथा जितना कम समय होगा उतना ही अधिक मूल्य पर माँग का प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने समय की दृष्टि से बाजार को प्रति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा अतिदीर्घकालीन चार भागों में विभाजित करके यह सिद्ध किया कि समय का वस्तु के मूल्य पर विवेक प्रभाव पड़ता है।

मार्शाल का उक्त मत ठीक है। अल्पकाल में पूर्ति की माँग बढ़ाई नहीं जा सकती। अतः माँग के बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि होती है तथा माँग के घटने पर मूल्य गिर जाता है। परन्तु जब माँग इतनी घट जाती है कि उत्पादक को वस्तु के लागत-व्यय में भी कम मूल्य मिल पाता है, तो वह घने अने पूर्ति को घटाकर माँग के अनुरूप कर लेता है तथा जैसे ही उसका उत्पादन-व्यय और बाजार मूल्य समान हो जाता है, वह उत्पादन को पटाना बन्द कर देता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है तथापि जितना अधिक समय होगा उतना ही अधिक प्रभाव मूल्य पर पूर्ति का पड़ता है।

अल्पकालीन बाजार (Short Period Market)—अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जो थोड़े समय अर्थात् एक-दो दिन या अधिक से अधिक

1—'We might as reasonably dispute whether it is the upper or lower blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper as whether value is governed by utility or cost of production'

प्रो० मार्शल के उपर्युक्त कथन की आलोचना—प्रो० मार्शल ने उपर्युक्त कथन के सम्बन्ध में निम्नांकित आलोचनाएँ भी ध्यान देने योग्य हैं :—

(१) असंगत समय-विभाजन—प्रो० मार्शल द्वारा निम्नांकित मूल्यकालीन एवं दीर्घकालीन समय-विभाजन असंगत एवं अन्वयावहारिक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के लिये दीर्घ एवं अल्पकाल भिन्न भिन्न होता है। जो एक वस्तु के लिये दीर्घकाल है, वह दूसरी वस्तु के लिये अल्पकाल हो सकता है। इस सम्बन्ध में स्वयं प्रो० मार्शल ने ही दो बड़े उचित उदाहरण दिये हैं। वे कहते हैं कि मछली की पूँट को माँघ के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होने के लिये एक या दो दिन भी दीर्घकाल है, परन्तु जहाजों की पूँट को माँघ के अनुसार परिवर्तित होने के लिये एक या दो वर्ष भी दीर्घकाल नहीं है। लर्नर (Lerner) ने इसी कारण उक्त विभाजन की आलोचना करते हुये बताया कि यह विभाजन दिन, माह एवं वर्षों की भाँति पूर्ण नहीं है और न जतना स्पष्ट ही है। मूल्यकाल इतना लम्बा न होना चाहिये कि माँघ और पूँट में स्थिर अनुपात स्थापित हो सके। इस घन्टर को इस प्रकार भी प्रकट कर सकते हैं कि जहाँ मूल्य में केवल प्रमुख व्यय है सम्मिलित हो सके, वह अल्पकालीन मूल्य और जहाँ प्रमुख एवं पूरक दोनों व्यय सम्मिलित किये जा सकें, वह दीर्घकालीन मूल्य कहलावेगा।

(२) सीमान्त लागत व्यय की असत्य कल्पना—प्रो० मार्शल का कथन है कि मूल्य एवं दीर्घकाल दोनों ही में सीमान्त-लागत-व्यय सीमान्त मूल्य के बराबर होता है। परन्तु इसमें दोनों कालों में इस प्रकार समानता स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं की।

वास्तव में, सीमान्त लागत व्यय बहुत कुछ अंशों में इस बात पर निर्भर रहता है कि उन्हे अनुत्पन्न में कितना समय लगेगा। अल्पकाल में मूल्य सीमान्त लागत व्यय के बराबर तथा दीर्घकाल में सीमान्त लागत-व्यय एवं सीमान्त लागत-व्यय के दोनों के बराबर हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि अल्पकाल में सीमान्त लागत-व्यय सीमान्त लागत-व्यय में कम होया, तो उनके अन्तर की राशि स्थिर उत्पादन-साधना के स्वामी को मिल आवेगी, परन्तु सीमान्त लागत-व्यय दीर्घकाल में बाजार मूल्य से कम नहीं रह सकता। अतः जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होती है, नये नये उत्पादक उद्योग के प्रति आकृष्ट होने एवं लाभ उठाते हैं जिससे मूल्य गिरता है, लागत-व्यय घटता है। मूल्य और सीमान्त लागत-व्यय बराबर हो जाते हैं, भाँति और पूँट में अनुत्पन्न स्थापित हो जाता है।

बाजार मूल्य (Market Price)—किसी वस्तु का किसी स्थान और समय पर जो मूल्य प्रचलित होता है वह वस्तु का बाजार मूल्य कहलाता है। इसे अल्पकालीन मूल्य (Short Period Price) भी कहते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य में अल्पकाल में प्रचलित मूल्य से ही होता है। यह मूल्य प्रत्येक वस्तु के समय-समय पर परिवर्तन होने वाले मूल्यों को बताता है तथा इसी के आधार पर बाजार में वस्तुओं का लब्ध-विक्रय होता है। यह मूल्य न केवल दिन-प्रतिदिन ही बदलता है, बल्कि एक ही दिन में कई बार बदलने भी देखा गया है। उदाहरणार्थ फल, साग-भाजी, बर्फ, मछलियाँ आदि का मूल्य बहुधा सुबह के समय अधिक, मध्याह्न को मध्यम तथा सायंकाल में अल्प रहता है। इस मूल्य पर दिकाने

पाती वस्तुओं के घटने वृद्धि को समुचित समय नहीं मिल पाता । अतः, मूल्य-निर्धारण में मांग का ही प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है । मूल्य का उत्थारण व्यय से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । कभी मूल्य उत्थादन-व्यय से अपेक्षित हो जाता है और कभी कम ।

दूसरे शब्दों में इस को कहा जा सकता है कि वास्तव में प्रभाव तो माँग और पूर्ति दोनों का ही पड़ता है कि नु अल्पकालीन बाजार में समय इतना कम होता है कि वस्तु की अधिक मांग हो जाने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है, अर्थात् न तो वह बाजार में प्राप्ति की जा सकती है और न उत्पन्न या तैयार हो जा सकता है । इसी प्रकार मूल्य कम हो जाने पर वस्तु की पूर्ति सुगमता से कम भी नहीं की जा सकती है । यहाँ पर यह है कि बाजार मूल्य निर्धारित करने में पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव होता है अर्थात् अल्पकाल में मांग का प्रभाव अधिक होता है और पूर्ति का केवल निमित्त । अल्पकालीन बाजार में मूल्य बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि केवल स्टाक के बराबर तक ही हो सकती है । परन्तु यदि वस्तु का मांग और भी अधिक बढ़ जाय तब पूर्ति में वृद्धि नहीं हो सकती के कारण उसका मूल्य बढ़ जायेगा । माँग कम हो जाने पर वस्तु का मूल्य कम हो जायेगा ।

बाजार या अल्पकालीन मूल्य की विशेषताएँ (Characteristics)—
बाजार मूल्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) बाजार मूल्य परिवर्तनशील है अर्थात् घटता-बढ़ता रहता है—
घटना बढ़ना अथवा परिवर्तनशीलता बाजार मूल्य की मुख्य विशेषता है । इस प्रकार के परिवर्तन प्रतिदिन भी हो सकत है और एक दिन में कई बार भी हो सकते हैं ।

(२) बाजार या अल्पकालीन मूल्य का सीमान्त लागत-व्यय से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है—पूर्ति के सीमांत लागत व्यय का मूल्य से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । अल्पकालीन बाजार में मूल्य लागत व्यय से अव्यभिचार हो सकता है, क्योंकि यह तो केवल माँग की संतुल्यता पर निर्भर होता है ।

(३) बाजार मूल्य, माँग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन से निर्धारित होता है—साधारणतया मूल्य माँग और पूर्ति के संतुलन द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु एक अल्पकालीन बाजार में यह संतुलन क्षणिक होता है अर्थात् बदलता रहता है । अतः हम कह सकते हैं कि बाजार मूल्य माँग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन का परिमाण है ।

(४) बाजार या अल्पकालीन मूल्य पूर्ति की अपेक्षा मांग से अधिक प्रभावित होता है—अल्पकालीन बाजार में मूल्य के घटने वृद्धि में माँग के अल्पकालीन समय नहीं लगता किन्तु पूर्ति को घटाने वृद्धि के लिये पूर्णतः समय की आवश्यकता होती है । अतः, अल्पकाल में पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती और मूल्य मुख्यतः मांग के प्रभाव से ही निर्धारित होता है ।

(५) बाजार मूल्य अस्थायी कारणों और चर्चित घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है । उदाहरण के लिये, किसी दिन दूध की मांग कम हो जाने के कारण बढ़ जाती है तो दूध का मूल्य भी बढ़ जायगा । इसी प्रकार यदि कहीं पानी कम हो जाय, तो उस क्षण में दूध की पूर्ति अस्थायी रूप से बढ़ जायगी जिससे कारण मूल्य फिर जायगा ।

(६) यथेष्ट समय मिलने पर बाजार मूल्य की प्रवृत्ति दीर्घकालीन मूल्य अथवा सामान्य मूल्य (Normal Price) के बराबर रहने की होती है—यद्यपि किसी समय में बाजार-मूल्य लाखों या बड़े-बड़े अर्थिक या कम हो सकता है तथापि यथेष्ट समय मिलने पर इसकी प्रवृत्ति सामान्य अथवा सामान्य मूल्य के बराबर रहने की होती है। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु के बाजार-मूल्य में अचानक वृद्धि होती है तो आर्थिक कारणा की प्रक्रिया में मूल्य में ह्रास होने लगता है। यदि बाजार-मूल्य में अर्थिक घटी होती है तो आर्थिक कारणा की प्रक्रिया में मूल्य की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार प्रत्येक समय बाजार-मूल्य की यह प्रवृत्ति रहती है कि एक स्थिर मूल्य अथवा सामान्य मूल्य के पास हो रहे।

बाजार या अल्पकालीन मूल्य कैसे निर्धारित होता है

किसी वस्तु का बाजार-मूल्य माग और पूर्ति के परस्परिक प्रभाव से निर्धारित होता है। माग और पूर्ति का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इनमें परस्परिक सम्बन्ध का प्रभाव से निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाय, तो माग घट जाती है और पूर्ति बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप इन दोनों में एक नया संतुलन उत्पन्न होता है। यदि माग बढ़ जाय, तो मूल्य भी बढ़ जाता है और पूर्ति भी बढ़ जाती है तथा एक और नया संतुलन पैदा हो जाता है। इसके विपरीत, यदि पूर्ति बढ़ जाय तो मूल्य घट जाता है और माग बढ़ जाती है, और इस प्रकार एक विभिन्न संतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार माग और पूर्ति का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसी के फलस्वरूप अस्थायी संतुलन उत्पन्न होता रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार-मूल्य माग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन (Temporary Equilibrium) द्वारा निर्धारित होता है। इस बाजार-मूल्य को प्रो० मासाल के अस्थायी संतुलन मूल्य (Temporary Equilibrium Price) कहकर पुकारा है।

यद्यपि माग और पूर्ति दोनों मिलकर मूल्य निर्धारित करते हैं परन्तु मूल्य के साथ मूल्य का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक या कम होता हो सकता है। अतः अल्पकालीन या बाजार-मूल्य के निर्धारण के लिए माग और पूर्ति का होना आवश्यक होते हुए भी माग का अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि समय-समय पर होता है कि माग के अनुसार उत्पादन में वृद्धि सहज नहीं की जा सकती। इसीलिए माग के घटने-बढ़ने के अनुसार ही मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। बाजार-मूल्य निर्धारण का विषय विवरण इसी अध्याय में पीछे देखिये।

सामान्य मूल्य (Normal Price) - दीर्घ काल में प्रचलित होने वाले मूल्य को सामान्य मूल्य कहते हैं अर्थात् माग के अनुसार पूर्ति के सम्बन्ध के नियम अर्थात् समय मिल जाने के पश्चात् जो मूल्य प्रचलित होगा वह सामान्य मूल्य कहलायेगा। सामान्य मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य (Long Period Price) भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ति का माग के अनुसार सम्बन्ध (Adjustment) करने में लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। उदाहरणार्थ, यदि माग बढ़ गई है तो उद्योग में उत्पादन-साधना में वृद्धि कर दी जायगी, और यदि माग स्थायी रूप से कम हो गई है तो

उत्पादन-साधनों को हटा लिया जायगा। यद्यपि मूल्य-निर्धारण में माँग और पूर्ति दोनों का पारस्परिक प्रभाव आवश्यक है, परन्तु फिर भी जिस प्रकार अल्पकाल में माँग अधिक क्रियाशील देखी जाती है, उसी प्रकार दीर्घकाल में माँग की अपेक्षा पूर्ति प्रभावित उत्पादन-व्यय (साग्न) का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुये यों कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन-व्यय के बराबर होता है और यही 'सामान्य-मूल्य' कहलाता है। मोरलैंड के शब्दों में, दीर्घकालीन मूल्य वह मूल्य है जो साग्न के बराबर होता है।¹ यदि सामान्य-मूल्य साग्न में अधिक होगा तो पूर्ति बड़ जायगी और यदि वह कम होगा तो पूर्ति घट जावेगी। इस प्रकार सामान्य मूल्य साग्न-व्यय द्वारा निर्धारित केन्द्र पर अभिमुख रूप से स्थिर रहेगा अर्थात् सामान्य मूल्य राईब दीर्घकाल में साग्न-व्यय के बराबर रहता है।

समय की कितनी अवधि दीर्घकाल या अल्पकाल कहलायेगी, यह उद्योग के स्वभाव तथा उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। कुछ उद्योगों के लिये एक या दो वर्ष ही दीर्घकाल हो सकते हैं, परन्तु अन्य के लिये यही अवधि अल्पकाल हो सकती है।

बाजार या अल्पकालीन मूल्य अस्थायी तथः परिवर्तनशील परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। दीर्घकाल में अस्थायी परिस्थितियाँ विलीन हो जाती हैं और मूल्य स्थायी कारणों से प्रभावित होता है। प्रो० मार्शल ने बताया है कि जब एक प्रकार की प्राथमिक परिस्थितियाँ पर्याप्त समय तक रहती हैं तो उन्हें अपना पूरा प्रभाव दिखाने का अवसर मिल जाता है और अस्थायी और परिवर्तनशील कारणों का प्रभाव विलीन हो जाता है। अतः, ऐसी परिस्थितियों में वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित होता है वह 'सामान्य मूल्य' कहलाता है। दीर्घकाल में उत्पादकों को माँग के अनुसार पूर्ति में घटाने-बढ़ाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। पूर्ति में परिवर्तन होने में मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है और अतः में ऐसा मूल्य निर्धारित होता है जिस पर माँग और पूर्ति का समुत्तम हो जाता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य माँग और पूर्ति में स्थायी सन्तुलन (Permanent Equilibrium) में निर्धारित होता है। प्रो० सीगर² ने बाजार और सामान्य मूल्यों का इस प्रकार विवेचन किया है—
“बाजार मूल्य अर्थात् वह मूल्य जिस पर बिना वास्तव में विक्रय है, परिवर्तनशील

1—“Long-Period Price may be defined as “the price which corresponds with the cost of production.”

Moreland *An Introduction to Economics*, pp 203-9

2—“Market prices, that is, the prices at which goods are actually sold from day to day, are variable and irregular in their operations. But behind most market prices are normal Prices, which are much less subject to changes. This is because the conditions of production are more stable than the market conditions under which goods are bought and sold and serve constantly to recall prices from the more or less violent fluctuations of the market.”

Seager - *Principles of Economics* p 120

और प्रतियार हाता है। ... किन्तु अधिकांश बाजारों के पीछे सामान्य मूल्य होने हैं जिनमें परिवर्तन बहुत कम होने है। इसका कारण यह है—उत्पत्ति की दशा में उन बाजार-दशाओं में जिनमें मांग का अत्यधिक होना है, अधिक होना है, और वे प्रवृत्ति से भटके बढ़ने वाले बाजार मूल्यों को अपने पास पुन बुलाती हैं।

मार्ग में, बाजार और सामान्य मूल्य दोनों पर ही मांग और पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। पहली दशा में मांग क्रियाशील होती है और दूसरी दशा में पूर्ति (उत्पादन-व्यय) क्रियाशील होती है (Briggs & Jordan) के शब्दों में "मांग की तुलना में पूर्ति की घटा बड़ी का मूल्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, मूल्य का प्रभाव पूर्ति की परिस्थितियों पर एवं उसके द्वारा निर्णय-मूल्य में सामान्य व्यय पर पड़ता है।" बाजार-मूल्य पर पूर्ति का वेबसाइट इतना ही प्रभाव पड़ता है कि मांग के घटने-बढ़ने से सामान्य मूल्य अपने स्थिर अनुमान-बैन्ड में बंधी-कब्दी प्रभावित के लिये इधर उधर हट जाता है।

सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) सामान्य मूल्य में स्थिरता रहती है—दीर्घकाल में एक बार मांग और पूर्ति में अनुमान स्थापित हो जाने पर वह शायद विचलित नहीं होता। प्रत्येक प्रकार एक तापमान में छोटी-छोटी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य में भी छोटी-छोटी परिवर्तन होता है।

(२) सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य स्थायी कारणों एवं घटनाओं से प्रभावित होता है—दीर्घकाल का सामान्य मूल्य स्थायी कारणों से प्रभावित होता है, क्योंकि पूर्ति का पूर्ण अनुमान के साथ घटने बढ़ने का प्रवृत्ति रहता है। इसके लिये नये नये कारणों भी मौलिक जा सकते हैं तथा अधिन-कुशल कार्यकर्ताओं की जाने का भी प्रवृत्ति रहता है।

(३) सामान्य मूल्य, मांग की अपेक्षा पूर्ति से अधिक प्रभावित होता है—दीर्घकाल में मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है अर्थात् पूर्ति की स्वतन्त्रता पूर्ण मूल्य स्थिर करने के लिये समुचित समय मिल जाता है।

(४) सामान्य मूल्य, मांग और पूर्ति के स्थायी अनुमान से निर्धारित होता है—दीर्घकाल में पूर्ति में मांग के अनुसार समन्वय होने का पर्याप्त अवसर मिल जाने के कारण मांग और पूर्ति में स्थायी अनुमान स्थापित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य, मांग और पूर्ति के स्थायी अनुमान से निर्धारित होता है।

(५) सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य लागत व्यय के बराबर होता है—दीर्घकाल में मांग और पूर्ति में स्थायी अनुमान स्थापित हो जाता है। स्थायी अनुमान की अवस्था में मूल्य उत्पादन-व्यय (लागत) के बराबर होता है। यदि मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक होता है, तो उत्पादकों की अधिक लाभ होगा, पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य गिरावा और उस समय तक गिरता रहेगा जब तक मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर न हो जाए। इसके विपरीत, यदि मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है, तो उत्पादकों को हानि होती है और उत्पत्ति की मात्रा में कमी होती है और मूल्य में उस समय तक वृद्धि होती है जब तक वह लागत-व्यय के बराबर न हो जाए। इस प्रकार दीर्घकाल में सामान्य मूल्य लागत व्यय के बराबर होता है।

(६) सामान्य मूल्य दीर्घकाल में ही सम्भव है—मांग और पूर्ति के मतुलन के लिये पूर्ण प्रतिस्पर्धा की सुविधा तथा उनके घटने-बढ़ने के लिये प्रशेष समय की आवश्यकता । अर्थात् यह दीर्घकाल में ही सम्भव हो सकता है ।

(७) सामान्य मूल्य केन्द्र है जिसमें चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है—सामान्य मूल्य वह केन्द्र है जिसमें चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है । बाजार की मांग और पूर्ति में हर फेर होने के साथ बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य (जो लागत व्यय के बराबर होता है) के ऊपर उठ जाता है और कभी नीचे गिर जाता है परन्तु उसकी प्रवृत्ति मदा सामान्य मूल्य के बराबर होने की होती है ।

(८) सामान्य मूल्य एक से अधिक प्रकार का हो सकता है—एक ही वस्तु के एक से अधिक सामान्य मूल्य हो सकते हैं, जैसे अल्पकालीन सामान्य मूल्य और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य ।

सामान्य मूल्य या दीर्घकालीन मूल्य का निर्धारण

(Determination of Normal or long Period Price)

अल्पकालीन या बाजार मूल्य की मांग दीर्घकालीन प्रथमा सामान्य मूल्य भी मांग और पूर्ति की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही निर्धारित होता है । जिस प्रकार अल्पकाल में बाजार-मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति की दो शक्तियाँ का पारस्परिक प्रभाव साक्ष्यक होने हुए भी मांग का अधिक प्रबल प्रभाव देखा जाता है ठीक इसी प्रकार दीर्घकाल में भी सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति की पारस्परिक क्रियाओं के साक्ष्यक होने हुए भी पूर्ति के प्रभाव की अधिक प्रबलता देखी जाती है । इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में निम्नो वस्तु का सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की दो शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु फिर भी पूर्ति अर्थात् उत्पादन-व्यय (लागत) का प्रभाव निर्णयात्मक होता है । यदि सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय (लागत) से अधिक होगा, तो लाभ प्राप्ति में प्रेरित होकर नये उत्पादक उद्योग की ओर सर्वाधिक हाथों और पुंगने उत्पादक अपने विद्यमान साधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पत्ति में वृद्धि करने की चेष्टा करेंगे । इससे परिणामस्वरूप पूर्ति बढ़ जायगी और मूल्य गिर जायगा । इसके विपरीत यदि सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय (लागत) से कम हुआ तो हानि में बचने के लिये कुछ उत्पादक अपना उत्पादन-कार्य स्थगित कर देग और शेष उत्पादक कम मात्रा में उत्पादन करेंगे जिससे पारस्परिक पूर्ति में कमी हो जायगी और मूल्य बढ़ जायगा । इस प्रकार दीर्घकाल में किसी वस्तु के सामान्य मूल्य की प्रवृत्ति अपने उत्पादन-व्यय (लागत) के बराबर रहने की होती है । अतः यह स्पष्ट है कि दीर्घकाल में सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति अथवा उत्पादन व्यय (लागत) मांग की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखती है ।

अल्पकालीन सामान्य मूल्य और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य

(Short-Period Normal Price & Long Period Normal Price)

सामान्य मूल्य का विवरण करने हुए मिल्मनर तथा अन्य आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों ने सामान्य मूल्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया है—अल्पकालीन

सामान्य मूल्य और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य । अब यह देखना है कि किस प्रकार सामान्य मूल्य अल्पकाल तथा दीर्घकाल में निर्धारित होता है ।

अल्पकाल में सामान्य मूल्य (Normal Price in Short Period)—अल्पकाल में माँग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन तो हो सकता है, परन्तु उद्योग में तय हुई फर्मों की संख्या तथा कारखाने का आकार-प्रकार पूर्ववत् ही रहता है क्योंकि यह परिवर्तन स्थायी रूप में अधिक समय तक स्थिर रहने वाला नहीं होता है । अल्पकाल में जब माँग में वृद्धि होती है तो उत्पादक-गण अपने उत्पात्ति के वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पात्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि माँग में वृद्धि होने के कारण मूल्य में वृद्धि होगी जिससे फलस्वरूप प्रत्येक उत्पादक लाभ-प्राप्ति में प्रेरित होकर अपने उत्पात्ति के मौजूदा साधनों पर उस सीमा तक उपयोग करेगा जहाँ तक कि उनकी अधिकतम उत्पादन सामर्थ्य है । ऐसा करने में अधिक लाभ होगा क्योंकि प्रतिशतगता के कारण सभी उत्पादकों की उत्पात्ति एक ही मूल्य पर विकेयी । अस्तु प्रत्येक उत्पादक उत्पादन वृद्धि के लिये उस सीमा तक प्रयत्नशील रहता है जब तक मूल्य सीमान्त उत्पादन-व्यय (Marginal Cost of Production) के बराबर नहीं हो जाता । जब तक उसे अपने सीमान्त उत्पादन-व्यय से अधिक मूल्य प्राप्त होता रहेगा, तब तक वह उस वस्तु का अधिक उत्पादन करता रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिकतम लाभ होता रहेगा । परन्तु मूल्य के सीमान्त उत्पादन व्यय से कम होने ही हानि में बचने के लिये उत्पादन कम कर दिया जाएगा । इस प्रकार अल्पकाल में वर्तमान साधनों के अधिकधिक उपयोग द्वारा पूर्ति का माँग की वृद्धि के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है । अस्तु, अल्पकाल में वह मूल्य जो सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होता है अल्पकालीन सामान्य मूल्य कहलाता है ।

दीर्घकाल में सामान्य मूल्य (Normal Price in Long period)—दीर्घकाल में पूर्ति का माँग के साथ स्थायी रूप में समन्वय स्थापित होने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है । अतः कई नये साहसी अथवा उद्योगपति उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, मौजूदा उत्पादक अपने कारखानों का विस्तार कर सकते हैं, नई मशीनों की प्रयोग में ला सकते हैं तथा अधिक कुशल अधिक काम पर लगाये जा सकते हैं । शोध में, माँग की वृद्धि के साथ उत्पात्ति के साधनों में वृद्धि की जा सकती है । इसी प्रकार माँग बढ़ होने पर सीमान्त उत्पादक (Marginal Producers) उत्पादन क्षेत्र से हट जाते हैं जिससे पूर्ति का घटती हुई माँग में समन्वय हो सकता है । इस प्रकार पूर्ति को माँग में पूर्णतया समन्वित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाता है और माँग तथा पूर्ति में स्थायी अनुनत स्थापित हो जाता है । माँग और पूर्ति में स्थायी अनुनत की आवश्यकता में मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर होता है । यदि मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक होता है, तो उत्पादकों को अधिक लाभ होगा जिससे नये उत्पादक उद्योग की ओर आकर्षित हो जायेंगे और पुराने उत्पादक अपने वर्तमान उत्पात्ति के साधनों या अधिकतम सीमा तक उपयोग कर उत्पात्ति को बढ़ाने में सफल हो पायेंगे । इसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि होगी और मूल्य घिरेगा और उस समय तक निरन्तर रहेगा जब तक मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जाय । इसके विपरीत यदि मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है, तो उत्पादकों को हानि होगी जिससे कारण कई उत्पादक अपनी उत्पादन कार्य स्थापित कर देंगे । इसका परिणाम यह होगा कि पूर्ति को माना में बढ़ी हो जायगी और मूल्य बढ़ जाएगा और यह उस समय तक घटता रहेगा जब तक वह उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जाय । स्थायी रूप में सामान्य मूल्य

नागन प्रभार्य उत्पादन व्यय से अधिक ऊँचा या नीचा नहीं रह सकता। सामान्य मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर होने को नेष्टा करता है। इस प्रकार दीर्घकालीन में स्थायी सतुलन की अवस्था में उत्पादन-व्यय से निर्धारित मूल्य दीर्घकालीन सामान्य मूल्य कहलाता है।

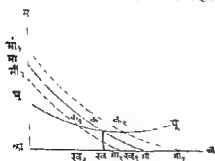
उत्पत्ति के नियम और सामान्य मूल्य (Laws of Returns and Normal Price) — सामान्य मूल्य के निर्धारण में सागत-उत्पादन व्यय का निर्णायक प्रभाव पड़ता है और उत्पादन-व्यय में उत्पत्ति के नियमों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अतः सामान्य मूल्य का उत्पत्ति के नियमों में प्रभावित होना स्वाभाविक है। अस्तु, अब हम इस बात का विवेचन करेंगे कि किन प्रकार सामान्य मूल्य पर उत्पत्ति के विविध नियमों का प्रभाव पड़ता है।

(१) उत्पत्ति ह्रास नियम और सामान्य मूल्य (Law of Diminishing Returns & Normal Price)—यदि किसी वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति-ह्रास-नियम' (Law of Diminishing Returns) अथवा तात्पर्य वृद्धि नियम (Law of Increasing Cost) के अनुसार होता है, तो माँग के बढ़ने पर लागत अर्थात् उत्पादन व्यय यह जायगा और माँग के घटने पर उत्पादन-व्यय कम हो जायगा, और परिणामतः सामान्य मूल्य में भी इस प्रकार परिवर्तन हो जायगा। उदाहरण के लिये, मान लीजिये कि कोयला उद्योग पर उत्पत्ति-ह्रास-नियम लागू है। जब कोयले की माँग बढ़ती है, तो इसका मूल्य भी बढ़ जायगा। इस वृद्धि में लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्पादकगण पूर्ति में विस्तार करते जिसके परिणाम-स्वरूप उत्पत्ति में वृद्धि होगी। किन्तु उद्योग पर 'उत्पत्ति ह्रास-नियम' लागू होने के कारण जितना अधिक कोयले का उत्पादन होगा, उतना ही ऊँचा उसका उत्पादन-व्यय होगा। इस प्रकार कोयले की प्रतिरिक्त उत्पत्ति अथवा श्रद्धावृद्धि अधिक लागत पर होगी। इसका तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल में मूल्य ऊँचा हो जायगा अर्थात् सामान्य मूल्य में वृद्धि हो जायगी। कृषि उद्योग तथा खनिज और मछली निर्यात करने वाले उद्योगों में भी इसी प्रकार होता है। अब हम इस रेखा-चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रस्तुत चित्र में माँ

सेगो । यह पू पू' वक्ररेखा को क_२ बिन्दु पर कटती है । अतः मूल्य घटकर क_१ ख_२ हो जाता है ।

इस चित्र में हम देखने हैं कि पूति को वक्र-रेखा ऊँची होनी जानी है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन 'उत्पत्ति-ह्रास नियम' अथवा 'लागत वृद्धि-नियम' के अनुसार होता है, उनकी पूति को माना में वृद्धि करने से वस्तु की इकाइयाँ क्रमशः बढ़ते हुए लागत-व्यय पर प्राप्त होती हैं । इस प्रकार यह साद है कि उन उद्योगों में जिनमें उत्पत्ति-ह्रास-नियम अथवा लागत-वृद्धि-नियम लागू होता है, दीर्घकाल में माँग में वृद्धि होने पर सामान्य मूल्य बढ़ता है और माँग में कमी होने पर यह घटता है ।

उत्पत्ति-वृद्धि-नियम और सामान्य मूल्य (Law of Increasing Returns & Normal Price)—यदि किसी वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति वृद्धि-नियम' (Law of Increasing Returns) अथवा 'लागत-ह्रास-नियम' (Law of Decreasing Cost) के अनुसार होता है, तो माँग के बढ़ने पर लागत अर्थात् उत्पादन-व्यय कम हो जायेगा और माँग के बढ़ने पर उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा और परिणामतः सामान्य मूल्य में भी इसी प्रकार परिवर्तन हो जायगा । इसका कारण स्पष्ट है कि उद्योगों में उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अनुसार उत्पादन होता है, उन्में उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने में विविध प्रकार की बचत (Economies) सम्भव हो जाती हैं जिनके कारण उत्पादन-व्यय बराबर घटता जाता है अर्थात् उत्पत्ति की बढ़ती हुई इकाइयाँ कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं । यह बात कपड़ा उद्योग के उदाहरण से भी प्रबलर समझी जा सकती है । मान लीजिये कि लोगों के जीवन-स्तर या जन-सङ्ख्या में वृद्धि होने के कारण कपड़े की माँग बढ़ जाती है । माँग में वृद्धि होने के कारण मूल्य में वृद्धि हो जायगी, जिसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन बढ़ी मात्रा में होने लगेगा । यदि उद्योग में उत्पत्ति-



उत्पत्ति-वृद्धि-नियम और सामान्य मूल्य
(Law of Increasing
Returns & Normal Price)

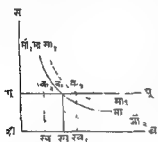
वृद्धि नियम लागू है, तो जितना अधिक उत्पादन होगा, उतनी ही लागत कम होगी । माटर कार, माइकिन, रेडियो, कागज आदि निर्माण उद्योगों में जिनमें मशीन द्वारा उत्पादन होता है, इसी प्रकार होता है । इसे रेखा-चित्र द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :-

प्रस्तुत रेखा-चित्र में माँ

माँ माँग की वक्र रेखा और पू पू' पूति की वक्ररेखा है वे दोनो रेखाएँ क बिन्दु पर

मिलती है। इस काल स्थूल मुख्य है, अर्थात् दही सामान्य मुख्य है। अब यदि किसी कारणवश में वृद्धि हो जाय, तो माँग माँ माँ, का स्वर धारण कर लेगी। यह वक्ररेखा पू पू की क_२ बिन्दु पर काटती है अतः क_२ ख_२ सामान्य मुख्य होगा। इस प्रकार माँग में वृद्धि हो जाने से मुख्य घट जाता है। इसी प्रकार यदि माँग में कमी हो जाय, तो माँ, माँ, का स्वर धारण कर लेगी। यह पू पू वक्ररेखा से क_२ बिन्दु पर मिलती है। अतः क_२ ख_२ सामान्य मुख्य है। इस प्रकार माँग के कम हो जाने से मुख्य बढ़ जाता है।

(३) उत्पत्ति-स्थिर नियम और सामान्य मूल्य (Law of Constant Returns & Normal Price)—यदि किसी वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति-स्थिर नियम' (Law of Constant Returns) अथवा 'लागत-स्थिर-नियम' (Law of Constant Cost) के अनुसार होता है, तो माँग के घटने बढ़ने का लागत अर्थात् उत्पादन-व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् वह स्थिर रहेगा जिसके परिणाम-स्वरूप सामान्य मूल्य भी स्थिर रहेगा। इस प्रकार की अवस्था तभी उत्पन्न होती है जब कि उत्पत्ति-वृद्धि नियम और उत्पत्ति-ह्रास नियम समान रूप से अनुमित हो जाते हैं। यह अवस्था एक सम्बन्ध समय तक स्थिर नहीं रहती।



उत्पत्ति-स्थिर नियम और सामान्य मूल्य

(Law of Constant Returns
& Normal Price)

अब यदि माँग बढ़ जाती है, तो माँग की वक्र रेखा माँ माँ, पूर्ण की वक्र रेखा पू पू की क_२ बिन्दु पर काटती है, अतः क_२ ख_२ सामान्य मुख्य होगा। परन्तु क_२ ख_२ और क_२ ख_२ बराबर है, अतः माँग के बढ़ने पर भी उत्पादन-व्यय स्थिर रहेगा। इसी प्रकार माँ माँ, वक्ररेखा माँ माँ के घटने का प्रदर्शन करती है। यह पूर्ण की वक्र रेखा पू पू की क_२ बिन्दु पर काटती है, अतः क_२ ख_२ सामान्य मुख्य होगा। परन्तु क_२ ख_२ और क_२ ख_२ सामान्य है, अतः माँग के घटने पर भी सामान्य अर्थात् उत्पादन-व्यय स्थिर रहेगा।

उत्पत्ति-वृद्धि-नियम की अवस्था में मुख्य निर्धारण में कठिनाई—अभी हमने देखा कि किन प्रकार दीर्घकाल में सामान्य मूल्य उत्पादन-व्यय (लागत) के बराबर रहता है। परन्तु उत्पादन क्षेत्र में बहुत-सी समस्याएँ होती हैं—उनमें से

इस नीचे दिये हुए चित्र से हम प्रकार समझेंगे। प्रस्तुत चित्र में माँ माँ माँग की वक्र रेखा है पू पू की पूर्ण वक्र रेखा है। पूर्ण की वक्र रेखा (पू पू) अ व रेखा के समानान्तर (Parallel) है। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्ण की मात्रा चाहे कुछ भी हो, उसको लागत अर्थात् उत्पादन-व्यय वही रहेगा। माँ माँ माँग की वक्र रेखा पू पू की वक्र रेखा की क बिन्दु पर काटती है। अतः क_२ ख_२ सामान्य मुख्य है अर्थात् यहाँ सामान्य मुख्य है।

कुछ तो बहुत घबड़ी होती है, कुछ औसत दर्जे की और कुछ नीचे दर्जे की । अब यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि बाजार में मूल्य कौन सी फर्म द्वारा निर्धारित होता है । यदि कहा जाय कि मूल्य सर्वश्रेष्ठ फर्म की लागत द्वारा निर्धारित होता है तो यह यथार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसकी लागत अर्थात् उत्पादन व्यय सबसे कम होगा है, और यदि मूल्य इससे बराबर हो, तो कम कुशल फर्मों को उत्पादन बंद में हटना पड़ेगा जिसके कारण श्रेष्ठ फर्म बाजार में एकाधिकार (Monopoly) स्थापित कर लेगी । एकाधिकार स्थापित होने की अवस्था में मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में भी भिन्नता हो जाती है । अतः प्रतियोगिता (Competition) की अवस्था में यह तर्क यथार्थ सिद्ध नहीं होती । पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मूल्य सर्वश्रेष्ठ फर्म के उत्पादन व्यय में अधिक होता चाहिये । अतः यह सबसे अधिक कुशल अथवा सबसे अधिक लागत वाली फर्म का उत्पादन व्यय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्भव है वह बिल्कुल ही लाभ नहीं कमा रही हो । परन्तु दीर्घकालीन मूल्य में सामान्य लाभ का अवश्य समावेश होता चाहिये । अतः यह कहना कि मूल्य अधिकुशल फर्म के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है, उचित नहीं, क्योंकि सीमान्त उत्पादन व्यय (Marginal Cost of Production), जो दीर्घकाल में मूल्य के बराबर रहता है सबसे अधिकुशल फर्म का उत्पादन-व्यय नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह कहना भी कि मूल्य समस्त फर्मों के औसत लागत के बराबर होता है यथार्थ नहीं है, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में कार्य-संलग्न अनेक फर्मों की औसत लागत ज्ञात करना सम्भव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त अन्तिम इकाई के उत्पादन व्यय को सीमान्त उत्पादन व्यय कहा जा सकता है, परन्तु अन्य इस उत्पादन व्यय के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति-वृद्धि-नियम की अवस्था में अन्तिम इकाई का उत्पादन व्यय घटपड़ता होता है । अन्य इकाइयों को तैयार करने में अधिक उत्पादन-आग होता है । अतः, यदि मूल्य दीर्घकाल में अल्पतम लागत के बराबर हो तो अन्य इकाइयों की हानि में बेचना होगा परन्तु दीर्घकाल में ऐसा नहीं हो सकता । वास्तव में, विभिन्न फर्मों के उत्पादन-व्यय में बड़ी भिन्नता पाई जाती है । फर्मों का व्यक्तिगत इतिहास उद्योग का इतिहास नहीं माना जा सकता । अतः, एक उद्योग का सीमान्त उत्पादन व्यय जो कि कुल उत्पादन से सम्बन्धित हो, ज्ञात करने के लिये हम मार्शल द्वारा आविष्कृत 'प्रतिनिधि फर्म' की ओर दृष्टिपात करना होगा । दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में प्रतिनिधि फर्म के उत्पादन-व्यय द्वारा ही मूल्य-निर्धारित होता है ।

मार्शल की प्रतिनिधि फर्म (Representative Firm)—प्रो० मार्शल ने उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अन्तर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण की कठिनाई को दूर करने के लिये 'प्रतिनिधि फर्म' की विचार धारा को जन्म दिया । उत्पत्ति-वृद्धि नियम की दशा में किसी एक फर्म को लेकर उत्पादन की सीमा का ज्ञान किया जा सकता है, परन्तु उत्पत्ति-वृद्धि-नियम की दशा में किसी एक फर्म को लेकर उत्पादन व्यय का ज्ञान करना कठिन है । इस कठिनाई का हल मार्शल के मतानुसार 'प्रतिनिधि फर्म' में सन्निकटित है । यह न तो सबसे श्रेष्ठ और न सबसे निकृष्ट फर्म का उत्पादन-व्यय है और न उत्पत्ति की अन्तिम इकाई का ही उत्पादन व्यय है, बल्कि यह प्रतिनिधि फर्म का उत्पादन व्यय है जो दीर्घकाल में सामान्य मूल्य निर्धारित करता है । प्रत्येक उद्योग में कुछ फर्म उत्पत्ति

की अपरवा म होती हैं जो उद्योग की माँग और पूर्ति के समुन्तन की व्यवस्था प्रदर्शित करती हैं। ऐसी फर्म का हो 'प्रतिनिधि' फर्म कहते हैं और इसका उत्पादन व्यवस्था सामान्य मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। प्रो० मार्शल ने इस व्यवस्था प्रकार परिभाषित किया है हमारी प्रतिनिधि फर्म वह है जो पर्याप्त लम्बे समय से उत्पादन-कार्य कर रही हो, जिसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हो, जिसका संचालन सामान्य योग्यता से होता हो और जिसकी बाह्य और आन्तरिक वचनोत्तर सामान्य ढङ्ग से हो जोकि उसके कुल उत्पादन के परिमाण को प्राप्त हो, साधारणतया माल के प्रकार, मार्केटिंग (विपणन) दशाद्यो तथा आर्थिक वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है।¹ यह फर्म सारे व्यवसाय की प्रतिनिधि है। यह वर्तमान फर्मों की एक औसत फर्म तो नहीं है, परन्तु एक ऐसी फर्म है जो दीर्घकाल में व्यवसाय का समुन्तन होने पर सारे व्यवसाय या उद्योग के प्रत्येक विभाग का प्रत्येक है और एक प्रकार से समुन्तित व्यवसाय की कुल उत्पत्ति की दीर्घकालीन औसत फर्म है। इनसे हम व्यवसाय या उद्योग में उत्पादन-वृद्धि नियम लागू होने पर आन्तरिक एवं बाह्य बचतें (Economies) प्राप्त होने से योग्य लागत या उत्पादन व्यवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। इस लागत के अनुसार ही दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। मूल्य इसमें प्रविष्ट होने पर समस्त उद्योग की उत्पत्ति बढ़ेगी जिससे प्रत्येक फर्म का आकार एवं उत्पादन बढ जायगा। इस प्रकार प्रत्येक बचतें होने पर वस्तु का उत्पादन व्यवस्था और भी कम हो जायगा। इससे परिमाणान्तरण मूल्य कम होने पर उत्पादन कम और लागत अधिक हो जायगी। इस सम्बन्ध में कैलडर ने भी टीका ही कहा है प्रतिनिधि फर्म वह विद्वेषपण्यमक यन्त्र है जिसकी सहायता से पूर्ति की सकरेखा द्वारा कल्पित प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का यदि विद्वेषण नहीं, तो कम से कम बाह्य अभिव्यक्ति तो अवश्य की जा सकती है।

योग्य की समुन्तन फर्म (Equilibrium Firm)—प्रो० योग्य के प्रतिनिधि फर्म के स्थान में समुन्तन फर्म का प्रयोग किया है। समुन्तन फर्म वह व्यवस्था है जिसमें वह अपनी उत्पादन लागत का प्रयत्न करती है और न घटाने का, वर्तमान मूल्य पर उसकी उत्पत्ति माँग के अनुसार हो और इस उत्पादन पर इसको अधिकतम लाभ है। इस प्रकार व्यवसाय के समुन्तन में कुल उत्पत्ति के घटने या घटने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, इसकी कुल उत्पादन वस्तुओं का माँग

1—'Our representative firm must be one which has had a fairly long life, and fair success, which is managed with normal ability, and which has normal access to the economics, external and internal which belong to the aggregate volume of production, account being taken of the class of goods produced, the conditions of marketing them and the economic environment generally'

के बराबर होती है। व्यवसाय के संतुलन में इसकी भिन्न-भिन्न फर्मों का संतुलन आवश्यक नहीं है किसी की उत्पत्ति बढ़ती है, किसी की घटती है, किन्तु सबका योग मिलाकर उत्पत्ति समान रहती है : परन्तु सम्भवतः एक फर्म ऐसी होती है जिसके व्यवसाय के संतुलन की भाँति निजी संतुलन होता है और यह वस्तुमान मूल्य पर एक निश्चित उत्पत्ति करती रहती है, इसे 'संतुलन फर्म' कहते हैं।

प्रतिनिधि फर्म और संतुलन फर्म में भेद—प्रतिनिधि फर्म और संतुलन फर्म में यही भेद है कि संतुलन फर्म की भाँति प्रतिनिधि फर्म का संतुलन आवश्यक नहीं है। व्यवसाय या उद्योग का संतुलन हो या न हो, परन्तु इसमें प्रतिनिधि फर्म प्रवश्य होगी। व्यवसाय का संतुलन होने पर प्रतिनिधि फर्म संतुलन फर्म हो जायेगी और मूल्य इसकी सीमान्त व औसत लागत के बराबर होगा।

प्राधुनिक ग्रन्थशास्त्रियों की आदर्श फर्म (Optimum Firm)—प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार में मूल्य आदर्श फर्म द्वारा निर्धारित होता है। आदर्श फर्म वह फर्म है जिसने उत्पत्ति के साधनों का इस उत्तम विधि से सामञ्जस्य किया है कि उसकी प्रति इकाई लागत सबसे कम है। पूर्ण प्रतियोगिता के कारण वस्तु का मूल्य घट कर 'आदर्श फर्म' के मूल्य के बराबर होगा। इसमें कम या अधिक होने पर अधिक लाभ या हानि के कारण मूल्य स्थिर न रह सकेगा और अन्त में मूल्य आदर्श फर्म के उत्पादन-व्यय के बराबर ही होगा।

बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में भेद

(Distinction between Market Price & Normal Price)

(१) बाजार मूल्य अल्पकालीन प्रचलित मूल्य है परन्तु सामान्य मूल्य दीर्घकालीन प्रचलित मूल्य है।

(२) बाजार मूल्य किसी समय में माँग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन का परिणाम है। किन्तु सामान्य मूल्य माँग और पूर्ति के दीर्घकालीन अथवा स्थायी संतुलन का परिणाम है।

(३) बाजार मूल्य अधिकतर माँग के कारण और सामान्य मूल्य पूर्ति अर्थात् उत्पादन व्यय के कारण प्रभावित होता है।

(४) बाजार मूल्य अस्थायी कारणों तथा अन्तित घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है, परन्तु सामान्य मूल्य स्थायी अथवा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाले कारणों का परिणाम है।

(५) बाजार-मूल्य में दिन प्रतिदिन यहाँ तक कि घण्टे-घण्टे भर में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु सामान्य मूल्य अधिक स्थिर रहता है। माँग और पूर्ति में अस्थायी परिवर्तन होने के पश्चात् बाजार मूल्य भी प्रवृत्ति सामान्य मूल्य में परिवर्तित होने की होती है, अर्थात् सामान्य मूल्य एक केन्द्र है जिसके आग-प्यास बाजार मूल्य प्रसूता है।

(६) बाजार मूल्य वह मूल्य है जो किसी भी समय वास्तव में प्रचलित होता है तथा इसके अनुसार सौदे होते हैं। परन्तु सामान्य मूल्य एक काल्पनिक धारणा है अर्थात् यह वह मूल्य है जिसके होने की केवल प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है अथवा यदि अवस्थायें सामान्य हों, तो इसका होना सम्भव होगा। अवस्थायें सामान्य होने पर

जब सामान्य मूल्य के प्रचलित होने का समय आता है तो यह प्रचलित मूल्य भर्षात् बाजार मूल्य कहलाने लग जाता है ।

(a) बाजार मूल्य समुद्र जल की भांति है जो सर्वत्र ऊपर नीचे होता रहता है, परन्तु सामान्य मूल्य समुद्र के उम रतर की भांति है जहाँ यदि लहरें न हों, तो पानी स्थिर हो जायगा ।

(c) सब वस्तुओं का बाजार मूल्य हो सकता है, परन्तु सामान्य मूल्य केवल उसी वस्तुओं का हो सकता है जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता हो । यदि वस्तुओं का निर्माण विनष्टता सम्भव नहीं हो, तो सामान्य मूल्य भी नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन व्यय से ही सामान्य मूल्य प्रभावित होता है और जब उत्पादन व्यय ही नहीं तो सामान्य मूल्य का अस्तित्व कैसे हो सकता है ।

किसी वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु के सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है (Market Price of a commodity oscillates round about its Normal Price)

अपवाद

किसी वस्तु का मूल्य स्थायी रूप से उत्पादन-व्यय (लागत) से अधिक ऊपर या नीचे नहीं रह सकता । (The value of a commodity cannot be permanently much above or below its cost of production)

उपपुस्तक कथन का निवेदन करने से पूर्व यहाँ पुनः बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिये । बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है जो किसी समय पर बाजार में प्रचलित होता है तथा उसने अनुसार ही वस्तुओं का बारम्बारिक रूप में क्रय-विक्रय होता है । यह बहुत ही अल्पकालीन बाजार मूल्य होता है, अतः यह स्थायी रूप से बाजार में स्थिर नहीं रह सकता । बाजार मूल्य वास्तव में उम वस्तु की माँग और पूर्ति के पारस्परिक सम्बन्ध का परिणाम होता है । अतः, यह स्पष्ट है कि माँग और पूर्ति में निरन्तर परिवर्तन होने रहने के कारण बाजार मूल्य में भी सर्वत्र परिवर्तन होता रहता है । सामान्य मूल्य वस्तु का वह मूल्य है जो दीर्घकाल में प्रचलित होता है । यह दीर्घकालीन बाजार मूल्य होता है जो लगभग उत्पादन-व्यय (लागत) के बराबर रहता है । यह अधिक स्थिर होता है अर्थात् बाजार-मूल्य की भांति इसमें परिवर्तन नहीं होता ।

अतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण उन वस्तु की माँग और पूर्ति में भी सर्वत्र परिवर्तन होता रहता है । परन्तु बाजार मूल्य में यह परिवर्तन अनिश्चित रूप में नहीं होता अर्थात् बाजार मूल्य अक्षोभित मात्रा में घट या बढ़ नहीं सकता । दूसरे शब्दों में, बाजार मूल्य में निरन्तर घटा-बढ़ी होती रहती है परन्तु इन घटा-बढ़ी की भी एक सीमा होती है । इसका तात्पर्य यह है कि बाजार मूल्य एक सीमा अथवा बिन्दु के चारों ओर ही परिवर्तित होता रहता है और अन्त में पुनः उसी बिन्दु पर आकर टिक जाता है । जिस प्रकार जल के सम-स्तर पर निरन्तर परिवर्तन होता रहता है और अन्त में जब अपने वास्तविक सम-स्तर पर टिक जाता है, ठीक इसी

और पूँति का स्थायी सन्तुलन रहे, इसलिये बाजार मूल्य व सामान्य मूल्य की स्थायी अवस्थाएँ वारंवारिक जीवन में कभी प्राप्त नहीं होती। प्रस्तु सामान्य मूल्य एक प्रादुर्भाव के समान है जिसको प्राप्त करने की बाजार मूल्य की प्रवृत्ति रहती है।

पुन उत्पादन न हो सघने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण
(Determination of Price of Non reproducible Goods)—

अब तक हम पुनरुत्पादनीय (Reproducible) वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का विवेचन करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने यह देखा कि किस प्रकार पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का मूल्य बाजार और पूँति की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। अब हम यहाँ ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का विवेचन करेंगे जिनका पुनरुत्पादन नहीं हो सकता है अर्थात् जिनकी पूँति में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। रफ़ेन (Raphael) के कलापूर्ण चित्र, मिल्टन व शेक्सपियर के स्वहस्ताक्षर (Autographs) आदि दुर्लभ एवं अनोखी वस्तुएँ इसी प्रकार की वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। जहाँ तक मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त का प्रश्न है दोनों दशाओं में—अर्थात् वस्तुओं का पुन उत्पादन हो सकता हो या नहीं—मात्र और पूँति की पारस्परिक क्रिया द्वारा मूल्य निर्धारण का ही सिद्धान्त लागू होगा। परन्तु दूसरी दशा में जबकि वस्तुओं का पुनरुत्पादन सम्भव नहीं हो, पूँति की माग में वृद्धि नहीं की जा सके के कारण उत्पादन व्यय अथवा लागत का प्रश्न ही प्रस्तुत नहीं होता। ऐसी अवस्था में विशेषतः एकाधिकारी (Monopolist) की स्थिति में रह जाता है और एकाधिकार के अधिकतम लाभ के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने लगता है।

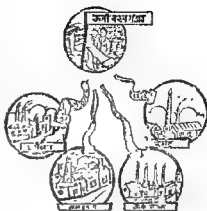
इस प्रकार पुन उत्पादन नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में 'माँग' का प्रभाव अधिक त्रिज्याशील दया जाता है पूँति निर्दिष्ट रहती है। इस अवस्था में पूँति पक्ष में 'पुन मूल्य (Supply Price) बचाव सीमान्त लागत के वस्तु स्वामी के भावुक मूल्य (Sentimental Value) द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात् सीमान्त लागत का रचान वस्तु स्वामी को वस्तु में पृथक् होने की 'सीमान्त अनवस्था' (Marginal Unwillingness) बहस कर लेती है।

प्रतियोगिता और एकाधिकार (Competition and Monopoly)

मूल्य निर्धारण पर इस बात का विशेष प्रभाव पड़ता है कि बाजार में प्रतियोगिता की साम्राज्य है अथवा एकाधिकार का। प्रस्तु यह जानना आवश्यक है कि प्रतियोगिता और एकाधिकार किस कहते हैं और इन दोनों का प्रभाव मूल्य पर किस प्रकार पड़ता है। इसलिये अब हम इसी की विवेचना करेंगे।

प्रतियोगिता (Competition)—प्रतियोगिता का आशय उम परिस्थिति से है जिसमें मनुष्य बिना बाहरी हस्तक्षेप या प्रतिस्पर्ध के उत्पादन, उपभोग, व्यापार आदि सभी आर्थिक क्षेत्रों में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह जिस भी काम या व्यवसाय को लाभप्रद समझे बिना किसी बाहरी बाधा के कर सकता है। आधुनिक युग स्वतन्त्रता का युग है और वर्तमान विचारधारा के अनुसार एक देश भर में समस्त वस्तुओं की आर्थिक समृद्धि के लिये सब प्रकार से पूर्ण स्वतन्त्रता अनिवार्य है। इस पूर्ण स्वतन्त्रता को ही 'प्रतियोगिता' कहते हैं।



प्रतियोगिता के प्रकार—
प्रतियोगिता दो प्रकार की हो सकती है—(१) पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition)

और (२) अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition)। पूर्ण प्रतियोगिता—उस परिस्थिति का नाम है जिसमें उपभोक्ता, उत्पादक, क्रय और विक्रेता प्रादि बड़ी संख्या में, बाजार ज्ञान से परिपूर्ण, स्वतन्त्रतापूर्वक बिना किसी प्रतिस्पर्धा के आर्थिक क्षेत्रों में कार्य-समन्वय हो। इन बातों के प्रधान को अपूर्ण प्रतियोगिता का सूचक समझना चाहिए।

पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ—पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पत्ति के साधनों का समुचित प्रयोग होता है—सर्व प्रथम उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को स्वैच्छानुसार तथा अपनी पसन्द के व्यवसाय या उद्योग में कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। यदि किसी निश्चित प्रकार के श्रम की मजदूरी अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम है, तो श्रमिक इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसायों में जाने लगेगे और इन व्यवसाय में श्रम की मजदूरी बढ जायेगी और यह प्रवृत्ति उस समय तक प्रचलित रहेगी जब तक इन व्यवसाय में श्रम की मजदूरी अन्य व्यवसायों के समान न हो जायेगी।

(२) क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में हों—पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता यह है कि किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में हों अथवा वस्तु के मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा।

(३) क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार सम्बन्धी पूर्ण जानकारी हो—प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि बाजार में प्रसूत वस्तु कहाँ पर और किस भाव में विक्रि रही है।

(४) प्रतियोगिता की दशा में सारे बाजार में मूल्य एक-सा हो रहेगा—प्रतियोगिता की दशा में बाजार में एक ही वस्तु के अनेक भाव नहीं रहेंगे।

सकते। एक वस्तु का एक गणव्य में गारे बानार में एक ही भाव रहना पूर्ण प्रतियोगिता प्रदर्शित होने की एक परीक्षा है।

(५) पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन व्यय और मूल्य बराबर होते हैं—यदि मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक है, तो उत्पादन-गण लाभ प्राप्ति में प्रेरित होकर उस वस्तु का उत्पादन बढ़ावेगा जिससे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी और मूल्य घट कर उत्पादन व्यय के बराबर हो जायेगा। इसी प्रकार यदि मूल्य उत्पादन व्यय में कम है, तो उत्पादन गण वस्तु का उत्पादन कम कर देगा जिसके कारण मूल्य बढ़ेगा और वह जब तक बढ़ेगा जब तक कि उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जायेगा।

प्रतियोगिता से लाभ (Advantages)

(१) प्रतियोगिता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और कार्य-कुशलता के अनुसार अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है—जब एक व्यक्ति अपनी दैनिकी उत्पत्ति के लिये अधिक से अधिक कार्य करने की चेष्टा करता है, तो उसके व्यावसायिक और शैक्षणिक गुणों तथा कार्य-शक्ति का पूर्ण विकास होता रहता है। इस प्रकार न केवल उस व्यक्ति को ही लाभ होता है बल्कि गारे गणव्य तथा देश को भी लाभ पहुँचता है।

(२) प्रतियोगिता द्वारा ही एक देश की मानव शक्ति, श्रम की कुशलता, योग्यता और एक देश के शैक्षणिक साधनों का समुचित प्रयोग सम्भव है—प्रतियोगिता के कारण ही आधुनिक समय में श्रम-विभाजन की इतनी उत्पत्ति हुई है कि दससे अधिक, उत्पादकों, व्यापारियों, जन साधारण तथा समाज एक देश को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं।

(३) प्रतियोगिता नये नये आविष्कारों की जननी है—कार्य-कुशलता योग्यता तथा सतत प्रतियोगिता के कारण दिन-प्रतिदिन नवीन आविष्कार होने रहते हैं जिससे उत्पत्ति की मात्रा में उत्तरोत्तर उत्पत्ति होती रहती है।

(४) प्रतियोगिता उत्पादन को उच्च कोटि का बना देती है—अधिको की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाने के कारण उत्पादन भी बहुत उच्च कोटि का होता है।

(५) प्रतियोगिता उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध कराती है—उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं का मूल्य घट जाता है और उपभोक्ताओं को वस्तुएँ कम मूल्य पर उपलब्ध होने से उनको बहुत लाभ होता है।

(६) बाजार की सीमाओं का विस्तार होता है—उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने से बाजार का क्षेत्र भी बढ़ जाता है और नये बाजारों का विकास होता रहता है।

(७) धन वितरण की असमानता कुछ अथ तक कम हो जाती है—सस्ती वस्तुएँ प्राप्त होने से निर्धन व्यक्तियों को विशेष लाभ होता है तथा इस प्रकार धन-वितरण की असमानता कुछ अथ तक कम हो जाती है।

प्रतियोगिता से हानियाँ (Disadvantages)

(१) उत्पादन अत्यन्त ही अनिश्चित हो जाता है—उत्पत्ति माँग से नहीं बहुत अधिक हो जाती है और कभी बहुत कम। इससे व्यापार को डेरा पहुँचती है।

(२) कठछेदी प्रतियोगिता (Cut-throat Competition) समाज के लिये अहितकर सिद्ध होती है—कठछेदी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी प्रायः ऐसे साधन का प्रयोग करने लगते हैं जिसका फल सारे समाज को भोगना पड़ता है।

(३) टिवाऊ और लागप्रद वस्तुओं के स्थान में दिवावटी और हानिकारक वस्तुएँ तैयार की जाती हैं—प्रतियोगिता के कारण टिवाऊ और लागप्रद वस्तुओं के स्थान में दिवावटी और हानिकारक वस्तुएँ तैयार की जा सकती हैं जिनमें लोग के स्वास्थ्य और चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(४) प्रतियोगिता में खर्चीले विज्ञापनों का प्रयोग वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देता है—प्रतियोगिता में बहुत-सा धन खर्चीले विज्ञापन में व्यय किया जाने से उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जाती है और जिसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ जाता है।

(५) प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं की किस्म विगड़ जाती है—गारम्परि प्रतियोगिता के कारण सस्ती वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है जिससे वारण्य उनकी किस्म का विगड़ना स्वाभाविक है।

(६) प्रतियोगिता से न तो उत्पत्ति ठीक ढङ्ग की ही हो पाती है और न वेवारी की सम्भवा से छुटकारा हो मिलता है।

निष्कर्ष—अस्तु मानव और सामाजिक लाभ की दृष्टि में अत्यधिक प्रतियोगिता पर सरकार द्वारा योजित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धीय है। वर्तमान युग योजनाओं का युग है। इस समय प्रत्येक राज्य देश में आर्थिक प्रगति के लिये योजनाएँ बन रही हैं और उनके अनुसार कार्य हो रहा है। योजना में प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं होता है। अतः प्रतियोगिता द्वारा होने वाली हानियों से बचन कर यह माथन प्रावधान अपनाया जा रहा है।

एकाधिकार^१ (Monopoly)

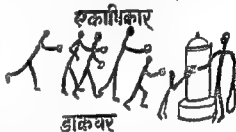
अब तब हमने इस बात का अध्ययन किया है कि किस प्रकार मूल्य इतना प्रतियोगिता (Free Competition) की अवस्था में निर्धारित होता है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मूल्य एकाधिकार की अवस्था में निर्धारित किया जाता है।

एकाधिकार की परिभाषा (Definition)—साधारणतया प्रतियोगिता की अनुपस्थिति को एकाधिकार कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकार में माँग या पूर्ति का बहुत बड़ा भाग होना है जिसके द्वारा मूल्य मुगमना से इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है तो उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। अन्य शब्दों में, एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तुओं अथवा सेवाओं की माँग अथवा पूर्ति पर प्राकृतिक या कृत्रिम नियन्त्रण हो।

१—यह विषय केवल नागपुर, सागर तथा पटना विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ही सम्मिलित है। उ० प्र०, मध्यभारत तथा अजमेर दोड़ों व राजपूताना विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है।

तेजी (Diy) व अनुसार “एकाधिकार किसी व्यापार में सलग्न एक या एक से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक व्यापारिक एकता है जिसके द्वारा, यद्यपि पूर्णतया नहीं तो, विधायन या मूल्यसम्बन्धी अर्थात् नियन्त्रण (Exclusive Control) प्राप्त होता है।”¹ मिल (Mill) के अनुसार पूर्ति का कम करना ही एकाधिकार कहलाता है। व्यावहारिक जीवन में मांस का एकाधिकार होना कठिन होता है। इस कारण एकाधिकार शब्द का प्रयोग प्रायः केवल पूर्ति के एकाधिकार के सम्बन्ध में ही किया जाता है। परन्तु पूर्ति के एकाधिकार के सम्बन्ध में भी यह कठिनाई है कि वह पूर्ण एकाधिकार (Absolute Monopoly) नहीं होता जब तक कि वह सरकारी एकाधिकार न हो, जैसे डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत सेवाएँ आदि। इसका कारण यह है कि समार में एक वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं तथा एक वस्तु की स्वामतापन वस्तुएँ भी होती हैं। इसमें एकाधिकार शब्द का प्रयोग वरुदा अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition) के अर्थ में ही किया जाता है।

व्यापार अथवा व्यवसाय की दृष्टि में सरकार द्वारा स्थापित एकाधिकार का कोई विरोध महत्व नहीं है। महत्व तो उन एकाधिकारों का है जो व्यावसायिक मिलन या संयोजन द्वारा स्थापित होते हैं। यह-वर्षे व्यवसाय प्रतिभोगिता के दुरे परिणामों से बचने तथा व्यावसायिक मिलन की अनेक वस्तुओं से लाभ उठाने के निमित्त परस्पर मिलकर एकाधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की व्यवस्था में इतना जोर पड़ा कि इनके रोकने के निमित्त विभिन्न रूप से कानून बनाये गये।



एकाधिकारी के सामने अधिकाधिक लाभ की दृष्टिकोण — स्वतन्त्र प्रतियोगिता की अवस्था में किसी वस्तु के बहुत से उत्पादक होते हैं, अतः उनमें पारस्परिक प्रतियोगिता होता स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में इच्छानुसार मूल्य लगा सम्भव नहीं होने के कारण उन सभी मूल्य लेना पड़ता है जो दूसरे लेते हैं। इस कारण उत्पादक का बहुत कम लाभ होता है। इससे विपरीत एकाधिकारी का कोई प्रतियोगी नहीं होने के कारण अपनी वस्तु या सेवा का अनमाना मूल्य ल सकता है। उसने सामने केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्ति का ही उद्देश्य रहता है और वह इसी दृष्टिकोण में प्रेरित होकर उत्पादन कार्य करता है।

एकाधिकारों के प्रकार एवं लाभ-हानियाँ — इतना विस्तृत विवरण इस पुस्तक में पाठे दिया जा चुका है।

1—“Monopoly means,” remarks Fly, “that substantial unity of action on the part of one or more persons engaged in some kind of business which gives exclusive control, more particularly, although not solely, with respect to price”

एकाधिकार मूल्य-निर्धारण का सिद्धान्त

(Theory of Determination of Monopoly Price)

परिचय (Introduction)—यह सर्वनिश्चित तथ्य है कि एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकारिक लाभ-प्राप्ति का होना है। यही उद्देश्य उत्पादक का प्रतियोगिता की अवस्था में भी होता है। परन्तु प्रतियोगिता की अवस्था में कोई उत्पादक व्यक्तिगत रूप में मूल्य में परिवर्तन नहीं कर सकता और न मूल्य उत्पादन-व्यय में अधिक ह्रास कर विशेष लाभ उठा सकता है। एकाधिकार की अवस्था में ये सब बात सम्भव हैं। एकाधिकार उत्पादन मात्रा में परिवर्तन कर मूल्य को घटा-उठा सकता है तथा वह उत्पादन-व्यय में अधिक व्यय कर विशेष लाभ उठा सकता है। तब तो एकाधिकारी अधिकारिक लाभ प्राप्ति के लिए अधिक में अधिक मूल्य पर अधिकतम लाभ वेचने का प्रयत्न करेगा। परन्तु यह उसको भविष्य के बाहर है क्योंकि वह विक्री की मात्रा के साथ-साथ मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि वह ये दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पर उसका अधिकार तो अवश्य है पर माँग पर उसका अधिकार नहीं है। किसी मूल्य पर वह जितनी मात्रा बेच सकेगा, यह माँग की स्थिति पर निर्भर है। अतः वह दोनों में से केवल एक ही बात कर सकता है—चाहे तो वह मूल्य निर्धारित करे या पूर्ण की मात्रा का वह वेचना चाहता है।

इसमें यह स्पष्ट है कि एकाधिकारी मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में इतना स्वतन्त्र नहीं है जितना कि साधारणतया वह समझा जाता है। उसे भी माँग और पूर्ण सम्बन्धी बातों का दूर-दूरा ध्यान रखना पड़ता है।

माँग और पूर्ण की शक्तियों का पारस्परिक प्रभाव—एकाधिकार की अवस्था में भी माँग और पूर्ण की शक्तियों का पारस्परिक क्रिया प्रभाव होती है। परन्तु इसमें अन्तर यह है कि पूर्ण के अनुसार स्वतन्त्र माँग होने के विषये स्वतन्त्र नहीं रहती। वह एकाधिकार के नियंत्रण में होती है। पूर्ण नियंत्रित होने के कारण एकाधिकारी या तो मूल्य नियंत्रण कर उस पर जितनी मात्रा माँगी जाय उसी पूर्ण कर सकता है अथवा वह पूर्ण की मात्रा का नियंत्रित कर मूल्य को स्वतन्त्र छोड़ सकता है। ऐसी अवस्था में मूल्य उद्योग द्वारा नियंत्रण की गई पूर्ण तथा बाजार की माँग के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर होता है।

किन्तु ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूल्य भी नियंत्रण कर और साथ ही लोगों का उसी मूल्य पर स्वतन्त्र निश्चित मात्रा का खर्च करना के लिए भी विवश करे। इन दोनों बातों में से वह केवल एक बात ही कर सकता है। एकाधिकारी के समझ केवल एक ही उद्योग रहता है—यह है अधिकतम लाभ-प्राप्ति। अतः, इन तथ्यों की प्राप्ति के हेतु उसे अपनी वस्तु में सम्बन्धित माँग और पूर्ण को अलग-अलग मानना पड़ेगा।

माँग पर—माँग पर के विषय में एकाधिकारी को माँग की मात्रा का विवरण देना पड़ेगा क्योंकि उसे यह देखना पड़ेगा कि वस्तु की माँग तो दार (Elastic) है या बेदाह (Inelastic)। यदि माँग में अधिक लचक है, तो मूल्य कम रखने में उसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि ऐसा करने में माँग बहुत बढ़ जायेगी। यदि माँग बेलाच है तो मूल्य अधिक रख जा सकता है, क्योंकि चाहे तो भी मूल्य बढ़, उपभोक्ता माँग में कम नहीं कर सकते।

पूर्ति पक्ष—माँग की सोच के साथ-साथ पूर्ति सम्बन्धी बातों पर भी उसे ध्यान देना होगा, प्रचलित उत्पत्ति नियमों की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादन व्यय (Cost of Production) के गिरने या बढ़ने की ध्यान में रखना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति-वृद्धि-नियम के अनुसार चल रहा है, तो उत्पत्ति के साथ सीमान्त लागत में कमी होगी। ऐसी दशा में मूल्य कम रहने से विक्री बनेगी और एकाधिकारी को अधिक लाभ होगा। यदि उत्पादन उत्पत्ति-ह्रास नियम के अन्तर्गत होगा, तो जितना अधिक उत्पादन होगा, उतनी ही अधिक लागत होगी। अतः वह उत्पादन छोटे परिमाण में रहेगा। यदि माँग कहीं बेनाम होई, तो ऊँचा मूल्य रहने में उसे अधिक लाभ होगा।

मूल्य निर्धारण—इस प्रकार दोनो पक्षों की इन बातों को ध्यान में रखते हुये एकाधिकारी वह मूल्य नियत करने का प्रयत्न करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। वह यह जानता है कि लाभ दो बातों पर निर्भर है (१) प्रति इकाई मूल्य और (२) विक्री की मात्रा। यदि वह मूल्य अधिक रहता है, तो माँग घट जाने में विक्री कम हो जायगी जिससे फन्क्शन्स कुल लाभ घटिततम न होगा। दूसरी ओर, यदि वह अधिक मात्रा में माल बेचता है किन्तु प्रति इकाई मूल्य बहुत कम है, तो भी कुल लाभ घटिततम न होगा। इनलिये एकाधिकारी को न तो बहुत ऊँचा मूल्य रखने में और न अधिक मात्रा बेचने से अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, बल्कि उसे मूल्य और विक्री की मात्रा के मध्य एक ऐसा समन्वय (Adjustment) ढूँढ निकालना पड़ेगा कि जहाँ उसे अधिकतम-अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

उदाहरण—(Illustration)—निम्नांकित उदाहरण द्वारा एकाधिकारी मूल्य निर्धारण का मिथान्त भन्नी प्रकार समझा जा सकता है —

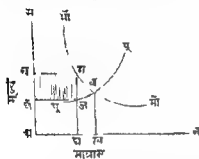
एकाधिकारी उत्पादन (सारणी)

उत्पत्ति की इकाइयों	प्रति इकाई लागत	मूल्य	प्रति इकाई लाभ	कुल शुद्ध लाभ
	२०	६०	४०	४०
१००	४	५	५	३००
२००	४	७	३	६००
३००	३	६	३	९००
४००	२ १/२	५	२ १/२	१,०००
५००	३	४	१	४००
६००	४	३	०	०

उपर की सारणी में यह स्पष्ट है कि एकाधिकारी ४०० इकाइयों की उत्पत्ति करने पर अपने अधिक शुद्ध लाभ (Net Monopoly Profit) प्रचलित १००० ०० प्राप्त कर सकेगा। इस लाभ को पाने के लिये वह बाँच ४० प्रति इकाई मूल्य निर्धारित करेगा जो लागत व्यय से २ १/२ ०० अधिक है।

रेखा चित्रण (Diagrammatic Illustration)—न के दिखे हुए रेखा चित्र द्वारा यह सातानी में बतलाया जा सकता है कि एकाधिकारी किम बिन्दु पर मूल्य निर्धारित करेगा :—

नीचे के रेखा चित्र में माँ माँ माँग की वक्ररेखा और पू पू पूर्ति की वक्ररेखा एक दूसरे को बिन्दु पर काटती हैं। प्रतियोगिता की अवस्था में मूल्य वक्र के



एकाधिकार मूल्य-निर्धारण

वक्रपर होगा, क्योंकि इस मूल्य पर माँग और पूर्ति समान है। एकाधिकारी विशेष लाभ उठाने की दृष्टि से इसमें अधिक मूल्य रखेगा। मान लीजिए वह राश मूल्य नियत करता है जो वह स्वयं मूल्य में अधिक है। इस मूल्य पर माँग माप लेख मका, क्योंकि उपभोक्ता इतनी ही मात्रा खरीदने को तैयार हैं। अधिक मात्रा कुछ उत्पादन थाय माँ प ज छ मायन (Rectanglo) में बरानर है। इस माप का दबन में उप कुल मूल्य माँ प म च मायन में बरानर

एकाधिकारी द्वारा मूल्य में भिन्नता—एकाधिकारी का मायन सभी स्थानों पर एक ही मूल्य पर विज्ञा करता है, परन्तु वह सभी जगहों विभिन्न स्थानों के मायन में भिन्न भिन्न मूल्य भी रक्ता है क्योंकि इसमें उसका लाभ बढ़ जाता है। ऐसा होता गया है कि वे सभी जगहों वेस में अधिक मूल्य पर तथा विदेश में कम मूल्य पर एकाधिकार-मूल्य रख कर एकाधिकार-मूल्य का उत्पादन बढ़ाने एवं विदेशी बाजार पर अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं।

भिन्न भिन्न मूल्य लवना उन एकाधिकारियों के विषय बहुत महत्त्व है जो मका द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जैसे दारुण यहीन मादि। प्रायः वह डॉक्टर गरीबों में कम फीस लेते हैं और धनीयों में अधिक। ऐसा करने में वे गरीबों की बेचन भलाई ही नहीं करते अपितु अपनी प्रायः मा दशन है। यदि वे सभी में एक ही फीस लें, तो बहुत से रोगी निरुध्द होकर कारण उनके पास न मा भवत। इसलिए वे भिन्न भिन्न रोगों का न व्यसिधा के विषय प्रत्यक्ष मायन काम रक्ता है। यहाँ पर यह सम्भव नहीं कि सभी रोग गरीबों के रूप में प्रत्यक्ष मायन का भेद कर अपनी दवा कर सकें।

मायन—बहुत ना तात्पर्य यह है कि मायन का यह कथन मका मायन है कि एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य मायन के अनुसार इस प्रकार पूर्ति मा मायन रूढ़ि करना

होता है कि उस अधिकतम लाभ हो सके। वह इस बात का प्रयत्न नहीं करता कि उसकी एकाधिकार वस्तु का मूल्य उत्पादन व्यय के समान हो जाय।¹

एकाधिकार और प्रतियोगिता मूल्य में अंतर

(१) प्रतियोगिता की अवस्था में मूल्य और उत्पादन-व्यय दोनों बराबर होने हैं परन्तु एकाधिकार की अवस्था में उत्पादन-व्यय मूल्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। एकाधिकारी को प्रतियोगिता का भय नहीं रहता। इसलिए वह मांग की ताब को ध्यान में रखते हुए उत्पादन-व्यय में अधिक मूल्य रखता है।

(२) एकाधिकारी भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न मूल्य न सक्ता है परन्तु प्रतियोगिता की अवस्था में ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(३) प्रतियोगिता में उत्पादक एक दिव्य हुए मूल्य पर बाह्य जितनी बिज्री कर सकता है परन्तु एकाधिकार में मूल्य घटाकर ही बिज्री बढ़ाई जा सकती है।

(४) प्रतियोगिता में मूल्य पर कोई अधिकार नहीं होता परन्तु एकाधिकार में मूल्य पर बाढ़ा-बहुत नियंत्रण रहता है। वह मूल्य का बाह्य जितना बचाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। परन्तु चूंकि यह प्रावश्यक नहीं है कि उसे वह मूल्य पर लाभ अधिक हो हाँ मत वह प्रावश्यकता पड़ने पर मूल्य कम करके भी अधिकतम लाभ पाने का प्रयत्न करता है।

(५) बिना उद्योग में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है वहाँ पर अनन्यतम इकाई के आधार (S/c) का बचपम पाई जाती है परन्तु एकाधिकार में केवल एक ही कम सम्भव है। एकाधिकारी विभिन्न उपायों द्वारा वनमान विरोधी व्यापारियों का नष्ट कर देता है तथा अधिक मूल्य भी एकाधिकार-योग्य प्रकाश करी करन देता।

(६) एकाधिकार मूल्य में परिवर्तन का अवयव कर सकता है परन्तु उसकी यह शक्ति अपरिमित नहीं है। उस कई बातों का भय रहता है। यदि वह बहुत ऊँचा मूल्य रखता है तो सम्भव है राज्य की धार में हस्तक्षेप होने लगे या प्रतियोगिता फिर से उपस्थित हो जाय। उस कम बात का भी भय रहता है कि कहीं सामाजिक मन उसके विरुद्ध न हो जाय या मांग उस वस्तु के स्थान में दूसरी स्थानापन्न वस्तु को उठा प्रयोग में न लाने लग जाय। प्रतियोगिक मूल्य इन सब बातों से मुक्त रहता है।

इन सब बातों का होने भी यह सोचना भूल होगी कि एकाधिकार और प्रतियोगिक मूल्य निर्धारण में बड़ा भेद है। मूल्य मांग और पूर्ण व सिद्धान्त द्वारा ही निर्धारित होता है। एकाधिकार का माझ-मध्य हाँ मध्या प्रतियोगिता का।

एकाधिकार पर नियन्त्रण—सरकार एकाधिकार पर नियन्त्रण करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप मूल्य और लाभ पर नियन्त्रण उत्पादन का राष्ट्रीयकरण प्रचार द्वारा सामाजिक बहिष्कार आदि उपायों का अवलम्बन करती है। यद्यपि समय-समय

1— The Prima facie interest of the owner of a monopoly is to supply to adjust the supply to demand and to secure the price at which he can sell his commodity shall just cover its expenses of production but in such a way as to afford him the greatest possible total revenue
—Marshall

पर इन नियमों द्वारा एकाधिकार की बुझाइ को दूर कर दिया जाता है, तथापि यह देखा जाता है कि वे विभिन्न उपायों द्वारा या तो इन नियमों को निष्फल कर देने हैं अथवा उनको भूनाधिक मात्रा में कम कर लेने हैं।

यह नियमों में इसलिये आवश्यक होता है कि एकाधिकारी मूल्य में कुत्रिम वृद्धि न कर सके, उत्पादन पर नियम न रख सकें तथा अन्य व्यापारियों के व्यापार को नष्ट न कर सकें।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—वाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अन्तर बताइए। किसे वस्तु का दीर्घकालीन मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ?
- २—'किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य बाजार पर और दीर्घकालीन मूल्य पूर्ति पर निर्भर होता है। इस कथन को पुष्टि कीजिये।
- ३—शिली वस्तु का मूल्य उसके लागत-मूल्य से न बहुत अधिक और न बहुत कम रह सकता है। इस कथन को व्याख्या कीजिये। चित्र बनाकर उदाहरण द्वारा समझाइयें। (रा० बो० १९५८)
- ४—वाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में क्या भेद है ? समझाइयें कि इनमें तत्प्रेक्ष्य मूल्य का निर्धारण कैसे होता है ?
- ५—अल्पकालीन और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य में क्या अन्तर है ? समझाकर लिखिये। (रा० बो० १९६०)
- ६—वाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अन्तर समझाइयें। सामान्य मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? (रा० बो० १९५७)
- ७—पूरा प्रतियोगिता की दशा में किसे दिन किसी वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? चित्र भी कीजिये। (रा० बो० १९५५, मार्ग १९५२)
- ८—'किसी मनुष्य या सामान्य मूल्य स्थायी तौर से इसके उत्पादन-व्यय मात्र तो अधिक ऊँचा और न नीचा ही रह सकता है।' इस कथन की पूर्णतया व्याख्या कीजिए। (प्र० बो० १९५०, प्र० भा० १९५५)
- ९—यदि मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन होता है, तो माँग विप्लव दिया में वदन्ती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं ? कारण दीजिए और समझाइयें। (नागपुर १९५५)
- १०—एकाधिकार में किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। (माग १९४६)

इष्टर एग्जिक्शन्स

- ११—पूर्ण स्टांडर्ड के अन्तर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण का विवरण दीजिये और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये कि वाजार मूल्य सामान्य मूल्य के अन्तर पर संशोधन करता है।
- १२—प्रश्न क्या है ? इसका निष्पत्ति कैसे विधा जाता है ? अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य के निष्पत्ति करने में जिन कारकों (फैक्टर) की सहायता प्रदाननी होती है, उन्हें समझाइयें। (प्र० बो० १९५६)
- १३—मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है :—
 (अ) दीर्घकालीन बाजार में ? (आ) अल्पकालीन बाजार में ?
 (इ) काला बाजार में ? (रा० बो० १९५८)

परिचय (Introduction)

जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि सम्यता की प्रारम्भिक अवस्था में जबकि मनुष्य की आवश्यकताएँ अल्प एवं सीमित थी, वस्तु-विनिमय प्रथा (Barter System) प्रचलित थी। सम्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी और उसे अपने दैनिक कार्यों में वस्तु-विनिमय प्रथा द्वारा अनैक प्रसुविधायें तथा कठिनाइयाँ होने लगीं जिससे परस्पर रूप में मुद्रा-विनिमय प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। सम्यता की बढ़ती हुई विनिमय-समस्याओं को सुलझाने में मुद्रा-विनिमय का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का प्रयोग अपरिहार्य (Indispensable) है तथा हमारी समृद्धि मुद्रा पर ही निर्भर समझी जाती है। मुद्रा के द्वारा ही हम वस्तुओं का अन्त-विशेष करते हैं; नौकरी का वेतन चुकाने हैं तथा मुद्रा के द्वारा ही देशी और विदेशी व्यापार सम्पन्न होता है। आज के युग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुद्रा के प्रति आवश्यक नहीं होता? एक वास्तव में मिठाई या चटपटी खरीदने के लिये चाहता है, एक विद्यार्थी इसे अपनी पुस्तकें खरीदने और स्कूल कॉलेज की फीस देने के लिये चाहता है, एक माधु या फकीर अपना पेट भरने के लिये इसकी याचना करता है तथा एक गृहस्थी इसे अपनी और अपने कुटुम्बिका की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चाहता है। माराध यह है कि आधुनिक युग में कोई भी कार्य बिना मुद्रा के सम्भव नहीं है। अस्तु, आधुनिक युग को यदि, 'मुद्रा युग' कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

प्रबन्ध हम मुद्रा का जोकि आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है, विस्तृत विवेचन करेंगे।

मुद्रा का जन्म तथा विकास (Origin & Growth of Money)

वस्तु-विनिमय की आधुनिक प्रसुविधाओं में मुद्रा का जन्म दिया, इसमें तनिष भी सन्देह नहीं हो सकता। वस्तु-विनिमय के दोषों में छुटकारा पाने के लिये मनुष्य ने इतिहास के आदिवासी में ऐसी माध्यमिक वस्तुओं को खोजा जोकि सार समार में वस्तुओं व सेवाओं के बदले स्वीकार की जाने लगीं, जिनके द्वारा समस्त वस्तुओं का मूल्य मापा जा सकता था तथा जिसके द्वारा मूल्य सुगमता से उपविभाजित एवं संचित किया जा सकता था। ऐसी मध्यस्थ वस्तु मुद्रा (Money) के नाम से सम्बोधित होने लगी।

भिन्न भिन्न वस्तुओं के समय और स्थान की भिन्न-भिन्न दशाओं के अनुसार मुद्रा का रूप धारण किया। मानव के अर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अर्थात् आदिवासी युग में जंगली जानवरों की खाल मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की गई। पशुपालन

अवस्था में भेद और साथ तथा कृषि-अवस्था में व उत्तरे पश्चात् घनाज, तेल, तम्बाकू, गमक, मूती बरस, चमड़ा, गुनाम, माना के गनिये, मोपे, गुंगा, कीड़ियाँ आदि वस्तुएँ मुद्रा की भाँति प्रयुक्त की जाती थी। अमीका के कुछ भागों में मनुष्य की तोपड़ियाँ को विनिमय के लिये प्रयोग में लाया जाता था। चीनी तोप बड़े अफीमखी थे। धनः उन्होंने अफीम का प्रयोग मुद्रा के स्थान पर बहुत समय तक किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय व स्थान पर जिस वस्तु की सभी लोग माँग करते थे, वह वस्तु उस समय तथा स्थान पर विनिमय के काम आने लगी। किन्तु ये सभी वस्तुएँ किसी-न-किसी वसा में दूषित पाई गईं, इसलिये कालान्तर में इनका स्थान सोने और चाँदी में ले लिया। मुद्रा का सबसे मया रूप पत्र-मुद्रा है जो मुद्रा का सबसे अधिक सुविधाजनक एवं निश्चयी रूप है।

मुद्रा की परिभाषा (Definition)

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी हैं। कुछ ने इसकी परिभाषा संकीर्ण अर्थ में दी है और कुछ ने विस्तृत अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा से अभिप्राय केवल धातु मुद्रा (Metallic Money) अर्थात् धातु के सिक्कों में ही होता है। विस्तृत अर्थ में मुद्रा का आशय प्रत्येक प्रकार के विनिमय साधनों से होता है और उसमें धातु-मुद्रा अर्थात् धातु के सिक्के, पत्र-मुद्रा (Paper Money) अर्थात् करेन्सी नोट और क्रेडिट मुद्रा (Credit Money) अर्थात् बैंक, बिल ऑफ एक्सेप्ट, प्रोमिसरी नोट व इण्डिया—सभी सम्मिलित किये जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री इन दोनों के बीच की परिभाषा देने हैं। उनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जोकि ऋण के अन्तिम भुगतान में बिना सदेह के साधारणतया स्वीकार की जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा का आशय केवल धातु मुद्रा अर्थात् धातु के सिक्कों और पत्र मुद्रा अर्थात् करेन्सी नोटों में ही होता है। धातु के सिक्कों और कागजी नोटों का सेन-सेन वाटून की दृष्टि से अनिवार्य होता है। परन्तु बैंक, बिल ऑफ एक्सेप्ट, इंडी आदि साधन-पत्रों का आदान-प्रदान सर्वथा ऐच्छिक होता है, कानून द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिकतर इन साधन-पत्रों का सेन देन परिचित व्यक्तियों तक ही सीमित होता है। ये सर्वसाध्य एवं विधि ग्राह्य (Legal Tender) नहीं होते। अस्तु, इन्हें मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता।

मुद्रा के विभिन्न अर्थ विम्नाहित चित्र द्वारा अवगत किये गये हैं :—

संकीर्ण अर्थ में मुद्रा = धातु मुद्रा (धातु के सिक्के)

विस्तृत अर्थ में मुद्रा = धातु-मुद्रा (धातु के सिक्के)

पत्र-मुद्रा (करेन्सी नोट)

साध-मुद्रा (बैंक, बिल, प्रोमोट, इंडी)

सही अर्थ में मुद्रा = धातु-मुद्रा + पत्र-मुद्रा

चित्र का स्पष्टीकरण—आगे के चित्र से मुद्रा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। चूतसंख्य १ मुद्रा का संकीर्ण अर्थ प्रदर्शित करता है, चूतसंख्य १+२+३ मुद्रा का



विस्तृत अर्थ प्रकट करने है और वृत्तखण्ड १+२ मुद्रा का सही अर्थ बताते हैं।

मुद्रा को कुछ प्रचलित परिभाषाएँ

यहाँ कुछ प्रसिद्ध परिभाषाओं द्वारा दो बड़े मुद्रा की परिभाषाएँ दी जाती हैं।

(१) ऐली (Ely) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में व्यवहार्यतापूर्वक एक रूप में दूसरा रूप में होकर निवर्तनी है और सामान्यतया लोगों के अन्तिम मुद्रागत के दिवस स्वीकार की जाती है।"^१

मुद्रा का अर्थ (वृत्तखण्ड १+२=मुद्रा)

(२) रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो माल के मुद्रागत में दीयता किन्हीं व्यापार-सम्बन्धी दायित्व में मुक्ति प्राप्त के लिए स्वीकार की जाती है।"^२

(३) जी० टी० कोल (G. D. H. Cole) इस प्रकार परिभाषित करते हैं। "मुद्रा अस्तित्व है—कुछ ऐसी चीज है जो व्यवस्था के स्वीकार के काम आती है।"^३

(४) मार्शल (Marshall) के अनुसार "मुद्रा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित की जा सकती हैं जो किसी समय और स्थान पर बिना मन्दिर और विशेष जोख-खटान के वस्तुओं और सेवाओं के रूप के दिवस और अन्तिम-मुद्रागत के लिए सामान्यतः स्वीकार होती हैं।"^४

(५) जे० एम० केन्स (J. M. Keynes) इस प्रकार परिभाषित करते हैं। "मुद्रा वह वस्तु है जिसके मुद्रागत में अर्थ व्यवस्था तथा व्यवस्थाओं के मुद्रागत मित जाता है और जिसमें अन्य मित निहित होती है।"^५

(१) "Money is anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts"

Ely : *Elementary Principles*

(२) "Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of any business obligation"

Robertson : *Money*, p 21.

(३) "Money is purchasing power—something which buys things"

Cole : *What everybody wants to know about money*, p 2.

(४) "Money includes all those things which are (at any time and place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services and of defraying expenses"

Marshall *Money, Credit and Commerce*, p 13

(५) "Money is that by delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which general purchasing power is held."

J. M. Keynes *Treatise on Money*, Vol. I

(६) हार्टले विदर्स (Hartley Withers) कहते हैं “मुद्रा वह पदार्थ है जिसमें हम वस्तुएँ खरीदने और बेचना हैं।”¹

(७) ज्यॉफ्रे क्रॉउथर (Geoffry Crowther) के शब्दों में “मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय-माध्यम के रूप में सर्वग्राह्य हो अर्थात् जिसमें कच्चा का निवटारा किया जा सके और साथ ही साथ मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती हो।”²

(८) सेलिगमैन (Seligman) का परिभाषित करने है—“मुद्रा वह वस्तु है जिसमें श्रान्त होतो है।”³

(९) टॉमस (Thomas) के अनुसार “मुद्रा वह वस्तु है जो समस्त अन्य वस्तुओं के मध्य मूल्य-मापन और विनिमय-मापन के लिए सर्व-स्वीकृति में चुनी गई हो।”⁴

(१०) किन्ले (Kinley) के अनुसार “मुद्रा विनिमय माध्यम का वह भाग है जो विनिमय बाजारों और अणु-भुगतान में स्वतन्त्र रूप में प्रचलित होता है और इसकी स्वीकृति में किसी तीसरे पक्ष के दायित्व तथा इसके न चलने पर भुगतान करने वाले के पुनः भुगतान करने की प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं होती।”⁵

(११) वॉकर (Walker) के शब्दों में “जो वस्तु सम्पूर्ण अणु-भुगतान के लिये एक दूसरे के प्रति बिना किसी सन्देह के अनिवार्य रूप में हस्तांतरित होती है तथा जो देने वाले व्यक्ति की साज की वृद्ध-नाश के बिना निस्सन्देह स्वीकृत होती है, ऐसी किसी भी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं।”

मुद्रा की एक निश्चित एक स्वीकृत्यजनक परिभाषा देना कठिन है। सत प्रो० वॉकर (Walker) के ये शब्द कि “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है”⁶—मुद्रा की

(1) “Money, then, is the stuff with which we buy and sell things
Hartley Withers. *The Meaning of Money*, p. 267.

(2) “As anything that is generally acceptable as a means of exchange (i. e. as a means of settling debts) and at the same time acts as a measure and as a store of value.”

Geoffry Crowther. *An Outline of Money*, p. 35

(3) “Money is one thing that possesses general acceptability”
Seligman: *Principles of Economics*

(4) “Money is a commodity chosen by common consent to serve as a measure of value and a medium of exchange between all other commodities”
Thomas: *Elements of Economics*

(5) “Money is that part of the medium of exchange which passes freely in exchange and settlements of debts without making the discharge of obligations contingent on the action of a third party or on the action of the payer by promising if the money article does not pass”
—Kinley

(6) “Money is what money does”

Walker: *Political Economy*.

परिभाषा की कठिनाई के सूचक हैं। बॉकर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा वस्तुतः मुद्रा के कार्य ही हैं। इस परिभाषा से हार्टले विद्वत् भी सहमत हैं।

ऊपर की परिभाषाओं से ज्ञान होना है कि मुद्रा वह वस्तु है जो व्यक्तियों के मध्ये एवं ऋण चुकाने के लिये सभी व्यक्तियों द्वारा गृह्य एवं स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकार की जाती हो। दूसरे शब्दों में, वह वस्तु जिसमें सामान्य ग्राह्यता का गुण न हो मुद्रा नहीं कहला सकती। बतंगान युग में चैक, बिल, ट्रेडिआदि यदि भी विनिमय-माध्यम का कार्य करने हैं, परन्तु वे विभिन्नाय (Legal Tender) नहीं हैं और उन्हें कोई भी अपरिचित व्यक्तियों से या सर्वव्यापक भाग वाले व्यक्तियों से नहीं लेता है। प्रत्येक स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकृत नहीं किन्तु जाने और न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ही जाने-जाने हैं। प्रत्यु, उन्हें मुद्रा नहीं माना जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सब प्रकार के विनिमय-माध्यम मुद्रा नहीं कहें जा सकते यद्यपि सब मुद्रा अनिवार्य रूप से विनिमय-माध्यम होती हैं। इसलिये मुद्रा एक विविध प्रकार का विनिमय माध्यम है, अर्थात् मुद्रा वह विनिमय-माध्यम है जो सर्वमान्य एवं विधि-प्राप्त है।

संक्षेप में, मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है; चाहे वह धातु का बना हो या कागज का अथवा सरकार या विदेश-प्राप्त बैंक द्वारा प्रचलित किया हुआ नोट हो जो जन-साधारण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और देश के भीतर अपरिचित व्यक्तियों में बिना रोक-टोक के प्रयुक्त किया जाता है।

मुद्रा के मुख्य लक्षण

(Essential Characteristics of Money)

(१) सर्वग्राह्यता—मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी सर्वग्राह्यता है अर्थात् इसे सब स्वीकार करें। साधारणतया मान्य होने के लिये यह प्राथमिक है कि उस पदार्थ की, मुद्रा के अनिवार्य उपयोगिता भी हो। यही कारण है कि पुर्नो समय में चैक, बिल, चमड़ा, जानवर आदि मुद्रा का कार्य करने थे। आधुनिक समय में मुद्रा के मान्य होने के लिये उसका अन्य रूप में उपयोगिता होना आवश्यक नहीं है। प्रायः सभी देशों में पत्र-मुद्रा का प्रचलन है। यद्यपि पत्र-मुद्रा की अन्य कोई उपयोगिता नहीं है फिर भी यह मान्य है, क्योंकि कानून ने इसको स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया है। प्रत्यु, मुद्रा का स्वीकार किया जाना इसका मुख्य लक्षण है।

(२) ऋण-मुक्ति—मुद्रा के प्रयोग में ऋण की मुक्ति इसका दूसरा लक्षण है। व्यक्ति प्राप्त के ऋणों को मुद्रा द्वारा चुका सकते हैं, सरकारें ऋण भी मुद्रा द्वारा चुकाये जा सकते हैं और मन्त्रालय अपने ऋण भी मुद्रा के प्रयोग से चुका सकते हैं। चैक, बिल, ट्रेडी आदि ग्राहकों के प्रयोग में ऋण से मुक्ति नहीं बिल सकती, क्योंकि इनके अन्वय (Dishonour) से ऋणों पर से उत्तरदायित्व हो जाता है। अतः ये मुद्रा नहीं कहलाये जा सकते।

(३) विनिमय-माध्यम—मुद्रा एक प्रकार का विनिमय माध्यम है, इसका अन्य रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे घटस्थ हैं जो इसका विनिमय के रूप में प्रयोग कर लाभ उठाने के लक्ष्य में खिंच कर खानन्द उठाते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं और इनका व्यवहार सर्वसाधन के क्षेत्र के बाहर है।

मुद्रा के कार्य (Functions of Money)—मुद्रा मूल्य सामंदायक रूप सम्पन्न करती है जिनमें से मुख्य चार हैं जो बाहर द्वारा दी गई निम्न दो पनिया के रूप में सरलता में स्मरण रखे जा सकते हैं —

Money is a matter of functions four

A medium a measure a standard a store

चार कार्य के हन हा मुद्रा वस्तु महान ।

माध्यम माप प्रमाण ग्रह संचय कार्य प्रधान ॥

(१) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)—विनिमय माध्यमता मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। माध्यम नाम वह तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का अन्य विषय इनका गारा हो। हमारे द्वारा वस्तु विनिमय (Barter) की समस्त कठिनाइयाँ दूर होकर विनिमय काय सुगम एवं सरल हो गया है। प्रत्येक वस्तु का अन्य विषय प्राप्त करने मुद्रा द्वारा हो सम्भव होता है क्योंकि हम प्रत्येक मनुष्य बिना तादेह के स्वाकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि हमें वह क्षमता सन्निहित होती है कि हमारे द्वारा मुद्रा पान वाला जब चाहें तब अपनी आवश्यकता को वस्तुओं प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रकार में पारस्परिक वस्तु है जिसके द्वारा विनिमय कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान युग में जाति के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्रचलित है। इसलिये यह मुद्रा का एक आवश्यक कार्य माना गया है।

(२) मूल्य का माप (Measure of Value)—मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को मापने का एक साधन है। जिन प्रकार रमई मशीनोटर का माप जानी है विजली बिलोमेट में मापी जाती है और कपड़ा गज से मापा जाता है उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यक मद्रा द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त हमें मूल्यों को तुलना भी ठाक ठग से की जा सकता है जिनमें विनिमय-क्षम में बहुत सुविधा होती है। उदाहरणार्थ यदि १ रु० का १ सर चावल और १ रु० के २ सेर गहूँ पाये हैं तो हम तुरन्त कह सकते हैं कि चावल का मूल्य गहूँ से दुगुना है।

(३) स्थगित या भावी भुगतान का प्रमाण (Standard of Deferred Payment)—मुद्रा स्थगित या भावी लेन देना का भुगतान का एक सुगम साधन है। आज के युग में साधारणतया एय व्यापारियों को एक-दूसरे से उधार लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि कृष्ण मुद्रा की धारा में वस्तुओं के रूप में लिया जाय, तो कृष्ण चुकावे समय ठीक उसी प्रकार की वस्तुएँ लौटाने तथा ध्यान देने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य में बहुत परिवर्तन होता रहता है जिसमें कृष्णता और कृष्ण को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा द्वारा कृष्ण देने और लेने में इन प्रकार का समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसलिये मुद्रा द्वारा ही लेन-देन का कार्य किया जाता है। आधुनिक समय में भावी लेन देना के कार्य का कितना महत्व है यह किष्का से सिद्धा नहीं है।

(४) मूल्य का संचय (Store of Value)—साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिक की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कुछ धन संचित करने रखता पाय है

करता है। यदि वह वस्तुओं को संचित करता है, तो वे बोले समय के पश्चात् सङ्गत मन्ती है तथा उनके मूल्य में परिवर्तन भी हो सकता है। इन्के प्रतिरिक्त वे स्थान भी बहुत बेगुनी है। ऐसी अवस्था में वस्तुओं या जानवरों को घन के रूप में संचित नहीं किया जा सकता। घन संचय करने का कार्य मुद्रा द्वारा भली शक्ति सम्पन्न होता है। मुद्रा का किसी भी समय उपयोग हो सकता है तथा उसके नाट होने का भय नहीं रहता है और उनके मूल्य में अधिक परिवर्तन नहीं होता। उसकी माँग स्थायी तथा सार्वभौम होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुद्रा ने मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है परन्तु इसके मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बहुत कम परिवर्तन होता है। दधपि वरन्नी मोट मचय के लिये इतने अनुकूल नहीं हैं, फिर भी सरकार पुराने मोटा को समय समय पर बदल कर पराव होने से बचाती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य-संचय का सर्वोत्तम एवं आदर्श माधन है।

मुद्रा के कार्यों का अन्य प्रकार से विभाजन—पुछ भव्यशास्त्रियों ने मुद्रा के सम्पूर्ण कार्यों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया है :—

१—प्रमुख या आवश्यक कार्य (Primary or Essential Functions)

२—गौण या सहायक कार्य (Secondary or Derived Functions)

३—संभाव्य या नैमित्तिक कार्य (Contingent Functions)

१—प्रमुख या आवश्यक कार्य (Primary or Essential Functions)
मुद्रा के प्रमुख या आवश्यक कार्य वे हैं जो मुद्रा द्वारा किसी समय तथा किसी भी समाज में आवश्यक रूप में किये जाते हैं। ये कार्य मुख्यतः दो हैं—(अ) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) और (ब) मूल्य का माप (Measure of Value) इसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है।

२—गौण या सहायक कार्य (Secondary or Derived Functions)
—मुद्रा ने प्रमुख या आवश्यक कार्य वे हैं जो प्राथमिक व्यवस्था की प्रारम्भिक अवस्था में मुद्रा द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, परन्तु गौण या सहायक कार्य समाज का प्राचीन विनाश होने के उपरांत ही दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में देखा जाय तो मुद्रा के इन कार्यों की उत्पत्ति हमने प्रमुख या प्रारम्भिक कार्यों में ही देखी है, इसी कारण इन्हे गौण या सहायक कार्य (Secondary or Derived Functions) कहा गया है। ये कार्य मुख्यतः तीन हैं—(अ) स्वर्गित या भावी चुकतान का प्रमाण (Standard of Deferred Payment), (ब) मूल्य का संचय (Store of Value) और (ग) मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)। इनमें से प्रथम दो कार्यों का वर्णन ऊपर दिया जा चुका है। अतः यहाँ पर तीसरे का ही विवेचन किया जाता है।

(ग) मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)—मुद्रा मूल्य-संचय करने का सर्वोत्तम माधन होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को तथा एक समय से दूसरे समय को इसका हस्तान्तरण कभी सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा का

सुविधाजनक रूप होने के कारण उनके स्वातन्त्र्य अथवा हस्तान्तरण में कोई कठिनाई नहीं होती है ।

३. गभाव्य या नैमित्तिक कार्य (Contingent Functions) — मुद्रा की सहायता से समाज का विकास हुआ और समाज के विकास के साथ मुद्रा का भी विकास हुआ । मुद्रा का कार्य खैर दिनों-दिन विस्तृत होता गया और इसी के परिणाम स्वरूप आज हम मुद्रा को धनेको ऐसे कार्य सम्पन्न करने दृग् पाते हैं जिनकी मुद्रा के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में कल्पना तक नहीं हुई होगी । प्रो० किन्ले (Kinley) ने अनुसार हुए इन कार्यों को सम्भाव्य या नैमित्तिक कार्य कह सकते हैं । जो निम्नलिखित हैं :

(अ) राष्ट्रीय आय-विन्यास का आधार (Basis of distributing National Dividend) — आज के समुक्त एवं सामूहिक उत्पत्ति के युग में वित्त मुद्रा के माध्यम से समुचित वितरण सम्भव नहीं है । आवश्यक सभी वस्तुओं वित्त के विषये उत्पादन की अन्तिम और मुद्रा द्वारा रिती करने में समुक्त आय का सुविधापूर्वक विन्यास हो जाता है ।

(ब) अधिकतम तृप्ति का माधन (Means of Maximum Satisfaction) — समुक्त अपनी आय को भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर दृग् प्रकार व्यय करता है कि उन वस्तुओं में मिलने वाली कुछ उपयोगिता अधिक-से अधिक हो । यह कार्य मुद्रा द्वारा ही सम्भव हो सकता है । यदि मुद्रा न होतो तो भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर कितना व्यय करना चाहिए, यह शक नहीं हो सकता था । प्रस्तु, मुद्रा द्वारा ही समुक्त भिन्न-भिन्न वस्तुओं की दरीक कर अधिक-से-अधिक उपयोगिता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है ।

(ग) साध्य का आधार (Basis of Credit) — आज की विशाल मात्रा-अवस्था मुद्रा द्वारा ही सम्भव है । यदि मुद्रा नहीं होतो तो उधार में लेन-देन का काम नहीं हो सकता था । अब मुद्रा के होने में वस्तु उधार लेकर बदने में कभी भी मुद्रा चुकाई जा सकती है । बैंक अपने कोष में कुछ प्रविष्ट मुद्रा रखते हैं और उनकी के आधार पर वे साध्य वसते हैं और अग्र-विन्यास करते हैं इस रोकट संचित (Cash Reserve) के कारण ही उनकी आर्थिक स्थिरता तथा साध्य के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता रहता है और इसी कारण उनके गोट और बैंक सरकारी बोर्डों की आज्ञा विनियम माध्यम के रूप में चलते रहते हैं ।

(द) पूँजी की गतिशीलता में सहायक (Mobility of Capital is facilitated) — मुद्रा पूँजी की गतिशील बनाती है अर्थात् मुद्रा के द्वारा पूँजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और एवं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है । मुद्रा के रूप में पूँजी मुख्यतः में उम व्यापार में लगाई जा सकती है जिसमें अधिकतम आय की सम्भावना हो । इन प्रकार मुद्रा पूँजी को अधिक गतिशील बना देती है और उसकी उपयोगिता में अत्यधिक वृद्धि कर देती है ।

(ध) पूँजी को तरल बनाने में सहायक (Helps in making capital liquid) — कीन्स (Keynes) जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के इन कार्य पर बहुत बल देते हैं । उनका कहना है कि मुद्रा अपनी सम्भावना के कारण पूँजी को तरल बना देती है । जनता अन्य वस्तुओं को लेने से इन्कार कर सकती है, परन्तु मुद्रा का

नेन में कभी टूटकर नहीं बर मरती। उसका के कारण ही मुद्रा की मर्त्य है। मुद्रा की इसी विशेषता पर कोई कोन्व का व्याज का गिद्दाल धारित है।

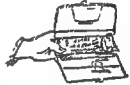
उत्तम मुद्रा-पदार्थ के गुण (Qualities or Characteristics of good money-material) कम ता किसी भी पदार्थ को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु पर उत्तम या आदर्श मुद्रा पदार्थ के निम्न निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है —

(१) सर्वमान्यता या उपयोगिता (General Acceptability or Utility) — मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए



कि उस समाज के सभी व्यक्ति (योग्य) कर, अन्यथा उसके द्वारा वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है। सर्वमान्यता के बिना पदार्थ की उपयोगिता होना आवश्यक है जिसमें विभिन्न मान्यता के अनिश्चित उसके निजी स्वयं के कारण भी उसमें शक्ति हो। सोना-चाँदी इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

(२) वहनीयता (Portability) — एक उत्तम-मुद्रा पदार्थ में वहनीयता का गुण भी होना चाहिए अर्थात् उसे सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सक। इसमें विशेष यह आवश्यक है कि छोटे ही भार या वजन में अधिक मूल्य रखने का सामर्थ्य होना चाहिए। अन्य पदार्थों की तुलना में माना चाँदी इस दृष्टि में उत्तम पदार्थ है क्योंकि इनकी छोटी-सी मात्रा में पर्याप्त मूल्य होता है। किन्तु पर मुद्रा वहनीयता में सबसे अधिक ध्यान रखना है।



(३) अक्षय्यता या नाशहीनता (Durability or Indestructibility) — मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो हवाय, मनुष्य या हास्य में न निरस्त हो। इसमें यह भी पदार्थ की बनी हुई होनी चाहिए कि धीरे-धीरे न घिस जाय अथवा नष्ट न हो जाय। इस दृष्टि में सोने के सिक्के अक्षय्यता का गुण में परिपूर्ण होते हैं।



एक सोने के सिक्के की उम्र लगभग आठ हजार वर्ष होती है। चाँदी के सिक्के इनकी तुलना में नहीं होती, किन्तु भी वह बहुत धीरे-धीरे घिसती हैं। घन, मान-चाँदी के हजारों वर्षों के सिक्के अभी तक भी उपलब्ध होते हैं और उनमें प्राचीन सम्पत्ति की अनुमान लगाया जा सकता है। पर मुद्रा

1—उत्तम-मुद्रा पदार्थ के गुणों या विशेषताओं का बाद स्थान के निम्न श्रेणी



वाक्य CUPDISH (कपडिश) बना मार्केट निद होता है। इस वाक्य के प्रत्येक अक्षर में उत्तम मुद्रा पदार्थ के गुणों का बोध होता है। इन गुणों में अनिश्चित ट्रांसजर्न या कुर्यता और ज्ञात देना चाहिए। इन शब्दों के अनुसार मुद्रा पदार्थ के गुण इस क्रम में हैं : Cognisability (गणि्यता), Utility (उपयोगिता), Portability (वहनीयता), Divisibility (विभाज्यता), Indestructibility (अक्षय्यता), Stability (स्थिरता), Homogeneity (समान्यता), Malleability (कुर्यता या दराज्यता)।

बहुत शोध नष्ट हो जाती है। इसी कारण सरकार समय समय पर पुराने नोटों के बदल नये नोट जारी करती रहती है। जेवन्स (Jeavons) के अनुसार एक उत्तम मुद्रा के गुण यह हैं 'इसे भय की भाँति उठना नहीं चाहिए, पशु-पदार्थ की भाँति सड़ना नहीं चाहिए, सड़ने की भाँति गमना नहीं चाहिए और लोह की भाँति जल नहीं लगना चाहिए। छोटे सूखी मछलियों, पशु या तेज जैसी नाशवान वस्तुएँ अवश्य मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हानी हैं परन्तु जिन वस्तु को हम मुद्रा मानते हैं उसे बाद में किसी दिन शोध हो जा लेना चाहिए।'

(४) **समजातीयता (Homogeneity)**—मुद्रा पदार्थ की विसमता समाप्त होनी चाहिए। उससे सब भाग एवं स हानि चाहिए जिनसे कि समान वस्तु भाँटे टुकड़ा का समान मूल्य हो। कोई भी पदार्थ मूल्य का मापदण्ड नहीं हो सकता है जब



1—It must not evaporate like alcohol nor putrefy like animal substance, nor decay like wood nor rust like iron. Destructible articles such as eggs, dried cod fish, cattle or oil have certainly been used as currency, but what is treated as money one day must soon afterwards be eaten up.

—W. S. Jeavons, pp 35-37.

कि उनकी इकाइया प्रत्येक दशा में समान हों। एक ही मात्रा में दो जवाहरात भिन्न भिन्न मूल्य के हो सकते हैं परन्तु एक ही रूप एक ही मात्रा और एक ही तौल के दो सामान के टुकड़ प्रायः भिन्न भिन्न मूल्य के नहीं हो सकते क्योंकि इस धातु के प्रत्येक टुकड़े का भौतिक और रासायनिक बनावट एक ही होती है। इसलिये सामान्य भावी को मुद्रा बनाने के साथ में मापा जाता है परन्तु जवाहरात मुद्रा के निम्न अनुपयुक्त हैं।

(२) विभाज्यता (Divisibility) — मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे छोटे छोटे भागों में बाँटा जा सके और विभाजन करने में उसका मूल्य कम या गलत न लगे। सामान्य और भावी ऐसी पण्य है जिसे सुगमता से विभक्त किया जा सकता है और उसमें मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने टुकड़ा को चाहे कितनी ही बार गंगा में डाला मिला कि उसने मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ा। इस दृष्टि से हारा जवाहरात जानकर सामान्य भावी पदार्थ मुद्रा के लिये सच्चा अनुपयुक्त है।



(३) कुट्टयता या टनाकूपन (Malleability) — मुद्रा पदार्थ के निम्न गुणों में से एक है। वह ऐसा होना चाहिए कि सुगमता से गलाया जा सके और इष्टानुसार विभिन्न मात्रा में ढाला जा सके। नतीजतन इतना सघन हो कि वह गलने में लगे और न वह ऐसा मुलायम हो कि सोने की भाँति धूल में पिघल जाय या जेब में कपड़ों की गरमी पाकर रमदार बन जाय। सुगम पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिस पर आवश्यक बिंदु और अक्षर स्पष्ट चकित हो सकें। सोने चाँदी में यह गुण विद्यमान है परन्तु चाँहे या प्लैटिनम में इसका अभाव है।



(४) परिचयता (Cognisability) — मुद्रा वस्तु ऐसी होना चाहिए जो जन साधारण द्वारा मरलता से पहिचाना जा सके। उस पर कुछ ऐसे चिह्न बिंदु होने चाहिए जिन्हें देखने से ही कोई पहिचान ले। जैसे मरलता से साधारण से साधारण तथा अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी पहिचान लेता है। सोने चाँदी में भी यह गुण विद्यमान है। वे चाँहे मित्र के रूप में ही चाँह धातु के रूप में और चाँह आभूषण के रूप में ही सुगमता से पहिचान जा सकते हैं। जवाहरात या हीरा सोने के साथ यह बात नहीं है। इनका पहिचान के लिये मोहरी की महामाया लगी जाती है। अतः यह मुद्रा के लिये अनुपयुक्त है।



(५) मूल्य की स्थिरता (Stability of value) — मुद्रा वस्तु का मूल्य स्थिर होना चाहिए। जो पदार्थ अनुधा और नयाया को मूल्य मापने में प्रयुक्त किया

जाता है व जिसके द्वारा घन संचित किया जाता है तथा भावी सुगमता भी होत है, यह आवश्यक है कि उसमें मूल्य में परिवर्तन न हो। समाज की वार्षिक व्यवस्था के लिये मुद्रा वस्तु में मूल्य का स्थिर रहना परमानन्दक है। चाँदी की अपेक्षा सोने में यह गुण अधिक पाया जाता है, क्योंकि सोने का वार्षिक उत्पादन उसकी विद्यमान मात्रा की तुलना में बहुत कम है। यही कारण है कि सोने का मूल्य बहुत कुछ स्थिर रहता है, परन्तु चाँदी का मूल्य इतना स्थिर नहीं है। सूक्ष्मवस्त्रिय एवं मुद्रा की अपेक्षा सोने में स्थिर रखा जा सकती है यद्यपि अयोग्य अधिकारी होने से अमनाधिक्य का भय रहता है।

निष्कर्ष—सोने और चाँदी में व समस्त कुछ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनीलिये समार के अधिकांश देशों में इन्हीं का मुद्रा या मुद्रा के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कम मूल्य के सिक्का व लिये निरुक्त अथवा ठोका चाँदी धातु की अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यदि न सोने चाँदी के वनाप जाय, ना वे बहुत ही छोटे हुए जिसमें उनकी कलाई और प्रयोग सम्भव न होगा।

यदि दूसरी ओर भी दृष्टि डाली जाय ना तब १० वर्षों के आर्थिक इतिहास में ज्ञात होगा कि सोने-चाँदी के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन हुए और देश की वार्षिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सोने चाँदी में कम परिवर्तन हुए है। इन दोनों में भी चाँदी की अपेक्षा सोने में कम परिवर्तन हुए है। अतः, सोना और चाँदी सर्वोत्तम तथा आदर्श मुद्रा पदार्थ माने जाते हैं और समार के सभी प्रगतिशील देशों में इनका अपनापन है।

मुद्रा का महत्त्व (Importance of Money)—आज के समय समाज में मुद्रा का बड़ा महत्त्व है। वस्तुओं के मूल्य विवरण, देशों और विदेशी व्यापार वड़े-वड़े उद्योग विधान उत्पादन-व्यवस्था, सरकारी लेख-दल आदि सभी कार्य समाज में मुद्रा द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। मनुष्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा की महत्ता का अनुभव होता है। यहाँ तक कि कलाकार, कवि, लेखक, नाटककार और सम्पादक की सेवाओं की भी मुद्रा में माँका जाता है और उनकी सेवाओं के बदले में मुद्रा का ही उपयोग किया जाता है। आज छोटे और बड़े सभी लोग अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा द्वारा ही करते हैं। मुद्रा के बिना कोई भी सरकार अपना शासन एवं सेवा-कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती। मुद्रा ही समाज में प्रतिष्ठा की मापक है। मुद्रा ही एक शक्ति है। जिसके नाम जितना ही अधिक द्रव्य होता है वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। मनुष्य ने धर्म और कर्म सभी मुद्रा में प्रभावित होने हैं। मानस में, मुद्रा मानव वार्षिक विकास का दर्शा है, यह उसकी सम्पत्ता के इतिहास का मार है।

मुद्रा का समाज में सर्वदा से ही सम्मान होता रहा है। महाभारत में मुद्रा का महत्त्व "मयं पुरुषो दासः" कहकर बताया गया है। इसी प्रकार मुलमीदासजी की इस पंक्ति में धन की महत्ता प्रकट होती है : "नहि दग्धि सम दृष्ट जग माही।"

कवि होरेस (Horace) ने लिखा है : "अपस्त मानवीय और देवी वस्तुएं, स्थान और सम्मान, मुद्रा के मन्दिर के सामने सिर झुकती हैं।"¹

1—"All thing human and divine, renown,
honour and worth at money's shrine go down"

प्रो० डेवनपोर्ट (Devanport) ने भी मुद्रा की सामाजिक महत्ता का वर्णन इस प्रकार किया है: 'धार्मिक मानवीय प्रयत्न, मानवीय हित व दृष्टि' तथा 'प्रभिन्याय' मुद्रा के सामान्य प्रयुक्त के अधीन है। उत्तम स्वास्थ्य उस व्यक्ति के लिये सुगम है जिसके पास भोजन तथा औषध के लिये, यात्रा करने, परिवर्तन करने तथा कुशल डाक्टर को सेवाओं से लाभ उठाने के लिये मुद्रा हो। कुछ सीमा तक प्रेम, दया, सादर और शांति भी बाजार में सरोदे और बेचे जाते हैं। समस्त आर्थिक तुलनाएँ मुद्रा के रूप में की जाती हैं, सौन्दर्य या कला या नैतिक बातों में नहीं।"¹

प्रो० मार्शल (Marshall) ने मुद्रा का महत्त्व इन शब्दों में बतलाया है। 'मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर धर्मशास्त्र केन्द्रित है।'²

सादम स्मिथ ने मुद्रा के महत्त्व को इन शब्दों में प्रकट किया है: "जिस प्रकार आवागमन के साधन होने में एक स्थान का अन्य स्थान पर पहुँचाया जा सकता है ठीक उसी प्रकार मुद्रा के होने से एक देश की वस्तु दूसरे देशों में लाई जा सकती हैं। यदि किसी देश में वस्तुएँ उत्पन्न न होती हों यहाँ तक कि चाय भी पैदा नहीं होती हो—ऐसे देश को भी मुद्रा की सहायता से भ्रम में भरपूर किया जा सकता है।"

जेवन्स (Jevons) नामक एक धर्मशास्त्री ने लिखा है: "क्योंकि हम अपने जीवन के आरम्भ में ही मुद्रा की देखने और प्रयुक्त करने प्रारंभ हैं, हमलोग हमें मुद्रा के वास्तविक महत्त्व और उसके द्वारा होने वाले लाभ का अनुभव नहीं हो पाता। यदि हम समाज के बहुत प्राचीन रूप को देख जहाँ वस्तुएँ मुद्रा का बिन्दु भी न था, तो हम मुद्रा के न होने से हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं का महत्त्व ही पूरा पूरा जानें जो आदमी और सभी हम मुद्रा के आर्थिक महत्त्व को समझ भी सकते हैं।"

रॉबर्टसन (Robertson) नामक एक धर्मशास्त्री ने लिखा है 'समुच्च मुद्रा के द्वारा ही प्रथम श्रेणी की वस्तु का अनुमान लगाया है। मुद्रा के द्वारा ही समाज में वह पद लगाया जा सकता है जिस वस्तु का किसी आवश्यकता है क्या वस्तु पहले कितनी चाहिए और कितनी मात्रा में बनानी चाहिए तथा उस वस्तु का सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार करना चाहिए।'

गार्गसल, सभी गुरु मुद्रा पर आश्रित हैं। मुद्रा समाज का एक चिह्न है और मानव के आर्थिक विकास का साधक है। मुद्रा के द्वारा ही व्यापार, उद्योग और

1—"More and more human efforts human interests and desires and ambitions fall under the common denomination of money. Health is easier for him who has the wherewithal to pay for goods, foods and medicines to travel and employ good nursing and to command capable physicians and efficient surgeons. And in their degree also love and pity, respect and place are bought and sold upon the market. All economic comparisons are made in money terms not in terms of beauty or of artistic merit or of moral deservings."
—Davenport

2—"Money is the pivot around which economic science clusters."
Marshall *Money, Credit and Commerce.*

३—मैग्गुल्ल: वाचनमाध्यम

कृषि की उन्नति सम्भव हुई। वास्तव में, मुद्रा ने मानव के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक एवं भौतिक विनाश में अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी महत्ता निम्नांकित क्षेत्रों में विशेष उल्लेखनीय है :-

(१) मुद्रा का सामाजिक महत्त्व—मुद्रा के कारण ही आज हमारा इतना सामाजिक विकास सम्भव हो सका है। जिना इसकी सहायता के आधुनिक सभ्यता के विकास का स्वयं तक भी नहीं देखा जा सकता था। जब समाज और मजदूरी वस्तुओं में दो जाती थी, तो कृषकों और श्रमिकों को बहुत हानि होनी थी और वे मात्र जमींदारों व पूँजीपतियों के दास थे। आजकल मजदूरी मुद्रा द्वारा दी जाती है अतः वे लोग स्वतन्त्र हैं और अपने परिश्रम का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा ने दास-प्रथा का अन्त कर और प्रत्येक मनुष्य के भुगतान को बचाव वस्तु के रोकड़ में परिणत कर जनता का सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में पूर्ण सहायता प्रदान की है।

(२) मुद्रा का राजनैतिक महत्त्व—मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय एवं राजनैतिक संगठन में पर्याप्त सहायता मिली है। मुद्रा व आर्थिकार के पूर्व देश में न प्राचीन और न विदेशी व्यापार था, न आवागमन तथा यात्रा दोनों के साधन जैसे साधन थे और न व्यापार की सुविधा के लिये आज जैसे बैंक थे। यदि-यात्रा के आवश्यकता की सभी दस्तुन उल्लेख करने का प्रयत्न किया जाता था और वहीं लोग अपनी अपनी वस्तुओं का अवसा-मयता कर दिया करते थे। परन्तु मुद्रा के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज इन सब समस्याओं को दूर कर राजनैतिक क्षेत्र में क्रांति-पट्ट भर दी है। वैश्वीय बैंक और अन्य विविध प्रकार के बैंकों द्वारा प्रस्तुत सुविधाएँ उत्तम वर्ग की प्रणाली विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। 'ब' ने मुद्रा का रूप धारण कर राज्यों को अपने-अपने भाग्य-निर्माण के लिये स्वतन्त्र कर दिया है। मुद्रा न ही अमेरिका आदि देशों को अपूर्व राजनैतिक शक्ति प्रदान की है। मुद्रा न ही अज्ञान-शामल-प्रणाली को जन्म दिया है। राजनैतिक दास शक्ति का प्रत्यक्ष, जमींदारों-प्रथा व गवामन्त्री शासन का पतन आदि का मूल कारण मुद्रा ही है। पूँजीवाद, समाजवाद आदि राजनैतिक संगठन इसी के रूप हैं।

(३) आर्थिक महत्त्व—मुद्रा का आर्थिक महत्त्व इनके सामाजिक एवं राजनैतिक महत्त्वों के कहीं अधिक है। अथवात्र मुद्रा पर ही आर्थिक है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का यह माप-दण्ड है। मुद्रा की सहायता से ही हम मनुष्यों की आवश्यकताओं को माप सकते हैं। जिस प्रकार मजदूर मज से कपड़ा नापता है और वस्त्रों मनुष्य-संख्या से अन्न आदि तोलता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्री मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा द्वारा माप सकता है। मुद्रा ही अर्थशास्त्र का दूता है जिस पर अर्थशास्त्र रूपी वृक्ष खड़ा है। वास्तव में, मुद्रा समस्त आर्थिक क्रियाओं की प्रेरण है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक शास्त्र में इसका महत्त्व देखा जाता है जो निम्नलिखित है :-

(अ) मुद्रा और उपभोग—व्यय के अन्वेषण में सीमांत उपयोजना, आवश्यकताओं की सीमांत व वस्तु के उपभोग में प्राप्त तुल्य आदि समस्त क्रियाओं को माप मुद्रा द्वारा ही होती है। मुद्रा की सहायता से ही उपभोग अपनी सीमांत प्राप्ति से सम-सोमल-उपयोगिता नियम के अनुसार अधिकतम तुल्य प्राप्त कर सकता है। मुद्रा द्वारा 'उपभोग की बचत की धारणा' का ज्ञान हो सकता है।

(ब) मुद्रा और उत्पादन—आधुनिक बड़े परिमाण की उत्पत्ति, धर्म-विभाजन, विशेषीकरण आदि बातें जिनमें उत्पादन-क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है, मुद्रा के प्रयोग

का ही परिणाम है। मुद्रा के द्वारा ही आज की सधुन-उत्पादन प्रणाली को जन्म मिला है। यह मुद्रा के प्रयोग का फल है आज उत्पादन केन्द्र एक स्थान या देश के लिये ही नहीं ब्रिया जाना बल्कि विदेशों के लिये भी किया जाना है।

(स) मुद्रा और विनिमय—मुद्रा का जन्म ही विनिमय-कार्य को सुनाह रूप में सम्पन्न करने के लिये हुआ है। इनके अदना-बदलो अर्थात् वस्तु-विनिमय को सामग्री कठिनाईयाँ को दूर कर विनिमय-कार्य को बड़ा सुखम एवं सरल बना दिया है जिससे उपभोग, उत्पादन, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं की सम्पन्नता में बड़ी महायत्ना मिली है। देश में प्रचलित करँसो, बैंक-नोटवाले, धक, बिना धातु-एकमंच आदि साम्य-पत्रों के प्रयोग का लाभ मुद्रा द्वारा ही उपलब्ध हो सका है। देशों और विदेशी व्यापार मुद्रा के ही विन है। अस्तु, विनिमय-क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्त्व है।

(द) मुद्रा और वितरण—आज की सधुन-उत्पादन प्रणाली में कई उत्पत्ति के साधक एक साथ मिल कर कार्य करते हैं। प्रत्येक को सेवा का भूमात्रन कर उसको अपनी सेवा का पुरस्कार देना मुद्रा का एक विशेष कार्य है। आधुनिक-वितरण-समस्या का हल मुद्रा में ही अभिहित है।

(य) मुद्रा और राजस्व—वर्तमान समय में हर मुद्रा के रूप में दिया जाता है जो राज्यों के प्रायः का एक साधन है। इस साधन के अभाव में राज्य अपनी शासन-कार्य नहीं चला सकत। इसलिये यह कहा जा सकता है कि राज्यों के कार्य एवं उनकी कार्य-कुशलता उनके पास की मुद्रा पर निर्भर है। राजीन व्यय करने समय अधिनाधिक सामाजिक लाभ का दृष्टिकोण मुद्रा में ही सम्भव हो सकता है।

(४) औद्योगिक विकास—मुद्रा की महायत्ता में पूँजी के गतिशीलता का जानी है और वह उन व्यवस्था के हाथ में आ जाती है जो उसका सबसे बड़ा उपयोग कर सकती है। इस प्रकार मुद्रा द्वारा सीमित क्षमता की सधुन, पूँजी वाली कम्पनियों का जन्म हो जाता है। यह मुद्रा की ही देन है कि आज सधुन पूँजी वाली कम्पनियों लाखों रुपये थोड़े ही समय में एकत्रित करने में सफ़ा हो सकी है। इसमें बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और धन विभाजन, बड़े गणिताण की उत्पत्ति तथा निष्पत्तीकरण को बड़ा प्रोत्साहन मिला।

उपसृत विवरण में यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्त्व अत्यधिक है। इसलिये प्रो० मार्शल ने ठीक ही कहा है कि “सम्मान अर्थशास्त्र मुद्रा पर केन्द्रित है”

मुद्रा के दोष (Evils of Money)—यद्यपि “मुद्रा द्वारा सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं,” फिर भी मुद्रा अवशुलों से मुक्त नहीं कही जा सकती। मुद्रा की सब दोषों की जड़ कहा गया है। इसकी पुष्टि लुडविग वॉन मिसेज (Ludwig Von Mises) नामक एक मुद्राशास्त्री के इन शब्दों में हो जाती है, “मुद्रा ही चोरी, हत्या, धोखाधड़ी व विद्रोहसपात का मूल कारण है। मुद्रा का दोष उस समय जान होता है जब बच्चा अपने दाँतों को बेच देता है और व्यापारीय धन लेकर भाग के बिना फँसला दे देता है। मुद्रा का दोष नैतिकवादी उस समय बताते हैं जबकि

वे अ अधिक भौतिकवाद का विरोध करने हैं। सोम मुद्रा स पैदा होता है और सोम राम पापा की जड़ है।^१ तथापि ये मुद्रा निम्नलिखित अवयुक्तों में दूषित है —

(१) अमितव्ययता—यह सत्य है कि मुद्रा में उबार लेन-देन में सहायता मिलती है परन्तु यह इसका बड़ा भारी दोष भी है। उबार मिलने की सुविधा से लोग अमितव्ययी अर्थात् किनारे-की बन जाते हैं और अपना धन से अधिक व्यय करने लगते हैं।

(२) सूर्य की अस्थिरता—मुद्रा का एक बड़ा दोष यह है कि इसका सूर्य अर्थात् द्रव्य-वस्तु सदैव पृथक् रूप में स्थिर नहीं रहती जिनसे समाज को बड़ी हानि पहुँचती है। मुद्रा के रूप में होने वाले परिवर्तनों में अस्थिरता तथा उल्लोको पर दुरा प्रभाव पड़ता है।

(३) धन वितरण में असमानता—मुद्रा का मध्यम बड़ा दोष यह है कि इससे वारण धन वितरण में असमानता आ जाती है। कुछ ही लोगों के पास बहुत मुद्रा अर्थात् धन इकट्ठा हो जाता है और अधिकांश लोग इसके विरुद्ध बचत ही रहते हैं। वनमान समाज का पूँजीवाद (Capitalism) मुद्रा का ही परिणाम है धन पूँजीवाद के बड़े दोषों के लिये मुद्रा को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है।

(४) भूमि (मजदूरी) में प्रतियोगिता की वृद्धि—मुद्रा के कारण भूमि अर्थात् मजदूरी में प्रतियोगिता बढ़ती है जिससे धर्मिका की हानि होती है। किसी को तो इतना कम मिलता है कि उदरपूर्ति में भी कठिनाई होती है और किसी को इतना अधिक मिलता है कि वह उसे सचित कर पूँजीपति बन बैठता है। यदि मुद्रा के व्यापन में अक्षम होती तो इस प्रकार का तथ्य सम्भव नहीं हो सकता था।

(५) भयंकर युद्धों की जन्म मिलना—मुद्रा ने केवल राजनैतिक दान एक जनन प्राप्त सम्प्राप्ति में ही दोष उत्पन्न नहीं किया है बल्कि यह भयंकर युद्धों को भी जन्म देती है जिससे धन जन आदि का बड़ा परिणाम में विनाश होता है। वारतम में, मुद्रा आधुनिक पूँजीपति वर्ग का जीवनावधार है। जैसा कि रूसिन (Ruskin) ने कहा है मुद्रा के दैत्या (शैतानों) ने मनु जीवन धारण कर लिये हैं। किसी भी धन या दान में भूमि नहीं जो उन्हें निकाल बाहर कर सके।^२

निष्कर्ष—मुद्रा के लाभ और दोषों पर यदि विचार किया जाय तो हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा के लाभ इसके दोषों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं।

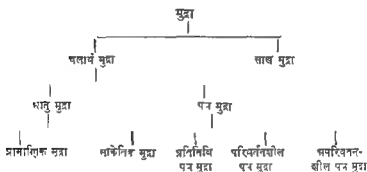
1— Money is regarded as the cause of theft and murder of deception and betrayal Money is blamed when the prostitute sells her body and when the bribed judge perverts the law It is money against which the moralist declaims when he wishes to oppose excessive materialism Significantly enough avarice is called the love of money and all evil is attributed to it

Ludwig Von Mises The Theory of Money & Credit p 93

2— The deities of money have come to possess their souls No religion or philosophy seems to have the power of driving them out —Ruskin

यदि प्रयत्न किया जाय तो मुद्रा के कुछ दोष दूर किये जा सकते हैं। सारास यह है कि मुद्रा-नीति को इस प्रकार काम में लाना चाहिए कि वह मानव जाति का कल्याण करे। नगी मुद्रा न होने बाने साम्य का अधिकारिक उपयोग किया जा सकेगा।

मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of Money)—मुद्रा का वर्गीकरण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार में किया है। परन्तु इसका मुख्य वर्गीकरण निम्न प्रकार में है —



मुद्रा के मुख्यतः दो भेद हैं—(१) चलार्थ मुद्रा और (२) साध मुद्रा।

(१) **चलार्थ मुद्रा (Currency Money)**—जो मुद्रा जिना जिनो सकोच के लेन-देन के प्रयोगों में आती है वह चलार्थ मुद्रा कहलाती है। जैम भारतवर्ष में रुपये कागजी नोट तथा अन्य स्टान्डर्ड बैंकों के चलार्थ या कर्नेन्सी मुद्रा कहलाते हैं। इस वास्तविक मुद्रा (Actual Money) भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा न होने पर ही सम्मान वस्तुओं का क्रय विक्रय, जग्गा का भुगतान तथा बाधारहित कृय दायित्व का समर्थन किया जाता है।

(२) **साध मुद्रा (Credit Money)**—वह मुद्रा जो विनिमय माध्यमता है परन्तु जिसका चलन साध पर निर्भर है साध मुद्रा कहलाती है। जैसे बैंक नोट व ड्राफ्ट, चैक, चिन आर्डर एक्चचेंज इत्यादि। इन **वैच्छिद्र्य मुद्रा (Optional Money)** भी कहते हैं क्योंकि इन वस्तुओं का चलन इच्छा पर निर्भर है यथावत् इन्हें स्वीकार करने के लिये कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं हो पाता।

चलार्थ मुद्रा का वर्गीकरण चलार्थ मुद्रा का रूप (Form) और चलन (Currency) के अनुसार हम पुनः-पुनः वर्गीकरण कर सकते हैं। रूप के हिसाब से चलार्थ मुद्रा दो प्रकार की होती है—(१) धातु मुद्रा और (२) पत्र मुद्रा।

(१) **धातु मुद्रा (Metallic Money)**—वह मुद्रा है जो धातु की बनी या धातु पर छपी हुई हो। जैम भारतवर्ष में चाँद व निकल के दान हुए रुपये, आँटी व पन्नी तथा बिकरन भी बने हुए दानों व दात, पाँच व दस रुपये के सिक्के और साव व पीतल का दाना रुपया एवं नया पैसा, धातु मुद्रा हैं। धातु मुद्रा की विशेष

(Coins) कहते हैं जो सर्वमान्य धातु से निश्चित भार तथा रूप में सरकारों द्वारा (Mints) में दान जाते हैं। उन पर राज्य के चिन्ह, उनका मूल्य, इत्यादि का समय यदि वांछित कर दो जातो है और उनके किनारे वैज्ञानिक ढंग से दम प्रकार बनाये जाते हैं कि उनका अवैधानिक दम पर हात्ता जाना सम्भव न हो सके।

(२) पत्र-मुद्रा (Paper Money) — सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित करेंसी नोट पत्र-मुद्रा कहलाते हैं। इन नोटों के ऊपर राज्य-चिन्ह, मूल्य तथा मूल्य को मुद्रा में चुवाने की प्रतिज्ञा छपी रहती है। आजकल सभी सम्म एवं उन्नत देशों में पत्र-मुद्रा का बढ़ता हुआ प्रचार देखा जाता है। भारतवर्ष में सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित ₹ ५०, ₹ १०, ₹ ५, ₹ १, ₹ ०.५०, ₹ ०.२०, ₹ ०.१० के नोट पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत आते हैं। भारत सरकार के ₹ ५० के नोट के प्रतिष्ठित सभी नोटा वा भुगतान धातु मुद्रा में रिजर्व बैंक क किसी भी निर्णय कार्यालय (Issue office) में मौजने पर नोट बाहक को दिया जा सकता है।

चलन या कानूनी दृष्टि से भी मुद्रा दो प्रकार की होती है—(१) असंमित विधि ग्राह्य मुद्रा (Unlimited Legal Tender Money), और (२) सीमित-विधि ग्राह्य मुद्रा (Limited Legal Tender Money)

विधि ग्राह्य (Legal Tender) मुद्रा का अर्थ—पूर्व इसके कि विधि ग्राह्य मुद्रा के भेद का विवेचन किया जाय, विधि ग्राह्य मुद्रा वा अर्थ समझ लेना चाहिये। विधि-ग्राह्य मुद्रा वे सिक्के तथा नोट हैं जिन्हें विधि (कानून) द्वारा ऋण तथा सेवादि के बदले भुगतान में स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, साल मुद्रा को छोड़कर जिसमें बैंक नोट, ड्राफ्ट, बैंक आदि सम्मिलित हैं, सामान्यतः अन्य सब मुद्रा विधि-ग्राह्य हैं। यदि कोई विधि ग्राह्य मुद्रा को अपने भुगतान में स्वीकार करने में इंकार करे तो यह कानूनी अपराध होगा और उसे कानून के अनुसार दंड भुगतना पड़ेगा।

विधि ग्राह्य मुद्रा के भेद—विधि ग्राह्य मुद्रा के दो भेद किये जा सकते हैं—
(१) असंमित विधि ग्राह्य मुद्रा और (२) सीमित विधि-ग्राह्य मुद्रा।

(१) असंमित विधि ग्राह्य मुद्रा—वे सिक्के तथा कागजी नोट हैं जिन्हें भुगतान में किसी भी मात्रा में स्वीकार करने के लिये कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, भारतवर्ष में विभिन्न मूल्यों के नोट, रूपया तथा यन्त्रों असंमित विधि ग्राह्य मुद्रा हैं क्योंकि इनकी महात्मा से लाखों और करोड़ों रूपयों (अर्थात् असंमित मात्रा में) का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जा सकता है।

(२) सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा—वे सिक्के हैं जिन्हें ऋण भुगतान में किसी निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। जैसे भारतवर्ष में पच्चीस, दस, पाँच, दो व एक नया पैसा, इन्को और पैसा सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा हैं क्योंकि भुगतान में इनका प्रयोग केवल १०, ५० तक ही अनिवार्य रूप से किया जा सकता है।

विधि-ग्राह्यता परिवर्तनशील है—सरकार किसी भी नोट या सिक्के को विधि-ग्राह्य होने से बन्द कर सकती है। जैसे पुराने १८० शेन के रुपये जिनमें ११/१२ गूंड चाँदी थी, अब भारतवर्ष में विधि-ग्राह्य (Legal Tender) नहीं है। सन् १९४६ ई० में भारत सरकार ने ५०० १००० व १०,००० रुपये के नोटों को अविधि-ग्राह्य घोषित कर दिया। साधारणतया नबना सहैय्य चलसर्थ (Currency) के अनुत्पादन रचना (Hoarding) को बन्द करना होता है।

धातु-मुद्रा (Metallic Money)—वर्तमान युग में धातु-मुद्रा ने निक्कों का रूप धारण कर लिया है। प्राचीन समय में मोने-चाँदी जैसे बहुमूल्य धातु को पासी, घड़ा व कीली आदि के रूप में प्रयुक्त करते थे। विनिमय के समय प्रत्येक बार उनकी तोल और परीक्षा करनी पड़ती थी तथा इन कार्य के लिये लोग अपने साथ बाँट, माप, पैमाने और कनोदियाँ लेकर चलते थे। यह मारग्राह्य या तोल द्वारा मुद्रा-प्रणाली (System of Currency by weight) अनुविधाजनक सिद्ध हुई और इनमें व्यापार-विकास में बहुत बाधा पहुँचायी तथा लगी और घोरेबागों की दूनरा को ठगने व घोडा देने का प्रसर दिया। इन बाधाओं से बचने के लिए धातु के पासी और टुकड़ों पर विशेष चिन्ह और मुहर घड़िन की जाने लगी जो उनके तोल और गुडना को प्रमाणित करती थी। सब प्रत्येक बार सिक्कों को तोलने और उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि गिनते मात्र में ही मुद्रा का लेन देन होने लगा। इस प्रकार तोल द्वारा मुद्रा प्रणाली का स्थान गणनग्राह्य या गिनती द्वारा मुद्रा प्रणाली (System of Currency by tale or Counts) में ले निमा। यहाँ से ही सिक्को का प्रारम्भ होता है। वास्तविक में सिक्को के तिनारों से बारीक कटाई (Clipping) होने लगी, तथाब या अन्य नीच रसायन के प्रयोग से धातु की मात्रा कम (Swelling) की जाने लगी तथा उनको रील में डालकर और हिना कर उनमें से छोटे छोटे कण अलग (Abrasion) किये जाने लगे। तब इन सब बाधाओं से बचने के लिये सिक्कों पर अड़्डिन चिन्ह अधिकाधिक जटिल तथा उनके तिनारे घारीदार या गिरीदार (Milled) बनावे जाने लग। इस प्रकार वर्तमान निक्का का जन्म हुआ।

सिक्को (Coins) की परिभाषा—प्रो० जेवन्स (Jevons) ने सिक्को की परिभाषा इस प्रकार दी है। “सिक्के धातु के ऐसे टुकड़े (Ingots) होते हैं जिनका भार तथा गुडता उन पर अड़्डिन मुहर द्वारा प्रमाणित होता है।”¹

आदर्श या उत्तम सिक्का प्रणाली के लक्षण—एक आदर्श या उत्तम सिक्का-प्रणाली में निम्न गुण होने चाहिये—

(१) सिक्को में समानता होनी चाहिये—सिक्कों में समानता होनी चाहिये अर्थात् एक ही मूल्य के सब निक्के तोल और मात्रा में अविभक्त एक-से होने चाहिये।

1—Coins have been defined as “ingots of which the weight and fineness are certified by the integrity of designs impressed upon the surfaces of the metal”

(२) एक ही मूल्य के सब सिक्के तोल में बिल्कुल सही (Accurate) होने चाहिये—एक मूल्य के सब सिक्के तोल में बिल्कुल सही होने चाहिये । यदि कोई सिक्का भारो हल्का और कोई हल्का हुआ तो भारी सिक्का को लोग मलाने लगेंगे और केवल हल्का सिक्का ही बाजार में रह जायगा ।

(३) सिक्के की वनावट, आकृति और तोल सुविधाजनक होना चाहिये—देश में प्रचलित सिक्के का वनावट, तोल और आकृति ऐसी होनी चाहिये जिससे उनके रखने और ले जाने में सुविधा रहे और बेईमान लोग उनमें से धातु न चुरा सकें । प्रायः गोल सिक्के ही इस बाय के लिये उत्तम रहते हैं ।

(४) जायसाजो से नक्ली सिक्को का निर्माण रोका जा सके—सिक्के ऐसे होने चाहिये कि जिनको नकल करके दूसरे सिक्के बनाना लोगों के लिए सम्भव न हो सके ।

(५) कपटपूर्ण सिक्को से धातु के कण हटाने से रोका जा सके—सिक्के ऐसे होने चाहिये कि जिनमें से किसी भी प्रकार में धातु के कण हटाना सम्भव न हो सके ।

(६) सिक्के टिकाऊ होने चाहिये—सिक्के सक्षम होने चाहिये जिससे जितने-जितने रूप रंग और आकार में भीषण हो कोई बिघोष खराबी न आयें ।

(७) सिक्के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक होने चाहिये—सिक्के उन्हें प्रचलित करने वाली सरकार तथा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों का कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक होने चाहिये ।

(८) सिक्को सरलता में पहचाने जा सकें—सिक्के ऐसे होने चाहिये कि जितने लोग सरलता से पहिचान सकें और अच्छे बुरे का भेद कर सकें ।

धातु-मुद्रा या सिक्को से लाभ (Advantages)

१—सिक्को के प्रयोग के कारण धातु के तोलने और परखने की आवश्यकता नहीं रहती ।

२—सिक्को की सुदृढ़ता तथा भार मरम्भार द्वारा प्रमाणित होने के कारण मनुष्य धोमियावा से सुरक्षित रहते हैं ।

३—सिक्को के बिना वैज्ञानिक ढङ्ग से मने होने के कारण उनकी गणना करना कठिन होता है तथा काट-छाँट कर उनमें से धातु के चोरी हो जाने की सम्भावना नहीं रहती ।

४—सिक्के मिश्रित धातु में बनाये जाने के कारण बड़े होते हैं जिससे सिक्का की पिघावट कम होती है और मूल्यवान् धातु नष्ट होने में बच जाती है ।

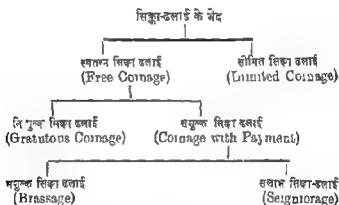
५—सिक्को का आकार ऐसा होता है कि उनमें प्रयोग से जनता को बड़ी सुविधा रहती है ।

६—सिक्को पर सुन्दर चित्र और राष्ट्रीय स्मारक अंकित किये जा सके हैं । जिससे उनका ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ाया जा सकता है ।

७—सिक्के अधिक टिकाऊ, सरलता में पहिचाने जाने वाले तथा सुविधाजनक संयोजन करने योग्य होते हैं ।

सिक्का-दलवाई (Coinage)—धातु के किसी निश्चित तोल के टुकड़े को मुद्रा का रूप देने और उसके भूलभ्रष्ट आदि को उस पर अंकित करने को सिक्का-दलवाई या टंकन कहते हैं। आवश्यकतानुसार के सभी राज्य देशों में यह कार्य वहाँ की सरकार द्वारा सम्पन्न होता है जिसमें सब निष्पक्ष ही प्रचार से और एक ही मूल्य के हो सकें और तोला को उबला गुदना और भार जानने और तोलने की आवश्यकता न हो। जिस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे टंकशाला (Mint) या टंकशाला कहते हैं। हमारे देश में मुख्य टंकशालें बम्बई और कलकत्ता में हैं।

सिक्का-दलवाई के भेद—सिक्का को दलवाई निम्न प्रकार से होती है —



(१) **स्वतन्त्र सिक्का दलवाई (Free Coinage)**—जब सरकार द्वारा यह अधिकार है कि जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी धातु ले जाकर सरकारी टंकशाला में उसके सिक्के ढलवाने, तो इस हम स्वतन्त्र सिक्का दलवाई या प्रवाद्य टंकन कहेंगे। स्वतन्त्र सिक्का दलवाई प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपना चाही या मन कोई धातु ले जाकर सरकारी टंकशाला में सिक्के ढलवाए। भारतवर्ष में सन् १८६३ में हर्श (Hersch)) कमेटी की सिफारिश के अनुसार रुपये की स्वतन्त्र सिक्का दलवाई बन्द कर दी गई। इङ्ग्लैंड में सन् १६३१ तक स्वतन्त्र सिक्का दलवाई प्रचलित था।

(२) **सीमित सिक्का दलवाई (Limited Coinage)**—जब जनता को स्वतन्त्र मुद्रा-दलवाई का अधिकार प्राप्त न हो, अर्थात् सरकार धातु सरोद कर अपनी ही ओर से सिक्के ढालती हो तो इसे सीमित सिक्का-दलवाई कहेंगे। भारत-वर्ष में सन् १८६३ के परवाना और इङ्ग्लैंड में सन् १६३१ के बाद सीमित सिक्का दलवाई हो गई।

स्वतन्त्र सिक्का-दलार्ड के प्रकार—जब सिक्का-दलार्ड का अधिकार सरकार द्वारा जनता को होता है, तो सरकार सिक्के निःशुल्क या मुफ्त में भी डाँट सकती है अथवा सिक्के ढालने वाले से केवल वास्तव्य या इन्गे भी अधिक वसूल कर सकती है। जो फीस वसूल की जाती है उसे सिक्का ढालने या बनाने की फीस अथवा शुल्क (Mintage) कहते हैं। प्रायः यह फीस अलग न लेकर धातु में गे ही काट ली जाती है। फीस लेने या नहीं लेने की दृष्टि में सिक्के-दलार्ड के तीन भेद किये जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(अ) निःशुल्क सिक्का-दलार्ड (Gratuitous Coinage)—जब सरकार सिक्का ढालने के लिये जनता से कुछ भी सागन वसूल नहीं करती, तब इसे निःशुल्क सिक्का दलार्ड कहते हैं। जब सिक्का को दलार्ड निःशुल्क होता है, तो जितनी धातु का एक सिक्का बनता है उगके मूल्य और सिक्के के अंकित मूल्य में कोई अन्तर नहीं होता। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ ई० के पूर्व एक फीस मॉन्गे के बदले में टंकसास ३ पौण्ड, १७ शि० और १०३ पें० नुस्त दे देती थी। कुछ समय पूर्व एक इङ्ग्लैंड और अमेरिका में यह प्रचाली प्रचलित थी।

(ब) राशुल्क सिक्का दलार्ड (Brassage)—जब सरकार सिक्का दलार्ड पर उनना ही शुल्क लेती है जितना सिक्का ढालने में उसका खर्च पड़ता है, तो उसे राशुल्क सिक्का-दलार्ड या टाँका कहते हैं। इस प्रथा के अन्तर्गत सिक्का-दलार्ड का शुल्क या फीस धातु में से काट लेते हैं। अतः इस प्रकार जो सिक्के बनते हैं, उनके अंकित मूल्य और धातु के वास्तविक मूल्य में कुछ अन्तर आ जाता है। काल में इसी प्रथा का प्रचार है।

(ग) सन्नाभ सिक्का-दलार्ड (Seigniorage)—जब सरकार सिक्का-दलार्ड पर लागत-व्यय से अधिक मूल्य वसूल करती है, तो इसे सन्नाभ सिक्का-दलार्ड या सिक्का दलार्ड-कर कहते हैं। उदाहरणार्थ, सन् १९४३ के पूर्व रुपये में १९५ ग्रेन चाँदी तथा १५ ग्रेन अन्य धातु थी, उसमें चाँदी का मूल्य केवल ६ पाने २ ३/४ पाई या बिन्दु रुपये का अंकित मूल्य १६ पाने होने में उस पर ६ पाने ६ ३/४ पाई प्रति रुपया सिक्का-दलार्ड या टङ्कण लाभ लेती थी। इस प्रथा के अन्तर्गत सिक्के का अंकित मूल्य इसकी वास्तविक धातु के मूल्य से अधिक होता है। इस प्रकार सिक्के को पिघला कर धातु प्राप्त करने का साधन नहीं रह जाता। यह शुल्क जवता से दो प्रकार में वसूल किया जाता है : (१) शुल्क के मूल्य के बराबर धातु निकाल कर उससे कम मूल्य वाली धातु (Alloy) मिला दी जाती है। (२) निर्धारित शुल्क अलग से वसूल कर लिया जाता है। सिक्के-दलार्ड में लाभ लेने की प्रथा केवल इसलिये प्रचलित हुई कि जनता टंकमालों पर अत्यधिक काम न लादे। स्वतन्त्र सिक्का-दलार्ड मुद्रा-स्फीति (Inflation) व चलनाधिक्य (Over-issue) को रोकती है।

सरकार प्रत्येक सांकेतिक (Token) सिक्का ढालने में यह लाभ वसूल करती है। हमारे देश में तो सरकार अत्यधिक सिक्का-दलार्ड लाभ वसूल करती है।

उदाहरण—मान लीजिये वास्तव्य में स्वतन्त्र सिक्का-दलार्ड-प्रथा प्रचलित है। यदि आप चाँदी देकर बिना किसी खर्च के उसके सिक्के ढलवा सकते हैं, तो यह

नि गुरुक मुद्रा-प्लाट बड़ी जायगी। यान नीजिये चाँदी का एन रुपया बनान में दो घान व्यय होत है। यदि सरकार जनता से दो घान ही वसूल करे तो उस 'मसूक' मिस्का प्लाट बटव और उस मूल्य का टकमाती या टकन व्यय अवका टीका (Brassage or Mintage) कह्ये। यदि सरकार दो घान व्यय करे परन्तु जनता से नान घान वसूल करे तो उस नानास मिस्का प्लाट कह्ये और एक घान की 'टकमाती' नाम (Seigniorage) कह्ये।

मिक्को की निरुप्यता या स्वाटापन (Debasement)—सरकार द्वारा मिक्का का नान या घुड़ना अवका दोनों की उस करने की मिक्के की निरुप्यता कह्ये है। उपा आधिक गवट के समय सरकार मिक्के कापन में बाबूत द्वारा निश्चिन घण्टा घानु की माथा का कम बरक गर्नी घानु की प्रतिक मिनाबट बर दता है और कभी कभी घण्टा घानु कम बरक बनव भाग का भी कम कर दता है। अस्तु, मुद्रा के दालन में घण्टी घानु का कम करने की क्रिया को निरुप्यता (Debasement) कह्ये है। उदाहरणार्थ भारतीय मुद्रा-बाबूत के अनुसार शव म मन् १६८१ से पूर्व १६५५ सेन मुद्रा चाँदी और १५ सेन मिनी हुई घानु थी। परन्तु उगव पञ्चान् टगम १० सेन मिनी हुई घानु रह गई। इसी का 'निरुप्यता' कह्ये है। निरुप्यता अनियमित हयी है, अस्तु सरकार व अनिरित अव्य अतिथा द्वारा मर बाव अवध मर दादनाय हाता है। गरम द्वारा निरुप्यता राक्षसा के समय म हूमा पगनी थी। जनन-नामक मामन म सरकार इस प्रकार के अनियमित कार्य नहा करती, क्योंकि सरकार का माथ उठ जानी है और जनता में समताप उत्पन्न हो जाता है। जनता द्वारा जाना मिक्का बनान तथा मिक्का की बापन तथा छीनकर निगाहन पर बर दव्य किया जाता है। फिर भी नाम निम्नलिखित विधिया म यह अवध बाव करने रह्ये है—

(१) आवर्तन (Clipping) मिक्का के विनाश म तब बाहु या अन्य भाग म बहुत सूक्ष्म भाग बतर किया जाता है।

(२) धुनन (Scratching)—नेजव अवका अव्य सामायनिक पदावों में मिक्का को टारकर घानु निवार ली जाती है।

(३) मघर्ष (Abrasion)—घुड़ने मिक्का को एक पैनी म टारकर बार म हिताया जाता है जिसम घानु के बग बट जाते हैं।

मिक्को की निरुप्यता का राहत का उपाय—इस प्रकार मिक्का की बटाई घांर मिनाई का रोवन के निम सरकार मिक्का व विभाग पर घास या घिरी (Milling) दालने लगी तथा उनको घुड़ना एवं तान का प्रमाणित करन के लिये इन पर मुहर चिह्न घट्टित किये जल लगे।

मुद्रा हान, निरुप्यता और अवमूल्यन में अन्तर

(Difference between Depreciation, Debasement & Devaluation)

सरकार द्वारा अवका अन्य निर्द्दी वारग्या में मुद्रा के आवश्यकता म अतिव प्रमाण (मुद्रा स्फीति) के कारण मुद्रा के मूल्य में हान हो जान अवान् उनका प्माणित निर जान ना मुद्रा हान (Depreciation) कह्ये है। जैसे मउ महापुड म तथा

उसके बाद आवश्यकता से अधिक मुद्रा के प्रचलन अर्थात् मुद्रा-म्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य गिर गया यानी उसकी क्रय-शक्ति में ह्रास हो गया जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई ।

सरकार द्वारा सिक्के के तोन (Weight) या घुबला (Thickness) अथवा दोनों को कम करने को निकृष्टता (Debasement) कहते हैं । उदाहरणार्थ, सन् १६४१ से पूर्व हमारे देख के रुपये में १६५ ग्रेन सुद्र चांदी गया १५ ग्रेन खोद होता था । इनके पदनाम्न उसमें चांदी और खोद की मात्रा ६०-६० ग्रेन कर दी गई । सन् १६४७ के पदचक्र जो रुपये जारी किये गये हैं उनमें चांदी नहीं के बराबर है अर्थात् वह गिनाटा का है । इस प्रकार भारतीय रुपया सन् १६४१ के पदचक्र 'निकृष्ट' होता चला गया ।

सरकार द्वारा देश के विनिमय दर को कम करने को अवमूल्यन (Devaluation) कहते हैं । यह तब किया जाता है जबकि देश के भीतर का मूल्य-स्तर निरन्तर प्रमत्त करने पर भी न घटता हो और इस कारण विदेश की सामान निर्यात करने में कठिनाई पड़ती हो । अवमूल्यन करने में इस देश की मुद्रा विदेशियों के लिये मजबूती हो जाती है और वे इस देश में सामान खरीदने लगते हैं । इसके विपरीत देश के लोगों के लिये विदेशी मुद्रा मजबूती हो जाती है और वे विदेशों में सामान खरीदना कम कर देते हैं । इस प्रकार इस देश का निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाता है । १७ सितम्बर १९४६ को इंग्लैंड ने गीण्ड स्ट्रलिंग की विनिमय दर डालर के रूप में ४.०३ से घटा कर २.८० कर दी । इसी प्रकार आखण्ड वर्ष से भी १६ सितम्बर को रुपये की विनिमय दर डालर के रूप में ३०.२२५ सेटों में घटा कर २१ गटा के बराबर कर दी । इसी को 'अवमूल्यन' कहते हैं ।

सिक्कों के भेद—सिक्के दो प्रकार के होते हैं—

(१) प्रामाणिक सिक्का (Standard coin) और (२) साकेतिक सिक्का (Token Coin) ।

(१) प्रामाणिक सिक्का (Standard Coin)—प्रामाणिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य (Face Value) उसके वास्तविक मूल्य (Intrinsic Value) के बराबर होता है, जो देश का मुख्य सिक्का (Principal Coin) होता है, जो असंमित विधिप्राप्त (Unlimited Legal Tender) होता है तथा जिसकी स्वतन्त्र डलाई (Free Coinage) होती है । इसका अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर होने के कारण इसे पूर्णकाय सिक्का (Full Bodied Coin) कहते हैं । सितम्बर सन् १९३१ के पूर्व इंग्लैंड में सोने के सिक्के प्रामाणिक सिक्के थे । आखण्ड वर्ष से मही अथवा कोई भी प्रामाणिक सिक्का नहीं है । हमारा प्रामाणिक सिक्का रुपया है, क्योंकि वह देश का प्रमुख सिक्का है और असंमित विधिप्राप्त है । यह साकेतिक सिक्का भी है, क्योंकि इसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है और इसकी सीमित मुद्रा-डलाई होती है । इन मिश्रित रुपए के कारण ही वे साकेतात्मक प्रामाणिक सिक्का (Token Coin) कहते हैं ।

सांकेतिक सिक्का (Token Coin) उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, जो देश का सहायक सिक्का (Subsidiary Coin) होता है, जो सीमित विधिग्राह्य (Limited Legal Tender) होता है तथा जिसकी सीमित मिकदा-दमाई होती है। भारतवर्ष में चक्की, हक्की पैसा, दस, पाँच दो एक नया पैसा आदि सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, क्योंकि ये सीमित विधिग्राह्य हैं अर्थात् किसी का इन्हें मुद्रास्नान में स्वीकार करने के लिये केवल १० रुपये तक ही वास्तविक आग का व्यवसाय किया जा सकता है। ये सहायक सिक्के हैं क्योंकि ये रुपए व सन्निहित चक्रवर्त हैं। सांकेतिक सिक्का को आदेश या वाचनिक सिक्के (Fictitious Coins) भी कहते हैं, क्योंकि उनका मूल्य सिक्के के वास्तविक मूल्य पर निर्भर न रहकर राज की आज्ञा पर निर्भर रहता है। सांकेतिक सिक्का का निर्माण मुख्यतः तीन कारणों से होता है। पहला कारण यह है कि पूर्णकाल्य सिक्का की आवश्यकता पर सिक्का कम पड़ा है। दूसरा, सांकेतिक सिक्का के चलने की आसक्ति कम होती है। तीसरा, आर्थ-शास्त्री राज की विविध सुविधापूर्वक करने के लिये ये सिक्के बनाये गए। बम्बई-कम्पनी दस सिक्का व पाण्डे के मूल्य में इनकी वृद्धि हो जानी है कि ये पूर्णकाल्य सिक्के हो जाते हैं। तब ये समाप्त भी जा सकते हैं और अंकित भी बिये जाते हैं।

प्रामाणिक और सांकेतिक सिक्कों का भेद

प्रामाणिक सिक्का	सांकेतिक सिक्का
१—प्रामाणिक सिक्का का अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य समान होता है।	१—सांकेतिक सिक्का का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक होता है।
२—ये देश के प्रमुख सिक्के होते हैं।	२—ये देश के सहायक सिक्के होते हैं।
३—ये सीमित विधिग्राह्य सिक्के होते हैं।	३—ये सीमित विधिग्राह्य सिक्के होते हैं।
४—इन सिक्कों की स्वतन्त्र मुद्रा-दमाई होती है।	४—ये सिक्के सरकार द्वारा ही बनाये जाते हैं। जनता को स्वतन्त्र सिक्का दमाई का अधिकार नहीं होता।
५—इन सिक्कों द्वारा समस्त वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य तथा कर निर्धारित किया जाता है।	५—अधिकतर सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य इन सिक्कों द्वारा निर्धारित नहीं होता।
६—ये सिक्के नगरे उत्तम धातु के बनाये जाते हैं।	६—ये प्रायः बनावटी या कम मूल्य की धातु से बनाये जाते हैं।

रुपया किस प्रकार का सिक्का है—प्रामाणिक या सांकेतिक ?—भारतीय मुद्रा-नियन्त्रण में रुपये का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें प्रामाणिक तथा सांकेतिक दोनों ही प्रकार के गुण समाविष्ट हैं। असीमित विधिग्राह्यता एवं देश का प्रमुख सिक्का होने इसे प्रामाणिक सिक्कों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें सांकेतिक सिक्कों के गुण भी पाये जाते हैं। इसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता तथा इसकी सीमित मुद्रा-दमाई इसे सांकेतिक सिक्कों की श्रेणी में रखते हैं। अतः,

यह स्पष्ट है कि रुपया न तो प्रामाणिक सिक्का ही है और न साकेतिक ही। इन मिथित मुद्रों के कारण ही यदि इसे सकेतारूपक प्रामाणिक सिक्का (Token Standard Coin) कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा ?

भारतवर्ष की वर्तमान सिक्का प्रणाली—भारतवर्ष की वर्तमान सिक्का-प्रणाली रुपये का प्रमुख स्थान है। रुपया ही देश का प्रामाणिक सिक्का (Standard Coin) है, क्योंकि यह असीमित विधि-ग्राह्य है तथा मंगल धातुओं और मेदाओं के मूल्य का मापक है न इसी से मूल्य के माप अन्य सहायक सिक्कों के मूल्य सम्बन्धित है। सहायक सिक्का में हमारे देश में अठन्नी, चवन्नी, इकन्नी, दम, पाँच, दो व एक रुपये के सिक्के हैं। ये सिक्के अधिकतर लघु राशि के भुगतान के निम्ने प्रयुक्त किये जाते हैं। ये साकेतिक सिक्के (Token Coin) कहलाते हैं। रुपये का प्रकृत-मूल्य उसके धातु मूल्य से अधिक है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व रुपये में ११/१२ विघुट बाँदी होती थी, परन्तु युद्धकाल में इसमें से बाँदी की मात्रा कम कर दी गई। भारतवर्ष में गिनट का रुपया प्रचलित है जिसका वास्तविक अर्थात् धातु-मूल्य एक दो पीतल तबले के बराबर जाते हैं। ये प्रायः सस्ती धातु के डाले जाते हैं।

भारतवर्ष में सन् १८६३ ई० तक तो स्वतन्त्र सिक्का-डलाई (Free Coinage) थी, परन्तु इसके गदबात् हर्षोल कमोशव की मिकारिश के अनुसार स्थगित कर दी गई। अब हमारे देश में सीमित सिक्का डलाई (Limited Coinage) है, अर्थात् रुपये या सहायक-सिक्कों में से किसी के लिये भी 'स्वतन्त्र सिक्का डलाई' नहीं है। सिक्के बनाने का कार्य भारत सरकार या रिजर्व बैंक का है और ये सरकारी टकसालों में ही डाले जाते हैं।

भारतीय सिक्कों का धाकार दो प्रकार का है—गोल या वर्गाकार। सिक्कों के एक ओर उनका नाम, वर्ष और मूल्य तथा दूसरी ओर भारतीय प्रजातन्त्रात्मक राज्य का प्रशोक चिन्ह प्रकट रहता है। रुपया असीमित विधि-ग्राह्य है तथा अन्य सहायक-सिक्कों सीमित विधि-ग्राह्य है। सहायक सिक्कों को केवल

कुछ देशों के प्रामाणिक सिक्के नीचे दिये जाते हैं :—

इंग्लैंड का पौंड स्टर्लिंग	ऑस्ट्रिया का क्रोन	अर्जेंटाइना का पिरो
फ्रांस/लिया का पौंड (फ्रांस/लिया का)	स्पेन का पेसेटा	ब्राजील का क्रुजेरो
अमेरिका का डॉलर	बेल्जियम का बेल्लम	इटली का लीरा
नैनेडा का डॉलर (नैनेडा का)	हॉलैंड का ग्लूडेन	पाकिस्तान का रुपया
जापान का ग्रैंड	स्वीडन का क्रोना	(पाकिस्तान)
जर्मनी का मार्क	ज्यापान का येन	बर्मा का रुपया (बर्मा)
रूस का रुबल	तुर्की का पियास्त्रे	लका का रुपया
		(लका)

१० रुपये तक के मुगलान के लिये स्वीकार करने में कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है। देश में गिरफ्तार होने का प्रबंध आदि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया करता है तथा उसी के पास इनका हिस्सा रहता है।

भारतवर्ष में टक्कान—भारत सरकार की दो मुख्य टक्कान हैं एक बम्बई में और दूसरी कनकन में घाँसीपुर में। बम्बई का टक्कान प्रतिदिन १० लाख सिक्के तैयार कर सकती है और घाँसीपुर की नई टक्कान प्रत्येक आठ घंटे के समय में १९ लाख सिक्के तैयार कर सकती है। हैदराबाद में भी भारत सरकार की टक्कान है जोकि १ अप्रैल १९५० में बम्बई टक्कान की छाया हुआ गई। यह एक दिन में ३ लाख सिक्के तैयार कर सकती है। इस प्रकार भारतवर्ष में प्रतिदिन ९५ लाख सिक्के तैयार किए जा सकते हैं।

पत्र मुद्रा (Paper Money)

पत्र मुद्रा का जन्म एवं विकास—पत्र मुद्रा जिसको हम नोट कहते हैं प्राचीन काल में ही प्रचलित है। मुद्रा के विद्याविद्या का विचार है कि पत्र मुद्रा का जन्म सब प्रथम मधी शताब्दी में चीन में हुआ जहाँ काल में मुद्रा जबकि यह और चीन में मित्रता के भावों के कारण चीन के लोग को चीन के अनुविषय उपनष्ट हुई। इस पत्र मुद्रा जापान और फारस में भी इनका प्रयोग होने लगा था। और धीरे धीरे एशिया के अधिकतर देशों में इनका प्रचार हो गया। एशिया के बाद फिर यूरोप के देशों में भी पत्र मुद्रा चलने लगा। यूरोप में इस प्रथा के प्रचार का थोड़ा व्यापारिक और स्वयंसेवकों को है। इन लोगों का मान्य रहती थी। अतः लोग इनके पास अपना राशि छोड़ देने के और इनसे प्रमाण पत्र के लिये और आवश्यकता पड़ने पर इन पत्रों का दिखाने पर अपनी राशि वापस प्राप्त कर लेते थे। जो लोग का यह विचार हुआ कि प्रमाण पत्र के दिखाने ही उनका राशि वापस मिल जावेगी तो ये अपने मौलिक वस्तु इन प्रमाणपत्रों का लाने लगे थे। यही न जाने का चलन प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार १७ वीं शताब्दी के अन्त तक उत्तरीय देशों में परिवर्तनशील पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money) का जन्म हो गया था और १८ वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सरकार की शक्ति के कारण अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Money) का चलन भी प्रारम्भ हो गया था। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप रंग के नोट बनाए जाते थे। प्रथम महायुद्ध काल में तो नोटों का प्रचार बहुत हो गया था।

पत्र मुद्रा के यदुत हुए प्रचार के कारण—प्राथमिक युग में मध्यम मूल्य देशों में पत्र मुद्रा का प्रयोग उत्तरीय देशों में होता जा रहा है। इसका प्रयोग कारण यह है कि वर्तमान युग में व्यापार उत्तरीय देशों में अधिक मात्रा में आया जाता है। इसी वृद्धि हो गई है कि कच्चे मान और चीन का मुद्रा में हो काम चलाना असम्भव है। चीन और चीन की प्रति भी मिलने लगे हैं कारण इनकी मुद्रा का मात्रा भी अधिक मात्रा में मिलने लगी है और इससे इन चीन का मुद्रा में समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण होता हो सकता है। पत्र मुद्रा को पूर्ण में आवश्यकताओं के अनुसार महत्व ही वृद्धि का जा सकता है। अतः इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। वस्तुतः आज के समय में पत्र मुद्रा का प्रयोग मध्यम का बहुत माना जाता है। भारतवर्ष में मार्च सन् १९५२ में २००० करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलित थी जिसमें १२०० करोड़ रुपये के नोट और ८०० करोड़ रुपये के कान्वार मिलते थे।

पत्र-मुद्रा छापने का अधिकार—धातु मुद्रा की भांति पत्र-मुद्रा छापने का अधिकार प्रायः केवल सरकार को ही होता है, परन्तु प्राधुनिक युग में यह अधिकार प्रायः देश के केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होता है। भारतवर्ष में यह अधिकार रिजर्व बैंक को है।

पत्र-मुद्रा के लाभ (Advantages)—पत्र-मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं :—

१. **वहनीयता**—पत्र-मुद्रा बहुत हल्की होती है और इसमें वहनीयता (portability) का गुण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हजारों पावों रुपये के नोट सरलतापूर्वक कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाये जा सकते हैं। एक सौ रुपये के नोट में १०० रुपये के सिक्कों की तुलना में कुछ भी बजन नहीं होता, अतः उनके द्वारा दूर तक भुगतान सरलता में व कम खर्च में किया जा सकता है।

२. **बहुमूल्य धातु की वचत**—पत्र-मुद्रा से सोना-चांदी की वचत होती है, क्योंकि धातु मुद्रा चलन में चिपावट में होने वाली हानि नहीं होती। इस प्रकार से चलन में बचाई गई धातु अथवा रूपा-कौशन के कार्यों में अथवा औद्योगिक विकास में लगाई जा सकती है। आदम स्मिथ ने लिखा है कि “पत्र-नोट धातु-मार्ग की भांति होते हैं जिनकी मोचे की भूमि को भी काम में लाया जा सकता है और उन पर अनेक आदि उत्पन्न करने अनुप्य की दूसरी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है।”

३. **मितप्रयत्ना**—पत्र मुद्रा बनाने में खर्च बहुत कम पड़ता है। लाखों, करोड़ों रुपये के नोट छापने में केवल कागज, स्पाही और बौटा धम व्यय होता है। यदि धातु के सिक्के बनाना हो, तो इतनी ही धातु चाहिए जिसका प्राप्त करना सरल नहीं।

४. **सामाजिक लाभ**—पत्र-मुद्रा द्वारा समाज को भी लाभ होता है। प्रथम, धातु-मुद्रा की गिराई की हानि की वचत होती है। दूसरे, धातु-मुद्रा डालने में जो आवश्यक श्रम, पूँजी आदि लगते हैं उनको किसी दूसरे जन-उपयोगी उद्योगों में लगाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा चलन में बचाई मूल्यवान धातुओं को देश में उद्योगों की वृद्धि के लिये तथा विदेशों में आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है अथवा उनका विदेशों में निवेश कर अधिक आय कमाई जा सकती है।

५. **सुरक्षा**—रुपयों की अपेक्षा नोटों के कूटे या चुराये जाने का भय कम रहता है। रुपये का वजन दिखाया नहीं जा सकता। हजारों, लाखों रुपये के नोट घेब में डाले जा सकते हैं और बिना किसी सन्देह के दूसरे स्थान पर ले जाये जा सकते हैं। इसमें केवल जब कतरने वालों से ही सावधान रहना पड़ता है।

६. **नोच**—पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि आवश्यकता-नुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यह बात धातु मुद्रा में नहीं पाई जाती। आवश्यकतानुसार नोटों को बढ़ाने में केवल कागज और स्पाही की आवश्यकता होती है।

७. **मकट काल में सरकार की सहायता**—मुद्रा काल में जब राष्ट्र को मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है और प्रजा ग कर या शरा के रूप में आवश्यक धन प्राप्त नहीं होता, तब इसकी पूर्ति केवल पत्र-मुद्रा द्वारा ही की जा सकती है।

८. गिनने व परखने की सुविधा—पत्र मुद्रा के भ्रगव वे अधिक सख्या में रुपये का गिनना व परखना बैंकों के लिये कठिन कार्य हो जाता है। बड़ी सख्या में रुपया का भुगतान अधिक मूल्य वाले नोटों से किया जा सकता है जिससे बैंकों का गिनने का कार्य श्रान भी सरल हो जाता है।

९. मूल्यों के परिवर्तन पर नियंत्रण—धातुओं के मूल्य में कभी-कभी अत्यधिक परिवर्तन हो जाते हैं जिससे मूल्यों पर बड़ा बम्भीर प्रभाव पड़ता है। मुद्रा रूप में नियन्त्रित पत्र-मुद्रा के प्रयोग से मूल्य के परिवर्तन को नियन्त्रित रखा जा सकता है।

पत्र मुद्रा की हानियाँ (Dis-advantages)—जहाँ पत्र मुद्रा के इतने लाभ हैं वहाँ उनकी कुछ कमियाँ भी हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

१. सीमित चलन—पत्र-मुद्रा का वास्तविक मूल्य सूख होता है। अतः इसका चलन देश की सीमा तक ही सीमित रहता है। देश के बाहर इसको कोई भुगतान में स्वीकार करने के लिये मँथार नहीं होता। इसलिये नोट 'राष्ट्रीय-मुद्रा' कहलाते हैं। इनका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कुछ भी नहीं होता।

२. सामाजिक मूल्य स्थिरता की कमी—धातु-मुद्रा की अपेक्षा पत्र मुद्रा में मूल्य-स्थिरता की कमी है, क्योंकि पत्र-मुद्रा का चलन सरकारी नीति पर अवलम्बित है तथा अर्थिक प्रसार होने में इसके मूल्य का ह्रास होता है और वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं जिससे सामाजिक तथा अर्थिक हानि होती है। इस प्रकार की सम्भावना धातु-मुद्रा में नहीं होती, क्योंकि मुद्रा धातुओं का उत्पादन सीमित है।

३. पत्र-मुद्रा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है—नैसर्गिक या मानवीय कारणों से भोग जाने पर नोट खोज हो पड़ाव हो जाते हैं। उन पर अधिक सख्या मिट जाने पर उनका कोई मूल्य नहीं रहता। भिन्न इतने शीघ्र नष्ट नहीं हो सकते। ऐसी दशा में पत्र मुद्रा समाज में केवल धोखाधड़ी है।

४. सरकार की नीति पर पूर्णतया अवलम्बन—पत्र-मुद्रा अर्थी शासकी नोटों का चलन पूर्णतया सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। यदि कभी सरकार नोट को अर्थी धोखाधड़ी कर दे तो जनता के पाम रहे हुए नोटों का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। उनके पाम केवल कागज के टुकड़े शेष रह जाते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। यह बात निम्नो के साथ नहीं होगी। उनके अर्थी धोखाधड़ी हो जाने पर उन्हें पाम कर उनकी धातु को बाजार में बेचा जा सकता है। कुछ लोगो का तो यह कहना है कि "पत्र-मुद्रा किसी देश की सबसे अधिक अर्थी बोझारी है। जितना बट्ट किसी भवकर से भयकर बोझारी में किसी व्यक्ति को होता है उससे भी अधिक बट्ट पत्र मुद्रा में समाज को हो सकता है"।

५. पत्र-मुद्रा का मूल्य सरकार को साक्ष पर निर्भर है—पत्र-मुद्रा का वास्तविक मूल्य नहीं होने से इसका मूल्य केवल सरकार की धयवा पत्र-मुद्रा चलाने वाले सख्या की साक्ष पर निर्भर रहता है।

६. चलनाधिक्य (Over-issue) का भय—पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें चलनाधिक्य का भय रहता है। अब सरकार लालचवश या अवयवश इसकी मात्रा इसनी अधिक बढ़ा देती है कि उसका परिणाम मुद्रा-स्फीति

नोट छापकर चलाता है और रिजर्व बैंक व गवर्नर इन बातों का भयान देखते हैं कि नाट बाहक का सींग पर उस नोट के बदल में उस पर अधिक मूल्य रूप के सिक्कों में बिना भी निम्न-व्यापार पर चुकाया जावेगा। धातु भारतवर्ष में २ ½ १० और १०० रूपय के नाट परिवर्तनशील कावजी नोट (पत्र मुद्रा) है जिनको कभी भी राय के विना गवर्नर चलाया जा सकता है। ये नाट धातु मुद्रा के साथ साथ नो देण में चलाये जाते हैं।

प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में भेद

परिवर्तनशील पत्र मुद्रा वास्तव में विस्तृत प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के समान ही होता है। जिस प्रकार प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बदल में किसी भी समय धातु मुद्रा का धातु प्राप्त हो जा सकता है। उसी भाँति परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बदल में भी किसी भी समय धातु मुद्रा या धातु प्राप्त हो जा सकता है। इतना हाट हट भी पत्र मुद्रा मुद्रा का प्रतिनिधि नहीं होता। इसमें प्रत्येक रूपय के नोट के लिये एक रूपय का सिक्का सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ इस सिद्धान्त का मान कर चलाया जाता है कि सब बातें एक साथ प्रदान नहीं होनी चाहिए वस्तु के लिये नहीं। इसलिये पट्टा के सिक्के पूरी मात्रा में मुद्रा न रखकर उनको ही मुद्रा रखी जाती है जिसमें प्रस्तुत किया जाना सम्भावित मात्रा के लिये मर्यादित न हो। इस प्रकार परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के लिये मर्यादित मर्यादित सिद्धान्त स्थापित कर लेते हैं जिससे कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के द्वारा होता है।

प्रत्येक के द्वाय बैंक या सरकार अनुभव से जानती है कि कुल प्रचलन के कितने प्रतिशत के नाट तक समय में भुगतान के लिये आवश्यक हैं और उदा अनुमान के आधार पर एक या अधिक नुत प्रचलन का निर्दिष्ट प्रतिशत धातु मुद्रा या धातु में रूप में जमा रखती है। इन जमा का सुरक्षित रूप या निधि (Reserve) कहते हैं। ये भाग राज्य प्रतिभूतियाँ (Govt Securities) के रूप में रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य प्रतिभूतियाँ का मुद्रा बाजार में बेचकर बाजार के भुगतान के लिये तुरन्त राशि प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुत चलाय (Currency) का वह भाग जिसके लिये प्राणागिक धातु मुद्रा या धातु सुरक्षित रखी जाती है रक्षित भाग (Covered) या धातु निधि (Metallic Reserve) कहलाता है तथा जो भाग केवल राज्य प्रतिभूतियाँ (Govt Securities) के आधार पर ही प्रचलित होता है उसे अरक्षित या विश्वासायित भाग (Uncovered or Fiduciary Issue) कहते हैं। उदाहरण के लिये १०० रूपय के नोट की पत्र मुद्रा बाजार में है। उनमें लिये काय में ४० रूपय की धातु मुद्रा या धातु सुरक्षित है तथा ६० रूपय की राज्य प्रतिभूतियाँ हैं जो ४० रूपय वाले भाग को रक्षित भाग (Covered Issue) या धातु निधि (Metallic Reserve) तथा ६० रूपय वाले

१. राज्य प्रतिभूतियाँ (सरकार सिक्काटिका) का अर्थ है सरकार का दिया गया कर्ज के प्रमाण-पत्र जैसे (Debentures Bonds etc.)। सरकार का कर्ज देने पर या सरकार द्वारा कर्ज का प्रमाण-पत्र मिलता है उसे राज्य प्रतिभूति या सरकारी सिक्काटिका कहते हैं।

भाग को अरक्षित (Uncovered) या विश्वासार्थित (Fiduciary) भाग कहें।

उनमें एक प्रवर्तनशील देशों में पत्र मुद्रा का रक्षित कोष १५ से २५ प्रतिशत तक पुराना समझा जाता है, परन्तु अरक्षित एवं आर्थिक दृष्टि में खिद्य हुए देशों में यह कोष ५० प्रतिशत तक होता है। भारतवर्ष में मोन और स्टैंडार्ड द्वारा ४० प्रतिशत रक्षित कोष की मांग रखी गई है तथा चलाय का ५० प्रतिशत भाग अरक्षित है।

लाभ व हानि—परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वास्तव में निर्धारित धातु मुद्रा या धातु कोष में रख कर नेप भाग को प्रतिभूतिपत्र (Security) में लगा दिया जाता है जिससे सरकार व्याज कमा सकती है। इसके प्रतिरूप ऐसा पत्र मुद्रा के प्रयोग में धातु मुद्रा के प्रयोग में अवधिक शक्ति होती है और इन अमूल्य मोद्रिक धातु मुद्रा का प्रयोग देश के व्यापार और उद्योग में हित में किया जा सकता है। यह लाभ लगभग ये ही हैं जो ऊपर पत्र मुद्रा के खाना के पीपक में वर्णित हैं।

इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका चलन देख कर राजस्विक मामलों तक ही सीमित रहता है तथा इसके मोद्रिक खराब व खपट होने का भय रहता है। इसमें अचानाविरम का भय भी बना रहता है।

अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Money)—वह पत्र मुद्रा है जो धातु या धातु मुद्रा में नहीं बदली जा सकती। इस प्रकार की पत्र मुद्रा में चलाने वाली तथा की ओर से उस धातु या धातु मुद्रा में बदलने का कोई आश्वासन नहीं होता तथा वह बदल में धातु मुद्रा या धातु के लिये वैधानिक तौर पर बाध्य नहीं होती। इस प्रकार की पत्र मुद्रा के चलने का कारण केवल सरकार की साम्य में जनता का विश्वास अथवा सरकार का भाग्य होती है। इसी कारण इसे आदेश मुद्रा (Fiat Money) भी कहते हैं। मुद्रा तथा धातु मुद्रा में देकर साम्य का कागज में बदल देने है। ऐसी प्रणाली आजकल भारत में है। उदाहरण के लिये गत महायुद्ध-काल में एक रुपये के नोट बनाये गये जो अपरिवर्तनशील थे। ये नोट आज भी हमारे देश में चलते हैं। विचारविषय में ऐसा होना कि 'I promise to pay' आदि छप्राजी के शब्द छपे नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब नोटा की आति सरकार इन नोटा के बदल में सिक्के देने का बंधन नहीं देखी। भारतवर्ष में इन नोटा को रिजर्व बैंक नहीं चलाता बल्कि भारत सरकार के वित्त सचिवालय (Ministry of Finance) द्वारा जारी किया जा रहा है।

इस प्रकार की पत्र मुद्रा का चलन तभी होता है जब सरकार की मुद्रा की अपेक्षा आवश्यकता होता है जस युद्ध काल में। इस प्रकार की पत्र मुद्रा को यदि सरकार द्वारा प्रिन्ट व्याज लिया गया तब तो अनुचित नहीं होगा। फ्रांस की राज्य शक्ति के दिना में फ्रांसोमी नोट (Assignats) अमेरिकन ग्रीन बुक काल में अमेरिकन नोट (Green Backs) प्रथम महायुद्ध के दिना में जर्मनी नोट (Mark) और द्वितीय महायुद्ध के समय समग्र सभी देशों के नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के उदाहरण हैं। भारत में पत्र मुद्रा द्वारा भय में परिवर्तनशील है कि उनके चल में स्पष्ट लिये जाते हैं परन्तु वर्तमान समय स्वयं धातु पर छपे हुए नोट हैं।

आदेश-मुद्रा (Fiat Money)—अंग्रेजी भाषा में 'फियट' शब्द का अर्थ है 'आज्ञा अथवा फियट या आदेश-मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करती, न जिसमें कोई अधिकार ही है तथा जिसको लोग संचालने आज्ञा के कारण ही स्वीकार करने के लिये बाध्य होते हैं।

तथाकथित लाभ—यदि अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का कोई लाभ है तो यह है कि युद्धकाल जैसे सकट समय में जबकि मुद्रा बनाने के लिये धातु उपलब्ध नहीं होती तथा सरकार को मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता होती है तब इसकी पूर्ति का एकमात्र साधन अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा ही है। आवश्यक मात्रा में ही यथासंभव मात्रा में मुद्रा बनाई जा सकती है, परन्तु इसका आवश्यकता से अधिक मात्रा में चलना अहितकर होता है।

अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा की हानियाँ (Evils of Inconvertible Paper Money)—अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा में सर्वत्र चलनाधिक्य (Over-issue) का भय रहता है। इस प्रकार के नाटो के उठने में कोप में धातु के सिक्के रखने की आवश्यकता नहीं होती, अतः सरकार बिना किसी डर और रिजर्विवाहट के ऐसे नोट छाप छाप कर चलानी रहती है जिसके कारण आवश्यकता से अधिक नोट छपकर चलन में आ जाते हैं। इसका परिणाम मुद्रा-स्फीति (Inflation) होता है। मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के भाव बढ़ने लगते हैं। वस्तुओं के भाव बढ़ने में लोग का जीवन व्यय भी बढ़ जाता है। व्यापार में उथल-पुथल भी मच जाती है तथा व्यापारिक मौला में घोर-वाजारी, नफाखोरी आदि आदि दुरावस्था आ जाती है। अपरिवर्तनशील नाटो के चलने में लोग सिक्कों को छिपाकर रखने लगते हैं। सिक्का को छिपाकर लोग या गो गला कर सोने, चाँदी के रूप में बेचने लगते हैं या उन्हें विदेशों में भेजकर धातु के रूप में बेच दिया जाता है।

वस्तुओं के भाव में वृद्धि हो जाने में सट्टेबाजी बढ़ जाती है और वस्तुओं की उत्पादन विधि गिरावटी जाती है। अमिको तथा जनसाधारण को बड़ी कठिनाई होती है। अधिक मात्रा में अपरिवर्तनशील नाटो चलाने में विदेशी विनिमय दर (Foreign Exchange Rate) में भी गड़बड़ हो जाती है और विदेशी व्यापार में विपत्ति आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में घनी और अधिक घनी बनते जाते हैं तथा निर्वन और अधिक निर्धन बन जाते हैं। किन्ले (Kinley) नामक एक मुद्राशास्त्री ने लेख लिखा है कि "अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (नाट) एक ऐसी मर्दिर है जिसकी दो चार युद्धों में ही जनता और सरकारों अक्सर न दिमाग मग्न हो गते हैं। एक दफ्तर अमेरिकी का, एक दूसरे रूसी है और वे अपरिवर्तनशील नाटो छाप कर चलन या न चलने के विषय में कोई सम्भार निर्णय नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि सभाज और व्यापार में दुरावस्था बढ़ जाती है और वे इतनी भयंकर हो जाती हैं कि उनको दूर करना असम्भव हो जाता है।"

भारत में अपरिवर्तनशील नोट—नव मद्रास में ब्रिटिश सरकार ने इनकी अधिक मर्यादा में अपरिवर्तनशील नोट बनाने कि मुद्रा का कृत्रिम मिर गया और वस्तुओं के भाव बढ़ने में धमिकी, उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों के भावों को घटाने का सामना करना पड़ा। वस्तुओं के उत्पादन में उपलब्धता हो गई तथा व्यापार में भी प्रस्थितता आ गई। भाव बढ़ने में व्यापारियों ने काले-बाजार (Black-Marketing) किया, कट्टे किए, नकालोरी की तथा माल को भी छिपा छिपाकर रख दिया। इन बुरादमों को दूर करने के लिये सरकार ने कानून बनाये तथा जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाये। परन्तु इनका कोई विशेष परिणाम न निकला। समाज में ये सब बुराईयाँ आज भी दिखलाई देती हैं। यह परिस्थिति किन्ते (Kinties) के कथन की पुष्टि करती है : “आवश्यकता में अधिक मात्रा में अपरिवर्तनशील नोट बनाने में सामाजिक बुराईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उन्हें दूर करना कठिन हो जाता है।

भारतीयों में वर्तमान नोट (पत्र-मुद्रा) व्यवस्था—भारतवर्ष में पत्र-मुद्रा का प्रादुर्भाव अंग्रेजों के शासन-काल में हुआ, यद्यपि इण्डिया सरकार प्रस्तावित प्रमिसरी (Promissory notes) का प्रचार पहले न ही था। सबसे पहले नोट बनाने का कार्य सीन प्रीमीडेली बैंक को दिया गया परन्तु सन् १८६१ में यह कार्य भारत सरकार में अपने हाथ में ले लिया। अब सरकार ‘निश्चित भरोसा प्रणाली’ (Fixed Fiduciary System) के अनुसार नोट चलाने लगी। इनके प्रचरण ४ करोड़ रुपये के रूप के नोट प्रतिष्ठितियों (Securities) के बल पर चलाने का मकसद और यदि सरकार को इनके अधिक नोट चलाने होंगे तो सरकार को अपने पास चौकी का एक मजिद काय रखना पड़ता था। धन, धन, प्रतिष्ठितियों के आधार पर चलाने वाले नोटों में वृद्धि होनी बड़ी और जहाँ तक कि प्रथम महायुद्ध में १०० करोड़ रुपये के नोट केवल प्रतिष्ठितियों के आधार पर ही जारी किये गये थे। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक के स्थापित होने पर यह कार्य उसके सुपुर्दे कर दिया गया। जनवरी १९४६ में १००, १००० और १०,००० रुपये के नोटों का चलन में हटाने के लिये इनका नवन प्रबंध घोषित कर दिया गया। युद्ध-काल में रिजर्व बैंक द्वारा २२० के नोट और प्रागम सरकार द्वारा १०० के नोट प्रचलित किये गये।

इन समय हमारे देश में अपरिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के नोट प्रचलित हैं। २, ५, १०, १०० रुपये के वर्तनी नोट अपरिवर्तनशील नोट हैं जो कि इनके बदले में रिजर्व बैंक प्रामाणिक धातु-मुद्रा देने का वचन देती हैं। १ रुपये के नोट अपरिवर्तनशील नोट हैं जिनका प्रकाशन भारत सरकार के वित्त-विभाग द्वारा होता है। एक रुपये के नोट अतः महायुद्ध-काल में बनाये गये थे और ये आजकल भी प्रचलित हैं। ये अपरिवर्तनशील इनलिज कहलाते हैं कि इनके बदले में वरतार धातु-मुद्रा देने की प्रतिज्ञा नहीं करती। प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा हमारे देश में प्रचलित नहीं है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व जब सरकार स्वयं नोट चलाती थी तब ‘वर्तनी निम्नलिखित’ का पालन किया जाता था। परन्तु आजकल ‘प्रोपोरशनल निम्नलिखित’ का पालन किया जाता है जिनके अनुसार देश के निम्नलिखित बैंकों रिजर्व बैंक को नोट-प्रचरण का एक निम्नलिखित मिला हुआ है।

नोट-प्रचरण में रिजर्व बैंक ‘प्रामाणिक कोष प्रणाली’ (Proportional Reserve System) का पालन करता है। इन प्रणाली के अनुसार नोट जारी करने में पूर्व रिजर्व बैंक को नोटों के बदले में उचित-कोष (Reserve) रखना पड़ता है जिनमें

सामान्य मान के निम्न विन्नी प्रतिभूतिषा स्थाप्य तथा स्थायी प्रतिभूतिषा रखी जाती है। चत्वार्य आन बाज नाग व भूय व वदन म सचिन बाध का कम न कम ४० प्रतिशत भाग सामान्य मान व निम्न तथा विन्नी प्रतिभूतिषा म रखना पड़ता है। अन्य हर समय कम-न-कम ४० करोड़ रुपय व भूय का सामान्य मान व निम्न रखना प्रतिबन्ध है। सचिन बाध का रुप ६० प्रतिशत भाग स्थायी प्रतिभूतिषा म अन्य भाग विन्नी म रखा जा सकता है। सन् १९४६ म पुन जल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व प (International Monetary Fund) का निमाण नष्ट हुआ था रिजर्व बैंक का प्रथम सचिन-बाध म स्टर्लिंग प्रतिभूतिषा (Sterling Securities) रखकर उनमें वस पुन नष्ट चत्वार्य का अधिकार था। परन्तु जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाज का सम्मेलन हुआ तो रिजर्व बैंक कवन स्टर्लिंग प्रतिभूतिषा व वन पर नष्ट करवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाध व सचिन-बाध का निष्कारिद्वारा प्रथम प्रतिभूतिषा व वन पर नाग बना सकता है। अब हमारा देश म नाग-प्रवस्था पदान्तर नागदार है। १ जनवरी १९६० म रिजर्व बैंक द्वारा निम्न का राष्ट्रीयकरण हुआ जान म रिजर्व बैंक द्वारा नोट चत्वार्य का उत्तरदायित्व धारण करनेवाला का भा उत्तरदायित्व धारण गया है।

म १५ म भारत का वर्तमान पुन मुद्रा (नष्ट व्यवस्था की सम्मेलन विनियम) य है—(१) परिवर्तनीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीय नाग दान प्रचार व नाग का प्रचरण (२) नाग चत्वार्य व वचिन निम्न का चत्वार्य और (३) आनुवांशिक-नाग प्रणाली क प्रणाली नाग का चत्वार्य।

पुन सम्मेलन म आदेश पुन मुद्रा प्रणाली व पुन—एक स्थायी व आदेश पुन मुद्रा प्रणाली म निम्नलिखित पुन हान चत्वार्य —

(१) नाग (Elasticity)—पुन मुद्रा प्रणाली एका जना चाहिए जिसका प्रचरण पुन का प्रचार एवं गुरुत्व दान का आदेश एवं आधुनिक आधुनिकता का प्रचरण हान सब और निम्न वसुधा व भूय निम्न रह गया।

(२) निम्नव्यवस्था (Economy)—पुन मुद्रा प्रणाली एका हान चाहिए जिसका सम्मेलन आनुवांशिक व कम-न-कम प्रचार हान नाग निम्न वसुधा का कम हान।

(३) परिवर्तनीयता (Convertibility)—पुन मुद्रा प्रणाली का आदेश वसुधा का निम्न है। अस्त वसुधा म उम्मेद प्रति धरा और निम्न वसुधा करन व निम्न नागना नाग का माध पर माध या नाग म वसुधा नाग आदेश है। यह नाग उपभुक्त गन व नाग व नाग (निम्न) नाग वसुधा प्रचार सम्मेलन हान सकता है।

(४) स्वयं चत्वार्य पुन नाग (Automatic)—निम्न देश का पुन प्रणाली म यह नाग विनियम हान चत्वार्य व पुन पुन सम्मेलन वसुधा नाग व विन्नी म सामान्य पदान्तर सामान्य नाग रता हान और पुन सम्मेलन वसुधा नाग विन्नी का नाग रता हान यह नाग तथा सम्मेलन है जब सम्मेलन वसुधा नाग म वसुधा नाग और व देश म सामान्य नाग पर पुन का वसुधा नाग तथा पुन म सामान्य नाग पुन मुद्रा का कम वसुधा नाग है। एका १९१४-१५ व महापुन म पुन हाना का।

(५) वसुधाविक्रय व विरुद्ध मुद्रा (Safety against over issue)—पुन मुद्रा म वसुधाविक्रय का सम्मेलन नाग हान है। अस्त पुन मुद्रा

प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुद्रा प्रसार आवश्यकता में अधिक न होने वाले तथाकि इससे बहुत रुढ़िवादियों का सामना करना पड़ता है ।

(६) मूल्यों में स्थिरता (Stability)—प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि पत्र-मुद्रा के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता रह सके ।

(७) अनिश्चितता रहित (Free from Uncertainty)—देश में प्रचलित मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि उसमें किसी प्रकार की भी अनिश्चितता न हो । मुद्रा सम्बन्धी देश में प्रचलित कानून निश्चित एवं निष्पक्ष पैदा करने वाला होने चाहिए ।

(८) सरलता (Simplicity)—पत्र मुद्रा प्रणाली सरल सुबोध एवं साधारण होनी चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक उसे समझ सके ।

विविध पत्र मुद्रा प्रकाशन प्रणालियाँ—पत्र मुद्रा चलाने की मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) निश्चित अरक्षित या विश्वासार्थित प्रणाली (Fixed Fiduciary Issue System)—इस प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय बैंक को एक निश्चित राशि के नोट बिना किसी मोने व चांदी के कोष (Reserve) के निकालने का अधिकार दे दिया जाता है । नोटों के इस भाग को अरक्षित भाग (Fiduciary portion) कहते हैं और यह राज्य प्रतिभूतियों के आधार पर निकाला जाता है । परन्तु इस भाग के ऊपर जो नोट निकाले जाते हैं उनके लिये गवर्नर प्रतिशत सोने व चांदी का रिजर्व रखा जाता है । भारतवर्ष में सन् १८६१ में नोट चलाने के लिये यह प्रणाली काम में लाई गई थी । इसने अन्तर्गत ४ करोड़ रुपये के नोट प्रतिभूतियाँ (securities) के बल पर चलाए जा सकने में और इसमें अधिक नोट चलाने के लिए अपने पास सोने चांदी का रिजर्व रखना पड़ता था । सर्व शर्तें प्रतिभूतियों के बल पर चलाने जाने वाले नोटों का मूल्य बढ़ाया जाता रहा और प्रथम महापुद्गलान में १२० करोड़ तक पहुँच गया । सन् १८४४ में जब इंग्लैंड में इस प्रणाली को मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी तब कुल १४० लाख पाउंड के नोट प्रतिभूतियों के आधार पर छप सकते थे ।

गुरु दोष—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इनमें मुद्रा-स्फीति (Inflation) का भय नहीं रहता क्योंकि निश्चित सीमा के ऊपर नोट छपवाना मना प्रतिशत सीमा चांदी कोष में रखना पड़ता है । इसका दूसरा दोष यह है कि इसमें नोट परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि अमरक्षित भाग के ऊपर एक पाउंड के बदले एक पाउंड मोटा रखना पड़ता है । परन्तु इस प्रणाली में नोटों की लोच (Elasticity) समाप्त हो जाती है क्योंकि नोट बढ़ाने के लिये पहले मोना चाहिए ।

(२) अनुपातिक वाप प्रणाली (Proportional Reserve System)—इस प्रणाली के अन्तर्गत नोट चलाने वाले बैंक को चालू नोटों के बदले अनुपात द्वारा सोना या चांदी की निश्चित मात्रा सुरक्षित कोष (Reserve) के रूप में रखनी पड़ती है । भारतवर्ष में चालू नोटों के बदले में कम से कम ४० प्रतिशत भाग सोना सोने के सिक्के तथा सोने की प्रतिभूतियाँ में रखना पड़ता है । नोटों के बदले में रखे जाने वाले मोने की मात्रा चिन्न चिन्न देना मना चिन्न चिन्न है । भारत के अनिश्चित पत्र प्रणाली अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, नर्वे, टर्की, जूरोन, यूगोस्लाविया आदि देशों में अपनाई जाती है ।

मुद्रा-दोष—इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके अनुसार वम-मुद्रा-प्रणाली जोचदार हो जाती है अर्थात् देश की आवश्यकतानुसार नोटा की मात्रा में अनुवर्धिता की जा सकती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि देश में से कभी सोना बाहर जान लगे और केन्द्रीय बैंक के नोटा में से सोने की मात्रा कम हो जाय ता नोटा का चलने में एक साथ रोक कर उनकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार देश में नोटा की कभी पट सकती है। इस प्रणाली में यह भी दोष है कि थोड़ा सा सोना कोष में बढ़ने से उसमें अधिक मुद्रा के नोटा छापे जा सकते हैं जिससे देश में मुद्रा-स्फीति होने का भय सदा बना रहता है।

(३) निश्चित अधिकतम सीमा-प्रणाली (Fixed Maximum Limit System)—इस प्रणाली के अनुसार एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है जिससे ऊपर नोटा नहीं छप सकते। इस सीमा के भीतर केन्द्रीय बैंक बिना किसी स्थिति रहित रूप से जब्त सरकारी खाल-पत्रों के आधार पर नोटा प्रकाशित कर सकता है। प्रायः यह अधिकतम सीमा नोटा के भीतत वार्षिक व्यय से साधारणतया ऊँची रखी जाती है।

मुद्रा-दोष—इस प्रणाली के अन्तर्गत देश में मुद्रा स्फीति होने का भय कम रहता है। परन्तु इस प्रणाली में एक बड़ा भारी दोष यह है कि इसमें देश की वम-मुद्रा व्यवस्था आनन्दार नहीं बन सकती। इसमें दूसरा दोष यह है कि इस प्रकार नोटा चलाने में अनिश्चितता रहती है।

(४) साधारण जमा पद्धति (Simple Deposit System)—इस प्रणाली के अन्तर्गत नोटा के मुद्रा के बराबर ही रूप में स्थण्डित रखा जाता है।

मुद्रा-दोष—इस प्रणाली के अन्तर्गत नोटा पूर्ण रूप से बदले जा सकते हैं और मुद्रा-स्फीति का भय भी नहीं रहता। परन्तु यह प्रणाली बहुत ही कम लचीली है और कठिनी है। इसमें बहुत सा सोना धारण रख से स्थण्डित-नोटा में पड़ा रहता है और इसका कुछ उपयोग नहीं हो सकता।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—उत्तर के आरम्भ में प्रश्न ? उत्तर के प्रधान भागों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।

२—पूर्ण रूप से समझ कर लिखिए :—

भारतीय रुपया प्रामाणिक-मानेतिव निववा है।

३—मुद्रा की परिभाषा दीजिये और उसके मुख्य कार्य बताइये।

४—मुद्रा का आरम्भ कैसे हुआ ? मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं ? भारत की मुद्रा के क्या लाभ हैं ?

५—मुख्य सिक्के (Standard Coins) और उप-सिक्के (Token Coins) में भेद दर्शाइये।
(रा० बो० १९५६)

६—“मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है।”—इस वचन की व्याख्या कीजिये।
मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं।
(रा० बो० १९५७, ५४)

७—अन्तिम मुद्रा के गुण पर टिप्पणी लिखिये।
(रा० बो० १९५०)

८—मुद्रा के क्या कार्य हैं ? क्या वस्तु विनिमय अव्यवधिना है ? (प्र० बो० १६६०)

९—मुद्रा के मूल्य ह्रास, मुद्रा की पितावट, मुद्रा का अवमूल्यन इन तीनों में अन्तर बताइये । (प्र० बो० १६५७)

१०—मुद्रा के क्या कार्य हैं ? वस्तु-परिवर्तन को प्रया का कसे अन्त होना जा रहा है ? (प्र० बो० १६५६)

११—कागजी-मुद्रा—उमके लाभ और हानियों पर टिप्पणो लिखिये । (म० भा० १६५६)

१२—मुद्रा क्या है ? इसके कार्यों को तथा अवमोलनामा को इनके लाभों को पूर्णतया व्याख्या कीजिये । (सागर १६५६)

१३—कागजी मुद्रा के लाभ और हानि को पूर्णतया स्पष्ट कीजिए । कागजी मुद्रा धात्विक मुद्रा से किम प्रकार उत्तम है ? (रा० बो० १६५६)

इण्टर एप्रोक्ल्वर परोक्षाण

१४—मुद्रा को परिभाषा लिखिये । इनके कार्यों का पूर्णतया वर्णन कीजिये । (प्र० बो० १६५७)

१५—मुद्रा क्या है ? कितने प्रकार के मुद्राया में आन परिचित हैं ? भारत का विमान कसे धातु-मुद्रा को ही अधिक प्रधानता देना है ? (प्र० बो० १६५६)

मुद्रा का मान, ग्रेशम का नियम,

मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त,

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन ।

(Monetary Standard, Gresham's Law,

Quantity Theory of Money & changes

in the Value of Money)

मुद्रा का मान

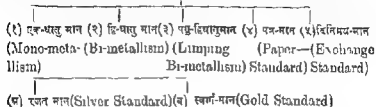
(Monetary Standard)

मुद्रा के मान का अर्थ एवं परिभाषा—जिस प्रकार निम्न निम्न वस्तुओं का मूल्य मुद्रा द्वारा प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य अर्थात् उसकी विनिमय-शक्ति का माप दण्ड दूसरी वस्तुएं हैं। परन्तु मुद्रा की विनिमय-शक्ति मात्र पदार्थों द्वारा व्यक्त नहीं की जाती बल्कि इन कार्य के लिये कोई एक वस्तु छांट ली जाती है और उसी से यह कार्य मिया जाता है। अतः जहाँ जिस वस्तु में मुद्रा की विनिमय-शक्ति व्यक्त की जाती है वहाँ उसी प्रकार का मुद्रा मान होता है। यदि यह कार्य स्वर्ण (सोने) से लिया जाता है, तो स्वर्ण-मान (Gold Standard) हुआ, यदि रजत (चाँदी) से लिया जाता है तो रजत मान (Silver Standard) हुआ, और यदि कागज से लिया जाता है, तो कागज या पत्र-मान (Paper Standard) हुआ। कभी-कभी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के आश्रित रहती है, तो ऐसी दशा में इसे विनिमय-मान (Exchange Standard) कहें। अतः, मुद्रा का मान वह आधार है जिसके अनुसार किसी देश की मुद्रा का संचालन, नियंत्रण और मूल्य-निर्धारण किया जाता है। विभिन्न देशों में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केवल सोने अथवा सोने-चाँदी दोनों अथवा कागज की मुद्रा प्रचलित की जाती है। तबु मुसलमान के लिये विभिन्न धातुओं में बने सवैतिव सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा-मान की मुद्रा-प्रणाली (Monetary System) भी कहते हैं।

मुद्रा-मान के प्रकार (Kinds)—मुद्रा मान मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं.—

(१) एक धातुमान (Mono-metallism), (२) द्वि-धातुमान (Bi-metallism), (३) पगु द्विधातुमान (Lumping Bi-metallism), (४) पत्र-मान (Paper Money), और (५) विनिमय-मान (Exchange Standard)

मुद्रा-मान (Monetary Standard)



(१) एक धातुमान (Mono-metallism)—वह मुद्रा प्रणाली है जिसके घटतागत देश की प्रामाणिक मुद्रा (Standard Money) एक ही धातु की घनी हुई होती है। एक-धातुमान के घटतागत किसी एक ही धातु (प्रायः सोने या चांदी) के सिक्के देश की प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं। इन्हीं के द्वारा देश में वस्तुओं और सेवाओं का मुख्य-मापन किया जाता है तथा इन्हीं के साथ देश में प्रचलित अन्य सार्वजनिक मुद्राओं का मुख्य सम्बन्धित होता है।

एक धातुमान की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) इसमें केवल एक ही धातु के सिक्के प्रामाणिक सिक्के होते हैं। (२) ये सिक्के असंमित विधिप्राप्त (Unlimited Legal Tender) होते हैं। (३) उन धातु की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई (Free Coinage) होती है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति उस धातु को ले जाकर उसके बदले में सरकारी दफ्तर में सिक्के बनवा सकता है। (४) प्रामाणिक मुद्रा के प्रतिरिक्त देश में अन्य प्रकार की सार्वजनिक मुद्राएँ भी प्रचलित होती हैं, य मुद्राएँ सामान या किसी गस्ती धातु की घनी होती हैं तथा ये सीमित विधिप्राप्त (Limited Legal Tender) होती हैं। (५) इन सार्वजनिक मुद्राओं को किसी भी समय सोने या चांदी में बदला जा सकता है।

चलन—१८३३ के पूर्व अमेरिका में एक-धातुमान का चलन था जिसके घटतागत जहाँ सोने का दर्ज़र प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलता था। मई १८६३ में पूर्व हमारे देश में भी एक धातु प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें चांदी का रूपया प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलता था।

एक धातुमान के भेद—एक धातुमान में प्रामाणिक सिक्का बनाने के दिष्ट प्रायः चांदी या सोना नाम में लाया जाता है। ऐसी स्थिति में एक-धातुमान दो प्रकार का हो सकता है—रजत (चांदी) या स्वर्ण (सोना) मान।

(घ) रजत मान (Silver Standard)—जिस प्रणाली का प्राधार चांदी होता है उसे रजत-मान कहते हैं ।

विशेषणार्थ (Characteristics)

(१) चांदी की मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा होती है तथा वह अनमीमित विधियाद्य होती है । (२) चांदी की मुद्रा की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई जाती है । (३) यदि साथ ही म पत्र मुद्रा चलती है तो वह चांदी की मुद्रा में बदली जा सकती है । (४) चांदी की मुद्रा के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार के बहिष्कृत (मार्केटिंग) मिक्चर भी चलते हैं, परन्तु ये सीमित विधियाद्य होते हैं ।

चलन—रजत-मान का सबसे बड़ा दोष यह है कि चांदी के मूल्य में बहुत बड़ा बदला होता है । इसी कारण प्रायः सभी देशों में मुद्रा-मान के रूप में व्यवहार नहीं हो रहा है । नवल चीन और हाँगकांग बहुत समय तक इस रूप में व्यवहार करते रहे, परन्तु उन्होंने भी नवम्बर १९३५ में इसे त्याग दिया ।

भारतवर्ष में रजत-मान—भारतवर्ष में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में सन् १६३५ के अनुसार रजत-मान स्थापित किया गया था जिसके अन्तर्गत चांदी का रूपया देश की प्रामाणिक मुद्रा बना दी गई । इस रूपये में ११ मासे (१६५ ग्रैम) चांदी और एक मासे मिश्र धातु (Alloy) था । रूपये की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई गयी तथा वह अनमीमित विधियाद्य था । रूपये के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार के छोटे मिक्चर भी चलन में । इनका मूल्य रूपये के साथ सम्बन्धित था तथा इनको रूपये या चांदी में बदलवाया जा सकता था । परन्तु १८७१ के पदचाल चांदी का मूल्य गिरने लगा जिससे फलस्वरूप रूपये का मूल्य भी घटने लगा । अन्त में १८६३ में स्वतन्त्र मुद्रा बनाई स्थापित कर दी गई जिसमें रजत मान समाप्त हो गया ।

(व) स्वर्ण-मान (Gold Standard)—वह मुद्रा प्रणाली है जिसके अन्तर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा सोने की बनी हुई होती है अथवा उसका मूल्य सोने में निर्धारित होता है । रॉबर्टसन (Robertson) के शब्दों में 'स्वर्ण-मान उस देश की कहते हैं जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य और सोने के एक निश्चित तोल का मूल्य एक-दूसरे के बराबर रखता है ।'

स्वर्णमान के भेद—स्वर्ण-मान के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं :—

(१) स्वर्ण-मुद्रा-मान, (२) स्वर्ण धातु मान और (३) स्वर्ण विनिमय मान ।

(१) स्वर्ण-मुद्रा मान (Gold Currency Standard)—वह है जिसके अन्तर्गत सोने के सिक्के देश में प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं । ये सिक्के विनिमय माध्यम का काम भी करते हैं और मूल्य मापन के काम में भी होते हैं । इनके प्रतिरिक्त देश में अन्य प्रकार की मुद्राएँ भी प्रचलित होती हैं, परन्तु उनका मूल्य सोने के प्रामाणिक सिक्के के साथ सम्बन्धित होता है तथा इनको सोने में या सोने के प्रामाणिक सिक्कों में बदलवाया जा सकता है और यदि साथ ही साथ पत्र मुद्रा अर्थात् बाणज के नोट भी चलते हैं तो वे सोने की मुद्राओं में परिवर्तनीय होते हैं ।

चलन—स्वर्ण-मुद्रा मान सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में सन् १८१६ में चालू किया गया था, यद्यपि बाद में संसार के अन्य देशों ने भी आदर्श मानकर उसको अपना लिया। परन्तु प्रथम महायुद्ध-काल तथा उसके बाद स्वर्ण-मुद्रा-मान का चलन बन्द हो गया और उसने स्थान में अन्य प्रकार के स्वर्णमान चलने लगे।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) सोना मूल्य-मापन तथा विनिमय-माध्यम दोनों का काम करता है। (२) स्वर्ण-मुद्रा-मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के प्रायोगिक मुद्रा के रूप में चलते हैं। (३) सोने के सिक्कों की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई जाती है। (४) सोने के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। (५) सोने के सिक्कों के ताब कागज के नोट तथा अन्य प्रकार के विदेशी चलते हैं जो सोने के सिक्कों में परवर्तनीय होते हैं।

(२) स्वर्ण-धातु-मान (Gold Bullion Standard)—बहु मुद्रा प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सोना 'मूल्य-मापन' का काम करता है परन्तु 'विनिमय-माध्यम' का काम नहीं करता अर्थात् सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते। देश में कागज के नोट तथा चाँदी के सिक्के चलाये जाते हैं, परन्तु इनके बदले में सोना (धातु के रूप में) लिया जा सकता है। सोने के आयात-निर्यात पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। देश की सरकार निश्चित दर पर जनता को सोना बेचती है तथा जनता से खरीदती है।

चलन—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वर्ण-मुद्रा-मान को चलाना प्रामाण्य था। इन कारण उस समय स्वर्ण-धातु-मान चलन में आया। स्वर्ण-धातु मान उन सब देशों में प्रचलित किया जिनके पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोष था। इन प्रकार इस मान को १९२५ में हंगरी ने, १९१८ में फ्रांस ने तथा १९३४ में अमेरिका ने स्वर्ण कोष-एक्ट पास करके एक दूसरे रूप में प्रचलित किया। सन् १९२५ में हिस्टन-यंग कमिशन ने भारत के लिये भी इसी मान को बहाल करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार ने सुझाव को मान लिया और सन् १९२७ से १९३१ तक भारत में भी पहले के लिये यही मान रहा पर वास्तव में इस देश में 'स्टैलिज्म-विनिमय मान' रहा।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) स्वर्ण-धातु-मान के अन्तर्गत सोना केवल 'मूल्य-मापन' का ही काम करता है। (२) स्वर्ण-धातु मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते। (३) कागज के नोट, चाँदी के सिक्के तथा अन्य प्रकार के मध्यमक सिक्के चलते हैं जो सोने में परिवर्तनीय होते हैं। (४) सिक्कों व नोटों के बदले में निश्चित दर पर तथा निश्चित-राशि में सोना खरीदा जा सकता है। (५) सोना किसी भी काम के लिये खरीदा जा सकता है। (६) सोने के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। (७) सोने के सब विषय का काम सरकार का होता है जिसके लिये सरकार को सोने का एक कोष रखना पड़ता है।

(२) स्वर्ण-विनिमय-मान (Gold Exchange Standard)—बहु मुद्रा-प्रणाली है जिसके अन्तर्गत स्वर्ण धातु-मान को मालि सोने के सिक्के नहीं चलाय जाते। सोना केवल विदेशी मुद्रातान के लिये ही प्रयुक्त किया जाता है। देश के आन्तरिक प्रयोग के लिये पत्र-मुद्रा तथा चाँदी के सिक्के

योग का महायज्ञ सिद्ध करना जान ह जितना मूल्य गढ़ सान का निश्चित माना म निरास्त किया जाना है । यह म चरण वाली भावना म न मूल स्थायी रहने का काम करता है ।

सन १८७३ में स्वर्ण विनिमय मान का सत्र प्रथम मंत्र १८७३ में हावरा न चारू किया था। फिर मंत्र १८८२ में कम और आम्बिया व हग्रा न भा इग अचना दिया था प्रथम मंत्रावृत्ति व पत्रावृत्ति भा मध्य मूराण व कल दगा न ग्यना अचना का प्रदान किया। मंत्र १८९० का विनवा कायम न मा कम मान का प्रयोग करने का समाव दिया था।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) मान व निरर वहा चदार ताग । माना विनिमय माध्यम का काम तथा करता वरन मूल्यमान का काम हा करता है । (२) एग म दानागिक प्रपाग क निर वरमपाग चाग क सिक्क तथा श्रव प्रसार न मय निरर वनाय ताग क जिन्का मूल्य मान क गाव गभस्थित कर रिमा जाता है । (३) विन्गा भुगतान व निय मन्वार विन्चिन् मूल्य पर रन नाग क रिक्ता क बन्द म मान रन क बाध्य हुता है । सरकार माना का मान पर आधारित पाय मुग भा न सकता है । (४) माना वरन विन्गा भुगतान वरन क निर ह मन्वा ता सकता है एग कामा क निय नहा । (५) मान का म्यन बायान नियम नहा एता । (६) माना वरन का काम सरकार का हाता है । मन निय सरकार का बाय वनाम रन रन पन्त — ताक एग म श्रीर हमरा विन्गा म ।

भारत में स्वयं विनिमय मान—भारत में यह पद्धति १९०७ ई. में स्थापित
 की और प्रथम मण्डल-काउन्सिल ने कानून बनाया। उस समय १ मण्डल १ गि० ८ प० व
 शराब देना दिया गया। १ मा. दर पर १ पा० १५ मण्डल व शराब देना था।
 भारत सरकार के पास दो तरह के कापे जमाद में भारत सरकार के पास रखा
 था और दूसरा वह कापे भारत में रखा जाता था। यह पद्धति तब तक १९१७ तक चलता
 था। प्रथम महाभुज में भारत के मूल्य में गृह में मूल्य में मूल्य के मूल्य में प्रति किलो
 पनी और मूल्य का मूल्य २ गि० ८ प० तक न बढ़ा और मूल्य में मूल्य के
 मूल्य के प्रतिशत के कारण मूल्य में प्रभाव पड़ा। मूल्य १९२७ में मूल्य १९२७
 तक न बढ़ाया। देश में प्रचलित मूल्य में स्वयं विनिमय मान तथा स्वयं मानमान
 का सम्बन्ध था।

मिनट १८३१ में स्टर्लिंग का स्वयं मान दर्जित का परिणाम कर लिया
 निम्न कारणों से भारत के स्वयं निम्न मान का अंतर था गया। भारत में व मध्य का
 मूल स्टर्लिंग का कारण था (Sterling) में १ गि० ६ गि० के वगैरह निम्न मान कर
 लिया। भारत में व मध्य पर स्टर्लिंग का अंतर था। स्वयं व मध्य वगैरह
 कर सकता था। मध्य प्रणाली का स्टर्लिंग निम्न मान (Sterling Exchange
 Standard) कर था। मध्य प्रणाली का अंतर था। व मध्य वगैरह निम्न मान
 मध्य १८३१ में मध्य वगैरह का अंतर था। भारत में व मध्य का स्टर्लिंग मध्य
 व मध्य वगैरह का अंतर था। भारत में व मध्य का स्टर्लिंग मध्य व मध्य
 वगैरह का अंतर था। भारत में व मध्य का स्टर्लिंग मध्य व मध्य वगैरह
 का अंतर था। भारत में व मध्य का स्टर्लिंग मध्य व मध्य वगैरह का अंतर था।

(२) द्विधातुमान (Bi metallism)—वह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत दो धातुओं (प्रायः सोने या चांदी) के सिक्के अलग-अलग मुद्रा के रूप में चलते हैं। दोनों धातुओं के सिक्के असीमित विधिप्राप्त होते हैं और इनकी स्वतन्त्र ढलाई होती है। दोनों सिक्के एक ही नाम, रूप और नाव के होते हैं तथा दोनों की एक ही मान्यता होती है। दोनों धातुओं की विनिमय दर अर्थात् टकरावो दर (Mint Ratio) वास्तु द्वारा निर्दिष्ट की जाती है जिसे पर कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक बदले जा सकने हैं। दोनों धातुओं के आपात निर्दान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) दो धातुओं के सिक्के अलग-अलग प्रामाणिक सिक्के होते हैं। (२) दोनों प्रकार के सिक्के प्रामाणिक विधिप्राप्त होते हैं। (३) दोनों धातुओं के सिक्के का पारस्परिक विनिमय मूल्य वास्तु द्वारा निर्धारित होता है। (४) दोनों धातुओं की स्वतन्त्र ढलाई होती है। (५) दोनों धातुओं के सिक्के का 'प्रकृत मूल्य उनके वास्तविक मूल्य' मुद्रा के बराबर होता है। (६) दोनों धातुओं के सिक्के विनिमय माध्यम (Medium of Exchange) तथा मूल्य मापन (Measure of Value) का काम कर सकते हैं। (७) दोनों धातुओं के आपात निर्दान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

चलन—द्विधातुमान का प्रचार १६ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। फ्रांस में इसका मन् १८०३ में प्रारम्भ किया और मन् १८७४ में रद्द कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विधातुमान को १७९२ में अपनाया और यह वहाँ मन् १८७३ तक प्रचलित रहा। मन् १८६५ में फ्रांस, बेल्जियम, इटली व स्विट्जरलैंड आदि देशों ने द्विधातुमान को लागू रखने के लिये एक 'लैटिन संघ (Latin Union)' बनाया परन्तु यह प्रयत्न कुछ समय तक ही चल सका और अन्त में यह इस व्यापन ही पड़ा। इसका सत्य बड़ा कारण यह था कि दोनों धातुओं की निश्चित विनिमय दर स्थिर नहीं रही या सही। कभी सोने की तुलना में चांदी सस्ती हो जाती थी और कभी चांदी की तुलना में सोना सस्ता हो जाता था जिससे 'वैधानिक नियम' (Gresham's Law) लागू हो जाता था।

उदाहरण—मान लीजिये, किसी देश में मान धोरा चांदी दो धातुओं के सिक्के प्रचलित हैं और उसकी पारस्परिक विनिमय दर अर्थात् उनका 'कानूनी मूल्य' (Legal Value) या 'टकरावो दर' (Mint Ratio) ११५ है। इसका अर्थ यह है कि १ सोने के सिक्के के बदले १५ चांदी के सिक्के मिल सकते हैं। अब यदि मान की पूर्ति की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो चांदी के सिक्के मान के सिक्के की तुलना में तेज हो जायेंगे। मान लीजिये यह अनुपात अब ११५ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि १ मान के सिक्के बदले में अब केवल १५ ही चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, अर्थात् चांदी का बाजार मूल्य बढ़ गया और मान का गिर गया। दूसरे शब्दों में यह कहें कि चांदी का अधिमूल्यन (Over valuation) हुआ अर्थात् धोरा सोने का अधामूल्यन (Under-valuation) हो गया। ऐसी परिस्थिति में चांदी के व्यक्ति चांदी लेकर उनका मूल्य बढ़ाना पसन्द नहीं करेंगे और न चांदी के व्यक्ति १५ चांदी

के सिक्के देकर १ सोने का सिक्का ही लेना पसन्द करेगा, क्योंकि बाजार में चाँदी का मूल्य बढ़ जाने के कारण १३ चाँदी के सिक्कों के बदले में १ सोने के सिक्के से अधिक मिल सकेगा। अब तो प्रत्येक व्यक्ति सोना से जाकर उसने धुपके बनवाने लगेगा जिसके परिणाम-स्वरूप देश में सोने ही सोने के सिक्के बिसाई होंगे और चाँदी के सिक्के ग्रहण हो जायेंगे। इसका कारण स्पष्ट है। चाँदी का मूल्य बढ़ जाने में लोग चाँदी को गला गला कर धातु के रूप में बेचने लगेंगे या विदेशी भुगतान के लिये विदेशों में निर्यात कर देंगे। इस प्रकार दोनों धातुओं के बाज़ूनी या टकासाती दर में विपरीतता हो जायगी।

इसके विपरीत, यदि चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो सोने की तुलना में चाँदी सस्ती हो जायगी। मान लीजिये अब यह अनुपात १ : १७ हो जाता है, अर्थात् सोने का अधिमूल्य हो गया और चाँदी का अधोमूल्य हो गया। अधोमूल्य (Under-valued) धातु अर्थात् चाँदी अधिमूल्य (Over valued) धातु अर्थात् सोने की तुलना में बाहर करने लगेगी। सोने का मूल्य बढ़ जाने से अब लोग सोने को या तो गला कर धातु के रूप में बेचने लगेंगे अथवा भुगतान करने के लिये विदेशों में भेज देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि देश में चाँदी ही चाँदी के सिक्के बिसाई होंगे और सोने के सिक्के ग्रहण हो जायेंगे। दूसरे शब्दों में, 'प्रेचम का नियम' लागू हो जायगा।

(३) पंगु-द्वि-धातुमान (Limping Bi-metallism) - यह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत दो धातुओं (प्रायः सोने और चाँदी) के सिक्के देश में मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं तथा वे असीमित विधिप्राप्त होते हैं और दोनों का एक दूसरे से निश्चित अनुपात में सम्बन्ध होता है, किन्तु इनमें से केवल एक ही धातु (प्रायः सोने) की स्वतन्त्र मुद्रा डलाई होती है। दूसरी धातु के सिक्के बालने का अधिकार सरकार को ही होता है।

यह प्रणाली शुद्ध द्वि-धातुमान का विकृत और अपूर्ण रूप है। इसलिजिये यह पंगु अर्थात् लंगड़ा द्वि-धातुमान कहते हैं। जब कभी देश में शुद्ध द्वि-धातुमान हो परन्तु प्रेचम के सिद्धान्त ने अनुसार एक सिक्का दूसरे सिक्के को चलाने में बाहर निकाल दे तो सरकार उन दोनों धातुओं में से सस्ती धातु की स्वतन्त्र मुद्रा डलाई बन्द कर देती है। उसी समय पंगु-मान (Limping Standard) स्थापित हो जाता है।

विशेषताएँ (Characteristics)

- (१) दो धातुओं के सिक्के अलग अलग प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं।
- (२) दोनों असीमित विधिप्राप्त होते हैं।
- (३) दोनों का वास्तविक मूल्य धातुओं द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- (४) परन्तु केवल एक धातु को ही स्वतन्त्र मुद्रा डलाई होती है।

चलन—यह प्रणाली प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के पूर्व फ्रांस और अमेरिका में प्रचलित थी तब वहाँ सोने और चाँदी के सिक्के असीमित विधिप्राप्त मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। परन्तु स्वतन्त्र मुद्रा डलाई केवल सोने की ही थी।

भारतवर्ष में पंगुमान (Limping Standard in India)—भारतवर्ष में फोल्जर कमेटी (Fowler Committee) ने मई १८९८ में पंगुमान

स्थापित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि देश में सोने और चांदी दोनों ही धातुओं को मुद्राएं प्रामाणिक हों, परन्तु स्वतन्त्र मुद्रा बनाई केवल सोने की ही हो।

(४) पत्र मान (Paper Standard)—यह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत कागज के नोट ही मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा के रूप में विनिमय-माध्यम और मूल्य-मापन का काम करने हैं और जिनका मूल्य किसी भी धातु के साथ निश्चित नहीं किया जाता। ये अपरिमित विधिप्राप्त होते हैं तथा इनका अपना कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। ये केवल सरकारी आज्ञा के कारण ही चलते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इन कागज के नोटों के बदले बाजार में सोना या चांदी नहीं मिल सकता वरन् इनका यह अभिप्राय है कि इन नोटों के बदले सरकार जिन प्रकार भी सोना या चांदी देने के विवेक बाध्य नहीं की जा सकती। इस प्रकार की मुद्रा-प्रणाली प्रायः युद्धकाल या अन्य खट के समय कार्यरत में लाई जाती है।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) पत्र मुद्रा ही विनिमय माध्यम एवं मूल्य-मापन का काम करती है।
(२) पत्र-मुद्रा ही देश की मुख्य एवं प्रामाणिक मुद्रा होती है। (३) ये असीमित विधिप्राप्त होते हैं। (४) पत्र-मुद्रा का मूल्य सोने या चांदी से सम्बन्धित नहीं होता और न इसका सोने या चांदी में परिवर्तन ही हो सकता है। (५) मूल्य स्तर में समानता रखने के लिये सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा इस प्रणाली का संचालन किया जाता है। (६) विदेशी मुद्राओं के भुगतान के लिये देश में स्वर्ण-कोष की आवश्यकता होती है, किन्तु प्राक्कृत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुद्राओं का भुगतान होने के कारण ऐसे कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती।

नियंत्रित मुद्रा-प्रणाली (Managed Currency System)—यह मुद्रा प्रणाली है जिसका नियंत्रण एवं संचालन सरकार या केन्द्रीय बैंक द्वारा होता है जो आवश्यकतानुसार नोटों की सख्या कम या अधिक करता रहता है जिससे देश का मूल्य-स्तर सदा ठीक रहे।

(५) विनिमय-मान (Exchange Standard)—यह मुद्रा-प्रणाली है जिसके अन्तर्गत देश के आन्तरिक व्यवहारों के लिये चांदी अथवा कागज की सानेतिम मुद्रा उपयोग में लाई जाती है तथा विदेशी विनिमय के लिये उसका सम्बन्ध किसी दूसरे प्रमुख देश की मुद्रा से किसी निश्चित दर पर जोड़ दिया जाता है। जिस देश की मुद्रा के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उक्त देश की मुद्रा के पीछेमान का नाम रखा जाता है। जैसे, स्टर्लिंग विनिमय-मान, डालर-विनिमय-मान आदि।

भारतवर्ष में विनिमय मान—भारतवर्ष में मई १९२५ से १९४७ तक एक रुपया स्टर्लिंग के १ शिलिंग ६ पैसे (१ = पैसे) पर सम्बन्धित रहा। अतः हमारे देश में मार्च १९४७ तक 'स्टर्लिंग विनिमय मान' (Sterling Exchange Standard)

या। चतुर्थ बार भारत के 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष' का सर्वोच्च होना से एक भारतीय रुपय का मूल्य स्वयं में निर्दिष्ट होने में रोपण स्टैनिज़ का सम्बन्ध विच्छेद होकर अपना अन्तराष्ट्रीय प्राथम्य में स्वतन्त्र हो गया है।

भारतवर्ष का वर्तमान मान—१ अप्रैल १९४७ में गैर-स्टैबिलिटी गणनायक हुआ गया। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) तथा पुनर्निर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction & Development) का सदस्य हो गया है। मुद्रा-बाप के मूल्य में बदलावों में अपनी अपनी मुद्रा का सम मूल्य (Par Value) मान में व्यक्त कर दिया है। भारत ने भी रुपय का मूल्य मोनरी में ०.२६८६०१ ग्राम शुद्ध स्वर्ण निर्दिष्ट कर दिया है। इस प्रकार संसार के अधिकांश देशों की मुद्राओं का मूल्य मोनरी में व्यक्त होना के कारण एक प्रकार से एक स्तर मान पुनः स्थापित हो गया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सात सद्भावना का मूल्य मापक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य देशों की मुद्राएँ प्रायः एक बाप की सहायता से एक वृत्त में बँधी जा सकती हैं। यद्यपि अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि आज स्तर मान पुनः एक नवोदय रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है जिसमें अधिकांश मुद्राओं का मूल्य मापक है। हम दूसरे शब्दों में हमें या आ कह सकते हैं कि आज बहु-मुद्रा मान प्रणाली (Multiple Currency Standard) है जिसमें एक मुद्रा का प्राथम्य प्रणाली में सम्मिलित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मान (International Standard) है।

उनमें मुद्रा मान यथवा मुद्रा प्रणाली के लक्षण

(१) मूल्य स्थिरता (Stability in Value)—उत्तम मुद्रा-मान प्रणाली मुद्रा प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे। मुद्रा का मूल्य = स्थिरता होने से समाज के विभिन्न वर्गों, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(२) लचक (Elasticity)—मुद्रा मान प्रणाली में लचक का होना भी आवश्यक है जिससे का व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का परिमाण बढ़ाया घटाया जा सके। मुद्रा का मूल्य में स्थिरता नाव के लिये मुद्रा मान में लचक होना आवश्यक है।

(३) सरलता (Simplicity)—मुद्रा प्रणाली जटिल नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी सरल और कोमल है कि साधारण जनता भी उसे सरलतापूर्वक समझ सके।

(४) मितव्ययता (Economy)—मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अधिक व्यय न हो। इन तीनों लक्षणों के लिये मूल्यवान् साधनों की आवश्यकता होती चाहिए और न उन्हीं प्रायः एक समाधान में अधिक व्यय होना चाहिए। स्वयं मुद्रा मान और स्वयं वास्तु मान प्रणालियाँ बहुत सरल हैं, अतः उन्हीं चर्चा के लिये अल्प व्यय करना पड़ता है।

(५) स्वयं पूर्ण कार्यशीलता (Automaticity)—मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं ही चलती रहे और जिसमें सरकार का हस्तक्षेप का अधिक आवश्यकता न हो। निम्न प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है उसमें जनता का विश्वास कम हो जाता है अतः मुद्रा प्रणाली स्वयं पूर्ण कार्यशील होना चाहिए जिसमें उन्हीं प्रतिबिम्बित न रहे।

(६) जनता का विश्वास (Public Confidence)—मुद्रा लोग के मान नुसार एक उत्तम या श्राव्य मुद्रा प्रणाली का विशेष गुण यह है कि वह जनता में यथेष्ट स्थान बना ले और लोगों का उसमें विश्वास हो । यदि जनता का उसमें विश्वास न होगा तो मरल व सरल प्रणाली का चलाना भी नष्ट हो जायगा । विश्वास बनाने के लिए प्रणाली में मूल्य स्थिरता लाने को सामर्थ्य होनी चाहिए ।

सारांश—मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत छोटे व बड़े मूल्य की सब प्रकार की मुद्राएँ चल सकें जिसमें छोट मोट सब प्रकार के भुगतान में सुविधा रहे । मुद्रा प्रणाली लोचदार, कम खर्चीली, सरल तथा एसी होना चाहिए जिसमें परिनिधि के अनुरूप परिवर्तन हो सके ।

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)

परिचय (Introduction)—ग्रेशम का नियम मनुष्य के स्वभाव पर प्राप्ता रिक्त है । जब मने या अच्छे और पुर्ण या गिम हुए मिके मान का स विधियाएँ होने हैं, तो मनुष्य अपने खरीद के लिए प्रायः पुराने या घिमे हुए मिके का काम में लाता है और अच्छे या नये मिके को अपने पास भणित रखने हैं । उदाहरणार्थ किसी मनुष्य की जेब में एक छोटा या घिमा रुपया तथा एक अच्छा या नया रुपया हो तो वह पहला रुपया या पुराने रुपया का चलाने का ही प्रयत्न करता है । उगो प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास एक चाँदी का मिके हो और दूसरा चाँदी का मोटा हो, तो स्वभावतः वह व्यक्ति चाँदी के मिके का चलाने का प्रयत्न करता है और मोटे में भुगतान करता है । यदि किसी के पास एक सिक्का तथा मोटा हो और दूसरा पैसा हो तो वह पैसा मोटे का पहला चलाने का प्रयत्न करता है और नये मोटे को अपने पास रख लेता है । इन सब उदाहरणों में यह स्पष्ट है कि बुरी या घिमी मुद्राओं का लोग चलाने का प्रयत्न करते हैं और अच्छी या नई मुद्राओं का चलाने का प्रयत्न नहीं करते । यह मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति ही ग्रेशम का नियम है ।

इस नियम का नाम सर थॉमस ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) के नाम पर रखा गया है जो कि लंदन का एक प्रसिद्ध व्यापारी था और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ (Elizabeth) का आर्थिक सलाहकार था । एलिजाबेथ ने पहला ल्यूडर (Luder) राजशाही में बहुत ही निष्पक्ष और घिमी हुई मुद्राएँ चलाने की थीं । इंग्लैंड में मनुष्यों की देश के लिए बाधा की बात नहीं थी । इसलिए महारानी ने बाह्य देशों से निर्यात वस्तु की पूर्ण मात्रा के लिए लंदन में परन्तु जैसे ही नये मिके चलाने में आये, वैसे ही वे निकलने लगे । इस प्रकार कई बार नये मिके प्रचलित किये गए परन्तु वे चलन में बाहर हो गए । चित्तिन हाकर एलिजाबेथ ने सर थॉमस ग्रेशम के सलाह की । ग्रेशम ने बताया कि जब किसी देश में अच्छी और बुरी मुद्राएँ एक साथ प्रचलित होती हैं, तो अच्छी मुद्रा चलन में लोप हो जाती है क्योंकि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन में निर्यात बाहर करती है । मुद्रा की यह प्रवृत्ति अर्थशास्त्र में ग्रेशम के नियम या सिद्धान्त के नाम से विख्यात है । इस नियम का प्रति-

1—The main need of the hour today is more confidence. There can be no surer route to—establishment of confidence than the stabilization of exchanges' —L. Robbins

पादन प्रेशम से पहले भी हो चुका था, परन्तु प्रेशम ने ही सबसे पहले इसे वैज्ञानिक ढंग में रखा था। मेकलियाड ने सर्व प्रथम इस नियम का नाम 'ग्रेशम का सिद्धान्त' रखा।

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)—ग्रेशम का नियम इस प्रकार है बुरी या निकुष्ट मुद्रा में अच्छी या उत्कृष्ट मुद्रा को चलन से बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है।^१

नियम की कुछ ज्ञातका वात

(१) बुरी एवं 'अच्छी' मुद्राएँ (Bad & Good Money)—ग्रेशम का नियम सम्भन्ध के लिये 'बुरी' और 'अच्छी' मुद्राओं का अर्थ समझना आवश्यक है। बुरी मुद्रा का अर्थ यहाँ केवल खोटी मुद्रा से ही नहीं है बल्कि उस मुद्रा से भी है जो अपनी जैसी मुद्राओं की प्रपेक्षा तोल में कम हो या रूप-रंग और प्राकृति में बुरी हो, मैसी हो, बिसी हो धमका कटी फटी हो। यही नहीं यदि दो धातुओं की मुद्राएँ किसी निश्चित मिलनियम पर पर देश में प्रचलित हों, तो बाजार-दर पर कम मूल्य की मुद्रा बुरी या निकुष्ट मुद्रा होगी और उसके अनुपात में अधिक मूल्य की मुद्रा अच्छी या उत्कृष्ट मुद्रा कहलायेगी।

(२) ग्रेशम नियम की विचित्रता—ग्रेशम के नियम में एक बड़ी विचित्रता है। साधारणतया अनुप्य वस्तुओं के अति में उत्तम वस्तु का उपयोग करता है और बुरी या निकुष्ट वस्तु का बहिष्कार करता है। परन्तु मुद्रा के चलन में यह बात विरुद्ध विपरीत देखी जाती है। बुरी मुद्राओं को लोग काम में लाते हैं और अच्छी मुद्राएँ संचित कर रखते हैं। इसका कारण यह है कि अच्छी मुद्रा में धातु के रूप में मूल्य अधिक होता है, इसलिये या तो गाड़ कर अपने अनुत्पादित सचय (Hoarding) के रूप में रख देने हैं या उसको गला कर जेवर आदि बना लेते हैं अथवा उनको विदेशी भुगतान के लिये निर्यात में भेज देते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा को खरीद कर धातु के मूल्य में भुगतान स्वीकार करता है।

मार्शल (Marshall) द्वारा इस नियम की परिभाषा—प्रो० मार्शल ने इस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है बुरी या निकुष्ट मुद्राएँ यदि मात्रा में सीमित नहीं हैं तो अच्छी या उत्कृष्ट मुद्राओं को चलन से बाहर निकाल देती हैं।^२ इस परिभाषा में मार्शल ने अपनी ओर से ही ये शब्द लगाये हैं यदि मात्रा सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि बुरी मुद्रा की मात्रा सीमित हुई और अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएँ मिलकर लोगों का मुद्रा की आवश्यकताओं से कम हुई तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का चलन से बाहर नहीं निकाल सकेगी। परन्तु यदि बुरी मुद्रा की मात्रा असीमित हुई, तो वही मुद्रा भुगतान करने के काम में अपनी रहेगी और अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जायेगी।

ग्रेशम नियम के नाम होने की परिस्थितियाँ, अर्थात् ग्रेशम-नियम का क्षेत्र (Scope)—ग्रेशम का नियम निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में किसी देश में लागू होता है—

1—Bad money tends to drive good money out of circulation

2—An inferior Currency, if not limited in quantity, will drive the superior Currency out of circulation

—Marshall

(१)—एक धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत (Under Mono metal-
 lism)—जब किसी देश में एक ही धातु बने किन्तु विभिन्न तोल (Weight)
 या विभिन्न शुद्धता (Pineness) अथवा विभिन्न तोल व शुद्धता के सिक्के
 एक ही संकित मूल्य (Face Value) पर प्रचलित हों, तो बुरे सिक्के अच्छे
 सिक्कों को चलन से बाहर कर देंगे । यहाँ बुरे सिक्कों में धर्म है कम तोल या शुद्धता
 वाले सिक्को से और अच्छे सिक्को में है पूर्ण तोल या शुद्धता वाले सिक्कों में
 धर्म उदाहरणार्थ, जब हमारे देश में एडवर्ड के रुपये चल रहे थे तब एक रुपये के नोट
 और निकल के रुपये बनाये गये, तो जीझ ही एडवर्ड के रुपये जो अच्छी मुद्रा थी चलन
 से लुप्त हो गई ।

(२)—द्वि-धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत (Under Bi-metallism) —
 जब किसी देश में दो विभिन्न धातुओं के सिक्के अलग-अलग किसी
 निश्चित अनुपात पर प्रचलित हों, तो जिस धातु का मुख्य बाजार में बड़
 जाता है उस धातु के सिक्के चलन से हट जाते हैं ? उदाहरणार्थ, मास लीजिये
 किसी देश में सोने और चाँदी दोनों के सिक्के प्रचलित हैं और उसका टकमाली- अनुपात
 १:१५ है, अर्थात् एक सोने का सिक्का बराबर है १५ चाँदी के सिक्कों के । यदि
 बाजार में चाँदी का भाव बढ़ जाय और एक सोने के सिक्के में केवल १४ चाँदी के
 सिक्के मिलने लगें, तो इसका अर्थ यह होगा कि दोनों सिक्कों की कागुनी विनिमय दर
 या टकमाली-अनुपात और बाजार-विनिमय-दर में अंतर हो गया, अर्थात् टकमाली
 अनुपात १:१५ है और बाजार-अनुपात १:१४ हो गया । ऐसी परिस्थिति में चाँदी के
 सिक्के अधिमूल्यित (Over-valued) हो गये और सोने के सिक्के अधोमूल्यित
 (Under valued) हो गये । अब प्रत्येक व्यक्ति चाँदी के १५ सिक्के बेकर सोने का १
 सिक्का लेने के स्थान में चाँदी के १४ सिक्के गलाकर बाजार में उनकी चाँदी के बदले में
 सोने का एक सिक्का खरीदने लगेगा और इस प्रकार उसे चाँदी के एक सिक्के की बचत हो
 जायगी । अतः चाँदी के सिक्के चलने लगेंगे और चलन में सोने के सिक्के ही रह जायेंगे । इसी
 प्रकार चाँदी का बाजार-भाव फिर जाने पर बाजार-विनिमय-दर १:१६ हो जायगी
 अर्थात् चाँदी अधोमूल्यित हो जायगी और सोना अधिमूल्यित हो जायगा जिसके फल-
 स्वरूप चाँदी (बुरे सिक्के के रूप में) चलन में रहेगी और सोना (अच्छे सिक्के के रूप
 में) चलन में हट जायगा ।

इन प्रकार द्वि-धातुमान प्रणाली में वैधम का नियम लागू होगा ।

(३)—पत्र-विनिमय के अन्तर्गत (Under Paper Standard)—यदि
 किसी देश में उसकी वास्तविक आवश्यकता में अधिक पत्र मुद्रा जारी कर दो
 जाय, तो मूल्यवान् धातुओं के सिक्के चलन से हट जायेंगे । सम्परिवर्तनीय पत्र-
 मुद्रा मूल्यवान् धातु-मुद्रा की तुलना में प्रचल्य ही खराब है । यदि इसको मात्रा में
 प्रसाधारण्य रूप में वृद्धि कर दी जाय, तो अच्छी मुद्रा अर्थात् धातु के सिक्के चलन में हट
 जायेंगे । मुद्राकाल में जब हमारे देश में रुपये के सिक्के तथा नोट चलने लगे तो धोरे-
 धोरे रुपया का चलन बन्द हो गया और नोटों की संख्या बढ़ती गई ।

(६) द्विधातुमान के अन्तर्गत यदि टकगत्ती-दर (Mint Ratio) और बाजार-दर (Market Ratio) समान रहे जहाँ अथवा टकसाली दर को बाजार-दर के साथ साथ बदलता हुआ रखा जाय तो यह नियम लागू नहीं हो सकेगा ।

(७) नियन्त्रित चलान्ध प्रणाली (Managed Currency System) अथवा पत्रमान (Paper Standard) के अन्तर्गत यदि पत्रमुद्रा का चलानाधिक्य (Over issue) नहीं होने दिया जाय तो यह नियम लागू नहीं हो सकेगा । पत्रमुद्रा का चलानाधिक्य होने में इसका मूल्य धातु मुद्रा की तुलना में गिर जायगा और लोग धातु मुद्रा को संचय करने लग जायेंगे ।

भारतवर्ष और श्रेष्ठम का नियम—भारतवर्ष में समय-समय पर प्रचम का नियम लागू होता रहा है । ११ वीं शताब्दी के मूल में तथा इस शताब्दी के प्रारम्भ में यहाँ पर चाँदी के रूप्य तथा सोने के मात्रिन (Sovereigns) चलते थे । सोने के मात्रिन को लोग गला गला कर जेवर बनवान के काम में लाने से या संचित कर रखने से या विदेशी भुगतान के लिये विदेश में निर्यात कर देते थे । द्वितीय महायुद्ध-काल में भी श्रेष्ठम का नियम लागू होता रहा है । चाँदी की कमी के कारण सरकार ने नये रूप्य में चाँदी की मात्रा कम कर दी जिसमें देश में दो प्रकार के रूप्य हो गये । अधिक चाँदी की मात्रा वाले रूप्य को लोग संचय करने लगे अथवा गला कर बेचने लगे और देवल कम चाँदी वाले रूप्य ही चलन में रह गये । उस समय अपरिवर्तनीय पत्रमुद्रा अर्थात् एक रूप्य के कागज के नोट भी चलते थे । तब इन नोटों और चाँदी के सिक्कों में प्रति-योगिता होने लगी । नोटों ने चाँदी के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया ।

मुद्रा का मूल्य निर्धारण

(Determination of Value of Money)

मुद्रा के मूल्य का अर्थ—पिछले अध्यायों में यह बताया जा चुका है कि विभिन्न वस्तुओं का मूल्य रूप्ये अथवा मुद्रा के रूप में प्रकट किया जाता है । परन्तु मुद्रा का मूल्य हम मुद्रा के ही रूप में तो प्रकट नहीं कर सकते । यह कहना कि एक रूप्ये का मूल्य एक रूप्य है—कोई तथ्य नहीं रहता । इसलिये मुद्रा का मूल्य प्रकट करने के लिये हम माध्यम वस्तुओं की सहायता लनी पड़ी और इसलिये मुद्रा का मूल्य भी वस्तुओं के मूल्य के साथ के समान होता है । यदि हम एक रूप्ये के बदल वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकते हैं तो रूप्ये का मूल्य अधिक होता है और यदि एक रूप्य के बदल वस्तुओं और सेवाओं की कम मात्रा प्राप्त होती है तो रूप्य का मूल्य कम होता है । इससे विपरीत, जब वस्तुओं का मूल्य कम हो तो हमको मुद्रा के बदल इनकी मात्रा अधिक प्राप्त होती है अर्थात् मुद्रा का मूल्य अधिक होता है । इस प्रकार वस्तुओं का मूल्य अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य कम होता है और वस्तुओं का मूल्य कम होने पर मुद्रा का मूल्य अधिक होता है । सरल यह है कि मुद्रा व मूल्य में वृद्धि या आगम वस्तुओं के मूल्य में कमी से होता है और मुद्रा व मूल्य में कमी का आगम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से होता है । मुद्रा मूल्य का इस प्रकृति को मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) कहते हैं जिसका विस्तृत विवेक प्रायः लिया जाता है ।

मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त

(Quantity Theory of Money)

परिचय (Introduction)—जिस प्रकार वस्तुओं का मूल्य उनकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर होता है। प्रस्तु, दोनो के लिये मूल्य-निर्धारण वा एक ही सिद्धान्त हो सकता है। परन्तु मुद्रा के माँग और पूर्ति पक्षों की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिससे मुद्रा के मूल्य निर्धारण का पृथक् सिद्धान्त हो सकता है, यद्यपि कुछ सर्वसाधारण अर्थ भी दोनों के लिये एक ही सिद्धान्त रखने के पक्ष में हैं।

मुद्रा की माँग (Demand for Money)—प्रत्येक वस्तुओं की माँग मुद्रा वस्तु का प्रत्यक्ष रूप में कोई उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं मुद्रा में उपयोगिता नहीं होती बल्कि इसका उपयोग अन्य वस्तुओं को इसके द्वारा प्राप्त करने में होता है। सैलिगमैन (Seligman) के अनुसार "मुद्रा एक प्रकार का टिकट है जो इसके स्वामी को इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करने में सहायता करता है, यह विनिमय-माध्यम है।" मुद्रा एक क्रय-शक्ति (Purchasing Power) है और इसकी आवश्यकता और माँग इसलिए होती है कि वर्तमान युग में मुद्रा के बिना किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये मुद्रा की माँग अन्य वस्तुओं की माँग पर निर्भर है। यदि वस्तुओं की माँग अधिक होती तो मुद्रा की माँग भी अधिक होगी। मुद्रा की माँग की एक विशेषता यह है कि इसमें माँग की तीव्रता इकाई के बराबर होती है जबकि अन्य वस्तुओं में ऐसा कभी-कभी ही होता है। लोग मुद्रा की मात्रा की माँग नहीं करते हैं बल्कि उसकी क्रय शक्ति की मात्रा की माँग करते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति पहले से दुगुनी हो गई है और, अन्य बातें स्थिर रहे तो लोग उन्हीं वस्तुओं के खरीदने के लिये दुगुनी मुद्रा की माँग करेंगे, यद्यपि मूल्य दुगुने हो जावेंगे। इसी प्रकार यदि मुद्रा की पूर्ति आधी हो गई है, तो लोग आधी मुद्रा की ही माँग करेंगे, क्योंकि मुद्रा का मूल्य अर्धान्तर उसकी क्रय-शक्ति बढ़ जायगी।

मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money)—मुद्रा की पूर्ति से आशय है प्रचलित मुद्रा के कुल स्टॉक से। इसमें केवल धातु मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा ही सम्मिलित नहीं होती है बल्कि बैंक द्वारा निकाले जाने वाला बैंक-जमा भी सम्मिलित होता है। मुद्रा की कुल प्रभावपूर्ण पूर्ति की गणना करते समय मुद्रा के चलन की गति (Velocity of Circulation) का भी विचार करना होगा। मुद्रा की चलन गति में यह आशय है कि मुद्रा की प्रत्येक इकाई दिये हुए समय में कितने बार हाथ बदलती अर्थात् हस्तान्तरित होती है। उदाहरणार्थ, १००० हजार रुपये प्रचलित है और प्रत्येक रुपया पाँच बार हाथ बदलता है, तो मुद्रा की कुल पूर्ति ५,००० होगी।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का मूल स्वरूप (Original form)—मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त हमने प्रारम्भिक रूप में इस प्रकार है, : यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो मुद्रा का मूल्य उसके चलन के परिमाण के अनुसार ठीक उसके विपरीत अनुपात में बदलता रहता है।^१ उदाहरण के लिये, यदि प्रचलित मुद्रा का

1—Other things being equal, value of money varies exactly in inverse proportion to its quantity in circulation

परिमाणु दुगुना हो जाता, तो उसका मूल्य आधा हो जाता है। किन्तु अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। उनके सम्बन्ध में, यदि उनकी पूर्ति के बढ़ने से उनका मूल्य घट जाता है और घटने में बढ़ जाता है, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यह समान अनुपात में हो। किन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में ऐसा ही है।

‘यदि अन्य बातें स्थिर रहें’ शब्दों का महत्त्व—सिद्धान्त के ये शब्द बहुत ही महत्त्वशाली हैं। इनमें कई मान्यताएँ सम्मिलित हैं, जैसे—(१) केवल विधि-माला मुद्रा ही चलन में हो, (२) मुद्रा की चलन-गति (*Velocity of Circulation*) में कोई परिवर्तन न हो, (३) मुद्रा बनाकर न रुकी जाय—सब की सब चलन में हो, (४) सब वस्तुओं का प्रत्य-विशेष मुद्रा से ही होता हो, (५) उच्चा प्रवाह न हो, (६) वस्तुओं के चलन की गति में कोई अन्तर न पड़े, (७) उत्पादन, वितरण-प्रत्य और ऊर्ध्व-सम्बन्ध में भी कोई परिवर्तन न हो। किन्तु इस परिवर्तनशील समाज में ऐसा होना सम्भव नहीं है।

सिद्धान्त का मूल समीकरण (*Original Equation of the Theory*) सामान्य मूल्य-स्तर, मुद्रा का परिमाण, मुद्रा की गति और मुद्रा का सम्बन्ध इस प्रकार व्यक्त किया गया था :

$$P \cdot T = M \cdot V \text{ or } P = \frac{M \cdot V}{T}$$

$$\text{गु. ग.} = \text{मु. ग. या मु.} = \frac{\text{मु. म.}}{\text{ग.}}$$

यहाँ पर P का अर्थ है मूल्य-स्तर (μ) में, T का अर्थ है व्यापारिक सम्बन्ध (γ) में, M का अर्थ है मुद्रा के परिमाण (μ) में, और V का अर्थ है मुद्रा की गति (γ) में।

उपरोक्त समीकरण (*Equation*) के दो पक्ष हैं—एक तो वस्तु या माल-पक्ष (*Goods Side*) जो $P \cdot T$ द्वारा प्रदर्शित किया गया है और दूसरा मुद्रा-पक्ष (*Money Side*) जो $M \cdot V$ द्वारा प्रकट किया गया है। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिये। प्रस्तुत समस्त व्यापार का ($P \cdot T$ या $\mu \cdot \gamma$) बराबर होना चाहिये। मुद्रा की समस्त प्रभावपूर्ण पूर्ति ($M \cdot V$ या $\mu \cdot \gamma$) के केवल मूल्य-स्तर P (μ) $M \cdot V$ ($\mu \cdot \gamma$) को T (γ) में विभाजित कर मान्य किया जा सकता है।

इस समीकरण का अर्थ-व्यक्तिपूर्ण है, क्योंकि यानु एव एव-मुद्रा के प्रतिरिक्त माल-पक्ष, जैसे—पैय, विल व दुर्गियाँ आदि भी आधुनिक सम्य समाज में प्रत्य-शक्ति के साधन हैं। इसलिये इन्हें भी सम्मिलित करना चाहिये। साख-मुद्रा (*Credit Money*) के प्रतीक $M' \cdot V'$ ($\mu' \cdot \gamma'$) इस समीकरण में दाईं ओर जोड़ देने से यह पूर्ण हो जाता है और यह एक नया रूप धारण कर लेता है।

सिद्धान्त का आधुनिक रूप—यह सिद्धान्त नये रूप में इस प्रकार प्रति-पादित किया जाता है : “मूल्य के मापण स्तर की प्रवृत्ति प्रचलित मुद्रा के परिमाण और उसी चलन की गति की औसत के गुणनफल (अर्थात् मुद्रा की पूर्ति) के परिवर्तन के अनुसार उसी दिशा में तथा अनुपात में बदलने की रहती है और विविध के बापों (अर्थात् मुद्रा की मात्रा) के जो विविध के लिये धार्य हुए सामान तथा

उनके मूल्य के गुणवत्तन से निर्धारित होते हैं, परिवर्तन के अनुसार ठीक उनके विपरीत बढ़ा तथा अनुपात को बदलने की रहती है।”

प्रो० इविंग फिशर का सूत्र (Formulae)—

$$PT = MV + M'V' \text{ or } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$\text{मू. व्या} = \text{मु. व} + \text{मु' व'} \text{ या मू. व्या} = \frac{\text{मु. व} + \text{मु' व'}}{\text{व्या}}$$

यहाँ पर P सामान्य मूल्य-स्तर (मू)

T = समस्त व्यापारिक कीदें (व्या)

M = प्रचलित मुद्रा (पानु एव वन-मुद्रा का परिमाण) (मु)

V = मुद्रा की गति (व)

M' = साव्य मुद्रा (मु)

V' = साव्य मुद्रा की गति (व')

इस नियम में मुद्रा की गति को उसकी मात्रा के बराबर बताया गया है। मूल्य-स्तर को व्यापारिक लेन-देन से घुणा करने पर व्यापारिक लेन-देन का मूल्य आता है, जिसका अर्थ है मुद्रा की मात्रा (PT या मू व्या) यह मुद्रा की गति के बराबर है, इसमें रोकड़ी मुद्रा व साव्य मुद्रा अलग चलन की गति के साथ है।

($MV + M'V'$ या $\text{मु. व} + \text{मु' व'}$) ।

प्रो० फिशर ने प्रस्तावित है कि अल्पकाल में T, V, V' (व्या, व, व') स्थिर रहने हैं। M' का M (मु' का मु) में अनुपात भी समान रहता है। अतः P (मू) M (मु) के अनुसार बदलता है। दूसरे शब्दों में, यदि M (मु) को बढ़ा दें तो P (मू) उसी अनुपात में बढ़ जायगा। मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण अर्थात् मात्रा पर निर्भर है। इसलिये इस सिद्धान्त को 'मुद्रा का परिमाण-निर्धारण' कहते हैं।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

(१) इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह सिद्धान्त कुछ कल्पनाओं पर आधारित है अर्थात् श्रम्य बातें स्थिर रहने पर यह लागू होता है। परन्तु वास्तव में इस परिवर्तनशील जगत में ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं—कभी प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, कभी जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ने लगता है, कभी मुद्रा के चलन की गति में परिवर्तन होना लगता है और कभी साव्य-मुद्रा की मात्रा में बढ़ाव हो जाता है। अल्पकाल में भी ये परिस्थितियाँ जमी की तैमरी नहीं रहती। अतः मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक स्थायी मूल्य नहीं जान पड़ता।

(२) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण (Equation) में यह निदि करने का प्रयत्न किया है कि प्रचलित मुद्रा की मात्रा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से सामान्य मूल्य-स्तर में समानुपातिक परिवर्तन कर देता है। परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता।

1. The general level of prices tends to vary directly in proportion with the quantity (i.e. supply) and inversely with the activity of exchange (i.e. the demand for money) indicated by the number of goods to be exchanged & multiplied by their prices.

(३) प्रो० कीन्स का कहना है कि मुद्रा द्वारा किये अधिकांश लेन-देन या तो औद्योगिक-सम्बन्धी होते हैं या व्यापार या आर्थिक-सम्बन्धी होते हैं। उनमें से बहुत कम वस्तु-सम्बन्धी लेन-देन हैं जिनको व्यापार की माना में प्रबल किया जाता है। अतः प्रसार का समीकरण मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं नापता है बल्कि रोबो लेन-देन के स्तर को नापता है।

(४) प्रो० मार्शल का कहना है कि 'मुद्रा का सिद्धान्त चलन की गति के कारणों की व्याख्या नहीं करता।'।

(५) इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग की अपेक्षा पूर्ति पर ही अधिक बल दिया गया है जिसका प्रभाव मुद्रा की कृप-शक्ति या वस्तुओं के मूल्यों पर अधिक पड़ता है।

(६) यह सिद्धान्त व्यापार-चक्रों (Trade Cycles) में होने वाले मूल्य-स्तर के परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है।

(७) कुछ लोगों का विश्वास है कि यह सिद्धान्त मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित एक स्वयं-सिद्ध सत्य है जिसको बहुत अधिक महत्त्व दे दिया गया है।

(८) यह सिद्धान्त कल्पनिक गण्य अपूर्ण है क्योंकि इसमें हम किसी भी भ्रम मुद्रा चलन के परिमाण का ठेक-ठीक आंकड़ा नहीं मापूँ कर सकते जो केवल अनुमान पर निर्भर है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन बातों को हम स्थिर मानते हैं वे वास्तविक दृष्टि में कभी स्थिर नहीं रहती। अतः यह सिद्धान्त केवल स्थिर समाज को ही लागू हो सकता है, परिवर्तनशील समाज को नहीं।

(९) किसी विशिष्ट देश के मूल्यों की तेजी-थमी के कारणों का विवेचन इस सिद्धान्त द्वारा नहीं हो सकता तथा उसके लिये अन्य देशों के मूल्यों का सर्वत्र मेका आवश्यक है।

सिद्धान्त की वास्तविक उपयोगिता—यद्यपि इस सिद्धान्त के विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और उनमें से कुछ सही भी हैं, परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त का अपना कुछ महत्त्व अवश्य है।

(१) आर्थिक सिद्धान्त होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की विवेचना करता है।

(२) यह हमें बतलाता है कि यदि अन्य बातों का उचित ध्यान रखा जाय तो मुद्रा प्रसार, मुद्रा-संकुचन तथा व्यापारिक क्रियाया का क्या प्रभाव पड़ेगा।

(३) सामान्य मूल्य-स्तर को घटाने व बढ़ाने के विचार में मुद्रा-प्रसार व मुद्रा संकुचन करते समय मुद्रा अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हैं।

(४) यह सिद्धान्त हमें मूल्य-परिवर्तन का एक मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बतलाता है। इसी सिद्धान्त के सहारे प्रचलित मुद्रा की माना में न्यूनाधिकता व अधिकता के मूल्य स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।

(५) यह सिद्धान्त मूल्य की स्थिर बनाने के मार्ग का प्रदर्शन करता है। रॉबर्टसन (Robertson) नामक एक मुद्रा शास्त्री ने लिखा है कि—“मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिये एक विविध सत्य है—यह एक ऐसा सत्य है जिसे वास्तविक जीवन के अन्तर्गत मुद्रा की माना और वस्तुओं के मूल्यों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए समझना अनिवार्य है।”

(६) क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार इस सिद्धान्त के द्वारा यह बातें मालूम हो सकती हैं कि प्रथम महायुद्ध तथा उसके पश्चात् का मूल्य-स्तर में होने वाला वृद्धि हुई उसका कारण युद्ध-काल में सरकारों द्वारा छपाई हुई पत्र-मुद्रा का ।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन

(Changes in the Value of Money)

परिचय (Introduction)—मुद्रा का मूल्य समय-समय पर बदलता रहता है—कभी मुद्रा का मूल्य ऊँचा हो जाता है और कभी मुद्रा का मूल्य नीचा गिर जाता है और कभी मुद्रा का मूल्य बिल्कुल ठीक रहता है और कभी मुद्रा का मूल्य ऊँचा हो जाता है । इस प्रकार मुद्रा का मूल्य और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है । मुद्रा का मूल्य में परिवर्तन होने से कई लोगों का काम होता है और कुछ को नानि भी होता है । यहाँ पर हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

(१) मुद्रास्फाति (Inflation)

मद्रा स्फाति का अर्थ (Meaning)—जब मद्रा (मिचल नाम और साव मद्रा) का मात्रा किसी देश के व्यापार और उद्योग का आवश्यकताओं से अधिक प्रचलित हो तो उस मुद्रा-स्फाति कहते हैं । कमरर (Kemerer) के अनुसार मुद्रा का मात्रा-मुद्रा का अधिकता का मुद्रा-स्फाति कहते हैं अर्थात् व्यापार के उद्योग के परिमाण में वृद्धि (Currency) के मत मान का मुद्रा स्फाति कहते हैं । प्रा० पीगू (Pigou) के अनुसार जब जब धातु प्राप्त करने वाले कार्यों के अनुपात में अधिकता हो जाती है तो मुद्रा-स्फाति कहता है । प्रायः वक्ता से अधिक मुद्रा प्रसार होने से मुद्रा के मूल्य में ह्रास (Devaluation of Money) हो जाता है अर्थात् मद्रा का क्रय-शक्ति (Purchasing Power) गिर जाता है जिससे परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाता है ।

मुद्रा-स्फाति के चिह्न (Signs)—जिसे दो बातें से मुद्रा-स्फाति का पता चलता है—(१) मुद्रा का क्रय-शक्ति का कम होना (२) जबकि उच्च वस्तुओं के भावों में वृद्धि होना ।

मुद्रा स्फाति के प्रकार (Kinds)—जब धातु वस्तु में वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और मूल्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो ऐसा अवस्था को खुला मुद्रा-स्फाति (Open Inflation) कहते हैं । यदि धातु वृद्धि का मद्रा के अन्दर नहीं रखा जाता तो मुद्रा प्रसार बन्द हो जाता है । तब इस अवस्था को मुद्रा-स्फाति (Galloping Inflation) कहते हैं । जब धातु अधिक मुद्रा प्रसार हो जाता है तो इस अवस्था को मुद्रा स्फाति Hyper Inflation) कहते हैं । प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अनेक देशों में आपस में मुद्रा स्फाति हुई । जर्मनी में भी ऐसा हुआ । उस समय धारणा बिया । सरकार ने नए अधिक मात्रा (Marks) छपा दिये कि उनका मूल्य भी मूल्य में रह गया । बहुत अवस्था होनी ही में १९४८-४९ में चीन का मुद्रा

की हुई। मुद्रा-स्फीति केवल वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में ही प्रतिबिम्बित नहीं होती, बल्कि सोम रोकटो धन को छानने पास व बैंक में जमा करने लग जाते हैं और अन्य सम्पत्ति को भी रखने लग जाते हैं, तब मुद्रा स्फीति इन कारणों में भी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार की अवस्था को छिपी हुई मुद्रा स्फीति (Suppressed Inflation) कहते हैं।

मुद्रा स्फीति के कारण (Causes) मुद्रा स्फीति के कारणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) नैसर्गिक कारण और (२) कृत्रिम कारण।

(१) नैसर्गिक कारण (Natural Causes) नैसर्गिक या स्वाभाविक कारणों में हम ऐसे कारणों का समावेश करते जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते बल्कि स्वाभाविक होते हैं, जैसे—[अ] सोने या चांदी की खाना में अधिक उत्पादन होना, [आ] नई खानों की खोज तथा [इ] सोना चांदी का अधिक आयात होने लगना। सन् १८६६ से १९११ तक दक्षिणी अफ्रिका में सोने की नई खानों की खोज के कारण मूल्य में वृद्धि हो गई।

(२) कृत्रिम कारण (Artificial Causes)—

(अ) वस्तुओं और सेवाओं की कमी (Scarcity of Commodities and Services) — जब मुद्रा की पूर्ति तो बहुत बढ़ जाती है परन्तु वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति मुद्रा के बराबर नहीं बढ़ती तो वस्तुओं और सेवाओं की इस कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। केमरर नामक मुद्रा शास्त्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि— यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय, तो मुद्रा स्फीति होती है।^१

(आ) जमा की गति में वृद्धि (Increase in Deposit Velocities) — बैंक जमा मुद्रा में भारी वृद्धि होना भी मुद्रा स्फीति का एक कारण है। उदाहरण के लिए यदि बैंक जमा बहुत बढ़ जाते हैं।

(इ) सरकार के बजट की कमी पूर्ति के लिये मुद्रा प्रसारण (Monetization for Govt. Deficits) — इसके अन्तर्गत सरकारी व्यय के भुगतान के लिये, कोष बढ़ाने के माध्यमों के लिये, सरकार द्वारा मुद्रा प्रसारण किया गया हो सके सम्बन्ध में बातें हैं। इसमें बैंक नोट व बैंक जमा सम्मिलित हैं।

(ई) जान-बूझ कर सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि (Deliberate increase in Quantity of Money by Govt) — यदि प्रादिक मण्डल में देश की सरकार जान-बूझ कर मुद्रा का प्रसारण करती है। मुद्रा सम्बन्धी बाजारों व लिये अत्यधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है जो प्रायः अपरिवर्तनीय व प्रचलित व पूँजी की जाती है। इनसे मुद्रा स्फीति हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, जब देश के उद्योग धन्य का विकास करने के लिए देश की सरकार जागतिक मूल्य स्तर की धोखा देना का धान्य मूल्य स्तर को बढ़ा करना चाहती है, तब वह माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर देता है।

मुद्रा-स्फीति के आर्थिक परिणाम (Economic Consequences of Inflation) से तो मुद्रा-स्फीति में सामान्यतः देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुँचती है, किन्तु भी विभिन्न वर्गों को मुद्रा-स्फीति विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। मुद्रा-स्फीति विभिन्न वर्गों को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है :—

(१) व्यापारियों और उत्पादकों को लाभ—मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं जिसमें उद्योगपतियों, उत्पादकों तथा व्यापारियों (खरिद व बिक्री व्यापारियों) को बहुत लाभ होता है। उन्हें मुख्यतः तीन कारणों से लाभ होता है : (अ) उनमें में अधिकता ऋणी होते हैं और ऋणियों को मुद्रा-स्फीति से लाभ होता है, (ब) वे ज्यादा मात्रा व अन्य वस्तुएँ पुराने और सस्ते मूल्यों पर खरीदते हैं, किन्तु वेबने उस समय है जब मूल्य बढ़ जाते हैं, (स) मजदूरी व अन्य व्यय इतने अधिक नहीं बढ़ते जितना मूल्य बढ़ते हैं। व्यापार एवं उद्योग धन्या में लाभ बर्तन में उत्पादन (Production) को प्रोत्साहन मिलता है, और रोजगार (Employment) में वृद्धि होती है।

(२) ऋणियों (Debtors) को लाभ और ऋणदाताओं (Creditors) को हानि—मुद्रा-स्फीति से मुद्रा की क्रय-शक्ति गिर जाती है जिससे ऋणियों को लाभ होता है और ऋणदाताओं को हानि होती है। ऋणियों को इसविधे लाभ होता है कि जब उन्होंने ऋण लिया था तब मुद्रा की क्रय-शक्ति अधिक थी, वे उससे अधिक वस्तुएँ खरीद सकते थे, परन्तु वे ऋण अब छोटा रहे है, जबकि मुद्रा की क्रय-शक्ति कम है तो इससे ऋणदाताओं को हानि होती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने सन् १९३६ में १०० रु० उधार दिये और वह राशि सन् १९५१ में उसे लौटाई गई, जब कि वस्तुओं के भाव पहले की अपेक्षा चौगुने हो गये, तो ऋणी को इससे लाभ हुआ, क्योंकि सन् १९३६ में इस राशि से वह चौगुनी वस्तुएँ खरीद सकता था और ऋणदाता को हानि हुई क्योंकि अब (सन् १९५१ में) वह राशि २५ रु० के बराबर है, अर्थात् वह इससे पहले की अपेक्षा बवल नौपाई वस्तुएँ ही खरीद सकता है।

(३) विनियोग-कर्त्ताओं (Investors) को मुद्रा-लाभ होता है और वास्तविक आय (Real Income) में हानि होती है—मुद्रा स्फीति व व्यापार में वृद्धि होने का कारण विनियोग-कर्त्ताओं को मुद्रा-लाभ होता है, क्योंकि उनके विनियोग पत्रों का मूल्य बढ़ जाता है। परन्तु जहाँ तक लाभांश (Dividend) व व्याज (Interest) का सम्बन्ध है, वह निश्चित मात्रा में मिलता है। क्रय-शक्ति कम होने से उनकी हानि होती है, अर्थात् उनकी वास्तविक आय (Real Income) घट जाती है।

(४) कृषकों को लाभ व भूमिपतियों को हानि—वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से कृषकों का, उत्पादकों और व्यापारियों की भाँति लाभ होता है। किन्तु जमींदार व भूमिपतियों (Landlords) को कुछ समय के लिये हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उनका लाभ निश्चित होता है।

(५) श्रमिकों और वेतन-भोगी व्यक्तियों को हानि—यदि वे वेतन पाने वाले व्यक्तियों (सरकारी व अमरकाये नौकर, अध्यापक आदि) को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में वे भुि (मजदूरी) व वेतन बहुत कम

बता है। मुद्रा की कम शक्ति में ह्रास होने से अपना निश्चित भाग में कम वस्तुएँ खरीद सकत है जिससे उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। अतः उन्हें भीयरण आर्थिक कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ता है। उनमें असंतोष फैलता है हताश होती है। उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही प्रकार भ्रष्ट आय काब छोटे छोटे जमींदार और किराये या व्याज की आय पर जीवन निवाह करने वालों का भी भाग्य वृद्धि के कारण वास्तविक आय घट जाने के कारण बुरा उठना पड़ता है।

(६) उपभोक्ताओं का हानि—मुद्रा स्थिति के कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को बहुत हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उन्हें पहले की अपेक्षा अब अधिक मूल्य देने पड़ते हैं जिससे वयन कम हो जाता है। रहन-सहन का व्यय आय की अपेक्षा कम जाता है।

(७) विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव—मुद्रा स्थिति का विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जागतिक मूल्य स्तर में भारतीय मूल्य स्तर ऊँचा होने से मुद्रा स्थिति बालू देग में माना महंगा हो जाता है। अतः परिणामस्वरूप विदेशी कम खरीदते हैं जिससे देग का निर्यात व्यापार कम हो जाता है। इसके विपरीत विदेशी वस्तुएँ मसूरी हानि से उनका आयात देग में कम हो जाता है। इन प्रकार के व्यापार में देग का असंतुलन व्यापार संतुलन (Unfavourable Balance of Trade) हो जाता है।

(८) सरकार के कर-दाताओं पर अनुकूल प्रभाव—जर देग में मुद्रा प्रसार होता है तो सरकार की आय बढ़ जाती है। सरकार प्रभा में करों के रूप में खूब रकम प्राप्त करती है। सरकार नई-नई योजनाएँ बनाती है जिसमें राष्ट्रीय पूँजी की मूल्य वृद्धि होती है। परन्तु दूसरी ओर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण आर्थिक कठिनाईयाँ फैलती हैं अतः आर्थिक हानि का कारण होता है।

मुद्रा स्थिति के निम्न में कर-दाताओं को अवश्य लाभ होता है क्योंकि वृद्धि उच्च कर कुछ अधिक देना पड़ता है परन्तु पहले की अपेक्षा वस्तुओं के अनुपात में वे कम राशि देते हैं। भूमि संपन्न (Land Revenue) का भार भी कम हो जाता है क्योंकि लोग सरकार को वस्तुओं के अनुपात में कम ही देते हैं।

मुद्रा-स्थिति के सामाजिक एवं नैतिक परिणाम

(Social and Moral Consequences of Inflation)

मुद्रा स्थिति के सामाजिक एवं नैतिक परिणाम भी भयंकर होते हैं। सब धनी के लोग का रहन-सहन का व्यय बढ़ता बढ़ जाता है कि इनका जीवन बनाना करना हो जाता है अधिक वष भी बढ़ा हुए धनियों के कारण अतः निश्चित प्रायः में अल्पों आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकत। अतः भविष्य (मजदूरों) बनाने का संघर्ष हताश आदि के रूप में चलता रहता है। मुद्रा स्थिति उपभोक्ताओं से निरपेक्षा निराशा व शत्रु की भावना फैलाती है। उत्पादन में वर्तमान के कारण बाजार में वस्तुओं की कमी का जाता है जिससे लोग वस्तुओं का इकट्ठा कर कर के छिपाने (Hoarding) प्रवृत्ति है। फिर चोरी के भाव उनके भाव पर विकसित लगता है। सरकारी राजस्व घटता है। सट्टाबाजी के लिये यह स्वयं ही प्रेरणा पर लाय उठता है। इस कारण टॉमस (Thomas) ने मुद्रा स्थिति को मुनाफाखोरा (Profiteers) और स्केमिंग के लिये स्वयं कहा है।

(३) उत्पादन में वृद्धि (Increase in production)—उत्पादन-वृद्धि मुद्रा-स्फीति के परिणामों का प्रभाव धूल्य करने का एक मध्यम उपाय सिद्ध हो सकता है। इसके द्वारा मुद्रा की माँग में वृद्धि हो जाती है जिससे आर्थिक मुद्रा-पूर्ति के कुछ प्रभाव नष्ट हो सकते हैं।

मगर यह है कि मुद्रा-स्फीति घटेरूपन वाला सर्वे है जिसे घटेरूपन राशियों में हदना चाहिए। कोई भी घटेरूपन उपाय प्रभावोत्पादक सिद्ध नहीं हो सकता।

भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति—यद्यपि मुद्रा के समर्थन में लगभग सभी देशों ने किसी-न-किसी मात्रा में मुद्रा-स्फीति हुई। भारतवर्ष में भी मुद्रा का अनाश्रय प्रसार हुआ। मुद्रा की माँगा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उसी मात्रा में नहीं बढ़ा जिसके पल्लवरूप मुद्रा का मूल्य (अर्थात् समस्त क्रय-शक्ति) गिर गया और वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये। वर्ष १९३६ में देश में लगभग १७६ करोड़ रुपये के नोट प्रचलित थे परन्तु दिसम्बर १९४७ में प्रचलित नोटों की संख्या लगभग १२४२ करोड़ हो गई। इसी अवधि में रुपये और छोटे मिरकों की संख्या भी क्रमशः लगभग १५० करोड़ और ७५ करोड़ से बढ़ गई थी। साथ-ही साथ साथ-मुद्रा का चलन भी बढ़ता गया।

भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति के कारण—(१) भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मिन राशियों को मुद्रा में सहायता देना था। (२) भारत सरकार ने इंग्लैंड और मिन-राशियों के सहायतायुक्त मुद्रा चलाने के लिये भारतीय बाजारों में मान लीदा। इन मान के बदले में इंग्लैंड की सरकार भारत-सरकार को नकद रुपया नहीं दिया बल्कि इंग्लैंड में भारत के हिस्से में बह राशि जमा कर ली जाती थी और वजने में गिजों बैंक की स्टर्लिंग प्रतिभूमियों (Sterling Securities) दे दी जाती थी। परन्तु भारत सरकार की तो इन मान का मूल्य भारतीय व्यापारियों को रुपये में चुकाना पड़ता था। अतः सरकार नोट छाप-छाप कर यह कार्य करती रही। (३) इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मुद्रा-चाल में प्रथम भी खूब किया जिसकी पूर्ति के लिये सरकार मुद्रा-प्रसार करती गई। (४) दूसरी ओर वस्तुओं का उत्पादन उसी मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सका। जो कुछ भी मान इसमें किया जाता था वह मिनिकों के लिये सेब दिया जाता था। इन कारण जनता के उपयोग के लिये वस्तुओं की कमी हो रही जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती ही गई।

भारत सरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय—(१) मुद्रा की बढ़ी हुई मात्रा की वापिस खींचने के लिये जमा पर गये-गये कर लगाये, (२) जनता से सरकार से ऋण भी लिया तथा सरकार ने मोता की बेचा जिसमें बाजार में प्रथम शक्ति कम हो जाय, (३) वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाया गया तथा देश में उत्पादन-वृद्धि की मुविधाएँ दी गई, (४) वैदेशी तथा राज्य सरकारों ने अपने-अपने व्ययों को भी कम करने का प्रयत्न किया। (५) और बाजारी दूर करने के लिये कठोर नियम भी लगाये गये, (६) जनता से खाली रुपया खींचने के लिये डिबैंक राश व राष्ट्रीय वनत योजनाएँ आदि निराली गई, (७) मद्रों के नोटों पर नियन्त्रण लगाया गया, (८) ती रुपये से ऊपर के नोटों को अविधि ग्राह्य घोषित कर दिया गया, (९) कम्पनियों के लाभांश (Dividends) को दर सीमित कर दी गई। इन सब उपायों के होने पर भी मुद्रा-स्फीति की शक्ति कम नहीं हुई और अब भी लगभग बड़ी शक्ति है जो मुद्रा चल में थी।

(२) मुद्रा सङ्कुचन (Deflation)

मुद्रा-सङ्कुचन का अर्थ (Meaning)—जब किसी देश में मुद्रा (जिसके नोट और सव्य मुद्रा) की मात्रा उसकी आर्थिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की तुलना में कम होती है तब उसे 'मुद्रा-सङ्कुचन' के नाम से सम्बोधित करते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी समय मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग में कम होती है तो उसे हम मुद्रा सङ्कुचन कहते हैं। प्रो० कोन्स के अनुसार "मुद्रा सङ्कुचन वह मुद्रा नाश है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और उसकी आवश्यकताओं के मध्य का अनुपात इतना कम कर दिया जाय कि जिससे मुद्रा की विनिमय शक्ति बढ़ जाय और वस्तुओं के मूल्य नाश हो जायें।" मुद्रा सङ्कुचन से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है (Appreciation of Money) जबकि मुद्रा की मूल्य-शक्ति बढ़ जाती है जिससे परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं।

मुद्रा सङ्कुचन के चिह्न (Signs)—(१) मुद्रा की क्रय शक्ति (Purchasing Power) का बढ़ना (२) लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य गिरना।

मुद्रा सङ्कुचन के कारण (Causes)—मुद्रा सङ्कुचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—(१) सरकार देश में प्रचलित अपरिवर्तनीय नोटों को रद्द कर देती है जिससे मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। (२) अन्तः पर भारी-भारी कर (Taxes) लगा कर मुद्रा की खपत में कम खाल पैदा होता है। (३) देश का केंद्रीय बैंक अपनी बट्टे की दर (Discount Rate) बढ़ा कर मुद्रा सङ्कुचन करता है। (४) केंद्रीय बैंक जनता में ऋण लेकर चलन में से मुद्रा की मात्रा कम कर देता है, और (५) वह अपनी खुली बाजार क्रियाओं (Open Market Operations) द्वारा जनता को निम्नोरीटो नोटें कर बढ़ाने से मुद्रा उबर सक्षित कर सता है जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है।

मुद्रा सङ्कुचन के आर्थिक परिणाम (Economic Consequences of Deflation)—मुद्रा सङ्कुचन के आर्थिक परिणाम मुद्रा-स्फीति से विपरीत होते हैं जो नीचे दिए जाते हैं—

(१) व्यापारियों व उत्पादकों का हानि—मुद्रा सङ्कुचन के कारण वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं जिससे व्यापारियों (बाजार व पुटकर) उद्योगपतियों व उत्पादकों का हानि होती है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य गिर जाने से उनको आम में ह्रास हो जाता है जब कि वे अपने मजदूरों आदि सेमाने हो रहे हैं। उत्पादन कम हो जाता है जिससे बेकारी (Unemployment) फैल जाती है।

(२) ऋणियों का हानि और उत्पादकों का लाभ—मुद्रा सङ्कुचन में ऋण दानों का लाभ और ऋणियों का हानि होती है क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर्याप्त उनकी ऋण शक्ति बढ़ने में ऋणियों का सब अधिक भूत चुकाना पड़ता है।

(३) विनियामक वर्गों का वास्तविक आय का लाभ—मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाने से विनियामकों को निश्चित सामान्य व व्याज में सब अधिक वस्तुएँ प्राप्त होने से वास्तविक आय का लाभ होता है।

(४) वृषका को हानि और भूमिपतिया का लाभ—मन्दी के दिना में वृषका को उनकी उपज का कम मूल्य मिलता है जिसमें उन्हें हानि होती है। परन्तु भूमिपतिया या जमींदारों को उनके निश्चित उद्यान में कम अधिक वस्तुओं प्राप्त होते हैं लाभ होता है।

(५) श्रमिका और वेतन भोगी व्यक्तियों का लाभ—वस्तुओं में भाव निरंतर जान में श्रमिका तथा निश्चित वेतन पान वाले व्यक्तियों का लाभ होता है क्योंकि इससे वे अपनी कार्य करने में अधिक वस्तुओं खरीद सकते हैं। प्रायः मन्दी में मानिक नौकरों की छुट्टी करने तथा वेतन कम कर देना है। ऐसे परिणामों में श्रमिका और वेतन भोगियों (Salaried Persons) को अधिक लाभ रहा रहता है।

(६) उपभोक्ताओं का लाभ—मन्दी में वस्तुओं के मूल्य घटने के कारण उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि उपभोक्ताओं को मन्दी का प्रत्यक्ष फायदा होता है। मन्दी में अधिक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं।

(७) विदेशी व्यापार पर अच्छा प्रभाव—मुद्रा मजबूत का विदेशी व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे हम मूल्य निरंतर जाने में विदेशी वस्तुएँ सस्ती में प्राप्त कर सकते हैं जिससे निर्यात में वृद्धि होती है। तुलनात्मक हानि में विदेशी वस्तुओं में हानि होना संभावित कम होता है। इससे फायदेमंद व्यापार संचालन में मदद मिलती है (Favourable) होता है।

(८) सरकार और वरदानों पर प्रतिकूल प्रभाव—मन्दी के दिना में सरकार को आर्थिक व्यवस्था संभालना पड़ता है। सरकार को धन खर्च करना पड़ता है तथा महामना-कार्य (Relief work) करने पड़ते हैं जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होती है। देश में वित्तीय स्थिति खराब होने से सरकार को ऋण लेना पड़ता है। देश का विकास रुक पड़ जाता है।

मन्दी के दिना में करदानों को भी हानि हो जाती है क्योंकि यद्यपि वे मन्दी में कम कर चुकाने हैं परन्तु वस्तुओं में उन्हें अधिक देना पड़ता है।

मुद्रा मजबूत का सामाजिक एवं नैतिक परिणाम (Social & Moral Consequences of deflation)—मानव-समाज पर मुद्रा मजबूत का प्रभाव राजनैतिक संकट आदि अनेक विपत्तियों समय समय पर आती रहती है। परन्तु इस सबमें अधिक भयंकर विपत्ति मुद्रा मजबूत की है जिससे जिसके प्रत्यक्ष वस्तुओं के भाव में गिरावट कम हो गई है जिससे व्यापार रुक पड़ जाता है उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं समाज की प्रगति रुक जाती है आर्थिक व्यवस्था खिल गति होना लगता है तथा देश का सम्पूर्ण जीवन विगड़ जाता है।

मुद्रा मजबूत का सामाजिक एवं नैतिक परिणाम अत्यन्त ही भयंकर है। मन्दी के कारण उद्योगपति मजदूरों के स्तर को कम करना चाहते हैं जिससे मजदूरों और उद्योगपतियों में संघर्ष बनना रहता है। बेकारी बढ़ती है और सामाजिक अशांति पैदा हो जाती है। जिस प्रकार वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में हड़ताल (Strikes) को रोक मिलता है उसी प्रकार कर्मियों मूल्य हानि वास्तविकता को जानाबूझ (Lockouts) को रोक देता है।

भारतवर्ष तथा अन्य देशों में मुद्रा मजबूत—सन् १९२० से १९३० तक और सन् १९३० से १९४० तक का काल मुद्रा मजबूत का युग कहे जाते हैं। भारतवर्ष

मे मन् १९२० से १९३० तक के काल में मुद्रा-सकुचन की नीति काम में लाई गई जिसके अन्तर्गत लगभग ६० करोड़ रुपये का सकुचन किया गया था। इसी काल में इटली और फ्रांस में भी मुद्रा-सकुचन किया गया था। इटली की सरकार ने मन् १९३१ और १९३४ में दो बार मुद्रा-सकुचन किया। फ्रांस में मन् १९२५ में मुद्रा-सकुचन किया गया था, परन्तु वहाँ जनता के विरोध के कारण यह अधिक सफल नहीं हो सका।

मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-सकुचन (Inflation and Deflation)

किसी देश की आर्थिक प्रगति और व्यापारिक समृद्धि की दृष्टि में, मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-सकुचन दोनों ही हानिकारक हैं। प्रो० कीन्स के अनुसार “मुद्रा-स्फीति प्रत्याघ प्रणाली है और मुद्रा-सकुचन अनुचित है।” (Inflation is unjust and Deflation is inexpedient)।

प्रो० मैलिगमैन का भी कहना है कि “बढ़ते हुए तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण देश के आर्थिक क्षेत्र में एक ऐसी अस्थिरता आ जाती है जिसमें द्विप, व्यापार और उद्योग की स्थिति डरावनी हो जाती है और समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों को विषम अनुपात में लाभ व हानि होती है। ऊँचे और नीचे मूल्यों में इतनी हानि नहीं होती जितनी निरन्तर ऊँचे बढ़ते हुए और नीचे गिरते हुए मूल्यों में हानि होती है।” इसलिए यह साफ है कि न तो ऊँचे चलते हुए मूल्य मर्काट को हितकर होत हैं और न गिरते हुए मूल्यों से ही समाज को लाभ होता है। समाज के हित के लिए तो यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके मूल्य-स्तर स्थिर रखा रहे जिसमें द्विप, व्यापार और उद्योग में प्रगति की आशा बनी रहे। अतः प्रत्येक देश के मुद्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस दोनों रोगों से बचे रहें और मध्यम मार्ग का प्रयत्न करें। आदर्श मुद्रा-प्रणाली में मुद्रा की मात्रा न तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और न कम हो जानी चाहिए।

(३) मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation)

वर्तमान समय में विशेषतः गत महायुद्ध में ही यह शब्द प्रसिद्ध हो गया है। मुद्रा-अपस्फीति वह मुद्रा-नीति है जो देश में मुद्रा-स्फीति को रोक कर उसके दोषों को दूर करने के लिये काम में लाई जाती है। इन नीति को मरन मन्दा में ‘मुद्रा-स्फीति मुधार’ भी कह सकते हैं। गत महायुद्ध-काल में भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति ने बड़ा प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था। अतः इसकी रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा अनेक उपाय काम में लाये गये जिनका वर्णन पीढ़े कूट ४६३ पर किया जा चुका है। ये सब उपाय मुद्रा-अपस्फीति नीति के अन्तर्गत ही आते हैं।

मुद्रा-अपस्फीति और मुद्रा-सकुचन में अन्तर (Difference between Disinflation and Deflation)—यह भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि मुद्रा-अपस्फीति और मुद्रा-सकुचन एक ही ही वस्तु है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। मुद्रा-अपस्फीति के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति को कम करने के उपाय काम में लाये जाते हैं, परन्तु मुद्रा-सकुचन में वस्तुओं के मूल्य को घटाने और मुद्रा की उद्य-शक्ति बढ़ाने के उपाय काम में लाये जाते हैं। दोनों ही नीतियों में मुद्रा की मात्रा कम करनी पड़ती है, परन्तु मुद्रा-अपस्फीति के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा इतनी कम की जाती है कि वह व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं के समानुपात में हो जाय, मुद्रा-सकुचन

ये मुद्रा की मात्रा इनको कम कर दी जाती है कि व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं से भी कम हो जाती है जिससे देश में चांगे और मदी का बालावारा व्यापक हो जाता है। यद्यपि दोनों की एक ही विधि है, फिर भी दोनों नीतियों के उद्देश्य एवं परिणामों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

(४) मुद्रा संस्फीति (Reflation)

आर्थिक विवेचन में प्रायः इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अतः हम इसका भी अर्थ समझ लेना चाहिए। मुद्रा संस्फीति वह मुद्रा-नीति है जिसके अन्तर्गत मुद्रा-प्रसार द्वारा देश में स्थित मुद्रा-संकुचन को रोक कर उसके दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। कावे नामक मुद्रा-शास्त्री के अनुसार "मदी को दूर करने के लिये जान-बूझ कर जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है उसे मुद्रा-संस्फीति कहते हैं।" इसे सरल शब्दों में 'मुद्रा संकुचन मुधार' भी कह सकते हैं। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य मदी को दूर करके मूल्य-स्तर ऊँचा उठाना होता है। इसमें मूल्य-स्तर एक दम ऊँचा नहीं उठता बल्कि धीरे-धीरे ऊँचा उठता रहता है। मदी के कारण देश में बेकारी फैल जाती है उस दूर करने के लिये मुद्रा-संस्फीति का अवलम्बन लिया जाता है।

मुद्रा-संस्फीति और मुद्रा-स्फीति में अन्तर (Difference between Reflation & Inflation) - इन दोनों परिस्थितियों में मुद्रा प्रसार किया जाता है, परन्तु दोनों के उद्देश्य और परिणामों में पर्याप्त अन्तर है। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य मदी को दूर करने मूल्य-स्तर को ऊँचा करना होता है जिसमें बेकारी लोगों को रोजगार मिल सके और जब यह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो मुद्रा-प्रसार करना बन्द कर दिया जाता है। मुद्रा-स्फीति का उद्देश्य एक मात्र मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना होता है जिसमें मूल्य-स्तर एक दम ऊँचा हो जाता है। मुद्रा संस्फीति का सब तक ही अवलम्बन लिया जाता है जब तक कि देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था न हो जाय, परन्तु मुद्रा-स्फीति की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। मुद्रा-स्फीति में मूल्य-स्तर एक दम ऊँचा नहीं होता परन्तु मुद्रा स्फीति में यह एक दम ऊँचा होने लगता है। मुद्रा संस्फीति का परिणाम व्यापक होता है परन्तु मुद्रा-स्फीति का परिणाम विनाशकारी होता है। मुद्रा संस्फीति राष्ट्र और समाज के हित के लिये होती है, परन्तु मुद्रा स्फीति सरकार की स्वार्थ मिद्धि के लिये होती है।

(५) मुद्रा की मूल्य वृद्धि (Appreciation of Money)

जब मुद्रा का मूल्य अर्थात् उसकी कय-शक्ति (Purchasing Power) बढ़ जाती है तो उसे मुद्रा की मूल्य-वृद्धि कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पहले एक रुपया ४ सेर गेहूँ खरीदता हो और अब ५ सेर खरीदने लगे तो हम कहेंगे कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो गई। मुद्रा-संकुचन (Deflation) की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं। अतः मुद्रा के मूल्य-वृद्धि के कारण एक परिणाम ये हो है जो मुद्रा-संकुचन के सीधे तौर पर वर्णन किये जा चुके हैं।

(६) मुद्रा का मूल्य-ह्रास (Depreciation of Money)

जब मुद्रा का मूल्य अर्थात् उसकी कय-शक्ति घट जाती है तो उसे मुद्रा

का मूल्य ह्रास कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पहले एक छपा ४ मीर में खरीदा हो और अब केवल ३ मीर ही खरीद सके तो हम कहेंगे कि मुद्रा का मूल्य-ह्रास हो गया। मुद्रा-स्फीति (Inflation) की स्थिति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। यत मुद्रा के मूल्य ह्रास के कारण अब परिणाम यह हो है जो मुद्रा-स्फीति के उल्टे में नज़र आता है।

(७) अवमूल्यन (Devaluation)

परिचय—सितम्बर १९४६ ई० में जब रुपये का मूल्य घटाया गया ■
 में अवमूल्यन शब्द की ध्वनि अधिक सुनाई देने लगी है।

अवमूल्यन का अर्थ—साधारणतया प्रामाणिक मुद्रा की स्वतन्त्रता अटल भा अममूल्यन कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में देशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के अनुपात में मूल्य घटाने को अवमूल्यन कहते हैं। इसकी प्राक्क सप्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि जब देशी मुद्रा को विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में घटायता कम कर दी जाय तो यह देशी मुद्रा का अवमूल्यन समझा जायगा। मान लीजिए भारतीय १ रु० अमेरिकी के ३० सेंट के बराबर था—अब उसका मूल्य ३० सेंट से घटाने पर २१ सेंट कर दिया गया तो कहेंगे कि डॉलर के अनुपात में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया है।

अवमूल्यन के कारण (Causes)—(१) प्राय मुद्रा का अवमूल्यन देश की आर्थिक परिस्थिति के कारण नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति या न बाध्य होकर किया जाता है। जब किसी देश का निर्यात-आधार उससे आर्थिक मूल्य स्तर के ऊँचे हो जाते हैं कम हो जाता है तब निर्यात वस्तु के लब्ध मूल्य में देश की मुद्रा का मूल्य घटाने से अवमूल्यन कर दिया जाता है जिससे फलस्वरूप निर्यात बढ़न लगता है।

(२) जब किसी किसी देश का आयात करने का आवश्यकता हो परन्तु आयात का मूल्य घुसाने के लिए विदेशी मुद्रा या सोना न हो और देश के मूल्य स्तर घटने ऊँचे हो कि विदेश में निर्यात भी न किया जा सके, तो मुद्रा का अवमूल्यन करने निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

माराध्य यह है कि किसी देश का निर्यात बढ़ाने के लिए अवमूल्यन एक सरल एवं सन्तो विधि है।

अवमूल्यन का परिणाम—(१) अवमूल्यन करने वाले देश का निर्यात आधार बढ़ जाता है। आयात में ह्रास हो जाता है जिससे आयात आधार में कमी होन लगती है।

(२) आयात में ह्रास होने से देश का मूल्य स्तर बढ़न लगता है।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Indian Rupee)—भारत का डॉलर-क्षेत्र से बने और मर्यादित आदि पूँजीगत मान (Capital Goods) के आयात की आवश्यकता थी परन्तु इनका मूल्य घुसाने के लिए भारत सरकार के पास न तो धारण थे और न सोना था। भारत के मूल्य-स्तर घटने ऊँचे थे कि भारत के देश विदेशों में अमेरिकी रुपये के बाजार में मूल्य खरीद पान में जिसके कारण हम डॉलर कमान में असमर्थ थे। देश का मूल्य-स्तर नीचा करना कठिन था। अतः भारत सरकार ने १६ सितम्बर १९४६ को स्टैबिलिटी का माध्यम रूप का डॉलर के अनुपात में ३०.५% अवमूल्यन किया। अवमूल्यन के पूर्व एक रुपया लगभग ३० सेंट के बराबर था।

जो अमूल्यन के पश्चात् अश्वमेध २१ सेट ने बराबर रह गया । दूसरे साक्ष म अमूल्यन के पश्चात् इटलिय के साथ रुपये की दर तो १ सि० ६ पैसे हो गयी, किन्तु डॉलर में कम हो गई । पहले एक डॉलर २ रुपये १ आ० के बराबर था, अब अमूल्यन के बाद यह ६६० १२ भा० के बराबर हो गया । भारतीय रुपये के साथ-साथ लगभग २४ अन्य देशों ने अपनी अपनी मुद्रा का अमूल्यन किया, क्योंकि सभी के सामने नियति वृद्धि की समस्या थी । अमूल्यन के पश्चात् ही (अक्टूबर १९४८ से सितम्बर १९५०) निर्माण दंड जाने व आयात कम हो जाने से भारत के विदेशी व्यापार ६५.६ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—एक घातु चलन का अर्थ स्पष्ट कीजिये । स्वर्ण चलन मान, स्वर्णपाद मान तथा स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर को समझाइए । (उ० प्र० १९६०)
- २—'बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा' को चलन में बाहर कर देनी है ।' पूर्ण रूप से समझाकर लिखिए । (उ० प्र० १ ५७, ४७)
- ३—मुद्रा का अमूल्यन किसे कहते हैं ? भारत में मुद्रा के अमूल्यन का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? (स० भा० १९५७)
- ४—वैश्व नियम की व्याख्या कीजिये । इन नियम का क्षेत्र तथा मर्यादा स्पष्टतः समझाइए । (उ० प्र० १९५४, ४३, स० घ० १९५३)
- ५—मुद्रा मान में क्या तात्पर्य है ? स्वर्ण मान, स्वर्ण घातु मान, स्वर्ण विनिमय मान और इटलिय विनिमय मान का अन्तर बताइए । (उ० प्र० १९४५)
- ६—वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर ह्रास का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? भारतीय उदाहरण दीजिए । (स० घ० १९५०)
- ७—वस्तुओं के मूल्य में ह्रास और मूल्य वृद्धि का क्या अभिप्राय है ? भारत में समाज के विभिन्न वर्गों किसे प्रभावित होते हैं ? (स० घ० १९५५)
- ८—स्वर्ण विनिमय मान के मुख्य अंग क्या हैं ? स्टांप्ड विनिमय मान में इसमें क्या भिन्नता है ? (नागपुर १९५२)
- ९—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- वैश्व नियम (उ० प्र० १९५०, ४६; स० घ० १९६२, ५१, ४६, स० घ० १९५१, ५०, ४२, स० भा० १९५२, ५१; नागपुर १९५७)
- स्वर्ण घातु मान (उ० प्र० १९५५)
- स्वर्ण विनिमय मान (मागूर १९५०, ४६)
- चलन मान (मागूर १९५०)
- मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन (स० घ० १९५०)
- मुद्रा-मूल्य वृद्धि और मुद्रा-मूल्य-ह्रास (स० भा० १९५५)

इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षा

- १०—मुद्रा-मान में परिवर्तन में आय क्या समझते हैं ? वे कैसे होते हैं और इनसे क्या प्रभाव होते हैं ? (स० भा० १९५३)

भारतीय चलन प्रणाली (Indian Currency System)

भारतीय चलन प्रणाली दो भागों में बांटी जा सकती है—(१) आन्तरिक चलन प्रणाली और, (२) बाह्य चलन प्रणाली ।

(१) आन्तरिक चलन-प्रणाली (Internal Currency System)

चलन अधिकारी (Currency Authority)—भारत में चलन प्रणाली के दो अधिकारी हैं. (१) भारत सरकार, तथा (२) रिजर्व बैंक इण्डिया । भारत सरकार धातु मुद्रा बनाती है और रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा प्रचलित करता है । रिजर्व बैंक के प्रतिरित्त अन्य किसी मन्त्रालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः चलन अधिकारियों के अनुसार भारत की आन्तरिक चलन प्रणाली को दो भागों में बांटा जा सकता है—
(अ) धातु मुद्रा, और (आ) पत्र-मुद्रा ।

(आ) धातु मुद्रा (Metallic Money)—भारत में रुपया धातु का सबसे प्रमुख सिक्का है । यह देश की प्रधान मुद्रा है और सीमित विधि-प्राप्त है, अतः इसे देश की प्रमाणिक मुद्रा कहा जा सकता है । किन्तु प्रामाणिक मुद्रा की भाँति इसका वास्तविक मूल्य इसके अंकित मूल्य के बराबर नहीं है बल्कि बहुत कम है और न इसकी स्वतन्त्र दलाई होती है । इन बातों को देखते हुए हम यह सकते हैं कि रुपये में सार्वजनिक सिक्कों के मुख्य विद्यमान हैं । अतः भारतीय रुपया न तो पूर्ण रूप में प्रामाणिक सिक्का है और न सार्वजनिक सिक्का ही है । इसीलिए हम सार्वजनिक प्रामाणिक (Token Standard) सिक्का कहते हैं । रुपये की दलाई तो सार्वजनिक सिक्के की भाँति होती है, परन्तु काम यह प्रामाणिक सिक्के का करता है ।

हमारे देश में सबसे प्रथम ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाँदी का १८० ग्रेन का रुपया चलाया था । यह १७१२ मुद्र था । इस रुपये की स्वतन्त्र मुद्रा-दलाई थी, परन्तु १८१३ में स्वतन्त्र मुद्रा-दलाई बन्द कर दी गई । किन्तु धन्यता समीपिन विधि-प्राप्त अवश्य रहा । द्वितीय मराठुद्ध-युद्ध में रुपये की मुद्रता ११/१२ से कम करके १/१२ कर दी गई । सन् १८४० में सरकार ने गिल्ट का रुपया (Nickel Rupee) चालू किया । रुपये के प्रतिरित्त अठनी, चवनी, दुसनी, इननी, धधना, पैसा, पाई आदि धातु के सिक्के होते हैं । इनमें से अठनी का छोड़कर शेष सब सिक्के सीमित विधि-प्राप्त हैं । यद्यपि अठनीयाँ समीपिन विधि-प्राप्त हैं, परन्तु वे प्रामाणिक

मुद्रा में सम्मिलित नहीं हैं। भारत में समस्त सिक्के मरकेतिक हैं। उनकी दलाई से सरकार को लाभ होता है।

पत्र मुद्रा (Paper Money)—सन् १८४० के पूर्व देश में ५, १०, १००, १,००० और १०,००० रुपये के नोट प्रचलित थे। युद्ध काल में चांदी के रूप में वृद्धि हो जाने पर १ रु० और २ रु० के नोट चलाने लगे। जनवरी १८४५ में १०० रु० से ऊपर के समस्त नोट विमुद्रित (प्रचलित) घोषित कर दिये गये। अतः अब २, ५, १० और १०० रुपयों के नोट प्रचलित हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित किये जाते हैं। ये नोट निशान, छापवा कागज के रूप में परिवर्तनीय हैं। हमारे देश में एच २० का अपरिबर्तनीय नोट भी प्रचलित है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। १ रु० के नोट देखने में तो नोट है पर बाबून की दृष्टि से ये कागज पर छी सिक्के कह जा सकते हैं।

स्वर्णमान-बोप और पत्र चलाने का बोप (Gold Standard Reserve & Paper Currency Reserve)—सन् १८३५ के पूर्व जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी भारतभर में बागजा नोट (पत्र मुद्रा) भारत सरकार द्वारा निर्मित होते थे। उस समय कागजी नोटों के पीछे होने वाली सिक्के और प्रतिभूतियों (Securities) द्वारा निर्मित एक रिजर्व या बोप रखा जाता था जिसे पत्र चलाने का बोप या कागजा करसी रिजर्व (Paper Currency Reserve) कहते थे। यह बोप सन् १८६२ में स्थापित कर दिया गया था। इसके प्रयोग के बदलने के साथ साथ इसका रूप भी बराबर बदलता गया। पहले तो इसका एकमात्र ध्येय नोटों का भुगतान करना था। सन् १८६८ के स्वर्ण नोट विधान में इसका उद्देश्य चांदी के रूप के प्रयोग में भी आने लगा। सन् १८७५ से तत्पक्ष में स्थित स्थान तथा साथ पत्र विनियम दर स्थिर रखने के लिये भी काम में आने लगे। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से यह बोप नोटों के भुगतान करने और विविध दर की स्थिरता रखने के काम में आने लगा।

स्वर्णमान-बोप (Gold Standard Reserve)—स्वर्णमान बोप की स्थापना सन् १८७० में हुई। फाउण्डर कमेटी की विचारों के अनुसार धातु के सिक्के बनाने का लाभ को सधारा करने के लिये जिस बोप की स्थापना हुई वह स्वर्णमान बोप कहलाने लगा। इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे—(१) विनियम-दर मरबूत करना (२) विदेशी व्यापारिक विषयों का भुगतान, और (३) गृह-व्यय का भुगतान।

पत्र चलाने का बोप और स्वर्णमान रिजर्व सोने और चांदी के भागों में विभाजित थे। सोने वाला भाग ॥ दल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रहता था और चांदी वाला भाग भारत सरकार के पास।

इन बोपों को रुपये का विनियम अनुसार १ सि० ६ प० के बराबर स्थिर रखने के काम में लाया जाता था। हिस्ट्रिय कमीशन की सिफारिश के अनुसार रिजर्व बैंक के स्थापन के बाद दोनों बोप मिला दिये गये और साथ सोना रिजर्व बैंक को दे दिया गया।

भारतवर्ष में पत्र मुद्रा के निर्गम (Issue) की पुरानी रीति—सन् १८६१ के पूर्व कईवीं नोट मद्रास, बम्बई और कलकत्ते के प्रसीडेंट्स बैंक जारी किया करते

थे। जारी किये जा सकने वाले नोटों की अधिकतम सीमा निश्चित थी और ३३% का एक धातु का रिजर्व (Metallic Reserve) रखा जाता था।

सन् १८६१ ई० में पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य भारत सरकार ने स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। प्रतिभूतियाँ (Securities) के आधार पर ४ करोड़ रुपये तक के नोट जारी किये जा सकते थे, परन्तु उसके पश्चात् सत-प्रतिशत धातु का रिजर्व रखना पड़ता था। सन् १८६३ ई० में यह सीमा १४ करोड़ कर दी गई और सन् १८९४ में यह सीमा २० करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई। प्रथम महायुद्ध-काल में एक रुपये और आठ रुपये के नोट बिना किसी धातु का रिजर्व रखे जारी किये गये और उपर्युक्त सीमा २० करोड़ से १२० करोड़ रुपये कर दी गई।

बैंकिंगटन क्रिष्ण कमेटी ने यह सिफारिश की कि सब नोटों के पीछे ४०% का रिजर्व होना चाहिये और प्रतिभूतियाँ के आधार पर जारी होने वाले नोट १३० करोड़ रुपये में अधिक नहीं होने चाहिये। उक्त कमेटी का यह सुझाव था कि जिस समय व्यापार में दृढ़ि हो जाय, उस समय निर्यात वित्तों के आधार पर नोट जारी कर देना चाहिये। भारत सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी सुधार किया गया वह केवल इतना ही था कि धातु का रिजर्व ४०% के स्थान में ५०% कर दिया गया।

भारत में पत्र-मुद्रा के निर्गम (Issue) की वर्तमान प्रणाली :—सन् १९३५ में पूर्व भारत सरकार स्वयं कागजी नोट जारी करती थी, परन्तु रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने के पश्चात् यह कार्य उसके सुपुर्द कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक का निगम विभाग (Issue Department) नोट जारी करता है। निगम विभाग बैंकिंग विभाग में विलुप्त पृथक् है और उसका दायित्व केवल जारी होने वाले नोटों तक ही सीमित है। निर्गम-विभाग की सम्पत्ति और लेनदारी (Assets) निगमित अर्थात् जारी किये गये नोटों के कुल मूल्य के बराबर होने चाहिये। निगमित अर्थात् जारी नोटों के पीछे जो सम्पत्ति और लेनदारी होती है वह निम्न प्रकार है :—¹

(१) सम्पत्ति की कुल राशि का कम से कम ४०% भाग सोने के सिक्कों, सोने की धातु प्रथम स्टैंडर्ड सिन्थेटिकों के रूप में होना चाहिये। परन्तु यह प्रतिबन्ध है कि सोने के सिक्के और सोने की धातु का मूल्य किसी भी समय ४० करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

(२) शेष सम्पत्ति रुपये के सिक्कों, भारत सरकार की रुपये की सिन्थेटिकों और कुछ निर्गमित प्रकार के वित्तों और प्राप्तिपत्री नोटों के रूप में होगी।

(३) सोने के सिक्कों पर धातु की कुल राशि का कम-से-कम १०/१० भाग भारत में रहना चाहिये।

नोट निर्गम की वर्तमान प्रणाली की विशेषतायें

१. नोट जारी करने की वर्तमान प्रणाली अधिक वैज्ञानिक और लेनदार है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता अनुपातिक रिजर्व प्रणाली (Proportional Reserve System) है—समस्त नोटों के पीछे ४०% सोने का रिजर्व होना चाहिये।

२. यह अनुपात आवश्यकता पड़ने पर घटाया भी जा सकता है। यह ४०% रिजर्व ऐसा नहीं है कि कभी कम हो न किया जा सके। यदि रिजर्व बैंक को अधिक नोट चलाने की आवश्यकता प्रतीत हो, परन्तु इसके पास ४०% रिजर्व रखने के माध्यम न हों, तो यह निर्दिष्ट नोटों के कुल मूल्य के ४०% से कम किये जाने वाले भाग पर राष्ट्रपति नो कर (Tax) देकर घटाया जा सकता है।^१

नोट-निर्गम की नई और पुरानी प्रणालियों की तुलना—(१) नई प्रणाली के अन्तर्गत नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, सौंपा गया है। अब अर्थशास्त्री इस पर एक मत हैं कि केन्द्रीय बैंक द्वारा नोटों का जारी करना सरकार द्वारा जारी करने में कहीं उत्तम है। इसके कारण स्पष्ट हैं। (अ) प्रथम तो केन्द्रीय बैंक का व्यापारिक जगत् से घनिष्ठ सम्पर्क होता है जबकि सरकार का नहीं। अतः सरकार की तुलना में केन्द्रीय बैंक को देश की वार्षिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं का अधिक ज्ञान होता है। (आ) दूसरे, सरकार द्वारा नोट जारी करने में सबसे बड़ा भय चलनाधिक्य (Over-Issue) का रहता है, क्योंकि अर्थनीति पर राजनीति हावी हो जाती है। अतः यही उचित है कि नोट-प्रकाशन का कार्य केन्द्रीय बैंक के जिम्मे हो।

(२) हमारी चलन प्रणाली अब पहले की अपेक्षा अधिक लोचदार (Elastic) हो गई है। पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत कागजी चलन अधिक से अधिक १२० करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता था, परन्तु अब नई प्रणाली के अन्तर्गत उसके विस्तार की कोई भी सीमा नहीं है। बैंक जब चाहे जब ४० रुपये के सोने के पीछे १०० रुपये के नोट जारी कर सकता है। इससे चलन में पर्याप्त लोच आ जाती है किन्तु यदि चलन की आवश्यकता इससे भी पूरी न हो और ४०% सोने का रिजर्व न हो, तो कुछ कर देकर, रिजर्व की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी की जा सकती है। और यह कमी घटते-घटते हानी हो सकती है कि रिजर्व शून्य हो जाय।

निष्कर्ष—उप्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नोट जारी करने की वर्तमान प्रणाली पुरानी प्रणाली की तुलना में निरन्तर, यदि साधन नहीं, तो श्रेष्ठ अवस्था है।

(२) बाह्य चलन-प्रणाली

(External Currency System)

भारतीय मुद्रा का मान और विनिमय-दर—इस सलाखी के आरम्भ में

1—The Reserve Bank Act provides that in respect of period during which the holding of gold coins, gold bullion or sterling securities (i.e., gold reserve) is reduced below 40%, the bank shall pay to the Governor General in Council a tax upon the amount by which such holding is reduced below 40% of the aggregate value of notes issued. This tax shall be equal to the bank rate for the time being in force with an addition of 1% per annum when such holding exceeds 32% of the total amount of the assets and further 2% per annum in respect of every further decrease of 2% part of such decrease.

लेकर भ्रेशेजी धामन के अन्त तक हमारी मुद्रा स्वर्ण विनिमय मान और स्टलिङ्ग विनिमय मान के बीच झूलनी रही। सन् १९३१ में जबकि रिजर्व बैंक स्थापित किया गया उस समय उसके ऊपर यह उत्तरदायित्व रखा गया कि रुपये की विनिमय दर १ सि० ६ पै० पर कायम रहेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह १ सि० ५५५ पै० पर स्टलिङ्ग बेचेगा तथा १ सि० ६,३६ पै० पर स्टलिङ्ग सरीदेगा। रिजर्व बैंक ने इस कार्य को ठीक प्रकार से किया। युद्ध-काल में रिजर्व बैंक यह कार्य अपने 'विनिमय नियन्त्रण विभाग' द्वारा कर सका। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) का सदस्य बन गया और २ अप्रैल १९४७ को केन्द्रीय धारा सभा के निर्णय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के एक सदस्य श्री हैसियन से प्रथम बार रुपये का मूल्य स्वर्ण की भांति में निश्चित किया गया। इस प्रकार रुपये का विदेशी मूल्य सोने के द्वारा हर एक देश के साथ स्थापित हो गया है। यद्यपि नये मान के अनुसार भी अंग्रेजी मुद्रा से एक रुपये की विनिमय-दर १ सि० ६ पै० के ही बराबर है जो दर सन् १९२४ से चली आ रही है, परन्तु स्टलिङ्ग के साथ भारतीय रुपये का एकनिष्ठ सम्बन्ध विनिर्जित हो गया। अब रुपये का विनिमय मूल्य धन्य जत्तों (Currencies) के साथ सीधा स्थिर कर दिया गया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के ऊपर अब रुपये की विनिमय-दर को कायम रखने का उत्तरदायित्व नहीं है। अब रुपये की दर भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कोष के आदेशानुसार रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल करेगी। भारत के वर्तमान मान को हम अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard) कह सकते हैं।

भारतीय चलन प्रणाली के गुण व दोष

गुण—(१) हमारी वर्तमान प्रणाली एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ससार के अधिकांश देशों की प्रणाली भी ऐसी ही है।

(२) हमारी धान्तरिक करेन्सी का रूप सुविधाजनक है। हमारे यहाँ धान्तरिक और कागजी दोनों प्रकार की करेन्सियाँ चालू हैं। हमारे धान्तरिक करेन्सी भी बहुत लचीली नहीं है। जो पातु प्रयोग में लाई जा रही है वह काफी सख्ती है।

(३) नोटों का चलन केन्द्रीय बैंक के हाथ में है और उसमें पर्याप्त लोच है।

दोष—(१) भारतीय चलन प्रणाली कृत्रिम है अतः इस पर लोगों का विश्वास नहीं है। इसलिये वे अपनी वचत जमीन, मकान, सोने और चांदी में लगा रखते हैं; जिनसे व्यापार आदि को पूँजी प्राप्त नहीं होती।

(२) करेन्सी का मूल्य बराबर गिरता रहा है। इसके फलस्वरूप भी लोगों का इस पर विश्वास नहीं है।

(३) हमारे सम्पूर्ण करेन्सी साकेजिब है और वास्तविक मूल्य हमें नहीं भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्ण में उसका जो मूल्य रखा गया है, वह केवल नाम के लिये है। स्वर्ण तो हमें प्राप्त होता ही नहीं।

(४) हमारे नोटों के लिये जो कोष है वह अधिकांश स्टलिङ्ग में है। स्टलिङ्ग करेन्सी उसकी अच्छी नहीं रह गई जितनी अच्छी डॉलर करेन्सी है। हमें विदेशों में सामान प्राप्त नहीं होता है।

(५) हमारे नोट असीमित विपिप्राप्त हैं, किन्तु इन्हें सोने और चाँदी में बदला नहीं जा सकता।

(६) चाँदी के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती रहने के कारण हमारी मुख्य मुद्रा रुपये में भी निरन्तर मिलावट होती आ रही है और सम्भव है यह उत स्थिति तक होती रहेगी जब तक रुपया नोट के निकट तक नहीं पहुँच जाता ।

(७) भारतीय मुद्रा-चलन प्रणाली अब भी पूर्णतया नोचदार नहीं है ।

भारतीय चलन का इतिहास (History of Indian Currency)

भारतीय चलन की वर्तमान समस्याओं को यत्न-शक्ति समझने के लिये इसका विद्यमान इतिहास जानना आवश्यक है । इसलिये नीचे भारतीय चलन का इतिहास संक्षेप में दिया जाता है :—

(१) सन् १८०० से पूर्व—ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पूर्व भारत में हिन्दू और मुस्लिम शासकों द्वारा चलाई हुई कई प्रकार की और लगभग ६६४ सोने और चाँदी की मुद्राएँ प्रचलित थीं । इन मुद्राओं में परस्पर विनिमय-दरें निश्चित नहीं थीं । बाजार में मनुजान व सर्वांक विभिन्न मुद्राओं का मापेयिक मूल्य उन मुद्राओं में लगे स्वर्ण एवं चाँदी की तौल तथा गुणों के अनुसार निश्चित करते थे । इस प्रकार की मौद्रिक अवस्था ने अन्तर्वेशीय तथा विदेशी व्यापार में बड़ी कठिनाई होती थी । इसलिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में राज्य की जागडोर आने ही समस्त भारत के लिये एक प्रामाणिक मुद्रा चलाने का निश्चय किया गया ।

(२) सन् १८००—१८३५ : द्विधातुमान के परिचालन का प्रयास (Attempted Bimetallism)—इस युग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा चाँदी और सोने की मुद्राएँ जारी की गईं । इनके वैधानिक अनुपात, शुद्धता एवं माप सुनिश्चित थे । द्विधातु मुद्रा मान के परिचालन के प्रयास में कम्पनी को बहुत अधिक सफलता न मिल सकी क्योंकि बाजार में सोने और चाँदी के मूल्य स्थिर न थे । इसलिये कम्पनी ने क्रमशः एक धातु-मुद्रा-मान को अपनाते का निश्चय किया ।

(३) १८३५—१८६३ : रजत-मान (Silver Standard)—सन् १८३५ में भारतवर्ष में पूर्ण रूप से रजत मान (Silver Monometallism) स्थापित कर दिया गया । कम्पनी ने १८० पैर (११/१२ गुण चाँदी) चाँदी के रुपये को समस्त ब्रिटिश भारत में पूर्ण रूप से घोषित कर दिया । एक हजार सोने से अधिक चाँदी के मुद्राकन के लिये टुकसान लौट दिये गये । मुद्राकन मुक्त दो प्रतिघत और एक प्रतिघत मुद्राकन-न्यय लिया जाता था । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वर्ण मुद्रा पूर्णतया हट गई थी । सोने की मोहरे आदि जनता की दृष्ट्यापूति के लिये टुकसान में जारी जाती थी और सन् १८५१ में यह घोषित भी कर दिया गया कि सरकारी रकम के भुगतान के लिए स्वर्ण मुद्रा अपने अधिक मूल्य पर सरकारी खजानों में स्वीकार की जाएगी ।

मेक्सिको और संयुक्तराज्य अमेरिका में चाँदी की नई खानें खुल जाने के कारण सन् १८७३ के बाद से चाँदी का मूल्य निरन्तर घटने लगा, यहाँ तक कि जो रुपया सोने में दो शिलिंग के बराबर होता था, एक शिलिंग के बराबर रह गया । इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुएँ विप्रेषणार्थ अंग्रेजी वस्तुओं के दाम दुबने हो गये । इधर जो अंग्रेजी कर्मचारी भारत में काम करते थे और घर को रुपया भेजने थे, उन्हें रुपये के बढ़ने में आगे पीछे गिसने लगे । भारत सरकार को भी बहुत सा व्यय पीछे में करना

पड़ता था, यह भी दुगुना हो गया था। इन सचबटिनाइयो में अंग्रेजों की भाँति में वही चर्चनी पड़ी। इस बटिनाई का हल ढूँढ निकालने के लिये हरशल कमेट्री नियुक्त की गई।

(४) १८६३-१८६८ रजत मान का अन्न (Breakdown of Silver Standard)—हरशल कमेट्री की सिफारिश के अनुसार सन् १८६३ में जस्ता के लिये टक्कात बन्द कर दी गई अर्थात् जस्ता का रूप्य डलवान ना अधिकार छीन लिया गया। सरकार ने भी नये रूप्य व सिक्के डालना स्पष्ट कर दिया, जिस हरशल कमेट्री ने आदर्श बनाया था। आगे क्या बन्दम उठवाया जाय, इस पर राय देने के लिये भारत सरकार ने सन् १८६८ में फाउलर कमेट्री (Fowler Committee) नियुक्त की।

(५) १८६८-१८९४ स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange)—फाउलर कमेट्री ने भी यही सम्पत्ति दी कि रूप्य की विनिमय दर १ सि० ४ पैसे पर स्थिर कर देनी चाहिये। इससे अनिश्चित, उसने स्वर्ण मान स्थापित करने तथा ग्रेन के सोने के सिक्के सिक्के को विविधास्तु बना देने और उनकी स्वतन्त्र मुद्रा डलाई करने का मुझाव रखा। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, परन्तु उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं किया। मोन के मित्रों के निर्माण के लिये टक्कात स्थापित नहीं की गई। ईन्हें ईन्हें, सरकार की नीति में इस प्रकार परिवर्तन हुआ कि हमने स्वर्ण विनिमय मान का रूप धारण कर लिया जिसे न तो हरशल कमेट्री ने मोचा था और न फाउलर कमेट्री ने। अब सरकार ने विनिमय दर को १ सि० ४ पैसे पर हो रखने की कसरत की। कौन्सिल बिल (Council Bills) और रिवर्स कौन्सिल बिल (Reverse Council Bills) के अर्थ विवरण द्वारा इस तरह का स्थिर रखा गया।

कौन्सिल और रिवर्स कौन्सिल बिलों का अर्थ विवरण—कौन्सिल बिल (रूप्ये की हुँडिया) और रिवर्स कौन्सिल बिल (स्टैंडिंग हुँडिया) का अर्थ विवरण निम्न प्रकार होता था : यदि भारत से इंग्लैंड को अधिक मात्रा भेजा जाता और वहाँ से कम आता, तो इंग्लैंड में कौन्सिल बिलों (रूप्ये की हुँडियों) की माँग बढ़ जाती और रूप्ये के मूल्य बढ़ने की सम्भावना होती। उस समय भारत मनी १ सि० ४ पैसे की दर से, जो व्यापारी चाहता है उसे हुँडी बेचना शुरू कर देता। ये हुँडियाँ कौन्सिल बिल कहलाती थीं। इंग्लैंड का व्यापारी उसे खरीद कर भारतीय व्यापारी के पास भेज देता था। भारतीय व्यापारी उसे दिखाकर भारत सरकार से उतनी ही रूप्ये की राशि प्राप्त कर लेता था। इसी प्रकार यदि कभी भारत इंग्लैंड में अधिक मात्रा भेजता और कम भेजता तो भारत में स्टैंडिंग की माँग बढ़ जाती। ऐसी स्थिति में स्टैंडिंग का मूल्य बढ़ने की सम्भावना होती है। उसी समय भारत सरकार, जो भी व्यापारी चाहता उसमें रूप्ये लेकर १ सि० ४ पैसे की दर से भारत-मनी के नाम हुँडी कर देती। इन्हीं हुँडियों को रिवर्स कौन्सिल बिल कहा जाता है। भारतीय व्यापारी रिवर्स कौन्सिल बिल खरीद कर इंग्लैंड में अपने मान भेजते हैं जो देता था। वह उसे दिखा कर भारत-मनी से पौंड में मुतान प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार रूप्ये की दर को १ सि० ४ पैसे पर स्थिर रखने में और स्वर्ण मान के बजाय स्वर्ण-विनिमय मान स्थापित करने में भारत सरकार सफल हुई।

देनामिसा ने भारत सरकार की इस मुद्रा नीति की कड़ी आलोचना की जिसके पलस्वरूप सन् १९१३ में चेम्बरलैन कमिशन (Chamberlain Commi-

ssion) की नियुक्ति की गई। कमीशन ने भारत के लिये स्वर्ण विनिमय-मान उपयुक्त बनलाश और इसी को ही जारी रखने की सिफारिश की।

(६) १९१४-१९१८ युद्ध काल तथा विनिमय दर में हेर फेर (War time & Change in the Exchange rate)—चैम्बरलेन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों बाद प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। लोहा का मरकार में विश्वास न रहा और उनमें घबराहट फैल गई जिसके कारण लोगों ने ढाक़मानों से रुपये निकालना तथा क्रेन्सी नोटों के बदले में सरकार से सोना मागना शुरू कर दिया। माग इतनी बढ़ गई कि सरकार को सोना देना बन्द करना पड़ा। कुछ समय के लिये स्थिति काहू में आई, परन्तु १९१५ में फिर भीषण हो उठी। युद्ध-काल में भारत ने इंग्लैंड व अन्य देशों को बहुत माना गया परन्तु अग़ायब बहुत कम। उनके प्रतिरिक्त भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ पर बहुत-सा रुपया व्यय भी किया। जिम्मे कारण ब्रिटिश सरकार ऋणी हो गई। भारता में माँग पूरी करने के लिये कौन्सिल विल १ शि० ४ पे० की दर ने लेने लगे, परन्तु शीघ्र ही उनकी माग इतनी अधिक हो गई कि भारत सरकार द्वारा रुपये में उनका भुगतान करना कठिन हो गया। बाढ़ी के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई कि रुपये को गलाना लाभप्रद हो गया। सरकार ने कौन्सिल विला को असौमिल राशि में वेचना बन्द कर दिया और जो रुपये वह भी लैची दर पर, बिना रिजर्व रखे हुए एक रुपये और हाई रुपये के नोट भी जारी कर दिये गये। इस प्रकार विनिमय की दर जो सन् १९१४ में १ शि० ४ पे० थी, वह सन् १९१८ में २ शि० ४ पे० पर पहुँच गई।

(७) १९१९-१९२५ . बैबिंजटन स्मिथ कमेटी और विनिमय दर २ शि० पर स्थिर करने का प्रयास (Babington Smith Committee & attempt to stabilise the Exchange rate at 2 Sh.)—महायुद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात् बाकी मुद्रा नीति ने सामग्य में सम्पत्ति होने के लिये सरकार में बैबिंजटन स्मिथ कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने पुनः स्वर्ण विनिमय दर प्रयत्न और विनिमय दर २ शि० कर देने की सिफारिश की। सरकार ने इह स्वीकार किया। किंतु कुछ ही समय पश्चात् र्क घटनाओं ने कमेटी के विचारों को पूर्णतया प्रभावित कर दिया, क्योंकि बाढ़ी का मूल्य फिर यथा और व्यापार का प्रसार (Balance of Trade) भारत के प्रति कुन हो गया अर्थात् भारत को पाना कम और देना अधिक हो गया। इसने कलस्वदप स्टैलिङ्ग की माँग बढ़ी और रुपये का मूल्य गिरने लगा। तब सरकार ने उसे २ शि० पर बनाये रखने की चेष्टा की परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। विवेक होकर सन् १९२२ में सरकार ने रिजर्व कौन्सिल विला को वेचना स्थापित कर दिया और विनिमय दर को अपने हाल पर छोड़ दिया।

(८) १९२६—१९३१ हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission)—सन् १९२४ में विनिमय दर १ शि० ६ पे० के लगभग स्थिर हो गई, और सन् १९२५ में बाकी मुद्रा नीति के मन्वष में राय देने के लिये सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) को नियुक्त किया जिसने स्वर्ण-मानु मान (Gold Bullion Standard) अपनाते और रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पे० निश्चित करने की सिफारिश की।

सरकार ने कमीशन की सिफारिश को स्वीकार किया और ऊँहे कार्यान्वित करने के लिय सन् १९२७ में भारतीय चलन विधान (Indian Currency Act)

पात किया जिससे अनुसार रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पैं० या ८४७ शुद्ध स्वर्ण के घन के बराबर निर्दिष्ट की गई। इस दर को स्थिर रखने के लिये सरकार ने २१ द० ३ आ० १० पा० प्रति तोले के हिसाब से कम से कम ४० तोला या उससे ऊपर प्रमी-मित मात्रा में स्वर्ण के पाट सरीदने की जिम्मेदारी ली। इससे प्रतिरिफ, इसी दर पर सरकार ने जतना भी विविप्राह्य मुद्रापा के बदले ४०० शोम (१०६१ तोले) स्वर्ण या स्टर्लिंग केनेने की भी जिम्मेदारी ली। विविप्राह्य मुद्रापा के बदले रक्षण एवं स्टर्लिंग प्राप्त करने का अधिकार होने के कारण इस प्रणाली में स्वर्ण धातु-मान (Gold Bullion Standard) और स्टर्लिंग-विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) दोनों की विशेषता का सम्मिश्रण हो गया था। इस प्रकार जो मान स्थापित हुआ उसे न तो स्वर्ण धातु मान कहा जा सकता था और न स्वर्ण-विनिमय मान। यदि उस अनिश्चित स्वर्ण मान कहें तो उपयुक्त होगा, क्योंकि स्थिति में अनुसार और सरकार की इच्छा के अनुकूल अभी तो वह स्वर्ण-धातु-मान का स्वरूप ग्रहण कर लेता था और कभी स्वर्ण विनिमय मान का।

(६) १९३१—१९४० स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard)—सन् १९३१ में इंग्लैण्ड ने स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया जिसके कारण भारतीय रुपये की भी वैंता ही बनना पड़ा। रुपये की १ शि० ६ पैं० की दर पर स्टर्लिंग में बाँध दिया गया। क्योंकि अब स्टर्लिंग सोने में परिवर्तनशील नहीं था, इसलिये भारतीय मान विमुद्रा स्टर्लिंग मान हो गया। तब से लेकर सन् १९४७ तक भारत में यही मान रहा।

इस काल की महत्वपूर्ण घटनाएँ—इस काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई—(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना (१९३५), और (२) द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५)।

१—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना (१९३५)—सन् १९३५ तक हमारे यहाँ भारत सरकार ही चलने सम्बन्धी समस्त कार्यों का संचालन करती थी। सन् १९३५ में हमारे देश में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उसे यह सारा भार सौंप दिया गया, जिससे चलन का पूरा प्रबंध अब रिजर्व बैंक के हाथ में था गया। देश के समस्त अच्छे बैंक इसी सम्बद्ध हैं और सम्मिलित या अनुमूर्चित (Scheduled) बैंक कहाते हैं। इन्हें अपनी दैवदारिया (Liabilities) का कुछ भाग इसमें पास जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा व्यवस्था के प्रतिरिफ, सारी साधन व्यवस्था पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। स्वर्ण-मान रिजर्व (वोष) और कागजी चलन रिजर्व (वोष) दोनों के मुपुर्द कर दिए गये हैं। रुपये का बाहरी मूल्य १ शि० ६ पैं० के बराबर बनाय रखने का उत्तरदायित्व भी रिजर्व बैंक पर था।

२—द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५)—इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना द्वितीय महायुद्ध था जो सन् १९३९ में आरम्भ हुआ और सन् १९४५ में समाप्त हुआ। इस काल की कुछ उल्लेखनीय घटनाएँ निम्नलिखित हैं—

(अ) रण्यो की माँग में वृद्धि—युद्ध छिड़ने पर जनता में घेचैनी उत्पन्न हुई और लोग नाँटो की रण्यो में बदलाई के लिये भातुर हो उठे, जिससे कारण रण्यो की माँग बहुत बढ़ गई। बाद में व्यापार इतना बढ़ा कि यह माँग बढ़ती ही गई। अतः सरकार को इस समय १४९ करोड़ रुपये बनाकर जारी करने पड़े।

(घा) एक और दो रुपये के नोटों का चलनारम्भ—चाँदी के रुपये की माँग इतनी बढ़ती गई कि उसे इससे पूरा करना असम्भव हो गया। अतः निवृत्त होकर सरकार को एक और दो रुपये के नोट चलाने पड़े जो अभी भी प्रचलित हैं।

(इ) विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)—यह काल में विषम परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण आयात और निर्यात पर सरकार द्वारा नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। दूसरी लकड़ की तेवर भाग्य में मत मुद्रा काल में विनिमय नियंत्रण प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार ने यह कानून बना दिया कि निर्यात करने के जिस व्यक्ति को पोण्ड, डॉनर आदि प्राप्त हो वह रिजर्व बैंक में जमा करे, और जिन विदेशों से माल खरीदने के लिये विदेशी करेंसी की आवश्यकता हो, वह रिजर्व बैंक से विदेशी प्रिनिमय खरीदे। इस पद्धति को विनिमय नियंत्रण (Exchange Control) कहते हैं। यह पद्धति आज दिन भी प्रचलित है और इससे देश को बहुत लाभ पहुँचा है।

(ई) बड़ी राशि के नोटों का विमुद्रीकरण (Demonitisation)—मुद्रा-काल में खोरबाजारी, मुनाफाखोरी और दूसलों की वजह जोर रहा। इसमें सम्प्रदा कोषा में इस प्रकार सबैय इस में बड़ा धन कमाया जो अधिकतर बड़े नोटों में सवित कर रखा गया। इस कमाई को खत्म करने के लिये १२ जनवरी, १९४६ को भारत सरकार ने एक विमुद्रीकरण बिल पारित किया जिसके अनुसार १०० रुपये में ऊपर की राशि के नोटों का विमुद्रित कर दिया, अर्थात् ५००, १,०००, २० और १०,००० के नोटों को प्रविधि ग्राह्य घोषित कर दिया। उन्हें भुना कर उनके बदले में दूसरा चलन लेने के लिये २६ फरवरी, १९४६ तक का समय दिया गया। भुनाने वाले व्यक्ति का रिजर्व बैंक को एक फॉर्म भर कर गृह बनाना पड़ता था कि ये नोट कब और कहाँ से मिले, उन्हें पास में क्यों रखा गया और बैंक में क्या नवी जमा किये गये, आदि।

(१०) १९४७: अन्तर्राष्ट्रीय मान की स्थापना (Establishment of International Standard)—८ अप्रैल, १९४७ का भारतीय धारा सभा के निर्णय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य की श्रेणित में प्रथम बार भारत सरकार ने स्टाँडर्ड से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और भारतीय रुपये का मूल्य माने में निश्चित किया गया। इस प्रकार भारत में 'अन्तर्राष्ट्रीय मान' की स्थापना हुई।

(११) १९४९: रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee)—सन् १९४९ में करेन्सी सम्बन्धी एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। १८ सितम्बर १९४९ को ब्रिटिश राजा के आन्सलर सर स्टेफन क्रिप्स ने इंग्लैंड की विषम परिस्थिति के दबाव के कारण यह घोषणा कर दी कि ब्रिटेन ने डॉलर की तुलना में पोण्ड का मूल्य ३०.५९% घटा दिया। पोण्ड का मूल्य ४.०३ डॉलर से २.८० डॉलर कर दिया गया। उस समय भारत के सामने यह प्रश्न था कि वह स्टर्लिंग के साथ रहे मथवा डॉलर के साथ। स्टर्लिंग क्षेत्र से अधिक व्यापार होने के कारण भारत ने स्टर्लिंग के साथ रहने का निश्चय लिया। अवमूल्यन के बाद भी स्टर्लिंग के साथ रुपये की दर तो १ नि० ६ पै० ही रही, किन्तु डॉलर में कम हो गई। अवमूल्यन से पूर्व एक डॉलर ३.६० ५ ग्रा० के बराबर था। अब वह ४.६० ११ ग्रा० के बराबर हो गया है। पाकिस्तान के अतिरिक्त कॉमनवेल्थ के सब सदस्यों ने इसका अनुकरण किया।

(१२) १९६६-७० : मार तपाकिस्तान मुद्रा मतिरोध (Indo-Pakistan Monetary Dead-lock)—मार्ग न तो अपने रुपये का सममूल्यन कर दिया ; परन्तु पाकिस्तान न ऐसा नहीं किया । जिसके फलस्वरूप १०० पाकिस्तानी रुपये १४४ भारतीय रुपये के बराबर हो गये । इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पड़ा । मान गम्हार ने पाकिस्तानी रुपये की बढ़ी हुई दर को मानन से इनकार कर दिया जिसने परिणामस्वरूप मान नहीने तक यह मुद्रा मतिरोध चलता रहा और साग-साधार ठप्प हो गया । जूट का मायाल खगिन हो जाने के कमकत्ते की पूर्ण मित दन्द हो गई । विवाद होकर मार्ग सरकार का पाकिस्तानी रुपये की गई दर स्वीकार करने परी और २६ फरवरी, १९४१ का दाना देखा के मध्य एक व्यापारिक समझौता हो गया जिसमें स्थिति में कुछ सुधार हो गया ।

अदि पाकिस्तान की इस नीति पर आर्थिक दृष्टि में विचार किया जाय, तो यह नीति उचित नहीं है । पाकिस्तान न अपनी मुद्रा का मूल्य मनोवैज्ञानिक भावनाओं तथा राजनैतिक अवस्थाओं के आधार पर बढ़ाया । भाग्यवश विदेश-स्थिति पाकिस्तान न अनुकूल ही रही जिसमें यह अपनी विनिमय-दर रिकर रख सका । कारिया के युद्ध के कारण पाकिस्तान का रुपया और भी हड़ हो गया और भारत का बाध्य होकर पाकिस्तान की विनिमय दर का स्वीकार करना पड़ा । मार्च १९४२ के बाद तो स्थिति और भी बिगड़ हो गई । और बाजार में पाकिस्तानी मुद्रा का मूल्य भारतीय मुद्रा में भी कम हो गया १९४२ १९४३ १९४४ के लक्षण इस प्रकार हैं :

वर्तमान चलन सम्प्रदाय समस्याएँ

मुद्रा-स्फीति (Inflation)—मुद्रा-स्फीति मन् महायुद्ध का समय तथा प्रभाव है । इसके मुख्य कारण, प्रभावों साथ ही विषय विवरण मन् प्रख्यापन किया जा चुका है । मन् १९४६ में मुद्रा मुद्रा प्रसार १२०० करोड़ रुपये तन पहुँच गया था जसके मन् १९२९ में यह केवल २०० करोड़ रुपये ही था , वही स्थिति अभी भी जारी है । प्रन् स्पष्ट है कि चलन मपहूवे की अपेक्षा पाँच गुनी वृद्धि हो गई । मुद्रा-स्फीति के कारण मुद्रा की मय प्रक्ति कम हो गई और वस्तुओं के मय वृद्ध मय जिससे मध्यम वर्ग एक अधिक वर्ग की वृद्ध बाध पहुँची ।

मूल्यों का गटाने के नियम भारत सरकार कम्पनी की वृद्धि की रोकन का प्रयत्न मुद्रा जान से कर रही है । इसमें अपने मुद्रा स्फीति विरोधी कार्यक्रम को प्रयत्न मन् प्रवृद्ध १९४६ में ही, परन्तु यह नीति प्रभावोत्पादक मिद नहीं हुई । मन् १९४९-५० में मुद्रा-प्रसार में कमी की गई और मूल्य भी मिर । सरकार म मनी नीति का प्रवर्धन किया जिसमें देश की उपनि वही निर्धाल कम होकर आयात का प्रोत्साहन मिला, पर लगा कर मुद्रा चलन में मीची गई और कष्टाव द्वारा मुद्रा की कम करने का प्रयत्न किया गया । कारण यह है कि मुद्रा-स्फीति आज हमारी समय प्रमुख आर्थिक समस्या है जिसका हल निकालना निम्न वाटनीय है ।

स्टर्लिंग पावना (Sterling Balances)—द्वितीय महायुद्ध में पूर्व भारतवर्ष ब्रिटेन का करणी था, परन्तु युद्ध ने इस स्थिति को उल्टा कर दिया । दूसरे मय में युद्ध-काल में ब्रिटेन का मारा करण हुआ गया और मय ब्रिटेन भारतवर्ष का करणी हो गया । पीछ पावने में महायुद्ध-काल में जो वृद्धि हुई वह हमारे देश के मुद्रा-इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है । द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व ब्रिटेन

बैंक ने पाग पत्र-मुद्रा के रिजर्व के रूप में केवल ६४ करोड़ रुपये के बीड-पावने में जो बजट मई १९४२-४६ में १७३३ रुपये के बराबर हो गये ।

ब्रिटेन जितना भी पाल लेना उसके बदले स्टर्लिंग प्रतिज्ञा पत्र बिना देना जितना स्टर्लिंग मिक्सीरिटी बहन है । भारत सरकार यह सिक्कोरिटी रिजर्व बैंक को द देती जो उसके आधार पर लगे नोट जारी कर भारतीय व्यापारियों को भुगतान कर देता । कंठधान-मुद्रा स्वीकृति का यह एक मुख्य कारण है । रिजर्व बैंक अतिरिक्त के अनुमान कुल नोटों को ४०% भाग स्टर्लिंग प्रतिभूतियों या सिक्कोरिटीन में बंध करवा है परन्तु इसमें मर्यादित कर दिया गया और यह प्रतिज्ञा हटा दिया गया । आज स्टर्लिंग प्रतिभूतियों पर मुद्रा के ६०% में भी अधिक है । इस प्रकार भारतीय पत्र-मुद्रा का आधार ही स्टर्लिंग प्रतिभूतियों पर बस है ।

बीड पावने के संचय (Accumulate) होने का कारण — बीड पावने की पुत्र-पाल में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । इनके कई कारण थे । (१) ब्रिटेन ने युद्ध-काल में भारतवर्ष से बहुत-सा भाग खींचा । इस भाग के बदले उनका भारत को रुपये नहीं दिये और न सोना ही दिया बल्कि इंग्लैंड की सरकार ने विभिन्न अवधिपत्रों के प्रतिज्ञा-पत्र दिये । (२) भारत ने मित्र राष्ट्रों की जनता तथा सेनाओं का निज भी बहुत अधिक भाग देना जिसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार-मनुष्य इन देशों के भूतल रहा । (३) इंग्लैंड तथा भारत के मध्य होने वाले मई १९३९ के प्राथमिक समझौते के अन्तर्गत भी भारत सरकार ने मुरदा के लिये ब्रिटेन की सरकार के प्रति जो धन्य किया वह भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता हो गया । (४) युद्ध काल में ब्रिटिश भारत में रहने वाले सैन्य व्यक्तियों का डॉलर तथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं के रूप में जो धन जमा था वह भी ब्रिटिश साम्राज्य के डॉलर पूल के लिये प्रतिवर्ष रूप से नें लिया गया । (५) अमेरिका को निर्यात तथा अमेरिका की सेवा पर भारत में होने वाले धन धन्य के बदले न भारत को जो डॉलर प्राप्त हुए वे भी 'डालर पूल' में एकत्रित कर दिये गये । इन प्रकार भारतवर्ष को जो इंग्लैंड अथवा विदेशों में प्राप्त करना था उन सबके बदले स्टर्लिंग प्रतिभूतियों दी गई ।

बीड पावने का भुगतान और उसका उपयोग :— युद्ध समाप्त होने पर हम देश में इन धन की चर्चा हुई कि बीड-पावने का उपयोग किस प्रकार किया जाये । भागा के विभिन्न लोगों ने विभिन्न सुझाव रखे । (१) किसी ने कहा कि इनके बदले में इंग्लैंड में मशीनें मंगाई जाय । (२) किसी ने कहा कि इनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास धरोहर के रूप में रख कर कोष में भण्डा किया जाये । (३) किसी को यह राय रही कि यदि इंग्लैंड इस समय हमारे मशीनों की माँग को पूरा न कर सके तो इस ऋण का कुछ भाग डॉलर आदि अन्य दुर्लभ मुद्राओं में परिवर्तित कर दें जिससे भारत संसार के अन्य सब देशों में यह गाँव मँगा सके । (४) इस ऋण का कुछ भाग ब्रिटेन वालों को जो व्यापारिक पूँजी भारत में लगी हुई है उन, उचित दाम पर लौटने के काम में लाया जा सकता है । (५) यह रकम स्टर्लिंग पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन तथा युद्ध-भारतियों के लरी देने के काम में ली जा सकती है । (६) भारतीय युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तथा उद्योग धन्यों के यंत्रोत्पन्न करने तथा भारतीयों का विदेश में विदेश शिक्षा दिलाने के हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है ।

बीड-पावने सम्बन्धी समझौते

(Sterling Balances Agreements)

युद्ध समाप्त होने के बाद अगस्त १९४७ में भारत और ब्रिटिश सरकार के

बीच एक मध्यकालीन समझौता (Interim Agreement) हुआ । इस समझौते के अनुसार पौड पावने की राशि ११४७ करोड़ रुपये निश्चित की गई और इसमें से लगभग १११ करोड़ रुपये की राशि सन् १९४८ तक भारत को अपनी इच्छानुसार व्यय करने की स्वतन्त्रता दी गई । परन्तु भारत इस राशि में से केवल ४ करोड़ रुपये की राशि जून १९४८ तक खर्च कर पाया । जुलाई १९४८ में एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत को उसके गन वर्ष के वचे हुए १०७ करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त सन् १९५१ के जून तक १०६ करोड़ रुपये अपनी इच्छानुसार व्यय करने की स्वतन्त्रता दी गई । इसी वर्ष पौड पावने में से भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को लगभग ३५७ करोड़ रुपये मुद्रा मामलों के खरीदने तथा ब्रिटिश अफ़मरा की पेयन चुकाने के लिये दे दिये । जुलाई १९४९ के नये समझौते के अनुसार भारत सन् १९५१ के जून तक १०६ करोड़ रुपये के स्थान पर १३३ करोड़ रुपये तक पौड-पावने में खर्च कर सकेगा । इसी समझौते में यह भी निश्चय किया गया कि भारत १९४८-४९ के लिये भी लगभग १०८ करोड़ रुपये खर्च कर सकेगा । फरवरी १९५२ में इस सम्बन्ध में सबसे अन्तिम समझौता हुआ । यह समझौता ३० जून, १९५७ तक के लिये किया गया । इस समझौते के अनुसार १९५० तक हमारे पास केवल ३१ करोड़ पौड-पावने बच रहे थे । यह बड़े लेव की बात है कि हमने इस पौड-पावने की अधिकांश राशि विदेशों में खर्च तथा अन्य उपयोग की वस्तुएँ खरीदने में खर्च कर दी । आधा है अगले ६ वर्षों में प्राप्त होने वाली पौड पावने की राशि देना की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने तथा आर्थिक उन्नति करने में लगाई जायेगी । अब भारत सरकार ने अपनी अन्तिम जमा-पूँजी को दूसरी योजना की सफलता के लिये काम में लाना प्रारम्भ कर दिया है ।

अभ्यासाथ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली का वर्णन संक्षेप में कीजिये ।

(अ० बो० १९५४)

२—पत्र धनार्पण संचिति (Paper Currency Reserve) की विभिन्न पद्धतियाँ समझाइये । भारत के लिये कौन सी पद्धति उपयुक्त है और क्यों ?

(नागपुर १९५५)

३—सन् १९१९ से सन् १९३९ तक भारत की मुद्रा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास लिखिये ।

(दिल्ली हा० मे० १९४८)

४—वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली पर नोट लिखिए ।

(अ० बो० १९५२)

५—भारत की वर्तमान प्रणाली का संक्षिप्त विवरण लिखिए ।

(दिल्ली हा० मे० १९४७)

परिचय (Introduction)—यब तक हमने मुद्रा व करन्सी का अध्ययन किया है और देखा है कि इनमें व्यापार व उद्योग में क्या सहायता मिलती है। परन्तु बहुधा व्यापार में हम नकद दाम नहीं देते, बरन् अविष्य में देने का वचन देते हैं। हम देखते हैं कि उपभोक्ता फुटकर व्यापारी से, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से, थोक व्यापारी उत्पादकों या निर्माताओं से, उत्पादक या निर्माता बैंक से और बैंक जनता से साख पर उधार लेता है। अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक व्यापार व उद्योग साख ही आधार पर विरत है। हमारे शब्दों में, आधुनिक युग 'साख का युग' है और यत्न-मान आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ साख पर निर्भर है। उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय तथा वितरण सभी में साख की आवश्यकता होती है। पूँजीवाद-समयन में बिना साख प्रयोग के भेत शून्य पड़ें रहेंगे, बस कारखाने बन्द हो जायेंगे, विनिमय कार्य अवरुद्ध संकुचित हो जायगा और वितरण में अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी।

साख शब्द के विविध अर्थ—साख शब्द बहुत से अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे : साधारण अर्थ में, वही-खाते सम्बन्धी अर्थ में, व्यापारिक अर्थ में और अर्थशास्त्रीय अर्थ में।

(१) साख का साधारण अर्थ—साधारण भाषा में साख शब्द 'विदवान' या 'प्रशसा' के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। साख का अङ्ग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'क्रेडिट' (Credit) है और किसी प्रशसनीय कार्य के लिये 'क्रेडिबल' (Creditable) शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

(२) साख का वही-खाता सम्बन्धी अर्थ—लेखपाल (Accountant) साख के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'क्रेडिट' (Credit) को खाने के दाहिनी ओर के लिये प्रयुक्त करता है।

(३) साख का व्यापारिक अर्थ—व्यापारिक अर्थ में साख शब्द किसी व्यापारी या व्यापारिक-अवयव की आर्थिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा का सूचक है। व्यापारिक योग्यता, ईमानदारी, अच्छी आर्थिक स्थिति आदि उत्तम व्यापारिक साख की कुछ आधारभूत बातें हैं। शायद अच्छे साख वाले व्यापारी को बड़ी रकम भासानी में उधार मिल सकती है, परन्तु संदेहपूर्ण साख वाले व्यापारी को उधार भासानी से नहीं मिल सकती। इसलिये एक नये व्यापारी को उधार भाल बेचने के पहले उसकी साख सम्बन्धी पूछताछ की जाती है। साख वा व्यापारिक अर्थ उससे अर्थशास्त्रीय अर्थ में बहुत मिलता जुलता है।

(४) साख का अर्थशास्त्रीय अर्थ—साख शब्द का अग्रगो पर्यायवाची शब्द क्रेडिट (Credit) है जिसकी उत्पत्ति लेटिन (Latin) शब्द 'क्रेटो' (Credo) से हुई है। शब्दों का अर्थ है 'मे विश्वास करता हूँ।' परन्तु अर्थशास्त्र में साख शब्द इस अर्थ में नहीं लिया जाता। अर्थशास्त्र में साख शब्द का अर्थ 'उधार' है, अर्थात् जिस समय रुपय का भुगतान लेना चाहिए उस समय न लेकर किसी भविष्य के समय में लिया जाय। अधिक स्पष्ट करत हुए, साख मनुष्य को उस शक्ति को कहते हैं जिससे वह पर वह दूसरा न कुछ समय में लिये जायिक वस्तुओं या धन उधार से सञ्चाल है। अर्थात् जहाँ से बालों शक्ति या गुण को अर्थशास्त्र में 'साख' कहते हैं।

साख की विभिन्न परिभाषाएँ (Definitions)—साख के अर्थशास्त्रीय अर्थ को भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार परिभाषित किया है। जैसे, —

(१) मैकलियड (Macleod) ने लिखा है कि साख भविष्य में भुगतान पाने का वर्तमान अधिकार है।

(२) वालरस (Wallas) ने साख को पूँजी का उधार देना कहा है।

(३) जेवम्स (Jevons) ने अनुसार साख भुगतान कुछ निश्चय के परचाय करन के प्रतिरित और कुछ नहीं है।

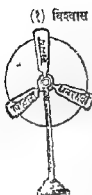
(४) टुकर (Tucker) नामक अर्थशास्त्री ने साख की या परिभाषा की है। "किसी एक व्यक्ति को मूल्यवान् वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति के पास हन विपदा के साथ हस्तांतरित होना कि वह भविष्य में इस मूल्य का वापिस चुका सकेगा, साख है।"

(५) प्रो० सेल्गमैन (Seligman) ने साख की परिभाषा इस प्रकार की है : "साख एक ऐसा विनिमय अथवा सीमा होता है जिसके अन्तर्गत भौतिक वस्तुमा, पूँजी अथवा केवल वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार अस्थायी रूप से हस्तांतरित कर दिया जाता है। साख की विनिमय अथवा वस्तुमा, वस्तुमा अपने को प्रयोग करने का अधिकार होता है।"

(६) प्रो० जीट (Gide) का कथन है कि विनिमय में प्रायः समय का तत्त्व प्रौर मिला दोगि, वम वह साख हो जायेगा।

सारांश यह है कि किसी भुगतान को भविष्य को किसी तिथि के लिये स्वगित करने का नाम ही साख है, अर्थात् विनिमित्त विनिमय (Protracted Exchange) को ही साख कहते हैं।

साख के तत्त्व (Essentials of Credit)—साख निम्नलिखित तीन तत्त्वों पर आधारित है—



(१) विश्वास (Confidence)—साख का आधार विश्वास है। एक मनुष्य दूसरे को तभी उधार देता है जबकि उसको एक दूसरे को ईमानदारी पर पूरा पूरा विश्वास होना है। इस कारण उधार केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सच्चे और ईमानदार समझे जाते हैं। भूटे और बेईमान व्यक्ति को कोई कभी उधार नहीं देता। अतः स्पष्ट है कि साख का मूल 'विश्वास' में निहित है। किसी मनुष्य में विश्वास कई बातों में होता है, उनमें से सदाचार (Character), सामर्थ्य (Capacity) और सम्पत्ति (Property) मुख्य हैं। इन बातों में आधार पर ही एक-दूसरे का विश्वास कर उधार दिया जा सकता है।

(२) धन राशि (Amount)—धन राशि साख का दूसरा आवश्यक तत्त्व है। साख शब्द का तभी प्रयोग किया जा सकता है जबकि कुछ धन या धन में बदली जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान उस समय व लेकर भविष्य में लिया जाता है। यदि धन-राशि का लेना-देना न हो, तो साख का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) समय (Time)—किसी भी साख-सीदे में समय का होता बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य किसी धन को उसी समय लता है जब उसको लाना चाहिये, तो वह उधार नहीं होता बरन् नकद सीदा होता है। परन्तु यदि वह मनुष्य धन को उस समय न लेकर भविष्य में लेने का वचन देता है तभी वह सीदा उधार कहलाता है। श्री० जी० ने ठीक ही कहा है "विनिमय में साप समय का तत्त्व और मिला दीजिये, वरा वह साख हो जायेगा" (Introduce the element of time into exchange and it becomes credit.)

उदाहरण—एक व्यापारी एक व्यक्ति को एक यहीने के लिये दो हजार रुपये का माल उधार देने को तैयार है, उसमें शक नहीं। इसका धर्म यह हुआ कि उस व्यक्ति को साख व्यापारी की दृष्टि में दो हजार रुपये हैं, और वह उसे एक यहीने से अधिक के लिये नहीं देना चाहता। इससे साख के तीनों आवश्यक तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं—प्रथम मूल तत्त्व विश्वास जो व्यक्ति-विशेष में व्यापारी रखता है, दूसरा धन राशि जो दो हजार निश्चित है और तीसरा समय जो इन उदाहरण में एक महीना निश्चित है।

साख का महत्त्व (Importance)—मैकलियड (Macleod) के कथनानुसार मनुष्य के लिये जितना आवश्यक इधन है, एतित साख के लिये जितना आवश्यक कलन (Calculus) है, उतना ही आवश्यक व्यापार में उद्योग के लिये साख है। व्यापार और उद्योग दोनों के लिये साख का बहुत महत्त्व है। वस्तुन प्राधुनिक व्यापार और उद्योग धर्मों में साख के प्रयोग पर ही आधारित है। निर्माता पूँजी, बचा माल तथा अन्य वस्तुएँ साख पर लेता है। धोक व्यापारी निर्माता से माल साख पर खरीदता है। धोक व्यापारी कुटकर व्यापारी को साख पर माल बेचता है। स्वयं कुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को वस्तुएँ साख पर देते हैं। इस प्रकार एक किनारे से दूसरे किनारे तक सारी धर्म-व्यवस्था साख के एक सूत्र में बँधी हुई है। साख के कारण ही आज की विशाल उत्पादन-व्यवस्था, अथ विशाल जन, मशीन का प्रयोग आदि बातें सम्भव हैं। बड़े-बड़े उद्योगों तथा व्यापार में जितने अधिक धन की आवश्यकता

(६) व्यापार की उत्थिति एवं विकास में सहायता—साधारणतया के प्रयोग एवं प्रसार से व्यापार में उत्थिति होती है। देश के भीतरी तथा बाह्य व्यापार में साधन तथा (बैंक ऋणों तथा जिन प्रकार के साधन) के द्वारा सुव्यवस्थापूर्वक सहायता मिलती है।

(७) मूल्यों की घटा बढ़ी पर नियंत्रण—साधन पर उचित नियंत्रण तब देश में मूल्य स्थिरता स्थापित की जा सकती है। उदाहरणार्थ नीचे के व्यापार की दर को बना साधन की वृद्धि को रोक मूल्यों के बढ़ने से रोका जा सकता है। अन्तर्गत मूल्यों में व्यापार की दर को घटा साधन की वृद्धि पर बहुत कुछ नियंत्रण में सहायता की जा सकती है।

(८) राष्ट्रीय सचट में सहायता—पुनर् तथा अन्य विभिन्न राष्ट्रीय सचट के समय सरकार अपनी साधन के द्वारा जनता से प्रत्यक्ष रोकर विपन्न स्थिति में साधन कर सकती है।

(९) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सहायता—साधन का उपयोग केवल सचट निवारण में ही नहीं बल्कि देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी साधन किया जा सकता है। अनेक देशों में आर्थिक पुनर्निर्माण में सरकार ने साधन की सहायता की है।

(१०) व्यक्तिगत सचट में सहायता—यदि कोई व्यक्ति या के प्रभाव में तत्काल भ्रमण करने में प्रसक्त है अथवा किसी आर्थिक गतिविधि में प्रसक्त हो गया है तो वह अपनी साधन पर अपना उधार लेकर अपनी गतिविधि को पुनर् कर सकता है।

(११) बैंक से रोकड़ साधन (Cash Credit)—साधारणतया बैंक में साधन रोकड़ तब पर उचित अधिक उधार दे सकता है। इस प्रकार तब बैंक तब द्वारा अपने को सचित करके रख कर दस हजार रुपये तक दे सकता है।

साधन के भय (Dangers of Credit)—साधारणतया साधन के अतिरिक्त होते हुए भी भय मुक्त नहीं बढ़ी जा सकती। साधन का प्रयोग अथवा उधार लेने से साधन बढ़ता है।

(१) अत्यधिक प्रसार का भय—साधन का अत्यधिक प्रसार तब तक भय होता अत्यधिक प्रसार है। यह साधन है कि बैंक साधारण साधन प्रसार करता है उधार की एक अधिक मात्रा का लाभ होता है। व्यापारिक अधिकृति (Debit) के समय जबकि अपने को अधिक साधन होती है तब तो साधन प्रसार का अधिक प्रभाव होता है। इससे बचत व आवश्यकता में अधिक साधन का प्रसार कर सकते हैं। इस परिणाम के साथ बैंक अधिक सचट में प्रसक्त होकर सचट में जान है।

(२) सट्टा बाजार एवं अयोग्य व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक तथा लाभहीन व्यापार की व्यवस्था—साधन की अत्यधिकता में अपना उधार लेकर अनेक सट्टा बाजार अयोग्य व्यक्ति अत्यधिक तथा लाभहीन व्यापार की व्यवस्था कर सकते हैं और साधन में प्रसक्त होने पर वे अपने साधन को बर्बाद कर देते हैं तथा साधन ही अत्यधिकता में भी न पहुँचते हैं। साधन द्वारा बहुत से व्यापारी अपना आर्थिक बर्बाद कर दिया। ऐसे में भी सचट रहते हैं।

(३) एनाधिकार की प्रोत्साहन—साधन द्वारा एनाधिकार का प्रसार। सचट की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ व्यक्तियों को साधन पर दाना मिलता है।

मिल जाता है कि वे किसी वस्तु के उत्पादन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर बाजार में अपना प्रमुख जमा लेंगे हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी उन्हें सामर्थ्य ठहर नहीं पाते । एकाधिकार-अवस्था में आपराध आदि अनेक अन्यायपूर्ण बातों का होना स्वाभाविक है ।

(४) उपभोक्ताओं को फिजूल-खर्ची के लिये प्रोत्साहन—जब किसी व्यक्ति को ग्रामानी या रण्य उधार मिलने लग जाता है, तो वह सोमों से बाहर खर्च करना प्रारम्भ कर देता है, जिससे ऋण वृद्ध हो जाता है । भारतवर्ष में ग्रामीण-ऋण (Rural Indebtedness) की उत्पत्ति एवं वृद्धि अधिकतर उपभोग के लिये उधार लिये गये धन के कारण हो गई है ।

(५) धोखेवाजी बेईमानों को प्रोत्साहन—साख की आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने पर लोग धोखेवाज और बेईमान हो जाते हैं । साख की महत्ता से शिवालिक भी कुछ दिना तक काम चला सवत हैं और बाई धन्दे व्यापारियों का दुबो देने हैं ।

(६) अत्यधिक व्यापार प्रसार एवं प्रति उत्पादन (Over-production) को प्रोत्साहन—मुलभ साख द्वारा व्यापार में अत्यधिक प्रसार हो जाता है तथा अति-उत्पादन के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं ।

निष्कर्ष—साख की हानियाँ को मुलभ में उसमें प्राप्त लाभ कहीं अधिक हैं । परन्तु साख का वास्तविक उपयोग सभी है जबकि उसका नियमित एवं उचित उपयोग किया जाय । साख नौकर की भाँति अच्छा काम कर सकती है, पर स्वामी होने पर दुबो देती है । अतः साख का उचित नियन्त्रण करने के लिये प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित किए जाते हैं जो देश की भलाई के लिये साख का नियन्त्रण करते हैं ।

क्या साख पूँजी है ? (Is Credit Capital ?)—साख पूँजी है या नहीं, इस विषय में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है । कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि साख पूँजी है । इस मत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मैकलेड (Macleod) के अनुसार मुद्रा और साख दोनों पूँजी हैं । साख की क्रिया के कारण साखपत्रों की जन्म मिलता है और भविष्य में धन के उत्पादन में सहायक होने के कारण साख पूँजी है ।

साधारणतया अर्थशास्त्रियों का मत इसके विरुद्ध है । उनका कहना है कि साख धन नहीं है, और जब धन नहीं है, तो उससे पूँजी होने का प्रश्न ही बँस उठ सकता है । भूमि और श्रम की भाँति साख उत्पादन का कोई स्वतन्त्र साधन नहीं है बल्कि विनिमय तथा श्रम विभाजन की भाँति उत्पादन का केवल उद्योग-साधन ही है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूँजी उधार लेकर उस उत्पादन के कार्य में लगता है । इस प्रकार साख द्वारा पूँजी का हस्तान्तरण हो जाता है । परन्तु हस्तान्तरण उत्पादन नहीं है । जिस प्रकार विनिमय द्वारा वस्तु उत्पादन नहीं हो सकती, उसी प्रकार साख द्वारा पूँजी उत्पन्न नहीं हो सकती । रेकार्डो (Ricardo) ने लिखा है कि 'साख पूँजी को जन्म नहीं देती, यह केवल इस बात की निश्चित करती है कि पूँजी किस के द्वारा उपयोग में लाई जायगी ।' इसी प्रकार मिल (Mill) ने कहा है कि 'साख केवल

दूसरे व्यक्ति की पूँजी वा उपयोग करने की आशा मात्र है। इसमें उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती, उनका केवल हस्तान्तरण ही सकता है।'

प्राचुरिक भ्रमवासियों के अनुसार यद्यपि साख साधारणतया पूँजी नहीं है, परन्तु कुछ भ्रमस्थाओं में साख द्वारा अवश्य पूँजी का निर्माण होता है। जैसे—(प्र) जब साख के कारण चलने से घातु मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तथा उत्पादन के लिये अधिक पूँजी उपलब्ध हो जाती है तब मात्र पूँजी कही जा सकती है। (घ) बिना साख के बहुत से लोग द्वारा बनाया गया मोटा-मोटा घन उत्पादन में नहीं आ पाता। बिना साख के बहुत में कुसम व्यापारी एवं उद्योगपति इतने बड़े उद्योग अपने स्थापित नहीं कर सकते थे। बैंक साख की व्यवस्था करता है और देश के विकास पर हुए घन को एकत्रित कर उन लोगों के हाथ में पहुँचाता है जो हमें उत्पादन कार्य में अपनी भाँति लगा सकते हैं। इस प्रकार साख के कारण पूँजी इकट्ठा करने में सहायता मिलती है तथा इसके द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अतः ऐसी समस्या में साख पूँजी की जन्मदात्री कही जा सकती है। (इ) बैंक प्रादि साख सस्थाएँ जितना घन उधार लेती हैं उतने अधिक मात्रा में घन उधार देती हैं। जितना अधिक उधार दिया जाता है उगी सीमा तक वे साख से नई पूँजी बनाती हैं।

साख व्यवस्था (Credit Mechanism)—साख का सर्वोत्तम उपयोग उसकी शुभल व्यवस्था वा संगठन पर निर्भर है। अतः साख व्यवस्था के विभिन्न अंगों का अध्ययन वांछनीय है। साख व्यवस्था के मुख्य दो अंग हैं—(१) साख पत्र जो उधार के सोदे के विनिर्मित प्रमाण होते हैं, जैसे—बैंक, बिल ऑफ एक्सेप्टेन्स, प्रॉमिसरी नोट प्रादि, (२) मात्र सस्थाएँ अर्थात् बैंक जो अपना उधार करने के और उधार देते हैं।

साख-पत्र और उसका अर्थ (Credit Instrument & its Meaning)—साख द्वारा क्रय-विक्रय में मुख्य का भुगतान भविष्य में होगा है जिसके लिये आश्वासन पत्र प्रस्ताव प्रतिज्ञा पत्र दिये जाते हैं। इनमें निश्चित तिथि पर या माँग पर भुगतान करने का आश्वासन लिया रहता है। ऐसे लिखित आश्वासन या प्रतिज्ञा पत्रों को ही साख पत्र कहते हैं। अतः ऐसे पत्रों को जिनमें साख द्वारा विक्री का प्रमाण रहता है तथा जिनमें भविष्य में राशि भुगतान के लिये लिखित आश्वासन होने हैं साख-पत्र कहलाते हैं। बैंक, बिल ऑफ एक्सेप्टेन्स, प्रॉमिसरी नोट, व हण्डी प्रमुख साख-पत्र हैं।

साख-पत्रों की आवश्यकता एवं महत्व—छोटे मोटे भुगतानों में तो बिना साक्षी के ही उधार प्राप्त मिल जाता है, परन्तु साख के बड़े व्यवहार में प्रमाण तथा साक्षी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें विश्वास टूट हो जाय और उधार को राशि वापस द्वारा वसूल की जा सके। इसलिये साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है और साख पत्र साख के आवश्यक मूलक है।

विनिमय माध्यम (Medium of Exchange) की दृष्टि में भी इनका बड़ा महत्व है। इनके द्वारा व्यापारिक सोदे वही सुविधा से नष्ट हो जाते हैं। एक ही साख पत्र द्वारा अनेक भुगतानों को सम्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, क ने ग से माल खरीदा और उस राशि के बदले में एक तीन महीने की अवधि का बिल आक एक्सचेंज दिया। ख ने ग में माल खरीदा और उसे वही बिल दे दिया, ग ने घ में

मान खरीदा और वही बिल उसे दे दिया। भागे भी इसी प्रकार बिल का पराक्रमण (Negotiation) होता रहेगा जब तक कि इनकी तीन महीने की अवधि समाप्त न हो जायेगी।

पत्र मुद्रा तथा धातु मुद्रा द्वारा भुगतान करने में बार-बार गिनन तथा परखने की आवश्यकता होती है परन्तु साख पत्रों के प्रयोग से यह अनुविधा दूर हो जाती है। अतः आधुनिक व्यापार-व्यवस्था में साख पत्र का बड़ा महत्त्व है।

साख पत्र और मुद्रा (धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा) में अन्तर

(१) मुद्रा (वाहे धातु मुद्रा हो या पत्र मुद्रा) विधिवत् (Legal Tender) होती है अर्थात् कृपया ऋणदाता को ऋण में भुगतान में इसे स्वीकार करने के लिये बाध्य कर सकता है। परन्तु साख पत्रों को ऋण के भुगतान में स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको स्वीकार करना ऋणदाता की इच्छा पर निर्भर है।

(२) मुद्रा विधिमय का सर्वमान्य साधन है, परन्तु साख पत्र उनमें सम्मिलित शक्तियों या सत्ता की मात्र, क्याति अथवा प्रसिद्धि के बल पर ही चलते हैं।

(३) कौन्सो नोट एक निश्चित मूल्य के होते हैं, जैसे—एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और सौ रुपये। ये छुटकर घाने पाइयों के बही होते। इसी प्रकार सिक्के भी, वाहे के प्रमाणाधिक हा अथवा सार्केलिक, निश्चित मूल्य के होते हैं। परन्तु साख पत्र किसी भी मूल्य के हो सकते हैं।

(४) साख-पत्र मुद्रा भुगतान के लिखित बाधे होते हैं जो स्वभाव में ही मुद्रा से भिन्न होते हैं। वे वास्तविक अर्थ में मुद्रा की ओरों में नहीं जा सकते, उन्हें सबीरों अर्थ में मुद्रा या एकाग्रपत्र (Substitutes) कहा जा सकता है।

साख-पत्रों के भेद—साख पत्र कई प्रकार के होते हैं जिनमें से बैंक, विल ऑफ एक्सेचन, प्रॉमिसरी नोट मुख्य हैं। इनका विवेचन ग्रन्थ में नीचे किया जाता है।

चैक (Cheque)

परिभाषा (Definition)—चैक एवं शर्नरहित लिखित आज्ञा है जिसमें वह व्यक्ति जिसका रुपया बैंक में जमा होता है बैंक को आज्ञा देता है कि उसमें अंकित राशि का भुगतान माँग पर बैंक में उल्लिखित व्यक्ति को, अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा चैक वाहक को कर दिया जाय। अन्य शब्दा में, यह किसी बैंक-विवेच पर लिखा गया शर्नी बिल या हुण्डी है।

चैक के प्रयोग की आवश्यकता—किसी आधुनिक बैंक में रुपया कई छात्रों में जमा कराया जा सकता है, उनमें से चालू खाता (Current Account) एक है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक के चालू खाते में अपना रुपया जमा कराता है, तब बैंक उसे एक चैक पुस्तिका (Cheque Book) देता है जिसमें बहुत से खाली बैंक के छत्रे हुए पार्श्व होते हैं। बैंक के नियमानुसार चालू खाते में से रुपया बैंक द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसलिये जब कभी वह स्वयं रुपया निकालना चाहता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है, उसे यह चैक भर कर देना पड़ता है। जब नियमानुसार भरा हुआ चैक बैंक की छिड़की (Counter) पर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक उसमें उल्लिखित राशि का भुगतान कर देता है।

यद्यपि बैंक में रखी किसी साधारण कागज पर आदेश लिखकर निकाला जा सकता है परन्तु बैंक अपनी सुविधा तथा समय के विषे और जानमाजी व गूट काम से बचने के लिये इसे हुए बैंका की पुस्तक अपने ग्राहक को दे देता है। ग्राहक इसे हुए बैंक के खाती स्थाना में आवश्यक बात भर कर तुरन्त बैंक जारी कर सकता है।

बैंक के आवश्यक गुण (Essentials of a Cheque)

- १ बैंक का आदेश अतर्हित (Unconditional) होना चाहिये।
- २ बैंक का आदेश लिखित होना चाहिये मौखिक नहीं।
- ३ बैंक किसी बैंक विशेष के नाम लिखा होना चाहिये।
- ४ बैंक में बाल्य निश्चित राशि देने का होना चाहिये।
- ५ बैंक को राशि मागने पर मिल जानी चाहिये।
- ६ बैंक पर बैंक में रखी जमा कराने वाल बर्षान् बैंक के ग्राहक के हस्ताक्षर होने चाहिये।

७ बैंक की राशि इसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भवता इससे बाह्य को मिल जानी चाहिये।

बैंक का स्वरूप (Form of a Cheque)—विभिन्न बैंका के बैंका के काम भिन्न भिन्न होने हैं परन्तु प्रत्येक एक ही रंग रफ व आकार के बैंक उपपत्ता है। बैंक दो भागों में विभाजित रहता है। बाई ओर के भाग में प्रतिनिधि (Counterfoil) रहती है और बाई ओर के भाग में मूल बैंक (Cheque Proper) का सली प्रपत्र बर्षान् काम रहता है।

बैंक का स्वरूप

(प्रतिनिधि)	(मुख्य बैंक)	
तथ्या	भागरा	१६६
तथ्या	स्टेट बैंक आफ इण्डिया भागरा ब्रांच	
तिथि		
आगत	श्री	भवता
	ग्राहक / आदेश को रख	
कारण	लेजिये।	
राशि	रु० =	
६०		
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	

(Specimen of a Cheque)

(Counterfoil)
No. Co. 25735(Cheque Proper)
No. Co. 25735 Dated Jaipur,
June 15, 1961.

Dated June 15, 1961

In favour of Shri
Gulab Chand Agarwal
in full settlement of
his accountThe Rajasthan Bank Ltd.,
Jaipur BranchPay to Shri Gulab Chand
Agarwal or bearer/order Rupees
one thousand fifty five, and nineteen
NayaPaisa only

Rs 1055/19 nP.

T. C. Verma Rs 1,055/10 Tara Chand Verma

चैक के पक्ष (Parties to a Cheque)—चैक के तीन पक्ष होते हैं—

(१) चैक देणक [घाट्कर्ता] (Drawer)—चैक लिखने या जारी करने
वाला व्यक्ति चैक-देखक कहलाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसका धनमा चैक में
जमा होता है। इस चैक का जमाकर्ता (Depositor) या ग्राहक (Customer) भी
बहुत सकता है।(२) देनदार चैक [आह्वार्यी] (Drawee)—यह बैंक होता है जिसके नाम
चैक जारी किया जाता है। इस मुपाना करने वाला चैक भी बहुत है।(३) लेनदार [आदाता] (Payee)—यह वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में
चैक लिखा या जारी किया जाता है। कभी-कभी चैक सवक (Darwer) लेनदार
(Payee) के स्थान पर 'स्वयं' (Self) लिख देता है। इसी स्थान में चैक-लेनक ही
लेनदार होता है।

चैक के प्रकार (Kinds of Cheques)

(१) वाहक या धनीजोय चैक (Bearer Cheque)—यह चैक है जिसका
मुपाना चैक वाहक (Bearer) को किया जाता है, अर्थात् जो भी व्यक्ति चैक चैक में
प्रस्तुत करता है उसका वा चैक का मुपाना कर दिया जाता है। उपर दिव हुए चैक का
उदाहरण। म यदि 'आह्वार्य' (Order) शब्द बरक दिया जाय तो वह वाहक या धनीजोय
(Bearer) चैक हो जायगा। जो भी व्यक्ति इस चैक को लिखने पर प्रस्तुत करता है,
वह उसका वा चैक का धनमा अदा कर सकता है। यदि चैक का मुपाना करने वाला व्यक्ति
को हा जाय, तो इसकी जिम्मेदारी चैक की नहा होती है। धन इस सुरक्षित नहीं कहा
जा सकता।वाहक या धनीजोय चैक का हस्तान्तरण (Transfer)—वाहक या
धनीजोय चैक का हस्तान्तरण कवन गुणवत्ता मान (by a mere delivery) में हो
सकता है, उस पर बेचान लेख या कृप्यकन (Endorsement) लिखने की कोई
आवश्यकता नहा होती है। आह्वारणक चैक चैक का मुपाना करने वाला व्यक्ति में उपर

पीछे हस्ताक्षर करा जाता है, अन्यथा जो भुगतान के बदले में एक नियमानुसृत रसीद बैंक को देनी पड़ेगी।

(२) ऑर्डर, नामजोम या आहजोम चैक (Order Cheque)—यह चैक है जिसका भुगतान बैंक में उल्लिखित व्यक्ति को प्रथम उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। उपर्युक्त बैंक के उदाहरणों में यदि 'वाहक' या 'बियरर' (bearer) शब्द काट दें तो यह आर्डर या नामजोम, प्रथम आहजोम (Order) चैक हो जायगा।

ऑर्डर चैक या हस्तांतरण (Transfer)—ऑर्डर चैक को हस्तांतरित करने के लिये यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के नाम में चैक है वह उमरा ध्यान करे, क्योंकि बैंक को पीछे पर सेनदार या प्राप्तकर्ता (Payee) उम व्यक्ति के नाम ध्यान करे जिसको वह चैक हस्तांतरित करना चाहता है। इस प्रकार चैक पर ध्यान दिए लिख कर फिर उसकी मुबुरंगी उम व्यक्ति को दे जिसको वह हस्तांतरित करना चाहता है। ऑर्डर चैक, वाहक या धनजोम चैक की विशेषता यह है कि मुद्रित होता है। ऐसे चैक का भुगतान करने वाले बैंक का यह वाक्य है कि यह इस बात की जाम-यश्ता है कि ध्यान से ले लें और अपने पाने वाला सही व्यक्ति है। यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति विशेष को बैंक में लिखा गया है और उसके ध्यान वाहक (bearer) या ऑर्डर (order) कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो उसे 'ऑर्डर चैक' ही माना जाता है।

ध्यान या पृष्ठावन (Endorsement)—चैक को हस्तांतरित करने के लिये ध्यान से ध्यान-लेख लिखकर हस्ताक्षर करने की प्रथा को ध्यान या पृष्ठावन कहा जाता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यानकर्ता या पृष्ठावक (Endorser) कहलाता है। जिस व्यक्ति के ध्यान में ध्यान दिया जाता है उसे ध्यानप्राप्त या पृष्ठाकर्मि (Endorsee) कहते हैं।

(३) रेषावित चैक (Crossed Cheque)—जब चैक के मुख पर दो तिरछी समान्तर रेखाएँ (Transversal Parallel Lines) खींची जाती हैं, तब यह रेषावित चैक (Crossed Cheque) कहलाता है। कभी कभी इन रेखाओं के बीच में "& Co", "A/o Payee only" आदि शब्द लिख दिये जाते हैं और कभी कुछ भी नहीं लिखा जाता है।

रेखावित चैक की भुगतान विधि—रेखावित चैक का भुगतान मोटे किमी व्यक्ति को बैंक की गिनती (Counter) पर नहीं दिया जा सकता है। सेनदार बैंक रेषावित चैक का भुगतान किसी बैंक को ही देगा। अतः ऐसे चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिये उसे अपने बैंक में जमा करा देना चाहिये। वह बैंक उसकी राशि सेनदार-बैंक से वसूल कर उस व्यक्ति के पाने में जमा कर लेगा। ऐसे चैक बहुत मुद्रित होते हैं, क्योंकि इनके ध्यानकर्ता को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।

रेखावित चैक के प्रकार—रेखावित चैक दो प्रकार का होता है—एक साधारण रेषावित और दूसरा विशेष रेषावित।

साधारण रेषावित चैक (Generally Crossed Cheque)—यह चैक है जिसमें केवल दो तिरछी समान्तर रेखाएँ खींची जाती हैं और कभी कभी "& Co" आदि शब्द भी लिख दिये जाते हैं। इस प्रकार के चैक का भुगतान किसी

व्याज को बैंक की लिडकी पर न मिल कर किसी बैंक के द्वारा मिलेगा। इसलिये इसे अपने बैंक में जमा कर उसके द्वारा देनदार-बैंक में राशि प्राप्त की जाती है।

विशेष रेखांकित चेक (Specially Crossed Cheque)—यह चेक है जिसमें लिखी समान्तर रेखाओं के बीच में किसी विशिष्ट बैंक का नाम लिख दिया जाता है। दूसरा तात्पर्य यह होता है कि देनदार बैंक ऐसे चेक की राशि का भुगतान किसी भी बैंक को न करेगा उसी बैंक को करेगा जिसका नाम दो समान्तर रेखाओं के बीच में लिखा हुआ है।

चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य (Object of Crossing a cheque)—किसी चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य यह होता है कि उसका भुगतान मध्यस्थ व्यक्ति को प्राप्त हो। रेखांकित चेक का भुगतान किसी बैंक द्वारा मिलने के कारण यह अधिक सुरक्षित होता है। माघारख दाक द्वारा भेजे जाने वाले चेक को अवश्य रेखांकित करना चाहिये।

(४) खुला या अरेखांकित चेक (Open Cheque)—यह चेक है जिस पर किसी प्रकार का रेखांकन (Crossing) न हो। ऐसे चेक के पुराण जाने व खोने का अधिक गम रहता है।

(५) झूट-चेक (Forged Cheque)—यह चेक है जिस पर चेक लेखक (Drawer) या धारक करने वाले (Endorser) के बनावटी हस्ताक्षर होते हैं।

(६) काल-तिरोहित चेक (Stale Cheque)—जो चेक छ मास से अधिक पुराना हो जाता है, उसे काल-तिरोहित या पुराना चेक कहते हैं। बैंक इस प्रकार के चेक का भुगतान बिना चेक-लेखक के पूछे नहीं करेगा।

(७) फटा या विकृत चेक (Mutilated Cheque)—यह चेक है जो अकस्मात या मुद्दे से फट गया है। बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है। इसका भुगतान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि पहले चेक बिपका लिया जाय और फिर "अकस्मात फट गया" या "Accidentally Torn" शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दे, तो बैंक उसकी राशि दे सकता है।

(८) प्रमाणित या चिह्नित चेक (Marked Cheque)—यह चेक है जिस पर बैंक अपने हस्ताक्षर कर देता है और यह प्रमाणित कर देता है कि ठीक समय पर चेक के उपस्थित विमों जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

चेक के प्रयोग से लाभ (Advantages)

१. चेक गणना देन-लेने का एक अति सरल मापन है। दूसरा मिट्टी के सिक्के की बजाय दूर हो जाती है तथा नकली सिक्के (Counterfeit Coins) से घोसा साने का भय नहीं रहता। २. चेक के उपयोग से मोना पौड़ी जैसी बहुसंख्य धानुओं को वक्त होती है। ३. चेक द्वारा गणना क्षीप्र व रुक-वर्क में स्थानान्तरित किया जा सकता है। ४. चेक अपने ही भुगतान का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। ५. चेक के उपयोग से थोड़ी आदि जातों की आसना नहीं रहती है। ६. चेक के प्रयोग में गणना बचाने की साझा पैदा हो जाती है। ७. चेक के प्रयोग से व्यापारियों के आदर और मान में वृद्धि होती है। ८. चेक द्वारा भुगतान करने में कार्यलय में राख-राशि रखने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः भुक्तान-सम्बन्धी बहुत सारा काम कम हो जाता है। ९. चेक के प्रयोग में वृत्ति मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है।

१०. बैंक का बेचान करके गये का लेन-देन सुसमता से हो सकता है। ११. बैंक प्रणाली द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य की असाधारण उन्नति होती है।

बैंक और बैंक नोट में अन्तर

बैंक	बैंक (करेसी) नोट
(१) यह विशिष्ट नहीं होता है।	(१) यह विशिष्ट होता है।
(२) यह वाहक या आर्बोर हो सकता है।	(२) यह सदैव वाहक (bearer) होता है।
(३) यह निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होता है।	(३) यह निश्चित राशि के भुगतान की प्रतिज्ञा होती है।
(४) इसे बैंक में रक्का जमा कराने वाला लिखता या बनाता है।	(४) इसे केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक बनाता है।
(५) यह रेखांकित किया जा सकता है।	(५) इसका रेखांकन नहीं किया जा सकता है।
(६) यह कितनी भी बड़ी राशि वा हो सकता है तथा इसमें आने-पाई भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं।	(६) बैंक नोट केवल निश्चित राशि के हो सकते हैं तथा इनमें आने पाई का प्रयोग नहीं होता है।
(७) इसका जीवन छोटा होता है, क्योंकि इनका विश्वास सीमित होता है।	(७) इसका जीवन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सब व्यक्तियों के विश्वास-पात्र होते हैं।

बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय-पत्र

(Bill of Exchange—B/E)

परिभाषा (Definition)—बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय-पत्र एक लिखित गतिरहित आदेश-पत्र है जिसमें अक्षदाता ऋणी को उसमें उल्लिखित राशि स्वयं को, या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा बिलधारी को मांग पर अथवा किसी निश्चित अवधि के पश्चात् देने की आज्ञा देता है। ऐसे बिल आम. उधार देने हुए मास के लिये विनि. जाने हैं।

बिल या विनिमय-पत्र की विशेषताएँ (Characterstics)—
(१) यह एक गतिरहित आदेश पत्र है। (२) यह आदेश लिखित होता है, मौखिक नहीं। (३) यह कागजी रूप में लिखा होता चाहिये। (४) राशि लेने वाला तथा देने वाला निश्चित होना चाहिये। (५) बिल-लेखक अर्थात् अक्षदाता के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा अक्षदाता ऋणी को स्वीकृत होना चाहिये। (६) राशि का भुगतान मांग पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात् होना चाहिये। (७) इसमें एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश होता चाहिये। (८) यह किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में लिखा जाता है, परन्तु इसका भुगतान उक्त व्यक्ति के आदेश में कोई अन्य व्यक्ति भी ले सकता है।

बिल के पक्ष—(Parties to a B/E)—बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पक्ष होते हैं :—(१) लेखक (Drawer)—वह व्यक्ति है जो बिल लिखता या बनाता है।

यह ऋणदाता (Creditor) अथवा भाल का विव्रेता होता है। (२) देनदार (Drawee)—वह व्यक्ति है जिस पर बिल लिखा या बनाया जाता है। यह ऋणी (Debtor) या भाल का ज्रेता होता है। (३) लेनदार (Payee)—वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में बिल लिखा या बनाया जाता है। यह ऋणदाता का भी ऋणदाता (Creditor's Creditor) होता है।

बिलों के प्रकार (Kinds of Bills of Exchange)

(क) धर्माधि के अनुसार—बिल दो प्रकार के होते हैं—(१) माँग या दर्शनी बिल (Demand or Sight Bill)—वे बिल होते हैं जिनका भुगतान जिस समय पर भी बिल प्रस्तुत किया जायें उसी समय करना पड़ता है। (२) मुहूर्ती बिल (Time or Usance bill)—वे होते हैं जिनका भुगतान एक निश्चित धर्माधि के पश्चात् होता है।

यदि बिल मुहूर्ती है, तो उल्लिखित धर्माधि में तीन अनुग्रह दिवस (Days of Grace) जोड़ देना चाहिये तब दातव्य तिथि (Due date) ज्ञात की जा सकती है। दर्शनी या माँग बिलों में अनुग्रह दिवस नहीं होते जाते हैं। मुहूर्ती बिलों पर भूष्यानुसार रेखापु टिक्क लगाया आवश्यक है, परन्तु दर्शनी या माँग बिलों पर टिक्क लगाना आवश्यक नहीं है।

बिल ऑफ़ एक्सचेंज प्रायः मुहूर्ती ही होते हैं। एच० बिदर्स ने लिखा है कि “समय के हस्त के ही कारण यह बैंक में मिलता है। बैंक में समय जोड़ दीजिये, वह बिल ऑफ़ एक्सचेंज हो जमगा।”

(घ) स्थान के अनुसार—भुगतान-स्थान के अनुसार भी हम बिलों को दो श्रेणियों में कर सकते हैं—(१) देशी बिल, (२) विदेशी बिल।

देशी बिल (Inland B/E)—वे हैं जिनका चलन एक भुगतान एक ही देश में हो। उदाहरणार्थ, यदि कोई बिल भारतवर्ष में लिखा जाय और वही उसका भुगतान किया जाय, तो यह देशी बिल होगा।

(१) देशी बिलों के उदाहरण

(क) माँग या दर्शनी बिल (Demand or Sight Bill)

RS 1,000/-/-

AJMER

June 16, 1960

On demand pay to Shri Ram Dhan Acharya or order the sum of rupees one thousand only, for value received.

Rameshwar Lal Gupta

To

Shri Ram Swarnp Agarwal,
Naya Bazar, Ajmer.

(ख) मुद्दी विल (Time or Usance Bill)

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">टिकट</p>	<p>₹ १,०००</p>	<p>कानपुर,</p> <p>१७ जून १९६० ई०</p>
<p>उपरोक्त तिथि के लिये माग परवाना हमें प्रकृष्टा हमारे आदेशानुसार एक हजार रुपये जिसका मूल्या प्राप्त हो चुका है, दीजिये।</p> <p>मेरा नाम— रामसुन्दर राममाल</p> <p>सर्वे श्री राममल्ल रामदेवमाल</p> <p>रविवर मासेट्ट, इन्दौर।</p>		

(२) विदेशी विल (Foreign B/L)—यदि विल एक देश में लिखे जायें और दूसरे में उनका भुगतान किया जाय, तो वे विदेशी विल कहलायेंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई विल भारतवर्ष में लिखा जाय और इंग्लैण्ड में उसका भुगतान किया जाय, तो वह विदेशी विल होगा।

विदेशी विल का उदाहरण

<p>Rs. 15,000/-</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Stamp</p>	<p>LONDON,</p> <p>18 th. June, 1960</p>
<p>Nancy days after sight of this First of Exchange (second & third of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Messrs. Ramlal & Co., the sum of rupees fifteen thousand, for value received.</p> <p>To Alexander & Co.</p> <p>Messrs Seksaria & Sons,</p> <p>Kalbadevi Road,</p> <p>BOMBAY.</p>	

स्वीकृति (Acceptance)—जब विल ड्राफ्ट (Drawer) द्वारा लिख लिया जाय और उसका भुगतान किया जाता है, तब वह ड्राफ्ट (Drawee) के पास स्वीकृति (Acceptance) के लिये प्रस्तुत किया जाता है। वह उसे स्वीकार करने के लिये उसके मुख पर "स्वीकार किया" या "Accepted" शब्द लिख देता है। स्वीकृति के पढ़ने विल केवल ड्राफ्ट (Draft) होता है। स्वीकृति के पढ़वाने विल पक्का रक्का हो जाता है और दोनों पक्षों पर लागू हो जाता है। स्वीकृति का अर्थ यह है कि ड्राफ्ट (Drawee) जो विल के स्वीकार करने के बाद स्वीकर्ता (Acceptor) भी कहलाता

है बिल-लेखक द्वारा लिखे गये बिल का वास्तविक स्वीकार करता है। दर्शनी मांग बिलों में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

बिल का पूर्व प्रापण या बिल भुनाना (Discounting a Bill of Exchange)—बैंक द्वारा मुद्दनी बिल का तात्कालिक मूल्य (Present worth) घटाया अवधि समाप्त होने के पूर्व ही बट्टा-कम (Less discount) बिल की राशि प्राप्त करने को बिल का पूर्व-प्रापण या भुनाना कहते हैं।

बिल के पूर्व प्रापण या भुनाने की विधि—वैभे बिल की राशि बिल की अवधि समाप्त होने पर ही देनदार अवकाश स्वीकर्ता में प्राप्त की जा सकती है। यदि बिलधारी को अवधि से पूर्व ही राशि की आवश्यकता हो, तो वह किसी बैंक द्वारा उसे भुना सकता है। बैंक बिल की राशि में से बिना बीती अवधि का व्याज घट्टे (Discount) के रूप में काट कर शेष राशि बिल भुनाने वाले को दे देता है। इस प्रकार का व्यवहार करने के पूर्व बैंक बिल के पक्षों की मास सम्बन्धी जाँच पड़ताल कर लेता है।

बिलों के प्रयोग से लाभ (Advantages)

(१) ऋणी को ऋण-मुक्तान के लिये एक निश्चित अवधि बिल जाती है। इस बीच में वह मास बेच कर भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।

(२) ऋण-भुगतान का यह यद्दत ही सुरक्षित एवं सुविधाजनक साधन है। इसके उपयोग से रकमा स्थानान्तरित करने में स्थूलतम कठिनाई तथा व्यय होता है।

(३) बिल में भुगतान करने की निश्चित तिथि होती है। अतः बिना का प्रयोग व्यापारियों में निश्चित समय पर रकमा देने की अति आवश्यक मादत साधता है।

(४) ऋणी, ऋण-भुगतान की एक निश्चित अवधि मिल जाने के कारण, ऋण-दाता या साहूकार के बार-बार राशि-भुगतान के तकाजों से मुक्त हो जाता है।

(५) बिल एक वास्तवीय कागज है और यदि यह सम्बोधित कर दिया जाय तो इसका भुगतान न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(६) ऋणदाता या साहूकार को यदि रोकड़-राशि की तुरन्त आवश्यकता हो, तो वह इन बिना को भुनाकर रोकड़ राशि प्राप्त कर सकता है।

(७) यदि किसी समय किसी व्यापारी के पास नकद रकमा न हो और उनके ऋणदाता उनसे तुरन्त ही रकमा माग रहे हो, तो वह अपने बिल का बेचान उनके पक्ष में कर सकता है।

(८) बिलों के प्रयोग में कब पत्र व्यवहार बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है और रोकड़-राशि के प्रयोग में वषण होती है।

(९) राशि-भुगतान के पश्चात् ऋण के लिये यह ऋणी-भुगतान का एक प्रजादय प्रमाण हो जाता है।

(१०) बिल के प्रयोग से व्यापारियों में ईमानदारी तथा स्वाभिमान की मात्रा अधिक हो जाती है।

प्रामिसरी नोट या प्रतिज्ञापत्र

(Promissory Note—P/N)

परिभाषा (Definition)—प्रामिसरी नोट वह लिखित दायरहित प्रतिज्ञापत्र है जिसके द्वारा उसका लेखक या बनाने वाला (Maker) किसी

व्यक्ति विशेष को, या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या वाहक की मांग पर, अथवा किसी निश्चित अवधि के पश्चात् एक निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है।

प्रॉमिसरी नोट के पक्ष (Parties)—प्रॉमिसरी नोट के केवल दो पक्ष होते हैं—(१) लेखक या बनाने वाला (Maker)—यह व्यक्ति होता है जो प्रतिज्ञा पत्र लिखकर राशि देने का वचन देता है। (२) लेनदार (Payee)—यह वह व्यक्ति या साहूकार होता है जिसके पक्ष में प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है तथा जिसको उस पत्र का स्वत्वा मिलता है।

प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा-पत्र के प्रकार (Kinds of Promissory Note)

(१) 'दर्शनी या मांग प्रॉमिसरी नोट (Sight or Demand P/N)—यह प्रतिज्ञा-पत्र है जिसमें मांग करते ही अथवा दिखते ही तुरन्त राशि भुगतान करनी पड़ती है।

(२) मुदती प्रॉमिसरी नोट (Time P/N)—यह है जिसमें राशि भुगतान की प्रतिज्ञा किसी निश्चित अवधि के पश्चात् करने की होती है।

मुदती प्रॉमिसरी नोट के उदाहरण

<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> टिकट </div>	₹,००० ००	वाराणसी, पून १४, १९६०
<p>मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपर्युक्त तिथि के तीन मास पश्चात् श्री मरनारायण को एक हजार रुपये जिनका मूल्य प्राप्त हो चुका है, दूँगा।</p> <p style="text-align: right;">हरनारायण</p>		

(३) एकल प्रॉमिसरी नोट (Single P/N)—यह है जिसमें एक ही व्यक्ति राशि भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। इसका उदाहरण ऊपर दिया गया है।

(४) संयुक्त प्रॉमिसरी नोट (Joint P/N)—यह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में राशि-भुगतान की प्रतिज्ञा करते हैं।

उत्तरदायित्व—यदि संयुक्त प्रतिज्ञा-पत्र का घनादरण (Dishonour) हो जाय, तो पत्रधारी सब पत्र लिखने वालों पर राशि-प्राप्ति के लिये संयुक्त रूप में अभियोग चला सकता है, न कि अलग-अलग।

संयुक्त प्रो-नोट का उदाहरण

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Stamp</p>	<p>Rs. 1,000/—</p>	<p>Delhi,</p> <p>June 14, 1960</p>
<p>Three months after date we promise to pay Shri Gyan Chandra Gupta, the sum of rupees one thousand only, value received.</p> <p>Ram Chandra, Harish Chandra</p>		

(५) संयुक्त एवं पृथक् प्रॉमिसरी नोट (Joint & Several P/N)—यह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में तथा प्रत्येक-प्रत्येक व्यक्ति-व्यक्तिगत की प्रतिज्ञा करते हैं।

उत्तरदायित्व—ऐसे प्रतिज्ञा-पत्र के प्रभावदरख हो जाने पर पक्षधारी चाहे तो सब पत्र मिलाने वालों के बिना संयुक्त रूप में अभियोग चलाने या उनमें से किसी एक या कुछ के ऊपर ही चलाने। प्रत्येक-प्रत्येक चलाने पर भी कोई पत्र लिखने वाला अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।

बैंक नोट और करेंसी नोट—जो नोट किसी देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं वे बैंक नोट कहलाते हैं, और जो नोट सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं वे करेंसी नोट कहलाते हैं। ये नोट पत्र-मुद्रा में सम्मिलित हैं। भारतवर्ष में बैंक नोट और करेंसी नोट में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक की यह प्रतिज्ञा होती है कि नोट-माहक को एक निश्चित रुपये की राशि मांगने पर भुगतान कर दी जायगी। इसलिये ये भी मांग या दर्शनी प्रॉमिसरी नोट ही होते हैं।

प्रॉमिसरी नोट और बैंक या करेंसी नोट में अन्तर

प्रॉमिसरी नोट	बैंक या करेंसी नोट
(१) यह किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिज्ञा होता है।	(१) यह देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिज्ञा होता है।
(२) ये लिसे जाते हैं तथा इन पर टिकट लगाये जाते हैं।	(२) ये छपे हुए होते हैं तथा इन पर टिकट अनिवार्य है।
(३) ये कई प्रकार के होते हैं—दर्शनी, मुहूर्ती आदि।	(३) ये सर्व्व दर्शनी होते हैं।
(४) ये विधियाद्य नहीं होते हैं, अर्थात् कोई भी व्यक्ति इनको लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।	(४) ये विधियाद्य होते हैं। इन्हे भुगतान में स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
(५) मुहूर्ती प्रो-नोट वेचान व सुपुर्व्वगी द्वारा हस्तान्तरित किये जाते हैं।	(५) ये सब दर्शनी होते हैं, इसलिये ये सुपुर्व्वगी-भाव से हस्तान्तरित किये जाते हैं।

- (६) ये किसी भी राशि के मिले लिखे जा सकते हैं। इनमें रुपये के अतिरिक्त घाने पाई भी होते हैं।
- (७) ये बाहक अथवा ऑर्डर होते हैं।
- (६) ये किसी निश्चित राशिमें के होते हैं। इनमें घाने पाई नहीं होते हैं।
- (७) ये सदैव वाहक होते हैं।

चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अन्तर

चेक (Cheque)	बिल (B/E)	प्रो नोट (P/N)
(१) यह सदैव बैंक पर लिखा जाता है।	(१) यह किसी व्यक्ति-विशेष, फर्म या कम्पनी पर लिखा जाता है।	(१) यह किसी व्यक्ति-विशेष, फर्म या कम्पनी की प्रतिज्ञा लिखी जाती है।
(२) यह बैंक के अमानत-दार या ग्राहक द्वारा लिखा जाता है।	(२) यह ऋणदाता या भाहूकार द्वारा ऋणी पर लिखा जाता है।	(२) यह ऋणी द्वारा ऋणदाता या साहू-कार के प्रति प्रतिज्ञा होती है।
(३) यह राशि-भुगतान का आदेश होता है।	(३) यह राशि-भुगतान का आदेश होता है।	(३) यह राशि-भुगतान की प्रतिज्ञा होती है।
(४) इसमें तीन पक्ष होते हैं—लेखक, देनदार-बैंक और लेनदार।	(४) इसमें तीन पक्ष होते हैं—लेखक, देनदार और लेनदार।	(४) इसमें दो पक्ष होते हैं—बनान वाला या देनदार और लेनदार।
(५) इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।	(५) इसमें देनदार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।	(५) इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि फरणी स्वयं प्रतिज्ञा करता है।
(६) ये सदैव मांग या दर्शनी होते हैं।	(६) ये दर्शनी और मुद्दनी दोनों ही होते हैं।	(६) ये दर्शनी और मुद्दनी दोनों ही होते हैं।
(७) ये देश के भीतरी चलन के काम आते हैं।	(७) ये देशी और विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं।	(७) यह भी देशी और विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं।
(८) इसकी एक ही प्रति बनाई जाती है।	(८) विदेशी बिल प्रायः तीन प्रतियां में बनाया जाता है।	(८) विदेशी प्रॉमिसरी नोट उचित एक ही प्रति बनाई जाती है।
(९) इसे रेखांकित कर सकते हैं।	(९) इसे रेखांकित नहीं कर सकते हैं।	(९) इसे रेखांकित नहीं कर सकते हैं।

- (१०) इसका हस्तान्तरण केवल सुपुद्गी-मात्र से ही हो सकता है ।
- (१०) दर्शनी विलो का तो हस्तान्तरण केवल सुपुद्गी मात्र में ही होता है, परन्तु मुद्गी विलो का हस्तान्तरण वेचान-लेख तथा सुपुद्गी दोनों से ही होता है ।
- (१०) इनका हस्तान्तरण भी विलो की भाँति होता है ।
- (११) चैको पर टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती है ।
- (११) माँग या दर्शनी विलो के अतिरिक्त सब प्रकार के विलो पर सूत्रानुसार टिकट लगाना कानूनी आवश्यकता है ।
- (११) माँग या दर्शनी तथा मुद्गी सभी प्रकार के प्रो-नोटो पर टिकट लगाना कानूनी आवश्यकता है ।
- (१२) हमसे गलती होने पर बैंक भुगतान नहीं देता ।
- (१२) इससे गलती होने पर भी यदि देनदार ने स्वीकार कर लिया है तो देनदार को भुगतान देने के लिये बाध्य किया जा सकता है ।
- (१२) इसमें भी गलती होने पर देनदार को बाध्य किया जा सकता है ।
- (१३) यदि बैंक के प्रस्तुत करने में विलम्ब हो जाय, तो इससे लेखक और वेचानकर्त्ता अपने दायित्व में मुक्त नहीं होंगे । हाँ, यदि बैंक फेल हो जाय तो बात दूसरी है ।
- (१३) विल यदि ठीक तिथि पर प्रस्तुत न किया जाये, तो अन्य सत्र सम्बन्धित व्यक्ति अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं ।
- (१३) इसमें भी देनदार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है ।
- (१४) बैंक अनादरण पर अनादरण सूचना देना आवश्यक नहीं है और न निकराई सिकराई ही आवश्यक है ।
- (१४) जिस अनादरण पर सम्बन्धित व्यक्तियों को अनादरण सूचना (Notice of Dishonour) देना आवश्यक है तथा उसको निकराई-सिकराई भी करानी होती है ।
- (१४) प्रो-नोटो में अनादरण सूचना तथा निकराई - सिकराई आवश्यक नहीं है ।

हुण्डी (Hundi)

हुण्डी शब्द का अर्थ एवं परिभाषा—हुण्डी शब्द संस्कृत 'हुण्ड' से बना जिसका अर्थ 'संग्रह' करता है। हुण्डी सामान्यतया एक अर्थ रहित लिखित आदेश पत्र है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि वह रुपये की एक निश्चित राशि उल्लिखित व्यक्ति को माँगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात् मुगतान कर दे।

हुण्डी का महत्त्व—भारतवर्ष में हुण्डी बहुत ही प्राचीन काल में प्रचलित है। आज भी हमारे देश के अन्तर्देशीय व्यापार में इसका बड़ा महत्त्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान को राशि भेजने का यह बड़ा अच्युत साधन है। हमारे द्वारा खपया सधारा भी लिया जा सकता है। जिस व्यापारी को रुपये की आवश्यकता होती है वह अपने एजेंट या चिन् व्यापारी पर एक हुण्डी लिख सकता है और उसे किसी बैंक में बट्टा देकर धुना सकता है।

बिना और हुण्डी में भेद—बस तो हुण्डी और बिल में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। हुण्डी बिल का रूपान्तर साध है, अर्थात् हुण्डी एक प्रकार से देशी बिल ऑफ एक्मचज है। परन्तु इन दोनों में जो भेद है उसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है।

१—बिल प्रायः अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसकी भाषा एक प्रकार से अन्तरवर्तमान होती है। परन्तु हुण्डी भारत की सभी भाषाओं में लिखी जाती है, और इसमें स्थानानुसार परिवर्तन भी होता रहता है।

२—बिल एक अर्थ-रहित आदेश है; परन्तु हुण्डी का आदेश शर्त-रहित भी हो सकता है, जैसे - भोभ्रमी हुण्डी।

३—बिल में ड्रेफ्ट (Draft) का नाम नीचे दाईं ओर लिखा जाता है, परन्तु हुण्डी में ड्रेफ्ट का नाम बीच में दिया जाता है।

४—बिल पत्र की भाँति नहीं लिखा जाता है बल्कि इसमें केवल तथ्य ही होते हैं। हुण्डी पत्र के रूप में लिखी जाती है, अतः इसमें अभिवादन आदि भी प्रयुक्त बिन्दु पाते हैं।

५—बिल के ड्रेफ्ट (Draft) का नाम नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। परन्तु हुण्डी में यह बीच में लिखा जाता है।

६—बिल में राशि दो बार अक्षुब्ध और अक्षरों में लिखी जाती है जिसमें राशि-परिवर्तन सुगमता से न हो सके। हुण्डी में राशि पाँच बार से कम नहीं लिखी जाती, अतः राशि-परिवर्तन अत्यन्त कठिन हो जाता है।

७—बिल की स्वीकृति, ड्रेफ्ट द्वारा आवश्यक है और यह बिल के मुख पर दी जाती है। हुण्डी में स्वीकृति आवश्यक नहीं है, केवल ड्रेफ्ट अपनी वही में इसका प्रयोग लिख लेता है।

८—बिल देशी और विदेशी दोनों प्रकार का होता है, परन्तु हुण्डी केवल देशी ही होती है।

६—बिल में तीन धनुषह दिवस या रियायती दिन (Days of Grace) मिलते हैं, परन्तु हुण्डी में रियायती दिना में न्यूनाधिकता होना सम्भव है।

१०—बिल प्रमादरख म निकराई सिकराई का होना आवश्यक है। हुण्डी में इसकी काद आवश्यकता नहीं है।

हुण्डी के पक्ष (Parties)—हुण्डी में प्राय तीन पक्ष होते हैं—(१) लेखीवाला या लेखक (Drawer) वह व्यक्ति है जो हुण्डी निश्चिता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। (२) ऊपर वाला या दनदार (Drawee)—वह व्यक्ति है जिस पर हुण्डी लिखी जाती है। यह जल्दी हाथ है जिस हुण्डी की राशि देनी होती है। (३) राख्या-वाला या आदाता (Payee)—वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में हुण्डी लिखी जाती है। इसे हुण्डी की राशि प्राप्त होती है।

हुण्डिया के भेद (Kinds of Hundies)—हुण्डियाँ मुख्यत दो प्रकार की होती हैं—दशमी और मुहूर्ती या मिली। (१) दर्शनी हुण्डी—वह है जिसका भुगतान मास पर करना पड़ता है। यह Sight or Demand बिना की जाती है। इस प्रकार की हुण्डिया में मुख्यत राशि स्थानान्तरण का प्रयोजन सिद्ध होता है।

(२) मुहूर्ती या मिली हुण्डी—वह है जिसका भुगतान किसी निश्चित अवधि के पश्चात् किया जाता है। इसमें उचितदिन अवधि में रियायती दिन (Days of Grace) का गिनतान चढ़ाना है जो एक से पश्चात् भुगतान किया जाता है। हुण्डियाँ ११ दिन में लेकर १२ महिना तक की अवधि (मुदत) में चिय सिली जाती है। अवधि व्यापार की प्रथा तथा स्थानानुसार परिवर्तनशील है।

मुहूर्ती या मिली हुण्डी का उदाहरण

॥ आगमजा ॥

विद्वत् श्री चम्पद रामस्वाम भाई श्री रामबाब राममुख जाग निजी आगमर मे अमरचन्द रामचन्द का जै गाराव बचनी। अवरच हुण्डी बीनी एक आवने ऊपर २० २००० प्रवन दो हजार रुपया व नीम रुपय एक हजार व हुन पूरे मही गम्मा श्री भाई पन्नाब बैंग लि० व पाठ मिली बैंगाल मुदी ६ मे दिन ६१ (इकसठ) पीछे नाम माह जाग हुण्डी बनन बनदार बना। मिला बैंगाल मुदी ६ सदद २०१७।

हुण्डी की व्याख्या (Explanation)—वह मुहूर्ती राष्ट्रीय हुण्डी का उदाहरण है। इसमें अमरचन्द रामचन्द तो लेखीवाला या लेखक है रामबाब राममुख ऊपरवाला या दनदार है और पन्नाब बैंग लि० गह्यावाला या आदाता है। हुण्डी की राशि दो हजार रुपया है और अवधि (मुदत) ६१ दिन की है।

हुण्डियों के अन्य प्रकार

(१) घनी जोष हुण्डी—वह है जो किसी घनी या हुण्डी धारक का देय होता है। भुगतान, दर, बाले की काद निम्नद्वारा करा जाता है। यह वास्तु या अवरर चैन का भाग होता है। (२) माह जाग हुण्डी—वह हुण्डी है जिसका भुगतान माह अर्थात् गम्मानित व्यक्ति का देय होता है। यह ख्यातिन चैन व गम्मान है। अतः इसका भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह वर्तव्य है कि वह इस बात की टंक-दीन जान करन कि प्रस्तुत करन

चाला व्यक्ति भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं। (३) फरमान जोग हुण्डी—वह हुण्डी है जो लेनदार या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को देय होती है। इसका प्रादुर्भाव भवन काम से हुआ और इसका प्रचार कहीं कहीं अब भी दृष्टिगोचर होता है। 'फरमान' शब्द आदेश का सूचक है। यह घोंवर चैक की भाँति है। अतः भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि भुगतान करने से पहले वेचान लेख को मनी-मोनि जाँच कर ले; अन्यथा वह उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं रह सकता। (४) देखन-हार हुण्डी—वह हुण्डी है जिसका भुगतान हुन्डीवाहक (Bearer) को देय होता है। अतः एसी हुण्डी के भुगतानार्थ देनदार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तुत करने वाले को भुगतान दे दिया जाता है।

दृष्टिगोचर के प्रयोग से लाभ—दृष्टिगोचर के प्रयोग से लाभ सम्भव है ही है जो बिना पॉलि एन्मर्सेस के अन्तर्गत वर्णित है।

बैंक ड्राफ्ट (Draft)

परिभाषा (Definition)—बैंक ड्राफ्ट वह चैक है जिसमें एक बैंक अपनी शाखा या एजेंट चैक या अन्य बैंक को लिखित आदेश देता है कि वह उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार अन्य किसी व्यक्ति को मांगते पर एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे।

यह एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने का अनुपम साधन है। जब कोई व्यक्ति किसी दूरस्थ व्यक्ति को रुपया भेजना चाहता है, तो वह भेजी जाने वाली राशि और मोटा सा वसीयत चैक से जमा कर बैंक-ड्राफ्ट खरीद कर भेज देता। इसके द्वारा राशि भेजने में बहुत कम खर्च पड़ता है। यदि राशि सीधे से भेजना हो, तो दार या प्यार देकर तार द्वारा टेलीग्राफिक ट्रांसफर (Telegraphic Transfer—T/T) भेज सकता है। बैंक-ड्राफ्ट अन्तर्देशीय और विदेशीय दोनों प्रकार के होते हैं।

अन्तर्देशीय बैंक ड्राफ्ट का उदाहरण

STATE BANK OF INDIA	
No. 2785 B/D	AJMER
Rs. 2,000/-	16th. June, 1960
On demand pay to Shri Suraj Bhan Agarwal or order Rupees two thousand only, value received.	
For State Bank of India, A. R. Contractor Agent.	
To	
The State Bank of India, AGRA	

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—हुण्टी और बैंक पर नोट लिखिये ।
- २—साख पत्र की परिभाषा दीजिये और उसके मुख्य कार्य बताइये । विनिमय विल और वरेंसी नोट में अन्तर बताइये ।
- ३—मुद्रा और साख पत्रों का अन्तर बताइये । प्राचुर्य, घाण्डव्य और उद्योगों से क्या नाम होता है ?
- ४—साख पत्र (Credit Instruments) की परिभाषा दीजिये । बैंक (Cheque) तथा करेंसी नोट (Currency Note) में क्या अन्तर है ?
- ५—साख में आप क्या समझते हैं ? भारत में उद्योग और व्यापार को साल में क्या महायना पहुँचाई ।
- ६—बैंक किम बहून है ? इसे रेखांकित करने का क्या उद्देश्य है ?
(रा० बो० १९५४)
- ७—साख किस कहते हैं ? साख-मुद्रा के लाभ हानि की विवेचना कीजिये ।
(रा० बो० १९५२)
- ८—हुण्टी पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।
(प्र० बो० १९५४, ५०, ४६)
- ९—निम्नलिखित पर नोट लिखिये :—
आउटर, बैंक बेगरर और ग्राँम हुए बैंक ।
(म० म० १९५४)
(रा० बो० १९६०, म० भा० १९५३)
- १०—विनिमय साख पत्रों के नाम बताइए । उनमें से किसी एक की परिभाषा दीजिए और इसकी कार्य-प्रणाली तथा महत्व को बताइए ।
(सागर १९५८)
- ११—बैंक और विनिमय विल में क्या भेद है ? बैंक के रेखांकित करने का क्या उद्देश्य होता है ? इससे लाभ बताइए ।
(सागर, १९५५)
- १२—'साख' शब्द की व्याख्या कीजिये । साख द्वारा समाज को क्या क्या सेवाएँ होती हैं ?
(सागर १९५६)
- १३—निम्नलिखित प्रत्यय-पत्रों के कार्य तथा उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विवरण दीजिए—(अ) विनिमय पत्र, (आ) धनादेश ।
(नागपुर १९५८)
- १४—धनादेश क्या होता है ? धनादेश के विविध प्रकारों को स्पष्टतया समझाइए । देश की भौतिक पद्धति में धनादेश का महत्व दीजिए ।
(नागपुर १९५७)
- १५—निम्नलिखित पर नोट लिखिए :—
साख-पत्र
हुण्टी और बैंक
प्रतिभा अर्थ-पत्र (प्रॉक्सरी नोट)
विल ऑफ़ एक्सेचेंज (विनिमय पत्र)
बैंक ड्राफ्ट
विल ऑफ़ एक्सेचेंज
बैंक और विल ऑफ़ एक्सेचेंज
(नागपुर १९५७, सागर १९५६)
(म० भा० १९५६)
(नागपुर १९५६)

बैंक की परिभाषा (Definition)—बैंक वह मस्था है जो मुद्रा (Money) और साख्त (Credit) का लेन-देन करती है, जहाँ रुपया जमा किया जा सकता है तथा खर्चा लिया जा सकता है, और जहाँ धन-सम्पन्नों के अनेक व्यवहार होने हैं। वक्त में वे व्यक्ति राशि जमा कराने हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक पूँजी होती है और जो उसे सत्ताम व्यापार में नहीं लगा सकते। बैंक उन लोगों को राशि उधार देता है जिनके पास आवश्यक निधि नहीं है, परन्तु जो उस निधि को लाभप्रद व्यापार या व्यवसाय में लगा सकते हैं। यह सब बैंक का कार्य मात्र (Credit) के अन्तर्गत आता है, इसलिये वेदों को माध्य सम्स्थाएँ (Credit Institutions) कहते हैं। मुद्रा और साख्त के उपयोग में व्यापार करने की क्रिया को बैंकिंग (Banking) कहते हैं।

स्पष्टतः बैंक प्राचुरित्व ढंग से लेन-देन करने वाली मस्था है। जिस प्रकार एक व्यापारी वस्तुओं का लेन देन करता है, ठीक उसी प्रकार बैंक मुद्रा और साख्त के उपयोग का लेन देन करता है। वे सर्वसाधारण से कम ध्यान पर रक्षा लेते हैं और उनसे ऊँची दर पर उसे उधार देते हैं। इस प्रकार का लेन देन ही वास्तव में इनका मुख्य धर्म है और इसी से उनकी अधिकता लाभ प्राप्त होता है।

बैंकों का महत्त्व (Importance)—बैंक प्राचुरित्व व्यापार का 'जीवन' है। आज के समय में बिना सुव्यवस्थित बैंकों के कोई भी देश व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकता। वे वाणिज्य व्यापार व उद्योग की बहुत सेवा करते हैं। जनता के रुपये को बचाने और लगाने का एक लोकप्रिय साधन निर्माण करने में जनता को अधिकारिय रूप से बचाने में भी-माहृत देते हैं। बैंक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की बचाई हुई छोटी-से-छोटी राशियों को एकत्रित करके समाज की अधिक दत्ता का पुष्ट बनाने हैं। एकत्रित राशि में से वे व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा इषकों को रुपया उधार देते हैं जिन्हें वे विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगाने हैं। बैंक एक प्रकार से मध्यस्थ का काम करते हैं जो लोगों की छोटी-छोटी बचत की रकमों को इकट्ठा करके बड़-बड़े कुशल और चतुर व्यापारियों, व्यवसायियों तथा औद्योगिक योग्यता रखने वालों का बहुत बड़ी रकम के रूप में देते हैं जिससे देश के उत्पादन में वृद्धि तथा अधिक उन्नति होती है। यदि बैंक न होते तो राष्ट्र की अधिकतर योग्यता व पूँजी व्यर्थ रहती जो कि एक बड़ी राष्ट्रीय हानि होती। इस प्रकार बैंक उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होकर औद्योगिक उन्नति के मुख्य साधन बन गये हैं।

बैंक द्वारा निर्माताओं तथा उत्पादकों को उचित समय पर रकमा मिल जाता है और इसमें देश की उत्पादन शक्ति में असाधारण वृद्धि होती है। सच तो यह है कि आधुनिक व्यापार नाम पर निर्भर है। बैंक वस्तु-निर्माता (Manufacturer) को उधार देता है, निर्माता बोल व्यापारी (Wholesaler) को उधार देता है, बोल व्यापारी फुटकर व्यापारी (Retailer) को और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता (Consumer) का उधार देता है। बैंकों द्वारा ही मुद्रा व साख की उपयोगिता का लेन देन होता है, इसलिए यह सारी व्यवस्था बिना बैंकों के सम्भव नहीं हो सकती।

मारास यह है कि बैंकों का आधुनिक आर्थिक जगत में इतना महत्त्व है कि यह आर्थिक जीवन का स्नायु-केन्द्र (Nerve Centre) कह कर पुकारा गया है, वास्तव में, इन्होंने की उन्नति पर देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति निर्भर है।

आधुनिक बैंक के कार्य एवं सेवाएँ (Functions & Services of a Modern Bank)—अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में बैंक के कार्यों की तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) प्रारम्भिक कार्य, (२) सामान्य उपयोगिता के कार्य और (३) एजेंसी कार्य।

(१) प्रारम्भिक कार्य (Primary Functions)—बैंक के दो प्रारम्भिक कार्य होते हैं—(अ) रकमा उधार लेना, और (आ) रकमा उधार देना।

(अ) रकमा उधार लेना (Borrowing of Money)—जनता में रकमा जमा लेना आधुनिक बैंकों का मुख्य कार्य है। जिन व्यक्तियों ने पाम रकमा है और जो उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा साथ-ही-साथ कुछ व्याज भी कमाना चाहते हैं, वे बैंक में अपना रकमा जमा कर देते हैं। इस प्रकार लोगों की बचत की बेकार पड़ो हुई छोटी व मोटी राशियाँ बैंक द्वारा एकजुट हो जाती हैं। इसी जमा के आधार पर बैंक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ऋण देकर उत्पादन में योगदान देते हैं। बैंक में रकमा कई जगहों में जमा कराया जा सकता है, उनमें से मुख्य ये हैं—चालू खाता, स्थायी-जमा खाता; और बचत बैंक खाता।

(१) चालू खाता (Current Account)—वह खाता है जिसमें से रकमा बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक द्वारा किसी भी समय कितनी भी बार निवाला जा सकता है। सामान्यतया इस पर कुछ व्याज नहीं दिया जाता है। परन्तु यदि एक निश्चित राशि सदैव जमा रखी जाय, तो उस पर थोड़ा-सा व्याज मिल जाता है। यह खाता विशेषतया व्यापारियों के लिये बड़ा उपयोगी है।

(२) स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit Account)—वह खाता है जिसमें रकमा एक निश्चित अवधि के लिये जमा कराया जाता है और उस अवधि में पूर्व रकमा नहीं निकाला जा सकता। ऐसे खाते पर अच्छा व्याज दिया जाता है।

(३) बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)—वह खाता है जिसमें ये राशि निकासन पर प्रतिकूल होना है, अर्थात् राशि सप्ताह में एक या दो बार ही निकाली जा सकती है। छोटी-साधु-साने व्यक्तियों में मितव्ययता का प्रोत्साहन देने के लिये इस खाते में जमा रकम पर व्याज भी दिया जाता है। यह खाता जाँच-पर के बचत करने की भाँति होता है।

(भा) रुपया उधार देना (Lending of Money)—बैंक जमा के साधारण पर ही उधार देने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। यतः बैंक अनेक व्यक्तियों की छोटी-छोटी राशियाँ एकत्रित कर अपने पास एक बृहत् निधि बना लेता है जिसमें से उन व्यक्तियों को दिनमें व्यापार और व्यवसाय चलायाने की योग्यता तो है, परन्तु जिनके पास पूँजी का अभाव है, बैंक ब्याज पर रुपया उधार देता है। इस प्रकार बैंक संचय करने वालों और उत्पादकों या निर्माताओं के बीच संपत्ति का मार्ग करके उत्पादन मूल्य को संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है। वैसे रुपया उधार देने की बहुत-सी रीतियाँ हैं, परन्तु जिस भूतना या डिस्काउन्ट करना, तथा साखू खाते पर अधिविकल्प (Overdraft) देना तथा रोबट साखू (Cash Credit) आदि मुख्य हैं। मुद्रा विलो या हुण्डियों की राशि बट्टा काट कर दातव्य तिथि के पूर्व देना, विल भूतना या डिस्काउन्ट करना कहलाता है। साखू खाते में से जमा की गई राशि से अधिविक्रयित देना अधिविकल्प या ओवरड्राफ्ट कहलाता है। छोटी राशि जमा करा कर इन्हें कहीं अधिक राशि उधार देना रोबट साखू कहलाती है। बैंक जिस लोगो की रुपया देता है उनसे उस रुपए के बढे कुछ धरोहर भी लेती है। यह धरोहर बहुत ऐसी होती है जो बाजार में कीमतिशील बिक सके; जैसे: अचल सम्पत्तियों के वेयर आदि। बैंक अचल सम्पत्ति (Immovable Property) की धरोहर के रूप में नहीं लेती, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से नहीं बेची जा सकती है।

(२) सामान्य उपयोगिता के कार्य (General Utility Functions)—उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक जन-साधारण के लिये भी बहुत से कार्य करता है जिनका वर्णन नीचे किया जाता है :—

(अ) नोट जारी करना—यह कार्य आवश्यक केवल केन्द्रीय बैंक ही करता है। भारतवर्ष में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को है जो देश का केन्द्रीय बैंक है।

(भा) चलन की पूर्ति—बैंकों द्वारा ही पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मुद्रा भी चलन में आती है, जो देश के चलन की पूर्ति करने में सहायक होती है।

(इ) साखू-पत्रों को जारी करना—बैंक, बैंक द्राफ्ट आदि साखू-पत्र बैंकों द्वारा ही जारी किये जाते हैं। इनके द्वारा राशि एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से तथा कम दरों में भेजी जा सकती है।

(ई) विदेशी विनिमय—बैंक एक देश के चलन का दूसरे देश के चलन से विनिमय करने में सहायता देने हैं। इन्हीं के द्वारा विदेशी व्यापार का लेन-देन होता है।

(उ) बहुमूल्य वस्तुओं की गुरक्षा—बैंको में बहुमूल्य वस्तुएँ, जैसे जेवर, दासताने आदि सुरक्षित रखे जा सकते हैं। रखने वाले को धान व चोरी का भय नहीं रहता। बैंक इस सेवा के लिये उनसे कुछ शुल्क लेता है।

(३) एजेंसी कार्य (Agency Functions)—उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों के लिये निम्नलिखित एजेंसी कार्य भी करते हैं—

(अ) बैंक अपने ग्राहकों के लिये चिक्योरिटोज (प्रतिवृत्तियाँ) और सेवर (अग) आदि तरीक़े और बेचते हैं। (आ) बैंक अपने ग्राहकों के लिये लाभांश (Dividend) और व्याज आदि वसूल करते हैं तथा उनके प्रति बीमा का बीमियम, आय कर, चन्दा, निराया आदि का भुगतान करते हैं। (इ) बैंक अपने ग्राहकों के लिये बैंक ड्राफ्ट और सात पत्र (Letters of Credit) आदि जारी करते हैं। (ई) नई कम्पनियाँ की पूँजी एवञ्जित करने में सहायता देने हैं। (उ) निवास गृह (Clearing House) का कार्य करते हैं। (ऊ) वे अपने ग्राहकों के बैंक, वित्त, हुण्डी आदि को राशि वसूल करते हैं। (ए) वे अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना देने हैं तथा दूसरों के पूछने पर अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखते हैं। (ऐ) वे ट्रस्टीज (Trustees), एटर्नी (Attorney) तथा एक्जिक्यूटर्स (Executors) आदि की भाँति भी अपने ग्राहकों के लिये काम करते हैं।

क्या भारतवर्ष में ग्रामीण महाजन या साहूकार यथार्थ अर्थ में बैंडूक हैं? यद्यपि ग्रामीण महाजन बैंक की ही भाँति अपने कार्य सम्पन्न करता है और आधुनिक नम्रम्र अपना विशेष स्थान रखता है, परन्तु फिर भी यथार्थ अर्थ में आधुनिक बैंकर नहीं कहा जा सकता। इनके कई कारण हैं जो नीचे दिये जाते हैं :

(१) प्रथम तो यह है कि महाजन या साहूकार तोष गँवो में ही प्रायः किसानों तथा कारीगरों को अपना उधार देते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को नहीं।

(२) वे आधुनिक बैंकों की भाँति दूसरों का अपना जमा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ही पूँजी से काम चलाते हैं।

(३) उनकी हिमाय-निचाय की रीति बहुत ही पुरानी है। वे आधुनिक ढंग से हिसाब नहीं चला सकते। बहुत-से तो हिसाब रखते ही नहीं हैं। वे केवल माद ही रखते हैं या रही तोर पर नाट कर संत है, हुण्डी का प्रयोग भी बहुत सीमित है।

(४) उनकी व्याज की दरें बहुत ऊँची होती हैं।

(५) अपनी वे खेन देन के माय वे अन्य कार्य भी करते हैं।

(६) बहुत-से ठा इम कार्य में खरिद की मजबूती ही नहीं, बल्कि छन बपद से गरीब किसानों का अपना इस्तेमाल करने का प्रयत्न ही करना रहते हैं।

(७) वे अपने ग्राहकों की वे सेवाएँ नहीं करते जोकि एक आधुनिक बैंक करता है। अतः हम उन्हें तब तक आधुनिक बैंकर नहीं कहें जब तक कि वे अपनी कार्य प्रणाली आधुनिक बैंकों की भाँति नहीं कर लेंगे।

बैंडूक जमा से अधिक ऋण देते हैं—यह बात कि बैंक जमा से अधिक ऋण देते हैं वैसे विचित्र प्रतीत होती है, परन्तु यह प्रामाण्य नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है : जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना जमा करता है, तो उसे राख-राशि ले जाना करना पड़ता है। इसे रोयड जमा (Cash Deposit) कहते हैं। किन्तु जब बैंक किसी को अपना उधार देता है, तो वह उसे नकद न देकर वह राशि उसका चालू खाते में जमा कर देता है और उसे उस राशि तक बैंक काउन् का अधिकार दे देता है। इसे साख जमा (Credit Deposit) कहते हैं। इस प्रकार 'उधार जमा बन जाती है'

(Loans make deposit)। बैंक इस बात को अनुभव से जानते हैं कि जमा किया हुआ रुपया तारा का-तारा किसी एक समय नहीं निकाला जाता। किसी भी समय जितना रुपया वापस माँगा जाता है, वह मुक्त जमा को हुई राशि का १०-११% से अधिक नहीं होता। इस प्रकार बैंक १०० रुपये जमा के पीछे १०००-११०० रुपये उधार देने में समर्थ होते हैं।

बैंक की आर्थिक स्थिति मालूम करना—किसी बैंक की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिये उसके दो मुख्य हिसाब पत्रों का अध्ययन करना आवश्यक होता है—एक तो लाभ-हानि लेखा, और दूसरा चिट्ठा या स्थिति-विवरण।

(१) लाभ हानि लेखा—(Profit & Loss Account)—यह व्यापार के वर्ष भर के लाभ-हानि का हिसाब होता है। इसमें आय और व्यय के घांके समानिष्ट होते हैं और यह विमुक्त लाभ या हानि (Net Profit or Loss) बताता है। इस लेख के बाईं ओर व्यय की मदें और दाईं ओर आय की मदें होती हैं। नीचे यह उदाहरण द्वारा समझाया गया है :

आजाद हिन्द बैंक लि० का लाभ-हानि लेखा
३१ दिसम्बर १९६० ई०

विवरण (व्यय)	राशि (रु०)	विवरण (आय)	राशि (रु०)
जमा-राशि पर व्याज	१,००,०००	घोष	१३,०००
वेतन व भत्ते	५०,०००	व्याज और बट्टा	१,२०,०००
प्रॉपिटेण्ट फण्ड	२,०००	कमीशन और दमाली	५५,०००
आहरेकटरी को फीस व भत्ते	१,०००	निराया-माहुरा	२७,५००
घाक व ठार-व्यय	३,५००	ग्रन्थ प्राप्ति	६,५००
स्टेशनरी और छपाई	५,०००		
मोर्टीगेज को फीस	८००		
नाया, बीमा, विद्वानों,			
कर भादि	१३,०००		
मरम्मत व चिट्ठाई	११,०००		
अन्य व्यय	३,०००		
विमुक्त लाभ	३५,७००		
योग ---	२,२५,०००	योग ..	२,२५,०००

व्याख्या—उपरोक्त लाभ-हानि लेखा में स्पष्ट है कि इस वर्ष में बैंक को ३५,७०० रु० का विमुक्त लाभ रहा है जो चिट्ठे में भी बताया गया है।

चिट्ठा या स्थिति-विवरण (Balance Sheet)—यह एक व्यापार की वार्षिक लेनी-देनी का गौरा होता है। लेनी में आनदों में जो राई गोर होने है, बैंक की सम्पत्ति (Assets) तथा वे राशिवां दिखाई जाती है जो बैंक को दूसरो से प्राप्त होती है। देनी के गौरा में जो राई गोर होने है बैंक की देनदारियां (Liabilities) तथा वे राशिवां दिखाई जाती है जो बैंक द्वारा दूसरो को देनी होती है। चिट्ठा या स्थिति-विवरण के ध्यानपूर्वक अध्ययन से व्यापारिक सम्पत्ति की वास्तविक वार्षिक-स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। नीचे चिट्ठे का उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देता है।

आजाद हिन्द बैंक लि० का चिट्ठा (Balance Sheet)

२१ दिसम्बर, १९६० ई०

देनदारियां (Liabilities)	राशि (₹)	सम्पत्ति (Assets)	राशि रुपये
प्रधिकृत पूँजी . (Authorised Capital) ५०,००० शेयर, १० रु० प्रति शेयर	५,००,०००	हस्तगत एक बैंकरोष रोका भाँग व प्रगत वृषणा का रक्का	३,००,०००
निर्धारित पूँजी . (Jesued Capital) २५,००० शेयर १० रु० प्रति शेयर	२,५०,०००	प्रतिवृत्तियों में विनियोज (Investment in Securities)	६०,००,०००
प्राप्ति पूँजी (Subscribed Capital) २०,००० शेयर १० रु० प्रति शेयर	२,००,०००	अग्र गोर उधार मुकाये गये बिल (Discounted Bills)	१,१०,३००
प्रगत पूँजी : (Paid-up Capital) १६,६०० शेयर १० रु० प्रति शेयर	१,६६,०००	बैंक भण्ड (भिसाई निकाल कर)	७५,०००
रिजर्व फण्ड	१,५१,०००	कर्मचर आदि (भिसाई निकाल कर)	१०,०००
कमा तथा अन्य लाते	१३,००,०००	स्टेशनरी स्टॉक में	२,७००
देय बिल (B/P Bills)	१०,३००		
अन्य दायित्व	५,०००		
लाभ हानि लावा	३५,७००		
योग	११,७०,०१,०००	योग -	१७,००१,०००

व्याख्या—देनदारियां (Liabilities) (१) पूँजी—पूँजी कई प्रकार की होती है : अधिक पूँजी (Authorised Capital) वह अधिकतम राशि होती है जिसे बैंक या कम्पनी को उसके स्मारक (Memorandum) द्वारा इकट्ठा करने का अधिकार होता है। उपर्युक्त चिट्ठे में यह राशि ५,००,००० रु० है। सामान्यतया सारी अधिकृत पूँजी निर्धारित नहीं की जाती—केवल उसका एक भाग ही निर्धारित किया

जाता है जिसे निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कहते हैं। उपर्युक्त बिट्टे से निर्गमित पूँजी २ ५० ००० रु० है। जिनकी पूँजी खरीदने के लिये जनता से प्रापना पन आने है उसे प्रार्थित पूँजी (Subscribed Capital) कहते हैं। इस बिट्टे में यह २ ०० ००० रु० है। प्रति शेयर जितनी पूँजी मांगी जाती है वह माँगी गई पूँजी (Called up Capital) कहलाती है। इस बिट्टे में १० रु० प्रति शेयर के हिसाब से २० ००० शेयर पर पूँजी माँगी गई है परन्तु केवल १६ ६०० शेयर होल्डरों ने ही १० रु० प्रति शेयर के हिसाब से दिया है। इसलिये १ ६६ ००० रु० प्रदत्त पूँजी (Paid up Capital) हुई। (२) रिजर्व फण्ड (Reserve Fund)—ताम का कुछ भाग न बाट कर इस कोष में संचित रख दिया जाता है ताकि सकल-नफा में ताम भा सके। (३) जमा तथा अन्य खातों का खपटा—यह वह खपटा है जिसे ग्राहकों ने विविध खातों में जमा दिया है। (४) देय बिल (B/P Bill)—बक अपने ग्राहकों के बिलों की स्वीकृति देने है जिससे वे भासानी से भुनाये जा सक। इसकी देनदारी बक की है। (५) अन्य दायित्व—इस शीपक के अन्तर्गत विविध देनदारियों की राशि जो ऊपर के मदों में उल्लिखित नहीं है दिखाई गई है।

सम्पत्ति (Assets)—(१) हस्तस्थ एवं दकस्थ रोकड़ (Cash in hand & at Bank)—जो राशि ग्राहकों के भुगतानाय बक से रहती है वह हस्तस्थ रोकड़ कहलाती है। इसके अतिरिक्त बक जो राशि किसी बड़ बक या केन्द्रीय बक में रखता है वह बकस्थ राशि कहलाती है। (२) माँग व अल्प सूचना का खपटा (Money at Call and Short notice)—यह वह खपटा है जो बक इस गण पर उधार देता है कि वह माँगने पर या कुछ दिना की ही सूचना देने पर उसे लौटा दिया जायगा। (३) प्रतिभूतियों में निविद्योग (Investment in Securities)—इस शीपक के अन्तर्गत वह राशि दिखाई गई है जो बक ने साप पत्रों के खरीदने में लगाई है तथा जिस पर बक को व्याज मिलता है। (४) ऋण और उधार (Loans)—यह वह खपटा है जिसे बक थोड़ा समय के लिये व्यापारियों को तथा उद्योग पण्ये बसला को उधार देता है। (५) भुनाये गये बिल (Discounted Bills)—वे निविद्यम बिल होते हैं जिन्हें बक ने खरीद लिया है। इनका खपटा बक को अपने ग्राहक से प्राप्त होजा है। (६) बर भवन (Bank Buildings) तथा (७) फर्नीचर आदि (Furniture & Fittings etc)—य राशियाँ दिखाई (Depreciation) नाद नर बताई गई हैं। (८) स्टेननरी स्टॉक में—इयता कार्य यह है कि १ ७०० रु० को स्टेननरी इस बक के अन्तर्गत स्टॉक में बच रही है। यह भी बक की सम्पत्ति है।

भारतीय व्यवस्था के अङ्ग—(Constituents of Indian Money Market) भारतीय मुद्रा बाजार तथा बचिग व्यवस्था के मुख्य अङ्ग निम्न-लिखित हैं—

(१) देशी बैंकर या महाजन, सर्राफ, साहूकार आदि (Indigenous Bankers) ।

(२) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

(३) विनिमय बैंक (Exchange Banks)

(४) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India)

(५) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

(६) ग्रन्थ बैंकिंग संस्थाएँ—(अ) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)

(आ) भूमि ऋण बैंक (Land Mortgage Banks), (इ) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks), (ई) डाकघर के बचत बैंक (Postal Savings Banks) आदि

(१) देशी बैंकर (Indigenous Bankers)

परिचय—भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही रुपये के लेन-देन का कार्य भला भा रहा है। वैदिक युग में भारतवर्ष की देशी प्रथा की बँकिंग प्रणाली मुचर रूप से चलाती थी। मनु की 'मनुस्मृति' तथा चाणक्य के 'ग्रन्थशास्त्र' में रुपये उधार देने व लेने तथा एक देश की मुद्राओं को दूसरे देश की मुद्राओं में परिवर्तित करने का उल्लेख मिलता है। इस्लामी शासन के समय इस प्रथा का कुछ ठेस लगी थी, किन्तु फिर भी सेठों का बैंकिंग कार्य उत्पत्ति पर था। राणा प्रताप के इतिहास में भामासाहू का नाम देशी बँकरो की नामावली में मका प्रकर रहेगा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में सेठ धमीचन्द, जगत मेठ आदि नाम इन बात के प्रमाण हैं कि देश में बैंकिंग कार्य उत्पत्ति पर था। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में बैंकिंग कार्य बड़ी उन्नत दशा में था।

देशी बैंकरो के विविध नाम—देशी बैंकर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये महाजन, बगिया, कोटी वाले, सेठ-साहूकार तथा चौहरे आदि के नाम से पुकारे जाते हैं। बंगाल में मारबाजी, मुत्तानी व सर्राफ कहलते हैं। पंजाब के शरी और खरोरा भी यही काम करते हैं। बंगाल में ये सेठ, बगिया व निधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। चत्तस में इन्हें बेट्टी और धुनरात व सिध में इन्हें टेहरी तथा मुन्तानी कहते हैं। साहूरो में ये प्रायः सर्राफ कहलते हैं और आंध्र में महाजन, मेठ, साहूकार। गहल बाँवो और बस्वों में गडान और बाबुली भी गह धन्धा करते हुए दृष्टिगोचर होने परन्तु आजकल ऐसा देखने में नहीं आता।

देशी बैंकर तथा साहूकार व महाजन आदि का अन्तर

(Difference between Indigenous Banker & Money Lender)

(१) देशी बैंकर प्रायः रुपया भी उगा करते हैं तथा दृष्टियों का लेन-देन भी करते हैं, परन्तु साहूकार इस प्रकार का बैंकिंग-कार्य बहुत कम करते हैं।

(२) देशी बैंकर व्यापार व उद्योग को अर्थ-सहायता देते हैं, परन्तु महाजन व साहूकार लाभ विशेषतया देशीयों व बस्वों में उपयोग के लिये रख देते हैं।

(३) देशी बैंकर आसुर देश समग्र इस तरह का अधिक ध्यान रखते हैं कि स्थल किस काम के लिये लिया जा रहा है, किन्तु महाजन इस बात की पूछ-ताछ बहुत कम करते हैं।

(४) देशी बैंकर महाजनों व साहूकारों की अपेक्षा ज्यादा भी कम सेठे हैं।

देशी बैंकों के कार्य (Functions)—(१) देशी बैंकों का मुख्य कार्य रपया उधार देना है। वे जेवर व जमीन गिरवी रख कर, प्रॉमिसरी नोट तथा कभी-कभी मोलिक बायदों पर रपया उधार देते हैं। गाँवों में निर्पन किसानों और छोटे-छोटे फ़ारीगरो को जमानत के अभाव में उनकी वैयक्तिक साध पर भी वे रपया उधार देते हैं। प्रायः इन्हें अधिक जोसिम उठानी पड़ती है, इसलिये इनकी व्याज-दर भी ऊँची होती है। (२) वे हुण्डियों के तय-विकय का काम करते हैं तथा हुण्डियों के साख पर अन्य बैंकों से भी उधार लेते हैं। वे लोग हुण्डियों द्वारा देश के भीतरी व्यापार को सहायता प्रदान करते हैं। (३) वे आन्तरिक व्यापार को अर्थ-सहायता देते हैं। देशी बैंक ऐसी की वस्तुओं के व्यापार में बहुत अर्थ-सहायता देते हैं। वे कच्चे आदितिया का काम करते हैं तथा किसानों को जस दम शर्त पर देते हैं कि वे अपनी समस्त उपज उन्ही के द्वारा बेचेंगे। (४) रपये के लेन-देन के प्रतिरिक्त वे व्यापारी भी करते हैं। वे गात खरीदने और बेचते हैं। इसलिये बैंक सम्बन्धी कार्यों के माय-साय व्यापार करना भी इनका कार्य है। (५) उनमें से कुछ रपये भी जमा करते हैं और उस पर थोडा व्याज भी देते हैं, किन्तु अधिकार ऐसा नहीं करते। (६) वे लोग सट्टा भी खेलते हैं। वे लोग सोने, चाँदी, कपास, अनाज और कम्पनियों के शेयरों को बेचने का सट्टा भी करते हैं।

देशी महाजगों व साहूकारों को यद्यपि हथ बैंकर कह कर पुकारते हैं, परन्तु वे पूर्णरूप से बैंकर नहीं बहे जा सकते। एक बैंकर का कार्य रपया उधार लेना व देना हीनी है, जबकि भारतीय साहूकार व महाजन प्रायः रपया उधार ही देने हैं उधार लेते नहीं। अस्तु, बैंकर के बजाय श्रणदाता (Money Lenders) या अर्थ-प्रवन्धक कहल जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

देशी बैंकों और आधुनिक बैंकों में भेद

(Difference between Indigenous Bankers & Modern Banks)

देशी बैंकर	आधुनिक बैंक
(१) देशी बैंकों की धर्मों का संगठन प्रायः पारिवारिक व्यवसाय के सिद्धान्त पर आधारित होता है।	(१) आधुनिक बैंक निश्चित पूँजी वाली कम्पनियों के सिद्धान्त पर संगठित किये जाते हैं।
(२) इनमें से बहुत थोड़े बैंकर दूसरों का रपया जमा करते हैं। वे अपनी ही पूँजी से काम करते हैं।	(२) रपया जमा करना इनका मुख्य कार्य होता है। अपनी पूँजी से यह रपया बड़ी गुना अधिक होता है।
(३) इनमें से जो कोई भी रपया जमा करते हैं वे रपया जमा करने की रसीद नहीं देते, बल्कि अपने बहीखाता में उगका जमा-खर्च कर लेते हैं।	(३) वे बिना रसीद के किय प्रकार का रपया जमा नहीं करते।

- (४) इनमें से कृषि या खानदान के रूप में निकाला जाता है ।
- (५) य कृषि या खानदान के रूप में उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के लोगों के लिए देते हैं ।
- (६) दशा वरकर प्रायः बैंकिंग के साथ-साथ व्यापार और सट्टा भी करते हैं ।
- (७) देशी बैंकरों की रजिस्ट्री किसी कानून के अन्तर्गत नहीं होती और न उनके कार्य कानून द्वारा नियन्त्रित होते हैं ।
- (८) देशी बैंकर अधिकतर कृषि या खानदान के रूप में उत्पन्न जमानत के उपार देते हैं । अतः उनको बहुत जोखिम उठानी पड़ती है ।
- (९) इनका अधिकतर कार्य-क्षेत्र गाँव और कस्बा में होता है ।
- (१०) इनकी सख्या बहुत अधिक है और वे देश के कोने-कोने में व्याप्त होते हैं ।
- (११) इनको वन-मुद्रा जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता है ।
- (१२) इनकी शाखाएँ नहीं होती । यदि हुई तो थोड़ी सख्या में होती है ।
- (१३) देशी बैंकर अपने हिसाब-किताब की न तो नियमित रूप से जाँच (Audit) करवाते हैं और न उसका प्रकाशन ही करते हैं ।
- (१४) इनकी व्याज दर ऊँची होती है ।
- (४) इनमें से कृषि या खानदान द्वारा निकाला जाता है ।
- (५) इनके द्वारा कुछ केवल उत्पादक लोगों के लिये ही दिया जाता है ।
- (६) प्राधुनिक बैंक बैंकिंग के साथ और कोई दूसरा व्यापार नहीं करते ।
- (७) बहुत पूर्ण जाने बैंकों की रजिस्ट्री पहले कम्पनी कानून के अन्तर्गत होती थी, परन्तु सन् १९४६ में अलग बैंकिंग कानून पास हो जाने के बाद उसके अन्तर्गत बैंकों की रजिस्ट्री होनी है ।
- (८) प्राधुनिक बैंक अधिक जमानत पर ही कार्य देते हैं । अतः इन्हें बहुत कम जोखिम उठानी पड़ती है ।
- (९) इनका कार्य-क्षेत्र बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में होता है ।
- (१०) ये सख्या में इतने अधिक नहीं हैं और इनका प्रसार भी अधिक नहीं है ।
- (११) प्रत्येक देश में वहाँ के केन्द्रीय बैंक को वन-मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है ।
- (१२) इनकी शाखाएँ बहुत अधिक होती हैं ।
- (१३) समुक्त पूर्ण जाने प्राधुनिक बैंकों को अपने हिसाब-किताब की जाँच निरी रजिस्टर्ड ऑडिटर से करानी पड़ती है तथा उसका प्रकाशन उन्हें अनिवार्य रूप से करना पड़ता है ।
- (१४) इनकी व्याज दर निर्दिष्ट और कम होती है ।

- (१५) ये मकान आदि अचल सम्पत्ति को गिरवी रखकर दीर्घकाल के लिये रपवा उपार देते हैं ।
- (१६) ये विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (Finance) नहीं करते और न विदेशी वित्तों को डिस्काउन्ट करते हैं ।
- (१७) ये छोटे किान, छोटे धिल्पकारों तथा साधारण व्यापारियों को आण देते हैं ।
- (१८) देशी बैंकरो का कार्य सीपा-सावा पुराने ढंग से होता है जिसको प्रत्येक व्यक्ति सरसता से समझ सकता है । आवश्यकतानुसार एक या दो मुनीम इस कार्य के लिये रख दिये जाते हैं जिनमे कार्य-संचालन में बड़ी मितव्ययता होती है ।
- (१९) देशी बैंकरो के कार्यालय में प्राधुनिक पर्जोचर का अभाव होता है तथा प्रायः गढ़े तकिये ही काम में लाये जाते हैं । उनके काम करने के घण्टे निर्दिष्ट नहीं होते । वे दिन-रात फिती भी समय आण दे देते हैं ।
- (२०) ये देश के केन्द्रीय बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की देख-रेख में काम नहीं करते बल्कि ये अपने कार्य-संचालन में स्वतन्त्र हैं । रिजर्व बैंक उन्हें कोई नाम प्रदान नहीं करता है ।
- (१५) ये अधिकतर तरल सम्पत्ति अर्थात् ऐसी सम्पत्ति जिसका पुरा रपवा सुस्त प्राप्त किया जा सके गिरवी रखकर अल्पकाल के लिये रपवा उपार देते हैं ।
- (१६) प्राधुनिक व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन करते हैं तथा विदेशी वित्तों को डिस्काउन्ट भी करते हैं ।
- (१७) ये बड़ी-बड़ी कम्पनियों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये अर्थ-प्रबन्धन करते हैं ।
- (१८) प्राधुनिक बैंकों का कार्यालय बड़ा होता है जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते हैं । इनके कामों को समझने के लिये विशेष ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता होती है । इनका कार्य जर्जला होता है ।
- (१९) प्राधुनिक बैंकों के कार्यालय प्राधुनिक पर्जोचर में सुसज्जित होते हैं । इनके काम शरों के घण्टे निर्दिष्ट होते हैं ।
- (२०) प्राधुनिक बैंकों को रिजर्व बैंक से सम्बन्ध स्थापित कर उसकी देख-रेख में काम करना पड़ता है । जिससे उन्हें सबसे फलितम लाभ भी प्राप्त होते हैं ।

देशी बैंकरो तथा साहूकारों का महत्त्व (गुण) — देशी बैंकर तथा साहूकार या महाजत भारतीय आर्थिक मण्डल के आधार हैं । इनकी सख्या लगभग ३ लाख है जो देश में सर्वत्र स्थित है । वे देश के वृत्त व्यापार के एक बहुत बड़े भाग को अधिक सहायता पहुँचाते हैं । व्यापार के अतिरिक्त बेटी तथा छोटे-छोटे उद्योगों की भी उनके द्वारा पर्याप्त सहायता मिलती है । गाँवों में बैंक न होने के कारण बेटी तथा छोटे-छोटे उद्योगों की आर्थिक सहायता केवल एकमात्र साधन महानन लोग

हैं। यदि ग्राम उनको गाँवा में से हटा दिया जाये, तो सेती और उद्योग-धन्ये विलुप्त होपट हो जायें। ग्रामीण साहूकार और देशी बैंकर ग्रामीण आर्थिक संगठन के परमादेशक अंग हैं। वे क्रिमान को सकृद-काल में, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि अवसरों पर, दौल तथा सेती के उपकरण खरीदने के लिये बिना पर्याप्त मात्रा में जमानत के पूँजी का प्रयत्न करते हैं। उम्मीद करता है कि वे विपरीत करते हैं, और उससे लिये आवश्यक वस्तुओं का सहाय करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण महाजन भारतीय कृषक का मित्र, सहायक तथा पथ प्रदर्शक होता है। यही नहीं, कस्बा और नगरी में देशी बैंक छापे छापे शिल्पकारों तथा बुटीर घन्टा की पूँजी देते हैं, उनको नक़्का मात देवते हैं और उनके लिये मात की विक्री करते हैं। उनमें से बहुत से जमा भी करते हैं, कृषि भी सिताते हैं और व्यापार के लिये भी पूँजी उधार देते हैं। ग्रामीण ऋण का रकम ₹२०० करोड़ रुपया के नवभण्ड है और उन्का आर्थिक शक्ति देने वाली सहकारी साज समितियों की कुल पूँजी ३३ करोड़ रुपय है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण साहूकार के साथ ही बात सोचना असंभव सिद्ध होती है।

इनके प्रतिरिक्त देशी बैंकरों की कार्य-प्रणाली इतनी सरल तथा बोधगम्य है कि प्रत्येक व्यक्ति भी उसे सुगमता से समझ लेता है। उन्का व्यवसाय भी परिष्कृत होता है और वे अप्रत्यक्ष जमानत पर या बिना जमानत के भी ऋण दे देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऋण किसी भी समय दिया जा सकता है। आधुनिक बैंकों की भाँति अधिक लागू की जायगी नहीं की जाती। अब ग्रामीण जनता के लिये इनकी उपयोगिता अत्यधिक है और वे ही उससे अर्थ-प्रवर्धन के एकमात्र साधन हैं। ग्राम बैंकिंग ऑफ़ कमेटी १९४० (Rural Banking Enquiry Committee) ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देशी बैंक तथा महाजन गाँव में साज प्रदान करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखते हैं।

उनके दोष—देशी बैंकरों तथा साहूकारों का इतना महत्व होने हुए भी उनके दोषों की उल्लेख नहीं की जा सकती। (१) देशी बैंकर एवं साहूकार अपनी सेवाओं के लिये जो मूल्य वसूल करते हैं वह अत्यधिक और घातक है। २४%, ३६%, ४८% वार्षिक तो व्याज की साधारण दर है। ३००%, ४००% वार्षिक व्याज भी वसूल किया जाता है। (२) वे शिक्षा-पढ़ी में भी बेईमानी कर लेते हैं। १०० रु० देकर २०० रु० का रुका लिखवाना तो साधारण कार्य है। प्रायः ऋणों का दिया हुआ रुपया उसके हाथों में जमा नहीं किया जाता और उसके ऊपर नावित करने अनुचित और अन्यायपूर्ण वसूली की जाती है। ऋण देने समय प्रायः एक मास का व्याज और इतनी और रुपयों कसर की रकम तो मूल में से काट ली जाती है। ऋणियों के बहुतों लंगवाकर अधिक रकम लिख लेना, खाता खुलाई, नजराना, वेवार लेना आदि बुराईयों के कारण वे नष्ट बदनाम हैं। इस प्रकार महाजन किसानों का बुरा तरह शोषण करते हैं। किसानों को अधिक ऋण देकर वे उन्हें आत्म-दास बना लेते हैं। ऋण मिलने का धन्य साधनों के धाव में किसान दूर भागकर बही जाता है। कुछ स्थानों में सहकारी बैंक भी खुल गये हैं, परन्तु वहाँ पर इतनी अधिक लिखा पड़ी होती है और रुपया मिलने में इतनी कठिनाई होती है कि किसान को गाँव में महाजन से ही रुपया उधार लेना पड़ता जान पड़ता है। (३) उपभोग करने के लिये भी वे रुपया उधार देते हैं जिससे लोगों में मितव्ययता नहीं हो पाती। (४) रुपये उधार देने तथा जमा करने के प्रतिरिक्त वे व्यापार भी करते हैं और जैन-जैन को पूँजी तथा व्यापार की रकम को रुपय नहीं

रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यापार में अचानक परिवर्तन से वे सफट-प्रस्त हो जाते हैं। (५) वे अपना हिसाब न तो भत्ती-भौति लिखते हैं और न ही प्रामाणिक ऑडिटर से उसकी जाँच कराते हैं। वे अपना बिन्डा (Balance Sheet) प्रकाशित नहीं करते हैं, अतएव उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगता है। इससे उनकी केन्द्रीय बैंक भी सहायता नहीं दे सकना तथा उनकी हूँदियाँ, बैंक भाँदि भुनाने में बड़ी शक्तिशाली होती है। उनकी आर्थिक स्थिति से अपरिचित होने के कारण चलना उनसे पाय स्वयं जमा करने में भी सकोन करती है।

देशी बैंकरो तथा साहूकारों के सुधार के सुझाव—देशी बैंकिंग तथा साहू-कारों प्रथा में बहुत से दोष हैं। फिर भी बिना किसी दूसरी व्यवस्था के इनका भग्न कर देने से भारतीय कृषि तथा कुटीर उद्योगों को बड़ी आर्थिक हानि पहुँचगी। इसलिये हमने कार्यप्रणाली में सुधार करना ही लाभदायक सिद्ध होगा। यह निम्नलिखित सुझावों द्वारा किया जा सकता है।—

(१) देशी बैंकरो तथा महाजना व साहूबारा को जमा पर रुपये प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे उनकी पूँजी में वृद्धि हो और लोगों में सवय-शीलता की प्राप्ति पड़े।

(२) उन्हें रामभाकर तथा कानून द्वारा उचित व्याज दर लेने के लिये बाध्य किया जाय। सहकारी माव्य समितियों को सख्या में वृद्धि करने से व्याज की दर घट सकेगी। कई राज्यों में ऐसे कानून पास हो चुके हैं जो प्रत्यक्षान् इन् वरा का निपटारा करने हैं।

(३) देशी बैंकरो तथा महाजना को समुचित ढङ्ग से नियमित हिसाब रखने के लिये बाध्य किया जाय और प्रामाणिक ऑडिटरों से उनकी जाँच कराई जाय।

(४) उन्हें व्यापारिक कारोबार की महाजनी वगैरों से अलग करने के लिये बाध्य किया जाय।

(५) उन्हें बिना हूँदियाँ स्फुराने के कार्य में प्रोत्साहित किया जाय और सट्टेबाजी तथा विभिन्न व्यापार करने से रोक जाय।

(६) देशी बैंकरो को अपना चिट्ठा और लाभ हानि लेखा प्रकाशित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय जिससे जनता का विश्वास बढ़े और सोय अपना धन उनके पास जमा कर सकें।

(७) उनका रिजर्व बैंक से सम्बन्ध होना चाहिए। जिस स्थानों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ इन्हें रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य सौंपना चाहिए।

(८) रिजर्व बैंक की स्वीकृत तालिका में उनका नाम होना चाहिए जिससे सदस्य या अनुसूचित बैंको (Scheduled Banks) की भाँति उन्हें भी सदस्य बैंक समझा जायें तथा हूँदियों की पुनःकीर्ती व अन्य बैंकिंग सुविधाएँ दी जायें। इसके लिये उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा है तथा रिजर्व बैंक के साथ एक नियत अनुपात राशी जमा करानी पड़ेगी है।

(९) समस्त व्यापारिक बैंक जिनमें स्टेट बैंक भी सम्मिलित है, इनकी हूँदियों को स्वतन्त्रतापूर्वक भुनाने।

(१०) रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक को चाहिए कि उन्हें मुद्रा भेजने की वे समस्त सुविधाएँ दी जायें जो अन्य बैंको को दी जाती हैं।

(११) देशी बैंकरों को चाहिए कि वे अपने आपको समुक्त पूँजी वाले बैंकों या गृहकारी बैंकों में सम्मिलित कर लें जिससे वे हुण्टी का खेत-देन कर सर्वे धीरे-धीरे व्यवस्था करने पर रिजर्व बैंक में भी सहायता प्राप्त कर सकें।

(१२) जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये उन्हें आधुनिक ढंग से कार्य करना चाहिए। सरकार का भी चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहन दे।

(१३) इनमें से अनुज्ञापन-पत्र (Licensed) बैंकों के एक वर्ग का निर्माण होना चाहिए।

(१४) बैंक का एक अतिरिक्त भारतीय ऐमोनिशियल होना चाहिए जिसमें स्थानीय देशी बैंकरों को भी मध्यम बनाया जाय।

(१५) जर्मनी के बैंक का क़ोमण्डित (Commandit) सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के अन्तर्गत जो अल्पपारो बैंक के व्यवस्थापक होते हैं, उनका दायित्व प्रसीमित होता है।

रिजर्व बैंक व देशी बैंकर—केन्द्रीय बैंकिंग जॉब समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये रिजर्व बैंक ने मई १९३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका अर्थ देशी बैंकरों का रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित करने का था। देशी बैंकरों ने इन सुझावों का साधारणतया स्वागत नहीं किया। बहुत कम ऐसे थे जो निर्धारित फॉर्म के अनुसार अपने खाने तैयार करें तथा अपनी आपसी बैंकिंग कार्य तक ही सीमित रखें, यद्यपि वे इन बातों पर राजी थे कि वे सट्टाबाजी का व्यापार नहीं करेंगे। व्यावहारिक रूप से सभी बैंकर जमा व ऋण के प्रवाहों को पक्षों पर समुचित नहीं हुए। मन्त्रेय समुक्त बैठिकाई यह थी कि वे बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यापार का छोटना नहीं चाहते थे। इसके अनिश्चित, सुलझानी, गुंजायनी व भारदाही मार्गों में, जो कि उस समय अधिप्राप्त हुटिया का व्यवसाय करने व इन विषय में कोई व्यापार नहीं किया, क्योंकि उन्हें इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से पर्याप्त सहायता मिल जाती थी।

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी देशी बैंकरों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करने के प्रयत्न किये गये। बुलाई मई १९५१ में देश के सम्पूर्ण देशी बैंकों का संगठित करने व अतिरिक्त बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त भारतीय सरकारी सम्मेलन किया गया। रिजर्व बैंक भी अतिरिक्त मातृ-व्यवस्था की पूर्ण जॉब कर रहा है।

(२) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

परिचय—भारतवर्ष में अधिकांश आधुनिक बैंक व्यापारिक बैंक हैं। ये सभी समुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ (Joint Stock Companies) के सिद्धान्तों पर स्थापित होनी हैं। देशी रजिस्ट्रेशन पहल जाइए स्टॉक कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत होता था, परन्तु १६ मार्च मई १९६६ में अतिरिक्त कृषि बैंकिंग एक्ट लागू हुआ गया, बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत होने लगा। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारम्भ १८ वीं शताब्दी में अजन्मी हाउस (Agency Houses) में हुआ। परन्तु भारतवर्ष में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का वास्तविक प्रारम्भ मई १८८१ ई० में ही सम्भवतः आदि कृषि अर्थ वॉलन्टियर बैंक (Oudh Commercial Bank) की स्थापना हुई। मई १९०७ में विदेशी आन्धान

से भारतीय बैंकों को बड़ा प्रोत्साहन मिला और अनेकों बैंक स्थापित हुए । सन् १९३३ तक इस प्रकार के बैंकों का संकट काल प्रारम्भ हो गया था । प्रथम महायुद्ध के कारण बैंकों की सहायता में पुनः वृद्धि हुई, परन्तु युद्ध समाप्त होते ही फिर बैंकों का वन्द होना प्रारम्भ हो गया । सन् १९२९ के आर्थिक संकट के कारण अनेकों बैंकों ने काम स्थगित कर दिया । सन् १९३१ से १९३६ के बीच लगभग २४० बैंक वन्द हो गए । सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध के खिड़ जाने से बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ और कई नये बैंक भी खुले ।

गत वर्षों में बैंकों के असफल (फेल) होने के कारण—(१) कानून की विधिवलता, जनता की प्रशानता, और प्रबन्ध की दुर्बलस्था, (२) अनुभवहीन ईमानदार कामचारियों का प्रभाव, (३) हिसाब-किताब में गोलमाल, (४) सट्टेबाजी (५) दीर्घ कालीन ऋणों में पूँजी को फँसाना, (६) पूँजी की कमी, (७) दूरगोच्य सरक्षित कोष, (८) प्रतिभूल जनमत, (९) केन्द्रीय बैंक की आर्थिक सहायता का प्रभाव, (१०) विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा ।

सफलतापूर्वक कार्य करने वाले कुछ आधुनिक व्यापारिक बैंक—प्राज कल निम्नांकित बड़े बैंक भारत में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं—(१) स्टेट बैंक, (२) सेंट्रल बैंक लि०, (३) पंजाब नेशनल बैंक, (४) इलाहाबाद बैंक, (५) बड़ोदा बैंक, (६) द्रोक बैंक इण्डिया, (७) मैसूर बैंक, (८) गुजराट बैंक, (९) बैंक ऑफ़ जयपुर आदि । इलाहाबाद बैंक का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में है, क्योंकि पी० एण्ड थो० बैंकिंग कॉरपोरेशन ने इसे खरीद लिया, और शेष सब बैंक स्वदेशी हैं । सन् १९२२ में सदस्य एवं असदस्य बैंकों की संख्या ५१७ और उनकी साक्षार्प ३,६०० थी ।

आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय समुक्त पूँजी वाले बैंकों की आवश्यकता—आधुनिक बैंकों का देश में अभी इतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिये । देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि में इन बैंकों की संख्या बहुत कम है । भारत में लगभग छह लाख मनुष्यों के पीछे एक बैंक है जबकि इंग्लैंड में चार हजार मनुष्यों के पीछे एक है । इसका अतिरिक्त, ये बैंक सहारा तथा व्यापारिक केन्द्री में ही अधिकतर स्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्र अभी व्यापारिक बैंकों की सेवाओं में वंचित है । अतः देश के व्यापार और उद्योग धन्यो को प्रोत्साहित देने के लिये यह आवश्यक है कि बैंकों का विस्तार अधिकतम किया जाय ।

व्यापारिक बैंकों के कार्य—इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—(१) आधुनिक बैंक स्थायी जमा खातों (Fixed Deposit A/cs), चालू खातों (Current A/cs), बचत खातों (Savings Bank A/cs), तथा घरेंतू बचत खाता (Home Safe A/cos) में जनता का स्वयं जमा करते हैं । (२) ये व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि को छोटे समय के लिये प्रप्तानी से बिक जाने वाली जमानत, जैसे—दोपट्टा, सोना, चाँदी, जेवर आदि के आधार पर या देशी बिल, हुण्डी की जमानत पर स्वयं उधार देते हैं । उद्योगों की कार्यशील पूँजी (Working Capital) का प्रबन्ध भी करते हैं । ये अपनी अल्पकालीन जमा की गई पूँजी को दीर्घकालीन ऋण में नहीं पँमाने, क्योंकि वे अपने धन को अधिकतर तरल (Liquid) अर्थात् नकदी में शीघ्र परिवर्तनीय

अवस्था में रहते हैं। नाविकों के मॉर्गने पर अपने अधिवासीओं को तत्काल रखा दे गये। व्यापारिकता के दृष्टि की आर्थिक सह्यता के लिये रखा नहीं देते। (३) वे देश के भीतरी व्यापार के लिये ग्रंथालयन करते हैं। वे व्यापारिक विल तथा ट्रिडिंग मुदान हैं। (४) वे यानों के लिये साख-पत्र आदि जारी करते हैं। (५) वे एक स्थान में दूसरे स्थान को रखा भेजते हैं, तथा अपने ग्राहकों की राय समूल करते हैं, तथा उनमें व्यवस्था चुकाते हैं। (६) वे अपने ग्राहकों के बैंक, ट्रिडिंग विल आदि का रखा इष्टुत करते हैं। (७) वे अपने ग्राहकों की ओर में समोशन पर शेयर या अन्य निवेशियों की खरीद और बिक्री करते हैं। (८) वे अपने ग्राहकों के जेवर, दातानेज तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सुरक्षित रखते हैं। (९) वे अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त कराने में सहायता देते हैं तथा अपने ग्राहकों की आर्थिक दशा का ज्ञान भी दूसरों को कराते हैं। (१०) वे ट्रस्टीज (Trustees), अटार्नी (Attorney) तथा एग्जीक्यूटिव (Executors) आदि की भी अपने ग्राहकों के लिये कार्य करते हैं।

व्यापारिक सेवा की कमियाँ और इनके दूर करने के उपाय—भारतीय व्यापारिक सेवा में सगठन और कार्य प्रणाली में घोर दुर्घटियाँ हैं, जिनका दूर होना परमावश्यक है। (१) बहुत से बैंकों की प्रगत पूर्णता बहुत सीधी होती है। इनका धन मन्त्रालय तथा अन्य व्यक्तियों व्यवसायों में लगा देते हैं, और ग्राहकों को बैंक की वास्तविक स्थिति में प्रत्यक्ष नहीं रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इनमें से बहुत से बैंक बंद हो जाते हैं। (२) एमार देश में व्यक्तिगत नाम पर बैंक स्थापित नहीं होते हैं। ऊँची सख्त बांधे व्यवस्था का व्यक्तिगत नाम पर अवश्य उपर निर्भर चाहिए। इस कार्य की अधिक क्षमता करने लिये भारत में इन्वेंस्ट की सिस्टम (Syed's), तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की डून (Dun's) और ब्रैड स्ट्रीट (Brad Street) जैसी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना देने वाली संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। (३) भारत में स्थित आनुमिक बैंक भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं बल्कि वे विदेशी बैंकों की नकलमान हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंकों का सगठन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो जिससे अधिक लाभ पहुँच सके। (४) भारतीय बैंकों का बिल डिस्काउन्ट की ओर कम जान है। इस उदासीनता के कारण भारत में बिल-ब्याजार्थ विकसित नहीं है। अतः इन बैंकों द्वारा अधिक-अधिक बिल डिस्काउन्टिंग को मुद्रित हो जाना चाहिए जिसमें बिल अधिक लोकप्रिय बन सकें। (५) भारतीय बैंकों में प्रत्यक्ष संचालन तथा अन्य अधिकारीय प्रायः योग्य अनुभवों, ईमानदारी तथा बुद्धिमान नहीं हैं जिससे बैंकों में जनता का विश्वास कम है। इसलिये जनता का बैंकों में हृदयिकता कायम रखने के लिये योग्य, कुशल एवं ईमानदार संचालन की आवश्यकता है। (६) प्रथम महायुद्ध के पूर्व तथा उपरान्त के वर्षों में अनेक भारतीय बैंक बंद हुए, जिनमें कारण जनता का बैंकों के प्रति विश्वास हट गया। द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में बैंकों की संस्थाओं तथा उनकी जमाओं में वृद्धि हुई, उसमें जनता का विश्वास फिर से बैंकों में जग गया मान्य होता है। (७) बैंक अधिकतर नगरी तथा बड़े शहरों में ही स्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्र इनसे वंचित हैं। इसलिये देश के प्रत्येक कोने में इनका प्रसार होना आवश्यक है। भारतीय ग्रामीण बैंकिंग जॉर्ज बनेटी १९३० की विचारों के अनुसार इन्हें ग्रामीण जनता में भी बैंकिंग पद्धति के प्रति जाग्रति पैदा करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों में वेबार् बढ़ी हुई एक विशाल धन-राशि राष्ट्र के नव निर्माण में काम आ सके। इन्ट्रिज्वे बैंक के कृपि-मास

विभाग की सहायता से ग्रामी में नई-नई शाखाएँ स्थापित करनी चाहिये। (८) बैंको में प्रान्त में प्रतिभोगिता है, जिसके कारण वे लाभ का एक बड़ा भाग साभास अर्थात् ट्रिदिष्ट के रूप में बाँट देते हैं। बैंको की प्रतिभोगिता को कम करने के लिये केन्द्रीय बैंकिंग आच कमेटी तथा विदेशी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि हम देश में 'एक प्रतिल भारतीय बैंक राश' होना चाहिये जोकि प्रतिभोगिता को कम करने का प्रयत्न करे। (९) भारत में अचल सम्पत्ति के कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके कारण व्यापारिक बैंक उनमें अपना रूपया नहीं लगा सकते। अतः भारत सरकार को हिन्दू तथा मुसलमानों के पंतुक सम्पत्ति के उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानून को उसका को दूर करना चाहिये तथा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमों में सुधार करना चाहिये ताकि बैंक इनके साधारण पर खर्च दे सकें। (१०) भारत के बैंको की विशेष प्रगति न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि ये बैंक अपना समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में करते हैं। उनके बैंक, बिल, साख-पत्र, रसीदें तथा हिसाब अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जिन्हें साधारण भारतीय समझ नहीं पाते हैं। अतः इन्हें अंग्रेजी के स्थान पर अधिकतर हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में कार्य करना चाहिये। (११) इनका संचालन-व्यय बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह स्टेट बैंक जैसा यडिया कर्नलर तथा अन्य सामान रखते हैं। अतः इन्हें अपने कार्य में बहुत मितव्ययता में काम लेना चाहिये। (१२) लोगों में बैंकिंग-प्रादत नहीं है। बहुत कम लोग बैंक का उपयोग करते हैं। लोगों में हमरा जोड़कर जमीन के भीतर गाड़ने की या देवर में मयान की यही प्रवृत्ति है। अतः बैंको को चाहिये कि वे अपनी सेवाओं को अधिक आकर्षित बना कर तथा लोगों को अधिक सुविधाएँ देकर उनमें बैंकिंग प्रादत पैदा करें। (१३) भारतीय बैंको को स्टेट बैंक से प्रतिभोगिता करनी पडती है। इनकी तुलना में स्टेट बैंक की स्थिति कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें सरकारी एवं प्रद-सरकारी सत्त्वामों की रमन क्षिा अत्यन्त के जमा रहती है। अतः सरकारी एवं प्रद-सरकारी सत्त्वामों को चाहिये कि वे व्यापारिक बैंको को भी अपनावे। (१४) भारतीय नये बैंको को विकास गृह (Clearing House) के सदस्य बनने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इन विकास-गृहों पर विदेशी बैंको का बहुत प्रभाव है और वे इन नये बैंको को उनका सदस्य बनने में बहुत अडक्ल डालते हैं। परन्तु रिजर्व बैंक के सरक्षण में यह कठिनाई भी प्रब धीरे-धीरे दूर हो जावेगी। (१५) सरकारों को चाहिये कि वे व्यापारिक बैंको के साथ ही सभी प्रकार की नर्म नीति का व्यवहार करें जिस प्रकार कि वे सहकारी बैंको के साथ करती हैं। (१६) विदेशी विनियम बैंको की प्रविडिडिता भी प्राधुनिक व्यापारिक बैंको की उत्पत्ति से स्कायड है। इनका कार्य बन्दरगाहों तक ही सीमित होना चाहिये और इनके द्वारा किये जाने वाले भीतरी साधारण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। जनता में इस बात का प्रचार किया जाये कि यह भारतीय बैंको को अपनाये। (१७) भारत का अधिकतर व्यापार विदेशियों के हाथ में रहने के कारण भारतीय व्यापारिक बैंको को अधिक कार्य नहीं मिलता था, क्योंकि लोग विदेशी बैंको से अपना सम्बन्ध रखते थे, जिससे उन्हें विदेशी बैंको, बोमा कम्पनियों, दलानों तथा जहाजी कम्पनियों से विशेष सुविधायें मिलनी थी। अब हमारी राष्ट्रीय सरकार को ये सब बातें देखनी चाहिये। (१८) प्रच्छे माल गोदामों के प्रभाव में बैंको को माल के ऊपर खर्च देने में कठिनाई होती है। अतः माल गोदामों की सुविधाओं के विकास के लिये एक वेयरहाउसिंग विभाग मण्डल (Warehousing Development Board) स्थापित किया जाय जिसमें केन्द्रिय सरकार, राज्य

सरकार व रिजर्व बैंक पूँजी लगायें। भारत में वित्त बाजार की स्थापना व विकास के लिये यह आवश्यक है।

रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का सम्बन्ध—इन बैंकों का सम्बन्ध रिजर्व बैंक ऐक्ट १९३४ तथा भारतीय बैंकिंग ऐक्ट १९४६ द्वारा निर्धारित होता है। इनके प्रनुसार व्यापारिक बैंकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में व गगनत राक्षस्य तथा असदस्य बैंक (Scheduled & Non-Scheduled Banks) हैं जिनकी प्रदत्त पूँजी (Paid-up Capital) तथा संचित कोष (Reserve fund) पाँच लाख रुपये से अधिक है। द्वितीय श्रेणी में वे समस्त समस्य बैंक हैं जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष एक लाख रुपये से अधिक और पाँच लाख रुपये से कम है। तृतीय श्रेणी उन बैंकों की है जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष पचास हजार से अधिक तथा एक लाख रुपये से कम है। चतुर्थ श्रेणी में वे बैंक होते हैं जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष पचास हजार से कम है। सन् १९३६ के बाब ५० हजार से कम पूँजी वाले बैंकों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रत्येक सदस्य बैंक का अपनी माँग देनदारियाँ (Demand Liabilities) का ५% तथा मुदती देनदारियाँ (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है तथा उन्हें प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक के पास अपनी बिल्ड (Balance Sheet) भेजना पड़ता है और उसमें न भेजने पर बड़े दण्ड का भागी होता है। इन बातों के चलते रिजर्व बैंक अपने सदस्य-बैंकों को सबोट के समय उधार देता है, उनका रुपया निगूँव या कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, उन्हें वित्तों की पुन बँटीती करता है, उनको परामर्श देता है तथा उन्हें प्रत्येक सुविधाएँ भी देता है। प्रत्येक बैंक को भी रिजर्व बैंक कुछ प्रकस्यामा में सुविधाएँ देता है।

गर्नु सन् १९४६ के नये बैंकिंग विधान के अनुसार रिजर्व बैंक को भारत के सब बैंकों का हर प्रकार का नियन्त्रण करने का अधिकार मिल गया है। अब रिजर्व बैंक के प्रनुज्ञा-पत्र (License) के बिना कोई भी बैंक बैंकिंग-कार्य नहीं कर सकता। उसकी अनुमति बिना कोई भी बैंक नई शाखा नहीं खोल सकता। इस ऐक्ट द्वारा रिजर्व बैंक को इन बैंकों का निरीक्षण, एकीकरण तथा विलीनीकरण करने तथा करवाने का पूरा-पूरा अधिकार दे दिया गया है। रिजर्व बैंक समस्त बैंकों को आर्थिक मदद के समय सलाह तथा सहायता भी दे सकेगा। इस प्रकार रिजर्व बैंक अब देश के समस्त बैंकों का निरीक्षक, प्रबन्धक, नियन्त्रणकर्ता तथा सरक्षक हो गया है।

विनिमय बैंक (Exchange Banks)

परिचय—भारतवर्ष में धर्मशास्त्र राज्य की स्थापना से ही विदेशी विनिमय बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ। विदेशी विनिमय बैंक वास्तव में व्यापारिक बैंक हैं जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं तथा उनकी शाखाएँ भारत में विद्यमान हैं। ये शाखाएँ अधिकतर भारतीय खन्दरगाहों तथा उन मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित हैं जहाँ से आयात निर्यात का व्यापार अधिक होता है। इन विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता तथा विनिमय की सुविधा प्रदान करना है, परन्तु वर्तमान काल में इन बैंकों ने अपनी शाखाएँ देश के आन्तरिक भागों में भी स्थापित कर ली हैं और अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति साधारण बैंकिंग-कार्य भी कर ली हैं। इस प्रकार ये भारतीय व्यापारिक बैंकों से बहुत अधिक प्रतियोगिता करते हैं और उनकी

उन्नति और विस्तार में बाधा डालते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश में कार्य करने वाले सभी विनिमय बैंक विदेशी हैं। जो दो-एक देशी विनिमय बैंक स्थापित किये गये वे विदेशी विनिमय बैंकों की प्रबल स्पर्धा और कठोर व्यवहार के कारण शीघ्र अवस्था में ही बंद गये।

भारत में प्रमुख विनिमय बैंक—वर्तमान समय में भारत में घनेका विदेशी विनिमय बैंक है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :—

(१) भारत, आस्ट्रेलिया तथा चीन का चार्टर्ड बैंक, (२) ईस्टर्न बैंक लि०, (३) हांगकौंग तथा शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, (४) भारत का मर्केन्टाइल बैंक, (५) भारत का नेशनल बैंक लि०, (६) टोमस कुक एण्ड सन्स, (७) साँचइस बैंक लि०, (८) प्रिन्सले एण्ड कम्पनी लि०, (९) नेदरलैंड ट्रेडिंग सोसाइटी, (१०) नोदरलैंड का इण्डिया कॉमर्शियल बैंक लि०, (११) न्यूयॉर्क का नेशनल सिटी बैंक, (१२) अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, (१३) बैंको नेशनल अल्ट्रामेरिनो, (१४) पेरिस बैंक, (१५) चीन का बैंक। प्रायः कल देश में १५ विनिमय बैंक कार्य कर रहे हैं, जिनकी ८० से अधिक शाखाएँ हैं।

विनिमय बैंकों के कार्य—इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता देना—जिस प्रकार व्यापारिक बैंक देश के आन्तरिक व्यापार के प्रत्यक्षानीन ऋण की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार विनिमय बैंक विदेशी व्यापार के लिये अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। ये बैंक भारतीय निर्याताओं द्वारा जारी किये गये निर्यात बिल खरीदते, उनको डिस्काउन्ट करते, तथा विदेश में भारतीय व्यापारी को पान खरीदते हैं—उनमें उन पर जारी किये हुये बिलों का निश्चिन समय पर रुपया वसूल करते हैं। इस प्रकार ये देश के विदेशी व्यापार प्रवाह आयात निर्यात व्यापार में सहायता पहुँचाते हैं।

(२) आन्तरिक व्यापार में आर्थिक सहायता देना—विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार की ही आर्थिक सहायता नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि आन्तरिक व्यापार की भी आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। इस कार्य को मुद्रास्वरूप में करने के लिये इन बैंकों ने देश के आन्तरिक भागों में अपनी शाखाएँ स्थापित कर ली हैं तथा कुछ भारतीय बैंकों की अपने अधिकार में कर लिया है।

(३) सोने-चाँदी का क्रय-विक्रय करना—आयात-निर्यात को आर्थिक सहायता पहुँचाते के अतिरिक्त वे सोना चाँदी खरीदते और बेचते हैं तथा उनका आभाव व निर्यात भी करते हैं। यह महापुद्ग में इनका यह कार्य सीमित हो गया, क्योंकि यह कार्य रिजर्व बैंक को दे दिया गया।

(४) विदेशी विनिमय बिलों, बैंक ड्राफ्ट, तथा तार द्वारा राशि भेजना—विदेशी विनिमय बैंक विदेशी विनिमय बिलों, बैंक ड्राफ्ट तथा तार द्वारा विदेशों में धन भेजने का भी प्रबन्ध करते हैं।

(५) विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय करना—विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में चले गये विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय करना भी इनका एक कार्य है। जब इनके पास इस प्रकार के बिलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब ये उनको रिजर्व बैंक को बेच देते हैं।

(६) अन्य साधारण वैकिंग कार्य करना—इन सब कामों के प्रतिरिक्त विदेशी विनिमय बैंक जनता से जमा के रूप में उधार लेते हैं, व्यापारियों को ऋण देते हैं, एजेंसी कार्य करते हैं; तथा एक स्थान से दूसरे को रफ़ा भेजते हैं ।

भारतीय वैकिंग प्रणाली में विनिमय बैंकों का स्थान—विनिमय बैंक भारत में दीर्घकाल से कार्य कर रहे हैं । भारतीय वैकिंग प्रणाली में विनिमय बैंकों ने प्रभावशाली स्थान ग्रहण कर रखा है । इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता कि सन् १९५२ में इनकी जमा १७६ करोड़ रुपये थी जोकि कुल बैंक में जमा किये हुए धन की १५% थी तथा इनका लाभ ३११ करोड़ रुपये था जोकि कुल भारतीय बैंकों द्वारा कमाये हुए लाभ का लगभग ५० प्रतिशत था । भारत का कुल विदेशी व्यापार लगभग ६०० करोड़ रुपये के मूल्य का होता है । इस व्यापार का ८५% विदेशी विनिमय बैंकों के हाथ में है, केवल १५% भारतीय व्यापारिक बैंकों के हाथ में है । इस प्रकार इन विनिमय बैंकों का विदेशी व्यापार में एकाधिकार ही नहीं बल्कि व्यापारिक बैंक क्षेत्र में भी ये बैंक भारतीय संयुक्त पूँजी वाले बैंकों के वड़े से बड़े प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि इनके आर्थिक साधन बहुत प्रचुर हैं तथा इनके सुप्रबन्ध की कुशलता इनकी उन्नति का दूसरा कारण है । इसके अतिरिक्त, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में है, अतः ये न केवल अपना ही कार्य इन बैंकों को सौंपने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि अन्य व्यापारियों को भी इनके विषे प्रोत्साहन देते हैं ।

विदेशी विनिमय बैंकों के दोष—यद्यपि इनके द्वारा भारत के विदेशी व्यापार को बहुत आर्थिक सहायता मिली है, परन्तु फिर भी इनके दोषों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । विदेशी विनिमय बैंकों ने मुख्य दोष निम्नलिखित हैं ।

(१) विदेशी विनिमय बैंक राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तथा भारतीय विनिमय बैंकों को अपनी कड़ी परीक्षा के कारण बचपने ही नहीं देते । (२) विदेशी विनिमय बैंक देशी व्यापार में भी भारतीय व्यापारिक बैंकों से स्पर्धा करते हैं और उनके व्यवसाय में हानि पहुँचाते हैं । (३) ये भारतवासियों से जमा के रूप में धन एकत्रित कर उसके विदेशियों को अधिक सहायता पहुँचाते हैं तथा भारतीय पूँजी को विदेशी उद्योग व मिकोर्पोरेटोन् (प्रतिभूतियाँ) में लगाने के भी दोषी हैं । (४) ये बैंक अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति तथा मुख्य पदार्थों के कारण कम व्याज पर जमा प्राप्त कर लेते हैं इसलिए भारतीय बैंकों का भी बाध्य होकर अपनी रजानेदार धनी पड़ती है । (५) विदेशी विनिमय बैंक विदेशी व्यापारियों को अच्छी स्थिति वाले भारतीय व्यापारियों के लिये सतोषप्रद सूचना नहीं देते जबकि बहुत बराबर आर्थिक स्थिति वाले विदेशियों के लिये भारतीय व्यापारियों को अच्छी सूचना दे देते हैं । (६) भारतीय व्यापारियों के क्रोधों को ये सभी डिस्वाउन्ट करते हैं जबकि वे अपने माल का विदेशी बीमा कम्पनियों में बीमा कराते तथा विदेशी जहाजी कम्पनियों द्वारा अपने माल को भेज । इससे हमारे बीमा ग्रीड जहाजी कम्पनियाँ फल नहीं पाती । (७) भारतीय व्यापारियों को सचिन नुबिजार्न् नही देकर अपनी फलपानपूर्णां नोबि का परिचय देते हैं । (८) ये भारतवासियों का ऊँचो नोबिरियों से घबित रखते हैं । (९) दूसरे देश की मुद्राओं के लिये बैंक भारतवासियों से अनुचित एवं बहुत अधिक दर लेते हैं । (१०) भारतीय महाउत्कर्षाओं की कर्मों को बाध्य होकर सुगमन वाले विमों (D. P.

Bills) की शर्तों पर व्यापार करना पड़ता है। (११) नाश-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रथम श्रेणी के भारतीय धायात-कर्ताओं की फर्म की भी वस्तुओं के मूल्य का १० से १५ प्रतिशत तक विदेशी विनिमय बैंकों के पास जमा कराना पड़ता है जबकि मुद्राविपर फर्मों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ और विनिमय बैंक—पहले विदेशी विनिमय बैंकों पर भारतीय कानून लागू नहीं होने थे। वे रिजर्व बैंक के नियन्त्रण के बाहर थे, किन्तु अब सन् १९४६ के भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अनुसार इन बैंकों को भी अनुज्ञापत्र (License) प्राप्त करना होगा तथा रिजर्व बैंक को सामान्य विवरण (Returns) और रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इसलिये अब रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बैंकों के भारतीय बैंकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर नियन्त्रण रख सकेगा।

भारतीय विनिमय बैंक—यह रूप का विषय है कि कुछ भारतीय बैंकों ने विदेशी विनिमय व्यापार करने में विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलने में बहुत रुचि दिखाई है। सन् १९५१ के अन्त में २५ सदस्य व १२ सदस्य ऐसे भारतीय बैंक थे जिन्होंने विदेशों में क्रमशः १११ व १६ कार्यालय स्थापित किये। सदस्य बैंकों के ७६ कार्यालय पाकिस्तान में, १२ मलाया में, ८ ब्रह्मा में, ३-३ सऊदी अरब इण्डिया में तथा २-२ जापान, थाईलैंड व ब्रिटेन में थे। प्रमुख बैंकों के कार्यालय केवल पाकिस्तान तक ही सीमित थे। केंद्रीय बैंक के बाद सबसे अधिक विदेशी कार्यालय (३०) इम्पीरियल बैंक के ही थे। अगस्त सन् १९५२ के अन्त में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की कुल देनदारो १०१ करोड़ रुपए थी, जिसमें से ७४ प्रतिशत जमा की राशि है। इस प्रकार भारतीय समुक्त पूँजी वाले बैंक विदेशी व्यापार में अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(State Bank of India)

परिचय—भारतीय बैंकिंग इतिहास में स्टेट बैंक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहले पहल इसकी स्थापना भारत सरकार ने सन् १९२० में एम्बर्डी ब्रिगाम-और मद्रास के तीनों प्रेसिडेन्सी बैंकों का एकीकरण करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट सन् १९२१ के अन्तर्गत इम्पीरियल बैंक के रूप में की। इसके बाद सन् १९४५ में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया जिसके फलस्वरूप 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९४५' लागू हुआ और इसकी स्थापना १ जुलाई सन् १९४५ को की गई।

उद्देश्य—(१) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का मुख्य उद्देश्य कृषि सम्बन्धी वित्त सुविधाओं को प्रदान करने का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्टेट बैंक देश भर में ४०० नई शाखाएँ प्राथमिक ५ वर्षों में खोलना। १ जुलाई सन् १९५५ से बैंक ने २० नई शाखाएँ खोली हैं। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक की सलाह से केन्द्रीय सरकार ने १०० नये केन्द्र इस कार्य के लिये चुन लिये हैं। ये नई शाखाएँ विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जावेंगी ताकि कृषकों को अधिक-से-अधिक वित्तीय सहायता मिल सके।

(४) स्वयं अनिश्चित स्टॉक का व्यापार और व्यवसाय का सात मुदिया को प्रदान करता है। यह व्यवहारवा प्रथा सचट न समय व्यापारिक बका को वित्तीय सहायता देता प्रथा।

(५) स्टॉक का स्थापना का उद्देश्य सामान्य धनार्थ बाजार सम्बन्धी सुविधाएँ देने का है। ताकि याता आ विमान अपना अनाद उन यन्त्राया में स्वरुप कर सकें और धनधारक न बाजार का भाग व अनुमान बच सकें जिसमें उनको उसका अर्द्ध मूल मिल सकें।

(६) स्वयं स्थापना का उद्देश्य सामान्य धनार्थ बाजार पर चतन बाध न हो सके या का आर्थिक या अन्य नुकसान का भा है।

पूजा (Capital)—स्टॉक बाजार हार्डवार्थ को अधिकृत पूजा (Authorized Capital) कहते प्रथा है जो मौजूदा समय में २० लाख रुपय प्रप्त (Fully Paid up) अर्थात् विभाजित है। स्वयं निश्चित पूजा (Issued Capital) ११ लाख रुपय १९४५ का १९४७ का १००१०० रुपय का १९४७५०० अर्थात् विभाजित था। यह पूजा निम्न प्रकार नाम में निश्चित है। रिजर्व बैंक का यह अधिकार दिया गया था कि वह स्मॉरियल बचक संगठनारिया का समस्त निश्चित पूजा का अधिकतम अधिकतम ८१% भाग सस्तिपूर्ति कर सकें और यदि भाग सस्ति ११% अवन प्राप्त रखे। स्टॉक बाजार का अधिकार है कि वह स्टॉक सस्तिार का स्वाहति देता प्रथमी पूजा का १२३ करोड रुपय तक बढ़ा सकता है। सम अधिक पूजा की वृद्धि देता कर्तव्य सरकार का स्वाहति व तह का पा सकता है।

प्रबंध (Management)—स्टॉक बाजार प्रबंध का दिशान्तर कर्तव्य बोड का स्थापना का है जिसमें कुल २० सचिव हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अनिश्चित या प्रबंध सचिव है जिसमें एक सचिव कर्तव्य सस्तिार गारा और दूसरा सचिव रिजर्व बैंक गारा नियुक्त किया गया है। गारा १८ सचिवता में ६ सचिव सस्तिार में ४ सचिव सचिवता में और २ सचिव सचिवता में नियुक्त है।

कार्य (Functions)—स्टॉक बाजार प्रथा का मुख्य कार्य निम्न निश्चित है—

(१) स्टॉक बाजार स्थापना प्रथा रिजर्व बैंक का नामांकन बना है रिजर्व बैंक का सचिव का काम करता है।

(२) यह स्टॉक बाजार प्रथा प्रविधुनिया (Securities) का जमानत पर अर्थात् एन्वॉसि (अग्रिम राशि, तथा नक्का साख देता है।

(३) विभिन्न माध्यम प्रथा अर्थात् विन अर्थात् का निश्चिता स्थापना करता प्रचना और द्रम विनय करता है।

(४) माना चीनी तथा माना चीनी का निश्चिता का द्रम विनय करता है।

(५) यह प्रथा का बाड अर्थात् अधिकार पत्र और अग्रिम प्रविधान वस्तुओं सुरक्षा रखता है।

(६) रिजर्व बैंक गारा प्रविधुनिया का एन्वॉसि का द्रम विनय करता है।

(७) अपने कार्यालयों, शाखाओं और एजसियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले मांग ड्राफ्ट (Demand Draft), तार भुगतान (Telegraphic Transfers) और अन्य प्रकार के राशि भेजने के पत्र सरोदना और साक्ष पत्र (Letters of Credit) लिखना तथा उन्हें जारी करना ।

(८) धन के बदले में प्राप्त हुई अथवा दूनी हुई चल व अचल संपत्ति को बेच कर राशि प्राप्त करना ।

(९) यह किसी दृष्टि की प्रतिभूतियों में, नगरपालिका जिन्हा बोर्ड या स्थानीय सभाया के कण पत्रों में, भारत स्थित निगमों के अथवा और धन पत्रों में कबला जगाना और ऐसे प्रवास व कण पत्रों का अभिगोपन (Underwriting) करना ।

(१०) जमाना से राशि जमा करना ।

(११) स्वयं का व्यापार करना तथा अपनी संपत्ति के आधार पर धन लेना ।

(१२) कमीशन लेकर एजेंट के रूप में काम करना ।

(१३) कोर्ट बांक वाड्म को उनकी संपत्ति की जमानत पर धन देना ।

(१४) १५ मास की अवधि तक के कृषि विला का कण करना ।

(१५) रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेकर दूसरे बैंकों के अथवा सरोदना ।

(१६) विदेशी विला (Bills of Exchange) और साक्ष पत्र (Letters of Credit) का लिखना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर अथवा उसके आदेशानुसार स्टेट बैंक द्वारा किंगी बैंकिंग कम्पनी का व्यवसाय अपने अधिकार में लेना ।

(१७) किसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति की संपत्ति (Liquidation) में समय उनकी संपत्ति और प्रतिभूतियों के आधार पर धन देना ।

स्टेट बैंक में निषिद्ध (Prohibited) कार्य—स्टेट बैंक ग्राहक इच्छित निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता —

(१) स्टेट बैंक आधारितया ६ मास में अधिक अवधि के लिये धन और पैसगी (एडवांस) नहीं दे सकता ।

(२) अपने ही अथवा अर्थात् रोयल व स्टॉक की जमानत पर धन और पैसगी नहीं दे सकता ।

(३) किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को एक समय में कुल मिला कर निर्धारित राशि में अधिक धन नहीं दे सकता ।

(४) अचल संपत्ति व उसके अधिकार पत्र की जमानत पर धन और एडवांस नहीं दे सकता ।

(५) बैंक को मौसमी कृषि कार्यों के लिये १५ मास की अवधि के लिये प्रत्यक्ष की और अथवा फर्मों के लिये ६ मास से अधिक की अवधि के लिये प्रत्यक्ष को बेतान करने और उनको जमानत पर धन व एडवांस देने का अधिकार नहीं है ।

(६) स्टेट बैंक को किसी विशेष व्यक्ति या फर्म के लिये विविध मध्य प्रत्यक्ष को बेतान करने, सरोदना या उसको जमानत पर धन व एडवांस देने का अधिकार नहीं है जिन्हे प्रति कम से कम दो विभिन्न व्यक्तियों या फर्मों का अनन्य मत उतर दाखिल नहीं है ।

(७) स्टेट बैंक को अपने व्यवसाय को चलाने के लिये तथा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास के लिये आवश्यक भवन तथा भूखण्डों के डल जाने के बदले में प्राप्त हुई सम्पत्ति को छोड़ कर अन्य किसी अचल सम्पत्ति को रखने, धरीदने या उसमें अपना कोई अंश रखने का अधिकार नहीं है।

स्टेट बैंक के कार्य पर एक आलोचनात्मक दृष्टि—सबसे पहला कार्य इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों की क्षतिपूर्ति करने का था। इस क्षेत्र में प्रगति सतोपजनक है। ३१ दिसम्बर १९५५ तक ६५६० अंशधारियों ने १८६५ करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन पत्र दिये थे जिनमें से ६४६१ अंशधारियों को १८३६ करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है। धारकों ५ वर्षों में ४०० लाखों लोनने की योजना भी तब चुकी है और सन् १९५५ के अंत तक २० स्थानों पर यह चालाई खोली भी जा चुकी है। इतना होने पर भी अभी विदेशी चालाई नहीं खुल पाई है जिसके कारण इम्पीरियल बैंक को विदेशी चालाई अभी बन्द नहीं की जा सकी है। चाहा है यह कतिनाई भी धीरे-धीरे दूर हो जावेगी। विनोद प्रतियोग के लिये बैंक द्वारा कुछ नियुक्तियाँ भी की जा रही हैं।

बैंक के कुछ आलोचकों का कहना है कि इसके ऊपर व्यापारिक एवं कृषि सम्बन्धी दोनों ही कार्यों का भार सौंप कर उसके उत्तरदायित्व को अनावश्यक रूप में बढ़ा दिया गया है जिससे यह आशङ्क है कि बैंक किसी भी कार्य को ठीक प्रकार नहीं चला सकेगा। इन आलोचकों का यह भी मत है कि कृषि सम्बन्धी साधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक अलग अलग भारतवर्षीय कृषि बैंक (All India Agricultural Bank) की स्थापना की जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मत है कि बैंक का संचालन कार्य प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली पर नहीं रखा गया है, क्योंकि ४५% अंशधारियों को ३०% संचालकों (Directors) को चुनने का अधिकार दिया गया है जो सचवा अनुचित है, यह बैंक भविष्य ही बता सकेगा।

स्टेट बैंक का भविष्य—जहाँ तक बैंक के भविष्य का सम्बन्ध है अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु फिर भी अब तक जो कुछ प्रगति हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक का भविष्य उज्ज्वल है। इस बैंक में कृषि, व्यापार और उद्योग सभी क्षेत्रों में लाभ पहुँचिगा।

(५) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

परिचय—भारत में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता बहुत समय पहले से अनुभव की जा रही थी, किन्तु भारत सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सन् १९१३ में जब कैम्बरलेन कमीशन विचारों को प्रस्तुत किया तो भारत सरकार का ध्यान एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की ओर आकर्षित हुआ। सन् १९१४-१८ में अर्थात् प्रथम महायुद्ध काल में भी केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता की अनुभव हुआ। सन् १९२१ में वेरिजवम के प्रसन्न नगर में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में भी मुख्यतः दिया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ भी ही केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाना चाहिये। अतएव सन् १९२१ में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। किन्तु इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए एक स्वतन्त्र और अलग अलग में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता हुई।

सन् १९२४-२५ में हिल्टन यम कमीशन ने एक स्वतन्त्र डेयरहोल्टर्स के वेन्द्रीय बन् की स्थापना का सुझाव दिया। वेन्द्रीय बैंकिंग जीव समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने भी हिल्टन-यम कमीशन के विचारों का समर्थन किया। अतः सन् १९३८ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ, जिसने फलस्वरूप १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

स्यामित्व एवं पूँजी—सन् १९३४ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक एक अधिधारित अर्थात् डेयरहोल्टर्स के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी अधिकृत पूँजी ५ करोड़ रुपये थी जो सौ-सौ रुपये के शेयरों, अर्थात् ४०,००० में विभाजित थी। बैंक २०,००० रु० के अर्ध-राष्ट्रीय सरकार ने खरीदे थे और शेष बैंक के प्राचीन शेयरों के निवासियों को निम्न अनुपात में बैंक दिये गये थे—कलकत्ता १४५ लाख, बम्बई १४० लाख, दिल्ली ११५ लाख, मद्रास ७० लाख, और एगून ३० लाख। आरम्भ में किसी भी व्यक्ति को प्राचीन शेयरों में अधिक शेयर नहीं दिये गये थे, किन्तु सन् १९४० में ऐक्ट में संशोधन कर यह निर्धारित कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अकेला या साझे में बीस हजार रुपये में अधिक के शेयर अपने नाम में नहीं रख सकेगा। प्रत्येक अंशधारी का पांच अंशों के पीछे एक मत देने का अधिकार था और कोई भी अंशधारी इस मत से अधिक नहीं दे सकता था।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् १ जनवरी १९४६ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इसके विधान में आवश्यक संशोधन भी कर दिये गये हैं। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के समस्त शेयर या अर्ध-डेयरहोल्टर्स को १०० रु० के एक शेयर के बदले में ११८ रु० १० पैसे के हिमाव से देकर खरीद लिये हैं। दो गैर-रकम में ३% तो सरकारी बांड दिये गये हैं और शेष रकम का नकद रूप में अनुदान कर दिया गया है। अतः रिजर्व बैंक पूर्णतया एक राष्ट्रीय बैंक बन गया है।

प्रबन्ध—रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इसका प्रबन्ध १४ सदस्यों का एक बोर्ड करता है जिसके सचालक अथवा डाइरेक्टर सरकार द्वारा निम्न प्रकार मनोनीत होते हैं—

(१) १ गवर्नर और २ डिप्टी गवर्नर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पाँच वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं तथा जिनका वेतन केन्द्रीय सरकार की सलाह से केन्द्रीय बोर्ड नियमित करता है।

(२) चार स्थानीय बोर्डों से सरकार द्वारा मनोनीत एक एक डाइरेक्टर।

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ६ अन्य डाइरेक्टर। इनमें से प्रत्येक दो बारी बारी से एक, दो, तीन वर्ष के पश्चात् चुनकें होते जाते हैं।

(४) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त १ सरकारी निवेष्टक।

स्थानीय हितों की रक्षा के लिये केन्द्रीय बोर्ड के अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड (Local Boards) स्थापित किये गये हैं—उत्तरी क्षेत्र का बोर्ड दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र का बोर्ड बम्बई, पूर्वी क्षेत्र का बोर्ड कलकत्ता, तथा दक्षिणी क्षेत्र का बोर्ड मद्रास। प्रत्येक बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य होते हैं। ये स्थानीय बोर्ड आवश्यक विषयों पर केन्द्रीय बोर्ड की सलाह देते हैं तथा अपने आदेशानुसार कार्य करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में है। परन्तु कोई भी तीन सचालक मिलकर भी गवर्नर से बैठक बुलाने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं। वर्ष-भर में ६ बैठकें बुलाना अनिवार्य है, किन्तु तीन महीनों में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय तथा विभाग

रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय—रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, तथा कानपुर में हैं। इसकी एक शाखा लन्दन में भी है जो अप्रैल सन् १९३६ में खोली गई थी। केन्द्रीय सरकार की आज्ञा में रिजर्व बैंक अन्य किसी स्थान पर भी अपनी शाखा खोल सकता है। जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक का अपना एक-मात्र एजेंट नियुक्त कर दिया है। ब्रिटिश महाप्रभु कास म जापान द्वारा वर्मा पर अधिकार होने पर उसका कार्यालय बम्बई कर दिया गया।

रिजर्व बैंक के मुख्य विभाग—रिजर्व बैंक के मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं—

१—नोट निर्गम विभाग (Issue Department)—इस विभाग का मुख्य कार्य पत्र मुद्रा, धर्मपत्र कापनी नोट जारी करना है। इस विभाग की शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों पर हैं। प्रत्येक शाखा दो विभागों में विभाजित है। प्रथम विभाग का कार्य नोट निकालने तथा उनका विनिमय करने का है और दूसरे विभाग का कार्य रजिस्ट्रेशन करने, नोटों को जांचने तथा रद्द करने, हिसाब रखने तथा आन्तरिक प्रवेक्षण (Audit) करना है।

२—बैंकिंग विभाग (Banking Department)—बैंक का यह विभाग अन्य बैंकों की अनुमति-पत्र (License) देने, उनके रोख-बोझ रखने उनकी वार्षिक सहायता तथा परामर्श देने, उनका निरीक्षण करने, उनकी सहायता को स्थानान्तरण करने का कार्य, तथा सरकारी लेन देन का उचित प्रवर्धन करना है। इस विभाग की शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों पर हैं। प्रत्येक शाखा का प्रवर्धन एक मैनेजर के अधीन होता है तथा वह पाँच विभागों में विभाजित होता है—घसा का हस्तान्तरण, जमा खात, प्रतिभूतियाँ, सरकारी जमा तथा सरकारी ऋण।

३—विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department)—इस विभाग की स्थापना विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण करने तथा विनिमय दर को स्थायी रखने के उद्देश्य से द्वितीय महाप्रभु कास म की गई थी। घन सन्तर्प विदेशी विनिमय कार्य इस विभाग द्वारा किसी विनिमय नियन्त्रण ऐक्ट १९४७ के अन्तर्गत नियन्त्रित होता है।

४—बैंकिंग विकास विभाग (Department of Banking Development)—इस विभाग की स्थापना अक्टूबर १९३० में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गाँवों तथा कच्चा में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण धर्म मयस्थाओं का अध्ययन तथा हस्त निरालने का है। ग्रामीण बैंकिंग अनुसन्धान समिती की सिफारिशों को कार्यान्वित करना भी इसका मुख्य कार्य है।

५—बैंकिंग क्रियाओं का विभाग (Department of Banking Operations)—इस विभाग की स्थापना सन् १९४६ में भारतीय बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १९४१ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की अन्य बैंकों के नियंत्रण तथा निरोधन के अधिकारों को उचित ढंग से काम में लाने के लिये हुई। अतः इस विभाग का मुख्य कार्य भारतीय बैंकिंग पद्धति का उचित नियंत्रण कर उसे सुदृढ़ और सुमनजित बनाना है।

६—अन्वेषण तथा समक विभाग (Department of Research & Statistics) मुद्रा व बैंकिंग आदि क्षेत्रों की खोज करना तथा मुद्रा बाजार, बैंकिंग व्याज दरें, उत्पादन, सामाज्य आदि से सम्बन्धित आंकड़ों का सङ्कलन कर प्रकाशित करना इस विभाग का मुख्य कार्य है।

७—कृषि साज विभाग (Agricultural Credit Department)—कृषि-साज विभाग का चलाना बैंक का बंधनान्वित कर्तव्य है। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(प्र) कृषि साज सम्बन्धी खोज के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति करना तथा उनके द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों तथा सरकारी विभागों को आवश्यक परामर्श देना।

(प) कृषि साज से सम्बन्धित बैंकों के कार्यों का नियन्त्रण करना और उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(स) कृषि-साज में आवश्यक सुधार करने के सुझाव प्रस्तुत करना।

(द) रिजर्व बैंक की कृषि साज सम्बन्धी नीति का निर्धारण करना।

इस क्षेत्र में बैंक का कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं हुआ है।

रिजर्व बैंक के कार्य (Functions)—रिजर्व बैंक के कार्यों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—(प्र) केन्द्रीय बैंक के कार्य, और (प्रा) साधारण बैंक के कार्य।

(अ) केन्द्रीय बैंक के कार्य—अन्य समस्त केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक भी निम्नलिखित केन्द्रीय बैंकिंग कार्य सम्पन्न करता है :—

१. पत्र मुद्रा जारी करना—कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। यह काम बैंक अपने निर्भय विभाग (Issue Department) द्वारा सम्पन्न करता है। कुल नोट चलन का ४०% होने के सिवा, स्वर्ण पाठ तथा स्टैमिंग प्रतिभूतियों से रखना आवश्यक है और किसी भी समय २१ ६० ३ भा० = पाई प्रति तोले के भाव से ४० करोड़ रुपये से कम का साठा नहीं होना चाहिए। इस कोष का दोष ६०% स्वयं, सरकारी प्रतिभूतियों, स्वीकृत व्यापारिक वित्तों, हुज्जियों या प्रतिज्ञा पत्रों में होना चाहिये।

२. बैंकों के बैंक का कार्य करना—रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देश के बैंकों का नियन्त्रण, पत्र प्रदर्शन तथा संगठन करना है। यह नियन्त्रण रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों की चासु जमा का कम से कम ५% और स्थायी जमा का २% नगद रूप में अपने पास रख कर करता है। सन् १९४६ की बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत तो अन्य अन्य बैंकों के लिये भी नगद कोष अपने पास या रिजर्व बैंक के पास रगाना अनिवार्य कर दिया है। रिजर्व बैंक इस केंद्रित धन-राशि को इन्हीं बैंकों को आर्थिक

सकट काल में प्रतिष्ठित कृषु-दाता के रूप में सहायता करने के काम में लाता है। रिजर्व बैंक खुल बाजार की क्रिया (Open Market Operations) तथा बैंक दर (Bank Rate) के द्वारा अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखता है।

३. सरकारी बैंकर का कार्य करना—रिजर्व बैंक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बैंकर का भी काम करता है। यह विभिन्न सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं से रुपया लेता और जमा करता है तथा उनके प्रति धन्य का भुगतान करता है। यह उन्हें सिधे विदेशी विनिमय, राशि स्थानान्तरण तथा सांख्यिकीय ऋण का प्रवर्धन करता है तथा उनके आवश्यक बैंकिंग कार्य करता है। सरकार की धर्म-नीति, मुद्रा नीति तथा विनियोग नीति के निमित्त करने में भी आवश्यक एलाह देता है।

४. विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करना—रिजर्व बैंक को रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना पड़ता है। ऐसा करने के लिये वह विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय भी करता है। रिजर्व बैंक एक्ट के १९४७ के एक संशोधन द्वारा रुपये और स्टर्लिंग का दैनिक सम्बन्ध तोड़ दिया गया है। मगर अब इनको न केवल स्टर्लिंग का ही क्रय-विक्रय करना पड़ता है बल्कि अन्य उन सब देशों की मुद्रा का भी क्रय-विक्रय करना पड़ता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में सदस्य हैं। यह क्रय-विक्रय उन दरों पर किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की शर्तों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट कर देती है।

५. निकाल-गृह का कार्य करना—रिजर्व बैंक एक केन्द्रीय बैंक के रूप में अन्य बैंकों के निकाल-गृह अर्थात् समाशोषण या ऋणमाशेन गृह का भी कार्य करता है।

(आ) साधारण बैंक के कार्य—रिजर्व बैंक निम्नलिखित साधारण बैंक के कार्य भी सम्भर करता है :—

१. सरकारी, बैंको, संस्थापना तथा व्यक्तियों से बिना व्याज के रुपया जमा करना। २. भारत में भुगतान होने वाले ६० दिन के मुद्रती बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-विक्रय तथा पुनर्नीटिती करना जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर ह। और इनमें से एक हस्ताक्षर सदस्य बैंक अध्यक्ष प्रांतीय सहकारी बैंक का हो। ३. भारत की केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों की अधिक-से-अधिक ६० दिव की अवधि के लिये ऋण देना। ४. भारत की केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की किसी अवधि की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना। ५. भारत से बाहर अन्य किसी देश की १० वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना। ६. बेनी सम्पत्तियों ६ महीने के मुद्रती बिलों का क्रय-विक्रय तथा पुनर्नीटिती करना। ७. अपनी शाखाओं को दर्शनी ड्राफ्ट देना। ८. सदस्य बैंकों को नम-से-नम दो लाख रुपये के बराबर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना। ९. अधिक-से-अधिक ३० दिन के लिये सदस्य बैंक अध्यक्ष किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक में ऋण देना। १०. केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के ऋण-पत्र देना। ११. मोने के सिक्कों और मोने का क्रय-विक्रय करना। १२. द्रव्य प्रतिभूतियों, जेवर तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। १३ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य-राष्ट्रों के किसी भी बैंक के साथ खाता खोलना तथा उसके एजेंट का काम करना। १४. बैंकिंग सम्बन्धी शर्तों का सङ्कलन कर प्रकाशित करना, आदि।

रिजर्व बैंक के निषिद्ध (Prohibited) कार्य- रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है—

- (१) रिजर्व बैंक कोई व्यवसायिक तथा व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता है।
- (२) वह अपने सम्पत्ति को रखन रखकर उम्र पर ऋण नहीं दे सकता है और न वह अपने सम्पत्ति को अपने निजी काम के अनिश्चित परोद में सकता है।
- (३) वह अपने शेयर या अन्य किसी बैंक या कम्पनी के शेयर नहीं खरीद सकता है और न उन सदस्यों को जमानत पर ऋण हो दे सकता है।
- (४) वह बिना प्रतिप्रतिभा के आधार पर कोई ऋण नहीं दे सकता है।
- (५) वह जमा होने वाले रुपये पर व्याज भा नहीं दे सकता है।
- (६) वह ऐम क्लो को नहीं खोल सकता है और न उह स्वाकार हो कर सकता है जिनका मौजने पर भुगतान न हो।

रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक का सम्बन्ध—जिन स्थावा पर रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं है वहा स्टेट बैंक इसका प्रतिनिधित्व करता है। स्टेट बैंक को इन कार्य के लिये यादिक निश्चित कमीशन मिलता है।

रिजर्व बैंक तथा सदस्य एवं असदस्य बैंक—देश के बैंको में सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सभी को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया है—

- (१) सदस्य बैंक और (२) असदस्य बैंक। सदस्य (Scheduled) बैंक वे बैंक हैं जो रिजर्व बैंक एक्ट की दूसरी मारणी (Schedule) में सम्मिलित होने हैं तथा जिनका नाम केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। कोई भी बैंक जो भारत में बैंकिंग कार्य करता है और जिसको पन्द्रहा पूँजी और सर्जन कोष ५ लाख रुपये से अधिक है तथा जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनीज या बैंकिंग एक्ट अध्याय किसी विदेशी विधान के अनुसार हुआ है, सदस्य बैंक बन सकता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को अपनी माँग जमा का १% तथा मुद्रा जमा का २% रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को प्रति मास केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक को एक साप्ताहिक विवरण (Weekly Return) भेजना पड़ता है।

असदस्य बैंक—जिन बैंकों के नाम रिजर्व बैंक एक्ट की दूसरी मारणी में सम्मिलित नहीं होते हैं वे असदस्य (Non Scheduled) बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक असदस्य बैंकों से भी जमा व मासिक विवरण प्रादि द्वारा सम्पर्क रखता है।

रिजर्व बैंक तथा देशा बैंकर—रिजर्व बैंक देशी बैंकरों की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के प्रथम मान के लिये प्रयत्नशील है। इसने सबसे पहले सन् १९३७ में देशी बैंकरों को नियमबद्ध करने के लिये एक योजना बनाई, परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसने बाद सन् १९४१ में इस प्रकार की एक नयी योजना बनाई गई परन्तु वह भी देशी बैंकरों के विरोध के कारण कार्य रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये रिजर्व बैंक ने सन् १९५१ में सम्बन्ध में हुई देशी बैंकों की समा में भी भाग लिया था।

रिजर्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं पुनर्निर्माण व विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—भारतवर्ष प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) तथा पुनर्निर्माण व विकास के लिये बैंक (International Bank for Reconstruction & Development) का सदस्य है। रुपये का मूल्य ८४७५१२ (स्वण) पन के बराबर निरासित किया था जो

सितम्बर १९४६ में ३०-४०% डॉलर के रूप में कम कर दिया गया। भारत का मुद्रा-होप में प्रमुख स्थान है। अर्थात् १९४६ से भारत ने कोष से डॉलर खरीदने का अधिकार छोड़ दिया है। अब भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का ६८ मिलियन डॉलर का सदस्य है।

पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—इस बैंक का मुख्य ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय साख्त कार्य में सहयोग देना है। इसकी पूर्णता में सब सदस्यों का भाग है। इसकी कार्यकारिणी में श्रद्धालुता व श्रद्धा दोनों ही राष्ट्र प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भारत को आर्थिक विकास के लिए अब तक कुल ६२ १/२ मिलियन डॉलर का ऋण मिल चुका है।

रिजर्व बैंक के कार्य का आलोचनात्मक अध्ययन—रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व बैंक-दर (Bank Rate) ७% से ८% थी। उसमें स्थिरता का लक्षण भी न था। परन्तु रिजर्व बैंक ने लगभग १५ वर्ष तक बैंक दर घटाकर ३% ही स्थिर रखा। केवल १५ नवम्बर १९५१ में यह बढ़ाकर ३ १/२% कर दी गई है। बैंक दर कम करने के कारण व्याज की दरें भी गिर गईं। उनमें विभिन्नता बहुत भंरा में बूर हो गई। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भारतीय मुद्रा-बाजार की मौतनी कमी समाप्त हो गई। पचास बैंक का मुद्रा-बाजार पर नियन्त्रण पूर्णतया नहीं हुआ है परन्तु फिर भी इसकी साख्त-नीति बहुत मर्याद तक सफल रही है। बैंक मुद्रा-बाजार के विभिन्न वर्गों में सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न में भी कुछ मर्याद तक सफल रहा है।

बैंक ने कृषि-साख सम्बन्धी एवं सहकारी साख्तों की समस्याओं में असी-भाति अध्ययन किया है और कृषि की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सहकारी बैंकों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ दी हैं। इसने कृषि साख सम्बन्धी आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अखिल भारतीय साख जाँच की व्यवस्था की है।

बैंक ने सरकारी बैंक के कार्य भी काफी योग्यता में किये हैं और भारतीय मुद्रा-बाजार में सरकार के लिये ऋण प्राप्त करने में बहुत सफल रहा। युद्ध-जन्म रक्षात्मक भावि महत्त्वपूर्ण समस्याओं को बैंक ने बड़ी योग्यता में हल किया है। बैंकों के बैंक के रूप में भी हमने अन्तर्गत कार्य किया है। इसी के प्रयत्नों से ही अनेक बैंकिंग सम्बन्धी विधान पास हुये जिसमें देश में बैंकिंग सम्बन्धी विकास की पथति प्रोत्साहन मिला। देश की आर्थिक समस्याओं पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रकाशन की गई हैं और जिनमें आवश्यक सुधार दिये गये हैं।

इतना होने हुए भी बैंक कई बातों में असफल रहा। उदाहरणार्थ, देशी बैंकों से बैंक अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका और हृषी या विल बाजार का विकास नहीं कर सका। युद्ध-काल में बैंक मुद्रा-स्थिति और मूल्य-वृद्धि को रोकने में भी असमर्थ रहा।

(६) अन्य बैंकिङ्ग संस्थाएँ

(अ) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)—सहकारिता वह मूल्य है जिससे अन्तर्गत अर्थिक स्वेच्छा में संगठित होकर सर्वोत्ति के लिए सम्मिलित कार्य करने हैं। सहकारिता में स्पर्धा का स्थान सहयोग से लेता है। भारतवर्ष में सन् १९०४ और सन् १९१२ के सहकारिता कानून के अनुसार देश में सहकारी समितियों की

स्थापना हुई। जो समितियाँ जमा करने और ऋण देने का कार्य करती हैं वे सहकारी बैंक प्रणाली द्वारा समितियाँ कहलाती हैं। सहकारी साख समितियाँ या सहकारी बैंक तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—(१) प्रारम्भिक सहकारी साख समितियाँ, (२) केन्द्रीय सहकारी बैंक, और (३) प्रांतीय सहकारी बैंक।

(१) प्रारम्भिक साख समितियाँ (Primary Co-operative Credit Societies)—ये देश के कोने-कोने में स्थित हैं और निर्धन किसानों तथा कारीगरों को ऋण देती हैं। ये केवल सदस्यों को ही ऋण देती हैं। ग्रामीण साख समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व असंमित होता है। परन्तु नगर साख समितियों का उत्तरदायित्व प्रायः सीमित होता है। इनको पूर्ण जमा और प्रवेण फीस आदि के रूप में एकत्रित की जाती है।

(२) सहकारी केन्द्रीय बैंक (Central Co-operative Banks)—प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो अपने जिले के प्रारम्भिक सहकारी समितियों का संगठन तथा नियन्त्रण करता है तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी देता है। ये देयर बैंक कर तथा राँगों को जमा स्वीकार कर अपनी पूर्णता का संगठन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये अपने राज्य के बैंक से जो इन सबके ऊपर होता है, ऋण लेते हैं।

(३) राज्य सहकारी बैंक (State Co-operative Banks)—राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक होता है जिसमें उस राज्य के समस्त केन्द्रीय बैंक सम्बन्धित होते हैं। राज्य सहकारी बैंक अपने राज्य के समस्त केन्द्रीय बैंकों का नियन्त्रण करते हैं तथा उनको आर्थिक सहायता देते हैं। राज्य सहकारी बैंकों की देख-रेख के लिये एक अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ नामक संस्था भी है।

भारत में सहकारी बैंकों की अवस्था तथा प्रगति वस्तुतः प्रशंसनीय है। उनकी अपूर्ण कार्य-प्रणाली, ग्रामीण जनता की अनिष्ठा, सहकारिता सिद्धान्तों की अज्ञानता, तथा उनकी ऋण-व्यस्तता और योग्य व ईमानदार कार्य-कर्ताओं का अभाव आदि इस अस्तोपजनक अवस्था के कुछ मुख्य कारण हैं। अतः उपर्युक्त दोषों को दूर करते हुए सहकारी बैंकों का पुनर्संरुद्धन अत्यन्त आवश्यक है।

(भा) भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks)—वे सम्पूर्ण हैं जो भूमि को बन्धक प्रयोजन के लिये स्मृति दीर्घकाल के लिये कृषकों को ऋण देती हैं। साख सहकारी समितियाँ कृषकों की भूमि तथा मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, परन्तु दीर्घकालीन ऋण के लिये भूमि-बन्धक बैंकों की ही सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है।

ऋण का उद्देश्य—भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा ऋण किरानों को प्रायः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दिया जाता है—(१) पुग्ने ऋण चुकाने के लिये, (२) भूमि खरीदने के लिये, (३) सिंचाई के लिये कुआँ बनवाने तथा मुख्यतः यन्त्रादि खरीदने के लिये, (४) भूमि में स्थायी सुधार करने तथा चकन्दो करने के लिये, (५) किसानों को भूमि व मकान मरती में छुड़ाने के लिये।

भूमि बन्धक बैंकों के भेद—यद्यपि सभी भूमि बन्धक बैंक सहकारी भूमि बन्धक बैंक कहलाते हैं, फिर भी वे तीन प्रकार के होते हैं—(१) सहकारी भूमि-बन्धक बैंक, (२) व्यापारिक भूमि बन्धक बैंक, और (३) अर्ध-सहकारी (Quasi-Co-operative)

बैंक । सहकारी भूमि-वन्धक बैंक महत्वादी सिद्धान्त धर्यात् पारस्परिक सहयोग की भावना में चलते हैं । लाभ वमाने के उद्देश्य में इनकी स्थापना नहीं की जाती है । व्यापारिक भूमि-वन्धक बैंक व्यापारिक बैंकों की भांति लाभ वमाने के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं । ग्रन्थ-सहकारी भूमि-वन्धक बैंक में व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंकिंग में सिद्धान्त का सामंजस्य रहता है ।

पूँजी—नेपथ्य, जमा तथा ऋण पत्रों (Debentures) आदि के द्वारा इनको पूँजी प्राप्त होती है । प्रायः इनके कुछ ऋण-पत्र राज्य-सरकारें खरीदती हैं अथवा उन पर निश्चित व्याज की गारंटी होती है ।

ऋण का आदान प्रदान—जिमान को या तो गिरवी रखी भूमि के मूल्य का आधा अथवा गिरवी रखी भूमि के मूल्य का ३० गुना तक ऋण दिया जा सकता है । ऋण के भुगतान परन्तु वा समय १६ वर्षों में ३० वर्षों तक होता है । ऋण व्याज सहित प्राप्त बापित सुविधाजनक बिम्बा में चुकाया जाता है । व्याज की दर लगभग ८% या ९% होती है ।

भारतवर्ष में भूमि-वन्धक बैंक—भारतवर्ष में पहिला भूमि वन्धक बैंक सन् १९२० में पंजाब में स्थापित हुआ पर वहाँ अल्पकाल रहा । फिर मद्रास में सन् १९२६ में भूमि वन्धक बैंक की स्थापना प्रारम्भ हुई । सन् १९३१ में धर्म्पई राज्य में एक ऐसा बैंक खोला गया । इसके पश्चात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी भूमि वन्धक बैंक स्थापित होत चले । सन् १९४७-४८ में भारतवर्ष में ११ केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक तथा २८३ प्रारम्भिक वन्धक बैंक थे जिनमें क्रमशः १,४१,४८३ और ३,३३,६८० सदस्य थे । द्रष्टव्य क्रमशः ४६२ लाख १० और २४२ लाख ६० का ऋण दिया था ।

निष्कर्ष—देश के विकास की दृष्टि से एक नव बहून कम भूमि-वन्धक बैंकों की स्थापना हुई है । कृषक को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का एकमात्र साधन होने के कारण यह आवश्यक है कि भूमि वन्धक बैंक का देश के कानून-कोल में प्रसार किया जाय ।

(६) औद्योगिक बैंक (Industrial Bank) —उद्योगों के विकास तथा उत्थान के लिए औद्योगिक बैंक की आवश्यकता होती है । जिस प्रकार व्यापारिक बैंक धातु पूँजी (Working Capital) का प्रवर्धन करते हैं उन्ही प्रकार औद्योगिक बैंक उद्योगों की स्थायी पूँजी (Fixed or Block Capital) का प्रवर्धन करते हैं ।

पूँजी—औद्योगिक बैंक सञ्चय तथा निधि ऋण देते हैं, अतएव वे अच्छा व्याज देकर स्थायी जमा करने में तैयार जमा करने हैं । इनसे अनिश्चित ग दली बैंकों से भी ऋण लेते हैं । उद्योगों के अर्थ-व्यवस्था का कार्य भारतवर्ष में मैनफैच्यूर एजेंसी द्वारा भी होता है ।

कार्य—(१) उद्योगों के लिए स्थायी धनका प्रचल पूँजी के लिए अर्थ-प्रवर्धन करना, (२) औद्योगिक कम्पनियों के अथवा (Shares) का अधिरोपन (Underwriting) करना तथा स्वयं उनके अम खरीदना, और (३) उनको औद्योगिक परामर्श देना ।

भारत में औद्योगिक बैंक—भारतवर्ष में औद्योगिक बैंक खोले जाने के अल्पकाल प्रवर्तन किये गये परन्तु इन प्रयत्नों की सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । स्वदेशी आन्दोलन

के समय बहुत से बैंक भारत में खोले गये, परन्तु वे सब कुप्रबन्ध तथा मन्थालको की सट्टेबाजी तथा वैदेशिकता के कारण डूब गये। इनमें पिपुल्स बैंक, अग्रतमर बैंक, मैसूर औद्योगिक बैंक, कलकत्ता औद्योगिक बैंक आदि थे। प्रथम महापुट-काल में सन् १९१७ में टाटा औद्योगिक बैंक स्थापित हुआ, परन्तु बुलबुलीन तेजी (Boom) समाप्त होने के बाद विश्व-व्यापी मन्दो (Depression) का शिकार बन गया और अन्त में इसे मेण्टून बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् कुछ प्रांतों में उद्योग-धन्धों के लिये दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था के लिये त्रिनिटि सम्बंधों की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश, बम्बई और महाराष्ट्र में भी औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जा रही है।

औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल (Industrial Finance Corporation)— भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भी देश के उद्योग-धन्धों की दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन रागव्यापों को हल करने के उद्देश्य में ट्रेडिन्ग होकर जुलाई सन् १९४८ में औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल की स्थापना की है। इसकी अधिकृत पूँजी १० करोड़ रुपये है जिनमें से ५ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त हो चुकी है। इसमें असाधारण (Shareholders) को भारत सरकार ने अंशों की राशि और ब्याज का आश्वासन दिया है। कांसेंसस अर्थात् प्रमण्डल के पाँच-पाँच हजार रुपये के दस हजार अंश अर्थात् पाँच करोड़ रुपये की राशि, रिजर्व बैंक, बीमा कम्पनियों और सहकारी बैंकों में खरीदे हैं। इसका प्रबन्ध १२ मन्थालको अर्थात् डाइरेक्टर्स के हाथ में है जिनमें से ९ सरकार द्वारा मनोनीत और ३ असाधारणों द्वारा नियुक्तित हैं। प्रमण्डल की पूँजी और सचिव-कोष के मूल्य का पान गुना कृपा उत्तार नै सकता है। यह जमा कम-से-कम पाँच वर्ष के लिये करता है। जो औद्योगिक सम्पत्ति हमने उधार लेंगी उन्हें अपनी लाभ दर को सीमित करना होगा।

अर्थ-प्रमण्डल के कार्य—(१) अर्थ-प्रमण्डल अधिक-से-अधिक २५ वर्ष तक संयुक्त पूँजी वाली औद्योगिक कम्पनियों तथा सहकारी बैंकों को ऋण दे सकता है। (२) उनके द्वारा लिये गये दीर्घकालीन ऋणों की गारंटी करना जो अधिक-से-अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिये पूँजी-बाजार में प्राप्त किम्वं गये है (३) उनके द्वारा जारी किये गये वेंचरो, स्टॉक, डिबेंचरो (ऋण-पत्र) आदि का अधिगोपन करना। (४) उनके ऋणपत्रों की सहीदना त्रिनका भ्रुमस्तान २५ वर्ष के भीतर-भीतर होने वाला है। (५) केन्द्रीय सरकार को अनुमति ग भारतीय उद्योगों को विदेशों में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण विनवाना, प्रावि।

अर्थ-प्रमण्डल द्वारा दिया गया ऋण—प्रथम वर्ष में (१९४८-४९) अर्थ-प्रमण्डल ने उद्योगों को ३ करोड़ ४२ लाख रुपये की राशि अथवा दूसरे वर्ष में (१९४९-५०) ३ करोड़ ७७ लाख रुपये की राशि सहज्यता की। यह महज्जना ऋण के रूप में ही गई है। जिन उद्योगों को राशि सहज्यता मिली है वे इस प्रकार हैं— सूती तथा ऊनी वस्त्र उद्योग, टेल्लरमल्ल, लोहा तथा इस्पात के उद्योग धातु-उद्योग, एलुमिनियम, इंजीनियरिंग, पीपी उद्योग, खाने, रेत (कृत्रिम रेत) उद्योग रसायन उद्योग, सोमेट उद्योग, चीनी मिट्टी तथा काँच के उद्योग आदि।

निष्कर्ष—भारत के आर्थिक विकास के लिये देश में उद्योगों की उन्नति होना आवश्यक है। उद्योगों की उन्नति का एकमात्र साधन औद्योगिक बैंकों की स्थापना

है। जर्मनी के उद्योग-मन्त्र्य ऐसी बैंकों की सहायता ही से इतनी अधिक उन्नति कर सके थे। दुर्भाग्य ने भारतवर्ष में औद्योगिक बैंकों की संस्था अत्यल्प है। अतः देश की आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक बैंक का खुलना निश्चित आवश्यक है।

(ई) डाकघर के संचय बैंक (Postal Savings Banks)—जन-साधारण में मित-व्ययता (Economy) तथा संचय (Saving) की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई है। जल्दा में राशि जमा करना, उसे निकालने की सुविधा देना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट देना, जीवन बीमा-सम्बन्धी व्यवहार करना, आदि कार्य डाकघरों के संचय बैंक द्वारा किये जाते हैं। डाकघरों के संचय बैंक में किसी भी व्यक्ति के खाने में अधिक से अधिक ₹५,००० रु० जमा किये जा सकते हैं। पदाधारित महिलाएँ अपना रुपया अपने प्रतिनिधि के द्वारा जमा कर सकती हैं तथा निकाल सकती हैं। नाबालिग प्रयात् अल्पवय (Minor) के नाम पर भी सरक्षक अभिभावक (Guardian) के द्वारा खाता चला जा सकता है और जिसमें अधिक से अधिक ₹५,००० रु० जमा किये जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जमा कराये गये ₹०,००० रु० तथा मृत्युक्त नाम के खाते में जमा ₹०,००० रुपये पर व्याज प्रतिवर्ष २½% मिलता है और इससे प्राप्ति की राशि पर प्रति वर्ष २ प्रतिशत। सेविंग्स बैंक का काम करने वाले सभी डाकघरों में सप्ताह में दो बार से अधिक-से-अधिक ₹,००० रुपये निकाले जा सकते हैं। सन् १९५८ से देश के समस्त हेड एन्ड सब डाकघरों में खाते रखने वालों को बैंक से राशि विवरणवे व जमा कराने की सुविधा प्रदान कर दी गई।

देश में डाकघरों के अनुरिक्त व्यापारिक बैंक भी अधिकतर संचय बैंक का कार्य करते हैं और उनके नियमादि भी लगभग डाकघर के संचय बैंक की भांति ही होते हैं। कुछ व्यापारिक बैंक संचय बैंक खाते में से बैंक द्वारा रुपया निवासने की सुविधा भी देते हैं।

बैंक निवास गृह (Bank Clearing House) — बैंक निवास गृह वह संस्था है जिसमें किसी एक स्थान के बैंकों के पारस्परिक लेन-देन का निपटारा किया जाता है। जिस सिद्धान्त पर हमने काम होता है वह बहुत ही सरल है। प्रत्येक बैंक इसमें के बैंक और दिन से जाते हैं जिनका उसे अन्य बैंकों में भुगतान मिलना है। इनके बदले में उसे के बैंक और दिन मिलते हैं जिसका भुगतान उसे करना होता है। सन लेन-देन का समायोजन कर लेप (Balance) प्राप्त कर लिया जाता है और उसका निपटारा केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य किसी अधिकृत बंद बैंक के बैंक से कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रति दिन बैंकों में हजारों लाखों के मापको मुनताब बिना रुपये के लेन देन के ही हो जाते हैं।

लक्ष्य—(१) इस व्यवस्था में धन और समय की बचत होती है, क्योंकि बैंकों को रकम की बकूली के लिये प्रत्येक बैंक में अपना खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। (२) बैंकों को अधिक नुकद कोप नहीं रखना पड़ता है। (३) इसमें गलत दा खनन होता है। (४) सुविधानुसार भुगतान-व्यवस्था में व्यापार में उन्नति होती है। (५) बैंक के नाम में वृद्धि होती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—व्यापारिक बैंक के प्रधान कार्य क्या है ? भारत में मिश्रित पूँजी वाले अन्य कौन से बैंक कार्य कर रहे हैं ? संक्षेप में उनके प्रधान कार्य भी लिखिए ।

(उ० प्र० १९५८, ५२)

२—प्राधुनिक बैंक के साधारण कार्यों का वर्णन कीजिये । भारत की स्वदेशी साहू-कारी प्रणाली किस प्रकार विभिन्न है ? उदाहरणों से अपना उत्तर स्पष्ट कीजिये ।

(उ० प्र० १९५७, ४६, ४३)

३—भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण दीजिये ।

(उ० प्र० १९५५)

४—भारत की देशी महाजनी प्रथा का संक्षेप में वर्णन कीजिए और इसकी प्राधुनिक बंको से तुलना कीजिए ।

(रा० बो० १९६०)

५—बैंक की परिभाषा क्या है ? बैंक की विभिन्न किस्में बतसाइये और जिस प्रकार के कार्यों में वे निरतिष्ठता प्राप्त करने हैं, उनका संक्षेप वर्णन कीजिए ।

(रा० बो० १९५७)

६—भारतीय रिजर्व बैंक का विभाग तथा कार्य संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

(प्र० बो० १९६०)

७—बैंक उत्पत्ति में किम प्रकार सहायक होने हैं ? भारतीय देशी बैंकों के कार्य और महत्व स्पष्ट कीजिये ।

(रा० बो० १९५०, प्र० बो० १९५१)

८—बैंक उद्योग और व्यापार को किम प्रकार सहायता देते हैं ? क्या हमें वृत्ति, व्यापार व उद्योग की ग्राह्यता पहुँचाने के सिधे भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों की आवश्यकता होती है ? क्या ?

(प्र० बो० १९५५, ५२, ४६)

९—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ? इसके लिये व्यापार पर क्या और क्या नियन्त्रण सगे हैं ?

(म० भा० १९५४)

१०—व्यापारिक बैंक से क्या अभिप्राय है ? यह किस प्रकार उधार देता है ?

(सामर १९५१)

११—भारत में समुक्त पूँजी आने बंको और देशी बंको की तुलना कीजिए । इनमें कौनसा अधिक उपयोगी है ?

(वित्ता हा० से० १९५०)

१२—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये —

भूमि पक्का बैंक (उ० प्र० १९४८, ४२, ४०, वित्ता हा० से० १९५१)

विनिमय बैंक (रा० बो० १९५६, ५२, ४६, नागपुर १९५३)

बैंक विकास शुद्ध (प्र० बो० १९५०)

समुक्त पूँजी वाले बैंक (प्र० बो० १९४३, ४१, म० भा० १९५२)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (रा० बो० १९५१, ५०, प्र० बो० १९५४)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (प्र० बो० १९५६)

अमर्त्य लाख ऋण में जम गये हैं। ऋण में जीवन व्यतीत करने हैं और मरने समय ऋण ऋण का भार अपनी भविष्य की संतान पर छोड़ जाते हैं।^१

—भारतीय कृषि राजनीय आयोग की रिपोर्ट

परिचय—यद्यपि ग्रहणित न भारतवर्ष में कृषि की उत्पत्ति के सभी साधन पदान्ता मात्रा में प्रधान क्रिय हैं परन्तु फिर भी यहाँ की कृषि अवनत दशा में है और भारतीय कृषक स्तन नियत है कि उन्हें भरपूर भोजन भी नहीं मिल पाता। इस शास्त्रीय दशा का मुख्य कारण कृषकों की भारी ऋण घनता है। किसान मिर में पैर तब ऋण में इतना डूबा रहता है कि उन गतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना भी स्वतंत्र हो जाता है। इमानिय यह कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में पैदा हुए हैं ऋण में जीवन व्यतीत करने तथा ऋण में ही मर जाते हैं। वास्तव में दशा जाय ता किमान महाजन क कष्टों में डूबा हुआ है और यहाँ ऋण के बंधन में जकड़ी हुई है।^२ जा पैदावार मर में होती है उसका अधिकांश भाग लगान चुकाद में चला जाता है। किसान के पास खान को भी नहीं बचता। फिर भी महाजन का ऋण बढ़ता ही रहता है क्योंकि किमान स फल में समय पूरा व्याज भी नहीं चुकता। इस प्रकार किमान महाजन का प्राज्ञम प्राधिक दाम हा वना रहता है। राष्ट्रीय वणिग कमटी के अनुसार भारतीय कृषक की वार्षिक आय ८२ रु० है और उसका घौमन ऋण प्राय २५ गुना अधिक है। कृषि की उत्पत्ति करने तथा कृषक को प्राधिक उत्पत्ति के माग पर अग्रसर करने के नियम प्रावश्यक है कि किमान के ऋणों का भार कम दिया जाय और उन्हें मोत्रातिगात्र ऋणमुक्त कराया जाय।

श्रीमती की अक्षमस्त्री आबद्धवनाएँ—धन्य उद्योग यथा की भानि कृषि व्यवसाय के चरान के नियम आ पूजा या धन की आबद्धवना हानी है। भारतीय कृषक नियत हान के कारण अपनी समस्त कृषि सम्पत्ति आबद्धवनाएँ की

— Innumerable people are born in debt live in debt and die in debt passing on their burden to those who follow them

Indian Agricultural Royal Commission Report

— The Country in the grip of the Mahayan It is the bonds debts that shackle agriculture

—H Wolff Cooperation in India p 3

पुति प्रायः ऋण लेकर ही करते हैं। अतः भारतीय किसानों के ऋण निम्नांकित भागों में विभक्त किये जा सकते हैं :-

(१) अल्पकालीन ऋण—भारतीय किसान अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो थोड़े समय के लिये ऋण लेता है उसे 'मध्यकालीन ऋण' कहते हैं। उदाहरणार्थ, खाद, बीज आदि खरीदने के लिये घोर लगान व यमिकों को देतन चुकाने तथा फसल बाँटने आदि का खर्चा चुकाने के लिये अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। इसकी अवधि अधिन में अधिक ६-१० महीने होती है तथा यह प्रायः फसल के उपरान्त ही चुका दिया जाता है। अतः व्याज की दर उचित होनी चाहिये।

(२) मध्यकालीन ऋण—पशु व कृषि के भोजन खरीदने तथा माधारण तथा भूमि में सुधार करने के लिये होने वाले व्ययों के लिये जो ऋण लिया जाता है वह 'मध्यकालीन ऋण' कहलाता है। इसकी अवधि एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक होती है।

(३) दीर्घकालीन ऋण—जो ऋण लूँचे सुदवाने, भूमि में स्थायी सुधार करने, पुराने ऋण चुकाने, भूमि खरीदने आदि कार्यों के लिये लिया जाता है वह 'दीर्घकालीन ऋण' कहलाता है। इसकी अवधि ५ से २० वर्ष तक की होती है।

विभिन्न ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन—भारत में ग्रामीणों को ऋण देने के लिये महाजन या माहूजार्, देशी बैंकर, सरकार, सहकारी माग समितियाँ, भूमि-बन्धक बैंक, श्वसार्थक बैंक, रिजर्व बैंक आदि सम्मान हैं। भारतीय किसान अपनी आवश्यकताओं का अधिकतम भाग गाँव के महाजन या माहूजार् से ऋण लेकर पूरा करता है। सरकार द्वारा उक्त तत्वाधी के रूप में ऋण मिलता है। गृहकारी सार समितियों द्वारा भी ग्रामीणों को ऋण की सुविधाएँ प्राप्त हैं। रिजर्व बैंक भी किसानों को ऋण देता है परन्तु यह अप्रचालित है। इनमें बंधक की वजह से अल्प तथा मध्यकालीन ऋणों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, परन्तु दीर्घकालीन ऋण के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। अतः भूमि बन्धक बैंकों के विकास एवं प्रसार में दीर्घकालीन ऋण की समस्या बहुत कुछ हल की जा सकती है।

ग्राम्य ऋण का रूप (Nature of Rural Indebtedness)—किसान को अपने उत्पादक (Productive) तथा अनुत्पादक (Unproductive) मामों के लिये ऋण लेना पड़ता है। किसान अपने उत्पादक-कार्यों के लिये बहुत ही थोड़ा ऋण लेता है। अनुमान लगाया गया है कि सम्पूर्ण ऋण का ३०% उत्पादक ऋण है, शेष ७०% अनुत्पादक ऋण है जो किसान द्वारा प्रायः विवाह, मृत्यु-भोज, आदि सामाजिक मामों के लिये लिया जाता है। डार्लिंग (Darling) का अनुमान था कि पंजाब के ऋण में से केवल २% भूमि सुधार के लिये व्यय किया गया था और अन्य स्थानों के विषय में भी यही अनुमान था।

उत्पादक मामों के लिये तो उक्त ऋण बैंकों आदि से मिल जाता है परन्तु अनुत्पादक-कार्यों के लिये उन्हे महाजनों, माहूजार् और गानुनियों आदि का गृहकार लेना पड़ता है। ये लोग कभी-कभी १००% से ४००% तक व्याज लेते हैं। इस प्रकार से भूलभन तो धोखा ही होता है परन्तु व्याज भुनघन से बड़े ठुना आगे बढ़ जाता है, और वे कई पीढ़ियों तक इस ऋण के बोध को ढोते रहते हैं।

ग्राम्य ऋण का अनुमान—भारतवर्ष में ग्राम्य ऋण की मात्रा का अनुमान नई बार लगाया जा चुका है। परन्तु यह सब अनुमान मात्र ही है वास्तविक स्थिति अभी भी प्राप्त नहीं हो सके हैं।

(१) सर्व प्रथम सन् १८७१ ई० में (Deccan Riots Commission) ने ग्राम्य ऋण की समस्या पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(२) सन् १८८० व १८८१ में दमिष्ट आयोग (Famine Commission) ने बताया कि लगभग एक तिहाई से अधिक किसान ऋण व सोहरे स्वी प्रियता में जड़ हुए हैं।

(३) सन् १८८४ में सर फ्रैंक निकोलसन (Sir F. Nicolson) ने अनुमान लगाया कि राष्ट्रीय ऋण में ग्राम्य ऋण की मात्रा ४४ करोड़ रुपये के लगभग थी।

(४) सन् १८९१ में सर एडवर्ड मकलन (Sir E. MacLagan) ने सम्पूर्ण ब्रिटिश इण्डिया में ग्राम्य ऋण का अनुमान ३०० करोड़ के लगभग बताया।

(५) सन् १८९४ में सर एम० ए०० डार्लिंग (Sir M. L. Darling) ने ग्राम्य ऋण की मात्रा ६०० करोड़ रुपये बताई।

(६) सन् १९०० में भारतीय केन्द्रीय जाच कमेटी (Central Banking Enquiry Comm.) का रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग १०० करोड़ रुपये था।

(७) सन् १९२४ में श्री स्वामीनाथन ने मद्रास का ऋण २०० करोड़ रुपये के लगभग आका था।

(८) सन् १९२३ में डाक्टर रामास्वमि मुकुर्जी ने मद्रासुसार यह १२०० करोड़ रखा था।

(९) सन् १९३७ में रिजर्व बैंक के कृषि साम्प्रदायिक विभाग ने खोजबीन करके निश्चय किया कि ग्रामीण ऋण १८०० करोड़ रुपये के लगभग था।

(१०) सन् १९३८ में मनम (E. V. S. Mainam) ने अनुमान यह १८०० करोड़ रुपये के लगभग था।

(११) सन् १९४१ में डाक्टर पी० जे० थॉमस (Dr P. J. Thomas) के अनुमान पर ग्राम्य ऋण की मात्रा ६००० करोड़ रुपये थी।

(१२) सन् १९४३ में कृषि ऋण प्रगतिता उप समिति ने अनुमान लगाया था कि ग्रामीण ऋण लगभग ८२५ करोड़ रुपये का रह गया है।

(१३) द्वितीय महायुद्ध के बाद यह ऋण धीरे-धीरे घटने में कम हो गया और यह अनुमान लगाया जाता है कि ऋण की मात्रा आधे से कम लगभग ५०० करोड़ रुपये ही है।

इन अन्वेषणों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण ऋण घटने में निश्चय ही कम हो गया है। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् ग्राम्य ऋणों के साथ साथ कृषि उपज में भी प्रायः वृद्धि हुई। वृद्धि होने पर ग्रामीणों के पास होने लगे हैं नष्ट रह गये हैं युद्धोत्तर काल में भी यही परिस्थिति है। इससे कृषकों की अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलने लगा और यद्यपि पुराने ऋण के कुछ भाग को चुकाने में समर्थ हो सके हैं। कुछ विद्वानों की यह भी धारणा है कि सहकारी आन्दोलन के कारण ऋण का भार कुछ कम हो गया है। भारतवर्ष में सह

कारिता मान्योलन की प्रगति प्राप्तातीव नहीं है, इसलिये ऋण के भार से कम होने वा सारा यश इनको नहीं मिल सकता ।

ग्राम्य ऋण के कारण (Causes of Rural Indebtedness)—
भारतवर्ष में ग्राम्य ऋण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

१. पतृक-ऋण—भारतीय ग्राम्य-ऋण की यह विशेषता है कि पिता का ऋण उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों पर चला जाता है । जनता को यह धारणा है कि यदि कोई मनुष्य ऋणी अवस्था में मरता है तो उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलती, अस्तु, मृतक पुरुष की सन्तान भगना धार्मिक कर्त्तव्य समझती है कि पतृक ऋण अवश्य चुकाया जाय । इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र के ऊपर ऋण का भार छोड़ जाता है इसीलिये कहा जाता है कि “भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है तथा ऋण में ही मरता है और ऋण का भार अपनी सन्तान पर छोड़ जाता है ।”

२. भूमि पर जन-सहया का दबाव—भाजक जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ाती जा रही है । किसानों का एक मात्र साधन ज़मीन करना होने के फलस्वरूप अत्यधिक परिवार सेतों की भाँति वे ही अपना भरण पोषण करते हैं । ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, तथापि भूमि पर अधिक दबाव पड़ता जाता है अर्थात् किसानों की आय कम होने में परिवार का सर्वा नहीं चल पाता और निम्न किसानों को विवश होकर ऋण लेना पड़ता है ।

३. सेतों का उग्र विभाजन एवं अपखण्डन—छोटे-छोटे एवं छिटके हुए सेत होने के कारण किसान प्राथमिक किसानों के दम प्रयोग में नहीं ला सकते । परिणाम यह होता है कि किसानों की आय बहुत कम हो जाती है जिससे परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो जाता है । ऐसी अवस्था में विवश होकर महाजन से ऋण लेना आवश्यक हो जाता है ।

४. ज़मीनों की अनिश्चितता—भारतवर्ष में ज़मीनी का काम ज़ुए वा चेल है । कभी वर्षा कम होती है जिससे फसल पड़ जाती है, कभी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं और कभी टिड्डियाँ ज़मीनी साफ कर देती हैं । किसानों को अपने जीवन निर्वह के लिये ऋण लेने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता ।

५. ज़मीनी की कम उपज—भारतीय कृषक के पास पर्याप्त भूमि नहीं है । जो कुछ भूमि है वह छोटे-छोटे और बिसरे हुए सेतों में है । अस्तु, गहरी सेतों नहीं हो सकती और उपज कम होती है । कम उपज होने के कारण किसानों की सब आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती और उसे विवश होकर ऋण लेना पड़ता है ।

६. पशुओं की मृत्यु—प्रकाश तथा बीमारी के कारण ज़मीनी के पशुओं की प्रकाश मृत्यु होने में किसानों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है और उसे बस प्रायः सरीसरे के लिये ऋण लेने के लिये बाध्य होना पड़ता है ।

७. पुराने ढंग के कृषि-यन्त्रादि—भारतवर्ष में जैसे प्राचीन एवं घने-घने ढंग के देश में पुराने औजारों से गहरी सेतों सत्ता नहीं की जा सकती । बिना सत्ता ज़मीनी के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता ।

८. **अच्छ और उत्तम धागा के जोड़**—सती की उपज में वृद्धि करने के लिये अच्छे और उत्तम बीजा का प्रयोग आवश्यक है। सती की उपज कम होने पर किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होना स्वाभाविक है।

९. **किमाना का दुःख स्वास्थ्य**—सती के समय किमान प्रायः मारिया प्रादि बीमारियाँ में ग्रस्त रहते हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनकी लायकता में ह्रास होने से किमान पूरा काम नहीं कर सकता जिससे ग्राम में धान कमो हो जाता है।

१०. **महायक उद्यान घाटा का अभाव**—किमान प्रायः वर्ष भर में ६ या ७ महायक प्रकार रहते हैं उस अवकाश के समय में वह कुछ काम करके अपना समय बर्बाद करते हैं किन्तु धान उद्यान घाटा के कारण उनका साथ कम रहती है और यदि नाई के समय उन्हें काम देना पड़ता है।

११. **ग्राम्य साक्षर संगठन का अभाव**—आजकल भास महात्मा समिति का जतनी कमा है कि किमान का विनाश होकर महाजन के पास जाना पड़ता है। महाजन किमान का एक बार बहुत में लिये बाद करने ही कठिनाई में निरन्तर देता है।

१२. **व्याज का ऊँची दर**—विशाल को जब काम नहीं पड़ता है वह धागा पीछा नहीं रखता और वह धाधिक मध्याह्न व्याज देने का तयार हो जाता है। जागतिक महाजन किमान की नियन्त्रिता तथा विनियमिता का पूरा काम जाता है और ऊँची व्याज का दर पर चलता है।

१३. **मुहदमवाजा**—भूमि तथा जल के कारण प्रायः कुछ मुहदमवाजी में काम चलता है। कभी कभी साम्प्रतिक बन्धु के कारण भी पीड़ितता हो जाती है और वे जाग बन्धु की पंथ चलते हैं। मुहदमवाजा में उन्हें काम देना पड़ता है। इस लक्ष का वे काम तब पूरा करते हैं।

१४. **किमान की पिछुनगी**—कभी कभी किमान बहुत में निरक्षरता होता है और धान खेत में खेद मूला रह कर हा समय निवान देता है परन्तु विवाह मृत्यु मोह आदि सामाजिक समारोह के अवसर पर वह श्रम तथा सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिये धान परियोजना के साथ ही काम करेगा और धान के निरक्षर तयार हो जाता है। वह इन अवसर पर अपने सामान्य के सहित खेद कर देता है जिसके कारण उन काम होना पड़ता है।

१५. **मजदूर का जमान नानि**—भारत में जपि का अवस्था खराब है (यह मजदूर में पुनः) जमान अधिक है और मजदूर में बहुत कृपा जाता है। जमान खराब हो जाने पर उन निरक्षर मजदूरों जमान खराब के निरक्षर होना पड़ता है। ऐसा अवमान किया गया है कि प्रायः वर्ष में एक जमान खराब होने से २ जमान साधारण होती है और १ खराब होता है। यही जमान होने पर उस इतना ही मिलता है जितना उस जीवन रखने के लिये आवश्यक है और जमान खराब होने पर दूसरा का कृपावान रहना पड़ता है।^१

१६. **कृषि का पवित्रित अवस्था**—जिसमें मजदूर के म्यापित होने पर मातापिता के व्यापार में वृद्धि हुई जिसके कारण भूमि का मूल्य बढ़ गया। भूमि का

मूल्य बढ़ जाने से किसान भी अपनी भूमि को धरोहर के रूप में रखकर अधिक ऋण लेने में समर्थ हो गये। आजकल सब वस्तुओं के भावों में वृद्धि हो जाने से भूमि का मूल्य भी बढ़ा हुआ है। इस कारण से किसान की अधिक ऋण मिल जाता है।

१७ महाजन और उसके दण्ड—महाजनों के कूट हिंसात्मक तथा मनकारियों के कारण भी किसान ऋण-ग्रस्तता के कुबज्र से नहीं छूट पाते। महाजन १०० ६० करण देकर २०० ६० का रुकवा लिखवा लेता है। कभी कभी फीरे स्क्वे गर ही निशानी मेंगूठा बनवा देता है, बहुधा किसान के दिव्य हुए रूपसे हिंसात्मक व्यवहार नहीं करता। बहो घाते में झूठी रकम नाम लिख देता है। इस प्रकार किसान ऋण के चक्र में नहीं निकल पाता।

१८ आशिक्षा—अधिकांश किसान अशिक्षित होते हैं। अतः वे शीघ्र ही महाजन क घोवे में घा जाते हैं और उनकी राय के अनुसार मुकदमबाजी तथा सामाजिक रीति रियाज पर किञ्चलतर्कों कर बैठते हैं जिससे ऋण लेने की आवश्यकता सदैव बढ़ती रहती है।

१९ ऋण मिलने की सुगमता—महाजन ने किसान ऋण की भी मगय विना कागजी नामवाही के सुगम प्राप्त कर सकता है जबकि सहकारी मास्त समितियों में सही कगिनाई व कागजी समय के बाद प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा उसे सर्व्व महाजन का ऋणी बनाय रखने का प्रोत्साहन देती है।

ऋण प्रस्तता क टायरिणाम (Debt of Indebtedness)—ऋण प्रस्तता का किसान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। (१) यह सदैव इस चिन्ता में डूबा रहता है कि ऋण को कम चुकाये। इस कारण धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसकी कार्य कुशलता नष्ट हो जाती है। (२) उसको इस बात की कोई चिन्ता नहीं रहती कि वह अपनी उलाति बढ़ाये क्योंकि वह जानता है कि वह जो भा उपन करेगा वह उसके पाम नहीं रहगा। अपने परिश्रम का फल न चखने के कारण वह निराशावादी हो जाता है। (३) ऋणी होने के कारण किसान अपनी पत्नी को उचित स्थान, समय और मूल्य पर नडा देय सकता। उसको अपनी फसल गाय के महाजन को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। इस प्रकार भूमि का बहुत-सा भाग महाजनों के हाथ में चला जाता है और किसान भूमि रहित बनकर बन जाता है। सन् १९२१-२२ के बीच दत्त प्रकार के भूमि रहित भनूरा की सक्या २६१ प्रति हजार से बढ़कर ४०७ प्रति हजार हो गई थी। (४) ऋण के दबाव के कारण किसान को महाजन के कई काम निगुलक करने पड़ते हैं। वह अपने को उससे सामने बहुत छोटा समझता है। एक प्रकार से किसान महाजन का दाघ बना रहता है और इस कारण उसका नैतिक पतन हो जाता है। (५) ऋण प्रस्तता के कारण किसान सर्व्व निधन रहता है और उससे रहन-गहन में कोई उन्नति नहीं हो सकती।

ग्राम्य ऋण-प्रस्तता की समस्या का निराकरण (Solution of the Problem of Rural indebtedness)—ग्राम्य ऋण प्रस्तता की समस्या का विवरण दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(अ) दुखने में डूबकर रहने वाले की समस्या और (ब) नया या भावी ऋण की समस्या।

१— In good years the Cultivator has nothing to hope for except bare subsistence and in bad years he falls on public charity

—Famine Commission, 1901

(अ) पुराने या भूतकाल के ऋण का समस्या का निराकरण

१ भूमि-वधक बैंक (Land Mortgage Banks)—यूयका का अधिकांश ऋण पुराना तथा फलन है। पुन अपने पिता के लिए हुए ऋण को चुकाना अपना परम कर्तव्य समझता है और उसका यह विश्वास होता है कि यदि वह उनका ऋण नहीं चुकाएगा तो वे नरकगामी होंगे। ऋण चक्रवृद्धि व्याज में इतना बढ़ जाता है कि उनके लिए ऋण का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः ऋण पिता ने पुत्र को हस्तांतरित होता रहता है। इस विधा में सहकारिता के आधार पर स्थापित भूमि-वधक बैंक का उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। य बैंक भूमि गिरवी रखकर एवं लम्बे समय के लिए ऋण देते हैं जिसमें पुराने एवं फलन ऋण चुकाना सुविधा मिल जाती है। परन्तु इन बैंकों में केवल वे ही लोग लाभ उठा सकते हैं जिनके पास गिरवी रखने की भूमि होती है अन्य नहीं।

२ सरकारी कानून—विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने शामिल ऋण को घटाने के लिए समय समय पर कई कानून पास किये। सबसे पहला प्रांतीय ऋण को भौतिकता का ध्यान रख १८७५-६० में दक्षिण में चलने कीमती में शामिल किया क्योंकि उसमें कई स्थानों पर किसानों ने महाजनों को पार जाना और उनके बहीखाने जला डार। उक्त कीमती ने महाजनों का मूढ़ को ऊँची दर सेना सबसे बुरा कारण बताया था।

(क) प्रांतीय ऋण का भार कम करने के लिये कई कानून पास किये गये। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में सन् १८७६ में (Agriculturist Relief Act) पास किया गया जिसके अनुसार कोई भी किसान ऋण न देने पर जेल नहीं भेजा जा सकता तथा कोई भी साहूकार अधिक व्याज की दर नहीं लगा सके। इसी प्रकार कीमती ऋण कानून (Usurious Loans Act) पास किया गया। इस कानून के अनुसार सरकार द्वारा अधिक-पछिक व्याज की दर निर्धारित कर दी जाती है। सरकार व्याज की दर को घटा भी सकती है। यह कानून पश्चिमी बंगाल भारत में प्रथम प्रदेश पूर्वी पंजाब उत्तर प्रदेश मद्रास बिहार आदि में कुछ संशोधन के साथ पास किया गया। पंजाब के भूमि-हस्तान्तरण ऐक्ट (Punjab Land Alienation Act) के अनुसार पंजाब में किसानों की भूमि ग्रहणकर्ता के पास सन् १९०० से नहीं जा सकती तथा सन् १९३६ में यह कृषक-महाजनों के पास भी नहीं जा सकती है।

(ख) किसानों का कम व्याज पर ऋण मिलने की सुविधा देने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कानून पास किए गए।

(१) तवाबी ऋण के कानून १८७१-७६-७६ में (Taqavi Act in 1871-76-79)

(२) भूमि सुधार के लिए ऋण देने के लिए कानून १८८३ (Land Improvement Loans Act 1883)

(३) किसानों को ऋण देने का कानून १८८४ (Agriculturist Loans Act 1884)

इनमें से पहले दो कानूनों ने अन्तर्गत भूमि के स्थायी सुधार के लिए सरकार सरती व्याज दर पर कई वर्षों के लिए ऋण देती है तथा दूसरे कानून के अनुसार उत्पादन बार्थों के लिए मोड समय के लिए कम व्याज पर ऋण दिया जाता है।

(४) सरकार ने सन् १९०४ में सहकारी समितियों का कानून भी पास किया जिसके अन्तर्गत ग्राम्य की दीधकासीन सर्वादा पुराने ऋण को चुकाने तथा भूमि पर स्थायी सुधार करने के हेतु भूमि-वचन बैंक खोले गये हैं तथा ग्राम्य की अल्पकालीन आवश्यकता पूर्ण करने के लिए सहकारी साधन समितियाँ कार्य कर रही हैं।

(५) महाजन को ऋण देने की दूषित कार्य प्रणाली को रोकने के लिये निम्न कानून पास किये गये।

(१) पंजाब का हिसाबा को नियमित रूप में रखने का कानून १९३० (Punjab Regulation of Accounts Act 1930)

(२) बम्बई का साहूकार सम्बन्धी कानून १९३८ (Bombay Money lenders Act 1938)।

(३) उत्तर प्रदेश का साहूकार सम्बन्धी कानून १९३४ (U P Money lenders Act 1934)

इन प्रान्तों के अतिरिक्त पंजाब, मध्य प्रदेश, आसम, मद्रास, बिहार व उड़ीसा में भी कानून पास किये गये हैं। इन कानूनों के अन्तर्गत साहूकारों या महाजनों को रजिस्ट्री कराना व लाइसेन्स (प्रमुखा पत्र) लेना, नियत व्याज और निर्धारित विधि में हिसाब-किताब रखने के लिए बाध्य किया जाता है।

(६) राज्य-सरकारों ने ऋण समझौता कानून (Debt Conciliation Acts) भी पास किये हैं। इन सम्बन्ध में C. P. Debt Conciliation Act 1933 Punjab Relief of Indebtedness Act 1934, Bengal Agricultural Debtors Act 1935, Assam Debt Conciliation Act 1935 Debt Reconciliation Act Madras 1936 पास हो चुके हैं। कई स्थानों में येन मिलान समितियाँ (Conciliation Boards) भी स्थापित किये गये हैं।

(७) कई प्रान्तों में कानून के द्वारा किसानों के ऋण में अनिवार्य रूप से कमी करने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में Madras Agriculturist Relief Act 1938, C. P. & Berar Relief of Indebtedness Act 1939, Bombay Agricultural Debtors Relief Act 1939, U P. Agriculturist Debt Redemption Act 1939 पास किये गये हैं। इनके अन्तर्गत ग्राहकताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऋणदाता को धूल के दुगम में अभिन राशि नहीं दिसतावेगे अर्थात् दमदुपट (Damdapat) नियम लागू किया जावेगा। इनके अतिरिक्त ऋणदाताओं को राशि में कमी करने तथा व्याज का हारा व निर्धारण में भी अधिकार दिये गये हैं।

(८) कानून जाब्ता दोबानी (Civil Procedure Code) में सुधार— इन कानूनों में संशोधन किया गया है जिसमें अनुसार किसान के अधिकार, सनो के अनुसार की दुरी तथा विशेष नहीं हो सकनी और किसान सम्बन्धी को नई नहीं दिया जाता और उसकी विस्तार द्वारा ऋण चुकाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

३. **मृत्यु दण्ड की अवधि में वृद्धि करने का कानून (Moratorium Laws)**—मृत्यु दण्ड की अवधि में वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम सन् १९३४ में उत्तर प्रदेश में U P Temporary Regulation of Execution Act पास किया गया। तदनन्तर मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रान्तों में भी इस प्रकार के कानून पास किये गये। इन कानूनों से अन्तर्गत इजिक्शिया की इजराय (Execution) को स्थगित कराने का अधिकार किमाना को प्राप्त हो गया।

(आ) नये या भावी मृत्यु की समस्या

१. **मृत्यु लेने वाले पर नियन्त्रण**—साधु देखा जाता है कि बिना अनुसादन कार्यों के लिए अर्थात् बिना किसी उत्तम या पर्याप्त धन उधार ले जाता है। अतः निम्न साधना द्वारा यह ऐसा करने में रोक जा सकता है।

(क) शिक्षा एवं प्रचार—शामीणों के लिए कम से कम प्राथमरी शिक्षा का प्रबन्ध व्यवस्था होना चाहिए। प्रचार (Propaganda) द्वारा वृषका के अनुसादन मृत्यु में भारी कमी की जा सकती है।

(ख) गणानुसंधान करना—सर्वप्रथम वाले वर्षों में गणानुसंधान कर दिया जाय।

(ग) डाकघर सचय धन का स्थापना—सर्वप्रथम डाकघर सचय धन स्थापित किया जाये जो गाँवों में निम्न-व्ययता का प्रचार करें।

(घ) सुव्यवस्थित रहन-सहन का प्रचार—शामीण समाज में सुव्यवस्थित रहन-सहन का प्रचार किया जाय।

(२) **मृत्युदाता पर नियन्त्रण**—मृत्युदाता का नियन्त्रण भी उन्मत्त की आवश्यकता है जिससे कि मृत्यु लेने वाले का। साहजिकीय व लोभ आदिगम प्राप्त करना आवश्यक करने के परिणामित मृत्युदाता के विचार-विचार तथा उनकी व्याख्या पर भी नियन्त्रण करना आवश्यक है। कई राज्यों में मृत्युदाता के नियन्त्रण का कानून भी पास कर दिया गये है।

३. **मृत्यु नियन्त्रण**—मृत्युदाता द्वारा मृत्यु का घोषण तथा उनका पुत्र पट्टावत का प्रदर्शन दण्डनीय सम्भवा जाता चाहिए। मध्य प्रदेश बम्बई बंगाल तथा उत्तर प्रदेश आदि में ऐम कानून बना दिया गये है कि यदि कोई मृत्युदाता मृत्यु का घोषण करने या उसका कष्ट पट्टावत की चप्टा करेगा तो उस व्यक्ति दण्ड दिया जायगा।

योजना और शामीण मृत्यु—शामीण सहकारी मृत्यु आन्दोलन द्वारा इस प्रकार उन्मत्तनीय प्रवृत्ति को मथी है कि उसका २०० करोड़ १० का जो निर्धारित लक्ष्य है वह विना पंचवर्षीय योजना बनने से अतः से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायगा।

१९२०-२१ की तुलना में गाँवों में प्रस्तावित मध्यम से अल्पवर्षीय मृत्युओं में लगभग ५०० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। १९५८-५९ के विषय में मध्य निर्धारित किया गया है उस वर्ष करके १५० करोड़ २० कर दिया जायगा। १९५७-५८ में सहकारी द्वारा मृत्यु की संख्या १०० करोड़ तक हो जायेगी।

निष्कर्ष—ग्राम्य ऋण समस्या को हल करने के लिये समय-समय पर बहुत-से प्रयत्न किये गये हैं पर अभी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। नाना प्रकार के नियंत्रण के लगाये जाने के कारण गाँव के महाजना ने कृषकों को ऋण देना बंद सा कर दिया है और उधर सहकारी माध्यम समितियाँ का अस्तित्व है। भारत सरकार ने किसानों की इस आवश्यकता को पूर्ण के लिये ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति गैडगिल कमिशन और कृषि सुधार-समिति नियुक्त की थी। इन समितियों का विचार था कि भूमि वधक बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा हो किसानों के दीर्घकालीन मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋणों का प्रयत्न कराया जाना चाहिए। गैडगिल समिशन ने कृषि साख बॉर्पोरेशन (Agricultural Credit Corporation) स्थापित करने का सुझाव भी दिया था। वर्तमान सरकार ने कृषि साख समिती के लिये नानावटी समिति की नियुक्ति की। सहकारी साख समितियाँ यदि कृषकों की कमल की वित्त की कार्य भी अपने हाथ में ले लें तो कृषकों की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सकती है तथा ऋण की मात्रा में भी घटो हो सकती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारतवर्ष में किसानों के ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के वर्तमान माध्यामों का विवेचन कीजिये। उनमें उत्तरी के लिये आप क्या सुझाव दे सकते हैं ?
- २—भारत में ऋण प्रणाली के क्या कारण हैं ? सहकारी माध्यम-समितियाँ ने इस समस्या का कहीं समाधान किया है ? (रा० बो० १९४६, म० बो० १९४९, ४६)
- ३—ऋणदानों का नाश हो' क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? कारण सहित उत्तर दीजिए। (रा० बो० १९४७)
- ४—भारतीय कृषकों की दृष्टि के क्या कारण हैं ? दृष्टिगत निवारणों का सुझाव दीजिए। (लागपुर १९४५, सागर १९४७)
- ५—भारत में ऋण श्रुतिता के कारणों का वर्णन कीजिये और उन्हें हल करने के उपाय बताइयें। (सागर १९४१)
- ६—भारत के ग्रामीण ऋण भार से आप क्या समझते हैं ? उसके व्यापार पर क्या नियंत्रण लग है ? क्या आप समझते हैं कि किसानों ने वसंत वर्षों में अपना ऋण भार घटा लिया है ? (म० बो० १९४४)

सहकारिता आन्दोलन (Cooperative Movement)

“यदि सहकारिता अमफल होनी है, तो ग्रामीण भारत की सर्वोच्च प्राप्ति भी अमफल हो जावेगी।”
—भारतीय कृषि राजकीय आयोग

परिचय (Introduction)—सहकारिता न पूँजीवाद है और न साम्यवाद है। यह इन दोनों के मध्य एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें पूँजीवाद के सब दुर्गुण दूर करते हुए समाजवाद के सब गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिये आज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहकारिता ध्वज-नन्ध हो गये हैं। यह निर्वर्तनीय का बल है, असहयोग का सहायक है, और निर्धनता का घन है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि सहकारिता आन्दोलन निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों के लिये होता है। इसमें वे सब लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों अथवा जिनको पूँजी-पतियों द्वारा लूटे जाने की घातका हो एक साथ मिल जाता है और कुछ घन एकत्रित करते हैं। इस घन में तब संगठन के बल पर अर्थ द्वारा प्राप्त किये हुए और घन से वे अपनी आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार अपनी योग्यतानुसार अपना पूर्ण विकास करते हैं। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जापान और जर्मनी तथा चीन ने जो महान् उन्नति की है वह सहकारिता, आन्दोलन के फलस्वरूप ही मुख्यवस्तुतः रूप में सम्भव हो सकी है। निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि सहकारिता आज राष्ट्रीय की रीढ़ है।

सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा—सहकारिता आन्दोलन का मुख्य सिद्धान्त पारस्परिक सहयोग तथा मदभावना है। अतः सहकारिता वह संगठन है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति स्वच्छ से संगठित होकर सर्वोत्तम के लिये सम्मिलित कार्य करते हैं। सहकारिता में स्वार्थ का स्थान सहयोग में होता है। अन्य वस्तु में, अपनी सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समान स्तर पर मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के ऐच्छिक संगठन को ही सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का आर्थिक अर्थ प्राप्त में मिल-जुलकर काम करना है, किन्तु अर्थशास्त्र में इसका व्यापक उक्त संगठन में होता है जिसमें पारस्परिक सहयोग ऐच्छिक है, सदस्यों का दर्जा बराबरी का है और उनका उद्देश्य किसी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना

¹ “If Cooperation fails, there will fail the best hope of rural India.”
—Report of Royal Commission on Agriculture.

का मुख्य उद्देश्य मध्यजनों (Middleman) का लोप करना और स्पर्धा की इतिशो करना है ।

सैलिगमैन (Seligman) के अनुसार सहकारिता का विशिष्ट अर्थ वितरण व उत्पन्न वन में स्पर्धा का अभाव तथा समस्त प्रकार के मध्यजनों के लोप से है ।^१ दूसरे, स्ट्रकलैंड (Stuckland) कहते हैं कि व्यक्तियों का प्रत्येक समूह जो समुक्त प्रयत्न द्वारा सर्वहित के लिए एक दूसरे से मिलता है, सहयोग देते हुए बहलाता है ।

सहकारिता की विशेषताएँ (Characteristics)—सहकारिता की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) सहयोग ऐच्छिक (Voluntary) होता है । (२) सदस्यों का दर्जा बराबरी का होता है । (३) इसका उद्देश्य किसी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना होता है । (४) आर्थिक विकास के साथ साथ इसमें नैतिक विकास पर भी उतना ही महत्त्व दिया जाता है । (५) इसमें गतिव्यवस्था, सहयोग, और सहृदयता आदि गुणों की पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है । (६) यह समूह जनतन्त्रात्मक होता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य को इसकी व्यवस्थापन में समान अधिकार होता है । (७) सहकारिता में शिक्षा सम्बन्धी प्रभाव को अधिक महत्त्व दिया जाता है ।

सहकारिता का प्रादुर्भाव—सहकारिता आन्दोलन का जन्म प्राधुनिक युग में से सबसे पहले पश्चिम में हुआ । १९ वीं शताब्दी में मध्य भाग में जर्मनी के दो राज-रोशन व्यक्ति रैफ़िजन (Raffesjen) और शुल्ज़ डेलिज़ (Schulze Delitzsch) इस आन्दोलन के नेता थे । उस समय जर्मनी के किसान और कारीगर साहूकारों के शिकार थे और उनकी दशा निर्धनता के कारण दयनीय थी । इस अवस्था को देखकर ये नेतागण बड़ दुःखी हुए और उन्होंने सहकारी समितियाँ खोलकर उनकी अवस्था में सुधार करने की चेष्टा की । रैफ़िजन महोदय ने छोटे छोटे शिमाओं की सहायता के लिये ग्रामीण सहकारी साक्ष समितियाँ स्थापित की और शुल्ज़ डेलिज़ ने छोटे छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की सहायता के लिये सहकारी-साक्ष समितियाँ खोलीं । समार में सहकारिता की सबसे अधिक उत्पत्ति जर्मनी और डेनमार्क में हुई है । भारतवर्ष में सहकारिता का सिद्धान्त तो बहुत प्राचीन काल से ही चलता रहा है । प्राचीन काल में राम पचायते और निधियाँ इसके प्रमाण हैं किन्तु अर्वाचीन अर्थ में इस आन्दोलन का सूत्रपात २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हुआ । हमारे देश में भी सहकारी भास्त्र-समितियों का निर्माण रैफ़िजन और शुल्ज़ डेलिज़ के सिद्धान्त पर ही हुआ है, अतः हमें इन दोनों की विशेषताओं को जान लेना चाहिये ।

रैफ़िजन समितियाँ (Raiffesen Societies)—श्री रैफ़िजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बण्णों की साहूकारों के पक्ष में मुक्त करने के लिये ग्राम्य सहकारी साक्ष समितियों को जन्म दिया । इन समितियों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

1—' Co operation in its technical sence, means abandonment of Competition in distribution and production and the elimination of middlemen of all kinds ”
—Seligman

(१) इन समितियों का कार्य क्षत्र सामित होता है। (२) कार्य-क्षेत्र सीमित होने से सदस्या में पारस्परिक जानकारी एवं व्यक्तिगत सम्पर्क होता है। (३) यश या श्रेष्ठता नहीं होने और पूँजी बहुत कम होती है। (४) उत्तरदायित्व प्रामोदित होता है। (५) ऋण केवल उत्पादन कार्यों के लिये ही व्यक्तिगत साधन पर दिया जाता है। यह छोटी-छोटी किराया भर्त्ता वर्षों में वापस लिया जाता है। (६) ऋण असदस्या का नहीं दिया जाता। (७) लाभ बाँटा नहीं जाता बल्कि एक रिजर्व कोष में जमा लिया जाता है तथा उदात्त सामाजिक हित के लिये व्यय किया जाता है। (८) प्रयत्न निःशुल्क होता है, केवल मजदूरी (मक टरी) को वेतन दिया जाता है। (९) इस सम्स्था का प्रबंध लोक-तन्त्रात्मक होता है और प्रबंधका का चुनाव सभी सदस्य मिलकर करते हैं। (१०) इस प्रकार का समिति-प्रकार उद्देश्य प्राप्ति के लिये नैतिक एवं आर्थिक उन्नति करता है। (११) प्रतिपक्ष एक साधारण मता होती है जिसका पक्षधरिता का चुनाव लिया जाता है तथा ऋण सम्बन्धी बातें निश्चित की जाती हैं। (१२) यह सम्स्था बाँटा के लिए विद्यमान उपयुक्त है।

शुल्ज डेलिज समितिया (Schulze Delitzsch)—यह शुल्ज डेलिज द्वारा शहर में रहने वाले छोटे छोटे नारीयों और गृहमाध्या को सहयोगार्थ गृहरी साधन समितियों का जन्म मिला। इन समितियों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) इनका कार्य-क्षेत्र स्थित होता है। (२) इनका कार्य-क्षेत्र विस्तृत होने से व्यक्तिगत सम्पर्क का सम्भाव होता है। (३) इन सम्स्थाओं के अर्थ या नगर होने हैं और पूँजी भी होती है। (४) उत्तरदायित्व सीमित और प्रामोदित दोनों प्रकार का होता है। (५) ऋण असदस्या का भी दिया जा सकता है। (६) लाभ का कुछ भाग रिजर्व कोष में जमा कर शेष लाभ प्रबंधधरिता का बाँट दिया जाता है। (७) यह सम्थायें थोड़े समय के लिये उधार देती हैं। (८) प्रबंधका को अपने कार्य के लिये वेतन दिया जाता है। (९) यह सम्स्था एक निरन्तर समितियों का भाँति नैतिक उन्नति पर जगता बल नहीं देती। इनका कार्य व्यापारिक दृष्टि से चलता है। (१०) ऋण उत्पादन तथा उप-भोग दोनों के लिये उत्तम प्रतिभूतियाँ का आधार पर दिया जाता है। (११) यह सम्थायें प्रायः छोटे-छोटे निरन्तरता तथा व्यवसायिकाओं को ऋण देने के लिये सोना देती हैं। (१२) यह नगर में गृहरी व लिये विशेष उपयुक्त है।

भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन

(On operative Movement in India)

प्रारम्भिक प्रयत्न—भारत में ग्रामीण ऋण समस्या को सुलझाने तथा भारतीय क्षुब्ध को उन्नत करने के उद्देश्य से प्रेरित सर विलियम वेड्डरबर्न (Sir William Wedderburn) तथा जस्टिस महादेव गाँविक रामाट में भारत में सहकारिता आन्दोलन का प्रथम सुझाव सन् १८८२ में प्रस्तुत किया था। इनकी दृष्टि-शेका (Agricultural Banks) की योजना ब्रिटिश राज में सरकार ने स्वीकार कर ली थी परन्तु वह भारत में ही द्वारा व्यवहारिक बतों पर अस्वीकार कर दी गई। सन् १८८२ ई० में मद्रास के एक उच्च राज्याधिकारी सर फ्रेडरिक निकलसन (Sir Frederick Nicholson) ने जर्मनी के डेलिज डेलिज देश की प्रणालि का अध्ययन करने के पश्चात् जर्मनी के रेडिजन बैंक के सिद्धान्तों के आधार पर भारतवर्ष में सहकारी साधन समितियों की स्थापना का सुझाव दिया। उसी समय मधुत प्रान्तीय निजिल सत्रिम के सदस्य श्री ड्यूपर्नेक्स (Dupernex) ने इस विषय पर प्रवृत्ति

“दी गीयुन्ड बैंक फॉर नदर्न इण्डिया” नाम की पुस्तक प्रकाशित की जिसमें निम्नल्लत को निफारिशो का समर्थन किया गया । सन् १९०१ ई० में दुश्मिन् ब्रान् नमेटो ने भी रेफिजन्ट बंको को स्थापना का पूर्णतया समर्थन किया । उन्नी वर्ष सार्ड कर्जन को सरकार ने श्रम्य-भाविव सर एडवर्टे सों की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इस समिति की निफारिशो ने आधार पर सन् १९०४ में सहकारी साख समितियों का प्रथम कानून पास किया गया ।

सहकारी साख समितियों का कानून १९०४ (Co-operative Credit Societies Act 1904)—इस कानून के द्वारा भारत में सहकारिता ग्रान्दोलन की नींव डाली गई । इस कानून के अन्तर्गत केवल सहकारी-साख समितियाँ ही स्थापना की व्यवस्था की गई और अन्य प्रकार की सहकारिता स्वगित कर दी गई । इस कानून की धाराओं के अनुसार अग्ररह बर्ष से अधिक धानु के कोई दम व्यक्ति, जो एक ही गाँव या नगर के हो, समिति की स्थापना के लिए श्रायना-ग्रन् दे सकते थे । यदि समिति के ४,५ सदस्य किमल हो, तो समिति श्रावीण सहकारी साख समिति कहलाती थी । श्रावीण समितियों के सदस्यों के अमोमित दायित्व का नियम रखा गया और कुल लाभ एक रिजर्व कोष में जमा होता था । शहरी समितियों में दायित्व का प्रथम मदस्मा की इच्छा पर छोड़ दिया गया और कुल लाभ का अनुवीर रिजर्व कोष में जमा करना पड़ता था । समितियाँ श्रावदयक पूँजी, प्रवेश शुल्क, प्रसा (श्रयरा) के श्रय सदस्यों की जमा, और बाहरी ऋण द्वारा एकत्र करनी थी और इसे कवल मदस्मा की ही उत्पादन बार्म के लिए ऋण में देती थी । समितियाँ के प्रयन्धका को वेतन नहीं दिया जाता था, परन्तु शहरी समितियाँ के प्रयन्धका की वेतन देने की भी व्यवस्था की गई थी । शारास यह है कि श्रावीण समितियाँ रेफिजन्ट मिश्रित पर और शहरी समितियाँ शुल्क डेलिज मिश्रित पर बनाई जाती थी ।

प्रत्येक प्रान्त में सहकारिता ग्रान्दोलन की देख-भाब करने के लिए एच रजिस्ट्रार (Registrar) नियुक्त कर दिया गया । उन्ने समितियों के निरीक्षण, हिमाय की प्रतिवार्य जाच, और श्रावदयकता पड़ने पर किम्य समिति को नग करने के अधिकार दिये गये । इस ग्रान्दोलन को प्रोत्साहन देने की इष्टि से इस कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड समितियों को सरकार की ओर से कुछ हिशमते और विवेपाधिकार दिये गये, जैसे—उन्ने श्राय कर (Income tax), रटाम्य, तथा रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना पड़ता था । उन्ने श्रय श्रावदयकताओं पर श्रापनता प्रस्त की ओर गई समिति को प्रथम तीन बर्षों के लिए सरकार की चीज में २,००० रु० तथा ध्याज-रहित ऋण प्रदान किया जाता था, यदि समिति इतना ही अन् स्वय एकत्रित कर लेती थी ।

इस कानून के अन्तर्गत सहकारी-साख-समितियों की प्रगति—इस ऐक्ट के पास होने से सहकारी-साख-समितियों की संख्या बढ़ने लगी । सन् १९०१ में समितियों की संख्या ४१ थी, वह सन् १९११ में ८,१७७ हो गई और उन्नी कार्यशील पूँजी (Working Capital) ३३१,७४,१६२ रुपये हो गई । सदस्यों की संख्या भी सन् १९११ में ४,०३,३१८ हो गई ।

इस कानून के दोष—सन् १९०४ के कानून के बनने के पश्चात् सहकारी ग्रान्दोलन की बड़ी उन्नति हुई । परन्तु इस कानून में निम्नलिखित दोष थे—

(१) इस कानून के अन्तर्गत साख समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं थी । (२) श्रावीण तथा शहरी समितियों

का जो वर्गीकरण किया गया वह दोषपूर्ण था। अनुविधानक था। (३) समितियों के सभा तथा केन्द्रीय बैठकों के निर्माण को भी कोई व्यवस्था नहीं थी। पञ्जाब तथा मद्रास आदि प्रान्तों में जहाँ ज़ेयर पूँजी का अधिक महत्व था असंमित दायित्व तथा लाभांश (Dividend) देने के ऊपर रोक लगा देने के कारण बहुत ही अनुविधा हुई। इन दोषों को दूर करने के लिये सन् १९१२ में एक नया कानून बनाया गया।

महकारी समितियों का कानून १९१२ (Co-operative Societies Act 1912)—सन् १९१२ में केन्द्रीय सरकार ने दूसरा कानून पास किया जिसके ध्येयार्थ (१) उपभोक्ता, सिनार्ड, पशु, चरबन्दी, विक्रय आदि सहाय (Non Credit) सहकारी समितियों की स्थापना को सरकार ने मान्यता दी। (२) ग्रामीण और शहरी समितियों के स्थान में रोमित दायित्व और असंमित दायित्व वाली समितियों का नया वर्गीकरण किया गया। (३) इसके अनुसार बैंकिंग संघ, केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्रांतीय सहकारी बैंक आदि की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस कानून में सभी समितियों का इस बात को आशय हो गई कि वे अपने लाभ का चौथाई भाग रिजर्व फंड में जमा करने के पश्चात् लाभ का १०% दान, विद्या आदि कार्य के लिये व्यय कर सकती थी।

इसके अन्तर्गत सहकारी समितियों की प्रगति—इस कानून के पास हो जाने में इस देश में सहकारिता के आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। इसके पश्चात् समितियों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या; तथा उनकी कार्यशील पूँजी में बहुत वृद्धि हुई। पर यह वृद्धि सब प्रान्तों में एक-सी न थी। रैयतदारी प्रान्तों में, जैसे—बम्बई, मद्रास आदि में, इस आन्दोलन ने बहुत उत्थिति की। पर जमींदारी प्रान्तों में अभी तक यह आन्दोलन बहुत कम लोगों तक पहुँचा है।

मैकलेगन कमेटी १९१४—सन् १९१४ में सर एडवर्ड मैकलेगन (Sir Edward Macleagan) की अध्यक्षता में एक कमेटी (जो बाद में मैकलेगन कमेटी के नाम से प्रसिद्ध हुई) नियुक्त की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सन् १९१५ में प्रस्तुत की। इन रिपोर्ट में सहकारिता-आन्दोलन के दोषों पर प्रकाश डाला गया और आन्दोलन को अधिक सफल बनाने के लिये अनेक सुझाव दिये गये। इस कमेटी के सुझावों के अनुसार आन्दोलन का पुनर्गठन किया गया और जो सवितया सहकारी आदर्श तक नहीं पहुँची थी उनका अन्त कर दिया गया।

भारत सरकार कानून १९१९ (Government of India Act 1919)—सन् १९१९ में 'माटेम्बू चैम्सफोर्ड सुधारों' (Montague Chelmsford Reforms) के अनुसार भारत सरकार का एक असंघित कानून पास किया गया जिसके अन्तर्गत सहकारिता एक प्रांतीय विषय बना दिया गया और इसका प्रबन्ध प्रांतों के मंत्रियों को सौंप दिया गया। इसके पश्चात् प्रांतीय सरकारों ने आवश्यकतानुसार अपने-अपने कानून पास करके इस आन्दोलन की उत्थिति की। बम्बई में सबसे पहले इस प्रकार का कानून सन् १९२५ में पास किया गया। बम्बई के पश्चात् मद्रास बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों ने भी अपने-अपने कानून पास किये। कुछ प्रांतों ने जॉब कमेटियाँ नियुक्त कीं जैसे—उत्तर प्रदेश में 'ओरुन कमेटी' और मद्रास में 'टाउनमेण्ड कमेटी' आदि। इन कमेटियों के सुझावों के फलस्वरूप सहकारी समितियों में बहुत

सुधार हुए और उनकी दशा पहले से काफी सुधर गई। असाक्ष समितियों पर ब्रह्म पर्याप्त चल दिया जाने लगा।

कृषि कमीशन १९२६ और भारतीय बैंकिंग जांच समिति १९३१ के सुझाव—मन् १९२६ ई० में कृषि कमीशन और मन् १९३१ में भारतीय बैंकिंग जांच कमेटी ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये और उनको सिफारिशों के अनुसार समितियों की जांच गठान कर दी होने लगी है। भूमि वषक बैंकों को प्रोत्साहन मिला और पुच्छने ऋण की वृद्धि को रोकने के प्रयत्न किये गये।

सन् १९२६-२५ को महान् आर्थिक मंदी—सन् १९२६-२५ को महान् आर्थिक मंदी के समय सहकारिता ग्रान्दोलन को काफी घबसा लगा। उत्पादन व्यक्तियों के धूल जाने में सम्पत्तियां भट्ट हो गई, बस्तियों की गति अत्यधिक धीमी पड़ गई और भवधि पार किये प्राप्ता की राशि की वेषपूर्ण उषव-गति के कारण अनेक केंद्रीय आर्थिक सगठन भट्ट प्रायः शीमा तक पहुंच गये थे। तब भारत सरकार ने सहकारी सम्मेलन मन् १९२४ में सबसे पहले बुलाया, और फिर बाद में कई बार ऐसे सम्मेलन बुलाये गये जिनमें समितियों के विस्तार के बजाय उनके पुनर्संगठन पर विशेष बल दिया गया।

युद्ध और युद्धोत्तर काल—युद्ध और युद्धोत्तर के वर्षों में सहकारिता ग्रान्दोलन की सभी दशाया में पर्याप्त प्रगति का अवसर मिला। इस काल में इस ग्रान्दोलन को खाद्य-उत्पादन एवं वितरण, भवन निर्माण, भूमि-उपनिवेशन और बस्तियां बसाने, बहुत एक कुटीर व्यवसायों को संगठित करने तथा सामों की पुनर्बात योजनाएं बनाने आदि का अवसर मिला, जिसमें ग्रान्दोलन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला।

सहकारी योजना समिति १९४६ (Co-operative Planning Committee)—मन् १९४६ में सहकारी योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ग्रान्दोलन के भारी विकास के मार्ग प्रदर्शन का विद्यमान कराया गया।

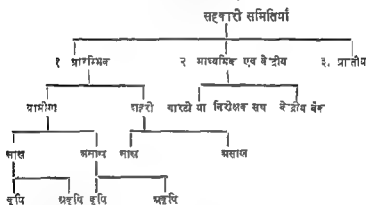
स्वतन्त्रता-प्राप्ति (१९४७) के बाद—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सहकारिता ग्रान्दोलन में गंभीर एव पुनर्संगठन की वृत्ति जाग्रत हुई। भूमि की परकवाशी तथा ग्राम-मुधार के लिये नवीन समितियां शोधना से बनने लगी। इन वर्षों में बहुप्रयोजन समितियां (Multipurpose Societies) का रजिस्ट्रेशन होने लगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मीर, बम्बई और मद्रास आदि राज्यों में इस ग्रान्दोलन की प्रगति पहले की अपेक्षा अधिक दृष्टिगोचर होने लगी सहकारी समितियों की स्थिति निम्न प्राकटो में स्पष्ट हो जाती है :—

	१९२१-२२	१९४७-४८
सहकारी समितियों की कुल संख्या	१,८५,६५०	२,५७,८२७
सदस्यों की संख्या	१,३७,६१,६८७	२,१४,३५,१५०
कार्यशील पूँजी (करोड़ रु० में)	३०६.३४	६६६.४६
कृषि साध समितियां	१,१५,४६२	१,६६,४४३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५६-६१)—दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता में निवेश के लिए ४७ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। योजना कास में सहकारी सहपाएँ २२५ करोड़ रुपये उधार दगी। वृषि उत्पादन की विज्ञी की सुविधा के लिए ५,८५० गादाम स्थापित निय जायेंगे।

भारतवर्ष में सहकारी समितियों का वर्तमान ढाचा (Structure)

भारतवर्ष में सहकारी समितियों का ढाचा निम्न प्रकार है —



सहकारी समितियों का विभाजन—सहकारी समितियों का विभाजन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं —

१. प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ
२. माध्यमिक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक
३. प्रांतीय या राज्य सहकारी बैंक

१. प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ (Primary Co-operative Societies)—प्रारम्भिक सहकारी समितियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—ग्रामीण और शहरी। इनमें प्रत्येक का सास और असास भाग में बाँट सकते हैं और फिर इन्हें वृषि और अवृषि समितियों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

प्रारम्भिक वृषि (ग्रामीण) सहकारी सास समितियाँ (Primary Agricultural (Rural) Co-operative Credit Societies)—ये समितियाँ हमारे देश की कुल समितियों की ७३% हैं। सहकारी आन्दोलन इन्हीं पर आधारित है। ये प्रायः जर्मनी की रीति-रिवाज प्रणाली के अनुसार स्थापित पड़े हैं। ये प्रायः गरीबों में ही होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रामीण सहकारी समितियाँ भी कहते हैं। इन समितियों की विशेषताएँ (Characteristics), इनका संगठन (Organisation) तथा कार्यशीलता (Working) निम्नलिखित हैं —

(१) आकार एवं सदस्यता (Size & Membership)—एक हो गांव ग्राम या जाति के कोई १० व्यक्ति जो अठारह वर्ष से अधिक आयु के हो समिति खोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या १०० से अधिक नहीं हो सकती। समितित आकार के होने से सदस्यों में पारस्परिक जानकारी हो सकती है।

(२) रजिस्ट्रेशन (Registration)—प्रारम्भिक कृषि साख समिति कम से कम १० या उससे अधिक (अधिक-से-अधिक १००) व्यक्ति द्वारा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री के नियमों के अनुसार बनवाई जा सकती है।

(३) कार्य क्षेत्र (Area of Operation)—रैफिज्ड निष्ठा के अनुसार एक गांव एक समिति का नियम है, अर्थात् इसका कार्य क्षेत्र उस गांव तक ही सीमित होता है जहाँ वह खोली जाती है, जिनमें लोग एवं दूसरे से भली-भाँति परिचित हो सकें।

(४) दायित्व (Liability)—प्रारम्भिक कृषि साख समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित (Unlimited) होता है, अर्थात् यदि किसी समिति की सम्पत्ति उसका ऋण चुकाने के लिये प्रयोज्य हो, तो इसकी कमी प्रत्येक सदस्य से अलग अलग राशि प्राप्त करने की जाती है और सदस्यों की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इस में लाई जाती है। असीमित दायित्व रखने का मुख्य कारण लोगों में विश्वास का विस्तार करना, सहयोग की भावना बढ़ाना, और ऋण प्रणालियों से समिति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना है।

(५) प्रबन्ध (Management)—इन समितियों का प्रबन्ध प्रजातन्त्रात्मक एवं प्रवैतनिक होता है। इनका प्रबन्ध दो समितियों द्वारा होता है—साधारण सभा (General Committee), तथा कार्यकारिणी सभा (Executive Committee) द्वारा। साधारण सभा का निर्माण समिति के समस्त सदस्यों द्वारा होता है। साधारण सभा द्वारा चुने गये कुछ सदस्य (१ से ६) समिति की कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं। साधारण सभा का कार्य कार्यकर्ताओं का चुनाव, मैकेटरी की नियुक्ति करना, बजट पार करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षण (ऑडिटर्स) की रिपोर्ट पर विचार करना, सभासदों और समिति के ऋण की सीमा बंधन, और समिति के उपनियमों में संशोधन करना है। कार्यकारिणी सभा का कार्य साधारण सभा के आदेशों का पालन करना, सभासदों की प्रार्थना पर ऋण देना, उनमें ऋण वसूल करना, तथा ऋण के लिये राशि का प्रबन्ध करना और समितियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना है।

(६) कार्यशील पूँजी (Working Capital)—समिति की कार्यशील पूँजी सदस्यों के प्रवेश धन, अर्थात् (यदि हा), लोगों की सभा में प्राप्त की जाती है। अर्थात् का निर्वहन केवल पञ्जाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास में ही होता है। सरकार, अन्य समितियों और केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करना समिति के पूँजी प्राप्त करने के एक साधन है। संवित्तियों के ऋणों को अत्यधिक देलने से यथा चला कि उनमें ऋण अधिकतर बाह्य साधनों से ही प्राप्त होता है।

(७) ऋण का उद्देश्य (Object of Loan)—ऋण साधारणतया उत्पादन-कार्यों और पुनर्निर्माण के लिये दिया जाता है। वैधानिक दृष्टि से उपयोग और अनुपादक कार्यों, जैसे—विवाह और अन्य सामाजिक तथा धार्मिक

उत्पन्ना व लिए नहीं देना चाहिए, परन्तु व्यवहार में ऐसा न करण दिया जाता है अन्यथा किसान के साहूकार के बहुत से फँस जाने का भय रहता है।

(८) ऋण-भुगतान (Repayment of Loan)—ऋण का भुगतान सुविधानवक किन्ता व रूप में होता है। भुगतान ऐसे समय पर मागा जाता है जब किमान व पाम इन को रफ़ा होता है।

(९) जमानत (Security)—इन समितिया के सदस्या का समीमित दायित्व होने व कारण ऋण कबल व्यक्तिगत जमानत पर ही दे दिया जाता है। सदस्य की सचाई तथा चरित्र ऋण प्राप्ति के लिये अधिक महत्व रखत है। परन्तु व्यवहार में ऋण देने वाला न दो सहयोग सदस्या की जमानत के अनिरिक्त चन व अचल सम्पत्ति भी जमानत व रूप में मागो जाती है।

(१०) व्याज की दर (Rate of Interest)—इन समितिया की व्याज की दर महाजन का हरा ने कम होती हैं। परन्तु व दर अधिक नीची नहीं होनी चाहिए अथवा गाव वाला भावश्यकता से अधिक ऋण नन व लिए प्रेरित हान।

(११) निरीक्षण एवं जाँच (Supervision & Audit of Accounts)—इन समितिया व नाम का निरीक्षण और हिसाब किताब की जाच सहकारी समितिया के रजिस्ट्रार के हाथ होती है जो इन काय के लिये निरीक्षक (Inspector) और हिसाब परीक्षक (Auditor) नियुक्त करता है। निरीक्षण कस निरीक्षण मध्य (Inspecting Union) और केन्द्रिय बैंक द्वारा भी होता है।

(१२) लाभ विभाजन (Distribution of Profits)—जिस समिति में अद्य नहीं होत उनका सारा लाभ रिजर्व कोष में जमा कर दिया जाता है। अगला साली समितिया में लाभ का काम के कम बोझाई भाग रिजर्व कोष में जमा कर दिया जाता है दोष का १०% निक्षेप तथा अन्य दान व परोपकार के कार्यों में व्यय किया जाता है, और दोष एक सारा तब अद्यधारिया की लाभाया (Dividend) के रूप में बाँट दिया जाता है।

(१३) पचायत (Arbitration)—समिति और सदस्या का पारस्परिक अग्रह पचायत द्वारा तय किया जाता है। इन अग्रह व लिए मायात्रय में नहीं जाना पड़ता है जिससे समझ, शक्ति तथा व्यय में बचत हाना है।

(१४) समिति का भंग होना (Dissolution)—रजिस्ट्रार द्वारा कोई भी समिति जो ठीक प्रकार से काय नहीं कर रहा हो तथा जिसके काय से रजिस्ट्रार असन्तुष्ट हो, भंग की जा सकती है।

(१५) कतिपय सुविधाएँ एवं रियायत (Some Facilities & Concessions)—समितिया की रनिपय सुविधाएँ एवं दिगायत भी मिरी हुई है, जैसे—आयकर रनिपय मुक्त और मुद्राक कर (Stamp Duty) को छू मादि। समितिया के अद्या की कुर्की नहीं हो सकता। अन्य उधार लन वाला में उह प्राथमिकता का अधिकार प्राप्त है।

(१६) वर्तमान स्थिति (Present Position)—सन् १९४० व पूर्व इन समितिया की स्थिति अनोपयुक्तक नहीं थी। इनक क्रम का बहुत सा भाग शमूल नहीं होने पाता था और ऋणा में भी भारी कमी हो गई थी। परन्तु द्वितीय विश्व

महापुद्ग के आरम्भ हो जाने तथा खेतों की उपज का मूल्य बढ़ जाने से किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इनका ऋण बमुक्त हो गया। सन् १९५० के पून के अन्त में इन समितियों की संख्या १,६६,१४३ थी और १,०२,२१,२४६ सदस्य थे। इनकी कार्यशील पूँजी १३३ ७१ करोड़ ८० थी। बम्बई, मद्रास और पंजाब में इन समितियों की विशेष उन्नति हुई।

प्रारम्भिक कृषि (ग्रामीण) सहकारी साख समितियों की आवश्यकता के कारण—इन समितियों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है, यद्यपि इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(१) अप्रशिक्षित पूँजी—समितियों के पास अप्रशिक्षित पूँजी होने के कारण इनकी साख-सम्बन्धी समस्या आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पाती जिससे किसान का गाँव के महाजन पर आश्रित रहना पड़ता है।

(२) ऋण अनुपादक कार्यों में शर्ष किया जाता है—इन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया ऋण अधिकांश में अनुपादक कार्यों में लगा दिया जाता है जिसमें ऋण की बमूली नहीं होने पाती।

(३) गाँव के साहूकार या महाजन का प्रभुत्व—सहकारी ग्राम्योपन के पश्चात् भी गाँव के महाजन का प्रभुत्व ही प्रभाव एवं प्रभुत्व है।

(४) अशिक्षा—इन समितियों के सदस्य पढ़े लिखे नहीं होने के कारण सहकारिता के सिद्धान्तों का नहीं समझते।

(५) समितियों का दोषपूर्ण संचालन, निरीक्षण एवं प्रवेक्षण—इन समितियों के संचालन, निरीक्षण एवं प्रवेक्षण (Audit) अभाव में अनेक दोष पाये जाते हैं जिसके कारण में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया है।

कृषि (ग्रामीण) सहकारी असाम्य समितियाँ (Agricultural [Rural] Co-operative Non credit Societies) - गाँव में कुछ सहकारी समितियाँ ऋण देने का काम नहीं करती बल्कि कृषि सम्बन्धी अनेक कार्य सहकारी सिद्धान्तों पर करती हैं, जैसे—बीज, सिंचाई, जोड़ार, खाद, कृषि-पदार्थों की शिक्षा, नेताओं चक्रवर्त्य आदि की समितियाँ। इन समितियों की उन्नति साख समितियों की अपेक्षा बहुत कम हुई है। सन् १९५४-५५ के अन्त में देश में ३०,१९७ प्रारम्भिक कृषि असाम्य समितियाँ थी। इनके सदस्यों की संख्या ७४,६४,१०० थी तथा इनकी पूँजी २०-७२ करोड़ २० थी।

प्रारम्भिक ग्रहणी (शहरी) सहकारी साख समितियाँ (Primary Non-Agricultural [Urban] Co-operative Credit Societies)—ऋण का सम्प्राप्य वेचन गाँवों में ही नहीं है बल्कि शहरों और कस्बों में भी पाई जाती है। शहरों और कस्बों के निर्माण जारीगर, मजदूर, तथा छोटे छोटे दूकानदारों को भी ऋण की आवश्यकता रहती है जिसको साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति के निम्ने इन समितियों का निर्माण हुआ है। ये शहरों में स्थित छोटे छोटे दूकानदारों, व्यापारियों, जारीगरों, तथा कारखाने वालों को जो ऋणक नहीं हैं, ऋण देती हैं। इसलिए इन्हें 'ग्रहणी (शहरी) सहकारी साख समितियाँ' कहते हैं। इनका निर्माण अधिकतर शुल्ज डेलिच (Schulze Delitzsch) के सिद्धान्तों के अनुसार होता है।

विशेषताएँ (Characteristics)—ग्रहणी (शहरी) साख समितियों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) सत्यापन (Information)—य गुह्य ऋतु के सिद्धांत पर बनाई जाती है। नगर व निधन कारीगर मजदूर तथा छोट दुकानदार आदि मिल कर इनका निमाण करते हैं जो इनको जमा देती हैं।

(२) पूँजी (Capital)—इनकी समस्त पूँजी भाग (Shares) में विभाजित होती है जो प्रत्येक सदस्य को खरीदने पड़ते हैं। प्रत्येक अंशधारक का एक वोट देने का अधिकार होता है। मृदा जमा तथा रिजर्व कोष भी इनकी वायगीन पूँजी को बनाते हैं।

(३) दायित्व (Liability)—इस समितियाँ के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

(४) प्रबंध (Management)—माध्यम सभा नाति नियमित करती है तथा कार्यकारिणी सभा या सभासदों (Directors) का वार्षिक समिति का प्रबंध करता है। समिति के प्रबंधका का कार्य करने के लिए बतल दिया जाता है।

(५) ऋण नीति तथा ऋण (Loan Policy)—य समितियाँ अपने सदस्यों में निम्नलिखित का प्रचार करती हैं तथा यह आश्वासन अनुसार प्रत्येक सदस्य को नियंत्रण देती हैं। य वह भी प्रयत्न करती हैं कि सदस्य अपना जमा भी कराव। बचत और वसूली में ये समितियाँ जानू जमा और संचय जमा भी लेती हैं और अपने भुगतान का काम भी करती हैं।

(६) लाभ वितरण (Distribution of Profits)—य एक लाभ २५% रिजर्व अर्थात् रक्षित कोष में जमा कर गये सदस्यों में बाँट दिया जाता है।

(७) निरीक्षण एवं जाँच (Supervision and Audit of Accounts)—इन समितियाँ का निरीक्षण एवं निरीक्षण विभाग को जाँच दृष्टि माध्य समितियाँ की भाँति रजिस्ट्रार द्वारा होती है।

(८) वर्तमान स्थिति (Present Position)—य समितियाँ दृष्टि माध्य समितियाँ को अनेक अधिक गहन हुई हैं क्योंकि इनके सदस्य नियमित होते हैं और नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। य समितियाँ स्वावलम्बी तथा मुक्त होती हैं। इनके पास अपना जमा जमा की पर्याप्त पूँजी होता है और इनका कर्जाय या प्राप्ति सहकारी सेवा में अग्रणी होने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इन प्रकार की समितियाँ न केवल सद्राज्य वसुंधरा और पंजाब में विपणन उत्पत्ति की हैं। जून १९५५ के अंत में इनकी संख्या ८३४८ तथा वस्तु संख्या की संख्या २८४७८४४ थी। इनकी आयूँ पूँजी ७८३२ करोड़ ४० थी।

प्रारम्भिक ग्रहण सहकारी अग्रणी समितियाँ (Primary Co-operative Non credit societies)—ग्रहणी अग्रणी समितियाँ न केवल समितियाँ की अपेक्षा अधिक उत्पत्ति ना है। य समितियाँ कई प्रकार की होती हैं—जमा बोना (Insurance) भवन निगम (Housing) उपभोक्ता भंडार (Consumer's Store) आदि। इन सबमें उपभोक्ता भंडार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जून १९५५ के अंत में इन समितियों की संख्या २४२६६ था उनमें सदस्यों का संख्या ३१५०३३३ था और कार्यपालन पूँजी ५२५५ करोड़ रुपया था।

२ माध्यमिक समितियाँ एवं केंद्राध्य सहकारी बैंक (Secondary Societies and Central Co-operative Banks)

(घ) ये समितियाँ प्रारम्भिक समितियों को संगठित करने, उनकी देहाभास करने और आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई जाती हैं। ये समितियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं—(१) गारंटी संघ (Guarantee) जैसे बम्बई में। (२) निरीक्षक संघ (Inspecting Union) जैसे मद्रास और बम्बई में। (३) साहूकार संघ, जैसे पंजाब में।

एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न समितियों के सम्मिलन से संघ का निर्माण होता है। इसका प्रबन्ध सदस्य समितियों की प्रतिनिधि कमेटी द्वारा होता है। गारंटी संघ सदस्य समितियों को केन्द्रीय बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की गारंटी करता है। निरीक्षक संघ प्रारम्भिक समितियों की वेम-रेख करता है और साहूकार संघ ऋण देता है। ये संघ प्रारम्भिक समितियों के बीच गृहला का भी काम करते हैं।

(आ) केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Banks)—इन बैंकों का संगठन सन् १९१२ के कानून के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। ये बैंक प्रारम्भिक समितियों को धन देने और उनके अनुत्तम केन्द्रों का कार्य करते हैं। समितियों को आर्थिक योगदान के अतिरिक्त ये बैंक जमा स्वीकार करना बिना की राशि संग्रह करना, बैंकों को भुनाना आदि काम भी करते हैं।

केन्द्रीय बैंक मिश्रित (Mixed) या शुद्ध (Pure) हो सकते हैं। मिश्रित केन्द्रीय बैंकों की सदस्यता व्यक्तिगत और समितियाँ दोनों के लिए खुली है किन्तु शुद्ध ढंग के बैंक की सदस्य केवल समितियाँ ही हो सकती हैं। शुद्ध ढंग के बैंक पंजाब और बंगाल में हैं। सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रायः जिले भर में एक ही होता है, इसलिए इसे जिला बैंक भी कहते हैं।

केन्द्रीय बैंकों की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) क्षेत्र (Area)—इनका क्षेत्र एक या एक से अधिक तालुका, तहसील या जिला होता है। दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में केन्द्रीय बैंक का क्षेत्र एक जिला होता है, परन्तु उत्तर भारत में अधिकतर एक तहसील में एक केन्द्रीय बैंक होता है।

(२) प्रबन्ध (Management)—केन्द्रीय बैंक के ससधारियों की संख्या को समारण सभा भी कहते हैं। सभा के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। इसी सभा द्वारा बैंक के मन्त्रालों का निर्वाचन होता है। निश्चित केन्द्रीय बैंकों में समितियों और व्यक्तियों के सभासदों की संख्या अधिक होती है। संचालक बोर्ड बैंक का प्रबन्ध करता है। जब संचालकों की संख्या अधिक होती है तो वह बोर्ड एक कार्य-कारिणी समिति चुन लेता है जो बैंक का सारा कार्य चलाती है। बैंक का प्रतिदिन का प्रबन्ध संचालक प्रबन्ध प्रेयरमेंट व अर्धतनिक सभा की सहायता से होता है। संचालकों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता और वे अधिकतर समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रेयरमेंट सरकारी कर्मचारी होता है।

(३) पूँजी (Capital)—केन्द्रीय बैंकों की पूँजी अंशों (Shares), रिजर्व फंड तथा ऋण के द्वारा प्राप्त होती है। सरकारी संघों (Unions) में केवल समितियाँ ही भाग खरीद सकती हैं, किन्तु केन्द्रीय मिश्रित बैंकों में समितियाँ तथा अन्य सदस्य व्यक्ति भी भाग खरीद सकते हैं। साधारणतया ससधारियों का दायित्व सभा के मूल्य तक ही सीमित रहता है, परन्तु कुछ प्रान्तों में ससधारियों का दायित्व सारा धन से दम धन तक होता है। २५% रिजर्व फंड में जमा किया जाता

है। वह भी कार्यशील पूँजी का काम करता है। बैंक असदस्यों में जमा भी स्वीकार करते हैं जो उनको सबसे अधिक कार्यशील पूँजी होती है। ये बैंक मुख्यतः मुदती और संचय जमा पर ही कार्य लेते हैं। चालू जमा में अधिक जोखिम होने के कारण चालू जमा बैंक बहुत कम लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, ये राजवीर सहकारी बैंकों से भी ऋण लेते हैं। कभी-कभी ये रिजर्व, स्टेट तथा अन्य बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

(४) ऋण नीति तथा कार्य (Loan Policy) — केन्द्रीय बैंक प्राथमिक सहकारी साख समितियों और ग्रामाल समितियों को ही ऋण देने है। प्रसीमित दायित्व वाली समितियों को प्रथम प्रीनोट प्रयत्न बाँड पर दिया जाता है, परन्तु अन्य सहकारी समितियों से उसके अतिरिक्त कुछ सम्पत्ति भी गिरवी माँगी जाती है। ये बैंक प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों से ७% व्याज लेते हैं और जमा पर ५% व्याज देते हैं। जो रुपया केन्द्रीय बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक होता है, उसे प्रांतीय सहकारी बैंकों में जमा कर दिया जाता है या ट्रस्टी-प्रतिभूतियों में लगा दिया जाता है।

(५) लाभ वितरण (Distribution of Profits) — केन्द्रीय बैंक के वार्षिक लाभ का २५% रिजर्व कोष में जमा कर दिया जाता है। लाभ का कुछ भाग स्टूट लाते, भण्ड, लाभ-हानि समुपन के लिये विविध कोषों में जमा करके क्षेत्र का ६ से १० प्रतिशत तक असाधारणों को सामाजिक के रूप में बाँट दिया जाता है।

(६) निरीक्षण तथा प्रवेक्षण (Supervision & Audit) — केन्द्रीय बैंकों का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा उसके अधीन अन्य कर्मचारियों द्वारा होगा है। प्रांतीय सहकारी बैंक भी केन्द्रीय बैंकों का निरीक्षण करते हैं। इन बैंकों में भाष-अध्यक्ष को जॉन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अन्वेक्षक (Auditor) करते हैं और इनको वार्षिक स्थिति के विषय में रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देते हैं।

(७) वर्तमान स्थिति (Present Position) — भारतवर्ष में सन् १९५७-५८ में ४१८ बैंकिंग संघ तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक थे जिनके संगणन ३,२२,८१६ सदस्य थे और कार्यशील पूँजी १४७ करोड़ रुपये थी।

३. राजकीय सहकारी बैंक या सीप बैंक (State Co-operative Bank or Apex Banks) — फिल्लेबन कमेटी १९१५ की रिपोर्ट के अनुसार इन बैंकों की स्थापना हुई। आजकल लगभग सभी राज्यां में ऐसे बैंक हैं जिनमें कम्बई, मद्रास और पंजाब के बैंक विशेष उल्लेखनीय हैं।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) संगठन (Organisation) — इन बैंकों का संगठन सब जगह एक-सा नहीं है। पंजाब और बङ्गाल में सहकारी समितियाँ और सहकारी केन्द्रीय बैंक उनके सदस्य और असाधारण होते हैं। दूसरे प्रांतों में अन्य व्यक्ति भी इनके असाधारण होते हैं।

(२) प्रबन्ध (Management) — इन बैंकों के कार्यसंचालन के लिए व्यापारिक बुद्धि तथा बैंकिंग योग्यता चाहिए। अतः इनके डाइरेक्टर असाधारणों के प्रतिष्ठित बाहरी व्यक्तियों में से भी चुने जाते हैं। सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार लगभग सभी राज्यों में इन बैंकों का या तो स्वयं नियुक्त (Self-appointed) डाइरेक्टर

पर्याप्त संचालक होता है यद्यपि यह कुछ टाइमेटरी या संचालको को मनोनीत (Nominate) करता है।

पूँजी (Capital)—इन बैंको की कार्यशीलता पूँजी धरो, जमा और रिजर्व काप में प्राप्त होती है। कभी-कभी ये बैंक कुछ समय के लिये नकद साव या प्रविधिकप (Overdraft) के रूप में स्टेट व व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा प्रारम्भिक सहकारी साव समितियों व अन्य राज्यीय बैंक से कुछ भी ले लेते हैं। ये बैंक चानु, वचन और मुहूर्त तीनों प्रकार की जमाएँ प्राप्त करते हैं। मुद्रा-साधार के अनुसार ही वे अपने व्याज की दर निर्धारित करते हैं।

(४) ऋण नीति एवं कार्य (Loan Policy)—य बैंक प्राय २० से ५०% तक अपनी कार्यशील पूँजी राज्य-प्रतिभूतियों (Govt. Securities) में लगाते हैं तथा कुछ पन व्यापारिक बैंक व अन्य राज्यीय बैंक में जमा करा देते हैं तथा शेष को अपने सदस्यों को उधार दे देते हैं। प्रारम्भिक समितियों को कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा दिया जाता है। ये बैंक समय-विशेष सघ व मौद्रिक सहकारी समितियों को भी ऋण देते हैं। ये तीन प्रकार की जमा लेने के प्रतिरिक्त वे सभी कार्य करते हैं जो एक व्यापारिक बैंक करता है। जिन बैंकों में केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक नहीं हैं वहाँ वे भूमि वन्धक बैंक के ऋण-पत्र (Debentures) बेचते हैं और उन्हें बीचमाल के लिए ऋण देते हैं।

(५) लाभांश-वितरण (Dividend)—सन् १९४५ की सहकारी अनुमदाय कमेटी ने कम-से-कम ३% लाभांश प्रथम पाँच वर्ष तक इसके प्रस्यारियों को देने को सिफारिश की है।

(६) निरीक्षण एवं प्रवेक्षण (Supervision & Audit)—ये बैंक कहीं-कहीं केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर नियन्त्रण भी करते हैं। वह वास्तवीय नहीं है, यद्यपि प्रान्तीय सहकारी बैंक द्वारा इनका निरीक्षण आवश्यक है। इसके हितान्वितान की जाँच रजिस्ट्रार को करनी चाहिए, परन्तु साधारणतया रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्रवेक्षक इनके हिसाबों की जाँच करते हैं। इन बैंकों को हर तिमाही एक प्राथिक स्थिति का लेखा रजिस्ट्रार द्वारा प्रान्तीय सरकार को भेजना पड़ता है जो उन पर अपना मत प्रकट करते हैं।

(७) वर्तमान स्थिति (Present Position)—राज्यीय सहकारी बैंक सम्बद्ध बैंकों तथा बैंकिंग संस्थाओं के लिये सतुलन केन्द्रों का काम करते हैं। सन् १९५७-५८ में देश में ऐसे २१ बैंक थे। जिनमें सम्पत्ति ३३,४४० तथा श्रितनी बालू पूँजी ७९,५४ करोड़ रु० की थी।

राज्यीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक—रिजर्व बैंक राज्यीय सहकारी बैंकों व उनमें सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकों को राज्य प्रतिभूतियों को जमागत पर तत्काल साव (Cash Credit) देता है। रिजर्व बैंक कुछ बैंकों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की भी सुविधा देता है, और इस कार्य के लिये उसने केन्द्रीय बैंक को राज्यीय बैंकों की मात्ता मान लिया है। रिजर्व बैंक का कृषि विभाग इन पर नियन्त्रण रखता है। यद्यपि राज्यीय बैंकों को रिजर्व बैंक में सभी सब सुविधाएँ नहीं मिली हैं,

किर भी अब एक अखिल भारतीय सहकारी या ग्रामोपरि बैंक की आवश्यकता नहीं रही है ।

अखिल भारतीय राज्यीय सहकारी बैंक—इस सपना का प्रादुर्भाव सन् १९२६ में हुआ था । इसका मुख्य कार्य प्रत्येक सदस्य की पूँजी के वास्तव्य तथा नमो के आँकड़ों जमा कर उनका ग्रन्थ सदस्यों का सूचित करना है जिसमें प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से परिचित हो जाय और लेन देन करने में सुविधा हो । यह सदस्य बैंकों को आर्थिक परामर्श भी देता है और उनकी सहायता भी करता है । राज्यीय बैंकों को समय समय पर पुनःकर सहकारी आन्दोलन को सहकरपूर्ण समस्याओं पर विचार करना भी इसका कार्य है । यह राज्यीय पैसा, रोजगार बैंक और सरकार का ध्यान इन्हीं सम्मेलनों द्वारा आकर्षित करता है ।

भारतवर्ष में सहकारिता से लाभ (Advantages of Cooperation in India)—प्रथम सहकारी आन्दोलन को हगारे देश में पूरी उन्नति नहीं हुई है और इसमें अनेक दोष हैं, परन्तु फिर भी हम आन्दोलन से देश को बहुत लाभ हुए है, जो इस प्रकार है,—

(१) आर्थिक लाभ (Economic Advantages)—सहकारी साख समितियों किसानों और शरीरवा की कम ध्यात्र पर प्रणु देती हैं और वे उनमें वृद्धि की माधना को प्रोत्साहित करती हैं । कई गाँवों में महाजन का प्रभुत्व एक प्रभाव समाप्त हो गया है और अपने व्याज की दर कम करती है जिससे जनसाधारण को लाभ पहुँचा है । सहकारी समितियों ने नृण कम करने में भी सहायता दी है । उन्होंने अनुपादक सचय (Hoarding) के रोवा है और वे नियन्त्रित साख प्रदान करती हैं । ग्रामाख समितियों से भी जनता का बहुत लाभ पहुँचा है । सहकारी विषय समितियाँ द्वारा विमान अपना माल प्रच्छेद दामों पर बेच सकता है । उपभोक्ता समितियाँ के द्वारा उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं में सस्ते भावों पर मिल जाती है । सहकारिता कुटीर उद्योगों के विकास का एक अनुपम साधन है । मद्रास में गुनहर सहकारिता सफल औद्योगिक सहयोग का बहुत ही उत्तम उदाहरण है ।

(२) नैतिक लाभ (Moral Advantages)—आर्थिक लाभा के अनिरुद्ध सहकारिता ने सदस्यों का नैतिक स्तर भी ऊँचा उठा दिया है । केवल ग्रन्थे अरिष वाता अति ही इन समितियों का सदस्य बन सकता है । सदस्यों के भगवत् पचायत द्वारा गुलभाये जाते हैं जिसमें गुरदमबाजी कम होती है । सदस्य एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते हैं जिससे विवृलसर्जी कम होती है । रूम० एल० डालिङ्ग ने ठीक ही कहा है कि 'समितियों के सदस्यों में सहकारिता की भावना उत्पन्न होने में विवृलसर्जी, गुरदमबाजी, मदिरा पान आदि आदतों के स्थान पर आम निग्राम, सवाई, सद्भावना अन्वब्ययता तथा पारस्परिक सहयोग आदि उत्तम बातें आ जाती हैं ।' इस समितियों द्वारा सच्चे नागरिकता का पाठ सिखाया जाता है ।

(३) शिक्षात्मक लाभ (Educative Advantages)—सहकारिता से समितियों के सदस्यों की वृद्धि और ज्ञान शक्ति का विकास हो जाता है । वे पढ़ना, लिखना, हिसाब रखना आदि अनेक बातें सीखते हैं जिससे वे अच्छे नागरिक बन जाते हैं । प्रत्येक सदस्य की समिति की बैठकों में भाग लेना पड़ता है और यदि वह किसी जिम्मेदार पद पर नियुक्त हुआ, तो उसे समिति के सब बाँवों का अध्ययन करना पड़ता है जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है ।

(४) सामाजिक लाभ (Social Advantages)—सहकारिता आन्दोलन से सामाजिक लाभ भी बहुत होने है। असीमित व्यक्ति के सिद्धान्त से पारस्परिक निपटण आवश्यक हो जाता है और फिजूलखर्चों से विरक्त लोकमत तैयार हो जाता है। विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर फिजूलखर्चों कम हो जाती है। समितियों द्वारा गांवों में कुत्तों की मरम्मत, सफाई, गन्दे पानी को नालियां में सुधार, सड़क साफ करवाने, गांव के गड़दे भरवाने, चिबिरिमा आदि जन हित एवं परोपकारा काय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, रहन-सहन सुधार (Better Living Societies) द्वारा गांव में स्वच्छ रहना, सबाना को हवादार बनाना, विवाह त्योहार आदि अवसरों पर फिजूलखर्चों नहीं करना आदि बात सीखने है।

(५) शासन-सम्बन्धी लाभ (Administrative Advantages)—सहकारी समितियों की सटपटता प्रजासत्तात्मक प्रणाली से सिद्धान्त का पाठ सिखाती है। समिति का प्रत्येक सदस्य अपने भताधिकार का सदुपयोग करना सीखता है। समितियों के कार्य से निम्नत्राग क्षेत्र होने से सदस्यगण नियमित रूप से काम करने से अभ्यस्त हो जाते हैं।

भारतीय सहकारिता के कुछ दोष (Defects of Indian Cooperation)—भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ हुए पचास वर्ष हो गये हैं, परन्तु फिर भी प्रादेशीय उन्नति दृष्टिकोण से नहीं होनी है। इसकी निम्नलिखित कमियाँ इस दशा का मुख्य कारण हैं—

(१) आर्थिक मर्यादी नियन्त्रण—इस आन्दोलन का पहला दोष यह है कि इसके ऊपर अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण (Official Control) अभी तक भी इतना अधिक है कि सहकारी समिति के सदस्य इसको 'सरकारी बैंक' समझते हैं। इससे सहकारिता का भाव पैदा नहीं होता और यह प्रवृत्ति उत्तरदायित्व नहीं समझते।

(२) सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता—बहुत-से सरकारी सहकारिता के सिद्धान्तों का नहीं समझने की बहुत आवश्यक है।

(३) निरक्षरता—अधिकांश जनता निरक्षर तथा पुराने िवारा की है, इसलिये उन्हें सहकारिता के सिद्धान्तों में कोई विश्वास नहीं होता है।

(४) वैयक्तिक-सम्बन्धी कार्यों की अनभिज्ञता—बहुत-से सरकारी और अंतरकारी कर्मचारी जो सहकारी आन्दोलन में सम्मिलित हैं, वैयक्तिक-सम्बन्धी कार्यों से अपरिचित हैं जिससे बैंकों का ठीक-ठाक प्रबन्ध नहीं कर सकते।

(५) दोषपूर्ण प्रवृत्ति—इन समितियों का प्रवृत्ति दोषपूर्ण है। प्रवृत्तियों को उचित प्रशिक्षण (Training) नहीं मिलती। प्रायः प्रवृत्तियों अपने मित्रों व सम्बन्धियों की ही प्रशंसा देते हैं और यत्पूर्वक व होंगे पर उन्हें विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण समितियों के अन्य सदस्यों को, जिनका प्रवृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, आवश्यक कार्यों के लिए रुका नहीं मिल पाता।

(६) प्रवृत्ति का कुछ ही सक्रियता व्यक्तिगत व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीकरण—बहुत सी समितियों का प्रवृत्ति पांडे व सक्रियता व्यक्तियों के हाथ में चला गया है जो छोटे-छोटे उत्पादकों से हित की रक्षा नहीं करते। बहुत-से केन्द्रीय बैंक भी अपनी समितियों के गांव व्यवहार में पक्षपात करते हैं।

(७) प्रबन्धको की स्वार्थपरायणता—प्रबन्धको की स्वार्थपरायणता के कारण सहकारों अर्थ-व्यवस्था अथवा सेवा, विलम्बकारी तथा लोचनी है। बहुत से सदस्यों को जहाँ से वे अनुविधायों का नामना करना पड़ता है और फिर भी उन्हें आवश्यकता-नुसार कुछ नहीं मिलता। इस कारण समितियों के होने हुए भी सहकार का पूर्ण प्रभुत्व तब प्रभाव रहता है और वृत्तक सदैव महाजन के चञ्चल में पड़ा रहता है।

(८) दोषपूर्ण निरीक्षण एवं अवेक्षण—सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं अवेक्षण ठीक प्रकार नहीं होता है जिससे वेईसाज प्रबन्धको द्वारा गवर्न की आशका बनी रहती है। कई राज्यों में समितियों का निरीक्षण तथा अवेक्षण भिन्न-भिन्न एजेंसिया द्वारा होता है जिसमें धन तथा समय का दुरुपयोग होता है। केन्द्रीय वॉकिंग ऑफ कमेटी के मतानुसार जर्मनी तथा फ्रान्सिया की भाँति का निरीक्षण, अवेक्षण आदि केवल जिला सभा द्वारा ही नुसारतापूर्वक किया जा सकता है।

(९) असाक्ष समितियों की उपेक्षा—देश में जो कुछ भी सहकारिता की प्रगति हुई है वह साक्ष समितियों की विचार में हुई है। असाक्ष समितियों की ओर कम ध्यान दिया गया है। सहकारिता की पूर्ण सफलता इसके सर्वाङ्गीण विकास पर निर्भर है। मत, साक्ष व असाक्ष तथा कृषि व ग्रहण समितियों का विकास एवं साथ होना आवश्यक है।

(१०) ऊँची व्याज दर—जहाँ प्रायः तीन सस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है राष्ट्रीय सहकारी बैंक केन्द्रिय सहकारी बैंक को जहाँ देने हैं, केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रारम्भिक सहकारी साक्ष समितियों को और मास समितियाँ सदस्यों को जहाँ देती हैं। इसमें धन्य बढ़ जाता है जिससे कर्तावश्य व्याज की दर में भी वृद्धि हो जाती है।

(११) अत्यधिक पुराने ऋणों की विद्यमानता—अत्यधिक पुराने ऋणों की विद्यमानता आन्दोलन का एक प्रमुख दोष है। जो सदस्य अपने पुराने ऋणों को क्षिप्त होते हैं उन्हें भी अनुत्पादक उद्देश्यों के लिये अडे-अडे जहाँ दे दिये जाते हैं। इन प्रकार समय पर जहाँ को चुकाना नहीं जाता जिसके कारण अत्यधिक जहाँ (Overdues) में पर्याप्त वृद्धि हो गई है।

(१२) ऋणों की वेदना आर्थिक माँग की पूर्ति—समितियों से कितना की छोटी सी माँग पूरी होती है, शेष के लिये उसे बाँच के महाजन या साहूदार पर निर्भर रहना पड़ता है।

(१३) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जहाँ में प्रायः भेद नहीं किया जाता—प्रारम्भिक साक्ष समितियों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जहाँ में अन्तर स्पष्ट रूप से नहीं समझा है। अनेक समितियाँ दीर्घकालीन जहाँ देती हैं जिसमें इनका धन लम्बे समय तक फँस जाता है। अन्य सदस्य जहाँ बड़ी कठिनाई में ल पाने हैं।

(१४) जहाँ देने की मात्रा निश्चित नहीं है—सदस्यों को जहाँ देने की मात्रा निश्चित नहीं है। वे इच्छा धन लेकर निरर्थक व्यय कर देते हैं।

(१५) विविध समुदाय एवं धनी, जहाँ, जहाँ, की उदासीनता—विविध समुदाय एवं धनी जहाँ इन और उदासीन रहते हैं, क्योंकि उनके स्वयं के लिए समिति की आवश्यकता नहीं होती और यदि वे मदद बन भी जाते हैं तो अनुचित लाभ उठाते हैं।

(१६) अव्यवस्थित कार्यकर्त्ताओं की लापरवाही—काम करने वाले नेतन न मिलने के कारण लापरवाही में काम करते हैं ।

(१७) ऊपरी दिखावा—सहकारी कर्मचारी अपना कार्य दिखाने के लिये समितियों की सभा बसा कर दिखाते हैं । ठोस कार्य नहीं करते । प्रायः यह देखा गया है कि बहुत सी समितियाँ स्थापित होने के बाद एक वर्ष में ही भंग हो जाती हैं । इससे अतिरिक्त समितियों के पदाधिकारी अपने हिसाब निताब में इस ढंग से हेर फेर कर देते हैं कि अव्यवस्थित ऋण अधिक प्रतीत नहीं होते ।

(१८) कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता—समितियों के पास कुछ कार्यशील पूँजी का बहुत कम भाग स्वयं की पूँजी होती है । इसका कारण यह है कि समिति के सदस्यों में धन जमाकर रखने की आदत नहीं होती । ये समितियाँ भरा पूँजी द्वारा अपनी पूँजी एकत्रित भी नहीं करना चाहती । इसी कारण उनके बाहर से ऋण लेना पड़ता है । ऋण पर लिये हुये धन को ऋण का रूप में देने के कारण समितियाँ अधिक व्यय लेती हैं । इसलिये समितियों के सदस्य समितियों से ऋण लेने में कोई विशेष लाभ नहीं समझते ।

दोषों को दूर करने के सुझाव (Suggestions)

(१) सहकारी नियन्त्रण की सहकारी आन्दोलन पर से कम करना चाहिये । सहकारी विभाग का कार्य केवल निष्ठा देना, निरीक्षण तथा भ्रमण करना होता है और सारा आन्तरिक कार्य सहकारी सभाओं पर छोड़ देना चाहिये जिससे जनता का विश्वास बढ़े ।

(२) प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों को केवल अल्पवयस्कीन तथा मध्य-कालीन ऋण ही देने चाहिये ।

(३) ऋण केवल उत्पादन कार्यों के लिये देना चाहिये ।

(४) साख समितियों को सदस्यों के ऋण वापिस करने की क्षमता को भी देखना चाहिये । यह भी देखना चाहिये कि उनके सदस्य अपनी सभा में अधिक व्यय न करें ।

(५) साख समितियों के हिसाब किताब आदि की जाँच भत्तो प्रकार होनी चाहिये जिससे जनता का विश्वास बढ़े ।

(६) समित के सदस्यों, सहकारी कर्मचारियों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को सहकारिता के सिद्धान्त एवं कार्य प्रणाली के विषय में शिक्षा देने का पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये ।

(७) ऋण की मात्रा निश्चित कर देनी चाहिये ।

(८) साख समितियों को सुदृढ़ रिजर्व कोष बनाना चाहिये ताकि वे भविष्य की अनिश्चयताओं से बच सकें ।

(९) निरीक्षण और भ्रमण में लिये जिला सच बनाने चाहिये जिनमें कुछ सहकारी अनुभवों कर्मचारी नियुक्त किये जायें ।

(१०) वेदमान सदस्यों और पदाधिकारियों को समितियों में भिन्नता देना चाहिये और सदस्यों को सभा में समान सम्पत्ति चाहिये ।

(११) व्याज की दर कम करने के लिये समितियों को सहरो तथा गाँवों में सस्ती दर पर ऋण देना चाहिये । मन्द-व्यापार के दिनों में त्रियाशीत व्यापार के दिनों के लिये सस्ते व्याज पर ऋण एकत्रित करना चाहिये ।

(१२) राजकीय व केन्द्रीय बैंकों का प्रबन्ध अनुमती और वैधिय योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए ।

(१३) साख-समितियों तथा रिजर्व बैंक के कृषि-विभाग में पूरा सहयोग होना चाहिए ।

(१४) खेतों की उपज के सत्रहवाँ गोदाम बनाने के लिए समितियाँ तथा केन्द्रीय बैंक को रियायती दर पर ऋण देना चाहिए ।

(१५) सरकार को इन समितियों को छाव कर, रजिस्ट्रेशन फीस, मुद्राक-कर, प्रतिगित-कर (Super tax) तथा न्यायालय शुल्क (Court-fee) से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि उनके व्यय कम हो जायें और वे व्याज की दर कम कर दें ।

(१६) सहकारी के बापों के विरुद्ध विशेष कानून बनाये जाने चाहिए ।

(१७) केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नियमन एवं कनेटो द्वारा होना चाहिए जो इन समितियों द्वारा बनाई गई हो ।

(१८) समितियों का विस्तार बढा न होना चाहिए । यदि सदस्यों की संख्या समिति में अधिक होगी तो उत्पन्न प्रसंग उत्पन्न हो जायगा । इससे निपरीत यदि सदस्यों की संख्या बहुत कम है, तो प्रबन्ध कठिन हो जायगा ।

(१९) सहकारी साख समितियों को पूर्ण सफलता प्राप्त होने के लिए गाँव वालों का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है ।

(२०) 'गैडगिल आयोग' (Gadgil Commission) ने राजकीय कृषि साख निगम (State Agricultural Credit Corporation) की स्थापना की सिफारिश की है जो प्रादेशिक आत्मसहायता को पूर्ण करेगा । परन्तु जहाँ राजकीय सहकारी बैंक हैं, वहाँ इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 'नानावटी कमेटी' ने भी इस निगम का समर्थन नहीं किया ।

(२१) भारत सरकार ने सन् १९४८ में एक ग्रामीण बैंकिंग जाँच कमेटी नियुक्ति की जिसने वितम्बर सन् १९४९ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । कमेटी ने सहकारी समितियों के लिए निम्न सुझाव दिये हैं : (अ) सरकार को सहकारी संस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए । (आ) ग्राम्य और मध्यकालीन ऋण देने के लिए राजकीय बैंकों की संस्था बढाकर उनको अधिक हट्ट बनाना चाहिए । जहाँ ऐसा सम्भव न हो तो वहाँ राजकीय कृषि साख प्रमण्डल स्थापित किये जान चाहिए । (इ) क्षेत्रीय स्तर पर ग्राम्य भूमि-विकास बैंकों द्वारा किये जाने चाहिए । जहाँ न नहीं है उनकी स्थापना होनी चाहिए । (ई) इन समितियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए । (उ) जमींदारों व राजामा आदि से जिनकी बचत बढ रही है समितियों को जमा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

(२२) एक-उद्देशीय समितियों (Single-purpose Societies) के स्थान पर बहुउद्देशीय समितियों (Multi-purpose Societies) की स्थापना होनी चाहिए ।

बहुवृत्तीय समितियाँ की स्थापना से विभिन्न प्रकार की अनेक समितियाँ (जैसे साख समिति, विपणन समिति, गृह निर्माण समिति, उपभोक्ता समिति आदि) स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

भारतीय सहकारी आन्दोलन की सफलताएँ (Achievements)—
सहकारिता आन्दोलन ने भारत में जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं वे इस प्रकार हैं —

(१) इस आन्दोलन के कारण कई ग्राम स्तरों में महाजनने अपना ध्यान को बर गिरा दो है।

(२) इसके कारण जनता में मितव्ययता का प्रचार हुआ है।

(३) इसके कारण अनाजव्ययक कृषि क्षेत्रों को प्रवृत्ति कम हो गई है।

(४) इसके कारण किसानों का नैतिक स्तर ऊँचा हो गया है।

(५) सहकारी भण्डारों से मध्यम वर्गों को इस भंडारों के समय बड़ा लाभ पहुँचा है।

(६) इसके कारण गृहरी प्रोजेक्टिया और कायकर्मियों के दिना म गाँवों के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है।

उपसंहार—भारत में सहकारिता आन्दोलन को प्रारम्भ हुए लगभग ५० वर्ष हो गये परन्तु फिर भी इसकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् आन्दोलन में कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण इसका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होने लगा है। द्वितीय महायुद्ध-काल में गया इसके उपरान्त कृषि उपजों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ जिसके कारण समितियाँ तथा केन्द्रीय बन्धन का विकास कृषि बल्लूत होने लगा। अब भी भारतवर्ष में सहकारिता के लिए सभी दिशाओं में प्रयास हो रहे हैं। अब तक भारत में लाखों की कृषक की जीवन के एक अंग को छुआ है। अब हमें बहुवृत्तीय समितियों (Multi-purpose Societies) प्रारम्भ करने अथवा नये सहकारिता से लाभ उठाना चाहिए। भारतवर्ष सभी का देश है और सहकारिता को ग्राम सुधार का सभा अंग के लिए मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए।

भारतवर्ष में असाख सहकारिता

(Non Credit Cooperation in India)

भारतवर्ष — सन् १९०४ में सहकारिता का प्रारम्भ किसानों की महाजनने के अग्रणी बचाने और उनकी कम धन पर अपना उधार देने के उद्देश्य से हुआ था किन्तु कम धन पर अपना उधार मिलने में ही तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सहकारी मात्र आन्दोलन तो नहीं सफल हो सकता है जब सेना उन्नत अवस्था में हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि सेना की चरचरी हो अन्तर्गत चीजों के वैज्ञानिक उद्योग अच्छी साद सिचार्ड ने समुचित साधन किसानों को उपलब्ध हो। अब असाख सहकारिता की आवश्यकता के परिणामस्वरूप सन् १९१२ में सहकारी समितियाँ का नया कानून पास हुआ जिसमें असाख समितियाँ के रजिस्ट्रेशन की आज्ञा दी गई। इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार की असाख समितियाँ की स्थापना हुई जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है —

सहकारी मार्केटिंग (विपणन) (Cooperative Marketing)—
यूरोप व अमेरिका आदि देशों में सहकारी मार्केटिंग ने बड़ी उन्नति की है। यह

अनुमान लगाया जाता है कि सेतो की उपज का लगभग २५% भाग सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाता है। यूरोप में मार्केटिंग सहकारिता की उन्नति का श्रेष्ठ उदाहरण है जहाँ यह आन्दोलन पूर्ण सफल सिद्ध हुआ है। जब कुछ व्यक्ति सहकारिता के सिद्धान्त पर आपस में मिलकर अपनी पैदावार को बेचते हैं तो इसे सहकारी मार्केटिंग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा धी बेचने वाली समितियाँ, बम्बई में रई बेचने वाली समितियाँ, मद्रास में बान की विभिन्न समितियाँ सहकारी मार्केटिंग के कुछ उदाहरण हैं।

सहकारी मार्केटिंग (हाट) समिति के मुख्य कार्य—एक सहकारी मार्केटिंग समिति के निम्नलिखित मुख्य कार्य होने हैं :—

(१) समिति के सदस्यों की पैदावार को सीधा उनसे खरीदना, (२) सदस्यों के माल पर कुछ प्रतिशत पेसगी देना, (३) उपयुक्त गोदाम की व्यवस्था कर सदस्यों के माल को संग्रह कर उसका स्टोरेज आदि करना, (४) सदस्यों के माल को बम्बईन के आधार पर बेचना।

सहकारी मार्केटिंग के लाभ (Advantages)—सहकारी विपणन-समितियों के प्रमुख लाभ हैं जैसे अधिक बिक्री, स्थिर उत्पादन, उत्पादकों की सीधा करने की शक्ति से वृद्धि, खर्चा घट जाना, उपज का ऊँचा मूल्य प्राप्त होना, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करना, उत्पादकों को सहकारी मार्केटिंग तथा सामूहिक प्रयत्नों से सिखे शिक्षित करना आदि।

भारतवर्ष में सहकारी मार्केटिंग की प्रगति—बम्बई में Cotton Sales Societies ने बड़ी उन्नति की है। मूलतः की Cotton Sales Societies ने हाल में ही अपना सच स्थापित कर कपास संशोधन के अपने ही कारखाने स्थापित कर लिये हैं। कलकत्ता में कई Paddy Societies बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य कर रही हैं परन्तु बंगाल की सूत समितियों ने अभी आरम्भगत उन्नति नहीं की है। पंजाब में कई सहकारी बम्बईन बूकानें हैं जो उत्पादकों की उपज को अपने गोदामों में संग्रह कर अच्छे मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करती हैं। मद्रास में भी इसी आधार पर कई निरक्षर समितियाँ बनी हुई हैं परन्तु उनको अभी अधिक सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश और बिहार की गन्ना विपणन समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की सहकारिता—सहकारिता से तान उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों की ही पहुँचता है। उत्पादकों ने अपनी बच, विपणन, बचवन्दी, निर्यात, पशु, बीमा आदि की समितियाँ सहकारी सिद्धान्तों पर स्थापित कर लाभ उठाया है, और उपभोक्ताओं ने अपने सहकारी मंडल संगठित कर लाभ उठाया है। नीचे दोनों प्रकार के सहकारी संगठनों का विवरण दिया जाता है—

सहकारी विक्रय समितियाँ (Cooperative Sales Societies)

परिचय—विज्ञान अशिक्षित तथा अशुद्ध हैं, अतः वे बाजार-भावों से अनभिज्ञ रहते हैं और बहूधा वस्तु के बेचन में उचित मूल्य नहीं पाते। साथ वे घनिष्ठ दू लेन देन के धड़े-बड़े व्यापारी तक सभी विज्ञान की अज्ञानता तथा निर्बलता का अनुभव लाभ उठाते हैं। इस घुसाई को दूर करने में तब सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित की गई हैं।

समितियों का निर्माण—तीन चार गांवों को मिलाकर एक समिति स्थापित की जाती है। केवल वे लोग ही इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं जो स्वयं उत्पादक हों।

पूँजी एवं दायित्व—पूँजी अशा में बँटी होती है। प्रत्येक सदस्य को एक अंश या शेयर सौंपी दना पड़ना है। उत्तरदायित्व सीमित रहता है।

कार्यप्रणाली—सदस्यों के लिये यह अनिवार्य होता है कि वे समिति के द्वारा हो अपनी उपज बेचें। फसल के समय उपज समिति एकत्रित कर लेती है और बाजार-भाव के आधार पर किसानों को अपना काम चलाने के लिये ६० प्रतिशत मूल्य पेन्शनरी (Advance) दे दिया जाता है। उपज समितियों के गोदाम में रख की जाती है। समिति के अधिकारी बाजार से सम्पर्क रखते हैं और उचित मूल्य मिलने पर बिक्री करते हैं। समितियों को बड़े दुकानदारों से प्रतियोगिता करने पड़ती है इसलिये बहुत-सी समितियाँ संघ स्थापित कर लेती हैं जिससे उन्हें बड़े दुकानदारों से प्रतियोगिता करने में कठिनाई नहीं होती।

लाभ विभाजन—लाभ बाँटने के पूर्व २५ प्रतिशत लाभ रिजर्व कोष में रख दिया जाता है।

राज्यानुसार विक्रय समितियों की प्रगति—इस प्रकार की समितियाँ अपने-अपने प्रांतों में स्थापित हो गई हैं। इनके स्थापित करने में बम्बई प्रान्त सबसे आगे रहा है। कपास की बिक्री के लिये प्रान्त भर में ११० समितियाँ कार्य कर रही हैं। सन् १९४१-४२ में इन समितियों ने १ करोड़ ३० लाख रुपये का कपास बेचा था। मद्रास प्रान्त में इस प्रकार की समितियाँ उपज के ऊपर खण देती हैं और उपज इकट्ठी करके बेचती हैं। कुल १८५ समितियाँ कार्य कर रही हैं और सन् १९४१-४२ में ७५ लाख की पैदावार इन समितियों के द्वारा बिकी थी। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बहुत सी समितियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें में गन्ने की सहकारी समितियाँ उल्लेखनीय हैं। जिलाना गन्ना कारखाने सेते हैं, सक्का ७० प्रतिशत बन्ना इन समितियों द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ६०० में अधिक गन्ना बेचने की, तथा ७०० में अधिक समितियाँ थी बेचने की है। इन समितियों के काम की उचित रीति से चलाने के लिये प्रान्तीय विज्ञान समितियाँ स्थापित की गई हैं। कई सहरो में आजकल बहुधा दूध की विक्रय समितियाँ स्थापित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में २५ से अधिक दूध विक्रय समितियाँ हैं जिनमें में १७ तो प्रकैल लखनऊ में ही हैं।

सहकारी विक्रय समितियों के मन्द-गति के कारण—विक्रय समितियाँ अपनी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है, क्योंकि उन्हें (१) धन की कठिनाई रहती है, (२) व्यापारी अनुचित प्रतियोगिता करके समितियों की भय करने का प्रयत्न करते हैं, (३) उपज सप्लाय गोदामों की कठिनाई होती है, (४) सदस्यों में सहकारिता के भाव का अभाव रहना है, (५) अधिष्ठा के कारण कुछ-अन्यक्तों का अभाव रहता है।

सहकारी क्रय समितियाँ (Cooperative Purchase Societies)

परिचय—क्रय समितियाँ अपने सदस्यों के लिये सस्ते भावों पर उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ खरीदती हैं, जैसे—किसान के लिये सेतों के धोआर, खाद, बीज आदि। ये समितियाँ अपने सदस्यों से पूछकर उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं

की मूची बना लेती है और थोक व्यापारी या सीधे कारखाने से थोक भाव पर खरीद लेता है। इस प्रकार सदस्यों को अच्छी वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिल जाती हैं।

पूर्वोक्त एव दागित्व—इन समितियों की स्थापना सीमित उत्तरदायित्व के आधार पर होती है और सदस्यों को ग्रस खरीदने पड़ते हैं। ग्रसों पर लाभदा भी बीटा जाता है। प्रवन्ध समिति का प्रवन्ध एव प्रवन्धकारणी कार्यसमिति के द्वारा होता है, जिसका निर्वाचन सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा में होता है।

भारतवर्ष में सहकारी क्रय समितियाँ—भारत में कुछ क्रय समितियाँ बहुत कम हैं। अधिकतर विभिन्न समितियाँ क्रय विभाग होना ही कार्य करती हैं। क्रय समितियाँ अधिक सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि सदस्य समितियों के काम में रुचि नहीं रखते और ये केवल वस्तुएँ क्रय ही करती हैं जिसमें यह कार्य सीमा ही समाप्त हो जाता है। इसलिये जो समितियाँ क्रय विभाग होना ही कार्य कर रही हैं वे ही अधिक सफल हुई हैं।

सहकारी चक्रवन्दी समितियाँ

(Cooperative Societies for Consolidation of Holdings)

परिचय—भारतवर्ष में लेती की हीन-शता का एक बारण्ड क्षेत्र का छोटा तथा दूर दूर छिटा होना है। इस घुसई को दूर करने के लिये चक्रवन्दी समितियों का निर्माण हुआ।

प्रवन्ध एव कार्यप्रणाली—चक्रवन्दी समितियाँ स्थापित करने के लिये किसानों को भेरी के बिछरे होने की घुसईयाँ समझाई जाती हैं और उन्हें इस बात पर महसूस किया जाता है कि वे अपने खेत बदल लें। जब वे राजी हो जाते हैं तब उन किसानों को सदस्य बनाकर सहकारी चक्रवन्दी समिति की स्थापना की जाती है और एक कार्य-करिणी समिति चुन ली जाती है। वायकरिणी समिति सहकारी विभाग के कमिश्नरिया के सहयोग से प्रत्येक खेत का भूमि की उपजाऊ सक्ति के आधार पर वर्गीकरण करती है, और प्रत्येक खेत का भूमि निश्चिन कर दिया जाता है। उपरर सूच्य भावे लेता के चक्र तैयार कर लिपि जाने हैं और प्रत्येक किसान को खेत के कुल पूंज्य के उपरर लेत एक चक्र म दे दिया जाता है; और नये बँटवारे की रजिस्ट्री हो जाती है।

भारतवर्ष में चक्रवन्दी समितियों की प्रगति—सहकारी चक्रवन्दी समितियाँ पंजाब में बहुत स्थापित हुई हैं, तथा उन्ह पर्याप्त सफलता मिली है। पंजाब में इस प्रकार की समभाग का हजार समितियाँ बनी हैं, तथा उनसे प्रतिवर्ष दो लाख एकड़ भूमि की चक्रवन्दी होती है। अन्य प्रांता में भी इस प्रकार की समितियाँ बनी हैं। उत्तर प्रदेश के मरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर, बुलन्दशहर, रामपुरेली आदि १४ जिला में यह कार्य चल रहा है। भारत द्वारा चक्रवन्दी अनिवार्य कर से जाने में इसमें सीमा सफलता मिल सकती है।

सहकारी सिंचाई समितियाँ (Cooperative Irrigation Societies)

परिचय—भारतवर्ष में जल वृषि प्रधान देश के सिंचे सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, सर्व विदित है। परन्तु हमारे यहाँ पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः सिंचाई की सुविधाओं के लिये सर्वे सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है। इस समस्या की भी सहकारिता प्रणाली के आधार पर हल करने का प्रयत्न किया गया है।

पूँजी एवं कार्य-प्रणाली—यहने समिति स्थापित की जाती है। इस समिति के सदस्य को अपनी मृत्ति के अनुपात में समिति के भूशेखर को खरीदना पड़ता है। साथ ही-साथ समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सरकार में कुछ लेकर सिचाई के साधन बनवाती है; और सदस्यों से पानी के बख्ते में जो धन प्राप्त होता है उसमें कुछ चुकाती है। ये समितियाँ सिचाई का उचित प्रबन्ध करती हैं।

भारतवर्ष में सिचाई समितियाँ—इन प्रकार की समितियाँ पहले बंगाल में प्रारम्भ की गई थीं। सिचाई समितियों ने बंगाल और बिहार में बड़ी उप्रति की है। पहले बिहार में इनकी संख्या लगभग १००० है। इन समितियों में बार लाख रुपये लगा हुआ है, और सदस्यों की संख्या लगभग २०,००० है। कुछ कार्य उत्तर-प्रदेश में भी हुआ है।

रहन सहन सुधार समितियाँ (Better Living Societies)

उद्देश्य—रहन सहन सुधार समितियों का मुख्य उद्देश्य गाँवों में प्रचलित कुरीतियाँ, जैसे—बिवाह, जन्म, मृत्यु आदि अवसरों पर अप्रत्यय करना, तथा गाँव वालों के रहन-सहन को ऊँचा करना है।

मुख्य कार्य—इन समितियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं (प्र) रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना है (भा) अप्रत्यय बन्द करना, (इ) मकानों में रोखनी, सफाई का प्रबन्ध करना, (ई) कुँआ को मरामत करना, (उ) गाँवों को सड़कों को बनवाना अप्रत्यय सुधार करना, (क) खाद के लम्बे बनवाना (ए) सुशिक्षित दास्यों का गाँव में रचना, (ए) जेवर पर अधिक व्यय न करने के लिए गाँव वालों को समझाना है।

संगठन एवं प्रबन्ध—इन समितियों के सदस्यों को अक्ष अप्रत्यय रोखर गहरी खरीदने पड़ते हैं, और न समिति की कोई धन पूँजी (Share Capital) हो होती है। प्रत्येक सदस्य को, जो समिति में नियमों और सिद्धान्तों को मानने के लिये सौम्य होता है, प्रवेश-मुक्त देना पड़ता है। समिति के सदस्यों में कोई चन्दा नहीं लिया जाता है। सदस्य मिलकर कुछ नियम बनाते हैं, जिनका पालन प्रत्येक सदस्य को करना आवश्यक है। जो सदस्य इन नियमों की अवहेलना करता है उसे दण्ड देना पड़ता है। समिति का साधारण सभा एक वर्ष के लिये योजना बनाती है और छत्ते कार्यान्वित करती है। प्रतिवर्ष नई योजना बवाई जाती है; किन्तु नव वर्ष का कार्य-क्रम बाध रहता है।

भारत में इनकी प्रगति—सर्व प्रथम पञ्जाब में इनकी स्थापना हुई किन्तु उत्तर-प्रदेश में इनके संगठन में बड़ी प्रगति दिखाई है। पञ्जाब में केवल १,६०० समितियाँ हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग ६,००० हैं। उत्तर प्रदेश में इन समितियों का संगठन ग्राम सुधार निगम के प्रयत्नों से हुआ है।

सहकारी गृह निर्माण समितियाँ (Cooperative Housing Societies)

सहकारी गृह निर्माण समितियाँ अपने सदस्यों के लिये मकान बनाती हैं, और मकान बनवाकर किराये पर उठा देती हैं। ये समितियाँ भाषा भवन का चौपाई रूप धारण करती हैं, और दोष रूप का मकान को जमानत पर उधार ले लेती हैं। ये समितियाँ भारतवर्ष में मद्रास, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, अलीपुरा आदि नगरों में पाई जाती हैं। इन समितियों को सत्ता दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

उपभोक्ता सहकारी भण्डार (Consumer's Cooperative Stores)

परिचय—उपभोग के क्षेत्र में सहकारिता अपनी ही आवश्यक है जिनको उत्पत्ति या माध्य के क्षेत्र में। वस्तुएँ खरीदने में गाँव तथा शहर दोनों के निवासी पाठे में रहते हैं, क्योंकि वस्तुओं का मुख्य अधिक देना पड़ता है; और शुद्ध वस्तुएँ नहीं मिलती। इसका और अधिक की तो बड़ी ठगाने हैं। वस्तुओं का मुख्य हमलिये अधिक हो जाता है कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच में बनेका मध्य-पुण्य रहने है, और प्रत्येक अपना अपना लाभ कमल करता है। यही नहीं, यदि मध्यजन इतने लाभ में मस्तुष्ट नहीं होते तो निम्न वस्तुओं का समिप्रभु भी कर देते हैं। इन्हीं सब बुगण्या को दूर कर करने के लिये उपभोक्ताओं के सहकारी भण्डारों का निर्माण हुआ है।

उद्देश्य—सहकारी भण्डार का उद्देश्य मध्य-पुण्यों के लाभ को रोकना तथा शुद्ध वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचना है।

सहकारी भण्डारों का जन्म—इन सहकारी भण्डारों का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। सन् १८४४ में रॉकेटन (Rochdale) नामक स्थान पर कृषाजीन बुनने वाले २८ बुनकर (Weavers) ने २५ पौंड की पूँजी ग मुक्तिप्राप्त रॉकेटन सहकारी भण्डार स्थापित किया। उन्होंने केवल पाँच आवश्यक वस्तुओं का ही बेचना प्रारम्भ किया। सभी सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ में खरीदते थे। धीरे-धीरे वह भण्डार बहुत बढन हुआ, और धीरे-धीरे वह उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के कार्यकर्त्ताओं का प्रोत्साहन दे रहा है। रॉकेटन भण्डार की सफलता के कारण इंग्लैंड में अधिक के प्रत्येक सहकारी भण्डार खुलें।

भारतवर्ष में सहकारी भण्डारों का संगठन एवं प्रवर्धन—भारतवर्ष में भी बनना उपभोक्ता-सहकारी-भण्डार खुले हैं। इन भण्डारों का संगठन इंग्लैंड के निमित्तियों के सिद्धान्तों पर हुआ है। मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—(१) प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व सीमित (Limited) होता है। (२) सहकारी भण्डार के प्रत्येक या दोषर होने हैं; और प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक शेयर खरीदना पड़ता है। अधिक शेयर भी खरीद जा सकत हैं, परन्तु प्रत्येक सदस्य केवल एक ही वोट देने का अधिकारी होता है। (३) भण्डार की कार्यशील पूँजी यशों के विषय से ही प्राप्त होती है। (४) सदस्यों का अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं भण्डार में खरीदने वाली वस्तुओं में से खरीदनी पड़ती हैं। (५) भण्डार साधारणतया नकद बिजने करला है, और वादावधान पर या हमने कम माय पर शुद्ध वस्तुओं की बिजने करता है। (६) एक चौपाई लाभ रिजर्व फंड में जमा किया जाता है; और मध्य सदस्यों के लिये के अनुपात में वोट दिया जाता है। (७) साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में, जिसमें सम्मेलन सभी सदस्य रहने हैं, सहकारी भण्डार की नीति, वार्षिक विवरण किताब का लेखा, तथा उनकी जीव, नाम विवरण के सिद्धान्तों का निर्णय किया जाता है। (८) साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में दिन प्रति-दिन के कार्य-समन्वयन के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन हा जाता है, जो भण्डार के वैनिक कार्यकारिणी के कार्य का निरीक्षण करता है।

भारतवर्ष में उपभोक्ता-सहकारी भण्डारों की प्रगति—भारतवर्ष में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की सङ्ख्या बहुत कम है। सन् १९४६-४७ के आँकड़ों के अनुसार

हमारे देश में इस प्रकार के केवल ८,९४६ भंडार थे । ये केवल नगरों में ही स्थापित हुये हैं । स्कूलों और बालिकाओं में विद्याविषय तथा घघ्याएकी की आवश्यकता की वस्तुएँ बेचने के लिये इनकी भंडार भुजे हैं । रेखवे तथा डरुवर के कर्मचारियों के लिये भी सहकारी भंडार खुले हैं, और इनकी पर्याप्त सफलता भी मिली है । मद्रास त्रिपलीकेन भंडार (Madras Triplicane Store) ने तो भारस्वजनक उत्ति की है । यह भंडार सन् १९०४ में प्रारम्भ हुआ था और अब इसके पास निजी भवन भी है । इसकी प्रस-पूजी १ लाख रुपये से अधिक है, इसका रिजर्व कोष २ लाख रुपये के लगभग है, और इसकी शाखाएँ नगर के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं । इसे लगभग १२ लाख रुपये वार्षिक का लाभ होता है । मद्रास, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में कुछ भंडार सफल हुए हैं । किन्तु इन भंडारों की सफलता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सहकारी उपभोक्ता भंडार भारतवर्ष में सफल हुए हैं ।

भारतवर्ष में सहकारी उपभोक्ता भंडारों की असफलता के कारण —

- (१) सहकारी भंडारों के पास पूँजी की कमी रहती है । अतः की बिक्री से शायी पूँजी एकत्रित नहीं हो पाती कि यौक-क्रय विषय जा सके ।
- (२) सीमित वार्षिक होने से वैदेशीय बैंकों से ऋण भी नहीं मिल सकता ।
- (३) सहकारी भंडार मध्यम वर्ग के मनुष्यों में सफल हो सकते हैं परन्तु मजदूरों में नहीं । मजदूर महाजन के शायी रहते हैं, इसलिये वे न तो सहकारी भंडारों के सदस्य हो पाते हैं और न वहाँ से आवश्यकता की वस्तुएँ हो खरीद सकते हैं । अधिकजान मजदूर सामान उधार खरीदते हैं । उपभोक्ता भंडार सामान उधार नहीं बेच सकते ।
- (४) सहकारी भण्डारों की व्यापार-कुशल कार्यकर्ता नहीं मिलते, जिससे वे व्यापार-नुशल वणिज से प्रतियोगिता करने में असफल रहते हैं ।
- (५) सदस्य सहकारी भण्डारों में व्यापार-भूत मिश्रणों की नहीं जानते । अतः वे यह प्रस्ताव करते हैं कि वस्तुएँ बाजार-भाव से कम मूल्य पर मिलें । बाजार भाव से कम मूल्य पर बेचने से छोटे समय के लिये तो भण्डार का काम थोड़ा चलता है, परन्तु बाजार-भाव गिरने पर भण्डार को पाटा हो जाता है, और सदस्यों का भण्डार में से विश्राम उठ जाता है ।
- (६) बहुत-से भंडार उधार बिक्री करते हैं, जिसके कारण वे समाप्त हो जाते हैं ।
- (७) प्रबन्ध कारिणी के सदस्य प्रबन्ध-कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते और दैनिक कर्मचारी निष्प्रण की शिक्षिता के कारण मनमाना कार्य करते हैं ।
- (८) प्रबन्धकारिणी के सदस्य ईमानदार न हुए तो वे मैनजर के द्वारा अनुचित लाभ उठाते हैं, या मैनजर ईमानदार न हुआ तो वह अच्छे पास में लच्छा मांस मिलाकर अनुचित लाभ उठावेगा ।
- (९) प्रायः कार्यालय की सजायट, कर्मचारियों के वेतन आदि पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर दिया जाता है ।
- (१०) युद्ध आदि श्लाधारण परिस्थिति में वैदेशीय कार्यकर्ता तथा प्रबन्धकों द्वारा 'जॉक मार्केट' किया जाता है ।
- (११) धर्मियों की निरक्षरता उन्हें इनमें लाभ उठाने में बाधक होती है ।

सहकारिता का पुनर्संर्र्गठन (Reorganisation of Cooperation)

भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन को प्रायातोत सफलता नहीं मिली है । अस्तु इसका पुनर्संर्र्गठन होना आवश्यक है । अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक-उद्देश्य समिति (single-purpose society) द्वारा, अर्थात् ऋण देने-मात्र में ही किसानों की समस्त समस्याएँ हल नहीं की जा सकती । इसलिये विभिन्न जाँच कमेटियों तथा रिजर्व बैंक ने यह अनुमान रखा है कि एक-उद्देशीय समितियों के स्थान में बहु

उद्देश्य-समिति (Multi-purpose Societies) स्थापित की जायें, जिनमें कृषि के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहकारिता के विद्यालय पर हो सके।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ

(Multi-purpose Cooperative Societies)

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का अर्थ—सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समितियाँ को बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक समिति कृषि देने के अतिरिक्त किसान की खाद, बीज, औजार, उपज बेचने आदि का भी कार्य करती है, तो यह बहु उद्देशीय समिति कहलाती है। इस व्यवस्था के अभाव में ये सब काम बजाय एक समिति के अनेक अलग-अलग समितियों द्वारा सम्पन्न किया जायगा जो भारतीय कृषक के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है।

बहुउद्देशीय समितियों की आवश्यकता—(१) केवल कृषि की समस्या सुलझाने में ही कृषक को सब समस्याएँ हल नहीं हो पायें। खाद, बीज व बीबी के उपकरण प्राप्त करना, चककड़ी करना, उपज बेचना आदि प्रश्न भी उसके सामने हैं। यदि सहकारी समिति इन समस्याओं को भी हल करे, तो कृषक को सहकारिता में अधिक लाभ हो सकता है। (२) किसान के पास इनका धन एवं समय नहीं है कि कई समितियों का सदस्य बन सके। (३) गाँवों में विविध एवं कृषक कार्योंका भी अभाव होने से अनेक समितियों का अस्तित्व कठिन हो जाता है।

अतः एक ही समिति द्वारा अनेक प्रयोजन सिद्ध करना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है।

बहुउद्देशीय समितियों के कार्य—ये समितियाँ किसानों को कृषि देने के अतिरिक्त उनकी उत्तम खाद, बीज व कृषि-उपकरण देती हैं। ये समितियाँ उपज की बिक्री, किसानों की आवश्यकता की वस्तुएँ उचित मूल्य पर बेचना, रहन-सहन में सुधार करना, ग्रामीण नम्रों का फैला करके मुक्तसेवाओं को कम करना, पत्नी की चककड़ी करना, गाँव की सफाई तथा प्रोपगण्डों का आयोजन करना, प्रौढ-शिक्षा का प्रवर्धन, कुपोषिता-निवारण आदि अनेकों कार्य करती हैं।

लाभ (Advantages)—(१) सदस्यों की सभी आवश्यकताएँ पूरी होने के कारण वे समिति के कार्य में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। (२) इसका प्रत्यक्ष वृत्त एवं कम सर्वांश होता है। (३) अधिक कार्य होने के कारण मुक्तसेवा दैनिक कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं। (४) अधिक मध्यम तथा अधिक पूँजी होने के कारण उन्हें केन्द्रीय बैंकों में भरोसा में जगह मिल सकता है। (५) ये शासक-सुधार का कार्य प्रभावना पूर्वक कर सकते हैं। (६) इन समितियों द्वारा विद्यालयों में छात्रों में अल्पतः सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जो भिन्न-व्युत्तर काम करने में सार्थक सिद्ध होता है। (७) ये विद्यालय की सब समस्याओं के लिये समवायु बोधार्थ का कार्य करती हैं।

दोष (Defects)—(१) अनेकों कार्य करने के कारण यदि किसी एक कार्य में हानि हो जाय, जैसे—बीज-वितरण में या कृषि देने के साथ में, तो उसका प्रभाव समिति के अन्य कार्यों पर पड़ता है। (२) समिति का कार्य बढ़ना बिगड़न हो जाता है कि उसे कुशलतापूर्वक संभालना कठिन हो जाता है। (३) एक ही समिति में बहुत से

कार्यो का हिसाब रक्खना सम्भवतः कठिन हो जाया है । (४) सम्भवतः कुछ होशियार सदस्य मिलकर समिति को अपने अधिकार में कर लें, तो इस प्रकार की सहकारिता का उद्देश्य समाप्त हो जायगा ।

निष्कर्ष—यद्यपि ये कठिनाइयाँ वास्तविक हैं, फिर भी इस प्रकार की समितियाँ स्थापित करना हमारे लिये कल्याणकारी सिद्ध होया । अन्य देशों में किसानों के लिये इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई हैं तथा उनसे किसानों को बहुत ही लाभ हुआ है । संशय में, यह कहा जा सकता है कि बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ ग्रामीण आर्थिक तथा सामाजिक संगठन का वेद्य होंगी और ग्रामीण जनता में स्वावलम्बन तथा आशावाद के भावों का संचार कर सकेंगी तथा गाँवों की सर्वाङ्गीण उन्नति करने में सफल होंगी ।

भारतवर्ष में बहुउद्देशीय समितियों की प्रगति—यद्यपि भारतवर्ष में बहुउद्देशीय समितियाँ प्रयोगात्मक अवस्था में हैं, परन्तु फिर भी इनमें से बहुत सी समितियाँ ने बड़ी सफलता प्राप्त की है । इस प्रकार की समितियों की उन्नति मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, बम्बई, मैसूर आदि राज्यों में विशेष उल्लेखनीय है । सन् १९४७-४८ में भारतवर्ष में १८,१६२ बहुउद्देशीय समितियाँ थी, जिनमें ५,७७,३८६ सदस्य थे, ७९२८ लाख रुपये की कार्यशील पूँजी थी और उस वर्ष उन्होंने १९७'२४ लाख रुपये का ऋण दिया था । उत्तर-प्रदेश की सरकार ने ग्राम उत्थान बोर्ड की सरक्षता में इस प्रकार की समितियाँ स्थापित करने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अनेकों बहुउद्देशीय समितियाँ स्थापित हो गई हैं । अब तक २,००० से अधिक बहुउद्देशीय समितियाँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुकी हैं ।

सहकारिता और योजना—ग्रामीण कृषि सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार द्वितीय योजना काल में १०,४०० बड़ी सहकारी समितियाँ, १,८०० प्राथमिक मार्केटिंग (हाट) समितियाँ, ३५ सहकारी चीनी कारखानों, ४८ सहकारी कपास मॉटार्ड मिलों तथा ११८ अन्य सहकारी समितियों के संगठन के लिए व्यवस्था की गई है । योजना में केंद्रीय तथा राज्यीय गोदाम नियमों द्वारा २५० गोदामों के निर्माण और मार्केटिंग समितियों के लिए ११०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए ४,००० गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है । योजना काल में १५० करोड़ ६० दीर्घकालीन ऋण, ५० करोड़ ६० मध्यकालीन ऋण और २५ करोड़ ६० अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था की गई है । जब कि प्रथम योजना में केवल ३७ करोड़ ६० के ऋण की ही व्यवस्था की गई थी ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—भारत में सहकारिता भान्दोलन पर एक छोटा निबन्ध लिखिए ।

२—सहकारी सास समितियों पर टिप्पणी लिखिये ।

३—भारत में ग्रामीण सहकारी समितियाँ किन सिद्धान्तों पर आधारित हैं ? सदस्यों के संयुक्त और अकेले दायित्व के सिद्धान्त के लाभ बताइये ।

४—भारत में सहकारी भान्दोलन के साधनों का वर्णन कीजिए और इसकी मर्यादाएँ समझाइए ।

(४० वी० १९६०)

५—संक्षेप में एक ग्रामीण सहकारी भास समिति की कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिये ।

(४० वी० १९५७)

- ६—बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर टिप्पणी लिखिये ।
(रा० वी० १९१५; अ० वी० १९५१, म० भा० १९५१)
- ७—‘किमन सहकारी समिति’ के सिद्धान्त स्पष्ट कीजिये । भारतीय सहकारी समितियों
दमका वही तब पानन करती हैं ? (रा० वी० १९५३)
- ८—हमारे गाँवों में सहकारिता प्रान्दोलन की उन्नति के लिए एक योजना निर्माण
कीजिए । (अ० वी० १९६०)
- ९—भारत में सहकारिता प्रान्दोलन ने क्या संयन्त्राण प्राप्त की है ? देश में सहकारी
प्रान्दोलन की घीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिये । (रा० वी० १९५६)
- १०—भारत में ग्राम सहकारों मात्र-समितियों विन-विन विद्यालयों के अनुसार स्थापित
होती हैं ? इनके सदस्यों की सुम्भितन और प्रसिद्धन निम्नकारी के विद्यालयों के
सामों की समझाये । (अ० वी० १९५७)
- ११—सहकारी स्टार पर नोट लिखिये ।
(अ० वी० १९५४, ५१, ४०, म० भा० १९५४)
- १२—सहकारी प्रान्दोलन की घीमी प्रगति के कारणों पर विचार कर और सुधार के
सुझाव कीजिये । (म० भा० १९५५, अ० वी० १९५८)
- १३—उपमोक्ष सहकारी स्टोर ने क्या आर्थिक लाभ है ? इनकी प्रगति के कारण
समझाये । (म० भा० १९५६)
- १४—प्रारम्भिक ग्रामीण सहकारी साम समिति की कार्य विधि का वर्णन करिये ।
(रा० वी० १९५८, अ० वी० १९५९, सगर १९५१)
- १५—भारत में सहकारिता प्रान्दोलन के विकास का सलित वर्णन कीजिये और इसके
धोनों का उल्लेख कीजिये । (दि० वी० १९५०, ४७)
- १६—भारतीय ग्राम्य-सहकारिता मण्डल का वर्णन कीजिये । उससे प्राप्त लाभ वसुध में
समझाये । (तामपुर १९५५)

इण्टर एग्जीनल्वर परीक्षाएँ

- १७—‘भारतीय वृषि की मयम्याया की मुनमाने व लिए सहकारिता का महत्व’
विषय पर लेख लिखिये ।
- १८—भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों स्थापित करके साम्रा का वर्णन
कीजिये । (अ० वी० १९५२)

"यदि कृषि और उद्योग राष्ट्रकी प्राप्ति का शरीर और हड्डियाँ हैं, तो यातायात उनके जीवन-जन्तु है।"

यातायात की परिभाषा—मनुष्यों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को यातायात कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार यातायात में वे सब साधन एवं सुविधाएँ सम्मिलित हैं जिनके द्वारा वस्तुएँ तथा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। पदार्थों तथा प्राणियों के स्थान परिवर्तनकारी सम्पूर्ण साधनों का सम्मेलन यातायात होता है।

यातायात का महत्व (Importance of Transport)—मानव सभ्यता के विकास में यातायात के साधनों का विशेष महत्व रहा है। यदि कृषि और उद्योग-धन्ये किसी देश के प्राथमिक जीवन के शरीर और हड्डियाँ बानी जायें तो यातायात को उस प्राथमिक ढाँचे की स्नायु-प्रणाली मानना चाहिए। व्यापार, कृषि और उद्योगों की उन्नति इसी की सहायता से सम्भव हो सकी है। बड़े-बड़े दूर के स्थान अब छोटे-से समय में ही पार किये जा सकते हैं। वास्तव्यवस्था, देश-रक्षा और समाज की दृष्टि से भी यातायात का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यातायात के साधनों का देश के उद्योग-धन्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कच्चा माल उत्पन्न होने के स्थान से कल-कारखानों तक और पक्का माल देश के कोने कोने में और विदेशों के बाजारों को भेजने में सहायता देते हैं। सस्ते, शीघ्र और उत्तम यातायात के साधनों की सहायता से ही देश में उद्योग-धन्यों की उन्नति हो सकती है। जहाँ यातायात के अच्छे साधन नहीं होते वहाँ उद्योग धन्यों का केन्द्रीकरण हो जाता है, जिससे देश, समाज तथा उद्योग-धन्यों को हानि पहुँचती है। यातायात के साधनों की उन्नति के परिणामस्वरूप सारा समार एक बाजार के रूप में परिणत हो गया है। वास्तव में, यातायात व सम्वाद के साधनों ने वसुधैव कुटुम्बकम् (समस्त विषय एवं कुटुम्ब ही हैं) की पूर्णतया श्रितार्थ कर दिया है।

यातायात से लाभ (Advantages of Transport)

[अ] कृषि पर प्रभाव (Effects on Agriculture)—यातायात के साधनों की उन्नति ने कृषि को निम्न प्रकार प्रभावित किया है :—

(१) कृषि का व्यापारीकरण (Commercialisation of Agriculture)—यातायात के साधनों ने कृषि को जीवन यापन व्यवसाय के स्थान पर एक व्यापारिक व्यवसाय बना दिया है। किसान लोग अब खेती से वे ही वस्तुएँ उत्पन्न नहीं करते जिनका वे स्वयं उपभोग करते हैं, बल्कि दूरस्थ बाजार में बेचने के लिये भी

कृषि-पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के कृषि-पदार्थों का व्यापार विस्तृत हो गया है।

(२) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (Perishable) की उत्पत्ति में वृद्धि—शीघ्रशीघ्रता यातायात के साधनों के कारण किसान लोग शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ फल-शाम-भाजी आदि पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करते हैं, क्योंकि उपज देने के द्वारा दूरस्थ बाजार में जा सकती है।

(३) कृषकों की शिक्षा—यातायात के साधनों में उन्नति होने से किसान व समस्त ग्रामीण जनता का एक स्थान से दूसरे स्थान को सुविधता में आना जाना होने लगा है जिससे उन्हें कृषि सम्पन्धी मेक, प्रदर्शनियाँ आदि देखने का अवसर मिलने लगा है, तथा शहरी अनुष्ठा के अधिवाधिक सम्पर्क में आने से उनकी ज्ञान-वृद्धि होने लगी है। उनमें रुचिकावित्ता, जाति-पाति का भेद न बन-ब सामाजिक नृपतिवर्गों में आने लगे हैं। उनका दृष्टिकोण विस्तृत होता जा रहा है।

(४) ग्रामीण धर्मिकों की गतिशीलता में वृद्धि—यातायात के साधनों से ग्रामीण धर्मिक प्रवक्ताओं के कारखानों आदि में काम करने में सिले जाने लगे हैं। अपनी गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों में जाने की हिचकिचाहट अब दूर हो गई है।

(५) कृषि प्रशासिकों में उन्नति—यातायात के साधनों के कारण कृषि-प्रशासिकों में उन्नति होने लगी है। बिमान दूर-दूर के स्थानों में हज़, ट्रंक्कर, तथा अन्य सव्य की धन्य मशीनों की प्राप्त कर सकता है। उसके नियंत्रण में बेसी व बीजारी बीज, बीर खादों के उपयोग की शिक्षा ग्रहण करने सम्भव हो जाता है। कृषि विभाग व अधिकाारी एक बर्मेचारी अब उस तक पहुँच सकते हैं और उस पशुधन व बीज तथा बीजपुष्पा की बीमारियों का उपचार सिला सकते हैं। सहकारी बिजली जाँच कृषक की प्राथमिक स्थिति सुधारने में सहायक है बिना यातायात के साधनों में सम्भव नहीं हो सकती।

(६) कृषि वस्तुओं के बाजार में विस्तार—यातायात के साधनों के कारण अब कृषि वस्तुएँ दूर के स्थानों में भी बाजार में लाना सम्भव हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उत्पत्ति बड़े परिणाम में होने लगी है।

(७) कृषि-उत्पादन के मूल्य में स्थिरता—यातायात के साधनों द्वारा कृषि-उत्पन्न एक स्थान में दूसरे स्थान का सीधे संपर्क में पहुँचाई जा सकती है। इससे एक मात्रा में अधिक उत्पन्न बढ़ाव नहीं होने पाता।

(८) कृषकों के रहने सहने के स्तर तथा उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव—यातायात के साधनों द्वारा कृषक अपनी उपज दूर के स्थानों को बेच सकते हैं, जिससे बाजार उन्हें अच्छे मूल्य मिल जाता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इन साधनों द्वारा अब कृषक अपने दैनिक जीवन में अपने-ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते लग गये हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर सम्भव नहीं होता था।

[ग्राम] उद्योग-धंधों पर प्रभाव (Effects on Industries)—
(१) यातायात के साधनों से देश के उद्योग-धंधों के विकास में पर्याप्त सहायता मिली है। शीघ्रशीघ्रता साधनों के कारण दूर-दूर तक पचा मास औद्योगिक-वैज्ञानिक तक

सुरक्षा से लाया जाता है; और नकार किया हुआ मान भी आसानी से सुदूर दशानों को भेजा जा सकता है ।

(२) बड़े परिमाण के उत्पादन को प्रोत्साहन—बड़े परिमाण का उत्पादन भी मानवापठ के कारण ही ممکن हो सता है ।

(३) वैदेशीयकरण के दोषों को दूर करने में सहायक—यह मानव समाज अन्वेषित वैदेशीकरण को हानि न पहुँचाता है, यद्यपि मानव विदेशीकरण में भी सहायक हो रहा है ।

[इ] व्यापार पर प्रभाव (Effect on Trade) व्यापार वृद्धि में सहायक—व्यापार की वृद्धि मानवापठ के साधनों पर ही निर्भर करती है । इसके कारण ही व्यापार स्थानों पर व्यापार बढन-बढन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिणत हो गया है । अतः यह कहा जा सकता है कि व्यापार और मानवापठ के साधनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

[ई] वनों पर प्रभाव (Effect on Forests) —वनों का उचित प्रयोग—वनों का उचित प्रयोग मानवापठ के साधनों में ही सम्भव हो सका है । फर्नीचर, वाहन आदि अनेक वन-उत्पादों को उद्योगों का विनाश मानवापठ के साधनों के कारण हो रहा है । आज मानवापठ के साधनों द्वारा दूर-दूर के वनों की लकड़ों व अन्य वस्तुओं को व वनों-वनों में पहुँचाया जा रहा है ।

[उ] सामाजिक प्रभाव (Social Effects) —(१) समाज की उन्नति—मानवता का प्रचार, ज्ञान की वृद्धि, विचार, अनुभव, और कला का विनिमय, अपभार का दूर होना आदि कार्य मानवापठ के ही कारण सम्भव हो गए हैं ।

(२) धार्मिक माना, शिक्षा प्रचार, पारस्परिक प्रेम, और सद्भावना का प्रचार—धार्मिक माना, शिक्षा प्रचार, पारस्परिक प्रेम व सद्भावना आदि माना के प्रकार का धर्म मानवापठ के साधनों की ही है ।

(३) पिछड़े हुए भू-भाग के मानव-समाज की सम्यक् वृद्धि में सहायक—साधुनिक साधनों ने जहाँ-जहाँ मानव-समाज का विशेषकर पिछड़े भू-भाग की सम्यक् वृद्धि में अनेक सहायक दिया है । इस साधनों के कारण समाज सुव्यवस्था-व्यक्ति सुव्यवस्था में दूर-दूर सन्तुष्ट को उद्देश्य देखर तथा उनमें सम्पूर्ण स्थापित करके उन्हें सम्यक् वृद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं ।

[क] शासन-प्रवन्धन पर प्रभाव (Effects on Administration)

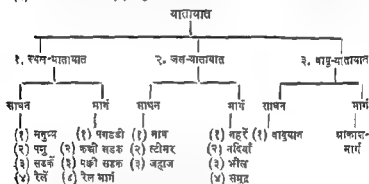
(१) शासन-प्रवन्धन पर नियंत्रण—उत्तम शासनापठ के साधनों में शासन प्रवन्धन में विविधता नहीं रहती । परन्तु भी अधिकारी प्रत्यक्ष स्थान पर सुव्यवस्था में निर्देशन के नियम पढ़े जाते हैं, जिससे शासन-प्रवन्धन में भाव सेन वात समझारी सन्तुष्टापूर्वक ध्यान कर्तन एवं दायित्व का सम्पन्न करने रहते हैं ।

(२) रक्षा-व्यय में मितव्ययता—सुव्यवस्था तथा शासनाधीन मानवापठ के साधनों में रक्षा व्यय भी कम हो जाता है । पुलिस तथा सेवा केन्द्रों पर स्थान पर रक्षा का महती है और वहाँ में प्रत्यक्ष सम्यक् मानवापठ के साधनों द्वारा बहुत प्रत्यक्ष स्थान की भरी जा सकती है । इसके अभाव में स्थान-स्थान पर सेवा व पुलिस रखना पड़े जिसमें रक्षा-व्यय बहुत बढ जाय ।

(३) युद्ध काल में यातायात के साधनों का महत्व—युद्ध-काल में प्रारम्भ या प्रतिरक्षा के लिये उत्तम यातायात के साधन नितान्त आवश्यक हैं। हमारे प्रतिरक्षा का दल हमारी सेनाओं का मकट ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से पहुँच जाने पर है।

(४) दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प आदि मकटों में—सहायक शीघ्रगामी यातायात के साधनों के द्वारा देश के विभिन्न भागों को दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प आदि मकटों में अधिकधिक सहायता पहुँचाई जा सकती है।

यातायात के साधन (Means of Transport)—यातायात के साधन समय, देश, जलवायु, तथा आर्थिक व वैज्ञानिक विवरण के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें हम मुख्यतया तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) स्थल यातायात, (२) जल-यातायात और (३) वायु यातायात।



१. स्थल-यातायात (Land Transport)—स्थल मार्गों में निम्न-लिखित साधन बोझ ढोने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं—

(१) मनुष्य—जब मात्र अधिक भारी नहीं होता है और अधिक दूर नहीं ले जाना होता है, तथा यातायात के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तब मात्र इंसान के लिये मनुष्य का उपयोग किया जाता है। मनुष्य द्वारा यातायात के राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक दृष्टि, जनसंख्या का घनत्व, भूमि की प्राकृतिक बनावट जलवायु आदि घने कारक हैं। यद्यपि मनुष्य का उपयोग बोझ ढोने में बहुत कम हो गया है, परन्तु प्रायः भी पहाड़ी प्रदेशों या वृत्तीय वनों में जहाँ सड़क बनाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है, वहाँ मनुष्य ही बोझ ढोने के काम में लाया जाता है। इसी कारण अफ्रीका के वनों में हवेली-भुली ही हाथी-दाँत, रबड़, नारियल आदि ढोते हैं, तथा तिब्बत, चीन व चिली के पर्वतीय ढालों पर, जहाँ पशु काम नहीं कर सकते, मनुष्यों द्वारा ही बोझ ढोया जा सकता है। इन स्थानों में लोभ साधारणतया २०० पाउंड उठाकर १२० मील की दूरी ७,००० फीट की औसत ऊँचाई पर २० दिन में पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध बाफ़ीक तथा मध्य अमेजन के बेसिन में विभिन्न कीलों के कारण पशु द्वारा यातायात में बाधा पड़ने के परिणामस्वरूप भारी बोझ ढोया हो जाते हैं। सामान्यतया पिछड़े हुए देशों में ही मनुष्य को बोझ ढोने का काम

निचा जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य द्वारा १५० मील बोझा द्रुतवाने का घन रेल द्वारा ८,००० मील के माटे में निचुना बँटता है।

मनुष्य-यातायात के गुण—(१) मनुष्य द्वारा यातायात में किसी विशेष मार्ग या सड़क बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। (२) छोटे बोझ तथा छोटी दूरी के लिये मनुष्य ही अन्य साधनों से अधिक है। (३) मनुष्य द्वारा सामान व पात मकान के भीतर तक टोपा जा सकता है।

दोष—(१) मनुष्य-यातायात द्वारा यात होने में अधिक धन और समय खर्च होता है। (२) मनुष्य के द्वारा अन्य साधनों की सहायता बहुत ही कम बोझा टोपा जा सकता है। (३) मनुष्य का पशुपन प्रयोग होता है।

(२) पशु—यद्यपि बोझा होने तथा मकानों के साधन के रूप में पशुओं का स्थान बहुत निम्न है, परन्तु फिर भी जहाँ तक लट्टू पशुओं की सहायता है और प्राकृतिक परिस्थितियों, सड़कों, घण्टा रेलमार्ग बनाने के अनुकूल नहीं है, वहाँ यातायात के लिये पशुओं का ही उपयोग किया जाता है।

घावगमन के साधनों के रूप में पशुओं का उपयोग किसी देश के विच्छेदन का सूचक है, परन्तु यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीनकाल में पशुओं का बहुत महत्व है। चीनोप्य प्रदेशों में घोड़ा घावगमन का एक सामान्य साधन है, परन्तु इसके निपरीत जपान-कटिबन्ध तथा चीनोप्य-कटिबन्ध के गर्म भागों में बैल ही प्रमुख साधन है। रेलमार्ग में ऊँट बोझा टोपने का काम करता है और दिन भर में ३० मील से भी अधिक दूर बोझा ले जा सकता है। भारत, ब्रह्म प्रदेशों के कुछ भागों में हाथी बोझा टोपे हैं। एशिया के जपान-कटिबन्ध सागरी के तटों में हाथी बड़ा काम करता है। अपने भारी डील-डौल तथा शक्ति के कारण यह साधारणतया १००० पौण्ड तक वजन धीरे धीरे ले सकता है। भूमध्य सागर के तटों के द्वीपों के देशों में, जहाँ यात की कमी है तथा पर्वतीय और पहाड़ी जमीन है, वहाँ बघे और खरबुर का ही उपयोग किया जाता है। ऊँट पर्वतों तथा दूरों की पार करने के लिये निश्चय में याक, हिमालय में भेड़ें, एशिया पर्वतों में खरबुर और दक्षिण पर्वत पर विकृत पशु तथा हर्षों में बकरों का उपयोग किया जाता है। उत्तर के अधिक ठण्डे और दक्षिण प्रदेशों में वही की परिस्थिति में पशु हुए रेड्डीयर और कहीं-कहीं कुत्ते बोझा टोपने के कार्य में प्रयुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान काल में उत्तमोत्तम यात्रिक यातायात के साधनों के होने हुए भी विश्व के कई भागों में पशुओं का प्रबल ही प्रयोग महत्व है।

भारत में पशु-यातायात—भारतवर्ष में याक टोपने के लिए पशु ही अधिक काम में लाये जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सम्पूर्ण भारत में १० लाख घोड़े, १५ लाख गधे, १० लाख बैल, ५ लाख ऊँट, १० हजार खरबुर, तथा कुछ बकरे व हाथी यातायात के साधनों के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। बल तो भारतीय पशु के एकमात्र साधन है।

पशु-यातायात के लाभ—(१) प्राकृतिक यातायात के साधनों का पूरक—जिन स्थानों में अन्य साधन काम में नहीं लाये जा सकते, वहाँ पशु यातायात ही प्रयुक्त किया जा सकता है। (२) मार्ग निर्माण व्यय न्यूनतम—पशुओं के चलने के लिए किसी प्रकार की सड़क आदि बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(३) राष्ट्रीय आश्रय में योग—छात्र, चमड़ा, हथौड़ी आदि के रूप में राष्ट्रीय आश्रय में वृद्धि होती है। (४) न्यूनतम लागत व्यय—पशु मार्ग में स्वयं बूढ़ों के पत्ते प्रादि साकर अपना निर्वाह कर लेते हैं। (५) आश्रय प्रारम्भ—अधिनाश पशु यातायात का साधन बनकर मनुष्य के मुख्य धन्य से होने वाली आश्रय को बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ— बंस कृषि का माछ काय करने से पदचात् बेकार समय में सामान लेकर, अथवा यात्रियों को ले जाकर अपने स्वामी को आश्रय बढ़ाते हैं।

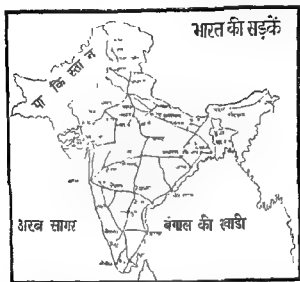
दोष—(१) पशु यातायात शर्तें गनी है। (२) चापेक्ष रूप से क्रम बोनड डो सकता है। (३) पशु के वृद्ध अस्वस्थ अथवा मृत्यु हो जाने पर उससे स्वामी को प्रौजोमत हानि उठानी पडती है। (४) अपिच दूरी से लिए पशु यातायात अपिच खर्चावा हो जाता है। (५) पशुमा की बोझा होने की छवि भिन्न-भिन्न होती है।

(३) सड़के—“सड़कें देश के चारों को नाडियाँ हैं जिनसे ज्ञात प्रत्येक प्रकार की उगति बौझी है।” —बेन्हुम

संक्षिप्त इतिहास—प्राचीन समय में भारत में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार मक्खी टाक थी। हिन्दू राजा कुँए बनवावा, मडकों आदि बनवाना अपना कर्तव्य समझते थे। मोहन जोदड़ो तथा हड़प्पा आदि प्राचीन शहरो की खुदाई के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व सड़क निर्माण कला में प्रवीण थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के राज्य मार्गों का वर्णन किया है। इसके पश्चात् मुस्लिम शासन-काल में भी सड़क-निर्माण कार्य में सत्तोषजनक प्रगति रही। मुगल काल में देश में २४ बड़ी-बड़ी सम्पी सड़कें थीं। ब्रिटेनी काल में मडका की और विशेष रूप में ध्यान दिया गया। लार्ड विन्डिहम ब्रिटिश काल में लाह डलहौजी में अपने शासन काल में मडकों बनाने की नीति को अपनाया जिसके फलस्वरूप अनेक मडका का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् लाह मैयो और लार्ड रिपन की प्रगतिशील स्थानीय-स्वराज्य-नीति के अन्वय में मडकों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

भारतवर्ष में सड़कों की वर्तमान स्थिति—भारतवर्ष में चार बड़ी-बड़ी सड़कें हैं जो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गई हैं और जिनमें अनेक दूसरी सड़कें आकर मिली हैं। ये सड़कें निम्नलिखित हैं—(१) सैवर ■ कलकत्ता तक राष्ट्रीय टूक रोड (२) दिल्ली से बम्बई तक (३) मद्रास से कलकत्ता तक और (४) मद्रास से बम्बई तक। सन् १९४३ में एक दस वर्षीय नागपुर योजना बनी गई जिसके अनुसार देश की सड़कें चार भागों में विभाजित की गई हैं—(१) राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways)—इसके अन्तर्गत वे सड़कें आती हैं जो आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से विभिन्न राज्यों की राजधानियाँ, केन्द्रीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों और मुख्य-मुख्य बन्दरगाहों को एक दूसरे से मिलाती हैं। (२) राज्यीय राजमार्ग (State Highways)—इन वगैरे वे सड़कें आती हैं जो प्रत्येक राज्य में व्यापार एवं उद्योग की दृष्टि से उस प्रदेश की मुख्य सड़कें समझी जाती हैं। (३) जिले की सड़कें (District Roads)—इनका कार्य जिले के मुख्य नगरों को मिलाना तथा जिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यातायात की सुविधा प्रदान करना है। ये राज्यीय सड़कों से मिल जाती हैं। (४) गाँव की सड़कें (Village Roads)—ये सड़कें प्राचीन क्षेत्र में छोटी-छोटी दूर की होती हैं जो गाँवों को आपस में एक

दूसरे से मिलती हैं। इनका सम्बन्ध निकटवर्ती राज्यों की सड़कों तथा जिले की सड़कों से होता है।



संसार में सड़कों की कुल लम्बाई १०,२४,००० मील है जिसमें से लगभग एक तिहाई सड़कें संयुक्त-राज्य-अमेरिका में है। इसके बाद रूस, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का स्थान आता है। संयुक्त-राज्य-अमेरिका में सबसे अधिक मोटरें चलती हैं। वहाँ पर संसार की ७५% से भी अधिक मोटरें चलती हैं। साधारण-तया वहाँ पर चार व्यक्तियों पर एक मोटर का प्रयोग पड़ता है। भारतवर्ष में सड़कों की कुल लम्बाई २,४६,००० मील है जिसमें ७०,००० मील लम्बी पक्की सड़कें और १,७६,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें हैं। इन कच्ची सड़कों में से केवल १,२६,००० मील की ही सड़कें मोटर चलाने योग्य हैं। इसमें स्पष्ट है कि भारत में सड़कें देश के विस्तार तथा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं।

भारत में अधिक सड़कों की आवश्यकता—भारत के विस्तार तथा जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ सड़कें बहुत कम हैं। यहाँ पर २,०१७ निवासियों के बीच एक मोटर गाड़ी या प्रोत्त पड़ता है। भारत एक कृषि-अर्थान्त्र देश है, जहाँ गाँव रेलवे से दूर-दूर स्थित हैं। अतः यहाँ यातायात के लिये सड़कों की बड़ी आवश्यकता है। कृषि की उन्नति बहुत-बहुत यातायात के साधनों पर ही निर्भर है। साग-सब्जों तथा अन्य व्यापारिक फसलों के उत्पादन की प्रोत्साहन देने के लिये, कृषि-उत्पादों को कम व्यय पर मण्डियों तक ले जाने के लिये, गाँवों के उत्तम धन्यों के पुनर्वितरण के लिये, बुनियादी ढाँचों को जीवन-यापन के लिए शहरों में जाने की सुविधा प्रस्तुत करने आदि बातों के लिये वर्तमान सड़कों का सुधार तथा अधिक सड़कों का निर्माण परमावश्यक है।

सड़कों का अर्थ-प्रबन्धन (Finance)—मड़क-निर्माण के लिए पूँजी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं —

(१) पेट्रोल-कर—यह कर केन्द्रीय सरकार एकत्र करती है परन्तु वह एक निश्चित योजना के अनुसार इसमें होने वाली आय को विभिन्न राज्यों में सड़क निर्माण कार्य के लिये बाँट देती है ।

(२) मोटर कर—मोटरों पर राजकीय सरकार द्वारा कर लगाया जाता है और इनमें होने वाली आय को राज्य अपने मड़क निर्माण पर व्यय करता है ।

(३) स्थानीय कर—सड़कों में प्रयुक्त किये जाने वाले यथायात के छावना पर स्पुलिसिबेटी आदि सस्याय कर लगा देती है और इस प्रकार प्राप्त आय को सड़क के निर्माण पर व्यय किया जाता है ।

(४) जिला बोर्डों की आय का भाग—स्थानीय सस्याय, बिरोपकर जिरा बोर्ड या ग्राम-न्यायालय, अपनी साधारण आय का कुछ भाग मड़क निर्माण में लगाती हैं ।

(५) ऋण—केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारें स्थायी सस्याय को सड़क निर्माण के लिए कम ब्याज पर ऋण देती हैं ।

सड़कों से लाभ (Advantages)—(१) मायारण दूर जान पाना के लिए मोटर-यातायात द्वारा सामान मीघ और सरलता में पहुँच सकता है । मोटरों या लॉरीयों द्वारा माल किसी भी स्थान पर पहुँचाया जा सकता है परन्तु रेल द्वारा माल किसी निश्चित स्थान पर पहुँचाया जा सकता है । (२) मोटरों द्वारा सामान भरने में उनकी दृढ़ दृढ़ का कोई भय नहीं रहता क्योंकि भाग में सामान को उठाने परने की आवश्यकता नहीं होती । (३) सड़क द्वारा माल दोनों में समय का बर्बाद प्रतिवन्ध नहीं होता । आवश्यकतानुसार सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है । (४) सड़क द्वारा यात्रा करने में बड़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि आवश्यकतानुसार कहीं पर रुका जा सकता है । (५) सड़क द्वारा माल रेलों तक पहुँचाया जा सकता है जिससे उपज का अच्छा मूल्य मिल जाता है । (६) सड़क-यातायात के द्वारा वाशवान् अर्थात् छोटी नष्ट होने वाली वस्तुएँ ममीपकरी गहरा में सुगमता से पहुँचाई जा सकती हैं जिससे इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है । (७) सड़क यातायात में भरे हुए उद्योग धर्मों को प्रोत्साहन मिलता है । (८) सड़क की सुविधा उद्योगों में निरन्तरकरण में सहायक सिद्ध होती है । इनके द्वारा पार्श्व दूरी पर रहने वाले शक्ति भी नारखाने पहुँच जाते हैं । (९) मड़क-यातायात से सम्पर्क बढ़ता है, जिससे ग्रामीणों का चरित्र विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है । (१०) सड़क यातायात रेल-यातायात की अपेक्षा सस्ता है, क्योंकि उसमें रेलों की भाँति स्टेसन, सिगनल, सार्जिन्स आदि बनाने का आवश्यकता नहीं होती है । (११) सड़क-यातायात में इतनी पूँजी नहीं लगाना पड़ती है जितनी कि रेलों में लगती है । (१२) सड़कों के द्वारा रेलों को काफी धन लाभ मिलता है ।

मड़क-यातायात के दोष—(१) भारतवर्ष में लगभग ३०% मड़क रेल के समानांतर हैं और लगभग सभी रेलवे लाइन्स सड़कों के समानान्तर चलती हैं । इस प्रकार की सड़कों का बनाना देश के लिए हानिकारक है । रेल और सड़क परस्पर सहायक नहीं चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी । (२) सड़कों के आवश्यकता में बहुत

कम है। (३) अनेक गाँव पक्की सड़कों से दूर पड़ते हैं। वहाँ की बच्ची सड़कें वर्षा-ऋतु में खराब हो जाती है और उनमें पानी भर जाता है। (४) कई सड़कों पर पुलिसवा-
द्यादि न होने से वर्षा-ऋतु में आवागमन बन्द हो जाता है। (५) जिन सड़कों पर गाड़ियाँ
चलती हैं उन पर सहूँ तथा गहारा-सी पड़ जाती है, जिससे सड़कों की दशा बिगड़
जाती है।

योजना और सड़कें—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए २७ करोड़
रुपया रखा गया था जबकि दूसरी योजना में ५५ करोड़ रु० का प्रायोगिक किया गया
है। भारत सरकार ने पहली योजना के प्रारम्भ में 'केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था'
(Central Road Research Institute) की स्थापना की। दूसरी योजना काल
में प्रथम योजना के काम को पूरा करने के अतिरिक्त ६०० मील दूरी हुई सड़क को पूरा
किया जायेगा। ६० पुन बनाय जायेंगे, १७०० मील सड़क का सुधार किया जायगा,
३७५० मील लम्बी सड़क चौड़ी की जायेंगे, १५०० मील नई सड़क बनाई जायेंगी।

(४) रेल—“रेल राष्ट्र का महानतम गार्वजनिक सेवा-व्यवस्था है और भावी
प्राथमिक निर्माण को रेलों आधार सिद्ध है।” —योजना आयोग

संक्षिप्त इतिहास—रेल सेवा में आन्तरिक यातायात का सबसे महत्वपूर्ण
साधन है। भारत में कुल रेलों की लम्बाई ७,५०,००० मील है। भारतवर्ष में रेलों
का प्राग्भविष्य वास्तविक रूप में सन् १८५३ में हुआ, जबकि लॉर्ड डलहौजी ने रेलों
विकास का सर्व प्रथम प्रयास किया था। प्रारम्भ में रेलों का निर्माण मुख्यतः सैनिक
आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था, परन्तु अब रेलों का निर्माण मुख्यतया
आर्थिक उद्देश्य में होता है। सबसे पहले रेलों का निर्माण गारखी-प्रधा के अन्तर्गत
प्रारम्भ हुआ जिसके अनुसार रेलों का निर्माण-कार्य भारत सरकार ने प्रीव्ही कम्पनिया
को दिया और उन्हें उनकी विनियोजित पूँजी पर ५% व्याज की गारण्टी दी। इसमें
लाभ न होने के कारण सरकार को बहुत क्षति पहुँची। अतः सन् १८६९ में सरकार
ने इसको अपने हाथ में लिया, किन्तु पूँजी के अभाव का अनुभव करते हुए रेलों का
निर्माण कार्य पुनः सन् १८८१ में प्राइवेट कम्पनियों को सौंप दिया गया। बीसवीं
शताब्दी के प्रारम्भ होने ही अर्थात् सन् १९०० से रेलों में लाभ पहुँचने लगा।
सन् १९२१ में सरकार ने एकवर्षीय कमेटी की नियुक्ति की, जिसके सुझाव के अनुसार
रेलों की अत्यन्त उन्नति हुई, और रेलों का प्रमुख विदेशी कम्पनियों में हटाकर स्वयं
सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। शून्य धर्मः सरकार ने लगभग सब ही रेलों का
प्रमुख और नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया है।

भारतीय रेलों की वर्तमान स्थिति—सन् १९५८-५९ में भारतीय रेलों की
कुल लम्बाई ३४,९०० ३ मील थी और इनमें १३६२८६ किलोमीटर २० की पूँजी लगी थी।
हमारे देश में क्षेत्रफल और जन-संख्या की दृष्टि से ये रेलें पर्याप्त नहीं हैं। यहाँ प्रत्येक
१००० मील के अन्तर्गत २५ मील की लम्बाई में रेलें हैं। संसार में सबसे अधिक रेलों का
जाल बेल्जियम में है। वहाँ प्रति १०० वर्ग मील में ४० मील रेल का जाल है, उसके
पश्चात् अष्ट्रेलिया में प्रति १०० वर्ग मील में २० मील रेल है। इन देशों की तुलना में भारतवर्ष की दशा बड़ी खोचनीय है—यहाँ केवल प्रति

१०० वर्ग मील में ३ मील के लगभग रेलों का जाल है। ४१% रेलें गंगा तथा सिन्ध के मैदान में हैं तथा ५१% रेलें अन्य भागों में हैं।

गेज (Gauge) के आधार पर भारतीय रेलों के मार्ग का वर्गीकरण

बड़ी लाइन (Broad Gauge)	१६,६११.४ मील
छोटी लाइन (Meter Gauge)	१५,५६०.८ " "
सबसे नया हल्की लाइन (Narrow & Light Line)	२,७३६.१ " "
योग	३४,६०८.३ " "

भारतीय रेलों की तुलनात्मक स्थिति

देश	प्रति १०० वर्ग मील पर रेल-मार्ग (मीलों में)	प्रत्येक १,००,००० जन-संख्या पर रेल-मार्ग (मीलों में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	७.५	१६७
ब्रिटिश भारत	२.३	४३
कनाडा	१.२	४११
ऑस्ट्रेलिया	२.१	१७५
फ्रांस	१.६	६६
जर्मनी	०.५	५६
सोवियत संघ	०.२	२६
चीन	०.२	१.३
भारतमध्य	२.८	६.४

रेलों से लाभ (Advantages of Railways)

आर्थिक लाभ (Economic Advantages)—रेलों ने अनेक आर्थिक लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(१) कृषि-सम्बन्धी लाभ—(क) कृषि का व्यापारीकरण—रेला के पहले कृषक अधिकतर खाद्य-पदार्थों की ही भती करते थे, पर आजकल वे ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेच सकें, जैसे—गन्ना, तम्बाकू, मखसो आदि। (ख) कृषि उपज का विस्तृत बाजार—रेलों के यातायात ने कृषि-उत्पन्न को दूर स्थानों में बिकना सम्भव कर दिया है। इसलिये इनका बाजार आजकल विस्तृत हो गया (ग) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का उत्पादन—रेलों के शीघ्रगामी यापन होने के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है; तथा इनका देश के एक कोने में दूसरे कोने में भेज

जाना सम्भव हो गया है। जैसे—बम्बई में मछली, खेड़ा व चमन में फल आदि।
 (घ) श्रम की गतिशीलता—रेलों द्वारा श्रमिक एक स्थान में दूसरे स्थान को ऊँचा
 चेतन वाले के लिये जा सकते हैं। (ङ) कृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार—रेल
 यातायात के कारण श्रम किसान अपनी उपज को उपयुक्त मरिदा में भेजकर अच्छा मूल्य
 प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा स्वाभाविक है।
 (च) कृषक के जीवन-स्तर में सुधार—किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा
 शहर वाला से सम्पर्क होने से उसका जीवन-स्तर पहले की अपेक्षा ऊँचा हो गया है।
 (छ) शिक्षा—अपनी उत्पत्ति को बढ़ाने के लिये ग्रामीणों की शिक्षा की आवश्यकता पड़ी,
 मतः रेलों के द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। (ज) ग्रामीण उद्योग धर्मों की
 उन्नति—रेल द्वारा कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है तथा बना हुआ माल दूरस्थ
 स्थानों को भेजा जा सकता है। इसमें ग्रामीण उद्योगों की प्रोत्साहन मिला है।
 (झ) अन्नान और भुवमरी को रोचने में सहायक—रेलों के द्वारा अन्नान और
 भुवमरी को रोचने में बहुत सहायता मिलती है। अन्नान वस्तु अन्नान में रेलों के द्वारा
 अन्य क्षेत्रों में दीर्घ ही अन्नान पहुँचा दिया जाता है। मन् १९४३ में अन्नान के अन्नान के
 समय यातायात के विविध माध्यम उपलब्ध न होने के कारण पर्याप्त अन्नान में अन्नान नहीं
 पहुँच सका।

(२) वन-सम्पत्ती लाभ—रेलों से वन-सम्पत्ती उद्योगों को भी प्रोत्साहन
 मिला है। स्वयं रेलों के लिए स्लोपर तथा डिब्बा के बनाने के लिये लकड़ी आवश्यक है।
 रेल यातायात के कारण अपने मूल्य पर अन्नान की लकड़ी पर-बैठे मिल जाती है।

(३) उद्योग धर्मों की उन्नति—रेलों ने नये-नये उद्योग धर्मों की स्थापना की
 है। उनके लिये कच्चा माल पहुँचाने तथा पक्का माल वितरित करने की व्यवस्था
 की है।

(४) व्यापार में लाभ—रेलों से देश के भीतरी और बाहरी व्यापार में बहुत
 सहायता प्राप्त होती है। इसमें वस्तुओं के मूल्यों में भी देश के विभिन्न भागों में समता
 बनी रहती है।

(५) बड़े परिमाण के उत्पादन को प्रोत्साहन—रेलों द्वारा देश-देशान्तर में
 माल पहुँचाया जाता है, जिसमें उत्पादन बड़े परिमाण में होने लगा है। बड़े परिमाण के
 उत्पादन का लाभ केवल उत्पादकों की ही नहीं हुआ है, बल्कि उपभोक्ताओं की भी हुआ
 है। बड़े परिमाण के उत्पादन में कम लागत पर वस्तुएँ तैयार होने में उपभोक्ताओं की
 भी वे मस्ती मिलती है।

(६) खनिज पदार्थ सम्पत्ती लाभ—खनिज पदार्थ सम्पत्ती उद्योग का
 विकास बहुत-कुछ रेलों पर निर्भर है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, तेल, पेट्रोल आदि सभी
 रेलों की सहायता में कारखानों तक पहुँचाए जा सकते हैं। इसमें खनिज-व्यवसाय की
 प्रोत्साहन मिलती है; तथा देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है।

(७) रेल-उद्योग से लाभ—रेल स्वयं एक प्रकार का उद्योग है, जिसमें हजारों-
 लाखों व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते हैं। इसमें अधिक परिमाण में लोहा, लकड़ी आदि
 अनेक कच्चे माल की प्रति वर्ष सप्ल होनी है। भारतवर्ष में वितरित रेल का बड़ा
 कारखाना है जहाँ रेलों के एन्जिन बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं, जिसमें अब विदेशों में
 जाने वाला बड़ा करोड़ रुपया बचाया जा गेगा।

(८) रेलों द्वारा दूर की सूचना कम समय में सस्ते मूल्य पर भेजने का लाभ—रेलों द्वारा हम अपना सन्देश एवं सूचना दूर-दूर कम समय में, तथा सस्ते मूल्य पर भेजकर लाभ उठा सकते हैं।

(९) श्रम की गतिशीलता—रेलों ने श्रम की गतिशीलता को बढ़ा दिया है। रेलों के द्वारा श्रमिक अपने काम वाले स्थान में पहुँचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इस आर्थिक उद्देश्य के प्रतिरिक्त मनुष्य एक स्थान में दूसरे स्थान पर किसी दुर्घटना या आपत्ति-बाल्य में भी शीघ्र पहुँच सकता है।

(१०) रेलों की स्थापना से जनसंख्या का समान वितरण—रेलों की स्थापना में निर्जन स्थान भी समाप्त हो गये हैं, तथा जन-संख्या का समान वितरण होने लगा है।

(११) रेलों से सरकार को लाभ—सरकार का रेलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ होता है। इस व्यवसाय से प्राप्त-लाभ सरकारी कोष में जाता है। रेलवे में सरकार के राजस्व कोष में सन् १९५९-६० में १४.७५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह सरकार का प्रत्यक्ष लाभ हुआ। रेलों से उत्पादन-वृद्धि होती है और आयात-निर्यात का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समस्त राष्ट्र सरकार का अप्रत्यक्ष लाभ होता है।

२. सामाजिक लाभ (Social Advantages)—(१) रेलों द्वारा देश में फैली हुई सामाजिक दुरावस्था दूर होती जा रही है, जैसे—शुआकूत, लड़कियाँ, धार्मिक कट्टरता, जाति-भेद का भेदभाव, आन्ध्रता की भावनाएँ आदि। (२) रेलों द्वारा मनुष्य-मनुष्य में, गाँवों और शहरों में, तथा देश-देशों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित हो गया है। (३) रेलों ने मनुष्य में देशाटन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी है, जिससे वह प्रदर्शन, मेले महत्वपूर्ण सम्मेलनों, देश-विदेश की यात्रा आदि में लाभ उठा सकता है। (४) रेलों द्वारा समाज-सुधारक अपने प्रचारार्थ स्थान-स्थान पर पहुँच सकते हैं। (५) रेलों ने सारे सत्तार को एक कुटुम्ब के समान बना दिया है। रेलों ने हाथ हम अपने विचारों को सत्तार के प्रत्येक कोण में पहुँचा सकते हैं, तथा समाज के रूप का और भी हल बना सकते हैं। (६) कृषि की नई-नई योजनाएँ तथा विपत्ति में रक्षा की योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिये रेलों से बड़ी सहायता मिली है।

३. राजनैतिक लाभ (Political Advantages)—रेलों द्वारा देश की एकता को बल मिला है। (१) केन्द्र में एक सुव्यवस्थित और सक्रियतापूर्ण सरकार की स्थापना हो सकी है। (२) देश की सुरक्षा और शान्ति स्थापना में रेलों ने बहुत सहायता प्रदान की है। (३) आन्तरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए रेलों द्वारा सेना शीघ्रानिर्गम्य भेजी जा सकती है। (४) रेलों की सुविधाओं के ही कारण सरकार ने देश के आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाने का सफल प्रयत्न किया है। (५) रेलों ने सरकार को बड़ी शक्ति मिली है, और इस प्रकार से सरकार देश की और अधिक उत्पत्ति करने में सफल होती है। (६) देशवासियों को भी रेलों से लाभ पहुँचना है, क्योंकि वे श्रमिक कर देने से बच जाते हैं। यदि सरकार को रेलों से अधिक आय न हो, तो उसे देशवासियों से उतना अधिक धन वसूल और करना पड़े।

रेलो से हानियाँ (Disadvantages of Railways)—रेलो से कुछ हानियाँ भी हैं, परन्तु इनके साथ इतने अधिक हैं कि हानियाँ का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता। रेलों से होने वाली मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं।

(१) धरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो गये—रेला की स्थापना और प्रसार के कारण मशीना द्वारा निर्मित सखी वस्तुएँ विदेशों से आने लगी, जिसके परिणामस्वरूप धरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो गये और शिल्पकार बेकार हो गये।

(२) भूमि पर दबाव—धरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो जाने के अधिकारों में मोम लेती की ओर झुक गये और भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो गये। इससे प्रतिरिक्त एकटा भूमि रेलों में ले ली। यदि इसके द्वारा उत्पादन होता तो देश को कितना लाभ होता।

(३) वनों का बट जाना—रेलो के बनने से कई जंगल अधाश्रुत काट दिये गए जिससे बहुत सी भूमि वर्षा के पानी में कटकर बह गई। वनों के बट जाने से कई स्थानों में वर्षा पहले की अपेक्षा कम होने लग गई है।

(४) रेलों के पुलों से नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा—रेलों के पुलों में नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पहुँचाने से अनेक स्थानों में पर्याप्त जल इकट्ठा हो जाने से मनेरिया हो जाता है जिससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(५) रेल की पक्षपात-पूर्ण नीति—ब्रिटिश राज्य में भारतीय रेलों को किया गया नीति इस प्रकार की रही कि देश में कच्चे मान का निर्यात अधिक होना था और बाहर से कच्चा मान अधिक आता था, जिसके फलस्वरूप देश में तब तक कृषि प्रधान हो रहा।

(६) बड़े बड़े नगरों की स्थापना और उनकी सामाजिक बुराईयाँ—रेलों के प्रसार से बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई और उतम अत्यधिक आबादी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई।

(७) रेलों में लगी हुई विदेशी पूँजी से हानियाँ—विदेशी पूँजी में देश की राजनीतिक हानि हुई। विदेशियों का पर्याप्त प्रभुत्व रहा।

(८) रेल-दुर्घटनाओं से क्षति—रेल दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष जान व मान की पर्याप्त हानि होती है।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कम महत्त्व—रेलों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कम महत्त्व है। इनका महत्त्व आन्तरिक यातायात तक ही सीमित है।

रेल-रोड प्रतिस्पर्धा (Rail Road Competition)—यातायात के विभिन्न साधनों का कार्य-क्षेत्र प्रत्येक होता है। इसलिये जब एक साधन अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे साधन के क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करता है तभी दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में देखा जाय तो रेल और रोड (सड़क) दोनों का क्षेत्र अलग-अलग है और अतएव एक दूसरे का विरोध करने के यातायात के में दोनों साधन

परस्पर सहायक बन सकते हैं। रेल प्रत्येक स्थान में नहीं जा सकती, परन्तु मोटर बसें और ट्रकों प्रत्येक छोटे से छोटे स्थान में भी जा सकती हैं। जहाँ रेलें नहीं हैं वहाँ से रेलों के स्टेशन तक माल पहुँचाने का कार्य मोटरों द्वारा हो सकता है। इस प्रकार इन दोनों में परस्परिक प्रेम और सहयोग रह सकता है।

जहाँ दूरी कम है वहाँ रेलों का बनाना और उनके द्वारा माल से जाना अधिक सस्तीया पड़ता है। रेल की लाइन बनाने का व्यय, स्टेशन, प्लेटफार्म, टिकट, इन्जिन, सिगनल, बल-पुर्जे, बम्बेचारिया आदि का इतना अधिक खर्चा पड़ता है कि रेलों की अपेक्षा सड़के बनवाना अधिक सस्ता पड़ता है। इससे शक्तिरिक्त छोटी दूरी के लिए मोटरों सबसे अच्छा साधन है क्योंकि ये किसी भी स्थान पर ठहर कर माल चढ़ा और उतार सकती हैं, तथा व्यापारी जब चाहे, समय पर समय अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्च में भेज सकते हैं। मोटरों किसी भी मार्ग पर, जहाँ इन्हें माल और यात्री मिलते हैं, गुणवत्ता से जा सकती है, जबकि रेल अपने निश्चित मार्ग अर्थात् पटरियों पर ही जा सकती है। मोटरों द्वारा माल से जाने में कच्चा-उपराई सम्बन्धी व्यय भी कम लगता है, तथा माल आदि के चोरी जाने का भी भय कम रहता है। इन्हें निपरीत, अधिक दूर की यात्रा के लिए मोटर बसें, कारियाँ आदि सड़क-यातायात के साधन अपेक्षा में हमें एक अनुविधानजनक सिद्ध होते हैं। रेलों के निर्माण में इतनी अधिक पूँजी लगती है कि इनके द्वारा कम दूरी की यात्रा अधिक महंगी पड़ती है, परन्तु इनमें 'जमागत घटन वाली लागत का नियम' लागू होने के कारण इनके द्वारा दूर की यात्रा मोटरों की अपेक्षा सस्ती पड़ती है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रेल और रोड दोनों का क्षेत्र मिल मिल है, और यदि दोनों का विस्तार अल्प अपने क्षेत्र में ही हो, तो उनमें प्रतिस्पर्धा का भय न रहे। परन्तु यह देखा जाता है कि रेलें और मोटर एक दूसरे के समान्तर चलती हैं और परस्पर स्पर्धा करती हैं। इससे दोनों को ही हानि होती है। हाल ही में सरकार ने स्वयं अपनी ही मोटरें बड़ी बड़ी चाख बरती है, अर्थात् मोटर-यातायात का राष्ट्रीय करण ही गया है। परन्तु अभी बहुत कम स्थानों में ऐसा हुआ है। अभी तक रेल और मोटरों में स्पर्धा चला आ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा से राष्ट्र को ही हानि होती है। अतः राष्ट्र के हित की दृष्टि में इसका समन्वय आवश्यक है।

रेल-रोड प्रतिस्पर्धा का समन्वय—सन् १९३० के पश्चात् भारतीय रेलों को मोटर-यातायात से अधिक हानि होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने सन् १९३३ में मिचेल किर्कनेस समिति (Mitchel Kirkness Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने बताया कि प्रतिवर्ष रेल मोटरों द्वारा हानि वाली केवल मात्रिका की प्रतिस्पर्धा ने परस्पर रूप से रेलों को २ करोड़ रुपये की हानि हा रही है। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार ने सन् १९३३ में रेलवे ऐक्ट की देश-भर में लागू किया, जिसने अन्तर्गत रेलों को अपनी बस सड़क चलाने का अधिकार दिया, और रेल तथा सड़क यातायात में समन्वय स्थापित करने के लिये सन् १९३५ ई० में एक 'केन्द्रीय यातायात परिषद्' (Central Transport Advisory Council) की स्थापना की गई। इस परिषद् ने रेल-रोड समन्वय के लिये एक रूपरेखा तैयार की, जिसके अनुसार मिचेल किर्कनेस

समिति द्वारा सिफारिश किये गये 'होमिंग प्रणाली' (Homing System) को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का आदेश दिया गया, नया मोटर वसों को तीसरे व्यक्ति की सुरक्षा के लिये बीमा करना आवश्यक सम्भत्ता गया। नियमित रूप से ड्राइवरो की डाक्टरों जाँच किया जाना भी आवश्यक माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मोटरों को एकाधिकार दिया ; तथा सहायक सड़कों का निर्माण रेलों के पूरक के रूप में करना निश्चय किया।

इतना सब होने पर भी रेल-रोड स्पर्धा कम नहीं हुई, वरन् वह बढ़ती ही गई। इससे रेलों की निरन्तर आर्थिक हानि हो रही थी। भारत सरकार ने सन् १९३६ में पुनः एक समिति वेजवुड कमेटी (Wedgewood Committee) के नाम से रेल-मोटर की प्रतिस्पर्धा की जाँच करने के लिये बिठाई। इस कमेटी ने बताया कि रेलों को इससे होने वाली आर्थिक हानि सन् १९३३ में २ करोड़ रुपये, सन् १९३४ में ३ करोड़ रुपये; और सन् १९३७ में ४२ करोड़ रुपये हुई। इस समिति ने सन् १९३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रेलों और मोटरों की अनुचित स्पर्धा को कम करने के लिए कई सिफारिशों की गई थी। कमेटी की इन सिफारिशों के अनुसार सन् १९३६ में मोटर गाड़ी कानून (Motor Vehicle Act) बनाया गया जिसके अन्तर्गत मोटरों पर प्रति-घण्टा चाल चलाने के लिये अनुज्ञापत्र (License), यात्रियों की निश्चित सख्या आदि बातों की रोकथाम लगाई गई। इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक यातायात अधिकारी (Regional Transport Authorities) नियुक्त किये गये हैं, जो मोटर गाड़ियों का नियन्त्रण करते हैं। सन् १९४३ में प्रत्येक मोटर का बीमा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

द्वितीय महायुद्ध काल में रेल-मोटर प्रतिस्पर्धा एकदम कम हो गई क्योंकि अधिकांश सवारी और सामान ले जाने वाली गाड़ियों को सरकार ने युद्ध-कार्य के लिये हस्तगत कर लिया था। निजी मोटर गाड़ियाँ भी पेट्रोल की कमी और मोटरों के पूर्ण न मिलने के कारण कम चलने लगीं। इसलिये रेल-मोटर प्रतिस्पर्धा एक प्रकार से रुक हो गई। युद्ध के पश्चात् सन् १९४८ में एक सड़क यातायात कॉरपोरेशन कानून (Road Transport Corporation Act) पास किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को इस बात का अधिकार दे दिया गया कि वे चाहे तो अपने यातायात कॉरपोरेशन स्थापित कर सकती हैं अथवा ऐसी कम्पनियाँ स्थापित कर सकती हैं जिसमें प्रान्तीय सरकार, रेल तथा सड़कों पर बस चलाने वाले सम्भेदार हों। अभी से उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा दिल्ली राज्यों की सरकारों ने मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण कर लिया है।

भारतीय रेलों का पुनर्वर्गीकरण

(Regrouping of Indian Railways)

पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता—भारतीय रेलों का पुनर्वर्गीकरण भारत की रेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रेल व्यवस्था भौगोलिक आधार पर आवश्यक भी थी और इस प्रश्न पर बत २५ वर्षों से विचार किया जा रहा था। १५ अगस्त १९४७ को देश के विभाजन का भारतीय रेलों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उत्तर-पश्चिमी रेल और बंगाल प्रान्त में रेल के बँट जाने के कारण कुछ रेलें ऐसी रह गई थी जिनके पास न अपने कारखाने (Workshop) थे और न प्रायिक दृष्टि से वे सम्पन्न हो पाईं। १ अप्रैल १९५० तक देशी राज्या का भारत के साथ विलय पूरा हो चुका था। अतः भारत सरकार ने मामूलीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और सबसे प्रथम अप्रैल १९५१ में दक्षिणी रेलवे ज़ोन (Zone) का निर्माण कर दिया और तबोत पद्धति से कार्य होने लगा। नवम्बर १९५१ में केन्द्रीय एवं पश्चिमी तथा अप्रैल १९५२ में उत्तरी पूर्वी और पूर्वी जोन्स के निर्माण के साथ भारतीय रेलों के वर्गीकरण का कार्य समाप्त हो गया।

पुनर्वर्गीकरण—२७ रेलवे प्रणालियाँ जो जो अगस्त १९४६ के पूर्व भारत में विद्यमान थी, घाट घेना में घाट दिया गया है। ये क्षेत्र निम्न वास्तिका में दिखाये गये हैं—

क्षेत्र	प्राप्त होने की तिथि	रेल क्षेत्र के अन्तर्गत साइने	मुख्यालय	३१ मार्च १९५६ को लाइन की लम्बाई (मीलों में)
दक्षिण	१४ अप्रैल, १९५१	मद्रास एवं बंशिरजी मद्रास, दक्षिणी भारत और मंगलूर रेल	मद्रास	व० ला० १८६९.१ म० ला० ४२०६.८ छो० ला० ६५७ <u>२९६८.६</u>
मध्य	५ नवम्बर, १९५१	ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर, मिजोरम स्टेट, सिंधिया और पोखपुर रेल	वधवाई	व० ला० ३८२०.७ म० ला० ८२३.१ छो० ला० ७२५.० <u>४३६८.८</u>

क्षेत्र	चात्र होने की तिथि	रेल क्षेत्र के घन्तगत लाइन	मुख्यालय	३१ मार्च १९५६ को लाइनों की लम्बाई (मीलों में)
पश्चिम	२ नवम्बर, १९५१	बम्बई, बडोदा एवं सेंट्रल इण्डिया, सोराष्ट्र, कान्हा, राजस्थान और जयपुर रेल	बम्बई	ब० ला० १७६६'६ म० ला० ३७२२'० छो० ला० ७५६'७ <u>६२४६'४</u>
उत्तर	४ अप्रैल, १९५२	पूर्वी पंजाब, जोधपुर और बीकानेर रेल और ईस्ट इण्डियन रेल के तीन अपर डिवीजन	दिल्ली	ब० ला० ४१६६'४ म० ला० २०५०'१ छो० ला० १६१'० <u>६४०७'३</u>
उत्तर-पूर्व	१४ अप्रैल, १९५२	असम एवं तिरहुत, असम रेल और पुरानी बम्बई बडोदा एवं सेंट्रल इण्डियन रेल का फतेहगढ़ जिला	गोरखपुर	म० ला० ३०७०'० <u>३०७०'०</u>
उत्तर-पूर्व सीमान्त	१५ जनवरी, १९५६		पाण्डू	ब० ला० २'२ म० ला० १६७६'२ छो० ला० ४२'० <u>१७३३'४</u>
पूर्व	१ अगस्त, १९५५	ईस्ट इण्डिया रेल (तीन अपर डिवीजनों को छोड़कर)	कलकत्ता	ब० ला० २३०७'३ म० ला० — छो० ला० १७'१ <u>२३२४'४</u>
दक्षिण-पूर्व	१ अगस्त, १९५६	बंगाल—नागपुर रेल	कलकत्ता	ब० ला० २६५१'० म० ला० — छो० ला० ६२४'० <u>३५७५'६</u>

नोट :—ब० ला० = बड़ी लाइन (५३'), म० ला० = मध्यम लाइन (३' - ३३')
तथा छो० ला० = छोटी लाइन (२' - ६" तथा २')



रेलो के पुनर्वर्गीकरण से लाभ (Advantages of Regrouping of Railways)—(१) अधिकतम बड़ी रेलों को एक-दूसरे से मिला देने से दिन-प्रतिदिन के खर्च में बहुत बचत हो जायगी। पुष्क-पुष्क रेलों के बीच में बहुत सा पथ व्यवहार बन्द हो जाने से व्यय कम हो जायगा और कार्यक्रम सरल हो जायगा; तथा कार्य-पहलू की अपेक्षा शोध होने लगेगा। बड़ी रेलों का एक ही क्षेत्र में एकीकरण होने से कार्य-कुशलता में उत्थिति तथा सासन प्रबन्ध में सुधार होने की संभावना है। (२) व्यापारी एवं व्यवसायी वर्ग को भी लाभ होगा, क्योंकि अब उन्हें पुष्क-पुष्क रेल-कम्पनियों के अधिकारियों से सम्बन्ध रखने के बजाय अब केवल एक धन के किसी अधिकारी से ही सम्बन्ध रखना पड़ेगा। (३) पूर्णजीगत व्यय में भी कमी होने की संभावना है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर सामूहिकरण होने में एन्जिन, डिब्बा आदि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। (४) कारखाना का पैतानीकरण हो जाने में तथा सामान के लगे देने में केन्द्रीकरण हो जाने से पर्याप्त लाभ की संभावना है।

रेलो के पुनर्वर्गीकरण से हानियाँ (Disadvantages of Regrouping of Railways)—(१) रेलवे नर्मान्तरिया की कार्य-पुशलता में कमी होने की सम्भावना है, क्योंकि कर्मचारियों के तबादले अब दूर-दूर अपरिचित स्थानों में होने लगेंगे, जिससे उनकी अनुविधाएँ बहुत बढ़ जायगी। (२) प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुखतः लगभग साठे पाँच हजार मील लम्बे रेल-मार्ग का प्रबन्ध करने में न तो कार्य-कुशलता हो रहेगी और न व्यय में ही किसी प्रकार की कमी होगी। (३) जितनी निरक्षरता

होगी, उससे व्यय कदा अधिक होगा, क्योंकि प्रत्येक क्षत्र में नये-नये हेड छांटते, कारखाने नभवारियाँ के लिये बसले एवं घाटस्थ आदि बनवाने में पर्याप्त खर्च करना पड़ेगा। (४) रेलवे स्टार रोलिंग स्टान तथा अन्य आवश्यक सामान खरीदने में भी रेलवे की कोई विशेष बचत नहीं होगी। इसीलिये कुंजम् कम्पनी ने पुन वर्गविरण की इस योजना को पांच वर्षों के लिये स्थगित करने का विचार प्रस्तुत किया था।

धैसे तो प्रत्येक समस्या के ऊपर पण तथा विपक्ष दोनों ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है परंतु भारतीय रेलों के पुनवर्गीकरण से लाभ ही अधिक प्रतीत होते हैं। इसलिए वर्तमान समय में क्षत्रीय आधार पर रेलों का पुन वर्गीकरण भारत के हित में ही होगा।

रेल और योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेल के विकास के लिये रु० ११२५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। तन् १९६०-६१ तक ८५० मील लाइन बनाई जायगी ८००० मील लाइन का नवोन्नीकरण होगा १६०७ मील लाइन दोहरी की जायगी १२६३ मील लाइन पर डोजन डोजन स गाड़ी चलाई जायगी २६५ मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जायगा और ८२६ मील लाइन का विद्युत्ताकरण किया जायगा। ५ वर्ष में आन्तर भारतीय रेलों द्वारा २२५८ डोजन १०७२४७ माल के टिके और ११३६४ सवारी टिके प्राप्त किए जायगे। ६ नये रेलवे कारखाने और एक छोटी लाइन के तबारी टिके बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जायगी। चिनरजन लोकोमोटिव का विस्तार किया जायगा।

७ जल यातायात (Water Transport)

एक देश जीवित प्राचीन विश्व के महादीपों में भूमि के अति जड़ा है जिनका समुद्र तट ४००० मील लम्बा है और अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण की जात है जिन्हें आसानी से नौका द्वारा भेजा जा सकता है प्रकृति द्वारा एक नाविक देश होने के लिये ही बना है।

संक्षिप्त इतिहास—सद्य के आर्थिक इतिहास में जल यातायात का बड़ा महत्व है। भारतवर्ष में जल मार्ग द्वारा यातायात प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। मुक्ति कल्पतरु नामक प्राचीन स्मृत पुराण समुद्र और नदी में चलने योग्य नावों की निर्माण वना का उल्लेख मिलता है। साधारण रूप में घूर्णों द्वारा पर जो जुड़ाई हो रही है उस पर एक नाव तैरती हुई बनाई गई है। इसमें यह बात सिद्ध होती है कि भारत में ईसा की गंगाजी व पूर्व गोवाआ द्वारा यातायात होती रही है। गंगाजी यात्री मगधप्रान्त तथा एरेल की भारत यात्रा द्वारा जो उद्घाटन दो हजार वर्ष पूर्व की भी यह ज्ञात होता है कि गंगा अपना १७ सहायक नदियाँ और मिचु अपनी १३ सहायक नदियाँ के साथ बहुत दूर तक नाव्य (Navigable) थी। मैगस्थनीज ने तो बहुत दूर कहा है कि २८ नदियाँ भारत में नाव चलाने लायक हैं। गिलालखा और अन्य प्रांत बख्शान के अनुसार यह ज्ञात होता है कि ईसा के १४ गंगादी के पश्चात् भी भारत की नदियाँ और नहरों द्वारा यातायात की जाती रही है।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि बहुत प्राचीनकाल से ही भारतीय जहाजों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। भिन्नन्दर की चीज तब भारतवर्ष में लौटने लगी तो २००० भारतीय जहाजों के वेत का उन्होंने अपना समुद्री यात्रा के लिये उपयोग किया था।

प्रकार के समय में मुख्यस्थित नौ-विभाग था, जिसका अध्यक्ष 'मोर नहरी' कहलाता था। उस समय बंगाल, काश्मीर और लाहौर में विभिन्न प्रकार के जहाजों और नौकाया का निर्माण किया जाता था। तत्पश्चात् विदेशी शक्तिओं ने भारत की जहाजों बना की बड़ी प्रशंसा की है। बावरी (१६६६-७० ई०), फ्रायर (१६७४ ई०) आदि नौका ने भारतीय विज्ञान जहाजों को देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। फ्रायर ने मूला में ऐसे बड़े जहाज देखे जैसे उसने यूरोप में नहीं देखे थे। इसी प्रकार कुस्तुनतुनिया का राजा अपने लिए ढाका और हुगली में जहाज तैयार करवाता था।^१ मध्य में हर समय ४०,००० नावें और जहाज भाड़े पर उपलब्ध हो सकने थे। गोलकुण्डा के राजा के पास एक मजदूर जहाजों बना था। राजा और उसके सरदारों के लिए अच्छे हाथी लाने के लिए कई जहाज घराबान, सनाखिम : और लका भी जाते थे। किसी किसी जहाज में तो २५ बड़े हाथी बँट जाते थे।^२ लिडसे नामक अंग्रेज सदाशिव भारत की जहाजों की शक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि "सन् १७८६ ई० में भारतीय व्यापारियों के पास इतने अधिक जहाज थे कि जितने ईस्ट इण्डिया कंपनी, डचा, फ्रांसिसिया और अमेरिका जाता के पास कुल मिला कर होंगे।"

१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में जहाजों के निर्माण में लड़की का स्थान तोड़ने में लिया और अब पुराने ढंग के जहाजों के स्थान में बाप से चलने वाले जहाजों की माँग अधिक बढ़ गई थी। अब भारत में चलने वाले पुराने प्रकार के जहाज अब उपयोगी नहीं हो सकते थे। यह परिस्थिति भारतीय नौ उद्योग के लिए घातक सिद्ध हुई परन्तु इसके विनाश का मूल कारण विदेशी शक्तियों की प्रतिबुद्ध नीति थी। यदि वे चाहते तो यहाँ भी नवीन ढंग के जहाज अन्य देशों की प्रेरणा अच्छे बन सकते थे, क्योंकि यहाँ उपयुक्त सामग्री तथा अनुभव उपलब्ध था। परन्तु उन्होंने ऐसा करना अपने हित के विरुद्ध समझा। इस परिस्थिति, भारत में रेल निर्माण भी देरी नावा से होने वाले व्यापार के लिये घातक सिद्ध हुआ।

जल-यातायात के सापेक्षिक गुण व दोष

गुण—जल यातायात अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इस पर कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है। इसके लिये रेल की पट्टी या पक्की सड़क, जैसे किसी विशेष मार्ग बनाना या उसकी मरम्मत की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। रेल-यातायात में लाइवें बनाने के प्रतिरिक्त स्टेशन प्लेटफार्म, सिगनल आदि बनाने और उनकी मरम्मत में प्रत्यक्ष आदि की व्यवस्था करने में पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है जबकि जल यातायात में घाटगाह, डाकघर जैसी आदि बनाने में बहुत ही कम व्यय करना पड़ता है। यदि जल-यातायात नदी, भेल या समुद्र द्वारा होता है, तो मार्ग निर्माण में कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जल-मार्ग प्राकृतिक बना होता है। केवल नाव स्टीयर व जहाज बनाने में ही व्यय करना पड़ता है जो रेल यातायात की तुलना में बहुत ही कम है। यदि यह यातायात नहरों व द्वारा होता है, तो नहरों का निर्माण करना पड़ता है, परन्तु ये नहरें मुख्यतः सिंचाई के लिये बनाई जाती हैं, इसलिये जल-यातायात में मार्गों में व्यय में प्रयुक्त करने में अल्प में व्यय

१—Economic History of India—R. K. Mukerjee

२—Indian Shipping—R. K. Mukerjee p p 245 52

नरने की आवश्यकता नहीं होती। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये तो समुद्री यातायात एक मुख्य साधन है।

जल-यातायात के द्वारा भारी एवं विस्तारवान् वस्तुओं का लाना भोर ले जाना सुगम और सस्ता है, जैसे कोयले, स्प्रोपर, सस्ते आदि। जगती में पेड़ों के बड़े-बड़े तने काटकर नदियों में बहा दिये जाते हैं, वे बहकर स्वयं ही निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हैं। दुइने वाली या हिलने से बचाव हो जाने वाली वस्तुओं के लिये जल-यातायात बहुत ही उपयुक्त होता है। आन्तरिक जल-मार्ग में एक बड़ा भारी लाभ यह है कि विदेशों में जाने वाले जहाज देश के आन्तरी भागों में सीधे घा सड़ते हैं। उनका मान संहरगाहों पर उतारकर रेलगाड़ियों पर लादने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन प्रदेशों में रेलों और सड़कों का अभाव है वहाँ जल-मार्ग इनकी पूर्ति करने हैं। भारी, कम मूल्य वाली और टिकाऊ वस्तुओं के लिये जल-मार्ग बहुत ही सस्ता साधन है। बहुत सी नदियाँ तथा नहरें अल्प यातायात के साधनों के दूरक का कार्य करती हैं।

दोष—जल यातायात मन्द-गति का प अनिश्चित होता है। यही इसका दोष है। भारतवर्ष में कुछ नदियों में तो वर्षा-ऋतु में बाढ़ आ जाती है और अविनाश योग्य-ऋतु में विलुप्त सूख जाती है जिससे ये यातायात-योग्य नहीं रहती।

भारतीय जल-यातायात के भेद—भारतीय जल-यातायात को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) भीतरी जल-यातायात और (२) समुद्री यातायात।

(१) भीतरी जल-यातायात (Inland Water Transport)—(अ) नदियाँ, और (आ) नहरें भीतरी जल-यातायात के मुख्य साधन हैं।

(अ) नदी यातायात (River Transport)—नदियाँ देश के अनिश्चित व्यापार का सर्वाधिक यातायात साधन हैं। नाव चलान योग्य नदियाँ गहरी तथा उदगम स्थान पर बर्फ पुक होनी चाहिये। जिन नदियों का वेध तेज होता है पदवा जिन नदियों में बहुत-से प्रपात होने हैं, वे यातायात के लिये सर्वथा अव्यक्त होती हैं। नदियों में लगानार जल-प्रवाह का होना भी आवश्यक है। इसलिये वे नदियाँ जिनमें प्रायः बाढ़ मानी है उसका जा वर्ष के कुछ महीने सूखी पड़ो रहती हैं, यातायात के लिये प्रयोग्य होती हैं। जो नदियाँ उपजाऊ और घनी आबादी वाले प्रदेशों में से होकर बहती हुई बर्फ में खुले सागरों में गिरती हैं वे भी यातायात की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखती हैं।

दुसरे देशों की भाँति भारतवर्ष की नदियाँ भी यातायात की प्राकृतिक सुविधाएँ नहीं हैं, फिर भी दक्षिण की नदियों की अपेक्षा उत्तरी भारत की नदियाँ में यातायात की अधिक सुविधाएँ हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पर्याप्त पानी रहता है, क्योंकि शीत-ऋतु में हिमालय पर्वत में वर्ष पिघल कर उनमें पानी जाता रहता है। ये नदियाँ देश के एक-उपजाऊ और सम्पन्न भाग में से होकर बहती हैं, जो गंगा-सिन्धु का प्रदेश कहलाता है। अतः उत्तरी भारत की नदियाँ में वर्ष-भर यातायात हो सकता है। परन्तु दक्षिणी भारत की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, इसलिये यातायात असम्भव हो जाता है।

भारत में वर्ष-भर बहने वाली नदियों में स्टोमर्स और बड़ी-बड़ी देशी नावें चलती हैं। जल-यातायात की दृष्टि में बंगाल, सागाम, मद्रास और बिहार महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत में जल मार्गों की लम्बाई उत्तर प्रदेश में ७४५ मील, बिहार में ७१५ मील, पश्चिमी बंगाल में ७७७ मील, आसाम में ६२० मील, उड़ीसा में २६७, और मद्रास में १७०० मील है। दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तथा ताप्ती नदियों के निचले भाग में ही नावें चल सकती हैं, इनका औष भाग पठारी है। गंगा नदी से ५०० मील ऊपर कानपुर तक स्टीमर चला करते हैं। छोटी-छोटी नावें तो हरिद्वार तक जा सकती हैं। परन्तु रेला के निर्माण से गंगा नदी द्वारा यातायात का महत्त्व कम हो गया है। यमुना नदी में प्रयाग से राजापुर तक वर्ष भर नावें चलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाने से डिब्रूगढ़ तक ६०० मील नावें चलती हैं। परन्तु इसमें निरन्तर नये नये द्वीप बनने रहने के कारण नावें चलाने में कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं अतिरिक्त, पर्षा-न्तु में पानी की लगी के कारण नावों के उलट जाने का डर रहता है। हुगली नदी में भी नावियां तब जहाज पड़च सकती हैं। छोटी-छोटी नहरें बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ती हैं। अधिकांश बूट बाघ और चावल नावों से ही बड़े बड़े शहरों में पहुँचाया जाता है।

(आ) नहर यातायात (Canal Transport) — भारत में यातायात के योग्य नहरें बहुत कम हैं, यद्यपि थोड़ा बहुत यातायात गंगा नहर आदि कुछ नहरों द्वारा होता है जोकि सिंचाई के लिये बनाई गई हैं। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत सरकार के प्रधान इञ्जीनियर सर आर्थर कॉटन (Sir Arthur Cotton) ने एक पार्लियामेंट की कमिटी के समुल्लेखनात्मक रूप में इस प्रकार प्रकट किया था, “भारत कहना है कि भारत के लिए जल मार्ग अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। जहाँ पर जितना धन्य हुआ है, उससे आठवें भाग में नहरें उनाई जा सकती हैं जो मान को एक ध्यान में हमारे ध्यान पर बहुत कम धन में जा सकती हैं। इन नहरों में सिंचाई भी होगी और वे व्यापारिक जल मार्ग का काम भी दंगी। सर कॉटन ने नहरें बनाने की पूरी योजना बनाई थी जिसमें ३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया था। परन्तु ब्रिटिश पूँजीपतियों ने, जिनकी रेलों में पूँजी लगी थी इस योजना का पार विरोध किया जिससे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिंचाई के लिये निमित्त नहर यातायात के योग्य नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः उथली होती हैं और कम आवाह भाग में होकर बहती हैं। औद्योगिक बनीयत और राष्ट्रीय यातायात समिति ने रेलों और नहरों द्वारा यातायात विस्तार के लिए कई सिफारिशें की परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सिंचाई इसके कि सन् १९३० के Inland Steam Vessels Act द्वारा भीतरी जल-यातायात के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराये की दर नियत कर दी गई। अब अपनी राष्ट्रीय सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए।

भारत में आन्तरिक जल यातायात के विकासार्थ योजना — भारत एक विशाल देश है और इसमें मोटा सा नदियाँ इस प्रकार बहती हैं कि जल यातायात के काम में लाई जा सकती है। इनके अतिरिक्त, नहरों के निर्माण द्वारा जल-यातायात का अधिक विकास किया जा सकता है। केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई और नौका संचालन आयोग (Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission) ने देश के भीतरी जल मार्गों की उत्पत्ति करने के लिए एक विशाल योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत बंगाल में दामोदर घाटी योजना के पूरा हो जाने पर दामोदर की निचली बेल्ट की सहायक हुगली नदी में नहर द्वारा मिलाई जायेगी। इसी प्रकार में उत्तरीय बंगाल के जलमय तथा पूर्वीय बंगाल और कलकत्ता के बीच के

जलमार्गों का पुनरुद्धार किया जायगा । अन्नाम में कुछ नदियाँ जल यातायात के योग्य बनाई जायँगी । बिहार में गडक, कोसी तथा सोन नदियों को भी यथा सम्भव यातायात के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जायगा । केतवा व चबल नदियों के बाढ़ के पानी को रोक कर और उधे यमुना नदी में डालकर यमुना को भी अधिक यातायात के योग्य बनाया जायगा । उड़ीसा की नहरों को मद्रास की नहरों में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जायगा । हीराकुंड बांध के पूर्ण होने पर महानदी में भी तीन सौ मील तक जल यातायात की सुविधा हो सकेगी । पूना में एक नदी यातायात अनुसंधानशाला (River Research Institute) की स्थापना भी की गई है ।

फरवरी १९४० में भारतीय आन्तरिक जल-मार्गों के विकास के लिए एशिया और पूर्वी देशों के आर्थिक आयोग (Economic Commission for Asia and far East) के विशेष भी ओटो पोपर (Otto Popper) की मेनार्ड इस विषय में जोच-बजलात करने और भारत सरकार को सम्मति देने के लिए लौ गई थी । ओटो पोपर ने इस बात पर बल दिया कि "यदि व्यवस्थित रूप से भीतरी जल मार्गों का उपयोग किया जाय, तो ये रेखा के प्रतिस्पर्द्धी न होकर रेखा के पूरक होंगे ।" उनका कहना था कि न केवल वर्तमान जल मार्गों को ही गुंथारने की आवश्यकता है बल्कि देश के विभिन्न भागों में नये जल मार्गों का निर्माण होना भी आवश्यक है । उनकी यह सलाह है कि (अ) देशी मार्गों को गहवारिता के आधार पर संपादन करना चाहिये । (आ) गंगा के उत्तरी भाग में ताबा के छहरे के स्थाव (River Ports) और सामान उतारने चढ़ाने की मशीनों (Cranes) आदि आर्थिक साधना के प्रभाव की पूर्ति करना आवश्यक है । (इ) नदी को स्थान छोड़ने से रोकने के लिए नदी के किनारा पर भालियाँ लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया । (ए) देशी मार्गों के स्थान में आधुनिक मार्गों का चलन हो ।

आन्तरिक जल मार्ग और योजना—देश का आन्तरिक जल-मार्ग ४,००० मील में अधिक लम्बा है । गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियाँ पर होने वाले जल-यातायात के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने १९४२ में 'गंगा यमुना जल यातायात मंडल' स्थापित किया । आन्तरिक जल-यातायात के विकास के लिये द्वितीय योजना में ३ करोड़ २० निर्धारित किये गये हैं ।

(१) समुद्री यातायात (Sea Transport)—समुद्री यातायात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है । समुद्री-मार्ग विभिन्न देशों को मिलाने हैं और विदेश व्यापार का विकास करते हैं । भारतवर्ष में लगभग ४००० मील लम्बा समुद्री किनारा है । लगभग ६ परसेण्टे रण्ये शान का व्यापार विदेशों से समुद्र के द्वारा होता है, परन्तु यह वह भी बात है कि भारत के पास लगभग १०० जहाज हैं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ३,४६२, इंग्लैंड के पास ३,१०२, फ्रांस के पास २,१६, इटली और जापान में से प्रत्येक के पास ४२३ हैं । अब अपनी राष्ट्रीय सरकार इस धार विषय पर ध्यान दे रही है ।

माल में नौ-उद्योग के गुनर्जन्य का घेय मिन्डिया स्टीम नौवीमेनन कम्पनी (Scindia Steam Navigation Co.) को है जिनका मध्य प्रथम टग

दशा में पत्र प्रदर्शन किया। सिपिया कम्पनी द्वारा अपने विशालापट्टम कारखाने में निर्मित जल-ऊँचा नामक पहला भारतीय जहाज जिसकी लागत ६८ लाख रुपये है तथा वजन ८००० टन है, १४ मार्च १९४८ को पडित जवाहरलाल नेहरू के कर-कर्मता द्वारा जलावतरण कराया गया। इसके पश्चात् लगभग इसी परिमाण के जल प्रभा, जल पालक, जल गुदा आदि कई जहाज तैयार किये जा चुके हैं। सिपिया कम्पनी की योजना है कि वह प्रति वर्ष ८-१ हजार टन वाले तथा १५० फीट लम्बाई तक के जहाज तैयार करे।

जहाजी नीति समिति (Shipping Policy Committee) की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने एक बड़ी व्यापारिक योजना बनाई है, जिसमें तीन राष्ट्रीय निगमों (Shipping Corporations) की स्थापना की व्यवस्था है। प्रत्येक निगम के जिम्मे नियत क्षेत्र में व्यापार संचालन का कार्य रहेगा। इनमें से पूर्वी जहाजी निगम (Eastern Shipping Corporation) की व्यवस्था सिपिया कम्पनी को ७६.२४ के अनुपातिक भाषार पर सौंपी जा चुकी है। अन्य दो निगम इण्डिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी (India Steam Navigation Co.) और भारत लाइन्स लिमिटेड (Bharat Lines Ltd.) होंगे। इनके प्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को समुद्री यातायात की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए एक जहाजी बोर्ड (Shipping Board) भी स्थापित कर दिया गया है। जनवरी १९५१ में एक 'तटीय जहाजी सम्मेलन' (Coastal Shipping Conference) के निर्णय के अनुसार विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी समझौतों में यह धारा रखी जाय कि ५०% भाग भारतीय जहाजों में लाया जाएगा। इसके पक्षस्वरूप समुद्र तटीय यातायात केवल जहाजों के लिये सुरक्षित हो गया है। भारतीय जहाजों की अब ३० साल का बोझ प्रति वर्ष दोने को भिनाया जिसके लिये भारत को कम से कम ३,७५,००० टन शक्ति वाले जहाजों की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान समय में हमारे पास केवल २ लाख टन शक्ति के ही जहाज हैं। अब हमें १,७५,००० टन शक्ति वाले जहाजों की और आवश्यकता होगी।

भारतार्थ के समुद्री-मार्ग (Ocean Routes)—भारत के मुख्य समुद्री मार्ग निम्न पाँच प्रवाल बन्दरगाहों से आरम्भ होते हैं—बम्बई, कनकता, कोचीन, मद्रास और दिङ्गापट्टम। भारत हिन्द महासागर के किरे पर स्थित है जिससे होकर पूर्व से पश्चिम की व्यापारिक मार्ग निबालते हैं। यहाँ से पूर्व और दक्षिण पूर्व की समुद्री मार्ग चीन, जापान, पूर्वी द्वीपसमूह और आस्ट्रेलिया की, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में समुद्र राज्य अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका और दक्षिण में अरब की जाते हैं। इस प्रकार भारत पश्चिमी कना-कोशल-प्रधान देशों की पूर्वी कृषि-प्रधान देशों से मिलाने के लिये एक बड़ी की मान करता है।

समुद्री-यातायात और योजना—प्रथम योजना में समुद्री यातायात अर्थात् जहाजरानी के लिये व्यवस्था की गई थी जो बाद में बढ़ाकर २६३ करोड़ रु० कर दी गई थी। योजना काल में लगभग १८ करोड़ रु० के वास्तविक व्यय का अनुमान लगाया गया था। द्वितीय योजना में जहाजरानी के विकास के लिए ४१ करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं। छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए द्वितीय योजना में ५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जबकि प्रथम योजना में २४१ करोड़ रु० की ही व्यवस्था की गई थी।

३. वायु यातायात (Air Transport)

मक्षिप्त इतिहास—भारत के प्राचीन यंत्रों में आकाश यात्रा तथा वायुयानों का उल्लेख मिलता है। पुष्पक विमान के विषय में प्रायः सभी जानते हैं। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन भारत के निवासी वायुयान तथा आकाश-यात्रा से परिचित थे। यद्यपि युष्कारों द्वारा उड़ने का प्रयोग सन् १७०८ से ही किया जाने लगा किन्तु वास्तविक रूप से वायुयानों का प्रयोग २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही आरम्भ हुआ।

भारतवर्ष में आकाश यात्रा सन् १९११ से ही आरम्भ हुई जबकि कुछ स्थानों पर वायुयानों के उड़ान की प्रदर्शनी की गई थी। सन् १९१६ में भारत में अन्य तीस देशों के साथ वायु-यातायात को नियमित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर पेरिस में हस्ताक्षर किये। वायु-यातायात के विकास की योजना बनाने के लिए सन् १९२५ में 'भारतीय वायु बोर्ड' (Indian Air Board) स्थापित किया गया। इन बोर्ड की निगरानि के अनुसार सन् १९२७ में 'नागरिक उड्डयन विभाग' (Civil Aviation Department) की स्थापना की गई और सन् १९२८ में दिल्ली कलकत्ता, बम्बई और कराची में उड़ान क्लब (Flying Clubs) खोले गये। सन् १९२६ में इम्पीरियल एयरवेज (Imperial Airways) की सेवा द्वारा भारत को सन्धन से जोड़ दिया गया। सन् १९३० में टाटा एयरवेज लिमिटेड (Tata Airways Ltd.) स्थापित हुई और इससे इलाहाबाद, कलकत्ता तथा कोलम्बो और दाद में कराची और मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं की स्थापना की गई। इस समय ही भारत सरकार ने वायु-यातायात के विकास में सक्रिय भाग लेना आरम्भ किया। सन् १९३३ में इण्डियन नेशनल एयरवेज लि० (Indian National Airways Ltd.) स्थापित हुई जिससे कराची, जैकोबाबाद मुल्तान तथा साहीर की वायु-सेवा की स्थापना हुई। सन् १९३६ में एयर-मरिट्स ऑफ इण्डिया (Air Service of India) स्थापित हुई जिसने बम्बई, भावनगर, राजकोट, जामनगर, पोखन्दर की वायु-सेवा चालू की। इन देशी कम्पनियों के प्रतिष्ठित कुछ विदेशी वायुयान कम्पनियाँ भी भारत में काम कर रही थी। इनमें ब्रिटिश ओवरसीज एयर कॉर्पोरेशन (B.O.A.C.), डच एयर लाइन, के० एल० एम० (K.L.M.) एयर कांस और जर्मन एयर रविम मुख्य थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व लगभग १५६ वायुयान भारत में थे और वायु-मार्ग ६५०० मील या जो अन्य देशों को भीतर बहुत कम था।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्—सितम्बर १९३६ में महायुद्ध के छिड़ जाने से विदेशी वायुयानों में एकदम कमी हो गई। देशी वायुयानों का भी प्रयोग मुख्यतया युद्ध कार्यों के लिए होने लगा। सन् १९४३ के अन्त तक १७ नये वायु-राग चालू कर दिये गये। इस काल में वायु-यातायात के विकास की रयति प्रोत्साहन मिला। भारतीय नवयुवकों को वायुयान चलाने की शिक्षा देने के लिये कई उड्डयन क्लब खोले गये तथा कुछ को ट्रेनलैड भी भेजा गया। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व वायुयान निर्माण करने के लिये कोई कारखाना नहीं था, केवल वायुयानों की मरम्मत की ही व्यवस्था थी। यतः श्री बालचन्द्र होराचन्द ने संयुक्त सरकार के साथ दो हिन्दुस्तान एयरलाइन्स कम्पनी (The Hindustan Airlines Co.) बंगलौर में सन् १९४० में स्थापित की। सन् १९४१ में भारत सरकार ने भी इस कम्पनी में अपना भाग प्राप्त कर लिया। सन् १९४१ में इस कम्पनी द्वारा निर्मित पहला भारतीय

वायुयान प्रस्तुत किया गया और दूसरा एक महीने बाद । सन् १९४२ में इस कारखाने का पुनर्गठन किया गया । आजकल इस कारखाने में रेलवालों के डिब्बे भी बनते हैं ।

सन् १९४४ में भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन के विकास आदि विषयों के नियमों पर माहम्मद उस्मान के समामित्व में एक समिति की स्थापना की । इस समिति की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और अपनी वायु यातायात सम्बन्धी नीति सन् १९४६ में घोषित कर दी जिसमें अनुसार 'व्यापारिक वायु यातायात का विकास नीमित्त सस्था की निम्नी व्यापारिक सस्थाओं द्वारा करवान की सरकार ने इच्छा प्रकट की । इन कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने के लिए 'वायु यातायात लाइसेंस बोर्ड' की सन् १९४६ में स्थापित किया गया ।

वायु विकास के कार्यक्रम में पहला महत्वपूर्ण कदम सन् १९४७ में भारत और यु० के० के मध्य वायु सेवा स्थापित करने में उठाया गया । एक नई कम्पनी 'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल लिमिटेड' डाटा के सहयोग में स्थापित की गई । दूसरी वायु-सेवा २६ मई १९४८ में 'भारत एयरवेज लिमिटेड' द्वारा चालू की गई । यह कदमत्ता से बकाफ होती हुई हमकाग जाने की । तीसरी वायु-सेवा बर्म्हई एडन भीमवी के मध्य २१ जनवरी १९५० का 'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल लि०' द्वारा चालू की गई । चौथी वायु सेवा दिल्ली और मद्रास के मध्य चालू की गई ।



३० जनवरी १९४९ से बर्म्हई-मागपुर-कनकता और मद्रास-मागपुर-दिल्ली के लिए सेवाएँ डाक की वायुयानों द्वारा संचालित करने के लिए चालू की गई । सन् १९४९ में

राजाध्वश के समाप्तित्व में एक कमेटी नियुक्त की जिसने कम्पनियों के काम पर नियंत्रण रखने, भारत सरकार द्वारा दो जाने वाली आर्थिक सहायता सन् १९५२ के अन्त तक जारी रखने, राष्ट्रीयकरण की स्थिति रखने या उससे प्रभाव में वैधानिक कॉरपोरेशन द्वारा संभालन करवाने आदि के कई सुझाव दिये ।

वर्तमान स्थिति—सन् १९५३ के प्रारम्भ में भारतवर्ष में निम्नलिखित ६ वायु-यान कम्पनियाँ थी :—(१) एयर इण्डिया, बम्बई, (१) इण्डियन नेशनल एयरवेज, नई दिल्ली, (३) एयर सर्विसेज ऑफ इण्डिया, बम्बई, (४) डेकन एयरवेज, बेंगलूर, (५) एयरवेज (इण्डिया) कलकत्ता, (६) भारत एयरवेज, कलकत्ता (७) एयर इण्डिया इन्टर-नेशनल, बम्बई, (८) हिमालय एवियेशन, कलकत्ता और (९) कनिगा एयर लाइन्स, कलकत्ता । इनके प्रतिष्ठित मी० मी० ए० मी०, के० एम० एम०, टी० इन्डू० ए० तथा पान प्रमेरिकन आदि अन्तराष्ट्रीय महत्त्व की वायु यातायात की कम्पनियाँ द्वारा वायु यातायात की व्यवस्था भारत में हो गई है ।

भारतीय कम्पनियों की अधिकृत पूँजी २१ करोड़ ४० लाख रुपया थी । वायु-मार्गों की कुल लम्बाई २८,००० मील से कुछ अधिक है । दिसम्बर १९५३ तक भारतीय हवाई विभाग के नियन्त्रण में कुल ७८ हवाई अड्डे या मये थे ।

हवाई उड़ान की शिक्षा की व्यवस्था—वायुमार्गों को हवाई उड़ान में शिक्षा देने के लिए कुल मिलाकर १२ उड्डयन क्लब हैं जिनको भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है । वे क्लब ये हैं—दिल्ली बम्बई, मद्रास, बँकपुर, पटना, मुम्बई, लखनऊ, जालंधर, नागपुर, आसाम, हैदराबाद, बंगलौर । सन् १९४८ के १ दिसम्बर की मूला में भारतीय ग्लाइडिंग एसोसिएशन (Indian Gliding Association) की स्थापना की गई है जिसका कार्य Gliding को प्रोत्साहन देना है । इसे भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है ।

एरोनॉटिकल कम्प्यूनिवेशन (Aeronautical Communication) अर्थात् वायु यातायात सम्बन्धी सम्वाद के इस समय ५८ अड्डे स्टेशन हैं । इलाहाबाद में सन् १९४८ में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र (Civil Aviation Training Centre) है, जिनमें नार विभागों की शिक्षा दी जाती है—उड़ान, एरोड्रोम, एंजिनियरिंग और कम्प्यूनिवेशन, सहायनपुर में भी एक प्रशिक्षण केन्द्र है जहाँ वायुयान चालकों और रेडियो विशेषज्ञों की उपयुक्त शिक्षा दी जाती है । सरकार ने अधिकांश से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा देने के हेतु एव योजना बनाई है जिससे अनुगतर तीन वर्षों में ३००० चालकों को प्रशिक्षित किया जायगा । इसमें ७५ लाख रुपए पूँजीगत व्यय और २५ लाख रकम (स्वायी) व्यय होगा । बंगलौर में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा दी जाती है । अनु-सन्धान की व्यवस्था सफरखण हवाई अड्डे दिल्ली में की गई है ।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Air Transport)—वायु यातायात के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य में सन् १९५३ में 'वायु यातायात विनय अधिनियम' ('The Air Corporation Act') पारित किया गया, जिसके अनुसार १ अगस्त १९५३ से वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । इस अधिनियम में प्रथमतः दो विनय (Corporations)—एक आन्तरिक वायु सेवाओं को चलाने के लिये (Indian Airlines Corporation) और दूसरा वायु वायु सेवाओं को चलाने के लिये (Air India International Corporation)

स्थापित कर दिये गये। प्रत्येक कॉर्पोरेशन के लिये कम से कम ५ और अधिक से अधिक १ सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। वर्तमान वायु यातायात सलमन कर्पोरेशनों के से लेने का अधिकार और वायु यातायात का एकाधिकार इस कॉर्पोरेशन को दे दिया गया। इन दोनों निगमों को सहाय देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक एक 'अध्यासद्वय समित्त' (Advisory Council) नियुक्त कर दी गई है।

वायु यातायात समझौते—सन् १९५८ में भारत सरकार और सोवियत रूस, सेबनान गणराज्य तथा इटली गणराज्य की सरकारों के बीच वायु यातायात के समझौते हुए। अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ईराक, जापान, कर्डीलैण्ड, मोरारलैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन ब्रिटेन, मिथ, ग्रीनका, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-यातायात के समझौते करने में ही हुए हैं।

वायु यातायात और योजना—द्वितीय योजना काल में ८ नये हवाई प्रवाह स्थापित किये जायेंगे। योजना में हवाई यातायात के लिये ३६ १३ करोड़ २० को व्यवस्था की गई है - २४ ६ करोड़ २० इन्डियन एयरलाइन्स के लिये और शेष एमर इन्डिया इन्टरनेशनल के लिये हैं।

सम्वाद-वाहन के साधन—सरकारी डाक व सार विभाग का नागरिक जीवन में बड़ा सहक है। सबसे प्रथम डाक प्रणाली सन् १७६६ में लॉर्ड क्लाइव ने भारत में की परन्तु वह सरकारी कार्यालयों के ही उपयोग में आ सकती थी। वारेन हेस्टिंग्स के शासन-काल में यह डाक प्रणाली जनता को भी उपलब्ध होने लग गई थी। १५ अगस्त १९४७ में भारत में २२,१३६ डाकघर थे, परन्तु १९५८-५९ में इनकी संख्या ६४,६६३ हो गई जिनमें ३३ लाख व्यक्ति सम्मिलित थे। द्वितीय योजना में २,००० की जनसंख्या के प्रत्येक ग्राम-समूह के लिये एक डाकघर होगा। भारत में सबसे पहले तार सेवा (कलकत्ता-माधरा के बीच) अक्टूबर १८५३ में आरम्भ हुई थी। वर्तमान समय में देश में ६,८६३ तारघर हैं जहाँ प्रति वर्ष ३ ४३ करोड़ अन्तर्राष्ट्रीय तथा विदेशी तार प्राप्त किये जायेंगे। १९५८-५९ में देश में ३,७८,००० टेलीफोन थे।

भारत में रेडियो—भारतीय रेडियो द्वारा सात विदेशी भाषाओं में बात प्रसारित होती है जिससे राष्ट्रीय के मध्य पारस्परिक मैत्री बढ़ती है तथा सांस्कृतिक चेतना को बल मिलता है। अप्रैल सन् १९५२ में ६,०३,११० रेडियो के लाइसेंस थे। भारत में इस समय २३ स्थानों में बेतार का सार भेजा जा सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- भारत में रेलों के (अ) कृषि (ब) घरेलू उद्योगों और (ग) बड़े-बड़े उद्योगों पर क्या प्रभाव हुए हैं ? स्पष्टता से व्याख्या कीजिए। (उ० प्र० १९५०)
- भारत में यातायात व सम्वाद के क्या-क्या साधन हैं ? यदि आप से इनमें से एक के विकास के लिए कृपा जाये तो आप किसका विकास करना चाहेंगे ? कारण भी बताइए। (उ० प्र० १९४७, ३३)
- भारत में वायु-यातायात पर सख्त टिप्पणियाँ लिखिए। (उ० प्र० १९४४)
- भारत में रेलों और सड़कों के विस्तार से होने वाले सामाजिक हानि लाभों पर विचार कीजिए। (पटना १९५३)

५—भारत में रेलों के विकास के आर्थिक परिणाम समझाइए ।

(रा० बो० १९६०, ५८)

३—भारत में यातायात के साधनों (विशेषकर रेलों) के विकास का कृषि और ग्राम्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(रा० बो० १९५३)

७—भारत में रेलों के विकास के क्या आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव हुए हैं ?

(रा० बो० १९५२)

८—रेलों के निर्माण द्वारा भारत के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर पड़े वाले प्रभावों पर विस्तार से विचार कीजिए ।

(स० बो० १९५५, ४८, ४६, ४२, ४०)

९—भारत में रेलों के आर्थिक प्रभाव व्यक्त कीजिए ।

(म० भा० १९५४, माघ १९५०, पञ्चाव १९४८)

१०—मानव समाज के लिए यातायात के साधन क्या आवश्यक है ? भारत के लिए थोड़ा यातायात व्यवस्था का क्या महत्व है ?

(नागपुर १९४२)

११—भारत में सड़क यातायात को बढ़ावा देना चाहिए । क्या आप रेल-रोड समन्वय के पक्ष में हैं ? कारण भी लिखिए ।

(दिल्ली हा० से० १९४८)

"भारत एक विशाल देश है जिसकी सुप्त सम्पत्ति का उपयोग करके देश को विदेशी व्यापार पर निर्भर होने से बचाया जा सकता है।" — मायहू

परिचय (Introduction)— प्रत्येक देश का व्यापार साधारणतया दो भागों में विभक्तित किया जा सकता है—(१) आन्तरिक, भीतरी या देशी व्यापार और (२) बाह्य या विदेशी व्यापार। आन्तरिक या देशी व्यापार (Inland or Home Trade) वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं का आवागमन देश के भीतर ही सीमित रहता है। जैसे बम्बई और दिल्ली का व्यापार आदि। बाह्य या विदेशी व्यापार वह व्यापार है जिसके अन्तर्गत वस्तुओं का आवागमन विभिन्न देशों के मध्य में होता रहता है, जैसे इंग्लैंड और भारत के मध्य का व्यापार आदि। आन्तरिक या देशी व्यापार को हम राष्ट्रीय व्यापार और बाह्य या विदेशी व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय, प्रदेशीय और अन्तर्प्रदेशीय व्यापार सम्मिलित होता है। सीमा नष्ट होने वाली तथा कम मूल्य की भारी वस्तुएँ जैसे धातु, भाजी, दूध, ईट आदि का व्यापार थोड़ी दूर तक ही सीमित रहता है, यद्यपि इस प्रकार के व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। कुछ वस्तुओं का व्यापार पास-पड़ोस के जिलों में, पर एक ही प्रदेश के भीतर होता है, इस प्रदेशीय व्यापार कहते हैं। कुछ वस्तुओं का व्यापार विभिन्न प्रदेशों के मध्य पर देश की सीमा के भीतर ही होता है, इसे अन्तर्प्रदेशीय व्यापार कहते हैं।

भारतीय व्यापार (Indian Trade)— भारतीय व्यापार को मुख्यतः तीन भागों में बाँट सकते हैं—(१) आन्तरिक व्यापार, (२) तटीय व्यापार और (३) विदेशी व्यापार।

(१) **आन्तरिक व्यापार (Internal Trade)**— भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत का आन्तरिक व्यापार प्रति वर्ष ७००० से ८००० करोड़ रुपए तक का होता है और विदेशी व्यापार ६०० करोड़ रुपए तक का होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय आन्तरिक व्यापार विदेशी व्यापार से लगभग पन्द्रह गुना अधिक है। ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम और जापान जैसे छोटे-छोटे देशों में तो आन्तरिक व्यापार, बहुत कम होता है, उनका अधिकांश व्यापार विदेशी व्यापार होता है।

भारतवर्ष एक बहुत विशाल देश है जहाँ एक भाग दूसरे से अत्यधिक दूरी पर है। इसलिए एक स्थान की प्राकृतिक दया, जलवायु एवं पैदावार दूसरे स्थान की उपज से विपरीत मिश्र है। अनुषंगी की सम्पत्ति, रहन-सहन, खान-पान तथा वस्त्रादि में भी भिन्नता

है। इस विभिन्नता के कारण लोगों की मित-मित्र प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं। इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति देश के विभिन्न भागों में उत्पादित वस्तुओं द्वारा ही की जा सकती है। इस आवश्यकता के कारण देश के आन्तरिक भागों में विस्तृत व्यापार होता है। देश विशाल है, प्राकृतिक सुविधाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उत्पत्ति अधिक और विभिन्न प्रकार की होती है; जनसंख्या बृहद है, इसलिये आन्तरिक बाजार ही इतना विस्तृत है कि हमें विदेशी बाजारों पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत के आन्तरिक व्यापार की उन्नति की ओर हमारे विदेशी शासकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका हित विदेशी व्यापार की उन्नति में था न कि आन्तरिक व्यापार में। प्रो० नायडू का कहना है कि भारत एक विभाजित देश है जिसकी सुसम्पत्ति का उपयोग करके देश को विदेशी व्यापार पर निर्भर होने से बचाया जा सकता है। प्रो० सेन का कहना है कि देश में ही इतना विस्तृत बाजार है कि उभरती पूर्ति के प्रयत्न किये जायें, ता विदेशी व्यापार पर हम कम निर्भर रह सकेंगे। परन्तु भारत के आन्तरिक व्यापार को बढाने की आवश्यकता है।

(२) तटीय व्यापार (Coastal Trade) - तटीय व्यापार भारत के लिये एक प्रकार की प्राकृतिक देन है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह हिन्द महासागर के व्यापारिक मार्गों का मुख्य वेन्ड है। भारतवर्ष का समुद्र तट ४००० मील में अधिक लम्बा है परन्तु इस पर स्थिर बन्दरगाह बहुत कम हैं। भारत का तटीय व्यापार प्रायः अंग्रेजी जहाजी कंपनियों के हाथ रहा है यद्यपि कुछ भारतीय जहाजी कंपनियाँ देश का २५% व्यापार अपने हाथ में रखती हैं। श्री हाजी तथा दूसरे लोगों ने भारत सरकार पर बहुत जोर डाला कि भारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय किन्तु सरकारी धर्मोपदेशी सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत के पास केवल १३ साव टन के जहाज थे, जो फिर के व्यापारिक जहाजों का केवल २% था। स्वतन्त्र हो जाने के बाद में ही राष्ट्रीय सरकार जहाजी वेडे में वृद्धि करने में प्रयत्नशील है। सन् १९५१ के तटीय जहाजी सम्मेलन के निर्णयानुसार अब तटीय व्यापार अधिकतर भारतीय जहाजों द्वारा सम्पन्न होने लगा है।

भारतवर्ष का तटीय व्यापार भी बहुत बड़े महत्व का है। लगभग ७० लाख टन चावल, निलहन, कोयला, नमक तथा लकड़ी आदि तटीय मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की भेजा जाता है। भारत का अन्तर्राष्ट्रीय तटीय व्यापार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास आदि प्रदेशों में होता है क्योंकि ये ही राज्य समुद्र के किनारे हैं और इन्हीं राज्यों में बन्दरगाह पाये जाते हैं। भारत का कुछ तटीय व्यापार ब्रह्मा में भी होता है। भारत ब्रह्मा की सूती कपड़े, गेहूँ, जूट के बारे, दालें, मसाले, तम्बाकू, सोहें का सामान, चाय, निलहन, सब्जियाँ आदि भेजता है। इसके बदले में ब्रह्मा में चावल, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, लकड़ियाँ, चना व दाखे भारत को आते हैं। ये सारी वस्तुएँ तटीय मार्ग द्वारा ही आती-जाती हैं। बम्बई, कनकनूर, मद्रास, कोचीन, तूतीकोरन तथा विशाखापट्टम भारत के वे मुख्य बन्दरगाह हैं जो भारतीय तटीय व्यापार में एक विशेष स्थान रखते हैं।

भारत का विदेशी व्यापार (Foreign Trade of India) - भारत का विदेशी व्यापार अत्यन्त प्राचीनकाल से ही होता आया है। इसके व्यापारिक सम्बन्ध न केवल एशिया के देशों में ही थे, परन्तु उस समय की ज्ञातव्य दुनियाँ के सभी देशों से थे जिसमें पूर्व और पश्चिम के सभी उन्नत देश सम्मिलित थे। सन् ३००० ई० पू० में भारत और वेनीलोन में व्यापारिक सम्बन्ध था। सन् ई० १-२००० तक की पुरानी मिथ की वस्तुओं में जो सब हैं वे भारत का बहुत बड़िया मूलमूल तिपटे हुये पाये गये हैं। भारतीय लोहे और इस्पात का भी निर्यात फारस, अरब तथा इजिप्ट का होता था। रोम में भारत के तैयार माल की बहुत खपत थी। १३ वीं शताब्दी के आरम्भ में दक्षिणी भारत से ममालों (इलायची, लौंग, कालीमिर्च, जाबिती) और बपुर का निर्यात पश्चिमी देशों को बड़ी मात्रा में होता था। इसके अतिरिक्त भारत के माली, धमक प्रकार के वस्त्र, सिंध के बड़िया फल और गन्नीचे, हाथी-दाँत और उसकी बनी वस्तुएँ, गेहूँ के बमड़े व उसमें निहित वस्तुएँ, जूने, आरियन, बस्तुरी, नीम, काना नमक, अनेक प्रकार की औषधियाँ तथा मेवे ईराक, ईरान, मिथ और अरब को भेजे जाते थे। इनके बदले में अरब से थोड़े सोहा सोना, चाँदी सिक्क़र, मिथ से पत्ते की मंग्रठियाँ, हीरा, सूँचे और मिथी, मदिरा तथा ईरान में ऊनी वस्त्र, बैबडा, गुलाब-जल और मिट्टी का तेल आता था।

१६ वीं और १७ वीं शताब्दी में भारत में सुरत, कालीकट, मच्छलीपट्टम, सतगाँव, चिडगाँव आदि निगमन के मुख्य केन्द्र थे। इन स्थानों में छोट, मुल्गमान भूती वस्त्र, कपास, चावल, धक्कर, नील और काली मिर्च आदि का विदेशों को बड़े रूप में निर्यात होता था। सुती कपड़ पूर्ण ने हिन्दोचन, दार्जिलिंग, बलकेश जापान, चीन, मुसाशा, जापा आदि को जाते थे। पश्चिम में ये वस्त्र ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, मिथ तथा पश्चिमी अरब को जाते थे। टैक्सियर लिखते हैं कि टर्की, पोर्लैंड आदि में दक्षिणी भारत के छोटे हुए कपड़ों की माँग बहुत थी। जेरेरीस लिखते हैं कि "सारे ससार का सोना-चाँदी घूम-फिरकर अन्त में भारत में पहुँचता है।" इङ्गलैंड की औद्योगिक क्रान्ति एवं भारत में विदेशी राज्य की स्थापना में भारत की सम्पूर्ण परिस्थिति बदल गई। ब्रिटिश सरकार की नीति भारत के घने हुए पक्के गान का न केवल बच्चे माल को भेजने की थी। इससे गाँव-ही-गाँव भारत में हाथ से बना हुआ माल, इङ्गलैंड आदि देशों के मशीन में बने हुए सारे माल के सामने न टिक सका। स्वैश गहर के लुप्त जाने से पारस्पर्य औद्योगिक देशों का पक्का माल भारत में खूब आने लगा तथा यहाँ से बच्चा माल जाने लगा। इस प्रकार सारे सारे भारतीय गृह-उद्योग सब नष्ट हो गये और भारत केवल बच्चा माल निर्यात करने वाला देश हो गया। सन् १९०६ में विदेश-व्यापी मदी आरम्भ हुआ कई ब्रिटेन के परिणाम-स्वरूप भारत के कृषि-उद्योगों के भाव गिरे और भारत के विदेशी व्यापार को सति पहुँची। विदेश-व्यापी मदी का प्रभाव १९३२-३३ तक रहा। सन् १९३३-३४ में हमारे व्यापार में कुछ प्रगति हुई। निर्यात १३६-०७ करोड़ में १४०-२३ करोड़ रुपये को पहुँच गया और आयात में १७ करोड़ रुपये की कमी हो गई। सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ हो जाने से भारतीय कच्चे माल की विदेशों में माँग बड़ी ज़िम्मे परिणाम स्वरूप हमारा निर्यात बढ़ गया। अहाँ सन् १९३८-३९ में केवल १६३ करोड़

"All the silver and gold which circulates throughout the world at last centres here (in India)" —Europe Bleedeth ■ enrich Asia

रुपये का माल निर्यात किया गया वहीं सन् १९३६-४० में २०४ करोड़ रुपये का माल निर्यात हुआ। इसी प्रकार वहीं सन् १९३८-३९ में १५२ करोड़ रुपये के माल का आयात हुआ वहीं १९३९-४० में यह मात्रा १६५ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। सन् १९४०-४१ में आयात २०४ करोड़ रुपये का, निर्यात २१० करोड़ रुपये का तथा कुल विदेशी व्यापार ४१४ करोड़ रुपये का हुआ। सन् १९४७ में देश-विभाजन के कारण विदेशी व्यापार के रूप में परिवर्तन हुआ अर्थात् जूट और बड़िया कपास के लिये भारत पाकिस्तान पर निर्भर हो गया। सन् १९४८-४९ में हमारा कुल विदेशी व्यापार १४३६ करोड़ रुपये का था जिसमें आयात नवम्बर ८५६ करोड़ ६० और निर्यात ५८० करोड़ ६० का था।

भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएँ (Characteristics of Foreign Trade of India)—भारतवर्ष के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ पाँच कारण निम्नलिखित हैं :—

१. भारत का वर्तमान निर्यात कच्चे और उनके दोनों प्रकार के माल का होता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत केवल कच्चा माल ही विदेशों को भेजता था; परन्तु आक्रमण देश की औद्योगिक उन्नति के कारण उनके माल का निर्यात भी काफी बढ़ गया है।

२. भारत का आयात अब कच्चे और उनके माल के रूप में होता है। कृषि और उद्योगों के विकासार्थ आजकल कच्चा और वस्त्रादी दोनों प्रकार का माल आयात किया जाता है। शत युद्ध के पूर्व अधिकतर वस्त्रादी माल ही आयात किया जाता था। देश के औद्योगिकरण तथा देश विचारान के फलस्वरूप यह परिवर्तन हो गया है।

३. अधिकांश भारत का विदेशी व्यापार समुद्री-मार्ग द्वारा ही होता है—भारतवर्ष का विदेशी व्यापार समुद्री-मार्ग द्वारा व्यापार की तुलना में बहुत ही कम होता है। स्थली सीमा पर स्थित देश जैसे ब्रह्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि निर्धन और निछेड़े हुए हैं, अतः उनसे हमारा व्यापार बहुत ही कम होता है। हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर समुद्री मार्ग द्वारा पूर्व और पश्चिम के प्रगतिशील देशों से है।

४. स्वायत्त-पदार्थों का आयात पहले की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। पहले भारत चावल और गेहूँ निर्यात करता था परन्तु अब चावल और गेहूँ बाहर से मँगाता है। अन्त की कमी के कारण विदेशों को हमें शम भी पूरे देने पड़ते हैं।

५. भारतीय विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशों के हाथों में है। भारतीय आयात और निर्यात में ससम्बन्ध कम्पनियाँ विदेशी हैं। जहाजी और बीमा कम्पनियाँ तथा विभिन्न बैंक भी विदेशी हैं। अतः भारत के विदेशी व्यापार से होने वाला अधिकांश लाभ भी उन्हीं की शान्त होता है। अब भारत सरकार इस व्यापार को भारतीयकरण करने के साधनों की खोजने के लिए प्रयत्नशील है।

६. साधारणतया भारत का निर्यात आयात से अधिक होता है—सन् १९४५-४६ तक हमारा आयात, मूल्य की दृष्टि से, निर्यात को अपेक्षा अधिक ही रहा है। अन्य वर्षों में, व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) हमारे अनुकूल

(Favourable) ही रहा है। परन्तु साख पदार्थों के भारी आयात आदि कारणों से सब प्रतिफल (Unfavourable) हो गया है। हमारा पौंड-सन्तुलन (Sterling Balances) का बहुत-सा घट्टा जो बज्जलैड को हमें देना था, आज प्रतिवृत्त व्यापार अन्तर के कारण ही समाप्त हो रहा है।

७. भारत का समुद्र-मार्गी विदेशी व्यापार अधिकतर भारत के कुछ ही बन्दरगाहों द्वारा होता है। भारत का समुद्री-मार्ग द्वारा होने वाला ६० प्रतिशत व्यापार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों द्वारा ही होता है।

८. अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष का विदेशी व्यापार युनाइटेड किंग्डम से अधिक होता है। आज-भी घायाड़ और निर्मात दोनों में ही युनाइटेड किंग्डम का स्थान प्रथम होता है। इसका हमारे कुल विदेशी व्यापार में लगभग २७% भाग है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व यह लगभग ३०% था। हमारे विदेशी व्यापार का १९% भाग अमेरिका से होता है।

९. भारतवर्ष श्रमो देश से साहूकार देश बन गया है। गत युद्ध काल में इंग्लैंड को भारत ने बरोड़ा-सपे के सामान दिया जिसका मूल्य इंग्लैंड की सरकार नहीं दे सकी और वे पीठ पावने के रूप में इकट्ठे हो गये। इस प्रकार भारत एक ऋणी देश में साहूकार-देश हो गया।

१०. निर्यात पर वर्षों और जलवायु का प्रभाव कम हो गया है। पहले भारत का निर्यात कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं का था, परन्तु अब तैयार मान का भी है। अन्तु निर्यात पर वर्षों और जलवायु का पहले जितना प्रभाव नहीं रहा।

११. भारत का विदेशी व्यापार कामतवेत्थ के बाहर के देशों के साथ बढ़ रहा है। भारत का आयात निर्यात कामतवेत्थ के बाहर के देशों के साथ बढ़ रहा है और इंग्लैंड, जापान और जर्मनी आदि देशों के साथ घट रहा है।

१२. हमारे निर्यात की वस्तुओं की सूची में शोड़ी-सी वस्तुएं हैं, जैसे जूट का सामान, कपास, चाय, चमड़ा, धातु और खनिज पदार्थ, परन्तु आयात की सूची में बहुत वस्तुएं हैं।

१३. भारतवर्ष का प्रति व्यक्ति पीछे विदेशी व्यापार इंग्लैंड, अमेरिका आदि अन्य देशों की अपेक्षा कम है। भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से प्राथम सम्पन्न नहीं होने के कारण यहाँ के प्रति व्यक्ति का विदेशी व्यापार अन्य देशों की तुलना में कम है।

१४. हमारे निर्यात की मुख्य वस्तुएं—जूट का तैयार मान, चाय और सूती कपड़ा तथा आयात की मुख्य वस्तुएं—मशान, यन्त्राज, रुई, जूट का कच्चा मान, तेल आदि हैं।

१५. हमारे देश में उपभोग की वस्तुओं के आयात का स्थान औद्योगीकरण की वस्तुओं से रही है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हम केवल अपने उपभोग की वस्तुओं का ही आयात करते थे, किन्तु अब देश के औद्योगीकरण के फलस्वरूप मशीनें, औज़ार, रसायन, कच्चा मान आदि भी आयात हो गये हैं।

भारतीय विदेशी व्यापार की वस्तुयें (बनावट) (Composition of Foreign Trade of India) - हमारे निर्यात आयात की मुख्य वस्तुयें निम्न-निम्न हैं :-

भारतीय विदेशी व्यापार १९५५-५६
(समुद्रो, स्थली व वायु-मार्गों द्वारा) (करोड़ रुपये में)

निर्यात (Exports)		आयात (Imports)	
जूट की बनी वस्तुयें	११८.४	साधारण दान व भाटा	१७.५
चाय	१०६.२	खनिज तेल आदि	६०.२
		कपास और रई रुई	५७.०
		जूट-कच्चा	१६.३
लोहा व इस्पात		रासायनिक पदार्थ	
तथा अन्य वस्तुयें	२१.६	व सीपधियाँ	३३.०
वनस्पतिजन्य तेल	१६.३	विजनी का सामान तथा अन्य	१५.५
कपास और रई रुई	३६.४	मशीनरी (नौवोंमोटिव सहित)	१००.२
बनायी हुई खालें व चमड़ा	३०.२	लोहा व इस्पात का सामान	६९.५
मृत् तथा सूती धातु	६५.५	मोटर वाहियाँ	५६.०
अन्य वस्तुयें	१७५.३	अन्य वस्तुयें	२२४.३
योग	५६७.०	योग	६८८.०

भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुयें

(१) जूट का माल (Jute Goods) - भारतवर्ष के निर्यात में जूट का प्रथम स्थान है। देश विभाजन के पूर्व जूट के पश्चे भाग के आध-आध जूट का कच्चा माल भी निर्यात किया जाता था। कच्चे जूट पर भारत का एकाधिकार था, क्योंकि संसार का ६७% जूट उत्पाद भारत में पैदा होता था। हमारे कच्चे जूट के मुख्य ग्राहक ब्रिटेन (स्काटलैंड की इरी मिल), संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रान्स, इटली, बेल्जियम, जर्मनी और स्पेन थे। देश-विभाजन के परिणामस्वरूप भारत के भारी जूट-उत्पादनक्षेत्र पाकिस्तान में बने गये। जिसके कारण भारत स्वयं कच्चे माल के लिये पाकिस्तान पर निर्भर हो गया। अब जिनकी को बन्नी हुई माल को पूरा करने के लिए कई राज्यों में जूट की उपज बढ़ाई जा रही है।

भारत में कुल ११२ जूट की मिलें हैं जिनमें से ६७% बनरहा और गेय मदान, उत्तर प्रदेश आदि में हैं। इन मिलों में जूट के बारे (Gunny Bags), टाट (Hessian), मोटे काबोन और फर्शोपा, यनोने तथा रस्से (Cordage) और तिरपात (Turpentine) आदि बनाये जाते हैं। इन मिलों में १९५५-५६ में १०,२७,२०० टन सामान तैयार किया गया जो सार्वजनिक विदेशों को भेज दिया गया तथा कुछ पहले स्तर में से भी भेजा गया। भारतीय जूट के आयात के मुख्य स्रोतों में संयुक्त राज्य अमेरिका (४६%), इंग्लैंड (१८%), फ्रान्स (१८%) तथा आस्ट्रेलिया (१८%) हैं। भारत से टाट और गेय मिथ, दमोली, अमेरिका (जापान और फ्रान्स), दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका, जावा, ब्रिटेन, क्यूबा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया तथा जापान का आते हैं। जूट के पत्तों तथा छुट्टे बोरे तुलियाल को भी आते हैं।

वर्तमान समय में जूट के निर्यात पर नई बातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अमेरिका में जेड्रे भरने के नये वैज्ञानिक ढंग निकाल लिये गये हैं जिससे वहाँ धन भारत के बोरा की माँग कम हो गई है। इसके अनिरिक्त, नई देशों में जूट की स्थानापन्न वस्तुओं में काम चलाया जाता है। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड में लिनेक्स (Lenax) नामक रेशे के बोरा में ऊन भरा जाता है। रूस और अज़रबैजान में पलसी के रेशे बोरे बनाने में प्रयुक्त किये जाते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया में कागज और कपड़े के बोरे काम में लिये जाने लगे हैं। पूर्वी अफ्रीका में Sisal, मैक्सिको में Henequen, कोलम्बिया में Figue, ब्राजील में कैरोपा (Carop), स्पेन में एस्पार्टो घास (Esparto Grass) इटली में जूलीट (Julital) और जावा में रोसेला (Rosella) नामक विभिन्न प्रकार के रेशेदार पदार्थों में बोरे बनाये जाते हैं। परन्तु अभी भारतीय जूट के स्थान कोई भी पदार्थ स्थापनायक सिद्ध नहीं हुआ है।

(१) चाय (Tea)—हमारे देश की निर्यात-सूची में चाय का दूसरा स्थान है। चीन के सिवाय भारत चाय संसार में सबसे अधिक पैदा करता है। भारत में चाय की उत्पत्ति का ५५% आसाम में, २३% पश्चिमी बंगाल में, १७% दक्षिणी भारत में और ३०% उत्तर प्रदेश, बिहार व पूर्वी पंजाब में होता है। भारतवर्ष गर्म देश होने के कारण यहाँ चाय की खपत कम होती है। इसलिए भारतीय चाय की कुल उपज का तीन-चौथाई भाग विदेशों की निर्यात कर दिया जाता है। भारत की चाय का निर्यात ७०% इंग्लैंड को, १२% संयुक्त राज्य अमेरिका की, ७% कनाडा की, ५% आस्ट्रेलिया और ४% मध्य पूर्व के देशों को होता है। रूस, ईरान, अरब आदि भारत की चाय के प्रमुख ग्राहक हैं। ७५% चाय कलकत्ता बन्दरगाह से और २५% चाय मद्रास बन्दरगाह से निर्यात की जाती है। सन् १९५८ में १३६.५ करोड़ रुपये की चाय का निर्यात किया गया।

(३) सूत और सूती वस्त्र (Yarn & Cotton Goods)—भारत में सूती कपड़ों की मिलें मुख्यतः बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत में हैं। बम्बई व गुजरात राज्य बम्बई और अहमदाबाद नगरों की मिला में सारे देश के उपभोग का ३ सूत और ३ कपड़ा उत्पन्न करते हैं। भारतीय मिला की सूत मोटा होता है। इनमें अधिकांश सूत ३० नम्बर से कम का होता है। ४० नम्बर से ऊपर का सूत तो बहुत कम बनाया जाता है, क्योंकि भारत में उत्तम और लम्बे रेशे वाली रई का उपयोग कम किया जाता है तथा ज़रवायु भी मुख्य है। पश्चिम अफ्रीके कपड़ों के लिए भारत अब भी विदेशों पर निर्भर है। परन्तु फिर भी देश में तैयार किया हुआ कपड़ा हिन्द महासागर के किनारे वाले देशों—ईरान, ईराक, अरब, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, भियत, मूलान, टर्की, चीन, स्ट्रेट्स सेंटमेट, हिन्द-एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लका आदि देशों को निर्यात किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध-काल में जब इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से इन देशों को कपड़ा मिलना सम्भव हो गया था तभी से भारत में इन देशों की कपड़े की पूर्ति बग़ना आरम्भ की। इस प्रकार सन् १९३८-३९ में जहाँ २४ करोड़ रुपये के मूल्य का सूत कपड़ा विदेशों को निर्यात किया गया वहीं सन् १९४९-५० में १८ करोड़ और सन् १९५०-५१ में ११२ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात हुआ। सन् १९५८ में लगभग ४६.४६ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा निर्यात किया गया।

(४) रुई—कच्ची और रूई (Raw & Waste Cotton)—भारत में मुख्यतया दो प्रकार की कपास उत्पन्न की जाती है—लम्बे रेंगे वाली (Long-staple cotton) जो गुजरात, काठियावाड़ के कुछ भाग, दक्षिणी बम्बई और मद्रास के कुछ भागों में उत्पन्न की जाती है; छोटे रेंगे वाली (Short-staple cotton) जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बरार, मध्य भारत और राजस्थान में पैदा की जाती है। सारे भारत में २३% लम्बे रेंगे वाली, १०% मध्यम रेंगे वाली और १७% छोटे रेंगे वाली रुई पैदा की जाती है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारतवर्ष से २४ करोड़ रुपये की रुई जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बेल्जियम आदि देशों को निर्यात की जाती थी। परन्तु युद्ध काल से निर्यात बंद जाने वाली मात्रा में बहुत कमी हो गई है, क्योंकि देश में ही सूती वस्त्रों के कारखानों की वृद्धि हो जाने से कपास की खपत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सन् १९४७ में देश विभाजन के परिणाम-स्वरूप लम्बी रेंगे वाली कपास के प्रमुख उत्पादन-क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने में भारतवर्ष को उत्तम धोखी की कपास विनोदतः मिथ, मुजान, केजिया, समुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से आयात करनी पड़ती है। थोड़ा-बहुत मोटे रेंगे वाली कपास का निर्यात इंग्लैंड, अमेरिका, इटली और जापान को होता है। सन् १९५८ में २१.२ करोड़ रुपये की रुई—कच्ची और रूई निर्यात की गई।

(५) तेल और तिलहन (Oil & Oilseeds)—तेल-बीज पैदा करने वाले देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत में कबज तोयाफली, जूतून और ताड़ के सिवाय सभी प्रकार के तेल बीज पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किये जाते हैं। भारत में तिलहन की उत्पत्ति के मुख्य क्षेत्र में हैं—मलसी मध्य प्रदेश में; भू मसूनी मद्रास, बम्बई और हैदराबाद। राज् उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब में; तथा तिल राजस्थान और मारे दक्षिणी भारत में। पहले तेल बीजों का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता था परन्तु अब देश में ही तेल निकालने के कारण केवल खली ही अधिक मात्रा में निर्यात की जाने लगी है। सन् १९५६ में १७.५ करोड़ रुपये का तेन एवं तिलहन निर्यात किये गये थे। भारत से भू मसूनी का निर्यात फ्रांस, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड को होता है। मलसी इटली, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड को भेजी जाती है। भारत में तिल का तेन इंग्लैंड, पारिषाद, अरब, लका, फ्रांस मिथ, जर्मनी, बेल्जियम और इटली को भेजा जाता है। रेडी और रेडी का तेल फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जर्मनी, स्पेन, कनाडा और बेल्जियम को निर्यात किया जाता है।

(६) चमड़ा—कच्चा और कसाया हुआ (Hide & Skins—Raw and Tanned)—द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत से पर्याप्त मात्रा में चमड़ा चमड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता था परन्तु युद्ध-काल में जहाज आदि के उपलब्ध न होने की कठिनाई के कारण यह मात्रा कम हो गई। इसके प्रतिरिक्त, भारत में ही चमड़ा कमाने के कारखानों की स्थापना हो चुकी है, इसलिए कसाया हुआ चमड़ा ही अधिक मात्रा में निर्यात किया जाने लगा है। भारत के चमड़े की अधिक मांग इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में है। सन् १९५८ में कसाया हुआ चमड़ा लगभग १८.६३ करोड़ रुपये का और कच्चा चमड़ा लगभग ७.१७ करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

(७) तम्बाकू (Tobacco)—संसार में तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है। भारतवर्ष में तम्बाकू मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, मंगूर और बम्बई राज्यों में उत्पन्न की जाती है। तम्बाकू की उपज का भारत में ५० प्रतिशत घोंडी सूँघनी सिगरेट तथा चुट्ट में रूप में उपजाता है। दोन तम्बाकू बलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई बन्दरगाहों में इङ्ग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, बेल्जियम और नीदरलैंड को निर्यात की जाती है। सन् १९५८ में भारत से लगभग १४७ करोड़ रुपये की तम्बाकू निर्यात की गई थी।

(८) खनिज पदार्थ (Minerals)—संसार में सबसे अधिक अभ्र (Mica) भारत में होता है। सारा संसार का आधा अभ्रक यहीं पर विकसित है। इसी प्रकार मैंगनीज का लाख और इस्पात बनाने के काम में प्रयोग होता है, यहाँ पर अधिक प्रयोग होता है। इसमें कम के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अधिकांश अभ्रक और मैंगनीज दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी और जापान मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त, चूना, लोहा तथा अन्य औद्योगिक पदार्थों भारत से विदेशों को निर्यात की जाती है।

निर्यात की अन्य वस्तुएँ—इन्हीं अतिरिक्त, भारत में लाख, तरकारी व सब्जी ऊन तथा ऊनी मान, रेशम का सामान, गीद, लाख, कच्चा, मसाले, दाढ़कर आदि निर्यात की वृद्धि घटती चली है।

भारत सरकार की निर्यात-सम्बन्धी नीति—(Export Policy of the Government of India)—भारत सरकार निर्यात में वृद्धि के लिए चिन्तित थी। अतः उसने सन् १९४६ में 'गोवालाला निर्यात प्रोत्साहन समिति (Gorwala Export Promotion Committee) की नियुक्ति की और उसकी सिफारिशों का कार्यान्वित किया गया। सरकार ने निर्यात नियन्त्रण-नीति के विषय में सम्मति देने के लिए एक 'परामर्शदात्री परिषद्' (Advisory Council) की भी स्थापना की। प्रत्येक ६ मास बाद निर्यात नीति का सहायकीकरण किया जाता है और प्रचलित अवस्थाओं एवं वस्तुओं के अनुसार वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई जाती है या आन्तरिक दिया जाता है। सरकार दुर्लभ करेंसी क्षेत्र (Hard Currency Area) को अधिकतम मात्रा निर्यात करने का प्रयत्न कर रही है ताकि देश के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्राप्ति सुविधापूर्वक हो सके। अदला बदली के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर व्यापारिक समझौते की किये जाते हैं।

भारत के आयात की मुख्य वस्तुएँ

(१) खाद्यान्न (Food grains)—द्वितीय महायुद्ध में पूर्ण भारत विदेशों को खाद्यान्न का निर्यात करना था और ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा ईरान, अफगानिस्तान आदि खाद्यान्न के प्राप्ति के परन्तु द्वितीय महायुद्ध-काल में और उनके पश्चात् अन्य तक मानववर्ष विदेशों में खाद्यान्न की कमी रह गई है। देश विभाजन के पश्चात् ही भारत की खाद्यान्न अधिक मात्रा में माँगना आवश्यक हो गया है। सन् १९५१-५२ में ४७२ लाख टन खाद्यान्न (लगभग २२० करोड़ रुपये का) आयात किया गया। देश में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने की कठिनायनाएँ बनाई गईं और इसके परिणामस्वरूप सन् १९५२-५३ में १५६ करोड़ रुपये का ही आयात तथा आटा आयात किया गया। प्रार्थना है कि भविष्य में देश की कम आयात करता पड़ता।

साखान्न वा प्रायात अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, तर्मा, अर्जेन्टाइना आदि देशों से किया जाता है। सन् १९५८ में १०३*३ करोड़ रु० का साखान्न ही आयात किया गया।

(२) मशीनें (Machinery)—भारत को कृषि-प्रधान देश होने के कारण मशीनों, कल-युक्तों आदि के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश के औद्योगिकरण के फलस्वरूप अधिक मात्रा में मशीनों का आयात करना आवश्यक है, परन्तु घर्षायात के कारण और मशीनों के दाम बहुत ऊँचे होने के कारण पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं किया जा सका है। मशीनों का आयात मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जापान आदि देशों से होता है। सबसे-अधिक ट्रैक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। सन् १९४७-४८ में ३.९ करोड़ रुपये की मशीनों का आयात किया गया। तब से मशीनों के आयात में निरन्तर वृद्धि हो रही है और सन् १९४९-५० में १०४ करोड़ रुपये की मशीनों का आयात किया गया। परन्तु सन् १९५०-५१ में इसका आयात ८९ करोड़ रुपये का हो किया जा सका। सन् १९५८ में १४० करोड़ रु० की मशीनों का आयात किया गया।

(३) रुई (Cotton)—देश विभाजन के परिणाम-स्वरूप भारत में रुई पैदा करने वाले कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को चले गये तथा भारत में लम्बे रेशे की रुई का भी काफी प्रभाव है। इसलिए भारत का विदेशों से रुई खरीदनी पड़ती है। रुई विनोद-मिश्र, केनिया मूझन, पाकिस्तान, और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाती है। सन् १९४२-४३ में लगभग ७६३ करोड़ रुपये की रुई आयात की गई और सन् १९४६ में १३६ करोड़ रु० की रुई आयात की गई।

सूती कपड़े—ब्रिटेन, जापान, चीन, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी से आते हैं किन्तु हमारे मुख्य विक्रेता ब्रिटेन और जापान हैं।

(४) मोटर गाड़ियाँ आदि (Motor Cars etc)—यह महापट्ट के पश्चात् आयात सूची में मोटर-गाड़ियों का ऊँचा स्थान है। मोटर गाड़ियाँ, कारखानों आदि भारत में मुख्यतः ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली और जर्मनी से आती हैं। सन् १९४६ में १०४२ करोड़ का आयात हुआ।

(५) पेट्रोल (Petrol)—भारत में गलिय तेल की बहुत कमी है। मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल का आयात यहाँ चीन, बॉनिया, सुमात्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरान से किया जाता है। सन् १९५८ में १५*५८ करोड़ रुपये के मूल्य का पेट्रोल विदेशों से खरीदा गया था।

(६) रासायनिक पदार्थ एवं दवाइयाँ (Chemicals and Medicines) ये पदार्थ ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि से आयात किए जाते हैं। सन् १९४६ में इसका आयात ४१ करोड़ रु० का हुआ।

(७) लोहा, इस्पात तथा उनकी बनी वस्तुएँ—रमाणे यहाँ लोहे का सामान मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान से आता है। सन् १९४८ में लोहा, इस्पात तथा उनकी बनी वस्तुएँ ६७८ करोड़ रुपये की आयात की गई थी।

(८) कागज (Paper)—भारत में कागज ब्रिटेन, जाँ, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी से आयात किया जाता है। सन् १९४८ में ८ करोड़ रुपये का कागज आयात किया गया।

अन्य आयात की वस्तुएँ—अन्य वस्तुएँ जो भारत में आयात की जाती हैं वे हैं—वन-उपकरणादि, विजली का समान, रंग, मशीनों का तेल, कृत्रिम रेशम, विस्फोटकान का समान, ऊन और ऊनी गाल, फन व तरकारियाँ, रबर का समान, घानुएँ, कटलरी एवं हाईवेयर आदि ।

दृश्य (Visible) एवं अदृश्य (Invisible) आयात नियति—दृश्य आयात-निर्यात वे हैं जिनके आँकड़े (Statistics) आयात-निर्यात कर-विभाग के लेखों (Customs Returns) या अन्य प्रकाशित पत्रों में उपलब्ध हैं । परन्तु कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो प्रकाशित लेखों तथा आँकड़ों में सम्मिलित नहीं होती हैं, उनके आयात-निर्यात को अदृश्य आयात-निर्यात कहते हैं । भारत में दृश्य आयात-निर्यात की सूची ऊपर दी जा चुकी है । अब यहाँ भारत के अदृश्य आयात-निर्यात का विवेचन किया जाता है ।

भारतवर्ष के अदृश्य आयात (Invisible Imports of India)

१. भारत जब विदेशों से ऋण लेता है, तो वह विदेशी ऋण के उपयोग का अदृश्य आयात करता है ।

२. विदेशों से ऋण लेते समय भारत की प्रतिभूतियाँ (Securities) जमा कराती पड़ती हैं क्योंकि ऋण के भुगतान के समय वापिस हो जानी है । तब भारत अदृश्य प्रतिभूतियों का आयात करता है ।

३. भारतीय मानी जो विदेशों को जाते हैं और वहाँ जो रक्का धूप करते हैं और उसके बदले में जो सेवाएँ वे प्राप्त करते हैं, वे भारत के अदृश्य आयात में सम्मिलित हैं ।

४. भारतीय विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये जो धन भेजा जाता है तथा जिसके बदले में जो सेवाएँ प्राप्त होती हैं, वे भारत का अदृश्य आयात हैं ।

५. विदेशी जहाज़ी, बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ जो अपनी सेवाएँ भारत के लिए प्रस्तुत करती हैं, वे भी भारत की अदृश्य आयात हैं ।

६. भारत विदेशी साहस को आयात करता है तथा उसे विदेशी साहसियों को पारितोषिक के रूप में कुछ देना पड़ता है । अतः साहसियों द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का अदृश्य आयात होता है ।

७. भारत सरकार को क्रेयान के रूप में अथवा विदेशों से जो माल श्रय दिया जाता है, उसके लिये या सोना चाँदी के लिये 'होम चार्ज' देने पड़ते हैं—ये भी अदृश्य आयात होते हैं ।

भारत के अदृश्य निर्यात (Invisible Exports of India)

१. जब विदेशों ऋण का भुगतान किया जाता है, तो प्रतिभूतियों का निर्यात करते हैं ।

२. विदेशी यात्रियों द्वारा भारत में प्रस्तुत सेवाओं के बदले में व्यय करना भारत का अग्रदूत निर्यात है ।

३. विदेशियों द्वारा भारत में स्थिति मिशन आदि संस्थाओं के सहायताार्थ भेजा गया धन भारत का अग्रदूत निर्यात है ।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of India's Foreign Trade)—व्यापार की दिशा से हमारा अर्थ यह होता है कि भारत का विदेशिक व्यापार किन किन देशों से होता है तथा उन देश से भारत क्या खरीदता है अथवा बदले में क्या देता है ।

निम्न तालिका में भारत की समुद्र व वायुमार्गीय विदेशी व्यापार की दिशा बताई गई है :—

सन् १९५८

देश	आयात (लाख रुपये में)	निर्यात (लाख रुपये में)
ब्रिटेन	१६८,५२	१६५,२४
संयुक्त-राज्य अमेरिका	१६१,४६	६२,५६
भारत-तिमा	१५,३२	२१,३७
कनाडा	६८४	१४,५४
फ्रांस	१६,६६	७,०६
इटली	२५,५७	५,५०
जर्मनी (पश्चिम)	६२,६५	१४,७०
नीदरलैंड	६,८२	६,७२
सोवियट संघ	२१,७१	११,३१
मॉरिटानिया	७	६,२५
बर्मा	४५,५४	७,४८
पाकिस्तान	६,२८	७,१२
संका	१०,४५	१६,७५
जापान	१६,६६	२५,७७
निध	६,२४	८,६३

व्यापार का अन्तर या सन्तुलन (Balance of Trade)—विदेशों से आयात किये हुए माल तथा देश से निर्यात किये हुए माल के अन्तर को व्यापार का अन्तर या व्यापार-सन्तुलन कहते हैं । दूसरे शब्दों में, इस आयात और इस निर्यात का अन्तर व्यापार का अन्तर कहता है । यदि देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है, तो उसे अनुकूल व्यापार का अन्तर (Favourable Balance of Trade)

कहेंगे, और यदि निर्यात से आयात अधिक है, तो उसे **प्रतिकूल व्यापार का घन्तर** (*Unfavourable Balance of Trade*) कहेंगे । द्वितीय महायुद्ध काल से पूर्व भारत का व्यापार का घन्तर सामान्यतया अनुकूल रहता था, परन्तु भावकल यह प्रतिकूल हो रहता है, क्योंकि भारत को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ता है । केवल सन् १९५०-५१ में यह अनुकूल हो गया था । नीचे की तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है —

(करोड़ रुपया में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार का घन्तर
१९४६-४७	४६४.३९	४८५.३३	- १०८.९६
१९४७-४८	४६५.४६	४८६.८८	+ २१.४२
१९४८-४९	८६२.८४	७१५.४६	- १४७.३८
१९४९-५०	६३२.६५	५२६.७८	- १०५.८७
१९५०-५१	६८६.९६	५६३.५४	- १२३.४२
१९५१-५२	६२७.१६	६३७.४३	- १०.२७
१९५२-५३	८५६.१८	५८०.३०	- २७५.८८

भुगतान का घन्तर (Balance of Payment)—हर एक राष्ट्र अपने आयात निर्यात का हिसाब लगाने के पश्चात् जो व्यापार का घन्तर निकलता है, उसे भुगतान का घन्तर या खाते का घन्तर (*Balance of Accounts*) कहते हैं । यदि देश को भुगतान के समय कुछ मिलता है, तो इसे अनुकूल भुगतान या खाते का घन्तर कहेंगे और यदि देश को कुछ देना होता है, तो इसे प्रतिकूल भुगतान या खाते का घन्तर कहेंगे । इस प्रतिकूल भुगतान या खाते के घन्तर को ऋणदाता का घन्तर (*Balance of Indebtedness*) भी कहते हैं, क्योंकि देश ने जो विदेशों से उधार माल खरीदा उसका अब मूल्य चुकाना है ।

खाते के घन्तर का निपटारा—यदि खाते का घन्तर किसी देश के अनुकूल होता है, तो वह सोना भेजा कर या ऋण देकर निपटारा या भुगतान कर लेता है । इससे विपरीत, यदि खाते का घन्तर प्रतिकूल हुआ, तो सोने या निर्यात करने या विदेशों से ऋण लेकर उसका निपटारा या भुगतान कर दिया जाता है ।

व्यापारिक समझौते—मार्च १९५७ के बाद से अब तक १२ देशों ने साथ हुए व्यापारिक समझौते को नवीकृत किया गया और अफगानिस्तान, बेलोरोसिया, जापान, यूनान तथा श्री लंका के साथ नये समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये । इसाविया, जापान तथा यूनान के साथ व्यापारिक समझौते पहली बार हुए । भारत तथा २६ देशों के बीच व्यापारिक समझौते पहले से ही हो रहे हैं ।

सरकार की व्यापार नीति—निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार विभिन्न वस्तुओं के लिये व निर्यात प्रोत्साहन परिषद् स्थापित कर चुकी है । 'यूरो वन प्रोत्साहन परिषद्' की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल विभिन्न सम्बन्धी परिषद-

तियों के अध्ययन के लिये विदेशों की यात्रा पर गया। इस परिपद ने सूती पत्र के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने शाखायें भी खोल दी हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मेला में भी भाग लेता आ रहा है।

राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation)—मई १९५६ में १ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से एक सरकारी संस्थान के रूप में राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य, विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार को कमियों को पूरा करके व्यापार को समर्थन करना है। स्थापित होने के बाद से ही यह निगम नियमित प्रयोज्यवस्तुओं का निर्यात देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार में विस्तार करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के औद्योगिकीकरण पर कुछ भी प्रभाव डाले बिना इन देशों से इस्पात, सीमेंट तथा औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किये जा सकें। सीमेंट, सीडाभस्म, क्रास्टिक सोडा, बन्ना रेशम, उर्वरक तथा विभिन्न जैसी वस्तुयें रास्ते मूल्य पर पहले से ही लब्ध हुआ है। निगम ने जिन वस्तुओं के निर्यात में सम्बन्ध में व्यवस्था की है, उनमें कच्चे तिनज पदार्थ, जूने तथा स्मृतकारों की वस्तुयें आदि हैं।

योजना और विदेशी व्यापार—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्मात बढ़ाने पर बल दिया गया है और सन् १९६०-६१ तक इसके लिये निम्न स्तर निर्धारित किये हैं :—

जूट का सामान ६ लाख टन, गन्नी २ से ३ लाख टन, मैंगनीज १ लाख टन, समक ३ लाख टन, बलस्थिति २० से २५ हजार टन, स्टाच १० हजार टन, कोक ३० हजार टन, टिटेनियम एक हजार से बारह सौ टन, सूती कपड़ा एक हजार से बारह सौ मिलियन गज, रेशम १० मिलियन गज, वाइमिकल डेड मान और इजीनियरिंग का सामान ३ से ५ करोड़ रु० में मूल्य का।

विदेशी व्यापार से लाभ (Advantages of Foreign Trade)—

- (१) विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को वे वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं जिनका वह स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता। यदि विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, तो यूरोप के गरम देश काय बिना ठण्डे। यदि बर्मा काबल देश बन्द कर दे, तो भारत बिना काबल के रह जाय। (२) विदेशी व्यापार से देश के प्राकृतिक साधनों एवं शक्तियों का सम्यक् विकास और उपयोग सम्भव होता है। (३) विदेशी व्यापार का मुख्य आधार अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन है। धन धन विभाजन से जो लाभ होते हैं, वे भी सब उपलब्ध हो जाते हैं। (४) विदेशी व्यापार प्रत्येक देश को अपनी योग्यतानुसार उत्पादन करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिये उस देश में सब साधन हैं तथा जो वहाँ कम लागत पर उत्पादन की जा सकती हैं। (५) विदेशी व्यापार से राष्ट्रीय सम्बन्धित होना है उससे उनको उपयोगिता का लाभ होता है। (६) विदेशी व्यापार में बड़े परिमाण में उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है जिसमें कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उपयोगिताओं को सम्यक् रूप पर वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। (७) विदेशी व्यापार से लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा रहता है, क्योंकि नई-नई वस्तुयें उपयोग करने के लिये मिलती हैं। नई-नई वस्तुओं की मँग करने में विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। (८) विदेशी व्यापार की उपरति से वातावरण और शक्तियों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिसमें बड़े परिमाण के उत्पादन को सम्यक् प्रोत्साहन मिलता है।

(६) विदेशी व्यापार के कारण किसी वस्तु की न्यूनता का औद्योगिक अनुभव नहीं होता तथा देश की दुर्भिक्षों से रक्षा भी की जा सकती है। (१०) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विशेषतः देश कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर उनको निर्यात करेगा जिसमें उस देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी और वही औद्योगिक उन्नति होगी। (११) विदेशी व्यापार एकाधिकार-उत्पादन पर एक रोक है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता रहती है। (१२) विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए देश के आन्तरिक भागों में आतायात के साधनों की उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश के आन्तरिक भागों में वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता रहती है। (१३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश एक-दूसरे के सम्पर्क में आ जाता है। अतः परस्पर विचार-विनिमय के कारण उनकी आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक उन्नति सम्भव हो जाती है। (१४) विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को लाभ पहुँचता है (यदि वे सब समानता के आधार पर व्यापार करते हैं) और परस्पर प्रेम बढ़ता है। देशों का पारस्परिक प्रेम युद्ध की सम्भावना को प्रभावहीन कर देता है तथा विश्व में शान्ति स्थापित रखने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का आधार है।

विदेशी व्यापार की गृहानियतियाँ (Disadvantages)—विदेशी व्यापार के अन्तर्गत वाजार बहुत बिरतुन हो जाता है जिससे नभी कभी माँग का सही अनुमान नहीं लगता और उत्पादन मात्र से अधिक हो जाता है। अत्यधिक उत्पादन में देश और उत्पादक दोनों को ही हानि उठानी पड़ती है। (१) विदेशी सामान को देश में सड़ी मात्रा में आयात करने में कुछ उपयोग वस्तुओं की उन्नति में पड़ता पहुँचता है। (२) हानिकारक वस्तुओं के आयात में जो हानि पहुँच सकती है उसका अनुमान सही भाँति लगाया जा सकता है। (३) उत्पादन अधिक होने रहने में देश के प्राकृतिक साधनों के क्षीय हो समाप्त हो जाने का भय रहता है, जैसे कीमती, लहसुन आदि की खाद (४) निर्यात में आयात अधिक होने पर प्रतिवृत्त व्यापार सम्मुख हो जाता है जो देश को हानिकारक सिद्ध होता है। (५) विदेशी व्यापार से तब ही लाभ हो सकता है जबकि दोनों व्यापार करने वाले देश समानता के आधार पर व्यापार करते हैं, अन्यथा एक को लाभ और दूसरे को हानि होगी। (६) उन देशों में जो कृषि प्रधान है, विदेशी से आयात अधिक आ जान से उत्पत्ति लाभ-नियम पर जो प्रभाव पड़ता है, वह देश के लिये हानिकारक सिद्ध होता है।

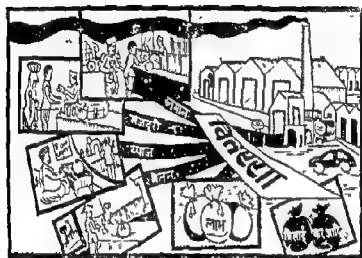
अभ्यासाथ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—तृतीय महायुद्ध के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ (Special Features) क्या हैं ? भारत के निर्यात तथा आयात की मुख्य वस्तुएँ बतलाइए।
- २—भारत के आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। पिछले दस वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में क्या-क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं ?
- ३—भारत में आयात और निर्यात का विवरण दीजिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत का निर्यात इतना कम क्यों हो गया है ?

- ४—भारतीय विदेशी व्यापार के मुख्य आयात और निर्यात पदार्थ क्या हैं ? इनमें प्रत्येक के सापेक्ष का विवेचन कीजिए ।
- ५—भारत के आयात-निर्यात व्यापार की प्रधान विशेषताएँ क्या हैं ? ग्रानकन विदेशों से खाद्य पदार्थ और वस्त्र मँगाने में भारत को क्या कठिनाइयाँ हैं ?
- ६—व्यापाराधिक्य (Balance of Trade) और ऋणाधिक्य (Balance Indebtedness) में भेद स्पष्ट कीजिए । भारत के निर्यात तथा आयात के प्रमुख मद कौन-से हैं ? (नागपुर १९५८)
- ७—वैदेशिक व्यापार के आर्थिक लाभ स्पष्टतया समझाइए । क्या आपकी राय में किसी देश के लिए वैदेशिक व्यापार हमेशा लाभदायी हुआ करता है ? (नागपुर १९५७)
- ८—‘भुगतान का अन्तर’ में क्या तात्पर्य है ? स्पष्ट कीजिए । (नागपुर १९४९)
- ९—भारत के विदेशी व्यापार के प्रधान लक्ष्य क्या हैं ? तृतीय महायुद्ध के बाद इनमें क्या परिवर्तन हुए हैं ? (सागर १९५६, ५१)
- १०—‘व्यापार-सन्तुलन’ से क्या तात्पर्य है ? क्या विदेशी व्यापार से किसी देश को लाभ होते हैं ? (सागर १९४९)
- ११—विदेशी आयात किए हुए माल का दाम कोई व्यापारी किस प्रकार मँदा करता है ? (पटना १९५२)
- १२—‘व्यापार का अन्तर’ और ‘भुगतान का अन्तर’ में क्या भेद है ? स्पष्ट कीजिए । (गुवा १९४६)
- १३—लिपिशिर्मा लिखिए :—
 भारत का अन्तर्देशीय व्यापार (रा० बो० १९६०)
 व्यापाराधिक्य (नागपुर १९५७)
 ऋणाधिक्य (Balance of Indebtedness) (नागपुर १९५६)
 अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार का सन्तुलन (सागर १९५७)
- १४—भारत के मुख्य आयात और निर्यातों का उल्लेख कीजिए । भारत का भीतरी व्यापार अथवा विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है ? (दिल्ली हा० से० १९४९)
- १५—भारत के भीतरी व्यापार की व्यवस्था का वर्णन कीजिए । (दिल्ली हा० से० १९४७)

वितरण (DISTRIBUTION)



“अर्थशास्त्रीय वितरण यह बताता है कि समाज द्वारा
उत्पादित धन उत्पात्ति के साधनों अथवा साधनों
के स्वामियों में उन्होंने उत्पादन में सक्तिय भाग
लिया है, किस प्रकार बाँटा जाता है”

—सर सिडनी चैपमैन

वितरण की समस्या (Problem of Distribution)

वितरण शब्द का अर्थ—वितरण शब्द का अतिमित्र प्रयोगों में भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वितरण शब्द का अर्थ 'बंटन' या 'बंटवारा' में होता है। व्यापारिक भाषा में वितरण शब्द से आशय वस्तुओं के विक्रय से है। धोक तथा फुलकर विक्रेता, यातायात व सम्वाद के साधन भादि मास के वितरण अर्थात् वस्तुओं को निर्माताओं या उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में बड़े सहायक है। इसलिये इन्हे वितरण के साधन (Distributive Agencies) कहते हैं। अर्थशास्त्रीय अर्थ में 'समुच्च रूप में उत्पादित धन को उत्पादन करने वाले समस्त साधन में बाँटने की क्रिया को वितरण कहते हैं।"

प्रो० चैपमैन ने लिखा है कि 'वितरण का विषय उत्पादन के साधनों के मध्य उनके द्वारा ही उत्पन्न की गई सम्पत्ति को बाँटना है, क्योंकि इसमें उनका प्रमुख हाथ रहता है।' प्रो० सेंटिगमैन के अनुसार "उत्पन्न की हुई सम्पत्ति को उत्पादन के विभिन्न साधन में बाँटने की क्रिया का ही नाम वितरण है।" अतः वितरण द्वारा प्राप्त सम्पत्ति प्रत्येक साधन के लिए पारिधमिक (Earnings) है न कि आय (Income)।

वितरण—अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में (Distribution—as a department of Economics)—उपभोग, उत्पादन और विनिमय की अति वितरण भी अर्थशास्त्र का एक विभाग है। 'इसके अन्तर्गत हम उन मिथ्यात्वों का अध्ययन करते हैं जिनके अनुसार किसी विषय औद्योगिक व्यवस्था की समुक्त उत्पत्ति उन व्यक्तियों में बाँटी जाती है जो उनके प्राप्त करने में सहायक होते हैं।"

प्राथमिक समय में उत्पत्ति मनुक्त रूप में की जाती है। भूमि, धन, पूँजी, सगठन और साहस उत्पादन के पाँच साधन हैं। ये सब मिलकर अपने समुक्त प्रयत्नों द्वारा धन का उत्पादन करते हैं। उत्पत्ति इन सब की ही सम्पत्ति है, अतः, इन सब में उत्पत्ति का व्यापपूर्ण बंटवारा ही 'वितरण' कहलाता है।

अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि यह वितरण किस प्रकार किया जाय, अर्थात्

1—All wealth that is created in society finds its way to the final disposition of the individual through certain channels or sources of income. This process is called distribution.—Seligman)

2—Wicksteed The Commonsense of Political Economy P 359

नैसे उत्पात्ति के साधनों का वारिधिमिक निर्धारित किया जाय। इसका सीधा उत्तर यह है कि जिसने जिसका काम किया उसने उसी अनुपात में उत्पात्ति का भाग मिलना चाहिये। इस प्रश्न को सरल करना कि किस साधन ने कितना कार्य किया अत्यन्त कठिन है। पूँजीपति कहता है कि मैं अधिक महत्व का कार्य किया है, धर्मिक कहता है कि सारा योग्य मुझको ही है और साहसी कहता है कि यदि मैं साहस न करता, तो उत्पादन होता ही नहीं। इस प्रकार सब ही साधन अपने अपने कार्य को ही महत्व देते हैं। वास्तव में ऐसा जाय तो महत्व तो सब ही का है, आवश्यकता सब ही की है और सबके संयुक्त प्रयत्नों से ही उत्पादन होता है। परन्तु प्रश्न यह है कि इनमें से प्रत्येक के महत्व का निर्णय कैसे किया जाय। दूसरे शब्दा में, प्राथमिक समय में धन का वितरण निम्न सिद्धान्तों पर निर्भर है तथा काल से सिद्धान्त उचित और व्यापपूर्ण हैं आदि वितरण-सम्बन्धी अनेक बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र के वितरण विभाग में किया जाता है। अतः वितरण उन सिद्धान्तों का विवेचनारम्भ, आलोचनात्मक तथा रचनात्मक अध्ययन है जिनके अनुसार उत्पात्ति के विभिन्न साधकों में धन का वितरण किया जाता है।^१

वितरण—एक व्यापक क्रिया के रूप में (Distribution—as an Economic act)—जब संयुक्त प्रयत्नों द्वारा उत्पादित धन की उत्पादन में भाग लेने वाले विविध साधनों के किन्हीं रीति से अनुसार बाँटा जाता है, तो वितरण एक व्यापक क्रिया सम्पन्न करते हुए कहा जाता है। इस प्रकार वितरण एक व्यापक क्रिया भी है।

वितरण की समस्या का प्रादुर्भाव (Origin of the Problem of Distribution)—प्राचीन समय में उत्पादन-प्रणाली बहुत ही सरल थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग की सभी वस्तुएँ स्वयं ही तैयार करता था। उत्पादन कार्य में जिन साधनों की आवश्यकता होती थी वह अपने-आप ही जुटाता था। उस समय श्रम का विभाजन बहुत कम हुआ था, इसलिए लोग स्वयं उत्पादन कर स्वयं उसका मूल्य पा जाते थे। गौव का रहने वाला नमक खूता अपने-आप या अपने कुटुम्ब के सदस्यों की सहायता से बनाता था और उसे स्वयं बेचकर मूल्य भी अपने पास रखता था। किसी के हाथ नईबारा नहीं करना पड़ता था। इसलिए वितरण की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु जैसे-जैसे समाज की उन्नति हुई धीरे-धीरे श्रम विभाजन तथा उत्पादन का परिमाण भी विस्तृत होता गया जिससे उत्पादन-प्रणाली भी कठिन होती गई। औद्योगिक क्रान्ति ने जो हमारी उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन कर दिया। अब उत्पादन सामूहिक रूप में, बड़े परिमाण तथा कठिन श्रम-विभाजन में होने लगा जिससे कारण वितरण की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हो गई। आज की उत्पादन प्रणाली मजदूरों का एक जोड़ा एक मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है बल्कि उसका उत्पादन में भू-स्वामी, श्रमिक, पूँजीपति, संगठनकर्ता

1—Distribution may, therefore, be described as the descriptive, critical and constructive study of the principles according to which wealth is distributed amongst the different Agents of Production

An Outline of the Principles of Economics—James, Ch. XIII.

तथा साहसी सभी मिलकर समुक्त रूप से काम करते हैं। यह स्वाभाविक है कि जो वस्तु कई मनुष्यों के श्रम एवं योग से बनी हो उसके मूल्य का वितरण करना कठिन हो जाता है। इसलिए वर्तमान आर्थिक समाज में व्याप्योचित वितरण की समस्या हमारे सम्मुख है।

वितरण में संघर्ष (Conflict in Distribution)—आधुनिक समुक्त उत्पादन प्रणाली में प्रत्येक उत्पादन साधन अपने कार्य एवं योग को दूसर से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। भूमिपतिवा (Landlords) का दावा है कि उन्हें उत्पत्ति का बड़ा भाग मिलना चाहिए, क्योंकि वे उत्पादन के लिये प्राकृतिक साधनों को प्रदान करते हैं जिनके बिना उत्पादन सम्भव नहीं है। श्रमिक (Labourers) का दावा है कि उन्हें उत्पादन का अधिक से अधिक भाग मिलना चाहिए, क्योंकि वे कच्चे माल को पक्के माल का रूप देते हैं तथा उत्पादन-प्रणाली के चालक हैं। पूँजीपतिवा (Capitalists) का कहना है कि वे पूँजी देकर बड़ परिमाण के उत्पादन को सम्भव बनाते हैं, अतः वे सबसे बड़े भाग के अधिकारी हैं। प्रबन्धका या संगठनकर्तावा (Organisers) के अनुसार उत्पत्ति की कार्यक्षमता उन्हीं के श्रम पर आधारित है, इसलिये उन्हें उच्चतम पुरस्कार मिलना चाहिये। इसी प्रकार साहसिकवा (Enterprisers of Entrepreneurs) का दावा है कि उत्पादन की सारी जोखिम वे भेसते हैं, अतः उन्हें उत्पादन का बड़ा भाग मिलना चाहिये। इस प्रकार उत्पादन साधनों के स्वार्थी में प्रबल संघर्ष है। इसी कारण वितरण अर्थशास्त्र का सबसे विवाद-युक्त विषय बन गया है।

अर्थशास्त्र में वितरण के अध्ययन का महत्व (Importance of Study of Distribution in Economics)—वितरण अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है और साथ ही-साथ मनोरंजक एवं रोचक भी है। हम सब किसी-न-किसी रूप में धनारति में हाथ बटाते हैं। इसलिये हम न इस बात की जानकारी की उत्कण्ठा होती है कि कुन उत्पत्ति में हमारा नाम कौन निर्धारित होता है।

वितरण प्रणाली का समाज के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक उन्नति और समृद्धि बहुत अंश तक वितरण पर निर्भर है। जितना व्यापपूर्ण और उचित वितरण का आधार होगा उतना ही अधिक वह समाज सुखी और उन्नति-शील होगा। यदि वितरण प्रणाली दूषित है, तो आर्थिक जीवन का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। परन्तु असाध्यवस्तु आज बहुत से देशों में धन वितरण का दंग प्रत्यक्ष हो दूषित है जिसके कारण वहाँ की जनता को अनेक कठिन आर्थिक और सामाजिक सबोटों का सामना करना पड़ रहा है। भारतवर्ष में भी धन का वितरण इसी प्रकार दूषित है। यहाँ राष्ट्रीय आय का एक खिझाई भाग से भी अधिक वैयक्त एवं प्रतिष्ठान लोगों के पास केन्द्रित है जिसके कारण देश में निर्धनता के व्यापक रूप फैल चुके हैं। देश की आर्थिक दशा सुधारन के लिये वर्तमान वितरण प्रणाली को बदल कर उस एक नया रूप देना निम्नतम आवश्यक है। इसलिये अर्थशास्त्र में वितरण विभाग का अध्ययन बहुत महत्व रखता है।

वितरण की समस्या (Problem of Distribution)—वर्तमान समय में वितरण-सम्बन्धी समस्याएँ बहुत गम्भीर एवं जटिल हैं, इसलिये उनका कई भागों में

विभक्त कर उनका अध्ययन करना सुविधानजनक होगा। वितरण की समस्या मुख्यतः निम्नलिखित तीन भागों में बाँटी जा सकती है :—

१. वितरण किस वस्तु का किया जाता है ?
२. वितरण में भाग लेने के कौन अधिकारी होते हैं ?
३. वितरण कैसे होता है और उत्पादन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुरस्कार किस प्रकार निर्धारित होता है ?

१. वितरण किस वस्तु का किया जाता है ? (What is to be distributed ?) — सबसे पहला प्रश्न प्रस्तुत होता है कि वितरण किस वस्तु का किया जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर एक साधारण व्यक्ति की भाँति यों दिया जा सकता है कि उस सम्पत्ति या धन का वितरण किया जाता है जिसका उत्पादन सयुक्त रूप में किया गया है। परन्तु यह उत्तर पूर्णतया ठीक नहीं है, क्योंकि जो सम्पत्ति मिलकर उत्पन्न की जाती है वह सारी की सारी उत्पादन के साधकों में वितरित नहीं की जा सकती। इसका कुछ भाग हमें उस पूँजी की क्षतिपूर्ति के लिये रखना पड़ेगा जिसका कि उत्पादन में उपभोग किया गया है। ऐसी पूँजी चल या अस्थिर पूँजी (Circulating Capital) हो सकती है जिसका अस्तित्व एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाता है, अथवा अचल या स्थिर पूँजी (Fixed Capital) हो सकती है जिसकी क्षति धीरे धीरे होती है। हमें सरकार एवं म्युनिसिपल आदि प्रदत्त-सरकारी सत्ताओं को कर (Taxes) भी देने पड़ते हैं। इन सबके दान के पदचाल जो धन भेष बचता है वही उत्पत्ति के विविध साधनों में वितरित किया जाता है। अधिक स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप में उत्पादित धन निम्नलिखित सत्ता की राशियों में पड़ना के पदचाल वितरण योग्य होता है —

(अ) चल या अस्थिर पूँजी का प्रतिस्थापन (Replacement of Circulating Capital) — उत्पादन किया गया चल पूँजी का उपयोग होता है जिससे उत्पाद अस्तित्व एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाता है। प्रत्येक उत्पादन जारी रखने के लिए उसका प्रतिस्थापन करना उसकी पुनः पूर्ति आवश्यक हो जाती है। उदाहरणार्थ, कपड़ों की मिल में रईय समाप्त हो जाने पर पुनः उसका खरीदा जाना आवश्यक है अथवा मिल बन्द हो जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार वर्गीकरण उद्योग में मशीनों का स्टॉक समाप्त होना ही उनकी पुनः पूर्ति आवश्यक हो जाती है। वस्तु उत्पादित धन में चल सम्पत्ति के प्रतिस्थापन के लिए एक पर्याप्त राशि गठाने की आवश्यक है और जो शेष बचे उसी का हम वितरण कर सकते हैं।

(आ) अचल या स्थिर पूँजी की घिसाई तथा प्रतिस्थापन (Depreciation and Replacement of Fixed Assets) — उत्पादन किया गया अचल या स्थिर पूँजी का प्रयोग होता है— जैसे मशीन, औजार, भवन आदि। यह अचल या स्थिर सम्पत्ति चल या अस्थिर पूँजी की भाँति एक बार के प्रयोग में ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि कई वर्षों तक इसका निरन्तर प्रयोग होता रहता है जिसमें इसके मूल्य में घटती, घटती रहता (Depreciation) होता जाता है और अन्त में बहुत अधिक अवधि के पश्चात् वह बेकार हो जाती है और उसके स्थान में नए मशीन का प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है। इसलिए सयुक्त रूप में उत्पादित धन का वितरण करने के पूर्व उसमें से प्रति वर्ष कुछ राशि निवृत्त कर घिसाई या प्रतिस्थापन कोष

(Depreciation or Replacement Fund) में जमा कर देना चाहिये जिससे समय पर बेकार या पुरानी (Obsolete) मशीन के बदले में नई मशीन के खरीदने के लिये राशि उपलब्ध हो सके। इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिये : यदि एक मशीन का मूल्य १०,००० रु० है और वह १० वर्ष तक काम दे सकती है तो हमें संयुक्त कमाई में से प्रति वर्ष १००० रु० पिछाई या प्रतिस्थापन कोष में डाल देना चाहिये जिससे १० वर्ष परवाना नई मशीन खरीद कर पुरानी या बेकार मशीन के स्थान में प्रतिस्थापित की जा सके।

(इ) कर (Taxes)—व्यवसायों को बहुत से कर सरकार की तथा ग्रह-सरकारी संस्थाओं को देने पड़ते हैं। इसलिये संयुक्त प्रयत्नों द्वारा उदासित धन को वितरण करने के पूर्व 'कर' की राशि को घटा देना चाहिये।

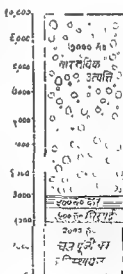
इन्हें प्रतिरिक्त बीमा-उपय (Insurance Charges) आदि भी वितरण के पहले सामूहिक उत्पादित-धन में घटा देना चाहिये।

कुल उत्पत्ति (Gross Product) और वास्तविक उत्पत्ति (Net Product)—उत्पादन के साधनों द्वारा सामूहिक रूप में उत्पादित सम्स्त धन को कुल उत्पत्ति (Gross Product) कहते हैं। कुल उत्पत्ति में बच या स्थिर पूँजी की प्रतिस्थापना, मजदूरी या स्थिर पूँजी की पिछाई एवं प्रतिस्थापना और कर आदि निभावने के बाद जो अवशेष रहता है उसे वास्तविक उत्पत्ति (Net Product) कहते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—मान लीजिये किनी व्यवसाय में किसी वर्ष की कुल उत्पत्ति (Gross Product)

१०,००० रु० की हुई। इसमें से २००० रु० बच या स्थिर पूँजी के प्रतिस्थापन के लिये, ५०० रु० मजदूरी या स्थिर पूँजी की पिछाई एवं प्रतिस्थापना के लिये और ५०० रु० कर आदि के लिये विनाश दिये गये, तो उक्त वर्ष की वास्तविक उत्पत्ति (Net Product) ७००० रु० की हुई। $१०,००० रु० - (२००० रु० + ५०० रु० + ५०० रु०) = ७००० रु०$ ।

राष्ट्रीय आय (National Income) या राष्ट्रीय लाभ (National Dividend)—उपयुक्त उदाहरण में एक व्यक्ति के व्यवसाय की उत्पत्ति बजलाई गई है। इसी प्रकार यदि सारे देश के व्यवसायों की वास्तविक आय निम्नोक्त प्रकार ली जाय, तो उस योग की सम्स्त देश की 'वास्तविक आय' कहेंगे। अन्य शब्दों में, यदि हम किसी देश के सम्स्त उत्पादकों की, किसी दिये हुए समय में, उत्पत्ति की गई वास्तविक उत्पत्ति को जोड़ दें, तो वह जोड़ उक्त देश की राष्ट्रीय आय



(National Income) होगी। यह देश के निवासियों में उत्पत्ति के विभिन्न साधकों के रूप में वितरित की जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय लाभान (National Dividend) भी कहते हैं।

पीगू की परिभाषा—प्रो० पीगू (Pigou) के अनुसार 'राष्ट्रीय आय से प्रतिप्रायः देश को उग आय से है जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित है जोकि मुद्रा द्वारा नापी जा सकती है। प्रो० स्टैम्प ने भी कुछ इसी प्रकार के शब्दों में राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है। इस प्रकार की परिभाषा के अन्तर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य सम्मिलित किया जाता है जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय होता है। यदि कुछ सेवाएँ ऐसी हों जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय न किया जाता हो, तो इस परिभाषा के अनुसार यह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। राष्ट्रीय आय की इस प्रकार से परिभाषा करना कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। इस बात को शायद प्रो० पीगू ने भी माना है। उनका कहना है कि यदि एक मनुष्य किसी गौरवान् की अपना भोजन बनाने के लिए रसता है और उसको ५० ६० मासिक पतन देता है, तो उसका वेतन राष्ट्रीय आय का अंग बन जायगा। परन्तु कुछ समय पश्चात् यदि वह व्यक्ति उग गौरवान् से अपना विवाह कर ले और विवाह का पश्चात् भी वह स्त्री उसके सिधे पहल के समान ही कार्य करती रहे, तो उसकी सेवा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित न की जायेगी, क्योंकि उसको अब कुछ देना न पड़ेगा। इस प्रकार यदि सत्य व्यक्ति अपनी गौरवान् को विवाह कर ल, तो राष्ट्रीय आय बहुत कम हो जायेगी। देखने में तो यह बात बड़ी विचित्र-सी लगती है, परन्तु राष्ट्रीय आय की इसी परिभाषा को सब लोग मानते हैं।

माशेल और फिशर की परिभाषाएँ—प्रो० माशेल के शब्दों में, 'किसी देश का धन और पूँजी, उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक तथा अर्थव्यवस्था की वस्तुओं का, जिनमें सब प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं, एक निश्चित योग (Net Aggregate) उत्पन्न करते हैं। देश की यही सच्ची वास्तविक आय या राष्ट्रीय लाभान है। वास्तविक आय मापन करने के लिए कुछ प्रायः मूल्य विस्तारण या विकास देना चाहिए। दूसरी ओर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वह मूल्य है जो उत्पन्न होने का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष रूप में उस वर्ष में उपयोग होता है। उदाहरण द्वारा देना परिभाषाओं का अंतर इस प्रकार समझाया जा सकता है मान लीजिए वर्ष भर में एक मशीन तैयार की गई है। माशेल के अनुसार मशीन के कुल मूल्य में उसको बनाने वाली मशीन को विस्तारण की घटाकर या घटाने से उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए। परन्तु फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत मशीन का मूल्य नहीं बल्कि केवल मशीन का वह भाग जिसका वास्तव में उस वर्ष में उपयोग किया जाय उस राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना

1 - 'The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true annual income or revenue of the country or national dividend'

Marshall Principles of Economics 1930, P 523

चाहिए। यदि देखा जाय तो फिसर की परिमाणा अधिक तर्क-संगत है परन्तु हमके स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण है कि वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली वस्तुया तथा सेवाओं की सूची बनाना तो सरल है, परन्तु वर्ष में उपभोग की गई वस्तुओं की सूची बनाना बड़ा कठिन है। यही कारण है कि मार्शल की परिभाषा में अज्ञानित दृष्टिकोण में कुछ दोष होने हुए भी प्रा० मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक दृष्टि में अधिक उपयुक्त मानी जाती है।

राष्ट्रीय आय का नापने के बटन—राष्ट्रीय आय नीव प्रकार में नापा जा सकती है—

(१) उत्पत्ति की गणना (Census of Production)—इसके अनुसार कुल उत्पत्ति का मूल्य जोड़ करके उसमें से घिमावट की राशि घटा दी जाय।

(२) मूल्य व्यक्तियों की आय का योग करना—इसमें सभी व्यक्तियों की आय जोड़ दी जाती है फारे वह आय-कर (Income-Tax) देने हों या नहीं।

(३) पेशेवर गणना (Occupational Census)—इस बटन के अनुसार देश में जितने पेशे हों उनकी गणना कर ली जाय जिससे उनके काम करने वालों की आय का पता चल सके। इस प्रकार के योग से जो गणना प्रायेण वह राष्ट्रीय आय के बराबर होगी।

राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने समय आन्तरिक अनुत्पादक ऋण (Internal Unproductive Debt), धन की आय, बुढ़ाई-वृद्धा की पेंशन तथा धोखेबाजी से प्राप्त की गई आय की गहरी जोड़ना चाहिये। राष्ट्रीय आय या लाभार्थ वह राशि है जो निरन्तर एकाग्रित होती रहती है तथा व्यय होती रहती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय लाभार्थ वहो हुए जलाशय को भानि है जो भूमि, धन, पूँजी, सगठन और साहम द्वारा निरन्तर भराया रहता है और गणान, मजदूरी, श्रमज, वेतन और लाभ के रूप में निरन्तर पाली होता रहता है तथा इसका एक भाग पूँजी की प्रतिस्थापना, घिसाई और बरा के रूप में निबन्ध जाता है।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय या लाभार्थ उत्पत्ति के माधनों की सेवाओं का पत्र है और साथ ही माय वह इन व्यक्तियों के परिश्रमों का बोध भी है।^२ परन्तु इसका यह प्रर्थ नहीं है कि वर्ष भर राष्ट्रीय आय को जमा किया जाता है और उसमें शत्र उसका वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय आय का उत्पादन और उसका वितरण माय-माय चलता रहता है। यह जलपाया के समान है जिसमें एक क्षर में जल भरता रहता है और दूसरे और से खानी होता रहता है।^३ इस निम्नांकित बिन्द में और भी स्पष्ट हो जाता है :

१—"National dividend is a stream, out of which all the factors of production are paid"

२—"The national dividend is at once the aggregate net product of, and the sole source of payment for all the agents of production"

३—Crew : Economics for Commercial Students, p 81.



राष्ट्रीय लाभांश का उद्गम तथा वितरण

(Origin & Distribution of National Dividend)

२. वितरण में भाग लेने के कौन अधिकारी हैं ? (Who are entitled to Share ?)—अब हमें प्रश्न यह है कि वितरण में भाग लेने के कौन अधिकारी हैं, अर्थात् राष्ट्रीय आय का वितरण किनके बीच होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सरलता में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय या लाभों उन्हीं व्यक्तियों के मध्य बाँटा जा सकता है जिन्होंने उसके उत्पादन में सहयोग दिया है। धनोत्पादन के प्रत्येक कार्य में भूमि, धन, पूँजी, समय और ग्राहक का सहभाग होता है सभी वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है और राष्ट्रीय आय या लाभों प्राप्त हो सकता है। अतः राष्ट्रीय लाभांश इन्हीं पाँचों साधनों के स्वामियों में वितरित किया जाता है। इन साधनों के प्रतिफल को मिल मिल नामों से पुकारा जाता है। भूमि प्रदान करने वाले के भाग में जो जाता है उसे जमान (Rent) कहते हैं। धन की सेवाओं के उपलक्ष में जो कुछ दिया जाता है वह मजदूरी या भृति (Wages) कहो जाती है। पूँजी के प्रतिकूल स्वल्प या पूँजीपतियों का प्राप्त होता है वह व्याज (Interest) कहलाता है। समस्तानर्त्ता या प्रकल्पन का प्रतिफल वेतन (Salary) कहलाता है और साहसो अपनी जोरिम के प्रतिफल स्वच्छ लाभ (Profit) का यजमान होता है।

३. वितरण की रीति (Method of Distribution)—इसके अन्तर्गत हम दो बातों का विचार करते हैं—(क) वितरण कैसे होता है ? (ख) उत्पादन के प्रत्येक साधन का भाग कैसे निर्धारित होता है ?

(ग्र) वितरण कैसे होता है ?—वितरण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय पर पुराने और नये भ्रमशास्त्रियों के दृष्टिकोण में बड़ा भिन्नता है ? पुराने भ्रमशास्त्री एडम स्मिथ (Adam Smith) ने लिखा है कि “कुल उत्पत्ति देश के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक रूप से वितरित हो जाती है।”¹ जान स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) ने यह बताया कि “यह उत्पत्ति स्वाभाविक बिया के द्वारा अपने प्राप वितरित हो जाती है।”² ये कथन सर्वथा अस्पष्ट हैं और वितरण की वास्तविक कार्य प्रणाली पर कोई प्रकाश नहीं डालते।

प्राधुनिक भ्रमशास्त्रियों का दृष्टिकोण हमारे विमुख भिन्न है। उनके अनुसार प्राधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था में साहसी (Enterpriser) वितरणकर्ता (Distributor) का कार्य करना है। उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व वह इन बातों का हिमाज लगाता है कि उसकी कितनी उत्पत्ति किस मूल्य पर बिक सकेगी; इसमें उसे कुल उत्पत्ति (Gross Produce) की भाव का अनुमान हो जाता है। कुल उत्पत्ति की राशि में से पूँजी के प्रतिस्थापन पिगार्ड और करों की राशि निकास कर वह वास्तविक उत्पत्ति (Net Produce) की भाव का अनुमान लगा लेता है। इसके पश्चात् वह उत्पादन के विविध साधनों की सहायता के पुरस्कार को निश्चित करता है। भूमि के उपयोग के लिए भूस्वामियों से, श्रम के लिए श्रमिकों से, पूँजी के लिए पूँजीपतियों से तथा साधन के लिए साधनवर्तों या प्रबन्धक से वान-बोत करना है। वह प्रत्येक उत्पत्ति के साधक का पुरस्कार निश्चय करने समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसे जोखिम भेदने के उपलब्ध में पर्याप्त पुरस्कार बच रहे। इस अनुमान के आधार पर वह उत्पादन प्रारम्भ करता है। जैसे जैसे माल तैयार होता जाता है वैसे वैसे ही बिकता जाता है। समय समय पर ध्यान, भाग, मजदूरी और वेतन चुकाए जाते हैं। नये व अन्त में वास्तविक उत्पत्ति में से ध्यान, भाग, मजदूरी और वेतन चुकाने के पश्चात् भी भाग बचता है वह साहसी का उत्तम पुरस्कार के उपलब्ध में मिल जाता है। यदि वास्तविक उत्पत्ति की भाव इन व्ययों के भुगतान से कम हुई, तो साहसी को हानि उठानी पड़ती है।

(घा) उत्पादन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति (साधक) का पुरस्कार किस प्रकार निर्धारित होता है ?—इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें उत्पादन के प्रत्येक साधक को एक वस्तु की भांति समझना चाहिए। जिस प्रकार बाजार में किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति की वारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति के प्रत्येक साधक का पुरस्कार भी निर्धारित होता है। साहसी जो वितरणकर्ता होता है साधारण वस्तु के खय की भांति उत्पत्ति के साधक की सेवाएँ सरोदता है। वस्तु जिस प्रकार साधारण वस्तु का होता जो अधिकतम मूल्य दे सकता है, वह उस वस्तु का सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) पर निर्भर होता है और उसी प्रकार साहसी उत्पत्ति के साधक

1—“Total Produce is naturally distributed among the different ranks of people”

2—“This produce distributes itself by spontaneous action”

मे उसकी सेवा का उपयोग तब करते समय जो वह उसका अधिकतम मूल्य दे सकता है वह उसकी सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) पर निर्भर होता है। इसलिये उत्पत्ति के साधन की सीमान्त उत्पादकता साहसी द्वारा दिये जाने वाले मूल्य की अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निर्धारित करती है। इसी प्रकार उत्पादन के साधन के स्वामी अपने-अपने साधन द्वारा प्रस्तुत सेवा का विनियम करते हैं और उनकी स्थिति आधारण वस्तु के विनिमय के समान होती है। अतः उत्पत्ति के साधक जो न्यूनतम मूल्य अपने साधन की सेवा के बदले में ले सकते हैं वह उनकी लागत (Expenses of Production) पर निर्भर होता है। इसलिये उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के स्वामी की लागत प्रत्येक साधक द्वारा दिये जाने वाले मूल्य की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निर्धारित करती है। वस्तु इसी दोनो सीमाओं के मध्य से माँग और पूर्ति की सापेक्षिक अवस्थानता और दोनो पक्षा का सोदा करने तथा भाव ताव करने की कुशलता द्वारा मूल्य एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। यहाँ केवल उत्पत्ति के साधकों के पुरस्कार के निर्धारण के साधारण सिद्धान्त का ही विवेचन किया गया है। जबलें घट्यालों में उत्पादन के प्रत्येक साधक का पुरस्कार वैसे निर्धारित होता है, इसकी विस्तृत विवेचना यथास्थान पर की जायेगी।

वितरण की समस्याएँ केवल विनिमय की समस्या की विशिष्ट दशाएँ हैं।^१ हम वचन की उत्पत्ति प्रकट करते हुए यो कहा जा सकता है कि वितरण और विनिमय दोनों की समस्याएँ समान हैं; वितरण की समस्याएँ विनिमय की समस्या का केवल विशिष्ट रूप मात्र हैं। (१) जिस प्रकार विनिमय में हम विनिमय सम्बन्धी अनेक समस्याओं का अध्ययन करते हैं—जैसे वस्तुओं का विनिमय क्या होता है, वस्तुएँ किस दर और रीति से विनिमय की जाती हैं, आदि। यदि हम वितरण की ओर भी दृष्टि डालें, तो वही बात पावेंगे। इसमें वस्तुओं के विनिमय के स्थान में विविध उत्पत्ति के साधकों की सेवाओं का विनिमय होता है। (२) जिस प्रकार विनिमय में मुद्रा के बदले में वस्तुओं के लेना उपस्थित होने है, उसी प्रकार वितरण में साहसी उत्पत्ति के विविध साधकों की सेवाओं को मुद्रा के बदले में खरीदने के लिये अपने धन को प्रस्तुत करता है। (३) जिस प्रकार विनिमय में वस्तुओं के विनिमय अपनी वस्तुएँ मुद्रा के बदले में लेना के लिये प्रस्तुत करत हैं, ठीक उसी प्रकार वितरण में मन्त्रियों, धर्मिक, पूँजीपति तथा सँगठनकर्ता या प्रबन्धक अपनी-अपनी सेवाएँ मुद्रा के रूप में पुरस्कार पाने के लिये वचने की प्रस्तुत करत हैं। (४) जिस प्रकार विनिमय में किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया (Interaction) द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति के प्रत्येक साधक की सेवा का पुरस्कार भी उसकी माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। (५) विनिमय में वस्तुओं व लेताओं की एक अधिकतम सीमा होती है जो वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता द्वारा स्थिर होती है और जिसमें अधिक के उनका मूल्य देने के लिये तैयार नहीं होते हैं, इसी प्रकार वितरण में साहसी का भी अधिकतम सीमा होती है जो प्रत्येक उत्पत्ति के साधक की सीमान्त उत्पादकता द्वारा स्थिर

1—The problems of distribution are only special cases of the problem of exchange.”

की जाती है और उससे अधिक वह उसका पुरस्कार देने को तैयार नहीं होता है। (९) विनिमय में वस्तु विक्रेता की एक न्यूनतम सीमा होती है जो उसके उत्पादन-व्यय (लागत) द्वारा निश्चित होती है और वह इससे कम मूल्य स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार वितरण में प्रत्येक साधक की लागत के अनुसार उसकी सेवा का न्यूनतम पुरस्कार निश्चित होता है जिसमें कम वह अपने पुरस्कार की राशि स्वीकार नहीं करता है। (७) जिस प्रकार विनिमय में वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी माँग और पूर्ति के संतुलन द्वारा होता है उसी प्रकार वितरण में भी उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की सेवाओं का मूल्य (पुरस्कार) उनकी माँग और पूर्ति के संतुलन से निर्धारित होता है। इस प्रकार विनिमय और वितरण की समस्याएँ बहुत कुछ समान हैं। (८) जिस प्रकार जाधारण वस्तु के मूल्य तब होने में उपभोक्ता और विक्रेता के मध्य सीढ़े एवं भाव नाथ (Eggshells and Bargaining) की निरन्तर बातचीत चलती रहती है, उसी प्रकार साहसी और उत्पत्ति के साधकों के बीच भी ऐसा होता रहता है।

बोनों की समस्याओं में भेद —(१) विनिमय में समस्त वस्तुएँ निर्जीव होती हैं जबकि वितरण में धन आदि वस्तुएँ जीवधारी धमिक वा ही भग होती हैं। इस प्रकार वितरण की समस्या के विवेचन में मानवीय तत्व (Human Element) का अधिक महत्व है। परन्तु विनिमय की समस्या में इस प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता है। (२) विनिमय के प्रत्यक्ष वस्तुओं के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाता है जबकि वितरण में उत्पत्ति के विविध साधनों पर पुरस्कार सम्बन्धी विषयों पर विचार किया जाता है। (३) उत्पत्ति के साधनों का मापन व्यय मात करना इतना सुगम नहीं है जितना कि वस्तुओं के उत्पादन-व्यय का है। (४) विनिमय में वस्तुओं की पूर्ति (Supply) में ग्युताधिकता सुगमता से हो सकती है, परन्तु उत्पत्ति के साधनों की घटा-बढ़ी या तो सम्भव ही नहीं होती और यदि होती है तो धीरे-धीरे होती है। उदाहरणार्थ भूमि का उपलब्ध-क्षेत्र सीमित होता है, इसमें न्यूनताधिकता नहीं है। इसी प्रकार धन आदि अन्य साधकों की पूर्ति में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है।

ग्रन्थासार्थ प्रश्न

इण्टर माड्स परीक्षाएँ

- १—वितरण की समस्या क्या है ? किसका वितरण होता है और किन सिद्धान्तों के अनुसार होता है ? (नागपुर १९५१)
- २—राष्ट्रीय साम्राज और वास्तविक उत्पत्ति (Net Product) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- ३—'वितरण की समस्याएँ विनिमय की समस्या की विशिष्ट दशाएँ हैं।' इस कथन पर विचार कीजिये। (म० बो० १९५६)
- ४—राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिये और बताइय कि वह किस प्रकार उत्पन्न होती है और वितरित होती है ? (पटना १९५०)
- ५—साप 'वितरण' के घटकगत क्या करते हैं ? राष्ट्रीय साम्राज की महत्ता स्पष्ट कीजिये और वितरण के 'सीमांत उत्पत्ति सिद्धान्त' (Marginal Product Theory) पर टिप्पणी लिखिये। (रा० बो० १९५६)

६—कुल और वाम्बविक उत्पत्ति पर टिप्पणी लिखिये ।

(अ० वो० १९५० ; म० भा० १९५४)

७—वितरण की मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? प्रत्येक की व्याख्या कीजिये ।

(म० भा० १९५४)

८—राष्ट्रीय लाभदा से क्या तात्पर्य है ? यह किन में बाँटा जाता है ? वितरण का सिद्धान्त क्या है ?

(सामर १९५१)

९—वितरण का अर्थ समझाइये और इसकी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिये ।

(दिल्ली हा० से० १९५०)

१०—‘राष्ट्रीय आय’ का उत्पत्ति के विभिन्न साधन में वितरण किस प्रकार होता है ?

११—निम्नलिखित पर नोट लिखिये —

(बिहार १९५७)

राष्ट्रीय लाभदा

(पञ्जाब १९५३, ४८)

समुक्त उत्पत्ति

(बिहार १९५४)

१२—‘वितरण’ की समस्याओं का विवेचन संक्षेप में कीजिये और समझाइये कि वितरण किस प्रकार होता है ?

(अ० वो० १९५९)

इष्टर एग्रीकल्चर परीक्षा

१३—वितरण में आप क्या अध्ययन करते हैं ? वितरण किस्का होता है और किस किस प्रकार होता है ?

(अ० वो० १९५७)

लगान शब्द का अर्थ (Meaning)—जिस प्रकार किसी वस्तु के प्रयोग के लिये कुछ धन-राशि देने को किराया कहते हैं उसी प्रकार भूमि के प्रयोग के लिये धन-राशि देने को लगान कहते हैं। उदाहरणार्थ मकान, मशीन, मोटर, वाईसिकल आदि अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रयोग के लिये धन राशि देने को किराया या भाड़ा कहते हैं। इसी प्रकार एक भूस्वामी या जमींदार कुछ वर्षों के लिए एक निश्चित राशि के बदले में अपनी भूमि किसी किसान को खेती करने के लिये दे देता है, तो इस निश्चित राशि को भूमि का लगान कहते हैं। साधारण भाग में किराया, भाड़ा और लगान ये शब्द प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं।

किराये शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। इसमें मकान बनाने में लगी हुई पूँजी का ब्याज, मकान को घिसाई, मरम्मत देना आदि तथा बीमा आदि का व्यय भी सम्मिलित होता है। इसी प्रकार एक कृषक जो लगान देता है वह केवल भूमि के प्रयोग के लिये ही नहीं देता है बल्कि वह भूमि पर बने हुए गुर्ग, गऊँ तथा अन्य प्रकार की जनति के लिये भी देता है। इस लगान को कुल लगान (Gross Rent) कहते हैं। परन्तु जो लगान केवल भूमि के प्रयोग के लिये ही दिया जाता है उसे वास्तविक या शुद्ध लगान (Net Rent) कहते हैं। यही वास्तविक या शुद्ध लगान आर्थिक लगान (Economic Rent) कहलाता है।

लगान का अर्थशान्त्रोय अर्थ—अर्थशास्त्र में लगान का अर्थ सीमित है। भूमि प्रयुक्त प्रकृति-दत्त अन्य वस्तुओं के प्रयोग से होने वाली आय को लगान कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि लगान किसी को दिया जावे। यदि भूमिपति स्वयं अपनी भूमि का उपयोग करता है, तो वह भी लगान प्राप्त करता है। अन्तर्धनोत्पादन में भूमि के उपयोग के लिये जो पुरस्कार दिया जाता है, उसे आर्थिक लगान कहते हैं। प्रो० मार्शल के शब्दा में भूमि तथा अन्य प्रकृति-दत्त साधनों के स्वामित्व से प्राप्त आय को साधारणतया लगान कहते हैं।¹ प्रो० टॉमस के अनुसार साहसी द्वारा भूमि के उपयोग के लिये दिये जाने वाले पुरस्कार

1—"The income derived from the ownership of land and other free gifts of nature is commonly called Rent "

Marshall • Economics of Industry, p 52

के भुगतान को लगान कहते हैं।¹ प्रो० कारवार ने कहा है कि किसी भूमि के टुकड़े का लगान उतना ही होगा जितना उस भूमि के टुकड़े की उपज अन्य न्यूनतम उपजाऊ खेत की उपज से अधिक होगी।² वास्तव में, लगान भूमि की उपज याति में अन्तर होने के कारण उत्पन्न होता है। जो लगान रूपक भूमिपति (जमींदार) को देता है उसमें वास्तविक या शुद्ध लगान के अतिरिक्त भूमिपति को सगे हुई पूँजी का ध्यान तथा सञ्चालन व्यय करने का पारिधमिक भी सम्मिलित रहता है। अस्तु, कुल लगान और वास्तविक या शुद्ध लगान में भिन्नता करने के द्विमे वास्तविक या शुद्ध लगान को अर्थशास्त्र में आर्थिक लगान (Economic Rent) कहते हैं।

भूमि की विशेषताएँ (Peuliarities of Land)—लगान की उत्पत्ति और भूमि की विशेषताओं का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः भूमि के लगान व कारणों का अध्ययन करने के पूर्व भूमि की कुछ विशेषताओं की जाँच लेना भी आवश्यक है।

१. भूमि प्रकृति-दत्त प्रसाद है (Land is a free-gift of Nature) भूमि प्रकृति दत्त वस्तु है, मनुष्य ने इस बनाने में कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः इसका मूल्य नहीं होता या अशून्य। परन्तु जन संख्या के बढ़ने और भूमि सीमित होने के कारण इसकी माँग इतनी अधिक हो गई कि भूमिपति अपनी भूमि के उपयोग का मूल्य अर्थात् लगान लेने लग गये हैं।

२. भूमि का सीमित मात्रा में होना—(Land is limited in quantity)—भूमि प्रकृति-दत्त होने के अतिरिक्त सीमित मात्रा में है। मनुष्य अपने प्रयत्न से इसकी माँग बढ़ाने पर अन्य साधनों की भाँति इसे बढ़ा नहीं सकता। जितनी ईरवर न क्षेत्र है उन्ही से काम चलाया होगा।

३. भूमि स्थिति में स्थिर है (Land is fixed in situation)—भूमि स्थिति की दृष्टि से स्थिर है। भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना सम्भव नहीं है। यदि जंगल की भूमि शहर के समीप साईं जा तब तो उसका मूल्य बढ़ जायगा, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है।

४. भूमि उपजाऊपन और स्थिति में भिन्नता रखती है (Land differs in fertility and situation)—कोई भूमि कम उपजाऊ और कोई भूमि अधिक। इसका परिणाम यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि पर बराबर व्यय करने से उपज कम या अधिक होती है।

५. भूमि की उपज में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। (Production from land is Subject to the Law of Diminishing Returns)—भूमि पर अतिरिक्त व्यय और पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने से अन्त

1—Thomas · Elements of Economics 243

2—"The rent of any given piece of land is what it will produce over and above what could be produced on the poorest land in cultivation by the same amount of labour and capital" —Carver

में उत्पत्ति की एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि जिसके परिचाय सभी हुई पूँजी और धन के अनुपात में उत्पत्ति कम होती जाती है। इससे वस्तु की मागत बढ़ जाती है।

रिकाडों का लगान-सिद्धान्त (Ricardian Theory of Rent)

परिचय (Introduction)—लगान-सिद्धान्त से रिकाडों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। डेविड रिकाडों (David Ricardo) एक प्रतिष्ठित (Classical) अग्रज अर्थशास्त्री ही चुके हैं, जिन्होंने सबसे प्रथम १८ वीं शताब्दी के अन्त में लगान सिद्धान्त वैज्ञानिक ढंग में प्रस्तुत किया था। अतः यह सिद्धान्त अथ नक उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। यह आधुनिक लगान-सिद्धान्त का आधार माना जाता है क्योंकि मार्शल आदि अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसमें ही कुछ हेर-फेर कर पुनः प्रतिपादित कर दिया है।

रिकाडों के लगान-सिद्धान्त की परिभाषा—रिकाडों ने लगान की परिभाषा इस प्रकार की है : लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति की भूमि की मूलिक और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिये दिया जाता है।^१

रिकाडों के लगान-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण—संगर की सभी भूमि यदि एक ही उपजाऊ होती तो क्याचित लगान का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु भिन्न-भिन्न भूमियों की उर्वरा (उपजाऊ) शक्ति असमान है। कोई भूमि अधिक उपजाऊ है और कोई कम। अतः यह स्वाभाविक ही है कि जो भूमि अधिक उपजाऊ है उस पर धन और पूँजी लगाने से जितनी उपज प्राप्त होती है उतनी समान धन और पूँजी लगाने पर भी कम उपजाऊ वाली भूमि से प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार अधिक उपजाऊ भूमि को कम उपजाऊ भूमि पर एक भिन्नक लाभ (Differential Advantage) प्राप्त होती है जो अधिक लगान सह्यता है। रिकाडों का सिद्धान्त इसी तथ्य पर आधारित है।

लगान का सिद्धान्त और विस्तृत खेती

(Theory of Rent & Extensive Cultivation)

उदाहरण—रिकाडों अपने लगान के सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा समझाता है। वह कहता है कि यदि एक नये खोजे हुए देश पर कुछ लोग जाकर बसें, तो सबसे पहले वे उन खेतों को खेतों जो अ धरणी के अर्थात् सबसे अधिक उपजाऊ होंगे। आरम्भ में इस प्रकार के खेतों में खेत खेते जायेंगे। परन्तु जन-संख्या के बढ़ने पर इसी प्रकार के अन्य खेत खेते जायेंगे। इस प्रकार अ धरणी के सब खेत समाप्त हों जायेंगे। देश गया है और भूमि अधिक पड़ी है, इतलिये कोई भी खेत अपनी इच्छा-नुसार जोड़ा जा सकता है। नये लगान देने की आवश्यकता न होगी। जब तक अ

1—"Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil."

धरणी के खेत जोते जायें तब तक सघन वा प्रसन्न ही नहीं उठता। जन संख्या के बढ़ने तथा सभ्यता के विकास होने पर जब खाद्य साधनों की माँग बढ़ती तब खेत जोतने वालों की व अथवा के अर्थान् पहले से कम उपजाऊ खेत जोतने पड़ते। वे बाँहे अथवा के खेतों पर गहरी खेती (Intensive Cultivation) कर सकते हैं अथवा उभी पूँजी व धन से व अथवा के खेतों पर खेती कर सकते हैं। दोनों दृष्टियों में परिणाम एक ही रहेगा। मान लीजिये वे व अथवा के खेतों को जोतते हैं तो उभी पूँजी व धन से इन पर व अथवा के खेतों की अपेक्षा कम उपज मिलेगी। अब शब्दों में, व अथवा के खेतों का उत्पादन-व्यय व अथवा के खेतों के उत्पादन व्यय से अधिक होगा। इस प्रकार व अथवा के खेतों को व अथवा की अपेक्षा एक भिन्नक लाभ (Differential Advantage) मिलेगा जिसको रिकार्डों में आर्थिक लगान (Economic Rent) कह कर पुकारा है। उदाहरणार्थ यदि व अथवा के खेत पर पूँजी और धन की एक निश्चित मात्रा लगाने पर ४० मन गेहूँ प्राप्त होता और व अथवा के खेत पर उभी पूँजी और धन से ३५ मन गेहूँ प्राप्त होता है तो ५ मन (४०-३५) व अथवा के खेत का आर्थिक लगान हुआ।

यदि जन संख्या और अधिक बढ़ती है और उसके साथ-साथ खाद्यान्न की माँग भी बढ़ती है तो व अथवा के खेतों के संपादन होने पर व अथवा के खेत जोते जाते रहेंगे। इन खेतों पर यदि व और व अथवा के खेतों के बराबर धन व पूँजी लगाई जाए तो इन दोनों प्रकार के खेतों से कम उपज प्राप्त होगी। मान लीजिये इस पर केवल २५ मन खाद्यान्न मिलता है जिसका मुख्य केवल उत्पादन व्यय के बराबर ही है। यह बात स्पष्ट है कि जब तक बाजार में २५ मन अन्न का मुख्य सगाई हुई पूँजी और धन के बराबर न मिलेगा तब तक ये खेत नहीं जोते जायेंगे। खेती जारी रखने के लिये कम से-कम उपज के रूप में उत्पादन व्यय तो अवश्य ही मिल जाना चाहिये। अस्तु व अथवा के खेतों को जोतने पर व अथवा के खेतों पर १५ मन (४०-२५) और व अथवा के खेतों पर १० मन (३५-२५) लगान प्रायेगा। व अथवा के खेतों पर कोई लगान न होगा। इसलिये इन प्रकार के खेत को लगान रहित (No rent) या मार्जिनल भूमि (Marginal Land) कहा जायेगा। जन संख्या के और अधिक बढ़ जाने पर व अथवा के खेत (व अथवा से कम उपजाऊ) जोते जायेंगे। इन खेतों पर पूँजी और धन की पुनर्बन्ध मात्रा लगाने से केवल १० मन ही अन्न मिलता है जिसका मुख्य इसके उत्पादन व्यय के बराबर है। अब व अथवा के खेतों को जोतने से अब व अथवा के खेतों पर लगान निम्न प्रकार होगा —

अ पर ३० मन = (४०-१०)

ब पर २५ मन = (३५-१०)

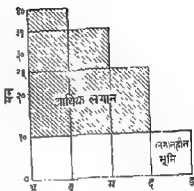
स पर १५ मन = (२५-१०)

द पर कुछ नहीं = (१०-१०)

मत यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्जिनल या लगानहीन भूमि कोई निश्चित नहीं है बल्कि परिवर्तित होती रहती है।

यह नीचे के चित्र से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुत चित्र में अब व अथवा प्रथम अथवा की भूमि है व सब अथवा द्वितीय अथवा की भूमि है

सदस्य अर्थात् तृतीय श्रेणी की ओर दृष्टि अर्थात् चतुर्थ श्रेणी की भूमि है। पूँजी और श्रम की समान मात्रा का उपयोग करने में जो उपज मिलती है वह चित्र में आयतों द्वारा प्रकट की गई है। दृष्टि को जो दृष्टि अर्थात् रो अर्थात् यई है, लगानहीन (No rent) भूमि है, अर्थात् यह कोई लगान नहीं देती। अन्य सब श्रेणियों की भूमि आर्थिक लगान देती है जो उनके क्रमशः आयातों में रेखांकित भागों में दिखाया गया है।



विभिन्न श्रेणी के भू-भाग—आर्थिक लगान

लगान का सिद्धान्त और गहरी खेती

(Theory of Rent and Intensive Cultivation)

अभी तक रिकार्डों का लगान-मिदाल विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) के सम्बन्ध में समझाया गया है। अब यहाँ पर यह बतलाया जायगा कि किस प्रकार यह लगान सिद्धान्त गहरी खेती की समस्या में लागू होता है। यहाँ पर यह सिद्धान्त इसलिये लागू होता है क्योंकि भूमि पर उत्पत्ति द्वारा नियम लागू होता है। गहरी खेती की समस्या में खेती एक ही भूमि के टुकड़े पर अधिकधिक श्रम और पूँजी की मात्रा से की जाती है। ज्यों-ज्यों श्रम और पूँजी की मात्रा (Dose) में वृद्धि की जाती है, त्यो-त्यो श्रम और पूँजी की प्रत्येक अणु की मात्रा से होने वाली उपज क्रमशः घटती जाती है और अन्त में एक ऐसी अवस्था आती है जबकि अन्तिम मात्रा की लागत उस उपज के मूल्य के बराबर होती है जो इस मात्रा द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसी मात्रा लगानहीन (No rent) या सीमान्त मात्रा (Marginal Dose) कहलाती है। लगानहीन या सीमान्त मात्रा श्रम और पूँजी की वह मात्रा है जिसकी उत्पत्ति का मूल्य उसकी लागत के समान होता है। श्रम और पूँजी की प्रत्येक प्रारम्भिक मात्रा के द्वारा जो उपज मिलती है वह सीमान्त अर्थात् अन्तिम मात्रा की उपज में अधिक होने के कारण उसमें उपज की वृद्धि (Surplus) सम्भव हो जाती है। अतः प्रत्येक मात्रा की उपज और सीमान्त मात्रा की उपज के अन्तर को प्रत्येक दशा में उसका आर्थिक लगान कहेंगे।

उदाहरण—ऊपर विस्तृत खेती के सम्बन्ध में दिये हुए चित्र से ही गहरी खेती में लागू होने वाले लगान के सिद्धान्त को अन्ती प्रकार समझा जा सकता है। गहरी खेती की समस्या में एक ही भूमि पर अधिकधिक श्रम और पूँजी की मात्रा स बार-बार देती की जाती है। मान लीजिये पहली मात्रा के प्रयोग से ४० मन अन्न उत्पन्न होता है। यदि उसी खेत पर दूसरी मात्रा का प्रयोग और किया जाय, तो उसकी उपज ३५ मन होती है। इसी प्रकार तीसरी मात्रा की उपज ३० मन तथा चौथी

अथान् प्रतिम मात्रा को उपज १० मन होती है। पहली मात्रा का मार्गिक लगान ३० मन = $(४० - १०)$, दूसरी मात्रा का २५ मन = $(३५ - १०)$, तीसरी का १५ = $(२५ - १०)$, और चौथी मात्रा का मूल्य = $(१० - १०)$ लगान है। अतः यह स्पष्ट है कि चौथी मात्रा लगानहीन माना है।

रिकाडों के लगान सिद्धान्त के निष्कर्ष—(१) रिकाडों के लगान-सिद्धान्त का आधार सीमान्त या लगानहीन भूमि है। सीमान्त भूमि (Marginal Land) वह भूमि है जिसकी लागत और उपज का मूल्य बराबर है और जो उत्पत्ति की सीमा पर है, अर्थात् उत्पादन का ऐसी अवस्था में यह साबित पड़ता है कि उस पर खेती की जाय या नही। इस भूमि पर कृषक को कोई दबत नहीं होती, अतः इसमें लगान भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण इस लगानहीन भूमि भी कहते हैं।

(२) बाजार में वस्तु का मूल्य भी सीमान्त भूमि के लागत-व्यय के बराबर होता है। इसीलिए उस पर कृषि सम्भव होती है।

(३) सीमान्त भूमि के अनुसार ही लगान निर्धारित होता है। इसके आधार पर ही अति-सीमान्त (Super-marginal) भूमि का लगान मँका जाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण एवं चित्र में छ व स भूमियों का लगान मँका गया है।

(४) सीमान्त भूमि की अवस्था स्थिर (Fixed) नहीं है। खेती की वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन के साथ ही सीमान्त भूमि भी बदलती रहती है। उपज का बाजार मूल्य बढ़ जाने पर जो भूमि अब तक सीमान्त थी वह अति-सीमान्त हो जाती है और अब सीमान्त (Sub-marginal) भूमि सीमान्त (Marginal) हो जाती है। इसके विपरीत, यदि उपज का मूल्य गिर जाय, तो सीमान्त भूमि की खेती स्थगित हो जायगी और जो भूमि अब तक अति-सीमान्त थी वह अब सीमांत हो जायगी।

(५) भूमि में उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होता है, इसलिये निम्न श्रेणियाँ की भूमि पर खेती करती पड़ती है। अन्यथा एक ही भूमि को उपज में आगे सवार की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

(६) लगान उस लोभा की उत्पत्ति के अनुसार निर्धारित होता है जो सबसे अधिक प्रतिफल परिस्थितियों में खेती करते हैं। लगान के कारण भूदान का भाव तब नहीं होता, बल्कि भूदान का भाव तेज होने के कारण लगान दिया जाता है।

(७) गहरी खेती में सीमान्त भूमि के स्थान पर थम और पूँजा की सीमान्त मात्रा (Marginal Dose) होती है। सीमान्त मात्रा थम व पूँजा की वह मात्रा है जिसकी उत्पत्ति में लागत और मूल्य बराबर होते हैं। अन्य शब्दों में,

जितनी लागान से किसान का बेवम गुजर हो सके, उसे सीमान्त मात्रा कहते हैं। गहरी सेती की उपज का मूल्य दूग सीमान्त मात्रा की लागत से निश्चित होता है।

(८) रिकार्डों ने पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता (Perfect and Free Competition) मान कर ही अपना लगान का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। यह प्रतियोगिता भूस्वामी (जमींदार) और कृषक के मध्य होती है। भूस्वामी चाहे तो भूमि लगान पर दे या न दे और दे तो जितना चाहें लगान ले न। उपर कृषक की इच्छा की बात है कि भूमि लगान पर न दे या न ले और यदि लगान अधिक हो तो वह सेती न करके दूसरा कोई धन्धा करे। इस प्रतियोगिता के कारण ही वस्तु का मूल्य सीमान्त भूमि की लागत के बराबर होगा और धन्य भू-भाग पर लगान में ऊपर बनस होगी। उन भू-भागों का लगान भी इस वस्तु के बराबर होगा। जहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है वहाँ रिकार्डों का लगान सिद्धान्त लागू नहीं होना है।

(९) रिकार्डों ने अपना लगान सिद्धान्त विस्तृत सेती के आधार पर प्रतिपादित किया था, परन्तु यह गहरी सेती पर भी लागू हो सक्ता है। दोनों दशाओं में लगान प्राप्त होता है।

(१०) लगान भूमि के उपयोग के प्रतिफल में दिया जाता है। भूमि के विशिष्ट गुणों के कारण कृषक भूमि का उपयोग करता है और इसके लिये उसे भू-स्वामी को लगान देना पड़ता है। इसी प्रकार भू-स्वामी उसका उपयोग स्वयं करे या दूसरे को करने दे। जब उसका उपयोग दूसरे को करने देता है, तब वह उसके बदले में लगान वसूल करता है। भूमि के सीमित मात्रा में होने के कारण भी लगान वसूल किया जाता है, यद्यपि भू-स्वामी को भूमि को उत्पन्न करने में कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भूमि एक अकृतित्व वस्तु है जो समाज को नि: शुल्क मिलती है।

रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Ricardian Theory of Rent)—रिकार्डों के लगान-सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार की गई है —

(१) रिकार्डों के अनुसार “लगान भूमि की मौलिक (Original) तथा अविनाशी (Indestructible) शक्तियों के उपयोग के कारण ही दिया जाता है।” यह कथन अशुद्ध है। भूमि की वे शक्तियाँ जिनके लिये लगान दिया जाता है, वे सदैव ही मौलिक नहीं रहती हैं। कभी-कभी वे प्राप्त भी हो जाती हैं। इसके प्रति-रिक्त, भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर प्रयोग से समाप्त हो जाती है तथा पुनः सिंचाई, खाद आदि माधनों द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। परन्तु यह धारणा निमूल है क्योंकि भूमि की स्थिति, जलवायु, तापक्रम, वर्षा, धूप आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो प्राकृतिक हैं तथा शोध नष्ट होने वाले नहीं हैं।

(२) रिकार्डों का यह ऐतिहासिक क्रम (Historical Order) कि सबसे पहले सर्वोत्तम भूमि पर सेती की जाती है मिथ्या प्रतीत होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सबसे पहले सर्वोत्तम भूमि को ही जोता जाय वास्तव में दखा जाय तो पहले लोग मुख्य एवं साधारण भूमि को ही जोतते हैं और फिर अच्छी भूमि

को । कहा जाता है कि अमेरिका में कम उपजाऊ भूमि की खेती सबसे पहले की जाती है । कैरे (Carey) और रॉशर (Roscher) का मत है कि सर्वप्रथम खेती उन्हीं खेतों पर होती है जो सरलता से उपजकर होते हैं—जहाँ वे बीसे ही हों, इमारतों, रिकार्डों की खेती का क्रम अमोघात्मक है । किन्तु यह कोई विशेष आरोप नहीं है क्योंकि रिकार्डों इस बात को कोई विशेष महत्त्व नहीं देता । वॉकर (Walker) ने इस आलोचना का सही उत्तर दिया है कि सर्वोत्तम सेत से तात्पर्य उन्हीं खेतों में है जो स्थिति और उर्वरा शक्ति के विचार में सर्वोत्तम होत हैं यद्यपि यह आरोपना विवेकहीन है ।

(३) रिकार्डों का सिद्धान्त पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर आधारित है । परन्तु वास्तविक जीवन में पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती ही नहीं । इसलिए इस सिद्धान्त का आधार निरुस है । वास्तविक जीवन में लगान केवल स्पष्ट ही निर्धारित नहीं होता बल्कि रीति रिवाज, कानून आदि बातों का भी प्रभाव पड़ता है । यह आलोचना किसी सीमा तक सत्य है, परन्तु अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी कल्पनाशा पर प्रत्यक्ष है और एक प्रवृत्ति (Tendency) मान है ।

(४) रिकार्डों की सीमान्त या लगानहीन भूमि की कल्पना निराधार बताई जाती है । यह आवश्यक नहीं है कि लगानहीन भूमि सदा बनी ही रहे । जो देश घने वने हुए हैं वहाँ निरुपेक्ष भूमि का भी लगान देना पड़ता है । यदि हम एक ही वस्तु को उत्पन्न करने वाले खेतों को अपने ही देश तक सीमित न रख और उदात्त वस्तु की पूर्ति करने वाले विदेशी खेतों को भी अपने बाजार में सम्मिलित कर लें, तो निश्चय ही कृषि नहीं लगानहीन भूमि मिल जायेगी । इस दृष्टि का आधार पर लगान निर्दिष्ट हो जाता है । इस प्रकार रिकार्डों ने लगान-सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है ।

(५) कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि रिकार्डों का यह कहना कि लगान का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है । उनका कहना है कि कुछ दशांश में लगान मुख्य भूमि सम्मिलित होता है जैसा कि आस्ट्रेलिया में एकाधिकार लगान के कारण मुख्य भूमि में वृद्धि हो गई है । परन्तु एकाधिकार लगान बहुत ही कम प्रभावशा में लागू होता है । इस कारण उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

(६) इस सिद्धान्त की सामाजिक आलोचना यह है कि लगान भूमि की विभिन्न उर्वराशक्ति के कारण नहीं होता बल्कि भूमि की स्वल्पता के कारण होता है । लगान का प्राथमिक सिद्धान्त इसी बात पर आधारित है ।

निष्कर्ष—रिकार्डों के सिद्धान्त के मूल ग्रन्थ अभी तक सही हैं और सामान्यतः लागू होते हैं । पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर रिकार्डों का सिद्धान्त विलुप्त होकर है । जहाँ यह सिद्धान्त लागू नहीं होता, वहाँ प्रायः प्राथमिक लगान (Economic Rent) का प्रश्न ही नहीं उठता । वहीं प्रत्यक्ष लगान (Contract Rent) होता है । पुराने देशों में जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण जन अधिक भूमि की माँग होती है, तब कम

उपजाऊ भूमि पर खेती प्रारम्भ हो जाना है ता रिवाडा का लगान सिद्धान्त लागू हो जाता है। नये देश में जहाँ भूमि का मात्रा बहुत अधिक है और जनसंख्या कम है वहाँ पर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता।

भारतवर्ष और रिकार्डों का लगान सिद्धान्त—भारतवर्ष एक प्राचीन देश है यहाँ जनसंख्या की अधिकता के कारण भूमि का मांग अधिक है। अतः लगान भूमि जनसंख्या का स्वतः पदार्थों की मांग का प्रतिफल के लिए कम। उदाहरण के लिए भूमि का भी मूल्य का जाना है जिसमें भूमि पर कुछ खर्च हो जाता है। अतः भारतवर्ष में रिकार्डों का लगान सिद्धान्त लागू है।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि भारतवर्ष में रिकार्डों का सिद्धान्त लागू होना है। भारतवर्ष में जनसंख्या का अधिकता के कारण तथा अल्प वसाय के कारण के कारण समस्त धनी और धन भूमि पर खेती का जाता है और इस पर लगान बहुत किया जाता है। अतः यहाँ पर कोई लगानहीन भूमि नहीं है। कम प्रतिफल रिवाडा का लगान सिद्धान्त पूरा तब स्वीकृत होता है प्राचिन है। परन्तु भारतवर्ष में स्वतन्त्र स्वतः का अभाव होने के कारण जो लगान दिया जाता है वह आर्थिक लगान (Economic Rent) में अधिक होता है। अतः यह स्पष्ट है कि रिवाडा का लगान सिद्धान्त भारतवर्ष में लागू नहीं होता।

लगान के भेद (Kinds of Rent)—आर्थिक दृष्टि से लगान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) आर्थिक लगान और (२) प्रचिन लगान।

(१) **आर्थिक लगान (Economic Rent)**—यह वह राशि या मूल्य प्रत्येक दाना में ही प्रत्येक भिन्नता रखने है। कोई भूमि अधिक उपजाऊ जाता है तथा उसकी स्थिति भी अच्छी होती है और कोई भूमि कम उपजाऊ जाता है तथा उसका स्थिति भी इतना बुरा नहीं होता है। जब यह प्रकार के दो भागों पर खेती का जाता है तो जिस विधि पर समय पर कोई भी जान वाला दो भाग एका प्रदान होता है जो जान जान वाला समस्त दो भागों में बराबर उपजाऊ होता है या विपरीत स्थिति में नष्ट होना है अतः जिसमें यह बात हो सकती है। अतः भूमि का लगानहीन भूमि (No rent Land) या सामान्य भूमि (Marginal Land) कहते हैं क्योंकि उसका उपज का मूल्य उस पर लगाई जाने वाले खर्च के बराबर ही होता है। अतः दो भागों में जो सामान्य भूमि का लगान अधिक उत्तम है अतः प्रति मोघात (Super marginal)। अतः यह अर्थ और पूरा गाना उपजाऊ होता है वह सीमाना या लगानहीन भूमि का अर्थ अधिक होता है। अतः प्रत्येक प्रति-सामान्य भूभाग पर कुछ बचत या आर्थिक उपज (Surplus) प्रत्येक भिन्नता लाभ (Differential gain) होता है जो आर्थिक लगान (Economic Rent) कहलाता है। उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी समय में वसुधैव कुटुम्बकम् का अर्थ होना है। अतः यह समस्त मान है और उसकी उपज १०० मन होना है। यदि हम वसुधैव कुटुम्बकम् को समस्त माना प्रत्येक की जाय तो अतः पर १०० मन अतः प्रत्येक पर ४०० मन और प्रत्येक पर ३०० मन अतः उपज होता है। वसुधैव कुटुम्बकम् मान लीजिए अतः अतः पर ४०० मन = (४०० - १००) लगान वसुधैव पर ३०० मन = (३०० - १००) अतः अतः पर २०० मन = (२०० - १००) लगान होता है। अतः पर अतः नहीं

होन से कोई लगान नहीं मिलता है। इसलिये इसे लगानहीन या सीमांत भूमि कहते हैं और रोप अथवा खेती की अधिक सीमांत भूमि माना जाता है।

अतः आर्थिक लगान इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है आर्थिक लगान भूस्वामी को प्राप्त होने वाली वह अतिरिक्त उपज (Surplus) या भिन्न लाभ (Differential gain) है जो लगानहीन भूमि (No-rent Land) की अपेक्षा उसकी भूमि की उर्वराशक्ति या स्थिति या दोनों की श्रेष्ठता के कारण उसे प्राप्त होता है।¹

आर्थिक लगान की उत्पत्ति के कारण (Causes of Economic Rent)—आर्थिक लगान निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है —

(१) भूमि की दुर्लभता (Scarcity)

(२) भूमि की उर्वराशक्ति (Fertility) तथा स्थिति (situation) में अन्तर होता, और

(३) उत्पत्ति-ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) का लागू होना।

लगान की उत्पत्ति का मुख्य कारण भूमि की दुर्लभता अर्थात् सीमित मात्रा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो लगान होगा ही नहीं। उस अवस्था में भूमि की उर्वराशक्ति तथा स्थिति में अन्तर होने के कारण लगान उत्पन्न होगा, क्योंकि समान लगान लगाने में उत्तम यत्ना पर अधिक उपज होगी और निरूप्यता पर कम उपज होगी। यदि सभी भूमि एक ही हो तो भी अधिक लगान उत्पन्न होगा क्योंकि उपज की मात्रा में वृद्धि होने में गहरी खेती की जायेगी और उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होगा जिसके कारण लगान उत्पन्न होगा। उत्पत्ति-ह्रास नियम के अनुसार लगातार इकाइयाँ की उत्पत्ति कम होती जायेगी और प्रारम्भ की इकाइयाँ पर अतिरिक्त लाभ अर्थात् लगान प्राप्त होगा।

आर्थिक लगान का निर्धारण (Determination of Economic Rent)—आर्थिक लगान का निर्धारण के प्रश्न पर विचार निम्न प्रकार किया जायगा

(क) विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) में आर्थिक लगान का निर्धारण—उत्पत्ति की बढ़ती हुई मात्रा की पूर्ति करने के लिये तथा उत्पत्ति-ह्रास-नियम का लागू होना के कारण जब कई प्रकार के भू-भागों पर जो उर्वराशक्ति या स्थिति अथवा दोनों में ही एक दूसरे से भिन्न हैं खेती की जाती है तब किसी विनिष्ट समय कोई-न कोई जोता जान वाला भू-भाग ऐसा अवश्य होगा जो जाने जान वाला अथवा भू-भाग की पुनरावृत्ति में कम उपजाऊ होगा या जिसकी स्थिति सर्वत्र निरूप्यता अथवा जिसमें यो दोनो ही वर्णन होगा। ऐसा भूमि को सीमांत या लगानहीन कहते हैं क्योंकि उसकी उपज का मुख्य बचन उस पर लगाई हुई लागन का बचन ही होता है। जो

1—Economic rent may be defined as 'the surplus or differential gain accruing to the owner of the land by virtue of its relative advantages of fertility or location or both over the no rent land'

जाने वाले प्रत्येक अधि-सीमान्त खेत पर सीमान्त खेत की अपेक्षा कुछ न-कुछ बचत या भिन्न लाभ होता है जो 'आर्थिक लगान' कहलाता है। यह आर्थिक लाभ भू-स्वामी को उसकी भूमि की उर्वरशक्ति या स्थिति या दोनों के सापेक्षिक लाभ के कारण उप प्राप्त होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिये—मान लीजिये अ व स द चार भूभागों पर समान श्रम व पूँजी आदि की मात्रा में खेती की जाती है। अ पर ५०० मन मध्य पैदा होता है, व पर ४०० मन, स पर ३०० मन और द पर १०० मन मध्य पैदा होता है। द सीमान्त या लगानहीन भू भाग है, क्योंकि उसकी उपज से जो मूल्य प्राप्त होता है वह केवल उसकी लागत के ही बराबर है। अ व स भू भाग अधि-सीमान्त खेत हैं क्योंकि इनकी उपज के मूल्य में लागत के ऊपर कुछ बचत रहती है। अतः सीमान्त या लगानहीन खेत की उपज इसमें से यदि घटा दी जाय, तो प्रत्येक का लगान प्रा जावेगा। इस उदाहरण में अ का ४०० मन (५००-१००), व का ३०० मन (४००-१००) और स का २०० मन (३००-१००) हुआ। द पर कोई लगान नहीं मिलता है (१००-१००), क्योंकि उपज का मूल्य तथा लागत बराबर हो रहे हैं। यदि उपज के मूल्य में वृद्धि हो जाय, तो इतने भी निम्न (Inferior) भूमि पर खेती की जाने लगेगी। इसको अनु-सीमान्त (Submarginal) भूमि कहते हैं। अनु-सीमान्त भूमि के जोते जाने पर द भूमि पर भी बचत हो जाने के कारण लगान प्राप्ति लगेगा।

माराप्त यह है कि विस्तृत खेती की अवस्था में सीमान्त या लगानहीन भूमि द्वारा लगान निर्धारित होता है।

(ख) गहरी में (Intensive Cultivation) आर्थिक लगान का निर्धारण—यदि किसी देश में अधिक भूमि उपलब्ध हो, तो बढ़ती हुई जन संख्या की माँग की पूर्ति करने के लिये सीमित भूमि पर ही अधिकार्थिक लागत लगा कर खेती करनी होगी। ज्यों-ज्यों श्रम और पूँजी की मात्रा में वृद्धि की जायगी, तथा त्यों उत्पत्ति द्वारा नियम के लागू होने के कारण प्रत्येक अगली मात्रा में होने वाली उत्पत्ति कमशः घटती जायगी और अन्त में ऐसी अवस्था प्रा जायगी जब कि लागत अधिकतम मात्रा में जो उत्पत्ति होगी उसका मूल्य केवल लागत-व्यय के बराबर होगा। ऐसी मात्रा को 'सीमान्त या लगानहीन मात्रा' कहेंगे। अतः श्रम व पूँजी की जो सीमान्त मात्रा भूमि पर लगाई जायेगी उससे पूर्व की मात्राओं पर सम्यक् स अधिक उत्पत्ति होगी और प्रत्येक अगले कुछ बचत या भिन्न लाभ होगा जो 'आर्थिक लगान' कहलावेगा। उपर्युक्त उदाहरण में मान लीजिये सीमान्त मात्रा द्वारा उत्पत्ति १०० मन होती है और इससे पूर्व की लागत की मात्राओं से क्रमशः ५०० मन, ४०० और ३०० मन उपज होती है, तो लागत की पहली मात्रा से ४०० मन (५००-१००), दूसरी से ३०० मन (४००-१००) और तीसरी से २०० मन (३००-१००) आर्थिक लगान मिलता है। चौथी प्रमाँ सीमान्त मात्रा से कोई लगान प्राप्त नहीं होता है (१००-१००=०)। इसीलिये इसे 'लगानहीन मात्रा' भी कहते हैं।

माराप्त यह है कि गहरी खेती की अवस्था में लागत की सीमान्त या लगानहीन मात्रा द्वारा आर्थिक लगान निर्धारित होता है।

(२) प्रसविदा लगान (Contract Rent)—जो लगान किसान भू-स्वामी को उसकी भूमि के प्रयोग के उपलक्ष में वास्तव में देता है, उसे

प्रसविदा लगान कहते हैं। इस प्रकार से लगान भी कहते हैं क्योंकि यह किसान और भूस्वामी के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों या व्यवहारनाम के अनुसार निश्चित होता है। यह एक प्रकार से भूमि के उपयोग का मूल्य है। प्रसविदा लगान परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक लगान के बराबर उगा कम या अधिक हो सकता है। पूरा प्रतियोगिता की अवस्था में प्रसविदा लगान अधिक लगान के बराबर होता है। जब भूमि की माँग अत्यधिक होता है और किसानों में भूमि की प्राप्ति करने के नियम बड़ी स्पर्धा होती है तथा कृषि के प्रतिरिक्ति अन्य कोई व्यवसाय नहीं होता है तब भूस्वामी किसानों में आर्थिक लगान में अधिक प्रसविदा लगान समूल कर लेते हैं। जब प्रसविदा लगान आर्थिक लगान में अत्यधिक होता है तब इसे अत्यधिक लगान (Back Rent) कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ कृषि बसाय करने वाले बहुत होते हैं और वह वह जमींदारों के पास इतनी भूमि हो कि वे स्वयं उस पर खेती न कर सकें वहाँ जमींदार अपनी जमीन या भूमि का उपयोग करने के दिव्य किसानों में आर्थिक लगान में भी कम लगान लेते हैं। तब तब देशों में प्रायः ऐसा ही होता है। परन्तु भारतवर्ष में प्राचीन देशों में जहाँ जन-संख्या का सामयिक भार है और कृषि के प्रतिरिक्ति औद्योगीकरण के दिव्य व्यवसायों का अभाव है भूस्वामी आर्थिक लगान में अधिक लगान लेते हैं। जब प्रसविदा लगान आर्थिक लगान में अधिक रहता है तब कृषकों की दशा विषम जाता है और वे प्रायः कष्टी हो जाते हैं।

आर्थिक लगान एवं प्रसविदा लगान में अंतर

(Difference between Economic Rent & Contract Rent)

(१) आर्थिक लगान एक सैद्धांतिक न पना है जबकि प्रसविदा लगान एक व्यवहारिक न पना है। (२) आर्थिक लगान एक अर्थ एवं मूल्य धारण है जबकि प्रसविदा लगान एक प्रत्यक्ष एवं कठु मर्याद है। (३) यह मर्याद की बात है कि अकस्मात् में एक दूसरे के निकट या दूर या बराबर हो जायें सम्बन्धों की एक ऊपर है या कभी दूसरा। (४) तभी बात में प्रसविदा लगान आर्थिक लगान में छोड़े रह जाता है और मर्याद बात में प्रसविदा लगान आर्थिक लगान में कदा प्रायः बढ जाता है।

प्रसविदा लगान का निर्धारण (Determination of Contract Rent)—जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसका माग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है उसी प्रकार प्रसविदा लगान भी जो कि भूमि के प्रयोग का मूल्य है माग और पूर्ति का क्रिया का पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। अब हम यह दर्शेंगे कि किस प्रकार माग और पूर्ति की क्रिया द्वारा प्रसविदा लगान निर्धारित होता है।

भूमि में उपयोग का माग—भूमि की माँग उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसके पास स्वयं या तो कोई भूमि नहीं होता है। वह दूसरी की भूमि किराये या लगान पर खरीद लेता है। एक जोर किसान या खेताली (tenants) कहलाते हैं। अतः कृषक भूस्वामी से भूमि उन समय यह विचार कर लेता है कि वह उन भूमि पर खेती कर सकेगा यदि वह करेगा या कि कुछ उत्पत्ति में से लगान व्यय निकाल करेगा कुछ बचता होगा। अतः कुछ माग भूस्वामी को भूमि

के प्रयोग के उपनक्ष्र में दे दिया। यह वचन ही मासिक लगान है। जो लगान कृषक भू-स्वामी को उसकी भूमि के प्रयोग के लिए दे सकता है यह इन वचन में अधिक न होगा। यतः यह वचन (Surplus) उसकी अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निर्धारित करती है। यह इस सीमा में अधिक देना स्वीकार नहीं करेगा। यह कृषक को अधिकतम सीमा भूमि की उर्वराशक्ति आदि बातों के साथ बदलती रहती है। यदि भूमि अच्छी हुई तो यह वचन अधिक होगा और फलतः उसकी अधिकतम सीमा भी अधिक होगी। यदि भूमि खराब है, तो यह वचन कम होगा जिससे परिणामस्वरूप अधिकतम सीमा भी कम होगी। अन्य शब्दों में यह कहना है कि कृषक की अधिकतम सीमा मिट्टी के स्वभाव, भूमि की स्थिति, बाजार या मंडी की निश्चिन्ता, माल की दूरी की सुविधाओं और उपज के मूल्य के साथ साथ बदलती रहती है।

भूमि के उपयोग की पूर्ति—भूमि के उपयोग की पूर्ति-सुव्यवस्था द्वारा की जाती है। भू-स्वामी या तो भूमि का उपयोग स्वयं करता है या उस बिना पर दे देता है; यदि वह किराये पर देता है, तो किराये पर देना समय इस बात का हिमाज लगा लेता है कि यदि वह स्वयं उस भूमि पर खेती करे तो कृषक काट कर उसे कितनी वचन होगी। इस कम-अधिक दोनों ही वचन वह शिराजदार में लगान के रूप में लेना चाहेगा। यदि हमने कम मिलेगा तो उनमें स्तर सेना करेगा या उस घन किसी कार्य में लेगा। इस प्रकार लगान की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निर्धारित हो जाती है। जो लगान भू-स्वामी अपनी भूमि के प्रयोग के बदल में किराया या दानाओं में लेना चाहेगा वह इस सीमा में कम नहीं होगा।

भूमि के प्रयोग की मांग और पूर्ति का मनुबल (Equilibrium of Demand and Supply of use of Land)—प्रत्येक लगान भूमि के प्रयोग की मांग और पूर्ति के मनुबल बिन्दु पर निर्धारित होता है। मांग द्वारा लगान की अधिकतम सीमा और पूर्ति द्वारा उसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित हो जाती है। यतः मोटे तौर पर प्रत्येक लगान इन दोनों सीमाओं के मध्य होगा। परन्तु ठीक लगान क्या होगा यह मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होता है—(क) भू-स्वामियों और किसानों की सापेक्ष आवश्यकता (Relative Urgency) और (ख) उनकी बात-बात करने (Haggling and Bargaining) की शक्ति। यदि पूर्ति की प्रस्ता मांग की तीव्रता अधिक है तो कृषकों में पारस्परिक प्रतियोगिता होगी और लगान कृषकों की अधिकतम सीमा तक पहुँच जायेगा, अर्थात् भू-स्वामी कृषक में अधिक लगान की सम्पूर्ण गति बसूल करने में सफल हो जायेगा। इसके विपरीत, यदि मांग की प्रस्ता पूर्ति की तीव्रता अधिक है, अर्थात् कृषकों की भूमि की मांग कम है तथा भू-स्वामी भूमि की कृषकों को देने के लिए बहुत उत्सुक है, तो प्रत्येक लगान भू-स्वामी की न्यूनतम सीमा तक पहुँच जायेगा और कृषकों को अधिक उनाल का कुछ ही घन भू-स्वामियों को देना पड़ेगा जिससे कृषकों को नान होने लगेगा। इस प्रकार ठीक लगान इन दोनों सीमाओं के बीच उत बिन्दु पर स्थित हो जाता है जहाँ पर कृषक और भू-स्वामी के मध्य समन्वय या समन्वय प्रत्येक सापेक्ष में इतर हो जाता है। इसीलिए तो इन प्रत्येक या इतरों लगान बहने है।

साधारणतया यह देखा में भूमि की मांग अधिक होने और उन मध्य कम होने के कारण सेन जोनन बातों की भूमि की मांग कम होती है। यतः ही न व

भूम्यामियों में अधिकाधिक भूमि पर खेती करवाने की उत्प्रेरणा के कारण उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है जिससे जनस्वरूप प्रसविदा लगान कम होता है। किन्तु प्राचीन देशों में जहाँ जन-संख्या अत्यधिक होने के कारण साधारण आदि की पैदावार के लिये भूमि की माँग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है जिससे जनस्वरूप कृषकों में ही आपस में प्रतियोगिता होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप जो लगान कृषकों को देना पड़ता है या तो वह अधिक लगान के बराबर होता है या उसमें अधिक होता है। यदि कृषि के अनिश्चित अन्य व्यवसायों का अभाव है, तो प्रसविदान-लगान और भी अधिक देना पड़ेगा। इसे 'अल्पविक्रय लगान वसूल करना' (Rack-renting) कहते हैं जो भारतवर्ष में एक साधारण बात है।

भारतवर्ष में प्रसविदा लगान का निर्धारण (Determination of Contract Rent in India)—भारत में प्रसविदा लगान माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु रीति-रिवाज, स्पर्धावैकल्पिक धन्यों का अभाव और कानून आदि बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है।

रीति-रिवाज (Custom)—पुराने समय में भारत में जन-संख्या का दबाव अधिक नहीं था, इसलिये जोतने के लिये भूमि मुक्तता में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी। किसानों और भूम्यामियों में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अच्छा था। उनमें एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा आशुभाव की भावनाएँ थीं। वे मार-पीट, चोरी, छद्मता आदि सब प्रकार के एक-दूसरे की सहायता करने से। भूमि का लगान बहुत कम था और वह भी परम्परा के आधार पर निर्धारित होता था। यह प्रायः प्रभाव के रूप में होता था। इस प्रकार उस समय जो लगान दिया व दिया जाता था उसका एक रिवाज था बन गया था। इसी रिवाज के अनुसार भूमि का लगान पीढ़ी दर-पीढ़ी दिया जाता था। परन्तु हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भूमि का लगान रीति-रिवाज से निर्धारित होता था।

स्पर्धा (Competition)—भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने के पश्चात् देश में मानि एक मुक्तता बड़ी। एक मानि-स्वायत्ता में देश में प्रादिक उत्पत्ति हुई जिसने परिणामस्वरूप भूमि की माँग बड़ी। साथ ही में जन-संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई जिसके कारण भूमि की माँग और भी बढ़ गई। अब भूमि का प्राप्ति करने के लिये मनुष्यों में आपस में प्रतियोगिता होने लगी। भूम्यामियों ने इस बदलती हुई परिस्थिति का लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया। रीति-रिवाज के आधार पर लगान-निर्धारण नुस्त ना हो गया और इसका स्थान स्पर्धा ने ले लिया। पारम्परिक सम्बन्धों के प्रभाव में व्यक्तिवाद भावना का प्रचार हुआ जिसके कारण भी स्पष्टता तीव्र हो गई और रीति-रिवाज द्वारा लगान-निर्धारण की प्रथा समाप्त हो गई। अतः अब भूमि का लगान स्पर्धा द्वारा निर्धारित होने लगा।

वैकल्पिक धन्यों का अभाव (Absence of Alternative Occupations)—ग्रन्थों की कृषि नीति द्वारा भारत में सब धन्य उद्योग धन्य नष्ट हो गये जिसके कारण भूमि पर दबाव और अधिक बढ़ गया। अब किसानों के पास सिवाय

सेतो करने के कोई अन्य उदर रीति का साधन नहीं रहा। यद्यपि उपको में भूमि प्राप्त करने के लिये स्पर्धा अधिक तीव्र हो गई जिससे कारण उन्हें अधिक लगान से भी अधिक लगान देना प्रारम्भ करना पड़ा। इस प्रकार वैकल्पिक धन्यो के अभाव का भी लगान-निर्धारण में बहुत प्रभाव पड़ने लगा।

लगान सम्बन्धी कानून (Tenancy Legislation)—अत्यधिक स्पर्धा के कारण अत्यधिक लगान देने में किसानों की दशा निम्न होने लगी और भूस्वामी बहुत शक्तिशाली हो गए। जब-तब किसान भूमि में सुधार करके उत्पादन में कोई वृद्धि करता तब ही भूस्वामी उस पर लगान बढ़ाकर उस उत्पादन का बहुत सा भाग स्वयं हूटप कर जाता। इस कारण किसानों को कृषि-सुधार में अधिक रुचि नहीं। अन्त में इस दोषपूर्ण दशा को देखकर सरकार को लगान-सम्बन्धी कानून बनाना पड़े। अब इनही कानूनों के आधार पर भूमि का लगान निर्दिष्ट किया जाता है।

सारारा यह है कि वर्तमान समय में भी रीति रिवाज, सदाई, वैकल्पिक धन्य का अभाव तथा लगान सम्बन्धी कानून प्रसिद्ध-लगान के निर्धारण में प्रभाव डालते हैं। अब जमींदारी प्रथा के अन्त किये जाने पर कुछ परिवर्तन हो रहा है।

लगान और मूल्य (Rent and Price)

लगान और मूल्य के मूल्य का पारस्परिक सम्बन्ध एक जटिल समस्या है। साधारण विचार द्वारा के अनुसार कानूनों के सार्वजनिक मूल्य का कारण अधिक लगान है। उदाहरणार्थ, यदि एक दुकानदार अपना मान अधिक मूल्य पर बेचना है, तो वह इसका यह कारण बताता है कि उसको लगान अर्थात् दुकान का किराया अधिक देना पड़ता है। किन्तु धर्मशास्त्राचार्य विचार-धारा इससे बिल्कुल भिन्न है। रिकार्डों के अनुसार भूमि में लगान और उसकी पैदावार के मूल्य में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। रिकार्डों के सिद्धांत है कि अनाज का मूल्य इसलिये अधिक नहीं है कि लगान चुकाया जाता है, बल्कि लगान इसलिये चुकाया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है।¹ इसका तात्पर्य यह है कि कृषि की उत्पत्ति के मूल्य पर लगान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

लगान मूल्य को निर्धारित नहीं करता है (Rent does not determine the price or enter the cost of production)—यह पहले बतलाया जा चुका है कि किसी भूमि का सांप्रदायिक लगान उस भूमि और सीमान्त भूमि के अन्तर के बराबर होता है। सीमान्त भूमि की उत्पत्ति का मूल्य उस पर खेती करने के लागत-अवयव के बराबर होता है, अर्थात् सीमान्त भूमि की उत्पत्ति पर जो लागत पड़ती है वह उस उत्पत्ति का मूल्य होता है। अधिक स्पष्ट करने हुए यों कहा जा सकता है कि बाजार में प्राप्त होने वाला मूल्य कम से कम सीमान्त भूमि की उत्पत्ति के उत्पादन-अवयव के बराबर होना आवश्यक होता है। चाहे अन्यथा उस पर खेती जारी रखना सम्भव नहीं हो सकता। यदि मूल्य उत्पादन-अवयव से अधिक हो, तो अनु-सीमान्त (Submarginal) भूमि पर भी खेती की जाने लगेगी और वर्तमान सीमान्त भूमि अधि-सीमान्त (Supermarginal) भूमि हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि मूल्य

1—Corn is not high because rent is high, but rent is high because corn is high.
—Ricardo

उत्पादन व्यय में कम हो, तो वर्तमान सीमान्त भूमि पर खेती करने में हानि होगी और उस पर नतीजस्वित्व कर दो जायगी और वह अनु सीमान्त भूमि हो जायगी। अतः यह स्पष्ट है कि कृषि उत्पत्ति का मूल्य सीमान्त भूमि की उत्पत्ति के उत्पादन-व्यय के बराबर होता है। मूल्य इसमें प्रविक्रय या कम नहीं हो सकता।

साथ ही, हम यह भी जानते हैं कि सीमान्त-भूमि लगानहीन भूमि होती है, अर्थात् डग पर कोई लगान नहीं मिलता है। चूंकि बाजार में कृषि-उत्पत्ति का मूल्य सीमान्त भूमि के उत्पादन व्यय के (जिसमें कि लगान का कोई अंश सम्मिलित नहीं होता है) बराबर होता है, ना वह मरज कहा जा सकता है कि लगान का मूल्य-निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, अर्थात् लागत में यह सम्मिलित नहीं होता है।

लगान की छूट एवं उसकी न्यूनाधिकता का मूल्य पर प्रभाव (Effect of Rent Remission and Increase or Decrease of Rent on price)—उपरोक्त तर्क-वितर्क में हम सभी प्रकार सम्भव करने हैं कि लगान मूल्य निर्धारित नहीं करता अर्थात् लगान मूल्य का कोई अंश नहीं होता बल्कि लगान स्वयं मूल्य पर साधित होता है। इसीलिए, यदि लगान कम भी कर दिया जाय, तो इसमें मूल्य में कमी नहीं होगी। यदि भूस्वामी लगान देना बन्द कर दे तो कृषि-उत्पत्ति का मूल्य वही रहेगा। इसी प्रकार यदि लगान कई गुना बढ़ा दिया जाय, तो भी मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अतः यह किन्तु स्पष्ट है कि लगान मूल्य का कोई अंश नहीं है। वास्तव में भूमि की उत्पत्ति का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति के पारस्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है न कि लगान की दर से। यही कारण है कि लगान को उत्पादकता का वक्षस (Surplus) कहा जाता है।

अपवाद (Exception) लगान कुछ अवस्थाओं में मूल्य को अवश्य निर्धारित करता है (Rent does determine price or enter the cost of production under certain conditions)—सार्वभौमिकता लगान सीमान्त-उत्पादन-व्यय का अंश नहीं होने के कारण कृषि-उत्पत्ति के मूल्य-निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं डालता। परन्तु कुछ अवस्थाएँ ऐसी हैं जिसमें लगान सीमान्त-उत्पादन-व्यय का अंश होता है और इसमें यह मूल्य पर प्रभाव डालता है। वे वहाँ जिनमें लगान मूल्य का निर्धारित करता है, निर्धारित है।—

१. सरकार या भूस्वामियों का भूमि पर एकाधिकार (Monopoly of State or body of Landlords on land)—यदि भूमि पर सरकार या भूस्वामियों के किसी छय का भूमि पर एकाधिकार हो, तो वह सीमान्त-भूमि पर भी किंगमा बनूँ कर सकता है। ऐसी अवस्था में लगान सीमान्त-उत्पादन-व्यय का अंश हो जायगा और मूल्य का निर्धारित करेगा। भारतवर्ष में भारत सरकार का समस्त भूमि पर एकाधिकार है और वह सीमान्त अर्थात् लगानहीन भूमि पर भी लगान वसूल करती है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि सार्वभौमिकता में लगान कृषि उत्पत्ति के मूल्य को निर्धारित करता है।

सगे । परिमाणगत, अमेरिका में भूमि की माँग बढ़ गई और अनु-सीमान्त भूमि सीमान्त तथा सीमान्त भूमि अधि-सीमान्त होने लगी और लगान में बराबर वृद्धि होने लगी ।

(घा) यातायात के साधनों में उन्नति होने से यदि किसी देश में सस्ते यात्र-पदार्थों का आयात बढ़ जाय, तो वहाँ हम पदार्थों का मूल्य घट जायगा जिसके फलस्वरूप लगान में भी कमी होने लगेगी । मूल्य में कमी होने के कारण घटिया अर्थात् अनु-सीमान्त भूमि पर सेलो स्थापित कर दी जायगी जिसके परिणाम-स्वरूप सीमान्त और अधि सीमान्त भूमि की उत्पत्ति में अन्तर कम हो जायगा और हमलिय आयात करने वाले देश में लगान कम हो जायगा । ऊपर के उदाहरण में जब इङ्ग्लैंड में अमेरिका के सस्ते खाद्य-पदार्थों का आयात बढ़ गया, तब वहाँ अनु-सीमान्त भूमि पर सेलो स्थापित कर दी गई तथा बहुत-सी अधि-सीमान्त भूमि सीमान्त हो गई और लगान बराबर गिरता गया ।

(२) कृषि की उन्नति का प्रभाव (Effect of Agricultural Improvements)—कृषि की उन्नति होने से उत्पादन अधिक होगा । उत्पादन अधिक होने से, यदि माँग वही रहे, मूल्य गिरेगा । मूल्य गिरने में सीमान्त भूमि पर कृषि कार्य बन्द हो जायगा, अर्थात् वह अनु-सीमान्त भूमि हो जायगी । अब सीमान्त अब अन्य प्रकार की भूमियों की उत्पत्ति का अन्तर कम हो जायगा, क्योंकि अब सीमान्त भूमि पूर्ववत् सीमान्त भूमि की अपेक्षा प्रच्छेदी होगी । उत्पत्ति का अन्तर कम होने के कारण लगान भी कम हो जायगा । यदि यह कृषि की उन्नति केवल प्रच्छेदी भूमि तक ही सीमित हो तब तो लगान में वृद्धि होगी, क्योंकि अब सीमान्त और अधि-सीमान्त भूमि की उत्पत्ति का अन्तर पहले की अपेक्षा अधिक हो जायगा । परन्तु यदि उन्नति घटिया भूमि में सम्बन्धित होगी, तो सीमान्त व अधि-सीमान्त भूमि की उत्पत्ति का अन्तर कम हो जाये के कारण लगान में कमी होगी ।

यदि कृषि उन्नति लगभग सभी प्रकार की भूमियों (बड़िया, घटिया एवं साधारण) पर हो जाय और यदि कृषि में उत्पत्ति ह्यम-नियम को सीधे लागू होने में रोकने वाला, तो अधिक घटिया भूमि को जोतने की प्रवृत्ति स्थिर हो जायगी और बड़िया एवं घटिया भूमियों की उत्पत्ति में अधिक अन्तरान की प्रवृत्ति भी कम जायगी । इसका परिणाम यह होगा कि न्यस्त भूमियों की उत्पत्ति में वृद्धि होगी जिसके कारण उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जायगी । यदि माँग पूर्ववत् ही है तो यही वृद्धि पूर्ति से मूल्य गिरने लागा जिसके कारण लगान भी कम होने लगेगा । यदि पूर्ति के साथ-साथ माँग में भी वृद्धि होने लगे, तो लगान कम होने की प्रवृत्ति में रुकावट उत्पन्न हो जाती है ।

कृषि में उत्पत्ति ह्यम नियम लागू होने का लगान पर प्रभाव—वास्तव में देखा जाय तो कृषि में उत्पत्ति-ह्यम नियम के लागू होने के कारण ही लगान उत्पन्न होता है । अतः इस प्रवृत्ति के लागू होने की अवस्था में लगान बढ़ता है । यदि अन्य बातें पूर्ववत् रह, तो उत्पत्ति-ह्यम-नियम को रोकने वाली बातें—जैसे कृषि-क्षेत्र व रोतियों में उन्नति आदि लगान को घटाती है ।

(३) जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव (Effect of Increase in Population)—जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण कृषि-पदार्थों की माँग बढ़ेगी

जिसकी पूर्ति विस्तृत एवं गहरी मेती द्वारा की जावेगी, अर्थात् या तो पटिया मानी मनु-सोमान्त भूमि पर खेती की जावेगी अथवा उसी भूमि पर पूर्वोक्त व थम की अधिकधिक मात्राएं लगाकर खेती करनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में अधि सोमान्त भूमि (Super-marginal Land) या अधि सोमान्त मात्रा (Super-marginal Dose) की अनिश्चित उपज का वृद्धि अधिक हो जायेगी जिसके फलस्वरूप लगान बढ़ जायेगा। इसके प्रतिरिक्त, जनसंख्या में वृद्धि होने से भूमि की मांग अनेक प्रकृति कार्यों के लिए भी बढ़ जायेगी, जैसे भवन एवं उद्योगशाला निर्माण आदि। इस कारण भी भूमि का लगान बढ़ जायेगा।

(४) सभ्यता के विकास का प्रभाव (Effect of Progress in Civilization) सभ्यता की उन्नति का प्रभाव भी लगान पर उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार कि जन-संख्या की वृद्धि का पड़ता है। इसे अधिक स्पष्ट करने हुए दो कथाएं दी जा सकती हैं कि सभ्यता के विकास से लगान में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाने से अधिकांश वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिनकी पूर्ति के लिये अधिक भूमि की मांग बढ़ जाती है। कृषि के प्रतिरिक्त वाय-वर्षाओं, खेत के मैदान आदि बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी। अस्तु, इस कारण भी भूमि का लगान बढ़ जायेगा।

लगान के कुछ अन्य स्वरूप (Other Kinds of Rent)

१. इमारती भूमि का लगान (Rent of Building Sites)—

इमारती भूमि का लगान भी उसी सिद्धान्त से विनिश्चित होता है जिस सिद्धान्त से कृषि-भूमि का। अन्तर केवल इतना ही है कि कृषि भूमि के लगान निर्धारण में उसकी उर्वरा शक्ति तथा स्थिति दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, परन्तु इमारती भूमि पर केवल उसकी स्थिति का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिये इमारती भूमि के लगान को स्थिति लगान (Situational Rent) कहते हैं। रहने की इमारतों के लिये स्वास्थ्यप्रद जनवायु, प्राकृतिक सौन्दर्यता, स्वच्छता, सुरक्षा, आवागमन व वातावरण को सुविधाओं युक्त स्थिति अत्यन्त सम्भवी जाती है। व्यापार के लिये ऐसा स्थान जहाँ बहुत सी अन्य दुकानें हों, बहुत से ग्राहक आने जाते हों तथा माल के यातायात की सुविधाएँ हों, अत्यन्त सम्भवी जाता है। अन्तु, जो भूमि बस्ती के मध्य अथवा बाजार आदि में स्थित होती है उसका लगान बहुत अधिक होता है, परन्तु जो भूमि बस्ती या बाजार से बहुत दूर स्थित होती है उसका लगान बहुत ही कम होता है, जैसे दिल्ली के चाँदनी चौक में स्थित भूमि का लगान महादर के पास वाली भूमि से बहुत अधिक होगा। इस प्रकार चाँदनी चौक की भूमि अपनी अत्यन्त स्थिति के कारण महादर के निकटवर्ती भूमि के ऊपर भिन्नक लाभ (Differential Advantage) प्राप्त करती है। इस स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ विषय वा अन्तर ही 'इमारती भूमि का लगान' कहलाता है।

अन्य: यह स्पष्ट है कि एक ही समय में विभिन्न भू-भाग (Plots of Land) विभिन्न स्थिति में बने हुए होते हैं। उनमें से एक भू-भाग ऐसा होता है जो भवन-निर्माण के लिए अनुपयुक्त होता है और उस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा

सू-भाग सीमान्त या लगानहीन होगा और अन्य सू-भाग जिनकी स्थिति भवन निर्माण की दृष्टि से अच्छी होती है, अर्थात् सीमान्त सू-भाग कहलायेंगे। अर्थात्-सीमान्त भूमि का स्थिति-सम्बन्धी अतिरिक्त या मिश्रक लाभ ही उसका लगान होगा।

भारतीय भूमि का लगान बढ़ता-घटता भी रहता है। यदि किसी भूमि के पास से भड़क निकल जाये या सरकारी कार्यालय अन्य स्थान में उठ कर आ जाये, तो उस भूमि का लगान अवश्य बढ़ जाता है। किसी के पास से सब प्रकार की सुविधाओं को हटा लेने से उसका लगान कम हो जाता है।

२. खानों का लगान (Rent of Mines and Quarries)—खानों का लगान भी उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार कृषि भूमि का। कृषि भूमि और खान के लगान में योधा या अन्तर अवश्य है और वह यह है कि कृषि-भूमि निरन्तर काम में आ सकती है परन्तु खान की कच्ची धातु कुछ समय के पश्चात् ही समाप्त हो जाती है। इस कारण खान के स्वामी न केवल इसलिये हानि लगान लेते हैं कि उनकी खान कच्ची धातु से परिपूर्ण है बरन् इसलिये भी लगान लेते हैं कि उनकी खान में कच्ची धातु बिकाली जाती है।

खान के लगान में दो प्रकार की राशि सम्मिलित होती है—(अ) अधिकार शुल्क या राजदान (Royalty) वह राशि है जो पट्टेदार खान में से खनिज-पदार्थ निकालने के उपलक्ष्य में खान के स्वामी को देता है। कृषि भूमि की उर्वरा-शक्ति के लिए इस प्रकार की कोई राशि नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि भूमि की उर्वरा-शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती। यदि भूमि का उपयोग सावधानी के साथ जाय तो इसकी उर्वरा-शक्ति कायम रह सकती है। (आ) वास्तविक लगान (Rent Proper) वह अतिरिक्त अथवा लाभ है जो खान खोदने तथा स्थिति सम्बन्धी सुविधाओं के कारण सीमान्त खान के ऊपर अर्थात् सीमान्त खान को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से कृषि-भूमि के लगान और खान के वास्तविक लगान में पर्याप्त समता है।

खनिज पदार्थ की माँग बढ़ने से या तो बटिया खानें खोद कर (Extensively) खनिज पदार्थ निकाला जाता है या अच्छी खानों पर ही अधिक-अधिक श्रम और पूँजी की मात्रा लगा कर (Intensively) खनिज पदार्थ निकाला जाता है। इस कार्य में खनिज पदार्थ निकालने के सुधरे हुए एवं अधिक मूल्यवान् द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। किसी निश्चित समय एक ऐसी खान अवश्य होगी जिसका खोदना कठिन होगा या जिसकी स्थिति खराब होगी। इसे सीमान्त या लगानहीन खान कहेंगे। अन्य खानें अर्थात्-सीमान्त होगी। इसी प्रकार गहरी खुदाई (Intensive Mining) में सीमान्त या लगानहीन श्रम व पूँजी की मात्रा अपर्याप्त होगी। अतः सीमान्त या लगानहीन खान और अर्थात्-सीमान्त खान के नाम के अन्तर या भिन्नक लाभ (Differential Advantage) को 'खान का लगान' कहते हैं।

३. मत्स्य क्षेत्र का लगान (Rent of Fisheries)—मत्स्य क्षेत्रों (मछली पकड़ने के स्थानों) का लगान भी कृषि-भूमि के लगान की भाँति ही निर्धारित होता है। कृषि-भूमि एवं मत्स्य क्षेत्र के लगान में पूर्ण समानता है। कुछ अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार कृषि-भूमि का सावधानतापूर्वक प्रयोग उसकी उर्वरा-शक्ति का नाश रखकर कृषि-कार्य को निरन्तर चलने योग्य बना देता है, ठीक उसी प्रकार यदि मत्स्य क्षेत्रों का सावधानी से प्रयोग किया जाय तो मछलियों की पूर्ण रखायी नहीं रहेगी और मछली पकड़ने का कार्य निरन्तर चलना रहेगा। कुछ मत्स्य क्षेत्रों में

मछलीयों बहुत अधिक तथा किनारे पर पाई जाती है जिसमें उन्हें सुगमता तथा कम व्यय में पकड़ा जा सकता है। परन्तु बड़े मत्स्य क्षेत्रों में मछलियाँ कम संख्या में तथा किनारे में हट कर दूर पाई जाती है जिसमें उन्हें पकड़ने में कठिनाई होती है तथा व्यय भी अधिक लगता है। अतः यह स्पष्ट है कि किंगी विविष्ट मत्स्य में कोई एक मत्स्य क्षेत्र पैदा होगा जहाँ मछलीयों पकड़ने का व्यय धीरे-धीरे में प्राप्ति प्राप्त कराया जायेगी और अन्य क्षेत्रों में धीरे-धीरे मछलीयों के पकड़ने में व्यय लगान में बड़ी अधिक होगी। दूसरा क्षेत्र सोमान्त या लगानहीन होगा और दूसरी क्षेत्रों में समान मत्स्य क्षेत्रों में सोमान्त होगा। अतः, धीरे-धीरे अर्थात् सोमान्त तथा अर्थात् सोमान्त मत्स्य क्षेत्रों के लाभ के अन्तर यानी भिन्नक लाभ (Differential Advantage) का 'मत्स्य क्षेत्रों का लगान' बढ़ने है।

४. **प्राभास या अर्थ लगान (Quasi-Rent)**—प्रभास या अर्थ-लगान की धारणा का प्रकाश प्रथम पहल प्रो० मार्शल ने किया था। मार्शल ने बताया कि जिस प्रकार भूमि पर लगान प्राप्त होता है उसी प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों पर भी लगान प्राप्त हो सकता है। भूमि के लगान तथा अन्य उत्पत्ति के साधनों पर प्राप्त होने वाले लगान में अंतर इतना ही अंतर है कि भूमि की पूर्ण सोमित एक निश्चित होता है और वह घटाई-वर्द्धाई नहीं जा सकती, किन्तु अन्य उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण कुछ समय के लिये तो निश्चित हो सकती है परन्तु यह सदा के लिये निश्चित नहीं हो सकती। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि अन्य उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण की मात्र के घटने पर बढ़ाया जा सकता है और मात्र के घटने पर घटाया जा सकता है। इस कारण भूमि में प्राप्त होने वाले प्रतिरिक्त उत्पत्ति या वचन (Surplus) और अन्य साधनों में प्राप्त होने वाले प्रतिरिक्त उत्पत्ति या वचन में अंतर करना आवश्यक है। पूर्ण भूमि की प्रतिरिक्त उत्पत्ति या वचन का नाम 'लगान' है, इसलिये अन्य साधनों की प्रतिरिक्त उत्पत्ति या वचन का नाम 'प्राभास या अर्थ-लगान' रखा गया है। अन्य उत्पत्ति के साधनों का प्रतिरिक्त लाभ भी भूमि के लगान के तुल्य होता है, इसलिये इसे प्राभास या अर्थ लगान कहा गया है। प्रो० मार्शल के शब्दों में प्राभास या अर्थ-लगान वह भिन्नक लाभ (Differential Advantage) है जो उत्पत्ति का साधन जिसकी पूर्ण धीरे-धीरे वर्द्धाई-घटाई जा सकती है, अपने ही जैसे अन्य उत्पत्ति के साधन के अंतर प्राप्त करता है। उत्पत्ति के इन साधनों में मछली, वारणान्त (पेंड्री), व्यापारिक-योग्यता, शिल्पकार की उद्यता व अन्य मनुष्य-नृत साधन सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ, मुद्रान्त में जबकि देश में अधिक मछलीयों लगाना या बाहर में पैमाना सम्भव नहीं होता है, तब मोड़दा कारणाने ही अन्यधिक लाभ बनाते हैं, क्योंकि मनुष्यों की मात्रा अन्यधिक बढ़ जाती है और पूर्ण में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। बुद्ध-मर्यादा के साथ ही यह विषय परिस्थिति भी सम्भव हो जाती है और सर्व धर्म पूर्ण वर्द्धाई की सुविधा मिलती जाती है जिसके कारण अल्पकालीन लाभ भी कम होने हुए तुल्य हो जाने है। इन अल्पकालीन लाभों को जोकि किसी उत्पत्ति के मानन की अस्वाभाविक न्यूनता के कारण उनमें स्थायी की प्राप्त होते हैं, सामान्य या अर्थ-लगान कहते हैं।

प्राभास या अर्थ-लगान के सम्बन्ध में धर्मशास्त्रियों में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार जिस समय में उत्पत्ति के साधन की पूर्ण नहीं वर्द्धाई जा सकती

उन काज की मारी प्रायः आभास या अर्द्ध-लगान कहलायेगी। इसके विपरीत पतन (Flux) आदि विज्ञान का कहना है कि माषाभ्य आय से जितनी अधिक प्रायः इस काल में प्राप्त होती है वेबल वही प्रायः आभास या अर्द्ध-लगान है। यह दूसरी धारणा कुछ अधिक ठेक प्रतीत होती है।

आभास या अर्द्ध-लगान के निर्धारण में समय का महत्व—आभास लगान के निर्धारण में समय का बड़ा महत्व है। आभास या अर्द्ध-लगान अल्पकाल के लिये ही प्राप्त हो सकता है। दीर्घकाल में यह घट जाता है या विलुप्त समाप्त हो जाता है यद्यपि हाल में परिवर्तित हो जाता है। यदि पुराने उत्पत्ति के माषना के स्थान पर नये माषना का प्रयोग होने लगे तो आभास लगान निम्नलिखित समाप्त हो जायगा।

आभास या अर्द्ध-लगान की धारणा का व्यावहारिक महत्व—आभास या अर्द्ध-लगान की धारणा व्यावहारिक दृष्टि में बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि यह जीवन के बहुत से क्षेत्रों पर लागू होती है। एक उदाहरण या निर्गता किसी व्यापारिक भेद (Trade Secret) के कारण कुछ समय तक बहुत सा लाभ उठा सकता है। भेद के खुलने ही वह लाभ समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक उत्तम मिलाली, एक दम ह जीनियर, एक पट्टे गायक जब तक उनके पयोग प्रतिद्वन्द्वी उत्पन्न नहीं होते, आभास या अर्द्ध-लगान प्राप्त कर सकते हैं।

लगान और आभास या अर्द्ध-लगान की समता या विषमता—
(१) भूमि एवं अन्य निष्पक्ष प्राकृतिक प्रसादों की प्रायः की लगान कहती है और मनुष्य द्वारा प्राप्त व उपकरणों की प्रायः की आभास लगान कहती है। (२) लगान स्थायी वस्तु है परन्तु आभास या अर्द्ध-लगान अस्थायी वस्तु है। (३) अल्पकाल में भूमि के समान आय उत्पत्ति के साधनों की भूमि भी निश्चित होती है और वह भूमि के समान बचाई नहीं जा सकती। दीर्घकाल में भूमि की पुष्टि तो फिर भी निश्चित रहती है, परन्तु अन्य साधनों की पुष्टि मनुष्य द्वारा बचाई जा सकती है। (४) अल्पकाल में आभास या अर्द्ध-लगान और भूमि का वही सम्बन्ध होता है जो सम्बन्ध लगान और भूमि का स्थायी रूप में होता है। (५) लगान भूमि का अर्थ नहीं होता। परन्तु दीर्घकाल में आभास लगान या तो लुप्त हो जाता है या भूमि का अर्थ बन जाता है। (६) अल्पकाल में लगान की भाँति आभास लगान भी अनावश्यक लाभ है, क्योंकि बहुत की लागत में कोई वृद्धि हुए बिना ही किसी साधन का भूमि बड़ा जाता है। परन्तु दीर्घकाल में आभास लगान का ही अर्थ हो जाता है, यह सामाजिक बचन नहीं रहता।

५. लगान में अनुपाजित वृद्धि (Unearned Increment)—भू-स्वामी द्वारा भूमि में सुधार कर देन से भूमि का मूल्य बढ़ जाता तो स्वाभाविक है। परन्तु कभी कभी ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण भूमि का मूल्य स्वन हो बढ़ जाता है और बिना प्रयास किए ही भू-स्वामी का लाभ होने लगता है। इन सामाजिक परिस्थितियों के कारण बिना भू-स्वामी के प्रयत्न के, भूमि में मूल्य में वृद्धि होने को, अनुपाजित वृद्धि (Unearned Increment) कहते हैं। इन प्रकार की मूल्य में वृद्धि कई कारणों से होती है—जैसे किसी बजार भूमि पर कारखाना स्थापित हो जाय, किसी भू-भाग के आस-पास कोई नगर बस जाय या वह किसी शहर से यातायात के साधन द्वारा मिला दिया जाय

भगवा वहाँ रेल का स्टेशन बन जाय, आदि । उदाहरणार्थ पहले दिल्ली में हजारों एकड़ भूमि व्यर्थ पड़ी थी किन्तु अब वहाँ नई दिल्ली, करीब बाग व कमला नगर आदि बसे जाने से उसकी माँग बहुत बढ़ गई है और फलतः उसका मूल्य बढ़ गया है । इस उन्नति का कारण नये स्वामियों का निर्माण है तथा इससे भू-स्वामियों का कोई प्रयत्न नहीं है । इसलिये ऐसी समान वृद्धि 'अनुपाजित-वृद्धि' कही जाती है ।

अनुपाजित वृद्धि सामाजिक कारणों का परिणाम होता है । इसमें भू-स्वामी को कोई प्रयत्न नहीं करने पड़े है । अतः बहुत से अर्थशास्त्रियों विशेषतया समाजवादियों (Socialists) का मत है कि इस पर भू-स्वामियों का व्यक्तिगत रूप में कोई अधिकार नहीं होना चाहिये, बल्कि सरकार के माध्यम द्वारा उसे जनहित कार्यों में व्यय करना चाहिये । अतः, सरकार या तो सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) कर अपनी ही वनासे भगवा इन वृद्धि को कर (Tax) के रूप में ले ले ।

१. योग्यता का लगान (Rent of Ability) — प्रत्येक व्यवसाय भगवा धन्य में कुछ व्यक्ति तो बड़े योग्य एवं कुशल वृद्धि करने होते हैं जिन्हें अधिक सीमान्त योग्यता वाले व्यक्ति कहा जा सकता है और कुछ अपेक्षाकृत कम योग्य होते हैं जिन्हें सीमान्त योग्यता वाले व्यक्ति कहा जा सकता है । अधिक-योग्यता योग्यता वाले व्यक्ति सीमान्त योग्यता वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कार्य करते हैं तथा अधिक कमाते हैं । अतः अधिक-योग्यता योग्यता वाले व्यक्तियों की भाव में सीमान्त योग्यता वाले व्यक्तियों की भाव की अपेक्षा कुछ बचत रहती है जिसे 'योग्यता का लगान' कहते हैं । अर्थशास्त्र में इसे लाभ (Profit) कहते हैं ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

१—आर्थिक लगान किस प्रकार निर्धारित होता है, समझाइए । कृषि-विधि में सुधार हो जाने से खेती के लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

२—लगान का क्या अर्थ है ? यह किस प्रकार निर्धारित होता है ?

(२० मार्च १९६०)

३—आर्थिक लगान (Economic Rent) और ठेके के लगान (Contract Rent) का अन्तर स्पष्ट कीजिये । आर्थिक लगान किस प्रकार निर्धारित होता है ?

४—रिकाई का लगान विद्वान्त समझाइये । भारत में लगान पर निम्न कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है :

(क) रीति-रिवाज और प्रतियोगिता, (ख) कृषि की संशोधित प्रणाली, (ग) यातायात के मन्दे साधन ।

५—लगान के विद्वान्त की व्याख्या कीजिये । यह भारतीय दशावधि में किन बातों के साथ लागू होता है ?

६—"लगान उस उत्पत्ति व्यय का भाग नहीं होता जो मूल्य को प्रभावित करता है ।" इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिये ।

७—कृषि भूमि पर लगान का उदय किस प्रकार होता है ? लगान पर कृषि प्रणाली में सुधार का क्या प्रभाव पड़ता है ?

- ८—रिक्तार्थों के लक्षण सिद्धान्त का वर्णन कीजिये और इसकी आलोचना भी करिये । (ग० बा० १६४२, घ० बा० १६४७, दिल्ली हा० स० १६५०, ४०)
- ९—आधिक लक्षण और ठेक के लक्षण में भेद दर्शाइये । 'लक्षण एक बृहत् त्राति का मुख्य अंग है । इस कथन की व्याख्या कीजिये । (ग० बा० १६५१)
- १०—आधिक लक्षण और ठेक के लक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिये । पूर्ण प्रतिबोधना में ये किम प्रकार निर्धारित हुए हैं ? (ग० बा० १६४९)
- ११—'अनाज के दाम इतनीय अधिक नहीं होंगे कि लक्षण लिया जाता है वरन् लक्षण इतनीय लिया जाता है कि अनाज के दाम अधिक होंगे ।'—रिक्तार्थों के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये । (घ० बा० १६५६)
- १२—इस भूमि पर लक्षण किम प्रकार उदय होता ? लक्षण पर निम्नलिखित का क्या प्रभाव पड़ता है —

(क) मातापिता के माधना में विद्वान्, (ख) जनसंख्या में वृद्धि ।

(स० बा० १६५१, घ० बा० १६५१)

- १३—(क) इस के माधना में सुता और (ख) मातापिता के माधना में उत्पत्ति का लेती के लक्षण पर प्रभाव बताइये । भारतीय उदाहरण देकर समझाइये ।

(घ० बा० १६५७)

- १४—एक उदाहरण देकर समझाइये कि बहरी लेती पर आधिक लक्षण किम प्रकार उदय होता है ? आधिक लक्षण के मुख्य लक्षण बताइये । (नागपुर १६५०, ४८)

- १५—आधिक लक्षण किम प्रकार निर्धारित होता है ? लक्षण उत्पादन व्यय का क्या नहीं है, समझाइये । (नागपुर १६४९)

- १६—आधिक लक्षण की परिभाषा लिखिये । बहरी लेती में आधिक लक्षण किम प्रकार निर्धारित होता है ? (नागपुर १६४८)

- १७—यदि निम्न अवस्थाओं में भी लक्षण का उदय होता है —

(क) भूमि के मूल द्रव्य उत्पत्ति और स्थिति में समान है ।

(ख) भूमिपति स्वयं भूमि का जानता है ।

(ग) यदि भूमि पर सामान्य उपज के घटन का नियम लागू न हो ।

(पंजाब १६२६)

इष्टर एग्रेविचर परीक्षा

- १८—आधिक लक्षण की परिभाषा लिखिये । यह किम प्रकार उत्पन्न होता है ? इसकी मात्र किम प्रकार की जाती है ? क्या उचित है कि लक्षण में वृद्धि होती है ?

भारत में भू-धारण-पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा

(Land Tenure and Land Revenue
System in India)

भू-धारण-पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा की आवश्यकता—भारत में भू-धारण पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा का विशेष महत्त्व है। भू-धारण-पद्धति (भूमि-पद्धति) का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। राज्य देश की भूमि की व्यवस्था करने के हक उस भूमि को या किसी निश्चित भूमि के भागों को किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को सौंप देता है। परन्तु इस अधिकार-प्राप्ति के उपलक्ष्य में व्यक्ति या व्यक्ति-समूह राज्य को लगान देता है। भूमि पर अधिकार-प्राप्ति को भू-धारण पद्धति और उसके बदले में लगान देने को मालगुजारी प्रथा कहते हैं। इनका प्रभाव कृषि के उत्पादन पर भी पड़ता है। यदि किसी हृषक की अपनी ही भूमि हो या भूमि पर सदा के लिये अपना ही अधिकार हो तथा राज्य को अधिक लगान नहीं देना पड़ता हो, तो वह बहुत लगन और उत्साह के साथ कृषि करेगा जिससे फलस्वरूप कृषि में उगाज अधिक होगी। अन्य हृषक जिसकी भूमि अपनी स्वयं की नहीं होती है या जिसकी भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है वे लगन और उत्साह से कृषि नहीं करते जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कम होता है। इस प्रकार भू-धारण-पद्धति तथा मालगुजारी प्रथा देशवासियों के जीवन-स्तर को भी प्रभावित करती है। इससे सन्देह नहीं कि जिस प्रकार राष्ट्रोन्नति के लिये मुख्यवर्षित शासन प्रबन्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कृषि की उन्नति के लिये भूमि की उचित व्यवस्था भी परमावश्यक है। अस्तु, कृषि की उन्नति और विकास के लिये तथा समाज में शान्ति और सन्तोष स्थापित करने के लिये न्याययुक्त भू-धारण पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा की परम आवश्यकता है।

भारत में भूमि से सम्बन्धित पक्ष—भारत में भूमि का वास्तविक स्वामी राज्य अथवा सरकार है क्योंकि भारत की समस्त भूमि एक प्रकार से उसी की ही है। इसलिये यह सबसे बड़ा जमींदार या सर्वोच्च भू-स्वामी (Supreme Landlord) कहा जा सकता है। सभी-कभी राज्य सरकार भूमि के निश्चित भागों को कुछ व्यक्तियों में वितरण कर उन्हें उन भूमियों में स्वामित्व का अधिकार दे देती है और वे इसके उपलक्ष्य में सरकार को मालगुजारी देने रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि पर वे स्वयं कृषि करे अथवा हृषक का लगान पर उठा दे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। इन व्यक्तियों का जमींदार (Zamindar) या भू-स्वामी

Landlord) कहते हैं। जब खेत जोतने वाले कृषि के लिए भूमि मीठी सरकार से लगान के आधार पर लेते हैं और उनके व सरकार के मध्य कोई अन्य भू-स्वामी नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका भूमि में सम्बन्ध होता है, कृषक (Cultivator or Tenant) या लगानदार (Rent-payer) कहलाते हैं।

भू-धारण-पद्धति एवं भालगुजारी प्रथा का अर्थ एवं परिभाषा—अंग्रेजी शब्द 'Land 'tenure' का अर्थ 'भू-धारण' से है। Land या अर्थ 'भूमि' और 'tenure' का अर्थ 'धारण' है। 'Tenure' शब्द लैटिन भाषा के 'tenere' शब्द से आता है जिसका अर्थ 'To hold' अर्थात् धारण करना है। प्रस्तु, भू-धारण-पद्धति से उम नियमों तथा शर्तों से आगम्य है जिनके आधार पर एक पक्ष दूसरे से कृषि के लिये भूमि प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में, भू-धारण पद्धति से हमारा उन अधिकारों तथा दायित्वों से आगम्य है जिनके आधार पर जमींदार, लगान इकट्ठा करने के लिये या खेतों करने के लिये कृषक-आसामियों को देने के लिये, सरकार से जो देश में समस्त उपलब्ध भूमि की सैद्धान्तिक रूप में वास्तविक स्वामी है, प्राप्त करता है, जबकि साधारणतया भू-धारण पद्धति में तात्पर्य होता है, उन शर्तों का जिनके आधार पर कृषक जोतने के लिये भूमि प्राप्त करता है।¹

भालगुजारी प्रथा (Land Revenue System)—यह प्रथा है जिसके अन्तर्गत नियमानुसार सरकार जमींदार से उसकी भूमि पर अधिकार देने के उपलक्ष्य में भालगुजारी वसूल करती है। जमींदार या भू-स्वामी कृषक और सरकार को मिलाते वाला धर्मात्ता है जो कृषक से लगान वसूल करके सरकार को भालगुजारी देता है और इस प्रकार कृषक और सरकार के मध्य सम्बन्ध स्थापित रखता है।

भालगुजारी (Land Revenue)—जो राशि सरकार जमींदार से वसूल करती है उसे भालगुजारी कहा जाता है। यह राशि उम लब्धन का एक भाग होता है जो जमींदार कृषक से वसूल करता है।

लगान (Rent)—जो राशि जमींदार या भू-स्वामी कृषक से भूमि जोतने के लिये देने के उपलक्ष्य में वसूल करता है, उसे लगान कहते हैं। इस लगान का अर्थ प्रसविदा लगान से है। वसूल किया हुआ लगान का लगभग ४० या ५०

1—"By Land Tenure we mean the rights and liabilities under which the landlord for the collection of revenue or for the letting of his land to the tenant cultivators holds his land from the Government which is in theory the real Proprietor of all the land available in the country while ordinarily Land Tenure means the terms or conditions on which the cultivator cultivates the holding."

प्रतिगत भाग जमींदार को मालगुजारी के रूप में सरकार या राज्य को देना पड़ता है ।

भू-धारण पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा का वर्गीकरण—भारतवर्ष में भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा दो भेदों में बांटी जा सकती है—(अ) स्वामित्व प्रथा और (आ) जुताई प्रथा ।

(अ) स्वामित्व प्रथा (Proprietary Tenures)—वे नियम या शर्तें जिनके आधार पर जमींदार या ट्युक सरकार से भूमि में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करता है, स्वामित्व प्रथा का निर्माण करती है । जमींदारी महसुलदारी और रयतदारी प्रथाएँ स्वामित्व प्रथा के कुछ उदाहरण हैं ।

(आ) जुताई प्रथा (Cultivating Tenures)—वे नियम या शर्तें जिनके आधार पर ट्युक जमींदार से (मगवा सरकार से जहाँ रयतदारी प्रथा प्रचलित है) जोतने के लिए भूमि प्राप्त करता है, जुताई प्रथा कहलाती है । उत्तर प्रदेश के सन् १९१५ के भू-धारण एवं मालगुजारी कानून अर्थात् कायस्थरी कानून (Tenancy Act) के अनुसार स्थायी-मध्यमय किसान, स्थिर लगान देने वाले किसान, पूर्व स्वामित्व वाले किसान, मोहसी किसान, गैर-मोहसी आदि किसान, जुताई प्रथा के कुछ उदाहरण हैं ।

(ग) स्वामित्व-प्रथा (Proprietary Tenures)—भारत में स्वामित्व प्रथा के अन्तर्गत प्रचलित भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथाएँ—भारत में अनेक प्रकार की भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथाएँ प्रचलित हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

१. जमींदारी प्रथा (Zamindari System)—इस प्रथा में अन्तर्गत राज्य या सरकार की ओर से जमींदार को भूमि के स्वामित्व का अधिकार होता है जिनके उपरान्त वे वह सरकार को निर्दिष्ट मालगुजारी देता है । इस प्रकार सरकार से प्राप्त भूमि या स्वामी जमींदार होता है और उस क्षेत्र या सम्पूर्ण गाँव की सरकारी मालगुजारी या भुगतान करने का उत्तरदायित्व जमींदार का ही होता है । ग्राम जमींदार स्वयं जोती नहीं करता बल्कि वह भूमि को लगान पर उठा कर किसानों से लगान वसूल करता है । इस लगान का लगभग ५० प्रतिशत भाग जमींदार को सरकार के लगाने में मालगुजारी के रूप में जमा करना पड़ता है और बाँक उसकी जेब में चला जाता है । इस प्रथा में किसान और सरकार के मध्य कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रथा प्रयाग, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी पूर्वी जिलों में तथा उत्तर प्रदेश में वाराणसी कमिश्नरी में प्रचलित है । इनके अतिरिक्त पंजाब मध्य प्रदेश और मद्रास के कुछ भागों में भी यह प्रथा पाई जाती है । अथवा वे तालुकदार भी जमींदार ही माने जाते हैं और वे बड़े बड़े इलाकों की मालगुजारी देते हैं । इनमें से कई प्रांतों में तो जमींदारी उन्मूलन की योजनाएँ बन चुकी हैं ।

जमींदारी प्रथा में मालगुजारी निर्धारित करने के ढंग—जमींदारी प्रथा में मालगुजारी निर्धारित करने के पुरुषार्थ दो ढंग हैं—(क) स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) और (ख) अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement) । स्थायी बन्दोबस्त अर्थात् स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों से तो जान बानी मालगुजारी सदा के लिए निर्दिष्ट कर दी गई है और उस दरवाजा

या घटाया नहीं जा सकता। यह उग बगाल विहार मगध के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तर प्रान्त में बाराणसी कमिश्नरी में प्रचलित है। इनके विपरीत अस्थायी बंदागस्त अर्थात् अस्थायी भूमि व्यवस्था में मालगुजारी को घटाने बटाने का अधिकार सरकार को होता है और निम्न चतुर्थाथ के पञ्चाय (प्राय १० २० ३० ४० वर्षों के पश्चात्) जाच पहनाल करके भूमि को ठबरा गति के आधार पर मालगुजारी की राशि में परिवर्तन कर दिया जाता है। बगाल व कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश व अवध के तालुकागारा में अस्थायी व्यवस्था है।

जमींदारों प्रथा के गुण (Ment) — (१) भारत में ईसा १८५० ई. में अंग्रेजी ने अधिकाधिक मानगुजारा प्राप्त करने व उद्देश्य में इसे अपनाया था और उनका यह उद्देश्य निरसादेह पूर्ण हुआ। उनका उग समय अंग्रेजों के विकास या भूमि की उन्नति से कोई सम्बन्ध नहीं था। (२) इन प्रथा में दूसरा नाम यह हुआ कि इसके अपमानों से एक ऐसा बग की जन्म मिला जा सबदा कम्पनी के शासन को स्थायी बनाने के लिये प्रयत्न करने रहे। इस प्रकार इस प्रथा ने राजनतिक दृष्टि से लाभ था।

दोष (Demerits) — (१) जमींदार बिना परिश्रम व धन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं समाज हित के लिए नहीं। निम्न जमींदार किसानों की गान्धी समाज में बड़े बड़े मोठ बघाते हैं।

(२) जमींदार बग देना हिन के लिये समाज का नेतृत्व ग्रहण करने में असमर्थ रहे हैं। अधिकतर जन दान प्रिटिंग साम्राज्यवाद के समर्थक व सहायक और राष्ट्रीय आंदोलन के शत्रु थे।

(३) जमींदार किसानों का नाना प्रकार से शोषण करते हैं। व गर मीनसों किसानों से मनमाना लगान वसूल करते हैं और समय समय पर उनको बेदखल करने की धमकी देते रहते हैं।

(४) जमींदार त्योहार तथा विवाह आदि व अवसरों पर किसानों से मजदूराना (भट) व अनेक भोग लाग लेते हैं।

(५) जब कोई कृषक अपने भेतों की स्थायी उन्नति के लिये श्रमवृद्धि या श्रम बाप करना चाहते हैं तब जमींदार उसकी स्वातंत्र्य नहीं दन ह। अधिकतर जमींदार बग सुधार विरोधी प्रकृति का होता है।

(६) जम दारी प्रथा व भारतीय कृषि और श्रमिक को नष्ट कर दिया है। इसने भारतीय कृषकों के आर्थिक जीवन के विकास को रखा ह तथा भारतीय कृषि को ठेस पहुँचाई है।

(७) जमींदार प्राय विनाशप्रिय बन रहे हैं। अधिकतर जमींदार गृहस्थ थे रहते हैं और अपनी जमींदारी का प्रबंध अपने कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं जो

नरानों से अनेक प्रकार की वेगार कराते हैं और अधिकाधिक लगान-प्राप्ति के लिये उन पर शत्याचार करते हैं।

(८) प्रायः कृषक जमींदारों के शत्याचारों के शिकार होते हैं जिससे उन्हें मुकदमेबाजी में पेशना पड़ता है। अतः जमींदारी प्रथा में कृषकों और जमींदारों में मुकदमेबाजी बढ़ती है।

(९) जमींदार प्रायः आर्थिक लगान से भी अधिक लगान वसूल करते हैं जससे किसानों को आर्थिक दबा विगड़ जाती है।

(१०) जमींदारी प्रथा के कारण साधारण कृषक का व्यक्तित्व दबा रहता है, वह अपने को नीचा तथा हेय समझता है और उसमें स्वाभिमान की भावना लुप्त हो जाती है।

२. महालगुजारी या संयुक्त ग्राम्य-प्रथा (Mahalwari or Joint Village System)—इस प्रथा के अन्तर्गत गांव की भूमि वा एक जमींदार-रक्षामी नहीं होता वा उस गांव को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रहें, यत्कि सारे गांव की भूमि के सह-भागी (Co-sharer) धावस में मिल कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सरकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व सने है। प्राय गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जिसे सम्बरदार या मालगुजार कहते हैं सरकार समझौता या इकरार कर लेती है जिसमें अनुसार मालगुजारी के भुगतान का प्रथम उत्तरदायित्व उस पर होता है। महाल वा पटवारी सम्बरदार को रबी और खरीफ की फसलों के आधार पर वसूल किये जाने वाले सरकारी लगान के व्योरे का विच्छेद बना कर दे देता है। वह इस विच्छेद के आधार पर प्रत्येक कृषक से लगान वसूल करता है और इस प्रकार वसूल हुई कुल राशि को सरकारी खजाने में जमा कर देता है जबवा समीक्षाईन द्वारा भेज देता है। सम्बरदार को इस कार्य के लिये समस्त वसूल की गई राशि पर निश्चित कमीशन दिया जाता है। गन्ध प्रदेश में उसे 'मालगुजार' कहते हैं। इस प्रथा में प्रस्थायी बन्दोवस्त (Temporary Settlement) होता है जो दोस या तीस साल के लिये किया जाता है। बन्दोवस्त के समय महाल (एक वा अनेक गांवों-गुप्त एस्टेट वा नाम महाल है) की भूमि का लगान-मन्वकी मूल्य (Rental Value) निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर ५०% से अधिक मालगुजारी निर्धारित नहीं का जाती है। यह प्रथा पंजाब, मध्य प्रदेश और समस्त उत्तर प्रदेश (अवध को छोड़ कर) में प्रचलित है।

गुण (Merits)—(१) सरकार को मालगुजारी समय पर मिल जाती है।

(२) मालगुजारी का भुगतान सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि गांव के भू-रक्षामियों वा कृषकों का सरकार को मालगुजारी के भुगतान के लिये व्यक्तिगत एवं समष्टिगत उत्तरदायित्व होता है।

(३) लगान अत्यधिक नहीं होता। महाल का पटवारी रबी और खरीफ की फसलों के आधार पर वसूल किये जाने वाले लगान का व्योरे-ज्याम विच्छेद बनाता है जिससे अनुसार सम्बरदार गांव के प्रत्येक किसान से लगान वसूल करता है।

(४) भूमि एवं कृषि में उन्नति की जा सकती है।

दोष (Demerits)—(१) इस प्रथा के अन्तर्गत जमीन-बसूनी के लिये नियत किये गये लम्बरदार को जमींदारों की ही भाँति व्यवहार करने का अवसर तो नहीं मिल पाता, परन्तु बन्दोबस्त के समय इन्हीं को किसानों की मानगुजारी निर्धारण में पक्षपात करते देखा गया है।

(२) इस प्रथा के अन्तर्गत ग्रामवासी बन्दोबस्त होने के कारण बन्दोबस्त के समय मानगुजारी बढ़ने का भय रहता है।

३. रयतवारी प्रथा (Ryotwari System)—इस प्रथा के अन्तर्गत सरकार तथा रयत (Ryot) अर्थात् कृषकों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष यानी सीधा होता है। सरकार और कृषक के बीच जमींदार या लम्बरदार जैसा कोई मध्यस्थ नहीं होता। प्रत्येक कृषक स्वतः ही बन्दोबस्त द्वारा निर्धारित मानगुजारी नियत समय पर सरकारी खजाने में जमा करने के लिये उत्तरदायी होता है। सब प्रकार की भूमि (जो भी हूँ या बेकार बड़ी हूँ) का प्रतिभूति स्वामी सरकार होता है। कृषक भूमि का अधिकार सरकार से प्राप्त करता है। कृषक को अपनी भूमि को जोड़ने, हटाने, बंटित करने और छोड़ने के अधिकार प्राप्त होते हैं। कृषक का भूमि पर उस समय तक पूर्ण-पूरा अधिकार रहता है जब तक वह सरकारी मानगुजारी बराबर देता रहता है। इस प्रथा में सरकारी प्रायः 'कर' के रूप में न होकर 'नगान' के रूप में होती है। इस प्रथा में ग्रामवासी बन्दोबस्त होता है, अर्थात् १० से ३० वर्षों के लिये मानगुजारी निश्चित कर दी जाती है। इस अवधि के पश्चात् सरकारी जमींदारी प्रत्येक शीघ्र में जाते हैं और पुनः-मापन (Land Survey) के पश्चात् फसलों के आधार पर नूति की उर्वरता-शक्ति का अनुमान लगा कर उसका वर्गीकरण करते हैं। इस प्रकार पहले १० से ३० वर्षों के लिए मानगुजारी पुनः निर्दिष्ट कर दी जाती है। प्रायः उपर्युक्त १० प्रतिशत अर्थात् प्रायः मानगुजारी के रूप में ले लिया जाता है। यह प्रथा बम्बई, उत्तरी मद्रास, बरार, आन्ध्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है।

गुण—(Merits)—(१) रयतवारी प्रथा में कृषक भूमि का स्वामी होता है और जब तक वह सरकार को मानगुजारी देता रहता है जब तक उसे वेदवन्ती (Ejectment) का तनिक भी भय नहीं होता है।

(२) इस प्रथा में कृषक दिल लगाकर खेती करना है और उसमें सुधार करने के प्रयत्न करता है। फलतः कृषि का विकास होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है।

(३) यह प्रथा जहाँ तक कृषकों का सम्बन्ध है बहुत सुविधाजनक और उपयोगी है। यदि एक कृषक भूमि को जोड़ना ठीक नहीं समझता है या नूति का लगान अधिक होने के कारण उसका जोड़ना अधिक हित में लाभकारी नहीं समझता है तो वह उस भूमि को बड़ी सुसज्जा में छोड़ सकता है।

(४) रयतवारी प्रथा में कृषक की स्थिति एक छोटे-मोटे जमींदार की भाँति

होता है जिसका सम्कार से सीधा सम्पर्क होता है और कोई बीच में मध्यस्थ नहीं होता है ।

दोष (Demerits) — (१) रैयतदारी प्रथा में सरकार किसी प्रकार भी किसी अनुपस्थित भू-स्वामी से कम नहीं है । सरकार सर्वदा अपना स्वार्थ तमान-बमूली या उसकी बढ़ि में रखती है ।

(२) भूमि पर मुजार करने का उत्तुङ्गाधिक सरकार पर न हाबत रूपक पर होता है और भारत में सरकार को मानपुजारी दान व पस्चान उनका पान जंयन-निर्वाह के लिये भी आय नहीं बचती । परिणामतः वह भूमि पर मुधार नहीं कर पाता है ।

(३) निम्नवत् रैयतदारी में रूपक और सरकार का बीच मध्यस्थ नहीं होता है । परन्तु ऐसा है कि रूपक अपनी भूमि अन्य किसानों को दे देने में और वह उनमें लगान लेने में निमग्न रैयतदारी प्रथा को उपयोगिता कम हो गई है क्योंकि उसमें जमींदारी की भांति अनेक दौर उत्पन्न हो गये हैं ।

(४) इस प्रथा का एक दोष यह भी है कि किसान भूमि मुधार के लिये बिना गये क्रय एवं श्रम का पूरा उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि बन्दावस्तु व समय मानपुजारी वद जान स दग वद हुए उबाधन का बहुत कुछ भाष लघान व रूप में बदा दिया जाता है ।

उपर्युक्त विभिन्न भू-धारण एवं मानपुजारी प्रथाओं का वर्गीकरण सन् १९२०-२२ ई० में निम्न प्रकार का —

भू-धारण एवं मानपुजारी प्रथा का नाम	खेदफल (लाक़ एक्ड़ में)	कुल भूमि का प्रतिशत भाग
१. जमींदारी (स्थायी बन्दावस्तु)	१३००	२१ ^० / _{१०}
२. जमींदारी तथा मजदूरी (स्थायी बन्दावस्तु)	१६६०	३६ ^० / _{१०}
३. रैयतदारी	१८३०	३६ ^० / _{१०}

बन्दावस्तु या भूमि व्यवस्था (Settlement) — भूमि के उन वर्गीकरण या विभाजन का जिसमें द्वारा (क) सरकार को भिन्न-भिन्न मानपुजारों की राशि, (ख) सरकार को मानपुजारी देने में निम्ने उत्तुङ्गाधिकी व्यक्तियों, और (ग) भूमि में व्ययित्तन अधिकांशों की निश्चय किया जाता है, उस बन्दावस्तु या भूमि व्यवस्था कहते हैं । बन्दावस्तु में सगरी प्रकार के रूपकों के व्यक्तिगत अधिकांश का स्पष्टीकरण होता जाता है, लगान-मुकतान व उत्तरदायी पक्ष का पना नम जाना है तथा लगान की निश्चित राशि जानी जा सकती है । बन्दावस्तु सरकार द्वारा किया जाता है ।

बन्दावस्तु के भेद (Kinds of Settlement) — भारतवर्ष में ३ प्रकार का बन्दावस्तु प्रचलित है :—

१. स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement), और २. अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement) ।

१. स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement)—यह भूमि-व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष समुत्त की जाने वाली मालगुजारी सदा के लिये निश्चित कर दी जाती है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया जाता है और उसे निश्चित मालगुजारी सरकार को देनी पड़ती है। जब तक वह निश्चित मालगुजारी देता जाता है, तब तक भूमि उससे नहीं छीनी जा सकती। जमींदार सरकार के बगाने हुये नियमों का पालन करते हुये मन-चाहा लगान किसानों से समुत्त कर सकता है। स्थायी बन्दोबस्त सन् १७८३ ई० में लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis) ने सबसे पहले बंगाल में जारी किया था। इसके पश्चात् यह प्रथा भारत के अन्य भागों में जारी की गई और यह प्राजक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, मालास, बाराणसी कॉम्पल्सरी और चम्पारन-राज्य में पारि जाती है।

स्थायी बन्दोबस्त का सक्षिप्त इतिहास—सन् १७६५ में १७६३ तक बंगाल में मालगुजारी इकट्ठा करने का काम कुछ ठेकेदारों को दिया जाता था। मालगुजारी इकट्ठा करने के ठेके नीलाम होते थे और बोली लगती थी। ठेकेदार किसानों से मनमाना लगान समुत्त करते थे और सरकार को भी अनिश्चित राशि मालगुजारी के रूप में मिलती थी। अन्तु, विषय होकर सन् १७६३ ई० में लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बन्दोबस्त का महाराज लगा पड़ा। मालगुजारी इकट्ठा करने वाले कारिग्रे जमींदार मान लिए गये और भूमि की मालगुजारी सदा के लिये निश्चित कर दी गई। सम्भव है कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार यह व्यवस्था उचित हो सकती थी, परन्तु समय बीतने के साथ इस व्यवस्था के दोष प्रकट होने लगे जिनके कारण अब इस प्रथा का अन्त होना प्रारम्भ हो गया है।

स्थायी बन्दोबस्त के गुण (Merits)—इस बन्दोबस्त में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं।

१. मालगुजारी की निश्चितता—इस व्यवस्था में सरकार को मालगुजारी की निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। इसमें मालगुजारी सम्बन्धी अनिश्चितता नहीं रहती।

२. बन्दोबस्त एवं लगान-बमुन्नी पर कम व्यय—इस प्रकार के बन्दोबस्त में सरकार बार बार बन्दोबस्त करने के अम्हट और व्यय में बच जाती है तथा उसे लगान समुत्त करने में कोई कठिनाई तथा व्यय नहीं होता। उन्हें नियत समय पर जमींदारों द्वारा मालगुजारी भी राशि प्राप्त होती रहती है।

३. भूमि के उत्पादन में वृद्धि—इस बन्दोबस्त में मजान के बढ़ने का भय नहीं रहता। अतः उत्साही जमींदार भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिये आवश्यक प्रयत्न और व्यय करने के लिये प्रोत्साहित होने हैं जिससे वे भूमि को अधिक लगान पर उठा सकें। इनके लिये जमींदारों का शिक्षित, परिश्रमी और योग्य होना आवश्यक है।

४. राजनैतिक लाभ—इस भूमि-व्यवस्था में जमींदारी-प्रथा को प्रोत्साहन

मिला। जमींदार सरकार ने अतः वन गये और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को अन्न तथा दवा सहायता दी।

५. जमींदार आराम्य निवासियों का स्वाभाविक नेता हो गया—स्वाधीन बन्दोबस्त के परिणामस्वरूप जमींदार के रूप में आम के निवासियों का स्वाभाविक नेता प्राप्त हो गया। रियासी बन्दोबस्त के प्रत्यक्ष और अनुसार जमींदारों ने किसानों की दशा सुधारने के लिये बहुत से स्तूप तथा अस्पताल आदि सुलवाय जिम्मेदार बनाने की दशा में सुधार हुआ। साथ ही साथ रियासी बन्दोबस्त से कृषि में सुधार भी हुआ।

स्वाधीन बन्दोबस्त के दोष (Demerits)—श्री एफ० एन० डी० पनाउड की अध्यक्षता में नियुक्त बंगाल मानवसंसाधन समीक्षा समूह १९४० ने स्वाधीन बन्दोबस्त की निम्नलिखित दोषों का वर्णन प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी —

१. सम्पत्ति की अनिश्चितता—कृषि की उत्पादन क्षति में वृद्धि, कृषि के विस्तार एवं जन मरणा के घटने में होने वाली भूमि के मूल्य-वृद्धि में सरकार को कुछ भी नहीं मिल पाता। बन्दोबस्त स्वाधीन होने के कारण साधारण जमींदारों का मिल जाना है। इससे अनिश्चित जमींदारों की भूमि में शायद जाने वाले खनिज पदार्थ, मछली आदि के उत्पादक होने वाले जल स्रोतों का स्वयं हस्तगत करने का अधिकार रहता है और सरकार को किसानों की सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। उक्त समीक्षा में अनुमान लगाया था कि मानवसंसाधन का रकब के लिये निर्दिष्ट कर देने का कारण बंगाल सरकार को २ करोड़ से ८ करोड़ रुपये का क्षति होता है।

२. औद्योगिक उन्नति में बाधा—स्वाधीन बन्दोबस्त प्रारम्भ करने समय सरकार का यह भाव था कि जमींदारों अपनी बर्तनी हुई प्राप्ति का उत्साह प्रभाव में लगायेंगे, परन्तु उन्होंने इस शक्ति का दुरुपयोग किया और उद्योग प्रवर्धन में न लगाकर आमोद प्रमाद प्रभावपूर्ण आदि में व्यय करना प्रारम्भ कर दिया था।

३. कृषि की उन्नति में उद्दामीनता—स्वाधीन बन्दोबस्त करते समय यह भी भाव था कि जमींदारों द्वारा कृषि की उन्नति होगी और किसानों की विपत्ति हुई दशा में सुधार होगा परन्तु यह दुराशा मान सिद्ध हुई। अधिकतर जमींदारों ने भूमि एवं कृषि की उन्नति का भार नहीं धारण किया। वे केवल किसानों का ही जीवन व्यतीत करते रहे।

४. सरकार और किसानों के मध्य प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव—सरकार तथा किसानों के मध्य जमींदारों एक दलाल की भूमिका रहती है। इन सरकारों और किसानों में कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता जिससे सरकार किसानों की सामाजिक दशा में अनभिज्ञ रहती है।

५. भूमि सम्पत्तियों रकाजों का अभाव—इस अवस्था में भूमि सम्पत्तियों के रकाज नहीं रखे जाते हैं, इसलिए भूमि एवं कृषि सम्बन्धी प्रगति का ठान अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा किसानों का अधिकार का ज्ञान भी नहीं हो पाता है।

कमोशन द्वारा बनाय गये उक्त दोषों का अनिश्चित स्वाधीन बन्दोबस्त के कुछ अन्य दोष निम्नलिखित हैं —

६. कृषकों का शोषण—जमींदार कृषकों का नामा प्रकार में शोषण करते हैं। वे कृषकों में मनोमानी बनाय चलाते हैं तथा उनसे वसूल करवाते हैं। त्योहार

व विवाह आदि अग्रमरी पर किसानों को नजराना आदि देने के लिये विवश करते हैं। वे शहर में विनाशिता का जीवन व्यतीत करते हैं और बाँवों में उनके कारिन्दे और दुगान्न किसानों को नूतने हैं तथा उन पर अत्याचार करते हैं।

७. **मुन्दमेवाजी को प्रोत्साहन**—इस भूमि व्यवस्था की सुविधा जमींदारी और किसानों के मध्य बड़ी हुई मुन्दमेवाजी का मूल कारण है। जमींदार किसानों को सहायक करने की बात जगाने रहने हैं।

८. **सकट-काल में लगान की छूट आदि सुविधा का प्रभाव**—अस्थायी बन्दोवस्त में सरान या बाढ़ के समय पत्तल मूट हो जाने पर सरकार द्वारा मालगुजारी या लगान कम कर दिया जाता है अथवा माफ कर दिया जाता है, परन्तु स्थायी बन्दोवस्त में इस प्रकार की सुविधा का पूरणतया अभाव होता है।

९. **जन हित एवं सामाजिक कार्यों का प्रभाव**—अधिकांश जमींदार अपने लाभ के लिये ही अधिक इच्छुक थे और इस कारण इन्होंने जनता की भलाई के लिए पाठशालाएँ, औपचारिक आदि नहीं खुलवाये।

१०. **जमींदारी प्रथा के राजनैतिक लाभ की प्रभाव शून्यता**—जमींदारी प्रथा का राजनैतिक दृष्टि में जो लाभ था उसका अब कोई मूल्य नहीं रहा। प्रशासन में यहाँ के समय और उनकी राजभक्ति की आवश्यकता नहीं होती अतः, जन-साधारण के समर्थन और देश-वर्षा की आवश्यकता होती है।

अस्थायी बन्दोवस्त (Temporary Settlement)—यह भूमि-व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष वसूल की जाने वाली मालगुजारी एक निश्चित अवधि के लिए ही निर्धारित की जाती है। इस अवधि के समाप्त होने पर पुनः बन्दोवस्त किया जाता है। प्रत्येक नये बन्दोवस्त के समय भूमि की बड़ी हुई उत्पादन शक्ति के अनुसार लगान में वृद्धि कर दी जाती है। मिन मिन प्रान्ता में बन्दोवस्त की अवधि पृथक् पृथक् है। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में ४० वर्ष, मद्रास में ३० वर्ष, मध्य प्रदेश में २०-३० वर्ष परन्तु बन्दोवस्त किया जाता है। पंजाब को छोड़कर सभी प्रान्ता में अस्थायी बन्दोवस्त पाया जाता है। यह बन्दोवस्त तीन प्रकार का होता है—जमींदारी-प्रथा, महानवारी प्रथा और रूमवारी प्रथा।

अस्थायी बन्दोवस्त के गुण (Merits)

(१) **स्थायी बन्दोवस्त के दोषों का निराकरण**—इसमें वे सभी दोष नहीं पाये जाते हैं जो स्थायी बन्दोवस्त में पाये जाते हैं। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

(२) **भूमि के मूल्य की वृद्धि का मालगुजारी पर प्रभाव**—इस प्रथा में एक निश्चित अवधि में सरकार पुनः लगान निर्धारित किया जाता है। इससे प्रत्येक बन्दोवस्त के समय भूमि के मूल्य में का बड़ी वृद्धि के अनुसार मालगुजारी भी बढ़ाई जा सकती है। इस बड़ी हुई आय को सरकार समाज-व्ययण के कार्यों पर व्यय कर देता है।

(३) **किसानों द्वारा भूमि-सुधार के लाभों का उपयोग**—बन्दोवस्त के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसानों द्वारा लगाय हुए आम और पौधों से जो उत्पादन वृद्धि हुई है उसका लाभ उन्हें भी मिल सके।

(४) सरकार के कृषि-भूमि के ज्ञान में वृद्धि—इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों की कृषि भूमि का आबखाना होता—राजौनी, खमरा आदि गाँवों में किया जाता है। इससे अनिश्चित जमीन की भूमि का क्षेत्रफल एवं उसकी अनुमानित पैदावार का भी विवरण रहता पड़ता है। पटवारी इस कार्य को गाँव के मुखिया और मुख्तियार की सहायता में किया करता है। इससे सरकार को न केवल वसूल करने में सुविधा होती है बल्कि किसानों की भी वसूल करने में समर्थ भूमि गाँवों या पटवारी द्वारा वसूल किया जाता है। इससे न किसानों में नुकसान नहीं मिल पाता।

(५) जमींदार कृषकों का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते—इस व्यवस्था में जमींदार कृषकों का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि जमींदारों को जमीन अधिकार होने पर सरकार में भी मालगुजारी चलाया जाता है।

(६) राज्य पाल में मालगुजारी की वसूलियाँ छूट-कटौत या घाट में समान सरकार मालगुजारी में आबखाने के वसूलियों को भी कर देती है जिससे कृषकों का घाट नहीं उठाना पड़ता।

(७) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मालगुजारी का रजिस्टर में फेर—प्रत्येकी वसूलियों का एक नाम यह भी है कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार सरकार मालगुजारी की रजिस्टर में फेर कर कर सकती है।

अस्थायी वसूलियों के दोष (Disadvantages)

(१) बार-बार वसूलियों करने की जरूरत व खर्चा—अस्थायी वसूलियों को समय समय पर करने की जरूरत एवं व्यय इसका एक मुख्य दोष है।

(२) अस्थायी वसूलियों से होने वाले असम्यक्त लाभों का अभाव—इसमें अस्थायी वसूलियों से होने वाले असम्यक्त लाभों की कमी रहती है। किसानों का भय है कि उनका लगान नहीं बढ़ेगा और अगले वर्षों को उन्नत करने में लिये के विषय प्रयत्नशील नहीं रहेंगे।

(३) मालगुजारी की अनिश्चितता—अस्थायी वसूलियों से मालगुजारी निश्चित नहीं होती और समय समय पर बदलती रहती है।

(४) वसूलियों के समय मालगुजारी में अनुचित वृद्धि—जिसे प्राप्त में वसूलियों ३० वर्षों बाद होता है तो किसी में २० वर्षों बाद और किसी में १० वर्षों बाद। यदि वसूलियों ऐसे वर्षों पर होता जहाँ फसल अच्छी हुई है तो किसानों पर मालगुजारी बहुत बढ़ा दी जाती है और अगले वसूलियों के समय तक उन्हें उतनी ही मालगुजारी देनी पड़ती है, चाहे पैदावार कम हो या अधिक।

(५) वसूलियों-विभाग में अछूत-विभाग—इस प्रथा का मुख्य दोष यह है कि वसूलियों विभाग में वसूलियों के समय लगान वृद्धि का भय होता है और किसानों को सताते हैं, उनसे भूगर्भ में लिया करत के तथा उन्हें अपने अपने और अन्य द्वारा बर्बाद गई उत्पादन क्षमता का लाभ नहीं मिलने के हैं। परन्तु आखिर इस दोषों को बहुत कुछ अंश में दूर कर दिया गया है। इसी से यह प्रथा सर्वप्रिय बन गई है।

[५] जुताई-प्रथा (Cultivating Tenures)—यह सब हमने भारत में स्वामित्व प्रथा के अन्तर्गत प्रचलित भू-धारण मालगुजारी पद्धतियों का विवेचन

किया है। अब हम जुलाई प्रथा के अन्तर्गत प्रचलित कृषकों के भूमि-गन्धर्वी अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारत में कृषि प्रांतीय विषय है अर्थात् इसका सञ्चालन एवं निबन्धन प्रांतीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। अतः विभिन्न प्रांतों के विभिन्न समय पर प्राप्त किए गए भू-धारण एवं मालगुजारी कानून अर्थात् कानूनकारी कानून (Laws) कृषकों के कामूनी अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। यहाँ सब प्रांतों के कारनकारी कानूनों के अन्तर्गत दक्षिण कृषकों के अधिकारों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। अतः पाठक-गण इस विषय की जानकारी आगे 'उत्तर प्रदेश की मालगुजारी प्रथा' के विवरण में कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश में भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा

(Land Tenures in U. P.)

सन् १९५२ के पूर्व तक की दशाः स्वामित्व वाली मालगुजारी प्रथाएँ (Proprietary Tenures)

स्वामित्व वाली मालगुजारी प्रथाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथाएँ प्रचलित हैं—(१) जमींदारी प्रथा तथा (२) महाजारी या सयुक्त ग्राम्य प्रथा। उत्तर प्रदेश में रैयतदारी प्रथा नहीं है।

(१) जमींदारी प्रथा (Zamindari System)—उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा बाराणसी जिल्लेजनों और अवध में प्रचलित है। बाराणसी जिल्लेजनों में म्यादी बन्दो-बस्त है और अवध में ताल्लुकेदारों के साथ मालगुजारी बन्दोबस्त है।

अंग्रेजों की देश के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित मालगुजारी प्रथाओं का उस समय ज्ञान न था और वे बंगाल का स्वामी बन्दोबस्त को ही अन्य प्रांतों में स्थापित करना चाहते थे। इसलिए सन् १७६३ ई० में उन्होंने बंगाल में जिल्लेजनों का पथन प्रारंभ करने के लिये कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर उनका भूमि में स्वामित्व का अधिकार दे दिया और साथ ही वे उनकी मालगुजारी मदा के लिये निश्चित कर दी प्रथा उनसे प्राप्त स्थायी बन्दोबस्त कर दिया। अब वे ही उत्तर प्रदेश में केवल बाराणसी जिल्लेजनों में ही जमींदारी प्रथा स्थायी बन्दोबस्त के रूप में प्रचलित है।

अवध में सरकार ने मालगुजारी भुगतान के लिये ताल्लुकेदारों में अन्धकारीय या प्रस्थापित सम्झौते किए। अतः, प्रथम में मालगुजारी-भुगतान का उत्तरदायित्व ताल्लुकेदारों पर होता है जो कृषकों में लगान समुदाय के रूप में व्यवस्था और कुछ भाग अपने लिये समुदाय को यह शक्ति है कि वह कर अपने सरकार को मालगुजारी का एक मनु देवे हैं। इन ताल्लुकेदारों का जमींदारी की भाँति भूमि पर कुछ भी अधिकार नहीं होता है। उनका कार्य तो केवल किसानों में लगान समुदाय के रूप में है। ताल्लुकेदारों के साथ मालगुजारी बन्दोबस्त प्रायः ३० वर्ष के लिये ही किया जाता है।

(२) महाजारी या सयुक्त ग्राम्य प्रथा (Mahalwari or Joint Village System)—बाराणसी-जिल्लेजनों और अवध में छोटे कर पेल उत्तर प्रदेश में महाजारी या सयुक्त ग्राम्य प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा में ग्रामजनों गाँव की भूमि के महाजारी ग्रामों में मिल कर सरकारी मालगुजारी के भुगतान का दायित्व एवं सामूहिक रूप में उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। व्यवहार में गाँव वालों का प्रतिनिधि जिसे लम्बेद्वार या मालगुजारी कहते हैं, सरकार में सम्झौता करता है। महाजारी का

साम्बरदार अपने मकाल व निमानों में जंगल समूह करने उसमें न कुछ प्रतिशत काट कर मासगुजारी मन्वजारी खजाने में जमा कर देता है। इस प्रकार लगान योग्य मासगुजारी का प्रत्येक वर्ष का आय है। इस प्रणाली में लगानों का वितरण हुआ है जो प्रायः २० या ३० साल के लिये होता है।

मुताई की मासगुजारी प्रणाली (Cultivating Tenures) — उत्तर प्रदेश के सन् १८३६ के नया नवारी कानून (Lachow Act) के अनुसार निम्न प्रकार के कृषक माने गये हैं —

(१) स्थायी मध्यस्थ निमान (Permanent Tenure Holders) — ये वे निमान हैं जो स्थायी व दोबारा के समय में ही लगानों को वसूल कराने का अधिकार रखते हैं। ये निमान पट्टे व फलानों के लिये जंगल पर रखी करने का अधिकार नहीं रखते हैं और जो जमींदार व वास्तविक निमान के लिये भूमि में सम्बन्ध होते हैं। इनका अधिकार दोबारा की जाने वाली जमीन है और उनका हस्तान्तरण हो सकता है। वे अपनी जमीन पर कर देने के लिये निरवरोध रख सकते हैं। इस प्रकार के कृषक वाराणसी जिला, बाजौर, गोरखपुर और आजमगढ़ के जिला में पाये जाते हैं।

(२) स्थायी मासगुजारी दर वाला निमान (Fixed rate Tenants) — ये स्थायी मध्यस्थ निमानों के लिये जंगल होते हैं जो निरवरोध मासगुजारी भी मकाल के लिये निश्चित होती है और इनकी भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार होता है। परन्तु भेद यह है कि ये जमींदार और निमान के बीच मध्यस्थ न होकर स्वयं कृषक होते हैं।

(३) पूर्ण स्वामित्व वाले निमान (Ex Proprietory Tenants) — ये वे कृषक हैं जो पट्टा भूमि के वास्तविक स्वामी के लिये भूमि उनका भूमि का स्वामित्व हाथ में निकल जाने से कानून द्वारा उन्हें और परन्तु करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इनका अधिकार पट्टा होता है और इनका स्वयं लगान देना पड़ता है।

(४) अधिपति के विशेषाधिकार वाले निमान — सन् १८८६ के अधिनियम के अन्तर्गत के पट्टा होने से पूर्व से ही कुछ निमानों के लिये ये अधिकार बन चुके हैं जो वहाँ के मौज्दमी किसानों के हैं। इन कुछ विशेष निमानों में भूमि निरवरोध भी जो उन्हें दशाब्दी में अधिकार उनके अधिकार में चली आ रही है।

(५) मौज्दमी किसान (Occupancy Tenants) — जो निमान बारह वर्ष तक निरंतर एक ही भूमि में जोतता रहे वह मौज्दमी किसान हो जाता है। लगान देने करने पर इसे बदलने नहीं कराया जा सकता। इनका लगान केवल व मौज्दमी के समय ही घटाना घटाया जा सकता है।

(६) वैतनिक निमान (Hereditary Tenants) — ये वे वैतनिक निमान (Statutory Tenants) हैं जो उ० प्र० वास्तविकी कानून सन् १८४० के अन्तर्गत वैतनिक निमान बना दिये गए हैं। वैतनिक निमान मौज्दमी निमानों से भिन्न हैं क्योंकि ये दोनों मकाल प्रत्येक वर्ष में लगान देते हैं।

(७) गैर मौज्दमी निमान — ये सामान्यतया जमींदारों की और या कुछ काश्त भूमि जोतते हैं। इनका लगान जमींदारों की मुविधानुसार घटाना घटाया जा

सकता है और इन्हें सुगमता से बेदखल किया जा सकता है। इन किसानों की शायिज दशा शोचनीय है।

(८) शिकमी-दर शिकमी किसान (Subtenants) — ये वे किसान हैं जिनके पास अपनी निज की भूमि नहीं होती है बल्कि दूसरे किसानों की भूमि बटाई या निश्चित लगान पर जोते हैं। यह लगान घटाया-बढ़ाया जा सकता है और इन्हें आसानी से बेदखल भी किया जा सकता है। इन किसानों की दशा शायिज दयनीय है।

वर्तमान भू धारण एवं भालगुजारी प्रथा

सन् १९५० के उत्तर प्रदेशीय जमींदारी उन्मूलन कानून के अनुसार १ जुलाई १९५२ को उत्तर प्रदेश के २० लाख जमींदार अधिकार ख़ुद कर दिये गये। पसल अब उक्त कानून के अन्तर्गत निम्न प्रकार के किसान पाये जाते हैं :—

१. भूमिधर (Bhumidhar) — उक्त कानून के लागू होने के ठीक पूर्व के जमींदार आदि जो सरकार और बिनाल के बीच में मध्यस्थ थे, जिनके पास बाग, छद काश्त न और की भूमि की तथा जिन्होंने शायिज लगान का दस गुना रुपया 'जमींदारी उन्मूलन बोर्ड' में जमा करा दिया है, वे भूमिधर होंगे। इनका भूमि पर स्थायी, बस-परम्परागत तथा हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। वे भूमि में हदमें नहीं जा सकते। अभी तक जो लगान वे देते हैं उसका आधा लगान ही इन्हें देना पड़ेगा और ४० वर्ष तक यह बदला नहीं जायगा। वे अपनी भूमि का इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु वे अपनी भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकते जिनके पास पहले से ३० एकड़ या उससे अधिक भूमि हो।

२. सीरदार (Sirdar) — इस कानून के लागू होने के ठीक पहले जिन किसानों को मोहसी अधिकार प्राप्त थे जिन्होंने भूमिधर एवं प्राप्त नहीं किया है, वे सब सीरदार बना दिये गये हैं। इनका भूमि पर स्थायी बस-परम्परागत अधिकार होगा पर वे भूमि को न तो बच सर्वे न बचक पर ही रख सकते। य भूमि को अपनी पस उलट करके तथा पशु पालने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं ला सकते। सीरदारों को अब जमींदारों को लगान देने की आवश्यकता नहीं, अब वे सीधे सरकार को लगान देंगे। कोई भी सीरदार यदि लगान का दस गुना सरकार को दे देगा तो वह भूमिधर बनने का अधिकारी हो जायगा।

३. आसामी (Assami) — इस कानून के लागू होने के ठीक पूर्व के किसान जो किसी बाग के शिकमी काल्पकार थे, जो स्थायी भूमि को जोते थे, जो किसी भूमिधर या सीरदार की भूमि पट्टे पर जोते थे तथा जिस सीरदार ने उनके पास भूमि रखी थी, आसामी कहलायेंगे। आसामी किसानों का अधिकार मोहसी होता है परन्तु यह स्थायी नहीं होता है।

४. अधिकारी (Adhvasi) — इस कानून के लागू होने के ठीक पहले जो व्यक्ति किसी बाग को भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि का शिकमी काल्पकार था या जो संरक्षक-काल्पकार था, वह अधिकारी बन गया। इनकी पाँच वर्ष तक भूमि अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है। कानून लागू होने के पाँच वर्ष के भीतर अपने लगान का गहरा गुना देने पर वे किसान भूमिधर बन सकते हैं।

जमींदारी प्रथा का जन्म एवं विकास तथा उन्मूलन

जमींदारी प्रथा का जन्म एवं विकास—भारतीय इतिहास का अध्ययन यह बताता है कि जमींदारी प्रथा का प्रादुर्भाव मुगल राज्य-काय में ही हुआ। मुगल साम्राज्य के अन्तिम सम्राट साहू शासन में सन् १६६१ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दोपानी अर्थात् मान्युजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बम्बोनी ने मान्युजारी वसूल करने का काम कुछ डेरेदारों को दे दिया। ये लोके नौनाय होने थे और दोनों लगता था। डेरेदार किसानों से सममाना लगान वसूल करते थे और सरकार को भी अनिवार्य रूप से मान्युजारी के रूप में मिलती थी। सन् १७६३ ई० में जब सार्द कार्नवालिस भारत में गवर्नर-जनरल बन कर आया तो उसने लगान वसूल करने वाले डेरेदारों (Revenue Farmers) को भूमि का स्थानीय मान लिया और इनसे वसूल को जाने वाली मान्युजारी को राशि सदा के लिये निश्चित कर दी और साथ ही उसे अपरिवर्तनीय भी घोषित कर दिया। इस प्रथा का क्याई बम्बोवस्त कहा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्राप्त हो गई और इंग्लैंड को भू-पद्धति के अनुसार भारतवर्ष में भू-स्वामियों का एक प्रभावशाली वर्ग उत्पन्न हो गया और कृषकों के सिर पर सदा के लिये जमींदार वर्ग लाद दिया गया।

जमींदारी प्रथा के दोष—इसी घण्टा में चौखे इनका विरोध किया जा चुका है। अतः पाठक-गण उन्हें गया-भ्यान पर देख लें।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन—जमींदारों के घत्याचारों ने जमींदारों के इन दोषों को और भी तीव्र बना दिया और इसलिये इस प्रथा का घोर विरोध किया जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जमींदारी उन्मूलन को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया। सन् १८३८ ई० में बंगाल सरकार ने मान्युजारी तथा स्थायी बम्बोवस्त की जाँच के लिये सी० एफ० एन० सी० पनाउड की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के बहुमत की यह राय थी कि जमींदारी प्रथा के दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय उसका उन्मूलन है। कमीशन ने यह भी राय प्रकट की कि जमींदारों को मुद्रावजा भी दिया जाए। कमीशन के सदस्यों में मतभेद होने के कारण मुद्रावजे की दर निर्धारित नहीं की जा सकी, परन्तु यह अनस्य स्पष्ट कर दिया गया कि मुद्रावजा नन्द स्थायी में या अन्वेषणी बॉन्डो में दिया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट पनाउड कमीशन ने सन् १८४० ई० में प्रस्तुत की और तभी से उन प्रांतीय सरकारों के जिनमें जमींदारी प्रथा प्रचलित है, जमींदारों उन्मूलन के निश्चय को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

जमींदारी उन्मूलन में कठिनाइयाँ—जमींदारों उन्मूलन का विज्ञान राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया जाने पर भी इस देश में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इसमें पहली कठिनाई यह है कि मुद्रावजे के लिये एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। मुद्रावजा देने के लिये लगभग ३४० करोड़ रुपये की धन-राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। प्रांतीय सरकारों के लिये इतनी बड़ी राशि को प्राप्त करना एक बड़ा कठिन कार्य है। दूसरी कठिनाई जमींदारों ने उत्पन्न की। उन्होंने इसका घोर विरोध किया और उन्मूलन कानूनों के पास होने में अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं। स्वीकृत उन्मूलन कानूनों को रद्द कराने के लिये उन्होंने सर्वोच्च

यायालय (Supreme Court) में प्रपीत की, परन्तु वहाँ भी इन्हें असफलता ही मिली।

जमींदारी उन्मूलन कानून—भिन जिन रा.या.म. भिन भिन जमींदारी उन्मूलन कानून पास किए गए हैं जिनका सक्षम में वर्णन किया जाता है —

उत्तर प्रदेश—जमींदारी उन्मूलन वि.जो.ग. १९५० में प्रस्तुत किया गया था उस उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने १० जनवरी १९५१ ई० को पास कर दिया और २४ जनवरी १९५१ का भारत का राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विधान १ जुलाई १९५२ ई० में लागू उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

कानून की विशेषताएँ—इस कानून की विभिन्न विधेयताएँ हैं।

(अ) इस कानून में अनुसार जमींदार का दो सौ बीघे भूमि तथा देकर अधिकार हटा कर दिया जायगा। सत्र सड़ जमींदार का उनकी व्यक्तिगत भूमि की कुल राशि तथा सबसे छोटा को दो सौ भूमि राशि सुधारने में स्व.भ. दे दो जायेगी।

(आ) जमींदारी उन्मूलन कोष की स्थापना—जमींदारों का भुसान्न के रूप में देने का नियम १७४ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया। इस बड़ी राशि को इकट्ठा करना एक बड़ा कठिन काम है। इस कठिनाई को हल करने के लिए इन्का का विषय यह आनपण रखा गया है कि जो कृषक अपने व्यक्तिगत भूमि की दो सौ भूमि राशि एक साथ इस कोष में जमा कर देगा उसे भूमि अधिकार नूतनी अधिकार प्राप्त हो जायगा। इस कोष में अभी तक ३५ करोड़ रुपये ही जमा हो सके हैं। इस व्यक्तिगत भूमि का प्यारह भूमि राशि जमा कराने पर भूमि अधिकार प्राप्त हो सके हैं।

(इ) विभिन्न प्रकार के कृषकों के अधिकार—इस कानून में अलग-अलग प्रकार के कृषकों का वर्णन है—भूमि अधिकार सारदार आसामी और अधिकारी। इनका भिन्न-भिन्न विवरण पत्र दिया जा रहा है।

(ई) कृषक स्वामित्व का समाजिककरण—सर्वकार विभिन्न विधेयताओं को अभी भी प्रमुख समाज के अधिकार में ला सकी है—(१) किस खेत या बाग को छोड़ कर बाग सभी भूमि (२) गांव की सामाजिक अधिकार स्थित सभी जंगल (३) खेत बाग या आवासीय पैदा के अधिकार सभी पर (४) मात्रात्मक रूप (५) भूमि अधिकार (६) हाथ बाजार (७) सामाजिक पोषक व्यक्तिगत मात्रा जंगल वनस्पति और आवासीय के रूप में।

(अ) सहकारी कृषि की अवस्था—इस कानून में अत्यंत सामाजिकता ३० एकड़ में अधिक बड़े भूमि में मात्र जिसमें भी जमादारी प्रथा पुनः स्थापित न हो सके। सहकारी कृषि (Cooperative Farming) का प्रस्तावना देन के नियम यह रूप रख दी गई कि कोई दस भूमि अधिकार या सौंदर्य जिनमें मात्र १० एकड़ या उससे अधिक भूमि हो सके भूमि का एक सहकारी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसे सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार करा सकते हैं। इससे फलस्वरूप प्राथमिक तथा वैधानिक दशा से खेती हो सकती। भविष्य में अनाधिकारिता (Uneconomic Holding) की कृषि का रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिये गए हैं। भविष्य में खेत ६१ एकड़ में कम के नए हान चाहिए।

(४) अन्य महत्त्वपूर्ण बात—(१) जमींदारी समाप्त होने पर तब सब जमादारों को जो १० हजार रुपये वापिस तब मानपुजारी दत्त है पुनर्निवास सहायता (Re-habilitation Grant) भी मिलेगी । जो जमींदार २५० रुपये वापिस या कम वर्य मानपुजारी देने है । उक्त वापिस धन की बीस गुनी पुनर्निवास सहायता भी जायगी । जैसे जैसे धन भविष्य होय यह सहायता भी कम होनी जायगी । (१) जिस दिन में जमादारियों समाप्त हुंया उनो दिन में मुआवजा (क्षति पूति) व पुनर्निवास सहायता की शर्ति पर २३ के हिसाब से जमादारों को भुगत दिया जायगा । जमींदारों को मुआवजा २० १० ५०० १००० ५००० और १०००० रुपये के टाइट में दिया जायगा जो बने नही जा सकत । इन टाइट की दर्या ४० वष की होगी और इनका रुपया बिना में गुनाया जायगा । (३) जमादारों को मुआवजा दव समय सभी सरकारों कर काट मिल जायगा । (४) जमादारों तब से होत का तारीख से बिना भा समय किमा को बढ़ात करन के नियम यदि कोई जमादार प्रायना पत्र देगा ता जमातय उन पर कोई बिना नही करेगा । (५) जो जमात समय पर जमाना देगा तो उसकी गिरनारी को जा सकैगी और उसकी प्रचल सम्पति तोलाव कर रकम कर्ज की जा सकैगी ।

वातून का समालोचना (Criticism)—इसके समर्थका का कहना है कि यह वातून जमींदारी प्रथा को गान्तिपूजन समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है । इनके विपरीति समालोचना (Critics) का कहना है कि जमींदारी का समाप्त होत ना सिद्धान्त बुनियादी तौर पर गलत है । इसमें निश्चय शरितिकता इसका का लाभ नही होगा बघावि भूमिधरों के बिगड़ उनको भ्रष्टारण अधिकार प्राप्त होना बदन कठिन होगा । इस प्रकार के व्यवस्था बना जमानार प्रथा को समाप्त कर छोटा जमादारी प्रथा की स्थापना करती है । बिना भूमि के राज्य सरकार के सिद्धान्त को अपनाय भारतीय बुद्धि में कोई आन्तिवारी परिवर्तन होना सम्भव नही । परन्तु इसका हम वातून में पूरणतया शक्य है । निश्चय रूप से वातून के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि इसका निर्माणाभा में देश काल क अनुसार जो मध्यमार्थ का अन्तस्मयन लिया है वह उचित ही प्रतीत होता है ।

वर्गाल—सन् १९४७ ई० में वर्गाल की विधान सभा ने दो वर्गाल लक्ष एनवाजोगन तथा टिन ती एक्ट पास किया । इस वातून के अन्तगत कर्मज जमीन वाले प्रदेशों के भू-स्वामियों के अधिकारों को खर देने की व्यवस्था है । किसानों का बचन एक बा हो रहेगा और उक्त शोशी अधिकार प्राप्त होगा । जोन का अधिकतम धन फल ६० बीघा या परिवार व प्रति मन्स्य व पीछे २ बीघा के हिसाब से हो सकेंगा ।

मद्रास—मद्रास में दो प्रकार की भ्रष्टारण एवं मानपुजारी प्रथा प्रचलित है—जमींदारी और रंयतवार । जमींदारी शर्िक विषय में दो वातून अब तो विराप्य कम करने के लिये और दूसरा सम्पत्तियों का अन्त करन और रंयतवारी प्रथा समाप्त करने के लिये पास किया गया । दूसरे वातून के अनुसार सरकार का अधिकार २५०० जमींदारी प्रथा वाली सम्पत्तिया तथा २५०० इनाम वाली रंयतवारी पर हो गया । इन सबका अथफल १४ लाख एकड़ है । क्षति पूति अर्थात् मुआवजा में लगभग १२३ करोड़ रुपये देना पडा । जो किमान भूमि को ५ वर्षों से जोतते पाय है उन्हें समुधर अधिकार उस भूमि में दे दिया गया है ।

बम्बई—बम्बई सरकार ने भागदारी और गन्तुदारी प्रथाओं का अन्त करने के लिये सन् १९४८ में कानून पास किया जिसके अन्तर्गत (अ) एक प्रकार के सुरक्षित किसानों का वर्ग बन गया है, (आ) किसानों को वेदखत करने पर बर्द प्रतिनित्य लगा दिये गये हैं, (इ) सहकारी-कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बर्द प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, आदि ।

मध्य प्रदेश—मध्य प्रदेश में मानसुजारी प्रथा का अन्त करने के लिये सन् १९५० में एक कानून पास किया गया । क्षति-पूर्ति के रूप में वार्षिक छुट्टी छाप की दम तुनी राशि दी जायगी और छोटे मानसुजारी को पुनर्स्थापन सहायता भी दी जायगी ।

मध्य भारत—जमींदारी प्रथा का अन्त करने के लिये मध्यभारत सरकार ने सन् १९५१ ई० में एक कानून पास किया । मुसाबजे के रूप में उनकी वार्षिक छाप की दम में २० तुनी राशि दी जायगी । जिन जमींदारों को छाप ३५०० रु० से कम है, उन्हें पुनर्स्थापन सहायता भी दी जायगी । यह राशि १५ किस्तों में चुकाई जायेगी ।

राजस्थान—सन् १९५२ में भूमि सुधार एवं जमीर पुनः प्राप्ति कानून (Land Reforms and Resumption of Jagirs Act) पास किया गया, जिसके अन्तर्गत उन जमींदारों की जमीनों से भी जायगी जिनकी जमीर की वार्षिक छाप ५००० रु० से अधिक है । ऐसे जमींदारों की मर्यादा रु०= है तथा जिनका क्षेत्रफल पाँच करोड़ बीस लाख एकड़ है । इसमें राजस्थान सरकार को लगभग १ करोड़ रुपये की छाप में वृद्धि हुई जायेगी ।

जमींदारी उन्मूलन से लाभ (Advantages)—जमींदारी उन्मूलन से निम्न लिखित लाभ होंगे —

(१) भूमि किसानों की हो जायेगी जिसमें किसान भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । (२) जमींदार जो सरकार और किसान के बीच में निरपेक्ष का मध्यस्थ या हट्टा दिया गया है और अब उसके द्वारा किसानों का दोषपूर्ण वश हो जायगा । (३) भूमिपरो की लगान घाटा रह जायगा । (४) अब किसानों की लागे एक बेगारे बन्द हो जायेंगी । (५) इसमें महंगारी-कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और भूमि-अपव्यवहन की प्रवृत्ति भी रुक जायेगी । (६) राज्य की छाप में वृद्धि होगी । (७) जमींदारों की जो मुसाबजे धर्मात् क्षति-पूर्ति को रकम मिलती उसमें उद्योग-प्रगति खोल जा सकेंगी । (८) जमींदारों की अपक्षा लगान बसूनी में कमी या भागी करने में सरकार ब्रह्म शक्ति उदार होगी है ।

जमींदारी उन्मूलन में हानियाँ (Disadvantages)—जमींदारी उन्मूलन में विरोधी दल द्वारा निम्नलिखित हानियाँ बताई जाती हैं —

(१) जमींदारों की आर्थिक हालि पड़नेगी । (२) जमींदारी उन्मूलन में सत्ताओं जमींदार, गन्तुदारी तथा उनके वारिन्धे प्रादि सब बेकार हो जायग जिनमें बेकारी की समस्या भवकर रूप धारण कर लेगी । पर हमने विद्द यह कहा जा सकता है कि जब कभी भी परिवर्तन होता है उसमें कुछ न कुछ हानियाँ प्रदश्य होती हैं । जमींदारी उन्मूलन में बहुत छोटे व्यक्तियों की हालि पड़नेगी पर लाभ उमम कहीं अधिक व्यक्तियों का होगा । बेकारी भी सामयिक होगी क्योंकि लगान बसूनी तथा छाप बापों के लिये राज्य सरकारों की कर्मचारियों की आयव्ययता होगी जिनमें बहुत से

व्यक्तियों को नौकरियाँ मिल जायेंगी । जमींदारों की मुद्राबन्दी को स्वयं मिनेगी जिसमें वे अन्य लाभदायक कार्य कर सकते हैं ।

(३) जमींदारों की धार में यह भी कहा जाता है कि जमींदारी सम्पत्ति में किसानों को अन्य कई बातों की हानि होगी । इन समय किसान जमींदारों में स्वयं उत्पन्न करने हैं, यह सुविधा फिर उपलब्ध नहीं हो सकेगी । इनके प्रतिरूप जमींदार समान समूहों में इतनी शक्ति का प्रयोग नहीं करने विवश कि सरकार स्वयं उत्पन्न करने में करती है । इसके विपक्ष यह कहा जा सकता है कि कृषि प्राप्त करने के अन्य बहुत से साधन उपलब्ध हो सकते हैं । जमींदारों की शक्ति समान समूहों में शक्ति का मार्ग करने में सरकार बहुत उत्तरदायी है ।

आदर्श भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा के लक्षण (Essentials of an Ideal Land Tenure)—आदर्श भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा में निम्नलिखित गुण होने चाहिये :—

१. उचित लगान (Fair Rent)—लगान उचित होना चाहिये । भूमि की उत्पादन शक्ति के अनुसार निश्चित लगान ही उचित माना जाता है । लगान या मान गुजारी देने के लक्ष्य के रूप में यह ध्यान रखना चाहिये कि वे भरण भोजन कर सकें । मसू, पैदावार का ३०-४० प्रतिशत ही लगान या मालगुजारी के रूप में लेना चाहिये । सर्वोच्च लगान भूमि की उन्नति में बाधक सिद्ध होता है ।

२. भू-धारण अधिकार की स्थिरता (Fixity of Tenure)—उपरोक्त के भूमि में अधिकार स्थायी, पक्का एवं हस्तांतरण योग्य होने चाहिये । उपरोक्त की भूमि से पैदावारी का भय नहीं होना चाहिये । यदि ऐसा रहेगा, तो किसानों की रचित भूमि-उन्नति में न रुकती ।

३. लगान-संग्रही का ढङ्ग (Method of Rent-Collection)—लगान-संग्रही का ढङ्ग सरल एवं सुगम होना चाहिये जिससे किसानों को कोई बर्झाई न उठानी पड़े । संग्रह करने वाला का व्यवहार उपरोक्त के माध्यम और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये । लगान-संग्रही में अधिक व्यय भी नहीं होना चाहिये ।

४. लगान से राज्य को निश्चित आय की प्राप्ति तथा रोजगार की सुदृढ़-हाली (Definite Revenue to Govt. and Prosperity to People)—लगान-प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये कि राज्य को प्रति वर्ष निश्चित आय प्राप्त होती रहे और किसान सुखान रहे ।

५. भूमि का हस्तांतरण सम्भव हो सके (Transfer of Land may be possible)—भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा ऐसी होना चाहिये कि जिसके अन्तर्गत भूमि सुगमता से हस्तांतरित की जा सके, अथवा वह संदेश प्रकृत रूपों में जोती जावेगी ।

६. पैदावार वृद्धि पर विशेष रियायत—यदि कोई कृषक अपने प्रयत्नों से भूमि की उत्पादन में वृद्धि करे, तो मालगुजारी प्रथा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उस पर मालगुजारी कटौती जाय और इन प्रयत्नों के उपलब्ध में उसे कुछ विशेष रियायतें मिलनी चाहिये ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि व्यवस्था का क्या रूप हुआ है ?

२—मालगुजारी प्रथा की आदर्श प्रणाली का उल्लेख करिये। वर्तमान मालगुजारी प्रथा की भूमिधारी प्रथा वहाँ तक आदर्श प्रणाली है ?

३—भारत में मालगुजारी के स्थाई बन्दोबस्त के कुछ दोष बताइये। क्या आपकी राय में इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है ? (रा० बो० १९५३)

४—भूमि की आमाओ प्रथा की आदर्श प्रणाली के नियमों का उल्लेख कीजिये। भूमिधारी प्रथा कहाँ तक इन आदर्श प्रणाली के अनुकूल है ? (अ० बो० १९५७)

५—भारत में जमींदारी उन्मूलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिये।

(अ० बा० १९५४)

६—रैयतवारी प्रथा के गुण-दोष बताइये।

(अ० बो० १९४६)

७—स्वाई घोर ब्रह्मादे बन्दोबस्त पर नोट लिखिये। (अ० बा० १९५०, ४४, ४२)

८—जमींदारी और रैयतवारी प्रथा के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिये।

(अ० भा० १९५३)

९—भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित मालगुजारी प्रथाओं का उल्लेख करिये।

(पत्राव १९४८)

१०—जमींदारी उन्मूलन में भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(दिल्ली हा० से० १९४६)

११—नोट लिखिये—

जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन

(रा० बा० १९५६)

इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ

१२—जमींदारी प्रथा का क्या दोष है ? इनके दूर करने के निम्न सुझाव दीजिये।

(अ० बा० १९४२)

मजदूरी (भृति) का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Wages)—मजदूरी (भृति) मजदूर या श्रमिक द्वारा विद्यमान धर्म का एक प्रकार से मूल्य है। प्रत्येक उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के विविध मापनों का सहयोग आवश्यक होता है। उत्पत्ति के साधना में एक साधन 'धर्म' भी है। अस्तु, उत्पादन-कार्य में लगे हुए श्रमिकों को उनके धर्म के प्रतिफल में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे मजदूरी या 'भृति' कहते हैं। प्रो० जोड के अनुसार मजदूरी वह पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को उसके धर्म के प्रतिफल में दिया जाता है जिसे साहसी (Entrepreneur) अपने उत्पादन कार्य में लगाता है। अन्य शब्दात्मक, मजदूरी या भृति राष्ट्रीय भाग (National Dividend) का वह भाग है जो श्रमिकों को उनके धर्म के प्रतिफल में दिया जाता है।

मजदूरी और वेतन में अन्तर—आपारण जोन चान में मजदूरी वेतन उसी पुरस्कार या पारिश्रमिक को कहते हैं जो हाथ-पैर की शारीरिक मजदूरी करने वाला को मिलता है, दिमागी श्रम या प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करने वाला के पुरस्कार को वेतन (Salary and Pay) कहते हैं। परन्तु श्रमशास्त्र में ऐसा कोई अन्तर नहीं है। सब प्रकार के धर्म के प्रतिफल में मिलने वाली धन-राशि को 'मजदूरी' (Wages) कहते हैं। चाहे धर्म शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे उच्चोत्थि का हो, चाहे अशिक्षित श्रमिक का, चाहे उसमें भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति हो, चाहे भौतिक वस्तुओं श्रम या संपत्ति की उत्पत्ति हो—प्रत्येक प्रकार के धर्म के लिये दिये गये पुरस्कार को श्रमशास्त्र में मजदूरी (भृति) कहते हैं। उदाहरणार्थ, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भी उन्हीं प्रकार मजदूरी है जिस प्रकार कि किसी कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का पारिश्रमिक है। अस्तु, श्रमशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। दोनों ही मजदूरी के अन्तर्गत आते हैं।

प्रायः मजदूरी और वेतन में सामाजिक पद एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से अन्तर किया जाता है। वेतन अधिक होता है और मजदूरी कम। वेतन मासिक प्रथम वार्षिक होता है जबकि मजदूरी दैनिक साप्ताहिक श्रम या पारिश्रमिक होता है। श्रमिक का स्तर समाज में कुछ उछाल प्रतीत होता है जबकि वेतन पाने वाला का बड़ा सम्मान होता है। मजदूरी शब्द का प्रयोग श्रमिकों के सम्बन्ध में किया जाता है जो समाज के निम्न-स्तर में सम्मिलित होते हैं जबकि वेतन शब्द का प्रयोग अध्यापक, वकील,

प्रबंधनकर्ता या संचाली अधिकारियों के सम्बन्ध में किया जाता है जो समाज के उच्च स्तर में सम्मिलित होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वेतन शब्द केवल सामाजिक प्रतिष्ठा का चेतक है अथवा दोनों में कोई छत्तर नहीं है।

मजदूरी की समस्या का महत्त्व (Importance of Problem of Wages)—वर्तमान औद्योगिक काल में उत्पत्ति के मुख्य पाच साधनों का बड़ा महत्त्व है। इन्हीं के भूयुक्त प्रयत्न द्वारा आज की उत्पादन व्यवस्था स्वर है। उत्पत्ति के समस्त साधनों में श्रम एक ऐसा साधन है जिसमें मानवीय तत्व (Human Elements) विद्यमान हैं। यद्यपि इस पर धार्मिक सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक आदि सब ही बातों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसलिये इसके धार्मिक अर्थ में मजदूरी के उचित निर्धारण की समस्या बाल्य में वितरण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसके समाधान पर लोकोट्टा धर्मिका का बहिष्कार और मृत्यु तथा समाज की गति और समृद्धि निर्भर है। परन्तु हम देखते हैं कि आज का श्रमिक वर्तमान धार्मिक मंडल में अत्यन्त अन्याय में है। अतः जब हमें उस अवसर मिलता है वह स्पष्ट होकर प्रकट होता है। यही कारण है कि सरकार और प्रबंधकारी आज इस समस्या का समाधान पर विचार विमग्न हैं।

श्रम की विशेषताएँ (Peculiarities of Labour)—श्रम का मूल्य (मजदूरी) का निर्धारण एक जड़ वस्तु के मूल्य निर्धारण से भिन्न है क्योंकि श्रम में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो श्रम वस्तुओं में नहीं पाई जाती हैं। अतः मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत के अध्ययन में पुनः इनकी जानकारी आवश्यक है। ये विशेषताएँ निम्न लिखित हैं—

१. **श्रम नाशवान है (Labour is perishable)**—श्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नष्ट होने वाली वस्तु है और इसलिये दूसरी वस्तुओं की भाँति इसका मूल्य सम्भव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रमिक का जितना समय व्यय होता जाता है प्रयत्न वह जितने समय के लिए बेकार रहता है वह उसी के लिए नष्ट हो जाता है क्योंकि बीना हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। श्रम वस्तुओं का मूल्य यदि उत्पादन व्यय (लाभन) से कम होता है तो साधारणतया विक्रता उस बेचते नहीं हैं। क्योंकि वे उसे दूसरे दिन पूरे मूल्य पर बेचने की आशा रखते हैं। परन्तु यदि श्रमिक को उसके जीवन स्तर द्वारा निर्धारित लागत से कम मूल्य ही दिया जाय और वह अपने श्रम को उस दिन में बेचें तो उस दिन का श्रम नष्ट हो जायगा और उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। इसलिये इस हानि में बेचने के लिये किसी भी मूल्य पर वह अपने श्रम को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उद्योगपति यह जानते हैं कि श्रमिक बेकार बैठ रहने की अपेक्षा कम मजदूरी पर काम करना अच्छा समझते हैं। इस कारण उद्योगपतियों का यही प्रयास रहता है कि श्रमिकों को कम से कम मजदूरी दी जाय। अतः श्रम की इन विशेषताओं का ठीक मजदूरी के निर्धारण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

२. **श्रमिक अपना श्रम बेचता है न कि अपने आपसे (The Labourer sells his labour but not himself)**—यद्यपि अन्य पदार्थों की भाँति खरिद और बेच नहीं जाते हैं। पुस्तकें, फैसलें, मशीनें और औजार आदि का मूल्य देने के बराबर होता है वह बेच जाते हैं और अगले इच्छानुसार इनका प्रयोग करते

है। इन वस्तुओं के बही मालिक हो जाते हैं। परन्तु धर्म में यह बात नहीं है। श्रमिक अपना धर्म बेचना है न कि अपने आपको। धर्मिक एक निश्चित समय तक मजदूरी करने के पश्चात् पुन स्वतन्त्र हो जाता है और अपनी इच्छानुसार काम करता है। प्राचीन समय में जबकि कही कही काम प्रथा (Slavery) प्रचलित थी, दास बेचे न खरीदे जाते थे। परन्तु अब इस प्रथा का अन्त हो गया है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि श्रमिक अपना धर्म बेचने के पश्चात् भी अपना स्वामी बना रहता है।

३. धर्म श्रमिक से पृथक् नहीं किया जा सकता (Labour cannot be separated from the labour)—धर्म में सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे श्रमिक अपने स अलग नहीं कर सकता, अर्थात् जहाँ उम्मे धर्म की आवश्यकता होती है तो उसे स्वयं को ही जाना पड़ता है। अतः उत्तर धर्म धर्म के स्थान का दातावरण उनके लिये अत्यन्त महत्व रखता है। पूँजीपति अपनी पूँजी को तब ही भूदायी अपनी भूमि को अपने से अलग कर सकता है, परन्तु धर्मिक अपने धर्म को अपने से अलग नहीं कर सकता।

४. धर्म का पूर्ति धीरे धीरे घटती-बढ़ती है (The Supply of labour increases or decreases very slowly)—धर्म वस्तु की भाँति धर्म की पूर्ति में सीमा घटा-बढ़ी नहीं हो सकती। यदि किसी समय किसी प्रकार के श्रमिकों की माँग अधिक हो जाय, तो उनकी पूर्ति तुरन्त ही नहीं बढ़ सकती, क्योंकि प्रथम तो यह देश की जन-संख्या पर निर्भर होती है जिसके बदल में पर्याप्त समय लगता है और द्वितीय श्रमिकों की अपना काम सीखने में कुछ न कुछ समय तो अवश्य ही लगता है। अन्य स्थानों को धर्म में अनेक बाधाएँ होती हैं। इसी प्रकार धर्म की पूर्ति में कमी भी धीरे धीरे हो सकती है, क्योंकि जो श्रमिक यह कार्य कर रहे हैं वह अपना कार्य तुरन्त ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, यह बात अवश्य है कि भविष्य के श्रमिक इस कार्य का कम सीमेंग।

५. श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति स्वामी की अपेक्षा कम होती है (The bargaining capacity of labourers is weaker than that of Employers)—श्रमिकों में सौदा करने की शक्ति स्वामी की अपेक्षा कम होती है। इससे निम्नलिखित कारण हैं—

(१) धर्म नाशवान—धर्म सीमा नष्ट होने वाली वस्तु होने के कारण श्रमिक कम मजदूरी पर ही काम करना स्वीकार कर लेते हैं।

(२) श्रमिकों की निर्धनता—श्रमिक निर्धन होने के कारण कुछ दिनों भी बँट कर खा नहीं सकते। एक वस्तु का विक्रेता जब तक बाजार में उसकी वस्तु के अच्छे दाम न मिलें उसे रोक सकता है पर धर्म का विक्रेता ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह निर्धन है। भूल रहने की अपेक्षा वे कम मजदूरी पर काम कर लेते हैं।

(३) गतिशीलता का अभाव—धर्म में गतिशीलता की भारी कमी है जिससे कहीं पर श्रमिकों की पूर्ति घट जाती है और कहीं बढ़ जाती है।

(४) धर्म की पूर्ति सुगमता से घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती—धर्म की पूर्ति का प्रभाव मजदूरी पर कम पड़ता है और माँग का अधिक।

(५) श्रमिकों में संगठन का अभाव—श्रमिकों में संगठन का प्रभाव होता है जिससे उनकी सौदा या माव-माव करने की शक्ति निर्बल रहती है।

(६) धमिका की अनभिज्ञता—धमिका को इतना ज्ञान नहीं होता है कि उसका धर्म का भूय किम म्याल में अधिक है और किम म्याल में कम है। अतः उसे जितना भी मिलना है उस म्योबाज कर लेता है।

(७) रीति रिवाज—नारनक्य में कही कही परम्परागत रीति रिवाज के अनुसार ही मजदूरी मिलनी है चाहे वह जितनी ही थोड़ी हो। मजदूरों की मजदूरी अतः जो साधारण आन मानित हो चली या रहो है।

(८) जन गह्वरा की वृद्धि—जन गह्वरा की वृद्धि न धर्म की पूर्ति बढ़ जानी है बल्कि पूर्ति बढ़ जाना में अधिक में स्पष्ट होकर मानी है। अतः उक्त कम मजदूरी पर ही मजदूरों को करना है।

अतः इन बातों में यह स्पष्ट होता है कि धमिका की मोटा करन की शक्ति मालिका की प्रयत्ना कम होनी है। ही, बनमान पुनः में धमिक मजदूर-मध्य प्राप्ति द्वारा सगठित हाथ न अपन अधिकांश जन का प्रयत्न करने मंगे हैं।

मजदूरी (भृति) का निर्धारण

(Determination of Wages)

मजदूरी के पुराने सिद्धान्त—पुराने अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी के निर्धारण को सम्भन व विप नमय-ममय पर कई सिद्धान्त प्रस्तुत किए, जैसे मजदूरी का जीवन-निवाह सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages), मजदूरी-आप सिद्धान्त (Wages Fund Theory), शेषाधिकार सिद्धान्त (Residual Claimant Theory) आदि, परन्तु ये सब सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण के तब को समझाने में असमर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि ये बहुत एव एव पर्याय थे। अतः ये मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार यह बताया गया कि मजदूरी का निर्धारण माँग और पूर्ति का बोझ ही घातिया द्वारा होता है। यह किसी एक शक्ति का काम नहीं है।

मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Wages)—आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी धर्म की माँग और उसकी पूर्ति पर निर्भर होती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का भूय माँग और पूर्ति की दो शक्तियाँ के अन्तर्गत द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार धर्म का भूय अर्थात् धमिका की मजदूरी की माँग और पूर्ति के नियमानुसार ही निर्धारित होता है। धर्म की कुछ निती निर्धारण आवश्यक हैं जिसके कारण मजदूरी-निर्धारण में तन्निश्चय अन्तर उपस्थित हो जाता है। धर्म मजदूरी निर्धारण का सिद्धान्त नीचे स्पष्ट दिया जाता है—

धर्म की माँग (Demand for Labour)—धर्म का माप उत्पादनशक्ति द्वारा प्रस्तुत हो जाता है जो धमिका का उत्पादन शक्ति में काम करने के लिए तैयार रहता है। धमिका का उत्पादन शक्ति में काम करने की शक्ति उसकी उत्पादनशक्ति (Productivity) कहानी है। उस उत्पादन शक्ति का मुद्रा में मापना या करना है। एक उत्पादनशक्ति तब तक धमिका को बनाना जाता है जब तक वह यह समझना रहता है कि उनके करने में उत्पादन बढ़ रहा है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु की ज्यादा माप्रा बननी जानी है त्या-त्या उसकी उत्पादनशक्ति धरनी जानी है ठीक उसी प्रकार ज्यादा धमिका की माप्रा बढ़नी जानी है त्या-त्या उत्पादनशक्ति हान-विषय (Law of

१—"The explanation of price by supply and Demand also holds good for labour ..."—Batson, *Political Economy*, p 27

Diminishing Utility) के अनुसार प्रतिरिक्त श्रमिका को उत्पादन शक्ति में भी ह्रास होता जाता है। अन्त में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि अन्तिम श्रमिक द्वारा उत्पादन की गई वस्तु का मूल्य उसको मिलने वाली मजदूरी से बराबर हो जाता है। ऐसे श्रमिक के प्रति उपयोगिता उत्पादन में रहता है, चाहे वह वह आ वना जाय क्योंकि उसके रहने में कोई विशेष लाभ नहीं होता और न उसके चल जाने में कोई विशेष हानि ही होती है। ऐसी श्रमिक के बाद फिर श्रम श्रमिक तो गया हो नहीं जायगा, अतः इसे अन्तिम या सीमान्त श्रमिक (Final or Marginal Labourer) कहते हैं और ऐसे श्रमिक को उत्पादन शक्ति सीमान्त उत्पादनता (Marginal Productivity) कहनाती है। अब एक ही काम करने के लिए कोई श्रमिक एक ही बुलावना धर्मार्थ समान उत्पादन शक्ति वाले रहे जान है तो कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि उन्त घनत्व-भाग मजदूरी में। और फिर ऐसा करने में उपयोगिता को भी हानि होगी। जब हम किसी उत्पादन कार्य के लिए बहुत से श्रमिकों पर एक साथ विचार करने हैं तो यही समझने है कि प्रत्येक श्रमिक एक ही कार्य-क्षमता ही रखता है। चाहे जिसकी हम सीमान्त भाग मरने हैं और उन्त हम धर्मार्थ-गोष्ट कर सकते हैं। अतः मूल्य श्रमिका को समान मजदूरी मिलनी अर्थात् सीमान्त श्रमिक को मिलने वाली मजदूरी ही मूल्य श्रमिकों को मिलेगी। इसलिए सीमान्त उत्पादन-शक्ति के बराबर ही सीमान्त श्रमिक को मजदूरी मिलना है इसलिए यह स्पष्ट है कि सीमान्त उत्पादन शक्ति या उत्पादनता ही श्रमिका का मांग मूल्य (Demand Price) है। अतः श्रमिकों को सीमान्त उत्पादनता मजदूरी ही अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निर्धारित करती है जिससे अधिक मजदूरी उद्योग पति कभी भी देने के लिये तैयार नहीं होता है।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)—श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा होती है। जिस प्रकार माधुर्य वस्तु के मूल्य निर्धारण में वस्तु का लागत व्यय उसको न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है उसी प्रकार श्रमिक का घनत्व-भाग जीवन स्तर मजदूरी को न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है।¹ अन्यथा श्रमिक अल्पतम रहने लगे का धर्मार्थ होता है, अर्थात् जीवन-मात्र आवश्यक, भुख एवं विलास वस्तुएं अनुप-मात्रा में उसे प्रत्यक्ष मिलना चाहिए अन्यथा उसे बहुत बर्छ होगा। इसे हम सीमान्त जीवन स्तर (Marginal Standard of Living) कहें सकते हैं। अतः उसे उतनी मजदूरी तो अवश्य मिलनी चाहिए जिससे कि वह उस स्तर पर रह सके अर्थात् मजदूरी कम से कम श्रमिक के जीवन स्तर के लागत व्यय के बराबर होनी चाहिये। जीवन स्तर के लागत व्यय में कम मजदूरी श्रमिक स्वीकार नहीं करेगा। यदि उसे इसमें कम मजदूरी दो जायगी, तो वह विवाह में विवश करेगा या आजीवन अविवाहित रह कर या ऊँची मजदूरी वाले धर्मार्थ या स्वार्थ में जायगा, या अपनी व्यक्ति-कार्यक्षमता उन्त कर कर धर्मार्थ में समर्पित होकर उत्पादन-शक्ति में संघर्ष करने श्रमिका अथवा किसी प्रकार से मजदूरी को जीवन स्तर के लागत व्यय के बराबर लाने का प्रयत्न करेगा। अतः

1—The standard of life in the case of labour replicates the expenses of production in the case of ordinary commodities

सामान्य जीवन-स्तर यमिकों का पूर्ति मूल्य (Supply Price) है। अस्तु, धमिक के जीवन-स्तर वा लागत-व्यय मजदूरी की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निर्धारित करता है जिससे कम मजदूरी धमिक कभी भी स्वीकार नहीं करता है।

माँग और पूर्ति की अन्तर्क्रिया (Interaction of Demand and Supply)—उपयुक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि धमिकों की उत्पादकता मजदूरी की अधिकतम सीमा है जिससे अधिक मजदूरी कभी नहीं हो सकती और धमिकों के रहन-सहन के स्तर वा व्यय मजदूरी की न्यूनतम सीमा है जिसमें कम मजदूरी कभी नहीं हो सकती। इसी दोनों सीमाओं के बीच में मजदूरी भ्रूणित रहती है और अन्त में उद्योगपति (मालिक) और धमिक को सार्वधिक आवश्यकता तथा उनकी भाष-ताव (Bargaining) करने की शक्ति द्वारा ठीक निर्धारित हो जाती है। अधिक स्पष्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि इन दोनों सीमाओं के बीच में मजदूरी उस स्थान पर निर्धारित होती है जहाँ उद्योगपति तथा धमिकों की प्रतिस्पर्धा की शक्ति बराबर हो जाती है अर्थात् जहाँ पर माँग और पूर्ति में समुत्तन हो जाता है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—माँग और पूर्ति की तात्त्विक वनाकर हम एक समुत्तन मजदूरी (Equilibrium Wage) का पता लगा सकते हैं। मान लीजिये विभिन्न मजदूरी पर धमिकों की माँग और पूर्ति निम्न प्रकार है :—

माँग (धमिकों की संख्या)	मजदूरी (रुपया)	पूर्ति (धमिकों की संख्या)
८००	२०	१००
६००	२५	३००
४००	३०	४००
३००	३५	६००
१००	४०	८००

ऊपर की तात्त्विक में जब मजदूरी ३० रुपये है तो माँग और पूर्ति दोनों बराबर है। अतः धमिकों की मजदूरी ३० रुपये पर निश्चित होगी। यही समुत्तन मजदूरी है। मजदूरी इससे अधिक होने पर अधिक धमिक भाग लेंगे। पूर्ति बढ़ने के कारण मजदूरी गिर कर अन्त में समुत्तन मजदूरी के बराबर हो जायगी। मजदूरी के इससे कम हो जाने पर मजदूरों की संख्या कम हो जायगी, जिसके कारण उत्पादकों की मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी और अन्त में वह समुत्तन मजदूरी के बराबर हो जायगी। इस प्रकार मजदूरी समुत्तन-मजदूरी से न तो कम हो सकती है और न अधिक।

धमिकों की मीढ़ा करने की शक्ति वा मजदूरी निर्धारण पर प्रभाव—यह तो पहले बताया जा चुका है कि धमिक एक नाचवेगम् वस्तु होने भावि कारणों से धमिकों को सौदा या भाष-ताव करने की शक्ति (Bargaining Capacity) उद्योग-पतिया या मालिकों की अपेक्षा कम होती है। इसलिये उन्हें केवल न्यूनतम दरवाँ जीवन-निर्वाह मात्र के लिये ही मजदूरी मिल पानी है। यदि वे अपना संगठन कर लें

तो मजदूर संघों (Trade Unions) द्वारा वे अल्पतम जीवन-स्तर को अपेक्षा अधिक मजदूरी या सकते हैं।

मजदूरी, कार्य क्षमता और जीवन स्तर

(Wages, Efficiency and Standard of Living)

मजदूरी, कार्य-क्षमता और जीवन-स्तर में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

मजदूरी का प्रभाव कार्यक्षमता और जीवन-स्तर पर—जितनी अधिक मजदूरी होगी उतना ही अधिक वे उत्पादन कर पायेंगे और उनकी गीष्क भोजन मिलेगा, रहने का उत्तम स्थान मिलेगा, विद्या, स्वास्थ्य और मगारजन की सुविधाएं मिलेंगी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

कार्यक्षमता का मजदूरी और जीवन-स्तर पर प्रभाव—अधिक जितने अधिक कार्यक्षम होंगे उतना ही अधिक वे उत्पादन कर पायेंगे और उनकी ही अधिक उनकी मजदूरी होगी। जब उनकी मजदूरी बढ़ेगी, तो उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। इस प्रकार कार्यक्षमता, मजदूरी और जीवन स्तर का सीधा सम्बन्ध है।

जीवन स्तर का कार्यक्षमता और मजदूरी पर प्रभाव—अधिको के जीवन-स्तर के ऊँचे होने से उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी और वे अधिक उत्तम वस्तुओं का उपभोग करेंगे। परिणाम यह होगा कि उनका स्वास्थ्य सुधरेगा जिससे उनकी उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होगी। इस वृद्धि से उत्पादन बढ़ेगा जिसके कारण उन्हें अधिक पारित्यक्तिक प्राप्त होगा।

मजदूरी, कार्यक्षमता और जीवन-स्तर का पारस्परिक प्रभाव—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजदूरी, कार्यक्षमता और जीवन स्तर में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। मजदूरी अधिक होने पर जीवन-स्तर धीरे-धीरे बढ़ेगा और जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है जिससे कार्यक्षमता बढ़ जाती है और कार्यक्षमता बढ़ने पर मजदूरी भी बढ़ जाती है। मजदूरी बढ़ने पर जीवन-स्तर और भी ऊँचा हो जाता है जिससे कार्यक्षमता में और भी वृद्धि हो जाती है और परिणाम मजदूरी पहले से भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार यह चक्र निरन्तर गतिशील रहता है। चाहे मजदूरी बढ़ जाय, चाहे कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाय, धनवान् रहन रहन का स्तर ऊँचा हो जाय—इससे वे कोई भी कार्य हो जाय, जो पुनः यह पारस्परिक प्रभाव का चक्र चल जाता है और निरन्तर चलता रहता है। यह साब में दिये गये चित्र में प्रकटित स्पष्ट हो जाता है।



मजदूरी, कार्यक्षमता और जीवन-स्तर का सम्बन्ध

मजदूरी और सामाजिक प्रथाएँ (Wages and Social Customs)—मजदूरी सामाजिक प्रथाओं द्वारा भी प्रभावित होती है। भारतवर्ष में गाँवों में प्रची तक अनेक कामों में मजदूरी सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरणार्थ, वटई, लुहार, नाई, धोबी, चमार, आदि को फसल के समय कुछ अनाज दे दिया जाता है जिसके बदले में वे वर्ष भर अपनी सेवाएँ करते रहते हैं। इसी प्रकार जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर नाई, धोबी, कुम्हार आदि को जो दिया जाता है वह भी परम्परागत रीति-रिवाजों के अनुसार ही दिया जाता है, चाहे उनका परिश्रम अधिक हो या कम। सामाजिक प्रथाओं द्वारा मजदूरी निर्धारण में श्रमिक अकर्मण्य एवं निरक्षर हो जाने से जिससे वे अपनी कर्म-कुशलता नहीं बढ़ा सकते। वे जानते हैं कि उन्हें वही वेँधा हुआ पैसा मिलेगा चाहे वे अधिक काम करें या कम, अच्छा काम करें या बुरा। इस सामाजिक प्रथाओं में जाति-पाति का भेद, सपुत्र परिवार प्रथा, बाल-विवाह और पर्दा प्रथा मुख्य हैं। इनका प्रभाव मजदूरी पर निम्न प्रकार है :—

मजदूरी पर जाति-प्रथा का प्रभाव (Effect of Caste System on Wages)—जाति भेद-भाव के कारण श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से नहीं जा सकता या एक व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकता। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की सीध और पूर्ति में बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। ऊँची जाति के मनुष्य कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसे नीची जाति के लोग करते हैं, यद्यपि उनसे अधिक प्राय ही क्यों न होती हो। इस प्रकार जाति-प्रथा ने समाज को ऐसे टुकड़ों में बाँट दिया है जिससे एक टुकड़े वाले व्यक्ति को दूसरे टुकड़े के व्यक्तियों के सम्बन्ध में काम करने का अवसर नहीं मिलता चाकि यह इच्छानुसार व्यवसाय में लग सके। परिणाम यह होता है कि सभी टुकड़ों के व्यक्तियों को काम खूब करना पड़ता है और उसके बदले में बहुत बड़ा पारिश्रमिक दिया जाता है।

मजदूरी पर सपुत्रपरिवार-प्रथा का प्रभाव (Effect of Joint Family System on Wages)—सपुत्र परिवार प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति परिवार की सम्पत्ति में बराबर का भाग ल सकता है। इस प्रथा के अन्तर्गत लोग भ्रमण्य एवं भ्रालसी हो जाते हैं, क्योंकि परिवार ने कुछ लोग तो कमाने हैं और कुछ बड़े व्यय करने हैं बिना किसी परिश्रम के परिवार की सम्पत्ति में मन्ना उठाते हैं। इस प्रकार श्रमिकों की पूर्ति में कमी पड़ जाती है जिससे मजदूरी में वृद्धि सम्भव हो सकती है। यदि सब मनुष्य परिश्रम करने लगें, तो श्रमिकों की संख्या बढे जाने और मजदूरी कम हो जाये। कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में आर्थिक कठिनाइयों से कुछ व्यक्त उभ स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर परिश्रम से दूसरे धनार्थ में अच्छी कमाई करते हैं जिससे उनका और उनके परिवार का निर्वाह हो जाता है। इस प्रकार श्रमिकों के पारिश्रमिक पर प्रभाव पड़ता है।

बाल-विवाह-प्रथा (Early Marriage System)—धार्मिक अथवा विश्वास तथा अन्य प्रचलित रूढ़ियों के कारण बाल-विवाह हो जाने से जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिससे मजदूरी का बिर जाना स्वाभाविक है। अधिकांश बच्चे निर्बल पैदा होते हैं जो जीवन-मरण्त बीमार-से रहते हैं। इस प्रकार उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में ह्रास हो जाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती

मजदूरी से तात्पर्य श्रमिक के धनो ने वास्तविक लाभों से है, अर्थात् अपने सेवाया के प्रतिफल में श्रमिक का जो जीविकार्थ प्रावश्यक मुख्य तथा विलास वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं उन्हें वास्तविक मजदूरी कहते हैं।^१ अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक मजदूरी में नकद मजदूरी द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं के अतिरिक्त श्रमिकों का अपने स्वामी से जितनी भी सुविधाएँ एवं रियायतें प्राप्त होती हैं वे सब ही सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिये घरेलू नौकर को नकद रुपये के अतिरिक्त रहने के लिये मुफ्त भोजन वस्त्र इनाम आदि मिला में काम करने वाले श्रमिकों को नि:शुल्क निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य-वृद्ध वाचनालय आदि की सुविधाएँ, रेल के श्रमिकों को की यात्रा पास, नि:शुल्क चिकित्सा रहने के लिये फाटस, सस्ता भोजन आदि वास्तविक मजदूरी के कुछ उदाहरण हैं।

उपयुक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि नकद या रोकड़ मजदूरी रुपये में ही पैसे में व्यक्त की जाती है और वास्तविक मजदूरी वस्तुओं तथा सेवाओं में।

नकद या रोकड़ मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सापेक्षिक महत्त्व—नकद या रोकड़ मजदूरी का महत्त्व उतना नहीं होता जितना कि वास्तविक मजदूरी का। दो विभिन्न व्यक्तियों को नकद मजदूरी बराबर होने पर भी उनकी वास्तविक मजदूरियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। एक श्रमीण श्रमिक को आठ घण्टे रोज मिला है तथा एक सहरी श्रमिक का एक सप्ताह रोज मिलता है। परन्तु श्रमीण श्रमिक सहरी श्रमिक को अपना आठ घण्टे के बदले में अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। इसका कारण यह है कि शान में सहरी की अपेक्षा छाद्य पशुधन, धूप आदि मुद्र तथा कम मूल्य में प्राप्त हो सकते हैं। गांव में यकान का कोई विशेष किराया नहीं होता है जबकि सहरी में यकान मिलने कठिन है और यदि मिलते हैं तो बहुत अधिक किराये पर। अतः एक श्रमिक के लिये यह महत्त्व की बात नहीं है कि उसे कितना रुपया मिल रहा है, उमन लिये यह महत्त्व की बात है कि रुपया से कितनी वस्तुएँ तथा सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है और नकद रुपया के अतिरिक्त भी उसे क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं। आदम स्मिथ (Adam Smith) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है श्रमिक या निर्धन, उन्हें उचित पुरुष्कार मिलता है या अनुचित, वास्तविक मजदूरी के अनुपात से कहा जा सकता है न कि नाममात्र मजदूरी से।^२ अस्तु अर्थशास्त्र में नकद या रोकड़ मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का भेद बहुत महत्व रखता है।

1—“Real Wages refer to the ‘net advantages’ of the worker’s occupation, i. e. the amount of necessaries comforts and luxuries of life which the worker can command in return of his services

—Dr S E Thomas *Elements of Economics*, P 262.

2—“The labourers are rich or poor, well or ill—rewarded, in proportion to the real wages, not the Nominal wages of his labour

—Adam Smith

पड़ती। अस्तु, वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाने समय शिक्षा-वाल एवं उसका व्यय अवश्य ध्यान में रखना चाहिये।

(४) व्यापारिक व्यय (Trade Expenses)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके संचालन में कुछ व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, एक बकीम की कानून की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं तथा कई पत्रिकाएँ भेजानी पड़ती हैं। एक डाक्टर का अपना कार्य करने के लिये निमित्त औषधियाँ तथा नये-नये औजार खरीदने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक प्राक्वेयर का भी अपनी ज्ञान वृद्धि के लिये पुस्तकें व पत्रिकाएँ आदि खरीदने में पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाने समय इन प्रकार के व्यापारिक व्यय नकद मजदूरी में से घटाने पड़ते हैं।

(५) व्यवसाय का स्वभाव (Nature of Employment)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ोर, भारचिक्कर, अस्वास्थ्यकर या खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिये, लान के भीतर काम करने यद्यपि भूरी में कीचल भागने वाला श्रमिक का काम बहुत बड़ोर एवं खपाने वाला होता है। याला वास्तव में कारखाना में कार्य संलग्न श्रमिक का जीवन सबैक सतरे में रहता है। मीना उद्योग वाक और अस्वाद का काम अत्यन्त भारचिक्कर है। परन्तु कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो रचिक्कर होते हैं। तथा जिनमें श्रमिक का पर्याप्त सुख मिलता है। जैसे चित्रकार व पद्यापक का कार्य। अतः काम की कठोरता तथा अस्वस्थ वास्तविक मजदूरी को घटा देना है और रचिक्करता तथा सुखदायकता वास्तविक मजदूरी का बढ़ा देना है।

(६) काम करने का समय तथा अवकाश (Working Hours & Holidays)—काम करने के घंटे तथा समय समय पर मिलने वाली छुट्टियाँ भी वास्तविक मजदूरी का प्रभावित करती हैं। एक बलिज का प्राक्वेयर की तुलना में जिस मुश्किल में नित्य तीन घण्टा कार्य करना पड़ता है तथा जिस वर्ष में लगभग छ महीने की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, एक बैंक मैनेजर की वार्षिक आय जिसे लगभग उसका बराबर ही वेतन मिलता है पर धाढ घण्टा नित्य काम करना पड़ता है और अप भर में एक महीने की ही छुट्टियाँ मिलती हैं, कम ही कही जायगी।

(७) कार्य का नियमितत्व (Regularity of Employment)—कुछ कार्य अस्थायी (Temporary) एवं मौसमी (Seasonal) होते हैं, जैसे बड़ई अथवा कृषक का कार्य जिसमें श्रमिक का पर्याप्त समय तथा बेकार बँट रहता पड़ता है। इसी प्रकार चीनी का कारखाना भी वर्ष में लगभग पाँच महीने ही चलता है। साथ व अस्थायी होने से वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है।

(८) अतिरिक्त आय (Extra Earning)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें अतिरिक्त आय कमाने की पर्याप्त सुविधा होती है अर्थात् अन्य व्यवसायों में उमा सुविधा का पूर्णतया अभाव होता है। उदाहरणार्थ, अध्यापक परीक्षक होकर या पुस्तक लिखकर अथवा प्राज्ञेष्ट अध्ययन करने, डाक्टर प्राइवट प्रैक्टिस द्वारा तथा बैंक का वर्क अवकाश के समय में बीमा कम्पनी के एजेंट का कार्य कर अपनी आम म वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार की अतिरिक्त आय कमाने की सुविधा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर देती है।

(९) आर्थिकों को काम मिलने की सुविधा (Employment of Dependents)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें श्रमिक व आर्थिकों अर्थात्

सन्ने घोर रक्त भादिका मोहरा दिवाने की पर्याप्त सुविधा होती है। उदाहरणार्थ, विगत साहस मन्द उद्योग बंदिन हस्त है वही स्थित स्वयं नाम बरना हा है घोर प्रपन्न कुटुम्ब व सदस्या। नो भी नाम दिया है। दग प्रसार वा सुविधा साम्यविश मजदुरों की वसती है।

(१०) भावी उन्नति की आशा (Prospect of Success)—जिन व्यवसायों में भावी उन्नति का आशा अधिक होता है उनमें लोग कम पैसा मरहूरी पर भाँकते हैं। उदाहरण के लिए एक मणिशिल्पि व्यक्ति वर्तमान में अपनी भाँकना देविता स्वीकार कर रहा है कि वह निश्चय भविष्य में हाथों से पैसा कमाएगा, लेकिन वह अभी भी अपनी भाँकना देविता स्वीकार कर रहा है। जो प्रकार का भाँकना होता है वह वह है जो व्यक्ति द्वारा भाँकना देविता स्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार वह अपने भाँकने के कारण ही भाँकना देविता स्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार वह अपने भाँकने के कारण ही भाँकना देविता स्वीकार कर दिया जाता है।

(११) स्वच्छता एवं मनोरंजन ता दानावरण (Cleanliness & Happy Atmosphere)—इत मय याता व प्रसिद्धि व्यवसाय वा मात-मुगल हाता उमम मनोरंजन हाव रहता प्रादि वारण न बागवति मरदगी दश दन १ ।

धन की माद और वास्तविक मूल्य (Money and Real Cost of Labour) — जिस प्रकार मजदूरों को दो भेद होते हैं—एक उसी प्रकार धन की माद में भी दो भेद मिल जाते हैं—(१) मजदूर या सामान्य धन की माद (२) वास्तविक माद।

(१) नकद या नाम मात्र लागू (Money or Nominal) (२६)—
 बिना श्रमिक को काम करने के बदले में जो नकद पिया जाता है उसे नकद या नाम मात्र लागू कहा है। उदाहरण बिना श्रमिक को
 २१०० मासिक पारिश्रमिक व रूप में दिया जाता है तो २५०० उन्हा नकद
 लागू है।

(२) वास्तविक लागत (Real Cost)—अति दुर्लभ मसूरी उत्तरी वास्तविक लागत कहा जाती है। उदाहरणार्थ यदि किसी धमिक का २५ रु० दिया जाने है और वह १०० इन्च वस्तु उत्पन्न करता है तो उसकी वास्तविक लागत १ इन्च = १/१०० रु० या ४ आन प्रति इन्च हुई। उत्पन्न धमिकों को उनकी वास्तविक लागत के आधार पर ही पास पर लगाते हैं। उत्तरी नष्ट लागत पर विचार नहीं करते। जिस धमिक की वास्तविक लागत कम होता है वह मज्जा पहना है और उत्पन्न धमिक उसे ही नाम पर लगाना है। उदाहरणार्थ २५ रु० पास वास्तविक धमिक यदि ५० इन्च वस्तु उत्पन्न करे और २५ रु० पास वास्तविक धमिक १०० इन्च वस्तु उत्पन्न करे तो दूसरे धमिक का नष्ट लागत अधिक होना पर भी उत्तरी वास्तविक लागत कम है और इस कारण वह मज्जा है।

(१) कच्ची मजदूरी सस्ती होती है (High Wages are Cheap Wages)—सार थमिका म एक सो नाथ गान्ता नही होती है । कुछ थमिक अधिक कुनस होत है और कुछ कम । जो थमिक अधिक कुनस होते है उन्हें मजदूरी भी अधिक मिनती है । यह धारणा कि कच्ची मजदूरी महंगी सिद्ध होती है, गलत है । थमिक महंगा है या सस्ता इसका अनुमान उसकी उत्पादन शक्ति या बाय कुनसता

से ही लगाया जा सकता है। यदि एक धमिक दिये हुए समय में दूसरे धमिक में पाँच गुना काम अधिक करता है और दूसरे की अपेक्षा मजदूरी केवल उस तिगुनी हो गिनती है तो वह निरसनेह्य मन्ता धमिक है, क्योंकि उसी काम को दूसरे मजदूर से करवाने में उद्योगपति को २५% अधिक व्यय करना पड़ता है। उद्योगपति का यह निरर्थक वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत पर अधारित होता है। यदि किसी दश धमिक को काम पर लगाने में उसे बड़ी हुई मजदूरी देने के अनुपात में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो वह ऊँची मजदूरी पर कुशल धमिक को काम पर लाना वासना करेगा। इस प्रकार मजदूरों की बुद्धि के अनुपात में अधिक उत्पादन प्राप्त होने के कारण ऊँची मजदूरी पर रखा गया धमिक मन्ता सिद्ध होता है।

(२) ऊँची मजदूरी काम लाना धमिक सन्तुष्ट रहता है। अतः वह अपना काम दिल लगाकर करता है और अन्य स्थान के छोड़-कर सालभर से इसे छोड़ कर नहीं जाता। कुशल धमिक का स्यायी रूप से रहकर काम करना उद्योगपति के लिये लाभप्रद सिद्ध होता है।

(३) ऊँची मजदूरी पर काम करने वाले कुशल एवं सन्तुष्ट धमिक मनीषित तथा औजारों का उपयोग बड़ी सावधानी से करते हैं जिससे उनके धिप्पन तथा नष्ट होने की हानि अधिक नहीं होती।

(४) ऊँची मजदूरी पाने वाला धमिक कम या अपर्याप्त मजदूरी पाने वाले धमिक की अपेक्षा अधिक ईमानदार होता है जिसके कारण उद्योगपति की निरीक्षण कार्य (Supervision Work) पर कम व्यय करना पड़ता है।

इन्हीं कारणों से अमेरिका आदि औद्योगिक दृष्टि से उत्कृष्ट देशों में उद्योगपति अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि धमिका को भुलने रहने के बजाय उन्हें अच्छी मजदूरी दी जाय तथा सन्तुष्ट रखा जाय, क्योंकि कुशल मजदूर काम अधिक करता है।^१ परन्तु भारतीय उद्योगपति अभी तक वही सोचने के कि धमिक जितना सस्ता हो उतना ही श्रेष्ठ। इस कारण वे सस्ते में-सस्ता मजदूर ढूँढते थे। परन्तु वे अब समझने लग गये हैं कि यहूना मजदूर ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसकी उत्पादन शक्ति अधिक होती है।

ऊँची मजदूरी होने की दशाएँ (Conditions favouring High Wages)

ऊँची मजदूरी निम्नलिखित दशाओं में सम्भव हो सकती है :—

१. कार्य-कुशलता—उत्पादन-शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मजदूरी अधिक होगी। धमिक की उत्पादन शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है : (अ) धमिक की कार्य-क्षमता, (ब) धमिक की बुद्धि और स्वास्थ्य, (इ) देश में प्रादुर्गत सामानों की प्रचुरता तथा (ई) उनका सदुपयोग।

१—यह एक पारसी (persian) में कहावत है : 'कुशल मजदूर कार बेस की कुन्द'।

२ पूँजी की बड़ी मात्रा—बड़ी मात्रा में पूँजी उपलब्ध होने पर ही इस का प्राप्ति एवं शोचनिक विभाग हो सकता है।

३ मशीन तथा अन्य वस्तुनिष्ठ उत्पादों का आविष्कार—इन सब बड़े परिमाणों का उत्पादन सम्भव होकर शोचनिक उत्पत्ति होती है।

४ वैयक्तिक गुणधर्म—बिना उचित वैयक्तिक गुणधर्मों के शोचनिक उत्पत्ति इस युग में सम्भव नहीं है।

५ श्रमिकों का संगठन—श्रमिकों का जितना अधिक संगठन होगा मजदूरी उतनी ही अधिक हो सकेगी।

मस्ती मजदूरी में हानि होती है (I am Wages are Dear Wages) —जितने प्रकार के लोग हैं कि जैसा मजदूर मस्ती होता है। उमा प्रकाश इसका विस्तृत उल्लेख भी करता है कि मस्ती मजदूरी में हानि होती है। इसके कारण विस्तृत स्पष्ट है। मस्ती श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होने से मजदूरी के अनुपात में कम उत्पादन होता है जिसके कारण धन का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष मजदूरी पान वाले श्रमिक संतुष्ट नहीं रहता, इससे वह सदा काम छोड़कर जाने की सोचता रहता है जिससे वह मन लगा कर काम नहीं कर पाता। अनुपुष्ट एवं अनुपुष्ट श्रमिक मशीन तथा मशीनों का उपयोग भी उचित मावधानों में नहीं करता जिसके कारण उनके घिसते तथा खराब होने आदि से हानि अधिक होती है। कम या अप्रत्यक्ष मजदूरी पान वाले श्रमिक संतुष्ट होते हैं और उनकी ईमानदारी पर पूर्णतया भिन्नता नहीं दिया जा सकता है। इसलिए उनके साथ पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण निरीक्षण व्यय में वृद्धि होकर वास्तविक व्यय बढ़ जाता है। इन कारणों से यह कहा जा सकता है कि मस्ती मजदूरी में हानि होती है।

अधिक समय तक काम करना लाभप्रद नहीं है (I am Hours are Unprofitable)—मनुष्य मशीन की भाँति लगातार काम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ घण्टा के निरंतर श्रम के पश्चात् वह थक जाता है जिसके कारण उसका काम उत्पादन कम होकर उत्पादन शक्ति में हानि हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन कम होने लगता है जिसके कारण वास्तविक मूल्य में वृद्धि होने लगती है। इसलिये यह आवश्यक है कि श्रमिकों का दो-तीन घण्टा काम करना पश्चात् थकावट का समय दिया जाए जिससे वे अपने ताँई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। अभी तक उद्योगपति यह समझते थे कि श्रमिकों में अधिक मजदूरी अधिक समय तक काम करना लाभदायक है। परन्तु अनुभव से वे अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि काम के बीच में श्रमिकों को कुछ प्राराम मिलना चाहिए तथा काम करने का समय बढ़ा होना चाहिए जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता बनी रहे और उत्पादन में कमो-कमी न हो पाये। अब यह स्पष्ट है कि अधिक समय तक काम करना में हानि पड़ती है।

विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की भिन्नता के कारण (Causes in Wages in different occupations) — निम्नलिखित श्रमिकों की मजदूरी कम की मात्रा और पूर्ण की परामर्शक प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित होती है। परन्तु प्रायः देखा गया है कि विभिन्न व्यवसायों या धनो में श्रमिकों की मजदूरी एक ही नहीं होती। किसी व्यवसाय में उनका अधिक मजदूरी मिलती है तो किसी व्यवसाय में कम। इस विभिन्नता के कई कारण हैं जो तीन दिये जाते हैं —

१. कार्य का स्वभाव (Nature of Occupations) — कुछ व्यवसाय या धनो अधिक (Agreeable) होते हैं, जिनमें श्रमिक प्रसन्नता में कार्य करने को तैयार होते हैं जैसे मिर्च, गीला, डाक्टर, डी.जी.एम. आदि का काम, और कुछ अधिक (Disagreeable) होते हैं जिनमें श्रमिक काम करना पसन्द नहीं करते, जैसे, भरी, खमार, बमारी, जलवा, आदि का काम। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें काम अधिक करना पड़ता है और कुछ में कम, जैसे शिक्षक का एक बच्चे की प्रशिक्षण कम काम करना पड़ता है। कुछ काम सामाजिक प्रशिक्षण की दृष्टि में प्रशिक्षण समझे जाते हैं — जैसे अध्यापक, डाक्टर, वकील, समाचार-पत्रों के सम्पादक का काम आदि। कुछ काम श्रमिक का जीवन कम कर देने हैं, जैसे वायुवाहन चालाना या कृषि, जो कुछ कर बहुत कठिन प्राप्ति। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें करने से श्रमिक की कार्य-क्षमता शीघ्र ही क्षीण हो जाती है, जैसे विद्या चालाना आदि। कुछ कार्यों में श्रमिक का जीवन सदा स्मरण में रहता है, जैसे साक्षात्कार के कारणान में काम करने वाले श्रमिक का, जिसमें में काम करने वाले व्यक्ति का। इस प्रकार श्रमिक को विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिलते हैं। इसलिए एक व्यवसाय या धनो जिनमें श्रमिक को प्रशिक्षण कम परिश्रम करना पड़ता है तथा अधिक लाभ नहीं पड़ता है, जो श्रमिक एक प्रिय होना तथा जिनमें व्यवसाय श्रमिक मिलता है और जिनमें करने में समाज में सम्मान एक प्रशिक्षण होता है, उनमें मजदूरी कम होती है क्योंकि इनकी श्रम वाले लोग उत्सुक रहते हैं।

२. अन्य सुविधाएँ (Incidental Advantages) — कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें निम्नलिखित मजदूरी के अतिरिक्त कई सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जैसे गुप्त भवन या कम निराश पर अच्छा भवन, यात्रा करने में लिये की पास, निम्नलिखित शिक्षा, विविधता एक बड़ा सस्ता खान पदार्थ, ईंधन आदि। अतः जिन व्यवसायों में इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं वहां मजदूरी कम हो जाती है।

३. काम या स्थायित्व (Regularity of Employment) — जो कार्य स्थायी रूप से निरन्तर चलते रहते हैं उनमें मजदूरी कम होती है, क्योंकि श्रमिक को देशांतर नहीं रहना पड़ता और जो काम अस्थायी या मोसमी होते हैं (जैसे चीनी का व्यवसाय आदि) उनमें श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है। इसलिए कार्य स्थायी है या अस्थायी इस पर भी मजदूरी में भिन्नता पाई जाती है।

४. शिक्षा का समय तथा व्यय (Period & Cost of Training) — बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें अध्ययन एवं प्रशिक्षण में पर्याप्त समय और धन लगता है, जैसे इंजीनियरिंग, डाक्टर आदि। अतः, जिस काम को सीखने में समय और धन अधिक लगता है उसमें पारिध्यिक अधिक होता है।

५. अतिरिक्त आय का सम्भावना (Possibility of Extra Earnings)—जिन व्यवसायों में अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है उसमें नवद मजदूरों कम होता है। जैसे अध्यापक, डाक्टर, प्राप्ति का कार्य। वगैरह। ॥ अधिकांश की प्रतिभाशाली धनवान् (Bonis) मिलने के कारण नव मजदूरों कम मिलता है।

६. व्यापारिक व्यय (Trade Expense)—मजदूरों की भित्ति का एक बड़ा भाग कारण है कि एक व्यवसाय का व्यापारिक व्यय अधिक होता है और दूसरे का काम उपाहारण के बिना बड़ा का धन काय संचालन के बिना प्रोत्साहन प्राप्त का प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन के कारण नव मजदूरों का प्रस्ताव है।

७. काम करने का समय (Working Hours)—अतिरिक्त व्यवसायों में अतिरिक्त काम करने का समय होता है। इसलिए उनमें मजदूरों का भी मिलता पाता सम्भावित है। अतः जिन व्यवसायों में कम समय काम करना पड़ता है वहाँ मजदूरों कम होता है।

८. श्रम की गतिगति (Mobility of Labour)—उप व्यवस्था में अतिरिक्त श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान का जाने में स्वतंत्र हैं। मजदूरों सम्भावना का प्राप्त होता है। परन्तु जहाँ पर सामाजिक राजस्व और धार्मिक विचार तथा प्रतिभा का अतिरिक्त है वहाँ श्रम की गतिगति नष्ट होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में नव अधिकांश का सम्भाव है वहाँ मजदूरों अधिक होगी और जहाँ अधिक व्यापार मात्रा में होता है वहाँ मजदूरों कम होती है।

९. ईमानदारी योग्यता एवं कार्य-कुशलता (Honesty Ability and Efficiency)—जिस कार्य में ईमानदारी परिश्रमों काय तथा कार्य-कुशलता अतिरिक्त का आवश्यकता होती है उसमें मजदूरों भी अधिक होता है। इस प्रकार यदि किसी कार्य में विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता होती है तब भी पारिश्रमिक अधिक मिलता है। अतः कारण है कि एक मजदूर आदमियों का सम्भावना, ईमानदारी का साथ-साथ अतिरिक्त का सम्भावना मिलता है।

१०. जीवन-स्तर (Standard of Living)—विभिन्न व्यवसायों में अधिकांश विभिन्न जीवन-स्तर के कारण भी मजदूरों में परोक्ष अंतर काय होता है। भारतीय अधिकांश जीवन-स्तर अतिरिक्त अधिकांश की प्रतीति बहुत गिरा हुआ है। इसलिए एक भारतीय अधिकांश मजदूरों पर ही राखी हो जाता है अतिरिक्त अधिकांश अधिक मजदूरों की होता है। अतः यह स्पष्ट है कि जिन लोगों में अधिकांश का जीवन-स्तर ऊँचा होता है वहाँ कार्य-कुशलता की प्रतीति मजदूरों अधिक होता है।

११. उत्तरदायित्व तथा मूल्यवान् वस्तुओं में सम्बन्ध (Responsibility and Dealings in Valuable Goods)—मजदूरों का परिश्रम अधिक होता है यदि उनका उत्तरदायित्व अधिक होता है। अतः प्रकार की तथा उत्तरदायित्व का साथ मूल्यवान् वस्तुओं का कार्य करने के कारण ॥ उत्तरदायित्व का साथ अधिक होता है।

१२. स्थानात्म्य परिस्थितियाँ (Local Conditions)—कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ वस्तुओं के मुख्य अधिक होने हैं और कुछ स्थानों पर कम। प्रस्तुत जहाँ वस्तुएँ महँगी होंगी वहाँ प्रायः मजदूरी भी अधिक होगी और जहाँ वस्तुएँ सस्ती होंगी वहाँ मजदूरी भी कम होगी।

१३. भावी उन्नति एवं सफलता की आशा (Future Prospects and Success)—यदि कार्य में अच्छे लाभ तथा सफलता की आशा निहित है, तो उसके निम्न श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और मजदूरी बढ जायगी। परन्तु यदि कार्य में असफलता की सम्भावना है या उसके लिये कम धनिक राजी होंगे जिससे मजदूरी की दर में घृष्टि हो जायगी।

स्त्रियों की कम मजदूरी के कारण (Causes of Low Wages of Women)

प्रायः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कम मजदूरी मिलती है। इसके निम्न-लिखित कारण हैं—

१. स्त्रियों की शारीरिक शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है—स्त्रियों की शारीरिक शक्ति कम होने के कारण अधिक परिश्रम वाला काम नहीं कर सकती। साथ ही वे लगातार और अधिक समय तक काम नहीं कर सकती। इस कारण उनकी उत्पादन-शक्ति कम होती है जिसके कारण उनकी मजदूरी भी कम मिलती है।

२. स्त्रियों के लिये कुछ ही पैसे सीमित हैं—मासिक या वार्षिक प्रतिबन्धों के कारण स्त्रियाँ सब उद्योगों में काम नहीं कर पाती। उनके लिये कुछ ही घन्टे खुले हुए हैं। घन-दम घोटों से उद्योगों में उनकी पूर्ति अधिक हो जाने के कारण उनकी मजदूरी कम हो जाती है।

३. स्त्रियों के काम में स्थायित्व का अभाव—स्त्रियों को विवाह के पश्चात् काम करने में रुचि नहीं पड़ती है। विवाह के पश्चात् उनके गृहस्थ जीवन के वांछित इतने अधिक बढ जाते हैं कि वे काम नहीं कर पाती। इस कारण उद्योगपति उन्हें काम पर रखना वसन्द नहीं करते जिसके कारण भी उन्हें मजदूरी कम मिलती है।

४. शिक्षा तथा ट्रेनिंग का अभाव—विवाह आदि बातों के कारण स्त्रियाँ स्वाधीन रूप से काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसलिए वे समय एवं श्रम लगाकर कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग या शिक्षा प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं होती। शिक्षा एवं समुचित ट्रेनिंग के अभाव में उनकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ती जिसके कारण उनकी मजदूरी भी कम रहती है।

५. अधिक मजदूरी प्राप्त करने की प्रेरणा का अभाव—स्त्रियों की आवश्यकताएँ पुरुषों की अपेक्षा कम होती हैं, अतः उन्हें कम द्रव्य की आवश्यकता होती है। वे अधिकतर अपने जीवन निर्वाह के लिये ही धन करती हैं जबकि पुरुष के ऊपर समस्त परिवार के पालन-पोषण का भार होता है।

६. मित्रों में सामान एवं प्रचन्न वार्य की योग्यता का अभाव—
सामान एवं प्रचन्न गन्वन्धी नीकरियाँ ऊँची बनन वाली होती हैं । परन्तु मित्रों में प्रायः
इस योग्यता का अभाव देखा जाता है । इसलिये उन्हें कम वेतन वा न कामों में ही रोजगार
करना पड़ता है ।

७. मित्रों में मजदूर का अभाव—मित्रों की यौदा या भाव-भाव करने की
शक्ति पुरुषों में भी कम है । इनमें मजदूर का पूर्ण अभाव है । इसलिए उन्हें कम मजदूरी
पर ही काम करने के लिये बाध्य होना पड़ता है । मित्रों की सभी लक्ष्य उनमें स्थायी
अधिक न होने के कारण मित्रों अपना मजदूर नहीं बन पाती ।

८. मित्रों की अल्प प्राथमिक दिनांशे वाले कुछ व्यवसाय—कुछ
व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें मित्रों की मात्र अधिक है और पूर्ण कम । उदाहरण के लिये,
कच्चा पाट बालाघों में वेतन की प्रत्यादिवाओं की ही आवश्यकता पड़ता है और वे कम
सरता में मित्रों हैं, इसलिए उन्हें वहाँ अच्छा वेतन मिलता है । इसी प्रकार मित्रों के
पाकानों और दाईयानों में मुनिमिन नगें और दाईयों की माँग पूर्ण की जाती है अधिक
होने पर उन्हें अच्छा वेतन मिल जाता है । टाटविस्त के काम में भी उनकी कार्य-
कुशलता के कारण उनकी माँग देखी जाती है जिसमें उनको वेतन अच्छा मिल जाता है ।

मजदूरी-भुगतान के दण (Methods of Wage-Payment)

प्रायः मजदूरी-का प्रकार से दो जाती है—(१) समयानुसार मजदूरी, और (२)
कार्यानुसार मजदूरी ।

(१) समयानुसार मजदूरी (Time Wages)—समयानुसार मजदूरी
यह मजदूरी-भुगतान का दण है जिसमें मजदूरी एक निश्चित समय के पश्चात् दो
जाती है । यह समय मासगणित या एक दिन, एक सप्ताह, एक पक्ष अथवा एक महीना
होता है । इस प्रकार के मजदूरी-भुगतान के दण में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा
जाता कि अधिक न जितना कार्य किया है वरन् अधिक का एक निश्चित कार्य मीट दिया
जाता है और वह कार्य की अपनी योग्यतानुसार करना रहता है । मजदूरी देन समय
अधिक में कोई यह नहीं पूछेगा कि उनमें कुछ दिनकी उलासि की है वरन् वेद न यह
बात देखी जावेगी कि अधिक न पूरे समय तक कार्य किया या नहीं । यदि वह कुछ
दिनों काम पर नव्य इच्छा में नहीं आता तो उनके दिनों की मजदूरी बाट कर उनका
दे दी जाती है ।

समयानुसार मजदूरी के लाभ (Advantages of Time Wages)
समयानुसार मजदूरी के निम्नलिखित लाभ हैं :—

१. काम की स्थिरता (Regularity of Employment)—जिन
धर्मियों की समयानुसार मजदूरी दी जाती है उनका यह दण नही रहता कि काम हाथ
पर उनको बेगमगार होता पड़ता ।

२. शारीरिक शक्ति की रक्षा (Protection of the physique of
labourers)—इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिक निश्चित समय में अधिक कार्य नहीं
करता । अतः उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है ।

३. बीमारी आदि अवस्थाओं में नियमित मजदूरी—का मिलना (Certainty of Wages in Illness etc.)—समयानुसार मजदूरी देने का यह लाभ होता है कि यदि श्रमिक बीमार पड़ जाय तो भी उसका मजदूरी मिल सकती है। इस प्रकार बीमारी के कारण श्रमिक का श्रमिक कठिनाई का सामना नहीं करता रहता।

४. हुनर व यारीक कारीगरी के काम के लिए उपयोगी (Useful for Delicacy and Perfection of Workmanship)—जिन काम में हुनर व यारीक कारीगरी की आवश्यकता होती है वहाँ इस प्रणाली का उपयोग लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे कामों के लिये कार्यानुसार मजदूरी मिलने पर काम जल्दी जल्दी किया जाता है जिससे वह अच्छा नहीं बन पाता।

५. जिन व्यवसायों में काम मापने की कठिनाई होती है उनके लिए उपयोगी (Useful for those occupations in which measurement of work is difficult)—बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें काम का मापना कठिन होता है—जैसे, निक्षेप, प्रत्यक्ष आदि के काम। इन कामों के लिए समयानुसार मजदूरी भुगतान-प्रणाली उपयोगी सिद्ध होती है।

समयानुसार मजदूरी की हानियाँ (Disadvantages of Time Wages)—समयानुसार मजदूरी में निम्नलिखित हानियाँ हैं—

१. उत्पादन में ह्रास और लागत व्यय में वृद्धि (Decrease in Production and Increase in Cost of Production)—मजदूरी के इस उतार का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें श्रमिक मुक्तों में काम करते हैं। उदात्त उत्पादन के बढ़ने और घटने में कोई दिनचर्या नहीं रहती। इस कारण उत्पादन कम होता है और लागत व्यय में वृद्धि हो जाती है।

२. कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का अभाव (Lack of incentive to increase efficiency)—इसमें अत्यन्त निरिच्छा प्रेरणार का आश्वासन हान के कारण श्रमिकों को अधिक और उत्तम कार्य कराने का प्रोत्साहन नहीं मिलना तथा परिश्रमी और कामदार श्रमिकों के समान ही पारिश्रमिक मिलता है।

३. निरीक्षण-व्यय में वृद्धि (Increase in Supervision Cost)—इसमें एक निश्चित पारिश्रमिक का आश्वासन हान के कारण श्रमिकों के कार्य में निरिच्छा आ जाती है। अतः उनके ऊपर देखभाल करने के लिए निरीक्षण करने पड़ते हैं जिसके कारण घर्षा बढ़ जाता है।

४. कुशल तथा कम-कुशल श्रमिकों में अन्तर करने की कठिनाई (Difficulty in Distinguishing between Efficient and Less Efficient Labourers)—इस प्रणाली में अत्यन्त कुशल तथा कम कुशल श्रमिकों में अन्तर करना कठिन हो जाता है। कुशल श्रमिकों का अपनी कुशलता में कम अनुमान में मजदूरी मिलती है और कम कुशल श्रमिकों का अधिक अनुमान में।

(२) कार्यानुसार मजदूरी (Piece Wages)—कार्यानुसार मजदूरी वह मजदूरी भुगतान का ढंग है जिसमें मजदूरी श्रमिकों के कार्य के परिमाण

४ काम शीघ्र समाप्त होने पर बेकारी का वृद्धि (Increase in Unemployment when the Work is finished)—जब अधिक काम को शीघ्र समाप्त कर देता है तो उस बेकारी का मुँह देखा पड़ता है। समयानुसार मजदूर मध्य धीरे धीरे काम करता है इसदिन काय बहुत समय तक चलता रहता है।

५ औजार शीघ्रता के कारण अधिक दूटते हैं (More Wastage of tools) यद्यपि अधिक का यह प्रयत्न रहता है कि औजार (उपकरण) न तो नष्ट भा काम क्षतिग्रस्त न करने के कारण औजारों में दूट पुनः होना स्वाभाविक है।

६ श्रमिका में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है (A spirit of jealousy and competition is created among labourers)—इस रीति के अनुसार काम करने वाले श्रमिका में पारस्परिक ईर्ष्या इतनी तब प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। साथ ही अथवा श्रमिका के साथ साथ काम करने पर जब दोष श्रमिका को प्रतीय मजदूरी मिलती है तो प्रयोग्य श्रमिका में इससे कारण भी उत्पन्न हो जाती है।

समयानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरी भुगतान की प्रणालियाँ का क्षेत्र (Scope of Time and Piece Systems of Wage payment)—उत्पन्न किन्तु यह स्पष्ट है कि मजदूरी भुगतान की कोई भी प्रणाली पूर्ण एवं निर्दोष नहीं है। ज्ञान ही प्रणालियाँ विविध क्षमता में प्रयुक्त भूँष्य रहता है। जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत काम के परिमाण का मापनीयता जा सकता है उनमें कार्यानुसार मजदूरी भुगतान का ढंग ठीक रहता है। उस विविध प्रकार के कारखानों में काम करने वाले श्रमिका के काम। परन्तु जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत काम का परिमाण मापना कठिन होता है उनमें समयानुसार मजदूरी भुगतान का ढंग अपनाया जाता है। जैसे ग्रन्थपत्र इजीनियर चार्ज प्रयत्न आदि के काम। इससे निर्दिष्ट समयानुसार मजदूरी भुगतान की रीति का उपयोग उन मामलों में भी किया जाता है जिनमें काम की विस्म (Quality) का पूरा ध्यान रखा जाता है तथा हुनर के कारण कारणों की आवश्यकता रहता है। जैसे यंत्रिका विस्म के यंत्रों के बनाने का काम गान हुनार तथा बेर-नूँट बनाने का काम आदि।

निष्कर्ष (Conclusion)—यदि हम दोनों प्रकार की मजदूरी भुगतान प्रणालियों की तुलना करें तो दोनों में ही कुछ दोष पाये जाते हैं। यद्यपि अब मजदूरी की एक ही प्रणाली निर्धारित नहीं किन्तु अब दोनों प्रणालियाँ मिला दी गई हैं। इस नई प्रणाली का मजदूरी भुगतान की प्रगतिशील पद्धति (Progressive System of Wage payment) या प्रीमियम बोनस प्रणाली (Premium Bonus System) कहते हैं। इसमें समयानुसार तथा मजदूरी दी जाता है परन्तु यदि अधिक योग्य है और वह अधिक काम कर सकता है तो उसका उस अधिक काम की भी मजदूरी दी जाती है।

निर्वाह मजदूरी (Living Wage)—फ्रांस के कृषि-अर्थशास्त्रियों (French Physiocrats) के मजदूरी के जीवन-निर्वाह के सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages) के अनुसार मजदूरी इतनी ही हो सकती है जितनी कि श्रमिक को अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करने के लिये आवश्यक है, वह न उसमें अधिक हो सकती है और न कम । इस जीवन-निर्वाह के सिद्धान्त को १९वीं सताब्दी के मध्य के प्रख्यात छोट्ट दिया गया और उसके स्थान पर जीवन-स्तर के सिद्धान्त (Standard of Living Theory) पर जोर दिया जाने लगा । इस सिद्धान्त में बताया गया कि मजदूरी श्रमिक के जीवन-निर्वाह की सीमा द्वारा निश्चित न होकर उसके जीवन-स्तर द्वारा निश्चित होती है । यदि श्रमिक को उसके जीवन-स्तर में कम मजदूरी दी जायगी, तो वह काम न करेगा । इस मजदूरी को निर्वाह-मजदूरी (Living Wage) कह कर पुकारा गया । अस्तु, निर्वाह मजदूरी वह पारिश्रमिक है जो श्रमिक के जीवन-स्तर द्वारा जिसका कि यह घम्यासी है, निर्धारित होता है । इस सिद्धान्त को भी पहले के समान छोड़ना पड़ा, क्योंकि यह भी केवल पूर्ति की ओर ही ध्यान देता है और माँग की उपेक्षा करता है ।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)—श्रमिकों को उद्योगपतियों की तुलना में सोरा या भय-साध करने की शक्ति बहुत कम होती है । अतः उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होना स्वाभाविक है । उद्योगपति श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी देते हैं कि वह उनके जीवन-निर्वाह के लिये अपर्णाप्त होती है । अतः अब इस बात को अच्छी तरह स्वीकार कर लिया गया है कि सामाजिक न्याय के दृष्टि में श्रमिकों की मजदूरी पर्याप्त होनी चाहिये जिससे श्रमिक स्वास्थ्य और साधारण सुखहासों के दृष्टिकोण से उचित और अच्छे रहन-सहन के स्तर से अपना जीवन-निर्वाह कर सके । श्रम का पानी बहाना अब अनुचित समझा जाता है । इसलिये एक ओर मजदूर संघ (Trade Unions) श्रमिकों को संगठित कर अच्छी मजदूरी दिलाने में प्रयत्नशील हैं तो दूसरी ओर सरकार कानून द्वारा 'न्यूनतम मजदूरी' निर्धारित कर उद्योगपतियों को अच्छी मजदूरी देने के लिये बाध्य कर रही है । श्रमिकों को पूर्ति चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ जाय, परन्तु कानून द्वारा निश्चित न्यूनतम मजदूरी तो उद्योगपतियों को प्रदत्त देनी ही पड़ेगी । अस्तु, न्यूनतम मजदूरी वह कानून द्वारा निश्चित पारिश्रमिक है जिसके द्वारा श्रमिक साधारणतया अच्छे रहन-सहन के स्तर से अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

भारतवर्ष में सबसे पहले सन् १९३१ में राजकीय श्रम-प्रायोग ने भारत सरकार का ध्यान दान और अत्यधिक क्रिया था, परन्तु देश-विकास के पूर्व तक सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया । सन् १९४८ में न्यूनतम मजदूरी विधान (Minimum Wage Act) पास करके कुछ उद्योग-धंधों में जिनमें श्रमिकों की दशा अत्यन्त दयनीय थी, न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का प्रयास किया गया । सन् १९५० में इस विधान में संशोधन किये गये जिनके फलस्वरूप सभी प्रकार के उद्योग-धंधों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की व्यवधि तीन वर्ष कर दी गई । कृषि में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने से पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों की स्थिति जहाँ न जाय । इसी भावना से प्रेरित होकर सन् १९४६ में यह कार्य प्रारम्भ किया

गया, किन्तु सन् १९११ तक यह कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण सरकार ने कृषि में न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने की अवधि मार्च १९१३ तक बढ़ा दी ।

उचित मजदूरी (Fair Wage)—देन की आर्थिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि श्रमिकों को इतनी मजदूरी अवश्य प्राप्त हो जिससे उनकी कम-अ-कम आवश्यकताएँ पूर्ण होने के अतिरिक्त उनके रहन सहन का स्तर भी ऊँचा रह सके । इसके अभाव में श्रमिकों में असन्तोष की भावना उत्पन्न होता स्वाभाविक ही है । सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति भी नियुक्त की जिसकी विचारों के आधार पर वैश्वीय मन्त्रिमण्डल ने सन् १९१० में एक विधेयक तैयार किया । इस विधेयक के अनुसार उचित मजदूरी की माग्रा न्यूनतम मजदूरी में अधिक किन्तु जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से कम मानी गई है । उचित मजदूरी द्वारा अब यह सम्भव हो सकेगा कि श्रमिकों की भोजन के अतिरिक्त कुछ कुछ वस्तुएँ भी उपलब्ध हो जायें । उचित मजदूरी का निर्धारण एब बोर्ड द्वारा होगा जो इसे निर्दिष्ट करते समय देन की वास्तविक आय, द्रव्य उद्योग घण्टों में प्रचलित मजदूरी दर, उद्योग की भुगतान-शक्ति, श्रमिकों की कार्य-क्षमता तथा श्रम की बकाबट, श्रमिकों के पारम्परिक उत्तरदायित्व तथा उनके अनुभवों को ध्यान में रखेगा ।

श्रमिक मध्य

(Trade Unions)

आवश्यकता (Necessity)—श्रमिकों का संघ या भाव ताव करने की शक्ति कम होती है । अतः वे उद्योगपतियों से प्रतियोगिता करने में निर्बल सिद्ध होते हैं । इस निर्बलता को दूर करने के लिये श्रमिक अपने आपको संगठित करने हैं । इन मजदूरों को ही 'श्रमिक मध्य' वा 'मजदूर संघ' आदि नामों से पुराण्ये हैं ।

परिभाषा (Definition)—साधारणतया श्रमिक मध्य में उस संस्था का तात्पर्य है जो श्रमिकों के हितों तथा उनके अधिकारों के रक्षण की रक्षा करता है । मिडनी वेब (Sidney Webb) तथा बेट्रिस वेब (Beatrice Webb) के शब्दों में श्रमिक मध्य श्रमिकों की वह स्थायी समस्या है जिसका उद्देश्य उनकी मौकरी-समस्या को दूर करना या उनमें सुधार करना है ।¹ क्लो (Clay) के अनुसार श्रमिक मध्य वह संस्था है जिसका उद्देश्य श्रम या भाव-ताव करने के मामले में श्रम के विक्रेता को श्रम के क्रय के बराबर शक्ति देना है ।²

1—Sydney Webb and Beatrice Webb define a trade union as "a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment."

2—"The Trade Union is an organization designed to put up the seller of labour on an equality with the buyer as regards bargaining strength"

श्रमिक सघों के कार्य (Functions of a Trade Union) — श्रमिक सघ के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं —

(१) श्रमिकों को संगठित कर उनकी मजदूरी बढ़वाना—विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रमिकों को एक सूत्र में बाँध कर संगठित करना श्रमिक सघ का मुख्य कार्य है। श्रमिक सघ सामूहिक रूप में श्रमिकों की माँगें प्रस्तुत करते हैं और उद्योगपतियों पर दबाव डाल कर उनकी मजदूरी बढ़वाते हैं।

(२) एकाग्र स्थापित करना तथा भ्रातृ भाव को बढ़ि करना—श्रमिक सघ श्रमिकों को संगठित कर, उनमें भ्रातृ भाव का संचार करते हैं तथा उनमें एकाग्र स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

(३) प्राप्त सुविधाओं तथा अधिकारों की रक्षा करना—श्रमिक सघ श्रमिकों को उनके अधिकारों का उचित ज्ञान करा देते हैं। जब कभी किसी श्रमिक के साथ उसका स्वामी दुर्व्यवहार करता है, तो सघ उसका पक्ष लेकर उचित अधिकारों के लिये सन्धन करते हैं।

(४) श्रमिकों की शिक्षा स्वास्थ्य आदि बातों की व्यवस्था कर उनकी वार्षिक क्षमता में वृद्धि करना—सघ श्रमिकों की शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों की ओर भी पूर्ण ध्यान देते हैं, क्योंकि इनकी समुचित व्यवस्था श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। सघ इस बात को भी देखते रहते हैं कि श्रमिकों को रहने के लिए उचित स्थान प्राप्त हो।

(५) बीमारी, बेकारी या अन्य आपत्ति-काल में अपने सदस्यों की सहायता करना—बीमारी के समय श्रमिक सघ अपने सदस्यों की सहायता करते हैं तथा बेकार हो जाने पर उनके भरण पोषण का प्रबन्ध करते हैं।

(६) श्रमिकों का जीवन स्तर ऊँचा करना—श्रमिक सघ अपने सदस्यों को स्वस्थ एवं शिक्षित बनाकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी मजदूरी में वृद्धि होती है। इन सबों कारण उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार होता है।

(७) श्रमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहन देना—श्रमिकों को विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों से परिचित करा कर उनको गतिशील बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

श्रमिक सघ और मजदूरी (Trade Union and Wages)—सघ मजदूरी में अधिकाधिक वृद्धि करवाने का प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है जबकि उनके सदस्य अधिकांश श्रमिक ही होते हैं। परन्तु यदि उद्योगपति कहीं बाहर से श्रमिकों को लाने में सफल हो जाता है तो मजदूरी का बढ़ना इस बात पर भी निर्भर होता है कि श्रमिक सघों के पास बेकारी के समय में श्रमिकों का भरण-पोषण करने के लिए कितना कोष है। यदि यह कोष धनसात है तो हड़ताल अधिक समय तक न चल सकेगी और मजदूरी न बढ़ सकेगी। श्रमिक सघ श्रमिकों को सोदा या भाव ठाव बनाने की शक्ति को बढ़ाकर भी मजदूरी में वृद्धि करवा सकते हैं या उन्हें शिक्षा आदि देकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर मजदूरी बढ़ा सकते हैं। परन्तु ये मजदूरी अधिक की सीमांत उत्पादनता (Marginal Productivity) से अधिक

गहरी बढ़वा मकानों और यदि वे इससे अधिक मजदूरी बढ़वाने में सफल भी हो गये तो इसके कारण बहुत से कारखाने बंद हो जायेंगे या ऐसे यन्त्रादि का आविष्कार किया जायेगा जिन पर काम करने के लिए कम से कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़े। इन दोनों परिस्थितियों में बेकारी बढ़ जायेगी और कुछ समय पश्चात् मजदूरी घट जायेगी। अन्तु अधिक सप भी मजदूरी को अधिक की उत्पात्कता में अधिक स्थायी रूप में वृद्धि कर सकते।

भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन

(Trade Union Movement in India)

श्रमिक संघ आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास—भारतवर्ष में सबसे पहले सन् १८६० में श्री लोत्तण ने बम्बई में 'बम्बई मिल् मजदूर-संघ' नामक संस्था स्थापित की और श्रमिकों की मांगों का प्रचार करने के लिए 'दीनबन्धु' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला। सन् १९०३ में छापाखाना युनियन कलकत्ता में डाक यंत्रियन बम्बई में और सन् १९१० में कामगार हितवृद्धक मन्त्रालय में स्थापित हुई। परन्तु अधिकतर श्रमिक संगठन का वास्तविक प्रारम्भ इस देश में प्रथम महापुरुष के पश्चात् ही हुआ। सन् १९१८ में श्रमिक संगठन ने बड़ा जोर पकड़ा। यद्वासे में श्री बी० पी० वाडिया तथा पन्नाब मन्ना राजपतराय के नेतृत्व में श्रमिक संघों की स्थापना हुई। कलकत्ता और बम्बई में श्रमिक संगठन सुदृढ़ हुए। सन् १९२० में महामा गांधी ने अहिंसवाद के सूत्री कण्ठा के कारणने का प्रसिद्ध श्रमिक संघ स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस की स्थापना हुई जिसका प्रथम अधिवेशन राजा राजपतराय की अध्यक्षता में उसी वर्ष बम्बई में सम्पन्न हुआ और श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बन गया। सन् १९२३ के पश्चात् श्रमिक संगठन कुछ निम्न पड़ गया। उस समय के श्रमिक संघ केवल हड़ताल समितियाँ (Strikes Committees) ही थी जो संघर्ष समाप्त हो जाने पर स्वयं व भी समाप्त हो जाती थी। सन् १९२६ में भारत सरकार ने इण्डियन ट्रेड युनियन एक्ट (Indian trade union Act) पारित किया जो श्रमिक आन्दोलन को सुदृढ़ और उत्तम करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून ने रजिस्टर्ड श्रमिक संघों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की। इसके अन्तर्गत पार्षदिक श्रमिक संघ या उद्योग श्रमिकों की औद्योगिक संघों को प्रोत्साहित करने से इनके दृष्टि नहीं किया जा सकता। इसके पूर्व उन पर पठन का कानून लागू होता था। इस प्रकार इस कानून से श्रमिक आन्दोलन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। परन्तु सन् १९२६ में अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस में फूट पड़ गई और वह दो भागों में विभक्त हो गई—ट्रेड युनियन काँग्रेस जिस पर मार्क्सवादी दल के नेताओं का जोर था और नेशनल ट्रेड युनियन फेडरेशन जिस पर नरमदली नेताओं का प्रभाव था। सन् १९३८ में श्री बी० पी० गिरि के प्रेरणा के अन्तर्गत्त दल दोनों में मिले हुए थे। परन्तु कुछ काल में पुनः फूट हो गई। सन् १९३६ में श्री एम० एम० राय ने एक अलग इण्डियन सेक्टर फेडरेशन स्थापित कर दी। सन् १९४७ में काँग्रेस के अनुयायियों ने श्री मुन्नाजीराव नन्दा के नेतृत्व में एक पृथक् श्रमिक संघ स्थापित किया और इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (Indian National Trade Union Congress) रखा।

सन् १९४७ में भारतीय ट्रेड युनियन एक्ट १९२६ में संशोधन किया गया। एम० मुन्नाजीराव नन्दा को कि स्वयं न्यायालय (Labour court) के आदेश

पर नियोजकों (Employers) को अनिवार्य रूप से ट्रेड यूनियन को मान्यता देनी होगी। जा अधिक सध मान्य होते है उन्हें अधिको की नियुक्ति, काम की परिस्थिति और शर्तों आदि अधिको के सम्बन्ध के सब मामलों में पूछ-ताछ और निश्चय करने का अधिकार होता है। उन्हें मिल या कारखाने के भीतर अपने नोटिफ आदि लगाने का भी अधिकार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सन् १९४७ के संविधान के अनुसार हुई है वह यह है कि मान्य अधिक सधों और मिल मालिकों के लिए कुछ बातों के बरने को अनुचित घोषित कर दिया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट में संविधान करने के उद्देश्य से सन् १९५० में एक ट्रेड यूनियन बिल भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया। इस बिल में अधिक सधों को अनिवार्य रूप से नियोजकों द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव मुख्य संशोधन था परन्तु इस दिन की धारा ३ की नीच आलोचना की गई। इसलिये सरकार ने इसे पास कराने के उद्देश्य को त्याग दिया।

अधिक सध आन्दोलन की वर्तमान अवस्था—सन् १९५७ ५८ में भारत में लगभग ६,८२९ रजिस्टर्ड अधिक सध थे और इनके सदस्यों की संख्या २६,७२,५३३ थी। इस समय अधिको के चार बड़ प्रमुख भारतीय सध है जिन पर चार प्रमुख राजनैतिक दलों का प्रभुत्व है। इनके नाम ये हैं—भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (Indian National Trade Union Congress), प्रखित भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (All-India Trade Union Congress), हिन्द मजदूर सभा (Hind Mazdoor Sabha) और संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस (United Trade Union Congress)। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (I. N. T. U. C.) मात्र भारत में अधिको की सबसे बड़ी प्रखित भारतीय संस्था है। इस पर कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। दूसरी बड़ी संस्था प्रखित भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिस पर साम्यवादियों का पूर्ण प्रभुत्व है। तीसरी बड़ी संस्था हिन्द मजदूर सभा है जिस पर समाजवादियों का पूर्ण प्रभाव है। संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस प्रकार की चौथी संस्था है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय लम संघटन (I. L. O.) का सदस्य होने के कारण भारतीय अधिक आन्दोलन को पर्याप्त बल मिला और उसने हमारे देश के आन्दोलन का अन्य देशों में सम्पर्क स्थापित कर दिया।

अधिक-मध्य आन्दोलन की प्रगति पर दृष्टिपात—एत वर्षों में अधिक आन्दोलन ने भारत में उत्प्रेक्षणीय उन्नति की है और आज सबसभ प्रत्येक पक्ष में अधिक संगठित हैं। यही नहीं कि औद्योगिक केन्द्रों में ही अधिक सभाएँ संगठित हुईं हो, परन्तु छोटे छोटे कर्मों में भी जहाँ एक दो कारखाने हैं अधिक सभ स्थापित हो चुके हैं। मोटर बस ड्राइवर, पॉपर हाउस तथा ताँगा और रिक्शावालों, दुकानों पर काम करने वालों, शपरासियों, डाकघर, रेल, बैंक व दफ्तरो के कर्मचारियों तक के सध स्थापित हो चुके हैं। अस्तु, अधिको में संगठित होने की पूर्ण आसक्ति हो चुकी है।

इतना होने हुए भी भारतीय लम आन्दोलन अभी इतना उन्नत नहीं हो सभा है जितना पश्चिमी देशों में। भारत में अधिक सधों के सदस्यों की संख्या औद्योगिक अधिको की सम्पूर्ण संस्था का केवल एक सप्तमात्र है। अधिकांश भारतीय अधिको में प्रशिक्षित होने के कारण उनके नेता प्रायः बाहरी होते हैं जैसे वकील राजनैतिक कार्यकर्ता आदि। हड़ताल की बाध रखने के लिये उनके पास पर्याप्त कोषों का प्रभाव है। बहुत थोड़े अधिक सध ऐसे हैं जिनके पास बेकारी, बीमारी और वृद्धावस्था के लाभ हैं। एक ही केन्द्र में स्थापित एक ही प्रकार के उद्योगों में कई अधिक सध बने हुए हैं। अधिक सध

श्रमिक सभा के केन्द्रीय सच भी बहुत से हैं। इन प्रकार भारतीय श्रमिक-संघ-प्रान्दोलन की प्रगति श्रमिक सन्तोषजनक नहीं रही।

भारतवर्ष में श्रमिक-संघ प्रान्दोलन की कठिनाइयाँ (Difficulties of Trade Union Movement in India)—भारत में श्रमिक-संघ-प्रान्दोलन को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :—

१. भारतीय श्रमिक की पर्यटनशीलता (Migratory Character of Indian Labour)—श्रमिकों का श्रमिक गाँवों के हाते हैं जो जमन में सबबारा मिसने पर सहरो में जा जाते हैं। परन्तु फसल के समय पुनः गाँव छोड़कर गाँव को नाने जाने हैं। केवल यही नहीं, के-बार वर्ष काम कर कुछ पया जोड़कर फिर गाँव में जा समते हैं। इस श्रमिकों की पर्यटनशीलता और अन्धाधों निवास उनके संगठन में बाधक सिद्ध होता है।

२. भारतीय श्रम की भिन्नता (Heterogeneous Character of Indian Labour)—हमारे औद्योगिक केन्द्रों में विभिन्न प्रान्द, जातियाँ तथा धर्मों के श्रमिक काम करते हैं जिनके रहन-सहन के ढंग तथा ऐति-रिवाज अलग-अलग होते हैं। अतः उनमें जाति द्वेष, प्रान्तीयता, भाषा भेद और धर्म-भेद पाया जाता है जिसके कारण उनमें एकता स्थापित नहीं की जा सकती।

३. शिक्षा का अभाव (Lack of Education)—अधिकांश श्रमिक अनशिक्षित होते हैं जिसके कारण संगठन के महत्व एवं लाभों को नहीं समझने पाते। श्रमिकों की प्रज्ञागता संगठन के विकास में बाधक सिद्ध होती है।

४. अनुशासन का अभाव (Lack of Discipline)—किसी संगठन की मुचाह रूप में स्थापित करने के लिए अनुशासन अत्यावश्यक है। परन्तु भारतीय श्रमिकों में अनुशासन की कमी है। उन्हें किसी नियम में बधना और उसके अनुसार मान्यता करना बहुत बुरा मान्य होता है।

५. निर्धनता (Poverty)—भारतीय श्रमिक की प्रसाधारण निर्धनता श्रमिक-संघों के विकास में बाधक सिद्ध होती है। अधिकांश श्रमिकों के लिये नाममात्र खादा भी भार स्वरूप होता है। इसलिये वे ऐसी संस्थाओं की मददयता से प्रायः जो बुराते हैं।

६. श्रमिक नेताओं की कमी (Dearth of Labour Leaders)—श्रमिक प्रायः शिक्षित नहीं होते इसलिये उनमें उनके स्वयं के नेता नहीं हो पाते। अन्य लोग अपने स्वार्थ को लेकर नेता बन जाते हैं और स्वार्थ सिद्ध होते ही पृथक् हो जाते हैं। अतः भारतीय श्रमिक प्रान्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये योग्य, सच्चे तथा ईमानदार व्यक्तियों के नेतृत्व की आवश्यकता है।

७. औद्योगिक केन्द्रों का दूर-दूर तथा बिखरे हुये होना (Distant & Scattered Industrial Centres)—भारत में औद्योगिक केन्द्र बहुत दूर-दूर और बिखरे हुये हैं। इस कारण भी श्रमिक प्रान्दोलन अधिन एकत्र नहीं हो पाता। यदि श्रमिक वसतिगृह आध-वास हों और औद्योगिक केन्द्र किसी क्षेत्र विशेष में हों तो श्रमिक प्रान्दोलन अधिक बलवान् हो सकता है।

८. विभिन्न राजनैतिक दलों की वैयक्तिकता का अग्रगण्य (Instrument to Various Political Parties) — आज अधिक वर्ग अनेक राजनैतिक दलों का सिकार बना हुआ है। प्रत्येक कार्यकर्ता अधिकांश का उपयोग अपने दल विशेष के लिये करना चाहता है। इन राजनैतिक दलों में आपस में बड़ा वैयक्तिक है। अतः नेता लोग आपसी भयंसा से घटे रहते हैं और अधिकांश की भलाई की ओर अधिक ध्यान नहीं देते।

९. अधिकांशों का निर्माण प्रायः हड़ताल के उद्देश्य से होता है, अन्य उद्देश्यों की उपेक्षा की जाती है (Trade unions are generally formed for strike purposes, other aims are neglected) — भारतवर्ष में अधिकांश आन्दोलन की एक बड़ी कमी यह है कि अधिकांश संस्था का निर्माण प्रायः हड़ताल करवाने के उद्देश्य से ही होता है; अन्य उद्देश्यों की उपेक्षा की जाती है। हड़ताल सकल हुई ही सभ स्थायी हो जाता है और यदि असफल हुई तो सिधित हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है।

१०. मालिकों का विरोध (Opposition of Employers) — मालिकों का विरोध भी आन्दोलन को सकल बनाने में एक बाधा है। मालिक कई प्रकार से इन संघों का विरोध करते हैं और उनकी सौदा करने की शक्ति अधिक होने के कारण वे सफल भी हो जाते हैं। अधिकांश के निरीक्षक (Superisors) भी इन संघों का विरोध करते हैं, क्योंकि अधिकांश के अग्रगण्य रहने पर ही उनका प्रभुत्व बाधित रह सकता है।

निष्कर्ष—इन बाधाओं के होने हुए भी भारत में अधिकांश आन्दोलन का अधिक उन्मुख प्रतीत होता है। शून्यः शून्यः यह आन्दोलन जोर पकटना जा रहा है जिनके कारण बाधाएँ भी कम होती जा रही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम हड़ताल, तगम और सबाई से इस ओर आगे बढ़ते जायें।

भारतवर्ष में मजदूरी

(Wages in India)

अन्य देशों की तुलना में भारत के अधिकांशों को कम मजदूरी मिलती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) औद्योगिक उन्नति की कमी—भारत में औद्योगिक उन्नति बहुत कम हुई है जिससे फलस्वरूप यहाँ पर कारखाने बहुत कम हैं। इस कारण अधिकांशों की माँग भी कम है। कृषि में उन्नति कम होने के कारण कृषक अधिकांशों को अधिक पारिधायिक नहीं दे सकते।

(२) जन-संख्या की अधिकता—भारत में जन-संख्या बहुत बढ़ रही है जिसके कारण काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। श्रम की पूर्ण माँग से अधिक होने के कारण मजदूरी की दर गिरता स्वाभाविक है।

(३) कार्यक्षमता में कमी—भारतीय अधिकांश निर्धन एवं अशिक्षित हैं, इस कारण उनका जीवन-स्तर नीचा है। इससे उनकी कार्य-क्षमता बहुत कम है। कार्य क्षमता कम होने के कारण वे अधिक उत्पादन नहीं कर पाते और उनकी मजदूरी अधिक नहीं बढ़ पाती।

(४) अधिक उत्पादन-थय—भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता कम होने के कारण उसके द्वारा होने वाला उत्पादन भी कम होता है जिससे प्रांत इकाई उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जाती है। इसलिये वही हुई लागत की दृष्टि से अधिक मजदूरी मिलना सम्भव नहीं है।

(५) थय की गतिशीलता में कमी—भारत में थय की गतिशीलता कम होने के कारण भी वहाँ श्रमिका की मजदूरी कम है।

गाँवों में शहरों की अपेक्षा कम मजदूरी—यदि हम भारत के गाँवों और शहरों में मिलने वाले मजदूरों की तुलना करें तो ज्ञात होगा कि गाँवों में शहरों की अपेक्षा मजदूरी कम है। इसके कई कारण हैं—(१) गाँवों में स्वास्थ्य, ईंधन आदि शहरों की अपेक्षा सस्ता है। (२) गाँवों में मजान कियाया भी सस्ता होता है। (३) गाँवों में मजदूरी प्रायः रीति रिवाजों द्वारा निर्धारित होती है जब कि शहरों में मजदूरी अधिकतर प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होती है। इसलिये गाँवों में मजदूरी का कम होना स्वाभाविक है। (४) श्रम में उत्पत्ति कम होने के कारण अधिक मजदूरी नहीं मिल सकती। (५) गाँवों में वास्तविक मजदूरी अधिक होने से मजदूरी कम होती है। (६) गाँवों में अधिक इतने समर्थित नहीं हैं जितने कि शहरों में। इसलिए वे अधिक मजदूरी पाने के लिए सक्षम नहीं कर सकते। यातायात व उद्योग के साधनों की उन्नति के प्रभाव के कारण शर्तें, धान, गाँवों और शहरों का सम्पर्क बढ़ता जा रहा है जिससे गाँवों में श्रमिका की कम मजदूरी बिचाने का कारण बन्य होवे जा रहे हैं।

अभ्यासाय प्रश्न

इन्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—मजदूरी का अर्थ समझाइये। वह कैसे निर्धारित होती है? जीवन स्तर का मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- २—भारतीय और नकद मजदूरी में क्या भेद है? बंगाल की प्रजातान्त्रिकता का मजदूरी की दर पर क्या प्रभाव है। अस्सी मजदूरी व कम मजदूरी जानने के लिये किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
- ३—थय की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? भारत में थय की गतिशीलता पर सामाजिक प्रथाओं का कहीं तक प्रभाव पड़ता है? मुखार व मुभाव दीजिए।
- ४—भारत में एक वृषण मजदूर विनी पड़े नगर में एक रुपये प्रतिदिन मजदूरी की अपेक्षा गाँव में आठ आना प्रतिदिन मजदूरी तथा अधिक धन देकर जाता है। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? (रा० बा० १९५६)
- ५—जीवन-स्तर का मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप अपने जीवन-स्तर में वृद्धि करके अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं? (रा० बा० १९५४)
- ६—भारत में और नकद मजदूरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में विभिन्न उद्योगों में मजदूरी में अंतर क्या है? (रा० बा० १९५२)
- ७—न्यूनतम और उच्च मजदूरी पर टिप्पणी लिखिए। (अ० बा० १९५३)
- ८—समस्तमुखार और शर्मानुसार मजदूरी पर टिप्पणी लिखिए। (अ० बा० १९५८, १०)

६—“श्रम एक नाशवान् वस्तु है ।” श्रम की विशेषताएँ समझाइये और यह बतलाइये कि इतका मजदूरी निर्धारण करने में क्या प्रभाव पड़ता है ? (स० भा० १९५७)

१०—श्रम की गतिशीलता का क्या अभिप्राय है ? इसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं ? क्या भारत में श्रम की गतिशीलता में कुछ बाधाएँ हैं ? यदि हैं, तो उन्हें स्पष्ट कीजिये । (स० भा० १९५४)

११—श्रम की सीमान्त उत्पादकता में श्रम का माँग मूल्य किस प्रकार नियत होता है ? (नागपुर १९५०)

१२—‘श्रम की गतिशीलता’ किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं ? यह किन बातों से प्रभावित होती है ? (सागर १९५०)

१३—नवव और असली मजदूरी का अन्तर स्पष्ट कीजिये । असली मजदूरी निर्धारित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिये । (पटना १९४६)

१४—स्वतन्त्र प्रतियोगिता में मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है ? (पञ्चाय १९५१)

१५—नोट लिखिये :—

मसल तथा नकद मजदूरी (स० बी० १९६०)

१६—नकद और असली मजदूरी में भेद स्पष्ट कीजिए । असली मजदूरी निर्धारण में किन बातों की ध्यान में रखेंगे । (रा० बी० १९६०)

१७—श्रमिक सभ का मजदूरी पर क्या प्रभाव है ? (रा० बी० १९५८)

इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ

१८—नवव और असली मजदूरी में क्या भेद है ? मजदूरी पर जीवन-स्तर और रोजी-रिवाजों का क्या प्रभाव पड़ता है ?

व्याज का अर्थ (Meaning of Interest)—व्याज शब्द के साधारण भाषा के अर्थ और अर्थशास्त्रीय अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। साधारण भाषा में हम व्याज उग राशि को कहते हैं जो उधार लेने वाला उधार देने वाले को उसी धन का उपभाग करने के बदले में देता है। अर्थशास्त्र में भी व्याज का यही अर्थ है। उत्पादन के पाँच माधनों में से पूँजी एक माधन है। एक साहसी (Entrepreneur) अपने उत्पादन में इन पाँचों माधनों में उनका उचित भाग वितरण करता है। अब, वह भाग जो पूँजी की सेवा के बदले पूँजीपति को दिया जाता है, व्याज (Interest) कहलाता है। अन्य चारों में, व्याज राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो पूँजीपति को उसकी पूँजी के लिये दिया जाता है। प्रायः पूँजी और व्याज शब्दों के रूप में दिये व लिये जाते हैं। व्याज प्रतिवर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है।

व्याज की परिभाषा (Definitions)—कारवर (Carver) के अनुसार व्याज वह आय है जो पूँजीपति को दी जाती है।¹

प्रो० सेल्गमैन (Selgman) के शब्दों में व्याज पूँजी उधार देने का प्रतिफल है।²

एल० ली मेसूरियर (L. Le Mesurier)—व्याज को इस प्रकार परिभाषित करते हैं—व्याज वह पुरस्कार है जो पूँजी को मिलता है।³

व्याज पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है—

(१) ऋण लेने वाले के दृष्टिकोण में (From Borrower's point

1—"Interest may be defined as the income which goes to the owner of capital"

—Carver Principles of Political Economy, p. 418.

2—"Interest is the return from the fund of capital."

—Selgman Principles of Economics.

3—"Interest is the reward paid to capital"

—L Le Mesurier Commonsense Economics, p. 65.

of view) —उधार ता हुई पूँजी उत्पादन में गहायन होती है, यथापि पूँजी में उत्पादन शक्ति है। अथवास्त्रेन हैनरी क्रे (Henry Crag) का कहना है कि व्याज पूँजी के प्रयोग के लिये दिया जाता है क्योंकि पूँजी में उत्पादन शक्ति होती है, इसलिये उधार लेने वाला इसको उधार लेकर हमका गहायना में अधिक उत्पत्ति करता है और वह इसमें से कुछ भाग पूँजीपति का उसकी पूँजी के उपयोग के बदले में दे देता है।¹ (२) उधारदाता के दृष्टिकोण से (From Lender's point of view) —पूँजी का इकट्ठी करने तथा उधार कर मूल्य में देने के लिए यह आवश्यक है कि उधारदाता उसका तात्कालिक उपयोग न करे। ऐसा करने में वह कुछ त्याग करता है जिसके लिये उस कुछ पुरस्कार मिलता है। इस आत्म-त्याग या मयम (Abstinence) का पुरस्कार का ही व्याज का नाम है सम्भावित करने है। इन्वर्स्ट का प्रसिद्ध अथवास्त्रो जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) का कहना है कि पूँजीपति पूँजी उधार देने समय आत्म-त्याग या मयम करने है। जब पूँजीपति पूँजी संचय करने में तो वह धन का प्रयोग नहीं करे। इस कारण उन्हें कष्ट होना है। इसी कष्ट का प्रतिफल व्याज है। मिल के सिद्धांत में व्याज आत्म-त्याग या मयम का प्रतिफल है।²

जब अथवास्त्रो मिल के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि धनी व्यक्तियों की प्रायः उतक मयम का अपेक्षा उनकी अधिकता होती है कि उन्हें मयम बचाने में कष्ट या त्याग नहीं करना पड़ता है किन्तु स्वयं स्वतः ही बचना रहता है। प्रो० मार्शल (Marshall) ने स्वयं कहा है कि पूँजी के मूल्य में बढ़ते सचयों बहुत धनी लोग होते हैं जिनमें से कुछ विनाशिता में रहने हैं और सचयुक्त के उम अर्थ में 'मयम' नहीं करने जिसमें यह 'आत्म-त्याग' का पर्यायवाची है।³

यह उचित है कि बहुत धनी लोग पूँजी संचय करने समय कुछ भी त्याग या मयम नहीं करते। परन्तु पूँजी उधार देने समय सभी पूँजीपतियों का प्रतीक्षा अवश्य करनी होती है। अतः स्पष्ट करने हेतु यह कहा जा सकता है कि जब पूँजीपति पूँजी उधार देते हैं तो यह स्वाभाविक है कि वे उसका उपयोग उस समय नहो कर संचयन बल्कि इस लिये पूँजी का लौटने तक उधार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें उन्हें कष्ट

1—"Interest is paid on the use of the capital because the capital is productive it enables its owner to produce more than he could without it and out of this additional product interest is paid."
—Henry Crag

2—"Interest is the remuneration for mere abstinence."

—J S Mill Principles of Political Economy, vol. I, p. 596

3—"The greatest accumulators of wealth are very rich some of whom live in luxury, and certainly do not practice abstinence in the sense of the term in which it is convertible with abstinence."

—A Marshall Economics of Industry, p. 136

हता है और व्याज इस कष्ट का पुरस्कार है। डॉ० रिचार्ड्स (Richards) के अनुसार व्याज प्राथमिक रूप से प्रतीक्षा का पुरस्कार है।^१ प्रो० मार्शल (Marshall) ने लिखा है कि "भविष्य के उपयोग के लिये वर्तमान के उपयोग के त्याग को अर्थशास्त्री 'समय' कहते हैं। यह शब्द भ्रमात्मक है, इसलिये इसका प्रयोग सत्ताम छोड़ा जा सकता है। वे कहते हैं कि धन-संचय आनन्द को स्थगित करने या उमकी प्रतीक्षा करने का परिणाम है।"^२

अतः हम व्याज को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं - व्याज पूँजी का वह पुरस्कार है जो ऋण लेने वाला पूँजी के उत्पादन-शक्ति के बदले में ऋणदाता को उसके आत्म-त्याग या समय के उपलब्ध में देता है।

व्याज की समस्या

(The Problem of Interest)

अध्ययन की दृष्टि से व्याज की समस्या को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

१. क्या नैतिक दृष्टि से व्याज दिया जाना चाहिए ?

२. व्याज क्या दिया या लिया जाता है :—

३. व्याज की दर कैसे निर्धारित होती है ?

१. क्या नैतिक दृष्टि से व्याज दिया जाना चाहिए ? (Should interest be paid on the moral and ethical grounds)

व्याज का देना नैतिक है या अनैतिक, यह अर्थशास्त्र का विवेचनीय विषय नहीं है। परन्तु प्रायः नैतिक समस्याओं की भाँति इस समस्या का भी आर्थिक दृष्टि से महत्त्व है। अतः यहाँ इसका विवेचन करना अनुपयुक्त न होगा।

प्राचीन एवं मध्य काल में व्याज की निन्दा (Condemnation of Interest in ancient and mediaeval Times)—प्राचीन एवं मध्यकाल में पाश्चात्य देशों में व्याज का लेना और देना विभिन्न कार्य सम्भाला जाता था। हजारों मूल्य, स्लेटी और अरस्तू भावि ने व्याज की कटार शब्दों में निन्दा की है। रोमन में कटो ने और ईसा पूर्व के गुरु पोप ने व्याज का लेना व देना विषेध कर दिया था। प्लेटो (Plato) मूल लोरी (Usury) को पवित्र कार्य समझते थे, और ग्रीक के

1— 'Interest, however, is primarily a reward for waiting

Dr R D Richards 'Groundwork of Economics, p 115

2— 'The sacrifice of present for the sake of future has been called 'abstinence' by economists since however, the term is liable to be misunderstood we may with advantage, avoid its use and say that the accumulation of wealth is generally the result of postponement of enjoyment or of a 'waiting' for it"

A. Marshall Principles of Economics, pp 232 3.

प्रसिद्ध दार्शनिक (philosopher) अरस्तू (aristotle) ने पूँजी को बल्का कह कर परिभाषित किया :^१ ईसाई धर्म की भाँति इस्लाम धर्म से भी व्याज लेना बुरा बताया गया है। इस प्रकार प्राचीन एवं मध्य काल में पाश्चात्य देशों में व्याज के प्रति ये भावनाएँ प्रचलित थीं। इसके मुख्यतया निम्नलिखित कारण थे :—

(१) उस समय यूरोप आर्थिक दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ था। जहाँ भी आर्थिक उन्नति हुई वह १५ वीं शताब्दी के बाद में होना प्रारम्भ हुआ। शून्य जहाँ जिनके पास पूँजी होती थी वह उन्हीं में ही काम चलाया था। यदि किसी समय किसी को धारणकता होती तो वह अपने छुट्टे मित्रों में ही बिना व्याज के ले लिया करता था। आर्थिक दृष्टि में पूँजी की कोई भाँति नहीं थी।

(२) उस समय जो ऋण लिया जाता था वह उपभोग के लिये ही लिया जाता था। उपभोगों के लिये लिया गया ऋण कठिनता में मोटाया जाता था। इसलिये इस प्रकार के ऋण-देनों से लोग बरबाद हो जाते थे। इन कारणों से व्याज तथा अनुचित समझा जाता था।

(३) उस समय सबकाल में ही कोई किसी से पूँजी माँगता था। तब समय में व्याज लेना अनुचित समझा जाता था। मानवता के लिये ऐसे समय पर दैवी ही समझाई जा सकती है। यदि व्याज लेने दिया जाय, तो ऋण-दाता अत्यधिक व्याज लेकर ही रहे। इस कारण उस समय व्याज लेना उचित नहीं समझा जाता था।

(४) यूरोप के अधिकांश श्रम-दाता यहूदी (Jews) थे जो ऋण लेने वालों में प्रायः निर्दयता का व्यवहार करते थे। इसके अतिरिक्त, यहूदी ईसाई नहीं थे इसलिए ईसाइयों द्वारा उनका यह काम पूरा की दृष्टि में देखा जाता था।

परन्तु भारतवर्ष में व्याज के सम्बन्ध में उस समय ऐसी विचार-धाराएँ प्रचलित नहीं थीं। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में व्याज लेने की निन्दा नहीं की गई है। मनुस्मृति में व्याज लेने का समर्थन मिलता है। कीटिय ने भी उन विषय पर पूर्ण विवेचन किया है। हमने व्याज लेने की निन्दा नहीं की बल्कि अत्यधिक व्याज-दर लेने में रोकने के लिये राजा द्वारा नियन्त्रण करने की सलाह दी है। यतः यह स्पष्ट है कि उस समय आधुनिक औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि में यूरोप आदि पाश्चात्य देशों का प्रवेश नहीं आधिक्य उन्नत था। इसलिये पूँजी की उत्पादकता (Productivity) का महत्व हमारे देश में अभी-जानि समझा जाता था। 'रक्का, रक्का पैदा कर सकता है', हमने प्रति उस समय भी यही आर्थिक धारणा थी।

व्याज का आधुनिक औचित्य (Modern Justification of Interest) — सही सही मसाले के दान आधिक्य उन्नति की ओर अग्रसर हुए। मशीनों का आविष्कार हुआ, उत्पादन बड़े परिमाण में होने लगा, यातायात व मर्याद के साधनों में वृद्धि हुई, उत्पादन-प्रणाली बनें सगे, बाजारों की सीमाएँ विस्तृत होने लगीं और व्यापार बढने लगा। ऐसी अवस्था में लोग पूँजी का महत्व समझने लगे जिनके फलस्वरूप पूँजी की भाँति होने लगी। उत्पादकों ने यह अनुभव किया कि पूँजी में उन्हीं उत्पादकों में बड़ी महाकाय मिलती है और ऋणदाता अपनी पूँजी देकर अपने तात्कालिक उपभोग का परित्याग करता है। ऐसी दशा में व्याज का देना उचित हो है। जब

१—"Money is barren, it cannot breed money."—Aristotle.

ऋण लेने वाला दूसरे के द्रव्य में कुछ पैदा करता है तब क्या यह उचित नहीं है कि वह उगने में कुछ भाग ऋणदाता को भी दे दे। अब उत्पादन के लिये ऋण लेना और उस पर व्याज देना न तो कष्टकर ही रहा और न अन्यायिक ही वरन् उसने ऋण लेने वाले की प्राय को बढ़ाया और उत्पादन में वृद्धि की इस प्रकार व्याज की प्रगतिविधता की युक्ति निर्वन हो चुकी है।

२. व्याज क्यों दिया या लिया जाता है ?

(Why is Interest paid or charged ?)

व्याज क्यों दिया जाता है ? उत्पादक या ऋण लेने वाला व्याज इसलिए देता है कि पूँजी के प्रयोग में उसका उत्पादन बढ जाता है। उदाहरणार्थ, जब एक दर्जी अपने हाथ से कपड सोता है तो उसकी प्राय केवल १ रु० प्रतिदिन ही होती है। और जब वह मशीन का प्रयोग करता है तो वह पहले की अपेक्षा अधिक कपडे ही सकता है जिससे उसकी प्राय २ रु० प्रतिदिन हो जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि पूँजी अपनी उत्पादकता के कारण उत्पत्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिये उत्पादक अपनी बड़ी हुई प्राय में से कुछ भाग व्याज के रूप में ऋणदाता को उसकी पूँजी का उपयोग करने के बदले में दे देता है। इस प्रकार उत्पादक या ऋण लेने वाले के द्वारा व्याज देने का कारण स्पष्ट हो जाता है।

व्याज क्यों लिया जाता है ? पूँजीपति या ऋणदाता व्याज इसलिए लेता है कि उसे पूँजी संचय करने में समय या साधन-त्याग करना पड़ता है। इसकी अधिक स्पष्ट करते हुए ये कहा जा सकता है कि वह कुछ राशि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय न करके उसे भविष्य में व्यय करने के लिये संचय करता है। ऐसा करने में उसे अपनी दृष्ट्याओं को दवाना पड़ता है तथा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रतीक्षा में ही उसका त्याग मज्झित है। अतः इस त्याग के लिये उसकी पारिजोषिक की बाह्यता स्वाभाविक ही है। प्रस्तु, पूँजीपति या ऋणदाता अपने त्याग या समय के कारण ही ऋण लेने वाले से व्याज लेता है।

३. व्याज की दर कैसे निर्धारित होती ?

(How is the rate of interest determined ?)

अर्थात्

व्याज निर्धारण का सिद्धान्त

व्याज-निर्धारण के पुराने सिद्धान्त

व्याज निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये, जैसे उत्पादकता सिद्धान्त, समय का सिद्धान्त, आस्तित्व या वट्टे का सिद्धान्त, समय-अपेक्षित सिद्धान्त आदि, परन्तु वे अपूर्ण, अवैज्ञानिक एवं एक-पक्षीय होने के कारण छोड़ दिये गये। अन्त में, व्याज का माँग और पूँजी का सापेक्षिक सिद्धान्त नव-वैज्ञानिक सर्वसाक्षियों द्वारा प्रतिपादित किया गया जो व्याज का सर्व मान्य सिद्धान्त माना जाता है।

व्याज का आधुनिक सिद्धान्त

(Modern Theory of Interest)

आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार व्याज माँग और पूर्ति की दो शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है उसी प्रकार व्याज की दर उस बिन्दु पर निश्चित होती है जहाँ पर पूँजी की माँग और पूर्ति में समतुल्य (Equilibrium) स्थापित हो जाता है, अर्थात् जहाँ पर माँग और पूर्ति दोनों हो बराबर हो जाते हैं।

पूँजी की माँग (Demand for Capital)—पूँजी उत्पादक (Productive) है, अतः इसकी माँग होती है। पूँजी की माँग प्रायः उद्योगपतियों, व्यापारियों, कृषकों तथा अन्य विनियोगकों (Investors) द्वारा होती है जो उसे उत्पादन कार्यों में लगा कर उससे द्वारा लाभ कमाने की आशा करते हैं। पूँजी की माँग सरकार द्वारा भी होती है। इसके अतिरिक्त उपयोग के लिए भी पूँजी की माँग होती है। ये सब मिलकर पूँजी की कुल माँग (Aggregate Demand for Capital) बनाते हैं। प्रत्येक उद्योगपति पूँजी तभी तत्काल उपयोग करेगा जब तक उससे द्वारा उसे लाभ होता रहेगा। जब उद्योगपति पूँजी की कई इकाइयाँ उत्पादन में लगाता है तो वह देखा गया है कि उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कुछ समय पश्चात् प्रत्येक अगली इकाई के द्वारा होने वाला उत्पादन गिरता जाता है और अन्त में एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जबकि पूँजी की अतिरिक्त इकाई लगाने से जो अतिरिक्त उत्पादन होता है वह पूँजी के बढ़ने से दिये जाने वाले व्याज से बराबर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उद्योगपति पूँजी की अधिक इकाइयों को उद्योग में लगाना बन्द कर देगा क्योंकि उसे उत्पादन कम मिलेगा और व्याज अधिक देना पड़ेगा। अतः उद्योगपति सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) अर्थात् पूँजी की अन्तिम इकाई की उत्पादकता (Productivity of Final Unit) में अधिक व्याज नही देगा। इस अन्तिम इकाई को सीमान्त इकाई (Marginal unit) भी कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पादकता केवल दिये जाने वाले व्याज के बराबर ही होती है, इसलिये इसके प्रयुक्त करने के विषय में उत्पादक उदासीन ही रहता है, अर्थात् वह इसे प्रयुक्त करे या न करे। इस प्रकार यह प्रयोग की सीमा पर होने के कारण सीमान्त इकाई कही जाती है। अतः पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्याज की अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निश्चित करती है जिससे अधिक व्याज देने पर उत्पादक कभी उत्तर नहीं होगा।

पूँजी की पूर्ति (Supply of Capital)—पूँजी की पूर्ति पूँजीपतियों द्वारा की जाती है जिन्हें पूँजी संचय करने में अपनी सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थापित करने से त्याग एवं समय करना पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में पूँजीपतियों को पूँजी इकट्ठी करने में शक्ति के लिये वर्तमान का त्याग करना पड़ता है तथा पूँजी के प्रयोग के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है।¹ अतः यह स्पष्ट है कि पूँजी

1—“The supply of capital is controlled by the fact that in order to accumulate it, men must act prospectively, they must ‘wait and ‘save’ they must sacrifice the present to the future”

के वर्तमान प्रयोग की त्यागने और भविष्य में प्रयोग के लिये प्रतीक्षा करने में पूँजीपतियों को कष्ट होता है। इस कष्ट या त्याग की पूँजी की लागत (Cost) कहा जा सकता है। अतः, यह कष्ट या त्याग व्याज की न्यूनतम सीमा (Minimum-Limit) निश्चय करता है जिससे कम व्याज लेने की वे कभी भी तैयार नहीं होंगे।

माँग और पूर्ति का समुत्तन (Equilibrium of Demand & Supply)—पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा व्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है, और पूँजी उधार देने में जो कष्ट होता है उसकी माँग व्याज की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच में व्याज की छेक दर माँग और पूर्ति की सापेक्षिक आवश्यकता तथा कुछ लेने वालों और देने वालों की लोभ या भावनाओं करने की शक्ति द्वारा उभ बिन्दु पर निर्धारित होगी जहाँ पर पूँजी की माँग और पूर्ति में समुत्तन स्थापित हो जायेगा, अर्थात् जहाँ पर माँग और पूर्ति बराबर हो जायेगी।

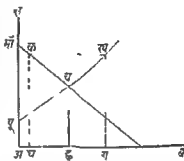
उदाहरण (Illustration)—इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये किन्ही बाजार में व्याज की विभिन्न दरों पर पूँजी की माँग और पूर्ति निम्न प्रकार है :—

व्याज की दर	पूँजी की माँग (लाख रुपये में)	पूँजी की पूर्ति (लाख रुपये में)
१%	१०	१
२%	८	४
३%	५	५
४%	४	८
६%	३	८
८%	२	६
१०%	१	१०

उदाहरण का स्पष्टीकरण—उपरोक्त उदाहरण में व्याज की विभिन्न दरों पर पूँजी की माँग और पूर्ति दिखाई गई है। बाजार में प्रचलित व्याज दर वह होगी जिस पर माँग और पूर्ति की मात्राएँ समान होंगी। प्रस्तुत उदाहरण में यह व्याज की दर ३ प्रतिशत है जहाँ पर माँग और पूर्ति की राशियाँ बराबर हैं, अर्थात् ५ लाख रुपये की हो माँग है और उतने ही रूपों की पूर्ति है। यदि व्याज दर ३% से अधिक होगी तो 'लेने' की पूर्ति घटित होगी और 'देने' वाले आपन में प्रतिक्रिया द्वारा दर को कम कर देंगे। इसके विपरीत, यदि व्याज की दर ३% से कम हो जाय तो 'देने' वाले व्याज पर रुपये लेने वाले आपन में प्रतिक्रिया करेंगे जिससे व्याज की दर बढ़ जायेगी। अतः व्याज की दर ३% ही हो जायेगी।

रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन (Diagrammatic Representation)—

प्रस्तुत रेखाचित्र में अ व रेखा पर पूँजी की मात्रा और म अ रेखा पर व्याज की दर दिखाई गई है। मा माँग को वक्र रेखा है और पू पूर्ति को वक्र रेखा है। ये रेखाएँ एक दूसरे को च बिन्दु पर काटती हैं जिसके फलस्वरूप च अ व्याज की दर हुई और माग व पूर्ति दोनों ही अ च के बराबर हुई। यदि व्याज की दर क घ हुई तो माग अ घ होगी और पूर्ति अ ग जिसकी वजह से होगी।



माग और पूर्ति के समुलन द्वारा
मूल्य निर्धारण

व्याज और सूदखोरी (Interest and Usury)—पूँजी उधार देने के लक्ष्य में उचित पुरस्कार प्राप्त करना व्याज कहलाता है, और अत्यधिक व्याज दर प्राप्त करना 'सूदखोरी' कहलाती है। व्याज साधारणतया उचित समझा जाता है, परन्तु सूदखोरी को सभी देश समझते हैं। डाक्टर ए० एस० ग्रीड के अनुसार "सूदखोरी अर्थात् व्याज से भिन्न होता है और इसका अर्थ उस व्याज की ओर है जिसकी दर उन दर से अधिक होती है जिसे विषय उचित मानता है। 'सूदखोरी (Usury) और अत्यधिक लगान वसूली (Ruel renting) में बड़ी समानता है। जिस प्रकार उचित व्याज में बहुत अधिक व्याज भग्न करने को सूदखोरी कहते हैं ठीक उसी प्रकार उचित लगान में कहीं अधिक लगान वसूल करने को 'अत्यधिक लगान वसूली' कहते हैं ये दोनों ही नैतिक दृष्टि से निवृत्त और सामाजिक दृष्टि से घृणित समझे जाते हैं।

व्याज के भेद (Kinds of Interest)—व्याज दो प्रकार के होते हैं—
(१) वास्तविक व्याज और (२) शुद्ध व्याज।

(१) वास्तविक व्याज (Net Interest)—जो व्याज केवल पूँजी के प्रयोग के लिये ही दिया जाता है उसको वास्तविक व्याज कहते हैं। वास्तविक व्याज में केवल पूँजीपति का पुरस्कार ही सम्मिलित होता है इसमें किसी अन्य कार्य का पुरस्कार जैसे जोखिम का पुरस्कार प्रभुत्व का पुरस्कार सम्मिलित नहीं होते। ब्रिटिश सरकार की प्रतिपूर्तियाँ (Consols) पर मिलने वाला व्याज वास्तविक व्याज होता है क्योंकि इसमें पूँजी को न तो कोई जोखिम हो उठानो पड़ता है और न उसका कोई प्रबन्ध ही करना पड़ता है। चैपमैन (Chapman) ने शब्दों में "शुद्ध व्याज पूँजी उधार देने का पुरस्कार है। जिसमें ख़तरा को कोई भी जाग्रिम, प्रभुत्व (मिवाय उसके जो मूल्य में होती है) यदि नहीं होती

1—"The term 'usury' is contra distinguished from interest proper, signifi s interest at a rate higher than that limited by law as legally allowable

है।^१ वास्तविक व्याज (Net Interest) का कुछ विज्ञान मुक्त व्याज (Pure Interest) या आर्थिक व्याज (Economic Interest) भी कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक या शुद्ध व्याज में वचन पूँजीपति के व्याज का ही पुरस्कार सम्मिलित होता है।

(२) कुल व्याज (Gross Interest)—यह व्याज है जिसमें वास्तविक व्याज के अतिरिक्त जागिम असुविधा, प्रत्यक्ष आदि सेवाओं के पुरस्कार भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार पूँजीपति द्वारा प्रस्तुत सभी वस्तुओं के उपनयन में जो राशि मिलती है उस कुल व्याज कहते हैं। चैपमैन (Chapman) के शब्दों में कुल व्याज में पूँजी उधार देने का पुरस्कार, क्षति प्रति के जागिमों का पुरस्कार चाहे वे (अ) व्यक्तिगत जागिम हों या (घ) व्यापारिक जोखिम, विनियोग की अनुविधाओं का पुरस्कार और विनियोगों सम्बन्धी बाध एवं चिंता का पुरस्कार सम्मिलित होते हैं।^२ कुल व्याज में जिस बात का समावेश होता है उसका विस्तृत विश्लेषण नीचे किया जाता है—

(अ) वास्तविक व्याज (Net Interest)—नेशन पूँजी के प्रयोग के निम्ने जो धन राशि दी जाता है वह कुल व्याज का एक अंग होती है।

(घ) जागिम का पुरस्कार (Remuneration for Risk)—प्रत्यक्ष पर दो मुख्य पूँजी के माध्यम से उत्पन्न लाभ में निम्ने की जोखिम सभी रहती है उनके नियन्त्रण के कारण कुछ कुछ पुरस्कार चाहता है। यह पुरस्कार वास्तविक व्याज में जोड़ दिया जाता है। प्रा० मार्शल (Marshall) के अनुसार यह जोखिम दो प्रकार की होता है—

(१) व्यापारिक जागिम (Business Risk)—यह जागिम है जो व्यापार में सम्मिलित होती है। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनमें जोखिम अधिक होता है जैसे मटरबाजी, लाल बुझाने का काम आदि, और कुछ व्यापार या व्यवसाय साधारण तथा सुरक्षित होते हैं, जैसे वस्त्रादि का व्यापार। अतः जागिमों व्यापार या व्यवसाय के निम्ने उधार दी गई पूँजी की व्याज दर कम जागिमों या रिस्क



कुल व्याज के अंग

1— Net interest is payment for the loan of capital when no risk is involved (apart from that involved in saving) and no work is entailed on the lender.

—Chapman Outline of Political Economy, p. 279

2— Gross interest includes payment for the loan of capital, payment to cover risks of loss which may be (a) personal risks, or (b) business risks, payment for the inconveniences of the investment and payment for the work and worry involved in watching investments, calling them in and investing.

—Chapman Outline of Political Economy p. 279-80

जोखिम वाले व्यापार या व्यवसाय की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसमें अनुपातिक जोखिम का पुरस्कार सम्मिलित होता है ।

(२) व्यक्तिगत जोखिम (Personal Risk)—यह जोखिम है जो श्रम लेने वाले के व्यक्तिगत चरित्र धर्मवा योग्यता के दोषों या कमियों में उत्पन्न होती है । कुछ श्रम लेने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने में वे अपना चुकाने में परमर्ष हो जाते हैं, यद्यपि उनकी इच्छा श्रम चुकाने की आवश्यक होती है । कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको श्रम चुकाने की सामर्थ्य नहीं होती है परन्तु वे ईसानी कर बैठते हैं और श्रम नहीं चुकाते । इस व्यक्तिगत जोखिम के कारण भी व्याज अधिक लिया जाता है ।

इस प्रकार पूँजी उधार देने समय पूँजीपति को व्यापारिक एवं व्यक्तिगत जोखिम उठानी पड़ती है और इसके बदले में जो पुरस्कार मिलता है वह कुल व्याज में मिला रहता है ।

(३) असुविधाओं का पुरस्कार (Remuneration for Inconvenience)—श्रमदाता को श्रम देने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । सम्भव है श्रमी अपना समय घर न लौटाये या ऐसे समय घर लौटाये जब उसे श्रमदाता किसी अन्य कार्य में न सहा सके । यह भी हो सकता है कि श्रमी एक साथ सब अपना न लौटा कर थोड़ा थोड़ा करके लौटाये जिससे श्रमदाता की सुविधा हो सकती है । कभी कभी तो श्रमदाता को श्रमी के बोझे बहुत समय तक धूमना पड़ता है तब जाकर श्रम वसूल होता है । कभी श्रमदाता को श्रम वसूल करने के लिये न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है । इन सब असुविधाओं के कारण श्रमदाता व्याज अधिक लेता है ।

(४) श्रम-व्ययस्था का पुरस्कार (Remuneration for Management)—श्रमदाता को लेन-देन का हिसाब रखने के लिये बड़ी-छोटी, मुनीम प्रमास्ते तथा अपना वसूल करने के लिये कारिन्दे रखने पड़ते हैं । इन व्ययों को भी श्रमी से अधिक व्याज के रूप में वसूल किया जाता है ।

अतः यह स्पष्ट है कि कुल व्याज में वास्तविक व्याज के अतिरिक्त श्रम-सम्बन्धी जोखिम, असुविधाओं तथा व्यवस्था के पुरस्कार भी सम्मिलित होते हैं ।

आर्थिक उन्नति का व्याज पर प्रभाव

(Effects of economic progress on Interest)

आर्थिक उन्नति का अर्थ—आर्थिक उन्नति में औद्योगिक (Technical) उन्नति का अर्थ है । यन्त्रीकरण (Mechanization), बड़े परिमाण में उत्पादन, जीवन-स्तर में वृद्धि आदि बातें देश-काल की आर्थिक उन्नति को सूचक हैं ।

आर्थिक उन्नति का व्याज-दर पर प्रभाव—व्याज की दर माँग और पूर्ति पर निर्भर होती है । इसलिये व्याज की दर इस बात पर निर्भर होगी कि पूँजी की माँग आर्थिक उन्नति के कारण बढ़ेगी या घटेगी । साथ-ही-साथ यह इस बात पर भी निर्भर होगी कि आर्थिक उन्नति के कारण पूँजी संचय की क्या गति रहेगी । प्रो० टॉजिंग (Toussing) के शब्दों में व्याज की दर संचय तथा उन्नति की दौड़ पर निर्भर होगी ।

आर्थिक उत्पत्ति का पूँजी की माँग पर प्रभाव—जब देश की आर्थिक उत्पत्ति हानि है तो पूँजी की माँग बहुत बढ़ जाती है। इसके कई कारण हैं—(१) देश में औद्योगिकरण व पत्रकार्य नये नये उद्योगों के श्रुति हैं जिनके सम्भारन के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है और परिणामतः पूँजी की माँग बढ़ जाती है। (२) देश में सामाजिक व साधना व विकास के लिये भी नई माँगें पूँजी की आवश्यकता पड़ती हैं। (३) आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापार भी बढ़ने लगता है जिसके कारण पूँजी की माँग बढ़ जाती है। (४) आधुनिक सरकार भी जन साधारण के हितों में औद्योगिक शक्ति जन विस्तार निवारण के लिये योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिये बड़ी मात्रा में पूँजी की माँग प्रस्तुत करने लग गई है। (५) कुछ प्राकृतिक तबाही आदि द्वारा बहुत सी पूँजी नष्ट हो जाती है जिससे पुनर्स्थापन के लिये नई पूँजी की माँग बढ़ जाती है। इन प्रकार देश में आर्थिक विकास के साथ साथ पूँजी की माँग बढ़ती जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजी की माँग बढ़ने से व्याज की दर में वृद्धि होना स्वाभाविक है। परन्तु यह एकपक्षीय विचार होना नहीं चाहिए जो गवना अब तक कि हम आर्थिक विकास का पूँजी की पूर्ति पर पूर्णतया विचार नहीं करते।

आर्थिक उत्पत्ति का पूँजी की पूर्ति पर प्रभाव—आर्थिक उत्पत्ति के साथ साथ सम्पत्ति का संग्रहण व विकास भी होता है जिसके कारण पूँजी गणन की प्रवृत्ति को भी सहज मिलता है। पूँजी संचय की प्रवृत्ति का प्रभाव निम्नलिखित कारणों से मिलता है—(१) जैसे जैसे सम्पत्ति का विकास होता जाता है वैसे ही वैसे मनुष्य की सुरक्षा बढती जाती है और वह कुछ न कुछ बचाने का प्रयत्न करता है। कोयला (Koyne) के सम्बन्ध में मनुष्य का तरलता अधिमान (Liquidity preference) कम हो जाता है। (२) सामाजिक उत्पत्ति के कारण उत्पादन क्षति भी बढती है जिससे जनसंख्या समाज में योग्यता की माँग बढ़ती है। साथ ही साथ पूँजी के अधिक संचय की सम्भावना हो जाती है। (३) सम्पत्ति के विकास के कारण जनसंख्या उस क्षति से नहीं बढ़ पाती जिस क्षति से उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे कम योग्यता के लिये कम उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कारण पूँजी की माँग में भी कमी हो जाती है। (४) जैसे जैसे समाज के पास धन की वृद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे मनुष्य अपने धन खर्च करता है और संचय प्रवृत्ति करता है। इन सब बातों के आधार पर यह स्पष्ट हो सकता है कि पूँजी की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा अधिक तीव्र गति प्राप्त कर लेती है।

निष्कर्ष—अभी हमने आर्थिक उत्पत्ति का प्रभाव पूँजी की माँग और उसकी पूर्ति पर धन-धन देखा। अब अब हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि समाज की आर्थिक उत्पत्ति व साथ साथ पूँजी की माँग में वही अर्थिक बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप व्याज की दर घट जाती है। इसी कारण पाश्चात्य उन्नत देशों में भारत की अपेक्षा व्याज की दर कम है।

धन्य व्याज की दर की सम्भावना

(*Probability of a low rate of Interest*)

मिल (Mill) व ग्रनुमार जैसे जगत् समस्त आर्थिक उत्पत्ति का और ग्रनुमार होता आया वैसे ही वैसे पूँजी अधिक बढ़ती होना जाना चाहिए और व्याज की दर निरन्तर गिरनी जानी चाहिए। व्यवहार में मिला कि यह विचार ठीक भी निश्चय रूप से हम देखते हैं

कि व्याज की दर बहुत गिर गई है। इस गिरती हुई व्याज की दर को देख कर प्रो० फिगर आदि कुछ अग्रजान्त्रो उस प्रवस्था की कल्पना कर बैठे हैं जबकि व्याज गिरने गिरते धूम हो सकता है। प्रो० गुम्पीटर की सम्मति में भी स्थिर (Static) समाज में व्याज की दर धूम हो सकती है।

सिद्धान्त में व्याज की दर धूम हो सकती है। यदि गव योग बचत कर तो इससे पूँजी बढ़ती परन्तु हो सकता है कि मनुष्य की आवश्यकता उस गति से न बढ़े जिस गति में पूँजी बढ़ती है। ऐसा होने पर उत्पादनमय पूँजी की मांग तब भी न करे जबकि उनकी पूँजी निरुक्त मिले अर्थात् व्याज की दर धूम हो जाय। यदि यहाँ स्थिति कुछ समय तक चलती रहूँगी ना एक दिन ऐसा हो सकता है जबकि बचत की रक्षा करने के लिए व्यक्त करने वाला को कुछ देना पड़े अर्थात् व्याज की दर नकारात्मक (Negative) हो जाय। परन्तु समाज तो मनुष्य प्रगतिशील (Dynamic) है इस बात का इतिहास साक्षी है। अस्तु ऐसी परिस्थिति जिसमें व्याज दर धूम हो जाय माने की कोई सम्भावना नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) व्याज एक पुरस्कार है जो पूँजीपति को उससे कुछ गव योग के उपलक्ष में दिया जाता है। अस्तु जब तक पूँजी के संचय में कुछ होना पूँजीपति का कुछ न कुछ पुरस्कार अप्रत्यक्ष देना हो पड़ता। ऐसी परिस्थिति की कल्पना करना जिसमें पूँजी के संचय में कुछ न हो सम्भव नहीं है। अतः व्याज की दर कभी भी धूम नहीं हो सकती।

(२) पूँजी उत्पादन है अतः व्याज की दर पूँजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है यदि व्याज दर धूम हो जाय तो इसका तात्पर्य यह होगा कि पूँजी की उत्पादकता धूम हो जायगी। ऐसी परिस्थिति की कल्पना जिसमें पूँजी के नमाने से उत्पादन बढ़े ही नहीं सम्भव है। अतः व्याज की दर कदापि धूम नहीं हो सकती।

(३) ऐसी अवस्था की कल्पना निराधार है जबकि हमारी समस्त भावश्यकताएँ पूर्णतया सन्तुष्ट हो जायँ और हम उत्पादन के लिए पूँजी की आवश्यकता बिना पड़ ही नहीं किन्तु हम जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएँ अक्षय्य हैं। जहाँ ही एक आवश्यकता सन्तुष्ट होती है वहीं ही दूसरी आवश्यकता भाती होती है। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक पूँजी के विनियोग करने के साधन भी अक्षय्य मिलते रहेंगे। इसलिये व्याज की दर धूम या नकारात्मक होना सम्भव नहीं है।

(४) व्याज की दर तभी धूम हो सकती है जबकि समाज व लोग अपनी भाग का एक बड़ा भाग बचाने परन्तु समाज में सब प्रकार के लोग हैं कोई अधिक बचाने की इच्छा रखता है तो कोई कम। इस प्रकार बहुत अधिक पूँजी इकट्ठा होने की सम्भावना नहीं है।

(५) समाज में औद्योगिक उन्नति (Technical Progress) की सम्भावना समाप्त नहीं हुई है। जब उत्पादन के नये नये ढंगों का पता लगने की माँग है तब तक पूँजी की माँग भी होती रहती और यदि वह भी मान लिया जाय कि उत्पादन बावजूद लिये पूँजी की कोई माँग न होगी तो भी सामाजिक कार्यों व लिए सा पूँजी का माँग बनी रहती।

(६) व्यक्ति व्यवस्था ने विकास के साथ तोषा को बचत जो कि धन के न होने के कारण प्रायः बेकार पड़ी रहती है तबोधपत्तियों की सुव्यवस्था में उपलब्ध हो जाती है। यही यही एक ठस जगह के आधार पर दस ग्यारह गुना अक्षय की सुविधा कर पूँजी को प्रति को असाधारण रूप से बढ़ा सकते हैं।

सारारा यह है कि जब तक समाज प्रगतिशील अवस्था में रहेगा, धन संचय करने में बाध का अनुभव होगा, ऋण देने में जोखिम तथा धनविधायी का सामना करना पड़गा और ऋण के प्रवन्ध की आवश्यकता होगी, कुछ-कुछ व्याज रहेगा ही, यद्यपि उसकी दर अवश्य नदलती रहेगी। अस्तु, व्याज दर धुन्य हा जाने की नत्थना निरावार प्रदीत होती है।

व्याज की दर में भिन्नता के कारण

(Causes of difference in the Rate of Interest)

साधारणतया वास्तविक व्याज (Net Interest) की दर सभी जगह लगभग एक ही होती है, क्योंकि पूँजी की माँग और पूर्ति की स्पर्धा (Competition) इसे एक ही स्तर पर म छाती है, परन्तु वास्तविक जीवन में देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों, व्यक्तियों और समयों पर व्याज की दर भिन्न-भिन्न कसूल की जाती है, प्रमाण कुल व्याज (Gross Interest) की दर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस कुल व्याज की भिन्नता के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं—

(१) व्यावसायिक जोखिम की भिन्नता—कुछ व्यवसाय या उद्योग अधिक जोखिमीय होते हैं और कुछ कम। अतः अधिक आखिरी व्यवसायों के मजालों में लिये कम जोखिमी व्यवसायों की प्रपेक्षा पूँजी प्राप्त करने में अधिक व्याज दर देनी पड़ती है।

(२) व्यक्तिगत जोखिम की भिन्नता—कुछ व्यक्ति अपनी सचाई और साध के लिये विश्वसनीय होते हैं। इनलिय ऐसे व्यक्तियों का कम व्याज पर रुपया उधार मिल जाता है। इसके विपरीत, जिन व्यक्तियों की सचाई व साध सखि होती है अथवा जिनका सेत देन ठीक नहीं होता है उन्हें या तो ऋण मिलना ही नहीं है या यदि मिलता है तो बहुत उँची दर पर मिलता है।

(३) आर्थिक स्थिति—कुल व्याज की दर रुपया उधार देने बाध की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होती है। जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त सम्पत्ति होती है उन्हें प्रायः कम व्याज दर पर रुपया उधार मिल जाता है, परन्तु कमजोर आर्थिक स्थिति वाले को अधिक व्याज-दर देनी पड़ती है।

(४) प्रमाण की अनुविधाओं की भिन्नता—पूँजी के उधार देने, उमके कसूल, जमा-खर्च और व्यवस्था करने में अधिक अनुविधाएँ हवा, उनमें ही व्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, कम पूँजी वाले या निचले व्यक्तियों का रुपया उधार देने में बहुत अधिक अनुविधाएँ होती हैं। उनमें रुपया बहुत धीरे-धीरे कसूल होता है। तकाज के लिये समय-मसम पर आदमी मेंना पड़ता है। उनमें थोड़ी थोड़ी राशि कसूल होने के कारण बार-बार जमा खर्च करना पड़ता है। इनके विपरीत, धनी एवं अच्छी साध वाले व्यक्ति निश्चित समय पर निश्चित राशि बिना माँग बाध कर देते हैं। अतः जिन लोगों को रुपया उधार देने में अनुविधाएँ अधिक होती हैं उनमें प्रायः अधिक व्याज की दर कसूल की जाती है। यही कारण है कि बाबू का सहायन विज्ञानी में अधिक व्याज-दर कसूल करता है।

(५) ऋण की अवधि की भिन्नता—कुछ जिनकी जमीन पदधि के लिये लिया जाता है उसमें उतनी ही अधिक जाखिम होती है। इनलिय लोपेक्षानीय ऋण पर अधिक व्याज-दर देनी पड़ती है और अल्पकालीन ऋण पर कम।

(६) समय की भिन्नता—प्रायः वर्ष के भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न व्याज की दर प्रचलित होती है। भारतवर्ष में विशेषतः वर्षों की फसलों के पैदावार होने के समय व्याज-दर ऊँची रहती है। यही समय विवाह आदि हान का भी हाना है जिससे पूँजी की माँग बढ़ जाती है और फसल व्याज-दर में वृद्धि हो जाती है। यथा धातु में व्यापार की मन्द-वृद्धि के कारण पूँजी की माँग कम हो जाता है जिससे फसल-व्याज-दर गिर जाती है।

(७) ऋण की जमानत—उचित जमानत पर दिये गये ऋण की दरों-दर बिना जमानत दिये गये ऋण का अपेक्षा कम होती है। प्रायः महाजन, सुवि, मोते-चौदी के अनुपपन्न आदि की जमानत पर ऋण कम व्याज दर पर मिल जाता है, परन्तु व्यक्तिगत जमानत (Personal Security) पर ऋण अधिक व्याज पर मिलता है। भारतीय रुपका और यंत्रों के पास जमानत के बिना कुछ नही होता है, इसलिए महाजन उतरी ऊँची व्याज दर पर रुपया उधार देते हैं।

(८) अनुपवादक कार्यों के लिये ऋण—प्रायः उपयोग, विवाह आदि अनुपवादक कार्यों के लिये जो ऋण लिया जाता है, उस पर ऊँचा व्याज दिया जाता है क्योंकि इस प्रकार के ऋण साक्ष्यों से नहीं सौंपा जा सकते हैं।

(९) वंशिक व्यवस्था का प्रभाव—जहाँ वंश का प्रभाव होता है वहाँ ऋण प्रायः महाजनों या साहूकारों से ही लिया जाता है या ऊँची व्याज दर पर रुपया उधार देने हैं। जहाँ वंश की उचित व्यवस्था होती है वहाँ ऋण कम व्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है।

(१०) प्रतियोगिता का प्रभाव—अनुपवादकों और ऋण देने वालों में पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता के प्रभाव के कारण भी व्याज की दर में भिन्नता रहती है। प्रतियोगिता के प्रभाव में महाजन किसानों में अत्यधिक व्याज वसूल करत हैं।

(११) पूँजी की गतिशीलता का प्रभाव (Lack of Mobility of Capital)—जहाँ पूँजी पूर्ण रूप से गतिशील होती है तब देश भर में प्रत्येक स्थान और व्यवसाय में व्याज की दर लगभग एक ही रहती है। परन्तु भारत में पूँजी स्थानीय नहीं है जिसके कारण देश में व्याज की दर भिन्न है।

भारत में व्याज की दर

(Rate of Interest in India)

भारत में व्याज की दर की विशेषताएँ—(Characteristics of the Rate of Interest in India)—भारत में व्याज की दर को तीन मुख्य विशेषताएँ—(१) ऊँची व्याज दर, (२) व्याज में स्थानीय भिन्नता और (३) व्याज में मौसमी भिन्नता।

(१) भारत में ऊँची व्याज दर के कारण (Causes of High Rate of Interest in India)—भारत में अन्य उन्नत देशों का अपेक्षा व्याज की दर बहुत ऊँची है। इसके निम्नलिखित मुख्य कारण हैं—

१. पूँजी की अधिक माँग (Huge Demand for Capital)—भारत में प्राकृतिक संपत्तियों का अभी अपेक्षा विनाश नहीं हुआ है। परन्तु अब इनका विकास

आरम्भ हो गया है, परन्तु पूँजी की माँग बहुत अधिक बढ़ गई है जिससे वारण-व्याज-दर भी ऊँची हो गई है।

२. पूँजी की कमी (Scarcity of Capital)—भारत में पूँजी का अभाव है। निचयना के कारण भारतवासियों में पूँजी के बचाने की शक्ति एवं दृष्टि बहुत कम है। अधिकांश दशावास्तियों की आय इतनी कम है कि वे अपना जीवन निर्वाह भी कठिनाई से कर पाते हैं। ऐसी दशा में उनमें बचत की प्रवृत्ति रखना दुर्लभाभावी है। इस प्रकार पूँजी की माँग की अभावता उनकी पूँजी की कमी होने के कारण व्याज-दर ऊँची रहती है।

३. अधिक जोखिम (Great Risk)—भारत में अधिकांश व्यक्ति निर्धन हैं। इसलिए उनका ध्यान देना बड़ा जोखिम या खतरा है। उनको धन देने में इसलिये भी जोखिम है कि उनके पास जमानत के लिये कुछ भी नहीं होगा, व व्यक्तिगत जमानत पर ही रक्कम उधार माँगे हैं। यही नहीं बल्कि उपभोग के लिये रक्कम उधार माँगे हैं जिससे कारण उन्हें धन देने में बड़ी जोखिम रहती है। इस जोखिम के कारण ही व्याज की दर ऊँची रहती है।

४. प्रबन्ध की असुविधा (Inconvenience of Management)—भारत में अधिकांश व्यक्ति निर्धन हैं। अतः उनमें रक्कम वसूल करना भी बड़ी असुविधा होती है। अतः वसूलियों के लिये बार-बार तयार करने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा रक्कम लोहान के कारण बार-बार लिखाना पड़ता है। परन्तु, इस असुविधा का पुरस्कार ऊँची व्याज की दर के रूप में वसूल किया जाता है।

५. बैंकिंग व्यवस्था का अभाव (Lack of Banking Organisation)—भारतवर्ष में बैंकिंग की समस्या बहुत कम है। अधिकांश बैंक शहरों में ही स्थित हैं, गाँवों में इनका सर्वथा अभाव है। इसका परिणाम यह है कि लोहान की सुविधा से रक्कम उधार नहीं मिल पाता। गाँवों में तो इस क्षेत्र में महाजनो का एक प्रकार में एकाधिकार है, इसलिए वे मनमाना व्याज वसूल करते हैं।

६. मूदखोरी (Usury)—भारतवर्ष में गाँवों का दश है। यहाँ की अधिकांश ग्रामीण जनता निर्धन है। इनके पास धन के लिये जमानत के रूप में दान की कुछ भी नहीं होता। इसलिए गाँवों में महाजन बहुत ऊँची व्याज-दर वसूल करते हैं। गाँवों में इनका प्रभुत्व एवं प्रभाव इतना अधिक होता है कि अन्य धन देने वाली संस्थाएँ इनकी प्रतिस्पर्धा में उतर नहीं सकती। इसलिये इनकी मूदखोरी की प्रथा अब तक भी भारतवर्ष में जीवित है।

७. उपभोग के लिए ऋण (Loans for Consumption Purposes)—उत्पादक कार्यों के लिये लोहान पूँजी का सामान्यो में जोड़ा जा सकता है। इसलिये ऐसे ऋण उचित व्याज पर मिल सकते हैं। हमारा अधिकांश ग्रामीणों का धन उपभोग, विवाह, मृत्यु भोज आदि अनुत्पादक कार्यों के लिये खर्च है जिससे कारण वे उसे लोहान में अमूल्य रहते हैं। अतः इस जोखिम के लिये ऋणदाता अधिक व्याज वसूल करता है।

(२) व्याज की दर में स्थानीय भिन्नता (Local Variations in the Rate of Interest)—स्थानानुसार व्याज की दर में भिन्नता भारत में प्रचलित

ब्याज-दर की दूसरी विशेषता है। भारत में स्थान स्थान पर ब्याज-दर भिन्न भिन्न होती है। यह अन्तर शहरी और गाँवों में विशेष रूप में पाया जाता है। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में मुद्रा के दो बाजार हैं—शहरी और देहाती। शहरी मुद्रा बाजार तो कुछ सुसंगठित है, इसलिये शहरी में ब्याज की दर कम और जगभग एक-सी होती है। परन्तु देहाती या ग्रामीण मुद्रा-बाजार समष्टित नहीं हैं। गाँवों में बैलों का सर्वथा अभाव है। हाँ कहीं-कहीं सहकारी साख सम्मितियाँ रपणों का उत्पादन कार्यों के लिये लेन देन व्यवस्था कर रही हैं। ग्रामवासियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ इनसे पूर्ण न होने के कारण उन्हें विवश होकर गाँव के महाजन के पास जाना पड़ता है। गाँव के महाजन ग्रामीणों की इस विवशता का लाभ उठाते हैं और उनसे अत्यधिक ब्याज वसूल करते हैं।

(३) ब्याज की दर में मौसमी भिन्नता (Seasonal Variations in the Rate of Interest)—भारत में कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। वहाँ रबी ऋतु की दो मुख्य फसलें होती हैं जो क्रमशः अक्टूबर मई और मई-जून नवम्बर में काटी जाती हैं। इन फसलों के समय कृषि पैदावार को गाँवों में कस्बों और शहरों की मर्चियों में ले जाया जाता है जहाँ उसका क्रय-विक्रय होता है। इस क्रय-विक्रय के कारण पूँजी की माँग बहुत बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज-दर में वृद्धि हो जाती है। इन्हीं मौसमों में प्रायः विवाह आदी भी अधिक होते हैं, इस कारण भी पूँजी की माँग बढ़ कर ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। यही नहीं, किसानों की इसी समय रबीदारों या सरकार को लगान देना पड़ता है। प्रायः न होने पर वे उधार लेकर लगान चुकाते हैं। इसलिये भी पूँजी की माँग बढ़ जाती है और ब्याज-दर में वृद्धि हो जाती है। इनके परिणामस्वरूप, वर्ष के इन्हीं महीनों में व्यापार भी अधिक होता है और इस कारण व्यापारी लोग रपण उधार लेकर दुकानों में माल अधिक रखते हैं। वर्ष के बीच महीना में पूँजी की माँग पड़ जाती है जिससे ब्याज की दर बिर जाती है। इस प्रकार भारत में ब्याज की दर में मौसमी भिन्नता पाई जाती है।

भारतीय गाँवों में बहुत ऊँची ब्याज-दर प्रचलित होने के कारण (Causes of the prevalence of very high rate of interest in Indian villages)—भारतवर्ष में गाँव में बहुत ऊँची ब्याज की दर बढ़ने की जाती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(१) ग्रामीणों की निर्बलता—भारतीय गाँवों में ब्याज की ऊँची दर का मूल कारण यह निपट बगलनी है जिसमें कि भारतीय ग्रामीणों की संपत्ति जीवन गुंथारना पड़ता है। वे इतने निर्बल होते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि दलनी का प्रायः का होता है कि वे अपना नार्थ बिना ऋण लिये नहीं चला सकते। अतः उनके लिये साहूकार के फंदे में फँसने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। इसलिये विवश होकर ऊँची ब्याज-दर पर साहूकारों से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

(२) ग्रामीणों के ऋण में अत्यधिक जोखिम का होना—ग्रामीणों को ऋण देना बड़ा जोखिमो है। प्रथम तो वे निर्बल होते हैं। द्वितीय, उनके पास जमानत के लिये कुछ नहीं होता, वे व्यक्तिगत गाँव पर ही रपण उधार लेते हैं। तृतीय, वे उपभोग के लिये ही ऋण लेते हैं जिससे कारण उसके चुकाने में कठिनाई होती है।

इन कार्यों में ग्रामीणों को श्रम देना तथा जोखिम होता है। अस्तु, साहूकारों द्वारा बहुत अधिक व्याज वसूल किया जाता है।

(३) प्रदण्ड की असुविधा—भारतीय ग्रामीण निर्धन होते हैं। उनकी प्रायः इतनी धन्य एवं अनिश्चित होती है कि वे वधनानुसार श्रम नहीं लौटा सकते। इसके अतिरिक्त, वे एक माघ पूरी ऋण-राशि नहीं लौटा सकते बल्कि सुविधानुसार थोड़ा थोड़ा रकमा लौटाते हैं जिसमें साहूकार को जमा-सर्ज करने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिये वह इस असुविधा का पुरस्कार ऊँची व्याज दर के रूप में वसूल करने का प्रयत्न करता है।

(४) गाँवों में रुपये के लेन-देन में महाजन का एकाधिकार—गाँवों में किसानों के लिये महाजन से श्रम लेने के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाजनक साधन नहीं है। अतः महाजन अधिक-से-अधिक व्याज लेने का प्रयत्न करते हैं। सहकारी-नाथ समितियाँ अभी पर्याप्त अन्तर्गत नहीं हो सकी हैं।

(५) अनुत्पादन कार्यों के श्रम—भारतीय ग्रामीण प्रायः श्रम उपभोग, बिबाह शादी आदि अनुत्पादक कार्यों के लिये लेते हैं वे रीति-रिवाजों का पालन करने में बहुत रकमा खर्च कर देते हैं। गृहस्थे बाजी के लिये भी वे श्रम लेते हैं। इस प्रकार के अनुत्पादक कार्यों के लिये श्रम देने में श्रमदाता को काफी जोखिम उठाना पड़ता है। अतः व्याज की दर ऊँची उठ जाती है।

(६) पूँजी की माँग में वृद्धि—भारतीय ग्रामीण अपने विविध कार्यों के लिये रकमा खर्च माँगते रहते हैं। इसलिये पूँजी की माँग ग्राम्य क्षेत्रों में सर्वत्र बनी रहती है। जिसके कारण व्याज दर भी ऊँची रहती है।

(७) पूँजी की पूर्ति में कमी—गाँव के साहूकारों की पूँजी भी ग्रामीणों की व्यापक माँगों को पूरा करने के लिये कम पड़ती है। वे प्रायः अपनी स्वयं की पूँजी को ही उधार देते हैं, दूसरों का रकमा जमा नहीं रखते। उनका मुद्रा बाजार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अतः श्रम लेने वालों की पारस्परिक प्रतिযোগिता से व्याज दर में वृद्धि हो जाती है।

(८) जमानत का अभाव—ग्रामीणों की अच्छी साख भी नहीं होती है। न तो वे श्रम के लिये कोई जमानत ही दे सकते हैं और न ही ग्रहण परिस्थितियों के कारण वे श्रम को समय पर चुकाने में समर्थ होते हैं वे भुगतान को ढालने रहते हैं। इस मनीवृत्ति में साहूकार अपनी पूँजी को खराब-ग्रस्त देखते हैं और इसलिये उनसे ऊँची व्याज-दर वसूल करते हैं।

(९) ग्रामीणों की अधिज्ञानता, अज्ञानता व रुढ़िवादिता—भारतीय ग्रामीण अधिज्ञान, पुरानी चाल के और अज्ञानी होते हैं, इसलिये वे गाँव के महाजनों के सहज शिकार हो जाते हैं। महाजन लोग हम अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हैं। श्रावण-काल के समय उनमें जितना सम्भव होता है उतना ही पैसा खींचने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, महसूस की कमी के कारण वे महाजनों की विभिन्न अनुचित कार्यवाहियों का विरोध करने में असमर्थ होते हैं।

(१०) अल्प आय, फसल की असुरक्षिता और ग्रामीणों का ह्रास—भूमि पर जन-सम्पत्ति के अत्यधिक दबाव के कारण ग्रामीणों की आय बहुत कम हो गई है। भारतीय-कृषि-व्यवसाय वर्षा का चूँचा बना हुआ है और समय समय

पर टिड्डी आदि कीड़ों में फलन नष्ट होने का भय रहता है। अणु, फलन की असुरक्षिता सदा बनी रहती है। आमोयोगों के नष्ट होने से कृषि के सिवाय ग्रामीणों के लिए प्रायः का अन्य कोई साधन नहीं रहता है। इसलिये वे निरन्तर श्रृंग सेन रहते हैं जिनमें पूँजी की माँग व्यापक रूप से रहती है। यही पूँजी की माँग व्याज की दर को ऊँचा उठाये रखती है।

(११) दुग्ध और रोगों के कारण हानि—समय-समय पर दुग्ध पटने रहते हैं जिससे जान व मान का क्षति होती रहती है। दुग्ध के समय चारा नहीं मिलन में पशुओं की भी काफी क्षति होती है। इसके अतिरिक्त, रोगों में भी पशुओं की पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है। इस क्षति को पूरा करने के लिये ग्रामीणों को निरन्तर नए सेना पटना है जिससे व्याज-दर ऊँची रहती है।

(१२) मालगुजारी या लगान का भार—लगान या मालगुजारी भारी होती है और भारतीय कृषक उसका बिना ऋण लिये देने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। इसलिए उसे समय पर जमा कराने के लिये ऊँची व्याज दर पर गाँव के साहूकार से ऋण लेना पड़ता है।

(१३) बैंक व्यवस्था का अभाव—भारतवर्ष में बहुत कम बैंक पाये जाते हैं। गाँवों में तो इनका सर्वथा अभाव ही है। इसलिये ग्रामीणों को विवश होकर महाजनों के ऋण में पँसा रहना पड़ता है।

व्याज-दर नीचे करने के उपाय

(Remedies for lowering the rate of Interest)

(१) सबसे पहला काम जो किया जाना चाहिये यह यह है कि ग्रामीणों को शिक्षित किया जाय जिससे कि फिट्ठनसर्तों, मुकदमबाजों और धालस्य से बचे।

(२) मालगुजारी बमूल करने की रीतियों में सुधार होने चाहिये।

(३) आमोयोगों का प्रसार होना चाहिये जिससे उनकी प्राप में वृद्धि हो सके।

(४) केती के ढाँचों में सुधार किये जायँ और सिचाई, बीज और खाद के लिये अधिकतम सुविधाएँ दी जायँ।

(५) कम व्याज पर अल्पकालीन ऋण के लिये सहकारी-भाय समितियों का और दीर्घकालीन ऋण के लिये सहकारी भूमि बन्धक बैंकों का प्रसार होना चाहिये।

(६) गाँव के साहूकारों को अपना जमा करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे पूँजी का अभाव न रहे।

(७) कानून द्वारा व्याज की दर नीचे गिराना चाहिये तथा साहूकारों का नियन्त्रण होना चाहिये।

(८) गाँव के महाजनों की सहकारी-समितियों के नियन्त्रण में लाना चाहिये। ये समितियाँ रैतीमन आदर्शों पर चलाई जानी चाहिये। इससे पूँजी की पूर्ति में वृद्धि होगी और व्याज दर फिर ज़ायमी।

(९) धन बचाकर भूमि में गाड़ कर रखने की प्रथा को तथा घटने प्रादि बनाने की प्रथा को कम करना चाहिये जिससे बचा हुआ धन पूँजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

(१०) ग्रामीणों में सामाजिक तथा धार्मिक रुढ़ियों के कारण जो अपव्यय की प्राप्ति पड़ गई है, उन कम करना चाहिये।

किस प्रकार सहकारी-साम्प्रदाय समितियाँ गाँव के महाजनो की अपेक्षा कम व्यय पर कृषको को रुपया उधार दे सकती है? ग्रामीण सहकारी-साम्प्रदाय समितियाँ कृषको को कम व्याज-दर पर रुपया उधार दे सकती है, क्योंकि (१) उनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनता की सहायता करना है। इससे विपरीत, गाँव के महाजन या मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना और कृषको का शोषण करना है। (२) सहकारी साम्प्रदाय समितियों को धन प्रांतीय या केन्द्रीय सहकारी बैंक से तथा जमा-राशि (Deposit Money) से कम व्यय पर प्राप्त होता है। (३) सरकार इन कम व्यय पर रुपया उधार देती है, इसलिये ये ग्रामीणों को कम व्यय पर ही रुपया-उधार देने में सफल हो सकते हैं। (४) सहकारी समितियों में काम करने वाले व्यक्ति दुरुवा बिना वेतन काम करते हैं जिससे इनका मजानन कम व्यय पर सम्भव है, परन्तु गाँव का महाजन अपना जीवन व्यय पर ही चलाता है तथा धन कमाता है। (५) सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों पर प्रभाव रखती हैं और उनसे धन के भाव उत्पन्न करती हैं। (६) ये कृषकों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने में सहायता करती हैं ताकि वे अपने लालच को चुकाने में समर्थ हो सकें।

व्याज-दर और पूँजी संचय में सम्बन्ध (Relation between Rate of Interest & Accumulation of Capital)—व्याज दर एक प्रकार से पूँजी का मूल्य होता है। संचित पूँजी ही पूँजी की पूर्ति होती है। अतएव व्याज दर तथा संचित-पूँजी का सम्बन्ध वही है जो किसी वस्तु के मूल्य और उसकी पूर्ति का होता है। प्रायः सबों में, इस दोनों का सम्बन्ध पूर्ति के नियम पर आधारित रहेगा जिसके अनुसार यदि किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। प्रत्यय इस में भी कह सकते हैं कि पूर्ति बढ़ने पर मूल्य कम हो जाता है और पूर्ति घटने पर मूल्य बढ़ जाता है।

ठीक इसी नियम के अनुसार यदि व्याज दर अधिक हो जाय तो पूँजी की पूर्ति बंद जायगी, क्योंकि अधिक व्याज-दर से लाभ बहेगा जिससे पूँजी संचय प्रवृत्ति को प्रावणहीन मिलेगा। इससे विपरीत, यदि व्याज दर कम हो जाय तो लाभ धन मचाना भी कम कर देवे जिससे पूँजी की पूर्ति में कमी हो जायेगी।

यदि पूर्ति व रुद्धिपूर्ण से देखा जाय तो यदि पूँजी की पूर्ति कम हो जाय और उसकी माँग जनता ही कमी रह तो पूँजी चाहने वाला सामग्री में स्पर्धा करके व्याज दर को बढ़ा देवे तथा इससे विपरीत, यदि पूँजी का पूर्ति बढ़ जाय और माँग जनता ही कमी रह तो पूँजी निविद्योगकता में पूँजी प्रदान व निच स्पर्धा हो जायगी और इस स्पर्धा में व्याज-दर कम हो जायगा। अतः व्याज दर और पूँजी संचय का पारस्परिक सम्बन्ध सारांश रूप में निम्न प्रकार है —

व्याज-दर के दृष्टिकोण से

१—व्याज दर बढ़ने में पूँजी की पूर्ति बढ़ती है।

२—व्याज दर बढ़ने में पूँजी की पूर्ति घटती है।

पूँजी की पूर्ति के दृष्टिकोण से

३—पूँजी को पूर्ति कम होने से ब्याज दर अधिक हो जाती है ।

४—पूँजी की पूर्ति अधिक होने से ब्याज-दर कम हो जाती है ।

भारत सरकार को एक कृषक, एक व्यापारी या एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी आदि की अपेक्षा कम ब्याज-दर पर ऋण प्राप्त होने के कारण—
(१) भारत सरकार की साम एक कृषक, एक व्यापारी या एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी से कहीं अधिक सुरक्षित है । इसलिये इनकी अपेक्षा उसे कम ब्याज-दर पर ऋण उपार मिल जाता है । ऋण देने वाले की सास का ब्याज दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । जितनी अधिक उत्तम सास होगी उतनी ही कम ब्याज-दर होगी । एक व्यक्तिगत ऋणी दिवालिया निकास्य मयता है तब कम्पनी समाप्त हो सकती है परन्तु देश की सरकार ह्मेशा होगी है और लोगों को उसको सास और स्वायत्तत्व में पूर्ण विश्वास होता है । सरकार जो ह्मेशा गारंटी करती है उसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ नहीं रहता है बल्कि सम्पूर्ण देश का हाथ रहता है । इसलिये नौग सरकारी सुरक्षा को सबसे अच्छा मानते हैं ।

(२) भारत सरकार के ऋण की ब्याज-दर बैंक दर (Bank Rate) की भाँति वास्तविक ब्याज का प्रतीक है । इनमें जोड़िय, प्रमुखिधा प्रबन्ध आदि के पुरस्कार सम्मिलित नहीं होते जैसे कि एक कृषक, एक व्यापारी या एक कम्पनी के ऋण की ब्याज दर में होते हैं । एक कृषक को ऋण देने में इन सब से अधिक जोड़िय होती है, इसलिये इसे सबसे अधिक ब्याज दर देनी पड़ती है ।

(३) इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है । लोग सरकार को उधार देने में अधिक गौरव समझते हैं । साधारण लोगों को उधार देना इतना महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जाता । यही कारण है कि सरकार को कम-से-कम ब्याज की दर पर भी अधिक-से-अधिक रुपया उधार मिल जाता है ।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन ब्याज-दर (Short-period and Long-period Rate of Interest) साधारणतया ऋण की प्रवृत्ति जितनी ही अधिक होगी, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी । इसका कारण स्पष्ट है । दीर्घकालीन ऋण में ऋण-राशि एक लम्बे समय तक फँसी रहती है, इसलिये इसमें अल्पकालीन ऋण की अपेक्षा जोड़िय रहती है । परन्तु, दीर्घकालीन ऋण को ब्याज-दर अल्पकालीन ऋण की अपेक्षा अधिक होता है । यही कारण है कि वापस राशि (Call Money) की जिसे बैंक किसी भी दिन वापस माँग सकता है, सामान्यतया ब्याज-दर बहुत कम यहाँ तक कि कई बार १% से भी कम हो जाती है । यदि ऋणदाताओं को भावी परिस्थितियों के प्रति पूर्ण विश्वास हो, तो दीर्घकालीन ऋण की ब्याज-दर भले ही कम हो सकती है ।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन ब्याज-दरों में गारंटीरहित भिन्नता होते हुये भी इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है । साधारणतया अल्पकालीन ब्याज-दर जब ऊँची होती है, तब दीर्घकालीन ब्याज-दर भी उसका अनुसरण करती है । वास्तव में, अल्पकालीन ब्याज-दर ही दीर्घकालीन ब्याज-दर की गतिविधि निर्धारित करती है । इसलिये यदि हम दीर्घकालीन ब्याज-दर घटाना चाहें तो हमें पहले अल्पकालीन ब्याज दर को कम करने का प्रयत्न करना होगा ।

लगान, आभास लगान और व्याज में सम्बन्ध (Relation between Rent, Quasi-Rent and Interest)—लगान भूमि पर मिलने वाला पुरस्कार है और व्याज पूँजी पर मिलने वाला पुरस्कार है। मशीना में लगी हुई पूँजी पर मिलने वाला लाभ को आभास या छद्म लगान (Quasi-Rent) कहते हैं। भूमि की भाँति मशीना को हम मुरत्त घटा-बढ़ा नहीं सकते। इस दृष्टि से यह लगान हुआ। परन्तु कालान्तर में हम इसे पूँजी की भाँति के अनुसार घटा-बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टि में यह व्याज हुआ। इसलिये प्रो० मार्शल ने इसे आभास या छद्म लगान कह कर पुकारा है। प्रो० मार्शल के अनुसार लगान, आभास लगान और व्याज एक ही जाति के विभिन्न भेद हैं।

लगान और व्याज में समानता (Similarity between Rent & Interest)—लगान और व्याज में निम्नलिखित बातों में समानता पाई जाती है —

(१) पूँजी मनुष्य कृत होती है। भूमि के ऊपर भी मनुष्य की उपज प्राप्त करने के पूर्व बहुत-सा कार्य करना पड़ता है।

(२) भूमि की पूर्ण निश्चित होती है, जब उसमें न्यूनतापिण्डता सम्भव नहीं है। अनन्तकाल में पूँजी की पूर्ति भी बहुत कुछ निश्चित होती है।

(३) भूमि में लगान पूँजी पर भी समानगति उत्पत्ति द्वारा नियम लागू होता है।

(४) लगान की दर (प्रसविका समान दर) जिस प्रकार भूमि की माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार व्याज की दर भी पूँजी की माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।

(५) भूमि के अन्दर अपनी स्वयं की नष्ट होने वाली अस्तित्व नहीं है। इसकी सर्वथा प्रति की इसी प्रकार बढ़ाना पड़ता है जिस प्रकार कि पूँजी आदि की पूर्ति का बढ़ाना पड़ता है।

इन्हीं सब बातों के कारण भूमि से प्राप्त हानि वास्तविक तथा पूँजी से प्राप्त हानि वाले व्याज से बड़ी अन्तर नहीं करना चाहिये। किसी भू भाग की मूल्य लगान द्वारा उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार कि किसी पूँजीगत वस्तु का मूल्य उमन प्राप्त होने वाली प्राप्ति से निर्दिष्ट किया जाता है।

लगान और पूँजी उपवृत्त दोनों में समानता रखने हुए भी यह बातों में यह एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं।

लगान और व्याज में भिन्नता

(Difference between Rent & Interest)

लगान (Rent)	व्याज (Interest)
१ यह भूमि पर मिलता है।	१ यह पूँजी पर मिलता है।
२. भूमि प्रकृति की देन है	२. पूँजी मनुष्य के परिश्रम का फल है और इस आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकते हैं।
तथा इस आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा नहीं सकते।	

1—'Rent, Quasi-Rent and Interest are species of the same genus
—A Marshall.

३. यह सामाजिक उत्पत्ति और जनसंख्या की वृद्धि के साथ घटता है।

४. भूमि की उर्वराशक्ति और स्थिति के अनुसार जमान में बड़ी गिनता पाई जाती है।

५. जमान निर्धारण में जमान हीन भूमि होती है।

६. उत्पत्ति के मूल्य का जमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह जमान हीन भूमि द्वारा निर्धारित होता है जिसमें कोई जमान सम्मिलित नहीं होता है।

७. जमान बढ़ाने में भूमि नहीं बढ़ सकती।

३. यह सामाजिक उत्पत्ति और जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार घटता है।

४. व्याज की सर्वोत्तम एकादश होने की प्रवृत्ति होती है। जमान कुल व्याज में ही भिन्नता पाई जाती है।

५. व्याज निर्धारण में कोई व्याज हीन पूँजी नहीं होती है।

६. उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर व्याज का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्याज हीन पूँजी कोई नहीं होती है। पूँजी की क्षीयमान उत्पादकता में व्याज सम्मिलित होता है।

७. व्याज की वृद्धि से पूँजी बढ़ती है।

समाजवादी राज्य में व्याज (Interest in a Socialist State) — एक समाजवादी राज्य में जहाँ उत्पत्ति के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, व्याज नहीं होगा। जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेगी व्याज पर कबया उधार लेना और देना चलता रहेगा। अतः केवल पूँजीवाद के उन्मूलन से ही व्याज दर का लोप नहीं हो सकता। व्याज की समाप्ति के लिये अतिरिक्त या निजी सम्पत्ति का अन्त होना आवश्यक है।

कृषि समाजवादियों ने व्याज की घोर निन्दा की है परन्तु समाजवादी राज्य में भी व्याज होता है। जब समाजवादी राज्य के व्यापार एवं उद्योगों की भाग उसकी समस्त योजनाओं का कार्य प्रबन्ध करने के लिये पर्याप्त रहने लगेगी है तो उसे मुद्रा बाजार से ऋण लेना पड़ता है जिसके लिये व्याज देना पड़ता है। पूँजी की पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध होने से लिये व्याज का प्रलोभन दृष्टिष्ट है। इसके अतिरिक्त पूँजी कहीं लम्बाई जाय यह पूँजी की भाग पर जो व्याज के रूप में होते हैं विभक्त होती है। जिस अतिरिक्त में भाग अधिक होती है उममें ही पूँजी अधिक लगाई जायगी। अतः समाजवादी राज्य में भी व्याज का अस्तित्व पाया जाता है।

अभ्यासाय प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—कुल मूद्र और वार्षिक मूद्र में क्या अन्तर है? भारतीय वृषभ द्वारा दी जाने वाली मूद्र की दर क्या इतनी ऊँची है?

२—व्याज की परिभाषा लिखिये। यह कैसे निर्धारित होता है? विभिन्न ऋण लेने वाला के लिये व्याज दर भिन्न होती है?

३—व्याज कैसे निर्धारित होती है ? ग्रामों में व्याज की दर अधिक होने के क्या कारण हैं ?

४—पूँजी की गतिशीलता का क्या अर्थ है ? भारत में पूँजी की गतिशीलता में क्या बाधाएँ आती हैं ? इन्हें दूर करने के उपाय भी बताइयें ।

५—व्याज किसे कहते हैं ? यह समझाइये कि व्याज की दर कैसे निर्धारित होती है ?
(रा० वो० १६५७)

६—कुल और विमुद्र व्याज पर नोट लिखिये ।

(मासिक १६५१, ५० ; ग्र० वो० १६४३)

७—“एक व्यापारी ६ प्रतिशत पर अपना उधार लेता है, जबकि एक किसान को १२ प्रतिशत व्याज दर देनी होती है, किन्तु ग्रामिक को २० प्रतिशत पर भी अपना उधार नहीं मिलता ।” व्याज-दर में इसकी भिन्नता के क्या कारण हैं ?

(म० भा० १६५३)

८—भारतीय गाँवों में महाजन ऊँची व्याज-दर क्यों लेते हैं ? व्याज-दर कैसे घटाई जा सकती है ?
(सागर १६५२)

९—राष्ट्रीय पूँजी और व्याज-दर का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये । (नागपुर १६५१)

१०—कुल और विमुद्र व्याज का अन्तर समझाइयें । यदि व्याज दर घुस्य हो जावे तो क्या वचानों की प्रवृत्ति पूर्णतः समाप्त हो जावेगी ?
(पटना १६५६)

११—कुल और विमुद्र व्याज का अन्तर बताइयें । क्या व्याज की अदायगी उचित है ?
(दिल्ली हा० मे० १६५०)

इष्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ

१२—ग्रामीण क्षेत्रों में व्याज दर कैसे निर्धारित होती है ? जब व्याज-दर बहुत ऊँची होती है, तो उसके क्या कारण होते हैं ?

१३—टिप्पणी लिखिये—

कुल और विमुद्र व्याज

लाभ का अर्थ (Meaning of Profit)—आधुनिक उत्पादन-क्रिया उत्पत्ति के विविध मापनों द्वारा मापूँहिए रूप में सम्पन्न की जाती है और प्रत्येक मापन अपने विशिष्ट कार्य के लिये पुरस्कार पाता है। आधुनिक विशाल उत्पादन-व्यवस्था में हानि-लाभ की जोखिम (Risk) उठाना एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। जो उत्पत्ति का साधन इन महान् कार्य को सम्पन्न करने का साहस करना है वह साहसी (Enterpriser or Entrepreneur) कहलाता है और जो पुरस्कार उसे इस जोखिम के उठाने के बदले में मिलता है उसे लाभ (Profit) कहते हैं। अस्तु, लाभ साहस का पुरस्कार है। साहसी का उत्पादन-कार्य करने में जो बचत होती है, उस लाभ कहते हैं। जिस प्रकार मूल के लिये भू-स्वामी लगान, श्रम के लिये श्रमिक मजदूरी, पूँजी के लिये पूँजीपति ब्याज और सगठन बर्ता वेतन पाते हैं, उसी प्रकार साहस के लिये साहसी को लाभ प्राप्त होता है।

साधारण बोनसाल की भाषा में शिमी व्यवसाय की धारा में जो उनके सारे व्ययों को निकालने के पश्चात् जो कुछ मालिक के लिये बचता है, वह लाभ कहलाता है। इस प्रकार साधारण बोनसाल में लाभ एक अभावक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु अर्थशास्त्रीय अर्थ में राष्ट्रीय आय में से साहसी को प्राप्त होने वाला लाभ कहलाता है। अतः साधारण बोनसाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले लाभ को कुल लाभ और अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले लाभ को वास्तविक या शुद्ध लाभ कहते हैं।

लाभ की परिभाषा (Definition of Profit)—लाभ साहसी के उस पुरस्कार को कहते हैं जो उसे उत्पादन-क्रिया में जोखिम उठाने के बदले में प्राप्त होता है। इसे यों भी परिभाषित कर सकते हैं : राष्ट्रीय आय या लाभान का वह भाग जो साहसियों को दिया जाता है, लाभ कहलाता है।¹ प्रो० टॉमस (Thomas) के अनुसार लाभ साहसी का पुरस्कार है।²

लाभ एक अवशिष्ट भाग है (Profit is a Residuum)—साहसी उत्पादन कार्य का संचालन करता है। वह कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही उत्पादन की

1—Profit may be defined as "the share of the national dividend accruing to the entrepreneur is known as profit"

2—"Profit is the reward of the entrepreneur"

S. E. Thomas 'Elements of Economics', p. 289.

माना जायत, भविष्य की किसी प्राप्ति मानी जाता वा अनुमान करने उत्पत्ति के चार साधना (भूमि, श्रम, पूँजी और सगठन) में प्रसविदे (Contracts) करता है और फिर इन प्रसविदे में अनुसार उन साधना की उनका भाग उत्पादन में देता है। गैर इसी वचना है वह उनका लाभ होता है। इसी कारण लाभ को एक अवशिष्ट भाग कहते हैं।

अब यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में प्रथम—चार साधन (Claimants) अर्थात् भूमि, श्रम, पूँजी और सगठन—प्रसविदे (इकरार) द्वारा निश्चित रूप से ही हुई आय के अविवरित भाग हैं, परन्तु साहसिक स्वयं एक प्रसविदे रहित (गैर इकरारी) आय का भागी होता है। इन प्रकार यदि प्रथम चार उत्पत्ति के साधना का उनका प्रसविदे के अनुसार निश्चित राशि बुकाने के पश्चात् कुछ भेग नहीं बचता है, तो साहसिक का हानि उठाना पड़ती है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि साहसिक को प्रथम उत्पत्ति के भागों की भाँति कोई निश्चित आय नहीं होती है।

लाभ एक प्रतिरिक्त आय है (Profit is a Surplus Income)—एक साहसिक या उद्योगपति की प्रतिरिक्त आय को लाभ कहते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिये एक उद्योगपति ने दोस हजार रुपये लगाकर पाँच व्यवसाय किया और एक वर्ष के पश्चात् उसका पाम बीस हजार रुपये अर्थात् चार हजार रुपये बच गये। यह चार हजार रुपये की प्रतिरिक्त आय उसका लाभ कहना सही है।

लाभ साहसिक का पुरस्कार (Profit is the reward for enterprise)—आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में जालिम ब्रह्मण का काम उत्पत्ति का एक आवश्यक अङ्ग माना जाता है। प्रत्येक कारखाने में किसी वस्तु की उत्पत्ति उस वस्तु की अनुमानित माँग के आधार पर की जाती है। यह अनुमान सदा यथार्थ मिष्ट हो ऐसा निश्चित नहीं रहता। अब यह स्पष्ट है कि यदि उत्पादित वस्तु का अनुमानित माँग असत निश्चय जान के कारण उसकी पूर्ण रूप में खपत न हो सके तो साहसिक का हानि उठानी पड़ती। इसके विपरीत यदि उत्पादित वस्तु माँग से अधिक हो के बचे हुए पड़े तो लाभ, तो साहसिक का निश्चित रूप में लाभ होगा। यह लाभ आश्रित उद्योग का पुरस्कार है और साहसिक जालिम उद्योग के लाभ इसका पूर्ण अपिवर्तनी भी है। वह व्यवसाय के प्रारम्भ में ही उत्पत्ति के प्रथम साधना के पुरस्कार तथा अन्यत्र व्यय का शेषिक खपत के कारण होता है तथा इस माध्यम में उत्पादित वस्तु के बिकने के पूर्व ही खपत घन लक्ष्य कर देता है। यही परिचरित्व में यदि उद्योग में मिन तो एक भाषण द्वारा ही और एक महान् प्रत्यायन हो सकता है। परन्तु इसका कुछ उपचार नहीं हो सकता। जालिम उद्योग निम्न हानि-लाभ दोनों ही सम्भावनाओं का समन्वय है, साहसिक का एक निश्चित कार्य है। यही उद्योग पुरस्कार का मूल आधार है।

लाभ की उत्पत्ति के कारण (Causes of existence of Profit)—वर्तमान युग में औद्योगिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि साहसिक या उद्योगपति को किसी वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व ही उस वस्तु का माँग या खपत का अनुमान लगाना पड़ता है। इसमें बड़ा जोखिम है। साहसिक यह अनुमान लगाता है कि समस्त वस्तु का उत्पादन में निरन्तर व्यय होगा और उसकी कितनी आय होगी तथा उसे में कितनी खपत होगी मनेगी। इस प्रकार बचत अनुमान के आधार पर ही उत्पत्ति की जाती है। परन्तु भविष्य की कति सदा अनिश्चित रहती है। सम्भव है कि

व्यवसाय के असफल हो जाने, फँडल में परिवर्तन हो जाने या माल का मूल्य अनुमान निकल जाने अथवा यथामाध्य पूँजी न मिलने या पूँजी का दुरुपयोग हो जाने व वह आर्थिक एवं औद्योगिक मकड़ में पड़ जाने। यह भी सम्भव हो सकता है कि देश में राजनैतिक स्थल-मुथल मच जाय, धार्मिक हठनाल करदे अथवा भूकम्प, बाढ़, दुर्भिक्ष व अग्निबाढ़ आदि दैवी प्रकोप के कारण उत्पत्ति का क्रम ही मंद हो जाय। ऐसी परिस्थितियों में साहसी वा अग्रगण्यता का मामला करना पड़ेगा। उत्पादन के अन्य साधनों को पुरस्कार सामान्यतया उत्पादन से पहले ही मिल जाता है। साहसी को तो इनाम के तौर पर वह मिलेगा जो कुछ उत्पादन के साधनों को देने के पश्चात् बच रहेगा। उसके लिए किलना तबेबा, यह उसकी योग्यता पर निर्भर है। इन सब बातों को विधान के लिये बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति चाहिये और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति नभो मिल सकता है जबकि उसे इन सब जोखिमों का भेदने के लिये पर्याप्त पुरस्कार द्वारा प्रेरणा मिल सके। अस्तु, प्रापुनिक औद्योगिक पद्धति में लाभ के अस्तित्व की अनिवार्यता सिद्ध होती है। अल्पकाल में भले हो उसे हानि की सम्भावना बिलार्दी पड़े, परन्तु दीर्घकाल में उसे निरवश रूप में लाभ मिलना चाहिये। यदि ऐसा न हो तो साहस की पूर्ति (supply) नहीं हो सकती।

(२) साजकर्म की औद्योगिक एवं धार्मिक पद्धति से व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, प्रवृत्त कुशलता उत्तरदायित्व और औद्योगिक मन के नियन्त्रण और निरीक्षण आदि कार्यों में साहसी की ओर से उत्पादन में पड़ा मध्यम मिनता है जिसके लिये उसे आवश्यक पुरस्कार मिलना चाहिये।

लाभ के भेद (Kinds of Profit)—लाभ दो प्रकार का होता है—(१) वास्तविक लाभ, और (२) कुल लाभ।

(१) वास्तविक लाभ (Real or Net Profit)—साहसी की उत्पादन-क्रिया में जोखिम उठाने के उपलक्ष में जो पुरस्कार मिलता है, उसे वास्तविक लाभ कहते हैं। इसमें अन्य किसी प्रकार के पुरस्कार सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिये इसे शुद्ध लाभ (Net Profit) भी कहते हैं। अर्थशास्त्रीय मर्थ में इसे आर्थिक लाभ (Economic Profit) भी कहते हैं। वास्तविक या शुद्ध लाभ दो प्रधान कार्यों का पुरस्कार होता है—

(अ) जोखिम उठाने का पुरस्कार (Reward for Risk-taking)—प्रापुनिक औद्योगिक व्यवस्था में जोखिम उठाना उत्पत्ति का एक आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में उत्पत्ति उपयोग के अनुमान के आधार पर की जाती है। इसलिये यदि साहसी का अनुमान सही नहीं निकलता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है, और यदि सही निकलता है तो उसे लाभ होता है। उत्पत्ति के अन्य साधनों का पुरस्कार प्रायः निश्चित होता है और वह उत्पादन में पहले ही मिल जाता है। परन्तु साहसी को तो भन्त में जो कुछ उत्पत्ति ने साधना को बाँटने के पश्चात् बच रहता है, मिलता है। उधने लिये नितना बचेगा, यह अनिश्चित होता है। अस्तु, जो पुरस्कार साहसी को जोखिम उठाने के बदले में मिलता है वह उसका वास्तविक या शुद्ध लाभ कहलाता है। इस सम्बन्ध में हैनरी क्ले (Henry Clay) के शब्द उल्लेखनीय हैं। यह बात कि व्यापार के स्वामी ही मुख्य जोखिम को भेनते हैं हमें तब

स्पष्ट होती है जबकि हम यह स्मरण रख कि वे वस्तु के तैयार होने के पूर्व ही बहुधा वस्तु के मूल्य का पता लगने के पहले ही, श्रम, पूँजी और भूमि को पुरस्कार दे देते हैं, और यदि निमित्त वस्तु की मांग न रहे और वह विक्रय न पावे तो उसने उत्पादन में मजदूरी, व्याज और लगान के रूप में व्यय की गई राशि वे पुनः प्राप्त नहीं कर सकने।¹

(आ) सौदा या भाव-नाव करने की क्षमता का पुरस्कार (Reward of bargaining skill)—साहसी उत्पत्ति के विविध साधनों की जुटाकर उत्पादन प्रारम्भ करता है। वह प्रत्येक में प्रयत्निता करते समय श्रम, पूँजी और भूमि का प्रयत्न करता है कि उसे कम से कम पुरस्कार देना पड़े। वह उसकी सौदा या भाव-नाव करने की योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर है कि वह कितने धन में भूमि तथा कितनी मजदूरी पर धनिका को रक्त कितने कम व्याज पर पूँजी इकट्ठी करे और कितने कम वेतन पर बुद्धिमान मजदूरों या प्रवक्ता को रखे। भाव-नाव करने की क्षमता अधिनियम योग्यता साहसी में होगी उतना अधिनियम उसे लाभ होगा। कारवर (Carver) के शब्दों में एक व्यापारी आवश्यक रूप में विविध धर्म में साहसी कहलाता है। साहसी वह है जो जोखिम का दायित्व स्वीकार करता है। इस जोखिम उठाने के विविध कार्य का पुरस्कार उत्तम सौदा या भाव-नाव करने की क्षमता के परिणामा सहित उस व्यापारी की एक विविध आय का निमाण करता है जो सिवाय जोखिम उठाने वाले के किसी दूसरे का कदापि प्राप्त नहीं होती है।²

सारांश यह है कि जोखिम उठाने और भाव-नाव करने की क्षमता के उपलक्ष्य में जो पुरस्कार साहसी को प्राप्त होता है वह उसका दायित्व लाभ कहलाता है।

1— That it is the owners of business who take the chief risks is clear when we remember that they have paid for the labour, capital and land before the commodity is finished often before its price can be found and if the Commodity when made is not wanted and cannot be sold they cannot recover wages interest and rent expended in the production of it

—Henry Clay *Economics for General Reader* p 337

2— The businessman is essentially an enterprise an enterpreneur as he is sometime called Both terms signify one who undertakes or assume risks It is the reward of the special function which together with the result of superior bargaining constitutes the peculiar income of the businessman such an income as is never earned by anyone except a businessman who undertakes risk

—Carver *Distribution of Wealth* pp 296 297

वास्तविक लाभ पर विभिन्न विद्वानों की विचार धाराएँ—अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लाभ को जोखिम उठाने और भाव ताक-करने की योग्यता का पुरस्कार बताया है। पुगने अर्थशास्त्री वास्तविक लाभ में उस पूँजी का व्यय भी सम्मिलित करते थे जो साहसी स्वयं लगाता है। उस समय के अनुसार यह विचारधारा सम्भवतः ठीक हो सकती थी, क्योंकि उस समय उद्योग घटने इतने नहीं थे जिससे साहसी हो सम्पूर्ण पूँजी लगाता था। परन्तु आज परिस्थिति बदल गई है। आधुनिक औद्योगिक विभाग व्यवस्था में ये काम कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये ये कार्य दो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। अमेरिकन अर्थशास्त्री बर्स्टर ने गवर्ने पहलू पूँजीपति और साहसी के बावों में अन्तर दिया था जो आज सबको मान्य है।

मांसन और उनके अन्य अनुयायी अमेरिकी अर्थशास्त्री वास्तविक लाभ में संगठनकर्ता का पुरस्कार भी सम्मिलित करने हैं, क्योंकि उनका अनुसार साहसी संगठनकर्ता का भी काम करना है। परन्तु यह विचारधारा मान्य नहीं है। आजकल हम क्या देखते हैं कि एक समुक्त पूँजीपति सभी कामों का संगठन-कार्य बतल मोड़ी प्रशस्त करने हैं कि अन्तर्गत जा उनके वास्तविक स्वामी हैं। अतः, यह आवश्यक है कि हम मध्यम और साहस को दो अलग-अलग उत्पत्ति के साधन मानें।

(२) कुल लाभ (Gross Profit)—कुल लाभ वह लाभ है जिसमें वास्तविक लाग अर्थात् जोखिम उठाने और भाव-भाव करने की योग्यता के पुरस्कार के अनिवार्य साहसी द्वारा सम्पन्न अन्य सेवाओं के पुरस्कार भी सम्मिलित होने हैं। कुल लाभ में जो-जो सेवाएँ सम्मिलित होती हैं उनका अलग-अलग किया जाता है:—

कुल लाभ के अंग (Constituents of Gross Profit)—कुल लाभ के निम्नलिखित अंग होने हैं:—

(१) स्वयं साहसी द्वारा प्रदत्त उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार (Reward of the factors of production supplied by the Entrepreneur himself)—नई बार और विशेष कर अविश्वसित औद्योगिक एवं आर्थिक अवस्था में साहसी जोखिम उठाने के अनिवार्य उत्पत्ति के अन्य साधन भी अपने पास-में लमा देता है जिसमें उनका पुरस्कार बाहर के व्यक्तियों का न देकर स्वयं ले लेता है। साहसी अपने प्रदत्त साधनों का पुरस्कार अलग में रहने नहीं देता बल्कि बाद में एक साथ लेता है और इस प्रकार वह कुल लाभ में सम्मिलित हो जाता है। ये पुरस्कार निम्नलिखित हो सकते हैं:—

(क) भूमि का मूल्य—यदि साहसी ने उत्पादन में अपनी निजी भूमि का उपयोग किया है, तो उनका पुरस्कार अर्थात् लगान कुल लाभ में से घटा देना चाहिये। (ख) श्रम की मजदूरी—कर्मियों को साहसी स्वयं एक श्रमिक की भाँति अपने कारखाने में काम करता है, तो उनका पुरस्कार अर्थात् जज्जुओं कुल लाभ में से घटा देना चाहिये। साहसी किस प्रकार एक श्रमिक की भाँति अपने कारखाने में काम कर सकता है यह भारतीय दृष्टि-साहसा के कार्य ने जनों-मौने जाना जा सकता है। (ग) पूँजी पर व्यय—आय: साहसी दूसरा से पूँजी इकट्ठा करने के

निये निश्वास पैदा करना चाहता है, इसलिये थोड़ी बहुत पूँजी खपने पाता तो भी सगाता है। इस लड़ाई हुई निजी पूँजी का व्याज उसका कुल लाभ का प्राप्ति हो। (६) अतः वास्तविक लाभ मापन करने के लिये इस व्याज को भी कुल लाभ में से कम कर देना चाहिये। (७) सगठन के लिए वेतन—यदि साहसी सगठन या प्रबन्ध कार्य भी करता है, तो इस कार्य का पुरस्कार अर्थात् वेतन वास्तविक लाभ मापन करने के लिए कुल लाभ में से घटा देना चाहिये।

(२) सरसा व्यय (Maintenance Charges)—मरसा व्यय में मुख्यतः दो प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं—(क) घिसाई कोष (Depreciation Fund) प्रत्येक उत्पादन यन्त्र एक निश्चित अवधि तक हूँ भसी प्रकार कार्य कर सकता है। उसके पदचान वह बेकार हो जाता है जिसके कारण उसका प्रतिस्थापन (Replacement) आवश्यक हो जाता है। इसका लिये एक कोष स्थापित किया जाता है जिसे घिसाई कोष (Depreciation Fund) कहते हैं। इसमें प्रति वर्ष कुछ राशि जमा कर दी जाती है जिससे अग्रेष्ठ समय पर प्रतिस्थापन के लिये राशि उपलब्ध हो जाती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिये एक यन्त्र का अनुमानित कार्यकाल १० वर्ष है, और उसका मूल्य बीस हजार रुपया है। तो घिसाई

कोष में $\frac{२०,०००}{१०} = २०००$ रुपया प्रति वर्ष जमा किया जायगा। जिसमें यन्त्र

निरर्थक हो जाने पर हमने प्रतिस्थापन के लिये अग्रेष्ठ राशि सुविधता में उपलब्ध हो सके। अतः वास्तविक लाभ जान करने के लिये घिसाई व्यय की राशि को कुल लाभ में से घटा देना चाहिये। (ग) बीमा व्यय (Insurance Charges)—अनेक आकस्मिक दुष्प्रभावों जैसे आग, चोरी आदि से बचन के लिये सर्व एष दूरदर्शी साहसी या उद्योगपति आकस्मिक प्राय बीमा कराते हैं। बीमा के लिये प्रति वर्ष जो प्रीमियम दिया जाता है वह कुल लाभ का घट है। अतः वास्तविक लाभ मापन करने के लिये कुल लाभ में से बीमा व्यय घटा देना चाहिये।

(३) अव्यक्तिगत लाभ (Extra Personal Gains)—अव्यक्तिगत लाभ दो प्रकार के होते हैं—(क) एकाधिकार लाभ (Monopoly Gains)—कभी कभी साहसी को वस्तु की प्रति पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। बाजार में वह अकेला ही विक्रेता होता है जिसका कारण वह अपनी वस्तु के लिये अधिक मूल्य वसूल करने में सफल हो जाता है। यह अधिकृत लाभ जोखिम का पुरस्कार न होकर उसकी विशेष स्थिति का पुरस्कार होता है। (ख) इसकी वास्तविक लाभ में गणना में यह कुल लाभ में करनी चाहिए। (ग) आकस्मिक लाभ (Chance Gains)—कभी कभी परिस्थिति के आकस्मिक अनुकूल परिवर्तन में साहसी का अनायास ही लाभ प्राप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, गन्त महामुद्र में वस्तुओं में भाव बढ़त बढ़ गये थे जिसमें उन व्यापारियों को जिनके पास वस्तुओं का स्टॉक था बड़ा लाभ हुआ। इसी प्रकार विहार के भूकम्प के समय चीनी व बहुत सारे सामानों में जो गये थे जिसमें जोनी के अर्थ कारणों की अदृशित अवस्थिति लाभ हुआ। इस प्रकार यह अधिकृत लाभ कुल लाभ का घट है न कि वास्तविक लाभ का।

अतः वास्तविक लाभ जान करने के लिये कुल लाभ में ग एकाधिकार लाभ एवं आकस्मिक लाभ घटा देना चाहिये।

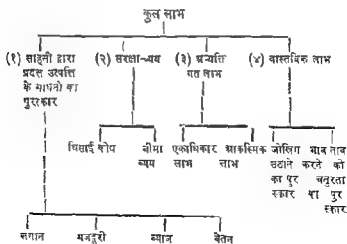
(४) वास्तविक लाभ (Net or Pure Profit)—यदि कुल लाभ में से साहसी द्वारा प्रदत्त साधनों का पुरस्कार सरक्ष व्यय एवं बच्यनिगम लाभों को घटा दिया जाय, तो बचा हुआ वास्तविक या शुद्ध लाभ होगा। अतः वास्तविक लाभ भी कुल लाभ का अंश होता है। वास्तविक लाभ मुख्यतः दो प्रधान कर्षों का पुरस्कार होता है—(क) जोखिम उठाने का पुरस्कार (Reward for Risk taking function)—साहसी भावी मूल्य और माग की मात्रा का अनुमान लगाकर उत्पादन प्रारम्भ करना है। यदि उम्मा अनुमान गलत होता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है। यही जोखिम वह भेजना है। अतः इसका पुरस्कार वास्तविक लाभ कहलाता है।

(ख) भाव-भाव करने की चतुरता का पुरस्कार (Reward for Bargaining skill)—उत्पादन के विभिन्न साधकों से मध्यविदा करते समय साहसी यह प्रयत्न करता है कि वह उनको सवावें सस्ती से सस्ती खरीदे। यदि वह सौदा या भाव-भाव करने में चतुर है तो उसे अधिक लाभ मिलेगा। इस प्रकार प्राप्त पुरस्कार वास्तविक लाभ का अंश होता है।



अतः जोखिम उठाने और भाव-भाव करने की चतुरता के पुरस्कार वास्तविक लाभ के अंतर्गत आते हैं। स्वयं वास्तविक लाभ कुल लाभ का अंश होता है।

कुल लाभ का रेखाचित्रण—कुल लाभ को हम एक रेखाचित्र द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—



लाभ का निर्धारण

(Determination of Profit)

लाभ—निर्धारण के सम्बन्ध में धर्मशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है जिसके कारण लाभ-निर्धारण के बहुत से विद्वान्त प्रतिपादित किये गये, जैसे लाभ का जगान सिद्धान्त, लाभ का मजदूरी सिद्धान्त, लाभ का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त आदि; परन्तु ये लाभ-निर्धारण के विषय को उचित प्रकार से नहीं समझा करने के कारण स्थापित किये गये।

लाभ निर्धारण का प्रचलित सिद्धान्त (Current Theory of Profit) —लाभ साहसी के जोखिम उठाने का पुरस्कार है। कुछ साहसी अधिक चतुर और योग्य होते हैं और कुछ कम। जो साहसी अधिक चतुर और योग्य होते हैं वे जोखिम घड़ी सुगमता से भेसते हैं। उनमें इतनी बुद्धि और योग्यता होती है कि वे अवश्य में होने वाले परिवर्तनों का ठीक ठीक अनुमान लगा लेते हैं जिससे उन्हें हानि की कम संभावना होती है। इसके विपरीत, अधोग्य साहसियों का भागी अनुमान ठीक नहीं निकलने में उन्हें हानि की धारणा रहती है। प्रो० वाकर के अनुसार जिस प्रकार भूमि के विभिन्न दूनड़ों की उर्वरा-शक्ति में भिन्नता के कारण लगान उत्पन्न होता है, इसी प्रकार सब साहसियों में समान योग्यता नहीं होने के कारण उनको लाभ प्राप्त होता है। कुछ साहसी तो बड़े चतुर होते हैं और उन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत कुछ साहसी ऐसे होते हैं जिनको केवल इतना ही लाभ होता है जिससे कि वे व्यापार में बने रहें, पर्याप्त जितनी धन्य उनके व्यय (निम्न सामान्य लाभ सम्मिलित होता है) के बराबर ही होती है। ऐसे निष्पट व्यापारियों को सीमान्त साहसी (Marginal Entrepreneurs) और इनसे अधिक योग्यता एवं दक्षता वाले उत्कृष्ट व्यापारियों को अधि-सीमान्त साहसी (Super-marginal Entrepreneurs) कह सकते हैं। प्रो० वाकर ने लाभ की लक्षण से तुलना करते हुए यह बताया कि उत्कृष्ट भूमि की भाँति उत्कृष्ट साहसी भी लगान कमाते हैं, और जैसे कि लगानहीन या सीमान्त भूमि होती है वैसे ही लाभहीन या सीमान्त साहसी भी होता है जिसे केवल व्यवस्था का पारिधमिक ही मिलता है। जैसे-जैसे साहसी की योग्यता, बुद्धिमत्ता और साहस अधिक होता जाता है, वैसे-ही वैसे लाभ के रूप में उसका पुरस्कार भी बढ़ता जाता है। अन्य शब्दों में, सीमान्त साहसी की अपेक्षा जो साहसी जितना ही अधिक योग्य एवं दक्ष होगा, उसको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा।

सामान्य लाभ (Normal Profit) —प्रत्येक व्यवसाय में वध-मे-धन इतना लाभ तो अवश्य होता है चाहिये जिसमें कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस कर सके क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। व्यवसाय में यह हानि सह सकता है परन्तु दीर्घकाल में तो उसे जोखिम सेतने और भावता करने का चतुरता का पुरस्कार अवश्य मिलना ही चाहिये। यन्त्र, ऐसी कम-से-कम लाभ को जो साहसी को जोखिम सेतने के लिये प्रोत्साहित कर सके, सामान्य लाभ (Normal Profit) कहते हैं। सामान्य लाभ में उत्पादन-व्यय (Expenses of Production) भी सम्मिलित होता है। सामान्य लाभ का लाभ-

निर्धारण में बड़ा महत्व है, क्योंकि सीमान्त साहसी की मांग सामान्य लाभ के बराबर ही होती है।

श्रीमती रोबिन्सन (Mrs Robinson) के अनुसार सामान्य लाभ वह है जिसमें प्राप्त होने पर न तो कोई नई फर्म उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करती है और न कोई पुरानी फर्म प्रवृत्ति उत्पादन ही बन्द करती है। इसमें कम लाभ प्राप्त होने पर कुछ फर्म उत्पादन बन्द कर देती हैं तथा इसमें अधिक लाभ प्राप्त होने पर नई फर्मों को उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है जिसमें उपादका की मर्यादा बढ़ जाती है प्रो० मार्शल के अनुसार सामान्य लाभ प्रतिनिधि फर्म (Representative firm) का लाभ है। इस प्रतिनिधि फर्म का आकार न घटता है और न बढ़ता है बल्कि समुत्तन रहता है।

सामान्य लाभ का निर्धारण—यह साहस की मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर होता है। यदि मांग पूर्ति से अधिक हुई, तो सामान्य लाभ की दर ऊँची होगी और विपरीत प्रवृत्ति में परिणाम विपरीत होगा। किसी निश्चित समय सामान्य लाभ की दर वह समुत्तन बिन्दु (Equilibrium Point) होता है जिस पर कि साहस की मांग और पूर्ति परस्पर बराबर होती है।

सामान्य लाभ की भिन्नता के कारण—माया-य लाभ किसी व्यवसाय में कम और किसी में अधिक होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—(१) उद्योग-धर्मों की जोखिम की न्यूनता। (२) उद्योग धर्म की व्यवस्था और उसकी विलक्षणता। (३) उद्योग धर्म की व्यवस्था तथा उनके प्रवृत्ति के विवेक भिन्न योग्यता की आवश्यकता।

अतिरिक्त लाभ (Surplus profit)—सामान्य लाभ में ऊपर हुये वाले लाभ को अतिरिक्त लाभ कहते हैं। प्राथिक विज्ञान के कमरबन्दन अधिक साहसी उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिससे अतिरिक्त लाभ की मात्रा कम होती जाती है।

लाभ योग्यता का लगान है (Profit is Rent of Ability)—प्रो० वॉकर ने लाभ को योग्यता का लगान कहा है। उन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार भूमि के विभिन्न भागों की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण संपादन उत्पन्न होता है, इसी प्रकार साहसियों की योग्यता में भिन्नता के कारण लाभ प्राप्त होता है। बहुत से साहसी ही बड़े चतुर होते हैं और बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। ऐसे साहसियों को अधिक सीमान्त साहसी कहा जा सकता है। इससे विपरीत कुछ भाग सीधे मन हीन हैं जिनको केवल उनके व्यवसाय जितना ही लाभ मिलता है। ऐसे साहसियों को सीमान्त साहसी कहा जा सकता है। इन दोनों सीमाओं के बीच के साहसियों की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है जिसके अनुसार उन्हें लाभ प्राप्त होता है। वॉकर के अनुसार जिस प्रकार लगानहीन भूमि व्यापक निश्चिन करती है उसी प्रकार लाभ भी उस साहसी द्वारा निश्चिन होता है जिसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। उसको केवल प्रवृत्ति का वेतन-भाज ही मिलता है। ऐसे साहसी न जितना भी अधिक योग्य कोई अन्य साहसी होगा उसका उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समानता के कारण लाभ योग्यता का लगान कहा जाता है।

लाभ और मूल्य (Profit and Price)—जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म के लाभतन्त्रय के अनुसार निर्धारित होता है, उसी प्रकार वस्तु के लागत-तन्त्रय में सामान्य लाभ (Normal Profit) अवश्य सम्मिलित होता है। यदि कोई साहसी विशेष रूप से दक्ष है अथवा उसे एकाधिकार जैसी अन्य सुविधाएँ प्राप्त हैं, तो उसको हम सामान्य लाभ से अधिक लाभ होगा। इससे विपरीत, जो साहसी सोमान्त साहसी में भी कम योग्य होते हैं, उन्हें घाटा होता है और वे धन को छोड़ बैठते हैं, यतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के मूल्य में केवल प्रतिनिधि फर्म का सामान्य लाभ ही सम्मिलित होता है, अधिक नहीं।

लाभों की भिन्नता के कारण (Causes of Variation in Profits)—लाभों की भिन्नता का मुख्य कारण माहसियों की योग्यता की भिन्नता है। औद्योगिक या व्यावसायिक योग्यता प्रायः मनुष्य में ईश्वरदत्त गुण होता है, परन्तु यह उचित शिक्षा एवं अनुभव पर भी निर्भर होती है। प्रायः यह देखा गया है कि कोई माहसी तो सौदा या भाव-भाव करने में दक्ष होते हैं और कोई प्रबन्ध कार्य में निपुण पाये जाते हैं। कुछ साहसियों में मनुष्यों की परखने और बच्चे मान की पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है तो दूसरों में इनका अभाव पाया जाता है। इससे परिचित, लाभ की भिन्नता के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी साहसी के पास उद्योग की अर्थ-व्यवस्था के लिए पर्याप्त पूँजी होती है तो दूसरे के पास इसका अभाव होता है। किसी साहसी को कुछ ऐसे व्यावसायिक भेदों की जानकारी हो सकती है जिसका ज्ञान सम्भवतः उसके प्रतिद्वन्द्वी को न हो। ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञ साहसी विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु सम्यता के विकास और प्रतियोगिता के कारण ऐसे विशिष्ट लाभ कम होते जा रहे हैं।

लाभ की गणना (Calculation of Profit)—प्रो० मार्शल के अनुसार लाभ की गणना दो प्रकार से की जा सकती है—(१) वार्षिक लाभ, और (२) विक्रय-राशि पर लाभ।

(१) **वार्षिक लाभ (Annual Profit)**—किसी व्यवसाय में लगी हुई कुल पूँजी पर जो वर्ष भर में लाभ होता है उसका कुल पूँजी पर प्रतिशत निकाला जाता है। इसे वार्षिक लाभ की दर कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यवसाय में २०,००० रु० की पूँजी लगी हुई है और उसमें वर्ष भर में २,००० रु० का लाभ हुआ

है, तो उसने वार्षिक लाभ की दर $\frac{२००० \times १००}{२००००} = १०\%$ हुई है।

(२) **विक्रय राशि पर लाभ (Profit on Turn-over)**—जब तैयार किए हुये मांग की वस्तु लगी हुई पूँजी के बराबर हो जाती है तो हम उसे पूँजी का एक फेर (Turn over) कहेंगे। वर्ष भर में यदि कुल विक्री पूँजी से चार गुनी हो जाय, तो हम कहेंगे कि पूँजी के चार फेर हुये। जब लाभ की वर्ष भर की कुल विक्री की राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उसे विक्रय-राशि पर लाभ कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में २०,००० रु० की पूँजी पर १०% वार्षिक लाभ होता है। यदि वर्ष में मांग लीजिये पूँजी के ऐसे चार फेर हुये अर्थात् कुल विक्री ८०,००० रु० की हुई तो विक्री की राशि पर लाभ की दर २३% हुई। यदि पूँजी के फेर दो ही हुये अर्थात् वर्ष भर में विक्री की राशि केवल ४०,००० रु० की हुई, तो कुल विक्री पर लाभ की दर ५% होगी।

कम लाभ और अधिक बिक्री (Small Profit and Quick Return)—इसका अर्थ उम नीति से है जिससे अनुसार व्यापारी बड़ा लाभ लेकर अधिक बिक्री करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह वस्तुओं को कम मूल्य पर बेचता है जिससे कुल बिक्री में वृद्धि होकर कुल लाभ बढ़ जाता है। इससे विपरीत, यदि वह वस्तुएँ अप्रिय मूल्य पर बेचता है तो कुल बिक्री में हाव होकर कुल लाभ घट जाता है। परन्तु जिन व्यवसायों में पूँजी का फेर (Turnover) अधिक होता है वहाँ फेर के लाभ की दर कम होती है। परन्तु कम लाभ होने पर भी मात्र को बेच कर पुन वस्तुएँ खरीद कर इससे और लाभ प्राप्त कर लिया जाता है जिससे कुल लाभ बढ़ जाता है। जैसे गोबर व्यापार में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। बिम्बु जहाँ मात्र इतनी सीधता से वही बिक्री और व्यवसाय में लगे हुए रकम बहुत समय पश्चात् मिलती है वहाँ पर पर प्रतिगत लाभ अधिक होता है। फुटकर व्यापार में प्रायः पूँजी का फेर इतना अधिक नहीं होता है इसलिये इसमें अधिक लाभ लेकर ही वस्तुएँ बेची जाती हैं। इसी प्रकार मोटर कार, रेडियो आदि वस्तुओं की बिक्री कम होने से पूँजी का फेर भी बहुत कम होता है जिससे इन वस्तुओं के व्यापार में लाभ की प्रतिगत दर बहुत ऊँची होती है। इसलिये ये वस्तुएँ प्रायः ऊँचे मूल्य पर ही बिकती हैं।

सामाजिक उन्नति और लाभ (Social Progress and Profit)

समाज की प्रगतिशील अवस्था में विविध योग्य एवं अनुभवी साहसियों की पत्नी होने के कारण बौद्धिक एवं मनी साहसी ही अत्यधिक लाभ कमाते हैं। परन्तु यद्यपि समाज उन्नति करता जाता है तब तब शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। समाज की प्रगतिशील अवस्था में नये-नये आविष्कार होने लगते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगता है जिससे कारण समाज के अधिक लोगों को आवादायिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होने लगता है। ऐसी दशा में आवादायिक एवं औद्योगिक योग्यता एवं दक्षता कुछ शोध में व्यक्तियों की सम्पत्ति न रहकर सब की वस्तु हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन होने पर अनेक साहसी या उद्योगपति व्यवसाय क्षेत्र में उतर आते हैं जिससे उनमें शार्वपरिक प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इससे फलस्वरूप आर्थिक एवं समाधारण लाभ नमाने के अवसर कम हो जाते हैं और लाभ की दर घट जाती है। यद्यपि सम्पत्ति के विकास के कारण मनुष्य की नई-नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नये-नये उद्योग घट्टे खुलने लगते हैं जिससे साहस की माँग भी बराबर बढ़ती जाती है परन्तु फिर भी साहस की माँग की पूर्ति उसकी पूर्ति की प्रेरणा कम रहती है जिससे लाभ घट जाता है। फिर भी लाभ घटने परन्तु मनुष्य के बराबर नहीं हो सक्ता, तथाकि ऐसी स्थिति में लाभ उठाने के लिये कोई भी तैयार न हो सकेगा। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ लाभ की प्रवृत्ति कम होने की है।

अवधि लाभ-प्राप्ति (Profiteering)—जब किसी विविध परिस्थिति में किसी उद्योग या व्यवसाय में साहसी या उद्योगपति द्वारा बहुत अधिक लाभ प्राप्त किये जाते हैं तो यह अवधि लाभ प्राप्ति कहो जाती है। उदाहरण के लिए, युद्ध काल में जबकि वस्तुओं के उत्पादन में कमी होकर उनकी पूर्ति माँग की प्रेरणा कम हो जाती है, तो उद्योगपति तथा व्यापारियों द्वारा उन पर अवधि लाभ प्राप्त किया जाता है।

जिससे उपभोगागो का शोषण होता है। नत महापुद्गल-वास मे भारतीय रेसो मे अत्यधिक लाभ प्राप्त किये। अत्यधिक लाभ प्राप्ति अनुचित होती है, इसलिये सरकार द्वारा समय-समय पर इसका नियन्त्रण होता रहता है। अत्यधिक लाभ-प्राप्ति उद्योग एवं व्यापार की उन्नति मे बाधक मिद्ध होगी है।

समाजवाद और लाभ (Socialism and Profit)—लाभ के विरुद्ध सबसे प्रथम आवाज उठाने वाले समाजवादी थे। प्रसिद्ध समाजवादी प्रुधो ने लाभ को वैधानिक चक्रेनी (Legalised Robbery) कह कर पुकारा है। समाजवादियों का कहना है कि श्रम ही उत्पत्ति का एक-मात्र साधन है और शारीर मर्माति धमिको की ही मिननी चाहिये। उनके मतानुसार श्रान और लाभ दोनों ही श्रम के शोषण के परिणाम है। पूँजीपति और साहसो समाज के लिये कुछ भी नहीं करते हैं। मन. कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के अनुसार श्रान और लाभ का सर्वथा उन्मूलन आवश्यक है।

अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि क्या वास्तव मे समाजवाद मे लाभ जैसी कोई वस्तु नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यो कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत श्राम के रूप मे समाजवाद मे लाभ का प्रवश्य अन्ध हो गया है, परन्तु श्राम व्यय के अन्तर के रूप मे लाभ का समाजवाद मे भी प्रस्तित्व है। अन्तर यही है कि लाभ दशाम किसी व्यक्ति-विशेष को मिलने के समाज को मिलता है और वह सामाजिक कल्याण के लिये व्यय कर दिया जाता है। यह बात सोवियट रूस के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। रूस मे उत्पादन के प्रमुख साधनों पर राज्य का एकाधिकार है। साधारणतया विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर जो लाभत व्यय पडती है, सोवियट सरकार उसमे कहीं अधिक मूल्य वसूल करती है। इस प्रकार राज्य-उद्योगों मे लाभ होता पाया जाता है। यह लाभ अशत प्रौद्योगिक विकास के लिये और अशत जन-हित कार्यों के लिये व्यय कर दिया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि समाजवादी राज्य मे भी लाभ का अस्तित्व पाया जाता है परन्तु वह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न होकर समाज की होती है।

लाभ का औचित्य (Justification of Profit)—आधुनिक उत्पादन प्रणाली मे साहसी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। साहसी ही उत्पादन की सारी व्यवस्था करता है। वह भूमि, श्रम और पूँजी को एकत्र करके उत्पादन का संगठन करता है। वह व्यवसाय प्रवसा उद्योग की नोब डालता है और उत्पादन-कार्य प्रारम्भ करता है। वह अविव्य की माग का अनुमान करन उसकी पूँति के लिये उत्पादन करता है, परन्तु अविव्य सदा अनिश्चित रहता है। अतः यह सम्भव है कि उसका मागो का अनुमान सही न निकल सके। इस प्रकार की अनक जोखिम हा मकती हैं जिनके कारण उसको हानि उठना पड। साहसी इन भव आखिना को केवला हुमा व्यापार मे अग्रसर होता है। अस्तु, उसे इन जोखिमा के बदल लाभ के रूप मे पुरस्कार प्रवश्य मिलना चाहिये अन्यथा वह व्यवसाय न करता। अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि मे लाभ का अस्तित्व नितान्त आवश्यक है। प्रो० निचोलसन (Nicholson) के शब्दों मे साहस सर्वोत्तम रूप मे, असाधारण जोखिम तथा असाधारण योग्यता का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार के साहस के कारण इतनी

अधिक आर्थिक उत्पत्ति हुई है ।¹ इसलिये साहस का पुरस्कार 'लाभ' आर्थिक उत्पत्ति का आधार है ।

लाभ का निन्दनीय है ? लाभ साहसी का पुरस्कार है और समाज के हित को हित में यह आवश्यक है । परन्तु अनुचित एवं अत्यधिक लाभ अवश्य निन्दनीय है । इस समाज में अधिक असमानता उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर करने के लिए सरकार अपनी कानूनी तथा धर्मिक की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण आदि उपायों द्वारा सदा प्रयत्नशील रहती है ।

लाभ और अन्य उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कारों में भेद (*Difference between Profit & Rewards of other Factors of Production*)

लाभ (Profit)	लगान (Rent)
१. लाभ साहसियों की योग्यता की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है ।	१. लगान भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है ।
२. यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया भेद के कारण प्राप्त होता है ।	२. यह प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया भेद के कारण प्राप्त होता है ।
३. आर्थिक उत्पत्ति के साथ इसकी प्रवृत्ति घटने की है ।	३. आर्थिक उत्पत्ति के साथ इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है ।
४. लाभ नकारात्मक हो सकता है, पर्याप्त हानि हो सकती है ।	४. लगान कभी नकारात्मक नहीं हो सकता ।

लाभ और लगान में समानता—(१) जिस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति या स्थिति प्रत्येक दोनो की भिन्नता से लगान में न्यूनधिकता हो जाती है, उसी प्रकार साहसी की जोखिम भेजने, भावनाय करने की क्षमता आदि की भिन्नता से वास्तविक लाभ में भी भिन्नता हो जाती है । (२) जिस प्रकार भूमि का कई उपयोग होता है उसी प्रकार साहसी भी कई प्रकार के हो सकते हैं । (३) जिस प्रकार सीमांत या लगावहीन भूमि होती है और उसके द्वारा लगान निर्धारित होता है उसी प्रकार सीमांत साहसी होता है और उसके सामान्य लाभ के अनुसार लाभ निर्धारित होता है । (४) जिस प्रकार लगान एक प्रकार की अतिरिक्त (Surplus) भाग है, ठीक उसी प्रकार लाभ एक अतिरिक्त भाग है ।

लाभ (Profit)	मजदूरी (Wages)
१. साहसियों की जोखिम उठाने के कारण है । इसलिये लाभ जोखिम का पुरस्कार है ।	१. श्रमिकों के काम में जोखिम नहीं रहता या बहुत कम रहता है ।
२. लाभ अधिकतर अवसर तथा भाग्य पर निर्भर होता है ।	२. मजदूरी तो श्रम करने से ही प्राप्त होती है ।

1—Enterprise, in the highest form, is a combination of exceptional ability with exceptional risk. It is enterprise of this kind that has played the great part in economic progress —Nicholson

३. लाभ पूर्णतया अनिश्चित होता है। सम्भव है साहसी का कभी हानि भी हो जाय।

४. लाभ की दर में बड़ा अंतर पाया जाता है।

५. पूँज-परिवर्तन के साथ लाभ में परिवर्तन होता है।

६. लाभ का निर्धारण सामान्य लाभ द्वारा होता है।

३. मजदूरी निश्चित तथा नियमित होती है। व्ययिक की हानि की घातका नहीं रहती है।

४. मजदूरी की दर में इतना अंतर नहीं होता है।

५. पूँज-परिवर्तन से मजदूरी में अंतर घटित परिवर्तन नहीं होता है।

६. मजदूरी का निर्धारण इसकी माँग और पूर्ति द्वारा होता है।

लाभ और मजदूरी में समानता—श्री० डॉब्रिज के अनुसार लाभ भी साहसी की योग्यता की मजदूरी है, क्योंकि उनको सम्पत्ति में साहसी का कार्य मानसिक मजदूरी है।

लाभ (Profit)	व्याज (Interest)
१. लाभ साहसी का मित्या है।	१. व्याज पूँजीपति का मित्या है।
२. लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है।	२. व्याज आत्म-व्याज या समय तथा प्रतीक्षा करने का पुरस्कार है।
३. लाभ क्षय के रूप में प्राप्त होता है।	३. व्याज असाज दिया जाता है।
४. लाभ अनिश्चित होता है—कभी कम और कभी ज्यादा तथा कभी हानि और कभी लाभ।	४. व्याज-दर प्रायः निश्चित होती है।
५. लाभ सामान्य लाभ के अनुसार निर्धारित होता है।	५. व्याज दर समय और पूर्ति की माँग द्वारा निर्धारित होती है।

लाभ और व्याज में समानता—व्याज की प्रकृति के साथ लाभ और व्याज में घटने की प्रवृत्ति होती है। इनके अतिरिक्त, जो वस्तुओं का पूँज बढ़ जाता है, सब दाना लाभ और व्याज में वृद्धि होने की प्रवृत्ति रखी जाती है।

भारतवर्ष में लाभ (Profits in India)

भारतवर्ष प्रायः उनमें ही दृष्टि में पिछड़ा हुआ है। यहाँ न उद्योग ऐसे अवनत दशा में है। यहाँ प्रायः एक अनुभवही माहविषय का भी अभाव है। परन्तु भारतवर्ष में लगभग सब उद्योग यथा ॥ लाभ कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब हम नीचे कुछ मुख्य उद्योग चलाएँ कि लाभ प्राप्ति पर विवरण करेंगे।

कृषि में लाभ (Profits in Agriculture)—भारत के एक कृषि प्रधान देश है, परन्तु यहाँ कृषि अवनत दशा में है। अरबों घण्टा के बाद हमें ॥ जन-मध्या का पूँज १८ में घटकर रह गया है। यहाँ न उपजाऊँ कृषि मशीन के लिए बहुत कम पूँज है और जो कुछ भी है वह छद्म उच्च दृष्टि के रूप में अत्यन्त स्थिर है जिसमें लाभप्रद नहीं की जा सकती। भारतीय कृषि निर्धन होत है जिसमें न तो अन्धे धोखे

प्रयुक्त कर सक्ने हैं और न अन्धरा बोन हो। मिचार्ड की सुविधाया के प्रभाव से भारतीय कृषि 'वर्षा का बुधा' बनी हुई है। इन कारणों से कृषि में उत्पादन कम होता है और कृषकों का लाभ कम ब्याज पर प्रायः हानि उठानी पड़ती है। परन्तु युद्ध-कालीन एवं युद्धोत्तर परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन का मुख्य बड़ जाने में कृषकों का कुछ लाभ बढ़ गया है।

कुटीर उद्योग-उत्पादों में लाम (Profits in Cottage Industries)—भारत का औद्योगिक प्रयोग जम्बू-विश्वान था। यहाँ का बना हुआ मात्र यूरुप आदि देशों में विक्रित था। औद्योगिक क्रांति, विदेशी प्रतिस्पर्धिता तथा भारत में अर्थोन्नति की प्रतिबन्धन नीति के कारण भारतीय घरेलू उद्योग-उत्पादों में जर्म जर्म नष्ट हो गए। जो शिल्पकार इन पन्थों को चलाते हैं उनकी दशा शोचनीय है। वे निर्धन हैं, अतः अपने प्रयत्नों के लिए उच्च मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनमें अत्यधिक कष्टों से बचूत करते हैं। इससे अनिश्चित उच्च कच्चा माल ऊँचे दर पर गरीबों को पड़ता है तथा निम्न मूल्य का अन्धरा मुख्य नहीं मिलता। इस प्रकार शिल्पकारों का बहुत कम वचना है। महात्मा गाँधी ने यह उद्योगों को उन्नत करने का विशेष ध्यान आकर्षित किया था तथा अब कांग्रेस सरकार भी इनकी ओर पर्याप्त ध्यान दे रही है। अतः इनका भविष्य आशाप्रद प्रतीत होता है।

बहु-उद्योग-उत्पादों में लाम (Profits in Large-Scale Industries)—भारतवर्ष में बहु-उद्योगों की संख्या बहुत कम है। परन्तु जो कुछ भी है वह अन्धरा लाम बचता है। इसके कई कारण हैं—(१) ग्राहकों की संख्या माँग की प्रवृत्ति कम है। (२) जो भी ग्राहकी है वे मुख्य एक कुम्हण हैं, जैसे रिक्का हाथमिमी, मिहानियाँ, मुन्धियाँ आदि। (३) ग्राहकों के पास उद्योगों में लगाने के लिए पचास घन राशि है। अतः, इनका आर्थिक लाम पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने हैं।

व्यापारियों को लाम (Profits to Traders)—व्यापारियों को कभी अन्धरा लाभ हो जाता है और कभी कम। कम भारतीय व्यापारी अपनी योग्यता एवं कार्य समता के कारण अन्धरा लाभ बना लेते हैं।

भारतवर्ष में साहस-क्षेत्र का विस्तार (Extension of the field of Enterprise in India)—आधुनिक भारत में साहस क्षेत्र में कुछ विस्तार अवश्य हुआ है, परन्तु देश का अर्थोन्नति, जनसंख्या एवं लामों की दृष्टि में यह बहुत कम है यद्यपि कर्म-कार्यवादी तथा अधिकारी की संख्या बढ़ती जा रही है, परन्तु फिर भी जनसंख्या का केवल १० प्रतिशत भाग ही आधुनिक उद्योग-उत्पादों में सम्मिलित है, और इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का भी सम्पूर्ण माँग का बचन छोड़ना भाग ही पूर्ण कर सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि अब भी भारत में साहस का विस्तार का लिय पर्याप्त क्षेत्र है।

भारतवर्ष में साहस का क्षेत्र (Scope for Enterprise in India)—भारत का आर्थिक एवं औद्योगिक उत्थान का लिय उन्नततम सभी क्षेत्रों में ग्राहकों का आवश्यकता है। किन्तु उद्योग-उत्पादों में अब भी साहस का विस्तार का लिय पर्याप्त क्षेत्र है, वे निम्नलिखित हैं :—

कृषि उद्योग—कृषि की वर्तमान अवस्था देश को देखकर कुछ लामों को यह धारणा हो गई है कि कृषि में अब उत्थान नहीं हो सकती, परन्तु यह धारणा निराधार एवं अशुभ है। हमारे देश में अभी तक अनिश्चित कृषकों का आशा प्रवृत्ति बढ़ाने का प्रोत्साहन की मर्यादा से खेती हानी रही है, किन्तु विज्ञान न कृषि-क्षेत्र में आन्तरिक-उन्नत

परिवर्तन कर दिया है। अतः आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधि द्वारा भारतीय कृषि उद्योग को उन्नत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में बहुत-सी वज्र एवं दमरुओं भूमि पड़ी हुई है जो कृषि-आय बढ़ाई जा सकती है। अतः कृषि उद्योग में साहस के लिये अब भी पर्याप्त क्षेत्र है।

वन सम्बन्धी उद्योग—भारतवर्ष में वनों का उपयोग ठीक प्रकार नहीं होता। इनसे प्रायः हानि वाली अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ हैं—जैसे रकड़ी, घास, ताम्र, रबड़, माँस, गोद, जड़ी-बूटियाँ आदि। देश के आर्थिक विकास के लिये इनका औद्योगिक उपयोग वांछनीय है। अतः वन सम्बन्धी उद्योग-धन्यो के विकासार्थ साहसियों की सेवाओं के लिये पर्याप्त क्षेत्र है।

घरेलू उद्योग-धन्यो—बहुल उद्योगों के साथ साथ घरेलू उद्योग-धन्यो का विकास भी वांछनीय है। भारतवर्ष में घरेलू उद्योग धन्यो के विकास के लिये साहस का विस्तृत क्षेत्र है। अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि औद्योगिक उन्नत देशों में वहाँ छोटे छोटे उद्योग परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं। मोटर उद्योग बम्पनी में भारत सरकार की परामर्श दिया है कि मोटर में छोटे छोटे पुर्जे कुटीर उद्योगों द्वारा बनवाये जायें। नदी-भाटों योजनाओं द्वारा भारत के लाखों गाँवों में जन-विद्युत्-शक्ति पहुँचाई जायगी। इसमें कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर चलाने में सहायता मिलती बिना शिक्षित, बेकार नवयुवकों को स्वावलम्बी बनने का अवसर प्राप्त होगा।

बृहद् उद्योग धन्यो—भारतवर्ष में बृहद् उद्योग-धन्यो के विकास के लिये भी प्रायः सभी मांगसिमा उपलब्ध हैं। वर्तमान उद्योगों का उत्पादन माँग की अपेक्षा कम है। बड़े उद्योग धन्यो अभी जलक अवस्था में ही हैं तथा बड़ी नव उद्योग-धन्यो की स्थापना वांछनीय है। इस प्रकार बृहद् उद्योग धन्यो में भी साहस के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। इस दान की पुष्टि निम्नलिखित उद्योगों के अध्ययन से हो जाती है।

सूती-वस्त्र-उद्योग—सूती-वस्त्र-उद्योग पूर्णतया भारतीय उद्योग है, क्योंकि हमारा प्रबल प्रवचन आदि भारतवासियों के हाथों में ही है। देश में जितनी कपड़े की माँग है उनका कपड़ा अभी तैयार नहीं होता है और हमें विदेशों में पैगाला पड़ता है। देशवासियों के जीवन-स्तर के बढ़ने पर यह माँग और भी बढ़ जायगी। इसलिए इस उद्योग में साहस का बहुत अधिक क्षेत्र है।

लूट उद्योग—भारतीय लूट उद्योग का अर्थ-अन्यत्र अब तक विद्वत्सियों के हाथ में था, परन्तु अब भारतीय इन आरंभ कर रहे हैं। अब तक यह देश के कच्चे लूट व आने भाग की ही वस्तुएँ तैयार करने में समर्थ है। भारत सरकार इन उद्योगों का कच्चे माल के लिये रक्षावर्धनी बनाने के लिये पूर्ण प्रयत्नशील है। अतः अधिक या इन उद्योगों की उन्नति की वही आशा है।

लोहा और इस्पात—लोहा की आवश्यकता में अनुसार अभी लोहा तथा इस्पात का माँगाने हमारे देश में नहीं बनता है। अधिकतर हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह उद्योग एक प्रकार से आधारभूत उद्योग है जिस पर अन्य उद्योगों की उन्नति आश्रित है। अतः, इसकी उन्नति के लिये साहसियों की बड़ी आवश्यकता है।

कागज उद्योग—कागज की माँग घुरी करन के लिये भारतवर्ष विदेशों पर निर्भर है। समाचार पत्रों के लिये कागज तो हमारे देश में बहुत कम तैयार होता है।

देश में शिक्षा के बढ़ते हुये प्रसार को देखते हुये हमने अत्यधिक साहस का धन दृष्टि-गोचर होता है।

रासायनिक उद्योग—यह उद्योग व्यापार-भूत माना जाता है, क्योंकि देश के अन्य उद्योगों की उन्नति इस उद्योग की उन्नति पर निर्भर है। हमारे देश का यह उद्योग प्रचुरता में है और हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अस्तु, इस उद्योग के विकासार्थ साहस का बहुत भारी धन है।

खनिज उद्योग—भारतीय जमदा-उद्योग उन्नतिशील अवस्था में नहीं है इसलिये अधिकतर कच्चा माल विदेशों को निर्यात किया जाता है जिससे देश को अधिक लाभ नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस उद्योग में साहस के लिये विस्तृत धन है।

अन्य उद्योग—रेशमी वस्त्र, चीनी, काग, दिवाभलाई, मोपेट, रेडियो, वाइ-सिक्किन, विजली का सामान आदि वस्तुओं के निर्माण उद्योगों के लिये साहसियों के लिये भारत में बड़ा भारी धन है।

वातायान सम्बन्धी उद्योग—आरतयर्ष में हवाई जहाज, सपुत्री जहाज, रेलें, मोटर आदि का निर्माण देश की आवश्यकताओं से बहुत कम है। इस देश के आर्थिक विकास के लिये वातायान सम्बन्धी सभी उद्योगों की उन्नति अभीष्ट है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

१—दिल्लियाँ लिखिये :—

सामान्य लाभ तथा अनिश्चित लाभ

कुल लाभ और वास्तविक लाभ

(प्र० वी० १६६०)

वास्तविक लाभ

(प्र० वी० १६५६)

२—लगान और लाभ में अन्तर बताइये। इन दोनों में जो समानताएँ हैं उन्हें समझाइये।

३—‘लाभ माहम का पुरस्कार है।’ स्पष्ट कीजिये। लाभ से मजदूरी और ब्याज का अन्तर बताइये।

४—कुल लाभ की व्याख्या कीजिए। लाभ त्रिन सेवाओं का पुरस्कार है, उन्हें बताइये।
(प्र० वी० १६५२)

५—‘लाभ को साहस का पुरस्कार कहा जाता है।’ आप इस कथन में कहीं तक सहमत हैं? लाभ को कमी कमी योग्यता का लगान क्यों कहा जाता है?
(प्र० भा० १६५४)

६—लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है? कुल लाभ और वास्तविक लाभ का अन्तर बताइये।
(प्र० भा० १६५३)

७—कुल लाभ और वास्तविक लाभ की परिभाषाएँ लिखिये और इनका अन्तर स्पष्ट कीजिये।
(लागवुर १६५०)

८—वास्तविक लाभ को व्याख्या करिये । यह किस प्रकार निर्धारित होता है ?

(सामर १६५०)

९—लाभ किस प्रकार निर्धारित होता है ? क्या यह कहना मत्व है कि लाभ का प्रभाव मूल्य पर नहीं होता ।
(दिन्सी हा० मे० १६५०)

इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएं

१०—लाभ का क्या अर्थ है ? साहसी क्या काम करता है ? क्या लाभ एक अवगोप है ?

११—नोट लिखिये :—

कुल लाभ और वास्तविक लाभ

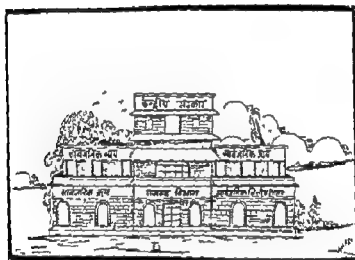
(अ० बो० १६६०)

लाभ के तत्त्व

(रा० बो० १६६०)

राजस्व

(PUBLIC FINANCE)



"राजस्व केवल अंशगणित ही नहीं है ; राजस्व एक महान् नीति है। बिना सुदृढ राजस्व के सुदृढ शासन संभव नहीं है, बिना सुदृढ शासन के सुदृढ राजस्व संभव नहीं है।"

—विल्सन

राजस्व का अर्थ (Meaning of Public Finance) — 'राजस्व' शब्द राजस्व + स्व के योग से बना है जिसका अर्थ होता है 'राज का धन'। अतः राजस्व अर्थ शास्त्र का वह विभाग है जिसमें राज्य की आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में, राजस्व वह विज्ञान है जो यह बताता है कि राज्य सरकार आय कैसे प्राप्त करती है और उसे कैसे व्यय करती है।

प्रत्येक सम्यक् समाज में राज्य संगठन की व्यवस्था होती है। राज्य का मुख्य कार्य देश की बाहरी शक्तियों से रक्षा करना और देश में शांति और सुव्यवस्था रखने हुए जनता को सुख-सुविधा में सहायक होना है। इस कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये राज्य को सेना, पुलिस, सरकारी बर्षाचारो आदि रखने होते हैं। राज्य जनता को नैतिक और आर्थिक उन्नति के लिये भी अनेक कार्य करता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिक्रिस्ता, मुद्रा, टुकड़ा की व्यवस्था आदि। कई आवश्यक कार्य जिन्हें नागरिक व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, राज्य की ओर से किये जाते हैं, जैसे देश में रेल, डाक व तार का प्रबन्ध करना, सिंचाई के लिये नहर निकालना, वनों और खानों आदि राष्ट्रीय सम्पत्तियों की रक्षा करना इत्यादि। इन विविध कार्यों को सम्पन्न करने के लिये धन की आवश्यकता पड़ती है और राज्य का व्यय चलाने के लिये आय की व्यवस्था करनी होती है। राज्य द्वारा धन की उत्पत्ति एवं उपभोग में सम्बन्धित समस्त कार्यों का उत्त्लेख 'राजस्व' में होता है। धन राजस्व वह विज्ञान है जिसमें राज्य की आय व्यय और सत्यमन्वन्धी बातों पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जाता है। राज्य या सरकार से यहाँ तात्पर्य केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिरिक्त स्थानीय सत्पाएँ जैसे नगरपालिकाएँ (Municipalities) और जिला परिषदों (District Boards) आदि से भी है।

राजस्व की परिभाषाएँ (Definitions)—विभिन्न विद्वानों ने राजस्व की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है —

१. सर सिडनी चैपमैन (Sir Sydney Chapman) के अनुसार "राजस्व अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि सरकारें किस प्रकार से आय प्राप्त करती हैं और किस प्रकार उसका प्रबन्ध करती हैं।"

1—"Public Finance is that part of Political Economy which discusses ways in which governments obtain revenues and manage them

—Sir Sydney Chapman *Outline of Political Economy*, p 395.
६२३

२. प्रो० फिन्ले शिराज (Prof. Findlay Shiras) व शब्दा मे "राजस्व वह विज्ञान है जो यह बताना है कि सरकार काय बंसे प्राप्त करती है और उसे कैसे व्यय करती है।"^१

३. प्रो० बैस्टेबल (Prof. Bastable) व अनुसार "राजस्व राष्ट्र के राजनीय अधिकारिया व आय व्यय, उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा आविष प्रसाप्तन व नियन्त्रण से सम्बन्ध रखता है।"^२

४ डाक्टर डाल्टन (Dr. Hugh Dalton) व शब्दों मे "राजस्व सत्ता की सम्पत्ति व आय और व्यय तथा उनके पारस्परिक सामञ्जस्य से सम्बन्ध रखता है।"^३

५ प्रो० एम० सैन (Prof. M. Sen) के अनुसार "राजस्व अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार व आय और व्यय तथा उनके प्रसाप्तन का विवेचन करती है।"^४

६. प्रो० एडम्स (Prof. Adams) के शब्दा मे "राजस्व सरकारी आय-व्यय का अनुसन्धान-मात्र है।"^५

७ श्रीमती ब्रोक्स (Mrs. Brooks) व अनुसार "राजस्व का मुख्य तत्त्व उन मापना और तिहासों का परीक्षण और विवेचन करना है जिनके द्वारा सरकारी सहाय्य आवश्यकताओं का सामूहिक रूप में समुचित करों का प्रयोग करती है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक धन प्राप्त करती हैं।"

८. आर्मिस्टेज स्मिथ (Armistage Smith) के मत में "सरकार काय और व्यय व स्वभाव व निष्ठा का ही राजस्व कहा जाता है।"

९. प्रो० प्लेह्न (Prof. Plehn) व अनुसार "राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञ की उन क्रियाओं का विवेचन करता है जिनके द्वारा वह राज्य

1—'Public Finance is the science which is concerned with the manner in which authorities obtain their income and expend it

—Findlay Shiras *The Science of Public Finance*, Vol. 1

2—'Public Finance deals with expenditure and income of public authorities, of the state and their mutual relation as also with financial administration and control

—Prof Bastable

3—'Public Finance deals with the income and expenditure of public authorities and with the manner in which the one is adjusted to the other

—Dr Hugh Dalton *Public Finance*

4—"Public Finance is that branch of Economics which deals with the revenues and expenditures of government and the administration of such revenues and expenditures

—Outline of Economics by M S n Part II (Edition 1930) p 344

के स्थानाधिक कार्यों को सिद्धि के लिए भौतिक साधनों की प्राप्ति और प्रयोग करता है।¹

राजस्व का महत्व (Importance)—प्राचीन समय में राजस्व का अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि सरकार ने बहुत थोड़े से कार्यों में, जैसे देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना आदि। इनके लिए सरकार को जनता से कर लेने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परन्तु आज वल सरकार के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि हो गई है। आज की सरकार का कर्तव्य है कि वह देश से शिक्षा और बेकारी दूर करके शांति को व्यवस्था करे, देश के उद्योग प्रयोगों की उन्नति करे और धन व वस्तु की समुविधाओं से देश को युक्त करे। इन तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है यह धन सरकार कर द्वारा प्राप्त करती है। अतः वर्तमान समय में राजस्व का महत्व बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, देश की समृद्धि बहुत कुछ सरकार की कर नीति पर भी निर्भर होती है। यदि सरकार की कर नीति अच्छी न हो तो देश का उत्पादन घट जायगा और व्यवसाय में उन्नति न हो सकेगी। फलतः बेकारी बढ़ती जायगी। इसके विपरीत, यदि सरकार की कर नीति अच्छी है, तो उत्पादन में वृद्धि होगी और देश का सर्वतोमुखी विकास हो सकेगा। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए राजस्व के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

राजस्व के विभाग (Divisions of Public Finance)—राजस्व के अध्ययन की गिनतिसिद्धि मुख्य चार भागों में विभाजित किया जाता है :—

- (१) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)
- (२) सार्वजनिक आय (Public Revenue)
- (३) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)
- (४) वित्त सम्बन्धी शासन (Financial Administration)

(१) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)—राजस्व के इस भाग में सरकारी व्यय का वर्गीकरण तथा उसके सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है जिनसे अनुसार सरकार द्वारा भिन्न भिन्न मदों पर होने वाली राशियों का परिमाण निश्चय किया जाता है।

(२) सार्वजनिक आय (Public Revenue)—राजस्व के इस भाग में राज्य के आवश्यक व्यय के लिए धन प्राप्त करने के साधन, प्रणालियाँ तथा कर लगाने के सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है।

(३) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)—राजस्व के इस भाग में सरकार द्वारा ऋण लेने व चुकाने के साधनों व सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है।

(४) वित्त सम्बन्धी शासन (Financial Administration)—राजस्व के इस भाग में इस बात का विचार किया जाता है कि सार्वजनिक प्रशासन व बजट किस प्रकार तैयार करके परमूर्त किया जाता है, किस प्रकार पद्धतियों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा सार्वजनिक व्यय का हिसाब किस प्रकार रखा जाता है और इसका भ्रमभङ्ग (Audit) किस प्रकार होता है।

1—"The science which deals with the activity of the statesman in obtaining and applying the material means necessary for fulfilling the proper functions of the State"

सार्वजनिक और व्यक्तिगत व्ययों की तुलना

(Public and Private Expenditures Compared)

(१) **प्रायः व्यय का सम्बन्ध**—किसी व्यक्ति का व्यय उसकी आय द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जबकि सरकार पक्ष भवने व्यय का अनुमान लगानी है और उसने पर्याप्त उद्योग ही धन प्राप्त करने के उपाय एवं मार्ग निकालती है। इस प्रकार व्यक्ति उद्योग ही पैसे पसारता है जितनी लम्बी उसकी चाल है। परन्तु सरकार पक्ष चालर का लम्बाई-चौड़ाई निर्दिष्ट करती है और तत्पश्चात् उसने लिए आवश्यक कपड़े का प्रयोग करती है।

(२) **उत्पन्न के दृष्टिकोण से अन्तर**—व्यक्ति अपनी आय में कुछ बचाना बुद्धिमानी एवं दूरदर्शिता समझता है। यत प्रत्यक्ष व्यक्ति यह प्रयत्न करता है कि जहाँ तक सम्भव हो आय में कम व्यय हो ताकि कुछ राशि बचिप्य के लिए बचाई जा सके। परन्तु सरकारी बजट में बचन (Surplus) होगा राजस्व ने सिद्धान्त के विपरीत समझा जाता है, क्योंकि उद्योग प्रवृत्ति यह हो जाना है कि देशवासियों को बेकार कर-भार से लाद कर धन एकत्रित किया गया है। इससे अतिरिक्त, राजस्व बजट में घटत होने से सरकारी अधिकारियों गलत व्ययों में शमावधानी कर बैठते हैं। इसलिये राजस्व का घाटर्ष यह है बजट में मोटी मो बनी (Deficit) रहे जिसमें सरकारी अधिकारी गलत व्यय करने में सावधानी धरते हैं।

(३) **व्ययों की अनिवार्यता से अन्तर**—सार्वजनिक व्यय अनिवार्य होता है जबकि एक व्यक्ति का व्यय बहुत कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, बाहरी आक्रमण के समय तथा अन्य सबद काल में देश की रक्षा के लिये सरकार की आवश्यकता ही व्यय करना पड़ता है।

(४) **साधनों का अन्तर**—सरकार और व्यक्ति के साधन में अन्तर होता है। सबद-काल में सरकारें अपने प्रापस, दश-विदेशों से श्रद्धा में सकती हैं, परन्तु व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत ही उपहार में सक्त है। इसके अतिरिक्त, सरकार मुद्रा प्रसार (Inflation) द्वारा भी धन की कमी का पूरा कर सकती है, परन्तु व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।

(५) **अवधि का अन्तर**—सरकार का बजट एक वर्ष के लिये होता है। परन्तु व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्त्व नहीं होता है, क्योंकि उसे किसी निश्चित प्रसंग के भीतर अपना बजट मनुष्यता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह धीरे धीरे व्यय करता रहता है।

(६) **उद्देश्यों में अन्तर**—व्यक्ति की प्रत्यक्ष-व्यवस्था में अधिकतम व्यक्तिगत सन्तुष्टि एवं लाभ का उद्देश्य रहता है। परन्तु सामाजिक व्यय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसने अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) हो और उद्योग उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय और राष्ट्रीय आय, धनरक्ष उपभोग आदि पर उत्तम प्रभाव पड़े।

(७) **नोच में अन्तर**—किसी भी व्यक्ति के लिए आय व्यय में एक विशेष सीमा से अधिक परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है। परन्तु सरकारी आय-व्यय में बड़ी सरलता या महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिये, यदि एक साम्प्रदायी दल के शासक में सत्ता आ जाय तो वह निश्चय रूप से सरकारी आय-व्यय

दोनों में कान्तिकारी परिवर्तन न हो सकता है। परन्तु व्यक्तिगत अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की लोच का अभाव है।

(८) अधिकारों में अन्तर—व्यक्ति अपनी आय प्राप्त करने के लिये किसी भी प्रकार के विशेष अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। परन्तु दूसरे विपरीत सरकार आय में वृद्धि करने के हेतु अनिवार्य सम्पत्ति का अपहरण कर सकती है, मरने पर लगा सकता है, वस्तुपूर्वक जनता में छुट्टा न मन्वी है और व्यक्ति को अनु-पाजित प्राप्त पर अधिकार कर सकती है।

(९) सोमन्त उपयोगिताओं का समीकरण—मम सोमा उ उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आधारस्वभाव अपनी आय को प्रत्येक वस्तु पर इस प्रकार व्यय करता चाहता है कि उसे धन की प्रत्येक इकाई में समान मरमान उपयोगिता प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह सतर्कता पूर्वक विभिन्न वस्तुओं के व्यय की उपयोगिता पर पूर्ण विचार कर लेता है। परन्तु जो सरकार धन की व्यय करती है तब उसके लिये इस प्रकार सर्वनापूर्वक विचार करना सम्भव नहीं है। विभिन्न राजनैतिक दलों के दबाव या अन्य कारणों से सरकार को सभी कभी अनुपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी धन व्यय करना पड़ता है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकारी व्यय सर्वे ही अविवेकपूर्ण होने है।

(१०) गोपनीयता में अन्तर—प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्थ-व्यवस्था को गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, जबकि सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था का आधार प्रचार है। सरकार अपने बहुत प्रति वर्ष प्रकाशित करती है और उनका प्रचार करती है।

राजस्व का न्यम एवं सिद्धान्त (Aim and Principle of Finance)—डॉक्टर डास्टन के अनुसार राजस्व का सर्व महत्पूर्ण लक्ष्य व सिद्धान्त अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) प्रदान करना है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुसार राज्य की आय और व्यय का समन्वय इस प्रकार किया जाना चाहिये जिनसे समाज को अधिकतम अधिक लाभ की सुरक्षा प्राप्त हो सके। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी एक निश्चित राशि में अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये सम-सीमान्त-उपयोगिता के सिद्धान्त (Law of Equi-marginal Utility) के अनुसार कार्य करता है और वह यह प्रमाण करता है कि उसे प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए जाने वाले धन की मरमान इकाई से समान उपयोगिता प्राप्त हो उसी प्रकार सरकार का भी इसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने अपने व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना चाहिये।

अधिकतम सामाजिक लाभ अर्पित के लिये यह आवश्यक है कि 'कर' लिये समय दम बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिनसे पाग अधिक धन है उन पर कर भार अधिक पड़ और धन-राशि व्यय करने समय यह ध्यान चाहिये कि निर्यात की अधिकता लाभ पहुँचे।

सार्वजनिक आय के साधन (Sources of Public Revenue)—सार्वजनिक आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं—

(१) सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Domain)—सरकार के स्वामित्व में भूमि, वन, खाने आदि होगे हैं और यह इनसे आय प्राप्त करती है।

(२) धर्म्य दण्ड या जुर्माना (Fines)—सरकार दोषिया को दण्डित करने है जिसमें उसको आय होती है ।

(३) भेट (Gifts)—कभी-कभी कुछ व्यक्ति अपनी दौलत में सरकार का कुछ धन राशि भेट करते हैं । यह भी सरकार का आय का एक साधन है ।

(४) फीस या शुल्क (Fees)—सरकार कुछ विशेष सेवाओं के लिये पुरूष भी वसूल करती है जिसमें सम्मको आय होती है । जैसे पिछा शुल्क, ताइमिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फास आदि । प्रो० सेलिगमन के अनुसार फीस सरकार के उन सावजनिक व्ययों को सुगम बनाने के लिये ली जाती है जो सावजनिक हित के लिये किये जाते हैं किन्तु जो साथ ही साथ फीस देने वाले का भी कुछ विशेष लाभ पहुँचाते हैं । फीस मन्दा से नागस से अधिक नहीं होती है क्योंकि इस प्रकार की सेवा में सावजनिक हित की भावना रहती है ।

(५) मूल्य (Price)—सार्वजनिक सरकार कुछ व्यवसाय भी करती है जैसे डाक, सार, रेल आदि । इन व्यवसायों के द्वारा सरकार जनता का भाल या नफा देखती है और जो मूल्य माता है वह सरकार की आय होती है ।

(६) दरें (Rates)—दरें विपणनर स्वामीय सुधारों की पूर्ति के लिये म्युनि सपैलिया तथा जिला बोर्डों द्वारा लगाई जाती हैं । वे साधारणतया नागरिकों की अचन सम्पत्ति पर लगाई जाती है । परन्तु ये दरें बिना किसी विपण सुधार या लाभ के भी लगाई जा सकती हैं । बराब स्वत्वानुसार भिन्नता पाई जाती है । कुछ विद्वानों के अनुसार मूल्य और दरा में कोई विशेष महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है ।

(७) विशेष कर निर्धारण (Special Assessment)—प्रो० सेलिगमन के अनुसार विशेष कर निर्धारण विशेष लाभ के अनुदान के लिये तथा एक अनिवार्य योगदान (Compulsory Contribution) है जो सावजनिक हित के लिये ली गई सम्पत्ति के विपण सुधारों की लागत को चुकाने के लिये लिया जाता है । उदाहरण के लिये पाक मन्च, बिजली, गार्डन आदि के सुधार से ग्रामवासियों के मकानों का मूल्य बढ़ जाता है । बिचाई के लिये सहारा कुया आदि के सुधार से भूमि का मूल्य बढ़ जाता है । मकानों तथा भूमि में मूल्य-वृद्धि उनके स्वामियों के प्रदाय के फलस्वरूप नहीं बरन् अनर्जित लाभ (Unearned Increment) है । मकानों और भूमि के स्वामियों के विकास या सुधार की लागत का कुछ भाग विपण कर निर्धारण के रूप में वसूल किया जाता है जिससे सरकार को लाभ होता है । प्रो० सेलिगमन के विपण कर निर्धारण की निम्नलिखित विफलताएँ बताई हैं —(अ) इस विपण लाभ को मापा जा सकता है । (इ) यह विपण कर निर्धारण प्रगतिमान रहा किन्तु प्राप्त लाभ के समानुपाती होता है । (ई) यह विपण कर स्वामीय सुधार के लिए लगाया जाता है । (उ) यह समाज के स्वामी पौदे के खर्च और सुधार करने के लिये लगाया जाता है ।

1— A Compulsory contribution levied in proportion to the special benefit derived to defray the cost of specific improvement to property undertaken in the public interest

—Seligman

८. कर (Taxes)—कर सरकारों द्वारा वा मन्त्रों द्वारा लापन है। कुछ विशेष माम हो या नही, नोया का कर तो देने ही पडता है। प्रचलाओ प्लेहन (Piehn) के शब्दों में "कर घन के रूप में दिया गया नाभान्य अनिवार्य दान-योग (Compulsory Contribution) है जो राज्य के निवासियों पर सामान्य लाभ (Common Benefit) पहुँचान के लिए, नियम व्यवस्था की पूर्ति के लिए जनता से लिया जाता है।"¹

प्रो० सेलिंगमन (Seligman) के अनुसार "कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया हुआ वह अनिवार्य योगदान है जिसे सरकारों के विशेष माम का ध्यान नहीं रखते हुए, सरकार अपने कल्याण के लिए व्यय करती है।"²

गुटानियो डी विटि डी मार्को (Antonio de Viti Marco) ने भी "कर का जनता को प्रायः वा बहु भाग बताया है जिस सरकार जन-साधारण का मया करन के लिए लेती है।"³

कर की विशेषताएँ (Characteristics)—कर की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं,—

- (१) यह जाता का अनिवार्य योगदान है।
- (२) जन-साधारण ही कर का मुख्य उद्देश्य है न कि किसी व्यक्ति विशेष की सेवा का।
- (३) कर में राज्य का मुख्य उद्देश्य प्राप्ति करना होता है।
- (४) प्रो० टॉमिंग (Taussig) के अनुसार "सार्वजनिक अधिकारों और कर-दाता के मध्य प्रत्यक्ष 'किसी की सेवा (quid pro quo) कर का समान ही कर तथा सरकारी कर्म-शाय में अन्तर पैदा करता है।"⁴

इस प्रकार कर में कुछ अनिवार्यता रहती है तथा दूसरा उद्देश्य जन-साधारण की सेवा है। तब मुख्य बात यह है कि कर में कर-दाता के लाभ और त्याग का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समान सम्बन्ध नहीं होता है।

मूल्य, फीस और कर में अन्तर (Difference between Price, Fee & Tax)—मूल्य उस वस्तु की राशि है जो कोई व्यक्ति सरकार का किसी वस्तु या सेवा के बदले में देता है। मूल्य और फीस में मुख्य अन्तर यह है कि फीस में विनाश लाभ के साथ साथ सार्वजनिक हित भी प्रमुख रहता है जबकि मूल्य सार्वजनिक

1—Introduction to Public Finance

—Piehn, p. 59.

2—"A tax is a compulsory contribution from the person to the Government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefits conferred"—Seligman.

3—"The tax is a share of the income of the citizens which the state appropriates in order to procure for itself the means necessary for the production of general public services."

—Antonio de Viti Marco, p. 111.

4—"The essence of a tax as distinguished from other charges by the Government is the absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority."

—T. W. Taussig, Principles of Economics, p. 46.

एन की सेवा के बदले में लिया जाता है, जैसे सरकारी रेलों द्वारा यात्रा करने की लागत, टिकट और लिफाके आदि खरीदने का मूल्य। मूल्य वर से भी भिन्न होता है। कर सामान्य लाभ (Common Benefit) के लिय दिया जाता है, जबकि मूल्य और फीस दो विशेष लाभ के लिए दिए जाते हैं। कर अनिवार्य होता है, परन्तु मूल्य और फीस वैकल्पिक होते हैं। प्रो० सेलिग्मैन ने इस अन्तर को इस प्रकार प्रतिपादित किया है। “प्रमुख सार्वजनिक उद्देश्य सहित विविष्ट लाभ का अस्तित्व फीस का आवश्यक गुण है। सार्वजनिक उद्देश्य का अभाव सुमतान को मूल्य बना देता है विविष्ट लाभ का अभाव उसे कर बना देता है।”¹

कर के सिद्धान्त (Canons of Taxation)—जैसे ने ही सरकार का मुख्य धाम होती है। अतः कर व सिद्धान्तों का ज्ञान सेना आवश्यक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ (Adam Smith) ने सबसे पहले कर के सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे जो धन सच भी मान्य समझे जाते हैं। आर्थशास्त्रज्ञानुसार बांध के विज्ञाना ने कुछ नये सिद्धान्त और जोड़ दिये हैं। वे इस निम्नलिखित हैं—

एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित कर के सिद्धान्त (Adam Smith's Canons of Taxation)²

१. समानता या न्याय का सिद्धान्त (Canon of Equality or Equity)—प्रो० एडम स्मिथ ने अनुसार “प्रत्येक राज्य की प्रथा का दया सम्भव अपनी योग्यताओं (Abilities) के अनुसार सरकार की सहायता के लिये पण देना चाहिये अर्थात् उस धन के अनुसार म जो राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत प्राप्त होती है।”³ प्रो० एडम स्मिथ का कहना है कि वर इस प्रकार लगाना चाहिये कि जो व्यक्ति धनी हैं उन्हें अधिक वर देना पड़े और जो निर्धन हैं उन्हें बहुत कम वर देना पड़े, अर्थात् वर लोग की वर देने की क्षमता या योग्यता के अनुपात में लगा चाहिये। इसे न्याय का सिद्धान्त (Principle of Equity) भी कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार को वर दायता से इतना वर वसूल करना चाहिए कि प्रत्यक्ष करदाता सरकार के लिये समान त्याग या बलिदान करें। नमान बलिदान या त्याग की दृष्टि से जो व्यक्ति लोग स उनकी धन के अनुपात में अधिक वर वसूल किया जाता है और निम्नोक्त अनुपात में कम, तो ऐसे वर को प्रगतिशील वर (Progressive Tax) कहते हैं। यही कर आजकल सर्वमान्य सम्झा जाता है।

1—“The essential characteristic of a fee is the existence of a special measured benefit together with a predominant public purpose. The absence of a public purpose makes the payment a price, absence of special benefit makes it a tax.” —Seligman

2—Adam Smith *Wealth of Nations* Bk II, chapter 2, Section 2

3—“The subjects of every state ought to contribute towards the support of the Government as nearly as possible in proportion to their respective abilities; i. e., in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state.”

—Adam Smith.

इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिये यदि १०० रु० मासिक आय वाले व्यक्ति स ३ पाई प्रति रुपया कर लेते हैं तो १,००० रु० मासिक आय वाले से एक भागा या अधिक प्रति रुपया कर लेना चाहिये। आरनवष में आय कर (Income Tax) इसी सिद्धान्त के अनुसार लगता है।

२ निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)—प्रो० एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो भोग्य करना है वह निश्चित होना चाहिये। और किसी को इच्छा कर निभार नही होना चाहिये। भुगतान का समय भुगतान की गति कर की मात्रा आदि करदाता तथा धन्य व्यक्ति के लिय स्पष्ट होनी चाहिये।^१ कर की निश्चितता करदाता तथा वित्त मंत्री दोनों के लिये ही आवश्यक व वजह को सम्बुद्धि करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। राज्य के इच्छानुसार कर नीति में धीमे परिवर्तन अनिश्चितता उत्पन्न करती है जिससे भ्रष्टाचार घूसखोरी भट आदि को प्रोत्साहन मिलता है। प्रो० एडम स्मिथ ने लिखा था कि कर के मामले में किसी व्यक्ति को जो पता देनी है उनको निश्चितता इतन महत्व की बात है कि मुझ विद्वान्त है कि सम्मेलन के अनुभव के अनुसार असमानता की कल्पना बड़ी माना इतनी भयानक नहीं है जितनी कि अनिश्चितता की बहुत थोड़ी मात्रा है।^२ 'ह्याडले' (Hadley) के मतानुसार समानता के समस्त प्रयत्न करा के निश्चित होने के बिना अनात्मक सिद्ध होते हैं। मस्तु करा की निश्चितता करदाता तथा सरकार दोनों के लिये ही परमावश्यक है। इसीलिये यह कहा है कि पुराना कर अच्छा कर है और नया कर बुरा कर है। (An old tax is a good tax and a new tax is a bad tax.)

३ सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)—प्रो० एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर ऐसे समय और एसी रीति से लगाना चाहिये जिससे कर दाता को उसके देने में अधिक सुविधा मिल सके।^३ उदाहरणार्थ लगान या मत्स्यजाली फसल के समय नही उचित है। उपभोगिता पर लगाये जाने वाले अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) भी सुविधाजनक होते हैं क्योंकि वे वस्तुओं के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिये जाते हैं। कर अधिकारी तथा करदाता को कर देने में व देने में अनावश्यक कष्ट नही होना चाहिये।

1—The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment the quantity to be paid ought all to be clear to the contributor and to every other person.

—Adam Smith *Wealth of Nations* Vol II

2—Adam Smith wrote the certainty of what individual ought to pay is in taxation a matter of so great importance that a very considerable degree of inequality it appears I believe from the experience of all nations is not near so great an evil as a very small degree of uncertainty

—Adam Smith *Wealth of Nations*, Vol II

3—Every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it

—Adam Smith *Wealth of Nations* Vol II

४. मितव्ययता का सिद्धान्त (Canon of Economy) प्रो० एडम स्मिथ व अनुसार प्रत्येक कर को इस प्रकार लगाना चाहिये कि जनता की जेब से जितना सभ्य हो उतना कम लिया जाय और इसका अधिकतम भाग राज्य कोष में जमा हो जाय।^१ उदाहरणार्थ, यदि १०० रुपये कर के रूप में वसूल करने में ३० या ४० पaise हो जायें, तो ऐसा कर मितव्ययी नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिये क्योंकि इससे जनता को कष्ट होगा और सरकार को अधिक प्राय भी नहीं हासिल होगा। अर्थशास्त्रज्ञ ह्यूम्स, रिकस्टोड, वानर और जोन्स उसी कर-अवस्था को उत्तम मानते हैं जिसमें वसूली व्यय कम हो। अस्तु, कर वसूल करने में ग्यूनतम व्यय होना चाहिये।

कर के कुछ सिद्धान्त—एडम स्मिथ ने उपर्युक्त कर-सिद्धान्तों के प्रतिरिक्त प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ और नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनका विवरण नीचे किया जाता है।

५. उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)—राम-स्य बार्नी बेस्टवेल (Bastable) ने उत्पादकता का कर-सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उनसे अनुसार कर-व्यवस्था अधिकतम उत्पादक होनी चाहिये। करों से प्राप्त होने वाली प्राय कम से कम इतनी प्रयत्न हो कि उससे सरकार को अपनी व्यवस्था सुचारु रूप में चलाने में कोई कठिनाई नहीं हो और प्रत्येक कर से सरकार मुक्त रहे। परन्तु जहाँ कर नीति का उत्पादन होना आवश्यक है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि कर द्वारा भारी न हो कि देश के उत्पादन पर उनका घातक मानव प्रभाव पड़े। जहाँ तक सम्भव हो करों की संख्या इतनी अधिक न हो कि जनता को घनावश्यक, कष्ट सहना पड़े और उत्पादन पर भी प्रतिफल प्रमाण पड़। मक्षेपण, इस सिद्धान्त व अनुसार एक कर जिसमें अधिक प्राय होती है, वह उन वस्तु में करा से घटता है जिनमें प्रत्येक से बहुत बोझ प्राय होता है। इसे पर्याप्तता का सिद्धान्त (Canon of Sufficiency) भी कहते हैं।

६. लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)—सरकार को कर-नीति ऐसी होनी चाहिये कि देश की सकृद्वि के साथ कर से होने वाली आय स्वतः ही बढ़ जाय। साथ ही किसी अनापारण्य परिस्थितिवा से कर की आय बढ़ाने की आवश्यकता भी न पड़ जाय, ता वसूल कर की दर बढ़ाने प्राय में हो काम चल जाय। अधिक कर वसूल करने का प्रयत्न न करना पड़। अतः यह स्पष्ट है कि लोच के सिद्धान्त में उत्पादकता तथा मितव्ययता के सिद्धान्तों का भी सम्मिश्रण है। भारतीय प्राय-कर, रेल, तार, डाक प्रादि की नीतियाँ लोचदार हैं।

७. कोमलता का सिद्धान्त (Canon of Flexibility)—इस सिद्धान्त व अनुसार कर-प्रदत्ति में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिये। कोमलता के बिना पर-व्यवस्था में लोच नहीं रहे सकती। कठोर कर-नीति में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वगान का स्वाधीन बन्दावस्तु कठोरता का

1—"Every tax ought to be so contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state."

एक उदाहरण है। कोमनता का ध्यान ही बचान के आर्थिक सकटों का एक मुख्य कारण है।

८. सरलता का सिद्धान्त (Canon of simplicity)—ग्रामिटेज स्मिथ (Armitage Smith) के अनुसार "कर-बद्धति सरल, सीधे घोर सर्व-साधारण के समझ में आने योग्य होनी चाहिये।" जटिल कर नीति से भ्रष्टाचार पनपता है, मुकद्देबाजी को प्रोत्साहन मिलता है तथा नागरिकों का नैतिक-स्तर गिरता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह सिद्धान्त एक खर्च चौकीदार या सतरी का कार्य करता रहता है। भारतवर्ष को अपेक्षा-रत प्रजायी सरल नहीं है।

९. विभिन्नता का सिद्धान्त (Canon of Diversity)—इस सिद्धान्त के अनुसार कर भिन्न-भिन्न प्रकार के होने चाहिये ताकि राज्य को किसी विशेष कर पर आश्रित न रहना पड़े। करो को सक्ता अधिक होने से उसका भार अपेक्षाकृत कम मान्य पड़ता है। इसलिये कर विभिन्न प्रकार के होने चाहिये जिससे कि सब नागरिकों से मोटा-बहुत श्रमा प्राप्त हो सके। माष-ही-माष यह भी ध्यान रखना चाहिये कि करो की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये कि उन्हें बचल करने में अधिक व्यय करना पड़े।

१०. औचित्य का सिद्धान्त (Canon of Expediency)—इस सिद्धान्त के अनुसार वे कर ही लगाये जाने चाहिये जो राष्ट्रकीय हों और जिनके देने में जनता घनाकानी न करे। इसलिये राज्य द्वारा जब कभी कोई नया कर लगाया जावे तब सावधानी बरती जावे ताकि जनता का कम-से-कम विरोध हो।

११. एक-सा एकरूप होने का सिद्धान्त (Canon of Uniformity)—निटी (Nitty) और कौनार्ड (Conard) नामक अर्थशास्त्रियों ने एक घोर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार एकरूप (Uniform) होने चाहिये। परन्तु इनके दो अर्थ हो सकते हैं। क्या करों का भार प्रत्येक कर-दाता पर एक सा पड़ना चाहिये? यदि हाँ, तो उससे समान त्याग की ध्वनि निकलती है जो कर नीति में आवश्यक है। कुछ अर्थशास्त्री इसका अर्थ करो कि दरो की समानता में लेते हैं जो त्रुटिपूर्ण है। उदाहरण के लिये, धाय-कर की दर तथा विक्रय-कर की दरों को समान करने से प्रत्येक कठिनाईयाँ उपस्थिति हो जायेंगी।

कर के प्रकार (Kinds of Taxes)—कर दो प्रकार के होते हैं :—

(१) प्रत्यक्ष कर, और (२) अप्रत्यक्ष कर।

(१) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़े जिससे वह लिया जाता है। प्रो० जे० एस० मिल (J. S.

Mill) — वे अनुसार “प्रत्यक्ष कर उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाना है जिनसे उसे लेने का सरकार का उद्देश्य है।”¹ इसे अधिक स्पष्ट करने हुए यों कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है कि जिसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर टापा नहीं जा सकता, अर्थात्, जिस व्यक्ति पर वह लगना है उसी का वह कर देना पड़ता है। हैटले (Hadley) के शब्दों में “जिन वस्तुओं का विचरित या बालन (Shifting) नहीं होना सम्भव है, उन पर प्रत्यक्ष कर है, जिनका चालन बिना पूर्वक हासिल तया व्यापारिक प्रतिक्रिया द्वारा जिन वस्तुओं पर टापा जा सकता है अत्यन्त पराले कर कहलाते हैं।”² उदाहरण के लिये, आय-कर (Income-tax) एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि आय-कर देने वाला अपना भार नहीं टाल सकता है।



(२) अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर (Indirect Tax) — अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर वह कर है जिसका भार कर देने वाला अन्य व्यक्ति पर टाल सकता है। प्रो० जे० एस० मिल के अनुसार “अप्रत्यक्ष कर ऐसे व्यक्ति से इस भाँति



[—“Direct tax is demanded from the very person who, it is intended or desired, should pay it” and indirect tax “demanded from one person in the expectation and intention that he should indemnify himself at the expense of another”

—J S Mill, *Principles of Political Economy*, eg III, Book V

2—Hadley, *Economics*, pp 459 61

मे लिया जाता है कि वह दूसरे व्यक्तियों में वसूल कर प्रपनी हानि का पूति कर लेगा ।' बैस्टबल (Bastable) के शब्दों में 'प्रत्यक्ष कर स्वाभाविक और बार-बार आने वाले समयों पर लगाये जाते हैं । विशेष अवस्थाओं में धीरे-धीरे-धीरे हो कर लगाये जाते हैं ।' बिजो-कर (Sales-Tax) इस श्रेणी का कर है । वर्यपि बिजो-कर को हो कर देना पड़ता है, परन्तु वह हुए-शून्या में वह उपभोक्ताओं में हो कर का वसूल कर देता है ।

प्रत्यक्ष करों के लाभ (Advantages of Direct Taxes)—प्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) राजनैतिक जागरूति—प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में प्रत्यक्ष कर नागरिकता की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण होते हैं । करदाता सम्झता है कि वह सरकार का कुछ दे रहा है तथा राजकीय बाधा में उसका भी भाग एवं उत्तरदायित्व है । अतः वह राजनैतिक बाधों में सक्रिय रुचि स्थितान सज्जता है ।

(२) न्यायपूर्णता—प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं, क्योंकि कर प्रत्यक्ष व्यक्ति का सामर्थ्य के अनुसार ही लगाया जाता है ।

(३) प्रगतिशीलता—प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील (Progressive) होते हैं तथा उनके भार का सीमा पर धाकानों में डाला जा सकता है और नियंत्रण जनता कर का भार से मुक्त रखी जा सकती है ।

(४) मितव्ययता—भारदार तथा कर-दाता के मध्य कोई मध्यस्थ न होने से कर कम लागू में वसूल हो सकता है । अतः ये छत्र मितव्ययी हान है ।

(५) उत्पादनशीलता—प्रत्यक्ष कर छत्र उत्पादक होते हैं । भारतवर्ष में आय-कर और मूल्य-कर दो प्रमुख कर हैं जिसमें भारत सरकार का बड़ी लाभ हुआ है ।

(६) लोक—प्रत्यक्ष कर बड़े लोकप्रिय होते हैं । भावश्यकतानुसार उन्हें घटाया-बढ़ाया जा सकता है ।

(७) निश्चिन्ता—इन करों में प्राप्त होने वाली आय निश्चिन्त रहती है । अतः सरकार ध्यान बचक में उनकी गलती निश्चिन्त रूप में कर सकती है । करदाता को भी यह ज्ञान रहता है कि उसे कितना, कहीं और कितना देना है ।

प्रत्यक्ष करों में हानियाँ (Disadvantages of Direct Taxes)

(१) अनुविधा—प्रत्यक्ष करों में करदाता को अनुविधा भी होती है, क्योंकि उसे बहुत-से फार्म भरकर सरकार का देना पड़ते हैं और आय-व्यय का पूरा तत्ता ध्यारे-वार रखना पड़ता है । कर की पूरी रकम का एक सम प्रकृति करना पड़ता है और उसके देने में करदाता को कष्ट होता है ।

(२) स्वेच्छाचारिता पूर्ण—प्रत्यक्ष करों का निर्धारण स्वेच्छा में होता है । अतः देश के लोगों को वे कितना धन्य हो सकता है ।

1—"These taxes are direct which are levied on permanent and recurring occasions, while charges on occasional and particular events are placed under the category of indirect taxation

—Bastable Public Finance.

(३) ईमानदारी पर कर—कुछ विशेषतः ऐसे करो को सचाई या ईमानदारी पर कर (Tax on Honesty) कहते हैं, क्योंकि करदाता को उनमें वेईमानी का पलोभन रहता है। भूँटा बही-खाता देकर कम कर दिया जा सकता है। फिर कर-प्रधिकारियाँ के भ्रष्ट होने की आशंका बनी रहती है। उन्हें घूस देकर उनके सहयोग से करदाता भूँटे बही-खाते सरलता से बना सकता है।

(४) कर से बचने की चेष्टा—कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कर देने को तैयार नहीं होता। यदि देना भी पड़े तो न्यूनतम कर देना पड़े। इसलिये वह गलत हिसाब बना कर तथा अन्य प्रकार से कर से बचने का प्रयत्न करता है।

(५) लोकप्रियता का अभाव—प्रत्यक्ष कर लोकप्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि कर सीधे दिये जाने से करदाताओं को बुरा लगता है। परन्तु अप्रत्यक्ष कर में कर देते समय यह पता नहीं लगता कि कब कर दिया गया।

(६) अल्प आय वालों से कर वसूल करने में कठिनाई—बोझी आप्र वालों पर प्रत्यक्ष कर लगाया ही नहीं जा सकता है, विशेष कर दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों तथा घरेलू नौकरों पर प्रत्यक्ष कर लगाना अत्यन्त कठिन है। साथ ही इस प्रकार से कर दबद्धा करने का व्यय ही बहुत अधिक होता है।

(७) धन संचय भावना में ह्रास होने की सम्भावना—यदि कर को माना में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाय तो जनता में धन की बचत करने की भावना कम हो जाती है।

अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों के लाभ

(Advantages of Indirect Taxes)

(१) सुविधापूर्वक—अप्रत्यक्ष कर बड़े सुविधाजनक होते हैं। ये प्रायः वस्तुओं के मूल्य में लिपटे होते हैं।^१ इसलिये करदाता को बिना ज्ञात हुए इनका भुगतान होता रहता है। इसके अतिरिक्त, ये एक मुक्त न देकर धीरे धीरे वस्तुओं के मूल्य में साथ दिये जाते हैं जिससे जनता को महँगा भी नहीं लगता कि उनमें कर लिया जा रहा है।

(२) लोचदार—आवश्यकतानुसार इनमें बढ़ा-बढ़ी की जा सकती है।

(३) निर्बलों से भी कर वसूली सम्भव—प्रत्यक्ष कर केवल धनी लोग ही देते हैं। परन्तु अप्रत्यक्ष कर निर्धन व्यक्ति भी देते हैं।

(४) मितव्ययी—इन्हें वसूल करने में विशेष व्यय नहीं होता है।

(५) ये टाले नहीं जा सकते—ये कर वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होते हैं, इसलिये वस्तुओं को खरीदने तथा उनका उपयोग करते समय उन्हें अवश्य देना ही पड़ता है।

(६) लोकप्रियता—अप्रत्यक्ष कर बड़े लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार वसूल किये जाते हैं कि करदाता को तबियत भी बुरा नहीं होता है।

1—"Indirect taxes are wrapped up in the price"

(३) सामाजिक लाभ—इन करों से एक सामाजिक लाभ भी होता है। सरकार जिन हानिकारक वस्तुओं का उपयोग कम या नहीं करना चाहती (जैसे शराब, धाराय प्रादि) तो उन पर कर लगाकर उनका मूल्य बढ़ा सकती है। सामाजिक वस्तुओं को कर-मुक्त रखकर उनका उपयोग बढ़ा सकती है।

(८) समानता—जिन्ना वस्तुओं पर भारी कर लगा कर, करों का भार धनियों पर डाला जा सकता है।

(९) आय का विस्तृत क्षेत्र—परोक्ष करों की सहायता से कर व्यवस्था का क्षेत्र बहुत विस्तृत किया जा सकता है। सरकार का आय के अनेक साधन मिल सकते हैं।

अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों में हानियाँ

(Disadvantages of Indirect Taxes)

(१) नागरिकों की भावना का अभाव—अप्रत्यक्ष करों द्वारा करदाता में नागरिकों की भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वह दाता वस्तुओं के मूल्य पर कर लगाने से अनुभव ही नहीं करता कि वह कर द्वारा उठे हुए करों के रूप में सरकार को भी धन दे रहा है।

(२) प्रतिगामी कर—यह कर प्रतिगामी (Regressive) होता है। इनका भार धनियों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। उदाहरण के लिए, गरीबों को अधिक कर और गरीबों को अधिक कर देना पड़ता है।

(३) अनिश्चितता—अप्रत्यक्ष कर अनिश्चित होते हैं। वस्तुओं के उपयोग की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। अतः सरकार द्वारा करों की मात्रा का नहीं अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है।

(४) उद्योग धर्मों पर प्रतिफल प्रभाव—जिन वस्तुओं पर कर अधिक लगा दिये जाते हैं उनके उद्योग-धर्मों के मूल्य हानि की सम्भावना रहती है। विदेशों में सस्ते मूल्य पर लगाया गया अधिक कर उसने लिए बहुत घातक सिद्ध होता है।

(५) सरकारी आय में हास होने का सम्भव—जिन्ना वस्तुओं पर कर लगाने से उनका मूल्य बढ़ जायगा तथा उनकी मांग घट जायगी अतः सरकार की आय भी कम हो जायगी।

(६) मितव्ययिता का अभाव—अधिक इन करों से नृजनदार अतिरिक्त कर-संग्रहकर्ता (Unpaid Tax-Collector) का कार्य करता है, परन्तु फिर भी इनमें कर वसूलने का अधिकार होता है। नागरिकों द्वारा सरकार और धनिकों के मध्य बर्तन मध्यस्थता मिलती है। वे कर की मात्रा को मिला कर वास्तविक मूल्य को बढ़ा देते हैं।

(७) लोच का अभाव—बहुत से कर लाचदार नहीं हैं, क्योंकि आय का नहीं पाने।

(८) छल-छपट एवं चोर-बाजारों की प्रोत्साहन—इन करों का दर अधिक होने से लोग माल छिपकर भण्डार और माल को चोर-बाजारों में बेचने की प्रवृत्ति पैदा होती है जो सामाजिक और नैतिक दृष्टि में अत्यन्त हानिकारक है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का तुलनात्मक निरूपण—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के गुण दोषों का अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि कोई एक प्रकार के कर पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। इन दोनों प्रकार के करा का उपयुक्त सांग्रह ही उत्तम राजस्व माना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य ने चलने में दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कर प्रणाली में इन दोनों प्रकार के करा का समावेश होना चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधान मंत्री म्लैडस्टन ने एक समय कहा था कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो सुन्दर बहिनों की भाँति हैं और एक चतुर राजस्व सचिव को दोनों का आदर करना चाहिए।



एक वित्त मंत्री का कर लगाते समय यह दखना चाहिये कि देश के सभी वर्गों पर कर का कुछ न कुछ भार पड़े। किसी एक भाषण में भाष्य प्रार्थित करने के लिए किसी एक वर्ग को अधिक कर-भार से सावधान उचित नहीं है। इसलिये कर के जितने विभिन्न साधन हैं उतना ही अच्छा। कर प्रणाली का प्रगतिशील (Progressive) रहने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी भाग का अधिक भाग प्रत्यक्ष करा में प्राप्त हो, परन्तु अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्रतिकी व साय-साय निधना को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार राजकीय व्यय में कुछ न कुछ हाथ बढ़ाने का अवसर देना चाहिये।

भारतवर्ष में कर-प्रणाली—विद्यमानतः प्रत्यक्ष कर ही अधिक प्रचलित हैं। यही कारण है कि पाँच सप्ताह देश में प्रत्यक्ष कर ही अधिक लगाये जाते हैं। परन्तु भारत वर्ष में कर-प्रणाली एक प्रकार में संतुलित नहीं है। यह अप्रत्यक्ष या परोक्ष करा पर अधिक प्रवृत्त है। अप्रत्यक्ष कर निधना का अधिक भार गृहस्थ निम्न होते हैं। इन सभी हमारे देश में आयात निर्यात कर (Customs & Duties), उत्पत्ति कर (Excise Duties), विपरीत कर खास प्रमुख परोक्ष कर के साधन हैं और कबल आय कर (Income tax) ही मरत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर का साधन है। हाव ही म सम्पत्ति कर (Estate Duty) व लग जान में प्रयोग कर व साधना में कुछ वृद्धि हो गई है।

कर सघात और कर भार (Impact and Incidence of Tax)—कर सघात (Impact of Tax) उस व्यक्ति पर होता है जो प्राप्ति में उसे देना है और कर भार (Incidence of Tax) उस व्यक्ति पर होता है जो अन्त में उसे सहन करता है। प्रत्यक्ष करा (Direct Taxes) में कर-सघात और कर-भार एक ही व्यक्ति पर रहता है। उदाहरण के लिये, जो व्यक्ति आय कर (Income-tax) देता है उसे इसका सघात (Impact) और भार (Incidence) दोनों ही सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर ही कर देना पड़ता है। परन्तु अप्रत्यक्ष करा (Indirect Taxes) में कर-सघात एक व्यक्ति पर और कर भार किसी अन्य व्यक्ति पर होता है। उदाहरण के लिये, यदि सूती वस्त्र पर उत्पादन कर (Excise Duty) लगा दिया जाय, तो प्रारम्भ में उसका भुक्तान बम्ब निर्यात सहन करता है और इस प्रकार इसका सघात (Impact) निर्यात पर ही पड़ता है। परन्तु वह इस कर का वजन के मूल्य में जोड़ देता है जो अनेक हस्तान्तरणा व पश्चात् बम्ब उपभोक्ताओं का सहन

करना पड़ता है। यद्यपि इसका भार (Incidence) वय के उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

एक उत्तम कर-प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Tax System)—एक उत्तम कर-प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए :-

(१) कर-निर्धारण के समस्त सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए—एक उत्तम कर प्रणाली कर के समस्त सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। कर-प्रणाली न्याय, निश्चितता, मितव्ययता, सुविधा, उत्पादकता, योग्य, सामयिक विभिन्नता, औचित्य आदि सिद्धान्तों से परिपूर्ण होनी चाहिये।

(२) न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त से परिपूर्ण होनी चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली का न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त (Principle of Minimum Sacrifice) के अनुसार समाज पर कम भार होना चाहिये।

(३) उत्पादन और वितरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली वह प्रणाली है जिसका देश के उत्पादन और वितरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिये और यह हर प्रकार से मितव्ययता पूर्ण होनी चाहिये।

(४) सरल, उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिये—एक उत्तम कर प्रणाली सरल, प्रापिक रूप से उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिये जिससे कि उसमें नई आवश्यकताओं भी पूर्ति हो सके।

(५) कर-प्रणाली इकहरी की प्रपेक्षा बहुरूपी होनी चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली इकहरी कर पद्धति (Single Tax System) की प्रपेक्षा बहुरूपी कर-पद्धति (Multiple Tax System) पर आधारित होनी चाहिये। याम्नाम न, एक उत्तम कर प्रणाली का क्या गम्भिर निगूत आधार होना चाहिये।

(६) प्रशासन की दृष्टि से सरल, योग्य तथा भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिये—एक उत्तम कर प्रणाली प्रशासन के दृष्टिकोण से सरल, योग्य तथा भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिये। यह भली प्रकार नियन्त्रित होनी चाहिए ताकि इस पर बेईमान व घोटब्राज व्यक्तियों का कोई प्रभाव न पड़ सके।

(७) प्रगतिशील होनी चाहिये—एक उत्तम कर प्रणाली को प्रगतिशील होना चाहिये। इसे व्यक्ति, समाज और सरकार के दृष्टिकोणों का सामन रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिये।

(८) सद्भावनापूर्ण होनी चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली पूर्ण रूप से सद्भावनापूर्ण होनी चाहिये। यह एक वास्तविक पद्धति होनी चाहिये कि मित्र मित्र करा का सप्रति-भाष। प्रत्येक कर समस्त कर-प्रणाली में ठीक ठीक जग जाना चाहिये जिससे कि वह मिली-जुली सम्पूर्ण प्रणाली का एक अंग हो सके। इससे द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त भी प्रकार पूर्ण होना चाहिये।

भारतीय कर-प्रणाली (Indian Tax-System)—एक उत्तम कर प्रणाली के गुणों के अध्ययन के पुरस्कार यह जानना आवश्यक है कि भारतीय कर प्रणाली में वे गुण किस सोमा तक पाये जाते हैं। यामन की दृष्टि से भारतीय कर-प्रणाली सुन्दर है। घोषा देने की दृश्य अधिक सम्भावना नहीं। कर प्रणाली

उत्पादन, सारल, सुविधाजनक, मितव्ययी, कोमल तथा बहुस्वी है। देश का प्रत्येक नागरिक राज्य को कुछ-कुछ देता ही है। वृषक लगान देता है तथा उत्पादन-कर तथा शराब-कर में अधिक भी हाथ बटाता है। परीक्षा करो को उचित स्थान प्राप्त है। भारतीय कर प्रणाली को लोग हम इसी से ज्ञात होती है कि हमने किस सकलता के साथ परतन्त्र तथा निर्धन होने हुए भी गन् महायुद्ध का व्यय सहन किया है। परन्तु इतना होते हुए भी यह कोई आदर्श कर-प्रणाली नहीं कहो जा सकती है, क्योंकि इसमें अनेक दोष पाये जाते हैं।

भारतीय कर-प्रणाली के दोष (Defects of Indian Tax System)—
भारतीय कर प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :—

(१) वैज्ञानिक ढंग से आयोजित नहीं है—भारतीय कर-प्रणाली अस्त-व्यस्त है तथा वैज्ञानिक ढंग से आयोजित नहीं है। कर-भार तथा कर का उत्पादन व वितरण पर पढ़ने वाले प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

(२) संतुलन का अभाव है—भारतीय कर-प्रणाली संतुलित नहीं है। देश में परोक्ष करों की गरगार है। यहाँ केवल आय-कर ही मुख्य प्रत्यक्ष कर का साधन है।

(३) मितव्ययतापूर्ण नहीं है—भारतीय कर-पद्धति मितव्ययतापूर्ण नहीं है, क्योंकि यह भारतीय उद्योग और वितरण पर उचित प्रभाव नहीं डाल रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन सम्बन्धी अत्यधिक व्यय होता है। सुरक्षा पर इतना अधिक व्यय होता है कि राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये बहुत कम बच रहता है।

(४) न्यायपूर्ण नहीं है—यह कर पद्धति न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि लगान, घुट्टी, शराबकारी और यहाँ तक कि रेलवे किराया कुल मिलाकर निम्नता द्वारा धनिकों की अपेक्षा अधिक दिया जाता है।

(५) प्रगतिशील नहीं है—भारतीय कर-प्रणाली प्रगतिशील भी नहीं है। भारत में आय-कर ही एक ऐसा कर है जो धनिकों द्वारा अधिक दिया जाता है किन्तु इसकी प्रगति भी इतनी कम नहीं है जितनी कि होनी चाहिए।

(६) अनिश्चिततापूर्ण है—भारतीय कर प्रणाली अनिश्चिततापूर्ण है। इसलिये भारतीय बजट 'मात्रमून का कुषा' माना गया है।

(७) अनुदार तथा अजिन और अनाजित आय में विशेष भेद करते वाली नहीं है—भारतीय कर-प्रणाली प्रति अनुदार तथा अजित और अनाजित आय में विशेष भेद करने वाली नहीं है।

(८) करो के आय के साधन अपर्याप्त एवं लाचरीन है—हमारे करो द्वारा आय के साधन बहुत कम हैं तथा उनमें लोच का अभाव है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की आय बहुत कम है।

(९) करो की दरों में समानता का अभाव है—देश में करा की दरें सब जगह एक-सी नहीं पाई जाती हैं तथा कर-प्रणाली में अप्रसृत सामान्य का भी अभाव है। उदाहरण के लिये, बिक्री कर (Sales Tax) भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दरों से वसूल किया जाता है। कई राज्यों में वृषि आय-कर से मुक्त है।

(१०) केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय करों की आय का विभाजन दोष पूर्ण है—सबसे अधिक आय वाले कर के माधन केन्द्रीय सरकार को दिये गये हैं, राज्य सरकारों को कम और स्थानीय सरकारों को बहुत ही कम आय के माधन प्राप्त है।

सुधार के लिये सुझाव (Suggestions for Reform)—(१) हमारे कर-प्रणाली का पुनर्निर्माण एवं पुनर्बुद्धि आवश्यक है। कर-भार के प्रभावा का पूर्ण रूप से परोक्ष होना चाहिये। (२) प्रत्यक्ष करों का अधिक घबलम्बन सेना चाहिये। (३) भूमि-लगान, जल-शुल्क (Water Charge) जीवनार्थ आवश्यक-वस्तुओं (Necessaries of Life) यदि पर कर पड़ा कर और ऊँची आय पर कर की दरें बड़ा वर भारतीय कर-प्रणाली को प्रगतिशील (Progressive) होने के दोष में बचाया जा सकता है। (४) देश के सब राज्यों में केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार एक-सो (Uniform) कर-दरें होनी चाहिये। (५) सर्वजनिक व्ययों में भी घोर परिवर्तन आवश्यक है। सुरक्षा (Defence) तथा प्रशासन (Administration) सम्बन्धी व्ययों में भारी कमी की जाय और सामाजिक सेवाओं व राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में अधिक व्यय किया जाय। (६) करों का भार योग्यता तथा बलिदान के आधार पर वितरित करना चाहिये। वर्तमान कर-प्रणाली को अधिक नित्यव्ययी, लोचसूत्र तथा न्यायपूर्ण बनाना चाहिये।

अनुपातिक प्रगतिशील और प्रगतिशील कर-प्रणालियाँ (Proportional, Progressive & Regressive Tax System)—अनुपातिक कर-प्रणाली के अन्तर्गत कर आय के अनुपात में निर्धारित होता है, अर्थात् अनुपातिक कर वह है जिसमें आय या चाहे जो भी मापक हो वही दर व प्रतिशत लिया जाता है। उदाहरणार्थ २,००० रु० वार्षिक आय वाले व्यक्ति पर ५% के हिसाब से १०० रुपये कर लगाया जाता है, तो २०,००० रुपये की आय पर वह १,००० रु० होगा।

प्रगतिशील कर-प्रणाली—इस प्रणाली के अन्तर्गत कर की दर आय के साथ-साथ बढ़ती है। प्रगतिशील कर का सिद्धान्त यह है कि जितनी अधिक आय हो उतना ही अधिक कर होता है और उसकी दरें भी आय की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हैं। एक निर्धन व्यक्ति के लिये एक रुपये का मूल्य एक धनिक की तुलना में बड़ी अधिक है, उदाहरणार्थ, यदि २,००० रु० वार्षिक आय पर ५% तो १०० रु० और २०,००० रु० पर १०% में २,००० रु० कर हो, अर्थात् अनुपात में अधिक हो, तो उसे प्रगतिशील कर कहा जायेगा। अतः प्रगतिशील कर-प्रणाली के अन्तर्गत जो सभी स्वीकार करते हैं। आधुनिक राजस्व शास्त्रियों ने अनुसार प्रगतिशील कर-प्रणाली द्वारा ही समानता या योग्यता के सिद्धान्त को स्थायी कर दिया है। प्रो० मार्शल ने निम्नलिखित दृष्टि में इसकी पुष्टि की है और बोल्य है प्रगतिशील कर-प्रणाली को पूर्ण रोजगार नीति का अतिप्रिय भाग माना है। निस्सन्देह प्रगतिशील कर-प्रणाली को विभिन्न वर्षों की आय को समानता की ओर ले जाने का उत्तम साधन बनाया जा सकता है।

प्रगतिशील कर-प्रणाली—जब कर आय के अनुपात में कम अनुपात पर लगाया जाता है, तो उन प्रगतिशील कर कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब कर का भार धनवानों की क्षमता निर्धनों पर अधिक पड़ता है, तो वह प्रगतिशील कर कहलाता है। यह प्रगतिशील कर का विस्तृत उद्देश्य है। उदाहरणार्थ, यदि २,००० रु० वार्षिक आय

पर १% से १०० रु० कर है और २०,००० रु० आय पर ३% से ६०० रु० कर लिया जाय, तो उसे प्रतिगामी कर कहेंगे। कोई भी सम्पत्ति एवं विवेकशील सरकार ऐसा कर नहीं लगाती जिसमें आय के बढ़ने के साथ कर घटना जाता हो। यह अनुचित होगा। परन्तु वस्तुधा पर लगने वाला ऐसे बहाने-से कर है जिनका भार मुख्यतः निर्धनों पर ही पड़ता है। भारतीय नमक-कर भी प्रतिगामी कर माना जाता था, क्योंकि उसका भार धनवानों की प्रशिक्षा निर्धनों पर ही अधिक था। वास्तव में इस कर का धनवानों को तनिक भी अनुभव नहीं होता।

ग्रन्थासार्थ प्रश्न

इन्टर प्रार्थ परीक्षाएँ

- १—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर मक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये।
- २—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का अन्तर स्पष्ट कीजिये और प्रत्येक के लाभ तथा हानियाँ बताइये। (रा० बो० १९६०, ५७)
- ३—कर विभे कहते हैं ? शुल्क (Fees) और मूल्य (Price) से इनका अन्तर स्पष्ट कीजिये। अच्छे कर के गुणों का वर्णन करिये। (रा० बो० १९५३)
- ४—एक अच्छी कर प्रणाली को क्या विशेषताएँ हैं ? भारतीय कर-प्रणाली को व्याख्या करिये। (रा० बो० १९४९)
- ५—कर क्या है ? प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में अन्तर स्पष्ट करिये। उदाहरण भी दीजिये। (ग० बो० १९५२)
- ६—एकन सिमथ द्वारा प्रतिपादित कर सिद्धान्तों का उल्लेख करिये। (सागर १९४८, नागपुर १९५१, ग० बो० १९५६, ५१, ५३)
- ७—प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का प्राशय समझाइये और इनका सापेक्षिक लाभ हानियों का वर्णन करिये। भारत सरकार ने कौन कौन प्रत्यक्ष और परोक्ष कर लगा रखे हैं ? (ग० बो० १९४९ ४७ ४८ ४९)
- ८—कर मघात और कर भार का अन्तर स्पष्ट करिये। उत्तर में तीन भारतीय उदाहरण दीजिये।
- ९—कर की परिभाषा लिखिये और कर के मुख्य लक्षणा का वर्णन करिये।
- १०—प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का अन्तर बताइये। इसमें किसको प्राथमिकता दी जाना चाहिये और क्या ? भारतीय कर प्रणाली के विभिन्न करों की उपयुक्त दो श्रेणियाँ में वर्गीकृत कीजिये। (ग० भा० १९५७)
- ११—न्यायोपण के 'सामर्थ्य सिद्धान्त' (Canon of Ability) को समझाइये। भारत में इसका पालन किन करों में होता है ? (सागर १९५२, ग० बो० १९५३)
- १२—कर की परिभाषा लिखिये और कर के सिद्धान्तों का वर्णन करिये।

इन्टर एपोकल्चर परीक्षा

- १३—कर लगाने के सिद्धान्त क्या हैं ? विक्री कर लगाने कहीं वह उचित है ?

भारत में केन्द्रीय राजस्व (Central Finance in India)

भारतीय राजस्व की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Finance)—भारतीय राजस्व निम्नलिखित बातों में प्रभावित होता है —

१. **कृषि उद्योग की प्रधानता**—भारत में कृषि का निम्नलिखित प्रभाव है और अपने उपयोग को अधिकतर वस्तुएँ स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। उन्हें कच्चा तौहा, नमक, शिपलासाई मिट्टी के सेन आदि के लिये दूसरा पर निर्भर रहना पड़ता है। सन सरकार उसी वस्तु पर कर लगा सकती है जो बर्हा जाते हैं।

२. **कृषि निर्भरता**—भारतवर्ष को अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर है और कृषि स्वयं प्रनिश्चित वर्षों पर निर्भर होती है। सन भारतीय कृषि वर्षों का जमा बना हुआ है। इस प्रनिश्चितता के कारण केन्द्रिय तथा राज्य सरकारों के वज्र भी प्रनिश्चित रहते हैं। प्रभावित के कारण मालगुजारी की प्रायः छूट के कारण कम हो जाती है किसानों को तकावी अर्पण देना पड़ता है तथा प्रकाश पाठिका की सहायता का प्रबन्ध करना पड़ता है। वज्र वित्त मन्त्री को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रायः वज्र और उत्पादन करों की प्रायः घट जाती है। रेलों की प्रायः भी कम हो जाती है।

३. **निर्धनता**—भारतवर्ष एक निधन देश होने के कारण यहाँ के निवासियों की वज्र देने की शक्ति बहुत कम है जिससे सरकार को प्रायः प्रायः नहीं हानी है। इस प्रकार भारत सरकार को प्रायः वज्र साधन सीमित होने में यह स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रयत्न जनोपयोगी कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं कर सकती।

४. **केन्द्रीय सरकार पर अधिकतर निर्भरता**—भारतीय जनता प्राचीन काल से ही केन्द्रीय सरकार को मुक्तपणी रहती है। वह सभी कार्यों के लिये प्रायः केन्द्रीय सरकार से ही करती है। सन भारत में केन्द्रीय राजस्व अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस कारण भारतवर्ष में स्वतन्त्र राजस्व का समुचित विकास नहीं हुआ है।

५. **भारतीय वज्र पर मेना व्यय का अधिकतर प्रभाव**—वज्र सरकार की प्रायः वज्र काफ़ी बड़ा भाग सन पर खर्च किया जाता है जिससे कारण राज्य निर्माण सम्बन्धी कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

केन्द्र और राज्यों का राजस्व सम्बन्ध—२६ नवम्बर १९४६ को स्वतन्त्र भारत का नया संविधान स्वीकृत हुआ और २६ जनवरी १९५० में वह भारतीय गणराज्य में लागू हुआ। नये संविधान में प्रस्तावित गई वित्त-व्यवस्था संविधानसभा सन १९३५ में विधान मंत्री की हुई व्यवस्था पर ही आधारित है। भारतवर्ष एक संघीय राज्य है।

केन्द्र के प्रतिरिक्त अ व स द श्रेणियों के कई राज्य कुछ बातों में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य कुछ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हैं। इस सम्बन्ध का आधार केन्द्र और राज्य की सरकारों के मध्य विभाजन पर निर्भर है। जो कार्य केन्द्र को करने हैं उनके व्यय का उत्तरदायित्व भी केन्द्र पर ही आता है और उनकी आय भी उसी को मिलती है। इसी प्रकार जो कार्य राज्य के करने के हैं उनसे सम्बन्धित व्यय तथा आय का उत्तरदायित्व राज्यों पर है। इसके अनिश्चित, भारतीय संविधान में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि केन्द्र और राज्य दोनों का आय के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। विभिन्न परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा राज्य को आर्थिक सहायता देने का भी विधान किया गया है। राज्यों की राजस्व व्यवस्था पर केन्द्र को आवश्यक नियन्त्रण रखने का भी अधिकार प्राप्त है।

भारतीय राजस्व के प्रकार—भारतीय राजस्व मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) केन्द्रीय राजस्व, (२) राज्यों का राजस्व, और (३) स्थानीय राजस्व।

(१) केन्द्रीय राजस्व (Central Finance)—केन्द्रीय सरकार के आय व्यय को केन्द्रीय राजस्व कहते हैं। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के आय के साधनों और व्यय की मदों का अध्ययन किया जाता है।

(२) राज्यों का राजस्व—इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों का आय के साधनों और उनके व्यय के मदों का अध्ययन किया जाता है।

(३) स्थानीय राजस्व (Local Finance)—इसके अन्तर्गत स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिन्ना परिषद् तथा ग्राम पंचायतों के आय-व्ययों का अध्ययन किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के आय के मुख्य साधन (Main Sources of Revenue of the Central Government)—नये संविधान के अनुसार भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं—

१. आयात-निर्यात कर (Customs & Duties)—यह एक परोक्ष कर (Indirect Tax) है जो देश के बाहर जाने वाली तथा देश के भीतर आने वाली वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। इन्हें प्रमुख निर्यात कर (Export Duties) और आयात कर (Import Duties) भी कहते हैं।

आयात-निर्यात कर का मुख्य उद्देश्य सरकार के राजस्व की पूर्ति करना है। परन्तु आयात-कर देश के उद्योग-धन्धा को संरक्षण (Protection) देने के लिए भी लगाये जाते हैं। सन् १९१४ से पूर्व हमारे यहां आयात करों का मुख्य उद्देश्य राजस्व ही था, परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् देश में भारतीय उद्योग धन्धा के संरक्षण के लिए प्रबल आन्दोलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप सरकार का बड़े वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करना पड़ा। सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख मण्डल (Tariff Board) समय समय पर इस सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करता रहता है।

आयात-निर्यात कर दो प्रकार से लगाये जाते हैं—मूलानुसार और परिमाणानुसार। (१) मूलानुसार कर (Ad Valorem) मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। (२) परिमाणानुसार कर (Specific Duty) सत्या, वाक

या विस्तार के अनुसार लगाया जाता है। भारतवर्ष में अधिकांश आयात-निर्यात कर मूल्यानुसार ही लगाया जाता है।

आयात-निर्यात कर सघीय सरकार की आय का मुख्य साधन है। इसमें कुल आय का लगभग ४०% प्राप्ति होता है। द्वितीय महायुद्ध में कुल पूर्ण अवधि सन् १९३८-३९ और सन् १९३९-४० में आयात-निर्यात कर से आय लगभग ४०.५१ और ४३.९४ करोड़ रुपये की थी। महायुद्ध काल में तथा उसके उपरान्त इन करों की दरों में पर्याप्त वृद्धि न हो गई थी और इनके नई वस्तुओं पर यह कर लगा दिये गये हैं जिनमें इस कर द्वारा भारत सरकार की आय बढ़ गई है। यह वृद्धि निम्नांकित सारणी से स्पष्ट हो जाती है :—

वर्ष	आय (करोड़ रु०)	वर्ष	आय (करोड़ रु०)
१९४६-४७	८६.२	१९४५-४६	१६५.००
१९४८-४९	१२६.२	१९४८-४९	१३६.००
१९४०-४१	१५७.२	१९४९-५०	१६०.००
१९४३-४४	१७०.०	१९५०-५१	१६०.००

गुण (Merits)—(१) आयात-निर्यात कर सघीय सरकार की आय के मुख्य साधन है। (२) ये सुविधाजनक होते हैं। (३) इनमें लोच होती है। (४) ये सत्यापन भी हैं। (५) राजनैतिक भावना को जख्म करने के लिए ये कर विषयों से भी वञ्चित किये जा सकते हैं। (६) यह कर सरलता से नहीं टाले जा सकते।

दोष (Demerits)—(१) आयात-निर्यात करों का भार निर्यात पर अधिक पड़ता है। (२) ये कर प्रतिस्पर्धित होते हैं जिससे उनके द्वारा होने वाली आय का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। (३) ये कर निर्यातपूर्वक नहीं होते हैं क्योंकि सरकार और अन्तिम कर-दाता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं जिनमें वस्तु का मूल्य बढ़ की मात्रा में अधिक बढ़ जाता है। ये कर दानाओं में नायरिक भाज्या जापान करने में अधिक मकर नहीं होते हैं क्योंकि कर दाताओं को यह ज्ञान नहीं होता है कि वे सार्वगो गोप में कर के रूप में कुछ दे रहे हैं।

केन्द्रीय उत्पादन कर (Central Excise Duties)—ये वे वस्तुओं की जाने वाली वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, उसे उत्पादन कर कहते हैं। उत्पादन-कर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों ही लगाता है। राज्य सरकारें तो केवल देशी शर्करा, जौ, गीला आदि जैसी मशीनी वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात पर यह कर लगाने हैं और शेष मसल वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार कर लगाने हैं। इस समय के हमारे देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा शर्करा, टिन्नामार्क, मोटर, मिट्टा, मिट्टी का तेल, पीतल, टाउन-शायर, एम्पाक, वनस्पति घी, बहवा, चाय, कोयला, साबुन, सुपाही, मुली वस्त्र कागज आदि पर उत्पादन-कर लगाया जाता है। उत्पादन-कर केभी केन्द्रीय सरकार की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहाँ सन् १९३७-३८ में उत्पादन कर में लगभग ६ करोड़ रुपये की आय थी, वहाँ सन् १९४०-४१ में १०८.२२ करोड़ रुपये प्राप्ति दिये गये और सन् १९५०-५१ में २६१.४१ करोड़ रुप की

आया हुआ है। निम्न तालिका द्वारा उत्पादन कर से होने वाली आय तुलनात्मक दृष्टि से देखी जा सकती है —

वर्ष	आय (करोड़ रुपये में)	वर्ष	आय (करोड़ रुपये में)
१९३६-४०	६०१३	१९४६-४७	१४४४४
१९४६-४७	४३००	१९४७-४८	३०११४
१९४०-४१	७१४०	१९४८-४९	२४८८२
१९४४-४५	१४०००	१९४९-५०	३६१४१

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन-कर लगाने की समस्या— जिस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय है उस पर उत्पादन-कर केन्द्रीय सरकार लगाये तथा जिस वस्तु का बाजार प्रादेशिक है उस पर उत्पादन कर प्रादेशिक या राज्य सरकार लगाये तब तो यह ठीक है कि यह कर लोगों सरकारों द्वारा लगाया जाता चाहिये परन्तु अब राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व दिनों दिन बढ़ रहा है, उन्हें अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसलिये यदि सब प्रकार के उत्पादन-कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया जाय, तो बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त, कारखानों से उत्पन्न बहुत सी समस्याओं का हल राज्य-सरकारों को ही करना पड़ता है जिसके लिये राज्यसरकारों को बहुत-सा खर्चा व्यय करना पड़ता है। अस्तु, इन कारखानों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर जो उत्पादन कर लगाया जाय उसकी आय भी राज्य सरकारों को ही मिलनी चाहिये। एक बात और भी है कि नजीकी वस्तुओं पर भाजकल प्रतिवन्ध लगाया जा रहा है जिससे इनका उपयोग तथा उत्पादन घीरे-घीरे कम हो जायगा। फलतः उत्पादन कर भी कम हो जायगा जिससे राज्य सरकारों को पाग पड़ने लगेगा। अतः इसकी पूर्वा करने के लिये यह कर राज्यसरकारों को सौंप दिया जाय।

स्वदेशी उद्योगों में मरकाज से भारी भावगत कर की आवश्यकता पड़ी जिसके फलस्वरूप भावगत गिरे और सरकार की आय कम होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिये उत्पादन-कर लगाये गये जैसे तम्बाकू, सिगरेट, स्त्री तथा वस्त्र, शक्कर, दिवालाई, टायर, चाय, कोयला, मोटर स्प्रिट, वनस्पति तेल, इस्पात की वस्तुएँ, सोलून, सुपारी, कागज आदि। बरदोषखु जाँच प्रायोगिक के मतानुसार मिट्टी के तेल, चीनी, दिवालाई, चाय तथा कपड़े पर तो करों की दर बढ़ाई जाये तथा साथ-साथ सिलाई की मशीन, तेल, लकी घन्टा, विस्फुट, विद्युत के बत्तन पर मोती दरां से उत्पादन कर लगाना उचित है।

उत्पादन-कर के मुरा—यह कर परोक्ष कर (Indirect Tax) है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) यह कर सुविधाजनक है, क्योंकि इससे वस्तुओं के साथ मिले रहने से कर-शक्ता को इसका ज्ञान भी नहीं हुआ। (२) नागरिक आदमी को जाग्रत करने के लिये यह निर्धना से भी वस्तुन किआ जा सकता है। (३) यह सोचदार भी होता है,

क्याकि यह जीवनावर्ष आवश्यक वस्तुओं पर लगाये जाते हैं । (४) इसे सरलता से टाला नहीं जा सकता ।

दोष—(१) विनाश वस्तुओं के अनिश्चित यह जीवनावर्ष आवश्यक वस्तुओं पर भी लगाया जाता है, इसलिये इसका भार अधिकतम निधनों पर पड़ता है । (२) यह वित्तव्ययतापूर्ण नहीं होता है, क्योंकि सरकार और अन्तिम करदाता में बीच में कई मध्यस्थ आ जाते हैं और वे वस्तु के मूल्य को कर की भांति से अभिन बढ़ा देते हैं । (३) यह कर अनिश्चित भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा होने वाली आय का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । (४) यह औद्योगिक विश्वास में अवरोधक सिद्ध होता है ।

सन् १९५२ के वित्त आयोग (Finance Commission) ने हाल ही में यह प्रस्तावित किया है कि लगभग दियाराबाई और बनारस उपत्यिका के संघीय उत्पादन कर की शुद्ध आय का ४०% भाग राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट देना चाहिये ।

आय कर (Income Tax)—भारत सरकार की आय का मुख्य साधन आय कर है । यह कर भारतवर्ष में सबसे प्रथम सन् १८६० ई० में सन् १८५७ के गदर द्वारा हुई आर्थिक हानि को पूरा करने के लिये लगाया गया था, परन्तु सन् १८६५ में यह स्थगित कर दिया गया इसके स्थान में सन् १८८६ में घाटा और व्यापार पर कर लगाया गया जो उछे वर्ष में पुनः आय कर में परिवर्तित कर दिया गया । इस प्रकार आय कर एक स्थायी आय का साधन सन् १८८६ से ही प्रारम्भ हुआ । कोष की आवश्यकतानुसार समय-समय पर आय कर की दरों में परिवर्तन होता रहा है । सन् १९१६ में प्रथम बार प्रगतिशीलता के सिद्धांत (Principle of Progression) का समावेश किया गया था । सन् १९२२ में एक विस्तृत आय कर विधान पार किया गया और उसमें समय-समय पर परिवर्तन किये गये । सन् १९३६ में स्लाब प्रणाली (Slab System) को अपनाया गया ।

आजकल यह कर सन् १९२२ के आय कर विधान के अन्तर्गत लगाया जाता है । आय कर लागू करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के ऊपर है, परन्तु खर्च बाँटने के पक्षों को कुछ आय रहती है उसका ५५% भाग राज्य सरकारों में निम्न प्रकार वितरित कर दिया जाता है —

राज्य	आय कर	मृत्यु कर
आन्ध्र	२*४४	३ ४६
बिहार	६*६४	१० १७
बम्बई	१५ ६७	१२*१७
मध्य प्रदेश	६ ७२	७ ४६
मद्रास	८*४०	७ ५६
मैसूर	५*१४	६ ५२
उड़ीसा	३ ७३	४ ४६
पश्चिमी बंगाल	१० ०८	७*२६
प्रा.प्र.प्रदेश	८*१२	६ ३८
केरल	३ ६४	३ ८४

राजस्थान	४०३	४७१
उत्तर प्रदेश	१६३६	१५६४
जम्मू काश्मीर	११३	१७५
	<u>१००००</u>	<u>१००००</u>

घायकर उन्हीं व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी वार्षिक आय १००० रु० से अधिक हो। संयुक्त हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family) पर घायकर सभी लग सकती है जब उसकी आय ६००० रु० से अधिक हो। वर्तमान घायकर की दरें निम्नलिखित हैं—

कुल आय के	३००० रु० पर	• • •	कुछ नहीं
आय के प्रगले	२००० रु० पर	• • •	३ प्रतिशत
आय के प्रगले	२१०० रु० पर	• • •	६ "
आय के प्रगले	२२०० रु० पर	• • •	६ "
आय के प्रगले	२६०० रु० पर	• • •	११ "
आय के प्रगले	३५०० रु० पर	• • •	१४ "
आय के प्रगले	४००० रु० पर	• • •	१८ "

अब अर्जित आय (Earned Income) नहीं होती है उसके स्थान पर बच्चों का लाभ (Childrens Benefit) मिलता है। एक बच्चे पर ३०० रु० और दो पर ६०० रु० और यदि अधिक भी हों तो ६०० रु० ही कुल लाभ में और धुमार हो जायेंगे। उदाहरणार्थ, यदि व्यक्ति के ५ बच्चे हों तो उसकी पहले ३६०० रु० की आय पर कुछ भी घाय कर नहीं लगेगा और बाद की आयदरों पर ऊपर दी हुई प्रणाली के अनुसार कर लगेगा। इसी प्रकार जीवन बीमा विधियों के तहत भी राशि पर भी कर की छूट (Rebate) दी जाती है, परन्तु ऐसी कुल राशि आय के चौथे भाग से अधिक नहीं हो। बीमा विधियों पर अधिकतम ६,००० रु० तक छूट मिल सकती है। त्रिज व्यक्तियों की आय २०,००० रु० से अधिक होती है उनको घायकर के अलावा अतिरिक्त-कर (Super-Tax) भी देना पड़ता है जो सम्पूर्ण कन्दोय सरकार द्वारा रख लिया जाता है। मुद्रास्वाम में घाय कर के अतिरिक्त अधिक लाभ कर (Excess Profit Tax) लागू किया गया था, परन्तु अब यह कर स्थगित कर दिया है।

वर्ष	आय (करोड़ रु० में)	वर्ष	आय (करोड़ रु० में)
१९४६-४७	८७.५	१९४८-४९	१६२.५०
१९४७-४८	६५.५४	१९४९-५०	१५२.५०
१९४८-४९	१५१.७४	१९५०-५१	१३५.००

घायकर के मुख्य—(१) घायकर सत्य अर्जित प्रत्यक्ष-कर (Direct Tax) है। (२) यह करलाभ की सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है। (३) इसका भार व्यक्ति व्यक्तियों पर पड़ता है। (४) यह व्यापकपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष भार पड़ता है उसका ठोक ठोक निरर्थक किया जा सकता है। (५) यह

तोबदार है, क्योंकि ग्राम के बढने-बढने के साथ-साथ यह भी घटया-बढाया जा सकता है। (६) यह कर निश्चित है। (७) यह कर मितव्ययतापूर्ण भी है, क्योंकि बर-सप्रह का व्यय कम पड़ता है। (८) इससे नागरिक भावना जाग्रत होती है।

दोष—(१) कुछ भय तक यह कर अनुविधानजनक होता है, क्योंकि कर-दाता को हिसाब-किताब रखने और फार्म भरने आदि में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। (२) यह ईमानदारी पर लगाया गया कर है। करदाता भूटा हिसाब-किताब रख कर इससे बच सकता है। (३) यह गृहस्थों के सदस्यों की संध्या पर कोई ध्यान नहीं देता। इससे अधिक व्यक्ति बाने परिवार पर इसका भार अधिक पड़ता है। (४) यह उपाजित और अनुपाजित वृद्धि में पर्याप्त अन्तर नहीं करता। (५) इपि-धाय पर केन्द्रीय आय कर नहीं लगता। इपि-धाय के कर मुक्त रहने का कोई न्यायपूर्ण कारण नहीं है।

निगम या कम्पनी कर (Corporation Tax)—यह कर होता है जो सीमित दायित्व वाली समस्त प्रजा की कम्पनियों पर इसलिये लगाया जाता है कि इन कम्पनियों को कानून में विशेष सुविधाएँ मिली हुई होती हैं जिनके कारण वे अधिक पूर्णो एकजिन्त कर सकती हैं। सब कम्पनियाँ को समान सुविधाएँ होने से समान कर देना होता है। इस कारण यह अनुपातिक-कर (Proportional Tax) है। भारत में सब कम्पनियों को यह कर देना होता है और कोई व्युत्पन्न सीधा कर देने की नहीं है। कम्पनियों के कुल मुद्र लाभ पर यह कर लगता है। कम्पनियों पर लगाने वाला एक प्रकार से अतिरिक्त लाभ (Super-Tax) ही कॉर्पोरेशन कर है। अतिरिक्त कर की भाँति कॉर्पोरेशन कर भी राज्यों में वितरित नहीं किया जाता है बल्कि सम्पूर्ण राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा ही रख ली जाती है। इस समय इससे केन्द्रीय सरकार को लगभग ₹३५ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। कॉर्पोरेशन-कर द्वारा केन्द्रीय सरकार की विगत व्ययों को धाय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय (करोड़ ₹० में)	वर्ष	आय (करोड़ ₹० में)
१९४१-४२	३९.७३	१९४८-४९ ...	४६.००
१९४१-४४ ..	३८.४०	१९४९-५० ..	७८.००
१९४६-४७ ...	४१.१८	१९५०-५१ .	११४.००

अफीम कर (Opium Duty)—अफीम के उत्पादन तथा वितरण दोनों ही पर नास्त सरकार का एकाधिकार है। पोश्त को लाइसेंस (प्रनुजा पर) लेकर ही बोया जा सकता है और उसका लाइसेन्स लेने वाले को अपना सम्पूर्ण उत्पादन सरकार के हाथ बेचना पड़ता है। इसको सरकारी कारखानों में बनाया जाता है। सरकार को इसके लाभ पर एकाधिकार में धाय होती है। पहले भारतवर्ष में करोड़ों रुपये की अफीम चीन को जाती थी और इसमें बड़ी आय होती थी। अब चीनो लोगों ने अफीम खाना बन्द कर दिया है केवल औपधियों के लिये थोड़ी अफीम विदेशों को भेजी जाती है। अतः इस स्रोत से आय बहुत कम होती है। सन् १९४३-४४ में ₹६६ करोड़ और सन् १९४७-४८ में ₹२८ करोड़ रुपये की आय हुई। सन् १९५०-५१ में इस मद में ₹५६ करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है।

सम्पदा शुल्क (Estate Duty)—वह कर है जो किसी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति (चल और अचल) के मूल्य पर कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि होने पर लगाया जाता है। इसे उत्तराधिकार (Inheritance) भी कहते हैं। मृत्यु-कर भारतीय संसद द्वारा सन् १९५३ में स्वीकृत किया गया तथा १५ अप्रैल १९५३ से लागू किया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना है। मृत्यु कर मनुष्य की समस्त चल और अचल सम्पत्ति पर निम्न प्रकार लगाया गया है :-

प्रथम १०,००० रु० पर कुछ नहीं	
१०,००० रु० से १ लाख रु० ४%
१ लाख रु० से १२ लाख रु० ७½%
१२ लाख रु० से २ लाख रु० १०%
२ लाख रु० से ३ लाख रु० १२½%
३ लाख रु० से ५ लाख रु० १५%
५ लाख रु० से १० लाख रु० २०%
१० लाख रु० से २० लाख रु० २५%
२० लाख रु० से ३० लाख रु० ३०%
३० लाख रु० से ५० लाख रु० ३५%
५० लाख रु० से ऊपर... ४०%

वर्ष	मात्र
	(लाख रु०)
१९५५-५६	१५६
१९५६-५७	२५०
१९५७-५८	२८५
१९५८-५९	३००

धन कर (Wealth Tax)—वह कर है जो किसी मनुष्य की सम्पूर्ण सम्पत्ति (चल या अचल) पर कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि होने पर लगाया जाता है। सम्पत्ति कर भारतीय संसद द्वारा सन् १९५७ में स्वीकृत किया गया तथा १ अप्रैल १९५७ से लागू किया गया। सम्पत्ति-कर मनुष्य की समस्त चल और अचल सम्पत्तियों पर निम्न प्रकार लगाया गया है :-

प्रथम २ लाख रु०	कुछ नहीं
२ लाख से १० लाख तक	...	½ प्रतिशत
१० लाख से २० लाख तक	१ प्रतिशत
२० लाख से अधिक पर	१½ प्रतिशत

सन् १९५७-५८ में इस कर से १२ करोड़ रु० की आय हुई और सन् १९६०-६१ में ७० करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

उपहार-कर (Gift Tax)—वह कर है जो किसी मनुष्य पर, यदि वह १०,००० रु० से अधिक किसी व्यक्ति को दान के रूप में देता है, तो सरकार उस पर निश्चित की गई प्रणाली के अनुसार टैक्स लगाने है। दान-कर भारतीय संसद द्वारा सन् १९५८ में स्वीकृत किया गया तथा १ अप्रैल १९५८ से लागू किया गया। सन् १९५८-५९ में इस कर से ३ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

व्यय कर (Expenditure Tax)—यदि कोई व्यक्ति अपनी आय में से १०,००० रु० प्रतिवर्ष से अधिक खच करता है तो सरकार इस सीमा में अधिक राशि खर्च करने पर निश्चित बराबरी टैक्स लगाती है। खच कर भी १ अप्रैल १९५८ से शुरू हो गया है। इस कर में मन्व १९६०-६१ में ६० लाख रु० का अनुमान लगाया गया है।

नमक-कर (Salt Tax)—यह एक बहुत पुराना कर है जो भारतवर्ष में अंग्रेजों के पहले से ही चला आ रहा है। इस कर से भारतवर्षी वड असुक्त थे। इसलिये स्वर्गीय महात्मा गांधी ने सन् १९३१ में नमक कर तोड़ने का आन्दोलन चलाया। इस कारण जब भारतीय नेताओं ने भारत की आगड़ोर संभाली तो १ अप्रैल १९४७ में इस कर को हटा दिया और अब नमक बनाने के लिए न किसी लाइसेंस की आवश्यकता है और न कर ही देना आवश्यक है।

नमक कर के पक्ष की तर्कें—(१) नमक कर में केन्द्रीय सरकार का प्रति वर्ष लगभग ६ करोड़ रु० की आय हो जाती थी। (२) यह एक करीब कर है और करदाता इसे अनुभव नहीं करते। (३) इसका दर भार बहुत ही कम है क्योंकि यह प्रति मनुष्य प्रति मास १ पैसा या तो ३ आने प्रति वर्ष पड़ता है जो कुछ भी भार नहीं है। (४) प्रत्येक नागरिक को कुछ न-कुछ कर सरकार को देना ही चाहिये। इन दृष्टि से भारत जैसे निधन देश में निम्ना में भी कर बमूल करने के लिए नमक कर ही सर्वोत्तम साधन है। (५) यह एक पुराना कर है। पुराना कर एक अच्छा कर समझा जाता है, क्योंकि लोग इसके आदो हो जाते हैं और वह उन्हें असह्यता नहीं है।

नमक कर के विपक्ष की तर्कें—(१) नमक का प्रयोग स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिये आवश्यक होने से इस पर कर लगाना रैडिकल दृष्टि में अ-आधुनिक है। (२) यह प्रतिगामी कर (Regressive Tax) है, क्योंकि इसका भार धनवानों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पड़ता है। (३) यह व्यावहारिक नहीं है। निधन नमक का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिये उन्हें यह कर अधिक मात्रा में देना पड़ता है। (४) इस कर के प्रति जन आचार्य का विरोध रहता है।

निष्कर्ष—नमक कर का देश के स्वतन्त्रता संग्राम में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता का नमक कर विरोधी आन्दोलन भारतवर्ष की स्वाधीनता में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है। अब नमक कर को पुनः नया देना महात्मा गांधीजी की आत्मा को कष्ट पहुँचाना होगा।

बिना कर के आय के साधन (Sources of Non tax Revenue)

सरकारी व्यवसाय (State Enterprises)—भारत सरकार में आधिकारिक विभागों में रेल, डाक व तार, जल मुद्रा और टेलीग्राफ मुख्य हैं।

रेलें (Railways)—सन् १९०० तक भारतीय रेलें घाटे में चलती रहीं थी। इसके पश्चात् रेलों ने लाभ कमाला प्रारम्भ किया और वे केन्द्रीय सरकार की आय का मुख्य साधन बन गईं। सन् १९३१ तक रेलों ने कुल ४२ करोड़ रुपये सरकार को दिये। १५ अगस्त सन् १९४७ से पश्चात् ७ मास तक रेलों का किसी प्रकार का कोई लाभ न हुआ किन्तु २७५ करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो रेलवे के गुरुवित्त कोष में से

पूरा किया गया। सन् १९५६-६० में ५७५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार को रेल विभाग में अयादान प्राप्त हुआ। सन् १९६०-६१ में २६४ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

डाक व तार (Post & Telegraph)—यह आय का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन नहीं है। ये विभाग मुख्यतया जन-कल्याण के लिये ही अताये जाते हैं। सन् १९५३-५४ तथा सन् १९५७-५८ में इन विभागों से होने वाली आय क्रमशः २४० और १२३ करोड़ रुपये थी। सन् १९६०-६१ में ४७ लाख रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

चल मुद्रा और टक्काल (Currency & Mint)—मुद्रा और टक्काल भी सरकार की आय का एक प्रमुख साधन है। भारत में सांकेतिक सिक्कों का ही चलन है जिससे सरकार को लाभ होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से अब उसकी कुल आय भारत सरकार को ही मिलती है। राष्ट्रीयकरण ने पूर्व भी इसमें अक्षयधारीयों में एक निश्चित दर से लाभ विभाजित किया जाता था और उससे अधिक लाभ भारत सरकार को ही मिलता था। सन् १९३८-३९ में केन्द्रीय सरकार को २० लाख रुपये रिजर्व बैंक से लाभ के रूप में मिले। सन् १९४८-४९ में यह बढ़ कर ६८ करोड़ रुपये हो गये। सन् १९५३-५४ और सन् १९५४-५५ में इन मदों की आय क्रमशः १५७४ और २०७१ करोड़ रुपये थी। सन् १९५८-५९ में ३६६२ करोड़ रुपये की आय हुई और सन् १९६०-६१ में ५०२२ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

ऋण व्यवस्था (Debt Services)—केन्द्रीय सरकार राज्या एवं औद्योगिक संस्थाओं की ऋण भी देती है। ऋण पर प्राप्त व्याज वृद्धि में ऋण-व्यवस्था के मद में दिखाया जाता है। सन् १९५८-५९ में व्याज में ८३६ करोड़ रुपये की आय हुई और १९६०-६१ में १५११ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

अन्य साधन (Other Sources)—नगर-निर्माण और विविध सार्वजनिक विकास कार्य (Civil Works & Miscellaneous Public Improvements)—इससे सन् १९५३-५४ में २२९ करोड़ रुपये और सन् १९५७-५८ में २७८ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। सन् १९५८-५९ में २७८ करोड़ रुपये की आय अनुमानित की गई है। विविध (Miscellaneous) में सन् १९५८-५९ में २६२१ करोड़ रुपये प्राप्त हुए और सन् १९६०-६१ में ३६७३ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

केन्द्रीय सरकार के व्यय

(Expenditure of the Central Government)

रक्षा व्यय (Defence Expenditure)—भारत सरकार के कुल व्यय का एक बड़ा भाग रक्षा पर व्यय होता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रक्षा-व्यय ५५ करोड़ के लगभग था। युद्ध काल में यह बहुत अधिक बढ़ गया। गुटोन्नतकाल में भी यह काफी अधिक रहा है। निम्न तालिका में रक्षा-व्यय तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है :—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
१९४४-४५	३९७.१०		
१९४७-४८	१८९.२१	१९५८-५९	२६६.८७
१९५०-५१	१६४.१३	१९५९-६०	२४३.७०
१९५६-५७	१९२.१५	१९६०-६१	२७०.२६ (बजट अनुमान)

प्रस्तुत तालिका में यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार वर्तमान में लगभग २०० करोड़ रुपये व्यय ५०% के समग्र प्रविषयों पर व्यय करती है। इस वृद्धि के कई कारण हैं—(१) पुरानी रियासतों का रक्षा-व्यय भी केन्द्रीय सरकार के पास आ गया है। (२) वायुसेना के भ्रमण के कारण भी व्यय बहुत हो रहा है। (३) नैतिक शिक्षा के प्रसार से भी व्यय बढ़ रहा है। (४) समुद्री एवं वायुयान तथा अन्य सैनिक सामान के अर्थ के कारण भी इस मद पर व्यय बढ़ रहा है। (५) भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध ठीक नहीं होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध की आशंका बनने रहने के कारण भी रक्षा व्यय में वृद्धि होना पाया जाता है। धन, निकट भविष्य में देश का रक्षा-व्यय कम होने की आशा नहीं की जा सकती।

राजस्व के प्रत्यक्ष व्यय (Direct Demands on Revenue)—हर वसूल करने के लिये सरकार को कर्मचारियों के वेतन आदि में व्यय करना पड़ता है। सन् १९३८-३९ में यह व्यय ४.२४ करोड़ रुपये था। सन् १९५३-५४ में २९.८३ करोड़ और सन् १९५७-५८ में ६२.१७ करोड़ रुपये इस मद पर खर्च किये गये। सन् १९५८-५९ में बजट-अनुमान ६४.४५ करोड़ रुपये का है।

साधारण-व्यय (Debt Services)—केन्द्रीय सरकार ने जो ऋण ले रखा है उसका व्याज उसे चुकाना पड़ता है और उसके भुगतान के लिये कुछ रुपया अलग कोष में जिसको (Sinking fund कहते हैं) रखना पड़ता है। सन् १९३८-३९ में यह व्यय १४.१२ करोड़ रुपये था। सन् १९५३-५४ में ४०.८२ करोड़ और सन् १९६०-६१ में १०७.३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है।

नगर प्रशासन (Civil Administration)—नगर प्रशासन व्यय में सामान्य शासन, विदेशों से सम्बन्ध, आप, पुलिस, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के सभी व्यय सम्मिलित होते हैं। युद्ध एवं युद्धोपरान्त काल में कर्मचारियों की संख्या एवं उनके वेतन में वृद्धि होने के कारण इस व्यय में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के परचार इस व्यय में और अधिक वृद्धि होने के मुख्य कारण थे हैं कि विदेशों में अनेक दूतावास (Embassies) स्थापित किये गये तथा भारत में संसद के सदस्यों, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की संख्या बढ़ गई।

व्यय के इस मद में गैर शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर बहुत कम खर्च किया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शासन-संचालन पर होने वाले व्यय को घटाकर राष्ट्र-निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय किया जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने सन् १९४७ में बचत-समिति (Economy Committee) नियुक्त

की, जिनमें अपनी रिपोर्ट में व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु, उक्त समिति की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। इस मद पर सन् १९५३-५४ में ६४.१६ करोड़ रुपये और सन् १९५८-५९ में १९९.७२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में २६७-७६ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान लगाया गया है।

चल मुद्रा और टक्कास (Currency and Mint)—इस मद में मुद्रा चलन व टक्कास आदि का व्यय तथा विनियम-दर निरूपित करने में जो हानि होती है, सम्मिलित है। सन् १९५३-५४ में २.६० करोड़ और सन् १९५८-५९ में १.५ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में १०.२७ करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

नगर निर्माण और विविध सार्वजनिक विचार-कार्य (Civil Works and Miscellaneous Public Improvements)—जो रस्ति-सिमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, राजकीय कार्यालय, सरकारी इमारतें, प्रकाश-गृह व मठों आदि के बनवाने में खर्च की जाती है, वह इस मद के अन्तर्गत आती है। इन्हें राष्ट्र-निर्माण-व्यय (Nation Building Expenditure) भी कहते हैं। सन् १९५३-५४ में १३.८५ करोड़ और सन् १९६५-६६ में १८.३२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में २०.३२ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

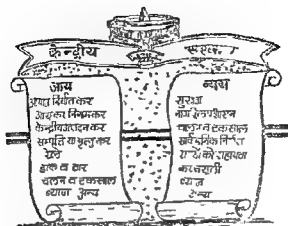
केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच अंशदान और समायोजन (Contribution and Adjustments between Central and State Governments)—केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनेक कार्यों जैसे शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ्य आदि के हेतु अनुदान देती है। राज्यों की अनुदानों की केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित विशेष तथा स्वीकृत कार्यों के लिये व्यय करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सन् १९५३-५४ में २५.९१ करोड़ रुपये और सन् १९६५-६६ में ४६.९५ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में बजट अनुमान के अनुसार ५१.८१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

असाधारण मदें (Extraordinary Items)—इन मदों में सन् १९५३-५४ में ११.७८ करोड़ रुपये और सन् १९५८-५९ में १५.२१ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में ३३.७५ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

केन्द्रीय सरकार का बजट

(Budget of the Central Government)

केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले गये धाया-यम विवरण को केन्द्रीय सरकार का बजट कहते हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार की धाया तथा व्यय की सभी मदों का व्योम होता है। द्वितीय महायुद्ध के समय में बजट में घाटे की कोई सम्भावना नहीं थी, किन्तु मुद्रोपशान्त युद्ध के पूर्व की शान्ति बजट में घुस घाटा होने लगा जो १९४९-५० तक चलेता रहा। सन् १९४९-५० में बजट में ४८ लाख रुपये की कचन बरपायी गई, किन्तु वास्तव में ३.७४ करोड़ रुपये का घाटा रहा। १९५०-५१ और १९५१-५२ में घाटा नहीं हुआ। सन् १९५३-५४ में ८.५ करोड़ की कचन हुई, परन्तु सन् १९५६-



५७ में कोई वकत नहीं हुई। अनुमानित बजट के अनुसार मत् १९६०-६१ में ६०'३७ करोड़ रुपये का माटा है।

भारत सरकार का राजस्व तथा व्यय (केन्द्रीय बजट)

राजस्व	(लाख रुपयों में)		
	बजट १९५६-६०	संग्रहित १९५६-६०	बजट १९६०-६१
सीमा शुल्क	१३२,७७	१६०,००	१६०,००
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	३२४,३२	३५०,८२	३५८,६१
निगमकर	५८,७५	७८,००	१३५,००
निगम कर के अतिरिक्त आय			
पर कर	८७,६३	७२,६८	५२,६४
मृत सम्पत्ति शुल्क	१४	६	१०
सम्पत्ति कर	१३,००	१२,००	७,००
रेल करिया कर	११	(-) ५१	११
व्याप्य कर	१,००	८०	६०
खान कर	१,२०	८०	८०
अपीम	३,६२	४,२६	४,६६
व्याप्य	१०,७५	८,२७	१५,७१
भौतिक प्रदायन	३५,८०	४७,५४	५३,१६

मुद्रा और टकराना	५१,६०	५१,८७	५७,२२
प्रौद्योगिक निर्माण कार्य	३,००	३,१३	३,०४
राजस्व के अन्य व्यय	८१,६३	३१,००	३६,७३
टाक और तार—सामान्य			
राजस्व में बालबिक			
अनुदान	४,२०	४,१६	४७
रेलें—सामान्य राजस्व में			
वस्तुनिष्ठ अनुदान	१,६८	१,७१	१,६४
जोड़—राजस्व	७८०,१०	८३८,६६	८६६,४४)
			+ २१,४३)

केन्द्रीय वजट एक दृष्टि में (१९६०-६१)

आय—११६*६८ करोड़ रु०

व्यय—१००,३५ करोड़ रु०

घाटा—६० ३७ करोड़ रु०

(लाख रुपयों में)

व्यय	वजट १९५९-६०	समाविष्ट १९५९-६०	वजट १९६०-६१
राजस्व से प्राप्त व्यय	१०१,६५	१०३,१४	१०७,३३
सिलाई	१६	१४	१७
नकल-व्यय	१७,८८	११,१४	७४,१६
प्रौद्योगिक प्रशासन	२२२,७३	२३३,३५	२६७,७६
मुद्रा और टकराना	६,८३	६,८६	१०,२७
प्रौद्योगिक निर्माण और विविध			
सार्वजनिक सुधार कार्य	१६,१५	१८,६४	२०,३२
वैधानिक	६,८३	१०,००	१०,११
विविध—			
विशेषाधिकार वर व्यय	१६,६६	२५,१७	२०,२८
अन्य व्यय	७१,३०	७३,०२	१११,७०
राज्यों को अनुदान आदि	४६,०२	४८,६८	५१,८१
प्रशासनिक मद	३५,२६	२२,२१	३३,७५
रक्षा सेवाएँ (वस्तुनिष्ठ)	२४२,६८	२४३,७०	२७२,२६
जोड़—व्यय	८३८,१८	८५४,०५	८८०,३५

(-) १६,०८ (-) ११,३६ (-) ६०,३७

नये करो से २३*१३ करोड़ रु० की आय—दूसरी पञ्चवर्षीय योजना समाप्ति पर है जो ८ त सरे पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ हान का समय निरुद्ध आ गया। उधर उत्तर सोता पर चीन ने जो प्रवाधारण परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दृष्टिनिष्ठ यह स्वाभाविक है या कि वजट में घाटा हो और नये कर लगाये जायें। तथापि केवल २३*१३ करोड़ रु० के नये कर आयाये गये हैं जो

समाधान से अधिक नहीं है। अधिकार्य कर अग्रत्यक्ष कर हैं और वे उद्योग पर लगाये गये हैं। मोटो, टीन व अलुमिनियम की चादरें, गारियों के इन्जन, विजनी मोटरों पर नये कर से जनता को विशेष हानि नहीं होगी। सादकित के पुर्जों, जूतों और दिजनी के बत्तों तथा पत्थी पर भी कुछ कर लगे हैं, इनका प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। यद्यपि मध्यम वर्ग पहले से ही पीडित वर्ग है, परन्तु फिर भी यह बोझ असह्य नहीं है और न प्रतिदिन पढ़ने वाला बोझ है। इनको बोटों की घोषणा एक नई चीज है जो दुग्रा होते हुए भी जनता की जेब से पैसा खींचने और इस तरह मुद्रा संकोच में शायद एक भग्न एक सहायक हो सके।

इस बजट में जिता प्रकार आय की बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है, उसी प्रकार बड़े हुए व्यय को कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रायः प्रत्येक मद पर व्यय बहुत बढ़ गया है और इन कारणों से यदि पिछले वर्ष संशोधित बजट के अनुसार पाठा १५.३६ करोड़ था तो इस वर्ष घाटा ६०.३७ करोड़ अनुमानित किया गया है। वस्तुतः सरकार को चाहिये कि वह प्रत्येक सनातन में होने वाले प्रभाव-शान्ति व्ययों पर भी नीच पड़ता करे। सांस्कृतिक कार्यों पर होने वाला अधिकांश व्यय मासाली से स्थापित किया जा सकता है। विभिन्न मन्त्रालयों के प्रकाशनों में भी व्यय कम हो सकता है। यदि मजसत देज में मन्त्रियों से उद्घाटन समारोह और भाषणों के चित्र व ब्लॉक बंद हो जायें और कागज की किस्म साधारण कर दी जाय तो एक विपुल राशि बच सकती है।

केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी कुछ सुझाव—(१) हिन्दू-संयुक्त-परिवारों के लिये ६००० रुपये वार्षिक आय पर कर की छूट बहुत कम है। परिवार की प्रत्येक शाखा से व्यय-वृद्ध कर लिया जाता चाहिये। (२) आय-कर से बचने के लिये बहुत-सी आय छिपाकर योग सरकार को धोखा देते हैं। इसको बन्द करने से अग्रत्यक्ष करो में छूट हो सकती है। (३) अन्य देशों की भांति भारत में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, भिक्षुता आदि जन-हित कार्यों पर विशेष व्यय करना चाहिये। (४) जीवमार्थ आवश्यक वस्तुओं पर कर बहुत कम होना चाहिये। (५) वृद्धता मण्डल की सिकारिश के अनुसार नमक वर पुनः लपाने से सरकार को ६-१० करोड़ की आय सुगमता से हो सकती है, नमोकि छूट होगे पर भी नमक सस्ता नहीं हो सका। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पश्चात् नमक का कर-मुक्त रहना, कोई कारण नहीं रह गया है। (६) राज्य की उन्नति के लिये श्रितव्यमता अपेक्षित है। बिना किसी विशेष प्रयोजन के सरकारी कार्यालयों तथा सचिवालय से कार्यकारियों की कृति नहीं होने चाहिये।

योजना और भारतीय राजस्व—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४६०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से केन्द्रीय सरकार २,५६६ करोड़ रुपये खर्च करेगी और राज्य सरकारें २,२४१ करोड़ रुपये खर्च करनी।

द्वितीय-पंचवर्षीय योजना का खर्च निम्नलिखित साधनों द्वारा पूरा किया जाएगा : पुराने परों से ३५० करोड़ रुपये, नये परों से ४५० करोड़ रुपये, सार्वजनिक ऋण १,२०० करोड़ रुपये, बजट के अन्य साधनों से ४०० करोड़ रुपये, रेलवे अशदान से १५० करोड़ रुपये, प्रायोजित फण्ड से २५० करोड़ रुपये, विदेशी सहायता से ६०० करोड़ रुपये, घाटे के वर्ष प्रवचन से १,२०० करोड़ रुपये, योग ४५०० करोड़ रुपये—योग ४०० करोड़ रुपये अन्य देशों साधनों से प्राप्त किये जायेंगे।

१,२०० करोड़ रुपये के घाटे में से २०० करोड़ पौंड पावना से प्राप्त हो जायेंगे ; परन्तु फिर भी १००० करोड़ रुपये का मुद्रा प्रसार करना पड़ेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

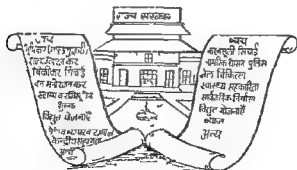
इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारत सरकार के आय-व्यय के मुख्य साधन क्या है ? पंचवर्षीय योजना के तहत आवश्यक धन कैसे प्राप्त किया जा रहा है ?
- २—भारत के केन्द्रीय सरकार के आय स्रोतों और व्यय की मदों का उल्लेख करें।
- ३—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये :—
 सम्पत्ति (wealth) तथा व्यय कर (रा० बो० १९५८)
 आयकर, (य० भा० १९५४), उत्पादन शुल्क, विक्री कर (घ० बो० १९५८)
 भारतीय पुनियन-सरकार की आय-व्यय की महत्वपूर्ण मद्दे। (म० बो० १९६०)
- ४—केन्द्रीय सरकार की मुख्य आय के साधनों तथा व्यय की मदों का विवेचन कीजिये। (रा० बो० १९५८, ५२, ५०)
- ५—भारतीय पुनियन सरकार की आय-व्यय की महत्वपूर्ण मद्दे कौन-कौन-सी हैं ? (म० बो० १९५७)
- ६—भारत सरकार की आय के स्रोत कौन-कौन से हैं ? प्रत्येक स्रोत का संक्षेप में विवेचन कीजिये। (म० बो० १९५९, पू०)
- ७—उत्पादन-कर के तात्पर्य रखने के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ दीजिये। (म० बो० १९५१, ४८)
- ८—क्या आय-नमक कर को दुबारा लागू करना चाहेंगे। यदि हाँ, तो क्यों ? (म० बो० १९५१)
- ९—केन्द्रीय सरकार की आय का वर्गीकरण 'टैक्स-आय' और 'नॉन-टैक्स आय' में कीजिये। (म० बो० १९५०)
- १०—भारत सरकार के मुख्य स्रोतों और व्यय-मदों का उल्लेख करें और उनके सापेक्षिक महत्व का वर्णन कीजिये। (रा० बो० १९५९, म० भा० १९५२)
- ११—भारत सरकार और भारतीय राज्य सरकारों की आय-व्यय की मदों का संक्षेप में वर्णन कीजिये। (दिल्ली हा० स० १९५५)

प्रारम्भिक—भारतीय संविधान २६ जनवरी, १९२० से सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया। इसके अन्तर्गत भारतीय प्रान्तों व राज्यों का वर्गीकरण मुख्यतः, क ख और ग भागों में कर दिया गया था। क भाग में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के प्रान्त सम्मिलित थे और ख भाग में देखी रियासतें व ग भाग में चीफ कमिश्नरी प्रान्त और कुछ नये प्रान्त सम्मिलित थे। राज्य पुनर्संगठन अधिनियम १९५६ के अनुसार भारतीय संघ में अब १४ राज्य तथा ६ क्षेत्र हैं। इन राज्य सरकारों की आय वृद्ध की दिग्दर्शित किया गया है।

राज्य सरकारों की आय की मुख्य स्रोत—

आय-कर तथा केन्द्र से सहायता—कुल आय कर का सर्वा काटने के पश्चात् ५५% भाग राज्यों को मिलता है। इस मिलने वाले भाग को प्रत्येक ५ वर्ष परचात वित्त-भाषा निर्धारित किया करेगा। छूट निर्धारित कर की सम्पूर्ण आय संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को जाती है। परन्तु इनके बदले में केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा को एक निश्चित राशि सहायता अनुदान में देता है। विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। समय समय पर केन्द्र राज्य-सरकारों को ऋण तो देता ही रहता है।



मालगुजारी (Land Revenue)—यह अत्यन्त प्राचीन कर है और राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकारों का केवल यही प्रत्यक्ष-

वर (Direct Tax) है और इससे उनको कुल आय का काफी बड़ा भाग मिलता है। पश्चिमी देशों जैसे राज्यों में स्थायी बन्दोबस्त के कारण मालगुजारी की आय में वृद्धि नहीं हो पाई है, परन्तु अस्थायी बन्दोबस्त वाले सभी राज्यों में इसकी आय में कुछ वृद्धि प्रत्यक्ष हुई है, यद्यपि वह बहुत कम है। वर की दृष्टि से मालगुजारी में कई दोष पाये जाते हैं—(१) इसमें नीच का प्रभाव है, क्योंकि इसकी आय में अधिक परिवर्तन नहीं होता। (२) यह धनविघाजनक है, क्योंकि इसकी वसूल करने में कठोरता से काम लिया जाता है और प्रमुख के लड़ हो जाने पर तो किसानों को सर्वस्व गिरवी रखकर मालगुजारी चुकानी पड़ती है। यद्यपि उन्हें छूट मजदूर दे दी जाती है परन्तु उससे कोई विशेष सहायता नहीं होती। (३) धनी एवं निर्धन सभी को ही समान दर पर मालगुजारी देनी पड़ती है जिससे निर्धन को भारवालों की घणघात अधिक बलिदान करना पड़ता है। (४) धार्मिक प्रगति के कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि होने से सरकार को विषय लाभ नहीं होता। (५) इसमें मितव्ययता का भी अभाव है, क्योंकि मासिक व्यय में मालगुजारी की जाच सगार घर में अधिक जटिल एवं लचीली होती है। (६) इसकी वसुली का आधार सब राज्यों में एकसा नहीं है, क्योंकि वही पर यह उत्पत्ति का आधार पर वसूल की जाती है ता वही पर उत्पत्ति के मूल्य के आधार पर। (७) जमींदारी उन्मूलन के कारण भूमिधरो का समान प्राप्ति हो जाने से मालगुजारी की आय में कमी होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में मालगुजारी राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत है। सन् १९६०-६१ में इस मद से २१-२८ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जमींदारी उन्मूलन के कारण जहाँ जहाँ भूमिधरो की संस्था में वृद्धि होती जायगी इन सब में प्राप्त-प्राप्त भी बढ़ती जायगी। उत्तर-प्रदेश के प्रतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास आदि राज्यों में भी यह आय का मुख्य साधन है। राजस्थान में इस मद से १९६०-६१ में ५१ करोड़ २० और बिहार में ११-८३ करोड़ २० होने का अनुमान है।

कृषि आय पर कर (Agricultural Income tax)—सार्वजनिक आय पर कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु कृषि में होने वाले आय पर राज्य-सरकारें कर लगाती हैं। सन् १९३७ में जब प्रान्तीय स्वायत्त शासन की देश में स्थापना हुई, कृषि आय पर राज्यों द्वारा लगाया जाने लगा। मध्य प्रदेश बिहार में यह कर सन् १९३५-३६ में लगाया। तत्पश्चात् प्रान्तीय, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर-प्रदेश में यह कर लगाया गया। क राज्यों में से इन पाँच राज्यों में ही कर लगाया जाता है। इन राज्यों में आधे और केवल में यह सन् १९४०-४१ तक था। जबकि अभी भूमि की आय पर यह कर लगता था जो लगान दती है। कृषि-आय पर का एक न्यूनतम भाग कर से मुक्त रहता है। क राज्यों की इस मद में कुल आय ३ करोड़ रुपये वार्षिक के लगभग है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में उस मद से आय और भी कम हो गई है।

राज्य-उत्पादन-कर (State Excise Duty)—सार्व सरकार की प्रति राज्य सरकार को भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर कर लगान का अधिकार है। शराब, मक्खन, गाँजा आदि नशीली वस्तुओं के उत्पादन पर राज्य सरकारें उत्पादन कर लगाती हैं। कुछ राज्यों में तो इस मद में सरकार की पर्याप्त आय प्राप्त होती है जैसे उत्तर-प्रदेश, बिहार आदि। मादक वस्तुओं का उपभोग सब प्रकार में प्रतिबन्धित होने के कारण लगभग प्रत्येक राज्य में यह विषय (Prohibition)

नीति अपनाई जा रही है जिससे इस मद से होने वाली आय घटती जा रही है। उत्पादन-कर से होने वाली राज्य सरकारों को कुछ विगत वर्षों की आय निम्न प्रकार है—

उत्तर प्रदेश में उत्पादन-कर में राज्य सरकार को अच्छी प्राय होती है। सन १९५८-५९ में ५.४६ करोड़ रुपये और सन १९६०-६१ में ५.६६ करोड़ रुपये और राजस्थान में ३.६ करोड़ रु० प्राप्त होने का आँगा है। मध्य निषेध नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नई जिला में मोनोपॉली कर दी है जिससे इसके द्वारा होने वाली आय में कमी हो गई है। इस नीति में मद्रास राज्य की १८ करोड़ रुपये और बम्बई राज्य की ६ करोड़ रुपये वार्षिक आय कम हो गई है।

मध्य निषेध नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण—मध्य निषेध-नीति आजकल विवादास्पद विषय बना हुआ है। जो लोग इसका विरोध है उनके अनुसार मध्य निषेध नीति द्वारा राज्य सरकारों को आय में एक बड़ा नुकसान हो रहा है और वेदना पैदा करने की नीति कायम में होना गुप्त नहीं है। इससे प्रतिरिक्त इस नीति को सफल बनाने के लिए अधिक गुप्त और अप्रत्याशित रूप से व्यवस्था को रखना पड़ रहा है जिससे आय कम हो रही है और व्यय बढ़ रहा है। साथ ही-नाथ राजा में राजा की राजा की आदत भी कम नहीं हुई है क्योंकि प्रतिस्थापन के कारण अब भी लोग लोग छिपे-छिपे जा रहे हैं।

इस नीति के सम्बन्ध में अनुसार उपर्युक्त नव अनुचित है मध्य निषेध नीति का कारोबार एक नैतिक प्रश्न होता है इसलिए जनता का अधिकारमय कल्याण मध्य निषेध-नीति को प्रभावित में ही सन्निहित है। मध्य निषेध से होने वाला आय की क्षति कम नये कर लगा कर पूरा की जा सकती है। इस नीति में निषेध रॉय प्रदान बर्माई का अपवाद करने से बच सकते हैं। अब मध्य निषेध-नीति की गंभीरता एवं बढोढ़ता के साथ साधन करना चाहिए।

बिक्री कर (Sales Tax)—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् राजा की आय का बिक्री कर एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। भारतवर्ष में बिक्री कर प्रांतीय कर है और वेग के भीतर वकी जाने वाली बहुत सी सेवाओं पर लगाया जाता है। भारत में यह प्रथम महत्वपूर्ण सन् १९३६ में मद्रास में लगाया गया था। जब से अब तक देश में राजा के इस कर को आय के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपना लिया है। यह कर राजा और बंगाल में सन् १९४१ में बम्बई में सन् १९४२ में बिहार में सन् १९४३ में उड़ीसा में सन् १९४४ में मध्य प्रदेश में सन् १९४७ में उत्तर प्रदेश में सन् १९८८ में और दिल्ली में सन् १९५१ में लागू किया गया। विभिन्न राज्यों में बिक्री कर के दर एक-दर भिन्न भिन्न हैं। इस कर से राज्य सरकारों की विगत वर्षों की आय निम्न प्रकार है।

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आय	वर्ष	आय
१९४६-४७	१२५	१९५२-५३	४५५
१९४८-४९	३३०	१९५४-५६	६५१
१९५०-५१	५१३		

विक्री कर का स्वरूप (Nature of Sales-Tax)—विक्री कर, जैसा कि नाम से विहित है, वस्तुओं एवं सेवाओं की विक्री पर लगाया जाता है। अतएव यह आयात निर्यात-कर की भाँति परीक्ष्य कर है। यह कर सरकार उस व्यक्ति से वसूल करती है जोकि वस्तु बेचता है न कि उस व्यक्ति से जो उस खरीदता है। अतएव यह व्यय कर नहीं है। परन्तु विक्रेता इस कर को वस्तुओं के दाम वटा कर देता है से वसूल कर लेते हैं। इसलिए यह बहने की विक्री-कर है पर वास्तव में यह व्यय-कर है। विक्री-कर अत्यन्त या परीक्ष्य कर होने के नाते इसका सभान (Impact) विक्रेता पर होता है और ग्राह (Incidence) उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

न्यूनतम छूट सीमा (Minimum Limit)—भारतवर्ष में यह न्यूनतम-छूट सीमा ₹ 1,000 रु० से ₹ 10,000 रु० वार्षिक विक्री के बीच में विभिन्न राज्यों में पाई जाती है तथा इस पर विविध-भार नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार कई वस्तुएँ जैसे खाद्यान्न, आटा, दाल, ईंधन, मसाला, मिट्टा का तल, पुष्पक खादी, साग आदि भी विक्री कर से मुक्त हैं।

विक्री कर के भेद (Type of Sales Tax)

(१) विक्री कर या टर्न ओवर कर (Sales-Tax) or Turnover Tax—जब कर केवल वस्तुओं की विक्री पर ही लगाया जाता है तो यह विक्री कर कहलाता है। परन्तु जब कर वस्तुओं और सेवाओं, दोनों की विक्री पर लगाया जाता है तब टर्न ओवर कर कहलाता है। भारतवर्ष में केवल विक्री कर ही पाया जाता है।

(२) आश्रित या पूर्ण विक्री-कर (Selected Commodities or Comprehensive Sales Tax)—जब विक्री पर चुनी हुई वस्तुओं जैसे मोटर रिफ्रिजरेटर, रेडियो, टेलीफोन आदि पर लगाया जाता है, तब आश्रित विक्री-कर कहलाता है। परन्तु जब कर सब वस्तुओं पर लगाया जाता है तब पूर्ण विक्री कर कहलाता है। मद्रास, उत्तर-प्रदेश तथा बंगाल राज्यों में पूर्ण विक्री कर लगाया जाता है।

(३) थोक या छुटकर कर (Wholesale or Retail Sales Tax)—जब विक्री कर उत्पादकों या थोक विक्रेताओं पर लगाया जाता है तो उसे थोक विक्री कर कहते हैं। परन्तु जब विक्री कर केवल छुटकर विक्रेताओं पर लगाया जाता है तो यह छुटकर विक्री कर कहलाता है।

(४) एक मुद्दी या बहु मुद्दी विक्री-कर (Single Point or Multiple Sales Tax)—जब विक्री-कर केवल एक ही बार या एक विक्री या छुटकर विक्री पर लगाया जाता है तब उसे एक मुद्दी विक्री-कर कहते हैं। परन्तु जब विक्री कर कई बार अथवा अनेक बार विक्री या उपभोग के बार लगाया जाता है तो उसे बहुमुद्दी विक्री-कर कहते हैं। दोनों प्रकार का विक्री कर हमारे राज्यों में पाया जाता है।

विक्री कर के गुण—(१) विक्री-कर राज्य-सम्बन्धी या आय का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका स्थान कोई अन्य कर नहीं ले सकता है। (२) विक्री-कर परीक्ष्य कर है, इसलिये करदाताओं का इसका भार भी अनुपातिक प्रकृति नहीं होता है। (३) इसका संग्रह करना भी सुगम है।

विक्री-कर के दोष—(१) यह प्रगतिशील (Progressive) नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता और प्रत्येक उपभोक्ता को यह कर समान दर से देना पड़ता

है। (२) यह कर परिवार को कर देने की योग्यता पर विचार नहीं करता है। जिसका परिवार बड़ा होता है उसकी कर देने की योग्यता कम रहती है, यदि उसकी आय उतनी हो रहती है। अतः जिसका परिवार बड़ा होता है उसनी हो खरीद भी अधिक होती है इसलिए उसे बिली कर भी अधिक देना पड़ता है। (३) बिली-कर के कारण बड़े-बड़े नाम्नाओं का एकीकरण हो जाता है जिसका अभिप्राय कर को टालना होता है। (४) कर की शायन सम्बन्धी गठिनाइयाँ अत्यधिक हैं और लोग इसमें चोरी बहुत करते हैं। (५) यह अनुविधानक है क्योंकि छोटे-छोटे दुकानदारों को थोड़ी-थोड़ी बिली का हिसाब रखना पड़ता है। (६) इसका भार निर्धन-उपभोक्ताओं पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है।

उत्तर-प्रदेश में बिली-कर—उत्तर-प्रदेश में बिली कर सन् १९४४ में चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश में १५,००० रु० वार्षिक आय में कम पर बिली कर नहीं लगता है। सन् १९६०-६१ में उत्तर-प्रदेश में बिली-कर में लगभग ७६० करोड़ रु० की आय और राजस्वान में ३४० करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

सिंचाई (Irrigation)—कुछ राज्यों में जहाँ उत्तम नहर प्रणाली है, सिंचाई राज्य की आय का एक अच्छा साधन है। किसानों को नहरों का पानी प्रयुक्त करने के लिए सरकार को कुछ कर देना पड़ता है। उत्तर-प्रदेश में सन् १९६०-६१ में लगभग १२८ करोड़ रुपये और राजस्वान में ७२५ लाख रु० इस मद से प्राप्त होने का अनुमान है।

वन (Forests)—वन राज्य-सरकारों की सम्पत्ति हैं। अतः वन की लकड़ी तथा अन्य वन-समृद्ध जैसे लाख, चपड़ी, गोद आदि बेचकर जो आय प्राप्त होती है वह राज्य-सरकार को ही मिलती है। उत्तर प्रदेश में वनों से सन् १९६०-६१ में ५६ करोड़ रुपये और राजस्वान में ८२ लाख रु० प्राप्त होने की आशा है। वनों का विकास करके राज्यों की आय बढ़ाई जा सकती है।

मनोरंजन कर (Entertainment Tax)—मनोरंजन कर सर्वप्रथम सन् १९२२ में बंगाल में लगाया गया था, तत्पश्चात् बरबई में सन् १९२३ में लगाया गया, प्रांतीय स्वायत्त सामन प्राप्त होने के पश्चात् यह कर अन्य प्रांतों में भी लगाया गया। प्रांतीय यह सम्पत्ति का भाग के राज्यों में लगा हुआ है। यह कर मनोरंजन-सुलभ के साथ ही व्यक्ति से वसूल कर लिया जाता है। यह कर वर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है और टिकट के मूल्य के हिसाब से लगाई जाती है। सन् १९५१-५२ में इस कर से व्यय की १५५ लाख, उत्तर-प्रदेश का ६८ लाख, मध्य-प्रदेश की ३२ लाख, उड़ीसा की ३ लाख रु० की आय हुई थी।

स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन (Stamp and Registration)—स्टाम्प को आय कई मदी से प्राप्त होती है। कई व्यापारिक लेन-देन में वास्तव के अनुसार टिकट लगाने पड़ते हैं। न्यायालय में दावा करने पर कोर्ट-फीस देनी पड़ती है जो स्टाम्प के रूप में दी जाती है। न्यायालय व कुछ अन्य सरकारी कार्यालयों में कुछ प्राथम-पत्रों पर भी टिकट लगाने पड़ते हैं। स्टाम्प जूडिशियल (Judicial) और नॉन-जुडिशियल दो प्रकार के होते हैं। नॉन-जुडिशियल स्टाम्पों में इकरारनाम व अन्य दस्तावेज लिखे जाते हैं। इन सबका उद्देश्य साथ कमाना नहीं होता है बल्कि उनके बदले सेवाएँ प्रस्तुत

करना होता है। सन् १९६०-६१ में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन से राज्य सरकारों को लगभग ३०६३ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

रजिस्ट्री (Registration)—भारतीय रजिस्ट्रेशन कानून ने अतहत कुछ प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य रूप में करानी पड़ती है अन्यथा न्यायालय में वे मान्य नहीं समझे जाते। इस कारण ऐसे दस्तावेजों द्वारा प्रत्यक्ष की रजिस्ट्री करानी पड़ती है जिनसे न्याय राज्य सरकारों को मिलती है। इन रजिस्ट्रियों की प्रतिनिधि देने के लिए भी फीस ली जाती है। सन् १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में ८४ लाख घोर राजस्वान में १२३ लाख रु० का अनुमान लगाया गया है।

अन्य प्रकार के कर—राज्य सरकारें मोटर-माफ़िया पर कर तथा मोटरों, मोटर माइक्रो, कारों और बोम्बों से जाने वाली कारों पर कर लगाती हैं। सन् १९६०-६१ में बिहार में इन कर से आय १३२ करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में ८६ करोड़ रु० और राजस्थान में ६० लाख रु० होने का अनुमान है।

प्रिजली टुन्क जुद्धा-कर, राजगार व पशु पर व्यापार-कर आदि कुछ अन्य राज्य-सरकारों की आय के साधन हैं।

राज्य मन्त्रालयों के व्यय की मुख्य मदें

राजस्व से प्रत्यक्ष व्यय (Direct Demand on Revenue)—यह वह व्यय है जो कर कसूली व दिए करना पड़ता है। समस्त अ राजस्व का इस मद पर व्यय लगभग २५ करोड़ रुपये है जो उस व्यय का ८% के लगभग आता है। उत्तर प्रदेश में इस मद पर सन् १९५१-५२ में ५४७ करोड़ घोर सन् १९५४-५५ में ८२ करोड़ रुपये घोर सन् १९५६-६० में १२ करोड़ रुपये व्यय किए गए। यह व्यय प्रथम है, अतः इसमें कमी करने का प्रयत्न होना चाहिए। राजस्थान में सन् १९५६-६० में इस मद पर ३५६ करोड़ रुपये व्यय किए गए।

सिंचाई (Irrigation)—जहाँ क निर्माण तथा सिंचाई व्यवस्था के संचालन तथा निरीक्षण पर राज्य सरकारों का व्यय करना पड़ता है। इस मन्त्रालय में लिय गए जंगल का आभ्यास दिया जाता है वह भी इसी व अन्तर्गत आता है। सन् १९६०-६१ में उत्तर-प्रदेश में ५५ करोड़ बिहार में ७८ लाख और मध्य प्रदेश में ७८५६ लाख रुपये और राजस्थान में ७८५३० लाख रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है।

सामान्य प्रशासन (General Administration)—इस मद का व्यय दो भागों में बाँटा जा सकता है। (क) दार्शनिक व मूल्य एवं साधारण शासन व्यय, पुलिस, जेल न्याय आदि का व्यय। (ख) दार्शनिक व्यय व अन्तर्गत आता है और राज्य-पाल मंत्रियों कायम-माध्यम, सरकारों के कार्यों आदि का व्यय साधारण शासन के अन्तर्गत आता है। (ख) राष्ट्र निर्माण कार्यों पर व्यय—इसके अन्तर्गत शिक्षा, विनिर्माण, कृषि, उद्योग, यन्त्रागत महत्कारना आदि के विकास के व्यय सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में सन् १९६०-६१ में इस मद पर ७२ और राजस्थान में २६ करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है।

ग्राम सेवाएँ (D.G. Services)—राज्य सरकारें अपनी विकास-योजनाओं आदि के लिए भारत सरकार से तथा जनता से ऋण लेती हैं जिनका व्याज चुकाना

पड़ता है। सन् १९५१-५२ में उत्तरप्रदेश में इसको राशि १ करोड़, बिहार में १५ लाख और मध्यप्रदेश में ८६ लाख रुपये थी। सन् १९६०-६१ में उत्तर-प्रदेश में यह राशि लगभग १२-३६ करोड़ रु० और राजस्थान में ४-३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश सरकार का वजेट

(१९६०-६१)

राजस्वगत प्राप्तिर्था	लाख रु०	राजस्वगत व्यय	लाख रु०
केंद्रीय उत्पादन शुल्क	१२४०*७०।	राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग	१२४१*८५
निगम कर-भिन्न भाग कर	६२७*५६	सिंचाई, नौकायन आदि	५६५*४७
सम्पदा शुल्क	३७*५३	ऋण सेवाएं	१५३६*१६
रेल किराया कर	२३७*५०	सामान्य प्रशासन	७२६*४२
लगान (घुड़)	२१२७*६६	न्याय प्रशासन	१८२*५६
राज्यीय उत्पादन शुल्क	५६६*०६	जेल	१५६*८१
टिकट	३८०*००	पुलिस	६८६*०१
घन	५६२*२१	वैज्ञानिक विभाग	१४*६१
पंजीयन	८३*६६	शिक्षा	१७२७*२८
मोटर गाड़ी कर	२५६*५३	विक्री कर	४६५*१६
विक्री कर	७६८*६०	माव जमिन स्वाध्याय	२२६*४१
अन्य कर तथा शुल्क	८०५*६६	कृषि तथा ग्राम विकास	८०६*८८
सिंचाई, नौकायन आदि (घुड़)	१६७*५५	पशुपालन	१६५*८५
ऋण सेवाएं	४४२*८४	सहकारिता	२०४*४६
अर्थनित्य प्रशासन	२२५१*६३	उद्योग	५८२*४७
अर्थनित्य कार्य आदि	२१६*७६	विविध विभाग	६४४*०१
विविध शुल्क	६६३*७३	अर्थनित्य कार्य आदि	५८०*२३
सामुदायिक योजनाएं आदि	४३६*२८	विद्युत योजनाएं	१३५*२५
प्रसाधारण	५७७*१६	विविध	१२६६*४०
		प्रसाधारण (सामुदायिक योजना आदि कार्य सहित)	११०६*६१
योग	१३०८६*६८	योग	१३३२३*२३

राज्यों के राजस्व के दोष (Defects of State Finance)—(१)

राज्यों के आय के साधन अपर्याप्त, लोचहोन एवं स्थिर है जो आवश्यकतानुसार घटते-बढ़ते नहीं जा सकते। (२) राज्य-कर प्रगतिशील (Progressive) है। राज्य-करों का भार मध्यवर्ग तथा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। विक्री कर भी अधिकतर निर्धनों को ही देना पड़ता है। (३) राज्य-कर-प्रणाली में समानता (Uniformity) का अभाव है। (४) राज्य-सरकारों की धर्म-नीति रुढ़िवादिवादीपूर्ण

भारत में राज्या का राजस्व]

२—उत्तर प्रदेश सरकार के आय और व्यय के मुख्य साधन क्या है ? सक्षिप्त व्याख्या कीजिये ।

३—उत्तर प्रदेश सरकार के आय व्यय की मुख्य मद क्या क्या है ? राज्य के बढ़ते हुए व्यय के लिए धन प्राप्ति के सम्बन्ध में क्या सुझाव है ?

४—मनोरंजन कर से गुप्त हाथ पर लिपिणी लिखिये ।

५—भारत की राज्य सरकार के आय और व्यय के मुख्य साधन क्या क्या हैं ? प्रत्येक पर संक्षिप्त नोट लिखिये ।
(स० बो० १९५१)

६—राजस्थान सरकार के आय के प्रमुख साधन क्या है ? प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।
(स० बो० १९६०)

७—भारत की राज्य सरकार के आय के मुख्य स्रोत और व्यय की मुख्य मदों का उल्लेख करिये और प्रत्येक पर संक्षिप्त नोट लिखिये ।

(स० बो० १९५१ ४८ ४७ ४२)

८—कट्टर तथा गन्ध्या में उत्पादन कर के लागू रहने के पक्ष तथा विपक्ष में युक्तिर्मा कीजिये ।
(स० बो० १९५१ ४८)

९—मध्य भारत सरकार के आय के मुख्य मदों पर लिपिणी लिखिये ।

(स० भा० १९५३)

१०—नावबर्जिन हिन की ने कौनसी मद है जिन पर राज्य की आय राज को जाती है ? ऐसे व्यय का क्या सामाजिक महत्व है ?
(पटना १९५२)

११—पंजाब सरकार के आय व्यय के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं ? (पंजाब १९५५)

१२—निम्नलिखित करा के विषय में बतलाइए कि कौन से भारत शासन और कौन से प्रादेशिक शासन के सम्बन्ध में हैं—(अ) आय कर (आ) सम्पत्ति-कर (इ) वृष्टि आय कर (ई) लगान (उ) सामा गुप्त और बिक्री कर । इनमें से कौन से प्रत्यक्ष कर और कौन से परागत कर हैं ?
(नागपुर १९५६)

१३—भारत सरकार और राज्य सरकारों के आय व्यय के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं ?
(दिल्ली हा० मे० १९५५ ५४)

भारत में स्थानीय राजस्व (Local Finance in India)

प्रारम्भिक—स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ भारतवर्ष में प्राचीन काल में ही चली आ रही हैं। ग्राम पूर्णतया स्वतन्त्र थे और उनका समस्त प्रबन्ध ग्राम पंचायतों द्वारा होता था। आधुनिक अर्थ में सब प्रथम स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का सृजनात् ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन काल में हुआ। सन् १८७७ ई० में मद्रास शहर के लिए एक म्यूनिसिपल बोर्ड तत्कालीन क्रमशः अन्य कई बड़े शहरों में मनोनीत सदस्याओं की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ स्थापित की गईं। सन् १८७१ ई० में प्रथम बार साईं मयो ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विषय निर्वाचन प्रणाली प्रारम्भ की। सन् १८८२ ई० तक रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कुछ नये अधिकार दिये। सन् १९१९ के भारतीय विधान के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का समस्त नियन्त्रण प्रांतीय सरकारों के हाथ में पहुँच गया। सन् १९३५ के विधान के अन्तर्गत प्रांताओं को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उससे परिणामस्वरूप स्थानीय-स्वायत्त शासन संस्थाओं का और भी अधिक प्रगल्भता मिली। स्वतन्त्र भारत के विधान ने ग्राम पंचायत स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकारों का दिया है। ये ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की भाँति गाँवों की सभी बातों का प्रबन्ध कर सकती हैं।

स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का वर्गीकरण (Classification of Local Self-government Bodies)—यह सब के लिए नगरपालिका (Municipality) ग्राम-क्षेत्रों के लिए जिला बोर्ड (District Board), और प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम पंचायत (Village Panchayat) है। कसबता, मद्रास, बम्बई दिल्ली और महमदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी (नगरपालिकाओं) के स्थान में कॉर्पोरेशन (Corporation)—निगम है। इनका प्रतिनिधित्व बन्दरगाहों का प्रबन्ध करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust—पत्तन प्रयान), नगरों की उन्नति के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (Improvement Trust—सुधार प्रयत्न) तथा छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए नोटिफाइड एरिया (Notified Area—अधिमूर्चित-क्षेत्र) नामक स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। इनमें सब प्रबन्ध समस्या के नाप, उत्तरदायित्व तथा आय के साधन एक दूसरे में भिन्न हैं।

नगरपालिकाएँ (Municipalities)—सन् १९४६-४७ में भारत में ३ निगम और ६२८ नगरपालिकाएँ थीं। इनकी कुल आय क्रमशः १२३५ लाख और १५१८ लाख रु० थी तथा इनके द्वारा लगायत करा का आर प्रति व्यक्ति क्रमशः १८ रु० ११ आ० १० पा० था। उत्तर प्रदेश में यह कर-आर प्रति व्यक्ति ६ रु०

१ आ० ४ पा० और उड़ीसा में २ ए० ६ आ० ६ पा० था। सन् १९५२-५३ में क राज्यों में ७७६, स राज्यों में ५०५ और म राज्यों में ३२ नगरपालिकाएँ थीं। सन् १९५६ के अन्त में १२ नियम, १४५३ नगरपालिकाएँ, ३८३ छोटी नगर समितियाँ और ८२ स्थितिपूर्वक क्षेत्र थे।

नगरपालिकाओं के कार्य—(Functions of Municipalities)—नगरपालिकाएँ दो प्रकार के कार्य करती हैं—(१) अनिवार्य और (२) वैकल्पिक। अनिवार्य कार्यों (Compulsory Functions) के अन्तर्गत सफाई, लोक-स्वास्थ्य, रोशनी, पानी, मजदूरी, शिक्षा—प्रारम्भिक एवं माध्यमिक—की व्यवस्था आती है। वैकल्पिक कार्यों (Optional Functions) के अन्तर्गत जैम-कूद के मैदान, स्मृतिस्थल, बाग बगीचे, पुष्पकान्ठ, मेन, जन्म मरणा का सेवा और प्रशस्तिपत्र आदि की व्यवस्था आती है।

नगरपालिकाओं की आय की आवश्यकता—नगरपालिकाओं को अपने निर्धारित कार्य सम्पन्न करने के हेतु धन की आवश्यकता होती है। यह धन विभिन्न प्रकार के कर लगाकर वसूल किया जाता है। प्रत्येक राज्य में नगरपालिका-विधान होता है जिसके द्वारा नगरपालिकाएँ संचालित होंगी हैं।

नगरपालिकाओं की आय के साधन (Sources of the Income of Municipalities)—साधारणतया नगरपालिकाओं के आय के साधन निम्न-लिखित हैं—

१. चुँगी (Octroi Duty)—यह नगरपालिकाओं की आय का मुख्य माधन है। जो वस्तुएँ बाहर से रेल, मजदूरी या नदी द्वारा नगर की सीमा के भीतर आती हैं उन पर यह कर लगाया जाता है। साधारणतया यह कर वस्तुओं के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। जो वस्तुएँ नगर से बाहर भेजी जाती हैं, उन पर यह कर नहीं लगाया जाता है, परन्तु यदि उनके आने पर चुँगी चुकाई गई है तो मागने पर उनकी वापसी (Refund) हो जाती है। सन् १९४६-४७ में उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं को इस मद से १७६ करोड़ रुपये की आय हुई थी जो कुल कर द्वारा आय का ६२.९% था। इसी प्रकार उनी वर्ष में मध्य-प्रदेश में नगरपालिकाओं को अपनी कुल आय का ६६.३% और पंजाब में ५४.६% प्राप्त हुआ था।

चुँगी कर के गुण—(१) यह पुनरावृत्ति कर है, इसलिये लाभ इसके आधी हो गये हैं। अतः, यह उनका भारस्वरूप प्रतीत नहीं होता है। (२) यह उत्पादन कर है। जहाँ जहाँ नगरी की उत्पत्ति होती है, इसकी आय भी बढ़ती जाती है। यह कर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में यथा समय दिया जाता है। इसलिये लोगों का विशेष कष्ट नहीं होता है। (४) यह निर्धनो से भी कर वसूल करने का अच्छा साधन है।

दोष—इसमें वसूल करने में व्यय अधिक होता है। (२) इसकी वसूली का कार्य अल्प-व्ययन भोगी कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है। इसलिये प्रायः इसकी वसूली में चोरी, धूसखोरी, कठोरतापूर्ण व्यवहार आदि अप्रत्याचार पाये जाते हैं। (३) यह कर व्यापार की उत्पत्ति में बाधक सिद्ध होता है। (४) जायदाद आवश्यक वस्तुओं पर यह कर लगने से निर्धनो पर इसका अधिक भार पड़ता है। (५) कर-भार (Incidence) अनिश्चित होता है तथा साधारणतया टाका जाता है। (६) इस कर की आय अनिश्चित होती है। (७) इस कर के वापसी की रीति-विधि बड़ी जटिल एवं अमुविधानिक होती है।

इस कर के दोषपूर्ण होने हुए भी नगरपालिकाएँ इसी कर को अपनाये हुए हैं, क्योंकि इनके स्थान की वृद्धि करण वाला कोई अन्य माध्यम नहीं है।

चुंगी के स्थानापन्न कर—मध्य-प्रदेश की नगरपालिका-कर समिति (१९०८ ई.) ने यह सिफारिश की थी कि चुंगी की प्रमुखिया को दूर करने के लिये सीमा कर और मार्ग शुल्क (राहदारी महसूल) लगाया जाय। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर भी और कुछ नगरपालिकाओं ने इसे अपना भी लिया।

सीमा कर (Terminal Tax)—यह कर नगरपालिका की सीमा के भीतर रेल द्वारा आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। अधिकतर यह रेलवे द्वारा महसूल या टिकट कर रूप में वसूल किया जाता है जो वास्तव में नगरपालिकाओं की मिल जाता है। इस वस्तुओं के निम्ने रेलवे को कुछ प्रतिशत (४ व० या ५ व०%) कमीशन मिलता है।

चुंगी और सीमा कर की तुलना—(१) चुंगी साल के मूल्य पर लगाई जाती है परन्तु सीमा कर साल के परिमाण पर लगाया जाता है जिससे उसके द्वारा अधिक की प्रमुखिया दूर हो जाती है। (२) सीमा कर का भार चुंगी की अपेक्षा कम होता है। (३) पुनः निर्धारण करने में सीमा कर में बाधनी नहीं मिलती है। (४) सीमा कर रेलों द्वारा ही अधिकतर वसूल होता है।

मार्ग शुल्क या राहदारी महसूल (Toll-Tax)—जब कर केवल रेल द्वारा लाई हुई वस्तुओं पर ही लगाया जाता है, तो व्यापारी साल भर एक और नदिया में लागे हैं। इन कारणों से साल के बाकी साल पर भी कर लगाया आवश्यक हो जाता है। जो कर सड़क और नदियों द्वारा लाये हुये साल पर लगाया जाता है, उसे मार्ग शुल्क या राहदारी महसूल (Terminal Toll) कहते हैं यह कर नगरपालिकाओं के अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है।

२. मकान, भूमि और सम्पत्ति-कर (Taxes on Houses, Land and Property) नगरपालिका के क्षेत्र में जितने घराने, दुकान आदि होते हैं उन सब पर तथा भूमि पर यह सम्पत्ति-कर लगायी है। इसमें अब अच्छी धारा प्राप्त हो जाता है। यह कर मकान या भूमि के वास्तविक मूल्य पर लगाया जाता है। वास्तविक मूल्य निर्धारण की धारा के अनुसार मान लिया जाता है और उस पर अधिकतम २२% की दर में यह कर वसूल किया जाता है। यह कर सम्पत्ति के स्वामियों से वसूल किया जाता है परन्तु कर-आधार अथवा किंगडम पर पड़ता है। सन् १९४६-४७ में उत्तर-प्रदेश में नगरपालिकाओं का अपनी कुल आय का कमसे कम १% और मध्य प्रदेश में ०% इन मद में प्राप्त हुआ था।

३. यात्री कर (Pilgrim-Tax)—जब विधानानुसार यह कर केवल केन्द्रीय सरकार ही लगा सकती है। परन्तु जो स्थानीय मन्त्रालय विधान के पूर्व यह कर लगाता था उसका एक नगण की शक्ति प्रदान कर दी गई है। यह कर रेलों से आने वाले तीर्थ-यात्रियों पर लगाया जाता है। यह रेल के टिकट में सम्मिलित कर दिया जाता है और स्थानीय प्रामाण्य-सम्बन्धों से रेलवे से वसूल कर ली है। उत्तर-प्रदेश में यह कर मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग, वाराणसी, आगरा आदि स्थानों में लगाया जाता है। राजभर में आने वाले यात्रियों पर भी यह कर लगाया जाता है।

४. राजस्व, पेशे व व्यापार कर (Taxes on Trades, Profession, Arts and Callings) यह बहुत कम स्थानों पर लगाया जाता है

और जहाँ लगाया भी जाता है वहाँ गाइमन्स फीस के रूप में वसूल किया जाता है। उत्तर-प्रदेश में घोड़ी-घाट के प्रयोग पर घोड़ियों में तृण पापिया शुल्क लिया जाता है।

५. व्यक्तियों पर कर या हैमियत कर (*Taxes on Persons or House-hold Tax*)—यह कर भाव पर नहीं लगाया जाता परन्तु कर दाताओं की सामाजिक स्थिति या कुटुम्ब के परिमाण पर लगाया जाता है और उनके स्वामियों से वसूल किया जाता है।

६. पशुओं और वाहनों पर कर (*Tax on Animals and Vehicles*)—नगरपालिकाएँ कुत्ता, घोड़ा, पशुप्रा बैमगाइडस याइडिंग, तांगी इक्की, रिक्शाओं, मोटर सारिया नावों आदि पर कर लगाती हैं जिसमें उन्हें कुछ भाग भी जाती है।

सफाई-कर (*Conservancy Tax*)—कई स्थानों में यह कर नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत सफाई सम्बन्धी गवाआ के उपलब्ध में गवान पानिकी से वसूल किया जाता है।

८. बाजार-कर (*Barar Tax*)—कुछ नगरपालिकाओं द्वारा बाजार पर लगाया जाता है। यह कर उन दूकानदारों से वसूल किया जाता है जो नगरपालिका द्वारा बनाये बाजारों में दुकानें खोलते हैं।

९. जल, बिजली आदि का शुल्क (*Prices for Water Electricity etc.*)—नगरपालिकाएँ जल, बिजली आदि की पूर्ति के बढन जा मूल्य वसूल करती हैं यह शुल्क फहलाता है। इस मद से भी उन्हें पर्याप्त भाव मिले हैं।

१०. विवाह कर (*Marriage Tax*)—यह कर केवल खर्चों में लगाया जाता है। प्रत्येक स्थानीय शासन संस्था को विवाह की रजिस्ट्री पर भी फीस लेनी चाहिये जिसमें दर १ रु० हो सकते हैं। इस विवाह की प्राणाधिक सूची भी संसार हो जायेगी।

११. उत्थति कर (*Betterment Tax*)—नगरपालिकाओं को पडन भूमि पर बाजार व नई वस्तियाँ बसाने चाहिए जिसमें उन भूमियों के मुख्य में वृद्धि हो और उनके स्वामियों से उत्थति कर वसूल किया जाय।

१२. आर्थिक दण्ड या जुर्माना (*Fines*)—नगरपालिकाएँ उनके नियमों को तोड़ने वालों से जुर्माना वसूल करती हैं। मटके हुए पशुओं (*Sticky Cattle*) को काँते होन में बन्द कर दिया जाता है और जुर्माना लेकर ही उनके स्वामियों को वापस किया जाता है।

१३. भूमि, भवन आदि का किराया (*Rent of Land, Buildings etc.*)—नगरपालिकाएँ कुछ भूमि, भवन व अन्य सम्पत्ति को स्वामिनी होती हैं। उनके किराये से इन्हें भाव प्राप्त होता है।

१४. व्यापारिक कार्यों से भाव (*Income from Municipal Enterprises*)—नगरपालिकाओं को इसके द्वारा किय जाने वाले व्यापारिक कार्यों से भी भाव होती है। उदाहरण के लिये, जल व बिजली की पूर्ति की व्यवस्था करने से उसमें होने वाले भाव, नगरपालिका द्वारा निमित्त बसाईस्थानों के किराये में होने वाली

ग्राम और नगरपालिका द्वारा जो गई यातायात की व्यवस्था से होने वाली ग्राम इस श्रेणी में आती है ।

१४ राज्य सरकार से आर्थिक सहायता (Grant in Aid from State Govt.)—रा तथा महमूना के परिचित नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से भी सहायता दो प्रकार की प्राप्त होती है —(अ) वार्षिक और (ख) मासिक । राज्य सरकार अपने अधीन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वार्षिक कुछ न कुछ सहायता शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सड़क आदि के लिये देती है । इस प्रकार की सहायता कभी कभी कुछ विशेष कार्यों के लिये अनुरोध ही दे दी जाती है जैसे वाटर वर्क्स, प्रसूताग्राह आदि के भवन निर्माण के लिए ।

१५ राज सरकार से ऋण (Loan from State Govt.)—वार्षिक सहायता के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ जाने पर राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बिना व्याज ऋण भी देती है ।

नगरपालिकाओं का व्यय

(Expenditure of the Municipalities)

नगरपालिका के व्यय को मुख्य भेद निम्नलिखित है —

अनिवार्य कार्यों पर व्यय

१. सार्वजनिक सुरक्षा—(क) प्राण म वचाव की व्यवस्था करना, (ख) प्रवाह की व्यवस्था करना (ग) हानि पहुँचाने वाले जानवरों से रक्षा का प्रबंध करना ।

२ जनसाधारण का स्वास्थ्य तथा चिकित्सा—(क) नली मोहल्ला तथा नालियाँ का सफाई सार्वजनिक टट्टियों बनवाना तथा उनकी सफाई और कुछ करवट की नगर स शहर कियवान पर व्यय करना (ख) गुड़ जल की व्यवस्था करना (ग) गंदे पानी के निकास का प्रबंध (घ) अस्फाल और टोप लगाने का व्यय (ङ) पशु चिकित्सा का प्रबंध करना तथा (च) वायु एवं पय पदार्थों में गिरावट को रोकने की व्यवस्था करना ।

३ सार्वजनिक शिक्षा—प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय करना ।

४ जनसाधारण की सुविधा—(क) मंडक भण्डाला और विधायन-गृह की व्यवस्था करना (ख) मंडका पर वृक्ष लगवाना औरहा पर फुलवाड़ी लगवाना,



दलहने तथा भूमि के लिए पाकों तथा व्यायामशालाओं का प्रबन्ध करना, (घ) पुस्तकालय तथा वाचनालय सुनवाना, म्यूजियम आदि स्थापित करना ।

५. विविध कार्यों पर व्यय—बाजार, मेले, प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था करना ।

जिला बोर्ड (District Boards)

सन् १९४६-४७ में भारत में १७६ जिला बोर्ड थे जिनकी आय १,५५५ लाख रुपये थी तथा इनके द्वारा कर-भार प्रति व्यक्ति पर ४ भा० १ पा० था । सन् १९५२-५३ में क राज्यों में १४६, नव राज्यों में ३३ और न राज्यों में ४ जिला बोर्ड थे । सन् १९५६ में ३०६ जिला बोर्ड थे ।

जिला बोर्डों के मुख्य कार्य (Chief Functions of District Boards)—जिला बोर्डों के मुख्य कार्य ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, ग्रामोद्योगों के लिए बिक्रीस्थानों खोलना, बेचक तथा हट्टे की रोकथाम के लिए टीके लगाने की व्यवस्था करना, मेला और प्रदर्शनियाँ का आयोजन करना, पशुधर्म की नश्व सुधारना तथा साइ-गृह स्थापित करना है । नदियों पर पुल बनवाना तथा नाव के यात्रियों को गार भवाना, घने-घटके पशुओं के लिए पशु-निरोधालय स्थापित करना, पुस्तकालय खोलना तथा वाचनालय स्थापित करना आदि कुछ अन्य कार्य हैं ।

जिला बोर्डों के आय के साधन

(Sources of the Income of District Boards)

१. स्थानीय भूमि कर (Land Tax)—यह जिला बोर्डों की आय का मुख्य साधन है । स्थानीय बन्दोबस्त वाले राज्यों में भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार और अस्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में वार्षिक आय पर यह कर लगाया जाता है । उत्तर-प्रदेश में सन् १९४८ से प्रत्येक जिला बोर्ड के लिए यह प्रतिवार्षिक है कि वह माल-पुजारी पर ३ आना प्रति रुपया की दर से स्थानीय भूमि-कर लगाये । इस कर की वसूली माजपुजारी के साथ साथ राज्यों के सरकारी वर्षेबारी करते हैं और फिर यह जिला बोर्डों को दे दी जाती है । सन् १९५२-५३ में उत्तर-प्रदेश के जिला बोर्डों को इस कर में ६२.१ लाख, बिहार में ८५.१ लाख, उड़ीसा में १.५ लाख और मध्य-प्रदेश में १७.६ लाख रुपये की आय थी ।

२. हैसियत या सम्पत्ति कर (Haltiyat or Property Tax)—यह कर मकान तथा अन्य सम्पत्ति के मूल्य पर तथा कार्यालय उद्योग-धन्यों से होने वाली आय पर लगाया जाता है । उत्तर-प्रदेश में ४६ में से २७ जिला बोर्डों को यह कर लगाने का अधिकार है । कर की दर कुल आय पर ४ पाई प्रति रुपया में अधिक नहीं हो सकती । इन २७ जिला बोर्डों को दस कर में आय १६ लाख रुपये है । यह कर प्रत्येक जिला बोर्ड द्वारा लगाया जाना चाहिए । यह व्यापार या उद्योग से होने वाली आय पर ही लगाया जाता है । कृषि-आय पर भी जो इतने सब तक मुक्त है, यह कर लगाना चाहिए ।

३. घाट, पुल, सड़क आदि पर कर—जिला बोर्डें घाट, पुल, सड़क, तात्का आदि के प्रयोग पर कर तथा कर अपनी आय करते हैं ।

४. किराया—जिला बोर्डों को अपना इमारतों तथा अन्य सम्पत्तियों से किराया भी प्राप्त होती है। इनके बगलों में ठहरने वालों से किराया भी लिया जाता है।

५. लाइसेंस शुल्क—शुल्क पेशों तथा व्यापार के लिए जिला बोर्ड लाइसेंस देते हैं, जिसके लिए लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। उदाहरणार्थ, कताइयो, पत्तपत्ति भी की दुकानों, घाटों की चरनी व अन्य कारखानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर यह शुल्क वसूल किया जाता है।

६. अधिक दण्ड या जुर्माना—जिला बोर्डों के नियम भंग करने पर वे संस्थाएँ जुर्माना वसूल करती हैं जिससे इन्हें फायदा होता है। उदाहरण के लिए, भट्कते हुए पशुओं को काँजी होना (Cattle Pond) में बन्द कर दिया जाता है और जुर्माना लेकर उन्हें स्वामियों को वापिस किया जाता है।

७. स्कूलों तथा अस्पतालों के लिए शुल्क—इस मद से भी जिला बोर्डों को कुछ फायदा होता है।

८. बाजार, बूकानों तथा मेलों व प्रदर्शनियों पर कर—इन सब पर भी शुल्क लगाया जाता है।

९. पशुओं के पानी पीने के स्थानों पर महसूल—यह कर लगा कर भी आय की जाती है।

१०. कृषि के मीजारों तथा चीजों विक्रय से आय प्राप्त की जाती है।

११. राज्य सरकार से आयिव सहायता—जिला बोर्डों की आय का एक सबसे बड़ा भाग राज्य सरकारों की आयिव सहायता होती है। इनका अपना आय का लगभग ५०% भाग सरकारी महामता से प्राप्त होता है। सन् १९४६-४७ में कुल ३१४ लाख की आय में से १५३ लाख रुपय सरकारी सहायता से प्राप्त हुए थे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए तो सरकार जिला बोर्डों को ८०% सहायता देती है।

जिला बोर्डों की व्यय की मदें

(Items of the Expenditure of District Boards)

जिला बोर्ड निम्नलिखित मदों पर व्यय करते हैं

१. शिक्षा—जिला बोर्डों की आय का सबसे बड़ा भाग शिक्षा पर व्यय होता है। इनका यह कार्य प्रारम्भिक शिक्षा तक ही सीमित रहता है।

२. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा—जिला बोर्डों का व्यय की दूसरी मद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा है। इसमें अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यय का प्रतिरिक्त चेखन व हेल्थ की रोग-प्रतिरोधक निग्र टोका लगाने की व्यवस्था करने का व्यय भी सम्मिलित होता है।

३. सड़कों, पुलों आदि के निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय करना।

४. पशुशास्त्र तथा पशु चिकित्सालय पर व्यय करना।

५. इमारतें, पशुओं की चरही आदि बनवाना।

६. पुस्तकालय खोलने तथा वाचनालय स्थापित करना।

७. मेले व प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना।

८. पशुओं का नस्ल सुधारने की व्यवस्था करना तथा सॉड-ग्रह स्थापित करना ।

९. कृषि और वायवानी पर व्यय करना ।

१०. भूमि की कृषि-योग्य (Reclamation of Soil) बनाने के लिए व्यवस्था करना ।

ग्राम-पंचायत (Village Panchayats)

ब्रिटिश-शासन-काल में ग्राम-पंचायतों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, इसलिये उनका विचार होने लगा । परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत के संविधान में ग्राम-पंचायतों को श्रेयसाह्वन मिला । अधिकतर राज्यों में ग्राम-पंचायतों के निर्माण के लिए विधान पास किये जा चुके हैं । उत्तर-प्रदेश इस काम में सबसे प्रगुप्त रहा है । उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत-एक्ट १९४६ में इन्हे विस्तृत अधिकार और कसप्य प्रदान किये हैं । उत्तर प्रदेश में इनके निरीक्षण तथा निपटण के लिए एक बृहत् संगठन है । ३१ मार्च १९५५ में १,६४,३२५ ग्राम-पंचायतें थी ।

ग्राम-पंचायतों के मुख्य कार्य—पानी तथा बहाने के लिये पानी की सफाई, दोहरी, जन-स्वास्थ्य-रक्षा, सड़न-निर्माण, प्राग्मिक शिक्षा, शिक्षिता, खेल-कूद के मैदान आदि की व्यवस्था करना, कुँए बनवाना तथा उनकी मरम्मत करना आदि कुछ इनके अनिवार्य कार्य हैं । पुस्तकालय, मेलों, शीप-गान्यों, अन्य मृत्यु का नक्का रखना, वृद्धारोपण आदि की व्यवस्था करना इनके कुछ वैकल्पिक कार्य हैं ।

ग्राम-पंचायतों को आय के साधन—भारत में ग्राम-पंचायतों के आय के साधन भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं ।

बम्बई राज्य में—ग्राम-पंचायतें मकान पर, बाटियों पर, मेलों पर, माल की बिक्री पर, गाँव में माल आने पर, विवाहों और शोशों पर, दूकानों तथा होटलों पर, पैल से चलने वाले इन्जिनो पर कर लगाती हैं । इनके अतिरिक्त, उन्हें मुल्दमों का 'भेदेबारा' करने की सील, गाँव के दूध-करबट की नीलाम, करों आदि के अतिरिक्त राज्य की सरकार से भी कुछ अधिक सहायता प्राप्त होती हैं ।

मद्रास राज्य में—ग्राम पंचायतें मकानों, दूकानों तथा बाटियों पर कर लगाने के अतिरिक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण, कृषि-भूमि, पशु, पेठ, बाजार आदि पर भी कर लगाती हैं ।

मध्य प्रदेश में—ग्राम पंचायतें मकान कर के अतिरिक्त मान के जेनामो, दवालों, आदतियों और तोलाथा से जुल्क लेती हैं तथा ग्रामवासियों में गाँव की सफाई, रोस्तों और पानी का प्रबन्ध करने के लिए भी सरचार्जें लगाती हैं ।

उत्तर-प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के आय के साधन

१. कृषि-भूमि पर कर—गाँव के कृषक कृषि-योग्य भूमि वा जितना लगान सरकार को देते हैं, उस पर एक आना प्रति रुपये के हिसाब से ग्राम-पंचायत भूमि पर कर वसूल करती हैं ।

२. व्यापार तथा घाँवों पर कर—ग्राम-पंचायतें गाँव के दुकानदारों, धार्मिकों, ध्वजधारियों पर कर लगाती हैं । परन्तु यह कर एक निश्चित राशि में अधिक नहीं हो सकता । जैसे जोलाओ व पत्तेदारों पर ३ ह० प्रति वर्ष, किराये पर

गाड़िया के चलाने वालों पर ३ रु० प्रति वर्ष का कर राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है, प्रावि ।

३. भक्षण कर—जो व्यक्ति भूमि-कर या व्यापारिक-कर या घाय-कर नहीं देने दे, उस पर घाम-पचायत भक्षान-कर लगा सकती है । परन्तु भक्षान-कर भक्षान के उचित वार्षिक मूल्य के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता । नियम व्याप्त इस कर में मुक्त किए जा सकते हैं । सरकारी इमारतों पर यह कर नहीं लगता ।

४. ग्राम्य माधन—उपयुक्त करों के अतिरिक्त, झगड़ों या निवृत्तादा करने की शौन तथा दुस्मान, सर्वजनिक स्थान का विरहता और ऐसे स्थानों पर लड़ी घाम या बुद्धा के निहत से ग्राम्य, गांव का भूभ-करवट, भूडियों की विपरी तथा भूत पशुओं की विपरी प्रावि से भी घाय प्राप्त होगी है ।

ग्राम पचायतो के व्यय की मदें—ग्राम-पचायतें प्रायः निम्नांकित मदों पर व्यय करती हैं —

(१) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, (२) गांव की सफाई एवं राजनी का प्रबन्ध, (३) दूध एवं सुपाना तथा उनकी सरम्मत करवाना, (४) रास्ता की ठीक करवाना, (५) गांव की जाँच तथा बाँरो में रखा करना, (६) गांव के धार्मिक स्थानों की रक्षा परमा, (७) जन्म-मरण और विवाहों का नक्का रखना तथा (८) ऐसी-बाड़ी तथा उद्योग पन्थों की उन्नति में सहायता प्रदान करना ।

स्थान में स्वायत्त शासन सम्स्याओं की दोषपूर्ण आर्थिक अवस्था—भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन सम्स्याओं की आर्थिक दशा बड़ी गौर्तनीय है, क्योंकि इनके प्राय के माधन बहुत कम और सीमित हैं । इनकी कम घाय व कारण निम्नलिखित हैं —

(१) भागतवर्ष में घाय के सभी मुख्य माधन वन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों को प्राप्त हैं । केवल छोटे मोट नाम मात्र के माधन स्थानीय स्वायत्त सम्स्याओं को सौं गये हैं ।

(२) नागरिका की नियमता तथा उनमें कर देने की प्रत्यत कम शक्ति, धनिका की कर दन में आवाकाशी तथा नगरपिताम्रा में माहस के प्रभाव व कारण स्थानीय स्वायत्त शासन सम्स्याओं को उठना कर प्राप्त बहा होना जितना होना चाहिए ।

(३) निवाचित सदस्य अधिक कर लगा कर जनता में वदनाम नहीं होना चाहते ।

(४) दोषपूर्ण निरीक्षण तथा अवकाश घामन व्यवस्था के फलस्वरूप घनेक शक्ति कर दन में पच जाता है जबकि कुछ नामा का अपनी शक्ति में आ धविन कर देना पड़ता है ।

(५) भारत के जोर पिठटे हैं । वे इन स्वायत्त सम्स्याओं का महस नहीं जानते । इसलिए जब भी वे सम्स्याएं घाय में बृद्ध करने के हेतु नये कर नमानों हैं तो वे उनका निरोध करते हैं ।

(६) स्थानीय स्वायत्त सम्स्याएं अपनी शक्ति से बाहर जाकर चिता तथा स्वास्थ्य की यकी बड़ी सम्स्याओं को अपने हाथ में ल लेती हैं और इसल उनको आर्थिक कठिनाइयाँ बढ जाती हैं ।

(७) स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का प्रबन्ध अधिकतर संघीय, प्रशिक्षित तथा स्थायी लोगों के हाथ में है जिन्होंने नवन, मोलमाल तथा मण्डप के दृष्टान्त इन संस्थाओं में विद्यमान होने को मिलते हैं ।

स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के सुझाव (Suggestions for Improvements)—भारत सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को दशा ज्ञान के और उनकी उन्नति के सुझावों की सिफारिश करने के लिये सन् १९४६ में श्री पी० के० बट्ट, मिनिस्टर प्रोवाइन्ट जनरल की अध्यक्षता में एक स्थानीय राजस्व समिति को नियुक्ति की । समिति ने सन् १९४९ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित सिफारिशों की —

१. स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को वर्तमान पर लगान की नीति में सुधार की जाय ।

२. राज्य सरकारें कुछ करा की भाग को सम्पूर्ण रूप में उन्नत दें । उदाहरणार्थ, माल तथा मकिया पर नया सीमा कर, मकान कर, चुँबी कर, रिजर्वी कर वित्तियन कर, बीज व छोटा गाड़ी कर, पशु व नाल कर, गवारा व व्यापारिक पर लगा कर लगा मनोरंजन कर राज्य सरकारों से हटा कर संस्थाओं स्वायत्त संस्थाओं को मिलना चाहिये ।

३. जिस स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार नहीं है वहें यह कर सीधे लगाने का अधिकार दे देना चाहिये ।

४. सम्पत्ति कर को विशेष रूप में अनिवार्य कर दिया जाय और पुँगी-नग के लिये एक आदर्श सूची नियत की जाये ।

५. अभी तक किसी एक पैरे पर अधिक से अधिक ३५० रु० का प्रति वर्ग भाग कर लग सकता है, इस सीमा का बढ़ा कर १,००० रु० प्रति वर्ग कर दिया जाये । जो स्थानीय संस्थाएँ ऐसा कर कर नहीं लगानी है, उन उनकी स्थिति करनी चाहिये ।

६. कराईखाना तथा टैक्साजरी में बीस ली जाती है वहें घटायना है और उसमें वृद्धि की आवश्यकता है ।

७. होटलों में ठहरने वालों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये ।

८. सरकारी सम्पत्ति पर स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने की शूट मिलनी चाहिये ।

९. राज्य सरकारों से स्थानीय संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये ।

१०. उच्च शिक्षा पर स्थानीय संस्थाओं को कोई व्यय नहीं करना चाहिये ।

११. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिये चेकक सपा हैजे के टीके, मधुमेह रोगों की रोकथाम तथा चिकित्सालयों का व्यय राज्य सरकारों को करना चाहिये ।

१२. एक बलवारी तथा यन्त्रायात के अन्य साधन कुटाने के लिये राज्य सरकारें स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें ।

१३. साम्य दोस्त व, बैलगाड़ियाँ तथा नगरी व रिक्शाओं पर कर लगाना जाये ।

प्र० दि०—६२

१४. सैनिक गादियाँ स्थानीय गड़कों को जो हानि पहुँचाती हैं उसके नियंत्रण स्थानीय मस्यामों को क्षति पूर्ति मिलनी चाहिए।

१५. यदि किसी स्थानीय मस्याम को ग्राम की आवश्यकता है, तो उसका प्रबन्ध राज्य सरकारें करे क्योंकि राज्य सरकारों को कम ध्यान पर ग्राम प्राप्त हो जाता है।

१६. स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ अपने प्रतिवर्ष के बजट में से कुछ बचत कर उस संचित रखें और वेबल संकट काल में हो राज्य सरकार को अनुमति में खर्च किया जाये।

१७. स्थानीय स्वायत्त मस्यामों के हिसाब विवरण की पूर्ण जाँच राज्य सरकार के अफेसर्स (Auditors) द्वारा होनी चाहिये।

ग्रामपंचायतों के सुधार के सुझाव

(१) ग्राम पंचायतों की निवारण रूप से मजान कर, सम्पत्ति कर या चुल्हा कर लगायें और गांव की सफाई के लिये शुल्क लगायें।

(२) पंचायती क्षेत्त्र में जो मालगुजारी सरकार को प्राप्त हो उसका १५% पंचायतों को मिलना चाहिये।

(३) अन्न सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर सवाना भी अव्यक्त आवश्यक है।

(४) पंचायत के कर्मचारियों के वेतन का ७१% राज्य सरकारों को देना चाहिये।

(५) गाँव की डाक तथा चौरा से रक्षा करने पर जो व्यय पंचायतों को करना पड़ता है वह सारा का सारा राज्य सरकारों द्वारा महन किया जावे।

(६) सरकारी कृषि, दुग्धशालाएँ तथा कसाईखाने चलाने का अधिकार भी पंचायतों को दिया जावे।

(७) ग्रामवासियों पर लगे मसत सरकारी कर ग्राम पंचायतों द्वारा संग्रह कराये जाकर उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जावे।

(८) शिक्षा तथा चिकित्सा का समस्त व्यय राज्य सरकार सत्न करे।

(९) पंचायतों का प्रबन्ध शिक्षित, योग्य, ईमानदार तथा जातीय वक्तापन रहित व्यक्तियों के हाथ में हो।

(१०) पंच गाँव की सफाई पर ध्यान न देकर अपने पेट पालने पर ध्यान दे रहे हैं। यस्तु अग्रिमक स्थिति से सुधार करने के लिये पंचों की इस मनोवृत्ति में सुधार करना आवश्यक है।

लोकतन्त्र का विवेकीकरण (Democratic Centralisation)—हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है कि शक्ति का स्रोत स्वयं जनता है। इसमें बड़ कर संविधान और लोकतन्त्र के प्रति न्याय निष्ठ हो सकती है कि प्रशासन के संचालन का काम संघमूल जनता को सौंप दिया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस कार्य का श्री गुरुदेव समने पढ़ने बत अवद्वन्द्व भाष में राजस्थान में हुआ। गांव ही मध्य प्रदेश व मद्रास राज्यों में भी इस और सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

उद्देश्य—(१) लोकाधिक विवेन्दोकरण का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। (२) लोकाधिक विवेन्दोकरण योजना में एक ऐसे समाज की रचना करना है जहाँ ग्रामीण यह अनुभव करें कि गांव और गांव की सब वस्तुएँ उनकी ही हैं और उनका विश्वास और विस्तार करना उनकी ही जिम्मेवारी है। (३) इसका उद्देश्य ग्रामीणजनता में ही ऐसे ग्रामीण नेताओं की खोजना है जो अपने भाग्य ग्रामीण समुदाय का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर अत्यन्त उत्साह, उमंग और जोश के साथ विकास योजनाओं को सफल बना सकें।

समूह—ग्राम-पंचायतें लोकाधिक विवेन्दोकरण की पहली कड़ी हैं। ये गांव समाजों द्वारा चुने जाते हैं। जिनमें गांव के सभी नवस्क व्यक्ति होते हैं।

कार्य—ग्राम पंचायतें ग्रामीणों के लिए नागरिक तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। शिक्षा, प्रभूतिका एवं बाल कल्याण सम्बन्धी सुविधाएँ, सार्वजनिक चरागाह, गांव की सड़कें, यलियाँ, छात्रावास और कुओं को ठीक हासत में कायम रखना, मकानों और पानी के बहाव आदि में व्यवस्था करना, ग्राम पंचायतों के कुछ अन्य कार्य हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा, गांव के भूमि-रेकार्ड तथा भूमि लगान की भी व्यवस्था करती हैं।

इनके अतिरिक्त गांवों में न्याय पंचायतें भी होती हैं जिनमें ग्राम पंचायतों में चुने हुए सरपंच ही होते हैं। न्याय पंचायतों की फौजदारी तथा अन्य स्थानीय मामलों के संतर्पित छोटे-छोटे मामलों के निपटाने के अधिकार होते हैं। २०० रु० तक के विधानों दारों के फौजदारी का भी अधिकार होता है। इनकी कार्य-प्रणाली मूख्य होती है तथा बकीलों की साने की दृजाजत नहीं है।

वित्त—इन गांवों को समर्थन करने के लिए मकानों, भूमि, जल और रोजगारी माल की विभिन्न मादि पर कर लगाये हैं तथा कई वस्तुओं पर चुकी लगान कर कट इकट्ठा करते हैं।

पंचायत समितियाँ—प्रत्येक राज्य विकास की दृष्टि से कुछ खंडों अर्थात् ब्लॉक में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड के स्तर पर एक पंचायत समिति होती है जिसमें समस्त पंचायतों के सरपंच और सड़ की समस्त तहसील पंचायतों के सरपंच सदस्य होते हैं। अधिनियम के अनुसार एक ऊपि निपुण, दो महिलाएँ, अनुसूचित जातियों का एक व्यक्ति भी सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था है। साथ-ही सड़ की सहकारी संस्थाओं की संबंध समितियों के सदस्यों में से एक व्यक्ति और ऐसे दो व्यक्ति जिनका प्रशासन, सार्वजनिक जीवन अथवा ग्राम विवास सम्बन्धी अनुभव पंचायत समिति के लिए सार्वजनिक सिद्ध हो सत्यतः लिए जायेंगे। सहयोगी सदस्यों के रूप में राज्य विद्यालय माल का सदस्य भी होगा, उसे बेटक में भाग लेने का अधिकार होगा, पर मत देने का नहीं।

कार्य—पंचायत समितियों के निम्न कार्य होते हैं—(१) सामुदायिक विकास—निर्माण, भूमि उत्सादन, ग्राम संस्थाओं का समूह तथा ग्रामीणों स्वावलंबन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना (२) ऊपि-सम्बन्धी कार्य—परिवार तथा ग्राम सड़ के लिए योजनाएँ बनाना, सड़ तथा जल सार्वजनिक प्रयोग, वैज्ञानिक दलों का प्रसार, २२,००० रु० से कम लागत वाले शिक्षण नव्यों का निर्माण तथा राज्य आयोजना में जलाई गई नीति से सार्वजनिक कर्मों का विकास करना। (३) पशु-पालन—हजिम पशुपालन केन्द्रों की स्थापना, रूज की बीमारी को रोकना, पशु-शोषणालयों की तथा दुग्ध शालाओं की स्थापना

करना। (४) स्वास्थ्य तथा सफाई—पीने-योग्य पानी की व्यवस्था करना, शौच-भालयो एवं प्रसूति केन्द्रों का निरीक्षण करना आदि। (५) शिक्षा—प्राथमिक शालाओं को बुनियादी पद्धति में परिवर्तन करना, माध्यमिक स्तरों तक छात्र वृत्तियों तथा आर्थिक सहायताएँ देना। (६) समाज सेवा एवं समाज शिक्षा—सूचना, सामुदायिक और विनोद केन्द्रों की स्थापना आदि (७) सहकारिता—सहकारी समिति की स्थापना में सहयोग देना तथा सहकारी आन्दोलन को वलशाली बनाना। (८) कुटीर उद्योग—कुटीर उद्योगों एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना। (९) पिछड़े वर्गों के लिए कार्य—पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों का प्रबन्ध करना, समाज कल्याण जैसे सङ्गठन को मजबूत बनाना।

ज़िला परिषद—प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला परिषद होता है। जिला परिषद में जिले की सभ्यत पचायत समितियों के प्रधान, उस जिले में रहने वाला राज्य सभा का सभासद और लोकसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित विधान सभा का सदस्य आदि सदस्य होते हैं। इनके प्रतिनिध, दो महिलाएँ, अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति का तथा ग्राम विकास सम्बन्धी अनुभवी व्यक्ति जिला परिषद के सदस्य बनाये जाते हैं। विकास अधिकारी पदेन सदस्य होता है, परन्तु मत देने का अधिकार नहीं होता है।

कार्य—(१) जिला परिषद पचायत समितियों के बजट की जाँच करेगी (२) जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुदानों का उनमें वितरण करेगी। (३) पचायतों तथा पचायत समितियों के कार्य का समन्वय करेगी (४) पचायतों तथा पचायत समितियों को सड़कों का वर्गीकरण, उनके सभी सरपचा, प्रधानों, पंचों, सदस्यों आदि के कम्प, सम्मेलन आयोजित करेगी। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास-कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देगी।

पचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सङ्गठन एवं कार्यों का उपयुक्त विवेचन राजस्वाम पचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १९५६ के प्राधार पर किया गया है।

प्रश्न

१—उत्तर प्रदेश की नगरपालिका सभा के आय तथा व्यय के मुख्य साधन क्या हैं ? प्रत्येक पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

२—उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों के आय-व्यय के प्रधान साधन बताइये।

३—उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपैलिटियों की आय के स्रोतों पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

४—नगरपालिका की आय के प्रधान स्रोत क्या हैं ? प्रत्येक पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ?

५—जिला बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत बताइये और उन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। इनकी आय पर द्वितीय महापुद्ग का क्या प्रभाव पड़ा है ?

६—बुँगों पर सक्षिप्त नोट लिखिये।

(स० बा० १९५४)

७—भारत में स्थानीय सस्थाओं की आय-व्यय को स्रोतों पर टिप्पणी लिखिये और इनके राजस्व में सुधार दीजिये।

(रा० बो० १९५६)

आर्थिक नियोजन (ECONOMIC PLANNING)



सोवियत रूस की पञ्चवर्षीय योजनाओं का सफलताओं के उपरान्त
नियोजन आर्थिक दोषों के बिना गमवाए औपधि समझी जाने
लगी है। यहाँ तक कि पूँजीपति और व्यापारी-वर्ग जो
नियोजन के शत्रु और स्वतन्त्र व्यापार
के पुजारी माने जाते हैं, वे भी
नियोजन के पक्ष
अनुयायी बन
गये हैं।

—वाडिया एवं जोशी

नियोजना का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Planning)—एल० लॉरविन (L. Lorwin) के अनुसार “नियोजन वह प्राथमिक संगठन है जिसमें एक निश्चित अवधि के भीतर जनता की आवश्यकताओं का अधिकतम पूर्ति के उद्देश्य से समस्त उन्नत साधनों के उपयोग के लिए सभी व्यक्ति तथा स्फुट वष, व्यवसाय तथा उद्योग सम्पूर्ण इकाई के समन्वित बहू समझे जाते हैं।”^१ प्रस्तुत प्राथमिक क्षेत्र में नियोजन का अर्थ यह है कि प्राथमिक साधनों का ऐसा समन्वित नियन्त्रण हो जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका अधिकतम उपयोग हो सके। भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति १९३७ (Indian National Planning Committee, 1937) ने जनसंगठनक व्यवस्था के अन्तर्गत योजना की परिभाषा इस प्रकार की है—‘नियोजन वह नि स्वार्थ विशेषज्ञों के द्वारा निश्चित सामाजिक हिमों के अनुसार एक अपूर्व औद्योगिक सम बण है। इस योजना पर केवल अधशासन एवं जीवन स्तर के उन्नयन की दृष्टि से ही विचार नहीं करना है वरन् उनमें सांस्कृतिक एवं प्राध्यात्मिक हिमों और जीवन क मानवीय पक्ष का भी सम्मिलित होना चाहिए।’^२

डिगानसन नियोजन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं • ‘प्राथमिक नियोजन का अर्थ मुख्य प्राथमिक निर्माण पर पहुँचना है अर्थात् किन्ना और किस प्रकार उत्पादन किया जाय और नि सर्वश्रेष्ठ सत्ता के विचारपूर्वक निश्चयो द्वारा किसी वितरण किया जाय जो संपूर्ण प्राथमिक प्रणाली के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित हो।’^३

उपयुक्त विविध परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्राथमिक नियोजन प्राथमिक संगठन की एक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सत्ताओं की योजनाएँ एक सम्पूर्ण प्राथमिक प्रणाली के विविध अंग स्वरूप होती हैं। इनका उद्देश्य अधिकतम उत्पादन क्षमता एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि कर राष्ट्र को अधिकतम सन्तुष्टि का होता है। इस प्रकार की प्राथमिक व्यवस्था की प्रणाली में वित्तिय व्यक्तियों, वर्गों तथा सत्ताओं की असन्तुष्टी एवं रोष का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इन प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि उत्पादन में वृद्धि कर उसका व्यापक वितरण करना ही प्राथमिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है।

1 “Planning is a system of Economic organization in which all individual and separate plants, enterprises and industries are treated as co ordinated units of a single whole for the purpose of utilising all available resources to achieve maximum satisfaction of the needs of the people within a given interval of time”

—L. Lorwin

2 Report of the National Planning Committee on Manufacturing Industries, Page 21

आर्थिक नियोजन की आधारभूत बातें

(Essentials of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन के लिए निम्नांकित सिद्धान्त आधारभूत माने जाते हैं —

१—विवेकपूर्ण निर्धारित निश्चित आर्थिक लक्ष्य (Conscious and deliberate economic aims i. e., targets)—निश्चित लक्ष्य आर्थिक नियोजन की आधारभूत आवश्यकता है, अतः बिना उसके वह निरर्थक समझे जाते हैं।

२—विविध आर्थिक क्रियाओं का सामंजस्य एवं संचालन हेतु एकल केन्द्रीय सत्ता का अस्तित्व (One Central planning authority Coordinating and directing various economic activities)—संपूर्ण प्रणाली के अन्तर्गत विविध आर्थिक क्रियाओं को समन्वय करने तथा उनका संचालन के लिए अतिभाजित एक ही केन्द्रीय सत्ता का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था के बिना नियोजन का संचालन श्रम नहीं हो सकता।

३—सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लागू होना (Planning must be spread throughout the entire economic field)—नियोजन सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के लिए होना चाहिए अर्थात् कोई भी पहलू इससे बाहर न हो तब ही नियोजन सफल हो सकता है अन्यथा समाज के एक भाग का विकास दूसरे भाग को जिस पर नियोजन लागू नहीं है, निरर्थक कर देगा।

४—सुव्यवस्थित ढंग से निश्चित लक्ष्यों को पूर्ति हेतु क्रमानुसार सीमित उपलब्ध प्रसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग (Rational use of the limited available resources on a well organized system of priorities targets and objectives)—सीमित उपलब्ध संपत्ति प्रसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना आवश्यक है अन्यथा अविनतम सामाजिक इच्छाओं की प्राप्ति के लक्ष्य में सफलता प्राप्त होना सम्भव नहीं हो सकता।

५—नियोजन संचालनार्थ सस्या शास्त्र प्रवीणों, वैज्ञानिकों तथा कला-कौशल विशिष्ट ज्ञान निपुण व्यक्तियों की बड़ी संख्या में कार्य सलग होना (The work of planning to be done by an army of statisticians, scientists and technicians)—आर्थिक नियोजन का कार्य सभी मुश्किल रूप से चल सकता है जबकि इसमें उन्नत सस्या में शास्त्रिकी शास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा कला-कौशल सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कार्य सलग हों। इन लोगों ने इस विषय को एक विशिष्ट ज्ञान का विषय बना दिया है, अतः नियोजन की सफलता के के लिए इनका सहयोग आवश्यक है।

६—राष्ट्रीय अन्तर्देशीय तथा अन्तराष्ट्रीय योजनाओं में पारस्परिक सामंजस्य (Linking of national plans with inter regional and

3 Economic planning is the making of major economic decisions what and how much is to be produced, and to whom it is to be allocated by the conscious decisions of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic survey of the economic system as a whole " —Dickenson, D H Economics of socialism

1939, p 41.

interational plans)—राष्ट्रीय योजना का अन्तर्राष्ट्रिय की योजनाओं से नहीं वलिक अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं से सामंजस्य एवं सम्पर्क होना चाहिए ।

आधुनिक समय में योजना का महत्व—आज का युग योजनाओं का युग है । ससार की सभी राजनैतिक व्यवस्थाओं में इसका महत्व भली प्रकार समझ लिया है । आर्थिक योजना का महत्व केवल देश के सुसंयोजित उत्पादन के लिए ही नहीं है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना प्रतिस्पर्धक बनने के लिए भी इसे ही आधारभूत बनाया जा रहा है । आधुनिक युग में आर्थिक योजना की विचार-धारा का प्रचार सबसे प्रथम रूस के द्वारा हुआ । रूस में क्रम में कई आर्थिक योजनाएँ बनाईं जो प्रायः सभी साम्यवाद के सिद्धान्तों पर स्थिर थीं । मारक्स यह है कि रूस और चीन की अमानक उन्नति इसी आर्थिक योजना की देन है । भारत में भी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् बोम्बे प्लान, पिपुल्स प्लान, गांधी प्लान आदि योजनाएँ बनाई गईं, परन्तु भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं पर ही भारत की भावी आर्थिक उन्नति की आशा स्थिर की गई है ।

भारतवर्ष में आर्थिक योजना की आवश्यकता—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत का आर्थिक ढाँचा प्रायः छिन्न-भिन्न हो गया । भारत विभाजन ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है । इनके प्रतिरिक्त, द्वितीय प्रकोपी में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर घुरा प्रभाव डाला । कहीं वर्षों के प्रभाव के कारण और कहीं बाढ़ों के कारण क्षय हुआ है । देश में खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक पदार्थों का भंडा अभाव हो गया और हम अन्य देशों का गहरा सेना पडा । देश में बेरोजगारी और निर्धनता ने अपना पर कर लिया है । हमारे उद्योग धंधे भा अथवा बहुत विपरीत दशा में है । केवल २२५ करोड़ व्यक्ति ही इन उद्योगों से उदर-पूर्ति कर पाते हैं । भारत की दो तिहाई जन-संख्या कृषि पर निर्भर है, परन्तु कृषि उद्योग अत्यन्त दशा में है । हमारे बड़े एक एकड़ भूमि से ६६० पींड मिलें प्राप्त हुआ है । जबकि जापान में १,७१३ पींड और विश्व में १६१८ पींड में उदर-पूरण किया जाता है । हमारा निम्न जीवन स्तर हमारी अर्थ-व्यवस्था की असमर्थता का द्योतक है । हमारी राष्ट्रीय आय २७५ करोड़ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जो उच्च जीवन-स्तर कायम रखने के लिए अतिक्रम अल्पवर्ष है । इन सब कारणों से सरकार ने अनुभव किया कि अग्रिम योजना निर्माण से इस अटल समस्या का हल होना सम्भव था । अतः भारत सरकार ने भारत के समुचित और आर्थिक विकास के लिए सन् १९५० ई० में एक योजना आयोग (Planning Commission) की नियुक्ति की ।

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना—मार्च सन् १९५० में भारत सरकार ने अपने प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की नियुक्ति की जिसने ३२ मास के निरन्तर परिधम के पश्चात् योजना का अन्तिम रूप ८ दिसम्बर १९५२ को भारतीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जा स्वीकार कर लिया गया । इस योजना को पूर्ण रूप से तैयार करने में २५ लाख रुपये व्यय हुए तथा २७५ कर्मचारी इसमें कार्य-सलग्न रहे । यह पंचवर्षीय योजना सन् १९५१-५२ से १९५५-५६ तक की अवधि के लिए थी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य—स्वतन्त्र भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य—(१) भारतवासियों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाना,

धारा (२) उनके लिए अधिक सुखी और सम्पन्न जीवन के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। योजना आयोग के शब्दों में पंचवर्षीय योजना देश के आर्थिक विकास की एक ऐसा मिनी-जुनी मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है जिसने अन्तर्गत सरकार और जनता दोनों के पुरस्कृत्य काय लेन है और अलग-अलग उत्तरदायित्व है।

योजना का स्वरूप—इस योजना में सरकार द्वारा देश के विकास पर लगभग २०६६ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन किया गया था जो विभिन्न मंडों पर निम्न प्रकार था —

	१९५१-५६ में व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि और मासूहिक विकास	३६०.४३	१७.४
मिर्बाई और बिजली	४६१.४१	२७.२
मालायात और सवहन	४६७.१०	२४.०
उद्योग-धन्धे	१७४.०४	८.४
सामाजिक सेवाएँ	३३६.८१	१६.४
पुनर्वास	८५.००	४.१
विविध	४१.६६	२.५
योग	२०६८.७८	१००.०

व्यय विभाजन—केन्द्र और राज्य-सरकारों में मध्य कुल व्यय का बँटवारा माटे तौर पर निम्न प्रकार था :—

	(करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय सरकार (रिजर्व सहित)	१,२४१
राज्य सरकारें : क भाग	६१०
ख भाग	१७३
ग भाग	३२
जम्मा व बरभोर	१३
योग	२,०६६

प्रथम योजना का उद्देश्य अविध्य में द्रुततर विनाश की धार बढना था। इस हेतु मार्गजनिक क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के प्रस्तावित व्यय के लिए प्रारम्भ में २,०६६ करोड़ रुपये रखे गये जो बाद में बढाकर २,३२६ करोड़ रुपये कर दिये गये।

प्रथम योजना-काल में मिर्बाई तथा बिजली-उत्पादन के साथ-साथ कृषि विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। परिवहन तथा संचार साधनों में विनाश का भी प्राथमिकता मिली। इस योजना-काल में औद्योगिक विनाश निजी उद्योगपतियों की पहल तथा निजी साधनों पर छोड़ दिया गया था।

प्रथम योजना में वास्तविक व्यय—प्रथम योजना के पंचवर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग १,६६० करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो २,३५६ करोड़ रुपये के सशोधित लक्ष्य से १७% कम था। इसका विवरण नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपयों में)

१९५१-५२	२५६
१९५२-५३	२७३
१९५३-५४	३४०
१९५४-५५	४७६
१९५५-५६	६१२
	<hr/> १,९६०

वित्तीय स्रोत—उपभुक्त व्यय के वित्तीय स्रोत निम्नलिखित थे :—

(करोड़ रुपयों में)

(१) राजस्व साते से (रेनवे के योगदान सहित)	७४५
(२) जनता से लिया गया ऋण	२०३
(३) छोटी बचतें तथा अनिहित ऋण	३००
(४) अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	१००
(५) बाहरी सहायता	११७
(६) घाटे की अर्ध-जम्बतरा से	४१५
	<hr/> १,९६०

प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अरूपकारीय तथा दीर्घकारीय उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिये गये। धरतु उत्पादन में वृद्धि हुई तथा अर्ध व्यवस्था काफी मुहृद हो गई। प्रथम योजना के अन्त में मूल्य-स्तर, योजना लागू होने से पूर्व के मूल्य-स्तर से १५% कम था।

प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय सन् १९५५-५६ में बढ़कर लगभग १०,८०० करोड़ रुपये हो गई जो सन् १९५०-५१ में ८,११० करोड़ रुपये थी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में १७% प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी काल में प्रति व्यक्ति आय भी २५३ रुपये से बढ़कर २८१ रुपये हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति उपभोग में ६ प्रतिशत की हो वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में विविधाय की दर में भी वृद्धि हुई।

प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ

	१९५०-५१	१९५५-५६ तक होने वाली वृद्धि (सहय)	१९५५-५६ (सफलताएँ)	१९५०-५१ पर १९५५-५६ में हुई वृद्धि
कृषि उत्पादन				
घाघान (लाख टन)	५४०	७६	६३५	+२५
कपास (लाख गॉर्ड)	२६०१	१२६	४००	+१००२
पटसन (लाख गॉर्ड)	३२०८	२१२	४१६	+८०
गन्ना गुड़ के रूप में (लाख टन)	५६०२	६०८	५००६	+२०४
सिलहून (लाख टन)	५१०	३६	५६०	+५०
मिर्चाली (लाख किलोग्राम)	२३	१३	४३	+२०
सिचाई (लाख एकड़)	५१०	१६७	६७८	+१६८
औद्योगिक उत्पादन				
तैयार इस्पात (लाख टन)	६०८	६०७	१२३	+२०६
सीमेंट (लाख टन)	२६६	२१०१	४५६	+१६०
प्रयोगिक सहस्रक (हजार टन)	४६०	४०४४	३६४०	+३४८०
रेल इंजिन (सहस्र)	३	१७०	१७६	+१७६
पटसन से बनी वस्तुएँ (हजार टन)	८६२	३०८	१,०५४	+१६२
मिर्च का बना वस्त्र (लाख गज)	३७१८०	६,८२०	५१,६६०	+१४,४८०
साहकिल (हजारों में)	१०१	४२६	५१३	+४१२
जहाजरानी (लाख औद्योगिक)	३०६	२०१	५०	+१०१
राष्ट्रीय रासायन (हजार मील)	१२०३	००६	१२०६	+००६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five-year Plan)

“हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करना, औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार करना तथा हमारे देश के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों को अवसर प्रदान करना तथा देश के सभी भागों का समुचित विकास करना है।”

—जवाहरलाल नेहरू

परिचय—प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् अगले पाँच वर्षों के लिये दूसरी योजना का समारम्भ हुआ। यह योजना भारतीय संसद में १५ मई १९५५

में पास की गई । योजना की सफलता के लिए २० भारतीय धर्मशास्त्रियों का एक मण्डल स्थापित किया गया है ताकि सबका सहयोग प्राप्त हो और योजना के प्रत्येक पट्टन पर भली प्रकार परामर्श किया जा सके ।

उद्देश्य—(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५% कर जन-साधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि करना । (२) विनोदकर मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ दत्त गति से देना का औद्योगिकरण करना । (३) रोजगार की अधिक सुविधाएँ देकर बेरोजगारी दूर करना । (४) भ्रष्टाचार और धन में पाई जाने वाली असमानता को कम करना ताकि समाजवादी समाज स्थापित किया जा सके ।

योजना का आकार व स्वरूप—इस योजना पर कुल ७२०० करोड़ रु० खर्च होगा जिसमें से ४८०० करोड़ रु० सरकार तथा २४०० रु० निजी उद्योगपति खर्च करेंगे । इस प्रकार जहाँ प्रथम योजना में सरकार व उद्योगपतियों का भाग ५०, ५० प्रतिशत था, वहाँ दूसरी योजना में यह क्रमशः ६१ व ३९ प्रतिशत है ।

योजना का समस्त व्यय और उसका आवंटन

व्यय की श्रेणियाँ	पहली योजना		दूसरी योजना	
	सारा व्यय करोड़ रुपये में	प्रतिशत	सारा व्यय करोड़ रु० में	प्रतिशत
१. कृषि और सामुदायिक विकास	३७२	१६	४६५	१२
२. शिक्षा और वादों का नियंत्रण	३६५	१७	४३८	११
३. बिजली	२६६	११	४४०	११
४. उद्योग और खनिज	१७६	७	८६१	२३
५. परिवहन और संचार	५५६	२४	१,३८४	३६
६. समाज सेवा, मकान और पुनर्वसि	१४७	२३	६४६	१७
७. विविध	४१	२	११९	३
योग	२,३५६	१००	४,८००	१००

४,८०० करोड़ रु० के कुल व्यय में से २,५५६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार तथा २,२४४ करोड़ रु० राज्य सरकारें व्यय करेंगी । कुल व्यय में से ३,८०० करोड़ रु० का उपयोग विनिर्माण के लिए तथा १,००० करोड़ रु० का उपयोग जल विचार व्यय के लिये किया जायगा ।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य

भेद	१९६०-६१ के लक्ष्य	१९५५-५६ पर १९६०-६१ की वृद्धि (प्रतिशत)
कृषि		
खाद्यान्न (लाख टन)	७५०	१५
रूपाय (लाख गांठ)	५५	३१
गन्ना (लाख टन)	७१	२२
निलहून (लाख टन)	७०	२७
पटसन (लाख गांठ)	७,०००	६
राष्ट्रीय विस्तार खण्ड (सक्या)	३,५००	६६०
भामुदायिक विवास खण्ड (सक्या)	१,१२०	५०
सिंचाई तथा बिजली		
बीबी गद्दे भूमि (लाख एकड़)	८८०	३१
विजली (लाख किलोवाट)	६६	१०३
खनिज		
बक्का लोहा (लाख टन)	१२५	१२१
कोयला (लाख टन)	६००	५८
घरे पैसे के उद्योग		
लैप्पर स्पार्क (लाख टन)	४३	२३१
एल्युमिनियम (हजार टन)	२५०	२३३
गोटर गाड़ी (सक्या)	१७,०००	१२८
रेल ड बिन (सक्या)	४००	१२६
सीमेंट (लाख टन)	१३०	२०२
उर्वरक		
(क) नाइट्रोजन युक्त (प्रमोनिमन सल्फेट) (हजार टन)	१,४५०	२८२
(ख) फास्फेट युक्त (सुपर फास्फेट) (हजार टन)	७२०	५००
मृत्ती बस्त्र (लाख बज)	८५,०००	१४
चीनी (लाख टन)	२३	३५
कागज तथा गत्ता (हजार टन)	३५०	७५
परिवहन तथा संचार-साधन		
(क) रेलवे		
सवारी गाड़ी मील (लाख)	१,२४०	१५
दोया गया सामान (लाख टन)	१,६२०	३५
(ख) मंडक		
राष्ट्रीय राजपथ (हजार मील)	१३ ८	७

पर्याप्त मजदूरी (इंजिनरी से)	१२५०	१०
(ग) डाक्टर (इंजिनरी से)	७५	३६
शिक्षा तथा स्वास्थ्य		
प्रारम्भिक बुनियादी स्कूल (लाभ)	३५०	१६
प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों के प्रत्यापन (लाभ)	१३४	३०
विश्वविद्यालय (इंजिनरी)	१०६	२६

राष्ट्रीय आय—२म योजना के पञ्चवर्षीय हमारी राष्ट्रीय आय जो १९५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपये थी वह बढ़ कर १९६०-६१ में १३,५०० करोड़ रुपये हो जायेगी। इस प्रकार हमारे २५ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति आय २८१ रु० में बढ़कर ३३० रु० हो जायेगी।

रोजगार—द्वितीय योजनाकाल में इच्छित क्षेत्रों में ८० लाख व्यक्तियों की पूरे समय का रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके परिणाम, गिवाई नया भूमि-मुपाय जैसी विज्ञान योजनाओं से काफी दूर तक नव रोजगारों का व्यवस्था करके बराबरगरी कम की जायेगी। द्वितीय योजनाकाल में कुल मिलाकर १ करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगारों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सभी बेकार श्रमिकों की काम में लगाना जा सके।

वित्तीय मायन—द्वितीय योजना के मार्गदर्शित क्षेत्र के व्यय व वित्तीय मायन निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
(१) चालू राजस्व में वृद्धि		८००
(क) करो की वर्तमान दरों में	३५०	
(ख) प्रतिशत करो में	४५०	
(२) जनता में ऋण		
(क) बाजार ऋण	७००	१२००
(ख) अन्य संचय	१००	
(३) अन्य बजट सम्बन्धी स्रोतों में		४००
(क) रेशों का समदान	११०	
(ख) प्रॉजिक्ट फंड और अन्य जमा	२९०	
(४) विदेशी सहायता		८००
(५) घाटे की शर्त-व्यवस्था		१,२००
(६) घरेलू मायनों में अनिश्चित वृद्धि करने पूरा किया जाने वाला अन्तर		४००
		<u>४,८००</u>

निजी क्षेत्र में विनियोग—निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रु० में विनियोग की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जो नीचे दिखाया गया है ।

	(करोड़ रु०)
सगठित उद्योग तथा खानें	५७५
बागान, विजनी तथा परिवहन (रेलों को छोड़कर)	१२५
निर्माण कार्य	१,०००
कृषि तथा ग्राम एवं छोटे पैमाने के उद्योग	३००
स्टॉक	४००
	<hr/> ४,४००

योजना का पुनर्मूल्यांकन—इसरी योजना को पूरा करने के वित्तीय साधनों की सम्पत्तिता ने स्थिति को गम्भीर बना दिया जिससे कमस्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) ने मई १९५८ के प्रथम सत्राह में इससे सशोधन का प्रस्ताव पास किया । प्रस्ताव में कहा गया कि योजना के 'क' भाग पर ४५०० करोड़ रु० खर्च होगा और ३०० करोड़ रु० 'ख' भाग पर उस हद तक खर्च किये जायेंगे जिन हद तक प्रतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे ।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न खर्चों पर किये जाने वाले व्यय का सशोधित आँकड़ों सहित स्पष्ट विवरण दिया गया है :—

सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न व्यय की मदें	मूल वितरण (करोड़ रु०) में	सशोधित विवरण (करोड़ रु० में)	४५०० करोड़ रु० की सीमा में वितरण (करोड़ रु० में)
१. कृषि एवं सामुदायिक विकास	५६८	५६८	५१०
२. सिंचाई व बिजली	६१३	८६०	८२०
३. ग्रामीण तथा छोटे उद्योग	२००	२००	१६०
विज्ञान उद्योग तथा खनिज पदार्थ	६६०	८८०	७६०
४. परिवहन तथा संचार	१३८२	१,३४५	१३४०
६. सामाजिक सेवाएँ	६४२	८६३	८१०
७. विविध	६६	८४	७०
योग	४८००	४८००	४५००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना और राज्य सरकारों का योजना व्यय

राज्य	योजना व्यय (१९५६-६१) (करोड़ रु०)
(१) असम	५०*६४
(२) आंध्र प्रदेश	१७४ ७७
(३) उत्तर प्रदेश	२५३ १०
(४) उड़ीसा	६६*६७
(५) केरल	८७*००
(६) जम्मू तथा कश्मीर	३३*६२
(७) पंजाब	१६२ ६८
(८) पश्चिमी बंगाल	१५७ ६७
(९) बम्बई	३५० २२
(१०) बिहार	१६० २२
(११) मद्रास	१५९ २६
(१२) मध्य प्रदेश	१६० ८६
(१३) मैसूर	१४५*१३
(१४) राजस्थान	१०५ २७

उत्तर प्रदेश—द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सन् १९५६-६१) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ने २५३ १० करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस राशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है —

विकास की गई	योजना में व्यय व्यवस्था (१९५६-६१) (करोड़ रु०)
-------------	--

कृषि एवं महात्मक विषय	४ *०४
सामुदायिक विकास योजनाएँ एवं	
राष्ट्रीय मिन्नार सेवा	२६ ६०
शिक्षा	२५ ८०
शक्ति	५४ ६२
उद्योग	१६ ४३
मानवपान	१७ ००
निर्माण	२६ ५६
समाय्य	२४ २३
आवास	१०*४५
विपद्ग्रस्त प्रांतों का बत्थाण	४ ७५
सामाजिक बत्थाण	१ २५
धर्म बत्थाण	१ ४२
विविध	२*६७

योग	२५३ १०
-----	--------

राजस्थान—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में १०५.२७ करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यय का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

विकास की मदें

योजना में व्यय व्यवस्था (१९५६-६१)

	(करोड़ रु०)
कृषि एवं सहायक विषय	१२.७७
सामुदायिक विकास योजनाएँ	
एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा	६७४
सहस्रद्वेसीय योजनाएँ	२४.६७
सिंचाई	११.७४
शक्ति	८.६५
उद्योग	६.०४
यातायात	२.४२
शिक्षा	१०.५६
स्वास्थ्य	७.३६
ग्रामास	२.६४
पिछड़ी जातियों का कल्याण	२.२८
सामाजिक कल्याण	०.४३
श्रम एवं श्रम कल्याण	०.६२
विविध	१.०१
	<u>१०५.२७</u>

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ

वस्तु	१९५०-५१	१९६०-६१ (समाप्ति)
मुख्य फसलों की पैदावार		
अन्न (लाख टन)	५२२	७४०
तिलहन (लाख टन)	५१	७२
गन्ना शुद्ध (लाख टन)	५६	७२
कपास (लाख गिठों)	२६	४४
पटसन (लाख गांठ)	३३	५१
उत्पादित वस्तुएँ		
तीव्रार इस्पात (लाख टन)	१०	२६
मध्यमीनियम (हजार टन)	३७	१७
डीजेल इंजिन (हजार)	५५	३३
मिजरो के तार (ए० सी० सी० भार कण्टेनर) (टन)	१,६७४	१०,०००
मशीन युक्त खर्वक (हजार टन)	६	२१०
गंधक का सेजक (हजार टन)	६६	४००

सीमेंट (लाख टन)	२७	६८
कोयला (लाख टन)	३२०	५३०
कच्चा लोहा (लाख टन)	३०	१२०
उपभोक्ता वस्तुएँ		
मिलों का सूती कपड़ा (लाख गज)	३७,२००	५०,०००
चीनी (लाख टन)	११	२२५
कागज और पत्ता (हजार टन)	११४	३००
बाइसिकल् (हजार)	१०१	१,०५०
मोटर गाड़ियाँ (संख्या)	१६,५००	५३,५००

योजना के मुख्य—(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम उपज है। (२) इसमें जनता की सम्पत्तियों तथा आसोचनाओं की पूर्ण प्रबलता प्रदान किया गया है। (३) योजना बड़े-छोटे सभी भी है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होगा और आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये जायेंगे। (४) सरकारी क्षेत्र का महत्व पूर्णतया ग्यापीकृत है, क्योंकि प्रत्यक्ष भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का समाजवादी नमूने का समाज-निर्माण है। यही कारण है कि योजना को बिरोधी दलों जैसे प्रजा समाजवादी और साम्यवादी दलों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। (५) दूसरी योजना में देश का औद्योगीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, इस विचार से कि लोगों को अधिक मौकियाँ दिला कर मजदूरी और वेतन के रूप में अधिक धन प्राप्त करके, अधिक वस्तुओं और सेवाओं तथा अधिक आर्थिक गतिविधि द्वारा जीवन स्तर को समग्र रूप से उठाया जाय। यह एक प्रयत्न है।

योजना के दोष (आलोचना)—(१) योजना आयोग के अध्यक्ष सदस्य श्री के. सी. निगोमी के अनुसार “भारत की दूसरी योजना प्रभावकारक और आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी है। यह प्रच्छा होता कि यद्यपि कुछ कम रकमें जाते जिनके पूर्ण होने की आशा तो होती।” (२) दूसरी आलोचना यह है कि गाँव का बजट बनाकर योजना को कार्यान्वित करने का जो विचार है उससे वेतन में मुद्रा-स्फीति में और भी वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप कम आय वाले लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। (३) योजना में भारी उद्योगों पर प्रमुखित्व रख और उन्हें प्राथमिकता दी है। संसार के सभी प्रगतिशील और बहुत अधिक औद्योगिक देशों में औद्योगीकरण का कम पहले प्रथम उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिये कारखाने बना कर आरम्भ किया, और तदनन्तर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएँ बनाने के लिये यत्नीयें बनाईं। हमारी दूसरी योजना में इन प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिपाटी को उलट दिया गया है और हमारी योजना फिर के बल खड़ी है। (४) योजना का वित्तीय आधार कमजोर है। ४५० करोड़ रुपये के गैर कर, १२०० करोड़ रुपये की भाटे की धर्म-व्ययर्था और ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता आती गई है। फिर भी ४०० करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। यदि इसे पूरा करने के लिए फिर नये कर लगाये गये तो जनता से अशक्तोप बढ़ने की आशंका है। (५) देश की यावयात को देश बहुत पराव है। इस समस्या को रोक, रोक, राष्ट्रीय जहाजरानों तथा आन्तरिक जल मार्ग उन्नत करके, सुव्यवस्था जा सकता है। परन्तु योजना में इसके महत्व को ठीक प्रकार नहीं समझा गया है। (६) प्रशासन के लिए योग्य तथा कुशल व्यक्तियों की कमी का प्रत्यक्ष

नहीं किया गया है। प्रणाम, अनुमोदनकर्त्ताओं आदि की बात तो क्या, साधारण श्रोतारमित्रों का हृदय, नमो आदि की देन में जारी नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि योजना बीच में ही रुक जायेगी। (७) इस योजना में सरकारी क्षेत्र को अनुचित महत्व प्रधान दिया गया है और उसका विकास अन्य भी निजी क्षेत्र को विशेषता देने से भी अधिक है। यह भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आज देश में प्रबल प्राविण उन्नति का है, इसका मही कि उसे कोन करता है। इसके अतिरिक्त देश में सरकारी समाजवाद तथा एकाधिकार स्थापित हो जायगा और एकाधिकार के सारे दोष उत्पन्न हो जायेंगे। (८) इस योजना में सभी क्षेत्रों को जो महत्व दिया गया है वह उन लोगों को पसन्द नहीं है जिन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। जहाँ कहीं भी किसान ने भूमि लेकर उसे सामूहिक प्रयत्न सामूहिक के खेतों में रूप में रखा गया है, वहाँ पैदावार बढ़ा है। सोवियत रूस और पूर्वी योरोपीय देशों में भी यही हुआ है। इसी कारण युगोस्लाविया और पोलैंड की साम्यवादी सरकारों ने अपने गन्तव्य का अनुभव किया है और उन्होंने किसानों को सामूहिक खेतों को छोड़कर अपनी अपनी खुद की जमीन की खेती में ही है। (९) सूती मिल उद्योग तथा हाथ करपा उद्योग के बीच में जो समन्वित किया गया है, वह नहीं चल सकेगा। इससे निर्यात करने में बाधा पड़ सकती है। (१०) कुटीर उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय में उत्तम वृद्धि न हो सकेगी। जितनी कि योजना में बताई गई है। (११) योजना में उद्योगों की वस्तुएँ उन्नत करने के लिए फैक्टरी और गैरफैक्टरी उत्पादों का बंटवारा किया गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि गैरफैक्टरी उत्पादों पर अधिक नतीजा नहीं किया जा सकता। (१२) योजना में निर्यात बढ़ाने के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार उद्योगों की प्रतिस्पर्धी शक्ति का बढ़ाने के लिए कई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। (१३) योजना में वैद्यकी की परिस्थिति या तथा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य व्यय के लिए काम देने का पूर्ण प्रावधान नहीं दिया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना



‘मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना सारा ध्यान तीसरी पंचवर्षीय योजना पर लगा दें। मान यह समय बड़ा काम है, जो हमें करना है। इससे पूरे होने में हमारे हमारे समसाम्यो व मुनश्काने में भी मदद मिलेगी।’

—जगहरलाल नेहरू

परिचय—द्वितीय पंचवर्षीय योजना ३१ मार्च १९६१ को समाप्त हो गई और १ अप्रैल, १९६१ से तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गई। इसका कार्यकाल सन् १९६५-६६ तक है। तीसरी योजना देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण चरण है। पहले दो योजनाओं में कृषि का विकास करने के लिए क्षेत्रीय समूहों और शासन स्तर को मजबूत बनाया जा चुका है। औद्योगीकरण में तेज चाल से आगे बढ़ने के लिए, दस्तावेज उद्योग, खाना, बिजली और परिवहन का विकास प्रभाव का काम करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इनके विकास में सब तक जी गति ला चुकी है, उसे तीसरी योजना में तीव्र करके, चौथी योजना में और अधिक बढ़ा दिया जाय।

उद्देश्य—प्रथम दो योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना निम्नांकित लक्ष्यों को सामने रख कर बनाई जा रही है :—

(१) तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो और पूँजी-वित्तियोग का स्वरूप ऐसा हो कि वृद्धि का यह क्रम अगली योजनाओं में भी जारी रहे।

(२) छापाओं के मामले में देश स्वावलम्बी हो जाय और कृषि की उपज इतनी बढ़ जाय कि उपर्युक्त उद्योगों और निर्माकियों की आवश्यकताएँ पूरी हों।

(३) दस्तावेज, ईंधन और बिजली सरीखे बुनियादी उद्योगों का विस्तार हो और यत्र मामूली बनाने की क्षमता इतनी बढ़ जाय कि हम वर्षों के भीतर भारी औद्योगीकरण की समस्त आवश्यकताएँ स्वदेशी छापाओं से ही पूरी हो सकें।

(४) देश की जन शक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग किया जाय और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो।

(५) आय और संपत्ति में विषमता घटे तथा आर्थिक समता का अधिक हल हो बिखरए हो।

योजना की हमरेखा—योजना में, सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के व्यय की बर्चा की गई है। तीसरी योजना में सत्र पिलावर १०,२०० करोड़ ४० पूँजी-वित्तियोग करने का विचार है। इसमें से ६,२०० करोड़ ४० सरकारी क्षेत्र में और ४,००० करोड़ ४० निजी क्षेत्र में समान जायेंगे। योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में अस्तावित व्यय निम्न सारणी से स्पष्ट होता है :—

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय

क्रमांक	विकास की मदें	व्यय		प्रतिशत	
		द्वितीय योजना	तृतीय योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१—	कृषि तथा छोटी सिंचाई योजनाएँ	३२०	६२५	६'६	८'६
२—	सामुदायिक विवास और सहकारिता	२१०	४००	४'६	५'५
३—	बड़ी और माध्यम सिंचाई योजनाएँ	४१०	६१०	६'८	६'०
४—	मिजस्ट्री	४१०	६२५	८'६	६'०
५—	ग्राम और लघु उद्योग	१८०	२५०	३'६	३'४
६—	उद्योग और खनिज	८८०	१५००	१६'१	२०'७
७—	परिवहन और संचार	१२६०	१४५०	२८'१	२०'०
८—	सामाजिक सेवाएँ	८६०	१२५०	१८'७	१७'२
९—	इकाकेट न आने देने के लिए जमा राशि	—	२००	—	२'८
	योग	४६००	७२५०	१००	१००

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभिन्न मदों पर तृतीय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विनियोग ने सम्बन्ध में तालिका निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विकास मंचे	सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग	निजी क्षेत्र में विनियोग	कुल विनियोग
१—	कृषि, छोटे सिंचाई तथा सामुदायिक विकास योजनाएँ	६७५	८००	१,४७५
२—	बड़े और माध्यमिक सिंचाई योजनाएँ	६४०	—	६४०
३—	शक्ति (विजली)	६२५	५०	६७५
४—	शाम और सड़क उद्योग	१६०	२७५	४३५
५—	उद्योग और खनिज	१,५००	१,०००	२,५००
६—	परिवहन और संचार	१,४५०	२००	१,६५०
७—	सामाजिक सेवाएँ	६५०	१,०७५	१,७२५
८—	जमा राशि	२००	६००	८००
योग		६,२००	४,०००	१०,२००

प्रस्तावित व्यय के केन्द्र और राज्यों में विभाजन का रूप तब ज्ञान होगा जब राज्यों की योजनाओं पर उनके साथ विचार होगा। परन्तु अपनी योजनाएँ बनाने में राज्यों की सहायता करने के लिए यहाँ का व्यय का अस्थायी विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है :—

केन्द्र और राज्यों में व्यय का विभाजन
(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	विकास-मंचे	योग	केन्द्र	राज्य
१.	कृषि, छोटे सिंचाई- शाम और सामुदायिक विकास	१,०२५	१७५	८५०
२.	बड़े और माध्यम सिंचाई-कार्य	६५०	५	६४५

३. बिजली	६२५	१२५	८००
४. ग्रामीण और छोटे उद्योग	२५०	१००	१५०
५. उद्योग और शालें	१,५००	१,५७०	३०
६. परिवहन और संचार	१,४५०	१,२२५	२२५
७. समाज सेनाएँ	१,२५०	३००	६५०
८. इन्वेस्टमेंट्स	२००	२००	—
सर्वा योग	७,२५०	३,६००	३,६५०

योजना के वित्तीय साधन—तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में जब तक के सम्पन्न के फलस्वरूप प्रस्तावित व्यवस्था की वित्तीय व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जो योजना तैयार की गई है, वह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाती है :—

सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन

(करोड़ रु०)

वर्ष	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. करो की वर्तमान दरों के आधार पर, राजस्व से बची हुई राशि	१००	३५०
२. वर्तमान आधार पर, रेलों से प्राप्त भाग	१५०	१५०
३. वर्तमान आधार पर अन्य सरकारी उद्योग व्यवसायों से होने वाली बचत	—	४४०
४. जनता से लिए हुए ऋण	८००	८५०
५. छोटी बचतें	३८०	४५०
६. प्राविष्टिष्ठ पण्ड, सुश्रुतामी कर, इत्यादि समीकरण बोध और पूर्णता खाते में जमा विविध राशियाँ	२१३	५१०
७. नए कर जिनमें सरकारी उद्योग व्यवसायों में अधिक बचत करने के लिए जाने वाले उपाय शामिल हैं	१०००	१,६५०
८. विदेशी सहायता के रूप में अर्जित प्रदायित रकम	६८२	२,२००
९. घाटे की पूर्ण व्यवस्था	१,१७५	५५०
योग	४,६००	७,२५०

निजी क्षेत्र में पूँजी का विनियोग—योजना के निजी क्षेत्र में पूँजी विनियोग का सम्बन्ध न केवल समर्पित उद्योगों, खानों, बिजली और परिवहन से, बल्कि इति, ग्राम तथा नए उद्योगों सहित तथा ग्रामीण आवास आदि से भी है। उपलब्ध तथ्याङ्क आधार पर इस सारे क्षेत्र के लिए पूँजी-विनियोग की कोई सार्वजनिक योजना प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं है। हाँ, गत वर्ष की प्रवृत्तियों के साथ तुलना करके इस बात का

थोड़ा-बहुत निश्चय आवश्यक किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में जितनी पूँजी लगाने की बात नहीं गई है, वह कहीं तक व्यवहारिक होगी। नीचे की तालिका में दिखताया गया है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत में लगाने वाले अनुमानों और रिजर्व बैंक द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के आधार पर संशोधित अनुमानों के साथ तुलना करने पर तीसरी योजना में निम्नी क्षेत्र की प्रमुख मदों में कितनी पूँजी विनियोग हो सकता है —

योजना के निम्नी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग

(करोड़ रु०)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना	
	प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान	अनुमान
१. कृषि (सिंचाई सहित)	२७५	६७४	८५०
२. बिजली	४०	४०	५०
३. परिवहन	८५	१३५	२००
४. ग्रामीण और लघु उद्योग	१००	२२५	३२५
५. बड़े और मध्यम उद्योग तथा खनिज पदार्थ	१७५	७००	१,०५०
६. आवास और ग्रन्थ इमारती काम	६२५	१,०००	१,१२५
७. इन्वेस्टिचों	४००	५२५	६००
योग	२,४००	३,३००	४,२००

विदेशी मुद्रा—तृतीय योजना में विदेशी मुद्रा का प्रश्न सबसे अधिक जटिल और महत्वपूर्ण है। यह अनुमान लगाया गया है कि तृतीय योजना में कुल मिलाकर ३,२०० करोड़ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जो कि इस योजना का लगभग ३ भाग है। इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

विद्युत प्रकाश और स्थापना के भुगतान के लिए	५०० करोड़ रु०
मशीनों और अन्य भारी सामान खरीदने के लिए	१,६०० " "
स्वायत्त सम्पत्ति की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के हेतु सामान खरीदने के लिए	२०० " "
सार्वजनिक खर्च करने के लिए	६०० " "

योग ३,२०० करोड़ रु०

चतुर्थ योजना की सम्पत्ति के आवश्यक उत्तर—इन क्षेत्रों के अन्तर्गत चौथे क्षेत्र में अनुमानित तीसरी योजना की सम्पत्ति के लिए निम्न बातों की आवश्यकता है :—

- (१) योजना की रूपरेखा पर सभी दलों की पूर्ण सहमति।
- (२) सभी क्षेत्रों में सही एवं निःस्वार्थ नेतृत्व।
- (३) योजना के उद्देश्यों का प्रचार।
- (४) समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में सक्रिय कदम।

(२) योजना का वा्याव्यिक करने के लिए सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा जनता और गैर सरकारी क्षेत्रों पर अधिक विश्वास ।

निष्कर्ष—योजना एक राष्ट्रीय विकास का कार्यक्रम है न कि किसी दल विशेष का । इस महान् राष्ट्रीय प्रयास को सफल बनाने के लिए सभी दलों के सक्रिय सहयोग का नितांत आवश्यकता है । डा० बी० के० गार० बी० राव ने अनुसार "तृतीय योजना भारत का समाजवादी समाज की स्थापना की ओर ले जायेगी, जहाँ न्याय, समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता होगी, जहाँ जनतन्त्रिय सहकारी एवं विनैम्दित व्यवस्था होगी, जहाँ निम्न आय के लोगों को उन्नति का अवसर मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, वार्षिकमत्ता में वृद्धि होगी, पूँजी निर्माण पर्याप्त होगा, प्राथमिक विकास की दर तथा विनिर्माण का स्वरूप ऐसा होगा कि सबल एवं स्वतः हो विकसित होने वाली अर्थ-व्यवस्था दृष्टिगोचर होने लगे ।" इस प्रकार भारत में तृतीय योजना का अग्रिम उद्देश्य है ।

सामुदायिक विकास योजनाएँ

(Community Development Projects)

"मेरा विश्वास है कि देश में महत्वपूर्ण उन्नति विकास देशाती क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्रावधानों के रूप में हुई है । पहली बार हमने देशों को समस्या को सही ढंग से हल करने का प्रयत्न किया, गाँव बांधों को प्रकृति समस्याएँ स्वयं हल करने के लिये प्रेरित करने । इस चीज ने हमें जीवन का संचार दिया, उनको घाँटें खुल गईं, उनके मुँह खुल गये । पहले से अधिक मजबूत हो गये और वे काम करने के लिए तैयार हो गये मानो उनके मनुष्य-जीवन का संचार हो गया ।"

—जवाहरलाल नेहरू

प्रारम्भिक—वर्तमान युग में राम राज्य अर्थात् ऐसे राज्य की स्थापना करना के लिए, जिसमें देश धन धान्य से पूर्ण हो, भय और बन्ध की प्रचुरता हो तथा जनता को सुख और शान्ति हो, सक्रिय ब्रह्म सबसे प्रथम राष्ट्रीय महात्मा गाँधी ने उठाया था । ब्रिटिश शासनकाल में समय-समय पर गाँवों की दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किये गये, परन्तु वे सब विफल रहे, क्योंकि प्रथम तो वे व्यवस्थित न हो और द्वितीय, उनमें इस बात पर जोर नहीं दिया कि गाँव की उन्नति मुख्यतः ग्रामीणों के अपने प्रयत्नों से ही होगी, सरकार केवल सहायता ही कर सकती है । भारत स्वतन्त्र हुआ और देश के सर्वोत्तमोत्तम विकास के लिये मई १९५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार आजकल कार्य चल रहा है । इस पंचवर्षीय योजना में एक नई बात का समावेश किया गया है और वह है सामुदायिक योजना । समस्त देश में योजना का उद्घाटन २ अक्टूबर १९५२ को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने एक भाषण प्रसारित करके किया । डा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में योजना को गाँव के स्वयं का मूल-भूत बनाने का उद्देश्य बताया—“भारत बहुत बड़े गाँवों में ही बनना है । . . . महात्मा गाँधी इसीलिए गाँवों की उन्नति पर बहुत जोर दिया करते थे । यह हम विचार है कि आज उनके जन्म-दिन पर इस सामुदायिक उन्नति का प्रारम्भ किया जा रहा है” ।

सामुदायिक योजना का अर्थ एवं परिभाषा—योजना आयोग के शब्दों में “सामुदायिक विनाश योजना यह उपाय है और देशों तक हमारे कार्यक्रम का विस्तार बढ़ा सामान है किन्हीं द्वारा पंचवर्षीय योजना हमारे गाँवों के सामाजिक एवं

मार्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहती है।¹ भारतवर्ष के लिए सयत्क राष्ट्र अमेरिका के औद्योगिक सहयोग प्रदातक श्री लॉशबाउ (Loshbough) के शब्दों में, जो सामुदायिक योजनाओं के विष्टी दादरेक्टर हैं, "सामुदायिक योजना गहरे विकास की समस्या की एक सुव्यवस्थित एवं आयोजित ढर्र है।"² अमेरिका में किसी बस्ती या गावादी (Settlement) की समुदाय (Community) बहते हैं और उसके विकास कार्य को सामुदायिक विकास योजना (Community Development Project) बहते हैं। इस अमेरिकन प्रथा के अनुसार ही भारतवर्ष में भी यह नाम रखा गया है।

योजना का उद्देश्य—इस योजना का उद्देश्य यह है : "योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के पुष्पा, स्थितियों व बन्धों के 'जीवित रहने के अधिकार' के स्थापन में एक मार्ग-प्रदर्शक व्यवस्था के रूप में सेनाएँ प्रदान करना, परन्तु कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस उद्देश्य की पूर्ति के मुख्य स्थापन राय की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जावेगा।"³ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित यातों की पूर्ति के लिए ध्यान दिया जावेगा :—

(१) खेती और उससे सम्बन्धित कार्य —(अ) पकत तथा बिना-डुनी भूमि का कृषि के लिये प्रयोग करना, (आ) सिंचाई के लिये नहरों, नल-कूपों, तालाबों आदि की व्यवस्था करना, (इ) उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना, (ई) कृषि के बीमारों की व्यवस्था करना, (उ) उपज की बित्री तथा सस्ती सास की व्यवस्था करना, (ऊ) पशु-पालन के लिये पशु प्रजनन-केन्द्र (Breeding Centres) की व्यवस्था करना तथा उनकी बीमारियों को दूर करने का प्रबन्ध करना, (ए) भूमि के पटाय की रीवने की व्यवस्था करना, (ऐ) फलों व सब्जियों की खेती का विकास करना, (ओ) मछली व्यवसाय का विकास करना, (ओ) मिट्टी के सम्बन्ध में गवेषणा की व्यवस्था करना, (म) सामुनिक ढय से सेती करने का प्रचार करना, तथा (म.) पेड पीधों की खेती और वृक्षारोपण की व्यवस्था करना।

(२) यातायात व सवाद के साधन :—(अ) सड़कों की व्यवस्था करना, (आ) पानिक सडक-परिवहन सेवाओं की प्रोत्साहन देना, व (इ) पशु-परिवहन का विकास।

(३) शिक्षा :—(अ) प्रारम्भिक अवस्था में अनिवार्य तथा नि-मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करना, (आ) मिडिल और हाई स्कूलों की व्यवस्था करना, (इ) सामाजिक शिक्षा तथा पुस्तकालय खुलवाने की व्यवस्था करना, तथा (ई) विदेशी दिलाकर प भाषण दिलाकर आणीला की बुद्धि का विरासत करना।

(४) स्वास्थ्य :—(अ) सफाई और सामाजिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना (आ) बीमारों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था करना, (इ) गर्भवती स्त्रियों की प्रसव

1. "Community Development is the method and Rural Extension the agency through which the Five year plan seeks to initiate a process of transformation of the Social and Economic life to villages"

First Five-year plan of the Government of India.

2. Community project is an organized, planned approach to the problem of intensive development."

—Loshbough.

न पहले और उसके उपरान्त देख-भाल करना तथा (ई) दाइयों की सेवाएँ उपलब्ध करना ।

(५) प्रशिक्षण ट्रेनिंग :—(घ) मौजूदा कारीगरों को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (Refresher Courses) की व्यवस्था करना, (घा) नए लोगों का प्रशिक्षण, (इ) क्षति-विस्तार अधिकारियों (Extension Officers) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना, (ई) निरीक्षकों (Supervisors) के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, (उ) कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, (ए) प्रबन्ध कार्य सम्भालने वाले कर्मचारियों की प्रशिक्षण-व्यवस्था (ऐ) स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था तथा (घो) योजना के कार्याधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(६) नियोजन (Employment)—(घ) मुखा या सहायक धन्यों के रूप में कुटीर-उद्योग व शिल्पों को प्रोत्साहन देना, (घा) अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाने के लिए छोटे-मोटे उद्योग-धन्यों को प्रोत्साहन देना, (इ) आयोजित (Planned) वितरण, व्यापार, सहायक तथा कल्याणकारी सेवाओं द्वारा कार्य उपलब्ध करने की व्यवस्था करना

(७) आवास (Housing) — देहात में घण्टे, नये और हवादार गकान बनाने के लिए अधिक उत्तम ढंगों और डिजाइनों की व्यवस्था करना ।

(८) सामाजिक कल्याण (Social Welfare) — (घ) स्थानीय प्रतिभा एवं संस्कृति के अनुसार जन-समुदाय के मनोरंजन की व्यवस्था करना, (घा) शिक्षा व मन बहलाव के लिए दिशा-मुना कर सम्भालने की व्यवस्था करना, (इ) स्थानीय तथा ग्राम प्रकार के खेल-कूद का प्रबन्ध करना, (ई) पेना का प्रबन्ध, तथा (उ) सहकारिता तथा 'घनो मदद पाओ' भा-सौजन्य का संगठन करना ।

योजना का संगठन :—योजना आयोग की सकारितों के अनुसार उन क्षेत्रों को सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत पहले लाना है जिनमें धर्याप्त बचा या सिंचाई की सुविधाओं के कारण अधिक लाभ होने की प्राप्ति है । सम्पूर्ण देश में लगभग ५०० सामुदायिक योजनाएँ स्थापित कराई जाने का योजना आयोग ने प्रस्ताव किया है । प्रथम अवस्था में ५५ योजना-क्षेत्र चुने गये हैं और महात्मा गांधी के जन्म दिवस, २ अक्टूबर १९५२ से इनमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । प्रत्येक सामुदायिक योजना के लिए जैसा कि इस समय लागू किया जा रहा है, ३०० गाँव हैं जिसमें कुल मिलाकर ४५० से ५०० वर्ग मील, १३ लाख एकड़ जेत तथा २ लाख जनसंख्या भा जानी है । एक-एक योजना को ३ विकास टुकड़ियों (Development Blocks) में बाँटा गया है जिनमें एक-एक में १०० गाँव और ६० से ७० हजार जनसंख्या प्राणी है । एक विकास टुकड़ी को पाँच गाँवों के हिस्से में बाँटा गया है । एक हिस्से में देहाती सनह पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता का दायरा है । मन् १९५२ में जो कार्यक्रम लागू किया गया, उसके दायरे में १३ करोड़ लोग भा गये ।

योजना में कार्य करने का ढग (Modus Operandi) — प्रत्येक योजना को पूरा करने में ३ वर्ष लगने तथा प्रत्येक योजना के पाँच भाग हूँ ।

(१) प्रारम्भिक विचार (Conception) — इसमें योजना के लिए क्षेत्र का चुनाव तथा उसका आर्थिक मापन एवं आयोजन किया जाता है । इस कार्य के लिए ३ मास की अवधि निर्धारित है ।

(२) प्रारम्भिक सामग्री जुटाना (Initiation)—कार्यकर्ताओं के लिए अध्यायी यात्राएँ बनवाना, कार्यक्षेत्र में शबाद के साधन स्थापित करना तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए ६ मास की अवधि निर्धारित है ।

(३) कार्य संचालन (Operation)—योजना की सम्पूर्ण क्रियाप्राप्ति के संचालन के लिए १८ मास रखे गये हैं ।

(४) एकीकरण (Consolidation)—कार्य की समाप्ति के लिए ६ मास रखे गये हैं ।

(५) अन्तिम कार्यवाही (Finalisation)—अन्तिम कार्यवाही के लिए ३ मास निर्धारित हैं ।

योजना का प्रवर्ध—सामुदायिक योजनाओं का प्रवर्ध निम्न प्रकार में किया जाता है :—

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम सामुदायिक विकास मन्त्रालय (Ministry of Community Development) द्वारा चालित किया जाता है । इस सम्बन्ध में प्राधारभूत नीति के जो जो मामल होते हैं, वे एक केन्द्रीय समिति के समुहसंग्रहित किये जाते हैं ।

१. केन्द्रीय स्तर पर नीति सम्बन्धी कार्यों में दिशा दर्शन कराने के लिए केन्द्रीय समिति (Central Committee) है । योजना आयोग के सदस्य इस समिति में सदस्य हैं और भारत के प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । इस समिति की सहायता के लिए एक परामर्शदाता समिति है जिसमें भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी हैं । योजनाओं का कार्य-संचालन करने के लिए प्रशासक (Administrator) है जो केन्द्रीय समिति का सचिव होता है । इस समय श्री एस० के० डे (S. K. Dey) प्रशासक का कार्य कर रहे हैं ।

२. राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक-एक 'राज्य-विकास समिति' है जिसके सदस्य राज्य के विकास-मंत्री, कृषि और सिंचाई मंत्री, वित्त मंत्री हैं और राज्य का प्रधान मंत्री अध्यक्ष होता है । कार्य-संचालन का मुख्य अधिकारी विकास प्रायुक्त होता है जिसकी सहायता एक परामर्शदाता समिति होती है । विकास प्रायुक्त (Development Commissioner) राज्य विकास समिति का सचिव होता है ।

३. जिला स्तर पर एक जिला विकास समिति है जिसके सदस्य विभाग विभागों के प्रतिनिधि होते हैं और कलेक्टर अध्यक्ष होता है । जिसे या विकास प्रमुख इस समिति का सचिव होता है और उसे सहायक कलेक्टर के अधिकार प्राप्त होते हैं ।

४. योजना-स्तर पर उनके द्वारा कार्य-संचालन करने वाला योजना प्रवर्ध अधिकारी (Project Executive Officer) है जो प्राथमिक सामुदायिक कार्य सम के लिए उत्तरदायी होता है । इसके अनुरित, एक योजना परामर्शदाता समिति होती है । इस समिति के सदस्य तसद तथा राज्य विधान मन्त्रालय के स्थानीय सदस्य जिन्हा बोर्ड के अध्यक्ष, प्रमुख आर्थिक नेता तथा किसानों के प्रतिनिधि होते हैं ।

योजना की वित्त व्यवस्था—द्वितीय योजना का म में सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए २०० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जबकि प्रथम योजना का

मे इस कार्यक्रम पर कुल १६.५ करोड़ डॉ० ही व्यय किये गये थे । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से वृत्तान्ति ला देने के प्रयास में भारत की अमेरिकी सरकार तथा कोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता मिलती रहती है । यत वर्षों में नकद सहायता ने अतिरिक्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विवेचना की सेवाएँ भी उपलब्ध हुई । कोर्ड प्रतिष्ठान हजारों योजना कार्यक्रमों के प्रतिष्ठान के लिए भारत की प्रारम्भ से ही सहायता देता आ रहा है । इसके लिए ५ जनवरी, १९५२ को भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका औद्योगिक सहयोग समझौता (Indo-U. S. Technical Corporation Agreement) हुआ था । योत्ते तौर पर अनावर्तक (Non-recurring) खर्चों में केवल ७५% और राज्य २५% तथा आवर्तक (Recurring) खर्चों में केवल ५०% और राज्य ५०% खर्च उठते हैं ।

सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रकार (Types of the Community Development Projects) — सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य योजना के प्रकार हैं :—

१. आधारभूत ग्रामीण सामुदायिक विकास योजनाएँ (Basic Type Rural Community Development Projects) — प्रत्येक आधारभूत ग्रामीण सामुदायिक योजना पर तीन वर्षों में ६५ लाख रुपया व्यय हुए और इसमें ३०० गाँव तथा २ लाख की जन-संख्या है । हमारी विकास योजनाएँ इस प्रकार की ही हैं ।

२. मिश्रित सामुदायिक विकास योजनाएँ (Composite Type Community Development Projects) — प्रत्येक मिश्रित योजना पर १११ लाख रुपया व्यय किया गया और इसमें गाँवों के लिए सहरी सुविधाएँ प्राप्त की जाती हैं ।

आलोचना (Criticism) — सामुदायिक योजनाओं की कड़ी आलोचनाएँ की गई । विरोधानाथे, भाषार्थ रूपरानी, प्रो० कुमारस्वामी जैसे व्यक्ति भी इनसे सहमत नहीं हैं । मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना और ग्राम-विकास योजनाओं का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है ।

(२) प्रत्येक योजना तीन वर्षों में पूर्ण की जायगी । योजना के समस्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह समय बहुत कम है ।

(३) इन योजनाओं की कार्यान्वित करने में अमेरिका की सहायता ली जा रही । परन्तु, देश के स्वाभिमान और स्वतन्त्र विकास में यह हानिकारक सिद्ध होगी ।

(४) विदेशी धार्मिक सहायता से हमारी विदेशी-नीति पर प्रतिकूल प्रभाव होगा ।

(५) विदेशी विशेषज्ञ हमारे ग्राम-जीवन से अनभिज्ञ होने के कारण गाँवों में खार करते में असफल रहेंगे ।

(६) सामुदायिक योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि बहुत ही अधिक है । हि सम्पूर्ण देश को ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाय, तो १,००० करोड़ रुपया खर्च की व्यय करना पड़ेगा । भारत के ग्राम धार्मिक साधनों में से इतनी बड़ी राशि न योजनाओं पर व्यय करना असम्भव-ना प्रतीत होता है ।

(७) राज्य-सरकारों के लिए भी इन योजनाओं के प्रति अपने हितों को राखि व्यवस्था करना कठिन है ।

(८) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी नर्मन्तरी ही नियुक्त किये गये हैं जो अपनी पाँचवींरी मनोवृत्ति के कारण जनता में सदस्य उत्साह और सहयोग की भावना को जाग्रत नहीं कर सकेगे ।

सामुदायिक योजनाओं का भविष्य (Future of Community Projects)—उपरोक्त दोषों के होने हुए भी सत्य ही इसके विरुद्ध धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ग्रामी कार्य प्रयोगात्मक व्यवस्था में ही है। वर्षों की सद्व्यवस्था और सक्रियता की गहरी नींव से छुटकारा दिताने के लिये समय और धन की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये योजनाएँ अपने प्रकार की पहली योजनाएँ हैं जो प्रथम बार भारत में प्रस्तुत की गई हैं। अभी भी इनके द्वारा लाभ प्राप्ति की बहुत गुआइश है। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं को सफल बनाने में सरकार को हार्दिक सहयोग दें और हम सब मिल कर काम करें। इस सम्बन्ध में सामुदायिक योजनाओं के प्रचारक ने ठीक ही कहा है—“समुद्रि ने तब कोई सुगम उपाय नहीं है। हम सबको कठिन परिश्रम करना होगा”¹

राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service)—‘ग्रामिक सन्न उपजाओ’ ज्ञान समिति ने यह प्रस्ताव रखा था कि ऐसा बड़ा राष्ट्रीय संगठन बनाया जाये जिसके द्वारा प्रत्येक किसान तक पहुँचा जा सके एवं देशी विकास का काम किया जा सके जो देश में विकास में हाथ बँटावे।

केन्द्रीय समिति ने अपनी १३ अप्रैल १९५३ की बैठक में यह निश्चय किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यक्रम से मिला दिया जाय जिससे दोनों के समुक्त कार्यक्रम में १२,००० गाँव सर्वान् भारत की देशी जनसंख्या का एक चौथाई भाग देश में सुधार के कार्यक्रम में लाया जा सके। तदनुसार २ अप्रैल १९५३ को राष्ट्रीय विकास सेवा (National Extension Service) का उद्घाटन किया गया। पंचवर्षीय योजना काल में ७०० विकास-टुकड़ियों (Blocks) में गहरा विकास कार्यक्रम (Intensive Development Programme) और ५०० विस्तृत टुकड़ियों में जिनमें प्रत्येक विकास टुकड़ा १ block) में लगभग सौ गाँव हैं, विस्तृत विकास कार्यक्रम (Extensive Development Programme) लागू किया जाएगा। गहरे विकास के लिए सामुदायिक योजनाओं का कार्यक्रम और विस्तृत विकास के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सामुदायिक योजनाओं के गहरे विकास के पूर्व राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम लागू करना गहरे विकास के लिए वृष्ट भूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

पंचवर्षीय-योजना-काल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए १२,००० ग्राम स्तर कार्यकर्ता (Village level Workers) की आवश्यकता है जिनमें से ४,५०० से अधिक तो अप्रैल १९५४ के अन्त तक शिक्षा पा चुके थे शिक्षा केन्द्रों में तृप्ति की जा रही है।

1 “There is no short cut to prosperity. All of us have to put in our best efforts. A much greater responsibility lies on the government officials and on those associated with the planning work. The greatest need of the country at the moment is increase of production and co-ordinated developments.”

—The National Administrator of Community Projects

प्रगति—सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक उपाय के रूप में तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को एक साधन के रूप में घणनाया गया है जिनमें माध्यम से गाँवों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में प्रगति लाने का उद्देश्य रखा गया है। द्वितीय योजना काल के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के लिए २०० करोड़ ६० बी राशि निर्धारित की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सहाय निषांरित लिये गये थे, वे प्राप्त कर लिये गये हैं। संशोधित-निर्देशन के अनुसार मई १९६० तक सारा देश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाता है १ अप्रैल १९५६ तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में लगभग १७.३ करोड़ व्यक्तियों ने मुक्त ३ ३६.५१० गाँवों में जिनमें २,५४८ विकास खण्ड थे।

भूदान यज्ञ (Bhoodan Yagya)—“न्याय और समानता के आधार पर
 दिके हुए समाज में भूमि पर स्वतः अधिकार होता चाहिए । इसलिए हम भूमि को प्रिणा
 नहीं मान रहे हैं बल्कि उन गरीबों का हिस्सा मान रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के
 अधिकारी हैं ।”

निनीषा मावे

निनोया भावे

प्रारम्भिक—भूदान यज्ञ भूमि-वितरण समस्या को हट करने का गांधीवादी प्रहितसमय ढाँचा है। १०. नेहरू के शब्दों में “साधारण विनोद भावे द्वारा बताया गया भूदान आन्दोलन एक प्रातिष्ठानिक आन्दोलन है जो अहिंसात्मक प्रणाली से देश की मुख्य समस्या को हल करने का मार्ग खोजना चाहता है।” जमींदारों उन्मूलन आदि भूमि-सुधार के कई उपपन्न निष्कर्ष गये हैं। परन्तु उन सब में भूदान मात्र एक अभ्युपगम था। जमींदारों उन्मूलन से केवल बचको का ही लाभ पहुँचता है, भूमिहीन व्यक्ति उन्हें उल्लेख नहीं करते हैं। परन्तु भूदान मात्र भूमिहीन व्यक्तियों का एकमात्र सहारा है। इसके प्रतिरिक्त, भूदान मात्र आन्दोलन में जमींदारों उन्मूलन की भाँति भूमि वनपूर्वक या अनिवार्य रूप से नहीं भी जाती है और न नृ-स्वामियों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना पड़ता है। अतएव यह कृषि सुधार का एक अहिंसात्मक ढाँचा है। मोक्षदा वाणीय ने अनुसार “भूमि का देने का आन्दोलन जो कि आचार्य विनोद भावे द्वारा चलाया गया है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसने द्वारा भूमिहीन व्यक्ति को प्रथमर मितता है जो उसे सम्पत्ति प्राप्त नहीं हो सकती है।” गांधीवादी अर्थशास्त्री प्रो० एस० एन० चक्रवर्ती लिखते हैं कि “भूदान मात्र देश में अल्पपूर्ण भूमि सुधारों के लिए स्वाभाविक एवं अनुपम वातावरण उत्पन्न करने के लिए गौरवता के साथ सकल हूषा है। हमने भूदान को यह बता दिया है कि भूमि की समस्या दायित्व दान में भी सम्प्रधान हल की जा सकती है।” प्रजा समाजवादी दल ने नेता श्री जे० पी० सारास्वत के शब्दों में “यह आन्दोलन देश में भूमि सुधार की दशा में एक महान प्रयास है।”

1 The Planning Commission remarks "The movement for making gifts of land, which has been initiated by Acharya Vinoba Bhave, has special value for, it gives to the land less worker an opportunity not otherwise easily available to him"

2 Bhoodan Yagya has eminently succeeded in creating a healthy and favourable atmosphere for the introduction of far reaching land reforms in the country. It has demonstrated to the World that the land problem could be effectively solved through peaceful methods." Writes the Gandhian economist prof S N Agarwal

3 In the words of Shri J. P. Narain, the Praya Socialist Leader, "The movement is a giant stride in the direction of agrarian reforms in the country."

उद्देश्य—इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना बिम्बी खुल सरावी के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।

प्रारम्भ तथा प्रगति :—भूदान यज्ञ का प्रारम्भ आचार्य विनोबा भावे द्वारा १८ अगस्त १९५१ को हैदराबाद राज्य के तिलमाता जिले के पोचमण्णो गाँव में हुआ। घटना इस प्रकार है कि जब आचार्य भावे पोचमण्णो गाँव में एक सदा की भाँति मध्याह्न के पदवात अर्पण विचार प्रकट कर रहे थे, तब वहाँ के हरिजन निवासियों ने अपना दुःखड़ा बताते हुए ८० एकड़ भूमि की माँग की। सत ने उधो समय पूछा कि क्या कोई दाता है जो इस माँग को पूरी करेगा? कुछ समय की साँत के पश्चात् रामचन्द्रजी रेडो नामक एक विनायक हृदय जमींदार खड़ा हो गया और संत को १०० एकड़ भूमि अर्पण कर दी। आचार्य भावे ने तुरन्त उस भूमि को उन भूमिहीन हरिजनों को बाँट दिया जिन्होंने भूमि की माँग की थी। बस इस घटना से भूदान यज्ञ आन्दोलन को जन्म मिल गया।

आचार्य भावे के अहिंसात्मक आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि साठ दिन में १२,३१८ एकड़ भूमि उन्हें दान में प्राप्त हो गई। इस प्रकार भूदान यज्ञ की कल्पना देश और दुनिया के सामने आई जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। भारत के भूमिहीनों की शोचनीय दशा को देखकर आचार्य ने सन् १९५७ ई० तक ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का महान् संकल्प किया। फिर क्या था देश में आन्दोलन की गति तीव्र हुई और भावे ने दान प्राप्त करने में तन-मन लगा दिया। सैकड़ कार्यकर्त्ता छुट पड़े। १३ नवम्बर १९५१ को वे दिल्ली पहुँचे। इस बीच में उन्होंने १९,४३६ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली।

दिल्ली में कुछ दिन ठहर कर उन्होंने उत्तर-प्रदेश की यात्रा प्रारम्भ की। एक जगह के दादा दूसरा तिला लायने हुए वे अगस्त १९५२ में बाबो पहुँचे। इस समय तक १,०२,३६१ एकड़ भूमि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। कान्पुर में १४ मील दूरस्थ मेवापुरी ग्राम में देश भर के सर्वोच्च विचारकों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने ५० लाख एकड़ भूमि अगस्त १९५४ तक जमा करने का प्रण किया।

अब तब सन्त विनोबा अकेले ही पैदल यात्रा कर रहे थे, परन्तु मेवापुरी सम्मेलन के पदवान् कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी इस कार्य को उठाया और वे भूमि प्राप्ति के हेतु धूमने लगे जिनमें सर्वश्री सकरान देव, सन्त तुरडोजी, जयप्रकाश नारायण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। देश भर में एक बड़ी गँववा में भूदान समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। इस आन्दोलन की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में बड़ी सहायता मिल रही है। काठून द्वारा भूमि के दान को सुविधाजनक बनाने इन्होंने इस आन्दोलन को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन्होंने यज्ञ में जतन ली भूमि से दान की है, जैसे मध्यप्रदेश सरकार ने २ लाख एकड़ भूमि दान की है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान बिहार में गौका के राजा ने किया जो १,०२,००१ एकड़ भूमि का है। अकेले बिहार प्रान्त में सम्पूर्ण दान का दो तिहाई भाग एरिशन हुआ। यज्ञ में सम्पूर्ण एरिशन भूमि के मे अब तक केवल ५५,८८५ एकड़ भूमि का हो बितरण हुआ है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के प्रतिरिक्त श्रम, औजार, बैल, बीज आदि भी दिये जाते हैं जिसमें कृषि कार्य भी प्रारम्भ किया जा सके।

धीरे धीरे भूमि-दान के पदवान् लोगों का सम्पर्क दान, धर्म दान, धुडि दान, हाम दान और यहाँ तक कि विनोबाजी ने जीवन दान तक के विषय तैयार किया। जयप्रकाश

१०१०]

[अर्थशास्त्र का दिग्दर्शन]

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ ।

(रा० बो० १६५८)

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना ।

(रा० बो० १६५७)

(ङ) सामूहिक विकास योजनाएँ ।

(रा० बो० १६५७)

(च) भूदान आन्दोलन

(छ) पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ ।

६—देश की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम उद्योग क्यों वा क्या महत्त्व है ?

७—भारत में ग्रामिक आयोजन के क्या उद्देश्य हैं ?

(म० भा० १६५७)

८—भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य व बुटीर उद्योगों के विकास की क्या मुख्य रूप से रक्षा है ?

(म० बो० १६५७)

९—निम्नावृत्ति पर नोट लिखिए —

(नाथपुर १६५६)

(अ) भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रोजगार पर प्रभाव ।

(आ) सामुदायिक योजनाएँ ।

(रा० बो० हा० से० १६६१)